

प्रकाशक  
विश्वरजन,  
सरस्वती-सदन, मरूरी

प्रथम मस्करण मार्च, १९५०  
परिवर्धित दूसरा मस्करण १९५१  
सशोधित तृतीय मस्करण १९५६

मुद्रक  
कुरेन्द्र प्रिंटर्स प्राइवेट लि०,  
सदर बाजार, दिल्ली ।

## प्रारम्भिक शब्द

‘यूरोप का आधुनिक इतिहास’ के दूसरे संस्करण के समान इस तृतीय संस्करण में भी मैंने अनेक संशोधन किये हैं। मुझे आशा है कि पाठक इस नये संस्करण को पहले की अपेक्षा भी अधिक उपयोगी पाएंगे।

स्वतन्त्रता के बाद भारत में अन्य देशों का इतिहास पढ़ने की रुचि बढ़ रही है। ज्ञान, विज्ञान, राजनीतिक संगठन आदि के क्षेत्र में यूरोप अब भी ससार का अग्रणी है। संसार की आधुनिक सभ्यता का विकास यूरोप में ही हुआ है। अतः उसके इतिहास का अध्ययन न केवल विद्यार्थियों अपितु सर्वसाधारण पाठकों के लिये भी बहुत उपयोगी है। स्वतन्त्र भारत का अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्त्व निरन्तर बढ़ रहा है। इस कारण भी भारतीय पाठकों के लिये देश विदेश की आधुनिक प्रगति से परिचित रहना अत्यन्त आवश्यक है। इसी दृष्टि से मैंने इस पुस्तक में यूरोप का (उसके निमित्त से अन्य महत्त्वपूर्ण देशों का भी) १९५५ तक का इतिहास दे दिया है, जिसके कारण इस नये संस्करण की उपयोगिता और भी अधिक बढ़ गई है।

मुझे प्रसन्नता है कि पाठकों ने मेरे इस इतिहास को पसन्द किया है। पाठ-३ साल के स्वल्प काल में तीसरे संस्करण का प्रकाशित होना इसका स्पष्ट प्रमाण है। यद्यपि पिछले सालों में यूरोप के इतिहास पर अन्य भी अनेक पुस्तकें हिन्दी में प्रकाशित हो चुकी हैं, पर इस इतिहास का अपना जो विशिष्ट स्थान है, उसमें उनसे कोई अन्तर नहीं आया। नये संस्करण में अनेक अध्यायों व प्रकरणों के क्रम में जो कतिपय परिवर्तन किये गये हैं, उनको पाठक अधिक उपयोगी पाएंगे, यह मेरा विश्वास है।

—सत्यकेतु विद्यालकार

## निवेदन

स्वतन्त्र भारत के आगमन-विधान में यह बात स्वीकृत कर ली गई है, कि हिंदी भारत की राष्ट्र-भाषा है, और अग्रे में अग्रे पन्द्रह सालों में भारत की गवर्नर, अपने प्रायः सभी कार्य हिन्दी में करने लगेगी। भाषा-युक्त के अन्तर्गत अनेक राज्य हिन्दी को अपनी राजभाषा स्वीकार कर चुके हैं। अनेक विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा भी हिन्दी के माध्यम द्वारा दी जान लगी है।

इस दशा में हिन्दी के लेखकों व प्रकाशकों पर विचार उत्तरदायित्व आ गया है। अब यह आवश्यक हो गया है, कि इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति, रसायन, भौतिक विज्ञान आदि सभी आधुनिक विषयों पर उच्च में उच्च ज्ञान हिन्दी में उपलब्ध हो। हिन्दी का साहित्य-भण्डार विविध विज्ञानिक व आर्थिक विषयों की उच्च श्रेष्ठ की पुस्तकों में उतना अधिक परिपूर्ण हो जाय, कि किसी को यह लगे कि अज्ञान नहीं, कि साहित्य की कमी के कारण हिन्दी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाने व सरकारी कार्यों के लिये प्रयोग करने में रुकावट होती है। हमारा प्रयत्न यह है कि विविध विषयों पर उच्च श्रेष्ठ की पुस्तकों हिन्दी में तैयार करके उन्हें प्रकाशित करें। 'योगेय का आधुनिक इतिहास' उनी माग पर हमारा पहला उद्देश्य था। हमें इस बात की प्रशंसा है, कि हिन्दी-मन्त्र ने हमारी इस पुस्तक का समुचित आदर किया। इस इतिहास का पहला संस्करण हमने मार्च, १९५० में प्रकाशित किया था। वह अठारह मास के स्वल्प मात्र में बिक गया था, और नवम्बर, १९५१ में उसका द्वितीय संशोधित व परिष्कृत संस्करण हमने प्रकाशित किया था।

अब हम इस इतिहास के तृतीय (संशोधित व परिष्कृत) संस्करण को पाठकों की सेवा में उपस्थित कर रहे हैं। इसमें लेखक ने पुस्तक का भौतिक संशोधन कर दिया है, और अनेक स्थलों पर पाठ्य-सामग्री को घटा बढ़ा दिया है।

विद्यार्थियों की सुविधा को दृष्टि में रखकर हम नये संस्करण को तीन विभिन्न प्रकाशकों में प्रकाशित कर रहे हैं। आगरा यूनिवर्सिटी ने वी० ए० की परीक्षा के दो खण्ड कर दिये हैं। प्रथम खण्ड में १७८९ से १८७१ तक का इतिहास रखा गया है, और दूसरे खण्ड में १८७१ से १९३९ तक का। इसीलिये हमने भी इस इतिहास के दो भागों में क्रमशः १७८९ से १८७१ तक का और १८७१ से १९३९ तक का इतिहास दिया है। अन्य यूनिवर्सिटियों के विद्यार्थियों की आवश्यकता को दृष्टि में रखकर पुस्तक ऐसे दो भागों में भी प्रकाशित की गई है, जिनमें पूर्ववत् क्रमशः १७८९ से १९१४ तक का और १९१४ से १९५५ तक का इतिहास रहे। पुस्तकालयों के लिये सम्पूर्ण ग्रन्थ को एक जिल्द में भी प्रकाशित किया गया है।

इस इतिहास के तृतीय संस्करण में १९५५ तक का यूरोपियन इतिहास दे दिया गया है, जिसके कारण इस पुस्तक की उपयोगिता और भी अधिक बढ़ गई है।

सरस्वती सदन, मसूरी

# विषय-सूची<sup>1</sup>

विषय

पृष्ठ

## पहला भाग

### पहला अध्याय—विषय-प्रवेश

१७

- १ प्रस्तावना
- २ प्राचीन काल
- ३ ईसाई धर्म का प्रादुर्भाव
- ४ मध्यकालीन यूरोप
- ५ क्रूमेड।
६. चर्च की स्थिति
- ७ मध्यकाल में यूरोप की दशा

### दूसरा अध्याय—नवयुग का सूत्रपात

४७

- १ यूरोप का पुन जागरण
- २ धार्मिक सुधारणा
- ३ नये प्रदेशों की खोज
- ४ स्वेच्छावारी निरकुश राजा
- ५ अमेरिका में यूरोपियन उपनिवेश
- ६ अमेरिका की स्वाधीनता
- ७ व्यापारिक क्रांति

### तीसरा अध्याय—अठारहवीं सदी के अन्त में यूरोप की दशा

६३

- १ विविध राज्य
- २ शक्ति-समत्तुल्य का सिद्धान्त
- ३ यूरोप की दशा

### चौथा अध्याय—फ्रांस में राज्यक्रान्ति का प्रारम्भ

७८

- १ राज्यक्रान्ति में पूर्व फ्रांस की दशा
- २ क्रान्ति की भावना का प्रादुर्भाव
- ३ मोलह्वे लुई का शासन
- ४ क्रान्ति का धीगणेश

### पांचवा अध्याय—राज्यक्रान्ति की प्रगति

१०३

- १ वैध राजसत्ता की स्थापना का प्रयत्न
- २ राजसत्ता का अन्त



छठा अध्याय—क्रान्तिकारी फ्रांस का यूरोप के साथ सघर्ष	११७
१ क्रान्ति के विरुद्ध जिहाद	
२ आतंक का राज्य	
३ डाइरेक्टरी का शासन	
सातवा अध्याय—नैपोलियन का उत्कर्ष	१३६
१ नैपोलियन का अभ्युदय	
२ पेरान काँमरु के रूप में नैपोलियन का शासन	
३ व्यवस्था की स्थापना	
४ सम्राट् नैपोलियन	
आठवा अध्याय—सम्राट् नैपोलियन	१४६
१ नवीन युद्धों का प्रादुर्भाव	
२ नैपोलियन का पतन	
३ नैपोलियन का उन्निहान में स्थान	
नवा अध्याय—यूरोप की नई व्यवस्था	१७०
१ राज्यक्रान्ति के परिणाम	
२ नैपोलियन के बाद यूरोप की समस्याएँ	
३ मेटरनिंग	
४ वीएना की कांग्रेस	
दसवा अध्याय—प्रतिक्रिया का काल	१८४
१ अन्तर्राष्ट्रीयता की ओर पहला पग	
२ फ्रांस में प्रतिक्रिया का युग	
३ अन्य यूरोपियन देशों में प्रतिक्रिया का काल	
ग्यारहवा अध्याय—राजनीतिक क्रान्तियों का फिर से प्रारम्भ	१९५
१ प्रतिक्रिया के काल का अन्त	
२ स्पेन की राज्यक्रान्ति	
३ पोर्तुगाल में क्रान्ति की भावना	
४ इटली में क्रान्ति की लहर	
५ अन्य देशों में क्रान्ति का प्रारम्भ	
बारहवा अध्याय—क्रान्ति की दूसरी लहर	२०७
१ फ्रांस की द्वितीय राज्यक्रान्ति	
२ बेल्जियम की स्वतन्त्रता	
३. पोलैण्ड का अग-भग और १८३० की क्रान्ति का उस पर प्रभाव	
४. अन्य राज्यों पर राज्यक्रान्ति का प्रभाव	
तेरहवा अध्याय—औद्योगिक क्रान्ति	२२२
१ आर्थिक परिवर्तन	
२. कृषि की उन्नति	

३	वैज्ञानिक आविष्कार	
४	औद्योगिक क्रान्ति के परिणाम	
५	अन्य देशों में औद्योगिक क्रान्ति	
चौदहवा	अध्याय—राष्ट्रीयता की भावना का विकास	२३५
१.	राष्ट्रीयता का प्रादुर्भाव	
२	१८१५ के बाद राष्ट्रीयता की भावना	
३.	नये शासन विधानों का निर्माण	
पन्द्रहवा	अध्याय—फ्रांस की तीसरी राज्यक्रान्ति	२४०
१	राजसत्ता का अन्त	
२	क्रान्ति की प्रगति	
३	फ्रांस की द्वितीय रिपब्लिक	
सोलहवा	अध्याय—क्रान्ति की तीसरी लहर	२४६
१	आस्ट्रियन साम्राज्य में क्रान्ति का प्रारम्भ	
२	जर्मनी में क्रान्ति का प्रभाव	
३	इटली में क्रान्ति की लहर	
४	अन्य देशों पर क्रान्ति का प्रभाव	
सत्रहवा	अध्याय—नैपोलियन तृतीय का शासन	२६३
१	सम्राट् नैपोलियन तृतीय का अभ्युदय	
२	सम्राट् नैपोलियन का शासन	
३	साम्राज्य विस्तार	
४	विदेशी युद्ध और पतन	
अठारहवा	अध्याय—इटली की स्वाधीनता	२७३
१	स्वाधीनता के लिये संघर्ष	
२	स्वाधीनता संग्राम का प्रारम्भ	
३	राष्ट्रीय एकता की स्थापना	
उन्नीसवा	अध्याय—जर्मनी का संगठन	२८६
१	राष्ट्रीय एकता का प्रादुर्भाव	
२	विस्मार्क का अभ्युदय	
३	डेन्मार्क के साथ युद्ध	
४	आस्ट्रो-प्रशियन युद्ध और उत्तरी जर्मन राज्यसंघ का निर्माण	
५	फ्रैंको-प्रशियन युद्ध और मजबूत जर्मन साम्राज्य की स्थापना	
बीसवा	अध्याय—इंग्लैण्ड में सुधार का काल	३०३
१	पुराना इंग्लैण्ड	
२	शासन में सुधार	
३	इंग्लैण्ड की जनन-वृद्धि	
४	अन्य सुधार	

- ५ धार्मिक स्वतन्त्रता और शिक्षा प्रसार
- ६ मजदूरी की दशा में मुद्दा
- ७ व्यापारिक नीति

इक्कीसवा अध्याय—आस्ट्रिया-हंगरी और रूस की प्रगति ३११

- १ आस्ट्रिया-हंगरी का संगठन
- २ रूस में नवयुग का प्रारम्भ
- ३ रूस में एतन्त्र स्वेन्डाचागी मन्त्राट्टा का शासन
- ४ रूस में मुद्दारा का प्रारम्भ

बाईसवा अध्याय—टर्की और बालकन प्रायद्वीप के विविध राज्य ३२५

- १ उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ में टर्की की दशा
- २ बालकन राज्यों में राष्ट्रीय जागृति का प्रागुर्भाव
- ३ बालकन प्रायद्वीप में अन्तर्गर्भीय प्रथम का प्रारम्भ
- ४ कीमियन युद्ध

तेईसवा अध्याय—सयुक्तराज्य अमेरिका ३३६

- १ अमेरिका का प्रसार
- २ गृह युद्ध
- ३ उन्नीसवीं सदी में अमेरिका की उन्नति
- ४ सयुक्तराज्य अमेरिका की राजनीति

चौबीसवा अध्याय—साम्यवाद की नई लहर ३५१

- १ सामाजिक संगठन सम्बन्धी नये विचार
- २ साम्यवाद का प्रारम्भ
- ३ कार्ल मार्क्स

पच्चीसवा अध्याय—पुराना और नया साम्राज्यवाद ३६१

- १ यूरोप का मध्यकालीन साम्राज्यवाद
- २ नवीन साम्राज्यवाद का प्रारम्भ
- ३ ईसाई धर्म प्रचारक और साम्राज्यवाद
- ४ साम्राज्य निर्माण के लिये संघर्ष

छवीसवा अध्याय—ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार ३७६

- १ ब्रिटिश साम्राज्य
- २ औपनिवेशिक राज्य-कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, दक्षिणी अफ्रीका
- ३ भारतवर्ष
- ४ क्राउन कोलोनी

सत्ताईसवा अध्याय—यूरोप का विस्तार ३८७

- १ यूरोप और एशिया
- २ रूस का एशिया में प्रसार
- ३ यूरोपियन जातियों का चीन में प्रवेश

४ दक्षिण पूर्वी एशिया	
५ यूरोपियन जातियों का अफ्रीका में प्रवेश	
अठारहवाँ अध्याय—विज्ञान, साहित्य और कला	४०४
१. वैज्ञानिक उन्नति	
२ साहित्य	
३ कला	

## द्वितीय भाग

उनतीसवाँ अध्याय—फ्रांस में तृतीय रिपब्लिक का शासन	४१७
१ फ्रांस में रिपब्लिक की स्थापना	
२ रिपब्लिक का शासन	
३ चर्च का राज्य में पथक् होना	
४ फ्रेंच साम्राज्य का विस्तार	
५. रिपब्लिक का शासन- विधान और राजनीतिक दल	
६ फ्रांस की परराष्ट्र नीति	
७ फ्रांस की प्रगति	
तीसवाँ अध्याय—जर्मन साम्राज्य की प्रगति	४४०
१ प्रशिया का शासन-विधान	
२ जर्मन साम्राज्य का शासन-विधान	
३ बिस्मार्क का कार्यकाल	
४ विलियम द्वितीय का शासन	
इकतीसवाँ अध्याय—रूस का उत्कर्ष	४५६
१ एशिया में रूस का विस्तार	
२ स्वाधीनता के लिये घोर संघर्ष	
३ रूस में वैध राजसत्ता का विफल प्रयत्न	
बत्तीसवाँ अध्याय—तुर्क साम्राज्य का ह्रास और बालकन राज्यों की स्वाधीनता	४६६
१ बालकन राज्यों की स्वाधीनता	
२ टर्की की विविध समस्याएँ	
३ टर्की में राज्यक्रान्ति और बालकन युद्ध	
४ पूर्वी यूरोप और तुर्क साम्राज्य में यूरोपियन राज्यों की प्रतिद्वन्द्विता	
त्र्तीसवाँ अध्याय—यूरोप के अन्य राज्यों की प्रगति	४८६
१ इटली	
२ आस्ट्रिया-हंगरी	
३ स्पेन	

- ४ पोर्तुगाल
- ५ हावैण्ड
- ६ वेल्जियम
- ७ स्विट्जरलैण्ड
- ८ डेन्मार्क
- ९ स्वीडन और नार्वे

चौतीसवा अध्याय—उगलैण्ड और उसके साम्राज्य की प्रगति ५०६

- १ नवीन गुधार
- २ उगलैण्ड की यागन-प्रति
- ३ धार्मिक स्वतन्त्रता और अन्य गुधार
- ४ आयलैण्ड की स्वाधीनता
- ५ साम्राज्य विस्तार
- ६ ब्रिटिश साम्राज्य का एक नव बनाने की समस्या

पैतीसवा अध्याय—अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति व साम्राज्य सम्बन्धी संघर्ष ५४०

- १ त्रिगुट का निर्माण
- २ फ्रांस और रूस का गुट
- ३ जर्मनी और उगलैण्ड
- ४ जापान का उ-कर्ष
- ५ चीन में साम्राज्यवादी देशों का हस्तक्षेप
- ६ रूस और जापान का युद्ध
- ७ उपसंहार

छत्तीसवा अध्याय—महायुद्ध के कारण ५६१

- १ आधारभूत कारण
- २ सहायक कारण
- ३ संघर्ष का श्रीगणेश
- ४ युद्ध का तात्कालिक कारण
- ५ युद्ध से पूर्व के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध

सैतीसवा अध्याय—महायुद्ध का इतिवृत्त ५८६

- १ युद्ध का विस्तार
- २ महायुद्ध की प्रगति
- ५ महायुद्ध का दूसरा वर्ष
- ४ अमेरिका का महायुद्ध में प्रदेश
- ५ महायुद्ध के आखिरी दो वर्ष
- ६ महायुद्ध का अन्त

अडतीसवा अध्याय—शान्ति की स्थापना ६०८

- १ शान्ति सम्बन्धी समस्याएँ

२	युद्ध के मध्य में शान्ति के प्रयत्न	
३	पेरिस की शान्ति परिषद्	
४	जर्मनी के साथ वर्मिय की सन्धि	
५	आस्ट्रिया के साथ सा जर्म की सन्धि	
६	बल्गेरिया के साथ नवीयरी की सन्धि	
७	हंगरी के साथ त्रियानो की सन्धि	
८	टर्की के साथ सेव्र की सन्धि	
९	अल्पसख्यक जातियों की समस्या	
उनतालीसवा	अध्याय—महायुद्ध के परिणाम	६२८
१.	जन और धन का विनाश	
२	राजनीतिक परिणाम	
३	महायुद्ध के आर्थिक व सामाजिक परिणाम	
चालीसवा	अध्याय—राष्ट्रसंघ (लीग आफ नेशन्स)	६३८
१	अन्तर्राष्ट्रीय भावना का विकास	
२	राष्ट्रसंघ	
३	अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय	
४	अन्तर्राष्ट्रीय नजदूर संघ	
५	राष्ट्रसंघ के विविध कार्य	
इकतालीसवा	अध्याय—जर्मनी का पुन निर्माण	६५०
१	जर्मनी में क्रान्ति	
२	जर्मनी का नया शासन विधान	
३	जर्मनी में रिपब्लिक का शासन	
४	लोकानों की सन्धि	
बयालीसवा	अध्याय—यूरोप के नये और परिवर्तित राज्य	६६२
१	आस्ट्रिया-हंगरी का अध पतन	
२	हंगरी	
३	चेकोस्लोवाकिया	
४	यूगोस्लाविया	
५.	रुमानिया	
६	पोलैण्ड	
७	फिनलैण्ड	
८	एस्थोनिया	
९	लैटविया	
१०	लिथुनिया	
११	युक्रेनिया	
१२.	बल्गेरिया	

१३ अन्वेषिता

१४ गीत

तैतालीसवा अध्याय—रूस की राज्यक्रान्ति

६८७

१ क्रान्ति में पूर्व स्वरूप की दशा

२ क्रान्ति के कारण

३. पहली राज्यक्रान्ति

४ बोल्शेविक पार्टी

५ बोल्शेविक क्रान्ति

६ ब्रम्ह-विद्रोह की शक्ति

७ गृह-युद्ध

८ बोल्शेविक सरकार

त्रिंशतीसवा अध्याय—टर्की का अभ्युदय

७१२

१ मुल्तनन का अन्त

२ कमाल पाशा

३ टर्की में राज्यक्रान्ति

४ राज्यक्रान्ति की प्रगति

५ लोजान और मोन्त्रो की सन्धि

पैंतालीसवा अध्याय—ब्रिटिश साम्राज्य की प्रगति

७२१

१ साम्राज्य में वृद्धि

२. धातुलै ड की स्वाधीनता

३ इजिप्ट के माय मघर्ष

४ पैलेस्टाइन

५ भारत में स्वराज्य आन्दोलन

६ ब्रिटेन का शासन

७ औपनिवेशिक राज्यों की स्वतन्त्रता

छयालीसवा अध्याय—फ्रांस का उत्कर्ष

७५१

१ आन्तरिक शासन

२ अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति

३. आल्सेस-लारेन की समस्या

४ सीरिया

सैंतालिसवा अध्याय—आर्थिक सकट

७६३

१ हरजाने की समस्या

२. अन्तर्राष्ट्रीय देनदारिया

३ अन्य आर्थिक समस्याएँ

४ आर्थिक सकट का प्रादुर्भाव

अडतालीसवा अध्याय—अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा की समस्या	७७८
१ राष्ट्रमय की निर्बलता	
२ सुरक्षा के साधनों की खोज	
३ नि शस्त्रीकरण की समस्या	
उत्तचासवाँ अध्याय—इटली में फैसिज्म का प्रारम्भ	७९३
१. फैसिज्म में पूर्व इटली की दशा	
२ मुमोलिनी	
३ फैसिस्ट शासन	
४ फैसिस्ट सिद्धान्त	
५ नई आर्थिक व्यवस्था	
६ फैसिस्ट शासन में इटली की उन्नति	
पन्नासवा अध्याय—नाजी जर्मनी	८०६
१ हिटलर का उदय	
२ नाजीज्म की सफलता के कारण	
३ नाजी व्यवस्था	
४ जर्मनी की सर्वनौमुखी उन्नति	
५ विदेशी राजनीति	
इकविनवाँ अध्याय—लोकतन्त्रवाद का ह्रास और फैसिज्म का उत्कर्ष	८२२
१ लोकतन्त्रवाद का ह्रास	
२ स्पेन में राज्यक्रान्ति	
३ फ्रांको का उत्कर्ष	
४ आस्ट्रिया	
५ अन्य राज्यों में लोकतन्त्रवाद का ह्रास	
बावनवा अध्याय—बोल्लेविक रुम	८३७
१ स्टालिन का उदय	
२ नई आर्थिक नीति	
३ कृषि सम्बन्धी क्रान्ति	
४ व्यवसायों का मंचालन	
५ पञ्चवार्षिक योजनाएँ	
६ वहिष्कार का अन्त	
७ शासन-विधान	
८ विरोधियों का विनाश	
९ रुम की उन्नति	
१० रुम में धर्म का स्थान	
तरपनवा अध्याय—अन्तर्राष्ट्रीय मात्स्यन्याय	८६०
१ जापान और चीन	



- २ इटली का साम्राज्य विस्तार
- ३ आस्ट्रियन गिप्लिड का अन्त
- ४ चेकोस्लोवाकिया का अन्त
- ५ अल्बेनिया पर इटली का कब्जा

### जीवनवा अध्याय—विश्व-संग्राम का श्रीगणेश

८७५

- १ युद्ध की पैगामी
- २ नई गटवन्दिया
- ३ युद्ध का श्रीगणेश
- ४ युद्ध का कारण

### तीसरा भाग

### पञ्चपनवा अध्याय—विश्व-संग्राम का उत्तिवृत्त

८८५

- १ पोलैण्ड का अन्त
- २ फिनलैण्ड पर रूसी आक्रमण
- ३ नावों और डेनमार्क का अन्त
- ४ हालेण्ड और बेल्जियम का अन्त
- ५ फ्रांस की पराजय
- ६ ब्रिटन पर आक्रमण
- ७ युगोस्लाविया और ग्रीस का अन्त
- ८ अफ्रीका पर आक्रमण
- ९ सीरिया, ईराक और ईरान
- १० रूस पर आक्रमण
- ११ जापान और अमेरिका का युद्ध में प्रवेश
- १२ पूर्वी एशिया पर जापान का प्रभुत्व
१३. पश्चिम में विश्व-संग्राम की प्रगति
- १४ रूस में घमासान युद्ध
- १५ वारसा की दुर्घटना
१६. इटली का पतन
- १७ स्वातन्त्र्य-आन्दोलन
- १८ पूर्वी एशिया की लड़ाइयाँ

### छप्पनवा अध्याय—विश्व-संग्राम का अन्त

- १ फ्रांस की स्वाधीनता
२. जर्मनी का अन्तिम प्रयत्न
- ३ जर्मनी की पराजय
- ४ जापान की पराजय
- ५ अमानुषिक युद्ध

६ नाजी शक्ति की पराजय के कारण

७. विज्व-पग्राम के परिणाम और यूरोप की नई राजनीति

सत्तावनवा अध्याय—शांति की स्थापना और यूरोप की नई व्यवस्था

१ समस्याएँ

२ सहायक समस्या

३ नई व्यवस्था के आदर्श

४ संयुक्त राज्यसंघ की स्थापना

५ परास्त देशों से सन्धिया

६ जर्मनी की नई व्यवस्था

७ आस्ट्रिया की व्यवस्था

८ जापान की व्यवस्था

९ पूर्वी यूरोप

१० रूस

११ अन्तर्राष्ट्रीय मुकदमे

१२ मानव योजना

१३ अर्थमंडल का प्रारम्भ

अठावनवा अध्याय—पाञ्चात्य साम्राज्यवाद का ह्रास

१ ब्रिटिश साम्राज्य

२ हालैंड का साम्राज्य

३ फ्रांस का साम्राज्य

उन्सठवा अध्याय—वर्तमान यूरोप

१ फ्रांस में चतुर्थ रिपब्लिक का शासन

२ ग्रेट ब्रिटेन की प्रगति

३ रूस

४ रूस का प्रभाव-क्षेत्र

५ चीन में कम्यूनिस्ट प्रभाव

६ इटली की प्रथम रिपब्लिक

७ वर्तमान जर्मनी

८ संयुक्त राज्यसंघ और अन्तर्राष्ट्रीय समस्याएँ

भाटवा अध्याय—वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति

१ अन्तर्राष्ट्रीय गुटबन्धियाँ

२ यूरोप की राजनीति का नया स्वरूप

३ उपसंहार

अपने प्रातः स्मरणीय स्वर्गीय पिता

श्री आशाराम

और

अपनी पूजनीया स्वर्गीय माता

श्रीमती रामरक्खी देवी

की

पुण्य स्मृति में

# यूरोप का आधुनिक इतिहास

## पहला अध्याय विषय प्रवेश

### १ प्रस्तावना

इस इतिहास का प्रारम्भ हमने सन् १७८९ से किया है। इस साल फ्रांस में राज्यक्रान्ति का सूत्रपात हुआ था। इस घटना को हुए अभी डेढ़ सौ वर्ष से कुछ ही अधिक समय हुआ है। डेढ़ सदी के इस थोड़े से समय में यूरोप ने जो असाधारण उन्नति की है, उसे देखकर आश्चर्य होता है। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, व्यावसायिक, धार्मिक—सभी क्षेत्रों में यूरोप में एक युगान्तर उपस्थित हो गया है। अठारहवीं सदी के अन्तिम भाग में प्रेच राज्यक्रान्ति के श्रीगणेश के समय यूरोप में एक भी देश ऐसा नहीं था, जहाँ लोकतन्त्र शासन हो। प्रायः सब देशों में वंशक्रम से आये हुए एकतन्त्र स्वेच्छाचारी निर-बुद्ध राजा राज्य करते थे। उनका शासन सम्बन्धी मुख्य सिद्धान्त यह था—“हम पृथ्वी पर ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, और हमारी इच्छा ही कानून है।” समाज में ऊँच-नीच का भेद विद्यमान था। कुछ लोग ऊँचे समझे जाते थे, क्योंकि वे कुलीन घर में पैदा हुए थे। दूसरे लोग नीचे समझे जाते थे, क्योंकि वे जन्म से नीचे थे। कल कारखानों का विकास उस समय नहीं हुआ था। रेल, मोटर, तार, हवाई जहाज आदि का नाम तक भी शोर्ट नहीं जानता था। सूत कातने के लिये तख्ते और चरख काम में आते थे। घोड़े या बैल में चलनेवाली गाड़ियाँ सवारी के काम आती थीं। समुद्र में जहाज चलते थे पर भाप व बिजली में नहीं, अपितु पाल व चप्पुओं से। कारीगर लोग अपने घर में बैठ कर पुराने ढंग के मोटे औजारों में काम करते थे। यान्त्रिक-शक्ति में चलनेवाले विशाल कारखाने यूरोप में उस समय तक नहीं बने थे। स्त्रियों को स्वाधीनता नहीं मिली थी। उनका कार्य-क्षेत्र घर था और घर में बाहर वे बहुत कम दिखाई देती थीं। धर्म के मामले में लोग बड़े सकीन और अमहिष्णु थे। प्रोटेस्टेन्ट और रोमन कैथोलिक लोगों का मधुप अभी समाप्त नहीं हुआ था। आजकल के ज्ञान विज्ञान उस समय विकसित नहीं हुए थे। जिन बातों पर आज यूरोप गर्व करता है, उनका प्रादुर्भाव उस समय तक नहीं हुआ था।

डेढ़ सदी के इस थोड़े से समय में कितना भारी परिवर्तन हो गया है। इस बीच में पाश्चात्य समाज ने कौसी आश्चर्यजनक उन्नति की है। आज यूरोप में एक भी ऐसा देश नहीं है, जहाँ किसी न किसी रूप में लोकतन्त्र शासन विद्यमान न हो। वंशक्रम में आए

हुए निरंकुश गजाओ के स्वेच्छान्तारी शासन आज यूरोप में नाट हो गये हैं। 'गजाओ का देवी अधिकार' अब स्वतन्त्र की बात हो गया है। समाज में ऊँच-नीच का भेद मिट गया है। जन्म के कारण न आज कोई ऊँचा है, न नीचा। रेल, तार, मोटर, हवाई जहाज और रेडियो ने देश और ताल पार कैंसी अद्भुत विजय पाप्न ली है। आज ब्रम्बई में बंठे लन्दन में बात की जा सकती है। दिल्ली में पेगिंग का मगीन गुना जा सकता है। दो दिन में हजारों मील की दूरी पार कर भान में यूरोप पहुँच सकते हैं। आज कपड़ा बनाने के लिये तकरी, चरखे व कर्पे की आवश्यकता नहीं रही। आज कपड़े की ऐसी मिल विद्यमान है, जो एक दिन में लाखों गज कपड़ा तैयार करती है। कल-कारखानों के विकास ने यूरोप के आर्थिक जीवन को बिल्कुल बदल दिया है। स्वतन्त्र कारीगर का स्थान आज पूँजीपति और मजदूर ने ले लिया है। स्त्रियाँ अब स्वाधीन हो चुकी हैं। उन्हें सब क्षेत्रों में अब पुरुषों के बराबर अधिकार मिल गये हैं। स्त्रियों की स्वाधीनता के कारण यूरोप के सामाजिक और पारिवारिक जीवन में भारी परिवर्तन आ गया है। धर्म के क्षेत्र में आज प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्र है। धर्म के कारण आज कोई व्यक्ति किसी अधिकार में वंचित नहीं रहता।

यह महान् परिवर्तन किस प्रकार आ गया, यही हम इस इतिहास में स्पष्ट करेंगे। पर यह ध्यान में रखना चाहिए कि यह परिवर्तन एकदम नहीं हुआ। मनुष्य जाति के इतिहास में कोई परिवर्तन अकस्मात् एकदम नहीं होता। मानव-जगत् के समान मनुष्य जाति भी एक जीती जागती चेतन मत्ता है। उसमें उन्नति और ह्रास दोनों धीरे-धीरे होते हैं। हमने १७८९ में यूरोप के आधुनिक इतिहास को शुरू किया है। उस वर्ष फ्रांस में राज्यक्रान्ति का श्रीगणेश हुआ था। पर यह नहीं समझना चाहिये, कि १७८९ में ये सब महान् परिवर्तन यूरोप में अकस्मात् शुरू हो गये थे। ये परिवर्तन देश में धीरे-धीरे हो रहे थे। १७८९ के बाद भी ये धीरे-धीरे होने रहें। पर सुगमता के लिये हमने १७८९ के साल को आधुनिक यूरोपियन इतिहास का प्रारम्भ करने के लिये चुन लिया है। जैसा मनुष्य के जीवन में बाल्य, यौवन और बुढ़ापा—तीनों अवस्थाएँ समझ आती हैं वैसे हम यह नहीं बता सकते, कि किस दिन बाल्य बाल समाप्त हुआ और यौवन का प्रारम्भ हुआ या यौवन का अन्त हो, बुढ़ापा शुरू हुआ। पर यह निश्चित है, कि किसी समय बाल्य के बाद यौवन और यौवन के बाद बुढ़ापा आ जाता है। हम केवल सुगमता के लिये यह मान लेते हैं, कि २५ वर्ष की आयु में यौवन और ५० वर्ष की आयु में बुढ़ापा शुरू होता है। इसी तरह मनुष्य जाति के इतिहास में परिवर्तनों के धीरे-धीरे होने के कारण वह नहीं कहा जा सकता, कि कब मध्यकाल समाप्त हुआ और आधुनिक काल का प्रारम्भ हुआ। पर इतिहास-लेखक अपनी सुगमता के लिये कोई निश्चित वर्ष चुन लेते हैं, और हम न इस इतिहास में फ्रांस की राज्यक्रान्ति के श्रीगणेश के वर्ष—मन १७८९ को आधुनिक यूरोपियन इतिहास को शुरू करने के लिये चुना है।

१७८९ से १९५१ तक लगभग डेढ़ सदी के इस काल में यूरोप ने जो आश्चर्यजनक उन्नति की है, उसी पर हम इस ग्रन्थ में प्रकाश डालेंगे। पर यूरोप के आधुनिक इतिहास को शुरू करने से पूर्व यह जरूरी है, कि हम प्राचीन और मध्यकालीन यूरोप के सम्बन्ध में

भी कुछ प्रकाश डाले। पुराने यूरोप को जाने बिना नवीन यूरोप को समझ सकना कठिन है।

## २ प्राचीन काल

यूरोप का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। आज से ढाई हजार वर्ष पूर्व यूरोप का बड़ा भाग जगली से आच्छादित था। जहाँ आजकल इङ्ग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, रूस, नार्वे, स्वीडन, आस्ट्रिया आदि के सभ्य और समृद्ध राज्य हैं, वहाँ उस समय प्रायः जगली और असभ्य लोग बसते थे। उस समय यूरोप में केवल दो देश ऐसे थे, जहाँ सभ्यता का विकास हो रहा था। ये देश थे, ग्रीस और इटली। आज से ढाई हजार वर्ष पहले ग्रीस अच्छा उन्नत और सभ्य देश था। वहाँ के लोग सुन्दर मकानों में रहते थे, खेती करते थे, समार के गूढ़ तत्त्वों पर विचार करते थे और विविध देवी-देवताओं की पूजाकर इहलोक और परलोक में सुखी होने का प्रयत्न करते थे।

यूरोप की प्राचीनतम सभ्यता—पर ग्रीक लोगों के इतिहास के रगमच पर प्रकट होने से पूर्व भी यूरोप में एक अन्य प्राचीन सभ्यता का विकास हुआ था, जिसका नाम ईगियन था। यह ईगियन सभ्यता ससार की प्राचीनतम सभ्यताओं—सुमेरियन, असीरियन, ईजिप्शियन, सिन्धु सभ्यता और चीनी सभ्यता की समकालीन थी।

इस सभ्यता का क्षेत्र भूमध्यसागर के तटवर्ती प्रदेश और ईगियन सागर के विविध द्वीप थे। इसका प्रधान केन्द्र क्रीट नाम का द्वीप था। उस में कनोस्सस नामक स्थान पर जो खुदाई हुई है, उसमें ज्ञात होता है कि किसी प्राचीन समय में वहाँ एक अत्यन्त समृद्ध और बभ्रवपूर्ण नगर विद्यमान था। इसमें बड़े-बड़े राजप्रसाद थे, जिनमें क्रीट के राजा बड़े विलास के साथ अपना जीवन व्यतीत करते थे। इन राजाओं को मीन कहते थे। मीन राजाओं के महल में वाकायदा स्नान-गृह बने हुए थे, जिनमें नलको द्वारा पानी आता था। कनोस्सस की खुदाई में न केवल राजमहलों के खण्डहर मिले हैं, अपितु उस काल के बहुत से वर्तन, वस्त्र, लेख, आभूषण, मूर्तियाँ और चित्र भी प्राप्त हुए हैं। इन्हें देख कर यह भलीभाँति ज्ञात होता है, कि क्रीट के निवासी बहुत उन्नत और समृद्ध थे।

क्रीट के समान एशिया माइनर, ग्रीस आदि के तटवर्ती अन्य भी अनेक स्थानों पर खुदाई द्वारा इस प्राचीन ईगियन सभ्यता के भग्नावशेष उपलब्ध हुए हैं। इनमें ट्रॉय, टिग्रिस और माइकेली मर्य है। समुद्र के क्षेत्र में रहने के कारण ईगियन लोगों को पत्तियों के मैदानों में रहनेवाली जगली व पशुपालक जातियों के हमलों का विशेष भय नहीं था। इसीलिये वे निश्चिन्त होकर एक डेढ़ हजार साल के लगभग शांति के साथ अपनी सभ्यता का विकास करते रहे। जहाँजहाँ के निर्माण पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया। वे न केवल अपनी विविध वस्तुओं में जहाँजहाँ द्वारा आते जाते थे, अपितु ईजिप्ट और पशिया की खाड़ी के मुद्रवर्ती प्रदेशों में भी व्यापार के लिये पहुँचते थे।

ग्रीक लोगों ने ईगियन सभ्यता का जन्म किया। ये ग्रीक लोग उस विशाल आर्य जाति की एक शाखा थे जिसकी पूर्वी शाखा ने भारत में प्रवेश कर सिन्धु और गंगा नदी की उन्नत सभ्यताओं का जन्म किया था। ग्रीक लोगों ने ईगियन सागर के क्षेत्र में १००० ई. पू. के लगभग प्रवेश करना शुरू किया। यद्यपि ईगियन लोग सभ्यता की दृष्टि

बहुत उबल रहे, पा ग्रीक लोग बीरता और पाहण में उन से बहुत आगे बढ़े हुए थे। सभ्यता के रोग ने उन्हें अभी निर्मल नहीं कर दिया था। ईगियन लोगो को पराग्न कर वे उनके प्रदेश में आबाद हो गये और पाजिन ईगियन लोगो में उन्होंने सभ्यता की बहुत सी बातें सीसी।

प्राचीन ग्रीक राज्य—आज जाति की जिम पञ्चमी जाति ने यूरोप में ब्राह्मण प्रायद्वीप में होकर ग्रीस में प्रवेश किया। उनके इस प्रदेश में बहुत से छोटे-छोटे राज्य कायम किये। ग्रीस की भूमि समतल व मैदान नहीं है। उसमें बहुत-सी पहाड़ियाँ हैं जिनके कारण यह देश बहुत सी घाटियों में विभक्त है। विविध ग्रीक लोक विविध घाटियों में बस गये और उनके राज्य एक दूसरे में पृथक् रहे। ग्रीक लोग ग्रीस में आगे बढ़कर ईगियन सागर के विविध द्वीपों और एजिया माइनर के समुद्र तट पर भी आबाद हुए। इस क्षेत्र में जो ईगियन सभ्यता पहले विद्यमान थी उसे ग्रीक लोगो ने प्रिय कर लिया। ईगियन लोगो को दास बना लिया गया। उन के साथ ही लोगो ने बड़ी व्यवहार किया जो भारत के आर्यों ने द्रविड़ों के साथ किया था। ईगियन लोगो ने नीकाआ और जहाजों का उपयोग सीखाकर ग्रीक लोग और आगे बढ़े और इटली तथा सिमरी के समुद्र तट पर भी उन्होंने अपने अनेक राज्य कायम किये। भूमध्यसागर के तट पर उन लोगो ने अपने राज्यों का एक जाल-सा बिछा दिया।

ग्रीक राज्यों की संख्या सैकड़ों में थी। उन में प्रमुख एथेन्स, स्पार्टा, थारिन्स, थेब्स, मेसस और मिलेटस थे। अत्रिकाश ग्रीक राज्यों की आबादी पचास हजार के लगभग थी। उनमें कोई भी राज्य ऐसा नहीं था, जिसकी आबादी तीन लाख में अधिक हो। इस आबादी में भी दासों की संख्या अधिक होती थी। स्वतन्त्र ग्रीक नागरिक संख्या में दासों की अपेक्षा बहुत कम होने लगे थे। ग्रीस की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी, कि वह एक शक्तिशाली साम्राज्य का विकास हो सकना सुगम नहीं था। विविध राज्य पहाड़ों की घाटियों, द्वीपों या समुद्र तट पर स्थित थे। किसी शक्तिशाली राजा के लिये यह सम्भव नहीं था कि वह आसानी से इन सबको जीतकर अपने अधीन कर ले और फिर दिग्विजय होकर उन पर शासन कर सके।

राजनीतिक दृष्टि से पृथक् रहते हुए भी इन विविध राज्यों में एक प्रजातन्त्र की एकता व एकात्मिकता विद्यमान थी। सब ग्रीक राज्यों की भाषा एक थी, सब अपने-पूरे पुण्यों की वीर गाथाओं का समान रूप से स्मरण करने लगे थे, होमर के ईलियड और ओडिससी का सर्वत्र समानरूप से आदर था। साथ ही, प्रति चार साल के बाद सब ग्रीक राज्यों के प्रतिनिधि एक स्थान पर एकत्र होते थे। यहाँ विविध खेलों में उनके साम्मुख्य होते थे। ग्रीक लोगो को कुस्ती व खेलों का बड़ा शौक था। ग्रीक नवयुवकों की यह महत्त्वाकांक्षा रहती थी कि वे इन खेलों में विजयी हो कर प्रथम पुरस्कार प्राप्त करें। ये खेल ओलिम्पिया नामक स्थान पर होते थे। ग्रीस में इन खेलों का इतना महत्त्व था कि ओलिम्पिया में टूर्नामेंट के अवसर पर विविध राज्य आपस के लड़ाई-झगड़ों व युद्धों को बन्द कर देते थे और सब राज्यों से न केवल खिलाड़ी अपितु दर्शक भी बड़ी संख्या में वहाँ एकत्र होते थे। ओलिम्पिया में विविध ग्रीक राज्यों के लोगो को आपस में मिलने का सुवर्णीय अवसर प्राप्त होता था और वे भली-भाँति अनुभव करते थे कि हम एक ही जाति के अंग हैं।

**शासन पद्धति**—विविध ग्रीक राज्यों की शासन-पद्धति भी भिन्न-भिन्न थी। कुछ में वंशक्रमानुगत राजा राज्य करते थे, कुछ में कतिपय कुलीन श्रेणियों का शासन था और कुछ में सर्वसाधारण जनता का राज्य था। राज्यों में शासन-पद्धति भी सदा एक सी नहीं रही। जहाँ पहले राजा का शासन था, वहाँ बाद में जनता का राज्य स्थापित हो गया। जहाँ पहले जनता का राज्य था, वहाँ बाद में किसी वीर पुरुष ने अपने एकतन्त्र शासन की स्थापना कर ली। ग्रीक के नगर राज्यों में शासन का प्रकार निरन्तर बदलता रहा। एथन्स ग्रीस का प्रमुख राज्य था, वहाँ लोकतन्त्र शासन प्रणाली विद्यमान थी। आज-कल लोकतन्त्र शासन का अभिप्राय यह समझा जाता है, कि राज्य के सब नागरिकों का शासन में भाग हो। पर एथन्स में केवल उन नागरिकों को राज्य में अधिकार था, जिनके माता और पिता दोनों एथोनियन हों। गुलाम इस अधिकार से वंचित थे, विदेशी ग्रीक लोगों को भी शासन में कोई स्थान प्राप्त नहीं था। एथन्स की शासन-पद्धति लोकतन्त्र थी, पर उसमें शासन सम्बन्धी अधिकार बहुत कम लोगों को प्राप्त था।

ग्रीक नगर राज्यों में इस बात की आवश्यकता नहीं थी, कि नागरिक लोग राजसभा के लिये प्रतिनिधियों का निर्वाचन करें। सब नागरिकों को अधिकार था, कि वे स्वयं सभा में एकत्र हो, वहाँ विविध मामलों पर बहस करें और बहुसम्मति द्वारा किसी बात का निणय करें। एथन्स जैसे समृद्ध राज्य की सभा में (इसे एक्लीजिया कहते थे) में हजारों नागरिक एकत्र होते थे। अनेक वक्ता इस बात का अभ्यास करते थे, कि अपने प्रभावशाली व जोरदार भाषणों द्वारा लोगों को प्रभावित करें और उन्हें अपनी बात मानने के लिये प्रेरित करें। वोट के समय नागरिक लोग 'हाँ' या 'ना' कह कर अपनी सम्मति प्रकट करते थे। जिस पक्ष में अधिक ऊँची आवाज रहे, वही स्वीकृत समझा जाता था। अनेक राजनीतिक नेता अपने अनुयायियों को यह मिखाते थे कि वे बहुत जोर से चिल्ला कर अपने मत को प्रकट करें।

कानून की दृष्टि में सब नागरिक एक समान होते थे। इसीलिये अनेक राज्यों में यह व्यवस्था थी, कि राजकर्मचारियों की नियुक्ति लाटरी द्वारा की जाय। लाटरी में जिसका भी नाम निकल आवे, वही राजपद पर नियत कर दिया जाता था। ग्रीस के इन प्राचीन नगर-राज्यों में राजनीतिक दल भी विद्यमान थे। कई बार जब विविध राजनीतिक दलों के नेताओं में उग्र मतभेद हो जाता था, तो वोट द्वारा यह फैसला किया जाता था, कि किस नेता को देश से बहिष्कृत कर दिया जाय। यह देश निकाला प्रायः दस साल के लिये दिया जाता था। इस प्रकार का वोट पंचियों द्वारा लिया जाता था।

श्रेणितन्त्र राज्यों में सब ग्रीक लोगों को भी शासन में अधिकार नहीं रहता था। कुछ कुलीन परिवारों के लोग शासन करते थे और शेष उन की प्रजा होते थे। राजतन्त्र राज्यों में वंशक्रमानुगत राजाओं का शासन होता था। पर इन राजाओं पर भी जनता के नियन्त्रण का अभाव नहीं था। अनेक राज्यों में यह प्रथा थी, कि जब कोई राजा राजगद्दी पर पर बैठने लगे, तो प्रजा उसे स्वीकार करे।

**ग्रीक सभ्यता**—पाचवीं सदी ई० पू० ग्रीक इतिहास में अत्यन्त समृद्ध और उन्नति का काल था। इस समय तक ग्रीस के बहुत से राज्यों ने परस्पर मिल कर अपना एक मध्य



बना लिया था जिसका नेता एथन्स था। इस समय एथन्स राज्य का पतान पैरिक्लीज था, जो बड़ा योग्य और कुशल नीतिज्ञ था। उसने एथन्स की समृद्धि और वैभव के लिये असाधारण प्रयत्न किया। उसके यत्न से एथन्स में बहुत सी नई उमांगें बनीं। उसके समय की बहुत सी सुन्दर मूर्तियों के अनेक अवशेष अब भी विद्यमान हैं, और उनमें यह भी भाति सूचित होता है कि पैरिक्लीज के समय का एथन्स कितना उत्तम, कलामय और समृद्ध था।

पैरिक्लीज ने एथन्स में बाह्य कलेवर की उत्पत्ति पर ही ध्यान नहीं दिया। साथ ही उसका यह भी यत्न था कि एथन्स ज्ञान, कला, कविता और साहित्य की दृष्टि में भी अनुत्तम हो जाए। उसी कारण उसने बहुत से नवीन दार्शनिक और विचारकों को एथन्स में निमन्त्रित किया। उन लोगों में कुछ के नाम इतिहास में अमर हैं। हीरोडोटस पैरिक्लीज के निमन्त्रण पर ४३८ ई० पू० में एथन्स आया और वहाँ उस ने अपने 'इतिहास' का प्रवचन किया। सम्भवतः हीरोडोटस पाश्चात्य समाज का पहला ऐतिहासिक हुआ है। उसने प्राचीन समाज की विविध जातियों और सम्प्रदायों के पुराने इतिहास की खोज कर एक ग्रन्थ लिखा, जो आज तक भी बड़े शोक में पढ़ा जाता है। अनेकसोरोस ज्योतिषी था। सूर्य, नक्षत्र तारे आदि के विषय में उसने महत्त्वपूर्ण खोज की थी। वह भी इस समय एथन्स में आया और वहाँ आकर उसने ज्योतिष सम्प्रदाय अपनी खोज को जारी रखा। अनेक कवि और नाटककार भी इस युग में एथन्स की शोभा बढ़ा रहे थे। ग्रीक भाषा में कविता पहले से विद्यमान थी। होमर के बाद अन्य भी अनेक कवि ग्रीस में उत्पन्न हुए, जिन्होंने अनेक उत्कृष्ट काव्यों की रचना की। पर पैरिक्लीज के जमाने में नाटकों की रचना विशेष रूप से प्रारम्भ हुई। एथन्स आदि विविध राज्यों के नागरिकों को नाटकों का बड़ा शौक था। ये नाटक सार्वजनिक रूप में खेले जाते थे, और ग्रीक लोग बड़ी सख्या में इन्हें देखने के लिये एकत्र होते थे।

पैरिक्लीज के समय में ही एक ऐसे विचारक का ग्रीस में प्रादुर्भाव हुआ, जिसका नाम दर्शन शास्त्र के इतिहास में सदा अमर रहेगा। इसका नाम सुकरात है। वह कहता था, कि सत्य ज्ञान से बढ़कर कोई बात नहीं होती। पर किसी मनु का मन्थ या यथार्थ ज्ञान तभी सम्भव है, जब मनुष्य प्रत्येक बात की सच्चाई को पर्यन्त देखने का प्रयत्न करे। अन्ध विश्वास से बढ़कर बुरी बात अन्य कोई नहीं। सुकरात की शिक्षा का यह परिणाम हुआ, कि उसके बहुत से अनुयायी उन सब बातों को मन्देह की दृष्टि में देखने लगे, जिन्हें ग्रीक लोग पुराने समय से मानते आये थे। सुकरात स्वयं तत्त्वज्ञानी था। यथार्थज्ञान से उसका अभिप्राय यही था, कि मनुष्य प्रत्येक बात को सत्य की कमौड़ी पर कसने का प्रयत्न करे। पर उसके बहुत से अनुयायी सत्य के नाम पर सभी पुरानी बातों के विरुद्ध विद्रोह करने लगे। ग्रीक लोगो ने इस बात को बहुत भयकर समझा। परिणाम यह हुआ, कि सुकरात को प्राणदंड दिया गया और उसने विष में भरा प्याला पीकर अपने जीवन का (३९९ ई० पू०) अन्त कर दिया।

सुकरात का प्रधान शिष्य प्लेटो या अफलातून था। उसका जन्म ४२६ ई० पू० में हुआ था। उसने एथन्स में एक एकेडेमी की स्थापना की। इसमें एकत्र हुए विद्वान् सत्य

की खोज में तत्पर रहते थे। प्लेटो कहता था, मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं विधाता है। हम अपनी इच्छाशक्ति का प्रयोग कर उन परिस्थितियों को बदल सकते हैं, जो हमारे कष्टों का कारण हैं। हम सोच समझ कर ऐसे समाज और ऐसे राज्य का निर्माण कर सकते हैं, जिसमें हम अधिक सुख में रह सकें। मनुष्य स्वयं नहीं जानते, कि उसमें कितनी शक्ति है। यही कारण है, कि वे विविध कष्ट उठाते हैं। प्लेटो ने समाज की नई कल्पना को जनता के सम्मुख रखा। यह कल्पना उसने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'रिपब्लिक' में विस्तृत रूप से प्रतिपादित की है।

प्लेटो का प्रधान शिष्य अरिस्टॉटल था। वह कहता था, कि मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं विधाता अवश्य है, पर वह तभी अपने प्रयत्न में सफल हो सकता है, जब कि वह सब बातों का सही-सही ज्ञान प्राप्त करने का यत्न करे। इसीलिये अरिस्टॉटल ने सब वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिये खोज के उपाय का आश्रय लिया। उसने १५८ राज्यों के शासन-विधानों का संग्रह किया और उनका अनुशीलन करके राजनीति-शास्त्र का निर्माण किया। इसी पद्धति में उसने अन्य क्षेत्रों में भी वैज्ञानिक खोज की कोशिश की। जिसे हम आजकल वैज्ञानिक खोज कहते हैं, उसका प्रारम्भ अरिस्टॉटल द्वारा ही हुआ था।

सुकरात, प्लेटो और अरिस्टॉटल के समान अन्य भी अनेक विचारक व दार्शनिक उस समय ग्रीस में उत्पन्न हुए। उनके प्रयत्नों से ग्रीस में तत्त्वज्ञान की खोज की एक भूख भी पैदा हो गई थी।

ग्रीक लोगो ने कला के क्षेत्र में भी बहुत उन्नति की। भवन निर्माण में तो वे अत्यन्त कुशल थे ही, पर मूर्तिनिर्माण कला में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। उन्होंने बहुत सी सुन्दर मूर्तियाँ बनाई, जो आजतक भी अपने शिल्पियों की योग्यता और प्रतिभा का परिचय देती हैं। ये ग्रीक मूर्तियाँ अत्यन्त सुन्दर और कलापूर्ण हैं। ग्रीक लोग प्रकृति की विविध शक्तियों की देवतारूप में पूजा करते थे। इन देवताओं की उन्होंने सजग मूर्तियाँ बनाई।

**मैसिडोनिया का उत्कर्ष**—ग्रीस के उत्तर में मैसिडोनिया नाम का एक राज्य था, जिसके निवासी ग्रीक लोगो की ही एक शाखा थे। उनकी भाषा ग्रीक में मिलती जुलती थी। पर सम्यता की दृष्टि से वे ग्रीक लोगो से बहुत पीछे थे। चौथी सदी ई० पू० में मैसिडोनिया में एक ऐसा राजा उत्पन्न हुआ, जिसने उसे एक शक्तिशाली राज्य बना दिया। इसका नाम अमिन्टस था।

अमिन्टस का लड़का फिलिप था, जो उसकी मृत्यु के बाद मैसिडोनिया का राजा बना। उसका बहुत सा समय ग्रीस में व्यतीत हुआ था। वहाँ रहते हुए उसने न केवल ग्रीस के साहित्य और दर्शन शास्त्र का अनुशीलन किया, पर साथ ही उसकी युद्धनीति में भी परिचय प्राप्त किया। मैसिडोनियन सैनिक ग्रीक सैनिकों की अपेक्षा अधिक उग्र और नाहमी थे। फिलिप ने उन्हें ग्रीक युद्धनीति की शिक्षा दी। परिणाम यह हुआ, कि मैसिडोनियन सेना की शक्ति बहुत बढ़ गई।

एक शक्तिशाली सेना का उपयोग फिलिप ने अपने राज्य के विस्तार के लिये किया। कुछ ही समय में सम्पूर्ण बाल्कन प्रायद्वीप उसके अधीन हो गया। पर फिलिप केवल

वना लिया था, जिसका नेता एथन्स था। इस समय एथन्स राज्य का प्रधान पैरिक्लीज था, जो बड़ा योग्य और कुशल नीतिज्ञ था। उसने एथन्स की समृद्धि और वैभव के लिये असाधारण प्रयत्न किया। उसके यत्न में एथन्स में बहुत सी नई इमारतें बनीं। उसके समय की बहुत सी सुन्दर मूर्तियों के अनेक अवशेष अब भी विद्यमान हैं, और उनमें यह भली भाँति सूचित होता है कि पैरिक्लीज के समय का एथन्स कितना उन्नत, कलामय और समृद्ध था।

पैरिक्लीज ने एथन्स के बाह्य कलेवर की उन्नति पर ही ध्यान नहीं दिया, साथ ही उसका यह भी यत्न था, कि एथन्स ज्ञान, कला, कविता, और साहित्य की दृष्टि में भी अनुपम हो जाय। इसी कारण उसने बहुत से कवि, दार्शनिक और विचारकों को एथन्स में निमन्त्रित किया। उन लोगों में कुछ के नाम इतिहास में अमर हैं। हीरोडोटस पैरिक्लीज के निमन्त्रण पर ४३८ ई० पू० में एथन्स आया और वहाँ उसने अपने 'इतिहास' का प्रवचन किया। सम्भवतः, हीरोडोटस पाश्चात्य समाज का पहला ऐतिहासिक हुआ है। उसने प्राचीन समाज की विविध जानियों और सभ्यताओं के पुराने इतिहास की खोज कर एक ग्रन्थ लिखा, जो आज तक भी बड़े शौक में पढ़ा जाता है। अनेकसेगोरस ज्योतिषी था। सूर्य, नक्षत्र, तारे आदि के विषय में उसने महत्त्वपूर्ण खोज की थी। वह भी इस समय एथन्स में आया और वहाँ आकर उसने ज्योतिष सम्बन्धी अपनी खोज को जारी रखा। अनेक कवि और नाटककार भी इस युग में एथन्स की शोभा बढ़ा रहे थे। ग्रीक भाषा में कविता पहले से विद्यमान थी। होमर के बाद अन्य भी अनेक कवि ग्रीस में उत्पन्न हुए, जिन्होंने अनेक उत्कृष्ट काव्यों की रचना की। पर पैरिक्लीज के जमाने में नाटकों की रचना विशेष रूप से प्रारम्भ हुई। एथन्स आदि विविध राज्यों के नागरिकों को नाटकों का बड़ा शौक था। ये नाटक सार्वजनिक रूप में खेले जाते थे, और ग्रीक लोग बड़ी संख्या में इन्हें देखने के लिये एकत्र होते थे।

पैरिक्लीज के समय में ही एक ऐसे विचारक का ग्रीस में प्रादुर्भाव हुआ, जिसका नाम दर्शन शास्त्र के इतिहास में सदा अमर रहेगा। इसका नाम सुकरात है। वह कहता था, कि सत्य ज्ञान से बढ़कर कोई बात नहीं होती। पर किसी बन्धु का सत्य या यथार्थ ज्ञान तभी सम्भव है, जब मनुष्य प्रत्येक बात की सचाई को परखकर देखने का प्रयत्न करे। अन्ध विश्वास से बढ़कर बुरी बात अन्य कोई नहीं। सुकरात की शिक्षा का यह परिणाम हुआ, कि उसके बहुत से अनुयायी उन सब बातों को सन्देह की दृष्टि से देखने लगे, जिन्हें ग्रीक लोग पुराने समय से मानते आये थे। सुकरात स्वयं तत्त्वज्ञानी था। यथार्थज्ञान से उसका अभिप्राय यही था, कि मनुष्य प्रत्येक बात को सत्य की कसौटी पर कसने का प्रयत्न करे। पर उसके बहुत से अनुयायी सत्य के नाम पर सभी पुरानी बातों के विरुद्ध विद्रोह करने लगे। ग्रीक लोगों ने इस बात को बहुत भयकर समझा। परिणाम यह हुआ, कि सुकरात को प्राणदण्ड दिया गया और उसने विष से भरा प्याला पीकर अपने जीवन का (३९९ ई० पू०) अन्त कर दिया।

सुकरात का प्रधान शिष्य प्लेटो या अफलातून था। उसका जन्म ४२६ ई० पू० में हुआ था। उसने एथन्स में एक एकेडेमी की स्थापना की। इसमें एकत्र हुए विद्वान् सत्य

की खोज में तत्पर रहते थे। प्लेटो कहता था, मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं विधाता है। हम अपनी इच्छाशक्ति का प्रयोग कर उन परिस्थितियों को बदल सकते हैं, जो हमारे कष्टों का कारण हैं। हम मोच समझ कर ऐसे समाज और ऐसे राज्य का निर्माण कर सकते हैं, जिसमें हम अधिक सुख में रह सकें। मनुष्य स्वयं नहीं जानते, कि उसमें कितनी शक्ति है। यही कारण है, कि वे विविध कष्ट उठाते हैं। प्लेटो ने समाज की नई कल्पना को जनता के सम्मुख रखा। यह कल्पना उसने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'रिपब्लिक' में विस्तृत रूप से प्रतिपादित की है।

प्लेटो का प्रधान शिष्य अरिस्टॉटल था। वह कहता था, कि मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं विधाता अवश्य है, पर वह तभी अपने प्रयत्न में सफल हो सकता है, जब कि वह सब बातों का सही-सही ज्ञान प्राप्त करने का यत्न करे। इसीलिये अरिस्टॉटल ने सब वस्तुओं का यथायथ ज्ञान प्राप्त करने के लिये खोज के उपाय का आश्रय लिया। उसने १५८ राज्यों के शासन-विधानों का संग्रह किया और उनका अनुशीलन करके राजनीति-शास्त्र का निर्माण किया। इसी पद्धति से उसने अन्य क्षेत्रों में भी वैज्ञानिक खोज की कोशिश की। जिसे हम आजकल वैज्ञानिक खोज कहते हैं, उसका प्रारम्भ अरिस्टॉटल द्वारा ही हुआ था।

मुकरात, प्लेटो और अरिस्टॉटल के समान अन्य भी अनेक विचारक व दार्शनिक इस समय ग्रीस में उत्पन्न हुए। उनके प्रयत्नों से ग्रीस में तत्त्वज्ञान की खोज की एक भूख भी पैदा हो गई थी।

ग्रीक लोगो ने कला के क्षेत्र में भी बहुत उन्नति की। भवन निर्माण में तो वे अत्यन्त कुशल थे ही, पर मूर्तिनिर्माण कला में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। उन्होंने बहुत सी सुन्दर मूर्तियाँ बनाई, जो आजतक भी अपने शिल्पियों की योग्यता और प्रतिभा का परिचय देती हैं। ये ग्रीक मूर्तियाँ अत्यन्त सुन्दर और कलापूर्ण हैं। ग्रीक लोग प्रकृति की विविध शक्तियों की देवतारूप में पूजा करते थे। इन देवताओं की उन्होंने सजग मूर्तियाँ बनाई।

**मैसिडोनिया का उत्कर्ष**—ग्रीस के उत्तर में मैसिडोनिया नाम का एक राज्य था, जिसके निवासी ग्रीक लोगो की ही एक शाखा थे। उनकी भाषा ग्रीक में मिलती जुलती थी। पर सभ्यता की दृष्टि से वे ग्रीक लोगो से बहुत पीछे थे। चौथी सदी ई० पू० में मैसिडोनिया में एक ऐसा राजा उत्पन्न हुआ, जिसने उसे एक शक्तिशाली राज्य बना दिया। इसका नाम अमिन्टस था।

अमिन्टस का लड़का फिलिप था, जो उसकी मृत्यु के बाद मैसिडोनिया का राजा बना। उसका बहुत सा समय ग्रीस में व्यतीत हुआ था। वहाँ रहते हुए उसने न केवल ग्रीस के साहित्य और दर्शन शास्त्र का अनुशीलन किया, पर साथ ही उसकी युद्धनीति में भी परिचय प्राप्त किया। मैसिडोनियन सैनिक ग्रीक सैनिकों की अपेक्षा अधिक उग्र और साहसी थे। फिलिप ने उन्हें ग्रीक युद्धनीति की शिक्षा दी। परिणाम यह हुआ, कि मैसिडोनियन सेना की शक्ति बहुत बढ गई।

एक शक्तिशाली सेना का उपयोग फिलिप ने अपने राज्य के विस्तार के लिये किया। शुरु ही समय में सम्पूर्ण बाल्कन प्रायद्वीप उसके अधीन हो गया। पर फिलिप केवल

वालकन प्रदेश को जीतकर ही मनुष्ट नहीं हुआ, उसने दक्षिण में उससे आगे बढ़कर ग्रीस पर भी हमला किया। धीरे-धीरे सम्पूर्ण ग्रीस उसके अधीन हो गया। पर ग्रीक लोग के लिये मैसिडोनियन फिलिप का शासन विदेशी नहीं था। फिलिप की अपनी शिक्षा ग्रीस में हुई थी, और मैसिडोनिया के निवासी जान्ती की दृष्टि में ग्रीक ही थे। ग्रीस के अनेक राज्य पहले भी एथन्स जैसे शक्तिशाली राज्यों के वशवर्ती थे। फिलिप ने अब एथन्स को परास्त कर सब ग्रीक राज्या को अपने अधीन कर लिया था। विविध राज्यों की पृथक् सत्ता और आन्तरिक स्वतन्त्रता अब भी कायम रही। भेद केवल इतना हुआ, कि अब सब ग्रीक राज्य फिलिप को अपना अधिपति स्वीकृत करने लगे।

३३६ ई० पू० में अपने पिता फिलिप की मृत्यु के बाद सिकन्दर मैसिडोनियन साम्राज्य का अधिपति बना। फिलिप द्वारा साम्राज्य-विस्तार की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, सिकन्दर ने उसे जारी रखा। उस समय एशिया माइनर, ईजिप्ट, तुर्किस्मान व अफगानिस्तान के प्रदेश पर्शियन साम्राज्य के अन्तर्गत थे। ६०० ई० पू० के लगभग जिस विशाल पर्शियन साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था, वह अब टाई गी मान के बाद बहुत कुछ निबल हो गया था। उसके सम्राट् और क्षत्रप भोग विलास में मग्न रहते थे। उन, सम्पत्ति और वैभव की प्रचुरता ने उन्हें निर्बल बना दिया था। सिकन्दर ने इस विशाल पर्शियन साम्राज्य पर आक्रमण किया। एशिया माइनर को जीतकर उसने ईजिप्ट में प्रवेश किया। ३३२ ई० पू० में ईजिप्ट सिकन्दर के अधीन हो गया और नील नदी के मुहाने पर उसने सिकन्दरिया नाम के एक समृद्ध नगर की स्थापना की। ३३१ ई० पू० में सिकन्दर ने मैसोपोटामिया की उपजाऊ घाटी पर आक्रमण किया। बैबिलोन, निनेवा आदि सब प्राचीन नगरों पर कब्जा करके सिकन्दर पर्शिया में प्रविष्ट हुआ। इस समय पर्शिया के राजसिंहासन पर डेरियस तृतीय विराजमान था। उसने सिकन्दर का मुकाबला करने की कोशिश की, पर वह सफल नहीं हुआ। ३३० ई० पू० में डेरियस के अपने सैनिकों ने उसकी हत्या कर दी। पर्शिया को विजय कर सिकन्दर ने मध्य एशिया में प्रवेश किया। वहाँ के क्षत्रप ने सिकन्दर की सेनाओं के साथ डट कर लड़ाई की, पर अन्त में वह भी परास्त हुआ। अब सिकन्दर ने हिन्दूकुश पर्वतमाला को पार कर भारत पर आक्रमण किया। भारत के विविध राज्यों ने डटकर मैसिडोनियन सेनाओं के साथ युद्ध किया। भारत में सिकन्दर को न केवल राजाओं और उनकी सेनाओं से युद्ध करना पड़ा, अपितु अनेक गण-राज्यों के साथ भी उसके युद्ध हुए। उस समय पंजाब में आरट्ट, क्षत्रिय, क्षुद्रक, मालव, शिवि, आग्नेय आदि अनेक गणराज्य विद्यमान थे। ग्रीस के एथन्स, स्पार्टा, थेब्स आदि राज्यों के समान ये भी अत्यन्त समृद्ध और शक्तिशाली थे। अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा के लिये इन्होंने सिकन्दर की सेनाओं के साथ घनघोर युद्ध किया। यद्यपि सिकन्दर इन्हें परास्त करने में समर्थ हुआ, पर इन लड़ाइयों से उसके सैनिकों की हिम्मत टूट गई और सिकन्दर ने यही उचित समझा, कि वह भारत में और अधिक आगे बढ़ने का प्रयत्न न करे।

३२३ ई० पू० में सिकन्दर की मृत्यु हुई। मृत्यु के समय उसकी आयु केवल ३३ साल की थी। इतनी छोटी आयु में सिकन्दर इतने विशाल साम्राज्य की स्थापना में समर्थ हुआ

यह उमकी अपूर्व प्रतिभा और साहस को सूचित करता है। पर उसको मृत्यु के बाद उमका विशाल साम्राज्य कायम नहीं रह सका। भारत में उसके प्रभुत्व के खिलाफ विद्रोह हो गया। चन्द्रगुप्त मौर्य नाम के एक साहसी युवक ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। साम्राज्य के जो प्रदेश अब भी मैसिडोनिया के अधीन रहे, उनमें भी सिकन्दर के विविध सेनापतियों ने स्वतन्त्र रूप से शासन प्रारम्भ कर दिये। ये सेनापति तीन थे मेल्लिकस, टालमी और एन्टीगोनस। हिन्दूकुश में एशिया माइनर तक के सुविस्तृत प्रदेश मेल्लिकस के आधिपत्य में आये। ईजिप्ट पर टालमी का अधिकार हुआ और मैसिडोनिया तथा ग्रीस पर एन्टीगोनस ने अपना स्वतन्त्र शासन स्थापित कर लिया। यद्यपि सिकन्दर का विशाल साम्राज्य अखण्ड रूप में कायम नहीं रह सका, पर उसके उत्तराधिकारी भी मैसिडोनियन थे। फिलिप और सिकन्दर के समान उनकी भाषा, सभ्यता और संस्कृति भी ग्रीक थी। उनकी सेनाओं में ग्रीक सैनिकों की प्रचुरता थी। इस दशा का परिणाम यह हुआ, कि इस समय (तीसरी सदी ई० पू० में) हिन्दूकुश में भूमध्यसागर तक के विशाल भूखण्ड पर ग्रीक लोगों का आधिपत्य था। ग्रीक लोग सभ्यता, संस्कृति, साहित्य और कला में बहुत उन्नत थे। उनके सम्पर्क से ईजिप्ट और पर्सिया के जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ।

**सिकन्दरिया**—सिकन्दर ने ७० के लगभग नये नगरों की स्थापना की थी। इन सबसे ग्रीक सैनिकों को आवास दिया गया था। ये ऐसे केन्द्र थे, जहाँ में ग्रीक सभ्यता अपने समीपवर्ती प्रदेशों पर अमर डालती थी। सिकन्दर द्वारा स्थापित इन नगरों में सबसे अधिक प्रसिद्ध वह सिकन्दरिया नगरी है, जो ईजिप्ट में नील नदी के मुहाने पर स्थित थी। टालमी ने इसे अपनी राजधानी बनाया और उसकी समृद्धि तथा उत्कर्ष के लिये अपनी सारी शक्ति को लगा दिया।

टालमी ने सिकन्दरिया में एक कलाभवन (म्यूजियम) की स्थापना की। यह कलाभवन एथन्स की एकेडेमी के समान एक विशाल विद्यापीठ था, जहाँ बहुत से विद्वान् मन्त्र की खोज और ज्ञान की प्राप्ति में तत्पर थे। यूक्लिड का नाम प्रत्येक विद्यार्थी जानता है। ज्यामिति का वह प्रसिद्ध विद्वान् था। यूक्लिड सिकन्दरिया के कलाभवन में ही रहता था। एरेटोस्थनीज प्रसिद्ध गणितज्ञ और भूगोलवेत्ता था। उसने पृथ्वी के आकार परिधि और व्यास का सही-सही ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की। एरेटोस्थनीज ने पृथ्वी का जो व्यास निकाला, वह वर्तमान वैज्ञानिकों द्वारा निकाले हुए व्यास के बहुत समीप है। उनमें केवल पचास मील का अन्तर है। हिप्पार्कस प्रसिद्ध ज्योतिषी हुआ है, उसने नक्षत्रों की गति व दूरी के विषय में खोज कर नक्षत्र-मण्डल का नक्शा तैयार करने का यत्न किया। आर्चिमीडिस ने वस्तुओं के आपेक्षिक गुरुत्व के विषय में नये मन का प्रतिपादन किया। ये नव वैज्ञानिक सिकन्दरिया के ही निवासी थे। अन्य भी अनेक विचारक और तत्त्ववेत्ता सिकन्दरिया के कलाभवन में रहते थे, और उनके कारण सिकन्दरिया अपने समय का सबसे महान् विद्यापीठ बन गया था।

टालमी ने सिकन्दरिया में एक विशाल पुस्तकालय की स्थापना की। उस समय ऐसा नहीं था। टालमी ने पुस्तकों की नकल करने के लिये हजारों पण्डितों को नियत किया।

ये लोग न केवल पुस्तकालय के लिये विविध पुस्तकों की नकल करते थे, अपितु विक्री के लिये भी बहुत सी उपयोगी पुस्तकों को लिख कर तैयार करते थे। सिकन्दरिया का यह पुस्तकालय पुस्तकप्रकाशक और पुस्तकविक्रेता भी था। इसका परिणाम यह हुआ था, कि पुस्तकें जनता को उपलब्ध हुईं और इसमें शिक्षा-प्रसार में महायत्ना मिली।

ग्रीक सभ्यता के सम्पर्क में आकर ईजिप्ट के लोगो ने बहुत सी नई बातें सीखीं। ग्रीक कला और तत्त्वज्ञान ने उनमें अनेक परिवर्तन उत्पन्न किये। यही प्रक्रिया अन्य प्रदेशों में भी हुई। अफगानिस्तान में उस समय बौद्ध धर्म का प्रचार था। बौद्ध लोग भगवान् बुद्ध की मूर्तियां बनाकर उनकी उपासना करने लगे। ग्रीक कला के सम्पर्क में गान्धार (अफगानिस्तान) देश के लोगो ने बुद्ध की जो मूर्तियां बनाईं, वे अन्यन्त मुन्दर थीं। उस समय गान्धार देश भारत का ही अंग था। भारत की मूर्ति-निर्माण कला में जो शैली 'गान्धार शैली' के नाम से प्रसिद्ध है, उसका विकास ग्रीक लोगो के सम्पर्क के कारण ही हुआ।

**रोम का उत्कर्ष**—जिस प्रकार आर्य जाति की एक शाखा ने ग्रीस में प्रवेश कर वहां अपने बहुत से राज्य स्थापित किये थे, वैसे ही आर्यों की एक अन्य शाखा ने इटली में प्रवेश कर वहां अपने अनेक राज्यों की स्थापना की थी। आर्यों की इस शाखा को लैटिन कहते हैं। लैटिन जाति के राज्यों में सब से प्रमुख रोम था। यह इटली के मध्य में टाइबर नदी के तट पर स्थित था। इस की स्थापना ७५३ ई० पू० में हुई थी। उन दिनों टाइबर नदी के उत्तर में ऐट्रस्कन लोगो का शक्तिशाली राज्य था। ये ऐट्रस्कन आर्य-भिन्न जाति के थे, और युद्ध में बहुत कुशल थे। इटली के आर्य राज्यों पर ये बहुधा हमला करते रहते थे। रोम की स्थापना इसी उद्देश्य से हुई थी, कि ऐट्रस्कन लोगो के आक्रमणों का भलीभांति मुकाबला किया जा सके। धीरे-धीरे रोम की उन्नति होती गई। छठी सदी ई० पू० तक वह इटली का प्रमुख नगर-राज्य बन गया। विविध लैटिन (आर्य) राज्यों के बहुत से साहसी व्यक्ति वहां आकर बसने लगे। टाइबर नदी के तट पर होने के कारण यह राज्य सामुद्रिक व्यापार के लिये बहुत उपयुक्त था। ऐट्रस्कन लोगो से निरन्तर युद्ध होते रहने से योद्धाओं को भी यहां बसकर अपनी वीरता प्रदर्शित करने का अच्छा अवसर मिलता था।

शुरू में रोम में राजाओं का था शासन। पर ४०६ ई० पू० में वहां राजतन्त्र शासन का अन्त होकर रिपब्लिक की स्थापना हुई। रोम के निवासी दो श्रेणियों में विभक्त थे, कुलीन (पैट्रिसियन) और जनसाधारण (प्लेबियन)। शुरू में रोम के शासन में सब शक्ति कुलीनों के हाथ में थी। ये कुलीन लोग मिलकर अपनी सभा करते थे। सब कानून यह सभा बनाती थी और साथ ही शासनकार्य के लिये विविध कर्मचारियों का चुनाव भी करती थी। प्रमुख राज-कर्मचारी कांसल कहलाते थे। रोम में एक साथ दो कांसल हुआ करते थे। इनका चुनाव हर साल होता था। जनसाधारण का शासन में कोई हाथ नहीं था, इस कारण उनमें बहुत अमतोष था। उन्होंने अपने अधिकारों के लिये संघर्ष शुरू किया। एक बार तो उन्होंने यह भी निश्चय किया, कि वे रोम को छोड़कर अन्यत्र जा बसे। पर कुलीन लोग उन्हें समझा बुझाकर रोम में वापस लौटा लाये। जनसाधारण के आन्दोलन का परिणाम यह हुआ, कि धीरे-धीरे उन्हें शासन में अनेक अधि-

कार प्राप्त हो गये। पर रोम में लोकतन्त्र शासन की स्थापना पूरी तरह से नहीं हो सकी। शासन कुलीनो के ही हाथों में रहा। जनसाधारण ने अपने अधिकारों के लिये अधिक संघर्ष की आवश्यकता भी नहीं समझी, क्योंकि इस समय रोम अपने साम्राज्य का विस्तार करने में लगा था। सम्पूर्ण इटली व अन्य प्रदेशों में धन सम्पत्ति प्रचुर परिमाण में रोम पहुँच रही थी। इस सम्पत्ति का उपभोग करने का अवसर रोम के प्लेबियन लोगों (जन साधारण) को भी प्राप्त होता था। वे इससे सन्तुष्ट थे।

चौथी सदी ई० पू० में रोम साम्राज्य विस्तार में प्रवृत्त हुआ। आर्यों की लेटिन शाखा के जो विविध राज्य इटली में कायम थे, उन्हें ३३८ ई० पू० तक रोम ने विजय कर लिया। २८० ई० पू० में रोम ने ऐट्रुस्कन लोगों के राज्य को भी जीत लिया। इटली के समुद्र तट पर जो अनेक ग्रीक उपनिवेश विद्यमान थे, वे भी २७५ ई० पू० में रोम के हाथ में आ गये। तीसरी सदी ई० पू० के अन्त तक सम्पूर्ण इटली में रोम का आधिपत्य स्थापित हो गया।

इटली विजय कर लेने से रोम एक अत्यन्त शक्तिशाली राज्य बन गया था। उस समय भूमध्यसागर के विविध द्वीपों और तटवर्ती प्रदेशों पर कार्थेज का अधिकार था। कार्थेज उत्तरी अफ्रीका के समुद्र तट पर एक समृद्ध व शक्तिशाली नगर था। इसकी स्थापना ८१४ ई० पू० में हुई थी। कार्थेज के निवासी फिनीशियन जाति के थे। इस जाति का निवासस्थान पैन्टेस्टाइन के उत्तर में भूमध्यसागर के तट पर था। टायर और सीडोन इन के प्रमुख नगर थे। समुद्रतट पर बसे होने के कारण फिनीशियन लोग जहाज बनाने और उनमें व्यापार करने में बहुत चतुर थे। टायर और सीडोन में बहुत से फिनीशियन व्यापारी निवास करते थे, और ये लोग समुद्र द्वारा दूर दूर तक व्यापार किया करते थे।

८१४ ई० पू० में टायर के कुछ फिनीशियन व्यापारी उत्तरी अफ्रीका में समुद्र तट पर कार्थेज में जा बसे थे। धीरे-धीरे कार्थेज एक समृद्ध व शक्तिशाली नगर बन गया। फिनीशियन लोगों के अपने प्रदेश पर पड़ोसी राज्य निरन्तर हमले करते रहते थे। अतः टायर और सीडोन के बहुत से समृद्ध व्यापारी कार्थेज में जाकर बसने लगे। कुछ ही समय में कार्थेज भूमध्यसागर में व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण केन्द्र बन गया।

जिस प्रकार रोम का नगर-राज्य अपना साम्राज्य बनाने में तत्पर था, वैसे ही कार्थेज भी अन्य राज्यों को अधीन कर अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा था। उन दिनों अफ्रीका के समुद्र तट पर, स्पेन के तट के साथ-साथ व भूमध्यसागर के विविध द्वीपों में अनेक छोटे-छोटे नगर-राज्य विद्यमान थे। अपनी जलशक्ति का प्रयोग कर कार्थेज ने उन्हें जीत लिया। कार्मिका और मार्टिनिया के द्वीप भी उसके हाथ में आ गये। मिस्र पर भी उसने आक्रमण किया, और इस द्वीप का बड़ा भाग कार्थेज के अधीन हो गया।

रोम इटली में अपना साम्राज्य स्थापित कर चुका था। उसकी इच्छा थी, कि मिस्र पर भी जीतकर अपने अधीन कर ले। कार्थेज भी मिस्र में अपनी शक्ति बढा रहा था। उस दशा में यह स्वाभाविक था, कि उनमें युद्ध शुरू हो। रोम और कार्थेज के इस संघर्ष को प्लूटार्क-युद्ध कहते हैं। २८१ ई० पू० में इस युद्ध का प्रारम्भ हुआ। रोम ने इसमें अत्यन्त ही प्रदर्शित की। जलशक्ति का विकास कर उसने शीघ्र ही मिस्र, मार्टिनिया



और कार्सिका को विजय कर लिया। पर कार्थेज इसमें निगड़ नहीं हुआ। हैनिवाल नामक वीर सेनापति के नेतृत्व में उसने स्थल मार्ग में इटली पर आक्रमण किया। उत्तरी अफ्रीका, स्पेन और फ्रान्स होती हुई कार्थेज की सेना ने इटली में प्रवेश किया और उत्तरी इटली का विजय करती हुई हैनिवाल की यह सेना रोम के समीप तक आ पहुची। पर अन्त में रोम की विजय हुई। हैनिवाल परास्त हुआ, और १४६ ई० पू० में रोम ने कार्थेज को बुरी तरह ध्वंस किया। प्यूनिक-युद्धों के कारण कार्थेज की शक्ति नष्ट हो गई, और जो भी प्रदेश उसके अधीन थे, वे सब रोम के साम्राज्य में शामिल हो गये।

रोमन साम्राज्य का विस्तार—कार्थेज की पराजय में रोम की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। मारा उत्तरी अफ्रीका उसके अधीन हो गया था। पश्चिमी भूमध्यसागर के सब द्वीप (कार्सिका, सिसली और सार्डिनिया) उसके हाथ में आ गये थे। स्पेन पर भी उसका प्रभुत्व स्थापित हो गया था। कार्थेज के सब जहाज अब रोम के हाथ में आ गये थे। उसकी जलशक्ति अब बहुत बढ़ गई थी। स्थल और जल, दोनों जगह वह अजेय था।

अपनी जलशक्ति का उपयोग कर रोम ने पूर्व की तरफ अपनी शक्ति का विस्तार शुरू किया। पूर्व के प्रदेश उन दिनों (दूसरी सदी ई० पू०) में मैसिडोनियन लोगों के प्रभुत्व में थे। सिकन्दर ने इन सब प्रदेशों का विजय कर विशाल मैसिडोनियन साम्राज्य की स्थापना की थी। सिकन्दर की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य किस प्रकार खण्ड-खण्ड होकर विविध मैसिडोनियन सेनापतियों के हाथ में आ गया था, इसका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। अब रोम ने इन विविध मैसिडोनियन राज्यों पर आक्रमण शुरू किया। १४६ ई० पू० में मैसिडोनिया और ग्रीस पर रोम ने आक्रमण किया। इनके शासक रोम की शक्तिशाली सेनाओं का मुकाबला नहीं कर सके। वे परास्त हो गये। सम्पूर्ण ग्रीस व मैसिडोनिया अब रोम के अधीन हो गये। कुछ साल बाद कैम्पियन सागर के विविध द्वीपों पर भी रोम ने अपना अधिकार कर लिया। ६४ ई० पू० में एशिया माइनर रोम के हाथ में आ गया। ३० ई० पू० में ईजिप्ट को भी उसने विजय कर लिया।

रोम अपना साम्राज्य का विस्तार केवल पूर्व की ओर ही नहीं कर रहा था। उसकी विविध सेनायें पश्चिम में भी रोम की शक्ति का प्रसार कर रही थी। स्पेन पहले ही उसके हाथ में था। अब फ्रांस का प्रदेश भी उसने विजय कर लिया। फ्रांस में उस समय गॉल नाम की जाति का निवास था। यह भी आर्य जाति की ही एक शाखा थी। इसे विजय कर लेने के कारण रोमन साम्राज्य की पश्चिमी सीमा अटलान्टिक सागर तक पहुँच गई। एशियामाइनर से अटलान्टिक सागर तक और आल्प्स की पर्वत माला से उत्तरी अफ्रीका तक अब रोम का अवाधित शासन था। भूमध्यसागर की स्थिति रोमन साम्राज्य के बीच में एक विशाल झील के समान थी।

इस विस्तृत साम्राज्य का स्वामी कोई एक शक्तिशाली सम्राट् नहीं था। इसका अधिपति रोम का नगर-राज्य था, जिसमें अब भी रिपब्लिक विद्यमान थी। रोम के कुलीन नागरिक अब भी प्रतिवर्ष अपने कांसलों का निर्वाचन करते थे। साम्राज्य के विविध नगरों के पराभव से उनकी अपार सम्पत्ति रोम में एकत्र हो रही थी, और इस

सम्पत्ति को रोम के महत्वाकांक्षी सेनापति अपने राजनीतिक उत्कर्ष के लिये प्रयुक्त करते थे। वोट प्राप्त करने के लिये इस सम्पत्ति को वे पानी की तरह बहाते थे। रोम के नागरिकों के लिये यह परम मन्तोष की बात थी।

रिपब्लिक का अन्त और सम्राटों का शासन—रोम का नगर-राज्य अब एक विशाल साम्राज्य का स्वामी था। शुरु में उसका विस्तार केवल बीस वर्गमील के क्षेत्र में था। उस समय यह सम्भव था, कि उसके नागरिक लोकसभा में सुगमता के साथ एकत्र हो सकें, और अपना कामन स्वयं कर सकें। पर साम्राज्य विस्तार के कारण यह बात सम्भव नहीं रही। इस समय रोम की आन्तरिक दशा में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए—

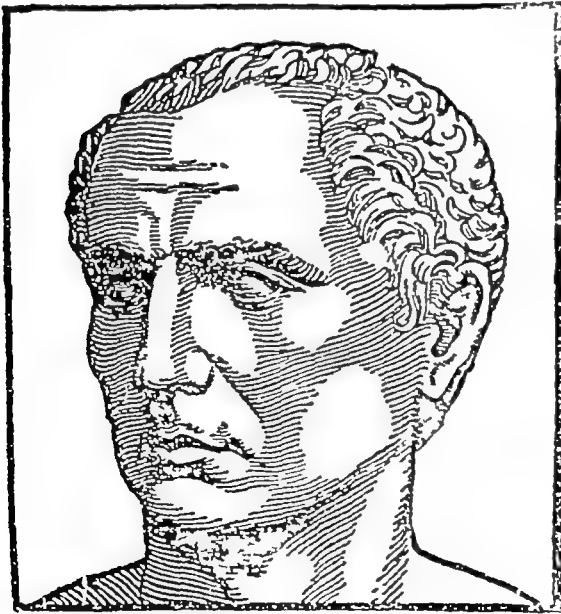
(१) रोम के बहुत से नागरिक सेना में भरती होकर साम्राज्य के दूरवर्ती प्रदेशों में रहने लगे। पहले ये नागरिक अपने खेतों में स्वयं खेती करते थे। अब इनके लिये यह सम्भव नहीं रहा, कि ये स्वयं खेती कर सकें। इनकी जमीनें रोम के धनी मानी लोगों ने खरीद ली और खेती का काम गुलामों द्वारा लिया जाने लगा। पराजित देशों के बहुत से लोग गुलाम के रूप में रोम में विक्री के लिये लाये जाने शुरू हुए, और रोम में कृषि, व्यवसाय आदि का सब काम गुलामों द्वारा होने लगा। रोम के अपने नागरिकों की अपेक्षा इन गुलामों की संख्या बहुत अधिक हो गई।

(२) मुद्गर प्रदेशों में निवास करने वाले रोमन नागरिकों के लिये यह सम्भव नहीं रहा, कि वे लोकसभा या सीनेट (रोम की रिपब्लिक में दो सभाएँ होती थीं, लोकसभा और सीनेट) के अधिवेशनों में शामिल हो सकें। प्रतिनिधि चुनने की प्रथा उस युग में नहीं थी। जो थोड़ा बहुत नागरिक रोम में रहते थे, सब राजसक्ति उनके हाथों में आ गई। ये नागरिक गुलामों की मदद से अपना कारोबार करते थे। इनका अपना काम भोग विलास और मीज बहार में मस्त रहना होता था।

(३) ज्यों ज्यों रोम के साम्राज्य का विकास होता गया, नागरिकता का अधिकार भी अधिक विस्तृत होता गया। इटली की विजय करने पर रोमन लोगों ने इटली के सब लटिन निवासियों को रोम का नागरिक बना दिया। बाद में वे सब इटालियन लोग रोम के नागरिक बना दिये गये, जो गुलाम नहीं थे। कुछ समय बाद साम्राज्य भर के सब स्वतन्त्र निवासियों को (गुलामों को नहीं) रोम की नागरिकता का अधिकार दे दिया गया। पर इन नागरिकों के लिये यह सम्भव नहीं था, कि ये रोम आकर लोकसभा व सीनेट के अधिवेशनों में शामिल हो सकें। अतः असली राजनीतिक शक्ति रोम में रहने वाले नागरिकों के हाथ में रही। कांसल या अन्य उच्च पदों को प्राप्त करने के लिये महत्वाकांक्षी राजनीतिज्ञों के परमस्व एक मांग था, वह यह कि इन राजनिवासियों नागरिकों के वोट प्राप्त हों। ये वोट एक ही तरीके से प्राप्त किये जा सकते थे, नागरिकों को रुपये द्वारा स्मूट किया जाय। जो मैनानि द्वाँ देशों में युद्ध कर उनके समृद्ध नगरों को रोमन साम्राज्य के अधीन कर लेते थे, उनके पास धन सम्पत्ति की कमी नहीं थी। लूट में वे अपार धन प्राप्त करते थे। इस धन का उपयोग वे इन बातों के लिये करते थे, कि रोम के निवासी नागरिकों को धन बाँटकर उनके वोट प्राप्त करें। परिणाम यह था, कि रोम के निवासी गुप्त व धन पाकर मीज बहार में मस्त रहते थे।

(४) पर रोम के निवासी नागरिकों व राजनीतिज्ञों के पास कोई ऐसा साधन नहीं था, जिससे वे अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें। असली शक्ति उन मेनाओं के पास थी, जो साम्राज्य के विस्तार व रक्षा के लिये साम्राज्य के दूरवर्ती प्रदेशों में रहती थी। यदि ये मेनाएँ रोम के रिपब्लिकन शासन के खिलाफ उठ खड़ी हों, तो उन्हें वहाँ लाने का रोम के कामल व नागरिकों के पास क्या उपाय था? इन मेनाओं के मेनापति अपने हाथ में ऐसी शक्ति रखते थे, जिसका प्रयोग कर वे साम्राज्य के शासन-विधान की सर्वथा उपेक्षा कर सकते थे। रोम की मेना में केवल रोमन नागरिक ही नहीं थे, वीरे धीरे बहुत से ऐसे सैनिक भी इसमें भरती कर लिये गये थे, जो न रोमन थे और न इटालियन। ये वेतन पर भरती किये गये थे, और उम मेनापति के प्रति अनुग्रह रहते थे, जो इन्हें वेतन देता था। इनकी सहायता में शक्तिशाली मेनापति रोम के शासन-विधान की सर्वथा उपेक्षा कर सारी ताकत को अपने हाथ में कर सकते थे।

इस दशा का परिणाम यह हुआ, कि जूलियस सीजर नाम के एक शक्तिशाली मेनापति ने रोम से रिपब्लिक का अन्त कर दिया और सारी राजशक्ति को अपने हाथ में कलिया। यह जूलियस सीजर रोमन साम्राज्य की पञ्चिमी मेनाओं का मेनापति था। उसका मुख्य प्रतिस्पर्धी पोम्पे था, जो स्वयं ही जूलियस के समान ही रोमन साम्राज्य का



जूलियस सीजर

एक प्रमुख मेनापति था। पोम्पे को परास्त कर जूलियस रोम का अधिपति बन गया। रोम में यह रिवाज देर में चला आता था, कि एक बड़े समय में किसी व्यक्ति को एकाधिकारी (डिक्टेटर) नियुक्त किया जा सकता था। जूलियस ने इस नियम का लाभ उठाया और सीनेट द्वारा अपने को एकाधिकारी नियत करा लिया। यह डिक्टेटर के पद पर उसकी नियुक्ति दस साल के लिये हुई। ४५ ई. पू० में उसने सीनेट से यह प्रस्ताव स्वीकृत करा लिया, कि डिक्टेटर के पद पर वह जीवन भर रहेगा। जूलियस की शक्तिशाली सेनाओं

के सम्मुख रोम की लोकसभा व सीनेट असहाय थी। वे उसकी इच्छा का विरोध करने का साहस नहीं कर सकती थी।

पर अभी रोम में अनेक ऐसे वीर पुरुष विद्यमान थे, जो अपने राज्य में इस प्रकार रिपब्लिक का अन्त होते हुए नहीं देख सकते थे। उन्होंने पटुपत्र करके जूलियस सीजर की हत्या कर दी। तेरह साल तक रोम के विविध राजनीतिक दलों और विभिन्न सेना

पतियो मे सघर्ष जारी रहा। इस सघर्ष में ओक्टेवियन सीजर को सफलता प्राप्त हुई। अपने सब विरोधियों को परास्त कर २७ ई० पू० मे ओक्टेवियन ने रोमन साम्राज्य की सारी राजशक्ति अपने हाथ मे कर ली। यह ओक्टेवियन सीजर जूलियस सीजर का भतीजा था। अपने चाचा के चरणचिह्नो का अनुसरण कर यह भी रोम का एकाधिकारी बन गया। ओक्टेवियन भलीभांति जानता था, कि रोम के नागरिको मे रिपब्लिक के प्रति प्रेम विद्यमान है। अतः उसने लोकसभा और सीनेट को कायम रखा। पर सारी राजशक्ति अब ओक्टेवियन के हाथ मे थी। उसकी शक्ति का आधार रोम के नागरिको की इच्छा नहीं थी। वह अपनी सेना के बल पर रोम का कर्ता धर्ता बना था और इस सेना पर ही उसकी सत्ता निर्भर थी।

राजशक्ति को अपने हाथ मे लेकर ओक्टेवियन ने प्रिंसिप और आगस्टस की उपाधिया धारण की। उसने अपने को डिक्टेटर नहीं कहा। यह उसकी नीति कुशलता थी। पर वस्तुतः जूलियस सीजर के समान वह भी रोम का एकाधिकारी था। अब रोम मे रिपब्लिक का अन्त होकर सम्राटो के शासन का प्रारम्भ हो गया था। ओक्टेवियन रोम का पहला सम्राट था। उसने २७ ई० पू० मे १५ ई० पू० तक शासन किया।

ओक्टेवियन सीजर के बाद अनेक प्रतापी सम्राटो ने रोमन साम्राज्य का शासन किया। इनमे कुछ के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। क्लोडियस (४१-५४ ई० पू०) के समय मे ब्रिटेन रोमन साम्राज्य मे सम्मिलित हुआ। आर्य जाति की केल्ट शाखा ने वहा जो अनेक राज्य कायम किये हुए थे, वे अब रोम के अधीन हो गये। रोमन साम्राज्य के उत्तर मे रूडन और डैन्यूब नदियों के क्षेत्र मे अनेक जातियो का निवास था। ६९ ई० के लगभग सम्राट व्स्पेसियन (६९-७९ ई० पू०) के समय मे ये रोमन साम्राज्य के अन्तर्गत हो गये। सम्राट ट्राजन (९८-११५ ई० पू०) के समय मे रोमन साम्राज्य अपने विस्तार की चरम सीमा तक पहुँच गया। पूर्व मे आर्मीनिया और मेसोपोटामिया के प्रदेशो को ट्राजन ने जीतकर अपने अधीन कर लिया। अब रोमन साम्राज्य की सीमा उत्तर मे रूडन नदी, पूर्व मे डैन्यूब नदी, दक्षिण मे सहारा का मरुस्थल और पश्चिम मे ब्रिटेन के पश्चिमी समुद्र तट तक विस्तृत थी।

साम्राज्य का पतन—पर यह विद्याल रोमन साम्राज्य देर तक कायम नहीं रह सका। उसके दो कारण थे—(१) साम्राज्य की आन्तरिक निर्बलता, और (२) विविध जातियो के आक्रमण। रोम मे सम्राटो की शक्ति का मुख्य आधार उनकी सेनाये थी। सेना जिने चाहती, सम्राट के पद पर बिठाती थी। कई बार ऐसा भी होता था, कि एक साथ अनेक व्यक्ति विभिन्न प्रदेशो मे अपने को सम्राट घोषित कर देते थे, और अपनी सेनाया की मदद से रोम की राजगद्दी पर अधिकार प्राप्त करने के लिये सघर्ष करते थे। सेनाया के विविध नेता सम्राट के राजमुकुट को पद की तरह उछालने लगे थे। इस दशा मे यह गुप्त नहीं था कि रोमन साम्राज्य विदेशी आक्रमणो का शिकार के साथ-साथ स्वदेशी का शिकार भी हो रहा था।

तीसरी सदी मे अनेक जातियो ने उत्तर की दिशा से रोमन साम्राज्य पर हमले शुरू किये। इन हमले रूडन और डैन्यूब नदियों के उत्तर मे अनेक पराक्रमी जातियाँ का

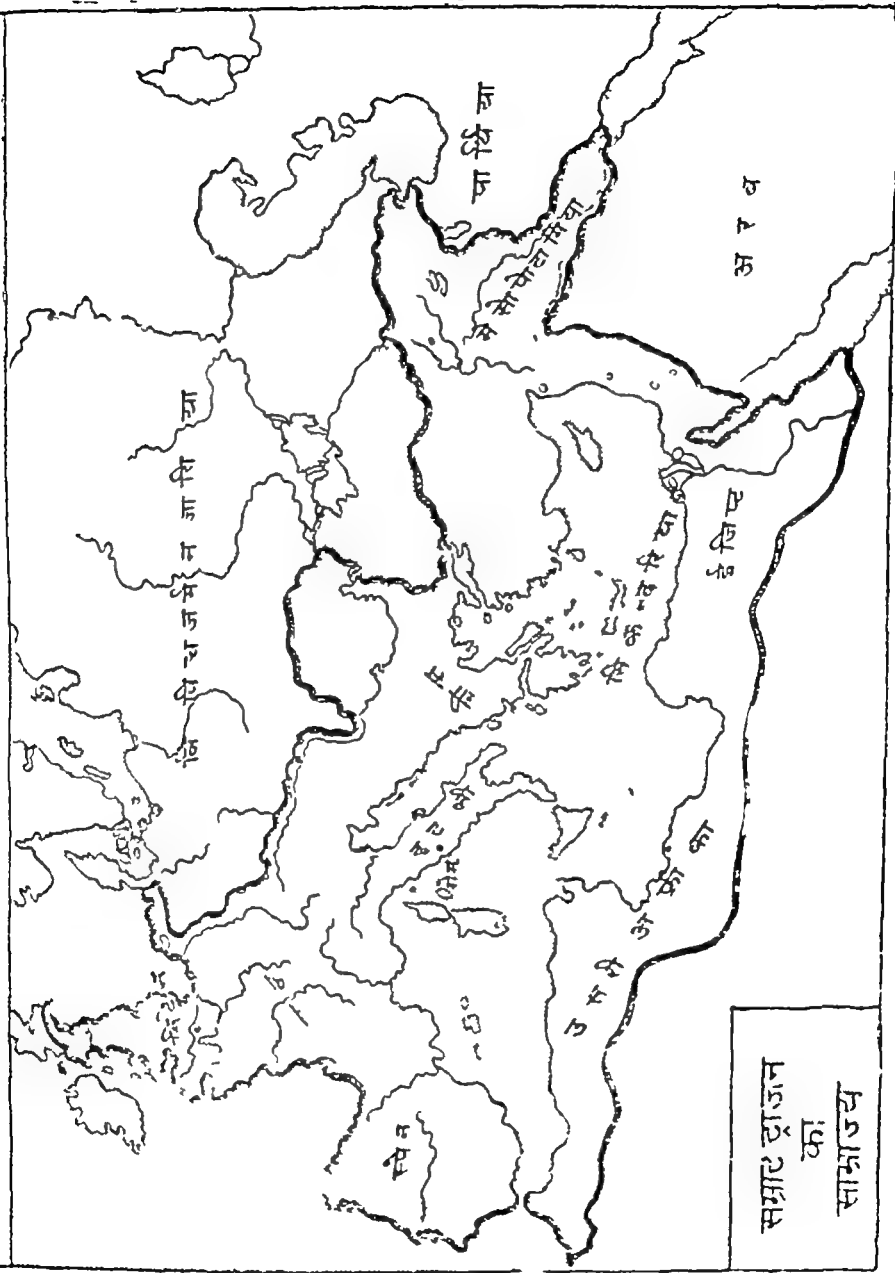
का निवास था। ये आर्य जाति की ही विविध शाखाएँ थीं, और इन्हें जर्मन व द्युटानिक कहते थे। तीसरी सदी में शुरू होकर चौथी और पाचवी सदियों में जर्मन जातियों के आक्रमण निरन्तर जारी रहे। फ्रांक, लोम्बार्ड, ऐंगल आदि जर्मन जातियाँ रोमन साम्राज्य के विविध प्रदेशों पर कब्जा कर के वहाँ बसनी शुरू हुई। आज भी इन प्रदेशों के नाम इन्हीं जातियों के नाम पर हैं। फ्रांक लोग जहाँ बसे, वह प्रदेश फ्रान्क कहलाता है। इसी तरह लोम्बार्ड लोगों के प्रदेश को लोम्बार्डी और ऐंगल लोगों के प्रदेश को इंग्लैण्ड कहते हैं।

रोमन लोगों के सम्पर्क में आकर इन जातियों ने रोमन सभ्यता और सभ्यता को अपना लिया। उन्होंने जो विविध राज्य कायम किये, यद्यपि वे स्वतन्त्र थे, पर उनमें से कतिपय रोमन सम्राट की प्रभुता को स्वीकार करते थे। यही कारण था, कि यद्यपि इन जर्मन जातियों के आक्रमणों में रोमन साम्राज्य खण्ड-खण्ड हो गया था, पर ऊपर से देखने पर उसका वैभव और प्रभाव अब भी कायम था।

**साम्राज्य का विभाग**—चौथी सदी के अन्तिम भाग में रोमन सम्राट के पद पर थियोडोसियस विराजमान था। उसके प्रधान सेनापति जर्मन जाति के थे। साम्राज्य की पश्चिमी सेनाओं का सेनापति स्टिलिको था, जो वेंडल जाति का था। पूर्वी सेनाओं का सेनापति एलेरिक था, जो गोथ जाति का था। वेंडल और गोथ दोनों जर्मन जाति की ही शाखाएँ थीं। यद्यपि सम्राट के पद पर थियोडोसियस था, पर वास्तविक राजशक्ति इन दो सेनापतियों के हाथ में थी। ३९५ ई० में सम्राट थियोडोसियस की मृत्यु हो गई। उसके दो लड़के थे, आर्केडियस और होनोरियस। रोमन साम्राज्य के राजमहामन पर कौन आरुढ़ हो, इस प्रश्न पर इनमें लड़ाई शुरू हो गई। सेनापति एलेरिक ने आर्केडियस का पक्ष लिया, और कान्स्टेन्टिनोपल में उसे सम्राट घोषित कर दिया। इसी तरह सेनापति स्टिलिको ने होनोरियस का पक्ष लिया, और इटली में उसके सम्राट बनने की प्रोपणा कर दी। इस समय से रोमन साम्राज्य दो विभागों में विभक्त हो गया—(१) पूर्वी साम्राज्य—इसकी राजधानी कान्स्टेन्टिनोपल थी। इसके अन्तर्गत प्रदेशों में ग्रीक भाषा और ग्रीक सभ्यता का प्रभुत्व था। (२) पश्चिमी साम्राज्य—इसका केन्द्र रोम था, और इनके प्रदेशों में लैटिन भाषा और रोमन सभ्यता का प्राबल्य था। पूर्वी रोमन साम्राज्य १४५३ ई० तक कायम रहा। तुर्क लोगों ने पन्द्रहवीं सदी में इस साम्राज्य का अन्त किया। पर पश्चिमी रोमन साम्राज्य की सत्ता देर तक कायम नहीं रह सकी। हूणों के आक्रमणों के कारण शीघ्र ही उसका अन्त हो गया।

**हूणों के आक्रमण**—मध्य एशिया के उत्तर में चीन की सीमा पर एक बर्बर जाति का निवास था, जिसे हूण कहते थे। इसी के आक्रमणों से परेशान होकर चीन के शक्तिशाली सम्राट टिशनशी ने १८०० मील लम्बी दीवार बनवाई थी। इसी के हमलों के कारण भारत का गुप्त साम्राज्य खण्ड-खण्ड हो गया था। पाचवी सदी में रोमन साम्राज्य पर भी हूणों के आक्रमण शुरू हुए। इस समय इनमें एक वीर नेता का प्रादुर्भाव हुआ, जिसका नाम एट्टिला था। मध्य एशिया से पश्चिम की तरफ आगे बढ़कर उसने र्हाइन नदी तक अपना प्रभुत्व कायम कर लिया। अब उसने रोमन साम्राज्य पर हमले शुरू किये। हूण लोग टिड्डी दल के समान आते थे। वे जिधर भी निकल जाते थे, शहरों और वस्तियों को ध्वस्त

# रोमन साम्राज्य का विस्तार



कर देते थे। वालरून प्रायद्वीप में उन्होंने ७० में ऊपर नगरो को नष्ट कर दिया। फ्रांस में उनके आक्रमणों से हाहाकार मच गया। इटली में हमला कर उन्होंने मिलान आदि कितने ही नगरो को भूमिमात किया। उनके आक्रमणों के कारण रोमन साम्राज्य की शक्ति जड़ में टूट गई। फ्रांस, लोम्बार्ड, वेन्डल, गोथ आदि विविध जर्मन जातियों के सरदार एट्रिला के मुकाबले में नहीं टिक सके। ४५६ ईस्वी में वींग हूण विजेता एट्रिला की मृत्यु हुई।

पश्चिमी रोमन साम्राज्य का अन्त—हूणों के आक्रमणों के कारण पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजशक्ति अत्यन्त निर्बल हो गई थी। सब जगह अव्यवस्था और अशान्ति विद्यमान थी। ऐसे समय में रोम में एक ऐसा शक्तिशाली सम्राट नहीं था, जो कि विविध सरदारों को काबू में कर के साम्राज्य को सम्भाल सके। ४५६ में ४५५ ई० तक बीस सालों में रोम में दस सम्राटों ने शासन किया। ये सब निर्बल और अशक्त थे। उस दशा में विविध जर्मन जातियों के सरदार अपने अपने प्रदेशों में पूर्ण रूप में स्वतन्त्र हो गये। ब्रिटैन, फ्रांस, स्पेन, लोम्बार्डी आदि सब प्रदेश रोम की अधीनता में मुक्त हो गये और वहाँ नये राज-वंशों ने स्वतन्त्र रूप से शासन प्रारम्भ कर दिया। ४५५ ईस्वी में ग्लाम रोम में भी गोथ जाति के एक सरदार ने अन्तिम रोमन सम्राट को पदच्युत कर अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर लिया। पूर्वी रोमन साम्राज्य का अब अन्त हो गया था। पर कान्स्टेन्टिनोपल में अब भी पश्चिमी रोमन सम्राटों का शासन विद्यमान था। वहाँ को तो कान्स्टेन्टिनोपल के सम्राट 'रोमन' थे, पर वस्तुतः उन के साम्राज्य में ग्रीक संस्कृति का प्रभुत्व था।

### ३. इसाई धर्म का प्रादुर्भाव

यहूदी लोग—हम इस इतिहास में फिनीशिया का जिक्र कर चुके हैं। यह प्रदेश एशिया माइनर के दक्षिण में भूमध्य सागर के तट पर विद्यमान था। फिनीशिया के ठीक नीचे पैलेस्टाइन का प्रदेश था, जिस में यहूदी लोग निवास करते थे। यद्यपि यहूदी लोग इस प्रदेश में १००० ई० पू० से भी पहले आबाद हो गये थे, पर उन्होंने किसी शक्तिशाली राज्य का विकास नहीं किया था। उनका प्रदेश मैसोपोटामिया और ईजिप्ट के बीच में था, अतः इन शक्तिशाली देशों के राजा समय समय पर इस पर आक्रमण करते रहते थे। बाद में जब पर्शिया, मैसोपोटामिया और रोम के शक्तिशाली राज्यों का विकास हुआ, तो पैलेस्टाइन उन के अधीन रहा। यही कारण है, कि राजनीतिक दृष्टि से यहूदी लोगों का सत्तार के प्राचीन इतिहास में कोई विशेष महत्त्व नहीं रहा।

जीसस ख्रिस्ट—जिस समय ओवर्टा दन सीजर रोम में रिपब्लिक का अन्त कर सारी राजनीतिक शक्ति अपने हाथ में कर रहा था, रोमन साम्राज्य के इस सुदूरवर्ती प्रदेश (पैलेस्टाइन) में एक महात्मा का प्रादुर्भाव हुआ, जिसका नाम जीसस या यीशु था। वह एक यहूदी कुल में उत्पन्न हुआ था। उसके प्रारम्भिक जीवन के सम्बन्ध में कोई वृत्तान्त उपलब्ध नहीं होता। इसाई लोग उसे ईश्वर का पुत्र मानते हैं, और यह समझते हैं, कि वह भगवान का अवतार था। जीसस ने यहाँ यों में एक नये धर्म का प्रचार करना शुरू किया। वह कहता था, हमें पृथिवी को स्वर्ग बनाने का यत्न करना चाहिए, पृथिवी पर स्वर्ग का राज्य स्थापित करना चाहिए। परमेश्वर का पिता है, उसके सामने सब बराबर है।

जिन प्रकार मूर्त्य प्राणिमात्र को समान रूप से रोगनी देता है, वैसे ही परमेश्वर की दी हुई वस्तुएँ भी सब के लिए एक सी हैं। ईश्वर किसी का पक्ष नहीं लेता, उसके लिये सब मनुष्य एक मद्दह हैं। जीसस ने जो उपदेश दिये, वे बाइबल में सगृहीत हैं। उसके अनुयायी ईसाई कहते हैं, और वे बाइबल को अपनी धर्म-पुस्तक मानते हैं। उनकी दृष्टि में बाइबल ईश्वरीय ज्ञान है।

धीरे-धीरे बहुत से लोग यीशु के शिष्य होते गये। वह एक ईश्वर के अतिरिक्त अन्य देवी-देवताओं को नहीं मानता था। पर उस समय के रोमन लोग विविध देवी-देवताओं की पूजा करते थे। जब रोम में रिपब्लिक का अन्त हुआ, तो साम्राज्य के निवासी रोमन सम्राट् की भी देवता के रूप में पूजा करने लगे। सम्राट् की पुरानी सभ्यताओं में राजा को देवता का रूप माना जाता था। ईजिप्ट, बैबिलोन आदि के शासक जहाँ राजा थे, वहाँ साथ ही प्रधान धर्माध्यक्ष भी होते थे। जनता उन्हें साक्षात् देवता मानती थी। विगल रोमन साम्राज्य के अन्तर्गत विविध प्रदेशों में राजा को देवी मानने की परम्परा देर से चली आती थी। जब रोम में रिपब्लिक का अन्त होकर सम्राट् (प्रिंसिप व सीजर) का शासन शुरू हुआ, तो जनता उसे भी देवी मानने लगी, और देवता रूप में उसकी पूजा भी करने लगी। पर जीसस कहता था, ईश्वर केवल एक है। केवल एक ईश्वर की ही पूजा करना उचित है, अन्य देवताओं की पूजा ठीक नहीं। रोमन साम्राज्य के कर्मचारियों ने इसे राजद्रोह समझा। जीसस को राजद्रोह में गिरफ्तार कर लिया गया और उसे प्राणदण्ड दिया गया। जीसस को मृत्ती पर चढ़ाने के समय में ही ईस्वी सन् का प्रारम्भ होता है। इसी पन को हम हम इतिहास में प्रयत्न कर रहे हैं।

ईसाई धर्म का प्रचार—जीसस के समय उसकी शिष्याओं का प्रचार केवल पैलेस्टाइन में हुआ था। पर उस के शिष्य बड़े कर्मठ थे। राज्य की शक्ति उन्हें प्राप्त नहीं थी, तब भी राजा और राज कर्मचारी उन पर घोर अत्याचार करते थे। पर सब प्रकार के कष्टों और अत्याचारों को सहते हुए भी ईसाई भिक्षु अपने गुप्त की शिक्षाओं के प्रचार में तत्पर थे। रोमन साम्राज्य में जनसाधारण की दशा अच्छी नहीं थी। दुःखी व पीड़ित जनता जीसस की शिक्षाओं से सान्त्वना और शक्ति प्राप्त करती थी। धीरे-धीरे ईसाई धर्म का प्रचार बहुत बढ़ता गया। सर्वसाधारण जनता उसकी अनुयायी होती गयी।

सम्राट् कांस्टेन्टाइन—३०६ ईस्वी में कांस्टेन्टाइन रोम का सम्राट बना। इस समय रोमन साम्राज्य पर जर्मन जातियों के आक्रमण बड़े प्रबल रूप में हो रहे थे। इनके कारण साम्राज्य की दशा बहुत खराब थी। कांस्टेन्टाइन ने अनुभव किया, कि साम्राज्य की रक्षा के लिये जनता की सहानुभूति प्राप्त करना उपयोगी है। उस ने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया। उस समय तक ईसाई में अच्छी शक्ति प्राप्त नहीं हुई थी। इन सब का सहयोग कांस्टेन्टाइन को प्राप्त हो गया और वह कुछ समय के लिये रोमन साम्राज्य को सन्तान प्रदान हुआ। कांस्टेन्टाइन का आख्य पक्ष ईसाई धर्म ने जीत भी उन्नति की। जब वह रोमन साम्राज्य का राजतन हो गया। कांस्टेन्टाइन ने साम्राज्य के पूर्वी प्रदेश में कांस्टेन्टिनियम को अपनी राजधानी बनाया था। उसके नाम से इस नगर का नाम कांस्टेन्टिनोपल हो गया। जब विगल रोमन साम्राज्य दो भागों में विभक्त हुआ, तो यह



कान्स्टेन्टिनोपल ही पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी बना।

## ४ मध्यकालीन यूरोप

**सामन्त पद्धति का विकास**—विविध जर्मन जानियों के जात्रमणों में विशाल रोमन साम्राज्य किस प्रकार गूँट गूँट हो गया था, इसका उन्हेन्ग हम पहले कर चुके हैं। पाचवी सदी के बाद यूरोप में रोमन साम्राज्य का सर्वथा शेष हो गया था, और उसके स्थान पर अनेक छोटे बड़े राज्य कायम हो गये थे। इन राज्यों की सभ्यता कम होती थी, सैकड़ों नहीं, अपितु हजार में भी अधिक थी। छठी और सातवी सदी, यूरोप के इतिहास में अव्यवस्था और अराजकता की सदिया थी। जिन जर्मन जानियों ने शत्रुमण कर रोमन राज्य को छिन्न-भिन्न कर दिया था, उनके सैकड़ों पन्तारों ने भिन्न-भिन्न स्थानों पर जपन स्वतन्त्र राज्य कायम कर लिये थे। उनके अतिरिक्त, जो प्रदेश जर्मन जानियों के जात्रमण में बचे रहे थे, उन पर पुगने युग के राजकर्मचारी या बड़े जमींदार स्वतन्त्रता के साथ शासन करने लगे थे। कोई-कोई प्रदेश ईसाई महन्ता के हाथ में थे। ईसाई मठों व गिरजा के पास विशाल सम्पत्ति थी, और उनके महन्त वैभव के साथ जीवन व्यतीत करने थे। रोमन शक्ति के क्षीण होने पर भी ये महन्त अपने-अपने प्रदेश में स्वतन्त्र हो गये थे। समुद्र या नदियों के तट पर अनेक व्यापारिक नगरों का विकास समन युग में हुआ था। इन नगरों के व्यापारी समूहों (निगमों) में संगठित थे, अब ये निगम स्वतन्त्र हो गये थे, और राजनीतिक शक्ति भी इन्होंने प्राप्त कर ली। मन्तव्य यह है, कि यह काल राजनीतिक दृष्टि से सर्वथा अराजकता का था। जिसके पाम गकिन थी, वही अपनी सत्ता कायम किया हुआ था। सर्वसाधारण जनता की जान और माल तब तक सुरक्षित नहीं थे, जब तक वह अपने को किसी शक्तिशाली व्यक्ति की मरझता में न ले आवे। इसी परिस्थिति में सामन्त पद्धति का जन्म हुआ।

अव्यवस्था और अराजकता के इस युग में सामन्त पद्धति द्वारा धीरे-धीरे व्यवस्था का विकास हुआ। जिन प्रदेशों पर कोई विजेता सरदार अपना अधिकार स्थापित करता था वहाँ वह जीते हुए प्रदेश को अपने साथियों में बाँट देता था। यदि उस विजेता परदाग का हम राजा कहें, तो उसके इन साथियों को हमें सामन्त कहना चाहिये। यद्यपि ये सामन्त अपनी जागीर राजा से प्राप्त करते थे, पर अपने प्रदेश के पूरे स्वामी होते थे। राजा के साथ उनका यह सन्ध रहता था, कि जब राजा को आयश्यकता होवे अपने सैनिकों के साथ राजा की सहायता करे। कौन सामन्त कितने सैनिक लावे, यह बात गिवाज द्वारा निश्चित होती थी। इस सैनिक सहायता के अतिरिक्त, ये सामन्त विशेष अवसरों पर राजा की सेवा में विविध प्रकार के उपहार भी भेंट किया करते थे। कोई निश्चित टैक्स इन्हें नहीं देना पड़ता था। जब तक ये राजा के विरुद्ध विद्रोह न करे, उस के प्रति अनुग्रहत रहे, तब तक जागीर पर इनका व इनकी सन्तान का अधिकार रहता था। सामन्त लोग भी अपनी जागीर को अपने साथियों में बाँट देते थे। इस प्रकार सामन्तों के भी सामन्त होते थे। उनका सम्बन्ध अपने स्वामी से ठीक उसी प्रकार का होता था, जैसा कि बड़े सामन्त का अपने राजा से।

जिन प्रदेशों पर किसी विजेता सरदार ने अधिकार स्थापित नहीं किया था, वहाँ भी इसी ढंग की सामन्त पद्धति का विकास हो गया था। वहाँ के निर्वल लोगो ने अपने प्रदेश के शक्तिशाली व्यक्ति के साथ और इन शक्तिशाली व्यक्तियों ने उस प्रदेश के और अधिक प्रबल मनुष्य के साथ इसी पद्धति में सम्बन्ध कर लिया था। सामन्त पद्धति एक पिरामिड के समान थी, जिसमें सब से ऊपर एक प्रतापी राजा व राजाधिराज होता था, उनके नीचे कुछ बड़े-बड़े सामन्त, उनके नीचे बहुत से राव राजा और सब से नीचे अनगिनत जागीरदार व ठाकुर होते थे।

सामन्त पद्धति के समय में विविध राजाओं में परस्पर संघर्ष चलता रहता था। जो राजा हार जाता था, वह प्रायः विजेता का सामन्त बन जाता था। अनेक प्रतापी सामन्त अपने राजा के विरुद्ध विद्रोह कर अपने को स्वतन्त्र राजा बनाने का भी उद्योग करते रहते थे। इस प्रकार सामन्त पद्धति के युग में शान्ति या व्यवस्था कायम नहीं रह सकती थी। पाँचवीं और छठी सदियों में यूरोप के विविध सरदारों व राजाओं में यह संघर्ष निरन्तर जारी रहा। बाद में कुछ शक्तिशाली राजा इस बात में सफल हुए, कि बहुत से सामन्तों व राजाओं को जीतकर उन्हें पूरी तरह से अपने अधीन कर ले और एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना करें।

**शार्लमेगन**—विविध सामन्तों और राजाओं के इस संघर्ष में सबसे अधिक सफलता चार्ल्स को मिली। यह चार्ल्स मार्टेल उन सब प्रदेशों का अधिपति था, महाराजाधिराज था जहाँ अब फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैण्ड, जर्मनी और आस्ट्रिया के राज्य विद्यमान हैं। यह मतलब नहीं कि इन विस्तृत प्रदेशों का वह एकलव्य सम्राट था। इन प्रदेशों में बहुत से छोटे-बड़े सामन्त राजा राज्य करते थे, पर वे सब इस चार्ल्स मार्टेल का आधिपत्य स्वीकार करने लगे। चार्ल्स मार्टेल का शासनकाल ७५१ ईस्वी में शुरू हुआ। उस के बाद उसका लड़का पपिन और फिर शार्लमेगन (७६८ ई०) इस विस्तृत साम्राज्य का अधिपति बना। शार्लमेगन ने अपने साम्राज्य को और अधिक विस्तृत किया। पहले उसने उत्तरी इटली का विजय किया और बाद में (७७५ ई०) रोम भी उसकी अधीनता में आ गया।

अब शार्लमेगन फ्रांस, जर्मनी, हॉलैण्ड, बेल्जियम आस्ट्रिया और इटली का स्वामी था। रोम उसके अधीन था। उसका साम्राज्य पुगने रोमन साम्राज्य का सम्मरण दिलाता था। रोमन साम्राज्य की स्मृति अभी तक जीवित थी। रोम का राजनीतिक साम्राज्य यद्यपि नष्ट हो चुका था, पर रोम का धार्मिक साम्राज्य अभी तक विद्यमान था। रोम के पापपाप के ईसाई जगत के धर्मचक्रवर्ती होने थे। रोम के धार्मिक साम्राज्य ने रोम के राजनीतिक साम्राज्य की वृद्धि को भी जीवित रखा हुआ था। अब शार्लमेगन द्वारा इसी वृद्धि को मनुष्य धारण करने का अवसर प्राप्त हुआ।

**पपिन रोमन साम्राज्य का प्रारम्भ**—७९५ ई० में पाप के प्रभावशाली पद पपिन को दीया गया था। रोम में लियोनतीस के विरोधी बहुत अधिक थे। ७९० ई० में जब रोम में एक जटिल नकल पहा था लियोन पन हमला हुआ और उसे विवश होकर रोम में भागना पड़ा। उस समय इटली शार्लमेगन के अधीन में था। उन स्वभाविक रूप से लियोन की वृद्धि को रोकने के लिये शार्लमेगन की सहायता की। ८०० ईस्वी में शार्ल-

मेगन की मृत्युता से लियो तृतीय ने फिर रोम में प्रवेश किया और पोप की गद्दी पर अगार किया।

८०० ईस्वी में त्रिपमस के दिन एक बड़ी महत्त्वपूर्ण घटना हुई। जिस समय चार्ल्स मेगन पीटर के गिरजे में प्रार्थना कर के उठ रहा था, पोप लियो तृतीय ने उसके लिए पर राजमुकुट धर उसे 'मीजर' और 'आगस्टस' के रूप में सम्बोधित किया। 'मीजर' और 'आगस्टस' प्राचीन रोमन सम्राटों की उपाधिया थी। चार्ल्समेगन को मीजर और आगस्टस बनाकर लियो तृतीय ने रोमन साम्राज्य का पुनर्स्थापन किया। क्योंकि य नए रोमन सम्राट् पोप से अभिषिक्त होकर सम्राट् पद को प्राप्त करने थे, अतः इन्हें 'पवित्र रोमन सम्राट्' और उनके साम्राज्य को "पवित्र रोमन रोमन साम्राज्य" (होरी रोमन एम्पायर) कहने लगे।

४७६ ई० में पश्चिमी रोमन साम्राज्य का अन्तिम रूप में विनाश हुआ था। जब आठवीं और नवीं शताब्दियों के मध्यकाल में, ८०० ईस्वी के त्रिपमस के दिन इसका पुनरुद्धार हुआ। यद्यपि कहने को यह रोमन साम्राज्य था पर इसकी शक्ति का केन्द्र इटली न होकर जर्मनी था। ये नये रोमन सम्राट् अशक्त रूप में एकत्रित सामन नहीं कर सकते थे, क्योंकि इनकी शक्ति उन अनगिनत सामन्तों पर आश्रित थी जो मद्रा विद्रोह और स्वेच्छाचार के लिये उद्यत रहते थे। पवित्र रोमन सम्राट् का पद भी चार्ल्समेगन के वंशजों में सदा स्थिर नहीं रहा। जब अन्य राजवंश अधिक प्रबल हो गये और अन्य राजाओं व सामन्तों को अपनी प्रभुता स्वीकृत कराने में समर्थ हुए, तो पवित्र रोमन सम्राट् का पद भी उन वंशों में चला गया।

चार्ल्समेगन के उत्तराधिकारी—८१४ ईस्वी में चार्ल्समेगन की मृत्यु हुई। इसमें सन्देह नहीं, कि वह बड़ा प्रतापी और शक्तिशाली सम्राट था। उसकी विजयों के कारण एक बार फिर कुछ समय के लिये यूरोप में राजनीतिक एकता स्थापित हो गई थी। पर यह एकता देर तक कायम नहीं रही। चार्ल्समेगन की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के सम्बन्ध में लड़ाई प्रारम्भ हो गई। चार्ल्समेगन का साम्राज्य बहुत विस्तृत था। उसमें भाषा, नस्ल आदि की दृष्टि से अनेक भिन्नताये थी। रूहाइन नदी को पारकर उसके पश्चिम व दक्षिण में जो जर्मन जातियाँ बसी थी, वे शीघ्र ही रोमन सभ्यता के असर में आ गई थी। प्रदेस रोमन साम्राज्य के अन्तर्गत रह चुके थे, अतः इनमें बसनेवाले फ्रेन्क आदि जर्मन जातियों के लोग बहुत कुछ रोमन प्रभाव में आ गये थे। इसके विपरीत रूहाइन नदी के उत्तर और पूर्व में आबाद हुए जर्मन लोग रोमन सभ्यता के असर में पर्वथा वंचित रहे। परिणाम यह हुआ, कि रूहाइन के पश्चिम और पूर्व के प्रदेशों में भिन्न-भिन्न प्रकार से सभ्यता विकसित होने लगी। चार्ल्समेगन के वंशधरों के पारस्परिक झगड़ों के कारण ये दोनों प्रदेश एक दूसरे से राजनीतिक दृष्टि से पृथक् हो गये। रूहाइन के पश्चिम में फ्रेन्क के पृथक् राज्य का निर्माण हुआ, जो पवित्र रोमन साम्राज्य के अन्तर्गत नहीं था। वह इनके पूर्व में विविध राजा व महाराजा पवित्र रोमन साम्राज्य के अन्तर्गत रहते हुए निरन्तर एक दूसरे के साथ संघर्ष में व्यापृत रहे। इन शक्तिशाली राजाओं की यह आकांक्षा रहती थी, कि वे अन्य सब को वशवर्ती रख कर रोम में जाकर पोप द्वारा अपना राज्याभि

पेक करवे, और इस प्रकार पवित्र रोमन सम्राट् के गौरवशाली पद को प्राप्त करे। फ्रांस के अतिगिम्न पश्चिमी यूरोप के विविध प्रदेश स्थूल रूप से इस रोमन साम्राज्य के अन्तर्गत मान जाते थे। पर इस 'साम्राज्य' की सीमा बढ़ती-बढ़ती रहती थी। यह पवित्र रोमन सम्राट् की अपनी शक्ति पर निर्भर था कि वह कितने सामन्त राजाओं (जो ड्यूक, अर्ल्, बॅरन् आदि कहलाते थे) को अपने अधीन व वशवर्ती रख सकता है।

इङ्ग्लैण्ड—इङ्ग्लैण्ड पवित्र रोमन साम्राज्य के अन्तर्गत नहीं रहा। वहाँ जिस एंग्लो-सैक्सन जाति ने आक्रमण कर रोमन शासन का अन्त किया था, उसी के विविध सन्तान वहाँ पर शासन करते रहे। धीरे-धीरे वहाँ भी सामन्त-पद्धति का विकास हुआ और नवी सदी के शुरू (८२८ ईस्वी) में एग्वर्ट नाम का राजा इङ्ग्लैण्ड के अन्य राजाओं को अधीनता में लाने में सफल हुआ। एग्वर्ट के उत्तराधिकारी भी प्रतापी और महत्वाकांक्षी थे। वे ग्यारहवीं सदी के मध्य तक इङ्ग्लैण्ड में अपना अवाधित शासन कायम रखने में सफल रहे।

## ५ क्रूसेड

छठी शताब्दी के अन्त में अरब के मरुस्थल में एक महान नेता तथा मुधारक का जन्म हुआ। इसका नाम था मुहम्मद। मुहम्मद से पूर्व अरब में बहुत सी छोटी-छोटी जातियाँ थीं जो निरन्तर आपस में लड़ती रहती थीं। अरब लोग देवी-देवताओं की पूजा करते थे और अनेक विविध-विधानों तथा पूजा-पाठ द्वारा उन्हें मनुष्य मानते थे। मुहम्मद ने अरब के इस पुराने धर्म में सुधार किया। ईश्वर एक है, सब मनुष्य उस एक ईश्वर के पुत्र हैं, सब परस्पर भाई हैं—उन सिद्धान्तों का प्रचार मुहम्मद ने किया। इतना ही नहीं, मुहम्मद ने अरब की विविध जातियों को संगठित कर उसे एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में परिवर्तित किया। उसके बाद अरब लोगों ने बड़ी उन्नति की। देवते-देवते अरब का साम्राज्य पूर्व में पिरमिड तक और पश्चिम में स्पेन तक विस्तृत हो गया। मिस्र, विलोचिस्तान, पर्सिया, ईरान, जाम्बीनिया, काशगर, तुर्किस्तान, एशिया माइनर, पैलेस्टाइन, ईजिप्ट, उत्तरी अफ्रीका और स्पेन—ये सब प्रदेश अरब साम्राज्य के अन्तर्गत थे। सभ्यता के क्षेत्र में भी अरब लोगों ने बड़ी उन्नति की। गणित, ज्योतिष, चिकित्सा आदि के क्षेत्र में इन अरबों ने बहुत सी नई बातें कीं। अरब लोग वैश्विक क्षेत्र में भी महिमा पाये। ईसाइयों की उस समय परलोकगत धर्म के साम्राज्य के अन्तर्गत थी—पर वह तीसरे वर्ग के शत्रु माने जाते ईसाइयों की। एग्वर्ट अन्तर्गत नहीं आने ।

सभ्यता और सभ्यता के क्षेत्र में अग्रेजी में परास्त हो गये। यूडिश, कुशाण और हूण जातियाँ जिन प्रकार भारत का उन्नत सभ्यता के सम्पर्क में आकर भारत की सभ्यता का अपना देने के लिये विवश हुई थी, वैसे ही तुर्क जातियाँ अग्रेजी की सभ्यता व धर्म को स्वीकार करने के लिये विवश हुई। जल की धारा के समान सभ्यता भी ऊपर से नीचे की ओर बहती रहती है। अग्रेजी की सभ्यता तुर्क सभ्यता की अधोष्ठा ऊँची थी। तुर्क लोग धर्म और सभ्यता के क्षेत्र में अग्रेजी द्वारा परास्त हो गये।

पर तुर्क लोग अग्रेजी के समान सहिष्णु नहीं थे। ईसाइयों की धर्म-भूमि पैलेस्टाइन अरब साम्राज्य के अन्तर्गत थी। ईसाई लोग बड़ी संख्या में पैलेस्टाइन में तीर्थयात्रा के लिये आते थे। अरब लोग उन पर कोई अत्याचार नहीं करने थे। पर अरब-साम्राज्य को नष्ट कर तुर्क जातियों ने अपने जो विविध राज्य कायम किये थे, उनके धार्मिक अग्रेजी के समान सहिष्णु नहीं थे। उन्होंने पैलेस्टाइन में आनेवाले ईसाई यात्रियों पर अन्याय-शुल्क किये और यूरोप के ईसाई जगत में इस बात पर भारी असन्तोष उत्पन्न हुआ।

**क्रूसेड का प्रचार**—उस समय रोम का पोप अर्बन द्वितीय था। उसने १०९५ ईस्वी में यूरोप के विविध राजाओं में अपील की, कि आपस के युद्धों को बन्द कर पैलेस्टाइन की पवित्र भूमि को तुर्कों की अधीनता में मुक्त करावे। पीटर नाम का एक ईसाई भिक्षु सारे यूरोप में इस बात के लिये आन्दोलन करना हुआ भ्रमण करने लगा, कि जनता पवित्र धर्मभूमि को तुर्कों से स्वतन्त्र कराने के लिये तैयार हो। पीटर नगे पैर सब जगह जाता था, उसके शरीर पर मोटे कपड़े रहते थे, उसके हाथ में एक विशाल क्रॉस होता था। वह सब जगह बाजारों और मण्डियों में जनता को एकत्र कर उन्हें धर्मयुद्ध के लिये प्रेरित करता था। पीटर और उसके साथियों के प्रयत्न का परिणाम यह हुआ, कि सारे यूरोप में धार्मिक जोश फैल गया, और लोग धर्मयुद्ध (क्रूसेड) के लिये निकल पड़े।

इतिहास में यह शायद पहला अवसर था, जब यूरोप की सर्वसाधारण जनता एक विचार व एक भावना से परिपूर्ण हुई थी। क्रूसेड में केवल वे लोग ही शामिल नहीं हुए थे, जिनका पेशा ही लड़ना था। इसमें सन्देह नहीं कि अनेक राजा महाराजा, सामन्त व ठाकुर पोप अर्बन द्वितीय की प्रेरणा से धर्मयुद्ध के लिये मैदान में उतर आये थे। पर सर्वसाधारण जनता ने इन क्रूसेडों में बहुत दिलचस्पी दिखाई थी, और किसान, कारीगर, व्यापारी आदि भी बड़ी संख्या में इनमें शामिल हुए थे। यूरोप के लोग इस समय यह अनुभव करते थे, कि उन्हें एक ऐसे उद्देश्य को सम्मुख रख कर लड़ना है, जिसके साथ उन पक्का सम्बन्ध है। विधर्मियों से अपनी धर्मभूमि की रक्षा करना उन्हें एक ऐसा उद्देश्य प्रतीत होता था, जिसके सम्मुख उन्होंने आपस के सब झगड़ों को भुला दिया था।

**क्रूसेडों का परिणाम**—कुल मिला कर आठ क्रूसेड (१०९५ से १२५० ई० तक) हुए। पहले दो क्रूसेडों में सम्मिलित धर्म-सैनिक पैलेस्टाइन तक पहुँच भी नहीं सके। उस समय तक लोगों को भूगोल का ज्ञान बहुत कम था। ईसाई धर्म के ये सैनिक पैलेस्टाइन की बजाय हगरी पहुँच गये और वहाँ के निवासियों को ही विधर्मियों तुर्क समझ कर उनके साथ उलझ गये। वहाँ उनका बुरी तरह से सहार हुआ।

१०९९ ईस्वी में क्रूसेडर लोग पैलेस्टाइन पहुँचने में समर्थ हुए। वहाँ भयंकर रूप से

नर हत्या हुई। घनघोर युद्ध के बाद ईसाई धर्म-सैनिक जेरुसलम (पैलेस्टाइन की राजधानी) पहुँच पाये, और उन्होंने अपने तीर्थस्थान को तुर्कों की अधीनता में मुक्त किया।

पर जेरुसलम देर तक ईसाइयों के हाथ में न रह सका। सलादीन नामक मुस्लिम सरदार ने ईसाइयों के विरुद्ध जिहाद (धर्मयुद्ध) का प्रारम्भ किया और मुस्लिम सैनिकों को संगठित कर ११८७ ई० में फिर जेरुसलम पर अधिकार कर लिया। सलादीन और उसके मुस्लिम धर्म-सैनिकों ने ईसाइयों पर घोर अत्याचार किये। इस पर यूरोप में फिर क्रूसेडों का संगठन किया गया। इन क्रूसेडों का वर्णन कर सकना यहाँ मभव नहीं है। पर अन्ततोगत्वा जेरुसलम और पैलेस्टाइन पर तुर्क लोगों का ही अधिकार रहा। ईसाई क्रूसेडर उन्हें तुर्कों से स्वतन्त्र नहीं करा सके।

यद्यपि क्रूसेडर अपना उद्देश्य पूर्ण नहीं कर सके, पर इनमें यह लाभ अवश्य हुआ, कि यूरोप के विविध राजा महाराजा कुछ समय के लिये एक उद्देश्य में संगठित हो गये, जनता में नये उत्साह का संचार हुआ और सर्वसाधारण लोगों को अन्य देशों के अवलोकन का अवसर मिला। इन धर्म युद्धों में व्यापार व पर्यटन को बड़ा प्रोत्साहन मिला। जनता की दृष्टि विद्याल होने में इनमें बहुत सहायता मिली।

## ६ चर्च की स्थिति

चर्च का महत्त्व—मध्यकालीन यूरोप में क्रिश्चियन चर्च का प्रभाव बहुत अधिक था। उस समय के राजाओं को प्रजा की भलाई का जरा भी ध्यान नहीं था। उन्हें आपस में लड़ने झगड़ने में ही फुर्तत नहीं मिलती थी। सामन्त पद्धति के कारण उस समय के राज्य बहुत असंगठित तथा अव्यवस्थित थे। परन्तु क्रिश्चियन चर्च की स्थिति इसमें सर्वथा भिन्न थी। चर्च का जनता पर अतुल्य प्रभाव था। सब ईसाई लोग पोप को अपना गुप्त मानते थे। चर्च का संगठन बहुत उत्तम था। म्यान-म्यान पर ईसाई मठ बने हुए थे। उनके पादरी पाप के अधीन थे, और उसकी आज्ञाओं का पालन करते थे। उस समय यूरोप में जो भी शिक्षा विद्या व प्रकाश का वह पत्र चर्च में केन्द्रित था। सर्वसाधारण जनता चर्च से जागरूक भान्ति और आश्वासन अनुभव करती थी। पादरी लोग जनता को रहस्योक्त व परलाव में गुप्त देने के लिये विविध उपायों का अवलम्बन करते थे।

चर्च की शक्ति—मध्य काल में यूरोप का चर्च बड़ा समृद्ध व शक्तिशाली था। लोग समय समय पर चर्च का दान दक्षिणा देने रहते थे। जिन लोगों के बोर्डे मन्तान न हो, वे प्रायः अपनी सम्पत्ति चर्च को दे देते थे। दान दक्षिणा चढ़ावा और विनाश में प्राप्त हुई सम्पत्ति के कारण चर्च बहुत अधिक समृद्ध व वैभवपूर्ण हो गया था। किसी-किसी देश में तो कुछ सम्पत्ति का चौथाई भाग तक चर्च में स्वतन्त्र में था।

करता था। चर्च व सम्बन्ध रखनेवाले व्यक्ति, पुरोहित व पुजारी राज-करो में मुक्त होते थे। चर्च की शक्ति पर राज्यकर नहीं लगा सकता था। इसके विपरीत, चर्च के टैक्सा में कोई वचित नहीं होता था। चर्च के अपने कानून थे, अपने न्यायालय थे, अपनी पुलिस था और अपनी दण्ड-व्यवस्था थी। चर्च का संगठन ठीक राज्यों का था। चर्च की अपनी सरकार थी। प्रत्येक मनुष्य चर्च की सरकार के अधीन होता था, चाहे वह पुरोहित हो या सामान्य व्यक्ति। पर चर्च के आदमियों पर राजा का कानून नहीं लगता था। उन्हें राजकीय न्यायालय दण्ड नहीं दे सकते थे।

**राजा और चर्च**—चर्च की स्थिति सब राज्यों व राजाओं में उपर थी। प्रत्येक राजा उसके अधीन होता था। यदि चर्च चाहें तो किसी भी राजा को पदच्युत कर सकता था। अपनी आज्ञा को मनाने के लिये चर्च के पाप चार बड़े साधन थे—

(१) धर्म-बहिष्कार—यदि कोई राजा व अन्य मनुष्य चर्च की आज्ञा को न माने, तो चर्च उसे धर्म-बहिष्कृत कर देता था। आजकल धर्म से बहिष्कृत हो जाना बड़ी बात नहीं है। पर मध्यकाल के यूरोपियन लोग धर्मप्राण होते थे। धर्म से बहिष्कृत कर दिये जाने पर उन्हें इस लोक और परलोक में कल्याण का मार्ग अवरोध प्रतीत होता था। धर्म-बहिष्कार के डर से वे तुरन्त काबू में आ जाते थे।

(२) धार्मिक हठताल—यदि कोई राजा धर्म-बहिष्कार में काबू में न आवे, तो चर्च उसके राज्य में हठताल कर देता था। वहाँ पादरी अपना काम बन्द कर देने थे। ब्रह्मा का वपतिस्मा नहीं होता था, मृतको का सम्कार नहीं हो सकता था, विवाह बन्द हो जाते थे। चर्च के घन्टे नहीं सुनाई देते थे। पादरी लोग शत्रुओं भक्तों में पाप श्रवण करना बन्द कर देते थे। धर्मप्राण जनता चिन्ताकुल हो क्लेशविमूढ़ हो जाती थी। सारे राज्य में हाहाकार मच जाता था। इस दशा में राजा को विवश होकर चर्च के सम्मुख मित्र बनना पड़ता था।

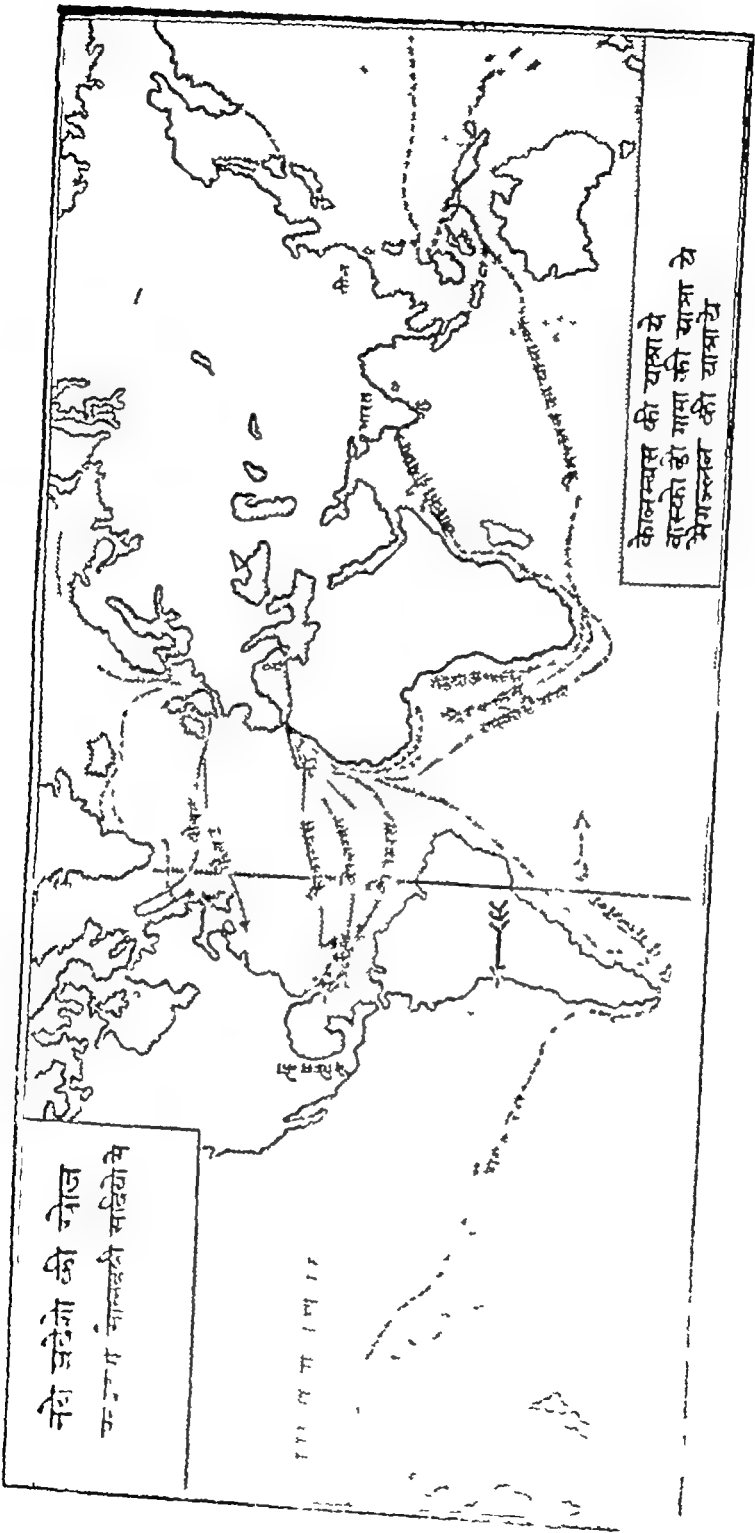
(३) पदच्युत करना—यदि इतने में भी कोई राजा चर्च के काबू में न आने लगे तो पोप उसे पदच्युत कर उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को राजा बनाने की घोषणा करता था और धर्मप्राण प्रजा को आज्ञा देता था, कि पदच्युत राजा का साथ छोड़कर नये राजा का अनुगमन करे। उस समय की यूरोपियन जनता पोप की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करती थी।

(४) क्रूसेड—यदि किसी प्रदेश में चर्च के विरुद्ध भावना हो और वहाँ के लोग पाप व उसके अधिकारियों की आज्ञा का पालन न करें, तो उस प्रदेश के विलाम्फ क्रूसेड (धर्म-युद्ध) की घोषणा कर दी जाती थी। भक्त ईसाइयों के दिल के दिल उन प्रदेश पर हमला करते थे और वहाँ की जनता पर भयकर से भयकर अत्याचार कर उसे पोप का वशवती होने के लिये बाधित करते थे। पोप की आज्ञा में केवल पैलेस्टाइन के विधर्मियों के खिलाफ ही क्रूसेड नहीं हुए, अपितु क्रिश्चियन जगत में भी उन प्रदेशों के विरुद्ध धर्मयुद्ध की घोषणा की गई, जो किसी भी प्रकार पोप व चर्च के आदेशों की उपेक्षा करने का साहस करते थे।

मध्यकाल में पोप और चर्च की यह अपार शक्ति थी।

नेवा प्रदेसो की गोज  
पुनः पुनः गोजसुदी सजिगी से

कौनम्हस की यात्रा से  
वास्को डी गामा की यात्रा से  
भैरगप्लन की यात्रा से





चर्च और राजा के मध्य सन्तर्पण—पाश्चात्यतया मध्यकालीन यूरोप के सब राजा चर्च व पोप के दायर्जनी थे । पर कुछ राजाओं ने उपका विरोध करने का भी साहस किया । उग पमग में फ्रेडरिक द्वितीय का नाम उल्लेखनीय है । यह बारहवीं सदी के अन्त (११९८ ई.पू.) में पवित्र रोमन सम्राट के गौरवमय पद पर आसित हुआ था । फ्रेडरिक द्वितीय का चर्चान निमन्त्री में व्यतीत हुआ था । यह द्वीप पट्टे अरबों के अधीन रह चुका था, अरब विचारधारा और मभ्यता का डम पर बहुत प्रभाव था । फ्रेडरिक की शिक्षा के लिये जो अव्यापक नियुक्त हुए थे, उनमें अनेक अरब भी थे । उस युग में अरब लोग ईसाइयों के समान सकीर्ण, धर्मान्ध व अमहाणु न थे । उनके सम्पर्क में रहने के कारण फ्रेडरिक के हृदय में भी वर्म की उदात्त व उदार रूपता विकसित हो गई थी और वह चर्च व पोप के प्रभुत्व को सहने के लिये तैयार नहीं था । शीघ्र ही पोप के साथ उपका झगडा हो गया और उसे धर्म बहिष्कृत कर दिया गया । पोप और फ्रेडरिक का मधुप निरन्तर जारी रहा । अन्त में सम्राट फ्रेडरिक द्वितीय की पराजय हुई । अब तक भी यूरोप में पोप व चर्च का सामना करने की शक्ति सम्राटों में भी नहीं थी ।

पर धीरे-धीरे यूरोप के शक्तिशाली राजा पोप का मुकाबला करने के लिये कटिबद्ध हो रहे थे । चौदहवीं सदी के शुरू तक यह दशा हो गई थी, कि फ्रांस के राजा को प्रम बहिष्कृत करने के लिये जब पोप ने इगदा किया, तो फ्रांस के राजा की आज्ञा में पोप को कुछ सैनिकों ने रोम में ही गिरफ्तार कर लिया । चौदहवीं सदी में पोप व चर्च का प्रभाव कम होने लग गया था । कारण यह है, कि धीरे-धीरे चर्च में विकार आने लगा था । पोप और अन्य पादरी लोग अपने कर्तव्य से विमुख हो भोग-विलास में मग्न रहने लगे थे । पोप एक बभ्रवशाली सम्राट के समान जीवन व्यतीत करता था । उसके विशपो व एगटों की स्थिति बड़े-बड़े सामन्तों और मनसबदारों के समान थी । सम्पत्ति बढ़ने के साथ-साथ पादरियों में अनेक बुराईया भी आने लगी थी । धर्म गुरु का असली कार्य सेवा, परेपकार व मन्मार्ग का प्रदर्शन है । पर यूरोप के मध्यकालीन धर्म गुरु पदों के लिये आपस में लड़ते थे, आमोद-प्रमोद में मस्त रहते थे और स्वार्थमय जीवन व्यतीत करते थे । इस स्थिति में यह स्वाभाविक था, कि चर्च का प्रभाव धीरे-धीरे कम होने लगे और लोग यह सोचने लगे कि क्या चर्च की यह अपार सम्पत्ति और भोगपूर्ण वातावरण क्रिश्चियन धर्म के अनुकूल है ।

चर्च के विरुद्ध आवाज—यही कारण है, कि तेरहवीं सदी में ही यूरोप में अनेक ऐसे आचार्य उत्पन्न होने शुरू हो गये थे, जिन्होंने चर्च की शक्ति और वैभव के विरुद्ध आवाज उठाई । वाल्डो, जान हस्स और विक्लिफ इनमें प्रमुख हैं । इन आचार्यों ने यत्न किया, कि ईसाई वर्म का सुधार किया जावे और चर्च फिर से अपने कर्तव्य का पालन करने लगे । पर पोप की दृष्टि में ये लोग काफिर और धर्मद्रोही थे । इनके विरुद्ध क्रूमेड की घोषणा की गई । वाल्डो के अनुयायी वाल्डेन्सियन कहाते थे । उनका निवास दक्षिणी फ्रांस में था । इन लोगों का प्रयत्न यही था, कि जीसस क्राइस्ट की शिक्षाओं के अनुसार सरल व परेपकार का जीवन व्यतीत किया जाय । पोप के क्रूमेडों ने इसका पूरी तरह में सहार किया । बोहेमिया में हस्स के अनुयायियों के खिलाफ बाकायदा सेनाएं भेजी गईं, और हस्स को जीते जी आग में जला दिया गया । विक्लिफ का मुख्य अपराध

यह था, कि उसने वाइवल का अनुवाद अंग्रेजी में किया था, ताकि सर्वसाधारण ईसाई जनता अपने धर्मग्रन्थ को स्वयं पढ़ सके, धर्म के ज्ञान के लिये उन्हें लैटिन के पण्डितों पर निर्भर न रहना पड़े। विक्लिफ को गिरफ्तार करने की आज्ञा दी गई। पर पोप के हाथ में पड़ने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई थी। इसलिये उसकी हड्डियों को कब्र में निकाल कर अग्नि में भस्म किया गया। पोप की इच्छा के विरुद्ध आचरण करनेवाले को यथोचित दण्ड न मिले, यह बात मध्यकालीन यूरोप में सम्भव नहीं थी।

## ७ मध्यकाल में यूरोप की दशा

शिक्षा और ज्ञान—मध्यकालीन यूरोप की तीन बड़ी विशेषताएँ थीं—सामन्त पद्धति, पवित्र रोमन साम्राज्य और गवित्तगाली चर्च। हम तीनों पर प्रकाश डाल चुके हैं। अब प्रश्न यह है, कि इस काल में सर्वसाधारण जनता की क्या दशा थी। इस काल में यूरोप में शिक्षा का प्रचार बहुत कम था। सर्वसाधारण जनता प्रायः अशिक्षित और निरक्षर थी। न केवल जनता, पर बड़े-बड़े राजा, महाराजा, सामन्त और अमीर उसका भी इस युग में प्रायः अशिक्षित ही होते थे। उस समय विद्या व ज्ञान यदि कहीं थे, तो किश्चियन मठों में ही थे। मठों में जो शिक्षा उस समय दी जाती थी, वह मुख्यतया धार्मिक होती थी। वाइवल और उसके भाग्य उस युग में अध्ययन की सब से उत्कृष्ट सामग्रियाँ थीं। चर्चों में गुरु और जियर लैटिन के अध्यापन और अध्ययन में व्यस्त रहते थे। लैटिन के व्याकरण का पढ़ाई धीरे-धीरे प्रथमता के साथ पढ़ा जाता था। फिर लैटिन ग्रन्थों को कण्ठस्थ करने की दौड़ जाती थी। स्वतन्त्र विज्ञानों का विकास उस समय तक नहीं हुआ था। लोगों में स्वतन्त्र विचार की प्रवृत्ति का प्रायः अभाव था। वाइवल और उसके भाग्यों में, प्राचीन शास्त्रों में जो कुछ लिखा है उसका पढ़कर कण्ठस्थ कर लेना उस समय की सब से बड़ी विद्वत्ता थी। अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन आदि भाषाएँ उस समय अशिक्षित जनसाधारण की भाषाएँ थीं। उनमें साहित्य का अभाव था। उस समय के विद्वान केवल लैटिन व ग्रीक भाषा पढ़ते थे। वे लोकभाषाओं को हीन दृष्टि में देखते थे।

गणप के अनेक विश्वविद्यालयों का प्रारम्भ मध्यकाल में हो गया था। पर धर्म में पण्डित आत्मबोध आदि के ये विद्यार्थी ईसाई मठों के ही आगे थे। इनमें मुख्यतया लैटिन और ईसाई शास्त्रों की ही शिक्षा दी जाती थी। इनका संचालन भी ईसाई पादरियों द्वारा होता था। ज्ञान-विकास का जैसा विकास इन विश्वविद्यालयों में आधुनिक युग में दिखता है, मध्यकाल में उसका संचालन अभाव था।

लोग, दूसरे मुहल्ले में अमीर व्यापारी लोग और तीसरे हिस्से में व्यवसायी लोग बसते थे। गरीब मजदूर लोग शहर में बाहर मँले-कुचैले झोंपड़ों में निवास करते थे। शहर के गनी व गम्पन्न लोग उन्हें अलूत समझते थे।

अज्ञान और अन्धविश्वास—यूरोप के इतिहास में मध्यकाल को अन्धकार और अज्ञान का युग कहा जाता है। उस युग में जनता में नरह-नरह के अन्धविश्वास प्रचलित थे। बीमारी का उलाज दवाई में ढराना पाप समझा जाता था। लोगों का ख्याल था, कि रोग ईश्वर के रोष के परिणाम होते हैं। अतः उनमें बचने का उपाय केवल पूजा व प्रार्थना है। विज्ञान का उग समग्र सवथा अभाव था। रोग समझते थे, जमीन स्थिर है, सूर्य उसके चारों ओर घूमता है। जमीन गोल नहीं, अपितु चपटी है। नक्षत्रों के सम्बन्ध में आम लोगों का विचार था, कि ये जीवित जागृत प्राणी हैं। भगोल का भी ज्ञान लोगों को बहुत कम था। उल्लैण्ड के पश्चिम में अटलांटिक पागर में परे क्या है? अफ्रीका कितना विद्याल है? भारतवर्ष कहाँ है? ये सब बातें ज्ञान तो ज्ञान नहीं थी। चीन और भारत का नाम तो यूरोप के लोग जानते थे, पर उन्हें यह माहूम नहीं था कि ये देश किस जगह पर स्थित हैं।

उस युग में यूरोप के लोग अपन अज्ञान में मन्नुट थे। उनमें जग भी जिज्ञासा नहीं थी। वे अपनी दशा से सर्वथा मन्तोप अनुभव करने हुए मोहमयी निद्रा में सो रहे थे। उसी काल के अरब, मङ्गोलिया, भारत तथा चीन की दशा यूरोप में बहुत उत्तम थी। उन देशों के मुकाबले में उस समय यूरोप 'अर्द्धसम्भ' था।

## दूसरा अध्याय

# नवयुग का सूत्रपात

## १ यूरोप का पुन जागरण

पुन जागरण के कारण—मध्यकाल में यूरोप एक मोहमयी निद्रा में सो रहा था। पर धीरे-धीरे उसमें जागरण के चिह्न प्रकट होने शुरू हुए। पुन जागरण की यह नई प्रवृत्ति तेरहवीं सदी में ही शुरू हो गई थी। पर इसने चौदहवीं और पन्द्रहवीं सदियों में गूढ़ गूढ़ धारणा किया। इसका प्रारम्भ निम्नलिखित कारणों व परिस्थितियों में हुआ—

(१) हम वनवाचक हैं, कि जब यूरोप में अविद्या का अन्धकार छाया हुआ था, तब अन्ध में ज्ञान का दीपक प्रज्वलित था। अरबों का साम्राज्य स्पेन तथा उत्तरी अफ्रीका में नीविस्तृत था। कुछ समय के लिये सिसली भी अरबों के अधीन रहा था। इन प्रदेशों में जहाँ न अनेक विद्यापीठ स्थापित किये थे, जिनमें ज्योतिष, गणित तथा अन्य विज्ञानों के अनिश्चित प्राचीन ग्रीक दार्शनिकों के ग्रन्थों का भी स्वाध्याय होता था। अरिस्टॉटल, प्लेटो आदि ग्रीक विचारक ठीक नहीं थे। उनके ग्रन्थों में दयन और ज्ञान का शुद्ध रूप में प्रतिपादन था। यूरोपियन लोग इन विद्यापीठों के संपर्क में आकर गेता ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ हुए जिससे ठीक ग्रीकों के साथ कोई सम्बन्ध नहीं था। अरब पण्डित बड़े स्वतंत्र विचारक तथा उदात्त थे। उनके सम्पर्क के कारण यूरोप के विचारों में भी स्वतंत्र विचार की प्रवृत्ति प्रारम्भ हुई।

योज के लिये परीक्षण शुरू किये। पहले यूरोपियन लोगो का यह विश्वास था, कि जा चीज बोज़ म सी गुना होगी, वह सी गुने वेग से नीचे गिरेगी। यह विश्वास ठीक है या नहीं उपर पर लोग शास्त्रीय विचार तो करने थे पर उनके लिये परीक्षण करने का कष्ट नहीं उठाते थे। गैलिलिया (१५६४-१६४२) ने पहले पहल परीक्षण करके इस विश्वास का अमृत्य सिद्ध किया। कोपर्निकस (१४७३-१५४३) ने पहले पहल यूरोप में इस सत्य का पता किया, कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उसके चारों ओर घूमती है। गैलिलियो और कोपर्निकस के समान अन्य भी अनेक विचारक जब यूरोप में उत्पन्न होने लगे, जो परीक्षा द्वारा सत्य की खोज कर नये-नये सत्यों का पता लगा रहे थे। उस समय के विद्वान इनका न केवल उपहास ही करते थे, अपितु उन्हें प्रमदोंही और डाफिर समझते थे। इन्हें भय दण्ड दिये गये। अनेक को जीने की आशा में जराया गया। वस्तुतः ये लोग विज्ञान के लिये गहरी दृष्टि रखते थे। चर्च के सब अन्याचारों के बावजूद भी बृद्धि-स्वातन्त्र्य और वैज्ञानिक खोज की यह प्रवृत्ति रुकी नहीं। आज समाज ने जो उन्नति की है उसमें यह प्रवृत्ति बड़ा कारण है।

(४) इसी समय यूरोप में कागज और छापेखाने का प्रवेश हुआ। पहले यूरोप में लिखन के लिये बकरी की खाल प्रयोग में आती थी। कागज का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। चीन में यह मंगोल लोगो ने सीखा। मंगोलों में अरबों ने और अरबों द्वारा यूरोप में कागज का प्रवेश हुआ। पहले पहल चौदहवीं सदी में यूरोप में कागज का निर्माण शुरू हुआ था। पन्द्रहवीं सदी में छापेखाने का यूरोप में प्रवेश हुआ और पुस्तकें अच्छी तथा सस्ती छपने लगी। जनता में ज्ञान-विस्तार के लिये पुस्तकों का प्राचुर्य का सस्ता होना बहुत आवश्यक है। विक्लिफ जैसे विद्वानों ने बाइबल का जो अनुवाद यूरोप की लोकभाषाओं में करना शुरू किया था, वह अब सस्ते मूल्य पर बड़ी मात्रा में जनता को उपलब्ध होने लगा। लोगो को अब यह अवसर मिला, कि वे स्वयं ईसाई धर्म के सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त कर सकें। चर्च ने प्रमाणवाद की जजीरो में यूरोप के दिमाग को जिन प्रकार जकड़ रखा था, उसमें अब शिथिलता आने लगी और लोग विभिन्न विचारकों के विचारों को पढ़कर अपनी बुद्धि से काम लेने के लिये तत्पर हुए। कागज और छापेखाने का प्रवेश यूरोप के पुनर्जागरण में बहुत सहायक सिद्ध हुआ।

**परिणाम—**बुद्धि-स्वातन्त्र्य का जो आन्दोलन यूरोप में धीरे-धीरे जोर पकड़ रहा था उसने अनेक महत्वपूर्ण परिणाम उत्पन्न किये।

(१) चर्च की अपार शक्ति के विरुद्ध जनता में भावना बढ़ने लगी। विक्लिफ, वाटर और ह्यूम जैसे व्यक्तियों के कारण चर्च के विरुद्ध जो असन्तोष व विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई थी, उसका उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं। आगे चलकर चर्च के खिलाफ वाक्पात विद्रोह शुरू हो गया।

(२) अरबों के सम्पर्क में यूरोप में अरबी समस्याओं और एलजवरा (बीज गणित) आदि का प्रवेश पहले ही हो चुका था। रसायनशास्त्र का पहला रूप अल्केमी था, जिससे द्वारा लोग एक ऐसे उपाय की खोज में थे, जिससे वे लोहे व अन्य सस्ती धातु को सोने में बदल सकें। साथ ही, वे किसी ऐसी औषधि की खोज में भी तत्पर थे, जिससे बुढ़ापे और मृत्यु

पर विजय पा सके। यूरोप में जल्केमी की उन्नति में भी अरबों का सम्पर्क बहुत सहायक हुआ। पर अब परीक्षणों द्वारा सत्य का निर्णय करने की जो नई प्रवृत्ति यूरोप में पैदा हुई थी, उसके कारण विज्ञान की निरन्तर उन्नति होने लगी। कोपर्निकस और गैलिलियो का उल्लेख हमने ऊपर किया है। डा० गिल्बर्ट (१५४०-१६०३) ने चुम्बक का पता लगाया, और यह प्रतिपादित किया कि वस्तुओं में एक दूसरे को खींचने की, अपनी तरफ आकर्षित करने की शक्ति किस प्रकार विद्यमान है। हाव (१५७६-१६५७) ने शरीर-विज्ञान के सम्बन्ध में बहुत से नये तथ्यों का पता लगाया। न्यूटन (१६४२-१७२६) बड़ा प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुआ है। उसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। बुद्धि-स्वातन्त्र्य और परीक्षण की प्रवृत्ति के कारण यूरोप के विद्वान इस समय नये-नये तथ्यों और सिद्धान्तों का प्रतिपादन करने लगे और उस अदभुत उन्नति का श्रीगणेश हुआ, जिसके कारण मनुष्य ने प्रकृति पर आश्चर्यजनक विजय प्राप्त की है।

(३) लोकभाषाओं में साहित्य का निर्माण यूरोप के पुन जागरण के आन्दोलन का महत्त्वपूर्ण परिणाम था। मध्यकाल में यूरोप के विद्वान लैटिन और ग्रीक का अध्ययन किया करते थे। अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन आदि जनसाधारण की भाषाओं में न कोई साहित्य था और न विद्वान लोग इन्हे विकसित करने की आवश्यकता ही समझते थे। पर अब इस दशा में परिवर्तन आया और अनेक ऐसे लेखक उत्पन्न हुए, जिन्होंने लोकभाषाओं में ग्रन्थ लिखने शुरू किये।

(४) इस समय यूरोप के लोगों में भूगोल का ज्ञान भी खूब बढ़ा। उन्होंने नये-नये प्रदेशों की खोज शुरू की। इसी प्रवृत्ति के कारण अमेरिका के महाद्वीप का पता लगा। अफ्रीका का चक्कर वाटरर यूरापियन लोग भारत, चीन आदि पूर्वी देशों में भी जाने-जान लगे। नये प्रदेशों की खोज के सम्बन्ध में हम एक पृथक् प्रकरण में अधिक विस्तार से प्रकाश डालेंगे।

## २ धार्मिक सुधारणा

कम्ता था। दूसरे एक पुगन-ग का पादरी था और धार्मिक प्रज्ञा पर शान्तीय दृष्टि से विचार किया करता था। वाज्वल तथा अन्य त्रि-चयन शास्त्रों का वह बड़ा गम्भीर विद्वान् था। उमन अनुभव किया, कि पाप-मोचन-पत्रा की व्यवस्था शास्त्रों के अनुकूल नहीं है अतः उसने उसके विरुद्ध एक निबन्ध प्रकाशित किया। यह निबन्ध सर्वमान्य जनता के लिये नहीं था। उसे लैटिन में लिखा गया था और केवल विद्वानों के सम्मुख अपने विचार प्रकट करने के उद्देश्य से ही दूसरे ने उसे प्रकाशित कराया था।

**प्रोटेस्टेन्ट चर्च**—पर राजाआ और जनता में चर्च के विरुद्ध जो अमनोप की अग्नि विद्यमान थी, वह उस घटना में प्रदीप्त हो गई। शास्त्रज्ञों का प्रवेग उस समय तक व्याप्त हो चुका था। चर्च के विरोधियों ने अपने विचार छाप-छापकर प्रकाशित करने शुरू किये। दूसरे उनका नेना बना। अनेक राजाआ ने उस आन्दोलन का साथ दिया। वे चर्च के वेभव तथा शक्ति को रूपा की दृष्टि में देखते थे। चर्च की सम्पत्ति को जन्म का जन्म शक्ति बढ़ाने का यह सुवर्णविमर उन्हें प्राप्त हुआ था। देखते-देखते चर्च और उसके विरोधियों की वाकायदा लड़ाई शुरू हो गई। उस समय यूरोप दो भागों में विभक्त हो गया। एक भाग वह, जो पोप और चर्च के प्रभुत्व को पूर्ववत् स्वीकार करता था और दूसरा भाग वह जो पोप के विरुद्ध विद्रोह कर उसके प्रभुत्व का विरोध करना था। पहले भाग को 'रोमन कैथोलिक चर्च' और दूसरे भाग को 'प्रोटेस्टेन्ट चर्च' कहते थे।

**चर्च के अधिपति राजा**—जहाँ पोप के विरुद्ध विद्रोह कर पृथक् चर्च की स्थापना हो रही थी, वहाँ भी वस्तुतः चर्च स्वतन्त्र नहीं हुआ था। वहाँ प्रायः चर्च के अधिपति राजा लोग हो रहे थे, जो चर्च की सम्पत्ति तथा जायदाद को जन्म का अपने कानून करते जाते थे। उत्तरी जर्मनी के विविध राजा महागराओ ने उसी तरह चर्च की सम्पत्ति जब्त कर अपने अधीन कर ली थी और अपने-अपने राज्य में स्वयं चर्च के अधिपति बन गये थे। इङ्गलैण्ड में भी हेनरी अष्टम (१५३०) ने अपने एक स्वार्थ को पूर्ण करने के लिये पोप के विरुद्ध विद्रोह किया और इङ्गलिश चर्च को पोप की अधीनता में मुक्त कर राजा के अधीन कर दिया। यही दशा अन्य अनेक देशों में भी हुई। अभिप्राय यह है, कि प्रोटेस्टेन्ट आन्दोलन इस समय यूरोप में चल रहा था, उसका उद्देश्य केवल धार्मिक मुक्ति नहीं था। उसमें अनेक राजाओं के निज स्वार्थ भी कार्य कर रहे थे।

**जैसुएट सम्प्रदाय**—पर इसमें सन्देह नहीं, कि इस आन्दोलन ने यूरोप में एक नई जागृति उत्पन्न करने में अवश्य सहायता की। इसमें रोमन कैथोलिक चर्च में भी नव जीवन का संचार हुआ। प्रोटेस्टेन्ट लोगों का विरोध करने के उद्देश्य से रोमन कैथोलिक लोगों में अनेक ऐसे सम्प्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ, जो बड़े सतर्क और जीवित जागृत थे। जैसुएट सम्प्रदाय इनमें प्रमुख है। इस सम्प्रदाय की स्थापना इग्नेटियस लोयोला (१५३९) ने की थी। लोयोला स्पेन का निवासी था। जैसुएट सम्प्रदाय आगे चलकर बहुत ही शक्तिशाली हुआ। दूर देशों में ईसाई धर्म के प्रसार के लिये इस सम्प्रदाय के पादरियों ने बड़ा भारी कार्य किया।

**चर्च का सघर्ष**—प्रोटेस्टेन्ट और रोमन कैथोलिक लोगों का पारस्परिक सघर्ष बड़ा ही बीभत्स और प्रचण्ड था। जहाँ के राजा प्रोटेस्टेन्ट थे, वे रोमन कैथोलिक लोगों पर

घोर अत्याचार करते थे। जहाँ के राजा रोमन कैथोलिक थे, वे प्रोटेस्टेण्ट लोगो को जीने नहीं देने थे। रोमन कैथोलिक राज्या में पोप की सख्ती में एक विशेष धार्मिक न्यायालय (इन्क्वीजिशन कोर्ट) का निर्माण हुआ था। जिन लोग पर जरा भी सन्देह होता था, कि वे चर्च के विरुद्ध सम्मति रखते हैं, उन्हें इस न्यायालय के सम्मुख पेग किया जाता था। वहाँ उन्हें कठोर दण्ड दिये जाते थे। मुख्य दण्ड यह था, कि ऐसे लोगो को जीते जी आग में जला दिया जावे। एक-एक राजा के शासनकाल में एक-एक देश में इस ढंग से हजारों आदमियों को केवल इसलिये प्राणदण्ड दिया गया, क्योंकि वे धार्मिक क्षेत्र में स्वतन्त्र सम्मति रखते थे। यूरोप के इतिहास में यह धार्मिक असहिष्णुता सचमुच बड़ी बीभत्स थी।

पर इन सब अत्याचारों और सघर्षों के होते हुए भी धीरे-धीरे यूरोप में एक नवयुग का प्रारम्भ हो रहा था। लोग स्वतन्त्रता के साथ विचार करने लगे थे। वे अपनी सम्मति और विचारों के लिये प्राणों की बलि तक देने लगे थे।

### ३ नये प्रदेशों की खोज

पन्द्रहवीं सदी तक यूरोप के लोगों को बाहरी दुनिया का बहुत कम परिचय था। उस समय समय में जो जहाज चलते थे, वे चप्पुओं में खेये जाते थे। दिग्दर्शक यन्त्र का प्रवेश भी तब तक यूरोप में नहीं हुआ था। ऐसे समय में उन जहाजों व नौकाओं में महामुद्रों का पाग पाना नितान्त कठिन था। पर पन्द्रहवीं सदी में दिग्दर्शक यन्त्र का प्रवेश पहले पहल यूरोप में हुआ। यह यन्त्र भी रागज के समान जन्म होता हुआ चीन में यूरोप में आया था। उस समय ही जब जहाज पहलें की अपेक्षा बड़े और मजबूत बनने लगे। चप्पुओं के साथ पाग पाना भी प्रयास शुरू हुआ। पाल में चलने वाले जहाजा ने यह सम्भव था, कि अनु-वायु के साथ महामुद्र को पाग किया जा सके।

उस समय यूरोप और एशिया का व्यापारिक मार्ग आरमानन में रूजिष्ट होता हुआ समुद्र मार्ग पहुँचता था। पर दूसरा मार्ग एशिया की ज़मीन में समुद्र मार्ग होता हुआ एशिया मानस के बदलावों पर जाता था। पहले उन व्यापारिक मार्गों पर जन्मों का रूजिष्ट था। जब लोग समुद्र में जाने व्यापार के सत्त्व को रूजिष्टानि जनम रखते थे। पर पन्द्रहवीं सदी में तब लोग न प्रदेशों के स्वामी बनने और एशिया व यूरोप के व्यापारिक मार्गों को जान लगे। तब १४९२ में जेम्स कोलम्बस द्वितीय ने नया इतिहास रचा। सी जीन कोलम्बस ने यूरोप के लोगों के लिये इन नए मार्गों के व्यापार का मार्ग उत्पन्न कर दिया था।



भारत पहुँचने से समर्थ हुआ।

अफ्रीका का चाकर काटकर एशिया पहुँचने का यह नया मार्ग इस प्रकार आविष्कृत हुआ। पर उगी समय कोलम्बस नामक एक इटालियन मल्लाह के मन में एक नई कल्पना उत्पन्न हुई। पृथिवी गोल है, यह वान उस समय तक जान हो चुकी थी। कोलम्बस ने सोचा, कि यदि अटलांटिक सागर में निरन्तर पश्चिम की ओर चलते जावे, तो जमीन के गोल होने के कारण भारत पहुँचा जा सकता है। कोलम्बस के उस विचार का इटली में किसी ने स्वागत नहीं किया। पर स्पेन के राजा ने उसकी सहायता की और १४९२ में वह अपनी कल्पना को क्रिया में परिणत करने के लिये चर पड़ा। उस के साथ छोट-छोटे तीन जहाज थे, जिनके मल्लाहों की कुल संख्या ८८ थी। अटलांटिक सागर में पश्चिम की तरफ चलते-चलते ११ अक्टूबर, १४९२ को जमीन के दृश्य हुए। कोलम्बस ने समझा, कि भारतवर्ष आ गया। वस्तुतः वह भारत नहीं था—वह एक नया महाद्वीप था, जो अब अमेरिका के नाम से परिचित है।

कोलम्बस को जो महाद्वीप अचानक ही प्राप्त हो गया था, वह अत्यन्त विशाल था। उसके अधिकांश प्रदेश में जङ्गली और अमभ्य जातियाँ निवास करती थीं। पर दो प्रदेश ऐसे भी थे, जहाँ अच्छे उन्नत सभ्य लोग बसते थे। ये प्रदेश थे, मैन्सिको और पेन। कोलम्बस स्पेन के राजा की सहायता में समुद्र-यात्रा के लिये निरग्न था, अतः स्वभाविक रूप से अमेरिका पर स्पेन का अधिकार हुआ। स्पेनिश लोगों ने बड़ी निर्दयता में अमेरिका के निवासियों को नष्ट किया। न केवल वहाँ के जङ्गली अमभ्य लोगों को, अजिनु एजटेक और मय लोगों का भी क्रूरता के साथ महार किया गया। यूरोप के लोग तब तक वारुद का प्रयोग जान चुके थे। वे बन्दूक चलाना भी सीख गये थे। बन्दूक की मार के सामने अमेरिकन लोग न ठहर सके और कुछ ही समय में उन लोगों का विनाश हो गया। स्पेनिश लोगों ने इस विशाल भूखण्ड में अपने उपनिवेश बसाने प्रारम्भ किये। यह प्रदेश खनिज पदार्थों की दृष्टि से बड़ा समृद्ध था। मोने चादी की खानों से आच्छात हो स्पेनिश लोग बड़ी संख्या में अमेरिका जाने लगे। इन नये प्राप्त हुए प्रदेशों से स्पेन की समृद्धि दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने लगी। स्पेन की होड में अन्य यूरोपियन राज्य भी अमेरिका जाकर बसने के लिये प्रयत्नशील हुए। दक्षिणी अमेरिका में स्पेनिश लोग बस रहे थे, वहाँ पर उनका कब्जा हो चुका था। अतः फ्रांस, ब्रिटेन आदि ने उत्तरी अमेरिका में बसना शुरू किया। जहाँ आजकल संयुक्त राज्य अमेरिका है, वहाँ ब्रिटेन के तथा जहाँ अब कनाडा है, वहाँ फ्रांस के उपनिवेश बसने शुरू हुए। अमेरिका के विस्तृत प्रदेशों पर अधिकार करने के लिये इन यूरोपियन राज्यों में परस्पर संघर्ष का भी प्रारम्भ हुआ।

अफ्रीका का चकर काट कर पहले पहल पोर्तुगीज लोग भारत आये थे। उन्होंने इस नये मार्ग से पूर्वी देशों के व्यापार को हस्तगत करना शुरू किया। इस व्यापार से पोर्तुगीज लोग बड़े समृद्ध हो गये। उनकी देखादेखी अन्य यूरोपियन राज्य भी इसी दक्षिण मार्ग से एशिया जाने लगे। हालैन्ड, फ्रांस, ब्रिटेन आदि में पूर्वी व्यापार को हस्तगत करने के लिये कम्पनियाँ खड़ी की गईं। ये कम्पनियाँ पूर्वी देशों के विविध बन्दरगाहों पर अपनी कोठियाँ कायम करती थीं, और अधिक से अधिक व्यापार पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का

उद्योग करती थी।

पर यूरोपियन जातियाँ केवल व्यापार से ही मन्तुष्ट नहीं रही। एगिया के विविध राज्यों की दगा उम समय उत्तम नहीं थी। भारत को ही लीजिये। अठारहवीं सदी में मुगल साम्राज्य क्षीण हो गया था, और विविध राजनीतिक सत्तायें शक्ति के लिये परस्पर संघर्ष करने लगी थी। यही दगा उम समय जावा, सुमात्रा, मलाया आदि देशों की थी। यूरोपियन लोगों ने इस राजनीतिक दुर्दगा का लाभ उठाया और व्यापार के साथ-साथ अपनी राजनीतिक सत्ता भी स्थापित करनी शुरू की।

अमेरिका की प्राप्ति तथा पूर्वी व्यापार के दक्षिणी मार्ग की खोज में यूरोप के उत्कर्ष में बहुत सहायता मिली,। जिन यूरोपियन लोगों को पहले यह भी ज्ञान नहीं था, कि भारत कहाँ है और अफ्रीका कितना विशाल है, वे अब सारे भूमण्डल की परिक्रमा करने लगे। वस्तुतः यूरोप का अब पुनः जागरण हो गया था।

## ४ स्वेच्छाचारी निरकुश राजा

यूरोप में सभ्यता का पुनः जागरण हो रहा था। सब ओर नवजीवन के चिह्न प्रगट होने लगे थे। पर राजनीतिक क्षेत्र में अभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। राजा पहले की तरह निरकुश और स्वेच्छाचारी थे। पोप की शक्ति कम हो जाने के कारण उनका प्रभाव और भी बढ़ गया था। बड़े-बड़े के साथ राज-प्रामादों में निवास करते थे, और आमोद-पमोद में अपना जीवन व्यतीत करते थे।

सामन्त-पद्धति का ह्रास—मध्यकाल के प्रारम्भ में सैकड़ों हजारों राजा, महाराजा और सामन्त यूरोप के विविध प्रदेशों पर शासन करते थे। ये आपस में निरन्तर लड़ते रहते थे। कोई किसी की प्रभुता को मुगमता में स्वीकार नहीं करना चाहता था। पर धीरे-धीरे उन बहुत से राजा महाराजाओं के बीच में कुछ शक्तिशाली राजाओं का विकास हुआ, जिन्होंने अपने सामन्तों को पूर्ण तरह काबू में रक्के

आर वारुद के सम्मुख मिट्टी के दुर्ग देर तक नहीं ठहर सकते थे। मंगोल लोभो द्वारा यूरोप में वारुद का प्रवेश हुआ। शक्तिशाली राजाओं ने मंगोलों से वारुद व तोपो का प्रयोग सीखा लिया और उनके हाथ में एक ऐसा हथियार आ गया, जिसमें वह सामन्तों के दुर्गों को आपसी में समझाने कर सकते थे। यही कारण है कि जब तोपो की मांग में दुर्ग नष्ट होने लगे, तो सामन्ता की शक्ति भी क्षीण होनी शुरू हो गई। उनके अनिर्गुण, चौदहवीं व पन्द्रहवीं सदियों में यूरोप के प्रायः सभी देशों में बड़े भयंकर युद्ध हुए। ये युद्ध विविध राजवंशों और विविध सामन्तों में परस्पर हुए थे। उनके कारण बहुत से राजकुल नष्ट हो गए, और विविध सामन्तों की शक्ति क्षीण हो गई। उसी का परिणाम हुआ, कि कुछ शक्तिशाली राजाओं के लिये उत्कर्ष का मार्ग साफ हो गया, और स्वतन्त्रता के निरंकुश राजाओं का विकास हुआ।

**शक्तिशाली राजा—**फ्रांस, इंग्लैण्ड, स्पेन, रूस आदि प्रायः सभी देशों में यह प्रक्रिया हुई। सत्रहवीं सदी तक इन सब देशों के शक्तिशाली राजाओं ने अपने-अपने सामन्तों को पूर्णतया काबू में करके अपनी सत्ता का भयानक विस्तार कर दिया था। इंग्लैण्ड का राजा हेनरी अष्टम (१५३०), फ्रांस का राजा चार्ल्स ९वां (१५६३), स्पेन का राजा फिलिप द्वितीय (१५५८), रूस का राजा पीटर (१६८०), सब इसी प्रकार के शक्तिशाली निरंकुश राजा थे। जर्मनी और आस्ट्रिया में किसी एक शक्तिशाली केन्द्रीय शासन का विकास नहीं हो सका था। वहाँ अभी अनेक राजा, महाराजा और सामन्त स्वतन्त्रतापूर्वक शासन में तत्पर थे, जिनका अधिपति मध्यकाल के समान अब भी पवित्र रोमन सम्राट होता था। पर पश्चिम के रूप में जर्मनी में भी एक ऐसे शक्तिशाली राजा का विकास हो रहा था, जिसके राजा फ्रांस और इंग्लैण्ड के राजाओं के समान ही शक्तिशाली और निरंकुश थे।

**राष्ट्रीयता—**सामन्त पद्धति के हटाने और शक्तिशाली केन्द्रीय राजाओं के विकास के कारण फ्रांस, इंग्लैण्ड और स्पेन सदृश राज्यों को अपनी शक्ति बढ़ाने का बहुत उत्तम अवसर हाथ लगा। आन्तरिक व्यवस्था और शान्ति किसी भी देश की उन्नति में बहुत सहायक होती है। सामन्त पद्धति के कारण देश में आन्तरिक व्यवस्था सम्भव नहीं रहती। फ्रांस, इंग्लैण्ड, स्पेन आदि में शक्तिशाली केन्द्रीय शासन के स्थापित हो जाने से इन देशों की बहुत उन्नति हुई। यही कारण है, कि ये देश उन्नति की दौड़ में बहुत आगे निकल गये। इसके विपरीत जर्मनी, इटली आदि अनेक देशों में बहुत से छोटे-बड़े राजाओं और सामन्तों का शासन जारी रहा। इसी कारण वे फ्रांस और इंग्लैण्ड के मुकाबले में बहुत पीछे रह गये।

इस स्थिति का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह भी हुआ, कि फ्रांस, इंग्लैण्ड आदि जिन देशों में शक्तिशाली केन्द्रीय राजाओं का शासन स्थापित हुआ, उनमें एक प्रकार की एकता की भावना भी उत्पन्न होने लगी। फ्रेंच राजा द्वारा शासित सब प्रदेश एक थे, उनके दरबार में एकत्र हुए सब अमीर उमरा एक भाषा बोलते थे, एक संस्कृति के रंग में रंगे हुए थे और अपने राजा के राज्य को एक देश समझते थे। इस दशा का परिणाम यह हुआ, कि धीरे-धीरे फ्रांस एक राष्ट्र बनने लगा, और उसके निवासियों में राष्ट्रीयता की अनु-

भूति विकसित होने लगी। वही प्रक्रिया इङ्ग्लैंड, स्पेन, पर्शिया आदि देशों में भी हुई।

राजाओं का जीवन—यामन पद्धति के ह्रास होने पर यूरोप में जो शक्ति-शाली निष्कृन्त राजा शासन करने लगे, वे बड़ी शान मौकत के साथ अपनी राजधानी में निवास करने थे। फ्रांस के राजाओं को लीजिये। वे हजारों पार्श्वचरों और अनुचरों के साथ वर्साय के राजप्रासाद में निवास करते थे। पेरिस में बाग़्हा मील दूर राजा और उनके दम्पतियों के भोग विलास का केन्द्र वर्साय नगर विद्यमान था। राजा का महल तीस कोट रुपये की लागत में बनाया गया था। राजदरबार में १५ हजार आदमी थे। अकेली रानी के नौकरों की संख्या ५०० में ऊपर थी। राजा के निजी खर्च की कोई भीमा न थी पचास लाख के लगभग रुपये प्रतिवर्ष भोजन में व्यय होते थे। राजा के आमोद-प्रमोद शान-मौकत और भोग-विलास का खर्च छ करोड़ रुपया सालाना में कम न था। जोंदना फ्रांस के राजाओं की थी, वही प्रायः अन्य यूरोपियन देशों के राजाओं की थी। छोटे-छोटे देशों के राजा भी अपने महल और दरबार पर लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया करते थे।

राज्य-शासन का विद्धात—यूरोप के राजाओं का शासन-सम्बन्धी मूल सिद्धान्त यह था कि राजा पृथ्वी पर परमेश्वर का प्रतिनिधि है। वह राजा है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे राजा बनाया है। जिस प्रकार सम्पूर्ण विश्व पर परमेश्वर विश्व के विविध प्राणियों की निम्नी भी प्रकाश सम्मति लिये बिना स्वेच्छा में शासन करता है, उसी प्रकार राजा अपने राज्य में प्रजा की सम्मति पर जरा भी आश्रित हुए बिना अपनी इच्छा में शासन करता है। यदि राजा दयालु है, तो प्रजा का सौभाग्य है, यदि राजा अत्याचारी है, तो किसी का क्या वर है। परमेश्वर के शासन में आश्रित होती है तूफान आते हैं, महामारिया फैलती हैं, भूकम्प आते हैं, इन सब ईश्वरीय विधानों के सम्मुख मनुष्य क्या कर सकता है? कुछ नहीं। इसी प्रकार यदि राजा अन्याचार करता है, कौन दारा जनता को पीड़ित करता है, तो मनुष्य को उस राजकीय प्रबोध को चुपचाप सहना ही चाहिये। फ्रांस का राजा लुई '१५वां अभिमान में कहा जाता था—“यह जानून है, क्योंकि मेरी ऐसी ही इच्छा है। राज्य की प्रभुत्व शक्ति मुझमें निहित है। जानून बनाने का हय वेदल मुझे है, उमने लिये मुने किसी का सहयोग लेने की आवश्यकता नहीं।”

न हो। भिन्न सम्प्रदाय को माननेवाली प्रजा पर इन राजाओं ने घोर अत्याचार किये। इस स्थिति का परिणाम यह हुआ, कि विविध देशों की प्रजा प्रधानतया एक ही धर्म व सम्प्रदाय की अनुयायिनी हो गई। साथ ही पोप और चर्च के प्रभुत्व के कारण यूरोप में जो एकता की भावना थी, वह नष्ट होने लगी। पहले यह विचार प्रचल था, कि मर्यादित जिनियन यूरोप एक क्षेत्र है, जिसे पर एक पोप का प्रभुत्व है। प्रोटेस्टेंट सम्प्रदाय के विराम और राजाओं की शक्ति के बढ़ने से यह विचार निरर्थक हो गया, और विविध राज्यों के पृथक्त्व की भावना जोर पकड़ने लगी। अठारहवीं सदी के शुरू तक फ्रांस, स्पेन आदि विविध देश बहुत कुछ पृथक् राष्टों का रूप धारण कर चुके थे।

**राजनीतिक जागृति**—निर्गुन शासन के इस युग में भी कोई कोई स्थान ऐसे थे, जहाँ जनता के शासन का धीरे-धीरे सूत्रपात हो रहा था। स्विट्जरलैंड की पहाड़ी घाटियों के निवासी चौदहवीं सदी में ही अपना शासन स्वयं करने लगे थे। हालैंड के निवासियों ने स्पेन के स्वेच्छाचारी शासन के विरुद्ध विद्रोह कर १६४८ में स्वतन्त्रता प्राप्त की थी। स्वतन्त्र होने के बाद हालैंड में जो गणराज्य कायम हुई थी, उसमें जनता का पर्याप्त हाथ था। पर निर्गुन स्वेच्छाचारी शासन का अन्त कर के लोकसत्तात्मक शासन की स्थापना के लिये सब से प्रबल मन्दपं उद्गारण्ड में हुआ। अठारहवीं सदी में स्टार्ट वंश के राजाओं के स्वेच्छाचारी शासन के विरुद्ध उद्गारण्ड में जो गाने हुए, उन पर हम आगे चलकर प्रकाश डालेंगे। पर इन थोड़े से अपवादों को छोड़कर अठारहवीं सदी तक यूरोप के सभी देशों के शासन पूर्णतया स्वेच्छाचारी रहे।

पर यूरोप में सर्वत्र जो पुन जागरण हो रहा था, जो युग परिवर्तन हो रहा था, जिस प्रकार ज्ञान, धर्म, भूगोल व आर्थिक जीवन के क्षेत्र में एक नये युग का सूत्रपात हो रहा था उसका प्रभाव राजनीतिक क्षेत्र पर न पड़े, यह असम्भव था। कुछ समय बाद अठारहवीं सदी के अन्त में फ्रांस में राज्यक्रान्ति हुई। इस क्रान्ति के साथ यूरोप के राजनीतिक जीवन में एक नवीन प्रवृत्ति का सूत्रपात हुआ, जिसे हम लोकतन्त्र शासन कहते हैं। आज यह प्रवृत्ति प्रायः पूर्णतया सफल हो चुकी है। यूरोप के प्रायः सब देशों में एकतन्त्र शासन का अन्त होकर लोकतन्त्र शासनो की स्थापना हो गई है। यूरोप के आधुनिक इतिहास में यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना है।

यूरोप के पुन जागरण का क्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत था। जब एक बार मनुष्यों ने पुरानी रूढ़ियों और अन्धविश्वासों का परित्याग कर अपनी बुद्धि से काम लेना प्रारम्भ किया, तो उनके बन्धन निरन्तर टूटते गये। प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति का मार्ग उनके लिये खुलता गया। न केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही, अपितु सामाजिक, आर्थिक, व्यावसायिक और धार्मिक क्षेत्रों में भी यूरोप ने असाधारण उन्नति की। इस इतिहास में हम इसी चौमुखी उन्नति पर प्रकाश डालने का यत्न करेंगे।

## ५. अमेरिका में यूरोपियन उपनिवेश

**स्पेन के उपनिवेश**—कोलम्बस ने किस प्रकार स्पेन के राजा की सहायता से अमेरिका के विशाल महाद्वीप का पता लगाया, इस पर हम पहले प्रकाश डाल चुके हैं। यह

महादीप धनधान्य में पूर्ण था, इसमें एजटेक और मय सभ्यताओं का विकास हो चुका था। मैक्सिको और पेरू के निवासियों के पास जो भी सम्पत्ति थी, उसे स्पेन के लोग लूट कर अपने देश में ले आये। वहाँ के निवासियों का उन्होंने बुरी तरह से सहार किया।

कुछ समय बाद स्पेन के लोगो ने अनुभव किया, कि अमेरिका के विस्तृत प्रदेशों में खेती बड़े पैमाने पर की जा सकती है। साथ ही, वहाँ बहुभूल्य धातुओं की खान भी है। उन्हें खोदकर सोना, चादी, लोहा आदि बड़ी मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है। पर इन दोनों कामों के लिये मजदूरों की आवश्यकता थी। स्पेनिश लोगो ने पहले यह कोशिश की, कि अमेरिका के मूल निवासियों को गुलाम बनाकर उनमें काम लिया जावे। इस उद्देश्य में बहुत से मूल अमेरिकनो को पकड़ा गया, उनपर भयंकर अत्याचार किये गये। पर मूल अमेरिकन लोग गुलामी के जीवन को जरा भी पसन्द नहीं करते थे। उन्हें गुलामी की ओरका मौन खधिक प्रिय थी। स्पेन के लोग मूल अमेरिकनो को गुलाम बनाने व उनमें काम लेने में सफल नहीं हो सके।

उस दशा में कुछ लोगो ने यह विचार किया, कि अफ्रीका महाद्वीप के ह्वडियो को पकड़कर उनमें अमेरिका में गुलामों का काम लिया जा सकता है। ह्वडो लोगो की तबियत गुलामी के जीवन में उतनी नहीं बिदकती थी, जितनी कि मूल अमेरिकनो की। उस समय तक यूरोप के लोग अफ्रीका में भी दूर-दूर तक प्रवेश करने लगे थे। उन्होंने ह्वडियो को बड़ी राशियाँ में पकड़कर गुलाम के रूप में बेचना शुरू किया। सोलहवीं सदी में यह एक बाजारवादा व्यापार बन गया और हजारों लाखों ह्वडो पशुओं के समान जहाजों में लादकर अमेरिका लाये जाने लगे। उनकी बाजारवादा मण्टी लगनी थी। अमेरिका में बसे हुए स्पेनिश लोगो का पास बन व जमीन की कमी नहीं थी। अपने विद्यालय खेतों व समृद्ध जंगलों में काम करने के लिये उन्हें गुलामों की जरूरत थी। ये गुलाम उन्हें अफ्रीका में मिलने लगे। सोलहवीं, सत्रहवीं और अठारहवीं सदियों में गुलामों का यह व्यापार निरन्तर जारी रहा, और बहुत से यूरोपियन व्यापारियों ने इस घृणित व्यापार में अपार धन कमाया। उस समय में यूरोप के लोग गुलामों की प्रशंसा व गुलामी के क्रय-विक्रय को घृणित बात नहीं समझते थे।

पश्चिम-पूरबी मध्य व दक्षिणी अमेरिका में स्पेन के अलग उपनिवेश बन गये। वेस्ट इंडीज, ब्राजील, मैक्सिको, पेरू आदि विविध अमेरिकन राज्य शुरू में स्पेन ही के उपनिवेश थे। अन्य बड़े देश इस विद्यालय अमेरिकन महाद्वीप में अपने उपनिवेश नहीं बना सक्ता थे, क्योंकि १८९४ ईस्वी में रोस के पोप ने यह घोषणा कर दी थी कि वेप बर्ड हीनस के २०० तीस पश्चिम में एक रेखा उत्तर में दक्षिण की तरफ खींच दी जाय, तो इस रेखा के पश्चिम के सब प्रदेश पर स्पेन का अधिकार रहता था। इस रेखा के पूर्व में पाँच भाग पड़े।

की सर्वथा उम्मेदों पर अमेरिका में अपन उपनिवेश बनाने शुरू किये। मोल्दोवी सनी क उत्तरार्द्ध में अङ्ग्लिश और फ्रेंच नाविक अमेरिका जाने लगे। स्पेन की वस्तुतया मध्य और दक्षिणी अमेरिका में जा बसी थी। जहाँ अब कनाडा और मध्यत राज्य अमेरिका के विशाल राज्य हैं, वे प्रदेश उस समय तक गंदारी पड़े थे। उन में केवल अङ्गली और अमर्य जानिया का निवास था। अङ्ग्लिश और फ्रेंच लोगों ने वहाँ अपने उपनिवेश बसान शुरू कर दिये। फ्रेंच लोग मुख्यतया कनाडा में बसने लगे और अङ्ग्लिश लोग उनके दक्षिण में मध्यत राज्य अमेरिका में।

मजदूरी नदी के शुरू में वर्जिनिया, न्यू इङ्ग्लैण्ड, मेरीलैण्ड, पेन्सिलवेनिया आदि अनेक अङ्ग्लिश उपनिवेश अमेरिका में स्थापित हो गये थे। उसी समय में फ्रेंच लोगों ने नोवा स्कोटिया और न्यूब्रंस में अपन उपनिवेश बना किये थे। अङ्ग्लिश और फ्रेंच का निरन्तर नये-नये उपनिवेश बनाने में तत्पर थे और अमेरिका में उनकी आवादी निरन्तर बढ़ती जाती थी। अटाहवी नदी के मध्य तक अमेरिका में बसे हुए अङ्ग्लिश लोग की संख्या दस लाख और फ्रेंच लोगों की संख्या एक लाख तक पहुँच गई थी। उन यूरोपियन लोगों के अतिरिक्त लाखों ह्वी गुलाम उनकी अमेरिका के उपनिवेशों में बसे हुए थे, जिन्हें वहाँ खेती और मजदूरी के लिये ले जाया गया था।

## ६ अमेरिका की स्वाधीनता

फ्रेंच शासन का अन्त—उत्तरी अमेरिका में फ्रेंच लोगों ने जो उपनिवेश बनाये किये थे, वे देर तक उनके अधीन नहीं रह सके। १७५६ ई० में १७६३ ई० तक यूरोप के विविध देशों में एक महायुद्ध हुआ, जो इतिहास में सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से परिचित है। यद्यपि इस महायुद्ध में यूरोप के अनेक देश शामिल थे, पर मुख्यतया इसमें फ्रांस और इङ्ग्लैण्ड एक दूसरे के साथ संघर्ष कर रहे थे। ये दोनों शक्तिशाली देश अमेरिका और एशिया में अपनी-अपनी सत्ता के विस्तार में लगे थे। यह स्वाभाविक था, कि इनमें संघर्ष हो। इस संघर्ष में ब्रिटेन सफल हुआ। कनाडा में जो अनेक उपनिवेश फ्रेंच लोगों ने बनाये किये थे, वे ब्रिटेन के अधिकार में आ गये। उस समय में कनाडा ब्रिटेन का उपनिवेश है। यद्यपि वहाँ फ्रेंच लोग बड़ी संख्या में बसते हैं, पर अब वह विशाल देश ब्रिटिश साम्राज्य का एक अंग है।

ब्रिटिश उपनिवेशों की स्वाधीनता—कनाडा के दक्षिण में ब्रिटिश लोगों ने न्यू इङ्ग्लैण्ड, मेरीलैण्ड, पेन्सिलवेनिया, वर्जिनिया आदि जो अनेक उपनिवेश बनाये थे, उन्होंने १७६६ ई० में इङ्ग्लैण्ड के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। इन उपनिवेशों में बसे हुए अङ्ग्लिश लोग यह नहीं चाहते थे, कि अटलान्टिक महासागर के पार से ब्रिटिश राज्य व ब्रिटिश पार्लियामेन्ट उन पर शासन करे। सप्तवर्षीय युद्ध (१७५६-१७६३) का उल्लेख हमने अभी किया था। इस युद्ध में ब्रिटेन को बहुत खर्च उठाना पड़ा था। विशेषतया कनाडा को फ्रेंच लोगों से जीतने में उन्हें सेना पर बहुत खर्च करना पड़ा था। इङ्ग्लैण्ड में इस समय जार्ज तृतीय का शासन था। वह शक्तिशाली और स्वेच्छाचारी राजा था। उसने विचार किया, कि सप्तवर्षीय युद्ध के खर्च को पूरा करने के लिये अमेरिकन उपनि-

वेगों पर विद्युत् टंक लगाया जाना चाहिये। अमेरिका के लोग यह बात सहन करने के लिये तैयार नहीं थे कि अटलान्टिक महासागर के पार बैठे हुए पार्लियामेन्ट के सदस्य उन पर टंक लगावे। वे कहते थे, ब्रिटिश पार्लियामेन्ट में हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है। बिना हमारे प्रतिनिधित्व के उसे क्या अधिकार है, कि हमारे ऊपर टंक लगाने का फैसला करे। उन्होंने उन टंकमो को देने में इनकार कर दिया। जो चाय ब्रिटेन में अमेरिका जानी थी, उस पर भी टंक लगाया गया था। जब इंग्लैण्ड का एक जहाज चाय की पेटिया लेकर बोस्टन के बन्दरगाह में प्रविष्ट हुआ, तो कुछ अमेरिकन लोग उस पर चढ़ गये और उन्होंने चाय की पेटियों को समुद्र में फेंक दिया। यह घटना १७७३ ई० में हुई थी। बोस्टन से विद्रोह की जो अग्नि भट्कानी गुरू हुई धीरे-धीरे उसने ब्रिटेन के सब अमेरिकन उपनिवेशों को व्याप्त कर लिया। सब जगह ब्रिटेन का मुकाबला करने के लिये स्वयंसेवक भर्ती किये जाने लग और इन स्वयंसेवक सेनाओं की ब्रिटिश सेनाओं के साथ बाकायदा लड़ाई शुरू हो गई।

अमेरिकन उपनिवेशों के लिये यह सम्भव नहीं था, कि वे स्वयं ब्रिटेन की सेनाओं का मुकाबला कर सकें। उस समय फ्रांस इंग्लैण्ड का कट्टर शत्रु था। सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस का इंग्लैण्ड में नीचा देवना पड़ा था। फ्रेंच लोग अपनी पराजय का बदला चुकाने के लिये उत्सुक थे। अब अमेरिकन लोगो ने फ्रांस में सहायता की अपील की। जनरल लफायट का नेतृत्व में फ्रेंच स्वयंसेवको न स्वातन्त्र्य युद्ध में अमेरिका की सहायता करने के लिये प्रस्थान किया।

उसी बीच में, जून १७७६ में अमेरिका ने अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी। फ्रांस ने अमेरिका की स्वतन्त्र सत्ता को स्वीकार कर लिया और जो जान में उसकी सहायता प्रारम्भ कर दी। १७८१ तक ब्रिटेन और अमेरिका की लड़ाई जारी रही। आगिर, ब्रिटेन पराजित हुआ और अमेरिका के ये उत्तरी उपनिवेश ब्रिटेन की अधीनता में मुक्त हुए।



## ७. व्यापारिक क्रांति

पन्द्रहवीं सदी के अन्त में नये प्रदेशों को खोज निकालने की जो प्रवृत्ति यूरोप में शुरू हुई थी, उसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं। इस प्रवृत्ति ने न केवल विनाल अमेरिकन महाद्वीप में उपनिवेश बनाने का अवसर यूरोपियन देशों को प्रदान किया, अपितु अफ्रीका के विविध प्रदेशों को हस्तगत करने और एशिया के साथ व्यापारिक सम्बन्ध बढाने लिये भी उन्हें प्रेरित किया। उसमें यूरोप के लोगों के सम्मुख व्यापार का एक विनाश क्षेत्र खुल गया और उसमें लाभ उठाने के आर्थिक समुद्र के मार्ग पर अग्रसर होने लगे।

नये प्रदेशों के परिज्ञान के कारण यूरोप की आर्थिक दशा में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन आया, उसे व्यापारिक क्रांति के नाम से कहा जाता है।

**व्यापारिक क्रांति का स्वरूप**—पहले यूरोप के सामुद्रिक व्यापार का वह भूमध्यसागर व अटलान्टिक महासागर के तटवर्ती प्रदेशों तक ही सीमित था। अब यूरोपियन नाविक अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में आने-जाने लगे। उनके व्यापार सुदूरवर्ती इण्डोचायना, इण्डोनीशिया, भारत, अमेरिका और अफ्रीका जैसी देशों के साथ व्यापार के लिये तत्पर हुए। जहाजों का आकार अधिक विनाश होने लगा। एनटवर्पन मय सभ्यताओं के विनाश द्वारा स्पेनिश लोगों को मोना और चादी अत्यधिक पैमाने पर लूट में प्राप्त हुए। अमेरिका में उन बहुमूल्य धातुओं की जो अनेक नई वस्तुएँ बनाई जाती थी, उनसे भी मोना चादी बहुत बड़ी मात्रा में यूरोप पहुँचने लगी। अफ्रीका की एशिया के साथ व्यापार के कारण भी यूरोपियन लोगों को बहुत अधिक जातिवस्तु प्राप्त हुआ। धन की वृद्धि से महाजनो की बहुत उत्पत्ति हुई। बहुत से नये बैंक खुले। बड़े व्यापार के लिये अधिक पूँजी की आवश्यकता होती थी। इसलिये जायन्ट स्टॉक कम्पनियाँ का संगठन शुरू हुआ और करोड़ों रुपये की पूँजी में नई-नई कम्पनियाँ खुलनी प्रारम्भ हुई। ईस्ट इण्डिया कम्पनी इस प्रकार की कम्पनियों का एक अच्छा उदाहरण है। इन जायन्ट स्टॉक कम्पनियों के हिस्से बाजार में खुले तौर पर विक्रित थे और इससे स्टॉक एक्सचेंज का भी प्रारम्भ हुआ, जो यूरोप के आर्थिक जीवन में एक सर्वथा नई चीज थी। आर्थिक उत्पत्ति के लिये अभी यूरोप में यान्त्रिक शक्ति का प्रयोग शुरू नहीं हुआ था। तैयार माल का उत्पादन पुराने तरीके से कारीगरों द्वारा ही किया जाता था, जो अपने घर पर बैठकर हाथ से सब काम करते थे। पर व्यापार का क्षेत्र और परिमाण अब पहले की अपेक्षा बहुत अधिक विशाल हो गया था।

व्यापार के सम्बन्ध में इस युग में (१५०० से १७५० तक) जिस नीति का अनुसरण किया जाता था, उसे मर्केन्टाइल सिस्टम कहा जाता है। इस नीति के अनुसार यूरोप का प्रत्येक देश यह यत्न करता था, कि वह अधिक से अधिक मात्रा में अपना माल और देशों को बेचे। आयात की अपेक्षा उसका निर्यात अधिक रहे, ताकि अपने माल के बदले में प्रचुर परिमाण में सोना चादी प्राप्त की जा सके। वह देश समृद्ध समझा जाता था, जो अपने माल की कीमत के रूप में अन्य देशों से सिक्का (सोने या चादी का) प्राप्त कर सके। इसलिये इस युग में प्रत्येक राज्य यह प्रयत्न करता था, कि अपने व्यवसाय को उन्नत कर

ब्राँन उनका तैयार माल अन्यत्र विककर राज्य की समृद्धि में महायुक्त हो। स्पेन, इङ्ग्लैण्ड, फ्रांस आदि देश इसी नीति का अनुसरण कर इस युग में धनी होने के लिये प्रयत्नशील थे।

**व्यापारिक क्रान्ति के परिणाम—**(१) व्यापारिक क्रान्ति का सब से महत्त्वपूर्ण परिणाम व्यावसायिक क्रान्ति का प्रादुर्भाव था, जो अठारहवीं सदी के अन्तिम भाग में यूरोप में शुरू हुई। अधिक में अधिक माल तैयार करने की वी प्रवृत्ति ने यूरोप के शिल्पियों को इस बात के लिये प्रेरणा दी, कि वे उत्पादन के नये तरीकों का अवलम्बन करें। हम इस व्यावसायिक क्रान्ति पर एक पृथक् अध्याय में प्रकाश डालेंगे। पर यहाँ यह ध्यान में रहना चाहिये, कि व्यवसायों के लिये नये साधनों के अवलम्बन के लिये जो प्रेरणा यूरोप के लोगों का प्राप्त हुई, उसका मूल कारण व्यापारिक क्रान्ति ही थी।

(२) नामाजिक क्षेत्र में व्यापारिक क्रान्ति ने अनेक महत्त्वपूर्ण परिणाम उत्पन्न किये। यूरोप के लोग दूर-दूर के देशों में व्यापार के लिये आने-जाने लगे, उन्हें नये देशों व नये लोगों ने परिचित हुआ। इसमें उनकी दृष्टि अधिक विगल हुई। वे अनेक नई वस्तुओं का अपने जीवन में उपयोग करने लगे। चाय और काफी का प्रयोग उन्होंने इसी युग में शुरू किया। तमाकू से भी पहले पहल परिचित उन्हें इसी समय में हुआ। अमेरिका और अफ्रीका के विगल प्रदेशों में बसने व व्यापार के लिये यूरोपियन लोग बड़ी संख्या में जाने लगे। इसमें यूरोप में जनसंख्या घटने लगी। इस समय तक यूरोप के किसानों की दशा अन्न-दाप की सी थी। आबादी के कम होने से इस दशा में अन्तर आने लगा और अफ्रीका के हन्सी गुलामों के कारण यूरोपियन किसानों को गुलामी में छुटकारा पाने में सहायता मिली। मध्यश्रेणी के लोगों को व्यापार और व्यवसाय द्वारा समृद्ध होने का अनुभव अवसर प्राप्त हुआ और धीरे-धीरे उनका महत्त्व बढ़ने लगा। अठारहवीं सदी में यूरोप में राज्यक्रान्ति की जो लहर प्रारम्भ हुई, उसका नेतृत्व मध्यश्रेणी के उन लोगों ने ही किया। मध्यश्रेणी में जो आत्मसम्मान और अपने महत्त्व की भावना प्रादुर्भाव हुई थी, उसका कारण यह व्यापारिक क्रान्ति ही थी।

प्रामाणिक रूप से यह जानने का अवसर मिला, कि आर्थिक दृष्टि से राज्य की कितनी दुर्दशा हो गई है।

**कैलोन**—नैकर के बाद उसके महत्वपूर्ण पद पर कैलोन को अधिष्ठित किया गया। कैलोन एक दरवारी था। आर्थिक क्षेत्र में उसका एक ही असूल था और वह यह, कि राजकीय व्यय के लिये जितने धन की आवश्यकता हो, उसे ऋण लेकर प्राप्त कर लिया जाय। राजा और उसके दरबारियों को मोज उड़ाने के लिये रुपये की जरूरत थी। टैक्सो से इतना रुपया प्राप्त नहीं होता था, कि सब आवश्यकताएँ पूर्ण की जा सकें। एक उपाय और था, वह यह कि कर्ज लिया जाय। कैलोन ने इसी का आश्रय लिया। चार सालों में उसने ९० करोड़ रुपये कर्ज लिये। पर कर्ज की भी कोई हद होती है। इससे अधिक कर्ज भी न मिल सका। लोग इतने वेवकूफ न थे, कि इस प्रकार कर्ज देते जावे। आखिर, कैलोन को भी सुधारो की सूझी। उसने राजा को सूचना दी, कि फ्रांस के दिवालिया होने में अब अधिक विलम्ब नहीं है। यदि इस विकट परिस्थिति से फ्रांस की रक्षा करनी हो, तो उसके लिये महत्वपूर्ण सुधारो की आवश्यकता है। कैलोन की सम्मति में सबसे अधिक महत्वपूर्ण सुधार यह था, कि कुलीन और पुरोहित श्रेणियों पर भी भूमिकर लगाया जाय। अब तक ये श्रेणियाँ प्रायः इस कर से मुक्त थीं। कैलोन चाहता था, कि सब लोगों पर भूमिकर एक समान रूप से लगाया जाय। इसलिये उसने राजा को सलाह दी, कि कुलीन श्रेणियों और चर्च के प्रमुख व्यक्तियों को बुलाया जाय और उनके सम्मुख ये सुधार विचार के लिये उपस्थित किये जावें।

**प्रमुख लोगों की सभा (१७८६)**—राज्य और चर्च के प्रमुख व्यक्तियों की सभा बुलाई गई। इस सभा में सर्वसाधारण जनता के प्रतिनिधि नहीं बुलाये गये थे। केवल विशेषाधिकार प्राप्त लोग इसमें आये थे। इस सभा के सम्मुख कैलोन ने फ्रांस की वास्तविक दशा का चित्र खींचकर अपने सुधार प्रस्तावित किये। कैलोन ने बताया कि फ्रांस को १२ करोड़ रुपया वार्षिक घाटा हो रहा है। राष्ट्रीय ऋण की मात्रा २४ करोड़ बढ़ गई है। अधिक किराया नहीं की जा सकती। कितनी भी किराया की जाय, घाटा दूर नहीं हो सकता। नया कर्ज भी अब नहीं मिलता। अब क्या किया जाय? सर्वसाधारण जनता पहले ही टैक्सों के बोझ से लदी हुई है, उस पर नये टैक्स नहीं लगाये जा सकते। हा, एक उपाय है। टैक्स की पद्धति के दोषों को दूर किया जाय, तो समस्या हल हो सकती है। बहुत से लोग टैक्स से मुक्त हैं, बहुत से लोग विशेषाधिकार प्राप्त हैं। हा, यदि इनसे भी टैक्स वसूल किये जावें, यदि टैक्स का कानून सब प्रदेशों तथा सब लोगों पर एक समान रूप से लागू हो, तो आर्थिक पहेली सुलझाई जा सकती है। कैलोन ने बड़ी निर्भयता से अपने कार्यक्रम को, अपने सुधारों को पेश किया। पर प्रमुख लोगों की इस सभा को कैलोन पर विश्वास न था, वे उसके सुधारों को स्वीकृत करने के लिये तैयार न थे। कैलोन बर्खास्त कर दिया गया और उसके साथ ही प्रमुख लोगों की यह सभा भी बर्खास्त कर दी गई।

आर्थिक समस्या को हल करने के लिये राजा ने स्वयं सुधार प्रस्तावित किये। इसके लिये राजा ने दो नये टैक्स लगान का निश्चय किया था। सामान्य रीति से इन टैक्सों को

द्वारा करने के लिये परिषद के न्यायालय (पार्लमा) के पास भेजा गया। पर इसका परिषद के न्यायालय ने असाधारण मार्ग का अवलम्बन किया। उसने इस नये दंडमात्रा दंड करने के ही उत्तर नहीं दिया। पर तब ही यह भी उद्घोषित किया, कि किसी स्थिर दंड का लगान की अनुमति के देने का अधिकार 'एस्टेट्स जनरल' में एकत्रित करना ही है, अन्य किसी का नहीं। इस उद्घोषणा के कुछ दिन बाद ही परिषद के न्यायालय ने राजा से प्रार्थना की, कि राज्य के 'एस्टेट्स जनरल' के अधिवेशन को बुलाया जाय।

राजा के लिये अब एक नई समस्या उत्पन्न हो गई थी। न्यायालय उसका ठे गो को दर्ज नहीं करने दे। उन्होंने तत्काल-पक्ष राजा तथा उसके महामन्त्रियों के बीच का विरोध करना शुरू कर दिया था। राजा ने परिषद के न्यायालय को बर्खास्त कर दिया और न्याय की नई पद्धति की स्थापना की। पर स्थिति अब उसके पास ने बाहर हाथ थी। क्रान्ति की भावना लगा मे गहरा स्थान प्राप्त कर गई थी। जाति, उस समय होकर 'एस्टेट्स जनरल' के अधिवेशन का बुलाने के लिये सहमति देनी पड़ी।

## ८ क्रान्ति का श्रीगणेश

**एस्टेट्स जनरल**—'एस्टेट्स जनरल' के अधिवेशन के साथ ही क्रान्ति का श्रीगणेश हो जाता है। राजा की यह प्रथम पराजय थी। उसे यह स्वीकार करना पड़ा था, कि वह अकेला अपनी इच्छा से—चाहे माझान् परमात्मा ने ही उसे राज्य करने के लिये नियुक्त किया हो—फ्रांस की आर्थिक समस्या का हल नहीं कर सकता। उसे जनता की महान् की आवश्यकता को स्वीकार करना पड़ा था। क्रान्ति के सिद्धान्त की यह भागी विजय थी।

एस्टेट्स जनरल क्या चीज थी, उसका निर्माण किस प्रकार होता था और उसके नियम थे—इन बातों को जाननेवाला उस समय कोई न था। इस सभा का १७५ साल से कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ था। सभी लोग इसकी चर्चा तो करते थे, पर उसका ठीक ठीक परिज्ञान किसी को न था। परिणाम यह हुआ, कि यह कार्य विद्वानों के मुँह किया गया। आखिरकार, फ्रांस के विद्वानों ने बड़े अनुपस्थान के अनन्तर यह पता लगाया कि एस्टेट्स जनरल का क्या स्वरूप था।

जिन दिनों फ्रांस में सामन्तपद्धति (Feudal System) प्रचलित थी, तब इस सभा के अधिवेशन हुआ करते थे। इसका निर्माण सामन्तपद्धति की परिस्थितियों को दृष्टि में रखकर हुआ था। यह सभा तीन विभागों में विभक्त थी और इन विभागों में स्वयं पुरोहित, कुलीन तथा तृतीय (सर्वसाधारण जनता) श्रेणियों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुआ करते थे। तीनों श्रेणियों के सदस्यों की संख्या बराबर-बराबर होती थी और प्रत्येक विभाग पृथक्-पृथक् वोट देता था। एक विभाग का एक वोट समझा जाता था। किस विभाग की क्या सम्मति है, यह बहुमत से निर्णय किया जाता था। तीन विभागों में से कम से कम दो जिसके पक्ष में हो, वह स्वीकृत समझा जाता था। मध्यकाल की परिस्थितियों के अनुसार यह व्यवस्था सर्वथा उपयुक्त थी। उस समय राष्ट्रीय भावना और लोकतन्त्रवाद का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था। पुरोहित और कुलीन श्रेणियों की महत्ता लोगों की दृष्टि में निर्विवाद थी। सर्वसाधारण जनता में अपने महत्व का विचार ही उत्पन्न नहीं हुआ था। उस

जमाने में यह भी बहुत बड़ी बात थी कि सर्वसाधारण जनता के प्रतिनिधि इस सभा में सम्मिलित हो। उस समय में यह बिल्कुल स्वाभाविक था, कि कुलीन और पुरोहित श्रेणियाँ पृथक् विभागों में वोट करें और अपने को साधारण जनता से अलग रखें। पर अब १७८८ में जमाना बिल्कुल बदल चुका था। अब सर्वसाधारण लोगों के प्रतिनिधि यह दावा करते थे, कि हम ९५ फीसदी से अधिक जनता के प्रतिनिधि हैं। पुरोहितों और कुलीनों को पृथक्-पृथक् जितने सदस्य प्राप्त हैं, केवल उतने ही हमें भी प्राप्त हों—यह कहा का न्याय है ?

**प्रतिनिधियों की सख्या—**इस समय राजा का प्रधानमन्त्री नैकर था। कैंलोन के पतन के बाद उसे फिर अपने पुराने पद पर नियत किया गया था। नैकर ने स्वीकार किया कि सर्वसाधारण जनता को दुगने प्रतिनिधि मिलने चाहिये। कुलीनों और पुरोहितों के तीन-तीन सौ प्रतिनिधि होते थे, अतः सर्वसाधारण जनता को ६०० प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया।

**वोट का प्रकार—**परन्तु इससे वास्तविक समस्या का हल नहीं हुआ। सर्वसाधारण जनता को दुगने प्रतिनिधि मिल गये—पर इससे लाभ कुछ नहीं हुआ। यदि तीनों विभागों को एक सभा में वोट देना होता, प्रत्येक सदस्य का एक वोट गिना जाता और सम्पूर्ण सदस्यों के बहुमत से निर्णय होता, तब तो अवश्य लाभ था। पर यदि इसके विपरीत अब भी पहले की ही तरह प्रत्येक विभाग का एक वोट गिना जाय और प्रत्येक विभाग अपना निर्णय पृथक् रूप से करे, तो इससे कोई लाभ नहीं था। अतः सर्वसाधारण जनता ने यह आन्दोलन शुरू किया कि वोट का ढग बदलना चाहिये। तीनों विभागों की पृथक्-पृथक् सभा न होकर एक साथ सभा होनी चाहिये और उसमें बहुमत से निर्णय किया जाना चाहिये। पर नैकर ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

**शिकायत-पत्र—**एस्टेट्स जनरल के लिये प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने के साथ ही पुराने रिवाज के अनुसार जनता को यह भी अवसर दिया गया था, कि सरकार और देश के शासन से उन्हें जो शिकायत हो, उन्हें लिखकर भेजें। लोगों ने इस अवसर का पूर्ण रूप से उपयोग किया। हजारों की सख्या में शिकायत पत्र लिखकर भेजे गये। साठ हजार के लगभग इस प्रकार के शिकायत-पत्र अब भी सुरक्षित हैं, और उनके अनुशीलन से भलीभाँति जाना जा सकता है, कि उस समय लोग क्या अनुभव करते थे और उन्हें क्या शिकायतें थी। इन शिकायत-पत्रों से, जिन्हें फ्रांस में काइए (cahiers) कहा जाता था, ज्ञात होता है कि उस समय फ्रांसीसी लोग रिपब्लिक नहीं चाहते थे, वे केवल राजा के स्वेच्छाचारी शासन का अन्त करने के लिये इच्छुक थे। वे प्रत्येक मनुष्य को वोट का अधिकारी नहीं समझते थे, लोकतन्त्र शासन का यह प्रारम्भिक तत्त्व उनकी समझ में नहीं आया था। परन्तु साथ ही उस समय के शासन के विविध दोषों की अनुभूति उनमें उत्पन्न हो चुकी थी और वे उन्हें दूर करने के लिये पूर्णतया उद्यत थे। एक भारी परिवर्तन के लिये लोग तैयार हो गये थे।

**अधिवेशन का प्रारम्भ (५ मई १७८९)—**५ मई १७८९ के दिन एस्टेट्स जनरल की प्रथम बैठक हुई। सदस्यों को आज्ञा दी गई थी, कि वे उसी पोशाक को पहनकर आवें,

जो कि मध्यकाल में इस सभा के सदस्य पहना करते थे। राजा अपनी आज्ञा में सदस्याक्त पोशाक को पुराना बना सकता था, पर उसकी भावनाओं और विचारों को पुराना बना उसकी सामर्थ्य में बाध था। वर्गों के एक शानदार महल में एस्टेट्स जनरल का प्रारम्भिक अधिवेशन शुरू हुआ। बीच में ऊँचे राजसिंहासन पर राजा विराजमान था। राना उसके पार्श्व में बैठे थे। सब ने पहले राजा का प्रारम्भिक भाषण सुना। राजा इस भाषण को रटकर लाया था और पाठशाला में पढ़नेवाले उड़ते ही तरह उसने उस उगड़ दिया। नैकर के भाषण में तीन घण्टे लगे। जब राजा और उसके प्रधान मन्त्री के भाषण हो चुके, तो जय जयकार की ध्वनि के बीच में राजा और रानी ने सभाभवन में प्रस्थान किया।

एस्टेट्स जनरल के इस अधिवेशन के प्रारम्भ होने ही कुछ ऐसी घटनाएँ हा ग जिनसे कि सर्वसाधारण जनता के प्रतिनिधि चिढ़ गये। जहाँ तक पुराहित और कुलीन श्रेणियों के प्रतिनिधि बैठ नहीं गये, तब तक उन्हें पड़े रहना पड़ा। राना जब अपना प्रारम्भिक भाषण दे रहा था, तब सब लोगों ने अपनी टोपिया उतारी हुई थी। नापा की समाप्ति के अनन्तर जब राजा अपने सिंहासन पर बैठे, तो उसने अपनी टोपी निरक्ष रख ली। उसके बाद कुलीनों और पुरोहितों ने भी अपनी टोपिया निरक्ष पर रखी। पर जब सर्वसाधारण जनता के प्रतिनिधि भी यहाँ करने लगे, तो उन्हें टोका गया। वहाँ मामूली थी, पर इनमें गुट में ही सर्वसाधारण लोगों के मन पर बहुत बुरा असर पड़ा।

वोट किस प्रकार में लिये जावे, इस बात का फैसला अभी नहीं हुआ था। इसी प्रारम्भिक अधिवेशन में सभाभवन से प्रस्थान करने में पूर्व राजा ने तीन विभागों को पुनः पृथक् जाकर अपना-अपना अधिवेशन करने का आदेश दिया था, पर तृतीय श्रेणी के प्रतिनिधि इसको मानने के लिये उद्यत न थे। वे निरन्तर अन्य दोनों विभागों को उन बातों के लिये निमन्त्रित कर रहे थे, कि वे उनके साथ मिलकर एक सभा के रूप में राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार करें। पर अन्य विभागों ने इन प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया। आखिर, जब तृतीय श्रेणी के लोग अन्य विभागों के व्यवहार में नर्वथा निराश हो गये तो उन्होंने एक बड़े साहस का कार्य किया। १७ जून को तृतीय श्रेणी के विभाग के मन्त्र यह प्रस्ताव उपस्थित किया गया, कि क्योंकि वे १५ फीसदी जनता के प्रतिनिधि हैं, और क्योंकि वास्तविक शक्ति यह सर्वसाधारण जनता ही है, अतः निश्चय किया जाता है कि जनता के ये वास्तविक प्रतिनिधि राष्ट्रीय महासभा का रूप धारण कर लें। इस प्रस्ताव के पक्ष में ४९१ वोट आये और विपक्ष में ९०। प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। एस्टेट्स जनरल के तृतीय श्रेणी के प्रतिनिधियों ने अपने को राष्ट्रीय महासभा के रूप में परिवर्तित कर लिया। कुलीनों और पुरोहितों की सर्वथा उपेक्षा कर दी गई।

जब राजा और उसके दरबारियों को यह समाचार मिला, तो उनको होश आई। राजा ने आज्ञा दी, कि तीनों विभागों का अधिवेशन एक साथ किया जाय, सभापति का पद पर वह स्वयं रहेगा। ऐसा ही किया गया। एस्टेट्स जनरल के तीनों विभाग एक सभा के रूप में एकत्रित हुए। राजा सभापति बना और उसने अपने श्रीमुख से अनेक सुधार प्रस्तुत किये। जब यह सब हो चुका, तो राजा ने बड़ी गम्भीरता से आज्ञा दी कि अब तीनों

विभाग १ थक्-पथक् चले जावें और अपने-अपने अधिवेशन करे। पुरोहित और कुलीन श्रेणियों के सदस्य राजा की आज्ञा का पालन कर उठकर चले गये। शेष सदस्य चुपचाप बैठे रहे। वे देख रहे थे कि अब क्या होता है। एक बार फिर राजकीय आज्ञा दोहराई गई। मिराबो ने इसका प्रतिवाद किया। अपने निधडक होकर कहा, कि हम तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे, जबतक कि वन्दूक के कुन्दों से हमें बाहर नहीं निकाल दिया जायगा। यह मिराबो सर्वसाधारण जनता का प्रमुख और प्रभावशाली नेता था।

**जनता की विजय**—अन्त में राजा की पराजय हुई। उसे जनता की मांग स्वीकार करनी पड़ी। उसने आज्ञा प्रकाशित की, कि तीनों विभागों का अधिवेशन एक साथ हो, कुलीन और पुरोहित-श्रेणियों के जो सदस्य अभी तक तृतीय श्रेणी के साथ राष्ट्रीय महासभा में सम्मिलित नहीं हुए हैं, वे सम्मिलित हो जावें। आखिर, सर्वसाधारण जनता अपने महत्व को प्रदर्शित करने में सफल हुई। कुलीन और पुरोहित श्रेणियों पर उसकी विजय हुई।

**दरबार की साजिश**—सर्वसाधारण जनता जिस ढंग से शक्ति प्राप्त करती जा रही थी, वह दरबार के लोगों को सह्य न था। वे अच्छी तरह जानते थे कि उनकी भलाई इसी में है, कि राजा का एकतन्त्र स्वैच्छाचारी शासन कायम रहे। ये लोग मुधार के जानी दुश्मन थे। वे अपने विरोधपाधिकारों को किसी भी प्रकार छोटने के लिये तैयार न थे। वे यह भी सहन नहीं कर सकते थे, कि राजा की स्थिति वैध शासक की हो जाय। फ्रांस के शासन में जनता का हाथ हो जाने पर उन्हें मीज उड़ाने का अवसर कैसे मिलेगा? रानी इन दरबारियों का हृदय से समर्थन कर रही थी। राजा का छोटा भाई आर्तोआ का काउन्ट भी उनका प्रबल पक्षपोषक था। ये लोग सर्वसाधारण जनता की हरकतों को बहुत ही खतरनाक तथा गंतानियत से भरी हुई समझते थे, और उन्हें कुचलने के लिये सब प्रकार के उपायों का जवम्बन करने के पक्ष में थे। इन्होंने साजिश की, कि राष्ट्रीय महासभा को तोड़ दिया जाय। पर ये यह भी जानते थे, कि जनता इसे सहन न कर सकेगी। वह गदर के लिये तैयार हो जायगी। इसलिये इसका प्रबन्ध वे पहले से ही रखना चाहते थे। उन्होंने गदर को कुचलने के लिये विदेशी सैनिकों का प्रयोग करने का निश्चय किया। उस समय में वेतन की खातिर बहुत से सैनिक दूसरे देशों में भी नौकरी किया करते थे। विशेषतया, स्विट्जरलैंड और जर्मनी के वीर योद्धा यूरोप के अनेक राजाओं के पास सैनिक की नौकरी किया करते थे। इन्हें केवल अपनी नौकरी से मतलब था। अपने मालिक के हुक्म से ये कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे। दरबार का गुट चाहता था, कि इन सैनिकों की एक सेना को वुलाकर पेरिस में तैनात कर दिया जाय, ताकि यदि राष्ट्रीय महासभा के विरुद्ध करने पर जनता विद्रोह करे, तो उसे कुचल दिया जा सके। उनकी यह भी इच्छा थी कि नौकरों—जो सर्वसाधारण जनता से सहानुभूति रखता था—पदच्युत कर दिया जाय।

राजा इस साजिश से सहमत हो गया। स्विट्स और जर्मन सैनिकों की सेनाएँ पेरिस में तैनात कर दी गईं। जब पेरिस की जनता को ये समाचार मिले, तब वह भडक उठी। एक उद्यान में बहुत से लोग एकत्रित थे और इसी विषय पर बातचीत कर रहे थे। कैमिल

देसमोला नाम का एक नवयुवक अविवारनवीम उनके बीच में पहुँचा और चिल्ला-  
नित्वाकर कहने लगा, कि यी त्र ही स्विम पिताही 'देशभक्तों' को कतल करने हुए दिवाइ  
पड़ेगे, अतः हम चाहिये कि अपने का शस्त्रों में मुसज्जिन कर संगठित करें, ताकि दरबार  
गुट से अपनी रक्षा की जा सके। देसमोला का आन्दोलन काम कर गया। मार्गे रात  
लोग पेरिस की गलियाँ में चक्कर लगाने फिरे। जितने भी हथियार मिल सके, एकत्रित  
किये गये। लूटमार मच गई।

**वस्तीय का पतन**—कुछ ही दिना के बाद पेरिस के लोग फिर डकठे हुए। उन्हें  
हथियारों की खोज थी। वे देशभक्ति का कोई महत्वपूर्ण कार्य करना चाहते थे। लोग  
की एक भीड़ वस्तीय की तरफ निकल गई। यह एक पुराना किला था, जो अब जेलवात  
के तौर पर इस्तेमाल होना था। लोग को उसमें विशेष घृणा थी। उनका क्याल था,  
कि फ्रांस की सरकार के कर अत्याचारों का यह एक महत्वपूर्ण केन्द्र है। उन्हें पूर्ण आना था,  
कि यहाँ बहुत से हथियार डकठे ही मिल जावेंगे। वस्तीय का किन्देश लौनी नाम का  
एक महानुभाव था। उसने किले को घोलने में उनका कर दिया। अब तक बहुत सी भीड़  
वहाँ इकट्ठी हो चुकी थी। दोनों तरफ से कूहागुनी होने लगी। पता नहीं, किस प्रकार  
वस्तीय की सेना ने भीड़ पर गोली चला दी। सी देशभक्त मर कर गिर पड़े। लोग में  
जोश फैल गया। हमला होने लगा। आगिर, शानी को मजबूर होना पड़ा, कि किल के  
दरवाजे खोल दे। कुछ जनता अन्दर घुस गई। कंदियों को बन्धन में मुक्त कर दिया गया।  
लौनी और उसके सम्पूर्ण सैनिकों के मिर बड में अलग कर दिये गये। उन सब मिरा का  
लाठियों और बरछों की नोक पर लटकाकर मारे पेरिस में जुलूम निकाला गया। वस्तीय  
को ध्वंस कर दिया गया। यह घटना १४ जुलाई, मन् १७८९ के दिन हुई थी। इस  
घटना का बड़ा महत्व है। फ्रांस में आज भी १४ जुलाई का दिन प्रधान राष्ट्रीय त्योहार  
के रूप में मनाया जाता है। निस्सन्देह, पुराने युग के एकतन्त्र शासन पर यह प्रथम  
आघात था। इस घटना से भलीभाँति स्पष्ट हो गया, कि कान्ति अब हुए बिना नहीं  
रहेगी। कुलीन श्रेणी के बहुत से लोग इसी समय में फ्रांस छोड़कर और देशों में जाने लग  
गये। सारे देश में अव्यवस्था फैल गई।

**राष्ट्रीय स्वयसेवक सेवा**—स्थिति इतनी विगड चुकी थी, कि उसे सँभाल सकना  
राजा की शक्ति के बाहर था। जब किसी देश में अव्यवस्था फैलने लगती है, शासनभंग  
ढीला पड़ता है, तो बदमाशों और लफड़ों की बर आती है। पेरिस की भी अब यही दशा  
थी। सारे शहर में हजारों की सख्या में भूखे, नगरे लोग तवाही मचाते फिरते थे। वे  
जिस पर चाहते हमला कर देते, जिस दुकान को चाहते लूट लेते। इस अव्यवस्था में  
पेरिस के लोगों की जान और माल की रक्षा करने के लिये राष्ट्रीय नेताओं ने एक 'राष्ट्रीय  
स्वयसेवक सेना' का संगठन किया। लफायत इसका सेनापति बनाया गया। पेरिस में  
शांति और व्यवस्था कायम रखने में राष्ट्रीय सेना को पूरी सफलता प्राप्त हुई। राजा का  
यह बहाना बनाने का अवसर नहीं दिया गया, कि इस अव्यवस्था की सम्भावना को दृष्टि  
में रखकर ही उसने विदेशी सैनिकों की सेना को बुलाया था।

**नागरिक सभा**—इतना ही नहीं, पेरिस के नागरिक शासन को भी नये ढंग से संग-





फ्रांस में राज्यक्रांति का श्रोगणेश (श्री देसमोला जनता के बीच में)

## यूरोप का आधुनिक इतिहास

टिन किया गया। राजा और उसकी सरकार की सर्वथा उपेक्षा कर जनता ने स्वयं परिषदी नगर-सभा का निर्माण किया। राष्ट्रीय महामुखा के एक सदस्य को ही इस नगर-सभा का अध्यक्ष नियत किया गया। फ्रांस के अन्य बड़े नगरों ने भी पेरिस का अनुसरण किया। मधुव नवीन नगर-सभाओं की रचना की गई और राष्ट्रीय स्वयमेवक मेला सगठित व गई।

देहाता में भी अव्यवस्था फैल गई। किसानों ने जमींदारों के मकानों पर हमले शुरू कर दिये। टैक्स वसूल कर सकना असम्भव हो गया। वस्तीय के ध्वम के साथ पल्लुह का प्रादुर्भाव हुआ था, वह पेरिस तक ही सीमित नहीं रही, उसने बड़ी शीघ्रता सम्पूर्ण फ्रांस को व्याप्त कर लिया।

एक दिन राजा १६वां लुई दिन भर शिफार में बहकर जब माझ को अपने विस्तर पर लेटने लगा, तो उसे ये समाचार दिये गये। समाचार सुनकर राजा ने चकित होकर पूछा—‘है! क्या कोई दगा हो गया है?’ खबर लानवाले ने जवाब दिया—‘नहीं मालिक दगा नहीं, क्रान्ति हो गई है।’

वस्तुतः, अब राज्यक्रान्ति का श्रीगणेश हो चुका था।

पाचवा अध्याय

## राज्यक्रान्ति की प्रगति

### १ वैध राजसत्ता की स्थापना का प्रयत्न

राजा का रुख—फ्रांस में जिस प्रकार अव्यवस्था और अशान्ति फैल रही थी, उससे १६वां लुई वस्तुतः चिन्तित था। राजा अपने आप में बुरा नहीं था। उसका दोष यही था, कि वह कमजोर था, इरादों का पक्का न था। उसके सलाहकार उसके लिये सबसे अधिक हानिकारक थे। यदि १६वां लुई इन सलाहकारों के प्रभाव से बच सकता, तो निस्सन्देह क्रान्ति की दिशा कुछ और ही होती। जब उसे वस्तीय के ध्वस का समाचार मिला, तब अगले ही दिन वह राष्ट्रीय महासभा के अधिवेशन में उपस्थित हुआ। वहाँ उसने प्रतिज्ञा की, कि विदेशी सैनिकों की सेनाओं को वापिस भेज दिया जायगा और नैकर को फिर प्रधानमन्त्री बनाया गया। इसके बाद वह २०० प्रतिनिधियों (राष्ट्रीय महासभा के सदस्यों) के साथ पेरिस गया, ताकि जनता को शान्त कर सके। पेरिस में जाकर राजा ने क्रान्तिकारियों के तिरगें झण्डे को भी नमस्कार किया। फ्रांस में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे थे, राजा ने उनके सम्मुख सिर झुका देने में ही अपना कल्याण समझा। निस्सन्देह, वह ठीक मार्ग पर चल रहा था। पर उसके सलाहकार ? उसके दरबारी ? वे उसे इस नई प्रवृत्तियों को कुचल देने के लिये उकसा रहे थे। आखिर, राजा ने रात-दिन अपने पास-पास रहनेवाले इन दरबारियों के कहने को मान लिया। १६वें लुई की यही निर्बलता थी। मानवीय स्वभाव की यह निर्बलता बहुत स्वाभाविक थी।

सामाजिक क्रान्ति—राज्यक्रान्ति की जो प्रक्रिया अब प्रारम्भ हो चुकी थी, वह अपना प्रभाव प्रदर्शित कर रही थी। गांव-गाँव में किसान लोग सभाएँ करके पुराने जमाने को कब्र में गाड़ देने के प्रस्ताव पास कर रहे थे। केवल प्रस्ताव ही पास नहीं हो रहे थे, काम भी हो रहा था। टैक्स वसूल करनेवाले पानी में डुबोये जा रहे थे। जमींदारों के किले ध्वस किये जा रहे थे, गोदामों में आग लगाई जा रही थी। सर्वसाधारण जनता सामाजिक दृष्टि से अपनी हीन दशा के खिलाफ विद्रोह कर रही थी। जिन कुलीन लोगों ने उन्हें सदियों में दलित बनाया हुआ था, उनसे पूरा-पूरा बदला लिया जा रहा था। सामाजिक भेदों पर कुठाराघात किया जा रहा था। राज्यक्रान्ति तो पेरिस में हो रही थी, ये देशों के लोग तो सामाजिक और आर्थिक क्रान्ति की तरफ पग बढ़ा रहे थे। मध्यकाल की सामन्तपद्धति के जो अवशेष इस काल में विद्यमान थे, उन्हें चुन-चुनकर नष्ट किया जा रहा था।

राष्ट्रीय महासभा की जो बैठक ४ अगस्त को हुई, वह बहुत महत्वपूर्ण थी। पेश

किया गया, कि सामन्तपद्धति को नष्ट कर दिया जाय, प्रस्ताव पास हो गया। प्रस्ताव किया गया, कि चर्च को दशाश वसूल करने का जो अधिकार है, वह नष्ट कर दिया जाय, प्रस्ताव पास हो गया। प्रस्ताव किया गया, कि शिकार के कानून नष्ट कर दिये जाय, यह भी पास हो गया। कुलीन और पुरोहित श्रेणियों को जो विशेषाधिकार प्राप्त हैं, उन्हें नष्ट करने का प्रस्ताव किया गया, उसे भी पास कर दिया गया। इसी तरह के अन्य भा बहुत से प्रस्ताव उपस्थित किये गये, जिनका उद्देश्य मध्यकाल के अन्यायों को नष्ट करना था। वे सब स्वीकृत हो गये। उस बैठक में मध्यकालीन समस्याओं के बहुत न अवशेषों का अन्त कर दिया गया। यह बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण थी।

इन चार महीनों में फ्रांस में दो महत्वपूर्ण क्रान्तियाँ हो गई थीं। राज्यक्रान्ति द्वारा फ्रांस की जनता ने राजा के एकतन्त्र स्वेच्छाचारी शासन का अन्त कर राजा का तनना की इच्छा को स्वीकृत करने के लिये बाधित किया था। सामाजिक क्रान्ति द्वारा फ्रांस में सामन्तपद्धति तथा उसमें सम्बद्ध समस्याओं को नष्ट कर जनता की विविध श्रेणियाँ न समानता स्थापित की गई थी।

**कुलीन लोगों का फ्रांस से भागना—**चार अगस्त की बैठक में राष्ट्रीय महामन्त्र ने जो रुख अस्तियार किया था, उसमें यह स्पष्ट हो गया था कि फ्रांस में पुराने जमान का अन्त होना अवश्यम्भावी है। इसलिये बहुत से उच्च पुरोहित तथा कुलीन लोग उस समय न फ्रांस छोड़कर अन्य देशों में चले गये। वस्तीय की जेल के खप के बाद ही हजारों की सन्ख्या में ये विशेषाधिकार प्राप्त लोग फ्रांस छोड़कर विदेशों में जाने शुरू हो गये थे। जब इस प्रवृत्ति की गति और भी बढ़ गई। यूरोप के अन्य देशों में अभी क्रान्ति की भावना उदित नहीं हुई थी। उन्हें आशा थी, कि वहाँ उन्हें आश्रय मिलेगा और वे दूसरे देशों के कुलीन लोगों तथा राजशक्ति की सहायता से फ्रांस में क्रान्ति को कुचल सकेंगे।

**पेरिस की भीड़ का राजप्रसाद पर हमला—**पर अभी बहुत से कुलीन लोग फ्रांस में विद्यमान थे। राजा को उसके दरबारी पहले की ही तरह घेरे रहते थे। दरबार के इस गुट ने राजा को उकसाना शुरू किया, कि चार अगस्त को राष्ट्रीय महामन्त्र ने जो प्रस्ताव स्वीकृत किये हैं, उन पर अपनी स्वीकृति न दे। राजा अपने दरबारियों के प्रभाव में आ गया। समय गुजरता गया, राजा ने उन प्रस्तावों पर हस्ताक्षर नहीं किये। तरह-तरह की अफवाहें फैलने लगी। लोग आपस में बातचीत करने लगे, कि राजा क्रान्ति को कुचलने के लिये तैयारियाँ कर रहा है। इसके लिये उसने बाहर से फौज मँगवाई है। पेरिस का वातावरण इसी प्रकार की अफवाहों से गरम हो गया। ठीक वही हालत हो गई, जैसा कि वस्तीय के पतन से पहले दिन था। इसी समय खबर आई, कि फ्लान्डर्स से एक फौज बर्साय पहुँच गई है। राजा की अगर्क्षक सेना ने उसका बड़ी वृमधाम से स्वागत किया है। इस फौज को जब सहभोज दिया जा रहा था, तो रानी भी वही उपस्थित थी। यह भी सुना गया है, कि सेना के अफसरो ने जोश में भरकर क्रान्ति के तिरगे झण्डे को पैरों से कुचला है। इस प्रकार की अफवाहों से जनता में जोश लहरे मारने लगा। पेरिस में भूखो नङ्गा की क्या कमी थी। गुण्डे और बदमाश भी ऐसे मौकों की प्रतीक्षा में रहते हैं। भूखे, गुण्डे, बदमाश, देशभक्त, क्रान्तिकारी—सब तरह के लोग कामकाज छोड़कर बाजारों में

निकल आये। गपशप उड़ने लगी। जरा सी देर में लोगो का एक जुलूस बन गया। हजारों औरतें और हजारों मर्द पेरिस की गलियों में जुलूस बनाकर फिरने लगे। जिधर भी ये गये, लोग साथ होते गये। पेरिस में चक्कर काट कर इस जुलूस ने वर्साय की तरफ—जहाँ राजा रहता था—प्रस्थान किया। लफायत अपनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेना को लेकर जुलूस के पीछे-पीछे हो लिया। उसे फिकर थी, कि कहीं दगा न हो जाय। स्थिति को कावू में रखने के लिये वह पेरिस की इस भीड़ के साथ-साथ वर्साय गया था। यह घटना ५ अक्टूबर को हुई।

पेरिस की इस भीड़ ने राजप्रासाद को घेर लिया। जब तक जुलूस वर्साय पहुँचा, शाम हो गई थी। लोगो ने राजप्रासाद के आसपास खुले आसमान के नीचे रात व्यतीत की। सुबह होने पर लोग फिर हल्ला-गुल्ला करने लगे। कुछ लोगो ने प्रासाद के सन्तरियों से छेड़छाड़ की। झगडा हो गया, अनेक सन्तरी मारे गये। कुछ लोग प्रासाद में घुस गये। ईंट और पत्थर फेंके जान लगे। कुछ समझदार लोग राजा के पास पहुँचे और निवेदन किया कि महाराज, भीड़ तब तक शान्त न होगी, जबतक आप उसे दर्शन न दे देंगे। राजा ने स्वीकार कर लिया। राजप्रासाद के झरोखे पर खड़े होकर राजा, रानी और राजकुमार ने जनता को दर्शन दिया। पर लोग इतने से भी सन्तुष्ट न हुए। वे आग्रह करने लगे, कि राजा को उनके साथ पेरिस चलना पड़ेगा। उन्हें विश्वास था, कि राजा ही सब सुख समृद्धि का मूल है। उसे पेरिस में अपन साथ रखकर वे समझते थे, कि उनकी सब समस्याओं का हल हो जायगा। फ्रांस की जनता अब तक भी हृदय से राजभक्त थी। रिपब्लिक की कल्पना अब तक भी उत्पन्न नहीं हुई थी।

**पुराने जमाने का मातमी जुलूस**—छ अक्टूबर को दिन के एक बजे जुलूस ने वर्साय से पेरिस के लिये प्रस्थान किया। पुराने जमाने का यह मातमी जुलूस था। मरे हुए सन्तरियों के कटे सिर वरछियों पर टांग लिये गये थे और लोग उन्हें हाथ में लेकर आगे-आगे चल रहे थे। राष्ट्रीय महासभा के सदस्यों को भी साथ ले लिया गया था। राजा, रानी और राजकुमार वाधित होकर जुलूस के साथ-साथ जा रहे थे। भूखी, नगी जनता आनन्द के आवेश में चिल्लाती जाती थी—‘रोटीवाला, रोटीवाली और रोटीवालो का लडका’। ये लोग समझ रहे थे, कि राजा हमारे साथ है, उसके पास रोटियों का अक्षय भण्डार है, अब उन्हें रोटियों की कमी नहीं रहेगी।

राजा और राष्ट्रीय महासभा को वर्साय से पेरिस ले आया गया। यह घटना फ्रेंच राज्यक्रान्ति के इतिहास में बहुत महत्त्व रखती है। अब राज्यक्रान्ति की प्रगति पर पेरिस की जनता का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया। पेरिस के लोगो की इच्छा क्रान्ति के स्वरूप को परिवर्तित करने लगी। पेरिस के आम लोग सुसंगठित न थे। वहाँ भूखो, नङ्गो, गण्डो और बदमाशों की प्रचुरता थी। इनके अतिरिक्त गैर-जिम्मेदार, बड़-बड़कर बात बनानेवाले लोग पेरिस में बड़ी संख्या में मौजूद थे। इन सब लोगो की सम्मति—सम्मति नहीं, क्षणिक मानसिक आवेश राष्ट्रीय महासभा के निर्णयों पर असर करने लगे। फ्रांस की राज्यक्रान्ति जनता की इच्छा को सर्वोपरि करना चाहती थी। यह तो हो गया, पर जनता की इच्छा अनेक बार ऐसे विकृत रूप में प्रकट हुई, कि उसकी उपादेयता में ही

छोटा को मन्दैह होने लगा। राजा को तुड़लरी के राजप्रामाद में रखा गया। वह उन पर जनता का कडा निरीक्षण था। उसी स्थिति कंदी में बहुत अच्छी नही रह गई थी।

मनुष्यों के आधारभूत अधिकार—जिस समय ये सब घटनाएँ हो रही थी, राष्ट्रीय महामा देश के लिये नवीन शासन-प्रधान का निर्माण करने में लगी थी। उसकी एक उपसमिति आपन-विधान का माका तैयार कर रही थी। अब उमने अपना कार्य पूर्ण कर दिया। जो नया शासन प्रधान बनाया गया, उसमें सबसे पहले जनता के आधारभूत अधिकारों की उद्घोषणा की गई। उन अधिकारों में से मुख्य-मुख्य निम्नलिखित थे—

(१) सब मनुष्य स्वतन्त्र उत्पन्न होते हैं, और उनके अधिकार एक समान हैं। तामा जित भद का आनार पावजनिक उपयोगिता के बिनाय अन्य कुछ नहीं है। (२) राज की स्वामित्व शक्ति जनता में निहित है। (३) स्वतन्त्रता का अभिप्राय यह है, कि प्रत्येक मनुष्य को वह सब कुछ करने का अधिकार है, जिसमें कि किसी दूसरे को हानि पहुँचाने की सम्भावना न हो। (४) सरकार का प्रयोजन मनुष्यों के आधारभूत अधिकारों का सुरक्षित रखना है। (५) जनता की सार्वजनिक इच्छा ही कानून है। प्रत्येक नागरिक को अधिकार है, कि स्वयं या अपने प्रतिनिधि द्वारा कानून का निर्माण करने में हाथ बँटावे। (६) प्रत्येक मनुष्य के लिये कानून एक ही होना चाहिये। (७) प्रत्येक मनुष्य तब तक निरपराधी समझा जायगा, जब तक कि कानून के अनुसार बने हुए न्यायालय उसे अपराधी साबित नहीं कर देगे। कानून के प्रतिकूल किसी मनुष्य को न कैद किया जा सकता है, न अपराधी कहा जा सकता है, और न सजा दी जा सकती है। (८) किसी भी मनुष्य को अपनी सम्मतियों के कारण—चाहे वे सम्मतियाँ धार्मिक मामलों के सम्बन्ध में भी हो, सजा नहीं दी जायगी, बशर्त कि ये सम्मतियाँ सार्वजनिक व्यवस्था में बाधा डालनेवाली न हो। (९) अपने विचारों और सम्मतियों को स्वतन्त्रतापूर्वक प्रकट कर सकता मनुष्य के सबसे अधिक बहुमूल्य अधिकारों में से एक है। अतः प्रत्येक मनुष्य को यह अधिकार है कि वह स्वतन्त्रता के साथ भाषण कर सके, लिख सके और मुद्रण कर सके। परन्तु यदि वह इस स्वतन्त्रता का दुरुपयोग करेगा—दुरुपयोग किस प्रकार का होना है, यह कानून स्पष्ट करेगा—तो जिम्मेदारी उसी की होगी। (१०) प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है, कि वह स्वयं या अपने प्रतिनिधि द्वारा इस बात का निश्चय करने में हाथ बँटावे, कि सार्वजनिक कोष के लिये कितने धन की आवश्यकता है, इस धन का खर्च किस प्रकार किया जाय और इस धन को प्राप्त करने के लिये कौन-कौन से टैक्स लगाये जावे, ये टैक्स किस प्रकार से वसूल किये जावे और कितने समय के लिये कायम रहे। (११) जनता को हक है, कि प्रत्येक राजकर्मचारी से उसके कार्य का व्यौरा ले सके। (१२) सम्पत्ति पर वैयक्तिक अधिकार एक पवित्र तथा अनुलघनीय अधिकार है।

इन आधारभूत अधिकारों को जनता के सम्मुख प्रकाशित करते हुए राष्ट्रीय महासभा ने निस्सन्देह यह ठीक दावा किया था, कि सदियों से मनुष्यों के इन अधिकारों का अपमान किया जाता रहा है। अब हम फिर इन अधिकारों की स्थापना करते हैं, और हमारी यह विजयि जत्याचारियों के विरुद्ध एक शाश्वत युद्ध-घोषणा का कार्य करती रहेगी।

शासन-विधान—आधारभूत अधिकारों की यह उद्घोषणा शासन-विधान की प्रस्तावना

मात्र थी। शासन-विधान का निर्माण प्रधानतया दो सिद्धान्तों को दृष्टि में रखकर किया गया था—(१) राज्य में जनता ही है, जिसमें कि राज्य की प्रभुत्व-शक्ति निहित रहती है। (२) सरकार के शासन, कानून-निर्माण तथा न्याय—ये तीनों विभाग पृथक्-पृथक् रहने चाहिये। इन सिद्धान्तों को आधार में रखकर जो शासन-विधान बनाया गया था, उसका ढाँचा निम्नलिखित था —

राजा को इस शासन-विधान में स्थान दिया गया था, पर उसकी स्थिति को एकतन्त्र स्वेच्छाचारी राजा से परिवर्तित कर वैध तथा शासन-विधान का अङ्गभूत बना दिया गया था। अब वह केवल परमेश्वर की कृपा से ही राज्य नहीं करता था, पर उसकी सत्ता जनता की इच्छा पर भी आश्रित थी। राज्य के कानूनों के अन्दर और उनके अधीन रहना उसके लिये आवश्यक था। वह मन्त्रियों को नियुक्त और बर्खास्त कर सकता था, पर ये मन्त्री व्यवस्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायी थे। व्यवस्थापिका सभा में जो प्रस्ताव व विधान स्वीकृत होते थे, उनके प्रयोग में आने में पूर्व राजा की स्वीकृति भी आवश्यक थी। पर यदि राजा किसी प्रस्ताव व कानून को स्वीकृत न करे, और व्यवस्थापिका सभा तीन बार निरन्तर पास करती जाय, तो राजा की स्वीकृति के बिना भी वह लागू हो जाता था। इस प्रकार राजा किसी प्रस्ताव का निषेध नहीं कर सकता था, वह केवल उसे स्थगित ही कर सकता था। पर शासन का संचालन उगी के हाथ में रखा गया था, सेना का प्रधान अध्यक्ष भी उसे ही बनाया गया था। पर वह न सन्नि के अधिकार रखता था और न विग्रह के। वह जनता की इच्छा का दास था, पर जनता की इस इच्छा के निर्माण में उसका कोई हाथ न था। जनता राजा की इच्छा की सर्वथा उपेक्षा कर सकती थी, पर राजा जनता की इच्छा की किसी भी दशा में उपेक्षा नहीं कर सकता था।

कानून-निर्माण का कार्य एक व्यवस्थापिका सभा को दिया गया था। इस सभा के ७४५ सदस्य होते थे। इस सभा का निर्वाचन दो साल के लिये होता था। प्रत्येक पुरुष (स्त्री नहीं) नागरिक, जो अपनी तीन दिन की आमदनी के बराबर धनराशि राज्य को कर के रूप में दे इस सभा के निर्वाचन के लिये वोट देने का अधिकार रखता था। इस व्यवस्थापिका सभा की शक्ति बहुत विस्तृत थी। कानून-निर्माण करना इस सभा का ही कार्य था।

मध्यकाल में सामन्तपद्धति के समय में फ्रांस जिन विभागों में विभक्त था—जिनका आधार मध्यकालीन सामन्तों के छोटे-बड़े और अस्वाभाविक राज्य थे—उन्हें अब उड़ा दिया गया था, और उनके स्थान पर कुल ८३ प्रान्त बनाये गये थे। इन प्रान्तों को जिलो, ताल्लुको और परगनों में बाँटा गया था। इन विविध विभागों में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की गई थी और राज-कर्मचारियों की नियुक्ति निर्वाचन द्वारा करने का तरीका जारी किया गया था।

चर्च में परिवर्तन—राष्ट्रीय महासभा ने चर्च के सम्बन्ध में भी बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन किये। इनमें चर्च के मगठन और स्वरूप में बड़ी भारी क्रान्ति हो गई। चर्च के पुराने दशाशय को तो ८ अगस्त के दिन ही उड़ा दिया गया था और आधारभूत अधिकारों की घोषणा करते हुए धार्मिक स्वतन्त्रता के सिद्धान्त को भी स्वीकृत कर लिया गया

भा। जब राष्ट्रीय महासभा ने और आगे कदम बढ़ाया। २ नवम्बर, सन् १३८१ के अधिवेशन में चर्च की सारी जायदाद जन्म कर ली गई। जन्म की हुई चर्च की जागीरा का बेच दिया गया और उसकी कीमत को राष्ट्रीय आय में शामिल कर लिया गया। इसे पहले फ्रांस में ११७ मठ थे, अब केवल ८३ मठ रहने दिये गये। प्रत्येक प्रान्त में एक मठ रखा गया। इन मठों के पादरियों के बारे में यह तय किया गया, कि राजकर्मचारियों की तरह उनका भी निर्वाचन किया जाय। उस निर्वाचन में न केवल रोमन कैथोलिक लोग ही भाग लें, पर प्रोटेस्टेन्ट, यहूदी और नाम्निकों तक को इनके निर्वाचन में वाद देने का अधिकार दिया गया। अपने पद पर नियत किये जाने में पूर्व प्रत्येक पादरी में शपथ ली जाती थी, कि वह राष्ट्रीय शासन-विधान का भक्त बना रहेगा। नाममात्र का रोम के पोप का चर्च पर स्वामित्व स्वीकृत किया गया, पर वस्तुतः चर्च राज्य के अंग हो गया। यह सर्वथा स्वाभाविक ही था, कि पोप, बिशप तथा अन्य पुरोहित श्रेणी के लोग इन सुधारों का विरोध करें। जिस समय राष्ट्रीय शासन-विधान के प्रति भक्ति का शपथ लेने का प्रश्न उत्पन्न हुआ, तो दो निहाई पादरियों ने यह शपथ लेने में इनकार कर दिया। जिन लोगों ने शपथ लेने में इनकार किया, उन्हें सार्वजनिक शान्ति और व्यवस्था का घातक समझा गया। उन्हें अपने पदों से हटाकर दिया गया। परिणाम यह हुआ, कि उच्च पुरोहित श्रेणी के अधिकांश लोग असन्तुष्ट कुलीन जमींदारों के साथ मिल गए। ये लोग भी क्रान्ति को कुचलने के लिये भरमरुत कोशिश करने लगे। केवल ये ही तब सर्वसाधारण जनता, जो कि क्रान्ति के अन्य सब कार्यों को सहानुभूति की दृष्टि से देख रही थी, चर्च के प्रति इस व्यवहार से बहुत असन्तुष्ट हो गईं। सर्वमापारग जनता में धर्म, चर्च तथा पुरोहित श्रेणी के प्रति श्रद्धा की भावना बहुत गहरी रही है। उनके प्रति इस व्यवहार को इन सर्वसाधारण लोगों ने सहानुभूति की दृष्टि में नहीं देखा।

**पत्रमुद्रा**—राज्य के पास धन की जो कमी थी, उसे पूर्ण करने के लिये राष्ट्रीय महासभा ने पत्रमुद्रा (Assignat) प्रकाशित करने का निश्चय किया। महासभा का यह विश्वास था, कि चर्च की जागीरों से राज्य को जो आमदनी होगी, वह इस पत्रमुद्रा के लिये अमानत का काम करेगी और उसके मूल्य को गिरने न देगी। इसी आशा से बहुत बड़े परिमाण में पत्रमुद्राएँ प्रकाशित की गईं, जो कि 'आसिया' के नाम से प्रसिद्ध हैं। पर शीघ्र ही इनका मूल्य गिरना शुरू हो गया। राज्यक्रान्ति के आगामी वर्षों में इनका कोई भी कीमत नहीं रह गई थी।

## २ राजसत्ता का अन्त

**क्रान्ति की विरोधी शक्तियाँ**—राष्ट्रीय महासभा अपना कार्य समाप्त कर रही थी। फ्रांस के स्वरूप में बड़ा भारी परिवर्तन आ गया था। सामन्त-पद्धति का अन्त हो गया था, श्रेणिभेद नष्ट कर दिया गया था, चर्च के विशेषाधिकार उड़ा दिये गये थे। राजा को 'वेच्छाचारिता' को हटाकर उसकी वैध सत्ता स्थापित कर दी गई थी। फ्रांस की राज्य क्रान्ति अपना कार्य कर चुकी थी। पर पुराने जमाने की शक्तियाँ इतनी आसानी से दब जानेवाली नहीं थी। वे क्रान्ति को कुचलने के लिये चुपचाप कोशिश में लगी हुई थीं।



जो कुलीन लोग क्रान्ति के प्रारम्भ होते ही फ्रांस छोड़कर विदेशों में भाग गये थे, वे शान्त नहीं बैठे थे। वहाँ जाकर वहाँ के एकतन्त्र स्वेच्छाचारी राजाओं तथा कुलीनों की सहायता प्राप्त करना तथा अपनी शक्ति को मगठित करना उनका एकमात्र लक्ष्य था। उस जमाने में राष्ट्रीयता का तत्त्व विकसित नहीं हुआ था। फ्रांस का कुलीन जमींदार अपने देश के किसान व मजदूर से कोई भी समता व एकता अनुभव नहीं करना था। जर्मनी के कुलीन जमींदार के साथ उसे अधिक सादृश्य नजर आता था। फ्रांस के ये कुलीन लोग विदेशी राजाओं के दरबार में आश्रय पाकर बदला लेने की तैयारी में लगे हुए थे। इनकी आकांक्षा थी, कि फ्रांस की नई सरकार के विरुद्ध युद्ध उद्घोषित कर दिया जाय। इस कार्य में यूरोप के अन्य राजाओं तथा कुलीनों की सहायता का इन्हें पूरा भरोसा था। केवल फ्रांस के बाहर ही नहीं, अपितु अन्दर भी ये कुलीन लोग अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिये कोशिश में लगे हुए थे। राजा को बहुत से कुलीन लोग हर समय घेरे रहते थे। राजा अब भी पूरी तरह उनके प्रभाव में था। ये लोग वैध राजमत्ता को सहन करना तो दूर रहा, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इनकी समझ में ही नहीं आता था, कि राजा भी कानून के अधीन रह सकता है। राजा की यह नवीन कल्पना इनके विचार से कोसों दूर थी। ये लोग राजा को निरन्तर उकसाते रहते थे। फ्रांस के बाहर भागे हुए कुलीन लोग भी उसे हमेशा सन्देश भेजते रहते थे। एक पूरा पड़्यन्त्र तैयार हो रहा था। इन लोगों ने साजिश की, कि राजा अपने परिवार के साथ चुपचाप पेरिस से भाग निकले। फ्रांस की उत्तर-पूर्वी सीमा पर एक सेना तैयार कर दी गई थी, जो कि राजा के वहाँ पहुँचते ही उसका स्वागत करे। इन कुलीनों का यह ख्याल था, कि यदि राजा किसी तरह क्रान्तिकारियों के प्रभाव तथा कब्जे से निकलकर बाहर चला आये, तो यूरोप के अन्य राजाओं से सहायता प्राप्त करना और भी अधिक सुगम हो जायगा। विशेषतया, १६वें लुई की रानी मेरी आतोआत के भाई लियोपोल्ड द्वितीय से, जो कि इस समय आस्ट्रिया का सम्राट था, उन्हें बहुत आशाएँ थी। निश्चय यह किया गया था, कि राजा के फ्रांस में चले जाने पर एक शक्तिशाली सेना फ्रांस पर आक्रमण करेगी और क्रान्ति को कुचलकर पर यथापूर्व एकतन्त्र स्वेच्छाचारी राजसत्ता की स्थापना कर देगी।

**राजा का भागने का प्रयत्न**—माजिश पूर्ण रूप से तैयार हो गई। १७९१ का साल था और जून का महीना। एक रात राजा, रानी, राजकुमार और उनके दो एक साथी वेग बदल कर चुपचाप तुइलरी के राजमहल से बाहर निकले। ग्यारह बज चुके थे। पेरिस की गलियों में शान्ति थी। सब तरफ अँधियारा छाया हुआ था। अपनी जिन्दगी में शायद पहली बार राजा और रानी चुपचाप पेरिस की गलियों में पैदल चलने लगे। उनके हृदय वडक रहे थे। अपने ही राज्य में वे चोरी और खन्दग लगानेवालों की तरह डरते-डरते चले जा रहे थे। एक अँधेरे मोड़ पर एक घोड़ागाड़ी तैयार खड़ी थी। बिना कुछ बोले वे उस पर बैठ गये। गाड़ी चल पड़ी। गाड़ी में बैठे हुए राजा और रानी के दिल में क्या ख्याल जा रहे थे? वस कुछ दूर और। उस पहाड़ी के पार—सब ठीक है। वहाँ पहुँचने की देर है, मैं निक सलाम करेंगे। अफसर पैर चूमेंगे। राजभक्ति कितनी मधुर चीज है, कम से कम उस आदमी के लिये जो राजा हो, या अगर राजा न हो, तो कम से

कम दरवारी ही हो। कुछ देर बहा सूत्र बूमधाम होगी। बहुत दिनों बाद पुगने नगर देखने को मिलेगा। और उस के बाद ? उन राजभक्त फौज के साथ पेरिस की तरफ प्रस्थान होगा। थोड़ी बहुत मोशायारी हो जायगी। कुछ ठोंग फामी पर चढ़ा दिय जावेंगे, कुछ गोली में उड़ा दिये जावेंगे। बस, सब जान्त हो जायगा। फिर कैलोन प्रदान मन्ना बनेगा, सपना जुटाने में उसकी जरूरत पूरा चलती है। बाकी कुठीन ठोंग भी वापिस चर आवेंगे। बर्माय ही वे बहार वे नाचरङ्ग—बस दो चार दिन की ही ता बात है।

सुबह हो चुकी थी। राजा और रानी उनी प्रकार नुनपुर कल्पनाए करने हुए चर जा रहे थे, कि वारन नाम के नगर में कुछ पर चड़े हुए कुछ मन्त्रिया ने अकस्मात् पू लिया—“जाफे पासपोट ?” मुगद रणनाजा का सारा महल मिट्टी में मित्र गया। राजा पकड़ लिया गया। उने दरबार मन्त्रि पेरिस वापिस के जाया गया। लाना न चुप चाप बिना एक शब्द भी कह, राजा का उस प्रकार वापिस आने हुए देखा। नुइ गंगे व महल पर कड़ा पहरा बिठा दिया गया राजा पहरे तो केवल नजरबन्द था, सब बिन्दु कैंद ही हो गया।

रिपब्लिक के पक्षपातियों का अभ्युदय—राज्यशक्ति के इतिहास में इस घटना बहुत महत्व है। उसने क्रान्ति के सपने को बिल्कुल बदल दिया। अब तक फ्रांस के क्रान्तिकारी राजसत्ता का जन्म नहीं करना चाहते थे। कोई भी महत्वपूर्ण दल उस प्रकार का नहीं था, जो राजा को हटाकर रिपब्लिक की स्थापना करने को तैयार हो। पर इस घटना के बाद से लोगों की प्रवृत्ति बदलनी शुरू हुई। अनेक ठोंग साफ-साफ यह बताने लगे, कि राजा की क्या आवश्यकता है ? रिपब्लिक क्यों न कायम की जाय ? एक ऐसा दल उत्पन्न हो गया, जो कि राजसत्ता का विरोधी और रिपब्लिक का पक्षपाती था। परन्तु स्मरण रखना चाहिये, कि अब भी उस दल की शक्ति बहुत कम थी। राष्ट्रीय सभा ने राजा के भागने की बात को दबाने की कोशिश की। उसकी तरफ ने यह प्रार्थना कर दिया गया, कि राजा भागा नहीं था, अपितु कुछ लोग उने पेरिस में बाहर ले गए थे। राजा के भागने की घटना के कुछ ही दिन बाद जुलाई के महीने में ही पेरिस में एक नया की जा रही थी, जिसमें कि राजा को च्युत कर देने के लिये लिये प्रार्थना-पत्र पेश करने का विषय उपस्थित था। इस सभा को बर्खास्त होने का हुक्म दिया गया। गोली चलाई गई और बहुत से आदमी गोली खाकर गिर गये। यह घटना १३ जुलाई, १७९१ को हुई थी, और इतिहास में यह ‘शा द मार’ के हत्याकाण्ड के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि राजा को च्युत कर रिपब्लिक स्थापित करने के पक्षपाती ‘शा द मार’ (पेरिस का एक स्थान) में एकत्र होकर अपनी सभा कर रहे थे। लोगों पर गोली चलाने का हुक्म पेरिस के मेयर बर्न के आदेश पर दिया गया था। अभी तक भी फ्रांस की जनता में रिपब्लिक का भाव प्रबल नहीं हुआ था। लोग राजसत्ता को ही कायम रखना चाहते थे। पर इसमें भी सन्देह नहीं कि ऐसा दल निरन्तर शक्ति प्राप्त करता जा रहा था, जो राजसत्ता को नष्ट कर देने के पक्ष में था। इस दल के प्रबल होने का मुख्य श्रेय राजा, उसके दरबारी तथा बाहर भाग हुए कुलीन लोगों के कारनामों को ही प्राप्त है। इनके कृत्यों के कारण ही जनता का सहानुभूति रिपब्लिक के पक्षपातियों की तरफ बढ़ती गई। राजसत्ता को कायम रखने-

वालो का पक्ष निर्वल होता गया ।

रिपब्लिक दल के नेता—इस नये रिपब्लिकन दल के नेता कौन थे ? राजसत्ता के विरोधी दल का सर्वप्रधान नेता डा० मरत था । डा० मरत बहुत ही विद्वान् व्यक्ति था । इङ्गलिश, स्पेनिश, जर्मन और इटालियन भाषाओं का उसे अच्छा ज्ञान था । उसने अनेक वर्ष इङ्गलैण्ड में व्यतीत किये थे । इङ्गलैण्ड के एक शिक्षणालय ने उसके सम्मान के लिये उसे एम० डी० की उपाधि प्रदान की थी । उसने वैज्ञानिक विषयों पर अनेक ग्रन्थ लिखे थे । विशेषतया, चिकित्साशास्त्र का वह बड़ा पण्डित था । वैजमिन फ्रैकलिन तथा गैटे जैसे विद्वान् उसके भातिकशास्त्र-विषयक ग्रन्थ को बड़े शौक से पढ़ते थे । डा० मरत ने अपने साहित्यिक और वैज्ञानिक जीवन का परित्याग कर राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश किया था । इन दिनों में वह “लोक-मित्र” नाम के एक समाचार-पत्र का संचालन कर रहा था । इस समाचार-पत्र द्वारा वह कुलीनों तथा उच्च-मध्य श्रेणी के लोगों पर भयंकर रूप से आक्षेप कर रहा था और साधारण जनता का शासन स्थापित करने के लिये जोर दे रहा था ।

रिपब्लिक दल का दूसरा नेता कैमिल देसमोला था । यह भी एक समाचार-पत्र का सम्पादक था । इसी देसमोला ने पेरिस की जनता को विदेशी सैनिकों से अपनी रक्षा करने के लिये तैयार होने को भड़काया था, जिसके कारण लोग हथियारों की खोज में निकल पड़े थे और वस्तीय के बस की घटना हुई थी । इस दल का एक अन्य नेता दातो (Danton) था, जो अपने जोशीले व्याख्यानो के कारण प्रसिद्ध था । वह वकाशत का पेशा करता था और पेरिस की जनता में बहुत लोकप्रिय था । ये तथा अन्य बहुत से नेता इस समय राजसत्ता के विरुद्ध आवाज उठा रहे थे । इनकी राय में राजसत्ता अब इतनी विकृत हो चुकी थी, कि उसके साथ किसी भी प्रकार का समझौता सम्भव न था । ये पूर्ण लोकतन्त्र रिपब्लिक के पक्षपाती थे ।

बंध राजसत्ता का पक्षपाती दल और उसके नेता—बंध राजसत्ता के पक्षपातियों के प्रधान नेता लफायत तथा मिरावो थे । लफायत स्वयं कुलीन श्रेणी का था, पर उसमें क्रान्ति और स्वतन्त्रता की भावनाएँ विद्यमान थीं । अमेरिकन स्वाधीनता के युद्ध में वह स्वयंसेवक के रूप में सम्मिलित हुआ था । फ्रांस की राज्यक्रान्ति में उसका शुरू से ही प्रधान भाग था । राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेना का संगठन उसी द्वारा हुआ था । मिरावो भी कुलीन श्रेणी का था । राज्यक्रान्ति का वास्तविक नेता वही था । एस्टेट्स जनरल के तीनों विभागों की एक बैठक एक साथ होनी चाहिये और प्रत्येक विभाग का एक वोट न होकर सदस्यों के बहुमत में निर्णय किया जाना चाहिये—इस आन्दोलन का प्रधान नेतृत्व मिरावो ने ही किया था । जिस समय राजा ने तीनों विभागों को पृथक्-पृथक् बैठक करने का आदेश दिया, तब मिरावो ही था, जिसने कि निर्भय होकर इसका विरोध किया था । मिरावो बहुत ऊँच किस्म का राजनीतिज्ञ था । वह बहुत दूरदर्शी तथा साफ दिमाग का आदमी था । राष्ट्रीय महासभा का सारा कार्य उसी के नेतृत्व में हुआ था । फ्रांस के लिये जो नया शासन-विधान बना था, वह बहुत अशो में उसी की कृति थी । राजा तथा रानी पर भी उसका बहुत प्रभाव था । वे उसे बहुत मानते थे । खद यही है, कि मिरावो देर तक न

जी सका। राजा के फ़ास भागने के लिये प्रयत्न करने में पूर्व ही २ अप्रैल, १७९१ के दिन उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु वंश राजसत्ता के पक्षपातियों के लिये एक भारा क्षति थी। यदि वह जीवित रहता, तो शायद राजा को अनेक भयकर भूलों में बचाने रखने में समर्थ होता। पर उसकी मृत्यु ने राजसत्ता को बहुत कमजोर कर दिया था।

**व्यवस्थापिका सभा**—राष्ट्रीय महासभा ने ३० सितम्बर, १७९१ को अपना काम समाप्त कर दिया। इसने कुल मिलाकर २५०० कानून पास किये। इसमें मन्वेह नह्रा, कि राष्ट्रीय महासभा ने बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया था। इसके नवीन विधान ने फ़ास के स्वरूप को सर्वथा परिवर्तित कर दिया था। फ़ास का नवीन शासन-विधान अब तैयार हो चुका था। अब उसके अनुसार कार्य प्रारम्भ हुआ। नये शासन-विधान में मुख्य शक्ति व्यवस्थापिका सभा को दी गई थी। इसका निर्वाचन हो गया था और अब इसकी प्रथम बैठक १ अगस्त, १७९१ के दिन शुरू हुई। व्यवस्थापिका सभा के कुल सदस्यों की संख्या ७४५ थी। इनमें प्रधानतया दो दल थे। (१) वंश राजसत्तावादी—इसकी संख्या बहुत अधिक थी। बहुमत इन्हीं का था। उनका विचार था, कि राज्यक्रान्ति का कार्य अब समाप्त हो चुका है। राजा की एतन्त्र स्येच्छाचारी सत्ता का अन्त हो गया है, और उसके स्थान पर जनता का अधिकार हो गया है। यह पर्याप्त है। अब फ़ास का भला इसी में है, कि १७९१ के शासन-विधान के अनुसार कार्य हो और नवीन युग के मुख का उपनाम किया जाय। (२) रिपब्लिक के पक्षपाती—इनकी संख्या २८० थी। इस प्रकार व्यवस्थापिका सभा में ये अल्प संख्या में थे। उनका व्यास था, कि राज्यक्रान्ति अभी पूर्ण नहीं हुई है, अभी कुछ और आगे बढ़ने की जरूरत है, राजसत्ता का सर्वथा अन्त किया जाना चाहिये। राजसत्ता को उड़ा कर रिपब्लिक की स्थापना इनका प्रधान लक्ष्य था।

**जेकोबिन क्लब**—यह रिपब्लिकन दल दो भागों में विभक्त था, जेकोबिन और जिरोदिस्ट। इन दोनों विभागों में क्या भेद था और इनके मृत्यु विचार क्या थे—इस बात पर प्रकाश डालने की आवश्यकता है। जिस समय राजा को वर्साय से पेरिस लाया गया, तब राष्ट्रीय-महासभा भी पेरिस ही चली आई थी। इसके अधिवेशन पेरिस में हो रहे लगे थे। इस राष्ट्रीय महासभा के कुछ सदस्यों ने—जिनके विचार आपस में मिल जुलते थे, महासभा के मकान के नजदीक ही एक बड़ा मकान किराये पर लिया था। ये सदस्य इस मकान में अपनी सभा किया करते थे। और आपस में विचार करने के अन्तर यह निश्चय करते थे, कि राष्ट्रीय महासभा में उन्हें किस नीति का अनुसरण करना चाहिये। शुरू-शुरू में इन सदस्यों की संख्या एक सौ थी, पर धीरे-धीरे और सदस्य इन सभा में शामिल होने लगे और इसे बहुत महत्व प्राप्त हो गया। किसी वक्त में यह मकान जेकाब का गिरजा था, अतः इस मकान में विद्यमान इस क्लब को जेकोबिन क्लब कहा जाने लगा। धीरे-धीरे यह क्लब अधिक-अधिक महत्व पकड़ता गया। पहले इसकी बैठक गुप्त होती थी, जनता उनमें शामिल नहीं हो सकती थी। पर अक्टूबर सन् १७९१ में जनता को भी यह अवसर दिया गया, कि वह क्लब की बहस में शामिल हो सके। परिणाम यह हुआ, कि लोगों की दिलचस्पी इस क्लब में बहुत बढ़ गई। यह क्लब पेरिस के राजनीतिज्ञों का अखाड़ा बन गया। इसमें खूब गरमागरम बहस होने लगी। जो लोग

सबसे आगे बढ़े होते थे, कोई नया परिवर्तन प्रस्तावित करते थे, वे इस क्लब में ऊँचा स्थान प्राप्त करते थे। डा० मरत, दातो और देसमोला इसके प्रमुख सदस्य थे। जब अभी बंध राजसत्ता के विरुद्ध भावना नहीं उत्पन्न हुई थी, तब भी इस क्लब में रिपब्लिक की गूज सुनाई दे जाती थी। पर जब बंध राजसत्ता का पक्ष कमजोर पड़ने लगा, तब तो यह क्लब बहुत ही आगे बढ़ गया। पुराने जमाने का सर्वनाश कर ससार का नये सिरे से निर्माण करना इसका आदर्श बन गया। पेरिस के अतिरिक्त अन्य नगरों में भी इस क्लब की शाखाएँ खुली हुई थी। जून, १७९१ में इसकी शाखाओं की संख्या ४०६ तक पहुँच गई थी। व्यवस्थापिका सभा के निर्वाचन में जेकोविन क्लब तथा उसकी शाखाओं ने बड़ा हिस्सा लिया। इनके प्रयत्नों का ही परिणाम था, कि २०० के लगभग प्रतिनिधि इस दल के निर्वाचित हो गये।

**जिरोदिस्ट दल**—जिरोद एक प्रदेश का नाम है, जो कि फ्रांस के दक्षिण-पूर्वी भाग में स्थित है। इस के प्रधान नगर का नाम है, बोर्दियो। यहाँ से जो प्रतिनिधि व्यवस्थापिका सभा में निर्वाचित हुए थे, वे भी राजसत्ता का अन्त कर रिपब्लिक की स्थापना करना चाहते थे। इनके प्रधान नेता का नाम वर्जैनियो था। यह एक होशियार वकील था और इसके बहुत से साथी भी वकालत का पेशा करने वाले थे। ये लोग भी पेरिस में परस्पर मिलते रहते थे और इन्होंने भी अपनी क्लब बना रखी थी। जिरोद के अतिरिक्त फ्रांस के देहातों के अनेक अन्य प्रतिनिधि भी इस क्लब में शामिल हुआ करते थे। रिपब्लिक के पक्षपाती होते हुए भी ये लोग बहुत गरम नहीं थे। ये जेकोविन दल की जल्दबाजी तथा गरम मनोवृत्ति को नापसन्द करते थे, और राजसत्ता को नष्ट करने के तरीकों के सम्बन्ध में भी मतभेद रखते थे। जेकोविन क्लब पेरिस की मनोवृत्ति का प्रतिनिधि था और जिरोदिस्ट दल देहातों का।

**व्यवस्थापिका सभा के सम्मुख विद्यमान समस्याएँ**—व्यवस्थापिका सभा ने अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया। उसका कार्य सुगम न था। फ्रांस के विशद आकाश में विपत्ति के उरावने बादल मँडरा रहे थे। भागे हुए कुलीन लोग अपना कार्य जोर शोर से कर रहे थे। फ्रांस के अन्दर भी समस्याएँ कम न थी। पादरी लोगों की बहुसंख्या चर्च की नई व्यवस्था को मानने के लिये तैयार नहीं थी। वे लोग अपने सम्पूर्ण प्रभाव को—और उस समय में फ्रांसीसी लोगों पर बर्ष का आतंक कम नहीं था, क्रान्ति के विरुद्ध प्रयुक्त कर रहे थे। राजा और उसके दरबारी चुपचाप गुप्त तरीके से विदेशी राजाओं से पत्र-व्यवहार करने में लगे थे। इस विकट परिस्थिति का व्यवस्थापिका सभा को सामना करना था। फ्रांस में राज्यक्रान्ति का समाचार सुनते ही यूरोप के अन्य राजाओं को खतरा अनुभव होने लगा था। उन्हें भय था, कि कहीं उनकी प्रजा भी फ्रांस का अनुकरण न करे। इसलिये वे अपना भला इसी में समझते थे, कि फ्रांस में क्रान्ति को कुचल दिया जाय। क्रान्ति भी छून का रोग है, जिसे फैलते हुए देर नहीं लगनी। जब आस्ट्रियन सम्राट् लिओपोल्ड द्वितीय ने सुना, कि फ्रांस का राजा १६वां लुई अपनी रानी सहित वारेन नगर में पकड़ लिया गया है, तो उसके क्रोध की कोई सीमा न रही। उसने कहा कि सम्पूर्ण राजाओं का सम्मान और सारी सरकारों की सुरक्षितता अब खतरे में पड़ गई है। उसने यूरोप के अन्य राजाओं

से अपील की, कि इस क्रान्ति की भावना को समूल नष्ट कर देना जीर फ्रांस के राजन पवित्र वर्मप्राण राजा और उसके परिवार को क्रान्तिकारियों के चंगुल में बचाकर फिर अपनी पूर्व स्थिति में स्थापित कर देना सब राजाओं का परम कर्तव्य है। इसी अपील का परिणाम हुआ, कि २७ अगस्त के दिन पिलनिटप की प्रसिद्ध उद्घोषणा प्रकाशित की गई। यह उद्घोषणा आस्ट्रियन सम्राट् लिओपोल्ड द्वितीय तथा प्रशिया के राजा द्वारा प्रकाशित की गई थी।

**पिलनिटप की उद्घोषणा**—उसमें कहा गया था, कि फ्रांस के राजा के अनुयायियों (भागे हुए कुलीन लोगों) की इच्छानुसार वे इस बात के लिये तैयार हैं, कि यूरोप के अन्य राजाओं के साथ मिलकर १७वे लुई को अपनी पूर्व स्थिति में स्थापित करें। फ्रांस में एक ऐसा शासन कायम होना चाहिये, जो कि राजाओं के पवित्र अधिकारों के अनुसार हो। उन्होंने केवल उद्घोषणा ही नहीं की, अपितु उसके अनुसार तैयारी भी प्रारम्भ कर दी। सेनाएँ संगठित की जाने लगीं और क्रान्ति की विरोधी मेनाप फ्रांस की तरफ बढ़ने लगीं।

**इस उद्घोषणा का परिणाम**—पिलनिटप की इस उद्घोषणा ने फ्रेंच लोगों में बराबर सनसनी फैल गई। वे लोग इस बात को महन न कर सके, कि फ्रांस के आन्तरिक मामलों में विदेशी लोग इस तरह हस्तक्षेप करें। यूरोप के दो शक्तिशाली राजा फ्रांस में क्रान्ति की भावनाओं को कुचलने तथा फिर से पुराने जमाने को स्थापित करने के लिये हमला करने को तैयार हैं, तथा अन्य राजाओं से सहयोग के लिये अपील कर रहे हैं, यह बात जनता नही सही गई। फ्रांस के भागे हुए कुलीन लोग अपनी माजिशों में इस प्रकार मरुल हो उठे हैं, यह जानकर जनता के रोष की कोई सीमा न रही। इसी बीच में १७वे लुई के नाई आर्तोआ के काउन्ट ने, जो कि स्वयं फ्रांस से भागा हुआ था, उद्घोषित किया कि, फ्रांस का असली राजा १६वा लुई जनता द्वारा कैद कर लिया गया है, अतः मैं स्वातन्त्र राजा के तौर पर कार्य करूँगा। क्रान्ति के विरुद्ध प्रवृत्तियाँ बस्तुन चाहे बहुत बलवती न हों, पर इन समाचारों से लोग सावधान हो गये। समाचार-पत्रों में जोश से भरे हुए भडकीले लेख निकलने लगे। १७८९ के बाद फ्रांस में वाक्यायदा असवार निकलने लगे थे। जेकोबिन क्रांतिकारी अखबार इन समाचारों से पूरा फायदा उठाकर लोगों को राजसत्ता के विरुद्ध भडका रहे थे। जेकोबिन क्लब में इसकी बड़ी चर्चा रहती थी। महीनो तक यही हालत रही। जनता में भयकर उत्तेजना फैली हुई थी। लोग स्वतन्त्रता की लाल टोपियाँ पहनने में शान समझते थे। मजदूरों के से लम्बे पाजामे पहनने का लोगों को शौक हो गया था। समझा जाता था, कि यह स्वतन्त्रता और भ्रातृभाव की निशानी है।

**आस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की उद्घोषणा**—यह परिस्थिति थी, जब कि २० एप्रिल, १७९२ के दिन व्यवस्थापिका सभा में आस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध उद्घोषित कर देने का प्रस्ताव उपस्थित किया गया। सदस्यों में युद्ध के लिये बड़ा उत्साह था। केवल सात आदमी थे, जिन्होंने युद्ध के खिलाफ वोट दिया। जिन लोगों ने युद्ध के खिलाफ आवाज उठाई थी, उसमें रोवस्पियर प्रमुख था। रोवस्पियर कट्टर रिपब्लिकन था, वह जेकोबिन क्लब का प्रमुख सदस्य था, पर इस युद्ध के विषय में उसका खयाल था, कि इससे गरीबों का सरासर नुकसान होगा। इससे फायदा पहुँचेगा, तो केवल अमीर लोगों को। जो लोग

क्रान्ति के पक्ष में थे, उन्हें कहा गया कि यह युद्ध आत्मरक्षा के लिये है, विजय करने के लिये नहीं। यह युद्ध अत्याचारी एकतन्त्र राजाओं के खिलाफ है, जनता के खिलाफ नहीं। यह युद्ध एक स्वतन्त्र राष्ट्र के अधिकारों की रक्षा के लिये है। निस्सन्देह, यह युद्ध फ्रांस के नये युग और यूरोप के पुराने जमाने के बीच में था। इसमें स्वतन्त्रता, समानता और भ्रातृभाव की प्रवृत्तियाँ स्वेच्छाचारी शासन, विशेषाधिकार और अन्याययुक्त विपमता के साथ संघर्ष कर रही थी। इसी युद्ध का यह परिणाम हुआ, कि फ्रांस के क्रान्तिकारी विचार यूरोप के अन्य देशों में भी फैल गये। क्रान्ति केवल फ्रांस तक ही सीमित नहीं रही। वह यूरोप भर में विस्तीर्ण हो गई।

राजा व्यवस्थापिका सभा के इस निश्चय को स्वीकृत करने के लिये तैयार न था, पर उसे बाधित होकर इस पर हस्ताक्षर करने पड़े। परन्तु फ्रांस की सेना युद्ध के लिये सुसज्जित न थी। सेना के सब अफसर पहले कुलीन लोग हुआ करते थे, और उन्हें ही सैन्य-संचालन का अनुभव था। पर प्रायः सभी कुलीन सैनिक अफसर इस समय फ्रांस छोड़कर विदेशों में भाग चुके थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेना आन्तरिक अव्यवस्था को दवाने में तो काम आ सकती थी, पर विदेशों की अनुभवी तथा सुसज्जित सेनाओं का मुकाबला करने का सामर्थ्य उसमें नहीं था। यही कारण है, कि जब आस्ट्रिया की सेना का मुकाबला करने के लिये पहले पहल फ्रेंच सेना भेजी गई, तब वह उसका सामना नहीं कर सकी।

व्यवस्थापिका सभा के प्रस्ताव और राजा द्वारा उन्हें वीटो किया जाना—जिस समय में फ्रांस की सेनाएँ विदेशी शत्रुओं का मुकाबला करने के लिये सीमा की तरफ प्रस्थान कर रही थी, उसी समय व्यवस्थापिका सभा देश में व्यवस्था कायम रखने तथा युद्ध के लिये साधन जुटाने की फिकर में लगी थी। इसीलिये उसने यह कानून पास किया, कि जो पादरी लोग चर्च की नई व्यवस्था मानने को तैयार न हों, वे एक महीने के अन्दर-अन्दर फ्रांस छोड़कर चले जावें। जब यह कानून राजा के पास स्वीकृति के लिये भेजा गया, तो उसने इन पर अपनी सहमति देने से इनकार कर दिया। इसी प्रकार व्यवस्थापिका सभा में एक प्रस्ताव पास किया गया, कि राजधानी की रक्षा करने के लिये बीस हजार स्वयंसेवकों की एक छावनी पेरिस के समीप ही डाली जावे। राजा ने इस प्रस्ताव को भी वीटो कर दिया।

राजप्रासद पर आक्रमण—राजा की इस कार्रवाई का यह परिणाम हुआ, कि उसके विरुद्ध भावनाएँ और भी अधिक प्रचल हो गईं। लोगों में राजा और रानी की बहुत बदनामी होने लगी। रानी को घृणा के साथ 'आस्ट्रियन औरत' और 'श्रीमती वीटो' कहा जाने लगा। लोगों का खयाल था, कि रानी फ्रांस के दुश्मनों से मिली हुई है, और उसने फ्रांस पर आक्रमण करने की एक योजना तैयार करके आस्ट्रिया के पास भेजी है। इन अफवाहों को सुनकर जनता के जोश की कोई सीमा नहीं रही। लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई, जुलूस तैयार हो गया। पेरिस की गलियों में चक्कर लगाकर इस जुलूस ने तुइलरी के राजप्रासाद की तरफ प्रस्थान किया। अनेक 'देशभक्त' राजप्रासाद में घुस गये। ईंट और पत्थर फेंके जाने लगे। भीड़ कावू से बाहर हो गई। ऐसे समय में राजा ने बड़ी बुद्धिमत्ता प्रदर्शित की। उसने क्रान्तिकारियों की लाल टोपी सिर पर पहन कर तथा

छोटे में निरोगे शत्रु को छाती पर लगाकर एक झरोखे में जनता को दर्शन दिया। राजा का उस प्रकार क्रांति के चिह्नों में युक्त देवमूर्त लोगों का जोश कुछ ठण्डा पड़ गया। राज-प्रामाद के उस जायमण का कोई विशेष अमर नहीं हुआ।

त्रुन्स्विक के ड्यूक की उद्घोषणा—पर जिस समय उस घटना का समाचार गुप्त के अन्य राजाओं ने गुना, तो उन्हें उस बात में जरा भी मन्देह नहीं रहा, कि फ्रांस के क्रांतिकारी अराजकता चाहते हैं। प्रशिया के राजा फ्रेडरिक ने उद्घोषित किया, कि वह भी फ्रांस के विन्दु लड़ाई में जाम्ब्रिया का साथ देगा। प्रशिया की मंत्री हुई और गति शाली मेना ने त्रुन्स्विक के ड्यूक के सेनापतिन्त्र में फ्रांस की तरफ प्रस्थान किया। फ्रांस की सीमा पर पहुँचकर त्रुन्स्विक के ड्यूक ने एक उद्घोषणा प्रकाशित की। उसमें कहा गया, कि जाम्ब्रिया और प्रशिया फ्रांस पर उनकी हमला कर रहे हैं, नाकि वह अराजकता का अन्त कर फिर से राजा के न्याय्य अधिकारों की स्थापना की जाय। फ्रांस के जो कोई आदमी जाम्ब्रिया और प्रशिया की सेनाओं का सामना करने का प्रयत्न करे, उन्हें युद्ध के कठोरतम नियमों द्वारा भयकर से भयकर सजा दी जायगी और उनके वस्त्रों को अग्नि में भस्म कर दिया जायगा। यदि पेरिस के लोग ने राजा व रानी का तगन अपमान किया और फिर तुडलरी के राजप्रामाद पर हमला किया, तो नारे पेरिस का को पूर्णतया तबाह कर दिया जायगा।

इस उद्घोषणा का परिणाम—उस उद्घोषणा ने लोगों में उत्तेजना और भी और बढ़ गई। यह विश्वास दृढ़ हो गया, कि राजा और रानी फ्रांस के दुश्मनों ने हार्दिक से नुभूति रखते हैं। रिपब्लिक के पक्षपातियों ने राजसत्ता का अन्त करने का निश्चय लिया। पेरिस की एक भीड़ ने फिर तुडलरी के राजप्रामाद पर हमला किया। यह हमला १० अगस्त, १७९२ को हुआ था। राजा, रानी और राजकुमार बड़ी कठिनाई में जवाबदार निकल सके। उन्होंने व्यवस्थापिका सभा के भवन में आश्रय लिया। तब दाताओं की गैलरी में उन्हें स्थान दिया गया। आज राजा को अपनी रक्षा के लिये व्यवस्थापिका सभा का आश्रय लेने के अतिरिक्त अन्य कोई चारा न था।

राजा की पदच्युति—अगले ही दिन व्यवस्थापिका सभा में प्रस्ताव पेश किया गया कि राजा को पदच्युत कर फ्रांस में रिपब्लिक की स्थापना की जाय। यह प्रस्ताव पारित हुआ। १६वां लुई अब फ्रांस का राजा नहीं रहा। परन्तु अब देश का शासन किस प्रकार हो? अब तक जो शासन-विधान विद्यमान था, वह वैध राजसत्ता के सिद्धान्त पर आधारित था। अतः निश्चय किया गया, कि नया शासन विधान तैयार करने के लिये एक कान्वेंशन सगठित किया जाय। कान्वेंशन के लिये व्यवस्था कर व्यवस्थापिका सभा की नर्मा कर दी गई। देश का शासन करने के लिये सामयिक रूप से जिस सरकार का निर्माण किया गया, उसका मुखिया दातो बना।



## छठा अध्याय

# क्रान्तिकारी फ्रांस का यूरोप के साथ संघर्ष

## १ क्रांति के विरुद्ध जिहाद

पेरिस की नागरिक सभा—सोलहवें लुई के शासन-च्युत किये जाने के अनंतर फ्रांस का शासन करने के लिये कोई व्यवस्थित सरकार विद्यमान नहीं रही थी। नये शासन-विधान का स्वरूप तैयार करने के लिये जो कान्फेन्शन बुलाया गया था, उसने अभी अपना कार्य प्रारम्भ ही किया था। इसमें सन्देह नहीं, कि एक सामयिक सरकार का सगठन कर लिया गया था, जिसका मुखिया दातो था, परन्तु इस समय शासन की वास्तविक शक्ति पेरिस की नागरिक सभा के हाथ में आ गई थी। यह नागरिक सभा बहुत व्यवस्थित तथा सगठित थी और स्वाभाविक रूप से क्रान्तिकारियों पर इसका प्रभाव बहुत अधिक था। पेरिस का शासन इसके हाथ में ही था, और क्योंकि राज्यक्रान्ति का नेतृत्व पेरिस द्वारा हो रहा था, अतः पेरिस की नागरिक सभा ही सम्पूर्ण देश में राज्यक्रान्ति का संचालन कर रही थी।

कान्फेन्शन का अधिवेशन—२१ सितम्बर, सन १७९२ के दिन कान्फेन्शन का अधिवेशन प्रारम्भ हुआ। इसके कुल सदस्यों की संख्या ७८२ थी। कान्फेन्शन में अधिक संख्या उन लोगों की थी, जो राजसत्ता के विरोधी और रिपब्लिक के पक्षपाती थे। इसमें ज़िरोदिस्ट दल के सदस्य सबसे अधिक थे। इस दल का विचार था, कि क्रान्ति का संचालन कानून और व्यवस्था के अनुसार ही किया जाना चाहिए। यह दल खून-खराबी के खिलाफ था, और शान्तिपूर्वक राज्य-परिवर्तन चाहता था। पर ज़िरोदिस्ट दल के शक्तिशाली होते हुए भी उसमें कोई प्रभावशाली नेता नहीं था। इस के विपरीत जेकोविन दल में दातो, मरत और रोवस्पियर जैसे योग्य व प्रभावशाली नेता थे। इन के कारण इस दल का प्रभाव बहुत बड़ा हुआ था। जेकोविन दल क्रांति के संचालन में व्यवस्था और कानून का आखिरी मोर्चा कर अनुसरण करने के पक्ष में नहीं था। मौके के अनुसार सब प्रकार के उपायों में सफलता प्राप्त करना ही उसका मूलमन्त्र था। कान्फेन्शन में पहले ज़िरोदिस्ट दल का प्राधान्य था, परन्तु कुछ समय बाद ही जेकोविन दल प्रबल हो गया और सम्पूर्ण शक्ति उसके प्रभावशाली नेताओं के हाथ में चली गई।

अपनी पहली ही बैठक में कान्फेन्शन ने यह प्रस्ताव पास किया, कि फ्रांस से राजसत्ता का अन्त करके रिपब्लिक की स्थापना की जाय। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ था। तीन साल पहले फ्रांस में एकतन्त्र स्वेच्छाचारी राजसत्ता विद्यमान थी, परन्तु अब इतने थोड़े में समय में ही वहाँ एक क्रान्तिकारी रिपब्लिक की स्थापना कर दी गई थी। फ्रांस

की जनता ने रिपब्लिक की उद्घोषणा का बड़े उत्साह में स्वागत किया। लोगो का था, कि अब एक नवीन युग का प्रारम्भ हो रहा है। स्वेच्छाचारिता का जमाना हो गया है, और उसके स्थान पर स्वतन्त्रता का युग शुरू हुआ है। १७९२ के फि मास के २२वें दिन मेण्ट्र नवीन सवत् का प्रारम्भ किया गया।

नवीन सवत्—यह फ्रेंच स्वतन्त्रता के सवत् का प्रथम वर्ष था। कान्तेन्यन के उपममिति पचाह्न का गुधार करने के लिये बनाई गई। उसने प्रस्ताव किया, कि मास में ३० दिन रखे जावें और प्रत्येक मास को दस-दस दिन के तीन 'दशाह' में किया जाय। साल में ३६५ दिन होते हैं, तीस-तीस दिन के १२ महीने होने में ५ दिन शेष रह जावेंगे। ये ५ दिन छुट्टी मनाने के लिये रखे जावें। दिना के नाम और पुराने सत्तों के नामों पर रखने के बजाय पालतू पशुओं, वनस्पतियों और के उपकरणों के नामों पर रखने का प्रस्ताव किया गया। यह कान्ति की भावना को सब क्षेत्रों में अपने को प्रकट कर रही थी।

क्रान्ति के विरुद्ध जिहाद—उधर जिस समय कान्तेन्यन देश के लिये नवीन विधान तैयार करने के कार्य में लगा था, उधर यूरोप के विविध राजा कान्ति के जिहाद कर रहे थे। जगस्त के समाप्त होने में पूर्व ही प्रशियन सेना फ्रान्स में प्रवेश कर थी। २ सितम्बर को वर्दून का किला जीत लिया गया था। ऐसा प्रतीत होता था शीघ्र ही पेरिस को घेर लिया जायगा। ऐसे विकट समय में फ्रेंच सेनापति डूमरे ने नामक स्थान पर प्रशियन सेना से मोरचा लिया। यहाँ पर फ्रान्स की सेना को बहुत नफ मिली। प्रशियन सेना का आक्रमण रुक गया, और सेनापति डूमरे इन आक्रान्ताओं को से बाहर खदेड़ने में समर्थ हुआ। इतना ही नहीं, फ्रेंच सेनाओं ने जर्मनी के प्रदेश पर आक्रमण किया और रूहाइन नदी के प्रदेश के अनेक दुर्गों को जीतकर अपने अधीन लिया। डूमरे के सैनिक नगे पैर थे, उनके पास सैनिक बर्दिया और शानदार हथियार नहीं थे। वे नये भर्ती किये हुए रेंगस्ट थे, पर उनमें क्रान्ति की भावना थी। वे उद्देश्य से—किसी भावना से युद्ध कर रहे थे। लड़ना उनका पेशा नहीं था। इन तीनों ने नीदरलैण्ड पर आक्रमण किया। यह प्रदेश उस समय में आस्ट्रिया के अधीन था। आस्ट्रिया की सेनाएँ परास्त हो गई, और नीदरलैण्ड पर फ्रांस का कब्जा हो गया। यह सचालन और समरनीति की विजय नहीं थी, यह क्रान्ति की भावना की विजय थी।

२, ३ सितम्बर के वीभत्स हत्याकाण्ड—इन युद्धों के प्रारम्भ होने के समय में की क्रान्तिकारी सरकार ने बहुत से लोगों को सन्देह में गिरफ्तार कर लिया था। सन्देह नहीं, कि उस समय फ्रांस में ऐसे लोगों की कमी नहीं थी, जो क्रान्ति के विरोधी और अपनी सम्पूर्ण शक्ति क्रान्ति को कुचलने के लिये लगा रहे थे। क्रान्तिकारियों बहुत से आदमियों को इसी सन्देह में कैद किया था। इनकी संख्या तीन हजार के लगभग थी। युद्ध के शुरू होने पर २ और ३ सितम्बर को इन सब कैदियों को कत्ल कर दिया गया इसके लिये जो कारण पेश किया गया, वह यह था कि हम लोग बेफिकर होकर शत्रु का मुकाबला करने के लिये कैसे प्रस्थान कर सकते हैं, जब कि तीन हजार शत्रु हम अपनी जेलों में बन्द हैं, और जो किसी भी क्षण जेल तोड़कर बाहर निकल सकते हैं।

हमारी स्त्रियो तथा बच्चो का सहार कर सकते हैं। निस्सन्देह, यह एक बड़ा ही वीभत्स और क्रूर कत्ल था। एक साथ तीन हजार आदमियो का कत्ल—वह भी केवल सन्देह के कारण और न्याय का उपहास करके—कितनी वीभत्स घटना है। स्वतन्त्रता और न्याय के नाम पर पुरानी राजसत्ता का अन्त किया गया था। परन्तु नये युग का यह श्री-गणेश कितना अन्यायपूर्ण, अत्याचारमय और वीभत्स था। रिपब्लिक और क्रान्ति की रक्षा के नाम पर, स्वतन्त्रता, समानता और भ्रातृभाव की स्थापना के लिये इन तीन हजार आदमियो की बलि दी गई थी।

कान्वेन्शन की क्रान्तिकारी उद्घोषणा—फ्रांस ने आक्रान्ताओ को परास्त कर जर्मनी और आस्ट्रिया के अनेक प्रदेशो पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। अब कान्वेन्शन ने निश्चय किया, कि सम्पूर्ण यूरोप में क्रान्ति की भावनाओ का प्रसार किया जाय। फ्रांस के क्रान्तिकारी नेता इस बात को खूब अच्छी तरह समझते थे, कि उनके देश में क्रान्ति तब तक सफल नहीं हो सकती, जब तक कि उनके अपने चारो ओर सम्पूर्ण यूरोप में एकतन्त्र स्वेच्छाचारी सरकार कायम है। अतः वे सर्वत्र क्रान्ति का प्रसार करने के लिये उत्सुक थे। कान्वेन्शन ने १५ सितम्बर, १७९२ के दिन उन प्रदेशो की जनता के नाम, जिन पर कि फ्रांस ने कब्जा कर लिया था, एक उद्घोषणा प्रकाशित की। इसमें कहा गया था कि “हमने तुम्हारे अत्याचारी शासको को खदेड़ दिया है। तुम अपने को स्वतन्त्र मनुष्य प्रदर्शित करो और हम तुम्हारी उन अत्याचारियो के प्रतिशोध से रक्षा करेंगे।” इस उद्घोषणा में यह भी कहा गया था, कि फ्रांस का उद्देश्य सर्वत्र समानता और स्वाधीनता की स्थापना करना है। जो लोग इसका विरोध करेंगे, उन्हें अपना शत्रु समझा जायगा और उनके साथ शत्रु के समान ही व्यवहार किया जायगा।

राजा को प्राणदण्ड—इस बीच में कान्वेन्शन के सम्मुख यह प्रश्न भी विद्यमान था, कि पदच्युत राजा का क्या किया जाय? बहुत से लोगो का खयाल था, कि उसने देश के विरुद्ध विद्रोह किया है। इसलिये उसके खिलाफ मुकदमा चलाया गया। दातो ने अपने भाषण में बड़ी जोर से गरज कर कहा—यूरोप के राजाओ ने हमको चैलेंज दिया है। हम उनके जवाब में राजा का मिर उनके पैरो में फेंक देंगे। मुकदमे के सिलसिले में कान्वेन्शन के सम्मुख एक सन्दूकची पेश की गई, जिसमें कि वह गुप्त पत्र-व्यवहार बन्द था, जो कि राजा और उसके परिवार ने विदेशी राजाओ तथा फ्रांस से भागे हुए कुलीन लोगो के साथ किया था। राजा को प्राणदण्ड दिया जाय या नहीं, इस विषय पर जब वोट लिये गये, तो ७२१ वोटो में से ३८७ वोट प्राणदण्ड के पक्ष में आये। राजा का फैसला हो गया। उसे प्राणदण्ड मिलना निश्चित हुआ। २१ जनवरी, सन् १७९३ के दिन राजा का मिर घड में जलग कर दिया गया। मरने से पूर्व राजा के अन्तिम वाक्य ये थे—‘मिरा खून फ्रांस की समृद्धि का कारण बने।’ इस प्रकार १६वें लुई का अन्त हुआ। फ्रांस की जनता लुई की दुश्मन नहीं थी। क्रान्तिकारियो का उद्देश्य राजसत्ता का अन्त करना नहीं था। वे एकतन्त्र स्वेच्छाचारी शासन का अन्त कर वैध राजसत्ता की स्थापना करना चाहते थे। यदि १६वा लुई चाहता, तो क्रान्ति के बाद भी इङ्ग्लैण्ड के राजाओ की तरह अपनी शानदार और सम्मानास्पद स्थिति रख सकता था। पर १६वा लुई बहुत कमजोर

व्यवित था। वह अपने अदूरदर्शी दरबारियों के प्रभाव से कभी ऊपर नहीं उठ सका। उसका अन्त इस प्रकार दुःखस्था के साथ हुआ, उसमें उसकी अपनी गलतियाँ प्रबल हुईं।

राजा के कत्ल का प्रभाव—१६वें लुई का कत्ल यूरोप के स्वेच्छाचारी राजाओं को सुला चैलेज था। उन्होंने उस चैलेज को स्वीकार करने में जरा भी देर नहीं की। इङ्ग्लैंड के राजा जार्ज तृतीय ने फ्रांस के राजदूत को जाने देग में निकल जाने का हुक्म दिया। प्रधानमन्त्री पिट ने पार्लियामेंट में भाषण देते हुए कहा, कि सम्पूर्ण मानव इतिहास में १६वें लुई के कत्ल के समान वीभत्त और जमानुषिक कार्य अन्य कोई नहीं हुआ है। जब पिट इङ्गलिश राज्यक्रान्ति में चार्ल्स प्रथम के कत्ल को भूल गया था। फ्रांस और इङ्ग्लैंड में सामुद्रिक प्रतिस्पर्धा विद्यमान थी। उङ्ग्लैंड ने समझा, कि अपने प्रतियोगी को कुचलने का यह सुवर्ण अवसर उपलब्ध हुआ है, उसको हाथ में नहीं जाने देना चाहिये। पिट ने पार्लियामेंट में प्रस्ताव किया, कि उङ्ग्लैंड को भी फ्रांस के खिलाफ आस्ट्रिया का प्रशिया की सहायता करनी चाहिये।

फ्रांस के विरुद्ध जिहाद—उधर फ्रांस में नाव्यन्गन के सम्मुख भी यह विषय पड़ा हुआ। इङ्ग्लैंड का राज्यक्रान्ति के प्रति जो नजर था, उसे दृष्टि में रखते हुए नाव्यन्गन ने उचित समझा कि इङ्ग्लैंड के विरुद्ध युद्ध उद्घोषित कर दिया जाय। एक फरवरी, सन् १७९३ के दिन इङ्ग्लैंड और फ्रांस में लड़ाई घोषित कर दी गई।

आस्ट्रियन नीदरलैंड की विजय के बाद फ्रांस की सीमा हाँलैंड में जा लगी थी। हाँलैंड फ्रांस की इस समृद्धि तथा सफलता को नहीं सह मानता था। इनने गन्निगन राज्य का अपनी सीमा तक आ पहुँचना उसे सह्य नहीं था। परिणाम यह हुआ, कि हाँलैंड ने भी फ्रांस के विरोधियों का साथ दिया।

फ्रेच राज्यक्रान्ति के शत्रुओं की सख्या निरन्तर बढ़ रही थी। आस्ट्रिया, प्रशिया इङ्ग्लैंड और हाँलैंड उसके विरुद्ध युद्ध उद्घोषित कर चुके थे। अब मार्च, १७९३ में स्पेन और पवित्र रोमन साम्राज्य भी फ्रांस के विरुद्ध लड़ने को तैयार हो गये। फ्रांस अपने सारे पड़ोसियों से अकेला लड़ रहा था। उसे विरुद्ध परिस्थिति का सामना करना था। यूरोपियन राज्यों की सदियों की सधी हुई सेनाएँ उसके विरोध में थी। उसके अपने कुलीन तथा उच्च पुरोहित श्रेणियों के लोग उसके विरुद्ध सर्वस्व न्यौछावर करने में तैयार थे। फ्रांस की क्रान्तिकारी सेनाएँ युद्ध-नीति में निष्णात नहीं थी। यही कारण है कि १८ मार्च के दिन नीदरविन्डन नामक स्थान पर आस्ट्रियन सेना ने फ्रेच सेनापति डूमर को बुरी तरह परास्त किया, और नीदरलैंड फ्रांस के हाथ से निकल गया। इस पराजय के बाद सेनापति डूमर फ्रांस का पक्ष छोड़कर शत्रुओं से जा मिला। लफायत इससे कुछ दिन पहले ही शत्रुओं से मिल चुका था। ये दोनों महानुभाव राज्यक्रान्ति के प्रमुख नेता थे। एकतन्त्र स्वेच्छाचारी राजसत्ता को नष्ट करने में इनका कर्तृत्व बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पर राजा को प्राणदण्ड मिलना इनकी दृष्टि में अक्षम्य अपराध था। य क्रान्ति के पथ पर इतनी दूर नहीं जाना चाहते थे। क्रान्ति को अपने काव से बाहर न निकल देख उन्होंने यही उचित समझा, कि शत्रुओं के साथ मिलकर क्रान्ति को कुचला जाय। राष्ट्रीयता की भावना उस समय तक भलीभाँति विकसित नहीं हुई थी। राष्ट्रीयता के

इस युग में इन्हें देश-द्रोही कहा जायगा, पर उस जमाने में देश या राष्ट्र ने मनुष्यों के विचारों में वह स्थान प्राप्त नहीं किया था, जो अब कर लिया है। राष्ट्रीयता की भावना भी, इसी प्रकार की अन्य अनेक भावनाओं की तरह, इतिहास की उपज है।

शत्रुओं का सुख-स्वप्न—नीदरलैण्ड फ्रांस के कब्जे से निकल गया, इस बात से क्रान्ति के विरोधियों की हिम्मत बहुत बढ़ गई। उन्होंने आपस में सलाह करनी शुरू की, कि फ्रांस को जीत कर परस्पर बांट लिया जाय। अब से कुछ दिन पहले सन् १७९३ में ही पोलैण्ड को जीतकर रूस, आस्ट्रिया और प्रशिया ने आपस में विभक्त कर लिया था। अब फ्रांस को भी इसी प्रकार बांट खाने का स्वप्न लिया जाने लगा। आस्ट्रिया की आख फ्रांस के उत्तरी प्रदेशों पर थी। इङ्गलैण्ड उपनिवेशों को हड़पने की सोच रहा था। स्पेन पिरिनीज की पर्वतमाला को पार कर दक्षिण फ्रांस में अपना हिस्सा लेने की फिरार में था। इस प्रकार राज्यक्रान्ति के सब विरोधी फ्रांस को लूट खाने का सुख-स्वप्न ले रहे थे। निस्सन्देह, फ्रांस के लिये यह विकट परिस्थिति थी। उसने जिस हिम्मत और बहादुरी से इसका मुकाबला किया, वह इतिहास में वस्तुतः अद्वितीय है।

## २ आतंक का राज्य

शक्तिशाली सरकार का संगठन—फ्रांस के लिये नवीन शासन-विधान बनाने का कार्य कान्वेन्शन कर रहा था। पर इस समय देश की मुख्य आवश्यकता शासन-विधान का निर्माण नहीं थी। इस समय बाह्य और आन्तरिक शत्रुओं से रक्षा करना ही प्रधान कार्य था। इसी बात को दृष्टि में रखकर ४ जनवरी, १७९३ के दिन कान्वेन्शन ने एक 'सामान्य रक्षा-समिति' का निर्माण किया। इस समिति का कार्य फ्रांस में शांति और व्यवस्था कायम रखना था। पर इस समय स्थिति इतनी गम्भीर और विकट होती जाती थी, कि एक अत्यन्त और मजबूत और शक्तिशाली सरकार की जरूरत थी। युद्ध या विद्रोह के समय लोकतन्त्र शासन के सिद्धान्तों को क्रिया में परिणत कर सकना सम्भव नहीं रहता। उस समय आवश्यकता होती है, कि किसी व्यक्ति व व्यक्ति-समूह को सारे अधिकार दिये जावें। फ्रांस में विद्रोह भी हो रहे थे, और बाह्य शत्रुओं से युद्ध भी जारी थे। इस दशा में कान्वेन्शन के लिये यह सम्भव नहीं था, कि वह एक लोकतन्त्र रिपब्लिक को स्थापित कर सके। कान्वेन्शन शासन-विधान निर्माण करने का अपना मुख्य कार्य करता गया, पर उसने सामयिक रूप से शासन करने के लिये एक ऐसी समिति का निर्माण कर दिया, जिसे कि शासन और व्यवस्थापन सम्बन्धी सब अधिकार प्राप्त थे। इस समिति का नाम 'सार्वजनिक व्यवस्था समिति' था, और इसका निर्माण ६ एप्रिल, १७९३ के दिन हुआ था। एक क्रान्तिकारी के अनुसार "राजाओं के स्वेच्छाचारी शासन का अन्त करने के लिये स्वतन्त्रता का स्वेच्छाचारी शासन स्थापित करना आवश्यक है", और इसी उद्देश्य से इस समिति का निर्माण किया गया था। इसके अतिरिक्त एक 'क्रान्तिकारी न्यायालय' की भी स्थापना की गई थी। क्रान्ति के विरोधियों को इस न्यायालय के सम्मुख पेश किया जाता था, और वहाँ उन्हें कठोर दण्ड दिये जाते थे। यह शक्तिशाली और सब राजकीय अधिकारों से युक्त सरकार अपने शासन में जनता के विचारों की परवाह नहीं करती थी। उस समय यह सम्भव

भी नहीं था। उस सरकार ने विदेशी आक्रमणों से फ्रांस की रक्षा करने के लिये भारी कोशिश की। सब लोगों के लिये सैनिक सेवा करना आवश्यक कर दिया गया। लावा की मर्यादा में मिठाही भर्ती किये गये। यूरोप और अमेरिका के विविध देशों में सहायता प्राप्त करने की कोशिश की गई, पर उसमें कोई सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। उस समय लोग फ्रांस की राज्याक्रान्ति को बड़े जानक और वृष्णा की दृष्टि में देख रहे थे। उनकी सम्पत्ति में फ्रांस में ऐसी घटनाएँ हो रही थी, जो न्याय और जोचित्व में सर्वथा शून्य थी। किसी भी नई लहर को लोग पटले पटले उसी दृष्टि में देखते हैं। फ्रांस को कहीं से भी सहायता प्राप्त नहीं हुई। परन्तु जेकोबिन फ्रांस ने उन विप्लव परिस्थितियों में जो कार्य कर दिखाया, वह वस्तुतः आश्चर्यजनक था। उसका प्रधान कारण फ्रांस के लोगों में क्रान्ति की भावना थी। उन्हें अपने सिद्धान्तों पर अटल विश्वास था। उनमें बड़ा जोश था, जो कि किसी नये धर्म के प्रचारका में होता है। वे क्रान्ति के लिये मर मिटने को तैयार थे।

**जिरोदिस्ट दल का पतन**—कान्वेन्शन ने पहले जिरोदिस्ट दल का बहुमत था। यह दल रिपब्लिक तथा क्रान्ति का प्रबल पक्षपाती होने हुए भी उस समय की विप्लव परिस्थिति का सामना करने के लिये उपयुक्त न था। उस दल के लोग कानून और व्यवस्था को बहुत महत्त्व देते थे। पर शायद इस समय फ्रांस में कानून और व्यवस्था की अपेक्षा तात्कालिक प्रत्युत्पन्नमतिता की अधिक आवश्यकता थी। फ्रांस एक अत्यन्त भयंकर परिस्थिति में फँसा हुआ था, और उसका मुकाबला करने के लिये जिस हिम्मत और अदीर्घमूर्तता की आवश्यकता थी, वह जिरोदिस्ट लोगों में मौजूद न थी। परिणाम यह हुआ, कि उन का विरोध बढ़ता गया और जेकोबिन दल प्रबल होता गया। जेकोबिन दल का मन्त्रालय था, और उसमें किस प्रकार क्रान्ति के अत्यन्त गरम नेता सम्मिलित थे, इस पर पहले प्रकाश डाला जा चुका है। पेरिस की नगर-सभा, जो फ्रांस के शासन-मूल का जनक अशो में संचालन कर रही थी, जेकोबिन दल के साथ थी। जिरोदिस्ट दल पेरिस की नगर-सभा के सख्त खिलाफ था। वह समझता था, कि इस नगर-सभा ने फ्रांस के शान्त में अनुचित रूप से बहुत अधिक स्थान प्राप्त किया हुआ है। इसलिये उसकी तरफ से कान्वेन्शन में प्रस्ताव उपस्थित किया गया, कि पेरिस की नगर-सभा को तोड़ दिया जाय और कान्वेन्शन के अधिवेशन पेरिस के स्थान पर किसी अन्य नगर में किये जावें, ताकि पेरिस की जनता का अनुचित प्रभाव कान्वेन्शन पर न रहे। जेकोबिन दल ने इन प्रस्तावों का घोर विरोध किया। उसका कहना था, कि पेरिस का प्रभुत्व निर्विवाद है, अन्य प्रदेशों को राजधानी का अनुसरण करना ही चाहिये। इस समय फ्रांस और विशेषतया पेरिस की जा मनोवृत्ति थी, उसमें कानून और कायदों का वाकायदा अनुसरण करना सम्भव नहीं था। चाहिये तो यह था, कि इन प्रस्तावों पर वाकायदा वोट लिये जाते और बहुमत से जो फैसला होता, उसे क्रिया में परिणत किया जाता। पर कानून-कायदों को तोड़कर अपनी तात्कालिकता से काम करने की प्रवृत्ति जब एक बार उत्पन्न हो जाती है, तो उसका प्रयोग मर्यादित नहीं रहने पाता। पेरिस के लोग जिरोदिस्ट दल के खिलाफ उठ खड़े हुए। २ जून, १७९३ के दिन कान्वेन्शन को घेर लिया गया। जिरोदिस्ट दल के सब नेता कैद कर लिये गये। यह सब कार्य पेरिस की सर्वशक्तिमान नागरिक-सभा के आदेश से हुआ था।

अब कान्फेन्शन म जेकोविन दल का प्रभुत्व निर्विवाद हो गया । जेकोविन दल पेरिस के लोगो पर आश्रित था । अतः यू कहना चाहिये, कि पेरिस के लोग ही अब कठपुतली की तरह कान्फेन्शन को नचाने लगे । पेरिस की नगर-सभा जो चाहती, वही करा लेती । उसका विरोध करनेवाला अब कोई न रहा ।

विद्रोह की अग्नि भड़क उठी—जिरोदिस्ट दल को कान्फेन्शन से बहिष्कृत कर दिया गया, इस बात का परिणाम अच्छा नहीं हुआ । इस दल में फ्रांस के दक्षिणी प्रदेशों के बहुत से प्रतिनिधि सम्मिलित थे । इन्होंने विद्रोह करने का निश्चय किया । सबसे पूर्व जिरोद—जहाँ के प्रतिनिधियों के कारण ही इस दल का नाम जिरोदिस्ट पड़ा था—के प्रमुख नगर बोर्दियो में विद्रोह हुआ । बोर्दियो का अनुसरण मार्सेय्य ने किया और धीरे-धीरे यह विद्रोहाग्नि दक्षिणी फ्रांस के बहुत से प्रदेशों में व्याप्त हो गई । लायन्स नामक नगर रेशम तथा इसी प्रकार की अनेकविध भोगविलास की वस्तुएँ बनाने का बड़ा भारी केन्द्र था । इनकी वस्तुओं की खपत सर्वसाधारण जनता में नहीं हो सकती थी । इनके खरीदार कुलीन वा उच्च श्रेणी के लोग ही होते थे । पर अब राज्यक्रान्ति के कारण फ्रांस के ये उच्च श्रेणी के लोग विदेशों में भाग गये थे, और लायन्स के सारे व्यवसाय तथा व्यापार तबाह हो गये थे । यहाँ के लोगो को क्रान्ति से बड़ी घृणा थी । इन्होंने भी विद्रोह का झण्डा खड़ा कर दिया । इसी प्रकार ब्रिटेनी के निवासी भी क्रान्ति के विरुद्ध इस विद्रोह में सम्मिलित हुए । यहाँ के निवासी और विशेषतया किसान लोग राजसत्ता के कट्टर पक्षपाती थे । देहात के लोगो में परिवर्तन बहुत धीरे-धीरे आता है, वे जमाने से बहुत पीछे पड़ जाते हैं । ब्रिटेनी के निवासी अभी तक क्रान्ति की भावना से प्रायः अपरिचित थे । वे अब तक भी राजसत्ता को पसन्द करते थे, पुरोहितों को पूजते थे और कुलीन जमींदारों का रोव मानते थे । जिरोद, ब्रिटेनी, लायन्स और मार्सेय्य के इन विद्रोहों ने फ्रांस की सामयिक सरकार का कार्य बहुत कठिन बना दिया । उसे केवल विदेशी आक्रान्ताओं का ही मुकाबला नहीं करना था, अपितु इन आन्तरिक विद्रोहों की भी व्यवस्था करनी थी । क्रान्ति के लिये यह अग्निपरीक्षा का अवसर था ।

शत्रुओं के आक्रमण—विदेशी आक्रान्ता अपने आक्रमण में निरन्तर सफलता प्राप्त कर रहे थे । आस्ट्रियन और इङ्गलिश सेनाएँ फ्रांस की भूमि पर पदार्पण कर चुकी थी, और एक के बाद एक दुर्ग को जीतती जाती थी । शत्रुओं की सेना पेरिस से कुल १०० मील दूर रह गई थी । साफ दिखाई दे रहा था, कि शीघ्र ही पेरिस पर हमला कर दिया जायगा और ब्रुन्स्विक के ड्यूक की उद्घोषणा क्रिया में परिणत हो जायगी ।

नवीन सरकार—ऐसी विकट परिस्थिति में स्थिति को संभालने का एक ही उपाय था । वह यह कि सरकार को और भी मजबूत किया जाय, लोकतन्त्र रिपब्लिक के उदात्त सिद्धान्तों को कुछ समय के लिये ताक में रख कर स्वेच्छाचारी मजबूत सरकार की स्थापना की जाय । नेशनल कान्फेन्शन ने रिपब्लिक के सिद्धान्त का अनुसरण कर जो नया शासन-विधान बनाया था, वह यू ही रखा रह गया । १७९३ में फ्रांस के लिये जो शासन-विधान तैयार किया गया था, वह क्रिया में नहीं जा सका । उस समय की परिस्थिति उस के लायक नहीं थी, उस समय एक शक्तिशाली सरकार की आवश्यकता थी, और सामयिक आवश्यकता

ने उसे बीरे-बीरे स्वयं उत्पन्न कर दिया था। इस सरकार का स्वरूप क्या था ? यह शासन के लिये स्वेच्छाचारिता और आतंक का प्रयोग करती थी। इसके तरीके वही थे, जिन पुराने एकतन्त्र स्वेच्छाचारी राजाओं के होते थे। तरीके पुराने थे, पर उद्देश्य नवीन था। इस नई सरकार के स्वरूप को संक्षेप में इस प्रकार प्रकट किया जा सकता है—

(१) सार्वजनिक व्यवस्था समिति—सार्वजनिक व्यवस्था समिति के कुल १२ सदस्य थे। इन्हें राज्य के शासन और व्यवस्थापन-सम्बन्धी सब अधिकार प्राप्त थे। इस समिति का निवासस्थान राजा का पुराना प्रामाद था। राज्यक्रान्ति का वास्तविक संचालन इसी के हाथ में था। आतंक के विविध साधनों का उपयोग भी मुख्यतः इसी के द्वारा होता था। यही समिति राजकीय आज्ञाएं प्रकाशित किया करती थी। इसी के हुक्म से हजारों आदमियों को प्राणदण्ड दिया जाता था। जनता में क्रान्ति की भावना को निरन्तर ताजा तथा गरम बनाये रखना इसी समिति का काम था। यह समिति स्वतन्त्रता के नाम पर काम करती थी, पर इसके हथियार जुम, जन्माय, जन्माचार और आतंक के बने हुए थे।

(२) सामान्य रक्षा समिति—सामान्य रक्षा समिति का प्रमुख कार्य फ्रांस में शांति और व्यवस्था कायम रखना था। इसके सदस्यों की संख्या २१ थी। यह शांति और व्यवस्था के नाम पर जिस आदमी को चाहती गिरफ्तार करती, जेल में डालती या न्यायालय के सम्मुख पेश कर सकती थी।

(३) क्रान्तिकारी न्यायालय—क्रान्तिकारी न्यायालय का निर्माण देश-द्रोहियों तथा क्रान्ति के खिलाफ साजिश करनेवालों के मामलों का फैसला करने के लिये हुआ था। इसके न्यायाधीशों की नियुक्ति सार्वजनिक व्यवस्था समिति की तरफ से होती थी। इसके पास कार्य की बहुत अधिकता थी। क्रान्ति के दुश्मनों के सब अभियोग इसी के सम्मुख पेश होते थे और इसके निर्णयों के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती थी। कार्य की अनेकता के कारण इस न्यायालय को चार भागों में बांट दिया गया था। फिर भी कार्य का बोझ कम नहीं हुआ और यही कारण है, कि इसके फैसले बहुत जल्दबाजी के साथ किये जाते थे।

(४) विशेष प्रतिनिधि—इस समय फ्रांस में जो विकट परिस्थिति थी, उसमें यह जरूरी था, कि विशेष कार्यों के लिये ऐसे कर्मचारी नियत किये जावें, जिन्हें अपनी सम्मति के अनुसार कार्य करने के पूरे अधिकार प्राप्त हों। इनकी नियुक्ति सार्वजनिक व्यवस्था समिति द्वारा की जाती थी, और नेशनल कान्फेरेन्स के सदस्यों को ही इस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया जाता था। ये लोग कानून की परवाह बहुत कम करते थे। ये एक प्रकार के स्वेच्छाचारी राजा होते थे, जो अपनी शक्ति का निरंकुश रूप से प्रयोग करने में जरा भी सकोच नहीं करते थे।

(५) जेकोबिन क्लब—जेकोबिन क्लब की शाखाएँ फ्रांस भर में व्याप्त थी। इनका संगठन बहुत विस्तृत तथा व्यापक था। उस अव्यवस्थित तथा अनिश्चित दशा के समय में इस क्लब के देशव्यापी संगठन का प्रयोग बहुत उत्तम रीति से किया जा सकता था। सार्वजनिक व्यवस्था समिति ने इन जेकोबिन क्लबों का पूर्ण रीति से उपयोग किया और इनसे



वे बहुत से काम लिये गये, जो किसी सरकारी महकमे से लिये जाने चाहियें थे ।

**विद्रोहो का दमन**—इस शक्तिशाली सरकार ने बड़ी योग्यता और क्षमता से क्रान्ति के बाह्य और आभ्यन्तर—दोनों प्रकार के शत्रुओं का मुकाबला किया । आन्तरिक विद्रोहो को बुरी तरह कुचला गया । लायन्स के विद्रोह को शान्त करने के लिये वाकायदा फौज भेजी गई । शहर का घेरा डाल दिया गया । गोलाबारी की गई, और लायन्स को आत्मसमर्पण करने के लिये विवश किया गया । लायन्स के लोगो के साथ बड़ा भयंकर वर्ताव किया गया । दो हजार के लगभग आदमी कत्ल कर दिये गये । सार्वजनिक व्यवस्था समिति का यह खयाल था, कि इस नगर को पूर्णतया भस्मसात् कर दिया जाय, पर सौभाग्य-वश यह निश्चय क्रिया में परिणत नहीं हो सका । पर इसमें सन्देह नहीं, कि लायन्स के इस पराजय ने फ्रांस की जनता के सम्मुख यह भलीभाति स्पष्ट कर दिया कि क्रान्ति के विरुद्ध विद्रोह करना हँसी-मजाक नहीं है, क्रान्तिकारी भी विद्रोहियों से भयंकर बदला लेते हैं । बोर्दियो और मासॅय्य के विद्रोही लायन्स की दुर्दशा को देखकर घबरा गये । उन्हें विश्वास हो गया, कि वे क्रान्ति का मुकाबला सफलतापूर्वक नहीं कर सकेंगे । इसलिये उन्हें परास्त करने में विशेष कठिनता नहीं हुई । दोनों नगरों में चार-चार सौ के लगभग विद्रोहियों को कत्ल किया गया और दक्षिणी फ्रांस का विद्रोह सुगमता के साथ शान्त कर दिया गया ।

त्रिटेनी प्रदेश के विद्रोह न बहुत व्यापक और प्रचण्ड रूप धारण किया हुआ था । विषपतया वेन्टी के लोग क्रान्ति का सर्वनाश करने पर तुले हुए थे । विदेशी लोग भी इन्हे गुप्त रूप से सहायता पहुँचा रहे थे । क्रान्ति की सेनाओं को इनके साथ वाकायदा युद्ध लड़ने पड़े । सार्वजनिक व्यवस्था समिति ने इस विद्रोह को शान्त करने के लिये जो विषय प्रतिनिधि नियत किया था, उसने अपना कार्य बड़ी निर्दयता से किया । यहाँ पर भी दो हजार के लगभग विद्रोहियों का क्रूरतापूर्वक घात किया गया ।

विद्रोहो को कुचलने में सार्वजनिक व्यवस्था समिति को पूर्ण सफलता हुई । पर विद्रोह की भावना अभी नष्ट नहीं हुई थी । क्रान्तिकारी नेताओं को हमेशा भय बना रहता था, कि क्रान्ति के विरोधी लोग कहीं विद्रोह न कर बैठें । फ्रांस में क्रान्ति के विरोधियों की कमी नहीं थी । बहुत से लोग क्रान्ति के खुल्लम-खुल्ला विरोधी थे, पर अधिक संख्या उन लोगो की थी, जो क्रान्ति की प्रगति को पसन्द नहीं करते थे । क्रान्ति के विरोध में जो कुछ भी सम्भव हो, उसे ये गुप्त रूप से करने को तैयार रहते थे । जनता की सहानुभूति और लोकमत भी महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं । यदि लोगो की सम्मति किसी बात के लिये खिलाफ हो, यदि लोगो की सहानुभूति किसी बात के विरोध में हो—तो वह स्वयं एक महत्वपूर्ण ताकत होती है । फ्रांस के क्रान्तिकारी नेता इस बात को खूब समझते थे । इसीलिये वे क्रान्ति की विरोधी भावनाओं को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिये तुले हुए थे । उनका खयाल था, कि क्रान्ति की सफलता के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है, कि जिन पर क्रान्ति का विरोधी होने का सन्देह हो, उन्हें भी क्षमा नहीं करना चाहिये । कोई आदमी क्रान्ति का पक्षपाती है, या कम से कम विरोधी नहीं है, यह जानने के लिये इतनी ही बात काफी नहीं है, कि उसने क्रान्ति के विरोध में कोई काम नहीं किया है । इस के लिये यह भी जरूरी है, कि उसने क्रान्ति के पक्ष में कोई कोशिश की है । यदि कोई आदमी आज उदा-

सीन है, क्रान्ति का जोरदार तरीके से पक्षापाती नहीं है, तो क्या भरोसा है, कि कल वह विरोधी न बन जायगा ? जब क्रान्ति के नेता ही शत्रुओं से मिल जाते हैं, तो उदासीना का तो भरोसा ही क्या ? इन सब दृष्टियों से कान्फेन्शन ने निश्चय किया, कि विरोधियों के हृदयों पर आतंक जमा दिया जाय, क्रान्ति का मित्रता बंधा दिया जाय, ताकि कां० आदमी क्रान्ति का विरोध करने की हिम्मत न कर सके। इसी नीति का परिणाम हुआ कि फ्रेंच राज्यक्रान्ति के इतिहास में वह काल प्रारम्भ हुआ, जिसे 'आतंक का राज्य' कहा जाता है। यह काल कब से कब तक रहा, यह निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता। पर मोटे तौर पर यह कहा सकता है, कि सितम्बर १७९३ में जुलाई १७९४ तक—दस मास के लगभग फ्रांस में 'आतंक का राज्य' रहा।

**आतंक का राज्य**—क्रान्ति के विरोधियों को प्राणदण्ड या अन्य भयकर दण्ड देने के लिये व्यवस्था पहले से भी विद्यमान थी, 'क्रान्तिकारी न्यायालय' पहले भी कार्य कर रहा था। पर १७ सितम्बर, १७९३ के दिन एक भयकर कानून पारित किया गया। इस कानून द्वारा यह व्यवस्था की गई, कि जो लोग अपने व्यवहार व क्रिया द्वारा, अपनी सम्मति व विचारों के प्रकट करने में अथवा अन्य किसी प्रकार में क्रान्ति का विरोध करें, उन सबका प्राणदण्ड दिया जाय। यह कानून अत्यन्त व्यापक था। क्रान्ति के विरुद्ध या क्रान्ति के किसी भी कार्य के विरुद्ध सम्मति प्रकाशित करना भी अब अपराध था, और उसके लिये प्राणदण्ड की व्यवस्था की गई थी। प्राणदण्ड के लिये इस काल में एक नवीन उपकरण का आविष्कार किया गया था, जिसे गुलेटिन कहते हैं। इसका आविष्कारकर्त्ता डा० गुलेटिन नाम का व्यक्ति था और उसी के नाम के कारण इसे गुलेटिन कहते हैं। इस उपकरण में दो स्तम्भों के बीच एक बहुत बड़ा फलका लटक रहा होता था, जिसे रस्सी द्वारा ऊपर या नीचे ले जाया जा सकता था। अपराधी को इन दो स्तम्भों के बीच में लेटाकर फलके की रस्सी ढीली कर दी जाती थी और वह भारी फलका बड़े वेग से और शब्द के साथ नीचे गिरकर अपराधी के सिर को धड़ से अलग कर देता था। इस उपकरण को दो पहियेवाली गाड़ी पर रखकर जहाँ चाहें, ले जा सकते थे। इस काल में पेरिस की गलियों में ये गुलेटिन सब नजर आते थे। प्रातः काल उठने पर इनका शब्द सुनाई पड़ता था। बड़े पैमाने पर अब क्रान्ति के विरोधियों का घात किया जा रहा था। इस वीभत्स और भयकर कत्ल के कारण ही इस काल का नाम 'आतंक का राज्य' रखा गया है।

**रानी मेरी का कत्ल**—अक्टूबर, १७९३ में १६वे लुई की रानी मेरी आतोआत पर मुकदमा चलाया गया। उसे क्रान्ति का विरोधी पाया गया। गुलेटिन ने रानी का—जिसका सारा जीवन भोग-विलास और आमोद-प्रमोद में व्यतीत हुआ था, सिर धड़ से अलग कर दिया। गुलेटिन की दृष्टि में राजा व रक सब बराबर थे। फ्रांस के क्रान्तिकारियों ने कत्ल की प्रक्रिया में कुल या जाति आदि किसी बात की परवाह नहीं की थी। रानी के साथ ही बहुत से कुलीन तथा उच्च पुरोहित श्रेणी के लोग कत्ल किये गये। जिरोदिस्ट दल के बहुत से नेता, जिन्हें पेरिस की नागरिक-सभा ने कान्फेन्शन की बैठक में गिरफ्तार कर लिया था—अब तक जेलों में पड़े थे। उन सब को भी कत्ल कर दिया गया। मदाम रोल्ला नाम की एक कुलीन महिला को जिस समय गुलेटिन पर कत्ल के लिये ले

जाया गया, तो उसने चिल्लाकर कहा—‘स्वाधीनते, तेरे नाम पर क्या-क्या अनर्थ किये जा रहे हैं ?’ रोला का यह कहना सर्वथा ठीक था। मनुष्य धर्म, राष्ट्रीयता, स्वाधीनता और देशभक्ति आदि उच्च भावों के आवरण में कैसे-कैसे वीभत्स कार्य करता है ? फ्रांस के क्रान्तिकारी निस्सन्देह एक विकट परिस्थिति का सामना कर रहे थे, उन्हें बाह्य और आभ्यन्तर—दोनों प्रकार के अनगणित शत्रुओं का मुकाबला करना पड़ रहा था। इस-लिये कुछ हद तक सत्ती की जरूरत थी। पर इसमें सन्देह नहीं, कि इस समय क्रान्तिकारी लोग अचित्य, न्याय और आवश्यकता की सीमा का उल्लंघन कर रहे थे।

**जैकोबिन दल में फूट—**शीघ्र ही जैकोबिन दल में भी मतभेद शुरू हो गये। दातो का खयाल था, कि अधिक खूनखराबी नहीं होनी चाहिये। वह कतलो और गुलेटिन से थक गया था। दूसरी तरफ़ पेरिस की नागरिक सभा के नेता हेवर् की राय थी, कि क्रान्ति को शीघ्र ही पूर्ण करना चाहिये और क्रान्ति को पूर्ण करने के एकमात्र उपाय आतंक और कतल है। ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है। ईश्वर के स्थान पर ‘बुद्धि’ की उपासना प्रारम्भ होनी चाहिये। एक सुन्दर नदी के रूप में ‘बुद्धि’ की प्रतिमा भी बनाई गई और उसको एक मन्दिर में प्रतिष्ठापित भी किया गया। रोवस्पियर और सेन्ट जस्टन न दातो से सहमत थे और न हेवर् से। ये दोनों नेता रूसो के कट्टर अनुयायी थे। क्रान्ति के सम्बन्ध में इनके निश्चित विचार थे। ये एक ऐसी रिपब्लिक की कल्पना करते थे, जिसमें न कोई जमीर हो और न कोई गरीब हो। बच्चों को पांच साल की उमर में राज्य के सुपुर्द कर दिया जाय और स्पार्टन तरीके से उनका शिक्षण किया जावे। रोवस्पियर परमेश्वर को मानता था, वह बुद्धि की उपासना के खिलाफ़ था। उसका सिद्धान्त था—‘यदि परमेश्वर की कोई सत्ता नहीं है, तो हमें उसका आविष्कार करना चाहिये।’ जैकोबिन दल के विविध नेताओं में रोवस्पियर का प्रभुत्व था। दातो तथा उस के अनुयायियों को इसलिये कतल किया गया, क्योंकि वे खूनखराबी से थक गये थे। हेवर् को इसलिये कतल किया गया, क्योंकि वह परमेश्वर को नहीं मानता था। इस काल में फ्रांस के क्रान्तिकारियों के पास एक ही उपाय था, अपने विरोधी के साथ व्यवहार करने का एक ही तरीका उन्हें मालूम था—कतल। जो हमसे मतभेद रखता है, वह क्रान्ति का दुश्मन है। उसकी एक ही मजा है—गुलेटिन। इसी मनोवृत्ति से फ्रांस के क्रान्तिकारी नेता अपने पुराने सहयोगियों को बंधक होकर कतल करते रहे। दातो और हेवर् के कतल के बाद रोवस्पियर का कुछ समय के लिये एकाधिपत्य हो गया।

**नवीन युग की सृष्टि—**यह ध्यान रखना चाहिये, कि रोवस्पियर पूरी तरह ईमानदार था। वह वस्तुतः समझ रहा था, कि वह जो कुछ कर रहा है, क्रान्ति के, फ्रांस के कल्याण के लिये है। रोवस्पियर के नेतृत्व में ‘सार्वजनिक व्यवस्था समिति’ ने जो कार्य किया, वह वस्तुतः अद्भुत है। जिन समस्याओं को हल करना आज भी मनुष्य जाति को बहुत कठिन प्रतीत हो रहा है, जिनको हल करने के लिये बड़े-बड़े विद्वान् आज तक परेशान हो रहे हैं, उनके लिये इस सार्वजनिक व्यवस्था-समिति के पास अत्यंत मुगम हल विद्यमान थे। क्रान्ति के जोश में, नये युग की सृष्टि करने के आवेश में क्रान्तिकारियों ने फ्रांस में बड़े-बड़े परिवर्तन किये। सम्पत्ति को एक बराबर करने की कोशिश की गई।

अमीरी की सम्पत्ति पर भारी टैक्स लगाये गये। बहुत से सम्पत्तिशाली लोगो की जायदादें उमलिये जप्त कर ली गई, ताकि गरीबों को उनसे फायदा पहुँच सके। यह व्यवस्था का गर्ट, फ्रिड्रिख आदमी जानी स्त्री और बच्चों के साथ आराम से अपने घर में रह सकें। मुनाफे को उठाने की कोशिश की गई। अर्थशास्त्रियों के लिये मुनाफा एक जटिल पहलू है। व्यापार और व्यवसाय के लिये मेहनत करने का उत्साह उस में उत्पन्न होता है। पर साथ ही उसमें बहुत से लोगों का दूसरा हाथ हिस्सा छीनकर अपने को अनुचित रूप से समृद्ध बनाने का भी अवसर मिलता है। १७१३ में फ्रांस में मुनाफे को मर्यादित करने के लिए कानून बनाये गये। सामाजिक-क्षेत्र में भी बड़े परिवर्तन किये गये। नज़ाक को उतारा आसान कर दिया गया, जितना कि विवाह। जायज और नाजायज बच्चों का भेद सर्वसम्मत नष्ट कर दिया गया। एक नये पञ्चाङ्ग का निर्माण किया गया, जिसमें मास को तीस-तीस दिन के १२ महीनों में बांटा गया। महीनों के नाम जुहवा, सर्पा, बर्फ, योग, फूल, मास, फल आदि रखे गये। महीनों में चार के स्थान पर तीन नप्ताह (या दशाह) रचे गये। दिन को चौबीस घण्टों के स्थान पर दस घण्टों में विभक्त किया गया। मुद्रापद्धति का नवीन प्रकार में निर्माण किया गया। नन के घण्टे प्रण्टियों को मित्राकर मुद्रा बनाने के काम में लाया गया। धार्मिक सहिष्णुता की स्थापना की गई। कुछ लोगों की कोशिश थी, कि क्रिश्चियन धर्म को भी उठा दिया जाय। परमेस्वर को नष्ट कर देने का प्रस्ताव तो क्रिया में भी आ चुका था, पर रोवस्पियर के विरोध पर यह बात देर तक नहीं रह सकी। तोल और भार मापने के लिये नये माप चलाये गये। दशमलव पद्धति पर तोल और भार के जिन परिमाणों को आज नारा मनार स्वीकृत किया जा रहा है, उनका आविष्कार इस 'आतंक के राज्य' के समय में ही हुआ था। प्रारम्भिक शिक्षा का प्रसार करने के लिये एक उत्तम योजना तैयार की गई। ये सब महत्त्वपूर्ण काम उस समय में किये गये, जब कि फ्रांस की राष्ट्रीय स्वयसेवक सेना विदेशी आक्रान्ताओं से घनघोर युद्ध कर रही थी, और क्रान्तिकारी नेता क्रान्ति के विरोधियों का सर्वनाश करने के लिये गुलेटिन का बड़े पैमाने पर प्रयोग कर रहे थे। निस्सन्देह, फ्रांस के लोगो की क्षमता और कार्यशक्ति इस समय में असाधारण रूप से बढ़ गई थी। वे लोग न केवल नाश के कार्य में लगे थे, पर बड़ी गम्भीरता तथा ईमानदारी से नये युग की सृष्टि में भी तत्पर थे।

**रोवस्पियर का पतन**—रोवस्पियर का यह एकाधिपत्य देर तक कायम नहीं रहा। जिस प्रकार उसने दातो तथा हेवैर् को कत्ल किया था, उसी प्रकार उसे भी कत्ल किया गया। उसके खिलाफ एक साजिश तैयार की गई। २७ जुलाई, १७९४ के दिन जब वह कान्तेन्शन में भाषण करने के लिये खड़ा हुआ, तब इन पड्यन्त्रकारियों ने चिल्लाया शुरू किया—'अत्याचारी हाय हाय।' रोवस्पियर हैरान रह गया। हैरानी और डर के मारे उस के मुख से आवाज नहीं निकली। एक आदमी ने चिल्लाकर कहा—'दातो का खून इसका गला घूट रहा है।' रोवस्पियर समझ गया, उसका अन्त भी समीप है। उस पर मुकदमा चलाया गया, और उसे दोषी पाया गया। विरोधियों ने उस पर हमला किया, और उसे गिरफ्तार कर लिया। पेरिस की गानरिक सभा तथो जैकाबिन क्लब अवश

उसके पक्ष में थे। जैकोविन क्लव ने कान्वेन्शन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। दोनों पक्षों में खुल्लमखुल्ला लड़ाई होने लगी। आखिर जैकोविन क्लव ने रोवस्पियर को छुड़वा लिया, और उसने अपनी क्लव के सुरक्षित विशाल भवन में आश्रय लिया। सारे शहर में सन-सनी फैल गई। सब तरह के जुलूस निकलने लगे। सुबह तीन बजे कान्वेन्शन की सेनाओं ने जैकोविन क्लव पर हमला किया। खुल कर लड़ाई हुई। उस समय जैकोविन सेनापति हेन्रियत शराब पीकर मस्त-सा पड़ा था। पेरिस की नागरिक-सभा के सिपाही कान्वेन्शन से मिल गये। जैकोविन क्लव अकेला रह गया। लड़ाई में रोवस्पियर के जवाड़े पर गोली लगी। वह बुरी तरह घायल हो कर गिर पड़ा। रोवस्पियर के अगले १७ घंटे बड़ी तकलीफ से गुजरे। इस बीच में वह एक शब्द भी न बोल सका। उसका फटा हुआ जवाड़ा एक मैले कपड़े से बांध दिया गया था। आखिर, रोवस्पियर को गुलेटिन के नीचे कतल करने के लिये ले जाया गया। कतल करने से पहले उसकी पट्टी उतार दी गई थी। गुलेटिन का फलका आया और उसके सब कपटों का अन्त कर गया।

**विद्वेचना**—अनेक ऐतिहासकों ने इस आतक के राज्य का बड़े बीभत्स रूप से वर्णन किया है। फ्रेंच राज्यक्रान्ति को वदनाम करने के लिये इस काल को इस रूप में पेश किया गया है, मानो इससे अधिक भयकर और बीभत्स काल इतिहास में पहले कभी हुआ ही नहीं। राजसत्ता के पक्षपातियों ने इस काल का वर्णन करके यह परिणाम निकाला है, कि मानव प्रवृत्तियों में जो सबसे अधिक घृणास्पद तथा रौद्र प्रवृत्तियाँ हैं, राज्यक्रान्ति द्वारा उनका प्रकाशन हो रहा था। पर वास्तविकता क्या है, इसे हमें अपनी दृष्टि में रखना चाहिये। सम्पूर्ण जातक के राज्य में कुल मिला कर चार हजार के लगभग आदमी कतल किये गये थे। यदि हम इस की तुलना पुराने राजसत्ता के जमाने के कारनामों से करें, तो इसकी भयकरता बहुत कुछ कम हो जायगी। चार्ल्स ५वें के शासन-काल में नीदरलैंड जैसे छोटे से देश में ५० हजार के लगभग आदमियों को जीते जी आग में जला दिया गया था। स्पेन बायो-लोमियों के दिन फ्रांस में दो हजार से अधिक निरपराध लोगों को तलवार के घाट उतार दिया गया था। राजसत्ता के जमाने में राजा तथा उसके अमीर उमरा मानवीय जीवन को जिस प्रकार तुच्छ और अगण्य समझकर उसे अपनी स्वेच्छा से नष्ट करते थे—यह कौन नहीं जानता। इस आतक के राज्य में तो एक विशेष सिद्धान्त की दृष्टि में रखकर कुछ खाम विकट परिस्थितियों में ये कतल हुए थे। पर इसी काल में इङ्गलैंड तथा अन्य देशों के मनुष्य, समाज और मानव जीवन की क्या दशा थी? इङ्गलैंड तथा अमेरिका में इसी काल में तुच्छ-तुच्छ अपराधों पर जितने आदमी कतल किये जा रहे थे, या जन्म भर के लिये जेलों में सड़ाये जा रहे थे, उतने फ्रांस में देशद्रोह के अपराध में कतल नहीं किये गये। फर्क इतना ही है, कि फ्रांस में जिन लोगों को मारा गया, वे राजघरानों के थे, कुलीन और उच्च श्रेणियों के थे। पर अन्य देशों में जो आदमी कुत्ते की मौत मर रहे थे, वे गरीब थे, नीची श्रेणियों के थे। उनका रोना रोने के लिये उस जमाने में कोई न था। पर एक कुलीन को गुलेटिन से मारने पर सारा यूरोप काप उठता था। यही कारण है, जिसमें फ्रांस के इस आतक के राज्य को इतना वदनाम किया गया है। परन्तु यह ध्रुव सत्य है, कि कतलों के इस काल में भी फ्रांस की सर्वसाधारण जनता का जीवन अधिक

अमीरों की सम्पत्ति पर भारी टैक्स लगाये गये। बहुत से सम्पत्तिशाली लोगों की जायदाद इसलिये जप्त कर ली गई, ताकि गरीबों को उनसे फायदा पहुँच सके। यह व्यवस्था की गई, कि सत्र आदमी अपनी स्त्री और बच्चों के साथ आराम से अपने घर में रह सकें। मुनाफे को उड़ाने की कोशिश की गई। अर्थशास्त्रियों के लिये मुनाफा एक जटिल पहेली है। व्यापार और व्यवसाय के लिये मेहनत करने का उन्माह डम में उत्पन्न होता है। पर साथ ही इसमें बहुत से लोगों को दूसरों का हिस्सा छीनकर अपने को अनुचित रूप में समृद्ध बनाने का भी अवसर मिलता है। १७९३ में फ्रांस में मुनाफे को मर्यादित करने के लिये कानून बनाये गये। सामाजिक-क्षेत्र में भी बड़े परिवर्तन किये गये। तलाक को उतना ही आसान कर दिया गया, जितना कि विवाह। जायज और नाजायज बच्चों का भेद सर्वशून्य नष्ट कर दिया गया। एक नये पञ्चाङ्ग का निर्माण किया गया, जिसमें साल को तीस-तीस दिन के १२ महीनों में बांटा गया। महीनों के नाम जुहरा, वर्षा, बर्फ, ग्रीष्म, फूल, मर्ग, फल आदि रखे गये। महीनों में चार के स्थान पर तीन सप्ताह (या दशाह) रखे गये। दिन को चौबीस घण्टों के स्थान पर दस घण्टों में विभक्त किया गया। मुद्रापद्धति का नवीन प्रकार से निर्माण किया गया। चर्न के पण्टे पण्टियों को पित्राकार मुद्रा बनाने के काम में लाया गया। धार्मिक सहिष्णुता की स्थापना की गई। कुछ लोगों की कोशिश थी, कि क्रिश्चियन धर्म को भी उड़ा दिया जाय। परमेश्वर को नष्ट कर देने का प्रस्ताव तो किया में भी आ चुका था, पर रोवस्पियर के विरोध में यह बात देर तक नहीं रह सकी। तोल और भार मापने के लिये नये माप चलाये गये। दशमलव पद्धति पर तोल और भार के जिन परिमाणों को आज मारा ममार स्वीकृत करता जा रहा है, उनका आविष्कार इस 'आतंक के राज्य' के समय में ही हुआ था। प्रारम्भिक शिक्षा का प्रसार करने के लिये एक उत्तम योजना तैयार की गई। ये सब महत्त्वपूर्ण कार्य उस समय में किये गये, जब कि फ्रांस की राष्ट्रीय स्वयंसेवक मैन विदेशी आक्रान्ताओं से घनघोर युद्ध कर रही थी, और क्रान्तिकारी नेता क्रान्ति के विरोधियों का सर्वनाश करने के लिये गुलेटिन का बड़े पैमाने पर प्रयोग कर रहे थे। निस्सन्देह, फ्रांस के लोग की क्षमता और कार्यशक्ति इस समय में असाधारण रूप से बढ़ गई थी। वे लोग न केवल नाश के कार्य में लगे थे, पर बड़ी गम्भीरता तथा ईमानदारी से नये युग की मुष्टि में भी तत्पर थे।

**रोवस्पियर का पतन**—रोवस्पियर का यह एकाधिपत्य देर तक कायम नहीं रहा। जिस प्रकार उसने दातो तथा हेवेंर को कतल किया था, उसी प्रकार उसे भी कतल किया गया। उसके खिलाफ एक साजिश तैयार की गई। २७ जुलाई, १७९४ के दिन जब वह कान्वेन्शन में भाषण करने के लिये खड़ा हुआ, तब इन पड़यन्त्रकारियों ने चिल्लाना शुरू किया—'अत्याचारी हाय हाय।' रोवस्पियर हैरान रह गया। हैरानी और डर के मारे उस के मुख से आवाज नहीं निकली। एक आदमी ने चिल्लाकर कहा—'दातो का खून इसका गला घूट रहा है।' रोवस्पियर समझ गया, उसका अन्त भी समीप है। उस पर मुकदमा चलाया गया, और उसे दोषी पाया गया। विरोधियों ने उस पर हमला किया, और उसे गिरफ्तार कर लिया। पेरिस की गानरिक सभा तथो जैकाविन क्लव अवर्भी

उसके पक्ष में थे। जैकोबिन क्लव ने कान्वेन्शन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। दोनों पक्षों में खुल्लमखुल्ला लड़ाई होने लगी। आखिर जैकोबिन क्लव ने रोवस्पियर को छुड़वा लिया, और उसने अपनी क्लव के सुरक्षित विशाल भवन में आश्रय लिया। सारे शहर में सन-सनी फैल गई। सब तरह के जुलूस निकलने लगे। सुबह तीन बजे कान्वेन्शन की सेनाओं ने जैकोबिन क्लव पर हमला किया। खुल कर लड़ाई हुई। उस समय जैकोबिन सेनापति हेन्रियत शराब पीकर मस्त-सा पड़ा था। पेरिस की नागरिक-सभा के सिपाही कान्वेन्शन से मिल गये। जैकोबिन क्लव अकेला रह गया। लड़ाई में रोवस्पियर के जवाड़े पर गोली लगी। वह बुरी तरह घायल हो कर गिर पड़ा। रोवस्पियर के अगले १७ घंटे बड़ी तकलीफ से गुजरे। इस बीच में वह एक शब्द भी न बोल सका। उसका फटा हुआ जवाड़ा एक मैले कपड़े से बांध दिया गया था। आखिर, रोवस्पियर को गुलेटिन के नीचे कतल करने के लिये ले जाया गया। कतल करने से पहले उसकी पट्टी उतार दी गई थी। गुलेटिन का फलका आया और उसके सब कट्टों का अन्त कर गया।

**विवेचना—**अनेक ऐतिहासकों ने इस आतक के राज्य का बड़े बीभत्स रूप से वर्णन किया है। फ्रेंच राज्यक्रान्ति को बदनाम करने के लिये इस काल को इस रूप में पेश किया गया है, मानो इससे अधिक भयकर और बीभत्स काल इतिहास में पहले कभी हुआ ही नहीं। राजसत्ता के पक्षपातियों ने इस काल का वर्णन करके यह परिणाम निकाला है, कि मानव प्रवृत्तियों में जो सबसे अधिक घृणास्पद तथा रौद्र प्रवृत्तियाँ हैं, राज्यक्रान्ति द्वारा उनका प्रकाशन हो रहा था। पर वास्तविकता क्या है, इसे हमें अपनी दृष्टि में रखना चाहिये। सम्पूर्ण आतक के राज्य में कुल मिला कर चार हजार के लगभग आदमी कतल किये गये थे। यदि हम इस की तुलना पुराने राजसत्ता के जमाने के कारनामों से करें, तो इसकी भयकरता बहुत कुछ कम हो जायगी। चार्ल्स ५वें के शासन-काल में नीदरलैंड जैसे छोटे में देश में ५० हजार के लगभग आदमियों को जीते जी आग में जला दिया गया था। नेण्ट वार्यों-लैमियों के दिन फ्रांस में दो हजार से अधिक निरपराध लोगों को तलवार के घात उतार दिया गया था। राजसत्ता के जमाने में राजा तथा उसके अमीर उमरा मानवीय जीवन को जिस प्रकार तुच्छ और अगण्य समझकर उसे अपनी स्वेच्छा से नष्ट करते थे—यह कौन नहीं जानता। इस आतक के राज्य में तो एक विशेष सिद्धान्त की दृष्टि में रखकर कुछ खास विकट परिस्थितियों में ये कतल हुए थे। पर इसी काल में इङ्ग्लैंड तथा अन्य देशों के मनुष्य, समाज और मानव जीवन की क्या दशा थी? इङ्ग्लैंड तथा अमेरिका में इसी काल में तुच्छ-तुच्छ अपराधों पर जितने आदमी कतल किये जा रहे थे, या जन्म भर के लिये जेलों में सड़ाये जा रहे थे, उतने फ्रांस में देशद्रोह के अपराध में कतल नहीं किये गये। फर्क इतना ही है, कि फ्रांस में जिन लोगों को मारा गया, वे राजघरानों के थे, कुलीन और उच्च श्रेणियों के थे। पर अन्य देशों में जो आदमी कुत्ते की मौत मर रहे थे, वे गरीब थे, नीची श्रेणियों के थे। उनका रोना रोने के लिये उस जमाने में कोई न था। पर एक कुलीन को गुलेटिन से मारने पर सारा यूरोप कांप उठता था। यही कारण है, जिसमें फ्रांस के इस आतक के राज्य को इतना बदनाम किया गया है। परन्तु यह ध्रुव सत्य है, कि कतलों के इस काल में भी फ्रांस की सर्वसाधारण जनता का जीवन अधिक

सुरक्षित, अधिक सम्मानास्पद तथा अधिक सुखी था—उस समय के मुकाबले में जब कि वूर्वी राजवंश के स्वेच्छाचारी राजा अपने कृपापात्रों के साथ वर्माय के राजप्रासाद में भोग-विलास में मस्त रहते थे।

### ३ डायरेक्टरी का शासन

आतंक के राज्य का अन्त—रोवस्पियर की मृत्यु के बाद 'आतंक का राज्य' समाप्त हो गया। लोगों पर अत्याचार करने के लिये, निधडक हो कर अपने स्वेच्छाचारी कृपा से भयानक क्रिस्म का आतंक फैलाने के लिये भी अमा मार्ग हिम्मत, प्रभाव और व्यक्तित्व की आवश्यकता होती है। रोवस्पियर की मृत्यु के बाद क्रान्तिकारी नेताओं में कोई ऐसा नहीं था, जो उसके समान साहसी और प्रभावशाली हो। इसके अतिरिक्त अब जनता खूनखराबी से थक चुकी थी। आतंकमय शासन को न्याय्य और समुचित समझ मरने के जो भी कारण पहले विद्यमान थे, वे भी अब धीरे-धीरे हटने जा रहे थे। आन्तरिक विद्रोह बहुत कुछ शान्त किये जा चुके थे। विदेशी आक्रान्ताओं को पराजित किया जा चुका था। १६वें लुई के कतल के बाद विदेशी राजाओं ने बड़ी तेजी के साथ फ्रांस पर हमला किया था, पर अब इन आक्रमणों का जोर घट चुका था। कर्ना नाम के क्रान्तिकारी नेतापति ने शत्रुओं का मुकाबला करने के लिये बड़ी भारी सेना का संगठन किया था। इसमें नाडे सात लाख सैनिक थे। इन्हें तेरह भागों में विभक्त कर विविध रणक्षेत्रों में शत्रुओं को पराजित कर फ्रांस से बाहर खदेड़ देने के लिये भेज दिया गया था। प्रत्येक सेना के नेतापति के साथ दो दो 'विशेष प्रतिनिधि' रहते थे। इसका उद्देश्य यह था, कि कहीं नेतापति विद्रोह करके शत्रुओं से न मिल जावें। हमारे और लफायत के उदाहरण ने फ्रांस के क्रान्तिकारियों में सन्देह और अविश्वास की भावनाओं को बहुत प्रबल कर दिया था। जैकोबिन इस के ये 'विशेष प्रतिनिधि' न केवल सेनापतियों को विश्वासघात से रोकने थे, पर नाथ ही सैनिकों में क्रान्ति के लिये असाधारण उत्साह और जोश को भी जागृत करते रहते थे। इन सैनिक प्रयत्नों का यह परिणाम हुआ, था कि फ्रांस के आक्रान्ता परास्त हो गये थे और क्रान्तिकारी सेनाएँ फ्रांस की सीमाओं से आगे बढ़कर जर्मनी और आस्ट्रिया पर आक्रमण कर रही थी। इस स्थिति में न आन्तरिक विद्रोह और न विदेशी आक्रमण ही इस आतंक के राज्य को—जो कि विशेष परिस्थितियों में आवश्यक हो गया था, न्याय्य और समुचित बना सकते थे। परिणाम यह हुआ, कि रोवस्पियर की मृत्यु के साथ अपने आप ही इसकी समाप्ति हो गई, और फ्रांस में लोकतन्त्र सिद्धान्तों के अनुसार रिपब्लिक स्थापित कर दी गई।

नवीन शासन विधान—यह नवीन शासन-विधान नेशनल कान्वेंशन द्वारा तैयार किया गया था। यद्यपि कान्वेंशन ने विशेष परिस्थितियों को दृष्टि में रखकर देश के शासनकार्य को सार्वजनिक-व्यवस्था समिति के सुपुर्द कर दिया था, पर स्थायी शासन-विधान बनाने का विचार छोड़ नहीं दिया गया था। १७९५ में यह नवीन शासन-विधान तैयार हो गया। इसमें भी सबसे पूर्व नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों की उद्घोषणा की गई। व्यवस्थापन विभाग दो सभाओं द्वारा बनाया गया—'पाच सौ की सभा, और 'बड़ों की परिषद्'।



बड़े की परिषद् के सदस्य के लिये आवश्यक था, कि उनकी उमर ४० साल से अधिक हो। इस परिषद् की सदस्यता के लिये विवाहित या विधुर होना भी आवश्यक था। कोई अविवाहित आदमी इसका सदस्य नहीं बन सकता था। दोनों सभाओं के लिये सदस्य चुनने का अधिकार सम्पूर्ण नागरिकों को नहीं दिया गया था। फ्रांस का जो पहला शासन-विधान बना था, उसमें वोट का अधिकार सब वयस्क लोगों को दिया गया था, पर इस बार इसके लिये टैक्स देने की शर्त लगाई गई थी। जो लोग राज्य को किसी किस्म का टैक्स नहीं देते थे, उन्हें वोट देने का अधिकार भी नहीं दिया गया था। शासन का कार्य एक समिति को दिया गया, जिसके सदस्यों की संख्या पांच नियत की गई। इनका निर्वाचन व्यवस्थापन-विभाग द्वारा किया जाता था। इस समिति को 'डाइरेक्टरी' कहते थे। पांचो सदस्य क्रमशः तीन-तीन महीने के लिये 'डाइरेक्टरी' के अध्यक्ष होते थे। जिसकी अध्यक्ष होने की बारी होती थी, वही तीन महीने के लिये फ्रांस का राष्ट्रपति समझा जाता था। इस नये शासन-विधान से सब लोग सन्तुष्ट नहीं थे। विशेषतया, राजसत्ता के पक्षपाती और पूर्णतया लोकतन्त्र की स्थापना चाहनेवाले क्रान्तिकारी लोग इसे नापसन्द कर रहे थे। राजसत्ता के पक्षपाती तो इससे सन्तुष्ट ही कब हो सकते थे? लोकतन्त्रवादी दल भी इसे अपूर्ण तथा असन्तोषजनक समझता था। कान्वेन्शन को भय था, कि नये चुने हुए सदस्य कहीं इस शासन-विधान को अस्वीकृत न कर दें। अतः उन्होंने व्यवस्था कि व्यवस्थापन-विभाग की दोनों सभाओं के दो-तिहाई सदस्य अवश्य ही कान्वेन्शन के सदस्यों में से चुने जावें। परिणाम यह हुआ, कि कान्वेन्शन के इस हुक्म के खिलाफ नये शासन-विधान से असन्तुष्ट लोगों ने विद्रोह किया। इस विद्रोह को शान्त करने का कार्य एक पतले मुकड़े नौजवान सिपाही के सुपुर्द किया गया था, जिसने बड़ी योग्यता और चातुर्य से इस विद्रोह को शान्त किया। इस सिपाहीका नाम नेपोलियन बोनापार्ट था। २६ अक्टूबर, १७९५ के दिन कान्वेन्शन बर्खास्त हो गया, और फ्रांस का शासनसूत्र डाइरेक्टरी के हाथ में चला गया।

डाइरेक्टरी की नई सरकार के सम्मुख सब से बड़ा प्रश्न विदेशी युद्धों का था। विदेशी आक्रान्ताओं के हमले का पहला जोर तो अब घट चुका था। १७९५ के शुरू में प्रशिया, स्पेन और हालैंड ने फ्रांस से सन्धि कर ली थी। परन्तु इङ्ग्लैंड, आस्ट्रिया, पीडमोंट और विविध जर्मन राज्य अब तक भी फ्रांस के साथ युद्ध में जुटे हुए थे। सेना और युद्ध की दृष्टि से फ्रांस इस समय बहुत अच्छी दशा में था। वे स्वयंसेवक लोग, जो नगे पैर और फटे कपड़े पहने हुए फ्रांस के क्रान्तिकारी सिद्धान्तों को सारी दुनिया में फैला देने के लिये सेना में भर्ती हुए थे, अब अच्छे कुशल सैनिक बन चुके थे। उनमें केवल सैनिक क्षमता ही नहीं थी, साथ ही असाधारण उत्साह और जोश भी था। इन सेनाओं के सेनापति भी पुराने कुलीन लोग नहीं थे। कोई भी आदमी सेनापति बन सकता था, बशर्ते कि वह अपनी क्षमता साबित कर सके। इतिहास में यह एक नई बात थी। पुराने जमाने में राजा और राजकर्मचारियों की तरह सेनापति के पद भी ऊँचे कुलीन लोगों के लिये ही सुरक्षित रहते थे। पर फ्रांस के सभी क्रान्तिकारी सेनापति बहुत साधारण स्थिति के आदमी थे। मूरो एक वकील था। जोर्डन कपड़े बेचने का काम करता था। मरट अर्दली

रह चुका था। नैपोलियन बोनापार्ट एक गरीब वकील का लड़का था। राज्य की तरह सेना भी अब सर्वसाधारण जनता की चीज बन चुकी थी। यह क्रान्ति का अत्यन्त महत्वपूर्ण परिणाम था।

नये आक्रमणों की योजना—नई भावनाओं और उमङ्गों में भरी हुई जन-साधारण की यह सेना विदेशी युद्धों में असाधारण सफलता प्राप्त कर रही थी। डाइरेक्टरी का शासन शुरू होने में पहले ही आस्ट्रियन नीदरलैंड (बेल्जियम) को जीता जा चुका था। रूइन नदी के पश्चिमी तट तक जर्मनी में विजय की जा चुकी थी। नीम और सेवाय पर फ्रांस का कब्जा था। ऐसी स्थिति में डाइरेक्टरी के सम्मुख प्रधान कार्य यही था, कि अन्य शत्रुओं को भी परास्त कर क्रान्ति के मित्रान्नों की विजय निरपवाद रूप में स्थापित कर दी जाय। क्रान्ति का सबसे बड़ा दुश्मन आस्ट्रिया था। इसलिए डाइरेक्टरी ने योजना बनायी, कि आस्ट्रिया पर दो मार्गों से आक्रमण किया जाय। एक सेना जोर्डन और मूगे के सेनापतित्व में दक्षिणी जर्मनी के मार्ग से आस्ट्रिया पर हमला करे, और दूसरी सेना नैपोलियन बोनापार्ट की अध्यक्षता में उत्तरी इटली को जीतती हुई दक्षिण की तरफ में आस्ट्रिया पर आक्रमण करे।

नैपोलियन का सैनिक गौरव वास्तविक रूप में इसी आक्रमण में प्रारम्भ हुआ। इन आक्रमणों में नैपोलियन ने जिस असाधारण वीरता और युद्ध-अभूता का परिचय दिया, उससे सम्पूर्ण यूरोप आश्चर्य-चकित रह गया। इन्हीं शानदार विजयों का परिणाम था, कि नैपोलियन फ्रांस का न केवल सबसे बड़ा सेनापति तथा राज्याधिकारी बन गया, पर कुछ ही समय में सम्राट् पद तक भी पहुँच गया।

नैपोलियन का आक्रमण—उत्तरी इटली के मार्ग से आस्ट्रिया पर आक्रमण करने हुए नैपोलियन ने सबसे पूर्व पीडमोंड के राज्य पर हमला किया। पीडमोंड मुगता में परास्त हो गया। नीस और सेवाय पर फ्रांस के अधिकार स्वीकृत करने के लिये पीडमोंड के राजा को बाधित किया गया। पीडमोंट के राजा ने इन दोनों प्रदेशों पर अपना अधिकार छोड़ना स्वीकृत कर सन्धि कर ली। इस के बाद नैपोलियन ने उत्तरी इटली के दो अन्य राज्य—लोम्बार्डी और मिलान पर हमला किया। दोनों प्रदेश फ्रांस के अधीन हो गये। १५ मई, १७९६ को नैपोलियन ने बड़ी घूमवाम के साथ मिलान की वैभवशाली नगरी में प्रवेश किया।

कैम्पो फोर्मियो की सन्धि—अब आस्ट्रिया पर आक्रमण करने का द्वार खुल गया था। मेन्टुआ और आर्कोल के रणक्षेत्रों में आस्ट्रियन और फ्रेंच सेनाओं में लड़ाइयाँ लड़ी गईं। आस्ट्रिया की पराजय हुई। अक्टूबर, १७९७ में कैम्पो फोर्मियो नाम के स्थान पर दोनों देशों में सन्धि हो गई, जो कि 'कैम्पो फोर्मियो की सन्धि' के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। इस सन्धि के अनुसार आस्ट्रियन नीदरलैंड (बेल्जियम) पर फ्रांस के अधिकार को स्वीकृत किया गया। उत्तरी इटली के जिन प्रदेशों पर नैपोलियन ने विजय प्राप्त की थी उन्हें संगठित कर एक रिपब्लिक के रूप में परिवर्तित किया गया। इस नई रिपब्लिक का नाम किसत्पाइन रिपब्लिक (आल्प्स पर्वतमाला की दक्षिणवर्ती रिपब्लिक) रखा गया। यह नई रिपब्लिक फ्रांस की सुरक्षा में उसी के नमूने पर बनाई गई थी। आस्ट्रिया ने इस

रिपब्लिक को भी स्वीकृत किया। इसके अतिरिक्त, रूहाइन नदी के पश्चिमी तट पर फ्रांस के अधिकार में किसी किसम की बाधा न डालने का वचन आस्ट्रिया की तरफ से दिया गया। इन सब बातों के बदले में वेनिस की प्राचीन रिपब्लिक आस्ट्रिया के सुपुर्द कर दी गई। वेनिस की रिपब्लिक को भी नैपोलियन ने जीतकर अपने अधीन कर लिया था। कैम्पो फोर्मियो की यह सन्धि मध्यकालीन राजनीतिक सन्धियों का एक अच्छा नमूना है। जनता और देश की जरा भी परवाह किये बिना विक्री के मामूली माल की तरह राज्यों का भी उस जमाने में सौदा होता था। कैम्पो फोर्मियो में भी नैपोलियन ने आस्ट्रिया के साथ इसी ढंग का सौदा किया था।

उधर तो नैपोलियन को यह शानदार विजय प्राप्त हुई थी, उधर जोर्डन और मूरो — जिन्होंने कि दक्षिण जर्मनी होकर आस्ट्रिया पर हमला करना था, रूहाइन नदी के तट पर परास्त होकर वापिस लौट गये थे। एक साल के अन्दर-अन्दर ही नैपोलियन ने १८ बड़े और ५० छोटे युद्ध लड़े। इन युद्धों के परिणामस्वरूप उसने पीडमोंट और आस्ट्रिया को परास्त कर उन्हें फ्रांस से संधि करने के लिये बाधित किया। इन लड़ाइयों का सारा खर्च नैपोलियन ने पराजित प्रदेशों से वसूल किया। इतना ही नहीं, अपना सारा खर्च निकालकर नैपोलियन ने १ करोड़ ८० लाख रुपया फ्रांस को भी भेजा। पेरिस के अद्भुत-ताल (म्यूजियम) को विभूषित करने के लिये वह बहुत सी कृतियाँ इटली से पेरिस ले गया। जब वह फ्रांस लौटा, तो लोगो ने एक भारी विजेता के रूप में उसका स्वागत किया। निस्सन्देह, इन विजयों के कारण फ्रांस की जनता उसे एक महान् वीर के रूप में पूजने लग गई।

पेरिस लौटकर नैपोलियन ने कोशिश की, कि वह डाइरेक्टरी का सदस्य चुन लिया जाय। अपनी गत विजयों से उसे भरोसा हो गया था, कि वह इस महत्त्वपूर्ण पद को सुगमता से प्राप्त कर सकेगा। पर उसे निराशा हुई। उसने अनुभव किया, कि अभी समय नहीं आया है। अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिये अभी और अधिक आश्चर्यजनक कृत्यों की आवश्यकता है। अभी मैदान भलीभाँति तैयार नहीं हुआ है। इसलिये उसने एक अन्य विजय की योजना तैयार की।

**विजय की नई योजना**—पीडमोंट और आस्ट्रिया के साथ सन्धि हो जाने के कारण अब फ्रांस की लड़ाई केवल इङ्ग्लैण्ड से जारी थी। इङ्ग्लैण्ड और फ्रांस में लड़ाई का कारण केवल क्रान्ति के सिद्धान्त ही नहीं थे। इन दोनों देशों में सामुद्रिक प्रतिस्पर्धा सत्रहवीं सदी में प्रारम्भ हो चुकी थी। इङ्ग्लैण्ड और फ्रांस—दोनों ही अपना-अपना सामुद्रिक साम्राज्य स्थापित करने के प्रयत्न में थे। अतः इनमें संघर्ष का होना स्वाभाविक था। नैपोलियन का विचार था, कि यदि ईजिप्ट को अपने अधीन कर लिया जाय, तो इङ्ग्लैण्ड के पूर्वी देशों में निरन्तर बढ़ते हुए सामुद्रिक व्यापार तथा राजनीतिक शक्ति को सुगमता से नष्ट किया जा सकता है। यूरोप और एशिया के पारस्परिक सम्बन्ध का मार्ग ईजिप्ट के उत्तर से होकर जाता है। ईजिप्ट पर जिसका अधिकार होगा, वह सुगमता से इस मार्ग का नियन्त्रण कर सकेगा। नैपोलियन स्वप्न ले रहा था, कि ईजिप्ट को जीतकर मैं भारतवर्ष पर आक्रमण करूँगा। जिस प्रकार बहुत पुराने जमाने में सिकन्दर ने भारत पर हमला

किया था, उसी प्रकार मैं भी एक हाथी की पीठ पर बैठकर सारे भारत को जीत लूँगा। उन दिनों में भारत में फ्रांसीसी और अङ्ग्रेज लोग विविध राजाओं का पक्ष लेकर, या विविध राजाओं को अपने हाथ की कठपुतली बनाकर आपस में शक्ति के लिये मघपं कर रहे थे। नैपोलियन ने टीपू सुलतान से भी पत्र व्यवहार किया था। भारतवर्ष की विजय कर वह पूर्वी ससार का स्वामी बनना चाहता था। वह उस चामत्कारिक तथा रहस्यमयी कीर्ति को प्राप्त करना चाहता था, जिसे सिकन्दर के बाद किसी अन्य पाश्चात्य विजेता ने प्राप्त नहीं किया था। उसका मयाल था, कि यदि इन विजयों के मिलमिले में ही फ्रांस के विरुद्ध यूरोपीय राज्यों का कोई नया गुट बना, तो उसका मुकाबला करने की सामर्थ्य मेरे सिवा और किसी में न होगी। स्वाभाविक रूप में डाइरेक्टरी मुझे फ्रांस की रक्षा करने के लिये निमन्त्रित करेगी और तब अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिये उपयुक्त अवसर आयगा। तब फ्रांस के रक्षक के रूप में वापिस जाना होगा और अपना मनोरथ सुगमता से पूर्ण हो जायगा।

**ईजिप्ट पर आक्रमण**—डाइरेक्टरी ने नैपोलियन की योजना को स्वीकृत कर लिया। इङ्ग्लैण्ड को परास्त करने का निस्सन्देह, यह उत्तम उपाय था। चालीस हजार सैनिकों और एक शक्तिशाली जहाजी बेड़े को लेकर नैपोलियन ने ईजिप्ट के लिये प्रस्थान किया। नेल्सन के नेतृत्व में इङ्गलिश जलसेना ने फ्रांस के बेड़े को परास्त करना चाहा। पर नैपोलियन बच गया, और ८ जुलाई, १७९८ के दिन ईजिप्ट के प्रसिद्ध बन्दरगाह एलेग्जेन्द्रिया पहुँच गया। पहली अगस्त को नील नदी के तट पर लडाई लड़ी गई। ईजिप्ट परास्त हो गया। ईजिप्ट को जीतने की योजना का परिज्ञान जब टर्की की सरकार को हुआ, तो उसने फ्रांस के खिलाफ युद्ध उद्घोषित कर दिया। इसीलिये ईजिप्ट को विजय कर लेने के अनन्तर नैपोलियन ने टर्की के साम्राज्य पर आक्रमण किया। इस बीच इङ्गलिश नौसेनापति नेल्सन फ्रेंच जहाजी बेड़े को नष्ट करने में व्यग्र था। उसे अपने प्रयत्न में सफलता हुई। फ्रेंच बेड़ा पूर्णरूप से नष्ट कर दिया गया। अब नैपोलियन सामुद्रिक मार्ग से फ्रांस वापस नहीं लौट सकता था। उसका फ्रांस से सम्बन्ध टूट गया था। अब उसके सम्मुख एक ही मार्ग था। वह सीरिया और टर्की को जीतता हुआ एशिया माइनर के रास्ते से ही फ्रांस वापस लौट सकता था। यह मार्ग कितना कठिन था, और इसमें उसे कितने राज्यों और शत्रुओं के साथ मुकाबला करना था, इसकी कल्पना सुगमता से की जा सकती है। पर विवश होकर उसे इसी मार्ग का आश्रय लेना पड़ा। टर्की फ्रांस के खिलाफ युद्ध उद्घोषित कर चुका था, इसलिये भी आवश्यक था कि वह उसके साथ लडाई लड़े।

**सीरिया में पराजय**—नैपोलियन ने पहले सीरिया पर आक्रमण किया। सीरिया उस समय तुर्की साम्राज्य के अन्तर्गत था। एकर नामक स्थान पर तुर्की सेनाओं के साथ नैपोलियन की बड़ी भारी लडाई हुई। इटालियन लोगों ने टर्की की सहायता की, और नैपोलियन परास्त हुआ। अब उसे वापस लौटने के लिये बाधित होना पड़ा। फ्रेंच सेना ने भारी मुसीबत का सामना किया। तुर्की गिरोह उस पर एक तरफ से हमला कर रहे थे, और उधर सेना में महामारी फैल रही थी। आखिर नैपोलियन ईजिप्ट वापिस आया। यहाँ उसे समाचार मिला, कि फ्रांस के खिलाफ यूरोपियन राज्यों का एक नया गुट तैयार हुआ

है, फ्रांस पर भयकर आक्रमण की तैयारी हो रही है। नैपोलियन इसी समाचार की इतने दिनों से प्रतीक्षा कर रहा था। इसे जानकर उसकी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही। उसने अपनी सेना की कोई भी परवाह नहीं की, और अपने अच्छे-अच्छे सैनिक कर्मचारियों के साथ गुप्त रूप से फ्रांस के लिये प्रस्थान कर दिया। ९ अक्टूबर, १७९९ के दिन वह फ्रांस पहुँच गया। नैपोलियन के फ्रांस वापस होते ही जनता में नवीन उत्साह का संचार हो गया। लोगो को आशा बँध गई। वे इटली और आस्ट्रिया के विजेता, ईजिप्ट में रहस्यपूर्ण कारनामों सम्पादित करनेवाले, अजेय सेनापति को फिर से अपने बीच में पाकर हर्ष से फूल उठे। अब समय आ गया था, मैदान तैयार हो चुका था। नैपोलियन अपनी महत्वाकांक्षा को अब सुगमता से पूर्ण कर सकता था। राज्यक्रान्ति की जो लहर वस्तीयों के ध्वंस के साथ शुरू हुई थी, उसने अब एक नया रुख स्वीकृत किया था। क्रान्ति का युग अब समाप्त होने लगा था—उसका स्थान ले रहा था, नैपोलियन, वह नैपोलियन जो कि अपनी सेना को ईजिप्ट में निराश्रित रूप में छोड़कर अपनी वैयक्तिक महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिये फ्रांस वापस आया था।

सातवा अध्याय

## नैपोलियन का उष्कर्ष

### १ नैपोलियन का अभ्युदय

नैपोलियन का कुल—नैपोलियन बोनापार्ट का जन्म १५ अगस्त, मन् १७६९ का कोर्सिका द्वीप में हुआ था। यह द्वीप १७६८ तक जिनाज़ा की रिपब्लिक (इटली में) के अधीन था। नैपोलियन के जन्म में केवल एक वर्ष ही इस पर फ्रांस का आधिपत्य स्थापित हुआ था। नैपोलियन के माता-पिता इटालियन थे। उनके पुरखा मोल्हर्वी सदी में इटली से कोर्सिका में आ बसे थे। उनकी जन्मभूमि फ्रांस के अधीन थी, और स्वाधीनता प्राप्त करने के लिये कोशिश कर रही थी। नैपोलियन के पिता का नाम कार्ल बोनापार्ट था। कहने को तो यह परिवार कुलीन श्रेणी का था, पर वस्तुतः इसके पास जमीन जायदाद का सर्वथा अभाव था। अन्य बहुत से कुलीन लोगों की तरह कार्ल बोनापार्ट का परिवार भी अब गरीब हो चुका था—कुलीनता तथा उच्चता की स्मृति ही शेष रह गई थी। कार्ल बोनापार्ट वकालत का पेशा करता था। वकालत में उसे इतनी आमदनी नहीं थी, कि अपने विशाल परिवार का खर्च सुगमता से चला सके। उनकी आठ सन्तानें थी। इतने बड़े परिवार को पाल सकना उसके लिये मुगम नहीं था। इसलिये उसने दो बड़े लड़कों, जोसेफ और नैपोलियन को फ्रांस में शिक्षा दिलाने का निश्चय किया। जोसेफ को पुरोहिताई की शिक्षा दी गई और नैपोलियन को ब्रीएन के सैनिक शिक्षणालय में भर्ती करा दिया गया। सैनिक शिक्षा प्रारम्भ करने के समय नैपोलियन की आयु केवल दन वर्ष की थी। फ्रेंच भाषा का प्रारम्भिक ज्ञान उसने फ्रांस आकर ही प्राप्त किया था। उसकी मातृ-भाषा इटालियन थी।

सैनिक शिक्षा—ब्रीएन के सैनिक शिक्षणालय में नैपोलियन का जीवन बड़ी मुसीबत में गुजरा। वहाँ के सभी विद्यार्थी उच्च कुलीन श्रेणी के तथा अमीर थे। वे नैपोलियन को बहुत तग करते थे, और उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया करते थे। एक बार नैपोलियन ने अपने पिता को पत्र में लिखा था—‘ये वेशर्म लड़के मेरी गरीबी पर जिस ढग से मजाक उड़ाते हैं, उससे मैं तग आ गया हूँ। ये लोग केवल सम्पत्ति में ही मुझसे ज्यादा हैं। वास्तविक योग्यता में ये लोग मेरा मुकाबला नहीं कर सकते।’ इस शिक्षणालय में फ्रेंच विद्यार्थियों के साथ पढ़ते हुए नैपोलियन ने अपनी मातृभूमि को स्वतन्त्र कराने की भावना भी निरन्तर प्रबल होती गई।

सैनिक शिक्षा समाप्त कर लेने पर नैपोलियन को सेना में लेफ्टिनेन्ट के पद पर नियत किया गया। उसे विशेष उन्नति की कोई आशा नहीं थी। अभी तक फ्रांस में १६वें लुई

का एकतन्त्र शासन कायम था। सब जगह कुलीनो और अमीरो की पूछ थी। नैपोलियन गरीब तथा साधारण स्थिति का आदमी था। उसकी सिफारिश करनेवाला कोई प्रभावशाली व्यक्ति नहीं था। फिर वह उन्नति किस प्रकार कर सकता ? इसी बीच में उसके पिता की मृत्यु हो गई। वह गरीब परिवार—जिसके प्रत्येक व्यक्ति को एक दिन राजा व रानी के पद तक पहुँचना था, जिसके समान सौभाग्यशाली परिवार सम्भवत इतिहास में अन्य कोई नहीं हुआ, कार्लो बोनापार्ट की मृत्यु से अब सर्वथा आश्रयहीन हो गया था। इस अवस्था में नैपोलियन के लिये आवश्यक था, कि वह कोसिका जाकर अपने परिवार की देखभाल करे। वह कोसिका लौट गया। वहाँ फ्रांस के शासन के विरुद्ध अनेक पड़यंत्र जारी थे। नैपोलियन में भी अपने देश को स्वाधीन कराने की भावना प्रबल-रूप में विद्यमान थी। वह भी पड़यंत्रकारियों में शामिल हो गया। कोसिका की फ्रेंच सरकार ने पड़यंत्रकारियों के दमन का उद्योग किया, और नैपोलियन को कोसिका छोड़कर बाहर चले जाने के लिये विवश होना पड़ा।

**राज्यक्रान्ति और नैपोलियन**—जब फ्रांस में राज्यक्रान्ति हुई, तो नैपोलियन को अपनी उन्नति के लिये अच्छा मौका मिला। वह अपने परिवार सहित फ्रांस वापस लौट आया, और वहाँ क्रान्तिकारी सेना में सम्मिलित हो गया। उसने उच्च सैनिक शिक्षा प्राप्त की थी। फ्रांस की सेना के पुराने कुलीन अफसर विदेशी शत्रुओं से जा मिले थे। कोई भी योग्य व्यक्ति इस स्थिति का उपयोग कर अच्छी उन्नति कर सकता था। नैपोलियन ने इस स्थिति से पूरा-पूरा लाभ उठाया। वह जैकोबिन दल में सम्मिलित हो गया। जैकोबिन दल की महत्ता के बढ़ने के साथ-साथ नैपोलियन की सैनिक क्षमता भी क्रान्तिकारियों के सम्मुख आने लगी। उसे जो भी कार्य सौंपा गया, सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। 'आतंक के राज्य' के समय उसने अनेक विद्रोहों को शान्त करने में भाग लिया। पर नैपोलियन को विशेष उन्नति का अवसर तब मिला, जब डाइरेक्टरी की सरकार स्थापित हुई। डाइरेक्टरी का एक सदस्य जनरल बरा उस पर मेहरबान था। इसकी सहायता से उसने क्रान्ति के प्रमुख नेताओं से परिचय प्राप्त किया। पेरिस के बड़े लोगों में उसका आना जाना होने लगा। इसी समय नैपोलियन ने सेनापति बोआर्ने की विधवा श्रीमती बोआर्ने से विवाह किया। सेनापति बोआर्ने को 'आतंक के राज्य' में कतल किया गया था। उसकी विधवा अनुपम सुन्दरी तथा प्रभावशाली महिला थी। उसके साथ विवाह कर लेने से नैपोलियन का महत्त्व व प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया। वह भी फ्रांस के महत्त्वपूर्ण और बड़े आदमियों में गिना जाने लगा। डाइरेक्टरी की सरकार ने जब आस्ट्रिया पर विजय करने के लिये आक्रमण की योजना बनाई, तो जनरल बरा के प्रयत्न तथा श्रीमती बोआर्ने के प्रभाव से उसे उत्तरी इटली होकर आस्ट्रिया पर आक्रमण करनेवाली सेना का प्रधान सेनापति नियत किया गया। इस इटालियन आक्रमण के समय नैपोलियन की आयु केवल २६ वर्ष की थी। वह ५ फीट २ इंच ऊँचा था। उसका शरीर पीला, पतला सुकड़ा तथा देखने में बहुत कमजोर मालूम होता था। इस पतले सुकड़े नौजवान को जिस सेना का सेनापतित्व दिया गया था, उसके अन्य बहुत से अफसर उसकी अपेक्षा बहुत अधिक आयु के तथा अनुभवी थे। पर नैपोलियन ने इस आक्रमण में जिस वीरता तथा प्रतिभा का परिचय

दिया, उससे वह अपनी सेना का हृदयेश्वर बन गया। इतना ही नहीं, सारा फ्रांस और मारा यूरोप इस नौजवान की प्रतिभा से आश्चर्यचकित सा रह गया।

**इटालियन आक्रमण**—नैपोलियन ने किस प्रकार इटालियन आक्रमण में सफलता प्राप्त की, इसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। उसके हृदय में अभी मे वे महत्वाकांक्षाएँ विद्यमान थीं, जिन्होंने जागे चलकर उसे सम्राट् पद तक पहुँचा दिया। वह डाइरेक्टरी के अधीन सेनापति मात्र बने रहने में मन्तुष्ट नहीं रह सकता था। वह सम्राट् बनना चाहता था। यही कारण है, कि जब मिलान की विजय की गई, तो नैपोलियन न वाकायदा दरवार लगाया। मिलान के समीप एक मुन्दर स्थान पर नैपोलियन का शानदार दरवार लगा। फ्रेच मेना के मंत्र मेनापति तथा नायक निश्चित बर्दी पहनकर दरवारी तरीके से एकत्रित हुए। बीच में ऊँचे मिहामन पर नैपोलियन विराजमान हुआ। इटली के बहुत से बड़े-बड़े वैभवशाली अमीर आदमी इस नौजवान विजेता के दर्शनों के लिये पधारे। नैपोलियन का एक दृष्टिपात उनके लिये अहोभाग्य की वान थी।

इस दरवार के सिलसिले में नैपोलियन ने एक बातचीत में कहा था—अब तक जो कुछ मैंने किया है, वह तो कुछ भी नहीं है। यह तो मेरी शानदार सफलताओं का प्रारम्भ मात्र है। क्या तुम समझते हो, कि इटली में जो विजय मैंने प्राप्त की है, वह डाइरेक्टरी के वकीलों के लिये है? क्या तुम समझते हो, कि मेरा उद्देश्य वस्तुतः रिपब्लिक की स्थापना है? कैना फिजूल खयाल है डाइरेक्टरी मुझ से शानपतिन्व लेकर तो देखे, उसे मालूम पड़े जायगा कि असली मालिक कौन है? राष्ट्र को एक स्वामी की आवश्यकता है, पर वह स्वामी राज्यशास्त्र के सिद्धान्तों पर बहस करनेवाला नहीं होना चाहिये, अपितु शानदार कृत्यों से उसकी कीर्ति उज्ज्वल हुई होनी चाहिये।

निस्सन्देह, नैपोलियन का यही राजनीतिक सिद्धान्त था। जिस समय वह राज्यक्रान्ति की विजयपताका को आल्प्स की पर्वतमाला पर फहरा रहा था, उस समय भी वह १६वें लुई की तरह द बार लगाने की फिकर में था, उस समय भी वह रिपब्लिक का जन्म कर वय सम्राट् बनने का स्वप्न ले रहा था। कोसिका के एक गरीब वकील का लटका इस छोटी सी उमर में न केवल फ्रांस अपितु सम्पूर्ण यूरोप का वादशाह बनने की धुन में था। उसकी यह आकांक्षा कितनी महान् थी, पर उसमें उसे सफलता भी कितने शानदार रूप में प्राप्त हुई।

उत्तरी इटली की विजय और आस्ट्रिया के साथ सन्धि कर चुकने के अनन्तर नैपोलियन फ्रांस वापस आया। पर अभी उपयुक्त समय नहीं आया था। वह ईजिप्ट चला गया। वहाँ उसे बहुत सफलता प्राप्त नहीं हुई। एकर के मैदान में तुर्की सेनाओं ने उसे परास्त किया। पर दूर बैठे हुए फ्रेच लोगों की दृष्टि में ईजिप्ट में वह असाधारण रूप से उज्ज्वल कारनामे कर रहा था। जब फ्रांस के विरुद्ध यूरोपियन राज्यों का नया गुट तैयार हुआ, तो नैपोलियन अपनी सेना को इकला छोड़कर स्वयं वापिस चला आया। जिस अवसर की वह प्रतीक्षा कर रहा था, वह अब उपस्थित हो गया था।

**डाइरेक्टरी का अन्त**—यूरोपियन राज्यों का मुकाबला करने के लिये फ्रांस को एक योग्य सेनापति की आवश्यकता थी। डाइरेक्टरी के वकील और भद्रपुरुष इस विकट



परिस्थिति में फ्रांस की रक्षा नहीं कर सकते थे। डाइरेक्टरी का शासन भी सर्वथा असन्तोषजनक था। परिणाम यह हुआ, कि नैपोलियन के नेतृत्व में डाइरेक्टरी का अन्त करने के लिये एक पड़्यन्त्र तैयार किया गया। व्यवस्थापन विभाग की दोनों सभाओं के अनेक सदस्य इन पड़्यन्त्रकारियों के साथी तथा सहायक थे। यह निश्चय किया गया, कि नैपोलियन अपने विश्वासपात्र सिपाहियों के साथ 'पाच सौ की सभा' पर हमला करे, और वहाँ जाकर अपने विरोधियों को बाहर निकाल दे। ऐसा ही किया गया। ९ नवम्बर, १७९९ के दिन जब 'पाच सौ की सभा' का अधिवेशन हो रहा था, नैपोलियन ने अपने सिपाहियों के साथ सभाभवन को घेर लिया। विरोधियों को एक-एक कर के बाहर कर दिया गया। केवल वे ही लोग बच गये, जो नैपोलियन के साथी व पक्षपाती थे। लूसियन बोनापार्ट के—यह नैपोलियन का भाई था, और 'पाच सौ की सभा' का अन्यतम सदस्य था—सभापतित्व में 'पाच सौ की सभा' का या उसके खण्डहर का अधिवेशन किया गया और निश्चय हुआ, कि डाइरेक्टरी की सरकार का अन्त कर शासनशक्ति तीन 'कौसलो' के हाथ में दे दी जाय, प्रधान कौन्सल नैपोलियन बोनापार्ट को बनाया जाय और ये तीनों कान्सल देश के लिये एक नवीन शासनविधान तैयार करे। डाइरेक्टरी का अन्त हो गया, और नैपोलियन के लिये अपनी महत्त्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने का द्वार खुल गया।

**नवीन शासन-विधान**—नवीन शासन-विधान का निर्माण करने में बहुत देर नहीं लगी। यह नया विधान मुख्यतया नैपोलियन की ही कृति था। इस द्वारा चार सभाओं की रचना की गई। एक सभा का कार्य कानून प्रस्तावित करना था, दूसरी सभा उस पर वृत्त करती थी। तीसरी सभा उस पर वोट देने के लिये थी और चौथी सभा यह निर्णय करती थी, कि कानून शासन-विधान के अनुकूल है या प्रतिकूल। इन सभाओं में सबसे प्रधान स्थान पहली सभा को था, जिसे राज्य-परिषद् कहते थे। यह केवल कानून प्रस्ताविन ही नहीं करती थी, साथ ही कानूनों का प्रयोग करना, शासन करना, और विदेशी मामलों तथा मेना का प्रबन्ध करना भी इसी का कार्य था। नैपोलियन बोनापार्ट स्वयं इसका सभापति बना और इसमें सब दलों के बुद्धिमान् लोगों को रखा गया। 'कौसलो' की व्यवस्था पहले के समान ही रखी गई, और नैपोलियन को ही प्रधान कौन्सल बनाया गया।

केन्द्रीय सरकार में इन परिवर्तनों के अतिरिक्त प्रान्तीय तथा स्थानीय सरकारों के स्वरूप में भी बहुत से परिवर्तन किये गये। नैपोलियन राजशक्ति को एक केन्द्र में केन्द्रित करना चाहता था। वह सारे देश का शासन पेरिस से ही संचालित करना चाहता था। इसीलिये उसने प्रत्येक प्रान्त में केन्द्रीय सरकार की तरफ से एक-एक सूबेदार को नियत करने की व्यवस्था की। इसी प्रकार प्रत्येक प्रान्त के अन्य छोटे विभागों में नायब सूबेदार नियत किये गये। नगरों के मेयर तथा पुलिस के प्रधान कर्मचारी तक केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत किये जाने लगे। और क्योंकि केन्द्रीय सरकार में वास्तविक शक्ति प्रधान कौंसल अथवा नैपोलियन के पास थी, अतः इन सब अफसरों की नियुक्ति उसी के हाथों में आ गई। देश के वास्तविक शासन में लोकसत्तावाद के तत्त्व नष्ट हो गये, और फिर से पुराने राजसत्ता के युग की स्थापना का सूत्रपात हुआ। राज्यक्रान्ति का प्रमुख तत्त्व यही था कि राज्यशक्ति को जनता के हाथों में दिया जाय, शासनकार्य कौन करे और किस प्रकार

करे—इसका निर्णय जनता स्वयं किया करे। पर १७९९ के इस नये शासन-विधान ने इस सब पर पानी फेर दिया। प्रान्तीय और स्थानीय सभाओं का महत्त्व लुप्त हो गया। वास्तविक शक्ति उन सूवेदारों और नायब सूवेदारों के हाथ में आ गई, जो प्रधान कांसल के प्रति जिम्मेवार थे, जनता के प्रति नहीं।

जनता द्वारा स्वीकृति—नैपोलियन शासन के मामलों में जनता की इच्छा को कोई महत्त्व नहीं देता था। वह कहता था, मामलों का राज-काज के मामलों को जानने ही क्या है? यहाँ तब उसमें और १६वें लुई में कोई भेद न था। पर उमका यह भी मयाल था, कि शासन का प्रकार क्या हो—इस विषय में सर्वसाधारण जनता को अपनी राय प्रगट करने का अधिकार है। यहाँ पर वह १६वें लुई में मतभेद रग्यता था। अपने विचारों के अनुसार उसने आवश्यक समझा, कि नये शासन-विधान को जनता द्वारा स्वीकृत करा लिया जाय। जनता की सम्मति ली गई। तीस लाख में अधिक लोगों ने नये शासन-विधान के पक्ष में वोट दिया। विरोध में सम्मति देनेवालों की संख्या १५६२ थी। यह नहीं समझना चाहिये, कि अधिकांश जनता इस शासन-विधान से मनुष्ट थी। बहुत में लोग इसमें परिवर्तन चाहते थे, पर उन्हें तो केवल पक्ष या विपक्ष में वोट देना था। इसे सर्वथा अस्वीकृत कर देने की अपेक्षा वे इसके पक्ष में वोट देना अधिक अच्छा समझते थे। बहुत में प्रश्न ऐसे होते हैं, जिन पर 'हाँ' या 'नहीं' में सम्मति नहीं दी जा सकती। शासन-विधान तो मुख्यतः इसी तरह का विषय है। नैपोलियन की इस सफलता का प्रधान कारण यह है, कि लोग एक स्थिर सरकार चाहते थे। अव्यवस्था और अस्थिरता में वे अब ऊब चुके थे। उन्हें आशा थी, कि नैपोलियन जैसा बहादुर आदमी जहाँ विदेशी शत्रुओं को परास्त करने में सफल होगा, वहाँ देश में भी व्यवस्था कायम रख सकेगा।

नैपोलियन प्रधान कांसल बन गया। वह वस्तुतः देश का राजा था, पर नाम में नहीं। नैपोलियन सबसे सतुष्ट नहीं रह सकता था। उसकी हार्दिक महत्वाकांक्षा के पूर्ण होने में अभी कुछ कसर बाकी थी।

## २ प्रधान कांसल के रूप में नैपोलियन का शासन

यूरोपियन राज्यों का नया गुट—फ्रांस के खिलाफ यूरोपियन राज्यों का जो नया गुट बना था, जिसके कारण नैपोलियन को अपने अभ्युदय का यह सुवर्णवसर मिला था, उसमें इङ्ग्लैण्ड, रूस, आस्ट्रिया और टर्की—ये चार राज्य शामिल थे। यह नया गुट क्या बना था, इस बात की व्याख्या की जरूरत है। इसे भलीभाँति समझने के लिये डाइरेक्टरी के शासन की कुछ महत्त्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख करने की आवश्यकता होगी।

नये रिपब्लिकन राज्यों की स्थापना—कैम्पो फोर्मियो की सन्धि के बाद (अक्टूबर, १७९७) फ्रांस यूरोप के किसी भी देश के साथ युद्ध में व्यापृत नहीं रहा था। उस समय भी अगर कोई राज्य फ्रांस से सघर्ष कर रहा था, तो वह केवल इङ्ग्लैण्ड ही था। पर इङ्ग्लैण्ड के युद्धों का यूरोप से कोई सम्बन्ध न था। इस प्रकार सब यूरोपियन राज्यों की फ्रांस से पूर्ण सन्धि थी। पर इस बीच में भी—इस सन्धि और शान्ति के काल में भी—फ्रांस के क्रान्तिकारी सिद्धान्त पड़ोस के अन्य देशों में क्रान्ति की भावना को फैला रहे थे। फ्रेंच

रिपब्लिक के नमूने पर समीप के राज्यों में भी नवीन शासन-विधानों की स्थापना हो रही थी। उत्तरी इटली में किसल्पाइन रिपब्लिक की स्थापना कर दी गई थी। नीदरलैंड में राजतन्त्र को नष्ट कर रिपब्लिक स्थापित कर दी गई थी। इस नई रिपब्लिक का नाम वेंदेवियन रिपब्लिक रखा गया था। फ्रांस के क्रान्तिकारियों ने उत्तरी इटली के एक अन्य प्राचीन राज्य जिनाआ में क्रान्ति कराके वहाँ लिगूरियन रिपब्लिक के नाम से एक नये लोकतन्त्र राज्य की स्थापना कर दी थी। नई रिपब्लिकों का सिलसिला यही पर खतम नहीं हुआ। नैपोलियन का भाई जोसफ बोनापार्ट रोम में फ्रांस का राजदूत था। उसके उकसाने पर रोम में विद्रोह हुआ। वहाँ के क्रान्तिकारी लोग पोप के शासन के खिलाफ उठ खड़े हुए। खुल्लम-खुल्ला गदर हो गया। इस गदर में एक फ्रेंच सेनापति मारा गया। फ्रेंच सेनापति का मारा जाना डाइरेक्टरी के लिये काफी अच्छा वहाँना था। उन्होंने एक सेना रोम में पोप के शासन का अन्त कर रिपब्लिक स्थापित कराने के लिये रवाना कर दी। इस सेना की मदद से रोम में रिपब्लिक की स्थापना की गई। पोप का अपमान किया गया। वार्षिक तथा राजकीय चिह्नों को छीनकर उसे रोम से बाहर निकाल दिया गया। इस प्रकार रोमन रिपब्लिक स्थापित की गई। स्विट्जरलैंड में भी इसी ढंग से फ्रेंच नमूने पर हेल्वेटिक रिपब्लिक कायम की गई। इस श्रेणी में आने वाले भी राजतन्त्र शासन विद्यमान न थे। स्विट्जरलैंड अने छोटे-छोटे प्रदेशों में, जिन्हें कैंटन कहा जाता है, विभक्त था। प्रत्येक कैंटन की अपनी अलग-अलग सरकार थी, और इन विविध कैंटनों को मिलाकर एक केन्द्रीय सगठन भी बना हुआ था। इसका शासन कतिपय कुलीन श्रेणियों के हाथ में था।

कुछ आन्तरिक झगड़ों से लाभ उठा कर फ्रेंच सेना ने स्विट्जरलैंड पर आक्रमण किया और श्रेणितन्त्र शासन का अन्त कर वहाँ हेल्वेटिक रिपब्लिक की स्थापना कर दी। नेपल्स में भी यही हुआ। पोप के राज्य में रिपब्लिक की स्थापना से नेपल्स का राजा बहुत भयभीत हो गया था। उसका खयाल था, कि यदि अपनी राजगद्दी को कायम रखना है, तो रोम में फिर से पोप के आधिपत्य को स्थापित करना चाहिये। इसलिये उस ने इङ्ग्लैंड के साथ मिलकर फ्रांस के विरुद्ध युद्ध उद्घोषित कर दिया। इस पर फ्रांस की एक सेना ने नेपल्स पर आक्रमण किया। बात की बात में नेपल्स परास्त हो गया। वहाँ भी पुराने राजतन्त्र राज्य का अन्त कर एक नवीन रिपब्लिक की स्थापना की गई, और उसका नाम पार्थेनोपियन रिपब्लिक रखा गया। इसके कुछ ही दिनों बाद फ्रांस की सेनाओं ने पीडमौन्ट पर आक्रमण किया। पीडमौन्ट परास्त हो गया। वहाँ का राजा भागकर सार्डिनिया के द्वीप में चला गया। पीडमौन्ट पर भी फ्रांस का आधिपत्य कायम हो गया।

ये सब घटनाएँ डाइरेक्टरी के शासनकाल में हुई थी। इनका परिणाम यह हुआ, कि फ्रांस की शक्ति बहुत बढ़ गई। हालैंड, स्विट्जरलैंड और सम्पूर्ण इटली पर फ्रांस का आधिपत्य हो गया। ये जो नई रिपब्लिकें बनी थी, वे पूणतया फ्रांस के प्रभाव में थी। इस समय फ्रांस सर्वत्र विजयी हो रहा था।

**नये गुट का निर्माण**—फ्रांस की यह असाधारण सफलता अन्य यूरोपीय राज्यों को नष्ट नहीं हुई। इसके अतिरिक्त, क्रान्तिकारी सिद्धान्तों का इस प्रकार विस्तार एकतन्त्र राजाओं के लिये भयकर खतरा था। यही कारण है, कि इङ्ग्लैंड अन्य अनेक राज्यों

को फ्रांस के खिलाफ लड़ने के लिये सुगन्त से तैयार कर सका। रूस का जार पात्र (राज्यारोहण काल १७९६ ई०) क्रान्ति का कट्टर दुश्मन था। इङ्ग्लैण्ड के चतुर प्रधान मन्त्री पिट ने इस शक्तिशाली सम्राट को फ्रांस के खिलाफ लड़ने के लिये तैयार कर लिया। निश्चय हुआ, कि जार अपनी सेनाएं फ्रांस में युद्ध करने के लिये भेजेगा और उनका खर्च इङ्ग्लैण्ड देगा। फ्रांस को कुचलने के इस भगीरथ प्रयत्न में सहायता देने में आस्ट्रिया का हार्दिक खुशी थी। वह भी इङ्ग्लैण्ड और रूस के साथ सम्मिलित हो गया। नैपोलियन के इजिप्शियन युद्धों के कारण टर्की के सुल्तान ने भी फ्रांस के खिलाफ युद्ध उद्घोषित कर दिया था—इसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। इस प्रकार डाइरेक्टरी के शासनकाल में ही इन चारों राज्यों का नया गुट फ्रांस के विरुद्ध बन गया था। इसी गुट का मुकाबला करने में डाइरेक्टरी की असमर्थता देखकर नैपोलियन ने उनके विरुद्ध पट्यन्त्र किया था, और जब प्रधान कौन्सल के पद पर अधिष्ठित होकर नैपोलियन को सब में पहले इसी गुट का मुकाबला करना था।

**युद्ध का प्रारम्भ**—यूरोपियन राज्यों का यह नया गुट फ्रांस के लिये बहुत हानिकारक सिद्ध हुआ। एकदम परिस्थिति ने पलटा साया। जो फ्रांस पहले सर्वत्र विजयी और मज्ज हो रहा था, वह अब सब तरफ से आक्रान्त हो गया। आस्ट्रियन सेनाओं ने फ्रांस को दक्षिणी जर्मनी में परास्त किया। रूसी सेनापति सुवेराफ ने आस्ट्रिया की सहायता में उत्तरी इटली से फ्रेंच सेनाओं को निकाल बाहर कर दिया और वहाँ में फ्रांस का कब्जा उठ गया। इस के बाद सुवेराफ ने स्विट्जरलैण्ड पर हमला किया। उसे आशा थी, कि एक अन्य तमी सेना जो उत्तर की तरफ से स्विट्जरलैण्ड को फ्रेंच अधीनता से मुक्त कराने के लिये आरम्भ कर रही थी, उसकी सहायता उसे प्राप्त हो जायगी और ये दोनों तमी सेनाएँ मिलकर स्विट्जरलैण्ड को स्वतन्त्र करा देंगी। पर उसे निराश होना पड़ा। जिस रूसी सेना ने उत्तर की तरफ से हमला किया था, वह फ्रेंच लोगों द्वारा परास्त की जा चुकी थी। सुवेराफ बहुत भयंकर कठिनाइयों का मुकाबला कर स्विट्जरलैण्ड पहुँचा था। उसे आग्स पर्वत-माला के विकट दरों को लाघना पड़ा था। इतनी कठिनाइयों का मुकाबला कर जब उसे निराश होना पड़ा, तो रूस का जार घबरा गया। उसने समझा कि आस्ट्रिया की वैईमानी और साजिशें रूसी सेनाकी असफलता की हेतु हैं। उसने आस्ट्रिया से सब सम्बन्ध विच्छिन्न कर दिया और सुवेराफ को वापिस बुला लिया।

**नैपोलियन द्वारा संधि का प्रयत्न**—इसी बीच में फ्रांस में डाइरेक्टरी का पतन हुआ और नैपोलियन के एकाधिकार का सूत्रपात हुआ। प्रधान कौन्सल नैपोलियन ने इङ्ग्लैण्ड के राजा जार्ज तृतीय और आस्ट्रियन सम्राट फ्रांसिस द्वितीय को वैयक्तिक पत्र भेजे। उसने लिखा—युद्ध करने से क्या लाभ है? यूरोप के पवित्र और धार्मिक सम्राट आपस में क्यों लड़ें? व्यापार, व्यवसाय, सुख, समृद्धि और शान्ति के महान् लाभों का खोखले वडपन के लिये क्यों कुर्बान किया जाय? नैपोलियन के इस सन्देश पर इङ्ग्लैण्ड ने कोई ध्यान नहीं दिया। प्रधान मन्त्री पिट ने उत्तर में लिखा, कि युद्ध की वास्तविक उत्तरदायिता फ्रांस पर है। यदि फ्रांस को सचमुच शान्ति की इच्छा है, तो उसका एकमात्र उपाय यह है, कि फिर से वृत्तों राजवंश का एकच्छत्र शासन स्थापित कर दिया जाय। ब्रिटन

मे इस समय पार्लियामेंट का जो 'वैध शासन' स्थापित था, वह फ्रांस में फिरसे निरकुश व रवेच्छाचारी सरकार की स्थापना के लिये उत्सुक था। वस्तुतः, अभी त्रिटोन में जनता का शासन प्रारम्भ नहीं हुआ था। आस्ट्रिया का उत्तर भी इसी प्रकार निराशाजनक था। नैपोलियन ने शान्ति के लिये जो हाथ बढाया था, इन दोनों राज्यों ने उसे घृणापूर्वक ठुकरा दिया। रिणाम यह हुआ, कि नैपोलियन ने युद्ध के लिये जे जो से तैयारी शुरू कर दी।

**आस्ट्रिया की पराजय**—आस्ट्रिया पर दो तरफ से आक्रमण करने की योजना की गई। सेना, जो मूरो को रूहाइन की तरफ से आक्रमण के लिये भेजा गया। नैपोलियन ने स्वयं आल्प्स की विकट और दुर्गम पर्वतमालाओं को पार कर सीधा आस्ट्रिया पर हमला करने का निश्चय किया। आस्ट्रिया पर हमला करने का यह बहुत ही विकट मार्ग था। सम्भवतः, प्रसिद्ध कार्पेजियन सेनापति हैनीवाल के बाद किसी अन्य सेनापति ने इस मार्ग का अवलम्बन करने का साहस नहीं किया था। उस समय में आल्प्स की पर्वतमाला पर कोई भडक विद्यमान नहीं थी। इसलिये मोटे-मोटे वृक्षों के तनों को खोखला कर उनमें तोपों को बन्द किया गया, और इस प्रकार वृक्षों के तनों को लुडका-लुडकाकर आल्प्स के पार पहुँचाया गया। आस्ट्रियन लोगों को स्वप्न में भी सम्भावना नहीं थी, कि आल्प्स की दुर्गम पर्वतमाला को पार कर कोई सेना उस पर आक्रमण कर सकती है। जब नैपोलियन आस्ट्रिया के मैदान में अपनी सेना सहित प्रवेश कर गया, तो उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। मनो नामक रणक्षेत्र में १४ जुलाई, सन् १८०० के दिन भयंकर लड़ाई हुई, जिसमें नैपोलियन की विजय हुई। आस्ट्रियन सेना बुरी तरह परास्त हो गई। दूसरी तरफ सेनापति मूरो भी निरन्तर आगे बढ़ रहा था। होहनलिण्डन नामक स्थान पर उसने आस्ट्रियन सेना को परास्त किया। इन दो पराजयों का यह परिणाम हुआ, कि आस्ट्रिया को सन्धि के लिये प्रार्थना करने को बाधित होना पड़ा। आखिर ९ फरवरी, १८०१ को फ्रांस और आस्ट्रिया में सन्धि हो गई। यह सन्धि लूनेविल की सन्धि के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें प्रधानतया कैम्पो फोर्मियो की सन्धि की शर्तों को ही फिर से दुहराया गया। आस्ट्रियन नीदरलैंड पर फ्रांस का अधिकार पुनः स्वीकृत किया गया। वैंटेवियन, हैल्वटिक, लिगूरियन, और किसल।इन रिपब्लिकों को पुनः संगठित किया गया और इनकी फ्रांस के अधीन सत्ता को आस्ट्रिया ने स्वीकृत किया। इसके अतिरिक्त, यह इन नदी के बायें तट पर भी फ्रांस के अधिकार को स्वीकृत किया गया। लूनेविल की इस सन्धि से फ्रांस की स्थिति बहुत सुदृढ़ हो गई। यूरोपियन राज्यों के दूसरे गुट ने उसको जो कुछ नुकसान पहुँचाया था, वह सब दूर हो गया।

**आमीन की सन्धि**—आस्ट्रिया के साथ सन्धि हो जाने पर अन्य राज्यों से सन्धि का माग साफ हो गया। रूस तो पहले ही आस्ट्रिया से नाराज होकर युद्ध से पृथक् हो चुका था। इंग्लैंड की शक्ति विशेष रूप से समुद्र में थी। ईजिप्ट में विद्यमान फ्रेंच सेना को (जिसे मेना जिमे लेकर नैपोलियन ईजिप्ट की विजय के लिये भेजा था, और जिसे निराश्रय छोड़कर वह स्वयं डाइरेक्टरी का अन्त करने के लिये फ्रांस चला आया था) इंग्लैंड जहाँजी बड़ा परास्त कर चुका था। अब और अधिक युद्ध जारी रखना निरर्थक था। फ्रांस और इंग्लैंड में भी आखिरकार सन्धि हो गई, जो कि आमीन की सन्धि के नाम से प्रसिद्ध

है। फ्रांस और इङ्ग्लैण्ड में आठ मास में निरन्तर युद्ध जारी था। दोनों राज्य अपनी सामुद्रिक प्रभुता तथा साम्राज्य विस्तार के लिये मघर्ष कर रहे थे। पिट फ्राम का कट्टर शत्रु था। वह फ्राम के पतन में ही इङ्ग्लैण्ड का अभ्युदय देखता था। १८०२ में पिट प्रधान मन्त्री न रहा। उसके पतन के अनन्तर ही फ्राम के साथ सन्धि सम्भव हो सकी। आमीन की इस सन्धि के अनुसार इङ्ग्लैण्ड ने फ्रांस की नवीन सरकार की मत्ता को स्वीकार किया। सीलोन और ट्रिनिडाड के अतिरिक्त अन्य मग्न फ्रेच उपनिवेश जो कि पिछले युद्ध में इङ्ग्लैण्ड ने फ्रांस में जीतकर अपने अधीन कर लिये थे—फ्राम को वापस दे दिये गये। लूनेविल की सन्धि की सब शर्तों को इङ्ग्लैण्ड ने भी स्वीकार किया। फ्रांस की राज्यक्रान्ति के बाद यह पहला अवसर था, जब कि यूरोप में लड़ाई बन्द होकर शान्ति की स्थापना हुई।

### ३. व्यवस्था की स्थापना

**नैपोलियन का विधायक कार्य**—यूरोपियन राज्यों में युद्ध की समाप्ति के पश्चात् नैपोलियन ने अपनी शक्ति का उपयोग फ्राम में व्यवस्था और शान्ति स्थापित करने के लिये किया। नैपोलियन केवल अनुपम योद्धा और विजेता ही नहीं था, विधायक कार्यों में न उनका असाधारण शक्ति और क्षमता प्रगट हुई थी। क्रान्ति के कारण फ्राम में पुराने जमाने का तो अन्त हो गया था, पुरानी मस्याएँ नष्ट-भ्रष्ट हो गई थी, पर नवीन रक्त और नवयुग की स्थापना का कार्य अभी तक नहीं किया जा सका था। रिपब्लिक के नाम में भी इसके लिये प्रयत्न किया गया था। पर आन्तरिक और बाह्य युद्धों के कारण क्रान्ति कारियों को इसके लिये उपयुक्त अवसर नहीं प्राप्त हो सका था। जब इनके समय के बाह्य इन युद्धों का अन्त हुआ था। अब इस बात का अवसर आ गया था, कि नये युग की स्थापना की जाय। इसमें सन्देह नहीं, कि नैपोलियन ने यह कार्य पर्याप्त सफलता के साथ सम्पन्न किया। नैपोलियन बाहर से यही प्रदर्शित करता था, कि वह राज्यक्रान्ति के सिद्धान्तों को ही क्रिया में परिणत कर रहा है। स्वाधीनता, समानता और भ्रातृभाव के उदात्त सिद्धान्तों का ही उसे अनुसरण करना है। क्रान्ति की नई कृतियों—रिपब्लिक, मनुष्यमान को मताधिकार, सामाजिक समता आदि को उसे अक्षुण्ण रखना है। पर मुह से यह कहें हुए भी वस्तुतः नैपोलियन राजनीतिक स्वाधीनता की जड़ पर कुटाराघात कर रहा था। वह शासन और व्यवस्थापन की सम्पूर्ण शक्ति को अपने ही हाथों में रखना चाहता था। और तो और रहा, न्यायालय भी वस्तुतः उसी के कब्जे में थे। पुलिस भी उसी के इशारा पर नाचती थी। कानूनों का वह इस ढंग से प्रयोग करता था, मानो फ्रांस में फौजी कानून जारी हो। सम्भवतः, उस समय की परिस्थितियों में यही उचित और आवश्यक था। बाहर से लोकतन्त्र शासन के सम्पूर्ण ढाँचे को कायम रखा गया था। बाहरी शरीर लोकतन्त्र और रिपब्लिक का था। पर असली शासन एक व्यक्ति की इच्छा पर आश्रित हो गया था। नैपोलियन का विश्वास था, कि फ्रांस को एक शक्तिशाली और मजबूत शासन की जरूरत है, जो कि देश में व्यवस्था और शान्ति स्थापित रख सके। निस्सन्देह, नैपोलियन का यह विचार ठीक था। मतभेद, पार्टीबन्दी और झगड़ों का अन्त करने के लिये उसने सब दलों के लोगों को एक समान रूप से राजनीतिक पद दिये। देश से बहि-

प्लूट कुलीन श्रेणी तथा उच्च पुरोहित श्रेणी के लोगो को फिरसे फ्रांस वापस आने की अनुमति दी। एप्रिल, १८०२ में क्रान्ति के विरुद्ध अपराध करनेवालो को एक सार्वजनिक उद्घोषणा द्वारा क्षमा प्रदान कर दी गई। इस के परिणाम-स्वरूप चालीस हजार से अधिक परिवार फ्रांस वापस लौट आये। क्रान्ति के समय की बहुत सी बातों को हटा दिया गया। अब प्रत्येक आदमी के लिये यह आवश्यक नहीं रह गया, कि वह दूसरे को 'नागरिक' शब्द से ही सम्बोधन करे। अब कूल और स्थिति के अनुसार 'श्रीमान्' 'हुजूर' आदि शब्दों का पुनः प्रयोग किया जाने लगा। नैपोलियन के रहन-सहन में भी अन्तर आने लगा। टुइलरी के राजप्रासाद में फिर रौनक, शानशौकत और धूमधाम नजर आने लगी। वूर्वों वंश के राजाओं का स्थान कोर्सिका के गरीब वकील के लडके ने ले लिया। कलेवर दूसरा था, पर आत्मा वही थी। नये रूप में फिर से वूर्वों ढग का एकतन्त्र राज्य फ्रांस में स्थापित हो गया। फ्रांस ने क्रान्ति की ओर जो पग बढ़ाया था, वह मार्ग में ही रुक गया। निस्सन्देह, फ्रांस जहाँ पहले विद्यमान था, अब वहाँ से आगे बढ़ गया था। पर उसने जो ऊँची उड़ान उड़नी चाही थी, उसमें वह असफल रहा था। वह तेजी से आगे बढ़ा था, पर अपने उद्देश्य तक न पहुँच कर रास्ते में ही रह गया था। मानवीय उन्नति का यही ढग है। मनुष्य जाति छलांग मारकर उन्नति नहीं करती है, वह धीरे-धीरे कदम बढ़ाकर अगे बढ़ती है। 'आतंक के राज्य' में रोवस्पियर और हेबेर् फ्रांस को जहाँ तक खींच कर ले गये थे, वहाँ वह टिक नहीं सका। वह पीछे लौट आया, पर इसमें सन्देह नहीं, कि वह लौटकर उस जगह तक नहीं गया, जहाँ कि वह लुई १६वे के समय में विद्यमान था। नया समुत्तलन स्थापित होगया—पर पुराने और नये के बीच में, वूर्वों शासन और रिपब्लिक के मध्यवर्ती स्थान पर।

**नैपोलियन विधान**—नैपोलियन के विधायक कार्यों में सबसे मुख्य स्थान उसके 'विधान' का है, जो नैपोलियन-विधान के नाम से प्रसिद्ध है। क्रान्ति से पूर्व फ्रांस में बहुत प्रकार के विधान प्रचलित थे। क्रान्ति ने इस सबको नष्ट करके सम्पूर्ण फ्रांस में एक ही कानून को प्रचलित करने का प्रयत्न किया था। इसी उद्देश्य से क्रान्तिकारी सरकारों ने अनेक नये कानूनों का निर्माण भी किया था। परन्तु ये सब कानून किसी एक विधान में संकलित नहीं थे। इसलिये नैपोलियन ने एक कमीशन नियत किया, जिसको कि इन सम्पूर्ण कानूनों को संगृहीत कर एक व्यवस्थित विधान तैयार करने का कार्य सुपुर्द किया गया। नवीन विधान के मसविदे को राज्य परिषद् के सम्मुख पेश किया गया। कुछ परिवर्तनों के साथ वह स्वीकृत हो गया। फ्रांस के वर्तमान कानून का मुख्य आधार यह नैपोलियन-विधान ही है। केवल फ्रांस में ही नहीं, परन्तु हालैंड, ब्रिजियम, पश्चिमी और दक्षिणी जर्मनी, इटली और लुईसियेना के राज्यों के प्रचलित कानून भी मुख्यतया इसी विधान पर आश्रित हैं। इसका कारण यह है, कि उस समय इन देशों पर भी फ्रांस का आधिपत्य था, और इनमें भी यही विधान प्रचलित किया गया था। यूरोप के अन्य देशों पर भी इस विधान का प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है।

**धार्मिक नीति**—नैपोलियन को किसी विशेष धर्म में आस्था नहीं थी। ईजिप्ट में वह इसलाम का आदर करता था, और फ्रांस में रोमन कैथोलिक धर्म का। वह जानता था, कि फ्रांस की अधिकांश जनता कैथोलिक धर्म को मानने वाली है। इसलिये बुद्धिमत्ता इसी में है,

कि स्वयं भी कैथोलिक धर्म का अनुसरण किया जावे। क्रान्ति के समय ईसाई चर्च में पूर्णतया अव्यवस्था मच गई थी। नैपोलियन समझता था, कि जनता की सहानुभूति को प्राप्त करने के लिये उनके धार्मिक विश्वासों का सम्मान करना आवश्यक है। इसीलिये उसने कैंट में पड़े हुए पादरियों को स्वतन्त्र कर दिया। जिन्हे देश निकाला दिया गया था, उन्हें फिर से फ्रांस लौट आने की अनुमति दी गई। रविवार को फिर से महत्त्व दिया गया। क्रान्ति के समय में जो नई छुट्टियां शुरू हुई थी, उन सब को हटा दिया गया। केवल १४ जुलाई, जो कि वस्तीय के जल के नवम का दिन था, तथा २० मितम्बर को—जो कि रिपब्लिक की स्थापना का दिन था, सार्वजनिक छुट्टी के तौर पर कायम रखा गया। क्रान्ति के समय की अन्य सब छुट्टियों को हटाकर फिर से धर्म पर आश्रित पुरानी छुट्टियों को जारी किया गया। यह सब जनता की सहानुभूति को प्राप्त करने के लिये ही था।

**कान्कार्डेट**—रोमन कैथोलिक चर्च की पुन स्थापना करने के लिये मितम्बर, १८०१ में पोप से वाकायदा सन्धि की गई। यह सन्धि 'कान्कार्डेट' के नाम से प्रसिद्ध है। इस कान्कार्डेट में उद्घोषित किया गया, कि फ्रांस की अधिकांश जनता रोमन कैथोलिक धर्म को माननेवाली है, अतः फ्रांस में इसी धर्म को राजकीय धर्म स्वीकृत किया जाना चाहिये। विशपो तथा चर्च के अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति प्रधान कौन्सिल द्वारा की जायगी, पर उसके लिये पोप से स्वीकृति लेनी आवश्यक होगी। बिशपो तथा अन्य पुरोहिता को राज्य की तरफ से वृत्ति दी जायगी। सब पुरोहितों के लिये आवश्यक होगा कि वे रिपब्लिक के शासनविधान के प्रति भक्ति की शपथ लें। चर्च की सम्पूर्ण सम्पत्ति क्रान्ति के समय में राज्य ने छीन ली थी। निश्चय किया गया कि जो सम्पत्ति अभी बची नहीं गई है, वह चर्च के सुपुर्द कर दी जाय। पर जो सम्पत्ति किसी व्यक्ति को बच दी गई है, उनको न छेड़ा जाय। इस सन्धि के अनुसार राज्य और चर्च को पृथक् नहीं रहने दिया गया। चर्च भी एक प्रकार से राज्य की ही अधीनता में आ गया। यद्यपि नाममात्र को पोप का आधिपत्य कायम रखा गया था, और बिशप आदि की नियुक्ति के लिये भी पोप की स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक थी, पर ये सब बातें नाम की ही थीं। वस्तुतः चर्च पर प्रधान कौन्सिल का, राज्य का ही अधिकार कायम हो गया था। इस प्रकार यद्यपि ऊपर से रोमन कैथोलिक चर्च का संगठन क्रान्ति से पहले जमाने का सा ही था, पर असल में उसमें भारी परिवर्तन हो गया था। अब न चर्च के न्यायालय रहे थे, और न चर्च के पृथक् टैक्स। अब चर्च राज्य का प्रतिद्वन्द्वी नहीं था, अब वह राज्य के अधीन एक सत्सामान्य था। सम्भवतः नैपोलियन चर्च के इस पुनरुद्धार का भी पक्षपाती नहीं था। पर जनता की सहानुभूति प्राप्त करने के लिये इसकी आवश्यकता थी, और इसीलिये उसने निस्संकोच भाव से इसे पुन स्थापित किया।

**शिक्षा प्रसार**—शिक्षा के प्रसार के लिये भी नैपोलियन ने विशेष रूप से प्रयत्न किया। प्रत्येक नगर में शिक्षणालयों की स्थापना की गई। शिक्षकों को राज्य की ओर से वेतन दिया जाने लगा। शिल्प और व्यवसाय के लिये विद्यालय खोले गये। पेरिस के विश्व-विद्यालय का पुन संगठन किया गया। सब शिक्षणालयों में राजभक्ति की शिक्षा देने के लिये विशेष रूप से जोर दिया गया। विद्या और शिक्षा के प्रसार के लिये भरसक



कोशिश की गई।

**आर्थिक नीति**—राज्यक्रान्ति के कारण फ्रांस की आर्थिक दशा पहले की अपेक्षा भी अधिक खराब हो गई थी। टैक्स नियमित रूप से वसूल नहीं हो पाते थे। रिपब्लिकन सरकार ने जो पत्र-मुद्राएँ जारी की थी, उनकी कीमत बहुत अधिक गिर गई थी। बाजार में उन्हें कोई पूछता नहीं था। डाइरेक्टरी आर्थिक दृष्टि से विलकुल दिवालिया हो गई थी। प्रधान कौन्सल के पद पर अधिष्ठित हो जाने पर नैपोलियन ने इस दशा में सुधार करने का प्रयत्न किया। उस के व्यवस्थित शासन में सरकारी टैक्स फिर से नियमित रूप से वसूल होने लगे। राष्ट्रीय ऋण को अदा करने के लिये एक नई निधि की स्थापना की गई। पुरानी गवर्नमेंट सिक्कूरिटी (सरकारी कागज) को अदा करने के लिये नई सिक्कूरिटी जारी की गई। फ्रांस के आर्थिक जीवन को सुव्यवस्थित करने के लिये बैंक ऑफ फ्रांस (१८००) की स्थापना की गई, और सरकार की आर्थिक नीति को संचालित करने का कार्य इस बैंक के सुपुर्द किया गया। नैपोलियन ने यह यत्न भी किया, कि फ्रांस के व्यवसायो और व्यापार में वृद्धि हो। व्यापार की उन्नति के लिये उसने पैंतीस नई सड़को का निर्माण किया, जो पेरिस से फ्रांस के विभिन्न प्रदेशों को मिलाती थी। उसने आल्प्स की पर्वतमाला पर भी दो नई सड़को का निर्माण किया। इन सड़को का उपयोग केवल सैनिक दृष्टि से ही नहीं था, व्यापार के लिये भी ये बहुत सहायक थी।

व्यवसायो की उन्नति के लिये नैपोलियन ने ऐसे अनेक शिक्षणालयों की स्थापना की, जिनमें श्रमियों को मशीनों के प्रयोग की शिक्षा दी जाती थी। नये वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण इस समय यूरोप में मशीनरी का प्रयोग प्रारम्भ हो चुका था। नैपोलियन ने प्रयत्न किया, कि फ्रांस के व्यवसायो में इन यान्त्रिक आविष्कारों का अधिकतम उपयोग किया जाय। इसी उद्देश्य से उसने अनेक प्रदर्शनियों की भी योजना की, जिनमें उत्कृष्ट वस्तुओं पर पारितोषिक दिये जाते थे। इङ्ग्लैण्ड के तैयार माल के मुकाबले से फ्रांस के व्यवसायो की रक्षा करने के लिये नैपोलियन ने आयात-कर (इम्पोर्ट ड्यूटी) की भी व्यवस्था की। नैपोलियन को यह भी चिन्ता थी, कि फ्रांस का अपना विशाल साम्राज्य होना चाहिये, ताकि उसकी आर्थिक समृद्धि में सहायता पहुँचे।

इस प्रकार नैपोलियन निरन्तर फ्रांस को सगठित तथा व्यवस्थित करने में प्रयत्नशील रहा। परन्तु उसको महत्वाकांक्षा अभी पूर्ण नहीं हुई थी। वह एक रिपब्लिक के प्रधान कौन्सल के पद से ही सन्तुष्ट नहीं रह सकता था। वह सम्राट् बनना चाहता था, और अपनी इस आकांक्षा को पूर्ण करने में उसे देर नहीं लगी।

## ४ सम्राट् नैपोलियन

**नैपोलियन का सम्राट् बनना**—नैपोलियन सम्राट् बनना चाहता था। वस्तुतः, प्रधान कौन्सल के रूप में भी नैपोलियन की शक्ति, अधिकार और शानशौकत सम्राटों से कम नहीं थी, पर उसे रिपब्लिक का ढाँचा भी सह्य नहीं था। इसीलिये उसके आदेश से शासन-विधान में इस प्रकार के परिवर्तन किये गये, जिनसे वह पूर्ण रूप से सम्राट् पद पर अधिष्ठित हो गया। पहले नैपोलियन को दस वर्ष के लिये कौन्सल बनाया गया। फिर १८०२

में उसे जन्म भर के लिये कौन्सल बना दिया गया। इस के बाद उसे यह भी अधिकार दित गया, कि वह अपना उत्तराधिकारी भी स्वयं चुन सके। १८०८ में यह प्रस्ताव पेश किया गया, कि नैपोलियन को फ्रेंच जनता का सम्राट् बना दिया जावे। प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। यह प्रस्ताव नैपोलियन की प्रेरणा से ही पेश किया गया था, और उसी की कोशिश में पास हुआ था।

**राज्याभिषेक**—२ दिसम्बर, १८०८ के दिन नैपोलियन का राज्याभिषेक वूडू वूधाम के साथ हुआ। उसका अभिषेक-समारोह पुराने वूवा राजाओं के राज्याभिषेक को भी मात करता था। उम महत्त्वपूर्ण अवसर पर पोप भी उपस्थित हुआ। परन्तु अभिमानी नैपोलियन यह नहीं सह सका, कि पोप उसके मिर पर राजमुकुट रखे। उस में पहले कि पोप राजमुकुट को उठाये, उसने उसे स्वयं उठाकर अपने मिर पर रख लिया। नैपोलियन कहा करता था कि 'मैंने फ्रान्स के राजमुकुट को धूल में पड़ा पाया, और तलवार की नोक से उठाकर उसे अपने मिर पर रख लिया।' निम्नन्द्देह, नैपोलियन का यह दावा ठीक था। वह इसलिये सम्राट् नहीं बना था, क्योंकि वह किसी सम्राट् का लडका था। वह अपनी तलवार के जोर पर इस गौरवमय पद पर ही अविष्टित हुआ था।

**पुरानी राजसत्ता का प्रारम्भ**—सम्राट् बनकर नैपोलियन ने राज दरबार, अग-रक्षक, अनुचर, पार्श्वचर आदि का फिर से संगठन किया। नये दरबारियों को दरबार के उग और कायदों को सिखाने के लिये सेजर, जो कि एक भागा हुआ कुलीन श्रेणी का आदमी था, और मदाम डि सापेन को, जोकि पहले मेरी आनोआत की पार्श्वचर थी, नियत किया गया। नैपोलियन के परिवार के आदमियों को सबसे ऊंचे पद दिये गये। एक विशाल अङ्गरक्षक सेना का संगठन किया गया। नये सिरे से लोगों को खिताब दिये जाने लगे। इस प्रकार, एक नवीन कुलीन श्रेणी का निर्माण किया गया। यह नवीन कुलीन श्रेणी नैपोलियन की कृति थी। इसकी सत्ता एक आदमी की इच्छा पर आश्रित थी।

सम्राट् बन कर नैपोलियन निरन्तर अधिक से अधिक स्वेच्छाचारी तथा क्रूर होता गया। अब वह सार्वजनिक समालोचना को नहीं सह सकता था। प्रधान कौन्सल बनते ही उसने समाचार-पत्रों की स्वतन्त्रता में बाधा डालनी प्रारम्भ कर दी थी। अनेक राजनीतिक पत्र बन्द कर दिये गये थे। नये पत्रों का प्रकाशन सर्वथा रोक दिया गया था। पर सम्राट् बनते पर नैपोलियन ने समाचार-पत्रों की स्वतन्त्रता का अपहरण करने में कम लही कर दिया। यह व्यवस्था की गई, कि सब समाचार सरकार की तरफ से पहुँचाये जावे। समाचार भेजने का कार्य पुलिस के सुपुर्द किया गया। पुलिस उन सब समाचारों को रोक देती थी, जो सरकार के खिलाफ जाते थे। नैपोलियन की अपनी इच्छा तो यह थी, कि सब समाचार-पत्रों को बन्द कर दिया जावे। केवल एक ही पत्र सरकार की तरफ से प्रकाशित हो। जनता को समाचार ही तो चाहिये, और ये समाचार एक पत्र द्वारा भी सुगमता के साथ दिये जा सकते हैं।

आठवा अध्याय

## सम्राट् नैपोलियन

### १. नवीन युद्धो का प्रादुर्भाव

**नवीन युद्ध**—यूरोप के विविध राजाओं ने नैपोलियन के इस उत्कर्ष को बहुत आतंक तथा आशंका की दृष्टि से देखा। निस्सन्देह, नैपोलियन सम्राट् था, पर साथ ही वह क्रान्ति की कृति भी था। यूरोप के राजा अच्छी तरह समझते थे, कि वह उन के ढग का सम्राट् नहीं है। वह एक प्राचीन राजवंश के खण्डहर पर, क्रान्ति के गम्भीर समुद्र-मथन से, जनता की इच्छा और सहमति से सम्राट् बना है। उसके हाथ में तलवार है, जो उनके राजसिंहासनो पर लुब्ध व क्रूर दृष्टि से देख रही है। वेशक, फ्रांस में फिर से राजसत्ता की स्थापना हो गई है, पर पिछले दस वर्षों की उथल-पुथल ने इस देश में एक महान् शक्ति का संचार कर दिया है, इसे आमूल-चूल परिवर्तित कर दिया है। यह नवीन शक्ति, यह नवीन राष्ट्र पुराने ढग की राजगदियों और दरवारों के लिये भारी खतरे का कारण है। नैपोलियन के व्यक्तित्व ने इस नई शक्ति में नवजीवन का ही संचार किया है। नैपोलियन के सम्राट् बन जाने से फ्रांस में इतना ही परिवर्तन आया है, कि क्रान्ति और परिवर्तन की शक्तियाँ और भी अधिक संगठित तथा नियन्त्रित हो गई हैं। परिणाम यह हुआ, कि यूरोप के विविध राजे-महाराजे इस नये खतरे के विरुद्ध तैयारी में व्यग्र हो गये। उधर नैपोलियन भी युद्ध के लिये उत्सुक था। उसके वैयक्तिक अभ्युदय के लिये आवश्यक था, कि फ्रांस अपनी मैनिक क्षमता को निरन्तर प्रदर्शित करता रहे। फ्रांस की समृद्धि के लिये नैपोलियन यह भी उपयोगी समझता था, कि उसका अपना विस्तृत साम्राज्य हो। १८०२ में राज्यपरिषद् के सम्मुख भाषण करते हुए उसने एक बार कहा था—‘यदि यूरोपियन राज्य फिर से युद्ध प्रारम्भ करना चाहते हैं, तो लड़ाई जितनी जल्दी शुरू हो उतना ही अच्छा है। जितना समय गुजरता जाता है, उन के पराजयों की स्मृति मढ़ पड़ती जाती है, और हमारा विजय-गौरव लोगों की दृष्टि से ओझल होता जाता है। फ्रांस को शानदार कृत्यों की आवश्यकता है—इसलिये युद्ध की भी जरूरत है।’ १८०४ में एक अन्य अवसर पर नैपोलियन ने कहा था—‘यूरोप में तब तक शान्ति स्थापित नहीं हो सकती, जब तक कि सम्पूर्ण महाद्वीप एक शासक के अधीन न हो जाय। यूरोप के ऊपर शासन करनेवाला एक ऐसा सम्राट् होना चाहिये, जिसके अधीन विविध राजा कर्मचारी के रूप में कार्य करते हों। जो एक आदमी को इटली का राजा नियत करे, दूसरे को वेनेरिया का, एक आदमी को स्विट्जरलैण्ड का शासक नियत करे, दूसरे को हालैण्ड का।’ निस्सन्देह नैपोलियन का यही आदर्श था, और इसका त्रिया में परिणत करने के लिये युद्ध—निरन्तर और भयंकर युद्ध के अतिरिक्त

अन्य कोई उपाय नहीं था। परिणाम यह हुआ, कि यूरोप में उन भयंकर युद्धों का प्रारम्भ हुआ, जो दस वर्ष तक निरन्तर जारी रहे और जिन्होंने यूरोप के नक्शों में भारी परिवर्तन ला दिया। यूरोप के आधुनिक इतिहास में ये युद्ध अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं।

**इङ्ग्लैण्ड के साथ युद्ध—**फ्रांस के साथ सबसे पहले युद्ध उद्घोषित करनेवाला राज्य इङ्ग्लैण्ड था। मई, १८०३ में आमीन की सन्धि की समाप्ति हो गई, और फ्रांस तथा इङ्ग्लैण्ड में युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध के अनेक कारण थे। फ्रांस और इङ्ग्लैण्ड में सामुद्रिक साम्राज्य के सम्बन्ध में प्रतिस्पर्धा इसका प्रधान कारण था। निम्नन्देह, नैपोलियन साम्राज्यवादी था। सत्तवर्षीय युद्ध में इङ्ग्लैण्ड ने फ्रांस के जिस सामुद्रिक और औपनिवेशिक साम्राज्य का अन्त कर दिया था, नैपोलियन उसका पुनरुद्धार करना चाहता था। १८०० में नैपोलियन स्पेन को इस बात के लिये प्रेरित करने में सफल हो गया था, कि अमेरिका में मिमिसिपी नदी की घाटी के प्रदेश को—जो लुसिणना के नाम से प्रसिद्ध है, फ्रांस को दे दे। इसके कुछ समय बाद ही सेनापति लेक्लेर्क को २५,००० सैनिकों के साथ हैयटी के द्वीप पर कब्जा करने के लिये भेजा गया था। भारत में अंग्रेज लोगों के बढ़ते हुए अधिकार और प्रभाव का मुकाबला करने के लिये सेनापति दकेन को अनेक सैनिक अफमरो के साथ भेजा गया था। इसी प्रकार अन्यत्र भी अपने साम्राज्य के पुनरुद्धार को दृष्टि में रख कर सेनापति भेजे गये थे। यद्यपि ये प्रयत्न प्रायः असफल ही रहे, पर अपने प्रतिद्वन्द्वी को इस प्रकार शक्तिसम्पन्न तथा प्रयत्नशील होत देखकर इङ्ग्लैण्ड का चिन्तातुर हो जाना सर्वथा स्वाभाविक था। वेशक, इङ्ग्लैण्ड की सामुद्रिक शक्ति का मुकाबला कर सकना फ्रांस के लिये सम्भव नहीं था। पर स्थल में फ्रांस की शक्ति अद्वितीय थी। इङ्ग्लैण्ड इस महान् सैनिक शक्ति को कदापि सहन नहीं कर सकता था। यूरोप पर फ्रांस का प्रभाव जिस दग ने बट रहा था, उससे इङ्ग्लैण्ड को भारी नुकसान था। कारण यह, कि फ्रांस इङ्ग्लैण्ड के यूरोपियन व्यापार को जब चाहे नुकसान पहुँचा सकता था। नैपोलियन यूरोप के अधिकांश भाग को जीतकर अपने अधीन कर लेना चाहता था, और बाह्य व्यापारी माल पर तटकर लगा कर इङ्ग्लैण्ड के सम्पूर्ण यूरोपियन व्यापार को आसानी से नष्ट कर सकता था। यही भयंकर खतरा था, जिस ने इङ्ग्लैण्ड को आमीन की सन्धि का अन्त करने और युद्ध शुरू करने के लिये बाधित कर दिया। नैपोलियन ने भी इस युद्ध का खुले दिल से स्वागत किया क्योंकि वह खूब अच्छी तरह से समझता था, कि इङ्ग्लैण्ड को कुचले बिना सम्पूर्ण यूरोप को अपने अधीन करने के स्वप्न को क्रिया में परिणत नहीं किया जा सकता।

**इङ्ग्लैण्ड पर आक्रमण की योजना—**इङ्ग्लैण्ड और फ्रांस में युद्ध शुरू हो गया। इस समय हैनोवर के प्रदेश का शासक इङ्ग्लैण्ड का राजा ही था। नैपोलियन ने उसपर हमला किया और बात की बात में उसे अपने अधीन कर लिया। फ्रांस के अधीन सब राज्य—जो पहले रिपब्लिक थे और नैपोलियन के सम्राट् बन जाने पर अब उस के द्वारा नियत किये गये शासकों के अधीन थे, पूर्णतया उस की सहायता कर रहे थे। स्पेन को भी इङ्ग्लैण्ड के विरुद्ध सहायता करने के लिये नैपोलियन ने तैयार कर लिया था। इस प्रकार हैनोवर से लेकर इटली तक का सम्पूर्ण समुद्री तट नैपोलियन के कब्जे में था, और इस परिस्थिति का प्रयोग उसने इङ्ग्लिश व्यापार को नष्ट करने के लिये किया। हैनोवर से लेकर इटली तक

इङ्गलिश माल का आना सर्वथा रोक दिया गया। सब बन्दरगाह इङ्गलिश माल के लिये बन्द कर दिये गये। इतना ही नहीं, इङ्गलैण्ड पर हमला करने के लिये भी धूमधाम से तैयारी की गई। वोलोन में डेढ़ लाख सैनिकों की एक विशाल सेना एकत्र की गई। नैपोलियन इस बड़ी सेना के साथ अवश्य ही ब्रिटेन पर आक्रमण करता, परन्तु दो कारणों से उसे अपनी योजना का परित्याग कर देने के लिये बाधित होना पड़ा। इङ्गलैण्ड का जहाजी बेड़ा जहाँ इस योजना की सफलता में बड़ी रुकावट था, वहाँ साथ ही यूरोपियन राज्यों का एक नया गुट भी फ्रांस के विरुद्ध युद्ध करने के लिये संगठित हो गया था।

**फ्रांस के विरुद्ध नवीन गुट का निर्माण**—यह नया गुट किस प्रकार बना था, इसे स्पष्ट करने की आवश्यकता है। इङ्गलैण्ड का शासनसूत्र इस समय फिर पिट के हाथ में आ गया था। पिट फ्रांस और नैपोलियन का पुराना दुश्मन था। आमीन की सन्धि के टूट जाने पर युद्ध का संचालन करने के लिये ही पिट को प्रधानमंत्री बनाया गया था। अपनी नीति तथा धन के बल से रूस और आस्ट्रिया को फ्रांस के विरुद्ध युद्ध उद्घोषित कर देने के लिये तैयार करने में पिट सफल हुआ। एप्रिल, १८०५ में रूस के जार अलेक्जण्डर प्रथम ने फ्रांस के खिलाफ इङ्गलैण्ड से सन्धि कर ली। इस सन्धि का उद्देश्य यह था, कि हॉलैण्ड, स्विट्जरलैण्ड, इटली और हैनोवर में फ्रांस को निकाल बाहर किया जावे। अलेक्जण्डर प्रथम नैपोलियन से बहुत नाराज था। उसकी नाराजगी का एक मुख्य हेतु यह था, कि उसने वूवा वंश के एक व्यक्ति एन्ड्रीन के ड्यूक को इसलिये प्राणदण्ड दिया था, क्योंकि उस पर राजद्रोह का अभियोग लगाया गया था। आस्ट्रिया भी १८०५ में ही इस नये गुट में शामिल हो गया। आस्ट्रिया फ्रांस के विरुद्ध बनाये गये किसी भी गुट में शामिल होने के लिये हमेशा उत्सुक रहता था। फ्रांस के अभ्युदय से सब से अधिक नुकसान आस्ट्रिया को ही पहुँचा था। प्रशिया को भी इस गुट में सम्मिलित होने के लिये प्रेरित किया गया। उस के राजा को यह भी लालच दिया गया, कि हैनोवर का प्रदेश उसे दे दिया जायगा। परन्तु प्रशिया का कमजोर राजा फ्रेडरिक विलियम तृतीय इतने पर भी इस गुट में सम्मिलित होने के लिये तैयार नहीं हुआ।

**फ्रेंच बेटे की पराजय**—इस नये गुट ने नैपोलियन की इङ्गलैण्ड पर आक्रमण करने की योजना को मिट्टी में मिला दिया। वोलोन में जो भारी सेना एकत्रित की गई थी, उसे एक दम आस्ट्रिया का मुकाबला करने के लिये दक्षिणी जर्मनी की तरफ भेज देना पड़ा। २१ अक्टूबर, १८०५ के दिन इङ्गलैण्ड के नौसेनापति नेल्सन ने ट्राफल्गर के अन्तरीप के समीप फ्रेंच और स्पेनिश बेटे को बुरी तरह परास्त किया। इस के अनन्तर इङ्गलैण्ड समुद्र में अजेय हो गया, और फ्रांस ने जल में इङ्गलैण्ड का मुकाबला करने का विचार छोड़ दिया। जब नैपोलियन ने अपना सम्पूर्ण ध्यान स्थल में ही अपनी शक्ति का विस्तार करने के लिये लगा दिया। आस्ट्रिया और रूस के साथ जो युद्ध अब प्रारम्भ हुए, उनसे नैपोलियन की सैनिक कीर्ति बहुत अधिक बढ़ गई।

**आस्ट्रिया के साथ युद्ध**—आस्ट्रिया के साथ युद्ध में नैपोलियन को असाधारण सफलता प्राप्त हुई। तीन सप्ताह में फ्रेंच सेनाएँ विजय प्राप्त पहुँच गईं। २ दिसम्बर, १८०५ के दिन उसने आस्टेरलिड्ज नामक स्थान पर रूस और आस्ट्रिया की सम्मिलित सेनाओं को

परास्त किया। इस पराजय के बाद रूसी सेनाएं अपने देश को लौट गईं, और आस्ट्रिया को सन्धि करने के लिये बाधित होना पड़ा।

प्रेसबुर्ग की संधि—२६ दिसम्बर, १८०५ को प्रेसबुर्ग में सन्धि कर ली गई। यह सन्धि आस्ट्रिया के लिये बहुत महंगी पड़ी। कैम्पो फोर्मियो की सन्धि के अनुसार वेनिस के (उत्तरी इटली में) जिस प्रदेश को आस्ट्रिया ने प्राप्त किया था, वह उसमें ले लिया गया। जर्मनी के अनेक राज्यो ने गत युद्ध में फ्रांस से सहानुभूति प्रगट की थी। आस्ट्रिया को नुकसान पहुँचाकर उन सबको इनाम दिया गया। वाइन और बवेरिया के राज्यो की सीमा में वृद्धि की गई। आस्ट्रिया का राजा पवित्र रोमन सम्राट् भी होता था। इस कारण जर्मनी के ये विविध राज्य उसके अधीन माने जाते थे। पवित्र रोमन सम्राट् की स्थिति में आस्ट्रिया के राजा को इस बात के लिये बाधित किया गया, कि बवेरिया और बुर्टेम्बुर्ग के शासकों को प्रशिया के राजा के समान ही 'राजा' की स्थिति तक पहुँचा दिया जावे। नेपोल्म ने फ्रांस के शत्रुओं से सहानुभूति प्रदर्शित की थी, अतः वहाँ के बूढ़ा राजवंश के राजा को पदच्युत कर दिया गया और वहाँ का शासन करने के लिये नैपोलियन के भाई जोसेफ बोनापार्ट को नियत किया गया। बटेवियन रिपब्लिक (हालैण्ड) को भी राजतन्त्र राज्य के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, और वहाँ का राजा लुई बोनापार्ट को नियत किया गया।

रहाइन के राज्यसंघ का सूत्रपात—प्रेसबुर्ग की सन्धि एक अन्य दृष्टि में बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। अनेक जर्मन राज्यो को पवित्र रोमन साम्राज्य से पृथक् कर नैपोलियन ने अपनी अधीनता में रहाइन के राज्यसंघ (कान्फेडरेशन) का निर्माण किया। इस संघ में बवेरिया, बुर्टेम्बुर्ग, वाइन तथा अन्य तेरह जर्मन राज्य सम्मिलित हुए। यह संघ फ्रेंच सम्राट् की सुरक्षा में बना था और इसकी वही स्थिति थी, जो कि हालैण्ड आदि की थी। आवश्यकता पड़ने पर फ्रांस के लिये यह भी उसी प्रकार काम आ सकता था, जैसे हालैण्ड, स्विट्जरलैण्ड, किमल्पाइन रिपब्लिक आदि अधीनस्थ राज्य। यह व्यवस्था की गई, कि यह संघ अपने सरक्षक नैपोलियन को ६६ हजार सिपाही प्रदान करेगा और फ्रेंच सेनापति इन्हें संगठित करेगा।

पवित्र रोमन साम्राज्य का अन्त—प्रथम अगस्त, १८०६ के दिन पवित्र रोमन साम्राज्य की महासभा के सम्मुख नैपोलियन ने उद्घोषित किया, कि क्योंकि मैंने रहाइन के राज्यसंघ के सरक्षक के पद को स्वीकृत कर लिया है, अतः अब मैं पवित्र रोमन साम्राज्य की सत्ता को स्वीकार नहीं कर सकता। यह साम्राज्य अब नाममात्र का ही रह गया था, और इसके अधीनस्थ अनेक राज्य अब स्वतंत्र स्थिति को प्राप्त कर चुके थे। इसकी सत्ता अब पारस्परिक झगड़ों का ही कारण बनी हुई थी। नैपोलियन की इस उद्घोषणा का परिणाम यह हुआ, कि इस प्राचीन साम्राज्य का अन्त हो गया। आस्ट्रिया का राजा, जो हगरी, बोहेमिया, क्रोटिया, गेलिसिया आदि अन्य भी बहुत से प्रदेशों का राजा था और साथ में पवित्र रोमन सम्राट् के गौरवशाली पद को भी प्राप्त किये हुए था, अब इस पद से विरहित हो गया। ६ अगस्त, १८०६ के दिन उसने स्वयं इस पद का परित्याग कर दिया। १८ सदियों से जो सम्मानित पद चला आ रहा था, उसका इस ढंग से,

अन्त हुआ। आस्ट्रिया का राजा अब पवित्र रोमन सम्राट् नहीं रह गया।

**प्रशिया से युद्ध**—रहाइन के राज्यसंघ के निर्माण से जर्मनी में नैपोलियन का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया था। यह बात प्रशिया कभी सहन नहीं कर सकता था। प्रशिया के राजाओं की बहुत समय से यह महत्वाकांक्षा रही थी, कि जर्मनी में अपने प्रभुत्व और प्रभाव को कायम रखा जाय। इसमें नैपोलियन द्वारा संगठित रहाइन का राज्यसंघ सबसे बड़ी बाधा थी। आखिर, फ्रेडरिक विलियम तृतीय ने निर्णय किया कि फ्रांस के खिलाफ गुट में शामिल होने में ही प्रशिया का भला है। इस कारण प्रशिया ने भी फ्रांस के विरुद्ध युद्ध उद्घोषित कर दिया। आस्ट्रिया आस्टेरलिट्ज के युद्ध में परास्त होकर फ्रांस में सन्धि कर चुका था। उसका स्थान अब प्रशिया ने ले लिया।

**जेना का युद्ध**—परन्तु प्रशिया को परास्त करने में नैपोलियन को देर नहीं लगी। १४ अक्टूबर, १८०६ को जेना के रणक्षेत्र में प्रशिया की बुरी तरह पराजय हुई। दस दिन बाद नैपोलियन ने प्रशिया की राजधानी बर्लिन में प्रवेश किया। वहाँ जाकर उसने महान् फ्रेडरिक की तलवार को विजयोपहार के रूप में पेरिस भेजा। प्रशिया से बहुत बड़े परिमाण में हरजाना लिया गया। इतना ही नहीं, प्रशिया से कुछ प्रदेश लेकर वेस्टफेलिया के नये राज्य की सृष्टि की गई, और उसका राजा नैपोलियन के छोटे भाई जेरोम जोनापार्ट को बनाया गया।

**रूस की पराजय और टिलसिट की सन्धि**—प्रशिया को परास्त करने के बाद रूस पर आक्रमण किया गया। बात की बात में रूस भी परास्त कर दिया गया। नैपोलियन की विश्वविजयिनी सेनाओं का मुकाबला करना किसी के लिये भी सम्भव नहीं था। फ्रीडलैण्ड के रणक्षेत्र में १४ जून, १८०७ के दिन रूस और फ्रांस में भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें रूस की पराजय हुई। आखिर, रूस और फ्रांस में भी सन्धि हो गई, जो टिलसिट की सन्धि के नाम से प्रसिद्ध है। इस सन्धि के कारण फ्रांस के विरुद्ध यूरोपियन राज्यों का गुट सर्वथा टूट गया। आस्ट्रिया पहले ही गुट से अलग हो चुका था। प्रशिया को जेना के युद्ध में बुरी तरह परास्त कर दिया गया था। अब रूस ने भी सन्धि कर ली। शेष बचा केवल इंग्लैण्ड, जो निरन्तर दस वर्ष तक फ्रांस से लड़ता रहा और जिसके ही अनवरत परिश्रम का परिणाम यह था, कि अन्त में नैपोलियन की पराजय हुई।

टिलसिट की सन्धि से फ्रांस और रूस में युद्ध ही बन्द नहीं हुआ, अपितु इससे नैपोलियन और जार अलेक्जेंडर प्रथम ने आपस में एक गुप्त समझौता भी किया। इस समझौते के अनुसार यूरोप के इन दो शक्तिशाली सम्राटों ने यह फैसला किया कि नैपोलियन को पश्चिमी यूरोप में अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने की पूर्ण स्वतन्त्रता हो और जार को पूर्वी यूरोप में। जार अलेक्जेंडर प्रथम ने नैपोलियन से बातचीत में कहा—‘यूरोप क्या है? मैं और तुम ही तो यूरोप हैं।’ निस्सन्देह, इन दोनों सम्राटों की यही धारणा थी। इस गुप्त समझौते में अलेक्जेंडर ने इंग्लैण्ड के विरुद्ध फ्रांस की सहायता करने का भी वचन दिया।

**टिलसिट की संधि से महत्वपूर्ण परिवर्तन**—रूस और प्रशिया के पराजय के अनन्तर यूरोप के राजनीतिक नक्शे में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, उनमें वेस्टफेलिया

और वारसा के राज्य सबसे प्रमुख हैं। वेस्टफेलिया का जिक्र पहले किया जा चुका है। पोलैण्ड का प्रदेश पहले प्रधानतया प्रशिया और रूस के अधीन था। इस समय नैपोलियन ने पोलैण्ड के अधिकांश प्रदेश को लेकर अपनी मरका में वारसा के नये राज्य का निर्माण किया और उसका शासक सेमनो के राजा को नियत किया। सेमनो जर्मनी का एक राज्य था। उसके राजा के साथ नैपोलियन की बड़ी दोस्ती थी। वारसा, मेकनो और वेस्टफेलिया—ये तीनों राज्य रूढ़ान के राज्यमण्ड में सम्मिलित कर लिये गये और इनके सम्मिलित हो जाने से रूढ़ान के राज्यमण्ड का महत्त्व बहुत अधिक बढ़ गया।

इंगलिश प्रतिरोध—फ्रांस के विरुद्ध यूरोपियन राज्यों का गुट इस समय पूर्णतया टूट चुका था। परन्तु इङ्गलैण्ड के साथ अब भी युद्ध जारी था। नैपोलियन को म्यूरीय युद्धों में असाधारण सफलता प्राप्त हुई थी। पर समुद्र में इङ्गलैण्ड की शक्ति अजेय थी। इङ्गलैण्ड में व्यावसायिक क्रान्ति के कारण जिस अपूर्व क्षमता तथा शक्ति का प्रादुर्भाव हो रहा था, अन्य यूरोपियन राज्यों में उसका सर्वथा अभाव था। इङ्गलैण्ड के कारणों से इस समय इतनी तेजी के साथ आर्थिक उत्पत्ति कर रहे थे, कि मरका का अन्य कोई भी देश इस क्षेत्र में उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। एक ऐतिहासिक ने कहा है, कि नैपोलियन को वाटरलू के रणक्षेत्र में परास्त नहीं किया गया था, उसकी वाम्बविक पराजय मान्चेस्टर के कपड़े के कारखानों तथा वरमिथम की रोहों की भट्टियों में हुई थी। उस कथन में बहुत कुछ सच है। इङ्गलैण्ड अपने व्यापार और व्यवसाय के जोर पर ही नैपोलियन का इतनी व्यग्रता के साथ मुकाबला कर सका था। नैपोलियन भी उस बात का भली-भाँति समझता था। वह जानता था, कि इङ्गलैण्ड पर किसी सेना द्वारा आक्रमण कर सकना तब तक असम्भव है, जब तक कि उसका जहाजी बेड़ा कायम है। इसलिये उसने इङ्गलैण्ड के व्यापार को तबाह करने का निश्चय किया। नैपोलियन को पूर्ण विश्वास था, कि जब इङ्गलैण्ड के व्यापार और व्यवसाय को धक्का लगेगा, तब वह “इकानदारो की काम” अपने आप सन्धि के लिये याचना करने को तैयार हो जावेगी। इस नीति को क्रिया में परिणत करने के लिये नैपोलियन ने निश्चय किया, कि इङ्गलैण्ड का कोई भी माल ग्रेट में न आने पावे। नवम्बर, १८०६ में वॉलिन में एक उद्घोषणा प्रकाशित की गई, जिसमें कि इङ्गलैण्ड तथा उसके सम्पूर्ण उपनिवेशों के साथ सब प्रकार का व्यापारिक सम्बन्ध निषिद्ध कर दिया गया। यह उद्घोषित किया गया, कि कोई भी इङ्गलिश जहाज यूरोप के किसी भी बन्दरगाह पर न आने पावे। फ्रांस तथा नैपोलियन के सरक्षित राज्यों में यदि कोई अंग्रेज पाया जावे, तो उसे कैद कर लिया जावे, और उसके माल को जब्त कर लिया जावे। इङ्गलैण्ड में किसी आदमी को कोई पत्र तथा पैकेट तक न भेजा जा सके। यदि किसी पत्र पर अंग्रेजी भाषा में पता लिखा हो, तो उसे भी जब्त कर लिया जावे। नैपोलियन इन सब आज्ञाओं द्वारा इङ्गलैण्ड का यूरोप से पूर्ण बहिष्कार कर देना चाहता था। उस की इस नीति को ‘इङ्गलिश प्रतिरोध’ के नाम से कहा जाता है।

इस नीति को क्रिया में परिणत करने के लिये नैपोलियन ने कोई भी उपाय उठा न रखा। यूरोप के बड़े भाग पर उस का कब्जा था। प्रशिया, आस्ट्रिया और रूस उसके साथ सन्धि कर चुके थे। रूस के साथ सन्धि के परिणामस्वरूप उत्तरी आर्कटिक सागर



से इटली तक के समुद्र तट तक नैपोलियन का अधिकार था। यूरोप के देशों को वह अपनी इङ्गलिश प्रतिरोध की नीति का अनुसरण करने के लिये बाधित कर सकता था। यदि कोई देश उसकी उपेक्षा करने का साहस करे, तो उसे उपयुक्त सजा देने के लिये नैपोलियन के पास पर्याप्त शक्ति विद्यमान थी।

**व्यापारी युद्ध**—इस नीति का इङ्गलैण्ड ने यह जवाब दिया, कि उसने भी फ्रेंच साम्राज्य के सम्पूर्ण बन्दरगाहों को 'प्रतिरुद्ध' उद्घोषित कर दिया। साथ ही इङ्गलैण्ड ने एक और बुद्धिमत्ता का कार्य किया। उसने उदासीन राज्यों को अपने साथ व्यापार करने के लिये प्रोत्साहित किया। परन्तु नैपोलियन के पास इसका इलाज मौजूद था। दिसम्बर, १८०७ में उसने मिलान (उत्तरी इटली में) से एक उद्घोषणा प्रकाशित की, जिसमें उद्घोषित किया गया, कि जो कोई देश इङ्गलैण्ड के साथ व्यापारिक सम्बन्ध रखेगा, उस के जहाजों को लूट लिया जायगा, तथा उसे हर तरह से नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जायगी। सभार के आधुनिक इतिहास में यह व्यापारिक युद्ध बहुत महत्त्व रखता है। वर्तमान युग के युद्ध मुख्यतया व्यापार और व्यवसाय की प्रतिस्पर्धा के कारण ही हुए हैं। इस ढंग के युद्धों में फ्रांस और इङ्गलैण्ड का यह युद्ध बहुत महत्त्वपूर्ण है।

**'इङ्गलिश प्रतिरोध' की नीति का सख्ती से प्रयोग**—यूरोप के जिस देश ने भी नैपोलियन की 'इङ्गलिश प्रतिरोध' की नीति का उल्लंघन करना चाहा, उसे सख्त दण्ड दिया गया। स्वीडन ने रूस की उद्घोषणा को मानने से इन्कार किया था। परिणाम यह हुआ, कि नैपोलियन ने रूस को फिनलैण्ड का प्रदेश स्वीडन से छीन लेने के लिये प्रेरित किया। जब डेनमार्क भी स्वीडन कावू में नहीं आया, तो वहाँ के राजा को राजगद्दी छोड़ देने के लिये बाधित किया गया, और नैपोलियन ने अपने एक सेनापति बर्नार्डो को स्वीडन का राजा नियत किया। हॉलैण्ड का राजा लुई बोनापार्ट—जो नैपोलियन का भाई था, सदा अपने नाई से विमुख रहता था। उसने भी 'इङ्गलिश प्रतिरोध' की नीति को अमल में लाने में जानाकारी की। नैपोलियन ने उसे भी राज्यच्युत कर दिया और हॉलैण्ड को फ्रांस के साथ मिला लिया। रोम के पोप ने इस मामले में उदासीन रहना चाहा, पर नैपोलियन यह कब नह सकता था। उसने पोप के राज्य को छीन लिया और उसे इटली के अन्तर्गत कर दिया। पोप अपना क्रोध एक ही तरह में प्रगट कर सकता था। उसने नैपोलियन को धर्म-बहिष्कृत कर दिया। पर नैपोलियन की तलवार के सम्मुख पोप की क्या ताकत थी। नैपोलियन ने उसे कैद कर लिया। कई सालों तक पोप कैद में पड़ा रहा। पोर्तुगाल के बन्दरगाह में इङ्गलिश जहाज आते जाते थे। नैपोलियन ने हुक्म दिया, कि पोर्तुगाल इङ्गलैण्ड के खिलाफ युद्ध उद्घोषित कर दे, और जितने भी अंग्रेज उस देश में हैं, उन सब का कैद कर उनकी सम्पत्ति को जप्त कर ले। पोर्तुगाल ने इस आज्ञा को मानने से इन्कार किया। परिणाम यह हुआ, कि नैपोलियन ने सेनापति जूनो को पोर्तुगाल पर हमला करने का आदेश दिया। वडी ही सुगमता से जूनो ने पोर्तुगाल को जीत लिया। राजकीय परिवार ने पोर्तुगाल में भागकर ब्राजील में आश्रय लिया। विजयी जूनो ने बडी वृम्वाम में लिम्बन में प्रवेश किया। नैपोलियन बडी सख्ती तथा व्यग्रता से 'इंगलिश प्रतिरोध' की नीति को अमल में ला रहा था। हजारों आदमियों को इसलिये सज़ाएँ

दी गई, क्योंकि उन्होंने बोखे से इङ्गलिश माल को मंगाने की कोशिश की थी।

**स्पेन पर कब्जा**—इस प्रकार नैपोलियन निरन्तर अधिकाधिक शक्तिशाली होता जाता था। सम्पूर्ण यूरोप में उसका आतंक-सा छाया हुआ था। यूरोप के सब राजा उसकी उँगली के इशारे पर नाचते थे। पोर्तुगाल को अपने अधीन कर लेने के अनन्तर नैपोलियन को स्पेन के राज्य को भी हस्तगत करने का सुवर्णविमर प्राप्त हुआ। वहाँ के राज्य-परिवार में कुछ झगड़े चल रहे थे। नैपोलियन ने इनका उपयोग कर वहाँ के राजा चार्ल्स चतुर्थ तथा युवराज फर्डिनेण्ड को इस बात के लिये मजबूर किया, कि वे दोनों स्पेन की राजगद्दी से अपने दावे का परित्याग कर दें। ६ जून, १८०८ को नैपोलियन ने अपने भाई जोसफ बोनापार्ट को स्पेन का राजा नियत किया। जोसफ पहले नेपोल्म का राजा था। वहाँ का शासन करने के लिये सेनापति मूरे को नियत किया गया। मूरे नैपोलियन का वफादार था। इस प्रकार स्पेन भी नैपोलियन के पूर्णतया अधीन हो गया। स्पेन पहले भी फ्रांस का मित्र तथा आजाकारी था, परन्तु अब तो वहाँ की राजगद्दी पर भी नैपोलियन का कब्जा हो गया।

स्पेनिश जनता ने नैपोलियन के इस कृत्य को सहन नहीं किया। वे विद्रोह करने के लिये कटिबद्ध हो गये। रोमन कैथोलिक पादरियों तथा भिक्षुओं ने यह कहकर लोगों को नैपोलियन के खिलाफ भड़काना शुरू किया, कि वह पोप तथा धर्म का दुश्मन है। युवराज फर्डिनेण्ड इस विद्रोह का नेता बना। फ्रेंच सेना परास्त कर दी गई, और जोसफ को मेड्रिड से बाहर निकाल दिया गया। पर शीघ्र ही नैपोलियन ने एक विशाल सेना के साथ स्वयं स्पेन पर आक्रमण किया। इस सेना में दो लाख सैनिक थे। स्पेनिश सेना परास्त हो गई। ४ दिसम्बर, १८०८ को मेड्रिड पर फिर नैपोलियन का अधिकार हो गया। स्पेन के आन्तरिक सुधार के लिये नैपोलियन ने अनेक प्रयत्न किये। एक महीने के लग-भग स्पेन में रहकर वह फ्रांस वापस चला आया, और अपने भाई जोसफ बोनापार्ट को सहायता के लिये एक अच्छी बड़ी सेना स्पेन में छोड़ दी गई।

**आस्ट्रिया के साथ युद्ध और विएना की संधि**—जिस समय नैपोलियन अपने दो लाख सैनिकों के साथ स्पेनिश विद्रोह को शान्त करने में व्यग्र था, आस्ट्रिया को अपने पुराने शत्रु फ्रांस से लड़ाई शुरू करने का अच्छा मौका हाथ लग गया। नैपोलियन की बढ़ती हुई शक्ति से आस्ट्रिया बहुत चिन्तित था। रूस से लेकर इटली तक उसका प्रभाव स्थापित हो चुका था। यूरोप का 'शक्ति समुत्तुलन' इस समय नष्ट हो गया था और फ्रांस की शक्ति इतनी अधिक बढ़ गई थी, कि कोई भी यूरोपियन राज्य व गुट उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। ऐसी दशा में स्पेनिश लोगों का विद्रोह आस्ट्रिया के लिये एक सुवर्णीय अवसर था। एप्रिल, १८०९ में आस्ट्रिया ने फ्रांस के खिलाफ युद्ध उद्घोषित कर दिया। परन्तु इस बार फिर नैपोलियन विजयी हुआ। उसने एकदम विएना पर हमला किया। ५ जुलाई, १८०९ को विएना के समीप वाग्राम नामक स्थान पर आस्ट्रियन सेना बुरी तरह परास्त हुई। आस्ट्रिया को सन्धि की याचना के लिये बाधित होना पड़ा। अक्टूबर, १८०९ में सन्धि हो गई, जो कि विएना की सन्धि के नाम से प्रसिद्ध है। इस सन्धि के अनुसार आस्ट्रिया को अपने राज्य का छठा हिस्सा, जिसके निवासियों की संख्या ४० लाख थी,

नैपोलियन को अर्पित कर देना पडा। यह भी व्यवस्था की गई, कि आस्ट्रिया की सेना डेढ़ लाख से अधिक न बढ़ने पावे।

नैपोलियन का विवाह—आस्ट्रिया के प्रधान मन्त्री मेटरनिख को अब विश्वास हो गया था, कि नैपोलियन अजेय है, उसे परास्त नहीं किया जा सकता। अतः उसने इसी बात में अपने देश का कल्याण समझा, कि नैपोलियन के साथ स्थिर रूप से सन्धि कर ली जाय। उसने भरपूर कोशिश की, कि नैपोलियन का विवाह आस्ट्रिया की राजकुमारी मेरिया लुईसा से हो जाय। नैपोलियन की पहली स्त्री जोसेफाइन की कोई सन्तान नहीं थी। नैपोलियन सन्तान के लिये उत्सुक था। साथ ही, वह यह भी चाहता था, कि यूरोप के सबसे प्राचीन राजवंश से उसका सम्बन्ध स्थापित हो जाय। हाप्सबुर्ग वंश की राजकुमारी को प्राप्त कर लेना कोसिका के गरीब वकील के लड़के के लिये कितने गौरव तथा अभिमान की बात थी। नैपोलियन इस विवाह में अपनी एक अत्यन्त ऊँची महत्वाकांक्षा की पूर्ति का अनुभव करता था। अब वह असल में 'सम्राट्' बन जायगा। कुल की दृष्टि से भी उसे कौन हीन समझ सकेगा ? जोसेफाइन को तलाक दे दिया गया। मेरिया लुईसा के साथ नैपोलियन का विवाह हो गया। १८११ में इस दम्पति के एक पुत्र उत्पन्न हुआ। नैपोलियन ने इसे 'रोम का बादशाह' की उपाधि से विभूषित किया।

अब नैपोलियन की शक्ति अपनी चरम सीमा तक पहुँच गई थी। प्रायः सम्पूर्ण पश्चिमी और मध्य यूरोप उसके अधीन हो चुका था। सारी दुनिया में नैपोलियन की तूती बोल रही थी। रूस उसका दोस्त था। प्रशिया की क्या ताकत थी, जो उसे किसी भी प्रकार का नुकसान पहुँचा सके। आस्ट्रिया बार-बार पराजित होकर सीधे रास्ते पर आ गया था। स्पेन, पोर्तुगाल, इटली, हालैण्ड, स्विट्जरलैण्ड, स्वीडन—सब नैपोलियन के अधीन थे। पर इस समय भी एक देश नैपोलियन के शक्ति के खिलाफ अकेला युद्ध कर रहा था—वह देश था इङ्गलैण्ड। किस प्रकार इङ्गलैण्ड कोसिका के इस गरीब हिम्मती सिपाही को, जिसने इतिहास में एक चमत्कार कर दिखाया था, परास्त करने में समर्थ हुआ, इस पर आगे प्रकाश डाला जायगा।

## २ नैपोलियन का पतन

साम्राज्य की कमजोरियाँ—नैपोलियन का साम्राज्य अपनी चरम सीमा तक पहुँच चुका था। परन्तु यह विशाल साम्राज्य किसी सुदृढ़ आधार पर आश्रित न था। इसमें अनेक कमजोरियाँ थीं। इन्हीं का यह परिणाम हुआ, कि यह साम्राज्य देर तक कायम नहीं रह सका। ये कमजोरियाँ निम्नलिखित थीं—

(१) यह साम्राज्य एक आदमी की प्रतिभा द्वारा बना था। यह एक व्यक्ति की वृत्ति थी। अतः इसकी सत्ता और स्थिति उस एक आदमी के जीवन तथा शक्ति पर ही निर्भर थी।

(२) शामिल जनता की सहमति और महानुभूति इस साम्राज्य के साथ नहीं थी। लोग इसे नहीं चाहते थे। यह जनता की इच्छा पर कायम न होकर सैनिकशक्ति तथा पाश-विक बल पर आश्रित था। सैनिकशक्ति पर आश्रित साम्राज्य देर तक कायम नहीं रह

सकते। जब कोई अन्य सेना तथा शक्ति बलवती हो जाती है, तो ऐसे साम्राज्य नष्ट हुए बिना नहीं रहते। नैपोलियन के साम्राज्य में लोकमत तथा लोकतन्त्र शासन को कोई स्थान नहीं था, वह एक व्यक्ति की इच्छा पर आश्रित था। यह बात समय की प्रवृत्ति के प्रतिकूल थी।

(३) राष्ट्रीयता की भावना इस समय यूरोप में प्रादुर्भूत होनी प्रारम्भ हो चुकी थी। यह भावना किस प्रकार आरम्भ हुई, इस पर हम फिर विचार करेंगे। परन्तु यह स्पष्ट है, कि नैपोलियन का साम्राज्य राष्ट्रीयता के पिद्वान्त पर आश्रित नहीं था, अतः यह नवीन भावना उसे नष्ट करने के लिये पूर्ण प्रयत्न कर रही थी। १८०८ के बाद स्पेन, इटली, जर्मनी तथा अन्य यूरोपियन देशों की जनता यह भलीभांति अनुभव करने लग गई थी कि हम लोग स्पेनिश हैं, इटालियन हैं, व जर्मन हैं। हमें किसी अन्य देश के अधीन नहीं रहना चाहिये। हमारा अपना पृथक् स्वतन्त्र राज्य होना चाहिये। ममार के इतिहास में यह एक नई भावना थी। इससे पूर्व लोग ऐसा नहीं समझते थे। इस भावना के कारण विविध राष्ट्रों में जो अद्भुत शक्ति उत्पन्न हुई थी, उसका मुकाबला करना नैपोलियन की अर्ध प्रतिभा तथा फ्रांस की विश्वविजयिनी मैना के लिये भी सर्वथा असम्भव था। नैपोलियन के पतन में यह प्रधान कारण है।

(४) 'इंगलिश प्रतिरोध' की नीति से यूरोप के व्यापार को भारी नुकसान पहुँच रहा था। व्यापारियों तथा सम्पत्तिशाली लोगों में इससे भारी असन्तोष था। व्यापार के अस्तव्यस्त हो जाने से सर्वसाधारण लोग भी बहुत तकलीफ उठा रहे थे।

(५) नैपोलियन की धार्मिक नीति जनता को बिल्कुल भी पसन्द न थी। पादरी तथा भिक्षु लोग उसको बदनाम करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। उसने पोप को कैद में डाल रखा था। चर्च को राज्य की कठपुतली बना दिया था। धर्म को अपनी राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने का साधन समझ रखा था। पादरी लोग इन सब बातों को कैसे सह सकते थे। वे उसे नास्तिक, काफिर तथा ईश्वर का दुश्मन कहते थे। सर्वसाधारण जनता इस धर्मद्वेषी नैपोलियन के विरुद्ध हो गई थी।

(६) क्रान्ति की जिस भावना से फ्रांस में अनुपम उत्साह तथा शक्ति उत्पन्न हुई थी, वह नैपोलियन के सम्राट् बन जानेसे अब मन्द पड़ गई थी। राज्यक्रान्ति ने लोगों में जिन नई उमङ्गों तथा भावनाओं का संचार किया था, वे अब खतम हो गई थी। नैपोलियन को तो इन्हीं भावनाओं, उमङ्गों तथा शक्ति ने इस आश्चर्यजनक स्थिति तक पहुँचा दिया था। पर उसके एकतन्त्र स्वेच्छाचारी सम्राट् बन जाने से इन सबका ही विनाश हो गया था। नैपोलियन ने स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। नैपोलियन कोई अलौकिक आदमी तो था ही नहीं। इतिहास में कोई भी व्यक्ति अलौकिक तथा दैवी नहीं होता। वह तो फ्रांस की विशेष परिस्थितियों की उपज था। जब वे परिस्थितियाँ ही नष्ट हो गईं, तो उसके नष्ट होने में क्या देर हो सकती थी ?

इङ्ग्लैण्ड का स्पेन में आक्रमण—ये बातें थी, जो नैपोलियन के पतन में कारण हुईं। इङ्ग्लैण्ड उसके साथ निरन्तर संघर्ष में लगा था। 'इंगलिश प्रतिरोध' की नीति से जरा भी न घबरकर इङ्ग्लैण्ड जी-जान से फ्रांस का मुकाबला करने में कटिबद्ध था। अगस्त,

१८०८ में इङ्गलिश सेनापति सर आर्थर वेलेज्ली (जो वेलिंगटन के ड्यूक के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हैं) ने एक अंग्रेजी सेना के साथ पोर्तुगाल में प्रवेश किया। फ्रेंच सेनापति जूनो के साथ उसके युद्ध हुए। जूनो परास्त हो गया और पोर्तुगाल छोड़कर वापस चले आने के लिये बाधित हुआ। इसके बाद, जिस समय नैपोलियन आस्ट्रिया के साथ युद्ध में व्यग्र था, अवसर देखकर वेलेज्ली ने स्पेन पर आक्रमण कर दिया। जोसफ बोनापार्ट वेलेज्ली का मुकाबला नहीं कर सका। परन्तु फ्रेंच सेना को स्पेन से निकाल सकना आसान कार्य नहीं था। इसके लिये निरन्तर युद्धों की आवश्यकता थी। अतः वेलेज्ली ने यह उचित समझा, कि पोर्तुगाल वापस आकर अपनी किलावन्दी को खूब मजबूत कर लिया जाय। इसके बाद फ्रेंच सेना के साथ उसके निरन्तर युद्ध होते रहे। स्पेन की जनता और इङ्गलिश सेना एक तरफ थी, और नैपोलियन की सधी हुई फ्रेंच सेना दूसरी तरफ। यह युद्ध बहुत देर तक जारी रहा। नैपोलियन की तीन लाख सेना तथा बहुत से योग्यतम सेनापति इन युद्धों में फसे रहे। इन युद्धों का मुख्य परिणाम यह हुआ, कि नैपोलियन स्पेन की तरफ से कभी निश्चित नहीं हो सका। अन्य देशों के साथ युद्ध करते हुए वह कभी भी अपनी सम्पूर्ण शक्ति का उपयोग नहीं कर सका। स्पेन में उसे हमेशा एक भारी सेना रजने की आवश्यकता बनी रहती थी। पिछले युद्धों में नैपोलियन की असफलता का एक मुख्य कारण यह भी था।

रूस के साथ युद्ध—यूरोप में देर तक शान्ति कायम नहीं रह सकी। सम्पूर्ण यूरोप में केवल रूस ही एक ऐसा राज्य था, जो नैपोलियन के कब्जे से बाहर रहने की हिम्मत कर सकता था। रूस इङ्गलिश प्रतिरोध की नीति से सन्तुष्ट नहीं था। जार अलेक्जेंडर प्रथम इस बात के लिये तैयार था, कि इङ्गलिश जहाजों को अपने बन्दरगाहों पर न आने दे, पर उसे यह उचित नहीं प्रतीत होता था, कि मिलान की उद्घोषणा के अनुसार इङ्गलैण्ड से व्यापार करनेवाले अमेरिका आदि उदासीन राज्यों के जहाजों का भी बहिष्कार किया जावे। इसके अतिरिक्त, रूस इङ्गलिश व्यापार का पूर्णरूप से बहिष्कार करके अपना काम नहीं चला सकता था। टिलसिट के समझौते के अनुसार रूस को पूर्वी यूरोप में स्वच्छाचार करने का अधिकार दिया गया था। परन्तु नैपोलियन बाल्कन प्रायद्वीप तथा टर्की के सम्बन्ध में रूस की नीति में हस्तक्षेप किये बिना नहीं रह सकता था। दूसरी तरफ, नैपोलियन भी रूस के गर्व को चूर्ण करने के लिये उत्सुक था। वह सोचता था, एक रूस को हरा दिया जावे, तो सारा यूरोप अपना है। यूरोप भर में एकच्छत्र साम्राज्य स्थापित करने में केवल एक ही तो बाधा है, और वह है रूस। यदि उसे परास्त कर उन पर भी अपना अधिपत्य स्थापित कर लिया जावे, तो मैदान साफ है। ये कारण थे, जिन्होंने टिलसिट की सन्धि को समाप्त कर दिया। नैपोलियन ने रूस पर आक्रमण करने के लिये तैयारी प्रारम्भ कर दी। १८१२ में उसने अनुमान किया, कि तैयारी पूर्ण हो गई है। उसके अनेक सहायकारों ने उसे सावधान भी किया, कि रूस पर आक्रमण करने में बहुत खतरे हैं। पर नैपोलियन ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। छ लाख सैनिकों की एक विशाल सेना एकत्रित की गई। एक हजार तोपें साथ ली गईं। नैपोलियन के सम्पूर्ण साम्राज्य से इस आक्रमण के लिये सैनिक एकत्रित किये गये थे।

**रूसी आक्रमण—**रूस के इस महान् तथा साहसपूर्ण आक्रमण का इतिहास बहुत ही भयंकर तथा कष्टनामय है। नैपोलियन का विचार था, कि तीन माल में सम्पूर्ण रूस का जीत कर अपने अधीन कर लिया जावेगा। नैपोलियन निरन्तर आगे बढ़ता गया, रूसी लोग पीछे हटते गये। रूसी लोगो ने युद्ध किया ही नहीं। वे चाहते थे, कि नैपोलियन उनके देश में बहुत अधिक आगे तक बढ़ जावे। जास्विर, ७ सितम्बर, १८१२ को वोगेडिना नामक स्थान पर रूसी सेना ने नैपोलियन का मुकाबला किया। रूसी लोग हार गये। पर रूस की भयंकर मौसम, प्रतिकूल परिस्थिति तथा युद्ध का यह परिणाम हुआ, कि जब विजयी नैपोलियन ने मास्को में प्रवेश किया, तब उसके साथ केवल एक लाख सैनिक रह गये थे। नैपोलियन की सेना को अपने भरण-पोषण के लिये अनाज तथा आश्रय न मिल सके, इसलिये रूसी लोगो ने मास्को को पहले ही अग्निदेव के अर्पण कर दिया था। रूसी लोगो का यही तरीका था। वे ज्यों-ज्यों पीछे हटते जाते थे, त्यों-त्यों अपने देश को उजाड़ते जाते थे, ताकि नैपोलियन को किसी भी किस्म की मदद न पहुँच सके। नैपोलियन ने मास्को पर कब्जा तो कर लिया, पर उसे स्थिर रूप में अपने अधीन रख सकना सम्भव नहीं था। सर्दी की मौसम आ गई थी। रूस की सर्दी अत्यन्त भयंकर होती है, सब ओर बरफ ही बरफ छा जाती है। एक ऐसे मुद्रवर्ती प्रदेश में जहाँ मनुष्य और प्रकृति दोनों ही दुश्मन हों, रह सकना नैपोलियन के लिये सम्भव न रहा। उसने वापस लौटने का निश्चय किया। वापस लौटते हुए फ्रेंच सेना ने बड़े वीर्यवान् कष्ट सहे। भयंकर सर्दी, भोजन का अभाव और रूसी लोगो के आक्रमणों ने इस सेना की बुरी हालत कर दी। सैनिक इतिहास में नैपोलियन की यह वापसी बहुत ही दुःखपूर्ण घटना है। जब वह वापस फ्रांस पहुँचा, तो उसके साथ केवल बीस हजार सैनिक ही रह गये थे।

**नये गुट का निर्माण—**इस भयंकर दुरवस्था से भी नैपोलियन निराश नहीं हुआ। उसने फिर सेना एकत्रित की। बाधित रूप से सैनिक सेवा की व्यवस्था कर एक बार फिर छ लाख सैनिक एकत्रित करने में वह समर्थ हुआ। पर इसी समय नैपोलियन के विरुद्ध यूरोपियन राज्यों का एक अन्य गुट सगठित हुआ। इस नये गुट में ग्रेट ब्रिटेन, रूस, प्रुशिया और रवीडन सम्मिलित हुए। यद्यपि यह गुट राजाओं ने सगठित किया था, पर जनता की सहानुभूति भी इसके साथ थी। इस समय न केवल राजा, पर जनता भी राजकीय मामलों में दिलचस्पी लेने लग गई थी। राष्ट्रीयता की भावना विकसित होती जा रही थी, और इस नवीन भावना के कारण जनता की शक्ति नैपोलियन का मुकाबला करने के लिये सज्ज हो गई थी। इस नवीन गुट ने अपना उद्देश्य यह घोषित किया, कि हम एक अत्याचारी के पजे से जनता को—अधीन राष्ट्रों को स्वतन्त्र कराने का उद्योग करेंगे। अलेक्जेंडर प्रथम या फ्रेडरिक विलियम तृतीय चाहे इस उद्देश्य को केवल जनता की सहानुभूति प्राप्त करने के लिये कह रहे हों, पर इसमें सन्देह नहीं, कि यह बहुत हद तक ध्रुव सत्य था। वस्तुतः ही नैपोलियन का साम्राज्य राष्ट्रीयता और स्वाधीनता के सिद्धान्तों की जड़ पर कुठाराघात था। इस नये गुट ने इस अस्वाभाविक साम्राज्य का अन्त कर सचमुच ही जनता के हित का सम्पादन किया।

**सब राष्ट्रों का युद्ध—**लाइप्जिग के रणक्षेत्र में प्रुशियन और रूसी सेनाओं ने मिलकर

नैपोलियन का मुकाबला किया। कुछ समय पूर्व आस्ट्रिया भी फ्रांस के विरुद्ध इस नये गुट में सम्मिलित हो गया था, और उसकी सेनाएँ भी लाइप्जिग में मौजूद थी। १६—१९ अक्टूबर, १८१३ को वह भयंकर युद्ध लड़ा गया, जो कि इतिहास में 'सर्व राष्ट्रों का युद्ध' के नाम से मशहूर है। इसमें नैपोलियन की पराजय हुई। इस युद्ध में एक लाख बीस हजार से अधिक सैनिक या तो मारे गये या बुरी तरह से घायल हुए। पराजित होकर नैपोलियन अपनी अवशिष्ट सेना के साथ रूहाइन पार कर फ्रांस वापस चला आया। उसके वापस आते ही रूहाइन का राज्य-संघ नष्ट-भ्रष्ट हो गया।

**साम्राज्य का अन्त**—जर्मनी में पवित्र रोमन साम्राज्य का अन्त कर नैपोलियन ने जिस संघ का निर्माण किया था, वह सैनिक शक्ति पर ही आश्रित था। इस सैनिक शक्ति के निर्वल होते ही यह संघ छिन्न-भिन्न हो गया। यही नहीं, हालैंड और वेस्टफेलिया से भी अब फ्रेंच शासन का अन्त हो गया। जेरोम बोनापार्ट वेस्टफेलिया का परित्याग कर वापस भाग आया, और डच लोगों ने फ्रेंच अफसरों को हालैंड से निकाल बाहर किया। उधर सर आर्थर वेलेजली (वेलिंगटन का ड्यूक) स्पेन में फ्रेंच सेनाओं से निरन्तर युद्ध कर रहा था। १८१३ के अन्त तक उसने फ्रेंच लोगों को स्पेन से भी बाहर निकाल दिया।

**नैपोलियन का राज्यच्युत होना**—यूरोपियन राज्यों के गुट की यह इच्छा नहीं थी, कि नैपोलियन को सर्वथा नष्ट कर दिया जावे। वे उसे फ्रांस की राजगद्दी पर विराजमान रखने के लिये उद्यत थे। फ्रांस का अभिप्राय वे उत्तर में रूहाइन नदी, उत्तर-पश्चिम में जाल्प्स की पर्वतमाला और दक्षिण में पिरेनीज पर्वत माला तक के प्रदेश से लेते थे। लुई १४वें की महत्वाकांक्षा इसी सीमा को प्राप्त करने की थी। नैपोलियन को इस विशाल फ्रांस का राज्य प्रस्तुत किया गया। परन्तु वह इतने से सन्तुष्ट नहीं रह सकता था। उसने फ्रांस की सीमा को नियमित करने से सर्वथा इन्कार कर दिया। उसे अपनी तलवार का भरोसा था। वह किसी भी किस्म के समझौते के लिये तैयार नहीं था। आखिर, १८१४ के प्रारम्भ में हून, प्रशिया और आस्ट्रिया की चार लाख सेना ने उत्तरी फ्रांस पर आक्रमण किया। उधर वेलिंगटन का ड्यूक दक्षिण की तरफ से फ्रांस पर आक्रमण कर रहा था। उसके साथ इङ्गलिश सेनाओं के अतिरिक्त स्पेन और पोर्तुगाल की भी सेनाएँ थी। नैपोलियन के ममुख विकट समस्या उपस्थित हो गई। ३१ मार्च, १८१४ के दिन पेरिस पर कब्जा कर लिया गया। इस दशा में नैपोलियन को राज्य छोड़ने के लिये बाधित होना पड़ा। नैपोलियन ने भरपूर कोशिश की, कि वह मुकाबला करे। पर अब क्या हो सकता था? आखिर, उसे स्वीकार करना पड़ा कि उसका तथा उसके परिवार का फ्रेंच राजगद्दी पर कोई अधिकार नहीं है। उसकी शान रखने के लिये उसकी 'सम्राट्' की पदवी कायम रखी गई, और उसे बारह लाख रुपया वार्षिक पेंशन दे दी गई। साथ ही, एल्वे के छोटे ने वीन में उसका अबाधित अधिकार स्वीकृत कर लिया गया।

**द्वौं राजवश का पुनरुद्धार**—विजेता राष्ट्रों के सम्मुख अब यह प्रश्न आया, कि फ्रांस की राजगद्दी के विषय में क्या निर्णय किया जाय। इस समस्या का हल करने में देर नहीं लगी। फिर से द्वौं राजवश का पुनरुद्धार कर दिया गया। लुई १६वें के भाई को १८वें लुई के नाम से राजगद्दी पर बिठाया गया। नैपोलियन के साम्राज्य का किम प्रकार

निवटारा किया जाय, इस बात पर विचार करने के लिए विएना में एक कांग्रेस बुलाई गई। इस कांग्रेस के सम्बन्ध में हम आगे चलकर विचार करेंगे।

**नैपोलियन का वापस लौटना**—इस बीच में नैपोलियन चुपचाप नहीं बैठा था। एल्वा के अपने 'साम्राज्य' में कैंदी की तरह रहता हुआ यह महान् 'सम्राट्' फ्रांस के आन्तरिक परिवर्तनों तथा विएना की कांग्रेस को बड़े ध्यान में देख रहा था। फ्रांस की जनता १८वें लुई के शासन से सतुष्ट नहीं थी। उसके विरुद्ध अमन्तोष निरन्तर बढ़ता जा रहा था। उधर विएना में एकत्रित राजा नैपोलियन के साम्राज्य के बटवारे के सम्बन्ध में आपस में खूब लड़-झगड़ रहे थे। नैपोलियन ने देखा, अब समय आ गया है। अकस्मान् वह एल्वा से भाग निकला, और १ मार्च, १८१५ के दिन फ्रांस जा पहुँचा। मेना अब भी उसकी भक्त थी। उसने उसका साथ दिया। ग्यून का एक भी कनरा गिराये बिना नैपोलियन एक बार फिर फ्रांस का सम्राट् बन गया। नैपोलियन में एक अद्भुत व चामत्कारिक व्यक्तित्व था। वह लोगों को अपने पीछे लगाना जानता था। लॉग बीरता तथा अद्भुत कार्यों के पीछे चलते हैं। नैपोलियन सचमुच वीर था। वह आग मीचकर छलांग मार सकता था। उसके व्यक्तित्व में एक प्रकार का जादू था। उसने लोगों में कहा—मैं तुम्हारी कुलीनो, जमींदारों और विपमताओं से रक्षा करने के लिये जाया हूँ। जो मत्र में बड़ा साम्राज्यवादी और स्वेच्छाचारी था, वह अपने को फिर सम्राट् बनाने के लिये जब लोक-तन्त्रवाद तथा क्रान्तिकारी सिद्धान्तों की दुहाई दे रहा था। नैपोलियन की यह विशेषता थी, कि मौके के अनुसार वह अपने को बदलना जानता था। दुनिया में ऐसे लोग आसानी से सफल हो जाते हैं।

**वाटर्लू का युद्ध**—१८वा लुई नैपोलियन के प्रगट होते ही फ्रांस छोड़कर भाग गया। सम्पूर्ण यूरोप में सनसनी सी फैल गई। विएना की कांग्रेस के सम्मुख एक भयानक समस्या उपस्थित हो गई। सारा यूरोप युद्ध की दुन्दुभी से प्रतिध्वनित हो उठा। फिर मे सेनाएँ सगठित की जाने लगी। वेल्गटन का ड्यूक एक लाख सैनिकों के साथ प्रशिया की एक लाख बीस हजार सेना से मिलने के लिये ब्रुसल्स की तरफ चल पड़ा। उसका खयाल था, कि इङ्गलिश और प्रशियन सेनाएँ मिलकर नैपोलियन को परास्त कर सकेंगी। आस्ट्रिया की सेनाएँ भी रूहाइन नदी की तरफ चल पड़ी। इस परिस्थिति में नैपोलियन के लिये आवश्यक था, कि वह भी तैयारी करे। जल्दी-जल्दी में उसने दो लाख सैनिक एकत्रित किये, और उनको लेकर वह उत्तर की तरफ चल पड़ा। उसका विचार था कि इङ्गलिश, प्रशियन और आस्ट्रियन सेनाएँ परस्पर न मिलने पावे, एक-एक करके तीनों को परास्त कर दिया जावे। १८ जून, १८१५ के दिन वाटर्लू के रणक्षेत्र में उसने अपन जीवन की अन्तिम लड़ाई लड़ी। सम्भवतः, वह वेल्गटन के ड्यूक की इङ्गलिश सेना को परास्त भी कर देता, पर सेनापति ब्लूचर की प्रशियन सेना ठीक मौके पर आ गई। नैपोलियन की सेना के पैर उखड़ गये। वह परास्त हो गया। वाटर्लू का युद्ध ससार के इतिहास में अत्यन्त प्रसिद्ध है। इसने इस बात का अन्तिम रूप से फैसला कर दिया, कि राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद के सिद्धान्त में से किसकी विजय होनी है, एक सैनिक ससार का शासन करने में सफल हो सकता है या नहीं।



सेन्ट हेलेना में कैद—वाटर्ल् मे परास्त होकर नैपोलियन पेरिस वापस आया। परन्तु वहा लफायत के नेतृत्व मे पार्लियामेंट ने शासनसूत्र को अपने हाथ मे सम्हाल लिया था। उसे राजगद्दी प्राप्त करने की कोई भी सम्भावना न रही। उसने निश्चय किया, कि अपने लडके के लिये राजसिंहासन का परित्याग कर स्वयं फ्रांस से चला जाय। सम्भवत उसका खयाल अमेरिका जाने का था। परन्तु ब्रिटिश जहाजी वेडा फ्रांस के समुद्र तट पर बड़े ध्यान से पहरा दे रहा था। वह नैपोलियन को कैद करना चाहता था। आखिर, नैपोलियन ब्रिटिश लोगो के हाथ पड ही गया। नैपोलियन चाहता था, कि उसके साथ एक परास्त राजनीतिज्ञ और पदच्युत सम्राट् का सा व्यवहार किया जाय। पर ब्रिटिश लोग इस बात के लिये उद्यत न थे। वे उसे भयकर आदमी समझते थे। एलवा के द्वीप से वह जिस तरह भाग आया था, उसे दृष्टि मे रखते हुए यह सुरक्षित नहीं था, कि उस पर कड़ी निगाह न रखी जाय। ब्रिटिश लोग उसे दुनिया के लिये एक भयकर उत्पात समझते थे। उसे ससार की दृष्टि से परे रखने मे ही कल्याण था। इसलिये निश्चय किया गया, कि उसे दक्षिणी अटलांटिक सागर के एक छोटे से द्वीप सेन्ट हेलेना मे ले जाकर कैद कर दिया जावे।

सेन्ट हेलेना मे नैपोलियन छ वर्ष के लगभग रहा। उस पर कडा पहरा रखा जाता था। उसने अपना समय मुख्यतया इतिहास तथा अपने जीवन के सस्मरण लिखने मे व्यतीत किया। नैपोलियन के लिखे ये इतिहास और सस्मरण आत्म-प्रशंसा और कल्पित विचारो से भरे हुए हैं। उसने अपने को क्रान्ति का पक्षपाती तथा क्रान्ति के विचारो का प्रसारक लिखा है। वह लिखता है, कि मैं शान्ति का पक्षपाती था। मैं पददलित राष्ट्रो को स्वतन्त्र कराना चाहता था। परन्तु यूरोपियन राज्यो और विशेषतया इङ्गलैण्ड ने मेरे प्रयत्न को सफल नहीं होने दिया। उसने लिखा है, कि मैं सम्पूर्ण यूरोपियन राज्यो को अमेरिकन कांग्रेस की तरह एक सगठन में सगठित करना चाहता था और मुझे विश्वास है, कि एक दिन मेरा यह विचार अवश्य ही क्रिया मे परिणत होकर रहेगा।

जन्त—५ मई, १८२१ के दिन यह महान् विजेता अपने गौरवमय कृत्यों की रग-रूमि से बहुत दूर एक छोटे से द्वीप में अपनी जीवन-लीला को समाप्त कर गया। उसका मृतक सम्स्कार वहीं हुआ। २० वर्ष बाद, १८४० में उसके मृत शरीर के अवशेषो को बड़े सम्मान के साथ पेरिस ले आया गया, और वहा पर एक बड़ी शानदार समाधि मे उसके नातिक अवशेषो को स्थापित कर दिया गया।

### ३ नैपोलियन का इतिहास मे स्थान

ससार के इतिहास में बड़े-बड़े विजेताओ और आक्रान्ताओ को बहुत अधिक महत्त्व दिया गया है। इतिहास की साधारण पुस्तको मे अलेक्जेंडर, सीजर, महमूद गजनवी, पाच, हैनीवाल और नैपोलियन को जितना अधिक स्थान दिया गया है, उतना बट-बट वर्म प्रवर्तको, वैज्ञानिको तथा विचारको को नहीं दिया गया। इतिहास मे इन्हें महान् की उपाधि दी गई है, और सामान्य पाठक इन्हें महापुरुष समझते भी हैं। नैपोलियन वा भी इतिहास में बड़ा गौरवपूर्ण स्थान मिला है।

परन्तु मसार के इतिहास में नैपोलियन का वास्तविक स्थान क्या है ? हम विषय पर लिखते हुए इतिहासकार को बड़ी कठिनाता का सामना करना पड़ता है। आप यदि नपोलियन-सम्बन्धी साहित्य को पढ़ें, तो दो प्रकार के लेखक मिलेंगे। एक वे विद्वान नैपोलियन को बहुत ऊँचा चढ़ा दिया है, दूसरे वे जो उसे जल्यन्त हीन समझते हैं। उनका जीवन-काल में लोग नैपोलियन को एक आश्चर्यजनक विजेता समझते थे, और उसकी जड़ों की र गाथाओं से सम्पूर्ण यूरोप चमत्कृत हो गया था। फ्रांस के लिये वह अनुपम विद्वान था। उसकी तलवार ने फ्रांस की शक्ति को रूस की बर्फ में आच्छादित प्रायिया और जल्यन्त की दुर्गम पर्वतमाला से भी परे बहुत दूर तक विस्तृत कर दिया था। फ्रेंच लोग क्या न उसका पूजते ? उसी का काम था, कि ईजिप्ट और मीरिया की रहस्यमय अद्भुत वस्तुओं में पेरिस का अद्भुतालय परिपूर्ण हो गया था। इटली, हालैण्ड और स्पेन में करोड़ों रूस फ्रांस को भेजे गये थे। उसकी मृत्यु के बाद जब फ्रांस की दुरवस्था शुरू हुई, फ्रांस का विशाल साम्राज्य बालू की भीत की तरह नष्ट हो गया, तब वहाँ के लोग उसका स्मरण कर आश्चर्य से चकित रह जाते थे। उनकी दृष्टि में एक जादूगर आया था, जो फ्रांस को इतने ऊँचे स्थान पर ले गया था। फ्रेंच लोगों की दृष्टि में नैपोलियन ने वह गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त किया, जो सम्भवतः अन्य किसी व्यक्ति को नहीं मिला। फ्रेंच इतिहास, साहित्य और काव्य में नैपोलियन सबसे अधिक उज्ज्वल, शानदार और पूजनीय व्यक्ति बन गया।

पर फ्रांस के शत्रुओं की दृष्टि में ? नैपोलियन एक भयंकर व्यक्ति था, जो सन्तान की शान्ति और व्यवस्था को नष्ट करने के लिये उत्पन्न हुआ था। उन्होंने उसे बदनाम करने के लिये जो कुछ भी बन सका, किया। उसके पतन के बाद भी उनके विद्रोह भावना प्रचण्ड रही। इंग्लिश ऐतिहासिकों ने नैपोलियन को कभी भी महानुभूति की दृष्टि से नहीं देखा।

पर आज नैपोलियन को अपनी जीवन-लीला समाप्त किये सवा सदी से अधिक समय व्यतीत हो चुका है। अब उसके सम्बन्ध में ठीक विचार बना सकना असम्भव नहीं रहा है। वस्तुतः नैपोलियन क्रान्ति की उपज था। फ्रेंच राज्यक्रान्ति ने जो असाधारण और अद्भुत शक्ति उत्पन्न की थी, वही नैपोलियन की शानदार विजयों में मुख्य कारण थी। वह नहीं समझना चाहिये, कि नैपोलियन कोई अलौकिक पुरुष था। इतिहास में कोई भी व्यक्ति अलौकिक नहीं होता। सब अपनी परिस्थितियों की कृति होते हैं। क्रान्ति ने एक अद्भुत शक्ति, एक अद्भुत लहर उत्पन्न की थी, जो यूरोप के अधिकांश देशों को व्याप्त कर रही थी। यह लहर नैपोलियन की कृति नहीं थी। उसे जो कुछ भी सफलता हुई, उसमें जो कुछ भी विजय प्राप्त की, वह उसकी अलौकिक शक्ति का परिणाम नहीं थी। उसमें कोई ऐसी असाधारण शक्ति नहीं थी—जिसने आस्ट्रिया, प्रुशिया, स्पेन और रूस को उनसे सम्मुख घुटने टेक देने को विवश कर दिया। वह अद्भुत शक्ति तो उन नई प्रवृत्तियों में—नवीन भावनाओं में थी, जिन्हें फ्रेंच राज्यक्रान्ति ने जन्म दिया था, नैपोलियन तो उन प्रवृत्तियों के हाथ में एक कठपुतली की तरह काम कर रहा था। यदि इस बात का हम अपनी दृष्टि में रखें तो हम नैपोलियन के सम्बन्ध में ठीक-ठीक सम्मति बनाने में समर्थ हो सकेंगे। जहाँ तक उसके गौरवमय असाधारण कृत्यों का सम्बन्ध है, वहाँ तक यह

अच्छी तरह समझ लेना चाहिये, कि यह उसके किसी जादू, किसी अलौकिक प्रभाव के परिणाम नहीं थे। जिस प्रकार पैगम्बर मुहम्मद के कार्य से अरब की जनता में एक अद्भुत शक्ति प्रादुर्भूत हुई थी और उसने अपने समय के सभ्य ससार के बड़े भाग को व्याप्त कर लिया था—अरब लोगों के विविध सेनापति तो उस शक्ति के प्रतिनिधि-मात्र थे, इसी प्रकार फ्रेंच राज्यक्रान्ति से जो अतुल्य शक्ति उत्पन्न हुई थी, वह सम्पूर्ण यूरोप को व्याप्त कर रही थी। नैपोलियन, मूरो आदि सेनापति तो उसके प्रतिनिधि, निशान व उपलक्षण-मात्र थे। नैपोलियन अपनी सैनिक प्रतिभा से उनमें अधिक सफल तथा अधिक प्रसिद्ध हो गया, पर वह शक्ति उसकी अपनी कृति नहीं थी।

नैपोलियन की वैयक्तिक योग्यता के सम्बन्ध में अपनी सम्मति बनाने का अवसर हमें तब प्राप्त होता है, जब वह घटनाचक्र से फ्रेंच रिपब्लिक का प्रधान कौन्सल बन गया था, जब राज्यक्रान्ति का सबसे प्रमुख नेता वही था। प्रधान कौन्सल के पद पर अधिष्ठित होने पर नैपोलियन को एक ऐसा अद्भुत अवसर मिला था, जैसा कि उससे पूर्व शायद किसी अन्य व्यक्ति को नहीं मिला। पुराने जमाने का अन्त हो रहा था, नवीन युग की सृष्टि की जा रही थी। विषमता, अन्याय, अत्याचार और सकीर्णता पर आश्रित मध्यकालीन सस्थाएँ नष्ट हो रही थी, और उनके स्थान पर एक ऐसी नई दुनिया का प्रादुर्भाव हो रहा था, जिस में सब लोग समान हों, कोई किसी पर अत्याचार करनेवाला न हो, सब एक दूसरे को भाई-भाई समझे। फ्रांस में यह नया युग बहुत कुछ प्रादुर्भूत हो चुका था, और आस-पास के राज्य आखिरी मीचकर उसका अनुसरण कर रहे थे। सारा यूरोप एक नये युग का स्वप्न देख रहा था। अब इस सम्पूर्ण प्रवृत्ति, इस सारी लहर का नेता था—नैपोलियन। निस्सन्देह, नैपोलियन इस महत्त्वपूर्ण उच्च स्थान पर पहुँच गया था। सारा फ्रांस उसके कब्जे में था, उसकी इच्छा ही वहाँ कानून थी, इसलिये नहीं, कि ईश्वर ने उसे इस पद पर पहुँचाया था, बल्कि इसलिये कि जनता ने उसे यह गौरवपूर्ण सम्मान प्रदान किया था। इन स्थिति का प्रयोग ससार में शान्ति और व्यवस्था स्थापित करने के लिये भी किया जा सकता था। नैपोलियन नये युग का स्थापक भी बन सकता था। पर उसने अपने गौरवपूर्ण अमाधारण पद का प्रयोग किस काम के लिये किया? क्या क्रान्ति को स्थिर और व्यवस्थित करने के लिये? क्या मातस्व्यू और हसो के सिद्धान्तों को एक क्रियात्मक सत्य बना देने के लिये? क्या सम्पूर्ण यूरोप के सम्मुख क्रान्ति के विधायक और उज्ज्वल रूप को प्रगट करने के लिये? नहीं, इसके लिये नैपोलियन ने प्रयत्न नहीं किया। फिर उसने क्या किया? वह १४वें लुई के पीछे चलना चाहता था। उसे दुइलरी के राज-प्रासाद में दरबारियों की सगति में रहने में आनन्द अनुभव होता था। उसने अपनी असाधारण शक्ति और स्थिति का प्रयोग फ्रांस में फिर से एकतन्त्र राजसत्ता का पुनरुद्धार करने के लिये किया। उसके प्रयत्न में फिर राज-दरवार का उद्धार हुआ, लोगों में ऊँच-नीच के भाव उत्पन्न हुए, भाषण, लेखन और मुद्रण की स्वतन्त्रता मर्यादित की गई। क्रान्ति में जो कुछ किया था, उस पर पानी फेरने के लिये—नैपोलियन के इन कार्यों का किन्ता असर हुआ।

वह नीजर का अनुसरण करना चाहता था। रोमन इतिहास उसे बहुत आकर्षित

करता था। 'कान्सल' शब्द उसने रोमन इतिहास से ही लिया था। प्राचीन रोमन रिपब्लिक के प्रधान को 'कान्सल' कहते थे, सीजर भी पहले कान्सल बना था। नैपोलियन भी पहले कान्सल बना। फिर सीजर सम्राट् बन गया। नैपोलियन ने भी उसका अनुसरण किया। वह भी 'कान्सल' से 'सम्राट्' बन गया। चाहिये तो यह था, कि वह राज्यक्रान्ति द्वारा उत्पन्न 'रिपब्लिक' को स्थिर और व्यवस्थित करता। यह न कर उमने सम्राट् बनने में ही गौरव समझा। इसके बाद उमने जो कुछ भी कार्य किया—वह अपनी 'सम्राट्' की स्थिति को दृढ़ करने के लिये ही किया। फ्रांस के बहिष्कृत कुलीन लोगों को उमने फिर वापस बुला लिया। रोम के पोप के साथ उसने समझौता किया। किस लिये? क्या उसे स्वयं रोमन कैथोलिक धर्म में श्रद्धा थी? क्या वह धर्म को मनुष्यों के लिये उपयोगी समझता था? नहीं। उमका विचार था, कि पोप के पक्ष में हो जाने से उमका स्थिति सुदृढ़ हो जावेगी। धर्म को साथ लिये बिना उमकी राजमन्ता कायम नहीं रह सकेगी—ऐसा विचार उमका था। उमने एक बार कहा था—“धर्म के बिना राज्य में व्यवस्था कैसे रह सकती है? विषमता के बिना समाज कायम नहीं रह सकता और विषमता रखने के लिये धर्म आवश्यक है। जब एक आदमी भूख के मारे तड़प-तड़प कर प्राण दे रहा हो और दूसरे के पास इतनी अधिक सम्पत्ति हो, कि वह यह भी न जानना हो, कि वह उसका क्या करे, इस हालत में वह भूखा मरना हुआ मनुष्य कैसे सन्तुष्ट रह सकता है, जब तक कि धर्म आकर उसे यह न समझावे—कि परमात्मा की ऐसी ही इच्छा है। ससार में अमीर और गरीब दोनों ही रहने चाहिये, परन्तु परस्पर में यह भेद न रहेगा।” नैपोलियन का खयाल था, कि लोगों को सन्तुष्ट रखने के लिये धर्म के बिना काम नहीं चल सकता। धर्म एक ऐसी उत्तम वस्तु है, जो गरीब, दुखी और अत्याचार-पीड़ित लोगों को अपनी दुर्दशा में भी सन्तोष और शान्ति सिखाती है, अपनी दुर्दशा को परम-कृपालु मङ्गलरूप भगवान की इच्छा जताकर लोगों को दुखी और दलित रहने के लिये बाधित करती है। नैपोलियन चाहता था, कि इस अत्युत्तम पदार्थ का अपनी महत्वाकाक्षाओं की पूर्ति के लिये प्रयोग करे। पहले जब वह जैकोबिन दल का सदस्य था, तब धर्म को अत्यन्त हानिकारक समझता था और हमेशा उसके खिलाफ रहता था। पर जब अपने स्वार्थ को पूर्ण करने के लिये वह धर्म का पक्षपाती बन गया था।

अपनी राजनीतिक महत्वाकाक्षाओं को पूर्ण करने के लिये ही नैपोलियन ने ईसाई धर्म का विदेशों में प्रचार करने का सकल्प किया था। उसने लिखा था, “मैं चाहता हूँ, कि ईसाई मिशनरों का फिर से सगठन किया जावे। रूस, अफ्रीका और अमेरिका में ये ईसाई मिशनरी मेरे लिये बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। ये जहाँ भी जावेगे, देशों का ठीक ठीक परिज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। उनकी पोशाक को देखकर कोई उन पर सन्देह नहीं करेगा। कोई यह भी नहीं जान सकेगा, कि वे राजनीतिक और व्यापारी दृष्टि से खोज कर रहे हैं।” धर्म में भी नैपोलियन का उद्देश्य राजनीतिक और व्यापारिक था।

शिक्षा के क्षेत्र में भी नैपोलियन के विचार बहुत सर्कीर्ण थे। १७९२ में फ्रांस के क्रान्तिकारियों ने बाधित और मुप्त शिक्षा की स्कीम तैयार की थी। उनका विचार था, कि एक भी फ्रेंच पुरुष व स्त्री ऐसा नहीं रहना चाहिये, जो शिक्षित न हो। जिस उपाय का

अवलम्बन सभी सभ्य देशों में उन्नीसवीं सदी के अन्तिम भाग में किया गया, फ्रेंच क्रान्ति-कारी उसे अठारहवीं सदी में ही प्रयोग में लाने का प्रयत्न कर रहे थे। यदि राज्यक्रान्ति के मार्ग में नैपोलियन की महत्वाकांक्षाएँ एक भारी विघ्न उपस्थित न कर देती, तो सम्भवतः फ्रांस में बहुत पहले शिक्षा का प्रसार हो जाता। पर नैपोलियन की दृष्टि में प्रारम्भिक शिक्षा का बहुत महत्त्व नहीं था। वह इस बात की कोई आवश्यकता नहीं समझता था, कि सर्वसाधारण जनता को शिक्षित किया जाय। निम्न-न्देह, उसके समय में बहुत से शिक्षणालय खुले। पर ये नैपोलियन की प्रतिभा के परिणाम नहीं थे। राज्यक्रान्ति ने लोगों में शिक्षा के लिये प्रबल आकांक्षा उत्पन्न कर दी थी। नैपोलियन तो उसमें एक बाधा रूप ही था। स्त्री-शिक्षा के विषय में नैपोलियन के विचार निम्नलिखित थे—मैं नहीं समझता, कि हमें लड़कियों की शिक्षा के सम्बन्ध में किसी योजना को तैयार करने के लिये अपने दिमागों को तकलीफ देने की जरूरत है। उनकी शिक्षा के लिए उनकी माताएँ ही काफी हैं। सार्वजनिक शिक्षा उनके लिये किसी काम की नहीं है, क्योंकि उन्हें जनता में आने की आवश्यकता ही कब होती है। उनके लिये तो रीति-रिवाज और व्यवहार की शिक्षा ही पर्याप्त है—आखिर, उन्हें विवाह ही तो करना है। यह मत समझिये कि ये विचार एक ऐसे आदमी के हैं, जो अर्वाचीन काल की रोशनी से पहले उत्पन्न हुआ था। ये विचार एक ऐसे सम्राट् के हैं, जिसे फ्रेंच राज्यक्रान्ति की नवीन भावनाओं ने इतने ऊँचे पद पर पहुँचाया था।

नैपोलियन यदि चाहता, तो राज्यक्रान्ति के विचारों को न केवल फ्रांस में, अपितु अपने सम्पूर्ण साम्राज्य में फैला सकता था। क्रान्ति द्वारा जिस नवीन युग की स्थापना की जा रही थी, और जिससे मनुष्य जाति का अनुपम कल्याण होना था, उसके लिए नैपोलियन असाधारण रूप से प्रयत्न कर सकता था। पर उसने इस दिशा में जरा भी प्रयत्न नहीं किया। उसके कृत्यों से क्रान्ति के अनेक प्रयोग नष्ट ही हुए। निम्न-न्देह, उसकी विजयों ने क्रान्ति की भावना को दूर-दूर तक विस्तृत कर दिया था। पर यह होना सर्वथा स्वाभाविक था। जो देश फ्रेंच लोगों के समर्ग में आते थे, वे नई भावनाओं से आप्लावित हुए बिना नहीं रह सकते थे। फ्रेंच सेनाएँ क्रान्ति की लपटों के समान थीं। वे जहाँ जाती थी, किलों और नगरों को ध्वंस करने के साथ-साथ पुराने जमाने की गन्दगी के ढेरों को भी भस्म करती जाती थी। इसमें नैपोलियन की क्या कृति थी? देखना तो यह है कि जब वह स्वयं फ्रांस का कर्त्ता धर्त्ता बन गया, तब उसने क्या किया, तब फ्रांस और उसके साम्राज्य का शासन किन सिद्धान्तों के अनुसार किया गया? क्या उस समय क्रान्ति की विजयों और सफलता के लिये कोशिश की गई? नहीं। सत्य बात तो यह है, कि नैपोलियन पुराने जमाने की लहर में बह गया। प्रधान कौन्सल के रूप में ही उसने अपने भाई बहिनों को ऊँचे-ऊँचे पदों पर नियत किया। बिना इस बात की परवाह किये कि वे उन कार्यों के योग्य ह, उन्हें अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पद दिये गये। यह कितनी स्वाभाविक बात है? पर साथ ही कितनी अनुचित भी है। जिस प्रकार पुराने जमाने के अमीर उमरा लोग अपने भाइयों, कृपापात्रों और आश्रितों को उचित व अनुचित सब प्रकार के तरीकों में ऊँचे पदों पर पहुँचाने की कोशिश किया करते थे, वैसे ही नैपोलियन ने भी किया। वह इस

स्वाभाविक मानव निर्वलताओं में ऊँचा नहीं उठ सका। क्रान्ति का सिद्धान्त था, कि मनुष्यों में ऊँच-नीच का कोई भेद नहीं है। प्रत्येक मनुष्य अपनी योग्यता में ही राजकीय पदा को प्राप्त करने का अधिकारी बनता है। पर डम शक्तिशाली, साहसी और मरुत नेपोलियन के भाई बहिन केवल डपलिये बड़े-बड़े राज्यों के शासक और कर्त्ता बर्त्ता बनाये गये, क्योंकि वे उसके निकट सम्बन्धी थे। नेपोलियन उनको सुग करना चाहता था, उनकी दृष्टि में बड़ा बनना चाहता था। अपने घर—अपने परिवार में बड़प्पन प्रदर्शित करना मनुष्य के लिये कितना स्वाभाविक होता है।

और जब नेपोलियन सम्राट् बन गया? फिर १९वें लुई का जमाना वापस लौट आया। वही राज-दरबार, वही पोशाकें, वही अनुचर और पार्श्वचर—वही सब शान-शौकत और धूमधाम। रिपब्लिकन फ्रांस के अधीन अन्य रिपब्लिकन राज्यों में भी उस राजतन्त्र शासन स्थापित किया गया, और उन पर शासन करने के लिये नियत किये गये नेपोलियन के भाई बहिन। कहा तो फ्रांस की क्रान्तिनारी नेनाए यूरोप भर में राजमना का अन्त करने के लिये सघर्ष कर रही थी, और कहा यह मरुत नेनाए रिपब्लिकन राज्यों में एकसत्तात्मक शासन स्थापित कर रहा था। कितना भारी परिवर्तन था? फ्रांस की क्रान्तिकारी भावनाएँ इस महान् सम्राट् के हाथ में पडकर कितनी विकृत और पतित रूप धारण कर रही थी।

नेपोलियन को तब तक सन्तोष नहीं हुआ, जब तक कि अपने आस्ट्रिया की राजकुमारी से विवाह कर अपने को यूरोपियन राजाओं की दृष्टि में कुलीन मानित नहीं कर दिया। सचमुच नेपोलियन इस बात के लिये उत्सुक था, कि लोग उसे अपने से ऊँचा समझे। सब लोग यह भूल जावे, कि वह कोसिका के एक गरीब बकौल का लडका है, जो ब्रीएन के सैनिक शिक्षणालय में अपने साथी कुलीन विद्यार्थियों द्वारा निरन्तर अपमानित किया जाता था। वह चाहता था, कि लोग उसे सम्राट् महान् नेपोलियन समझे, जो कि आस्ट्रिया के पवित्र उच्च हाप्सबर्ग सम्राट् का जामाता है, और जिसकी महारानी आस्ट्रियन राजकुमारी है। कैसा ऊँचा खयाल था? राज्यक्रान्ति इन्ही भावनाओं के प्रसार के लिये तो उत्पन्न हुई थी? रूसी जार अलेक्जेंडर के साथ टिलसिट में बैठकर उसने कैसे ऊँचे भावों को प्रगट किया था? 'यूरोप क्या है?' 'हम यूरोप हैं।' जनता कहा गई? यूरोप की जनता नेपोलियन को दृष्टि में कोई स्थान नहीं रखती थी। इस दृष्टि से अलेक्जेंडर और नेपोलियन—दोनों बिल्कुल एक जैसे विचार रखते थे।

इस स्थिति में हम नेपोलियन के सम्बन्ध में क्या सम्मति प्रगट करें? इसमें तो कोई सन्देह नहीं, कि वह असाधारण शक्तिसम्पन्न, साहसी और जवर्दस्त व्यक्ति था। उसके अन्दर एक किस्म की आकर्षण शक्ति थी, जिससे लोग उसके पीछे लग जाते थे। अपनी योग्यता और सामर्थ्य से ही वह अत्यन्त साधारण स्थिति से ऊँचा उठकर एक महान् सम्राट् के पद तक पहुँचा था। पर इस उन्नति में उसकी योग्यता ही एकमात्र कारण नहीं थी। नेपोलियन ने जो कुछ कर दिखाया, उसमें उसकी अपनी योग्यता के अतिरिक्त अधिक महत्त्वपूर्ण कारण—बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण कारण वह अद्भुत और अद्वितीय शक्ति थी, जिसे फ्रांस की राज्यक्रान्ति ने उत्पन्न किया था। उसी शक्ति का सहारा लेकर नेपोलियन

ने इतनी असाधारण विजये प्राप्त की। उसी शक्ति का दुरुपयोग कर वह एक उच्च सम्राट् के पद तक पहुँच गया, और सम्पूर्ण यूरोपियन राज्यों के लिये एक भयकर खतरा बन गया। यदि सैनिक शक्ति और साहस के अतिरिक्त नेपोलियन में प्रतिभा, विचार और सत्कल्पना भी होती, तो वह अपनी महत्त्वपूर्ण परिस्थितियों का उपयोग और ही प्रकार से करता। उस हालत में 'सब राष्ट्रों का युद्ध' उसके खिलाफ न लड़ा जाता, सब राज्यों की जनता भी अपने राजाओं के साथ उसका मुकाबला करने के लिये न उठ खड़ी होती। यूरोप भर की जनता उसे अपना रक्षक और नेता समझती, और उसकी सहायता प्राप्त कर अपने को स्वाधीन बनाने का प्रयत्न करती। नेपोलियन इस गौरवपूर्ण पद को प्राप्त कर सकता था। इसके लिये उसको कितना उत्तम अवसर प्राप्त हुआ था। पर उसने इस क्षेत्र में अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने का प्रयत्न नहीं किया। वह बह गया, उस धारा में—जो गिरावट और पतन की तरफ ले जाती थी।

नेपोलियन के युद्धों में कुल मिलाकर चालीस लाख के लगभग मनुष्यों के जीवन नष्ट हुए। इतने जीवनों का विनाश किस लिये हुआ? एक आदमी की महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिये। इससे बहुत कम, सम्भवतः इसके शतांश से नेपोलियन ससार को नवयुग का संदेश देने का कार्य कर सकता था। पर उसका ध्यान ही इस तरफ नहीं था। लुई सोलहवें का जीवन उसे अधिक आकर्षक प्रतीत होता था।

नवा अध्याय

## यूरोप की नई व्यवस्था

### १ राज्यक्रान्ति के परिणाम

सन् १७८९से१८१८ तक के पच्चीस साल यूरोप के इतिहास में क्रान्ति का काल था। फ्रांस में जिस राज्यक्रान्ति का मूत्रपात हुआ था, उसने न केवल फ्रांस के, अपितु यूरोप के अन्य बहुत से देशों के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। फ्रेंच राज्यक्रान्ति के तीन आदर्श थे—समानता, स्वाधीनता और भ्रातृभाव। इस युग में जिस नये समान के निर्माण का प्रयत्न किया गया, उसके ये ही आधार-स्तम्भ थे। इसमें मन्देह नहीं, कि फ्रेंच राज्यक्रान्ति यूरोप के इतिहास में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखती है, और न केवल यूरोप के, अपितु सम्पूर्ण ससार के इतिहास पर उसका प्रभाव पड़ा है। हम यहाँ मक्षेप में क्रान्ति के इन परिणामों पर प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे।

(१) लोकतन्त्र शासन—फ्रांस की राज्यक्रान्ति द्वारा यूरोप में लोकतन्त्रवाद का प्रारम्भ हुआ। राजा दैवी अधिकार से शासन करता है, और उसकी इच्छा ही कानून है, इस सिद्धान्त का अव अन्त हो गया। फ्रांस के लोगों ने पहले बंध राजसत्ता की स्थापना का यत्न किया था। यदि सोलहवा लुई अपने दरबारियों के प्रभाव में न होता, और समय के रत्न को पहचान सकता, तो सम्भवतः, फ्रांस में भी ग्रेट ब्रिटेन के समान बंध राजसत्ता विकसित हो सकती। राज्यक्रान्ति के बाद फ्रांस में जो पहला शासन विधान बना था, उसमें राजा की सत्ता को स्वीकार किया गया था। पर राजा लुई जनता की इच्छा के अनुसार, विधान के अधीन रहकर शासन करने के लिये तैयार नहीं था। इसीलिये उसे राज्यच्युत कर फ्रेंच लोगों ने रिपब्लिक की स्थापना की। नैपोलियन ने रिपब्लिक का अन्त कर सम्राट् पद प्राप्त किया। पर नैपोलियन दैवी अधिकार से सम्राट् न बनकर जनता की इच्छा से, मत-दाताओं के वोटों द्वारा सम्राट् बना था। उसकी असाधारण शक्ति और प्रतिभा के कारण ही जनता ने उसे स्वेच्छाचारी शासक बनने का अवसर दिया था। पर नैपोलियन के समय में भी फ्रांस में शासन-विधान विद्यमान था, पार्लियामेन्ट की सत्ता थी, और इस बात का प्रयत्न किया जाता था, कि सरकार का स्वरूप लोकमत के धनुकूल रहे। इसमें सन्देह नहीं, कि फ्रेंच क्रान्तिकारी बुरी वंश के निरकुश शासन का अन्त कर तुरन्त लोकतन्त्र शासन की स्थापना नहीं कर सके। पर मनुष्य की प्रकृति ही ऐसी है, कि उसमें और उसके समाज में कोई भी परिवर्तन अकस्मात् नहीं हो सकता। क्रान्तिकारी फ्रांस ने नैपोलियन के सम्मुख जो आत्मसमर्पण कर दिया, उसका यही कारण था। पर राज्यक्रान्ति द्वारा फ्रांस में लोकतन्त्रवाद की जो लहर शुरू हुई थी, वह निरन्तर सफल होती गई, यह



निर्विवाद है। नैपोलियन की विजयों का एक महत्त्वपूर्ण परिणाम यह हुआ, कि इटली, हालैंड, स्विटजरलैंड, स्पेन, जर्मनी आदि अन्य यूरोपियन देशों में भी लोकतन्त्रवाद का प्रवेश हुआ। कुछ समय के लिये इन देशों के बड़े भाग में भी निरकुश व दैवी अधिकार पर आश्रित राजसत्ता का अन्त होकर लोकतन्त्र शासनो की स्थापना हुई, और यूरोपका बड़ा भाग क्रान्ति के सिद्धान्तों का अनुयायी बन गया।

(२) नागरिक स्वतन्त्रता—लोकतन्त्रवाद का यह स्वाभाविक परिणाम हुआ, कि फ्रांस में पहली बार नागरिक स्वतन्त्रता का प्रारम्भ हुआ। क्रान्ति से पहले फ्रांस में सब नागरिक समान स्थिति नहीं रखते थे, सबके लिये टैक्स के नियम एक समान नहीं थे, कानूनों का प्रयोग भी सबके लिये समान रूप से नहीं होता था। राजकीय पदों पर नियुक्ति के लिये योग्यता को महत्त्व नहीं दिया जाता था। राजकीय पद राजा की कृपा-दृष्टि पर आश्रित होते थे। राज्यक्रान्ति ने इस दशा में परिवर्तन किया। जनता को पहली बार वोट का अधिकार मिला, और उसमें यह अनुभूति उत्पन्न हुई, कि शासन उसकी इच्छा पर आश्रित है। राजकीय पदों पर नियुक्ति योग्यता और कार्यक्षमता के आधार पर की जाने लगी। टैक्स के नियम सब के लिये एक सदृश किये गये, और सारे देश में एक कानून प्रचलित करने के लिये विधान का सकलन शुरू किया गया। नैपोलियन के समय में यह कार्य पूर्ण हुआ, जो 'कोड नैपोलियन' के नाम से प्रसिद्ध है। इस क्रान्तियुग में फ्रांस में जो शासन-विधान व कानून बने, उनमें नागरिक स्वतन्त्रता को प्रमुख स्थान दिया गया था। कानून की दृष्टि में सब नागरिक बराबर हैं, और उनके कतिपय ऐसे आधारभूत अधिकार हैं, जिनका उल्लंघन कर सकना किसी सरकार के हाथ में नहीं है, यह सिद्धान्त पहली बार फ्रांस में स्वीकृत किया गया। नैपोलियन की विजयों के कारण इटली, हालैंड आदि देशों में भी नागरिक स्वतन्त्रता के इस सिद्धान्त का प्रवेश हुआ।

(३) सामाजिक क्रान्ति—फ्रांस में जो राज्यक्रान्ति हुई, उसने वहाँ की जनता को केवल बूढ़ों वंश के निरकुश शासन से ही स्वतन्त्र नहीं किया, अपितु समाज में ममानता की भी स्थापना की। सामाजिक क्रान्ति फ्रेंच राज्यक्रान्ति का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण परिणाम है। क्रान्ति से पूर्व फ्रांस में कुलीन और पुरोहित श्रेणियों का किस प्रकार प्रभुत्व था, जमीन पर किम प्रकार कतिपय बड़े जागीरदारों का स्वामित्व था, और सर्वसाधारण जनता की दशा किस प्रकार अर्धदासों की सी थी—इन बातों पर हम पहले प्रकाश डाल चुके हैं। राज्यक्रान्ति द्वारा इस स्थिति में भारी परिवर्तन आया। क्रान्ति के समय में फ्रांस के बड़े कुलीन जागीरदार अपने देश को छोड़कर बाहर भाग गये थे। क्रान्तिकारी सरकार ने उनकी जमीनों को जब्त कर लिया था। बाद में उसे सर्वसाधारण जनता को वेंच दिया गया, और समृद्ध किसानों व मध्यश्रेणि के लोगों को यह अवसर मिला, कि वे भूमि के स्वामी बन सकें। जमीन के कानून में जो बहुत से सशोधन क्रान्तिकारियों द्वारा किये गये थे, उनमें साधारण किसानों का भी अपने खेतों पर अधिकार स्थापित हो गया। जमीन के पूर्णरूप से स्वामी न होते हुए भी ये किसान अपने खेत से वेदखल नहीं किये जा सकते थे, वे जमीन पर अपने अधिकारों को दूसरों को वेंच सकते थे और निश्चिन्ता व

स्वतन्त्रता के साथ खेती के कार्य में व्यापृत रह सकते थे ।

राज्यक्रान्ति के कारण मध्यश्रेणि का महत्त्व निरन्तर बढ़ने लगा । रिपब्लिक व नैगोलियन के शासनकाल में व्यापार और व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के लिये विशेष रूप से प्रयत्न किया गया था । इन कार्यों में लगे हुए मध्यश्रेणि के लोग न केवल सम्पत्ति और समृद्धि की दृष्टि से निरन्तर उन्नति कर रहे थे, अपितु वोट के अधिकार का प्रयोग कर राजशक्ति को भी अपने हाथों में ले रहे थे । मध्यश्रेणि के महत्त्व में बृद्धि फ्रेंच राज्यक्रान्ति का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण परिणाम था । फ्रांस के पुराने समाज में ऐसे कुलीनों और उच्च पुरोहितों का प्रभुत्व था, जिनकी स्थिति का आधार उनका किमी विशिष्ट कुत्र में उत्पन्न होना ही था । अब उसके स्थान पर मध्यश्रेणि का महत्त्व बढ़ने लगा, जिसका आधार सम्पत्ति व योग्यता थी ।

एक बार जब फ्रेंच लोग कुलीन श्रेणि के प्रभुत्व में मुक्त हो गये, और मध्यश्रेणि का महत्त्व बढ़ने लगा, तो यह स्वाभाविक था, कि लोगों का ध्यान आर्थिक विषमता की ओर भी आकृष्ट हो । अब राजसत्ता जिन लोगों के हाथ में थी, उनके लिये जनता के हृदय में वह आदर नहीं था, जो वंशक्रमानुगत कुलीन श्रेणि के प्रति होता है । जन कतिपय विचारकों का ध्यान इस बात की ओर भी आकृष्ट हुआ, कि समाज में विषमता का अन्त होकर समता की स्थापना होनी चाहिए । जिस प्रकार राजनीतिक और नागरिक दृष्टि में सबलोग एक समान हो गये हैं, वैसे ही आर्थिक क्षेत्र में भी उन्हें एक समान होना चाहिये । इसी लिये उन्नीसवीं सदी में फ्रांस व अन्य यूरोपियन देशों में अनेक ऐसे विचारक उत्पन्न हुए, जो आर्थिक समता की स्थापना के लिये समाजवाद का प्रतिपादन करने के लिये तत्पर थे ।

(४) आर्थिक परिवर्तन—स्वतन्त्रता और समानता की लहर ने आर्थिक क्षेत्र को भी प्रभावित किया । क्रान्ति से पहले फ्रांस के आर्थिक जीवन में स्वतन्त्रता का सर्वथा अभाव था । अनेक व्यवसाय राजा के एकाधिकार में थे, उन्हें अन्य लोग नहीं कर सकते थे । नगरों का व्यावसायिक जीवन श्रेणियों (गिल्ड) में संगठित था, प्रत्येक व्यवसायी के लिये यह आवश्यक था, कि वह इन श्रेणियों के नियमों के अधीन रहे । इस कारण शिल्पी व व्यवसायी लोग स्वतन्त्रता के साथ आर्थिक उत्पत्ति करने में असमर्थ रहते थे । देश के आन्तरिक व्यापार में भी स्वतन्त्रता का अभाव था । एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल ले जाने में अनेक प्रकार की बाधाएँ थी । क्रान्ति की लहर ने इस स्थिति में परिवर्तन किया । इस युग में इङ्ग्लैण्ड में व्यावसायिक क्रान्ति शुरू हो चुकी थी । फ्रांस के क्रान्तिकारी इस बात के लिये उत्सुक थे, कि उनके यहाँ भी व्यावसायिक क्रान्ति का प्रवेश हो, और नई मशीनरी और यान्त्रिक शक्ति का प्रयोग कर बड़े कल-कारखानों की स्थापना की जाय । इसीलिये उन्होंने व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में 'खुला छोड़ दो' की नीति को अपनाया । गिल्डों के सर्कीर्ण नियमों को नष्ट किया, और देश के आन्तरिक व्यापार की सब बाधाओं को दूर किया । अब शिल्पियों, श्रमियों और कारीगरों को यह स्वतन्त्रता प्रदान की गई, कि वे अपने श्रम को खुले बाजार में बेच सकें, और इस प्रकार अधिकतम मजदूरी प्राप्त कर सकें । इस कारण फ्रांस में कल-कारखानों और व्यापार व्यवसाय के विकास में बहुत सहायता मिली, और कुछ ही समय बाद आर्थिक क्षेत्र में भी फ्रांस इङ्ग्लैण्ड

का प्रधान प्रतिद्वन्द्वी बन गया ।

(५) शिक्षा में परिवर्तन—फ्रांस के क्रान्तिकारी जनता की शिक्षा को बहुत महत्त्व देते थे । वे भलीभांति समझते थे, कि शिक्षा के कार्य को चर्च के हाथ में छोड़ देने से काम नहीं चल सकता । इसीलिये उन्होंने राज्य की ओर से शिक्षा-प्रसार के कार्य को शुरू किया । नैपोलियन ने शिक्षा-सम्बन्धी जिस नीति को अपनाया था, उसका सूत्रपात क्रान्ति के नेताओं द्वारा ही किया गया था । पेरिस यूनिवर्सिटी का जो पुनः संगठन नैपोलियन द्वारा हुआ, वह यूरोप के अन्य प्रगतिशील देशों में आदर्शरूप माना जाता था । इसी युग में बर्लिन, ब्रेस्लो, लण्डन और न्यूयार्क की यूनिवर्सिटियों की स्थापना हुई, या उनका पुनः संगठन किया गया । इस कार्य में पेरिस यूनिवर्सिटी के संगठन को आदर्शरूप से स्वीकृत किया गया था । फ्रेंच क्रान्तिकारियों ने वैज्ञानिक अनुसन्धान के कार्य को भी बहुत महत्त्व दिया, और इसके लिये उन्होंने राज्यकोश से प्रचुर परिमाण में धन का व्यय किया । क्रान्ति के कारण फ्रांस और यूरोप में जिस नवजीवन का प्रारम्भ हुआ था, वह इस युग के लेखकों और कवियों की रचनाओं में भलीभांति प्रतिबिम्बित होता है । फ्रांस के विक्टर ह्यूगो और ला मार्टीन जैसे साहित्यिक क्रान्ति युग की ही उपज थे । ब्रिटेन के बायरन और शैले, और जर्मनी के हाइन जैसे साहित्यिकों पर भी इस युग की भावनाओं का प्रभाव बहुत स्पष्ट है ।

(६) चर्च में परिवर्तन—फ्रांस का पुराना चर्च राजाओं के निरंकुश शासन का प्रबल समर्थक था । इसलिये फ्रेंच क्रान्तिकारियों ने उसे नष्ट करने का प्रयत्न किया । नैपोलियन के समय में चर्च का पुनरुद्धार हुआ, पर यह नया चर्च पुराने चर्च से उतना ही भिन्न था, जितना कि फ्रांस का नया शासन सोलहवें लुई के शासन से भिन्न था । क्रान्ति की लहर ने जनता में स्वतन्त्रता की जिस प्रवृत्ति को जन्म दिया था, उसका प्रभाव धार्मिक क्षेत्र पर भी पड़ा । अब लोग अन्धविश्वास और प्रमाणवाद के चंगुल से मुक्त होकर धार्मिक विषयों पर भी स्वतन्त्रता के साथ विचार करने में प्रवृत्त हुए ।

(७) राष्ट्रीयता—फ्रेंच राज्यक्रान्ति का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण परिणाम राष्ट्रीयता की भावना का प्रादुर्भाव था । इस पर हम एक पृथक् अध्याय में विशदरूपसे विचार करेंगे ।

इसमें सन्देह नहीं, कि क्रान्ति द्वारा न केवल फ्रांस अपितु यूरोप के अन्य देशों में भी एक नये युग का सूत्रपात हुआ था । इसी को हम यूरोप का 'आधुनिक युग' कहते हैं ।

## (२) नैपोलियन के बाद यूरोप की समस्याएँ

नैपोलियन के पतन के बाद यूरोप के राजनीतिज्ञों के सम्मुख मुख्य समस्याएँ निम्नलिखित थी—

(१) क्रान्ति का दमन—फ्रांस की राज्यक्रान्ति को प्रारम्भ हुए एक चौथाई शताब्दि व्यतीत हो चुकी थी । इस काल में यूरोप में भारी उथल-पुथल मच गई थी । पुरानी समस्याएँ टूट रही थी, नवीन युग का प्रादुर्भाव हो रहा था । नई और पुरानी दोनों प्रकार की प्रवृत्तियों में भारी संघर्ष चल रहा था । नैपोलियन परास्त हो गया था, और उसके साथ ही फ्रांस का सैनिक गौरव भी मिट्टी में मिल गया था । पर इससे नई प्रवृत्तियों का अन्त नहीं हो गया था । 'स्वतन्त्रता, समानता और भ्रातृभाव' का निनाद अब भी यूरोप में गूँज रहा था ।

राष्ट्रीयता की भावना लोगों में नवजीवन उत्पन्न कर रही थी। एकतन्त्र शासन का स्थान लोकतन्त्र शासन ले रहा था। लोग आपस में बात करते थे, राज्य जनता का है, वोट का हक सबको मिलना चाहिये, राजा की सत्ता जनता की इच्छा पर आश्रित है। ये सब प्रवृत्तियाँ फ्रेंच राज्यक्रान्ति ने उत्पन्न की थी। १७९२ में लेकर १८१५ तक फ्रांस के गिलाफ जितने भी गुट बने, सब इन प्रवृत्तियों के दुश्मन थे, उन्हें नष्ट करने में ही यूरोप का कल्याण समझते थे। इन गुटों का उद्देश्य क्रान्ति को कुचलना तथा एकतन्त्र शासन को फिर से स्थापित करना था। अब जब कि ये गुट अपने उद्देश्य में सफल हो गये थे, जब इन्होंने फ्रांस को परास्त कर दिया था, तब स्वाभाविक रूप में उनका यही प्रयत्न था, कि नई प्रवृत्तियों को सर्वथा नष्ट कर फिर से पुराने जमाने को कायम कर दिया जाय। इंग्लैण्ड और प्रशिया में नये युग की रोशनी पहुँच चुकी थी, पर वहाँ के शासक भी इस बात को अच्छी तरह समझे हुए थे, कि उनका कल्याण इसी में है, कि रूस और आस्ट्रिया के साथ मिलकर नई प्रवृत्तियों को कुचल दिया जाय। इसलिये अब नैपोलियन को परास्त करनेवाले विजयी राज्यों के सम्मुख पहला प्रश्न यही था, कि कौन से ऐसे उपाय किये जावें, जिनमें क्रान्ति की भावनाओं का नामोनिशान ही ससार से मिट जाय।

(२) नैपोलियन के साम्राज्य की व्यवस्था—इसके अतिरिक्त, दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न उनके सम्मुख यह था, कि नैपोलियन के साम्राज्य की क्या व्यवस्था की जाय। नैपोलियन की असाधारण विजयों ने यूरोप के अनेक पुराने राजवगों को नष्ट कर दिया था। स्पेन, पोर्तगाल, इटली, नेपल्स, स्वीडन, हालैण्ड, आस्ट्रियन नीदरलैण्ड, पोलैण्ड आदि विविध देशों के पुराने शासक नैपोलियन द्वारा नष्ट किये जा चुके थे। इन सब पर नैपोलियन के बन्धु-बान्धव या सेनापति शासन करने थे। अब उसके पतन के बाद यह प्रश्न था, कि इन विविध राज्यों के शासन की क्या व्यवस्था की जाय। यह प्रश्न बहुत विकट था। क्रान्ति को कुचलने के प्रश्न पर तो सब राज्य सहमत थे, पर इन राज्यों की पुन व्यवस्था के सम्बन्ध में उनमें भारी मतभेद था। यूरोप के सभी राजा महत्वाकांक्षी, साम्राज्यवादी तथा स्वार्थ से परिपूर्ण थे। वे इस बात के लिये उत्सुक थे, कि इस विशेष परिस्थिति से लाभ उठाकर अपने स्वार्थ को सिद्ध करें। साथ ही, विविध व्यक्तियों के विविध राजगद्दियों के सम्बन्ध में दावों पर भी गम्भीरता के साथ विचार किया जाना था। उस जमाने में राज्य भी मामूली जायदाद की हैसियत रखते थे। जिस तरह जमीन जायदाद के मामले में अनेक दावेदार होते हैं, और उन पर कानून की वारी-कियों से फैसला करना होता है, उसी प्रकार राज्यों की भी दशा थी। नैपोलियन के साम्राज्य के पतन से जो बहुत से प्रदेश इस समय राजाओं से रहित हो गये थे, उनके दावेदारों की कमी नहीं थी। वीएना की कांग्रेस में इन सब के दावों पर विचार करके यह फैसला किया जाना था, कि कौनसा राज्य किस दावेदार के सुपुर्द किया जावे।

(३) चर्च की समस्या—चर्च का मामला और भी विकट था। राज्यक्रान्ति ने न केवल फ्रांस में, अपितु पश्चिमी यूरोप के बहुत से प्रदेशों में चर्च की व्यवस्था को सर्वथा नष्ट कर दिया था। प्रोटेस्टेंट और रोमन कैथोलिक चर्चों का भेद तो यूरोप में था ही, अब राज्यक्रान्ति के कारण धर्म के विरुद्ध भावना भी बलवती हो गई थी। नैपोलियन ने तो

चर्च को सर्वथा राज्य की कठपुतली बना दिया था। पोप को कैद कर तथा उसके राज्य को अपने कब्जे में करके नैपोलियन ने चर्च के सम्पूर्ण रोब को ही धूल में मिला दिया था। पुराने जमाने की स्थापना में लगे हुए वीएना में एकत्रित राजनीतिज्ञों के सम्मुख चर्च की व्यवस्था का भी प्रश्न विद्यमान था।

(४) शान्तिरक्षा का उपाय—साथ ही, ये राजनीतिज्ञ ऐसा उपाय ढूँढने के लिये भी प्रयत्नशील थे, जिससे यूरोप में युद्ध की सम्भावना कम हो जावे। पच्चीस वर्ष के निरन्तर युद्धों से यूरोप के राजा तग आ गये थे। नैपोलियन के विरुद्ध जो अन्तिम गुट बना था, उसमें यूरोप के बहुत से प्रमुख राज्य सम्मिलित थे। अब इन राज्यों के राजनीतिज्ञों का खयाल था, कि यदि इस गुट को कायम रखा जाय, तो एक ऐसे उपाय का सुगमता से आविष्कार किया जा सकता है, जिससे भविष्य में युद्ध की सम्भावना बहुत कुछ दूर हो जायगी। इस उपाय को ढूँढ निकालना भी उनके सम्मुख एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या थी।

### (३) मेटरनिख

नैपोलियन के पतन के बाद यूरोप में जिन राजनीतिज्ञों ने सर्वप्रधान स्थान प्राप्त किया, उनका नेता मेटरनिख था। प्रतिक्रिया और क्रान्ति की विरोधी प्रवृत्तियों को मेटरनिख के रूप में एक अत्यन्त योग्य नेता मिल गया था। मेटरनिख का जन्म १७७३ ईस्वी में हुआ था। वह रूहइन नदी के तट पर स्थित कोब्लेन्ट्स नामक स्थान का रहनेवाला था। उसके माता पिता कुलीन श्रेणी के व्यक्ति थे। उसका पालन-पोषण कुलीन वातावरण में हुआ था। जब वह विश्वविद्यालय की शिक्षा प्राप्त कर रहा था, तब उसने फ्रांस से भागे हुए कुलीन परिवारों की दुःख गाथाओं को सुना था। इन गाथाओं तथा राज्यक्रान्ति के वृत्तान्त को सुनकर उसके हृदय में नवीन प्रवृत्तियों के विरुद्ध तीव्र भावना उत्पन्न हो गई थी। उसकी पैतृक सम्पत्ति नैपोलियन ने जप्त कर ली थी, इस कारण वह क्रान्ति तथा नई प्रवृत्तियों का और भी अधिक दुश्मन हो गया था। आस्ट्रिया के प्रधानमन्त्री के परिवार में उसका विवाह हुआ। इस कारण उसकी महत्ता तथा वैभव बहुत अधिक बढ़ गये। अपने श्वसुर-कुल की सहायता से वह यूरोप के सभी राजनीतिज्ञों तथा राजकुलों से परिचित हो गया। धीरे-धीरे आस्ट्रिया के राजनीतिक क्षेत्रों में उसका महत्त्व बढ़ता गया। १८०९ में उसे आस्ट्रिया के प्रधान मन्त्री के पद पर नियत किया गया। मेटरनिख ४० साल तक निरन्तर आस्ट्रिया का प्रधान मन्त्री रहा। इस सुदीर्घ काल में उसने अपनी शक्ति को पूर्ण रूप से क्रान्ति की भावनाओं को नष्ट करने तथा पुराने जमाने को फिर से स्थापित करने के लिये लगाया। उसका सिद्धान्त था, कि क्रान्ति एक ऐसी बीमारी है, जिसका इलाज किया जाना चाहिये। यह एक ऐसा ज्वालामुखी है, जिसका शमन करना आवश्यक है। क्रान्ति एक ऐसा भयकर राक्षस है, जो हर समय सामाजिक व्यवस्था को निगलने के लिये तैयार रहता है। वह कहा करता था, कि राजाओं को अधिकार है, कि वे अपनी प्रजा के भाग्य का निवटारा करें। राजा केवल ईश्वर के सम्मुख ही उत्तरदायी होते हैं, जनता के प्रति नहीं। उसका मत था, कि यूरोप को स्वत-

न्वता की जरूरत नहीं है, उसे शान्ति और व्यवस्था की आवश्यकता है। वह अपने जीवन का यही उद्देश्य समझता था, कि समाज के क्षीण होने हुए मगठन की रक्षा करने के लिए नई प्रवृत्तियों तथा क्रान्ति की भावनाओं को जड़ में नष्ट कर दिया जावे।

केवल मेटर्निय ही नहीं, यूरोप के अन्य राजनीतिज्ञ भी इन्हीं विचारों को मानते थे। उस समय के यूरोपियन वातावरण में ये ही विचार मुख्यतया प्रचलित थे। इन राजनीतिज्ञों का यही मिश्रान्त था, कि जनता के अधिकारों की उपेक्षा की जाय। जनता शासन में हिंसा चाहती है, अपने अधिकार मांगती है—किननी फिज़ूल बान है। अधिकार तो राजा के है। दुनिया में रिपब्लिकों की जरूरत नहीं है। बँध शासन जीर ज़रारतना—एक ही बात है। यह प्रतिक्रिया का युग था। फ्रांस ने जिन नई प्रवृत्तियों को गुरु किया था, उनके विरुद्ध अब भयंकर प्रतिक्रिया हो रही थी। तलवार के जोर पर पुराने नमाने को स्थापित करने का उद्योग किया जा रहा था। मेटर्निय इस सम्पूर्ण प्रयत्न का प्रधान पुरोहित था। इसीलिये इस युग को 'मेटर्निय का युग' भी कहते हैं।

नैपोलियन के पतन के बाद यूरोप का पुनः निर्माण करने के लिये वीएना में जो कांग्रेस हुई, उसके सम्मुख सबसे महत्वपूर्ण विचारणीय विषय यही था, कि क्रान्ति के भूत में किस प्रकार यूरोप की रक्षा की जाय, और समाज को छिन्न-भिन्न होने में कैसे रोक दिया जाय।

### (४) वीएना की कांग्रेस

पेरिस की संधि—जिस समय नैपोलियन को फ्रांस में बहिष्कृत कर एल्बा के द्वीप में भेज दिया गया, और १८वें लुई को फ्रांस की गद्दी पर बिठाया गया, उसी समय कुछ महत्वपूर्ण तथा आवश्यक मामलों का फैसला कर लिया गया था। ३० मई, १८१४ को विजयी राज्यों ने १८वें लुई के साथ एक सन्धि की थी, जो कि पेरिस की सन्धि के नाम से प्रसिद्ध है। इस सन्धि के अनुसार फ्रांस पर ब्रूवों वश का अधिकार स्वीकृत किया गया, और फ्रांस की वह सीमा निश्चित की गई, जो कि १ नवम्बर १७९२ के दिखी थी। उस समय जो उपनिवेश फ्रांस के अधीन थे, वे भी उसे वापस लौटा दिये गये। नैपोलियन के भग्न साम्राज्य से नीदरलैंड के नये राज्य की सृष्टि की गई। इसे हालैंड और बेल्जियम को मिला कर बनाया गया था। इस नवीन राज्य पर शासन करने के लिये हालैंड के पुराने आरेन्ज राजवंश के अधिकार को स्वीकृत किया गया। स्विट्जरलैंड को स्वतन्त्र कर दिया गया। जर्मनी के विविध राज्यों को मिलाकर एक नवीन संघ की रचना की गई। इटली के विविध पुराने राज्यों का पुनरुद्धार किया गया, और इस प्रकार जो विविध रिपब्लिकन राज्य क्रान्ति द्वारा प्रादुर्भूत हुए थे, उन सबका अन्त कर दिया गया। पेरिस की सन्धि में मोटी-मोटी बातों का निबटारा कर लिया गया था। शेष बातें वीएना की कांग्रेस के लिये छोड़ दी गई थी। महत्वपूर्ण प्रश्नों का फैसला वीएना में ही किया जाना था।

कांग्रेस के प्रतिनिधि—सितम्बर, १८१४ में वीएना की कांग्रेस प्रारम्भ हुई। सत्ता के आधुनिक इतिहास में यह कांग्रेस अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखती है। राजनीतिज्ञों के

इसमें बड़ी-बड़ी आगाएँ थी। टर्की के सिवाय अन्य सब यूरोपियन देशों के प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित हुए थे। कुल मिलाकर ९० बड़े महाराजा और ५३ राजा या उनके प्रतिनिधि इसमें एकत्रित थे। आस्ट्रिया का सम्राट् फ्रांसिस प्रथम अपने योग्य प्रधानमंत्री मेटरनिख के साथ इस कांग्रेस का सम्पूर्ण प्रबन्ध कर रहा था। सब राजे महाराजे उसके अतिथि थे। रूस का जार अलेक्जेंडर प्रथम अपने मन्त्री नेसलरोड और जर्मनी के प्रसिद्ध नेता स्टार्न के साथ उपस्थित था। प्रशिया का राजा फ्रेडरिक विलियम तृतीय हार्डनबर्ग और फोन हुम्बोल्ट को साथ लेकर आया था। ग्रेट ब्रिटेन ने कंसलरे तथा वेलिंगटन के ड्यूक को अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा था। फ्रांस की तरफ से तेलीरा आया था, जो मृदुभाषिता और चाणाक्षता में अपना सानी नहीं रखता था। पोप की तरफ से कार्डिनल गानस ल्वी उपस्थित हुआ था। इनके अतिरिक्त, अन्य भी बहुत से प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और राजे महाराजे यूरोप के भाग्य का निर्माण करने के लिये वीएना में एकत्रित हुए थे। इतने महाराजाओं, अमीर उमराओं, सरदारों और श्रीमन्तों के उपस्थित होने से वीएना की गान का कोई ठिकाना नहीं रहा था। तरह-तरह की बढ़िया पोशाकें सब तरफ नजर आती थी। धूम-धाम और रौनक का कोई अन्त नहीं था। प्रतिनिधियों का स्वागत करने के लिये आस्ट्रियन सरकार ने कोई कसर नहीं उठा रखी थी। भोज, गान नाच, तमाशों की कोई हद नहीं थी। यूरोप भर से नाचने गानेवाले इकट्ठे किये गये थे। प्रतिनिधियों की आवभगत करते हुए आस्ट्रियन सरकार दिवालिया तक हो गई थी।

**कार्यनीति**—कांग्रेस के कार्य का कोई निश्चित ढंग नहीं था। कोई प्रस्ताव पेश नहीं होने थे, वोट लेने की भी व्यवस्था नहीं थी। नाचघर में राज्यों की सीमाएँ तय होती थी। नाच-तमाशों देखते हुए राज्यों को बढ़ाने या घटाने का फैसला हो जाता था। गम्भीर से गम्भीर राजनीतिक मामले सहभोजों, तमाशों और सगीत सम्मेलन में तय कर लिये जाते थे। किसी ने कोई हँसी मजाक की बात कही, औरों को पसन्द आ गई, मान ली गई। जिन देशों के भाग्य का निर्णय हो रहा है, उनकी जनता क्या चाहती है, इसकी किसी को परवाह नहीं थी। रूस, आस्ट्रिया, प्रशिया और ब्रिटेन के शक्तिशाली प्रतिनिधि जो चाहते थे, हो जाता था। कांग्रेस का कोई निश्चित सभापति नहीं था। मेटरनिख ही प्रधान और मन्त्री दोनों का कार्य करता था। वह जिस ढंग से चाहता, कार्य चलाता। आस्ट्रिया, प्रशिया, रूस और ब्रिटेन—इन चार मुख्य राज्यों ने आपस में गुप्त फैसला कर लिया था, कि सब मामलों पर पहले आपस में फैसला कर लेंगे, और फिर उसे कांग्रेस के सम्मुख पेश करेंगे। निर्वल राष्ट्रों की किसी को परवाह नहीं थी। नैपोलियन का पतन करने के लिये जो अन्तिम गुट बना था, उसने डके की चोट के साथ उद्घोषित किया था, कि हम निर्वल राष्ट्रों को साम्राज्यवादी नैपोलियन के पजे से मुक्त करना चाहते हैं, पर अब विजयी हो जाने के अनन्तर उन्हें अपने स्वार्थ-साधन के अतिरिक्त अन्य किसी बात की चिन्ता नहीं थी। फ्रांस का प्रतिनिधि तेलीरा ही था, जिसे निर्वल राष्ट्रों की फिकर नहीं थी। वस्तुतः, वह इन छोटे राज्यों की सहायता से अपने देश के हितों की रक्षा करना चाहता था। वह इस बात पर जोर देता था, कि कांग्रेस का कार्य अन्तर्-राष्ट्रीय कानून के अनुसार होना चाहिये। परन्तु प्रशिया का फोन हुम्बोल्ट उसे जवाब देता

या, 'जिसकी लाठी, उसकी भैंस' । हम अन्तर्गोष्ठीय कानून को मानते ही नहीं। विजयी राज्यों के प्रतिनिधि अपनी ताकत के जोर पर मनमानी करने पर तुल्ले हुए थे। पर उनके स्वार्थ भी आपस में टकराते थे। निर्वल राज्यों को डगी वान का भरोसा था। तेज़ीरा इन्ही मतभेदों और झगड़ों ने लाभ उठाकर अपने उद्देश्य को पूर्ण करने का प्रयत्न कर रहा था।

विचारणीय प्रश्न—वीणना की कांग्रेस के सम्मुख प्रधानतया निम्नलिखित कार्य थे—

(१) ब्रिजियम, हॉलैण्ड, स्वीडन का राज्यसंघ, डेन्मार्क के विविध राज्य, वारमा का राज्य और स्विट्जरलैण्ड की सीमाओं को निश्चित किया जाना था। यह भी निर्णय होना था, कि इन प्रदेशों को पृथक् राज्य के रूप में रखा जाय या नहीं।

(२) नैपोलियन के जमाने में जो विविध नवीन सामक यगोप के रण-मंच पर प्रगट हो गये थे, उनका निवटारा किया जाना था। साथ ही, पुराने राजवशों के पुनर्द्धार के विषय पर भी विचार होना था।

(३) फ्रांस फिर कभी यूरोप की शान्ति और व्यवस्था के लिये मनग न बन सके, इसका भी इन्तजाम आवश्यक था।

(४) जिन राज्यों ने नैपोलियन की सहायता की थी, या उसकी आज्ञाओं का पालन किया था, उन्हें क्या दण्ड दिया जाय, इस बात का भी निर्णय किया जाना था।

निर्णय करने के सिद्धान्त—इन समस्याओं का निर्णय बहुत जटिल नहीं था, पर शक्ति-शाली यूरोपियन राज्यों की पारस्परिक प्रतिस्पर्धा तथा स्वार्थभावना ने इसे बहुत जटिल बना दिया था। रूस का जार सम्पूर्ण पोलैण्ड पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था। प्रशिया की आख सेक्सनी पर थी। आस्ट्रिया इटली को हडप जाना चाहता था, और जर्मनी पर भी पूर्ववत् अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था। ग्रेट ब्रिटेन की इच्छा थी, कि फ्रांस के जिन उपनिवेशों पर गत युद्धों में उसने विजय प्राप्त की थी, उन्हें अपने कब्जे में रखे और साथ ही समुद्र पर भी उसका प्रभुत्व अक्षुण्ण बना रहे। फ्रांस अपने पुराने राज्य को कायम रखने की चिन्ता में था। छोटे राज्यों की अपनी जलज स्कीमें थी। ऐसी स्थिति में किसी भी मामले का निवटारा सुगमता से कर सकना सम्भव नहीं था। विजयी राज्यों का सिद्धान्त तो यह था, कि पराजितों के माल को आपस में बांट लिया जाय। इसी सिद्धान्त को लेकर वे अपना कार्य कर रहे थे। वे समझते थे, न्याय यह है, कि जो भी राजा राज्यक्रान्ति से पूर्व यूरोप के विविध देशों का शासन कर रहे थे, उन सब के वंशधरों को फिर से राजगद्दी पर बिठा दिया जाय। पर यह कर सकना सुगम नहीं था। इसलिये निश्चय किया गया, कि इन राजाओं को शासन के लिये कोई न कोई प्रदेश देकर सन्तुष्ट करने का प्रयत्न किया जाय। वीणना में एकराजनीतिज्ञों के सम्मुख 'राष्ट्रीयता' तो कोई कीमत ही नहीं रखती थी। राष्ट्रीयता की सर्वथा उपेक्षा कर वे 'परमेश्वर' द्वारा पृथिवी का शासन करने के लिये नियत किये गये राजाओं के अधिकारों और दावों की रक्षा करने के लिये कटिबद्ध थे। आज ससार में 'राष्ट्रीयता का सिद्धान्त' सर्वसम्मत है, पर उस समय यह एक भयंकर तथा क्रान्तिकारी सिद्धान्त था, जिसे राज्यक्रान्ति ने उत्पन्न किया था। उस समय के 'सभ्य' लोग इसे हानिकारक तथा अनुचित समझते थे।



मुख्य फैसले—वीएना की कांग्रेस ने यूरोप के राजनीतिक नक्शे में जो मुख्य-मुख्य परिवर्तन किये, उन्हें यहाँ उल्लिखित करना आवश्यक है—

(१) हालैंड, स्विट्जरलैंड और फ्रांस—पिछले दिनों में फ्रांस ने जिन प्रदेशों पर अधिकार प्राप्त कर लिया था, उनमें से बेल्जियम और लुक्समबुर्ग हालैंड के साथ मिला दिये गये और इन तीनों राज्यों पर शासन करने के लिये आरेन्ज के राजवंश को नियत किया गया। बेल्जियम और लुक्समबुर्ग की जनता हालैंड की जनता से सर्वथा भिन्न थी। परन्तु वीएना की कांग्रेस ने इस बात की जरा भी परवाह न कर उन्हें एक ही शासन के अधीन कर दिया। स्विट्जरलैंड को फिर स्वतन्त्र सघात्मक रिपब्लिक के रूप में परिणत कर दिया गया। फ्रांस में वूवों राजवंश का पुनरुद्धार किया गया। उसकी सीमाएँ वे ही रखी गईं, जो कि राज्यक्रान्ति से पूर्व थी। जब नैपोलियन एल्वा से वापिस आया था, तो फ्रांस की जनता ने उसका साथ दिया था। इस अपराध पर सेवाय के प्रदेश को फ्रांस से छीन लिया गया। फ्रांस को यह अच्छी सजा दी गई थी। उस जमाने का ढग ही यह था।

(२) जर्मनी—नैपोलियन के आक्रमणों से पूर्व जर्मनी में कई सौ राज्य थे। इनमें से अनेक राज्य चर्च की सम्पत्ति थे, और अनेक का विस्तार एक शहर से अधिक नहीं था। अधिकांश राज्य छोटे-छोटे थे। नैपोलियन ने इनमें से बहुत से राज्यों का अन्त कर कुछ अधिक महत्त्वपूर्ण राज्यों को सगठित कर रहाइन के राज्यसंघ का निर्माण किया था। जब यह तो असम्भव था, कि क्रान्ति के युग से पूर्व के सैकड़ों राज्यों का पुनरुद्धार किया जाय। वीएना के राजनीतिज्ञों ने जर्मनी के छोटे-छोटे राज्यों के दावों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सब मिलाकर ३८ राज्यों को कायम रखा और उनको एक नवीन संघ में सगठित किया। इस नवीन जर्मन राज्यसंघ (कान्फिडरेशन) की एक केन्द्रीय राजसभा बनाई गई, जिसका नेता आस्ट्रिया को नियत किया गया। आस्ट्रिया की अधिकांश जनता जर्मन जाति की ही है। परन्तु ऐतिहासिक घटनाओं ने उसे बहुत समय से जर्मनी में पृथक् किया हुआ था। पर वस्तुतः वह प्रशिया आदि अन्य जर्मन राज्यों के ही सदस्य था, और इस काल के जर्मन राज्यों में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण था। आस्ट्रिया के नेतृत्व में जब जिस नवीन जर्मन राज्यसंघ का निर्माण हुआ, उसमें सब राज्यों—जिनकी संख्या ४० थी—के प्रतिनिधि सम्मिलित किये गये। यह स्मरण रखना चाहिये, कि ये जनता के प्रतिनिधि न होकर राजाओं के प्रतिनिधि थे, और उन्हीं के प्रति उत्तरदायी होते थे। जर्मनी के जिन राज्यों की सत्ता को वीएना की कांग्रेस ने स्वीकृत किया था, उनकी सीमा निश्चिन करने हुए उसे बहुत कठिनता का सामना करना पड़ा। प्रशिया को बहुत नये प्रदेश दिये गये। रहाइन नदी का पश्चिमी प्रदेश, जिसको फ्रांस ने जीत कर अपने अधीन कर लिया था, जब प्रशिया को दे दिया गया। सैक्सनी के राज्य ने पिछले युद्धों में नैपोलियन की सहायता की थी, अतः उसे यह सजा दी गई, कि उसका ४० प्रतिशत प्रदेश प्रशिया के अधीन कर दिया गया। पोलैंड और पोमेरेनिया का भी कुछ प्रदेश प्रशिया को दिया गया। नैपोलियन को परास्त करने में प्रशिया का बड़ा हाथ था। जन स्वाभाविक रूप से उस वीएना की कांग्रेस में बहुत से नये प्रदेश प्राप्त हुए और वह यूरोप के प्रथम श्रेणी के राज्यों में गिना जाने लगा। प्रशिया सैनिक दृष्टि से तो पहले ही बहुत उन्नति कर चुका था,

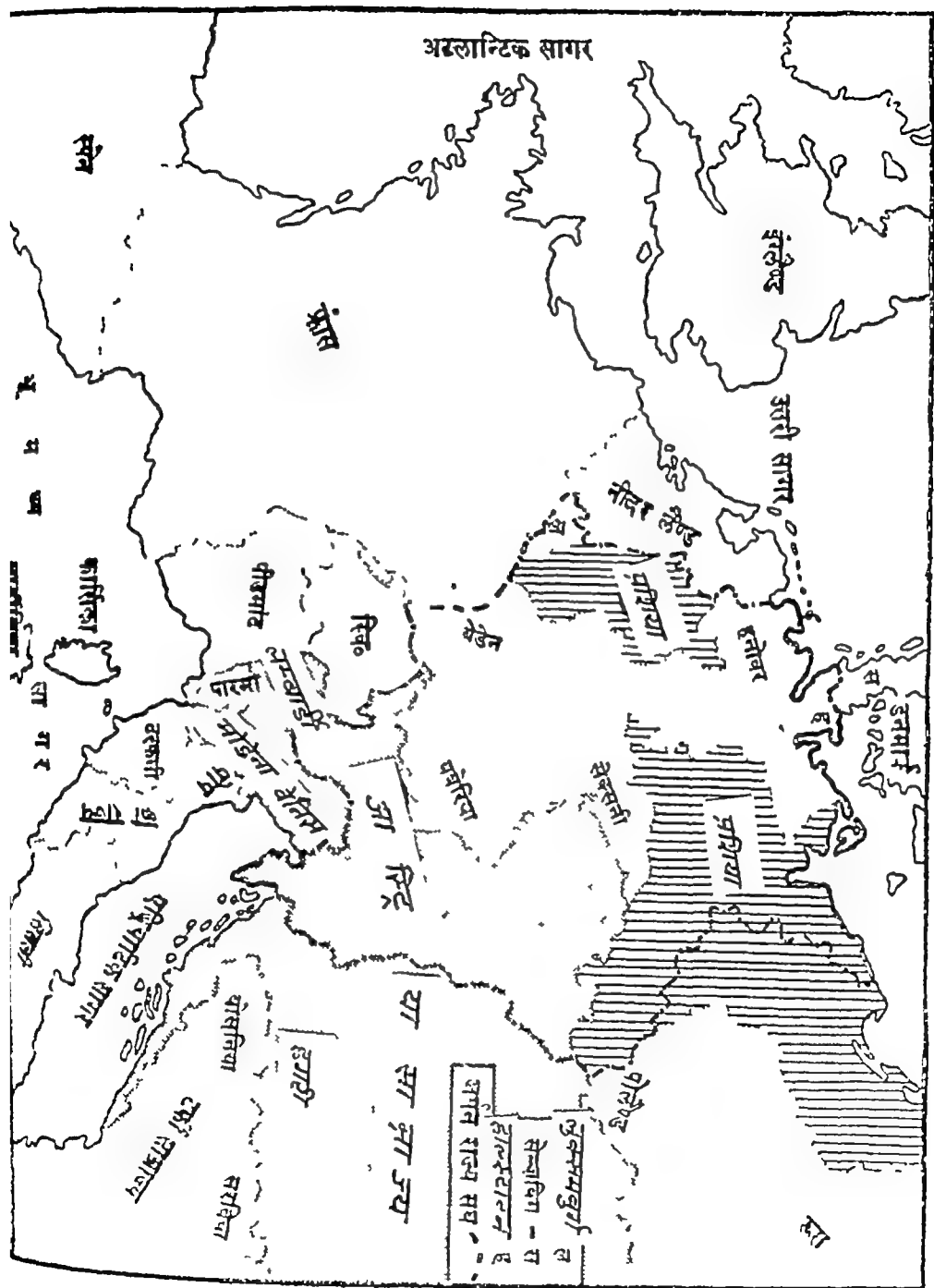
अब उसका क्षेत्र भी बहुत काफी विस्तृत हो गया।

(३) इटली—इटली के विविध राज्या को फिर से स्थापित किया गया। नेपल्स की राजगद्दी फिर वृत्ता राजवंश के अधीन की गई। पोप के प्रदेश फिर पोप के अधीन कर दिये गये। पीट्रमाण्ट का राज्य फिर सार्डिनिया के राजा को दिया गया। जिनाजा के प्राचीन रिपब्लिक भी इसी राज्य के साथ सम्मिलित कर दी गई। टस्कनी और मोडन से फिर से उनके पुराने राजवंशों की स्थापना की गई। परमा का राज्य नैपोलियन के वर्मपत्नी मेरिया लुइसा के, जो कि आस्ट्रिया की राजकुमारी थी, सुपुर्द कर दिया गया पहले वेल्जियम पर, जो आस्ट्रियन नीदरलैण्ड के नाम से प्रसिद्ध था, आस्ट्रिया का बना था। अब यह प्रदेश हालैण्ड को दे दिया गया था। अब आस्ट्रिया को मनुष्ट करने के लिए वेल्जियम के बदले में वेनिस की प्राचीन रिपब्लिक उसे माप दी गई। मिलान तो नैपोलियन के युद्धों से पूर्व भी आस्ट्रिया के अधीन था। अब वेनिस पर भी अफ्रिका हो जाने के कारण उत्तरी इटली का एक महत्वपूर्ण प्रदेश—जो कि लोम्बार्डो-वेनेटिय राज्य के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है, आस्ट्रिया के अधीन हो गया। इन प्रकार इटली में अनेक राज्य कायम हुए। नैपोलियन के आक्रमणों का एक बड़ा लाभ इटली के लिये यह हुआ था, कि वह प्रधानतया दो राज्यों में संगठित हो गया था—इटली का राज और नेपल्स। इससे इटालियन लोगों में अपनी एकता और राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न होने लग गई थी। पर अब फिर उसे अनेक भागों में विभक्त कर दिया गया, और इटली के एक संगठन में संगठित होने की सम्भावना सुदीर्घ समय के लिये दूर जा पड़ी।

(४) स्वीडन—फिनलैण्ड का प्रदेश स्वीडन में लेकर रूस को दे दिया गया। इस प्रकार पोमेरेनिया का प्रदेश प्रशिया के सुपुर्द किया गया। इनके बदले में नार्वे का राज स्वीडन को दे दिया गया। नार्वे पहले डेनमार्क के अधीन था, पर क्योंकि डेनमार्क के राज ने नैपोलियन की सहायता की थी, अतः उसे यह सजा दी गई, कि नार्वे उसमें छीन लिया गया।

(५) पोलैण्ड—पोलैण्ड को तीन टुकड़ों में विभक्त कर रूस, प्रशिया तथा आस्ट्रिया ने निगल लिया। इससे पूर्व भी पोलैण्ड को अनेक बार इन राज्यों ने किन प्रकार आपस में बाटा था, इस का वृत्तांत यहां लिखने की आवश्यकता नहीं है। इतना निर्दिष्ट करने पर्याप्त है, कि वीएना की कांग्रेस ने पोलैण्ड का मुख्य भाग रूस के अर्पित किया। वारस का जो राज्य नैपोलियन के समय में बनाया गया था, वह भी रूस को दे दिया गया। पोमरानिया और डान्ट्सिग के प्रदेश प्रशिया के हिस्से में आये। दक्षिणी गैलेसिया आस्ट्रिया के सुपुर्द किया गया।

(६) ग्रेट ब्रिटेन—ग्रेट ब्रिटेन ने बहुत से नवीन उपनिवेश प्राप्त किये। माल्टा सेण्ट लूसिया, टोबैगो और मोरिशस—ये द्वीप फ्रांस से लेकर ब्रिटेन को दिये गये। ट्रिनिडाड और टोबागो पहले स्पेन के अधीन थे। वे भी अब ब्रिटेन को प्राप्त हुए। इसी प्रकार सीलोन, केप कोलोनी और गायना का कुछ प्रदेश हालैण्ड से ब्रिटेन के हाथ लगा। ऊपर से देखने पर इन प्रदेशों व उपनिवेशों का विशेष महत्त्व नहीं मालूम होता, पर वस्तुतः ग्रेट ब्रिटेन इसी काल में अपने विशाल सामुद्रिक व औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव डाल रहा था।



अटलांटिक सागर

इंग्लैण्ड

अरबी सागर

होबोव

मोराया

मोराया

मोराया

मोराया

मोराया

मोराया

मोराया

मोराया

मोराया

मोराया

मोराया

मोराया

मोराया

मोराया

मोराया

मोराया

मोराया

मोराया

मोराया

मोराया

मोराया

मोराया

जो द्वीप उसने वीएना की कांग्रेस में प्राप्त किये थे, वे सामुद्रिक शक्ति की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे। विशेषतया माल्टा, सीलोन, केप कोलोनी और मोरीशस आगे चलकर ब्रिटेन के लिये बहुत ही उपयोगी मित्र हुए।

(७) स्पेन—स्पेन में फिर से बहा के पुराने बूबों राजवश की स्थापना की गई।

दाम प्रथा का विरोध—इन विविध राजनीतिक और प्रादेशिक परिवर्तनों के अतिरिक्त वीएना की कांग्रेस ने अन्य भी अनेक निर्णय किये। दामप्रथा के विरुद्ध प्रस्ताव पास हुआ, और यह उद्घोषित किया गया कि यह प्रथा भयाना और मानवीय अधिकारों के सर्वथा प्रतिकूल है। परन्तु इस प्रस्ताव को क्रिया में परिणत करना प्रत्येक राज्य की अपनी इच्छा पर छोड़ दिया गया। अठारहवीं सदी में दामों का व्यापार जिस क्रूरता से होता था, दासों पर जिस ढग से भयकर अत्याचार किये जाते थे, उससे पाश्चात्य समाज के सम्य विचारशील लोग उद्विग्न हो उठे थे। सबसे पूर्व अमेरिका ने दाम प्रथा के विरुद्ध जावान उठाई। उसके बाद मार्च, १८०७ में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस प्रथा को नष्ट करने का प्रस्ताव पास किया। १८१३ में स्वीडन ने दाम प्रथा को नष्ट किया, और एक वर्ष बाद १८१४ में हालैण्ड ने स्वीडन का अनुसरण किया। वीएना की कांग्रेस में पूर्व ही दामप्रथा के विरुद्ध वातावरण तैयार था, और इस कारण इस विषय में प्रस्ताव पास करना बहुत कठिन बात नहीं थी।

अन्तर्राष्ट्रीय विधान—दामप्रथा के विरुद्ध प्रस्ताव पास करने के अतिरिक्त वीएना की कांग्रेस ने अन्तर्राष्ट्रीय विधान तैयार करने के लिये भी उद्योग किया। यूरोप की नदियों में नौकानयन के लिये विविध देशों में क्या नियम हों, समुद्र का उपयोग विविध राज्य किस प्रकार करे, और राज्यों के आपस में व्यवहार करने के लिये क्या नियम हों—इन सब बातों को एक विधान में सकलित किया गया।

वाटर्लू के युद्ध से कुछ दिन पूर्व २ जून, १८१५ तक वीएना की कांग्रेस अपना कार्य समाप्त कर चुकी थी। सब समझौतों को एक निश्चित विधान में एकत्रित कर लिया गया था, और उन पर विविध राज्यों के हस्ताक्षर भी हो चुके थे।

कांग्रेस की भूलें—वीएना की कांग्रेस का यह कार्य बीसवीं सदी के ऐतिहासिक को बहुत ही अद्भुत तथा विचित्र प्रतीत होगा। वीएना में एकत्रित राजनीतिज्ञों की दृष्टि में राष्ट्रीयता के सिद्धान्त का कोई महत्व नहीं था। बेल्जियम के लोगों को अपना पृथक् राज्य बनाने का हक है, नार्वे को स्वीडन के साथ नहीं मिलाना चाहिये, फिनलैंड के नीचे नहीं रहना चाहते, पोलैंड में जो लोग बसते हैं, वे एक हैं, उन्हें तीन टुकड़ों में बाँटकर तीन लुटेरों के हाथों में नहीं सौंप देना चाहिये, इटली एक देश है, उसे एक संगठन में संगठित करना चाहिये—ये सब विचार वीएना के इन 'महान् राजनीतिज्ञों' को बहुत ही अस्वाभाविक, अनुचित तथा क्रान्तिकारी प्रतीत होते थे। साथ ही, राज्य के शासन में जनता की इच्छा को भी कोई स्थान प्राप्त है, यह बात इन राजनीतिज्ञों को समझ में नहीं आती थी। जनता के भी कोई अधिकार है, यह इनकी अकल में ही नहीं समाता था। इनकी दृष्टि में यदि किसी के अधिकार थे, तो केवल उन उच्च राजवशों के, जिन्हें साक्षात् भगवान् ने पृथिवी पर अपना प्रतिनिधि नियत किया है। वीएना में जो कुछ भी

हुआ, समय की प्रवृत्तियों के सर्वथा विरुद्ध हुआ। फ्रांस की राज्यक्रान्ति ने जिन प्रवृत्तियों को जन्म दिया गया था, वे एकदेशीय नहीं रह सकी थी। उन्होंने धीरे-धीरे सम्पूर्ण यूरोप को ही नहीं, अपितु सम्पूर्ण ससार को व्याप्त कर लिया था। वीएना में उन प्रवृत्तियों की उपेक्षा की गई। यह सर्वथा स्वाभाविक था, क्योंकि मानव जाति की एक निर्वलता है, वह नई बात को जल्दी नहीं समझ सकती, नई प्रवृत्तियों को सुगमता से नहीं पहचान सकती। परन्तु यह स्पष्ट है, कि वीएना में जो कुछ हुआ, वह समय को देखते हुए सर्वथा अनुचित तथा अस्वाभाविक था। यही कारण है, कि अगली एक सदी के यूरोपीय इतिहास ने वीएना की सम्पूर्ण कृति को पलट दिया। १८१५ के बाद १५ साल के अन्दर ही बेल्जियम हालैंड से पृथक् हो गया। ५० सालों में इटली और जर्मनी का स्वरूप सर्वथा परिवर्तित हो गया। इटली एक हो गया, सम्पूर्ण इटली में एक राज्य स्थापित हो गया। जर्मनी ने आस्ट्रिया से पृथक् होकर अपने नवीन सगठन का निर्माण किया। नार्वे को स्वीडन से पृथक् होने में देर नहीं लगी। १९१४-१८ के यूरोपीय महायुद्ध ने तो राज्यों की सीमा को राष्ट्रीयता के आधार पर निश्चित करने में कोई भी कसर उठा नहीं रखी। पश्चिमी ससार में उन्नीसवीं सदी का इतिहास राष्ट्रीयता तथा लोकसत्तावाद के सिद्धान्तों और पुराने जमाने के पारस्परिक संघर्ष के वृत्तान्त से परिपूर्ण है। आखिरकार, नये सिद्धान्तों की विजय हुई। आज ससार राष्ट्रीयता के सिद्धान्त को स्वीकार करता है, स्वभाग्य-निर्णय तथा लोकसत्तावाद के सिद्धान्तों में आज किसी को भी सन्देह नहीं रहा है। आज दुनिया वीएना की कांग्रेस के वातावरण से बहुत आगे बढ़ गई है।

कांग्रेस से लाभ—परन्तु वीएना की कांग्रेस से अनेक लाभ भी हुए। यूरोप में शान्ति की स्थापना हो गई। चौथाई सदी के निरन्तर युद्धों के बाद यूरोप की शान्ति की बहुत सरत जरूरत थी। कम से कम इस शान्ति की स्थापना में वीएना की कांग्रेस को अवश्य मफलता हुई। इसके अतिरिक्त, यह पहला ही अवसर था, जब यूरोप के सम्पूर्ण राज्यों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किये थे। इससे कम से कम राज्यों को यह तो अनुभव हुआ, कि हम परस्पर मिलकर भी कार्य कर सकते हैं, आपस में बातचीत करके भी किसी एक नमज्जौते पर पहुँच सकते हैं। राज्यों की अराजकता को नष्ट करने के लिये यह एक महत्वपूर्ण पग था। वीएना में यूरोप भर के प्रतिनिधि एकत्रित हुए थे। उन्होंने मिलकर अपनी समस्याओं पर विचार किया था, चाहे उनके विचार करने का ढग कितना ही निकम्मा क्यों न हो, चाहे उनके विचार कितने ही पुराने तथा भद्दे क्यों न हों—पर वे एक निश्चित उद्देश्य के लिये इकट्ठे तो हुए थे, और समय को देखते हुए यह बात भी कम न थी।

दसवाँ अध्याय

## प्रतिक्रिया का काल

### १. अन्तर्राष्ट्रीयता की ओर पहला पग

वीएना की कांग्रेस ने अपना कार्य अभी समाप्त किया ही था, कि नैपोलियन एल्बा के द्वीप से निकलकर फ्रांस पहुँच गया। किम प्रकार वाटर्लू के रणक्षेत्र में उसे सदा के लिये परास्त कर दिया गया, इसका वर्णन पहले किया जा चुका है। नैपोलियन के पतन के अनन्तर यूरोपियन राज्यों को निश्चितता और मनोप का माम लेने का अवसर मिला। यूरोप युद्धों में थक चुका था। केवल राजा ही नहीं, जनता भी शान्ति के लिये उत्सुक थी। लोग लड़ाई से ऊब चुके थे, और वस्तुतः यूरोप को उस समय किसी ऐसे उपाय की आवश्यकता थी, जिससे युद्धों की सम्भावना एक अच्छे बड़े समय के लिये दूर हो सके। इन दशा में यूरोप के प्रमुख राज्यों में स्वाभाविक रूप से ऐसे साधनों को अपनाने की प्रवृत्ति हुई, जिनमें वे अपने मामलों को परस्पर सहयोग व विचारविनिमय द्वारा, युद्ध के बिना ही निबटाने में समर्थ हो। आगे चलकर जिस अन्तर्राष्ट्रीयता का यूरोप में विकास हुआ, उसकी ओर यह प्रथम पग था।

**पवित्र मित्रमण्डल**—आस्ट्रिया, रूस, प्रशिया और ग्रेट ब्रिटेन ने आपस में मिलकर नैपोलियन को परास्त किया था। वीएना में भी ये चार राज्य ही सर्वप्रधान थे। अब इनके कन्धों पर ही इस बात की भी जिम्मेवारी थी, कि युद्ध की सम्भावना को दूर करने के लिये उपाय करें। सबसे पूर्व रूस के जार अलेक्जेंडर प्रथम ने यह प्रस्ताव पेश किया, कि राजा लोग मिलकर एक धार्मिक भाई-चारे का निर्माण करें, और यह मित्रमण्डल यूरोप में शान्ति स्थापित रखने की उत्तरदायिता अपने ऊपर ले। अलेक्जेंडर ने इसको 'पवित्र मित्रमण्डल' (होली एलायन्स) के नाम से पुकारा, और अन्य राज्यों से इसमें सम्मिलित होने की प्रार्थना की। प्रशिया के राजा और आस्ट्रिया के सम्राट् ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, और 'पवित्र मित्रमण्डल' का मसविदा दिसम्बर, १८१५ में प्रकाशित किया गया। इस मसविदे में रूस, प्रशिया और आस्ट्रिया के राजाओं ने यह उद्घोषित किया, कि वे सब आपस में एक दूसरे को भाई-भाई समझेंगे, और एक-की विपत्ति को सब अपनी ही विपत्ति मानेंगे। इस मसविदे के अनुसार सम्पूर्ण ईसाई जगत् का वास्तविक स्वामी परमेश्वर था, जिसने विविध राजाओं को अपनी प्रजा पर शासन करने के लिए नियुक्त किया था। सम्पूर्ण ईसाई जगत् का असली स्वामी ईश्वर ही था, अतः उस द्वारा नियत राजाओं को परस्पर सहयोग के साथ कार्य करना ही चाहिये। अन्य राजाओं को भी इस मित्रमण्डल में सम्मिलित होने के

लिये निमन्त्रित किया गया। बहुत से राज्यों ने निमन्त्रण को स्वीकार भी किया। ब्रिटेन इसमें शामिल नहीं हुआ। टर्की के सुल्तान को निमन्त्रण ही नहीं दिया गया था, और पोप ने इसमें सम्मिलित होने से इन्कार कर दिया था। विचारशील लोग इस मसविदे को दोखेवाजी के सिवा और कुछ नहीं समझते थे। सर्वसाधारण लोगों का खयाल था, कि जनता के अधिकारों को कुचलने के लिये ही यह नया गुट बनाया गया है। निस्सन्देह, इस बात में बहुत कुछ सचाई थी।

**चतुर्मुख मित्रमण्डल**—‘पवित्र मित्रमण्डल’ की यह स्कीम कामयाब नहीं हो सकी। इसके दो महीने बाद ही २० नवम्बर, १८१५ के दिन रूस, प्रशिया, आस्ट्रिया और ग्रेट ब्रिटेन—इन चार राज्यों ने मिलकर एक ‘चतुर्मुख मित्रमण्डल’ का निर्माण किया। यह मित्रमण्डल बहुत देर तक यूरोप के राजनीतिक मामलों का मचालन करता रहा। १८४८ की राज्यक्रान्ति द्वारा इस का अन्त हुआ। चौथाई शताब्दि के लगभग तक यह मण्डल यूरोप का भाग्यविधाता बना रहा। इस मण्डल का निर्माण इस उद्देश्य से हुआ था, कि यूरोप में क्रान्तिकारी विचारों को नष्ट किया जावे, नैपोलियन और उसके परिवार का कोई व्यक्तित्व फ्रांस व यूरोप की किसी राजगद्दी पर न बैठ सके, और राजाओं के अवाधित शासन को सर्वत्र अक्षुण्ण रखा जावे। इस मण्डल की धारणा थी, कि किसी भी राज्य के आन्तरिक मामलों में भी हस्तक्षेप किया जा सकता है। यदि यूरोप के किसी कोने में भी क्रान्ति की भावनाएँ नवीन प्रवृत्तियाँ बलवती होंगी, तो उनसे सभी राज्यों को नुकसान पहुँचेगा। जनता में कहीं किसी भी प्रकार का असन्तोष हो, तो उसको दवाना यह मित्रमण्डल अपना कर्तव्य समझता था। इस मण्डल ने यह भी व्यवस्था की, कि समय-समय पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते रहें, जिनमें कि यूरोप में शान्ति स्थापना के सम्बन्ध में विचार हुआ करे और अशान्ति के तत्वों को नष्ट करने के उपायों का निश्चय किया जाया करे।

**अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन**—यूरोपियन समस्याओं पर विचार करने के लिये पहला सम्मेलन एक्स-ला-शापेल में १८१८ में हुआ। इसमें वोट देने का अधिकार केवल रूस, प्रशिया, आस्ट्रिया और ग्रेट ब्रिटेन—इन चार राज्यों को ही प्राप्त था। पीछे से फ्रांस को भी यह हक दे दिया गया, क्योंकि उसने पेरिस की सन्धि की सम्पूर्ण शर्तों को पूर्णरूप से त्रिया में परिणत कर दिया था। इस प्रकार अब यह मण्डल ‘चतुर्मुख’ के स्थान पर ‘पञ्च-मुख’ हो गया। अन्य राज्यों को इस सम्मेलन में निमन्त्रित तो किया गया था, पर उन्हें वाट का अधिकार नहीं था। वे अपने विचार प्रकट कर सकते थे, उनसे सलाह ली जा सकती थी, पर इसके अतिरिक्त उनका कोई अधिकार नहीं था।

दूसरा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन १८२० में ट्रोप्पा नामक स्थान पर हुआ। १८२० में स्पेन और नेपल्स में क्रान्तियाँ हुई थीं, और उन्हीं पर विचार करने के लिये यह सम्मेलन बुलाया गया था। इसमें रूस, प्रशिया और आस्ट्रिया ने ‘हस्तक्षेप के सिद्धान्त’ का प्रतिपादन किया। इन राज्यों का कहना था, कि यदि क्रान्ति द्वारा सरकारों में परिवर्तन करने का प्रयत्न किया जायगा, तो हमें हस्तक्षेप करने का पूर्ण अधिकार होगा। ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने इसका विरोध किया। उनका कहना था, कि यह मामला

प्रत्येक राज्य का अपना है। दूसरों को उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये।

तीसरा सम्मेलन लैवण मे सन् १८२१ में हुआ। इस समय नेपल्स में पुन विद्रोह हुआ था। इस सम्मेलन ने आस्ट्रिया को यह अधिकार दिया, कि वह नेपल्स के इस आन्तर्गिक मामले में हस्तक्षेप कर विद्रोह को शान्त करे। इस प्रकार हस्तक्षेप के सिद्धान्त को क्रिया में परिणत किया गया, और आस्ट्रिया ने नेपल्स के विद्रोह को शान्त किया। इसी समय ग्रीस में टर्की के शासन के विरुद्ध ग्रीक लोगों ने विद्रोह किया। इसपर रूस ने उद्घोषित किया, कि हम इस प्रकार के विद्रोहों को विष्कुल पसन्द नहीं करते, और क्रान्तिकारियों को सावधान करते हैं कि वे भविष्य में इस प्रकार का कार्य कभी न करें।

१८२३ में वेरोना नामक स्थान पर चतुर्थ अन्तर्गन्तीय सम्मेलन किया गया। इस समय स्पेन तथा उसके अमेरिकन उपनिवेशों में विद्रोह हो रहे थे। इसी प्रकार, पीडमोंट तथा ग्रीस में भी विद्रोह की अग्नि भड़क रही थी। पीडमोंट में हस्तक्षेप करने का अधिकार आस्ट्रिया को दिया गया। स्पेन का मामला फ्रांस के तथा ग्रीस का मामला रूस के सुपुर्द किया गया। 'पचमुख मित्रमण्डल' अमेरिकन उपनिवेशों के मामले में भी हस्तक्षेप करना चाहता था। पर सयुक्त राज्य अमेरिका इस बात को नहीं सह सका। वहाँ की सरकार ने उद्घोषित किया, कि नई दुनिया (अमेरिका) के मामलों में पुरानी दुनिया (यूरोप) हस्तक्षेप न करे। इसी प्रकार अमेरिका भी यूरोपियन झगड़ों से कोई सम्बन्ध न रखे। सयुक्त राज्य अमेरिका के उस समय के राष्ट्रपति मूनरो के नाम से यह सिद्धान्त 'मूनरो सिद्धान्त' के नाम से प्रसिद्ध है। इसी के कारण यूरोपियन राज्य अमेरिकन उपनिवेशों में हस्तक्षेप न कर सके, और वे स्पेन की अधीनता से स्वतन्त्र हो गये।

**मित्रमण्डल का पतन**—निस्सन्देह, यह मित्रमण्डल यूरोप में शान्ति स्थापित रखने के कार्य में बहुत कुछ सफल हुआ। जहाँ तक शान्ति स्थापना का उद्देश्य था, वहाँ तक इसकी उपयोगिता थी, और इसका कार्य वस्तुतः लाभदायक था। पर नई प्रवृत्तियों को कुचलने की कोशिश बहुत ही अनुचित और हानिकारक थी। एकतन्त्र स्वेच्छाचारी शासन से तग आये हुए लोग जब अपने अधिकारों के लिये सघर्ष करने को उतार होते थे, तो यह 'मित्रमण्डल' उन्हें कुचल देने के लिये यूरोप भर की सम्मिलित शक्ति को लेकर आ खड़ा होता था। जनता की नई भावनाओं का यह सबसे बड़ा दुश्मन था। कुछ समय तक इसे निरन्तर सफलता होती रही, पर आखिरकार इसके विरोध में भी शक्तियाँ संगठित होने लगीं। ट्रोंप्पा के सम्मेलन में ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने इसके सिद्धान्तों का घोर विरोध किया था। 'मूनरो सिद्धान्त' स्पष्ट से इसके विरोध में था। १८३० और १८४० की क्रान्तियों से इसे जवर्दस्त धक्के लगे। इन सब कारणों से यह चतुर्मुख या पचमुख मित्रमण्डल आखिर नष्ट हो गया, और नई प्रवृत्तियों को क्रिया में परिणत होने का द्वार खुल गया।

**मित्रमण्डल की उपयोगिता**—१८१५ से १८४८ तक चतुर्मुख व पचमुख मित्रमण्डल यूरोप में कायम रहा। यूरोप के इतिहास में यह शान्ति का काल था। इस बीच में कोई बड़ी लड़ाई यूरोप में नहीं हुई। विविध राज्यों में जनता अपने स्वेच्छाचारी व निरंकुश शासकों के विरुद्ध सघर्ष अवश्य करती रही, कई जगह क्रान्तियाँ व विद्रोह भी हुए। पर



इन क्रान्तियों ने किसी बड़े युद्ध का प्रादुर्भाव नहीं किया। इसका प्रमुख श्रेय इस मित्रमंडल को ही है। इसमें सम्मिलित राज्य व राजा इस बात के लिये प्रयत्नशील थे, कि यूरोप में शान्ति और व्यवस्था कायम रहे, और परस्पर सहयोग द्वारा कार्य करे। बीसवीं सदी में राष्ट्रसंघ (लीग ऑफ नेशन्स) और संयुक्त राज्यसंघ (यूनाइटेड नेशन्स ऑर्गनाइजेशन) के रूप में संसार ने अन्तराष्ट्रीयता की ओर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कदम बढ़ाये। पर इस अन्तराष्ट्रीयता का प्रारम्भ उन्नीसवीं सदी में चतुर्मुख मित्रमंडल के रूप में ही हुआ था। बीसवीं सदी का राष्ट्रसंघ भी संसार में चिरशान्ति स्थापित कराने में असफल रहा। संयुक्त राज्यसंघ भी अपने उद्देश्य में कहा तक सफल होगा, यह बात सदिग्ध है। इसका प्रधान कारण शक्तिशाली राज्यों की साम्राज्यसम्बन्धी प्रवृत्तियाँ और निर्बल राज्यों की उपेक्षा है। इन्हीं कारणों से उन्नीसवीं सदी का मित्रमंडल भी अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सका था। रूस, आस्ट्रिया, प्रशिया और इंग्लैंड जहाँ यूरोप में शान्ति स्थापना के लिये इच्छुक थे, वहाँ साथ ही उनमें साम्राज्यसंबन्धी प्रतिस्पर्धा भी विद्यमान थी। इसके अतिरिक्त, वे जनता के अधिकारों को स्वीकृत करने के लिये तैयार नहीं थे। लोकतन्त्रवाद और राष्ट्रीयता की जिन नई प्रवृत्तियों को फ्रांस की राज्यक्रान्ति ने जन्म दिया था, चतुर्मुख मित्रमण्डल उनके विरोध में कार्य कर रहा था। इसी कारण, वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सका। पर साथ ही, हमें यह स्वीकार करना होगा, कि इस मित्रमण्डल का निर्माण अन्तराष्ट्रीयता के मार्ग पर महत्त्वपूर्ण कदम था, और इसने यूरोप में शान्ति स्थापित रखने में अच्छी सफलता प्राप्त की थी।

## २ फ्रांस में प्रतिक्रिया का युग

**अठारहवें लुई का शासन**—नैपोलियन के पतन के बाद सोलहवें लुई के भाई को अठारहवें लुई के नाम से फ्रांस की गद्दी पर बिठाया गया। क्रान्ति के प्रारम्भ होने पर जब अनेक कुलीन तथा राज-परिवार के व्यक्ति फ्रांस से भाग गये थे, तब वह भी उनके साथ चला गया था, और अन्य राजाओं के साथ मिलकर निरन्तर क्रान्ति के विनाश के लिये प्रयत्न कर रहा था। सोलहवें लुई को प्राणदंड मिलने के पश्चात् वह अपने को फ्रांस की राजगद्दी का वास्तविक उत्तराधिकारी समझता था। बीस वर्ष तक वह निरन्तर राजगद्दी के लिये कोशिश करता रहा। क्रान्ति का अन्त करने और नैपोलियन के पतन के लिये उसने भरपूर कोशिश की, और आखिर वह अपने प्रयत्न में सफल हुआ। जब वह राजगद्दी पर बैठा, तो उसका कोई खास विरोध नहीं हुआ। फ्रांस की जनता वर्षों राजवंश के शानन के अधीन रहने के लिये अभ्यस्त थी। क्रान्ति उन्हें नई तथा अद्भुत सी चीज मालूम होती थी। उन जमाने में सर्वमाधारण जनता राजनीतिक मामला में बहुत अधिक दिग्भ्रमि नहीं होती थी। क्रान्ति तथा उससे उत्पन्न रिपब्लिक प्रधानतया जैकोबिन दल की कृति थी। जनता का अधिकांश भाग इस बात से बेपरवाह था, कि कौन राजगद्दी पर बैठा है, और पेरिस में किसका प्रभुत्व स्थापित होता है। जब रिपब्लिक का टाका नायम करने हुए नैपोलियन ने सम्पूर्ण शासन-सूत्र को अपने हाथ में ले लिया, तो फ्रांस की सर्व-माधारण जनता को विशेष आश्चर्य नहीं हुआ। जब नैपोलियन सचमुच सम्राट बन गया

तब भी जनता को विशेष चिन्ता नहीं हुई, और जब वूर्वो राजवंश का ६० वर्ष का बूढ़ा लुई फिर उनके भाग्य का विधाता बन गया—तब भी उन्होंने इसे एक सामान्य सी बात ही समझा। वास्तविक बात यह है, कि फ्रांस की जविकाश जनता अब तक भी हृदय ने राजसत्ता की ही पक्षपाती थी। जनता के विचारों में पग्विर्तन बहुत धीरे-धीरे होता है। वह नये विचारों को एकदम ग्रहण नहीं कर सकती। मँकडों बगो में फ्रांस में राजा का शासन चला आ रहा था, जनता को राजाओं के शासन में रहने का अभ्यास था, राजसत्ता को मानने के स्कार उसमें बहुत गहरे थे। वे आमानी में नहीं बदल सकते थे।

परन्तु राज्यक्रान्तिने पच्चीस वर्ष तक जो काय किया था, उसे भी नष्ट नहीं किया जा सकता था। आखिर, क्रान्ति भी एक ध्रुव सन्य घटना थी। लोगों आदमियों का नून व्यर्थ में ही नहीं बहा था। वूर्वो वंश फिर फ्रांस की राजगद्दी पर आ गया, पर अब जमाना बहुत बदल चुका था। वूर्वो वंश के साथ पुगना जमाना वापस नहीं आया। मामल-पद्धति अब भूतकाल की चीज हो चुकी थी। चर्च अब राज्य का मुकाबला नहीं कर सकता था। कुलीन और पुरोहित श्रेणियों के विशेषाधिकारों को अब स्वीकृत नहीं किया जा सकता था। कानून की दृष्टि में सब लोग बराबर हो चुके थे। 'मद्रित पत्रों' में अब निमी को कैद नहीं किया जा सकता था। स्वतन्त्र भाषण, स्वतन्त्र लेखन और अपने विश्वासों व अन्तरात्मा के अनुसार धार्मिक विविधधानों का अनुसरण—ये ऐसी बातें थी, जिन्हें अब वूर्वो राजवंश भी नष्ट नहीं कर सकता था। इसीलिये अठारहवें लुई ने राजगद्दी पर बैठकर भी क्रान्ति के सिद्धान्तों को कायम रखा। उसने क्रान्ति के कार्य पर पानी फेरने का प्रयत्न नहीं किया। यदि वह चाहता, तो भी यह उसके वंश के बाहर की बात थी। क्रान्ति को सर्वथा मिटा सकना उसके लिये असम्भव था।

जून, १८१४ की घोषणा—बंध राजसत्ता की स्थापना—जून १८१४ में अठारहवें लुई ने एक उद्घोषणा प्रकाशित की। इसके अनुसार फ्रांस में बंध राजसत्ता को स्थापित करने की घोषणा की गई। फ्रांस का शासन करने के लिये एक पार्लियामेंट बनाई गई, जिसमें दो सभाएँ थी। एक सरदारों की सभा और दूसरी राष्ट्र प्रतिनिधि सभा। सरदारों की सभा के सदस्य राजा द्वारा मनोनीत किये जाते थे, और राष्ट्र प्रतिनिधि सभा के सदस्यों को जनता चुनती थी। निर्वाचन का अधिकार सब नागरिकों को नहीं दिया गया। जिनकी आयु ३० वर्ष से कम न हो, और जो कम से कम १८० रु० वार्षिक टैक्स देते हों, उन्हें ही वोट का अधिकार दिया गया। इस प्रकार अमीर लोग ही निर्वाचन में हिस्सा लेते थे। राष्ट्र प्रतिनिधि सभा सर्वसाधारण जनता की प्रतिनिधि नहीं थी, वह केवल अमीर व मध्यश्रेणी के लोगों की ही सम्मति को प्रगट कर सकती थी। परन्तु यदि इङ्ग्लैंड के उस समय के शासन-विधान से तुलना की जाय, तो फ्रांस का यह शासन-विधान निस्सन्देह अधिक लोकसत्तात्मक था। प्रतिक्रिया के काल में भी फ्रांस का यह शासन-विधान यूरोप के अन्य सब देशों की अपेक्षा अधिक उन्नत था। यह राज्यक्रान्ति का ही प्रभाव था, जिसे प्रतिक्रिया का काल भी नहीं मिटा सका था। अठारहवें लुई ने अपनी उद्घोषणा में जनसाधारण के आधारभूत अधिकारों को भी घोषित किया। अधिकारों की इस घोषणा में क्रान्ति के प्राय सभी सिद्धान्तों को स्वीकृत किया गया था। कानून के सम्मुख सब मनुष्य बराबर हैं, राजकीय

पदों पर नियुक्त होने के लिये सब मनुष्य एक समान रूप से अधिकारी हैं, टैक्स का निर्णय नागरिकों की सम्मति के अनुसार किया जायगा, प्रत्येक मनुष्य को वार्षिक तथा वार्षिक स्वतन्त्रता प्राप्त रहेगी, भाषण, लेखन तथा मुद्रण की सबको स्वतन्त्रता है—ये सब बातें उस अठारहवें लुई ने उद्घोषित की, जो कि सोलहवें लुई का भाई था, वूवों राजवंश का था, जिन्दगी भर क्रांति को कुचलने की कोशिश करता रहा था, और जिसे मेटर्निख तथा क्रान्ति के दुश्मनों ने राजगद्दी पर बिठाया था।

फ्रांस के विविध दल—(१) कट्टर राजसत्तावादी—अठारहवें लुई के साथ बहुत से कुलीन तथा उच्च पुरोहित श्रेणियों के लोग भी फ्रांस वापस लौट आये थे। ये क्रान्ति के कट्टर दुश्मन थे। क्रान्ति ने इन्हें तबाह कर दिया था। इनके हृदय में बदला लेने की आग धधक रही थी। ये फिर से पुराने जमाने को वापस ले आने के लिए तुले हुए थे। इन्होंने एक पृथक् दल संगठित किया, जो कि कट्टर राजसत्तावादी दल के नाम से प्रसिद्ध है। इस दल का नेता राजा का भाई 'आर्तोआ का काउण्ट' था। इसका कहना था, कि प्रेस को स्वतन्त्रता नहीं मिलनी चाहिये, कुलीनों की छिनी हुई सम्पत्ति उन्हें फिर वापस मिलनी चाहिये राजा का शासन एकतन्त्र तथा स्वेच्छाचारी होना चाहिये, और जनता का शासन में कोई अधिकार नहीं होना चाहिये। इस दल के लोग सख्या में बहुत अधिक नहीं थे, पर इनका प्रभाव तथा बल बहुत अधिक था।

(२) उदार राजसत्तावादी—राजसत्ता के पक्षपाती दल के सभी लोग इतने कट्टर तथा क्रान्ति के दुश्मन नहीं थे। 'आर्तोआ के काउण्ट' के दल के अतिरिक्त राजसत्तावादियों का एक और भी दल था, जो समय की गति को समझता था। ये लोग भली भाँति समझते थे, कि क्रान्ति के सम्पूर्ण कार्य को बात की बात में नष्ट नहीं किया जा सकता। इन्हीं के प्रभाव से राजा ने वह उद्घोषणा प्रकाशित की थी, जिनमें जनता के अधिकारों की रक्षा की गई थी, और नवीन शासन-विधान का निर्माण किया गया था। अधिकांश लोग इसी दल से सहानुभूति रखते थे। यह दल फ्रांस में इंग्लैंड के ढंग पर वैध राजसत्ता को स्थापित करना चाहता था।

(३) लिबरल—तीसरा दल लिबरल या उदार दल कहा जाता था। ये लोग राजा के विरोधी नहीं थे। राजा की सत्ता को वे शासन की स्थिरता के लिये आवश्यक समझते थे। पर इनका खयाल था, कि १८१४ की उद्घोषणा में जनता को पर्याप्त अधिकार नहीं मिले हैं। वोट देने के लिये १८० रु० वार्षिक टैक्स देने की शर्त बहुत अधिक है। इसमें बहुत कम लोगों को वोट का अधिकार प्राप्त होता है। वोट का अधिकार विस्तृत किया जाना चाहिये, और राजा को पूर्णतया मन्त्रियों के अधीन रहना चाहिये। मन्त्रियों का पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी होना भी आवश्यक है।

इन तीन दलों के अनिर्दिष्ट कुछ लोग वूवों वंश के शासन के पूर्णतया विरोधी थे। वे किसी भी प्रकार १८वें लुई के शासन से समझौता करने को उद्यत नहीं हो सकते थे। इन लोगों को निम्नलिखित दलों में विभक्त किया जा सकता है—

(१) बोनापार्टिस्ट दल—यह दल नैपोलियन बोनापार्ट को राजगद्दी पर बैठाने का पक्षपाती था। नैपोलियन के गौरवमय कृत्य इनकी आँखों के सामने मौजूद थे। ये प्रायः

नैपोलियन की सेनाओं के मिताही थे, जो अपने विश्वविजयी मेनापति की गौरव गाथाओं को किसी भी दशा में भूल नहीं सकते थे। जब तक नैपोलियन जीवित रहा, ये उसे राजगद्दी पर बिठाने का प्रयत्न करते रहे। जब वह मर गया, तो ये उसके लड़के 'रोम के बादशाह' को नैपोलियन द्वितीय के नाम में सम्राट बनाने के लिये प्रयत्नशील रहे।

(२) रिपब्लिकन दल—इस दल के लोग वृत्तार्थ राजवश और नैपोलियन, दोनों के विरोधी थे। ये फिर से फ्रांस में गिराविल की स्थापना करना चाहते थे।

१८वें लुई के शासन में उदार राजसत्तावादियों की शक्ति अधिक प्रबल थी। कट्टर राजसत्तावादियों ने पुराने जमाने को स्थापित करने के लिये बहुत कोशिश की। उन्होंने विद्रोह किये, मारकाट की, खून बहाया, पर उनका उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ। वे केवल इतना ही कर सकते, कि नैपोलियन के कुछ प्रमुख पक्षपातियों को फ्रांस में बहिष्कृत कर दिया गया। क्रान्ति को मिटा सकना उनकी शक्ति के बाहर था। परन्तु इसमें मन्देह नहीं, कि राजदरबार की बाहरी शान-शीकत और रोवको फिर से स्थापित करने में उन्हें पर्याप्त सफलता मिली। दरबार की पुरानी पोशाकें, शिष्टाचार तथा तोरतरीके बहुत हद तक फिर वापस आ गये। क्रान्ति के तिरगे झंडे की जगह बर्बो वश का सफेद झंडा फ्रांस के राजप्रमाद पर फिर फहराने लगा। कट्टर राजसत्तावादी बाहरी तरीकों को तो वापस ले आये, पर वास्तविक पुराने जमाने को पुनः स्थापित कर सकना उनके लिये सर्वथा असम्भव था।

दलों का संघर्ष—अठारहवें लुई के शासन में जब पहले पृथक् राष्ट्र प्रतिनिधि सभा का निर्वाचन हुआ, तो कट्टर राजसत्तावादी दल सबसे प्रबल रहा। वोट देने का अधिकार बहुत कम लोगों को था, अतः इस दल की विजय अस्वाभाविक नहीं थी। इन्होंने कोशिश की, कि १८८४ की उद्घोषणा में प्रतिपादित जनसाधारण के अधिकारों को वापस ले लिया जाय। इसके लिये निरन्तर ऐसे कानून पास किये जाने लगे, जिनमें कि राजा भी घबरा गया। उसे डर था, कि कहीं फिर क्रान्ति न हो जाय। उसने राष्ट्र प्रतिनिधि सभा को बर्खास्त कर दिया, और नये निर्वाचन की आज्ञा दी। नये निर्वाचन में वंश राजसत्तावादी तथा लिवरल दल को बहुमत प्राप्त हुआ। इन दलों के शासन में फ्रांस ने बहुत उन्नति की। सेना का पुनः संगठन किया गया। वोट देने का अधिकार अधिक विस्तृत किया गया, और इसी प्रकार के अन्य भी अनेक महत्वपूर्ण सुधार किये गये। १८२० में कट्टर राजसत्तावादी दल फिर प्रबल हो गया। इसी कारण इस काल में फ्रांस ने मेटर्निख की भावनाओं का पूरा साथ दिया। स्पेन की जनता के विद्रोह को शान्त करने के लिये फ्रेंच सेना भेजी गई, और वोट देने का अधिकार को फिर से सकुचित कर दिया गया।

दसवें चार्ल्स का शासन—१८२४ में १८वें लुई की मृत्यु हुई। उसके बाद उसका भाई 'अर्तोआ का काउण्ट' दसवें चार्ल्स के नाम से फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा। वह कट्टर राजसत्तावादी दल का प्रधान नेता था, और क्रान्ति व नैपोलियन का घोर शत्रु था। उसकी आयु का बड़ा भाग क्रान्ति के साथ युद्ध करने में ही व्यतीत हुआ था। वस्तुतः, वह उन्नीसवीं सदी का व्यक्ति नहीं था, उसे सतरहवीं सदी में उत्पन्न होना चाहिये था। राजा का दैवी अधिकार, असहिष्णु चर्च और कुलीन लोगों की स्वेच्छाचारिता ही उसकी दृष्टि में

सभ्यता के चिन्ह थे। उसकी उमर ६७ वर्ष की हो चुकी थी। इस बड़ी उमर में उससे यह आशा करना, कि वह अपने जन्म भर के सिद्धान्तों और मन्तव्यों का परित्याग कर देगा, उसके साथ अन्याय करना था। नई प्रवृत्तियों को कुचलने में उसने मैटरनिख को भी मात कर दिया। उसके स्वेच्छाचारी शासन से फ्रेंच जनता घबरा गई। यदि दसवाँ चार्ल्स भी अपने भाई की तरह समझदार और ससय की गति को पहचाने वाला होता, तो शायद बूवों वंश का शासन फ्रांस में स्थिर हो जाता। पर वैध राजसत्ता उसकी दृष्टि में कोई अर्थ ही नहीं रखती थी। वह राजा के दैवी अधिकार के सिद्धान्त को क्रिया में परिणत करने के लिये तुला हुआ था। इसलिये उसने बहुत से ऐसे कानून अपने विशेष अधिकार से जारी किये, जिनमें जनता के सम्पूर्ण अधिकारों को छीनने का प्रयत्न किया गया था। वह दृढ़ राजसत्तावादी दल का नेता रह चुका था। अब उसे अवसर मिला था, कि अपने सिद्धान्तों को क्रिया में परिणत करे। उसकी नीति का परिणाम यह हुआ कि १८३० में फ्रांस में फिर क्रान्ति हो गई। दसवें चार्ल्स को फ्रांस छोड़कर भागना पड़ा। १८३६ में आस्ट्रिया में उसकी मृत्यु हुई। वह अपने को शहीद समझता था। उसका क्याल था, कि जो कुछ उसने किया है, ठीक किया है। परलोक में उसे इसका फल मिलेगा।

दसवें चार्ल्स के राज्यच्युत होने के साथ फ्रांस में फिर क्रान्ति का काल प्रारम्भ हो गया। फ्रांस में नई और पुरानी प्रवृत्तियों में परस्पर संघर्ष चल रहा था। पुरानी प्रवृत्तियों के अभेद्य दुर्ग को नष्ट किये बिना नई प्रवृत्तियाँ कार्य में परिणत नहीं हो सकती थीं। मनुष्य मशीन नहीं है, वह एक जीवित जागृत व चेतन सत्ता है। इसी प्रकार मानव समाज और राष्ट्र भी मशीन नहीं है, वे भी जीवित जागृत और चेतन सत्ताएँ हैं। उनमें परिवर्तन आते हैं, परन्तु धीरे-धीरे। उनमें विकास होता है। जो फ्रेंच जनता सैकड़ों वर्षों से एक स्वामि का जीवन बिताती चली आ रही थी, उसे राज्यक्रान्ति एकदम कैसे बदल सकती थी? निम्सन्देह, क्रान्ति ने उसे बदला—बहुत बदला। पर उसकी पूर्ण सफलता के लिये अभी समय की आवश्यकता थी। यही कारण है, कि क्रान्ति के बाद प्रतिक्रिया का काल आया पर यह काल भी देर तक नहीं रह सका। कुल १६ वर्ष बाद ही फिर क्रान्ति का युग प्रारम्भ हो गया। १८३० की क्रान्ति पर हम अगले एक अध्याय में प्रकाश डालेंगे।

### ३. अन्य यूरोपियन देशों में प्रतिक्रिया का काल

फ्रांस की राज्यक्रान्ति ने जिन नई प्रवृत्तियों को जन्म दिया था, वे केवल फ्रांस तक ही सीमित नहीं रही थी। वे यूरोप के बड़े भाग में व्याप्त हो गई थीं। विशेषतया, फ्रांस के निवृत्त प्रदेशों को तो उन्होंने सर्वथा परिवर्तित कर दिया था। इटली, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड आदि देशों में तो पुराने एकतन्त्र शासनो का अन्त होकर रिपब्लिकों की स्थापना हो गई थी। नैपोलियन की विजयों ने क्रान्ति की लहरों को स्पेन, पोर्तुगाल, जर्मनी आदि देशों तक पहुँचा दिया था। अब नैपोलियन के पतन के बाद इन सब देशों में प्रतिक्रिया के काल का प्रारम्भ हुआ। पुराने राजा राजमिहासनों पर बिठाये गये और उनके साथ ही पुरानी समस्याएँ, रीतिरिवाजों और विचारों के भी पुनरुद्धार का प्रयत्न किया गया।

स्पेन में प्रतिक्रिया—नैपोलियन के पतन के बाद स्पेन का शासन फर्डिनेण्ड सप्तम के सुपुर्द किया गया। नैपोलियन ने स्पेन को अपने अधीन कर वहा की राजगद्दी पर अपने भाई जोसफ बोनापार्ट को नियत किया था। परन्तु राष्ट्रीयता की भावना के कारण जनता उसके शासन को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हुई। उसने विद्रोह कर दिया। वेलिंगटन का द्यूक अपनी इंगलिश सेनाओं के साथ जनता की सहायता करने के लिये कटिबद्ध था। परिणाम यह हुआ, कि नैपोलियन को अपने तीन भाग के लगभग मैनिंक स्पेन में सन्तुष्ट रखने पड़े। आगिर, फ्रेंच सेना की पराजय हुई, और स्पेन स्वतन्त्र हो गया। यह घटना १८१२ में हुई थी। स्पेन का राजकुमार फर्डिनेण्ड नैपोलियन की सन्ध्या में फ्रांस में नजरबन्द था, अब वह अपने देश को वापस नहीं आ सका। इस स्थिति में लाम उठाकर स्पेनिश जनता ने लोकमतात्मक शासन का संगठन किया। पार्लियामेण्ट की स्थापना की गई, और क्रान्ति द्वारा प्रादुर्भूत नये विचारों के अनुसार स्पेन का शासनविधान तैयार किया गया।

स्वतन्त्रता का अपहरण—१८१४ में नैपोलियन की पराजय के बाद फर्डिनेण्ड अपने देश में वापस आया। क्रान्ति की विरोधी प्रवृत्तियाँ पूर्णतया उसकी सहायता के लिये उद्यत थी। उसने राजगद्दी पर बैठते ही शासन-विधान को नष्ट कर दिया। पार्लियामेण्ट बर्खास्त कर दी गई। वैयक्तिक स्वतन्त्रता छीन ली गई, कुलीन और पुरोहित श्रेणियों के विशेषाधिकार स्वीकृत किये गये। १८१० के शासन-विधान में जिन उदार सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया था, उन्हें फ्रेंच राज्यक्रान्ति—जिसे बदनाम करना उन समय के राजनीतिक वातावरण में फैशन सा बन गया था—का प्रभाव बनाकर नष्ट कर दिया गया। उदार विचारों के लोगों को देश से बहिष्कृत किया गया, या जेल में डूब दिया गया। फिर पुराने ढंग की एकतन्त्र स्वेच्छाचारी राजसत्ता स्थापित की गई। विधियों को जीते जी आग में जला देने या अन्य वीभत्स दंड देने के लिये धार्मिक न्यायालय (इन्क्वीजिशन कोर्ट) कायम किये गये। जेसुइट सम्प्रदाय का फिर जोर हो गया। पुनर्त, अखवार आदि पर कड़ा निरीक्षण जारी किया गया। भाषण और लेख की स्वतन्त्रता छीन ली गई। चर्च की सम्पत्ति यथापूर्व चर्च को दे दी गई। फर्डिनेण्ड सप्तम ने जनता के अधिकारों की रत्ती भर भी परवाह नहीं की। 'जनता के अधिकार' उसकी सम्मति में कोई अर्थ ही नहीं रखते थे। देश की सम्पत्ति को दरबारियों के सुखोपभोग, आमोद-प्रमोद और भोग-विलास के लिये स्वाहा किया जाने लगा। फर्डिनेण्ड की नीति इतनी मूर्खतापूर्ण थी, कि मेटर्निख तक ने उसे उदार नीति आ अनुसरण करने का परामर्श दिया था।

जनता का विद्रोह—फर्डिनेण्ड के शासन का वही परिणाम हुआ, जो ऐसे शासनों का हुआ करता है। उपनिवेशों में विद्रोह शुरू हो गया। स्पेन में भी कुशासन के दोष प्रगट होने लगे। खर्च बहुत बढ़ गया, आमदनी रही नहीं। स्पेन दिवालिया हो गया। आखिर, १८२० में स्पेन में भी विद्रोह की अग्नि भड़क उठी। फर्डिनेण्ड इसे शान्त करने में असमर्थ था। पर यूरोपीय राजाओं का मित्रमण्डल उसकी सहायता करने को उद्यत था। १८२२ के अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में—जो कि वेरोना नामक नगर में हुआ था, स्पेनिश

विद्रोह को शान्त करने का कार्य फ्रांस के सुपुर्द किया गया। १५००० सैनिकों की एक सेना स्पेन गई और विद्रोह को शान्त करने में सफल हुई। विदेशी सहायता से फर्डिनेन्ड सप्तम अपनी राजगद्दी को कायम रखने में समर्थ हुआ। इसके बाद यह अत्याचारी एकतन्त्र राजा १८३८ तक स्पेन का शासन करता रहा। १८३८ में इसकी मृत्यु हुई। उस समय तक स्पेन पूर्णतया दिवालिया हो चुका था। जो स्पेन किसी समय यूरोपियन राज्यों में सबसे अधिक उन्नत और प्रगतिशील था, वह अब बिल्कुल क्षीण तथा अशक्त हो गया था।

फर्डिनेन्ड सप्तम के निर्बल परन्तु अत्याचारपूर्ण शासन में क्रान्ति की प्रवृत्तियाँ सर्वथा दबी हुई नहीं रही। १८३० में जब क्रान्ति की लहर ने एक बार फिर सम्पूर्ण यूरोप को व्याप्त कर लिया, उस समय स्पेन भी उसके प्रभाव से अछूता नहीं बचा। १८३४ में स्पेन में उदार विचारों की फिर प्रधानता हो गई और १८३७ में फर्डिनेन्ड को पार्लियामेन्ट तथा नवीन शासन-विधान को स्वीकृत करने के लिये बाधित होना पड़ा। उसकी मृत्यु से पूर्व ही स्पेन में वैध राजसत्ता की स्थापना हो गई थी। वह अपनी शक्ति को किसी भी ढंग से मर्यादित कराने के लिये उद्यत नहीं था। परन्तु नई प्रवृत्तियों को दबाकर रख सकना उसकी शक्ति से बाहर था। इसलिये यद्यपि उसके जीते जी ही स्पेन में क्रान्ति की भावनाएँ सफल हो गई, पर इसमें सन्देह नहीं, कि १८१४ के बाद यूरोप में जब क्रान्ति के विरुद्ध प्रतिक्रिया का युग आया, तो फर्डिनेन्ड ने एक बार फिर सतरहवीं सदी के 'स्वर्गीय दिवसों' की झलक कुछ समय के लिये यूरोप को दिखा दी।

**इटली में प्रतिक्रिया का काल**—वीएना की कांग्रेस ने इटली में फिर से पुराने विविध राज्यों का पुनरुद्धार कर दिया था। नैपोलियन के आक्रमणों और विजयों का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण लाभ इटली के लिये यह हुआ था, कि वहाँ के लोगों में एकानुभूति उत्पन्न हो गई थी, और इटालियन लोग अपने देश को एक राष्ट्र समझने लगे थे। युद्धों और विदेशी आक्रमणों से भी अनेक बार लाभ हो जाते हैं, और निस्सन्देह इटली के लिये नैपोलियन के आक्रमण इस दृष्टि से बहुत लाभदायक सिद्ध हुए थे। परन्तु वीएना में एकत्रित राजनीतिज्ञों के लिये इस नई प्रवृत्ति का कोई महत्व न था। वे जनता की इच्छा की अपेक्षा राजाओं के अधिकारों को अधिक महत्व देते थे। यही कारण है कि १८१४ के बाद मेटर्निख के शब्दों में इटली केवल एक 'भौगोलिक सजा' मात्र रह गया था। 'इटली' इस शब्द से किसी एक राज्य का ग्रहण नहीं होता था। यह तो केवल एक भौगोलिक देश का ही बोध कराता था। लोम्बार्डी (मिलान) और वेनिस् के प्रदेश आस्ट्रिया के कब्जे में थे। परमा, मोडेना और टस्कनी में विविध राजवंशों का शासन था, जो प्रायः आस्ट्रियन राजवंश की शाखाएँ मात्र थे। दक्षिणी इटली में नेपल्स का प्रसिद्ध और पुराना राज्य था, जो वर्वी राजवंश की एक शाखा के अधीन था। मध्य में पोप का राज्य था। पीडमोंट और सार्डिनिया पर राजा विक्टर एमैन्युजल का शासन था। इन विविध राज्यों के रहते हुए इटली की राजनीतिक एकता की आशा दुराशा मात्र ही थी।

**पीडमोंट में सुधारों का नाश**—नैपोलियन के काल में इटली के शासन में अनेक सुधार किये गये थे। सामन्त पद्धति का नाश कर कुलीन और पुरोहित श्रेणियों के विशेषाधिकारों का अन्त कर दिया गया था। क्रान्ति के सिद्धान्तों और नई प्रवृत्तियों को

उस समय पर्याप्त स्थान प्राप्त हो गया था। परन्तु अब प्रतिक्रिया के काल में इटली के विविध राज्यों में भी पूर्णतया पुराने जमाने को कायम करने का प्रयत्न किया गया। २० मई, १८१४ को सार्डिनिया और पीडमोंट के राजा विक्टर एमैन्युअल प्रथम ने अपनी राजधानी टूरिन में प्रवेश किया। राजगद्दी पर बैठने ही उसने सुधारों को नष्ट कर दिया। क्रान्ति के जमाने में उसके राज्य में जो भी महत्वपूर्ण कार्य हुए थे, उन सबको कलम की नोक से दूर हटा दिया गया। कुलीन श्रेणी को अपने विशेषाधिकार फिर प्राप्त हुए, पादरियों को चर्च की सम्पत्ति फिर वापस मिल गई। चर्च के न्यायालय फिर कायम कर दिये गये। प्रेस पर कड़ी निगाह रखी जाने लगी। धार्मिक स्वतन्त्रता छीन ली गई। फ्रांस के प्रति इतनी अधिक घृणा प्रगट की गई, कि राजप्रसाद के फ्रेंच राज-समान तक को नष्ट कर दिया गया। और तो और रहा, टूरिन के बाग में बहुत से पीढ़ों और वृक्षों को केवल इसलिये उखाड़ दिया गया, क्योंकि वे फ्रेंच लोगों द्वारा आरोपित किये गये थे। शिक्षा का कार्य फिर से चर्च के सुपुर्द कर दिया गया। उदार विचार के लोगों को राज्य के लिये अत्यन्त भयकर समझा जाने लगा। जरा सा मन्देह होने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था, और भारी दण्ड दिये जाते थे।

**पोप का राज्य**—केवल पीडमोंट में ही नहीं, इटली के अन्य राज्यों में भी यही अवस्था थी। पोप के राज्य में १८१४ में एक उद्घोषणा प्रकाशित की गई, जिसमें कि फ्रेंच क्रान्तिकारियों के सम्पूर्ण कार्यों पर पानी फेर दिया गया। फ्रेंच लोगों के नामोनिशान तक को मिटा देने की पोप को इतनी उत्सुकता थी, कि राम की गलियों में गैस के प्रकाश को इस लिए हटा दिया गया, क्योंकि वह फ्रेंच क्रान्तिकारियों द्वारा प्ररम्भ किया गया था। अधिक क्या, टीका लगाने की वैज्ञानिक प्रथा केवल इसलिये हटा दी गई, क्योंकि इसका आविष्कार फ्रान्स में हुआ था।

**उत्तरी इटली के विविध राज्य**—लोम्बार्डी और वेनिस सीधे आस्ट्रिया के अधीन थे। वहाँ पर मैटरनिख का शासन स्थापित था। उसके समान नई भावनाओं का दुश्मन यूरोप भर में अन्य कोई नहीं था, फिर यह आशा कैसे की जा सकती थी, कि इन प्रदेशों में नवीन युग का कोई भी चिह्न अवशिष्ट रह सकेगा? परमा, मोडेना और टस्कनी आस्ट्रियन राजवंश के विविध व्यक्तियों के अधीन थे। इन पर आस्ट्रिया का पूरा प्रभाव विद्यमान था। ये सब मैटरनिख के सिद्धान्तों का आखिरी मोचकर अनुसरण कर रहे थे।

नेपल्स की अवस्था भी अच्छी नहीं थी। वहाँ के वृद्धों शासक फिर से पुराने स्वर्गीय दिनों की स्थापना के लिये उत्सुक थे। सम्पूर्ण इटली में नई प्रवृत्तियों के विरुद्ध भयंकर प्रतिक्रिया चल रही थी। पर इटली में क्रान्ति के दिनों में जो भारी परिवर्तन आया था, उसे राजाओं और कुलीन श्रेणियों के ये सब प्रयत्न भी सुगमता से दूर नहीं कर सकते थे। लोगों के दिमाग बदल चुके थे, वे एक नये ढंग से सोचने लग गये थे। राष्ट्रियता की भावना इटालियन नवयुवकों के हृदयों में नवीन आशा का संचार कर रही थी। वे सगठित और स्वतन्त्र इटली का स्वप्न देख रहे थे।



ग्यारहवा अध्याय

## राजनीतिक क्रान्तियों का फिर से प्रारम्भ

### १ प्रतिक्रिया के काल अन्त

नैपोलियन के पतन के बाद जब क्रान्ति के विरुद्ध प्रतिक्रिया के काल का प्रारम्भ हुआ, तो लोगो ने समझा, अब क्रान्ति का युग हमेशा के लिये समाप्त हो गया है। क्रान्ति के विरोधी खुशिया मनाने लगे। विचारको ने समझा, क्रान्ति कितनी अस्वाभाविक चीज थी। क्या कभी ससार में सब लोग बराबर हो सकते हैं? सब लोगो का शासन—कितनी असम्भव, कितनी फिजूल बात है। सब लोगो की बुद्धि एक समान नहीं होती। सब की शक्ति भी बराबर नहीं होती। फिर सब लोगो के अधिकार कैसे बराबर हो सकते हैं। ऊँच नीच के विचार, राजा के दैवी अधिकार का सिद्धान्त, पुरोहितो की उत्कृष्टता का भाव और कुलीनो की श्रेष्ठता के विश्वास लोगो में बहुत गहरे थे। पुराने जमाने में अरिस्टोटल जैसे दार्शनिक ने लिखा था, कुछ लोग शासन करने के लिये ही उत्पन्न हुए हैं, और अन्य लोग शासित होने के लिये। अरिस्टोटल जैसे तत्त्ववेत्ता भी अपने समय से परे नहीं देख सके थे। उन्हें कुछ का मालिक और कुछ का गुलाम होना सर्वथा स्वाभाविक प्रतीत होता था। लूथर इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता था, कि किसानो को भूमिपतियो के विरुद्ध विद्रोह करने का हक है। उसके सुधारो के सम्पूर्ण उपदेश कुलीन लोगो के लिये ही थे, और उसकी दृष्टि में यह उन्ही का कार्य था, कि वे अपनी जागीरो में धार्मिक सुधार करे। लूथर ने किसानो पर भयकर से भयकर अत्याचार करने के लिये जर्मनी के जमींदारो को अपनी सहमति दी थी। वह भी अपने समय से परे नहीं देख सका था। फ्रांस की राज्यक्रान्ति के असफल होने के अनन्तर यदि यूरोपियन जनता अपने युग में परे न देख सकी हो, तो इसमें आश्चर्य ही क्या है? लोगो ने समझा, एक भयकर तूफान जाया था, जो अब वीत गया है। दुनिया में तो राजाओ का एकतन्त्र स्वेच्छाचारी शासन ही हमेशा के लिये कायम रहना है, यही ईश्वरीय विधान है, यही सदा से चला आ रहा है, और यही सदा रहेगा। कुछ समय तक मेटर्निक का प्रभाव निरपवाद रूप से सर्वत्र पायम रहा। क्रान्ति की भावनाओ को सब देशो में कुचला गया। 'स्वाधीनता, समानता और प्रातृभाव' ये मिद्धान्त जत्यन्त भयकर समझे जाने लगे। 'जनता के अधिकारो' में विश्वास करनेवाले लोग समाज और व्यवस्था के दुश्मन कहे जाने लगे। लोकतन्त्र शासन के पक्ष-पातियो का एक ही स्थान था, और वह था जेल। जो लोग कहते थे, जनता का शासन होना चाहिये, उन्हें सभ्यता के शत्रु समझा जाता था। नये विचारो का पहले पहल इसी प्रकार स्वागत होता है। आज ससार में जो मिद्धान्त सर्वसम्मत और निरपवादरूप से स्वीकृत

कर लिये गये हैं, वे कभी भयकर क्रान्तिकारी विचार माने जाते थे। जिन्हें आज क्रान्तिकारी और भयकर समझा जाता है, सम्भवतः, मध्य समार काल उन्हें सर्वसम्मत रूप से तथ्य मानने लगेगा। इतिहास में हमें यही कम दृष्टिगोचर होता है।

ससार में सबसे प्रबल शक्ति विचारों की है। तलवार और बन्दूक में इसका महार नहीं किया जा सकता। इसे जितना ही कुचलने का प्रयत्न किया जाता है, यह उतनी ही अधिक प्रबल होती जाती है। फ्रांस में जिन नवीन विचारों का प्रादुर्भाव हुआ था, उन्हें भी कुचल सकता असम्भव था। वे लोगों के दिमागों में घर कर रहे थे। क्रान्ति की चौथाई मदी ने मनुष्य जाति के सम्मुख अनेक नवीन रूपनाएँ उपस्थित की थी—एक नवीन दुनिया की सम्भावना प्रदर्शित की थी। प्रतिव्रिया के युग में यह नया चित्र लोगों की आँखों में ओझल नहीं हो गया था। एकतन्त्र राजाओं के अत्याचारों में तंग आये हुए लोगों के सम्मुख एक निश्चित और स्पष्ट मार्ग था, और उस मार्ग की स्मृति उनमें अभी विद्रुल ताजी थी। फ्रेंच राज्यक्रान्ति ने जिन नई प्रवृत्तियों को जन्म दिया था, वे अपना कार्य कर रही थीं। ससार में किसी वस्तु का विनाश नहीं होता। केवल ठोस भौतिक पदार्थ ही नहीं, विचार और सिद्धान्त भी कभी सर्वथा नष्ट नहीं हो पाते। किसी न किसी रूप में वे कायम रहते ही हैं। उनका प्रभाव मनुष्यों पर अमर रहता है। फिर फ्रांस की राज्यक्रान्ति ने जिन विचारसरणी की सृष्टि की थी, उसने तो प्रादुर्भूत होते ही सम्पूर्ण पाश्चात्य समार को जड़ में हिला दिया था। उसकी शक्ति असीम थी। उसका नष्ट हो मरना असम्भव था। इसी लिए पुराने युग का लोथ के समान भारी बोझ उसे दवा सकने में सर्वथा असमर्थ रहा। यही कारण है, कि वीएना की कांग्रेस के केवल पाच वर्ष बाद ही क्रान्ति की इन प्रवृत्तियों ने अपना कार्य फिर प्रारम्भ कर दिया। सर्वत्र विद्रोह और क्रान्ति के चिह्न नजर आने लगे। एक सदी के लगभग तक यूरोप में पुरानी और नई प्रवृत्तियों में संघर्ष चलता रहा। पाश्चात्य ससार का अगला इतिहास वस्तुतः इन प्रवृत्तियों के संघर्ष का ही इतिहास है। आखिर, फ्रेंच-राज्यक्रान्ति ने जिन भावनाओं को जन्म दिया था, वे सफल हुईं। सन् १८२० से १८४८ तक यूरोप का इतिहास नई प्रवृत्तियों के प्रगट होने व फूट पड़ने के वृत्तान्त से भरा हुआ है। १८४८ के बाद ये प्रवृत्तियाँ सर्वत्र सफल होती हुई नजर आने लगी। इस अध्याय में हमें इस बात पर प्रकाश डालना है, कि १८४८ तक किस प्रकार इन प्रवृत्तियों ने पुराने जमाने को नष्ट करने का प्रयत्न किया, और उन्हें कहा तक सफलता हुई।

## २ स्पेन की राज्यक्रान्ति

फर्डिनेन्ड के शासन से असन्तोष—फर्डिनेन्ड सप्तम ने किस प्रकार स्पेन में क्रान्ति की भावनाओं तथा नवीन सुधारों को कुचलने का प्रयत्न किया था, इसका वर्णन पहले किया जा चुका है। पुराने जमाने को फिर से वापस ले आने के लिये जो कुछ भी उससे बन पाया, उसने किया। परिणाम यह हुआ, कि जनता में असन्तोष की अग्नि सुलगने लगी। सुधार के पक्षपाती शान्तिमय उपायों से अपने उद्देश्य को पूर्ण करने में सर्वथा असमर्थ हो गये। राजा पर वे किसी भी प्रकार से अपना प्रभाव नहीं डाल सकते थे। राजा पूर्णतया कुलीन और पुरोहित श्रेणियों के प्रभाव में था। आखिर, निराश हो कर उन्होंने गुप्त

समितियों का संगठन करना शुरू किया। सर्वसाधारण जनता उनके साथ थी। क्रान्ति ने जनता को जो अधिकार तथा अवसर दिये थे, उन्हें वह आसानी से नहीं छोड़ देना चाहती थी। मध्यश्रेणी के बहुत से लोग जो अपने व्यवसायों तथा व्यापार के कारण काफी उन्नत तथा समृद्ध हो चुके थे, अब इस बात को नहीं सह सकते थे, कि कुलीन लोग ऐसे विशेषाधिकारों का उपयोग करें, जो उन्हें प्राप्त नहीं हैं। सैनिक लोग भी फर्डिनेण्ड के शासन से असन्तुष्ट थे। नेपोलियन के विरुद्ध लड़ते-लड़ते राष्ट्रीयता की भावनाएँ उनमें भी विकसित हो गई थी। जनता की इच्छा के विरुद्ध इस प्रकार का एकतन्त्र स्वेच्छाचारी शासन वे सहन नहीं कर सकते थे। विद्रोह के लिये मैदान तैयार था। १८२० में विद्रोह की अग्नि स्पेन भर में प्रचण्ड हो उठी। काडिज में सेना ने विद्रोह किया। क्रान्तिकारी लोग तो उप-युक्त अवसर की प्रतीक्षा में थे ही, वे भी उनके साथ शामिल हो गये। विद्रोह की अग्नि सम्पूर्ण स्पेन में व्याप्त हो गई। फर्डिनेण्ड के लिये अपनी राजगद्दी को सँभालना मुश्किल हो गया। आखिर, जनता को सन्तुष्ट करने के लिये उसने १८१२ के शासन-विधान को फिर से स्थापित किया। धार्मिक न्यायालय नष्ट कर दिये गये। उसने और अधिक नुधार करने की भी प्रतिज्ञा की। परिणाम यह हुआ, कि जनता धोके में आ गई। विद्रोह शान्त हो गया। दो वर्षों तक फर्डिनेण्ड ने नवीन शासन-विधान के अनुसार शासन किया। पार्लियामेंट का निर्वाचन किया गया। उदार विचारों के नेता मन्त्री नियत किये गये। परन्तु फर्डिनेण्ड की नियत साफ नहीं थी। वैध शासन की कल्पना भी उसे सह्य न थी। वह विदेशी सेनाओं की सहायता से वैध शासन को नष्ट करने के लिये पड़्यन्त्र रच रहा था। कुलीन और पुरोहित श्रेणियों के लोग उसके साथ थे। आखिर, फर्डिनेण्ड अपने मित्र मटरनिख को इस बात के लिये प्रेरित करने में समर्थ हुआ, कि वह 'चतुर्विध मित्रमण्डल' की शक्ति का स्पेन में स्वेच्छाचारी राजसत्ता को स्थापित करने के लिये प्रयोग करे। सन् १८२३ में वेरोना के अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में स्पेन का मामला पेश किया गया। सब राज्य इस बात के पक्ष में थे, कि फर्डिनेण्ड की सहायता की जाय। केवल इङ्ग्लैण्ड इसके विरुद्ध था। आखिर, यह निश्चय किया गया, कि फ्रांस की सेनाएँ फर्डिनेण्ड की सहायता के लिये भेजी जाय। ९५ हजार फ्रेंच सैनिक एकसत्तात्मक राजतन्त्र की स्थापना के लिये स्पेन में प्रविष्ट हुए। फ्रांस की सेनाएँ, जिन्होंने सारे यूरोप को क्रान्ति की लहरों से व्याप्त कर दिया था, अब इतनी अधिक परिवर्तित हो गई थी, कि जनता के न्याय्य अधिकारों को कुचलने के लिये एक स्वेच्छाचारी राजा की सहायता करने में सकोच नहीं करती थी। फ्रेंच सैनिकों की सहायता से नई प्रवृत्तियों को सर्वथा कुचल दिया गया। पार्लियामेंट बर्बाद कर दी गई। उदार मन्त्रिमण्डल पदच्युत कर दिया गया। स्पेन में फिर वही स्वेच्छाचारी राजसत्ता, वही धार्मिक न्यायालय, वही कुलीनों के विशेष अधिकार, अभि-प्राय यह है, कि वही पुराना जमाना स्थापित हो गया। उदार विचारों के लोगों पर भयकर अन्याचार किये गये। एक प्रकार का आतंक सा बिठाने का प्रयत्न किया गया। फर्डिनेण्ड १८३० तक इसी प्रकार एकतन्त्र और स्वेच्छाचारी रूप में शासन करता रहा। इस मूर्खी राज्य में उस के विरुद्ध विद्रोह करने का साहस किसी को न हुआ। उसकी सहायता करने के लिये मटरनिख अपनी सम्पूर्ण शक्ति के साथ उद्यत था। यूरोप के राजा अन्याचारों और

कृताओं के लिये उसकी पीठ ठोक रहे थे।

**विद्रोह की प्रवृत्ति का पुनः प्रारम्भ—**१८३० में जब फ्राम में राज्यक्रान्ति हुई, तो उसका प्रभाव स्पेन पर भी पड़ा। जनता में एक बार फिर माहम का संचार हुआ। उदार विचारों के लोग सुधार के लिये आन्दोलन करने लगे। परन्तु उन को सफलता न हुई। लोगों में उर बैठा देने के लिये सब प्रकार के उपायों को प्रयोग में लाया गया। गुप्तचरों की सख्या बढ़ा दी गई। फीजी न्यायालय कायम किये गये। मेड्रिड में एक विधायी को केवल इसलिये फासी पर चढ़ा दिया गया, क्योंकि उसने 'स्वतन्त्रता की जय' का नारा लगाया था। एक स्त्री को इसलिये प्राणदण्ड दिया गया, क्योंकि उसने एक झण्डे पर 'स्वतन्त्रता, कानून और समानता' ये शब्द लिखे थे। परन्तु इन सब अन्याचारों के बावजूद भी उदार और नवीन विचारों के लोग निरन्तर प्रचलित होते जाते थे। १८३४ में पार्लियामेंट में नवीन विचारों के लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई। फर्डिनेण्ड सप्तम की पार्लियामेंट नाम की ही व्यवस्थापिका सभा थी, उसके अधिकार नहीं के बराबर थे। उसे टैक्स पर वोट देने तक का अधिकार प्राप्त नहीं था। पर फिर भी पार्लियामेंट में बहुमत हो जाने के कारण नवीन विचारों के लोग राजा को शासन-सुधार करने के लिये विवश करने में समर्थ हुए। इस समय से स्पेन में नवीन विचारों की शक्ति निरन्तर बढ़ती ही गई। १८३७ में राजा को बाधित होना पड़ा, कि १८१२ के शासन-विधान के आधार पर एक नवीन शासन-विधान स्पेन में जारी करे। १८३७ के इस शासन-विधान द्वारा पार्लियामेंट की शक्ति फिर से स्थापित की गई। यद्यपि यह जनता की वास्तविक प्रतिनिधि नहीं थी, क्योंकि वोट देने का अधिकार बहुत कम लोगों को दिया गया था, पर राजा की एतन्त्र सत्ता अब अवश्य नष्ट हो गई थी।

**बंध राजसत्ता की स्थापना—**१८३७ के शासन-विधान से स्पेन में भी बंध राजसत्ता स्थापित हुई। पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी मन्त्रिमण्डल स्पेन का शासन करने लगा।

**स्पेनिश उपनिवेशों में स्वतन्त्रता की भावना—**सोलहवीं और सतरहवीं सदियों में जब यूरोपियन लोगों ने अपने सामुद्रिक साम्राज्यों का निर्माण आरम्भ किया, तो स्पेन इस क्षेत्र में सबसे आगे था। मध्य और दक्षिण अमेरिका में स्पेन ने अनेक उपनिवेशों की स्थापना की थी, इन स्पेनिश उपनिवेशों में स्वशासन का जरा भी अस्तित्व न था। ये पूर्णतया स्पेन के अधीन थे। जब अठारहवीं सदी के उत्तरार्द्ध में उत्तरी अमेरिका के इङ्गलिश उपनिवेशों में स्वराज्य के लिये आन्दोलन प्रारम्भ हुआ, तो उसका प्रभाव स्पेनिश उपनिवेशों पर पड़ना सर्वथा स्वाभाविक था। इङ्गलिश उपनिवेशों को अपने प्रयत्न में सफलता हुई। स्वतन्त्र होकर वे संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्माण करने में समर्थ हुए। जब स्पेन के उपनिवेशों ने देखा, कि उनके उत्तरी पड़ोसी स्वाधीन हो गये हैं, तो उनमें भी स्वराज्य प्राप्त करने की उत्कण्ठा प्रचलित हो गई। फ्रांस की राज्यक्रान्ति ने उनमें और अधिक साहस उत्पन्न किया, और वे स्वतन्त्रता के लिये सग्राम करने को सन्नद्ध होने लगे। उपनिवेशों में स्पेन का शासन बहुत ही कठोर और विकृत था। स्पेनिश लोग उपनिवेशों को वन उपार्जन और अपने लाभ का साधन मात्र समझते थे। फ्रांस की क्रान्ति के बाद जब नैपोलियन ने स्पेन पर कब्जा कर लिया, तो इन अमेरिकन उपनिवेशों को अपनी

राजनीतिक स्वतन्त्रता के लिये आन्दोलन करने का सुवर्णवसर हाथ लगा। साथ ही, अपने व्यापार को उन्नत करने का भी उन्हो ने विशेष रूप से प्रयत्न किया। इससे पूर्व वे स्पेन के अतिरिक्त अन्य किसी देश से व्यापार नहीं कर सकते थे। उन दिनों यूरोप की औपनिवेशिक नीति का यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था, कि उपनिवेश अपने मूल देश के अतिरिक्त अन्य किसी देश से व्यापार न करने पावे। नैपोलियन के समय की अव्यवस्था से लाभ उठा कर स्पेनिश उपनिवेशों ने सयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन के साथ व्यापार करना आरम्भ कर दिया। राजनीतिक स्वतन्त्रता के लिए भी इन उपनिवेशों में आन्दोलन चल रहा था। १८०४ के बाद उनमें निरन्तर विद्रोह होने शुरू हो गये।

**क्रान्ति का प्रारम्भ**—स्पेन उस समय नैपोलियन के कब्जे में था। वहां स्वयं गृह-कलह जारी था। स्पेन से किसी भी प्रकार की सहायता इन उपनिवेशों के विद्रोह को शान्त करने के लिये नहीं भेजी जा सकती थी। परिणाम यह हुआ, कि जो थोड़ी बहुत स्पेनिश सेनाएँ उपनिवेशों में विद्यमान थी, वे परास्त कर दी गईं, और वहां के स्पेनिश शासकों को पराजित कर बाहर निकाल दिया गया। इन विद्रोहों में सयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन की सहानुभूति विद्रोहियों के साथ थी। यद्यपि इंग्लैण्ड नैपोलियन के खिलाफ स्पेन की सहायता करने के लिये कटिबद्ध था, तथापि स्पेनिश साम्राज्य का भङ्ग होते देखकर उसे हार्दिक प्रसन्नता थी। अधिकांश स्पेनिश उपनिवेश इस समय स्वतन्त्र हो गये और उनमें सयुक्त राज्य अमेरिका व फ्रांस के नमूने के रिपब्लिकन शासन स्थापित हुए।

**मिक्सिको का हस्तक्षेप**—स्पेनिश उपनिवेशों की इन सफल क्रान्तियों को यूरोप के स्वैच्छाचारी राजा सहन नहीं कर सकते थे। जनता का विद्रोह, चाहे वह पृथ्वी के किसी भी कोने में क्यों न हो रहा हो, उन्हें सह्य न था। इसलिये वेरोना के अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में (१८२३) जब स्पेनिश विद्रोह को कुचलने का कार्य फ्रांस के सुपुर्न किया गया, तब साथ ही यह भी निश्चय हुआ, कि स्पेनिश उपनिवेशों के विद्रोहों को भी शान्त किया जाय और उन्हें फिर से फर्डिनेण्ड सप्तम की अधीनता में लाया जाय। फ्रांस की सेनाएँ बड़ी खुशी से इस महत्वपूर्ण कार्य को अपने हाथ में ले लेती, अगर ग्रेट-ब्रिटेन और सयुक्तराज्य अमेरिका इस बात का विरोध न करते।

**इंग्लैण्ड का विरोध**—ग्रेट ब्रिटेन दो कारणों से इसके विरोध में था। पहली बात यह, कि इसमें स्पेन के साम्राज्य का पुनः स्थापन होता था, और दूसरी बात यह कि पिछले दिनों में स्पेनिश उपनिवेशों के साथ उसका नया नया व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित हुआ था। ग्रेट ब्रिटेन को इस व्यापार में बहुत आशा थी। यह निश्चित था, कि यदि ये उपनिवेश फिर से स्पेन के अधीन हो जाते, तो वह औपनिवेशिक नीति का जवलम्बन कर अन्य देशों के साथ उनके व्यापारिक सम्बन्ध को सर्वथा रोक देता। ग्रेट ब्रिटेन इस भारी नुस्खे को सहने के लिये उद्यत नहीं था। अतः उसने उद्घोषित किया, कि अमेरिका के उन स्वतन्त्र राज्यों की स्वतन्त्रता में यदि यूरोप के राज्य किसी भी प्रकार से बाधा डालेंगे, तो ग्रेट ब्रिटेन उनका विरोध करेगा और आवश्यकता पटने पर शस्त्रों का भी उपयोग करेगा। नयुन राज्य अमेरिका भी यह नहीं चाहता था, कि इन उपनिवेशों में स्थापित हुआ उनका नया नया व्यापारिक सम्बन्ध इतनी सुगमता से नष्ट हो जावे। साथ ही वह यह भी

सहन नहीं कर सकता था, कि पुरानी दुनिया के राज्य नहीं दुनिया के मामलों में इस प्रकार से हस्तक्षेप करे।

**मुनरो सिद्धान्त**—इसीलिये १८२२ में संयुक्तराज्य अमेरिका ने कोलम्बिया, चिली, अर्जेंटीन और मैक्सिको (ये सब पहले स्पेन के उपनिवेश थे) को स्वतन्त्र राज्यों के रूप में स्वीकृत कर लिया, और अगले वर्ष १८२३ में राष्ट्रपति मुनरो ने अमेरिकन कांग्रेस के सम्मुख उस प्रसिद्ध सिद्धान्त का प्रतिपादन किया, जो अब तक उसके अपने नाम में विख्यात है। राष्ट्रपति मुनरो ने कहा—“यूरोपियन राज्यों के पारम्परिक युद्धों में हम ने अब तक कभी हिस्सा नहीं लिया है। न हमारी यह नीति ही है, कि हम यूरोप के आन्तरिक मामलों में किसी भी प्रकार में हस्तक्षेप करें। परन्तु जिम समय हमारे अधिकारों पर हमला किया जाता है, या उनको गहरे तरीके में हानि पहुंचाई जाती है, तभी हम जागरूकता के लिये तैयारी करते हैं, या नुकसान में अपना बचाव करते हैं। पर पृथिवी के इस भाग के आन्दोलनों और घटनाओं में हमारा अधिक मन्त्रिकट सम्बन्ध है, और इसका कारण कोई भी बुद्धिमान तथा निष्पक्ष व्यक्ति मुगमता में समझ सकता है। यूरोप के ‘मित्र-मंडल’ की राजनीतिक पद्धति हम लोगों में इस अर्थ में सर्वथा भिन्न है। हम उस बात को उद्घोषित करना चाहते हैं, कि यदि यूरोपियन राज्यों का ‘मित्रमण्डल’ अपनी राजनीतिक पद्धति को पृथिवी के इस भाग के किसी हिस्से पर प्रयुक्त करने का प्रयत्न करेगा, तो इसे हम अपनी शान्ति और सुरक्षा के लिये खतरनाक समझेंगे।” यही स्थापना इतिहास में ‘मुनरो-सिद्धान्त’ के नाम से प्रसिद्ध है। यह ध्यान में रखना चाहिये, कि इस सिद्धान्त के प्रतिपादन में ग्रेट ब्रिटेन के परराष्ट्र मन्त्रि जार्ज कैनिंग का भी हाथ था।

**स्वतन्त्रता की प्राप्ति**—राष्ट्रपति मुनरो की इस उद्घोषणा का यह परिणाम हुआ, कि यूरोपियन राज्यों के लिये स्वतन्त्र हुए स्पेनिश उपनिवेशों के मामलों में हस्तक्षेप करना कठिन हो गया। मेटरनिख तथा उसके साथी राजनीतिज्ञ परेशान रह गये। प्रबल इच्छा होती हुई भी वे उपनिवेशों को अधीन करने के लिये फर्डिनेण्ड की सहायता नहीं कर सके। फर्डिनेण्ड ने स्वयं भी कोई प्रयत्न नहीं किया। उसमें इतनी शक्ति नहीं थी, कि एक तरफ तो अपनी प्रजा की स्वाधीनता की भावनाओं को कुचलता रहे, और दूसरी तरफ सुदूरवर्ती अमेरिकन उपनिवेशों को भी अपने अधीन रख सके। परिणाम यह हुआ, कि स्पेन का औपनिवेशिक साम्राज्य नष्ट हो गया। क्रान्ति की जो भावनाएँ फ्रांस में प्रादुर्भूत हुई थी, वे यदि स्पेन में पूर्णतया प्रसारित नहीं हुईं, तो कम से कम समुद्र पार के उपनिवेशों में तो वे अपना कार्य कर ही गईं।

### ३ पोर्तुगाल में क्रान्ति की भावना

सन् १८२० में स्पेन के साथ ही पोर्तुगाल में भी राज्यक्रान्ति का प्रारम्भ हुआ। सन् १८०८ में नेपोलियन की सेनाओं ने पोर्तुगाल पर कब्जा कर लिया था और वहाँ का राजा जॉन चतुर्थ अपने अमेरिकन उपनिवेश ब्राजील में भाग गया था। इसके बाद पोर्तुगाल फ्रांस के अधीन हो गया, और राजा जॉन चतुर्थ ब्राजील में स्वतन्त्र रूप से शासन करता रहा। परन्तु पोर्तुगाल में फ्रेंच लोगों का शासन देर तक कायम नहीं रह सका। १८०८

के अन्त में ही बेलगटन के ड्यूक ने अपनी इङ्गलिश सेनाओं के साथ वहाँ प्रवेश किया, और फ्रेंच सेनाओं को परास्त कर पोर्तुगाल को अपने कब्जे में कर लिया। तब से लेकर १८२० तक (१८०८-१८२०) पोर्तुगाल इङ्गलिश अफसरों के शासन में रहा, जो कि ब्राजील भागे हुए पोर्तुगीज राजा के नाम पर वहाँ का शासन करते रहे। पोर्तुगाल के निवासी इङ्गलिश लोगों के शासन को जरा भी पसन्द नहीं करते थे। फ्रेंच राज्यक्रान्ति द्वारा प्रादुर्भूत नवीन भावनाओं ने उन पर भी प्रभाव डाला था, वे भी राष्ट्रीयता के भावों से प्रेरित होकर अपने देश को इङ्गलिश लोगों की हुकूमत से मुक्त कराने तथा जनता के अधिकारों को स्थापित करने के लिये उत्सुक थे। पोर्तुगाल पोर्तुगीज लोगों के लिये है, यह भावना सम्पूर्ण देश में व्याप्त हो रही थी। इस दशा में जब १८२० में स्पेनिश लोगों ने विद्रोह किया, तो पोर्तुगाल में भी विद्रोह की अग्नि प्रचण्ड हो गई। ब्रिटिश शासकों को बहिष्कृत कर दिया गया। धार्मिक न्यायालय (इन्क्वीजिशन) नष्ट किये गये। कुलीन और पुरोहित श्रेणियों से विशेषाधिकार छीन लिये गये। एक लोकसभा का संगठन कर यह भी उद्घोषित किया गया, कि कानून की दृष्टि में सब मनुष्य एक समान हैं, सबको लिवने, बोलने और म्र्दण की पूर्ण स्वतन्त्रता है। इस लोकसभा ने लोकतन्त्र के सिद्धान्तों के अनुसार देश के लिये एक नवीन शासन-विधान का भी निर्माण किया।

पोर्तुगाल की इस क्रान्ति को यूरोप के स्वेच्छाचारी राजा सहन नहीं कर सके। वे हस्तक्षेप करने का विचार करने लगे। ग्रेट ब्रिटेन ने भी पोर्तुगाल के विद्रोह को कुचल देने का निश्चय किया। ब्राजील भागे हुए राजा जॉन चतुर्थ को प्रेरित किया गया, कि वह अपने वास्तविक राज्य को वापस लौटकर अपनी खोई हुई राजगद्दी को फिर से सँभाल ले। राजा जान ने इस सुवर्णविसर को हाथ से नहीं जाने दिया। वह पोर्तुगाल वापस लौट आया। १८२१ में पोर्तुगाल वापस आकर राजा जॉन ने उद्घोषित किया, कि मैं नवीन शासन-विधान को स्वीकृत करने के लिये तैयार हूँ। जनता इससे बहुत सन्तुष्ट हुई। उसने उसे अपना राजा स्वीकृत कर लिया। इस प्रकार जॉन चतुर्थ एक बार फिर पोर्तुगाल का राजा बन गया। पर जॉन चतुर्थ के ब्राजील से प्रस्थान करते ही वहाँ विद्रोह हो गया। इस विद्रोह का नेता जॉन का बड़ा लड़का पेड्रो था। उसे ब्राजील में अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित करने देर नहीं लगी। जॉन एक ही देश का राजा रह सकता था, पोर्तुगाल का या ब्राजील का। दोनों देशों को सँभाल सकना उसकी शक्ति से बाहर था।

पोर्तुगाल वापस लौटकर जान ने जिस उदार नीति का परिचय दिया था, उसे वह देर तक वायम नहीं रख सका। शीघ्र ही वह कुलीन और पुरोहित लोगों के प्रभाव में आ गया। उसने शासन-विधान की उपेक्षा करनी प्रारम्भ कर दी। परिणाम यह हुआ, कि एक बार फिर विद्रोह की अग्नि प्रचण्ड हो उठी। पोर्तुगाल की जनता ने विद्रोह कर दिया। राजा जान चतुर्थ को भाग निकलने के लिये बाधित होना पड़ा। एक ब्रिटिश जहाज का जहाज लेयर वह अपनी जान बचाने में समर्थ हुआ। परन्तु यूरोप के एकतन्त्र राजा और विशेषतया ब्रिटेन उसकी सहायता करने के लिये कटिबद्ध थे। उन्होंने उसे फिर महारा दिया। 'मिगण्डल' की सहायता से राजा जॉन एक बार फिर पोर्तुगाल की राजगद्दी पर आनट गया। इस समय में कुलीन श्रेणियों और यूरोप के राजपरिवारों ने जनता के विद्रोह

एक भयकर पड़्यन्त्र किया हुआ था। जनता इस पड़्यन्त्र के सम्मुख सर्वथा असहाय थी।

१८२६ में राजा जान की मृत्यु होगई। उसका लड़का पेड्रो, जो इस समय ब्राजील का राजा था, अब पोर्तुगाल का भी राजा बन गया। मन् १८३४ तक जनता और राजा में निरन्तर संघर्ष जारी रहा। इस काल में पोर्तुगाल में एक प्रकार का गृह-युद्ध मा जारी था। जनता अपने अधिकारों के लिये कोशिश कर रही थी, और कुलीन श्रेणियों की सम्पूर्ण शक्ति उसकी न्याय्य मांगों को पायबिक बल का प्रयोग कर के नष्ट करने में तत्पर थी। जाविर, १८३४ में जनता की विजय हुई। राजा को एक उद्घोषणापत्र प्रकाशित करने के लिये बाधित होना पड़ा, जिसके अनुसार कुलीन और पुरोहित श्रेणियों के विशेषाधिकार नष्ट किये गये, चर्च की सम्पत्ति छीन ली गई, वैध राजमत्ता की स्थापना की गई और जनता के अधिकार स्वीकृत किये गये। पोर्तुगाल में भी राजमत्ता को पूर्णतया जनता के जमीन कर दिया गया। क्रान्ति की प्रवृत्तियाँ आगिरकार पोर्तुगाल में भी सफल हो गईं।

## ४ इटली में क्रान्ति की लहर

वीएना की कांग्रेस के बाद इटली के विविध राज्यों की जो व्यवस्था की गई थी, उस पर पहले प्रकाश डाला जा चुका है। उत्तरी इटली के बड़े भाग पर आस्ट्रिया का सीधा शासन था। साथ ही अनेक राज्य, जो सीधे आस्ट्रिया के शासन में नहीं थे, उसके प्रभाव में थे। पीडमोंट, नेपल्स, पोप का राज्य, लोम्बार्डी, टस्कनी आदि इटली के सभी राज्यों में एकतन्त्र स्वेच्छाचारी राजाओं का शासन था। पर इटली में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हो चुकी थी। इटालियन नवयुवक अपने देश को एक शासन में संगठित देखना चाहते थे, पर उनकी आकांक्षा के पूर्ण होने की कोई सम्भावना दृष्टिगोचर नहीं होती थी। वीएना के राजनीतिज्ञों ने जनता की इच्छा की सर्वथा उपेक्षा कर वहाँ पुराने राजवशों का पुनरुद्धार कर दिया था। ये छोटे-छोटे राजा अपने को परमेश्वर का प्रतिनिधि मान कर मनमानी तरीके से शासन करते थे। १८२० में जब स्पेन में राज्यक्रान्ति हुई, तो इटालियन लोगों में भी साहम उत्पन्न हुआ। वे भी अपने अधिकारों के लिये संघर्ष करने को उद्यत हो गये। इटली में गुप्त समितियों की कमी नहीं थी। १८१५ के बाद जब प्रतिक्रिया के युग का प्रारम्भ हुआ था, तभी वहाँ अनेक गुप्त समितियों का संगठन हो गया था। 'कार्बोनरी' नामक समिति के सदस्यों की संख्या साठ हजार के लगभग थी। इस सुप्रसिद्ध गुप्त समिति के अतिरिक्त अन्य भी बहुत सी गुप्त समितियाँ वहाँ विद्यमान थी, जो अपने देश को स्वतन्त्र तथा संगठित करने के लिये प्रयत्न कर रही थी। १८२० में इन समितियों को विद्रोह करने के लिये अत्यन्त उत्तम अवसर हाथ लगा। नेपल्स के लोगों ने अपने राजा फर्डिनेन्ड छठे के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, और उसे इस बात के लिये बाधित किया कि वह शासन-विधान का निर्माण कर उसीके अनुसार शासन करे। इसी प्रकार सिसली—जो कि नेपल्स के राजा के ही अधीन था, में भी विद्रोह हुआ। वहाँ भी जनता के अधिकारों को स्वीकृत कराने के लिये आवाज उठाई गई, पर उसे सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। आस्ट्रिया का प्रधान मन्त्री मेटर्निख यह सहन नहीं कर सकता था, कि इटली के लोगों में भी नवीन भावनाओं का संचार हो। राजा फर्डिनेन्ड छठे की सहायता के लिये आस्ट्रियन सेनाएँ तैयार



थी। उन्होंने न केवल सिसली के विद्रोह को ही शान्त किया, अपितु नेपल्स की जनता को भी अच्छा पाठ पढ़ाया। नेपल्स के नये शासन-विधान को नष्ट कर दिया गया। जिस किसी ने इसका विरोध करने की हिम्मत की, उसे भयकर दण्ड दिये गये। आस्ट्रियन मेनाओ की सहायता से नेपल्स के राज्य में फिर से पहले के समान एकतन्त्र स्वेच्छाचारी राजसत्ता की स्थापना कर दी गई।

१८२१ में पीडमोंट की जनता ने विद्रोह किया। पीडमोंट का राज्य फ्रांस के बहुत समीप था। क्रान्ति की लहरे उसे अच्छी तरह आप्लावित कर चुकी थी। नेपोलियन ने उसे जीतकर फ्रांस के अधीन कर दिया था, और वहां के निवासी स्वतन्त्रता और समानता के सिद्धान्तों पर आश्रित शासन का आस्वाद ले चुके थे। पीडमोंट के विद्रोहियों का कहना था, कि हमारे देश में भी शासन-विधान की स्थापना होनी चाहिये, एकतन्त्र स्वेच्छाचारी शासन का अन्त होना चाहिये, और उत्तरी इटली से आस्ट्रिया के प्रभाव को नष्ट कर सम्पूर्ण देश को एक सूत्र में मगठित किया जाना चाहिये। पीडमोंट का राजा विक्टर एमेनुअल प्रथम इस विद्रोह को शान्त करने में असमर्थ था। उसने राजगद्दी का परित्याग कर देने में ही कल्याण समझा। अपने भाई चार्ल्स फेलिक्स को राज्य सौंप कर वह पीडमोंट छोड़कर चला गया। चार्ल्स फेलिक्स बहुत हिम्मती और जबर्दस्त आदमी था। आस्ट्रिया और रूस की सहायता प्राप्त कर वह विद्रोह को शान्त करने में सफल हो गया। १८२० में क्रान्ति की जो लहर स्पेन में प्रारम्भ हुई थी, वह इटली तक पहुँचते-पहुँचते सर्वथा शक्तिहीन हो गई थी। इटालियन लोगों की आकांक्षाएँ पूर्ण नहीं हो सकी। परन्तु जो नई प्रवृत्तियाँ इटली में कार्य कर रही थी, वे सदा के लिये दवाई नहीं जा सकती थी। चौथाई सदी के बाद ही इटली एक राष्ट्र बन गया, और वहां नई भावनाएँ निया में परिणत हो गईं।

## ५ अन्य देशों में क्रान्ति का प्रारम्भ

**वालकन प्रायद्वीप—**अठारहवीं सदी के अन्त तक वालकन प्रायद्वीप के बड़े भाग पर टर्की के सुलतान का शासन था। वालकन प्रायद्वीप में अनेक जातियाँ निवास करती थीं। इन सब की भाषा, धर्म, नसल और जाति टर्की से भिन्न थी। फ्रांस की राज्यक्रान्ति द्वारा उत्पन्न नई प्रवृत्तियों ने इन पर भी असर डाला, और इन्होंने भी यह अनुभव करना शुरू किया कि हमें भी स्वतन्त्र होना चाहिये। ग्रीक लोग सोचने लगे, कि ग्रीक को टर्की के अधीन नहीं रहना चाहिये। सर्व, बल्गेरियन, रूमानियन आदि लोगों में भी इसी प्रकार के विचार उत्पन्न हुए। राष्ट्रीयता की भावनाओं से प्रभावित होकर वालकन प्रायद्वीप की इन जातियों ने स्वतन्त्र होने का स्वप्न देखना प्रारम्भ कर दिया। टर्की के सुलतान का शासन पूर्णतया स्वेच्छाचारी और एकतन्त्र था। वालकन प्रायद्वीप के निवासी प्रधानतया ईसाई धर्म को माननेवाले थे। वे एक मुसलमान सुलतान का शासन किसी भी प्रकार नहीं सह सकते थे। जिस समय नेपोलियन का पतन करने के लिये ग्रेट ब्रिटेन, प्रुशिया, रूस और आस्ट्रिया ने गुट का निर्माण किया और यह उद्घोषित किया, कि हम विविध जातियों को नेपोलियन के एकाधिपत्य से मुक्त कराने के लिये और यूरोप में स्वतन्त्रता तथा राष्ट्रीयता

की स्थापना के लिये सघर्ष कर रहे हैं, तो इन वाल्कन जानियों को बहुत आशा हुई। उन्होंने समझा, कि इस शक्तिशाली गुट की सहायता कर अन्त में हम भी अपनी अवस्था को उन्नत करने में समर्थ हो सकेंगे। विशेषतया, ग्रीस में नैपोलियन के विरुद्ध वन डम गुट की सहायता करने के लिये भारी आन्दोलन हुआ। १५ हजार के लगभग ग्रीक स्व-सेवक इस युद्ध में सम्मिलित हुए। आगिर, जब नैपोलियन का पतन हो गया, और यूरोप का पुनर्निर्माण करने के लिये विविध राजनीतिज्ञ बीणना में एकत्रित हुए, तब ग्रीक लोगो को आशा थी, कि हमारी तरफ भी ध्यान दिया जायगा और हमारे उद्धार के लिये भी कोशिश की जायगी। पर वे पूर्णरूप में निराश हुए। बीणना के राजनीतिज्ञ राष्ट्रीयता और स्वतन्त्रता के कट्टर दुश्मन थे। नैपोलियन के खिलाफ विविध लोगो की सहायता प्राप्त करने के लिये ही उन्होंने इन उदात्त मित्रानों का प्रतिपादन किया था। बीणना में निराश होकर ग्रीक लोगो ने अपने पहिये पर अपने आप कन्या लगाने का निश्चय किया। अनेक गुप्त सभा-समितियां संगठित की गईं। विशेषतया, 'मित्रसभा' नाम की मस्या ने इस समय बड़ा काम किया। इस सभा के सदस्य सम्पूर्ण वाल्कन प्रायद्वीप में फैले हुए थे। केवल कान्स्टेन्टिनोपल में ही इसके सदस्यों की मस्या मगरह हजारों के लगभग थी। इस सस्या ने राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिये बड़ा प्रचार किया। इसके आन्दोलनों का परिणाम यह हुआ, कि सम्पूर्ण वाल्कन प्रायद्वीप में स्वाधीनता की भावना प्रबल हो गई। १८२० में जब स्पेन, पोर्तुगाल और इटली में विद्रोह की अग्नि धधक रही थी, तो ग्रीक देशभक्तों में भी अपने देश में स्वराज्य स्थापित करने की आशा प्रबल हो उठी। उनका प्रधान नेता इप्सिलान्टीवडे आवेश में कहने लगा—'हेलन भाइयो! वस्तु आ गया है। अब हमें अपने धर्म और देश की स्वतन्त्रता के लिये कटिबद्ध हो जाना चाहिये।' मारे ग्रीस में यही भाव हिलोरे मारने लगा। परिणाम यह हुआ, कि १८२१ में ग्रीस का स्वाधीनता-नगम प्रारम्भ हो गया।

**ग्रीस की स्वतन्त्रता—**१८२१ में जब लैबल नामक स्थान पर यूरोपियन मित्रमण्डल की अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस हो रही थी, तब उन्हें यह चिन्ताजनक समाचार सुनने को मिला, कि एक अन्य देश ने न्याय्य और परमेश्वर के प्रतिनिधि सम्राट् के खिलाफ विद्रोह कर दिया है। मेटर्निख का मत था, कि ग्रीक विद्रोह को शान्त करने के लिये टर्की के सुलतान को सहायता दी जानी चाहिये। सुलतान ईसाई नहीं है, तो क्या हुआ। वह पन्नाइ तो है। उस जमाने में जाति, नसल और धर्म आदि तत्त्व लोगो में एकानुभूति उत्पन्न नहीं करते थे। यूरोप भर के राजा अपने को भाई-भाई समझते थे, जहां तक लोगो के अधिकारो को कुचलने का प्रश्न हो। फ्रांस के कुलीन अपने देश के किसान व जुलाहे को उतना 'अपना' नहीं समझते थे, जितना कि प्रशिया व रूस के कुलीन जमींदारो को। इस अवस्था में यह सर्वथा स्वाभाविक ही था, कि मुसलमान सुलतान के विरुद्ध क्रिश्चियन ग्रीक प्रजा के विद्रोह को कुचलने के लिये मेटर्निख प्रस्ताव उपस्थित करता। परन्तु अन्य राजाओ ने उसका समर्थन नहीं किया। सुलतान की शक्ति बहुत काफी थी। वह भयकर से भयकर उपायो का प्रयोग कर ग्रीक विद्रोह को शान्त करने का प्रयत्न कर रहा था। इस विद्रोह ने यूरोप के उदार विचारको को एक अच्छा अवसर दिया। जनता अपने अधिकारो के लिये कहीं

पर भी सघर्ष कर रही हो, उन्हें उसकी सफलता से हार्दिक खुशी होती थी। ग्रीस के लोग ईसाई धर्म को माननेवाले थे, और उनका सुलतान मुसलमान था। इस बात का इन उदार लोगों ने अच्छा उपयोग किया। मुसलमान अफसरो की तरफ से जो भयकर अत्याचार ग्रीस की ईसाई जनता पर किये जा रहे थे, उनके समाचारों को सुनकर यूरोप के ईसाई लोगों में हलचल मच गई। क्रान्ति के समर्थक उदार लोगों ने आन्दोलन करना प्रारम्भ किया, कि ग्रीक लोगों के मामले में हस्तक्षेप करना चाहिये, और मुसलमानों के पजे से अपने ईसाई भाइयों की रक्षा करनी चाहिये। ग्रीस के प्राचीन गौरवमय इतिहास को यूरोप निवासी अभी भूले नहीं थे। ग्रीस की प्राचीन सभ्यता का यूरोप पर भारी प्रभाव था। इस कारण यूरोप के लोगों को ग्रीस से स्वाभाविक सहानुभूति थी। वे उसकी सहायता करने के लिये तैयार हो गये। सब देशों से स्वयंसेवक लोग अपने ईसाई भाइयों की सहायता करने के लिये ग्रीस पहुँचने लगे। इङ्ग्लैण्ड का प्रसिद्ध कवि लार्ड बायरन भी इस युद्ध में स्वयंसेवक के रूप में सम्मिलित हुआ। यूरोप भर में ग्रीस की सहायता के लिये चन्दा एकत्रित किया गया। सब जगह से युवक सेना में भर्ती हुए। परन्तु अब भी मेटर्निख अपनी महाशक्ति के साथ ग्रीक जनता के विद्रोह को शान्त करने की चिन्ता में व्यग्र था। आखिर, वह इस बात में कामयाब हो गया, कि आस्ट्रिया और प्रशिया को किसी भी प्रकार से ग्रीस की सहायता करने से रोक रखे। पर अन्य देशों पर उसका जादू नहीं चला। जनता में ग्रीस की सहायता के लिये जो आन्दोलन चल रहा था, वह बहुत प्रबल था। रूस, फ्रांस और ब्रिटेन ने मेटर्निख की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वहाँ के लोग ग्रीस की सहायता करते रहे। कुछ समय बाद ही इङ्ग्लैण्ड को ध्यान आया, कि ग्रीस की स्वतन्त्रता का परिणाम यह होगा, कि टर्की की शक्ति निर्वल पड़ जायगी। अन्य बालकन जातियाँ भी ग्रीस का अनुसरण करेंगी, और अन्ततोगत्वा टर्की की शक्ति का सर्वथा विनाश हो जायगा। इङ्ग्लैण्ड अपने पूर्वी साम्राज्य की रक्षा के लिये यह आवश्यक समझता था, कि टर्की का विनाश न होने दिया जाय। यूरोप और एशिया के बीच के मार्ग पर इस समय टर्की का अधिकार था। पर यदि टर्की की शक्ति कमजोर हो जाय और इस महत्वपूर्ण मार्ग पर रूस व किसी अन्य शक्तिशाली राज्य का कब्जा हो जाय, तो इङ्ग्लैण्ड के लिये बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती थी। अतः इङ्ग्लैण्ड का कल्याण इसी में था, कि टर्की को नष्ट होने से बचाया जाय। टर्की से इङ्ग्लैण्ड को किसी प्रकार का खतरा नहीं था। आखिर, इस विचार से इङ्ग्लैण्ड ने ग्रीस की सहायता बन्द कर दी। परन्तु रूस और फ्रांस निरन्तर उसकी सहायता करते रहे। इसका परिणाम यह हुआ, कि ग्रीस को अपने मनोरथ में सफलता प्राप्त हुई। एड्रियानोपोल की सन्धि में (१८२९) ग्रीस की स्वतन्त्रता स्वीकृत कर ली गई।

अब ग्रीस में एक स्वाधीन राज्य की स्थापना हो गई। उसका शासन करने के लिये बेर्रिया के राजकुमार ओटो को—जिसकी आयु १८ वर्ष की थी, राजगद्दी पर बिठाया गया, और शासन-विधान का निर्माण कर वैध राजसत्ता स्थापित कर दी गई। यूरोप भर के उदार लोग इस बात से बहुत अधिक प्रसन्न हुए। क्रान्ति की भावनाओं के प्रारम्भ होने के बाद ग्रीस पहला राज्य था, जिसने लड़ कर विदेशी शासन के विरुद्ध स्वतन्त्रता प्राप्त की थी।

अन्य बालकन जातियों में भी ग्रीस के उदाहरण ने जमाधारण माहस का मन्थन किया।

वे सब स्वाधीनता के लिये कोशिश करने लगी। रूस डम प्रयत्न में उनका प्रबान सहायक था। यद्यपि जनता से उसे कोई सहानुभूति नहीं थी, पर वालकन राज्यों की स्वतन्त्रता से टर्की की शक्ति कमजोर हो जाती थी, और इस प्रकार वह इस क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ा सकता था। दूसरी ओर ग्रेट ब्रिटेन इन वालकन जातियों की स्वातन्त्र्य-भावना का प्रधान विरोधी था। ब्रिटेन को जनता की स्वतन्त्रता में विशेष विरोध नहीं था—परन्तु टर्की के निर्वल होने से उसे अपनी हानि प्रतीत होती थी। रूस और ब्रिटेन की इन भावनाओं ने वालकन प्रायद्वीप की समस्या को कितना जटिल बना दिया, इस बात का उल्लेख जागे चलकर किया जायगा। यहाँ इतना लिखना पर्याप्त है, कि क्रान्ति की लहर सम्पूर्ण वालकन प्रायद्वीप में स्वतन्त्रता के लिये उत्कट आकांक्षा का प्रादुर्भाव कर रही थी।

वारहवा अध्याय

## क्रान्ति की दूसरी लहर

### १ फ्रान्स की द्वितीय राज्यक्रान्ति

चार्ल्स दसम का शासन—सन् १८३० में फ्रांस में द्वितीय राज्यक्रान्ति का प्रारम्भ हुआ। १७८९ की राज्यक्रान्ति ने जिन नवीन भावनाओं को जन्म दिया था, वे निरन्तर अपना कार्य कर रही थी। वीएना की कांग्रेस ने इन भावनाओं को कुचलने का यथाशक्ति प्रयत्न किया। वूर्वों राजवंश का पुनरुद्धार करके वीएना के राजनीतिज्ञों ने फ्रांस में पुराने जमाने को फिर से वापस ले आने के लिये कोई भी कसर उठा नहीं रखी थी। पर नई प्रवृत्तियों को नष्ट कर सकना उनकी शक्ति के बाहर था। अठारहवें सदी के शासन से लोग बहुत अधिक असन्तुष्ट नहीं थे। उसने शक्ति भर जनता की परवाह करने का प्रयत्न किया था। पर चार्ल्स दसवा बहुत ही स्वेच्छाचारी तथा उद्धत राजा था। वह मच्चे अर्थों में राजा बनना चाहता था। वैध राजसत्ता उसकी दृष्टि में कोई अर्थ नहीं रखती थी। परिणाम यह हुआ, कि क्रान्ति की भावनाएँ फिर प्रबल हो गईं। चार्ल्स के शासन से जनता बहुत असन्तुष्ट थी। इसलिये क्रान्ति की प्रवृत्तियाँ निरन्तर जोर पकड़ने लगी। इसी कारण १८३० में फ्रांस में द्वितीय राज्यक्रान्ति का प्रादुर्भाव हुआ।

चार्ल्स दसवा जनता के अधिकारों का घोर शत्रु था। वह पहले कट्टर राजसत्तावादी दल का नेता रह चुका था। अठारहवें सदी की समझौते की नीति को देखकर वह गुस्से में दात पीसा करता था। वह कहा करता था, कि इंग्लैण्ड के राजा के समान 'वैध राजा' होने की अपेक्षा तो लकड़ियाँ चीरना कहीं अधिक अच्छा है। १८२४ में जब वह फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा, तब उसने निश्चय किया, कि मैं ईश्वर की इच्छा के अनुसार राज्य करूँगा, जनता की इच्छा से नहीं। वह पूर्णरूप से सोलहवें सदी के समान स्वेच्छाचारी राजा होना चाहता था। उसका दृढ़ संकल्प था, कि मैं क्रान्ति की सब भावनाओं को पूरी तरह से कुचल पर वास्तविक राजा की तरह फ्रांस का शासन करूँगा। राजगद्दी पर बैठने ही चार्ल्स ने अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया। लेख, भाषण, और प्रेस की स्वतन्त्रता छीन ली गई। बुलोन जमींदारों को हरजाने के तौर पर ६० करोड़ रुपये दिये गये। पादरियों को फिर से गारवर्ण स्थान प्राप्त कराया गया। शिक्षा का कार्य चर्च के सुपुर्द कर दिया गया। चार्ल्स ने निःसकाच रूप में पुराने जमाने को स्थापित करना प्रारम्भ कर दिया। इस नीति का परिणाम यह हुआ, कि फ्रांस में विद्रोह की अग्नि प्रचण्ड हो गई। उदार विचारों के लोग जोर पकड़ने लगे, और रिपब्लिक और क्रान्ति के पक्षपातियों को अपनी शक्ति बढ़ाने का उन्मत्त प्रयत्न हो गया। १८३० के राष्ट्र-प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन में उन लोगों की

सरया बहुत अधिक बढ़ गई, जो नवीन प्रवृत्तियों के पक्षपाती थे, और चार्ल्स दशम की नीति का विरोध करते थे। निर्वाचन के परिणाम को मुनकर चार्ल्स को बहुत क्रोध आया। २६ जुलाई, सन् १८३० के दिन अपने चार विशेष कानून जारी किये। इन कानूनों द्वारा निम्नलिखित व्यवस्थाएँ की गई थी—(१) प्रेम की स्वाधीनता का अपहरण किया गया। (२) नई राष्ट्र-प्रतिनिधि सभा को वर्चस्व कर दिया गया। (३) निर्वाचन का अधिकार किनको हो, इस सम्बन्ध में नये नियम जारी किये गये। इन नियमों में वोट का अधिकार बहुत कम लोगों को रह गया। तीन चौथाई लोग वोट के अधिकार में वंचित कर दिये गये। (४) राष्ट्र-प्रतिनिधि सभा का नया निर्वाचन करने के लिये हुकुम जारी किया गया।

**क्रान्ति का सूत्रपात**—चार्ल्स दशम को स्वप्न में भी मयाल नहीं था, कि उनके इन विशेष कानूनों का क्या परिणाम होगा। वह तो मजे में शिकार खेलने में अपना वक्त गुजार रहा था। परन्तु इन कानूनों के प्रकाशित होने ही फ्रांस भर में विद्रोह की ज्वालाएँ प्रदीप्त हो गईं। बोनापार्टिस्ट, रिपब्लिकन, वैध राजसत्तावादी—मद्य दल राजा की स्वेच्छाचारिता का विरोध करने के लिये एक हो गये। स्वाधीनता के जयजयकारों से पेरिस गूँज उठा। पुराने सिपाही, विद्यार्थी, मजदूर—सब भड़क उठे। पेरिस की गलियों में एक बार फिर किलाबन्दी की जाने लगी। पत्थर, ईंट, तम्बे, पुरानी मेज कुर्निया—जो कुछ भी मिला, इकट्ठा कर लिया गया, और उसमें मोर्चाबन्दी की जाने लगी। १७८१ और १७९२ के दिन एकबार फिर दृष्टिगोचर होने लगे। सारे पेरिस में सनसनी फैल गई। लफायत के नेतृत्व में पेरिस के उदार लोग खुल्लम-खुल्ला विद्रोह के लिये निकल पड़े। पेरिस विद्रोहियों के कब्जे में आ गया। राजा की सेनाओं ने उनका मुकाबला किया। पर वे जनता की शक्ति का सामना नहीं कर सकी। तीन दिन तक लगातार गलियों में लड़ाई होती रही। नेता की सहानुभूति विद्रोहियों के साथ थी। बहुत से सिपाही तो स्पष्ट रूप से विद्रोह में हिस्सा ले रहे थे। प्रथम राज्यक्रान्ति ने जो भावनाएँ उत्पन्न की थी, वीएना की कांग्रेस ने उन्हें केवल दबा दिया था। अवसर पाते ही ये एक बार फिर फूट पड़ी। आखिर, चार्ल्स की पराजय हुई। उसे जनता की इच्छा के सम्मुख सिर झुकाना पड़ा। अपने दस वर्ष के पोते को राजगद्दी पर बिठाकर वह स्वयं इङ्ग्लैण्ड भाग गया। स्वेच्छाचारी राजसत्ता के पुनरुद्धार के लिये जो प्रयत्न उसने प्रारम्भ किया था, वह शीघ्र ही विफल हो गया।

**लुई फिलिप**—क्रान्तिकारियों के सम्मुख अब यह समस्या पेश आई, कि शासन की क्या व्यवस्था करें। रिपब्लिकन दल का मत था, कि अब रिपब्लिक की स्थापना की जानी चाहिये। क्रान्ति के वास्तविक संचालक इसी दल के थे। मजदूर, व्यवसायी और विद्यार्थी इस दल में बहुसंख्या में सम्मिलित थे। ये सब रिपब्लिक के लिये उत्सुक थे। परन्तु मध्यश्रेणी के लोग—जिनका नेता थियर्स था, वैध राजसत्ता के पक्षपाती थे। लफायत ने मध्यस्थ का कार्य किया, और दोनों दलों में समझौता करा दिया। आखिर, रिपब्लिकन दल के लोग भी वैध राजसत्ता की स्थापना के लिये राजी हो गये। ७ अगस्त, १८३० को राष्ट्र-प्रतिनिधि सभा में यह विषय पेश हुआ, और निश्चय किया गया कि लुई फिलिप को फ्रांस की राजगद्दी पर बिठाया जाय। लुई फिलिप बूढ़ी राजवंश की एक शाखा

ऑर्लियनिस्ट वंश का था, और अपने विचारों में बहुत उदार था। लोग उसे बहुत चाहते थे। १८३० की क्रान्ति पूर्णरूप से सफल हुई। जनता ने स्वयं अपना राजा चुना। जनता के अधिकारों की यह स्पष्ट विजय थी। फ्रांस का नया राजा अपनी युवावस्था में जैकोबिन दल का भी सदस्य रह चुका था। उसने कातकारी सेना में सम्मिलित होकर क्रान्ति के विरोधियों से अनेक लड़ाइयाँ भी लड़ी थी। 'आतंक के राज्य' में जब फ्रेच राज्यक्रान्ति ने बहुत उग्र रूप धारण किया, तब लुई फिलिप उसका विरोधी हो गया था, और फ्रांस से भाग गया था। वीएना की कांग्रेस के बाद जब भागे हुए लोग अपने देश वापस आये, तब वह भी फ्रांस लौट आया। प्रतिक्रिया के काल में भी वह लोकतन्त्र शासन का पक्षपाती रहा, और यही कारण है, जहाँ जनता उसे बहुत चाहती थी। वह सामान्य लोगों की तरह रहता था। सड़े रहन-सहन की वजह से भी लोग उसके पक्षपाती थे। १८३० की राज्यक्रान्ति के बाद फ्रांस में रिपब्लिक की स्थापना नहीं हुई, परन्तु जनता ने अपनी इच्छा से—अपनी सम्मति से यह निश्चय किया, कि उनका शासक कौन हो। इस प्रकार, १८३० की क्रान्ति सब प्रकार से सफल हुई।

**नई व्यवस्था—**राष्ट्र प्रतिनिधि सभा द्वारा जब लुई फिलिप को राजा चुन लिया गया, तो उनके ९८ सदस्यों के हस्ताक्षरों से एक उद्घोषणापत्र प्रकाशित किया गया। इसमें कहा गया था—'फ्रांसीसी भाइयों! फ्रांस अब स्वतन्त्र है। एकतन्त्र स्वेच्छाचारी शासन अपना सिर ऊँचा उठा रहा था, पर पेरिस की जनता ने उसे पददलित कर दिया है। अब फिर व्यवस्था और स्वतन्त्रता की स्थापना हो गई है।' लुई फिलिप हमारे अधिकारों की रक्षा करेगा, क्योंकि वह अपने अधिकार हमसे ही प्राप्त करेगा।' नये शासन-विधान में प्रेस की स्वतन्त्रता को स्वीकार किया गया। लोग स्वतन्त्रता से सभा कर सके, इस अधिकार को माना गया। उन सब लोगों को वोट का अधिकार दिया गया, जिनकी आयु पच्चीस साल से अधिक हो, और जो अपनी जायदाद पर कम से कम १२० रु० वार्षिक कर देते हो, या यदि वे कोई पग करनेवाले हो, तो कम से कम ६० रु० वार्षिक टैक्स देते हो। इस प्रकार अब मध्यश्रेणी के लोगों को वोट का अधिकार प्राप्त हुआ। पर सर्वसाधारण जनता को—किसानों और मजदूरों को इस नये शासनविधान ने कोई भी अधिकार नहीं दिया। ६० रु० वार्षिक टैक्स देनेवाले लोगों की संख्या उस समय फ्रांस में अधिक नहीं थी। पर अब नये मतधिकार के अनुसार वोटों की संख्या दुगुने के लगभग हो गई थी, और समय की दृष्टि में रखने हुए यह कोई मामूली बात नहीं थी। इस नये शासन-विधान के अनुसार यह भी निश्चय किया गया, कि गैर धार्मिक धर्म का राज्य के साथ कोई सम्बन्ध न रहे, सब लोगों को धार्मिक स्वतन्त्रता प्राप्त हो, और शिक्षणालय भी चर्च के अधीन न रहे। इस प्रकार अठारहवें लुई और दसवें चार्ल्स के समय में क्रान्ति की भावनाओं के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया हुई थी, उसे बहुत जल्द तक १८३० की राज्यक्रान्ति द्वारा दूर कर दिया गया।

**लुई फिलिप का विरोध—**लुई फिलिप के मुख्य पक्षपाती मध्यश्रेणी के लोग थे। पर उनके विरोधियों की संख्या भी कम नहीं थी। कुलीन श्रेणी के लोग उनकी सत्ता को स्वीकृत करने के लिये तैयार न थे। वे वूर्वों राजवंश के किसी कुमार को फ्रांस की राजगद्दी पर देखना चाहते थे। साथ ही, वीनापार्टिस्ट दल और रिपब्लिकन दल भी उनके शासन को स्वीकृत करने के लिये उद्यत न थे। वीनापार्टिस्ट दल 'रोम के

वादगाह' को फ्रांस का राज्य देना चाहता था, और रिपब्लिकन लोग रिपब्लिक के आदर्श को पूर्ण करना चाहते थे। यद्यपि बहुत से रिपब्लिकन लोगों ने समझौते के तौर पर लुई फिलिप को राजा मान लिया था, पर उनकी वास्तविक जाकाक्षा रिपब्लिक स्थापित करने की ही थी। मजदूर, किसान, कारीगर और सामान्य स्थिति के अन्य लोग नये शासन से असन्तुष्ट थे। इन लोगों के बड़े भाग को वोट का अधिकार भी प्राप्त नहीं हुआ था, अतः शासन पर इनका कोई प्रभाव नहीं था। उनमें असन्तोष फैलने लगा। लोग कहने लगे—चार्ल्स दशम के स्वेच्छाचारी शासन का स्थान फ्रांस के अमीरों के स्वेच्छाचारी शासन ने ले लिया है। वास्तविक लोकतन्त्र का फ्रांस में सर्वथा अभाव है। परिणाम यह हुआ कि अनेक गुप्त समितियाँ सगठित की गईं, और मजदूर लोग अपनी हालत को अच्छा करने के लिये आन्दोलन करने लगे। काम करने के बड़े कम होने चाहिये, वेतन बढ़ने चाहिये, कारखानों की दशा को अधिक स्वास्थ्यप्रद बनाना चाहिये, कारखानों में काम करनेवाली स्त्रियाँ और बच्चों पर सख्ती नहीं की जानी चाहिये, तथा उनके लिये विशेष सुविधाएँ और नियम होने चाहिये—इस प्रकार की मांगें मजदूरों की तरफ से पैदा की जाने लगीं। मजदूर कहते थे—क्रान्ति में हमें क्या मिला है? चार्ल्स दशम के शासन का अन्त हुआ, तो हमें क्या लाभ पहुँचा। क्रान्ति हमने की, और उसका लाभ ले गये मध्य-श्रेणी के लोग। उन आवश्यकता इस बात की है, कि क्रान्ति को पूर्ण किया जाय। देश के शासन में जन-साधारण का हाथ हो, और मजदूरों और किसानों को भी वोट का अधिकार प्राप्त हो। इनका ही नहीं, उनकी दशा को उन्नत करने के लिये राज्य की तरफ से प्रयत्न भी किया जाय।

परन्तु फ्रांस की सरकार इस आन्दोलन को कुचलने के लिये तुली हुई थी। एमेल कान्टन पास किये गये, जिनसे मजदूर अपने को सगठित न कर सके। सगठन के बिना मजदूर अपनी उन्नति कदापि नहीं कर सकते थे, और फ्रांस की उस सरकार ने जिसका प्रादुर्भाव १८३० की राज्यक्रान्ति द्वारा हुआ था, इन्हीं सगठनों को गैर-कानूनी कर दिया था। मजदूरों ने अपनी दशा को सुधारने के लिये हड़ताल की। राज्य ने अपनी शक्ति का प्रयोग कर इन्हें तोड़ डाला। राज्य की इस नीति का परिणाम यह हुआ, कि मजदूर लोग विद्रोह के लिये तैयार हो गये। लियो के रेशम के कारखानों में काम करनेवाले मजदूर काले झण्डे लेकर निकल पड़े। विद्रोह हो गया। मजदूर लोगों की मांग थी, कि मनुष्य मात्र को वोट का अधिकार दिया जाय। इतना ही नहीं, राजनीतिक क्रान्ति के साथ-साथ वे सामाजिक क्रान्ति भी चाहते थे। उनकी मांग थी, कि आर्थिक उत्पत्ति के मुनाफे का हिस्सेदार मजदूरों को भी बनाया जाना चाहिये। वे केवल राजनीतिक अधिकारों से ही सन्तुष्ट नहीं थे। लुई व्ला आदि अनेक लेखक इस काल में आर्थिक विषमता की समस्या को लोगों के सम्मुख उपस्थित कर रहे थे। सम्भवतः, इतिहास में प्रथम बार जनता यह अनुभव करने लगी थी, कि राजनीतिक स्वतन्त्रता और समानता के साथ-साथ आर्थिक स्वतन्त्रता और समानता की भी समाज में शान्ति और सन्तोष के लिये आवश्यकता है।

इस आर्थिक असन्तोष के अतिरिक्त रिपब्लिक के पक्षपाती यह भी अनुभव करने लगे थे, कि १८३० की राज्यक्रान्ति वस्तुतः सफल नहीं हुई। लुई फिलिप को राजगद्दी पर बिठाना स्वीकृत कर हम ने भारी भूल की है। नये शासन में सर्वसाधारण जनता



की क्या दशा थी ? अधिकांश लोगों को वोट तक का अधिकार प्राप्त नहीं था । मजदूरों की शिकायतों का कोई अन्त नहीं था । क्या इस शासन को स्वराज्य व लोकतन्त्र कहा जा सकता था ? कभी नहीं । रिपब्लिकन लोग कहते थे—सर्वसाधारण जनता को शिक्षित करना चाहिये । अमीर गरीब का भेद न करके सब लोगों को समान रूप से राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिये । इस मनोवृत्ति का परिणाम यह हुआ, कि अनेक सभाएं संगठित की गईं, और बहुतसी गुप्त समितियां बनाई गईं । अखबारों में आन्दोलन होने लगा, नवीन शासन का मजाक किया जाने लगा । तानों और कार्टूनों से लुई फिलिप और उसके मन्त्रियों की मजाक उड़ाई जाने लगी ।

लुई फिलिप को चाहिये था, कि असन्तोष के वास्तविक कारणों को समझकर इस आन्दोलन को शान्त करता । पर उसने शक्ति के प्रयोग का निश्चय किया । पुराने ढङ्ग के स्वेच्छाचारी राजाओं का अनुसरण कर उसने आन्दोलन को कुचलने की कोशिश की । उद्घोषणा की गई, कि सब सभाएं व संगठन अपनी नियमावलियों को सरकार के सम्मुख पेश करें, और सरकारी अनुमति के बिना कोई संगठन कायम न रह सके । लोगों को स्वतन्त्रता से सभाएं करने का जो अधिकार प्राप्त था, उसे छीन लिया गया । रिपब्लिकन नभाजों और गुप्त समितियों को भग कर दिया गया । रिपब्लिकन समाचार-पत्रों को बन्द कर दिया गया, और उनके सम्पादक कैद कर लिये गये । राज्य की आलोचनाकरना, सम्पत्ति के वैयक्तिक अधिकार का विरोध करना या राजसत्ता के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के शासन-विधान का पक्ष लेना अपराध बना दिये गये । जो लोग इन कानूनों को तोड़े, उन्हें दण्ड देने के लिये विशेष न्यायालयों की रचना की गई । लुई फिलिप ने उदार और रोबमत्ता के पक्षपाती होने का ढोंग छोड़कर पूर्णरूप से एकतन्त्र और स्वेच्छाचारी ढंग से शासन करना प्रारम्भ कर दिया ।

वस्तुतः, १८३० की राज्यक्रान्ति असफल हो गई थी । जनता की इच्छा और अनुमति ने जो फिलिप राजगद्दी पर बैठा था, वह भी जनता पर ही अत्याचार करने लगा । उसे कतल करने के लिये छ बार कोशिश की गई, पर वह बचता गया । आखिर १८४८ की राज्यक्रान्ति ने उसके स्वेच्छाचारी शासन का अन्त किया ।

१८३० की राज्यक्रान्ति नई प्रवृत्तियों की सामयिक रूप से विजय थी । बार बार असफल हो कर भी क्रान्ति की प्रवृत्तियां निरन्तर अधिक अधिक प्रबल होती जाती थीं । पर पुनः जमाने को एकदम पलट सकना उनकी शक्ति के बाहर था । यही कारण है, कि एक बार कुछ समय के लिये सफल होकर भी वे शीघ्र ही फिर परास्त कर दी गईं ।

## २ बेल्जियम की स्वतन्त्रता

क्रान्ति का प्रसार—फ्रांस की द्वितीय राज्यक्रान्ति केवल अपने देश तक ही सीमित नहीं रही । एक ऐतिहासिक ने लिखा है, कि जिस प्रकार तालाब में पत्थर फेंकने से उसकी चट्टानें एवं स्थान में प्रारम्भ होकर सम्पूर्ण तालाब को व्याप्त कर लेती हैं, इसी प्रकार जब फ्रांस में राज्यक्रान्ति होती थी, तो उसका प्रभाव सम्पूर्ण यूरोप में व्याप्त हो जाता था । फ्रांस ११ प्रथम राज्यक्रान्ति ने यूरोप के अधिकांश देशों में कुलीन श्रेणी के विशेषाधिकारों को

नाट कर दिया था। राष्ट्रीयता और लोकतन्त्र की आवाज यूरोप भर में गुंजा दी थी। १८३० की इस हमरी क्रान्ति का प्रभाव भी बहुत व्यापक हुआ। यूरोप भर में एक प्रकार की मनमनी सी फैल गई। सब देशों की जनता में जमाधारण रूप में साहस और उत्साह का संचार हो गया। वीएना की कांग्रेस ने जिस प्रकार अस्वाभाविक रूप में यूरोप को पुनः मगठन किया था, उसके विरुद्ध सर्वत्र विद्रोह प्रारम्भ हो गये। नया जमाना पुराने जमाने को पलट देने के लिये एक भारी कोशिश करने को सन्नद्ध हो गया।

बेल्जियम में क्रान्ति—१८३० की क्रान्ति का प्रभाव सबसे पहले बेल्जियम में प्रगट हुआ। वीएना की कांग्रेस ने बेल्जियम को हालैंड के साथ मिला दिया था। भाषा, धर्म, नस्ल, हित आदि सब दृष्टियों में बेल्जियम के लोग उच्च लोगों से भिन्न थे। उच्च लोग प्रोटेस्टेन्ट धर्म को माननेवाले थे, बेल्जियन लोग रोमन कैथोलिक थे। उच्च लोगों की भाषा और नस्ल बेल्जियन लोगों से सर्वथा पृथक् थी। बहुमूल्य उच्च लोग किमान थे, इस वही उत्पन्न करना उनका मुख्य व्यवसाय था। उनका हित इस बात में था, कि मुक्तवाणिज्य की नीति का अनुसरण किया जाय। उनके विपरीत, बेल्जियम व्यवसाय-प्रधान देश था। पक्का माल तैयार करना वहां के लोगों का प्रधान पेशा था। बेल्जियम के विविध नगर खानों तथा वस्त्र-व्यवसाय के केन्द्र बन चुके थे। उनका मुख्य लाभ इसमें था, कि सुरक्षण की नीति का प्रयोग किया जाय। इसके अतिरिक्त, उच्च लोग फ्राम न घृणा करते थे, बेल्जियन लोग फ्राम के मित्र थे। बेल्जियम और हालैंड एक दूसरे में से सर्वथा भिन्न थे। राष्ट्रीयता और जनता की इच्छा की सर्वथा उपेक्षा कर वीएना की कांग्रेस द्वारा उन्हें एक साथ मिला दिया गया था। हालैंड का राजा विलियम प्रथम बेल्जियन लोगों पर अत्याचार करने में जरा भी मकोच नहीं करता था। उनकी राष्ट्रीय भावनाओं को कुचलने के लिये और उनके आर्थिक हितों को हानि पहुंचाने के लिये जो कुछ भी बन सका, उसने किया। व्यापारियों और व्यवसायियों पर भारी टैक्स लगाये गये। शासन के लिये बेल्जियम में भी उच्च आफिसर नियत किये गये, और उच्च कानून बहा जारी किये गये। प्रेस की स्वाधीनता नष्ट की गई। स्कूलों का निरीक्षण करने के लिये प्रोटेस्टेन्ट निरीक्षक रखे गये, यद्यपि बेल्जियम के विद्यार्थी और शिक्षक सभी रोमन कैथोलिक थे। हालैंड और बेल्जियम की पार्लियामेंट एक थी। यद्यपि बेल्जियम की आवादी हालैंड की अपेक्षा दुगने के लगभग थी, पर पार्लियामेंट में इन दोनों के प्रतिनिधियों की संख्या एक बराबर थी। मन्त्रिमण्डल में बेल्जियम के लोग बहुत कम होते थे। १८३० में इस राज्य के मन्त्रिमण्डल के सदस्यों की संख्या सात थी। उनमें से केवल एक मन्त्री बेल्जियम का था। इन बातों का यह परिणाम था कि बेल्जियन लोग अनुभव करते थे, कि उनके साथ अधीनस्थ देश का सा व्यवहार किया जा रहा है, और उच्च लोग अपने लाभ के लिये उनके हितों का विधात कर रहे हैं। उनमें स्वतन्त्रता की भावनाएँ निरन्तर प्रबल होती जाती थी। बेल्जियन लोगों में अपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता को प्राप्त करने के लिये आन्दोलन प्रचण्ड होता जाता था।

सफलता—१८३० में जब फ्रांस में राज्यक्रान्ति हुई, तब बेल्जियन लोगों में भी अपनी आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिये उत्साह का संचार हुआ। १८ नवम्बर के दिन बेल्जि-

यम मे विद्रोह हो गया। राष्ट्रीय स्वतन्त्रता उद्घोषित कर दी गई। नवीन शासन-विधान का निर्माण किया गया, और लियोपोल्ड प्रथम के नाम से एक जर्मन राजकुमार को राजगद्दी पर बिठाकर वैध राजसत्ता की स्थापना कर दी गई। चार अक्टूबर को बेल्जियम की स्वतन्त्र सरकार ने उद्घोषणा की, कि “बेल्जियम का प्रदेश शक्ति के प्रयोग से हालैंड से पृथक् कर लिया गया है, और अब उसे पृथक् स्वतन्त्र राज्य के रूप में परिवर्तित किया जाता है।” जुलाई १८३१ में लियोपोल्ड का राज्याभिषेक बड़ी धूमधाम के साथ बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में किया गया। इस प्रकार बेल्जियम हालैंड की अधीनता से मुक्त हुआ। अन्य यूरोपियन राज्यों ने उसकी स्वतन्त्रता को स्वीकृत कर लिया। इसके कुछ समय बाद १८३९ में ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, आस्ट्रिया, रूस और प्रशिया ने बेल्जियम की स्वाधीनता को स्वीकार करने के साथ साथ यह भी स्वीकृत किया, कि हम सब उसे उदासीन राज्य समझेगे। १९१४ तक बेल्जियम की यह उदासीनता कायम रही। किसी राज्य ने इसे नष्ट करने का प्रयत्न नहीं किया। पर १९१४ के यूरोपीय महायुद्ध के प्रारम्भ में जर्मनी ने १८३९ के समझौते को ‘कागज का टुकड़ा’ कहकर बेल्जियम पर आक्रमण किया, और इस अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि की उपेक्षा की। १८३० से १९१४ तक बेल्जियम पूर्ण रूप से स्वाधीन रहा और ‘उदासीन राज्य’ होने के कारण यूरोप के युद्धों से बचा रहा।

**बेल्जियम की उदासीनता—**१८३९ में ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, आस्ट्रिया, रूस और प्रशिया ने बेल्जियम को एक उदासीन राज्य के रूप में स्वीकृत किया था। यह बात उन्नीसवीं सदी के यूरोपियन इतिहास में बहुत महत्त्व रखती है। अतः इस सम्बन्ध में अधिक प्रकाश डालने की आवश्यकता है। नवम्बर, १८३० में जब बेल्जियम ने हालैंड के विरुद्ध विद्रोह कर अपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की घोषणा की, तो बेल्जियम के नेताओं का विचार यह था, कि फ्रांस के साथ उनके देश का सम्बन्ध बहुत घनिष्ठ हो। इसीलिये वे फ्रांस के राजवंश के एक राजकुमार को बेल्जियम की राजगद्दी पर बिठाना चाहते थे। भाषा, धर्म, और जाति की दृष्टियों से बेल्जियम और फ्रांस एक दूसरे से बहुत समीप थे। अतः यह विचार अस्वाभाविक नहीं था। पर ग्रेट ब्रिटेन नहीं चाहता था, कि फ्रांस का बेल्जियम पर किसी भी प्रकार का प्रभाव कायम हो। इससे फ्रांस की शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाती। इस समय ब्रिटेन का परराष्ट्र सचिव पामस्टन था। वह यह तो चाहता था, कि बेल्जियम की राष्ट्रीय आकांक्षा पूर्ण हो, और वह एक स्वतन्त्र राज्य के रूप में परिवर्तित हो जाय। पर उसका फ्रांस के प्रभाव में आना उसे असह्य था। ब्रिटेन के हस्तक्षेप का ही यह परिणाम हुआ, कि बेल्जियम की राजगद्दी लियोपोल्ड प्रथम (जो कि एक जर्मन राजकुमार था) को दी गई। आस्ट्रिया, रूस और प्रशिया तो इस बात के लिये भी तैयार नहीं थे, कि बेल्जियम की स्वाधीनता को स्वीकार करें। वीएना की कांग्रेस द्वारा जिन विद्वानों व अन्तर्गत यूरोप का पुनः निर्माण किया गया था, बेल्जियम की स्वतन्त्रता उनके विन्द्व होती। वे तो यह चाहते थे, कि बेल्जियम के मामले में हस्तक्षेप किया जाय, और उनका विन्द्व हालैंड के राजवंश की सहायता की जाय। पर इसी बीच में क्रान्ति की लहर पोर्टेण्ड को भी प्रेरित कर रही थी। रूस, आस्ट्रिया और प्रशिया भी इस ही पोर्टेण्ड के मामले में उत्पन्न हो गए, जो बेल्जियम पर विशेष ध्यान नहीं दे सके। इस स्थिति में बेल्जियम के मामले का

निर्णय फ्रांस और ब्रिटेन के हाथ में आ गया। फ्रांस बेल्जियम पर अपना प्रभाव न बढ़ा सके, इसी उद्देश्य से पारमस्टन ने उसे एक उदासीन राज्य के रूप में परिवर्तित करने का प्रस्ताव उठाया। फ्रांस इस के पक्ष में नहीं था। वह बेल्जियम में अपना घनिष्ठ सम्बन्ध समझता था। बेल्जियम के लोग भी यही अनुभूति रखते थे। पर १८३१ तक पोलैण्ड का विद्रोह समाप्त हो चुका था, और रूस, प्रशिया व आस्ट्रिया को बेल्जियम के मामले में हस्तक्षेप करने की फुरसत मिल गई थी। उन पर फ्रांस का नया राजा लुई फिलिप शान्ति लिये उत्सुक था। अतः वह बेल्जियम को एक उदासीन राज्य के रूप में स्वीकृत करने और उसकी पूर्ण स्वतन्त्रता को कायम रखने के लिये सहमत हो गया। इसी कारण, १८३९ में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, प्रशिया, आस्ट्रिया और हॉलैण्ड ने बेल्जियम की उदासीनता को स्वीकार किया था।

### ३ पोलैण्ड का अगभग और १८३० की क्रान्ति का उस पर प्रभाव

**पोलैण्ड**—रूस, प्रशिया और आस्ट्रिया ने पोलैण्ड के विविध प्रदेशों का क्रिम प्रकार अपने अधीन कर लिया था, इसका मक्षेप के साथ उल्लेख पहले किया जा चुका है। १८३० में पोलैण्ड नाम के किसी राज्य की यूरोप में मत्ता नहीं थी। पोल जाति के सब लोग इन तीन शक्तिशाली पड़ोसी राज्यों के अधीन थे। परन्तु पोल लोगों में राष्ट्रीय भावनाओं का अभाव नहीं था। वे लोग अपनी एकता और राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिये आन्दोलन कर रहे थे। १८३० में जब फ्रांस और बेल्जियम में राज्यक्रान्तियां हुईं, तो उनका प्रभाव पोलैण्ड पर भी पड़ा।

इस प्रकरण में पोलैण्ड के घटवारे के सम्बन्ध में कुछ अधिक विस्तार के साथ उल्लेख करना उपयोगी होगा, क्योंकि पोलैण्ड की समस्या को भलीभांति समझ लेना यूरोप के आधुनिक इतिहास के परिज्ञान के लिये बहुत आवश्यक है।

**मध्यकाल में पोलैण्ड की दशा**—मध्यकाल में पोलैण्ड यूरोप के प्रमुख शक्तिशाली व विशाल राज्यों में गिना जाता था। क्षेत्रफल की दृष्टि से वह रूस के बाद यूरोप का सबसे बड़ा राज्य था। पश्चिमी प्रशिया और लिथुएनिया के प्रदेश उसके अन्तर्गत थे। पोल लोगों के अतिरिक्त जर्मन और रूसी लोग भी उसमें बड़ी अच्छी संख्या में निवास करते थे। पोल लोग रोमन कैथोलिक धर्म के अनुयायी थे, जर्मन लोग प्रोटेस्टेण्ट धर्म का और रूसी लोग ग्रीक चर्च का अनुसरण करते थे। नस्ल, धर्म, भाषा और जाति की भिन्नता के कारण पोलैण्ड में राष्ट्रीय दृष्टि से एकता का अभाव था। मध्यकाल में यूरोप के अन्य राज्यों में जिस प्रकार सामन्त-पद्धति के कारण केन्द्रीय शासन निर्बल व अव्यवस्थित रहता था, वही दशा पोलैण्ड में भी थी। ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, प्रशिया, रूस आदि में सतरहवीं और अठारहवीं सदियों में जिस प्रकार सामन्त-पद्धति का ह्रास होकर शक्तिशाली केन्द्रीय शासन की स्थापना हुई, वैसे पोलैण्ड में नहीं हुई। अठारहवीं सदी के मध्यभाग में भी पोलैण्ड में सामन्त-पद्धति का जोर था। वहां सामन्तों और जागीरदारों की संख्या लाखों में थी। इनमें से बहुसंख्यक जागीरदार गरीब व छोटे-छोटे थे। पर उन्हें कुलीन श्रेणी के सब अधिकार

प्राप्त थे, और वे अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग निःसंकोच रूप से किया करते थे। पोलैण्ड का शासन एक राजसभा के अधीन था, जिसके सदस्य इन कुलीन सामन्तों व जागीरदारों द्वारा निर्वाचित किये जाते थे। राजसभा के प्रत्येक निर्णय के लिये यह आवश्यक था, कि वह सर्वसम्मति से किया जाय। यदि एक सदस्य भी किसी नीति, कानून व प्रस्ताव के विरोध में हो, तो वह उसे वीटो कर सकता था। इस दशा में पोलैण्ड की सरकार किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय पर पहुँच सकने में असमर्थ रहती थी। पोलैण्ड में कोई ईश्वरक्रमानुगत राजा नहीं होता था। राजा की मृत्यु होने पर जब कभी राजसिंहासन खाली हो जाता था, तो कुलीन सामन्त व जागीरदार राजसभा में एकत्रित हो नये राजा का निर्वाचन करते थे। ये निर्वाचन क्रान्ति के साथ नहीं हो सकते थे। पड़ोस के अन्य यूरोपियन राज्य राजा के निर्वाचन में दिलचस्पी रखते थे, और वे अपने उम्मीदवारों को पोलैण्ड का राजा बनाने के लिये शक्ति, रिश्तों व अन्य सब प्रकार के उचित अनुचित उपायों का अनुसरण करने में जरा भी संकोच नहीं करते थे।

इस दशा में यदि पोलैण्ड अपनी राजनीतिक स्वतन्त्रता को कायम रखने में असमर्थ हो, तो यह सर्वथा स्वाभाविक था। पोलैण्ड की सीमाएँ रूस, आस्ट्रिया और प्रशिया के साथ लगती थीं। ये तीनों राज्य अठारहवीं सदी में अच्छे शक्तिशाली व सुसंगठित थे। ये न केवल पोलैण्ड में राजा के चुनाव के अवसर पर उसके आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करते थे, अपितु विविध सामन्तों व जागीरदारों को अपने साथ मिलाकर उन पर अपना प्रभाव कायम करने में भी प्रयत्नशील रहते थे। १७६३ में पोलैण्ड के राजा आगस्टम तृतीय की मृत्यु हो गई। नया राजा कौन हो, इसके लिये इन की साम्राज्ञी कैथरिइन तृतीय ने एक उम्मीदवार का समर्थन किया। प्रशिया के राजा ने भी इस सम्बन्ध में रूस का साथ दिया और इन दोनों शक्तिशाली राज्यों के समर्थन में स्टेनिस्लास द्वितीय पोलैण्ड के राजसिंहासन पर आरुढ़ हो गया।

**पोलैण्ड का प्रथम अगभग**—पर स्टेनिस्लास द्वितीय एक योग्य व्यक्ति था। उसने अनुभव किया, कि जब तक पोलैण्ड की शासन-व्यवस्था में सुधार नहीं किया जायगा, राज्य-कार्य सुचारु रूप से नहीं चल सकेगा। अतः उसने प्रस्ताव किया, कि राजसभा के निर्णयों के लिये सर्वसम्मति का जो नियम है, किसी भी सदस्य को वीटो का जो अधिकार है, उसे रद्द किया जाय। पोलैण्ड के लोग शायद इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेने, पर रूस और प्रशिया ने इसका विरोध किया। उनका कहना था, कि पोलैण्ड में जो व्यवस्था मरिचों में चली जा रही है, और जिसके कारण पोलैण्ड व कुलीन लोगों की स्वतन्त्रता अब तक सुरक्षित रही है, उसे इस ढंग में नष्ट नहीं करना चाहिये। रूस और प्रशिया के उद्देश्य तो पोलैण्ड के अनेक जागीरदार और सामन्त स्टेनिस्लास द्वितीय का विरोध करने के लिये उठ खड़े हुए, और वहाँ गृहकलह का प्रारम्भ हो गया। रूस की सेनाओं ने इन गृहकलह में भी स्वच्छन्दतापूर्वक भाग लिया।

रूस, आस्ट्रिया और प्रशिया ने इस स्थिति में लाभ उठाना और उन्हाते जापान में मित्रों यह निर्णय किया, कि पोलैण्ड का अगभग कर उसके सुविन्तुत प्रदेशों में से तीन प्रदेशों को अलग कर उन्हें अपने अधीन कर लिया जाय। पश्चिमी प्रशिया का प्रदेश प्रसिया का

मिला, उत्तरी पोलैण्ड का एक अच्छा बड़ा प्रदेश (लियुएनिया का पूर्वी भाग) रूस ने प्राप्त किया, और गेलेशिया का प्रदेश आस्ट्रिया को दे दिया गया। इन तीन शक्तिशाली राज्या के सम्मुख पोलैण्ड सर्वथा असहाय था। रूसी सेनाएँ वारसा तक पहुँच गई थी। इस स्थिति में पोलैण्ड की राजसभा के सम्मुख उनके अनिश्चित अन्य कोई मार्ग न था, कि वे अपने देश के अग-भग को स्वीकृत कर ले। उस प्रथम अग-भग (१७३२) द्वारा पोलैण्ड का चौथाई प्रदेश उसकी अधीनता में मस्त हो गया।

**पोलैण्ड का दूसरा अग-भग**—१७७२ के अग-भग द्वारा पोलैण्ड के लोगों के आत्म-सम्मान को बहुत धक्का लगा। उन्होंने अनुभव किया, कि उन्हें अपने घर को मजालने के लिये कटिबद्ध होने की आवश्यकता है। इसीलिये स्टेनिस्लास द्वितीय के नेतृत्व में उन्होंने अपने शासन में अनेक सुधार किये। १७९१ में उन्होंने एक नये शासन-विधान को स्वीकृत किया, जिसके अनुसार राजा को निर्वाचित करने की प्रथा का जन्म कर राजा के पद को वंशक्रमानुगत बना दिया गया, और डन्डलैण्ड के ढग पर पार्लियामेंट की स्थापना की गई। इस युग में फ्रांस में प्रथम राज्यक्रान्ति हो रही थी, और मारा यूरोप क्रान्तिकारी व प्रगतिशील भावनाओं से परिपूर्ण हो रहा था। पोलैण्ड के लोगों ने प्रयत्न किया, कि वे भी समय के अनुसार अपने को परिवर्तित कर और अपने देश में अव्यवस्थित और निर्बल राजसत्ता व सामन्त पद्धति को दूर कर एक व्यवस्थित केन्द्रीय राजसत्ता (जो पार्लियामेंट के अधीन होकर शासन करे) की स्थापना करे। इसीलिये उन्होंने यह भी स्वीकृत किया, कि सामन्तों व जागीरदारों को जो वीटो का अधिकार है, उसे नाट कर दिया जाय।

पर पोलैण्ड के जागीरदार इन सुधारों में सन्तुष्ट नहीं थे। वे अपने परम्परागत अधिकारों को इस ढग से छिनता देखकर बहुत उद्विग्न हुए। उन्होंने सहायता के लिये रूस की साम्राज्ञी कैथेराइन से अपील की। रूस तो ऐसी स्थिति से लाभ उठाने के लिये मदा उद्यत रहता ही था। रूसी सेनाएँ पोलैण्ड में प्रविष्ट हो गईं। पोलैण्ड में जो लोग सुधार के पक्षपाती थे, उन्हें 'क्रान्तिकारी' कहकर वदनाम किया गया। प्रशिया भी इस दशा में चुप नहीं रह सकता था। उसने भी अपनी सेनाएँ पोल 'क्रान्ति' को कुचलने के लिये भेज दी। रूस और प्रशिया की शक्तिशाली सेनाओं के सम्मुख पोलैण्ड असहाय था। एक बार फिर (१७९३) पोलैण्ड का अग-भग किया गया। पोलैण्ड के सब पूर्वी प्रदेश रूस ने ले लिये, और उसके उत्तर पश्चिमी प्रदेशों पर (जिनमें डान्ट्सिग का महत्त्वपूर्ण बन्दरगाह भी सम्मिलित था) प्रशिया ने अपना अधिकार कर लिया।

**पोलैण्ड का तीसरा अग-भग**—पर पोल जनता में अपनी स्वतन्त्रता की भावना अभी नष्ट नहीं हुई थी। यद्यपि पार्लियामेंट ने विवश होकर रूस और प्रशिया के सम्मुख सिर झुका दिया था, पर इस समय पोल लोगों में एक देशभक्त नेता का प्रादुर्भाव हुआ, जिसने अपनी मातृभूमि के गौरव की रक्षा के लिये विद्रोह का झण्डा खड़ा किया। इस नेता का नाम कोस्किउस्को था। १७७६ में यह वाशिंगटन के नेतृत्व में अमेरिकन स्वाधीनता के लिये युद्ध कर चुका था, और देशप्रेम तथा राष्ट्रीयता की भावनाएँ इसमें कूट-कूट कर भरी हुई थी। उसके सुयोग्य नेतृत्व में पोल विद्रोह (१७९४) ने अच्छी सफलता प्राप्त की। पर रूस की साम्राज्ञी कैथेराइन इस विद्रोह को कुचलने के लिये तैयार थी। रूसी सेनाएँ पोलैण्ड

मे सर्वत्र छा गई, वारसा पर उनका अधिकार हो गया। इसी अवसर पर आस्ट्रिया भी पोलैण्ड के स्वातन्त्र्य-गृद्ध को कुचलने के लिये अग्रसर हुआ। रूस, आस्ट्रिया और प्रशिया की सम्मिलित शक्ति के सम्मुख पोल देशभक्त सर्वथा असहाय थे। पोलैण्ड के राजा को अपनी राजगद्दी को छोड़ने के लिये विवश होना पड़ा, और १७९३ के अग-भग के बाद जो कतिपय प्रदेश पोलैण्ड के स्वतन्त्र राज्य के रूप में विद्यमान थे, उन्हें भी इन तीन पड़ोसी राज्यों ने आपस में बांट लिया। इस तीसरे वटवारे (१७९५) में पश्चिमी गैलेसिया और दक्षिणी मैसोविया के प्रदेश आस्ट्रिया ने प्राप्त किये, पश्चिमी मैसोविया प्रशिया को मिला, और जेप सब प्रदेश रूस ने अपने अधिकार में कर लिये।

१८३० की राज्यक्रान्ति का प्रभाव—१७९५ के बाद पोलैण्ड नाम का कोई राज्य यूरोप में नहीं रहा था। वीएना की कांग्रेस में पोल लोगो की राष्ट्रीय आकांक्षाओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया था, और पोल लोग तीन भागों में विभक्त होकर तीन विदेशी राज्यों के अधीन थे। इस दशा में जब १८३० में क्रान्ति की लहर एक बार फिर यूरोप में प्रवल हुई, तो पोलैण्ड भी उसके प्रभाव से नहीं बच सका। पोलैण्ड का मुख्य भाग रूस के अधीन था। वहाँ के लोग विद्रोह के लिये तैयार हो गये। रूसी अफसरों को कत्ल कर दिया गया, या बाहर निकाल दिया गया। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के लोग पोल राष्ट्रीय भावनाओं के साथ सहानुभूति रखते थे। परन्तु उनको यह साहस नहीं हुआ, कि रूस के विरोध में पोल लोगो की सहायता कर सकें। साल भर तक रूस और पोलैण्ड में लड़ाई जारी रही। पोल लोगो के लिये रूस का मुकाबला कर सकना सुगम कार्य नहीं था। आखिर, वे परास्त हो गए। हजारों पोल देशभक्तों को प्राणदण्ड दिया गया, हजारों को देश निकाला देकर साइबेरिया भेज दिया गया। पोल विद्रोह को बुरी तरह कुचला गया। बहुत से लोगो ने भाग कर पश्चिमी यूरोप व अमेरिका में शरण ली। वहाँ वे अपने देश की स्वतन्त्रता के लिये प्रयत्न करते रहे। पर बीसवीं सदी के प्रथम यूरोपीय महायुद्ध (१९१४-१८) में पूर्व उन की आकांक्षा पूर्ण न हो सकी।

## ४ अन्य राज्यों पर राज्यक्रान्ति का प्रभाव

जर्मनी—जर्मनी के विविध राज्य भी १८३० की क्रान्ति की लहरों में जड़ते नहीं बच सके। स्वतन्त्रता और राष्ट्रीय एकता के भाव सम्पूर्ण जर्मनी में प्रवल हो उठे। लोग इस बात के लिये जानुर हो गये, कि जर्मनी को भी राष्ट्रीय दृष्टि से संगठित करना चाहिये और विविध जर्मन राज्यों का अन्त कर एक शक्तिशाली जर्मन राष्ट्र का निर्माण होना चाहिये। विविध जर्मन राज्यों में प्रशिया और आस्ट्रिया का शासन इतना शक्तिशाली और मजबूत था, कि वहाँ की जनता विद्रोह के लिये हिम्मत नहीं कर सकी। परन्तु जर्मनी के छोटे-छोटे राज्यों में अनेक स्थानों पर विद्रोह हुआ। ब्रुन्स्विक् की जनता ने अपने राजा चार्ल्स फ्रीड्रिख को राज्यच्युत कर नवीन शासन-विधान का निर्माण किया, और वैय राजतन्त्र की स्थापना की। सैक्सनी में विद्रोह हुआ, और राजा को बाधित किया गया, कि जनता द्वारा निर्मित शासन-विधान और सुधारों को स्वीकृत करे। हैनोवर में भी नवीन शासन की स्थापना की गई। हप्सबर्ग का वह राजा, जो लोगो को कोटे मारा करता था और विमन

रोटी के व्यवसाय को अपने अधिकार में किया हुआ था, उप वात के लिये वापिस किया गया, कि अपने राज्य में शासन-विधान की स्थापना करे। हेम्बेख नामक स्थान पर तीन हजार लोग इकट्ठे हुए। स्वतन्त्रता के गीत गाये जाने लगे। लोग कहने लगे—‘जर्मनी क संयुक्त राज्य’ का संगठन होना चाहिए, यूरोप में सर्वत्र रिपब्लिक की स्थापना की जानी चाहिये। एक वक्ता यहां तक जागे बढ़ गया, कि उसने कहा—‘ईश्वर की कृपा पर आश्रित सर्वोत्तम राज्य भी मानव जाति का दुश्मन होता है।’ फ्रांकोर्ट में विचारविधियों की सभा को भंग करने के लिये पुलिस को गोली चलानी पड़ी। विश्वविद्यालयों में विचारविधियों की सभाएं कायम हो गईं। सब जगह राष्ट्रीय गीत गाये जाने लगे। मानुभूमि की एकता और स्वतन्त्रता के लिये सम्पूर्ण जर्मनी में आन्दोलन प्रारम्भ हो गया। परन्तु यह ध्यान में रखना चाहिए, कि यह आन्दोलन संगठित नहीं था। मारे जर्मनी में स्वतन्त्रता और एकता के लिये भावना तो उत्पन्न हो गई थी, परन्तु विविध लोगों की आकांक्षाओं का एक सूत्र में संगठन नहीं हुआ था। यही कारण है, कि १८३० की क्रांति की लहर जर्मनी में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं ला सकी। मैटरनिख ने इस आन्दोलन को कुचरने का पूरा-पूरा प्रयत्न किया। वह क्षण भर के लिये भी यह नहीं सह सकता था, कि उनके अपने लोगों में—जर्मन लोगों में नई भावना का संचार हो जाय। उन समय में जर्मनिया जर्मनी से गृथक् नहीं था। मैटरनिख की पूरी शक्ति स्वतन्त्रता और एकता की प्रवृत्तियों को नष्ट करने में लगी हुई थी। जर्मन राज्य-सब की राजसभा में नवीन प्रवृत्तियों के विरुद्ध कानून पेश किये गये। उनको स्वीकृत कराने में मैटरनिख को विशेष तकलीफ नहीं हुई। नये कानूनों का परिणाम यह हुआ, कि सर्वत्र देशभक्तों और सुधार के पक्षपातियों पर भयंकर अत्याचार किये गये। अनेक देशभक्त नेता गिरफ्तार कर लिये गये। बहुतों को देश निकाला दिया गया। नवीन शासन-विधान नष्ट कर दिया गया। शासन-विधान के लिये अंग्रेजी में शब्द है—कान्स्टिट्यूशन। इसका एक और अर्थ होता है, वह है शरीर का संगठन। एक बार की बात है, कि आस्ट्रिया के राजा फ्रांसिस में किमी सरदार ने कहा—‘आपका कान्स्टिट्यूशन (शरीर का संगठन) बहुत उत्तम है।’ फ्रांसिस इस बात पर बहुत नाराज हुआ। उसने क्रोध में आकर कहा—“तुम क्या कहते हो? याद रखो, फिर कभी यह शब्द मेरे सम्मुख न बोलना। कहो, आपका शारीरिक स्वास्थ्य बहुत उत्तम है, या आपके शरीर की रचना बहुत अच्छी है, पर इस ‘कान्स्टिट्यूशन’ शब्द का प्रयोग कभी मत करो। मेरे यहां कोई कान्स्टिट्यूशन न अब है, और न भविष्य में कभी होगा। सैनान के सिवा अन्य किसी के पास कान्स्टिट्यूशन नहीं होता और न किसी को इसकी आवश्यकता ही है।” इसमें सन्देह नहीं कि उस समय के जर्मन शासकों में कान्स्टिट्यूशन के लिये इसी ढंग की घृणा विद्यमान थी। मैटरनिख कहता था, सब मुसीबतों की जड़ यह है, कि थोड़े से लोग खतरनाक प्रतिनिधिसत्तात्मक शासन के लिये आन्दोलन करते हैं। जर्मनी में मैटरनिख को पूर्ण सफलता हुई। सर्वत्र विद्रोह शान्त कर दिये गये। देश-भक्तों की आकांक्षाओं को कुचल दिया गया। पर यह नहीं समझना चाहिये, कि स्वतन्त्रता और राष्ट्रीय एकता के भाव सदा के लिये नष्ट हो गये। कुछ ही समय बाद जर्मनी एक संगठित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित हो गया, और उसमें लोकतन्त्र शासन स्थापित होने



मे भी बहुत देर नहीं लगी। यह सब किस प्रकार सम्पन्न हुआ, इस पर हम यथास्थान आगे चलकर प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे।

**इटली—**१८३० की क्रान्ति न इटली पर भी प्रभाव डाला। वीएना की कांग्रेस ने इटली को अनेक राज्यों में विभक्त कर दिया था। पर इटालियन देशभक्त अपने देश को एक सूत्र में सगठित करने तथा स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिये उत्सुक थे। १८३० की लहर ने उनमें नई आशा और उत्साह का संचार किया। इटली के लोगों को आशा थी, कि स्पेन और फ्रांस उसकी सहायता करेंगे। कुछ लोगों का खयाल था, कि नैपोलियन के लड़के को स्वतन्त्र इटली की राजगद्दी पर बिठा कर सम्पूर्ण देश को सगठित किया जा सकता है। इटली में गुप्त समितियों की कमी नहीं थी। लोगों में स्वतन्त्रता की भावना उत्पन्न हो चुकी थी। वे उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा में थे। १८३० में जब फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी और पोलैण्ड—सब जगह क्रान्ति की अग्नि बंधक रही थी, इटालियन लोगों ने भी विद्रोह का झण्डा खड़ा किया। मोडेना के लोगों ने अपने ड्यूक को बाहर निकाल दिया। परमा की गामिका नैपोलियन की रानी मेरिया लुइसा थी। परमा के लोगों ने उसे अपने पितृगृह आस्ट्रिया भाग जाने के लिये विवश किया। पोप के राज्य में भी विद्रोह हुआ। पो से लेकर टाइबर नदी तक सब जगह राष्ट्रीय तिरंगे झण्डे के नीचे लोग विद्रोह के लिये तैयार हो गये। इस विकट समय में इटली के विविध राजाओं को एक स्थान से ही सहायता की आशा थी, और वह था मँटरनिख। वह नदा 'ईश्वर के प्रतिनिधि' राजाओं की सहायता के लिये उद्यत रहता था। अपने उद्देश्य की पूर्ति के इस सुवर्णावसर को वह कब अपने हाथ में जाने दे सकता था। आस्ट्रियन सेनाएँ इटली भेज दी गईं। आस्ट्रिया की मधी हुई सेनाओं का मुकाबला करने की हिम्मत इटालियन देशभक्तों में नहीं थी। वे परास्त हो गये। पुराने राजाओं का पुनरुद्धार किया गया। १८३० की क्रान्ति की लहर में इटालियन लोगों ने जो कुछ भी प्राप्त किया था, उस सबको मटियामेट कर दिया गया। मँटरनिख ढग भर के लिये भी यह नहीं सह सकता था, कि आस्ट्रिया के पड़ोस में ही लोग 'स्वतन्त्रता' और 'राष्ट्रीयता' की बातें करें। उत्तरी इटली के अनेक प्रदेशों पर आस्ट्रिया का आधिपत्य भी था। इन 'भयंकर' प्रवृत्तियों के होते हुए यह प्रभाव व आधिपत्य किस प्रकार कायम रह सकता था ?

**स्पेन—**१८३० की क्रान्ति का प्रभाव स्पेन पर भी पड़ा। उदार विचार के लोग फिर जनता के अधिकारों को प्राप्त करने के लिये कोशिश करने लगे। परन्तु उन्हें सफलता नहीं हुई। फर्डिनेण्ड ने क्रूरता और अत्याचार का आश्रय लिया। क्रान्ति की भावनाओं में अपने देश को बचाने के लिये उसने सब प्रकार के उपायों का प्रयोग किया। परिणाम यह हुआ, कि कुछ समय के लिये क्रान्ति तथा सुधार की भावनाएँ दब गईं। १८३५ में ये भावनाएँ फिर बलवती हुईं। उस समय जनता को नवीन शासन-विधान की स्थापना में सफलता हुई, और स्पेन का शासन 'वैध राजसत्ता' के रूप में परिवर्तित हो गया।

**स्विट्जरलैण्ड—**स्विट्जरलैण्ड के विविध प्रान्तों (कैंटन) पर भी १८३० की क्रान्ति का असर हुआ। प्रायः सभी प्रान्तों में लोग अपने शासन-विधान में सुधार करने के लिये अग्रसर हुए। अब तक स्विट्जरलैण्ड के विविध प्रान्तों में जो शासन-विधान प्रचलित थे,

उनमें सर्वसाधारण जनता का बहुत कम हाथ था। सम्पूर्ण शक्ति कुछ कुलीन परिवार के पास थी। इनका शासन बहुत ही सकीर्ण, दोषपूर्ण तथा निन्दनीय था। १८३० में जनता ने कोशिश की, कि इस अवस्था में सुधार किया जाय। सब प्रान्तों में शासन-विधानों में सुधार किया गया। केवल प्रान्तीय शासन में ही नहीं, अपितु केन्द्रीय सरकार में भी सुधार के लिये आन्दोलन हुआ। स्थान-स्थान पर सभायें की गईं। आगिर, केन्द्रीय सरकार को भी जनताके सम्मुख झुकना पड़ा। उसमें भी अनेक परिवर्तन किये गये। यद्यपि १८३० की क्रांति की लहर ने स्विट्जरलैण्ड के शासन में अनेक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किये, परन्तु अभी वह पूर्ण रूप से लोकतन्त्र के सिद्धान्तों के अनुसार नहीं बन सका। इसके लिये अभी और अधिक आन्दोलन की आवश्यकता थी। १८४८ में जब फ्रांस में तीसरी राज्यक्रान्ति हुई और एक नई तथा अधिक प्रबल क्रांति की लहर का प्रारम्भ हुआ—उस समय म्विम लोग अपने उद्देश्य में सफल हुए, और स्विट्जरलैण्ड का शासन पूर्णतया लोकतन्त्र सिद्धान्तों पर आश्रित हो गया।

**ग्रेट ब्रिटेन**—ग्रेट ब्रिटेन भी क्रांति के प्रभावों में नहीं बच सका। १८३० में ग्रेट ब्रिटेन में टोरी (अनुदार) दल का प्रभुत्व था। इस कारण सर्व-साधारण जनता बहुत असन्तुष्ट थी। फ्रांस की राज्यक्रान्ति के समाचारों से उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा, और ब्रिटिश लोग भी अपने अधिकारों के लिये संघर्ष करने का प्रयत्न करने लगे। टोरी दल का प्रधान नेता विलिङ्गटन का ड्यूक, जो मैटरनिस्स का पक्का दोस्त था और उस समय में इङ्ग्लैण्ड का प्रधान मन्त्री था, जनता के अधिकारों से जरा भी सहानुभूति नहीं रखता था। उसने स्पष्ट उद्घोषित कर दिया, कि पार्लियामेंट के निर्वाचन के लिये वोट देने का अधिकार और अधिक विस्तृत नहीं किया जा सकता। उस समय इङ्ग्लैण्ड में वोट देने का अधिकार बहुत कम लोगों को प्राप्त था और निर्वाचनके ढग में भी बहुतसे दोष थे। जनता इनमें सुधार चाहती थी। पर टोरी पार्टी इससे सहमत नहीं थी। परिणाम यह हुआ, कि विलिङ्गटन के ड्यूक की निराशाजनक उद्घोषणा से लोग क्रुद्ध हो गये, और टोरी पार्टी बदनाम हो गई। पार्लियामेंट में ह्विग (लिवरल) पार्टी का प्राबल्य हो गया, और नये प्रधान मंत्री लार्ड जान रसल ने प्रथम सुधार बिल पेश किया। पर यह बिल पास नहीं हो सका। इस पर ह्विग प्रधानमन्त्री ने पार्लियामेंट को बर्खास्त कर नये चुनाव कराने का निश्चय किया। नवीन निर्वाचन में ह्विग दल की सख्या बहुत अधिक बढ़ गई। लोकसभा में द्वितीय सुधार बिल सुगमता से पास हो गया, परन्तु लार्ड सभा ने उसे अस्वीकृत कर दिया। जनता सुधार के साथ थी, पर लार्ड लोग उसे क्रिया में परिणत नहीं होने देते थे। जबतक कि दोनों सभायें प्रस्तावित सुधारों को पास न कर दें, तब तक वे स्वीकृत नहीं समझे जा सकते थे। परिणाम यह हुआ, कि जनता में आन्दोलन प्रारम्भ हो गया। बड़ी-बड़ी सभायें की गईं, जुलूस निकाले गये। कई स्थानों पर दंगे भी हो गये। लोग वैध उपायों से अपनी बात को मनवाने में असमर्थ रहे थे, अतः उन्होंने शक्ति प्रदर्शित करने का निश्चय किया। आखिर, सुधार के विरोधी लार्ड लोगों को जनता की इच्छा के सम्मुख सिर झुकाना पड़ा। १८३२ का सुधार-बिल दोनों सभाओं में पास हो गया। इस से जनता को बहुत बड़े परिमाण में अधिकार प्राप्त हुए, और ग्रेट ब्रिटेन का शासन बहुत अंश में 'लोकतन्त्र' हो गया। स्पेन्सर वालपूल

ने १८३२ के सुधारों को सबसे बड़ी क्रान्ति के नाम से पुकारा है। इन सुधारों के कारण ब्रिटेन में नई प्रवृत्तियाँ बहुत हद तक सफल हो गईं।

**अमेरिका—**१८३० की क्रान्ति की लहर केवल यूरोप तक ही सीमित नहीं रही। विशाल अटलान्टिक महासागर को पार कर अमेरिका में भी उसने अपना प्रभाव प्रदर्शित किया। अमेरिका में कुलीन श्रेणी का अभाव था। कोई ऐसे लोग नहीं थे, जिन्हें अपने जन्म की वजह से विशेषाधिकार प्राप्त हो। पर वहाँ की आर्थिक दशा ने ऐसे लोगों की एक श्रेणी उत्पन्न कर दी थी, जो बहुत ही अधिक धनी और समृद्धिशीली थे। अमेरिका की विस्तृत उपजाऊ जमीनों पर गुलामों के श्रम से खेती की जाती थी। इन जमीनों के मालिक गुलामों की कमाई को लूटकर असाधारण रूप से अमीर हो गये थे। इसके अतिरिक्त खानों तथा कल कारखानों के मालिक भी वहाँ बहुत समृद्ध थे। ये लोग स्वाभाविक रूप से सर्वसाधारण जनता के अधिकारों को पसन्द नहीं करते थे। १८३० की क्रान्ति की लहर ने सुधार के पक्षपातियों में नवीन उत्साह का संचार किया, और दामप्रथा के विरुद्ध आन्दोलन प्रचलित हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी प्रदेशों में एक हजार के लगभग दासप्रथा विरोधी सभाओं का संगठन किया गया। इन सभाओं की माग थी, कि दासप्रथा को एकदम नष्ट कर दिया जाय। इस आन्दोलन के अतिरिक्त गरीबों और मामूली लोगों की दशा में सुधार करने के लिये भी इस समय में बहुत प्रयत्न किया गया। कारखानों में काम करने वाले बच्चों और स्त्रियों के सम्बन्ध में विशेष कानून बनाये गये। वर्ज को अदा न कर सकने पर कैद में डाल देने के नियम को उड़ाया गया।

**मित्रमण्डल का श्रान्त—**हम पहले लिख चुके हैं, कि क्रान्ति की प्रवृत्तियों के खिलाफ जिस प्रतिक्रिया के काल का प्रारम्भ वीएना की कांग्रेस द्वारा हुआ था, वह देर तक स्थिर नहीं रह सका। शीघ्र ही नई प्रवृत्तियाँ प्रचलित हो गईं और पुराने जमाने को परास्त करने के लिये सघर्ष करने लगी। १८३० की क्रान्ति की लहर ने अनेक देशों में पुगनी भावनाओं को नष्ट कर दिया। अनेक देशों में इस नई लहर को असफलता भी हुई। परन्तु इसमें मन्देह नहीं, कि ममार जब धीरे-धीरे नई रोशनी से प्रकाशित होता जाता था। नई प्रवृत्तियों को चुनलने तथा पुराने जमाने को स्थिर रखने के लिये यूरोपियन राज्यों ने जिस 'मित्रमण्डल' का निर्माण किया था, १८३० की क्रान्ति की लहर से उसे भयकर धक्का लगा। ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस उसमें पूर्णतया पृथक् हो गये। मेटर्निख का प्रभाव कम हो गया। उसने रूस और प्रशिया के साथ मिलकर राजा के दैवी अधिकारों की रक्षा के लिये एक नवीन मंत्रालय निर्माण किया। पर ब्रिटेन और फ्रांस उसमें सम्मिलित नहीं हुए। १८३० की क्रान्ति ने ब्रिटेन में टोरी दल के प्रभुत्व को नष्ट कर दिया था। फ्रांस में तो जनता की इच्छा ने एक नवीन शासन का स्थापन हुआ ही था। इस दशा में यह कैसे सम्भव हो सकता था, कि ये दोनों राज्य मेटर्निख का साथ दे सकें। निस्सन्देह, १८३० की क्रान्ति की यह सन्ने भागी ब्रिजय थी। मेटर्निख तथा उसके साथी जिस प्रकार यूरोप को चलाना चाहते थे, १८३० की क्रान्ति ने मित्र कर दिया कि उसमें उन्हें कदापि सफलता नहीं हो सकती।

# तेरहवा अध्याय औद्योगिक क्रांति

## १ आर्थिक परिवर्तन

फ्रांस की राज्यक्रान्ति के साथ यूरोप में एक नवीन युग का प्रारम्भ हुआ था। उन्नीसवीं सदी में इस नवयुग का निरन्तर विकास होता रहा। पर राजनीतिक क्रान्तियों ने यूरोप के आधुनिक इतिहास में जितने परिवर्तन किये हैं, उममें कहीं अधिक परिवर्तन व्यावसायिक क्रान्ति द्वारा हुए हैं। सर्वसाधारण जनता के जीवन में परिवर्तन व उन्नति करनेवाली नौ शक्तियाँ उन्नीसवीं सदी में काम कर रही थी, उन्हें हम चार भागों में बांट सकते हैं—(१) व्यावसायिक क्रान्ति, (२) राष्ट्रीय भावना का प्रादुर्भाव, (३) वैद्य गणमनों का विकास, और (४) साम्यवाद की लहर।

इनमें से व्यावसायिक (औद्योगिक) क्रान्ति का महत्त्व बहुत अधिक है, क्योंकि उसके कारण सर्वसाधारण जनता के जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन हुआ है।

## २ कृषि की उन्नति

पिछली डेढ़ सदी में पाश्चात्य ससार की आर्थिक दशा में जो असाधारण उन्नति हुई है, उसका मुख्य श्रेय व्यावसायिक क्रान्ति को ही है। पर उसके लिये मैदान तैयार करने में व्यापारिक क्रान्ति और कृषि की उन्नति का बड़ा हाथ था। व्यापारिक क्रान्ति का उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। उसके द्वारा व्यावसायिक क्रान्ति के लिये किस प्रकार मैदान तैयार हुआ, इस विषय पर भी पहले प्रकाश डाला जा चुका है। यहाँ हम कृषि सम्बन्धी उन्नति पर संक्षेप में विचार करेंगे।

अब से कुछ समय पूर्व ससार के प्रायः सभी देश 'कृषि-प्रधान' थे। जनता का बड़ा भाग कृषि-कार्य से ही अपना निर्वाह करता था। व्यवसायों की अधिक उन्नति नहीं हुई थी। लोगों की आजीविका का मुख्य साधन खेती ही थी। आर्थिक उन्नति के क्षेत्र में जिस देश ने सम्पूर्ण ससार का नेतृत्व किया, वह इंग्लैण्ड है। उसी के उदाहरण को लीजिये। अठारहवीं सदी में इंग्लैण्ड भी एक कृषि-प्रधान देश ही था। वहाँ की जनता का बहुत बड़ा भाग देहातों में निवास करता था। गावों की भूमि दो प्रकार की होती थी, खेती के काम में आनेवाली और चरागाह के रूप में प्रयुक्त होनेवाली। किसानों के खेत एक स्थान पर नहीं होते थे। यदि एक खेत गाव के दक्षिण में था, तो दूसरा उत्तर में। खेत बहुत छोटे-छोटे तथा बिखरे हुए होते थे। एक खेत से दूसरे खेत को जाने में किसान का बहुत सा समय नष्ट हो जाता था। साथ ही बहुत सी जमीन रास्तों और पगडण्डियों में खराब

हुई रहती थी। आधुनिक समय के बड़े और इकट्ठे खेतों का उस समय तक इंग्लैण्ड में अभाव था। जमीन की पैदावार को कायम रखने के लिये आजकल के तरीकों का आविष्कार भी उस समय में नहीं हुआ था। हर तीसरे साल खेतों को खाली छोड़ना पड़ता था, ताकि उनकी उपज-शक्ति नष्ट होने से बची रहे। भिन्न-भिन्न किसम की फसलों को वारी-वारी से बोते रहने पर जमीनकी उपज-शक्ति को कायम रखा जा सकता है, इसका ज्ञान उस समय के अंग्रेज किसानों को नहीं था। खेती के लिये पुराने जमाने के वही औजार काम में आते थे। हल, फावड़ा और दराती से बढ़कर कोई अन्य औजार अठारहवीं सदी के इंग्लैण्ड के किसानों के पास नहीं था। खेती के लिये काम में आनेवाली जमीन के अतिरिक्त जो अन्य जमीन खाली पड़ी रहती थी, वह चरागाह के काम में आती थी, उसमें गाव भर के पशु स्वच्छन्द रूप से चर सकते थे। जलाने के लिये ईंधन भी इसी जमीन से एकत्रित किया जाता था। चरागाह को साफ रखने तथा पशुओं को बीमारी से बचाने का कोई प्रयत्न उस समय नहीं किया जाता था। परिणाम यह था, कि पशु बहुत कमजोर तथा दुबले पतले होते थे। इंग्लैण्ड की आबादी भी उस समय बहुत कम थी। अठारहवीं सदी के अन्त में इंग्लैण्ड के निवासियों की संख्या केवल ९० लाख के लगभग थी। शहरों का विकास तब बहुत कम हुआ था। शहर संख्या में थे ही बहुत कम, और जो थे भी, वे छोटे-छोटे और निहायत गन्दे होते थे। आवागमन के साधनों की उस समय बड़ी दुर्दशा थी। सड़क प्रायः कच्ची और टूटी फूटी थी। डाकुओं की बहुतायत के कारण इन पर आना जाना भी जासका और भय से शून्य नहीं था।

अठारहवीं सदी के अन्त में इस दशा में परिवर्तन आना प्रारम्भ हुआ। इंग्लैण्ड में कृषि-सम्बन्धी जो उन्नति हुई, उस पर हम दो दृष्टियों से विचार कर सकते हैं—(१) कृषि के तरीकों में सुधार, और (२) खेतों के स्वरूप में परिवर्तन।

कृषि के तरीकों में सुधार करने वाला पहला अंग्रेज वैज्ञानिक टल (१६७४-१७४१) नाम का महानुभाव था। इसने अनेक ऐसे आविष्कार किये, जिनमें कृषि की पद्धति में बहुत उन्नति हुई। बार बार खेत को जोतकर यदि मिट्टी को बिल्कुल बारीक कर दिया जाय, तो पैदावार बहुत बढ़ाई जा सकती है, इस सिद्धान्त का पहले पहल इसी ने पता किया। साथ ही, बीज बोने के ऐसे क्रियात्मक उपायों का, जिनसे बीज गेह में समान रूप में बोये जा सकें, बड़ी कम या अधिक न पड़े, परिज्ञान भी पहले पहल इसी ने किया था। इसी-लिये श्री टल के विषय में कहा जाता था, कि जिस जमीन में कोई अन्य आदमी एक दाना पैदा कर सकता है, वहां वह दो दाने पैदा करके दिखा सकता था।

टल के प्रसिद्ध अनुयायी श्री टाउनशैंड (१६७४-१७३८) ने भी कृषि के तरीकों में अनेक महत्वपूर्ण सुधार किये। उसकी अपनी जागीर पहले बिल्कुल उजाड़ तथा दलदलों से परिपूर्ण थी। पर टाउनशैंड ने उस निकम्मी तथा ऊंर जमीन को लहलहाते बन के रूप में परिवर्तित कर दिखाया। वारी-वारी में भिन्न-भिन्न फसलों को बोकर जमीन की उपज-शक्ति को निरन्तर कायम रखा जा सकता है, इस उमूल का परिज्ञान टाउनशैंड ने ही कराया। अनेकविध खादों के उपयोग से जमीन की उपज को बढ़ाने के महत्त्वपूर्ण भी उसी समय में किये गये। साथ ही पशुओं की तरक्की पर भी ध्यान दिया गया। गायें

वेकवल (१७२५-१७६५) ने पशुओं की नमल को उन्नत करने के लिये अनेक परीक्षण किये। उस समय तक इंग्लैण्ड के पशु बहुत ही पतले दुबले व कमजोर होते थे। उनके शरीर पर हड्डियाँ नजर आती थीं। पर वेकवल के प्रयत्न से इस दशा में सुधार शुरू हुआ। पशुओं के मांस को भोज्य पदार्थ के रूप में प्रयुक्त करने की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। कृषि के उपकरणों में भी उन्नति की गई। बौलों में चलनेवाले लकड़ी के हल के स्थान पर घोड़ा से चलनेवाले लोहे के भारी हल का आविष्कार हुआ। अनाज को भूसे में अलग करने के लिये भी मशीनों का निर्माण किया गया। इस मशीन का आविष्कारक एण्ड्रू मार्कवेल नाम का एक संज्जन था। इस समय के अंग्रेज किसान कितने अन्व-विश्वामी तथा अप्रतिष्ठित-वादी थे, इसका अनुमान इस बात से किया जा सकता है, कि वे लोग लोहे के नये हल को इस्तेमाल करने से इसलिए घबराते थे, क्योंकि उनके विचार में इनमें जमीन में जड़ घुस जाता था। नये हल के समान ज्यादा अच्छी किमम की दरानियों व फावड़ों का भी इस समय आविष्कार हुआ। बीजों को चुनने की तरफ भी लोग का ध्यान गया। बीजों के लिये बढ़िया बीजों की आवश्यकता है, इस पर विशेष जोर दिया जाने लगा।

खेती के लिये इन नये आविष्कारों का प्रचार करने की भी कोशिश की गई। आयरलैंड के आन्दोलन से सन् १७९३ में ब्रिटिश सरकार ने कृषि का एक पृथक् भाग खोल दिया। इसका काम ही यह था, कि किसानों में खेती के नये तरीकों का प्रचार करे। इसके कुछ समय बाद सन् १८३६ में रायल एग्रिकल्चरल सोसायटी की स्थापना की गई।

कृषि सम्बन्धी ये सब सुधार तब तक विशेष लाभदायक नहीं हो सकते थे, जब तक कि खेतों के स्वरूप में परिवर्तन न हो। खेतों के छोटे-छोटे व बिखरे हुए होने के कारण किसी किसान के लिये यह सम्भव नहीं था, कि वह खेती के उन्नत माधनों का प्रयोग कर सके। साथ ही नये सुधारों के लिये पूँजी की भी जरूरत होती थी। खेती के उन्नत तरीके तभी काम में लाये जा सकते थे, जब कि खेतों को एकत्र कर एक बड़े फार्म का रूप दिया जावे। इन उद्देश्य से ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा बहुत से ऐसे कानून पास किये गये, जिनसे खेतों के विविध स्वामियों के दावों पर विचार करके उनकी जमीन को एक स्थान पर एकत्र करने की व्यवस्था की गई। सरकार की ओर से इस काम के लिये अनेक कमिश्नर नियत किये गये। वे सब जगह जाकर इस बात की जांच करते थे, कि किस खेत पर किस किसान का हक है, और उस किसान की सारी जमीन को किस प्रकार एक जगह इकट्ठा किया जा सकता है। सन् १७०० से १८३९ तक इंग्लैण्ड में खेतों को एकत्र करने के लिये जो विविध कानून हैं। पास हुए, उनकी संख्या ४००० से भी अधिक थी। यह काम कितना महत्वपूर्ण था, इसका अनुमान इसी एक बात से किया जा सकता है। पर खेतों के एकत्र किये जाने से बहुत से छोटे-छोटे किसान बेरोजगार हो गये, और वे आजीविका की खोज में शहरों की तरफ आकृष्ट हुए। शहरों में इस समय व्यावसायिक क्रान्ति प्रारम्भ हो चुकी थी, नये-नये उद्योग-वन्धों का विकास हो रहा था। ये किसान अब श्रमिक के रूप में शहरों में जाकर बस जाने के लिये प्रवृत्त हुए।

### ३ वैज्ञानिक आविष्कार

जिन वैज्ञानिक आविष्कारों ने यूरोप में व्यावसायिक क्रान्ति का सूत्रपात किया, उन्हें हम तीन भागों में बांट सकते हैं। (१) ऐसे नवीन यान्त्रिक आविष्कार जिनसे मानव श्रम की वृद्धि हो। (२) जल, कोयला, भाप और बिजली—ये सब यान्त्रिक शक्ति के काम आ सकते हैं, इस बात का पता लगाना। (३) रसायन-शास्त्र की नई प्रक्रियाओं का परिज्ञान। हम इन पर क्रमशः विचार करेंगे।

**यान्त्रिक आविष्कार**—नवीन यान्त्रिक आविष्कार किस प्रकार मानव श्रम में वृद्धि करने में सहायक हो रहे थे, इसका एक उत्तम उदाहरण वस्त्र-व्यवसाय है। कपड़ा बनाने के लिये पहले रूई को सूत के रूप में कातना होता है, और बाद में सूत को बुनकर कपड़ा तैयार किया जाता है। अठारहवीं सदी के मध्य तक यूरोप में सूत कातने के दो ही माधन थे, तकली और चरखा। पर इन दोनों उपकरणों से मनुष्य एक समय में एक ही सूत कात सकता था। सन् १७६७ में जेम्स हर्श्रीव नाम के एक अंग्रेज कारीगर ने एक ऐसे चरखे का आविष्कार किया, जिससे आठ व दस सूत एक साथ काते जा सकते थे। इसका अभिप्राय यह हुआ, कि इस नये चरखे से एक कारीगर आठ या दस कारीगरों का काम कर सकता था। एक साल बाद, सन् १७६८ में रिचर्ड आर्क राइट नामक अन्य अंग्रेज शिल्पी ने एक ऐसी मशीन का आविष्कार किया, जिसमें बेलनों द्वारा सूत काता जाता था, और ये बेलन यान्त्रिक शक्ति द्वारा चलते थे। धीरे-धीरे सूत कातने के उपकरणों में उन्नति होती गई, और अठारहवीं सदी की समाप्ति में पूर्व इंग्लैण्ड में ऐसी मशीनें काम करने लगीं, जिनमें एक साथ दो सौ सूत काते जाते थे। ये मशीनें यान्त्रिक शक्ति में चलती थीं, और इनका संचालन करने के लिये एक या दो से अधिक कारीगरों की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। जो काम पहले सौ कारीगर करते थे, वह अब एक कारीगर करने लगा। उसमें आर्थिक उत्पत्ति में मानव-श्रम की कितनी वृद्धि हुई, यह सहज में ही भलीभांति समझा जा सकता है।

सूत कातने के नये उपकरणों के साथ-साथ कपड़ा बुनने के उपकरणों में भी उन्नति होना आवश्यक था। नई मशीनों द्वारा सत भारी तादाद में तैयार होने लगा था। तुल्यता लाभ अपने पुराने तरीकों से सूत की इतनी भारी मात्रा को कपड़े के रूप में परिवर्तित करने में असमर्थ थे। आवश्यकता आविष्कार की जननी कही गई है। अब अनेक शिल्पियों ने कपड़ा बुनने की खट्टियों में भी सुधार शुरू किये। १७८४ में डा० कार्टराइट नाम के शिल्पी ने एक ऐसी खट्टी का आविष्कार किया, जो जल की शक्ति में चलती थी, और जिसमें ताना-बाना अपने आप बुना जाता था। इस नई खट्टी ने १५ वर्ष की आयु का एक बच्चा उन्ना कपड़ा तैयार कर लेता था, जितना कि पुरानी खट्टी में दस बुद्धिमान कारीगर कर पाते थे। धीरे-धीरे डा० कार्टराइट की खट्टी में सुधार होने लगे, और इन नई मशीनों का व्यापक प्रयोग किस प्रकार बढ़ती गई, इसका अनुमान इस बात से किया जा सकता है, कि सन् १८३३ में एक लाख के लगभग नये नई खट्टियाँ इंग्लैण्ड में प्रयुक्त हो रही थीं।

उन बानने और बुनने के इन नये उपकरणों के कारण इंग्लैण्ड में कपड़ा बुनने की

मात्रा में तैयार होने लगा। स्वीडन में पैदा नहीं होती थी। वस्त्र व्यवसाय के लिये डेनमार्क को स्वीडन में मँगानी पड़ती है। सन् १७६८ तक, डेनमार्क बाहर में जो लकड़ कपड़ा बनाने के लिये मगाता था, उसकी मात्रा पचास हजार मन में अधिक नहीं होती थी। धीरे-धीरे बाहर से आनेवाली स्वीडन की मात्रा बढ़ती गई, और सन् १८४१ में डेनमार्क में जो लकड़ बाहर से आई, उसकी मात्रा ६५ लाख मन हो गई। ७५ वर्ष के लगभग समय में डेनमार्क में लकड़ की खपत सौ गुना से भी अधिक बढ़ गई। यह सब यान्त्रिक उपकरणों का ही परिणाम था। सन् १८१५ में राबर्ट जावन नाम का वस्त्र व्यवसायी अभिमान के साथ यह कहा करता था, कि उसके अपने एक कारखाने में दो हजार कारीगर जितना कपड़ा तैयार करते हैं, पुराने तरीकों में सारे स्काटलैंड के सब जुलाहे मिलकर भी उतना कपड़ा तैयार नहीं कर सकते थे। राबर्ट जावन की यह गर्वाक्ति मन्थ पर आश्रित थी। पिछले चालीस वर्षों में जो नये यान्त्रिक आविष्कार हुए थे, उन्होंने मानव-श्रम में भारी बचत कर दी थी, और आर्थिक उत्पत्ति पहले की अपेक्षा बहुत अधिक बढ़ा दी थी।

मशीनों की उन्नति के लिये यह आवश्यक था, कि उन्हें बनाने के लिये जिमी ऐमी श्रम का प्रयोग किया जाय, जो मजबूत और चिरस्थायी हो। आजार बनाने के लिये बहुत पुराने जमाने से लोहे का उपयोग किया जाया करता था। पर लोहा बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता था, और लोहे को साफ करके उसे मजबूत बनाने के साधन भी बहुत ही अप्रत्याशित थे। अठारहवीं सदी में, जिस समय आकराइट और हर्ग्रीव जैसे शिल्पी चरखे और करों की उन्नति में लगे थे, उसी समय कतिपय अन्य शिल्पी लोहे की उन्नति के नये साधनों की खोज में जुटे हुए थे। लोहे को तैयार करने में पहले लकड़ी का कोयला प्रयुक्त होता था। सन् १५५० में पत्थर का कोयला प्रकाश में आया, और उसकी तेज गरमी से लोहे की कच्ची धातु का पिघलाने व साफ करने का काम बहुत सुगम हो गया। धीरे-धीरे नई किस्म की भट्टियाँ तैयार होने लगी और साफ व मजबूत लोहा भारी मात्रा में बनने लगा। मशीनों की उन्नति में इस लोहे ने बहुत सहायता पहुँचाई।

**नई यान्त्रिक शक्ति**—पर नई मशीनों के आविष्कार ही पर्याप्त नहीं थे। जब तक नई मशीनों को चलाने के लिये नई यान्त्रिक शक्ति का आविष्कार न हो, उनसे पूरा लाभ नहीं उठाया जा सकता था। वायु और जल—इन दो प्राकृतिक शक्तियों का मनुष्य को प्राचीन काल से परिज्ञान था। अपने श्रम के अतिरिक्त मनुष्य देर से इनका भी उपयोग करना जानता था। पवनचक्की और पनचक्की मध्यकाल में भी प्रयुक्त होती थी। पर इनका उपयोग और क्षेत्र बहुत सीमित थे। मनुष्य जहाँ चाहें वहाँ और जिस प्रकार से चाहें, इन शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकता था। अठारहवीं सदी में भाप की शक्ति का आविष्कार हुआ, और पत्थर के कोयले से उत्पन्न तीव्र अग्नि और जल के संयोग से जो भाप प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होती है, उसे काबू कर मनुष्य एक नई यान्त्रिक शक्ति को हस्तगत कर सकता है, यह ज्ञात हुआ। भाप की इस शक्ति को प्रयुक्त करनेवाले उपकरण को 'स्टीम इंजन' कहते हैं। इसका सबसे पहले आविष्कार न्यूकामन नाम के शिल्पी ने किया था। बाद में जैम्स वाट ने उसमें बहुत सुधार किया। वस्त्र व्यवसाय में सबसे पहले सन् १७८५ में स्टीम इंजन का प्रयोग किया गया। अठारहवीं सदी के अन्त तक इंग्लैंड में हजारों की संख्या



में स्टीम इंजन प्रयुक्त होने लगे—और व्यवसाय के क्षेत्र में उनका प्रचार बहुत अधिक बढ़ गया। मध्यकाल में मनुष्य सब श्रम अपने हाथ व पैर से करता था। बैल व घोड़े की जो शक्ति उसे उपलब्ध थी, वह भी जीवित शक्ति होने के कारण अपनी एक सीमा रखती थी। पर अब लोहे के बने इंजन के रूप में मनुष्य के हाथ में एक ऐसा दानव आ गया, जिससे वह ग़लाम के तौर पर काम ले सकता था, और जो चेतन शरीर के समान श्रान्ति और क्लान्ति का शिकार सुगमता से नहीं हो जाता था। स्टीम इंजन के आविष्कार से भारी और बड़ी मशीनों का संचालन सम्भव हुआ और उस के कारण आर्थिक उत्पत्ति में बहुत वृद्धि हुई।

स्टीम इंजन के आविष्कार से आवागमन के साधनों में भी बहुत उन्नति हुई। नदियों और समुद्र में नौकाएँ पहले भी चलती थी, पर वे चप्पुओ और पाल के द्वारा चलाई जाती थी। सन् १८०२ में नौकाओं में भी स्टीम इंजन स्थापित किया गया, और ऐसी नौकाओं व जहाजों का निर्माण प्रारम्भ हुआ, जो चप्पुओ व पाल से न चल कर इंजन द्वारा चलते थे। धीरे-धीरे जहाजों के आकार में भी वृद्धि शुरू हुई। लाखों मन बोझ के विशाल जहाज समुद्र के वक्षस्थल को चीरते हुए तेज गति से दौड़ने लगे। पर यह सब केवल इसलिये सम्भव हो सका, क्योंकि उन्हें चलाने के लिये अब कपड़े के पाल व चप्पुओ पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रही थी। अब उन्हें चलाने के लिये भाप की यान्त्रिक शक्ति मनुष्य के वश में आ गई थी।

यदि भाप की शक्ति से जल में जहाज चलाये जा सकते थे, तो उसी शक्ति का उपयोग स्थल में गाड़िया चलाने के लिये क्यों नहीं किया जा सकता था? जिम प्रकार चप्पुओ व पाल का स्थान अब स्टीम इंजन ले रहा था, उसी प्रकार घोड़े व बैल का स्थान भी स्टीम इंजन क्यों नहीं ले सकता था? सन् १८१४ में जार्ज स्टीवन्सन ने एक ऐसे लोकोमोटिव (स्वयं संचालित होनेवाले इंजन) का आविष्कार किया, जो लोहे की पट्टी पर स्वयं भाप की शक्ति से चल सकता था, और अपने साथ में बोझ में भरी हुई गाड़ियों को भी खींच सकता था। इस लोकोमोटिव का पहला उपयोग खान से कोयले को टोकर नहर तक पहुँचाने के लिये किया गया। पर यह रेलगाड़ी के उस महान् आविष्कार का अंगणेश था, जिसने जागे चलकर मनुष्य के यातायात को बहुत सुगम कर दिया। सन् १८२५ में दग्लैण्ड में पहली रेलवे लाइन बनी। यह वारह मील लम्बी थी। पहली रेलगाड़ी की चाल भी अधिक से अधिक बारह मील प्रति घण्टा थी। इस गाड़ी को देखने के लिये लोगों में बड़ी उत्सुकता थी, कि जब पहले पहल यह रेलगाड़ी चलाई गई, तो भीड़ की पट्टी में पर रवाने के लिये कुछ घुड़सवार इंजन के आगे-आगे चलने के लिये नियत करके पड़े। १८३० में मंचेस्टर और लिबरपूल के बीच में वायायदा रेल चलने लगी। उस समय मन्चार्म मोड़ की इस लाइन को पार करने में गाड़ी को डेढ़ घण्टे का समय लगता था। तेरह साल में, सन् १८४३ तक दग्लैण्ड में १८०० मील रेलवे लाइन बन गई थी। अब दग्लैण्ड में लिबरपूल पहुँचने में केवल दस घण्टे लगते थे। रेल ने पहले तेज प्रोता गाड़ियों को भी में एक मन्चाह लग जाता था। नि सन्देह, मनुष्य ने स्टीम इंजन के आविष्कार द्वारा आगे बढ़ा और बाल पर भारी विजय प्राप्त कर ली थी।

रसायन शास्त्र—स्टीम इंजन व नये यान्त्रिक उपकरणों के आविष्कार के साथ-साथ

अठारहवीं सदी में यूरोप में रसायनशास्त्र की नई प्रक्रियाओं का भी परिज्ञान हो रहा था। रसायनशास्त्र बहुत पुराना विज्ञान है। मध्यकाल में इसी की सहायता से वैज्ञानिक लोह उम पारस पत्थर की खोज में लगे थे, जिसके स्पर्श में लोहा मोला बन सके। अब वैज्ञानिकों ने पारस को पाने की आशा तो त्याग दी थी, पर उन्होंने सचमुच अपने आविष्कारों में उन प्रक्रियाओं को जान लिया था, जिनमें वे मानव के कल्याण व हित के लिये बहुत कुछ काम कर सकते थे। लोहे को मजबूत बनाने की प्रक्रिया का परिज्ञान इसका एक उदाहरण है। इस एक रासायनिक आविष्कार में व्यावसायिक क्रान्ति में जितनी सहायता मिली, उसकी कल्पना महज में ही जा सकती है।

नई मशीनों के आविष्कार, धान्यिक शक्ति के परिज्ञान और नई रासायनिक प्रक्रियाओं के परिचय ने मिलकर आर्थिक उत्पत्ति के क्षेत्र में जिस नये युग का प्रारम्भ किया, उसके कारण मानव-समाज के व्यावसायिक संगठन में बड़ा भारी परिवर्तन आ गया। इसी को व्यावसायिक क्रान्ति कहते हैं। वस्तुतः, मनुष्य के जीवन में यह एक भारी क्रान्ति थी। इसका प्रभाव मनुष्य के हित व कल्याण के लिये उन क्रान्तियों में उन्हीं अधिक था, जिनके द्वारा मनुष्य ने राजा व चर्च के आधिपत्य का अन्त कर जनसाधारण के शासन का सूत्रपात किया था।

## ४ औद्योगिक क्रान्ति के परिणाम

यूरोप में औद्योगिक क्रान्ति ने मानव समाज के जीवन में जो भारी परिवर्तन किया है, उस पर प्रकाश डालना आवश्यक है—

(१) आर्थिक उत्पत्ति में वृद्धि—यूरोप में व्यावसायिक उत्पत्ति का प्रारम्भ इङ्ग्लैंड से हुआ। वहाँ आर्थिक उत्पत्ति में इतनी वृद्धि हुई, कि जहाँ सन् १७८० में इङ्ग्लैंड ने बाहर जानेवाले माल की कीमत बीस करोड़ के लगभग थी, वहाँ १८१५ में, केवल तीन वर्षों के अन्दर बीस करोड़ के लगभग का माल दूसरे देशों में विक्री के लिये जाने लगा। पिछली दसवीं सदी के इङ्ग्लैंड में अकेले कपड़े की पैदावार में ६०० गुना की वृद्धि हुई है। यदि सस्तर के सूत के स्त्री पुरुषों को सूत कातने और बुनने के काम में लगा दिया जाय, तो वे जितना कपड़ा सोलह महीने में तैयार कर सकेंगे, उसमें कहीं अधिक कपड़ा अकेले इङ्ग्लैंड में रुपये की मिलों द्वारा तैयार होता है।

केवल वस्त्र-व्यवसाय में ही नहीं, अन्य व्यवसायों में भी मशीनों के प्रयोग ने उत्पत्ति में भारी वृद्धि की है। उदाहरण के लिये पिन के व्यवसाय को लीजिये। इङ्ग्लैंड की एक साधारण फैक्टरी में सत्तर लाख पिन एक दिन में तैयार होते हैं, और इतनी उत्पत्ति करने वाली मशीनों को चलाने के लिये केवल तीन शिल्पियों की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार मशीनों के कारण छापेखानों (प्रिंटिंग प्रेस) में यह सम्भव है, कि एक पन्ध्रे में लाखों अधिक संख्या में समाचारपत्रों की प्रतियाँ छपी जा सकें। मध्यकाल में भी यूरोप में छापेखाने होते थे। प्रामैटर्स को कम्पोज करना, म्याही लगाना व छापना—सब काम हाथ से होता था। परिणाम यह था, कि एक दिन में कुछ सौ प्रतियाँ ही छापकर तैयार की जा सकती थीं। प्रयोगात्मक शक्ति और मशीनों के उपयोग के कारण अब मुद्रण-व्यवसाय

ने इतनी अधिक उत्पत्ति कर ली है, कि लाखों की सख्या में छपने वाले समाचार-पत्र प्रातः-काल छपकर तैयार हो जाते हैं, और दिन निकलने तक पाठकों के हाथ में पहुँच जाते हैं।

(२) गृह उद्योग का अन्त और विशाल कारखानों का प्रारम्भ—व्यावसायिक क्रान्ति से पहले मध्यकाल में गृह-उद्योग की पद्धति जारी थी। प्रत्येक कारीगर अपने घर पर काम करता था। उसका घर पर ही एक छोटा सा कारखाना होता था, जिसमें वह अपनी स्त्री व बच्चों तथा अन्तेवासियों (शागिर्दों) के साथ आर्थिक उत्पत्ति करता था। कुम्हार, जुलाहा, मोची, लुहार आदि सब व्यवसायी अपने-अपने घर पर काम करते थे। उनके काम करने के कोई घण्टे नियत नहीं होते थे। वे जब चाहते और जितने समय तक चाहते, काम करते और स्वयं ही अपने माल को देहात की पंठ में या शहर की मण्डी में बेच आते थे। कारीगरों का जीवन बड़ा भीषा, मरल और शान्तिमय था।

पर औद्योगिक क्रान्ति ने इस दशा को बदल दिया। नई मशीनों के मुकाबले में गृह-उद्योगों के लिये ठहर सकना कठिन हो गया। गृह व्यवसायों का स्थान वे कारखाने (फैक्टरी) लेने लगे, जिनमें नई मशीनें यान्त्रिक शक्ति द्वारा काम करती थीं, और जिनमें श्रमी (मजदूर) व कारीगर की अपेक्षा मशीनों का महत्त्व अधिक था, और एक-एक कारखाने में हजारों की सख्या में श्रमी लोग एकत्र होकर मशीन की सहायता से आर्थिक उत्पत्ति करते थे। कारीगर अब स्वतन्त्र उत्पादक न रहकर भ्रति (मजदूरी) प्राप्त करनेवाला हो गया। उसकी स्थिति एक ऐसे गुलाम की हो गई, जिसने अपने स्वामी (कारखाने के मालिक) के आदेश के अनुसार कार्य करना है।

मशीन के उपयोग के कारण श्रम-विभाग का भी बहुत विकास हुआ। पहले आर्थिक उत्पत्ति की सब प्रक्रियाएँ कारीगर स्वयं करता था। इस कारण यह गुजाड़न थी, कि वह अपनी प्रतिभा के अनुसार कला का प्रदर्शन कर सके। पर जो आर्थिक उत्पत्ति की प्रक्रिया अनेक छोटे-छोटे भागों में विभक्त हो गई, जिन्हें विविध मशीनें सम्पन्न करती हैं, और मनुष्य का कार्य केवल यह देखना है, कि मशीन ठीक प्रकार से अपना कार्य कर रही है। श्रमी व शिल्पी की प्रतिभा व कला को प्रयुक्त होने का अवसर इन कारखानों में नहीं रह गया है। वस्तुतः, उसकी स्थिति भी एक मशीन की हो गई है, जिसे दमन की दृष्टि के अनुसार गुलाम के रूप में काम करना है।

(३) पूँजीपतियों का प्रभाव—औद्योगिक क्रान्ति के कारण जो यह सम्भव नहीं रहा, कि कारीगर स्वतन्त्र रूप से आर्थिक उत्पत्ति कर सके। मध्यकाल में उत्पत्ति के लिये किसी बड़ी पूँजी की आवश्यकता नहीं होती थी। कारीगर को जिन औजारों व उपकरणों की आवश्यकता होती थी, वे सस्ते में खरीदे जा सकते थे, या कारीगर उन्हें स्वयं बना लेता था। पर मशीनों के इस नये युग में जो कीमती इस्जन व जटिल मशीनें नाम में आने लगीं, उन्हें हर कोई सुगमता से नहीं प्राप्त कर सकता था। उनके लिये अपनी की आवश्यकता होती थी। जिन लोगों के पास रुपया था, वे स्वयं शिल्पी न होने हुए भी अपने घर के दर पर मशीन खरीद कर कारखाना कायम कर सकते थे, और सैकड़ों हजारों मजदूरों का जतन कर आर्थिक उत्पत्ति या संचालन कर सकते थे। यह व्यापारिक या जि उन नये युग का प्रभाव आर्थिक क्षेत्र में बटता जाय, जो धीरे-धीरे सब आर्थिक उत्पत्ति स्वतन्त्र

शिल्पियों के हाथ से निकलकर इन वस्तुओं व पूजीपतियों के हाथ में आ जाय। उन्नीसवीं सदी के शुरु से यह प्रक्रिया निरन्तर जोर पकड़ने लगी, और पूजीपति श्रेणि सम्पूर्ण व्यवसायों को अपने हाथ में करने लगी।

यह ठीक है, कि व्यावसायिक क्रान्ति में पूर्व भी यह पूजीपति श्रेणि जोर पकड़ना शुरू कर चुकी थी। जब से दिग्दर्शक यन्त्र का आविष्कार हुआ, यूरोप का व्यापार एशिया व अफ्रीका में बढ़ने लगा। ऐसे व्यापारी प्रगट हुए, जो जहाजों पर बड़ी मात्रा में भात लोदकर बाहर ले जाते थे, और व्यापार द्वारा प्रचुर धन कमाने थे। पहले ये लोग स्वतन्त्र शिल्पियों से कपड़ा व अन्य माल खरीदा करने थे। पर धीरे-धीरे उन्होंने अनुभव किया, कि व्यापार की दृष्टि में यह अधिक अच्छा है, कि शिल्पियों को नौकर रखकर उनसे माल तैयार कराया जाय। ये बड़े-बड़े धनिक व्यापारी सैकड़ों हजारों की संख्या में शिल्पियों को अपने पास नौकरी में रखकर आर्थिक उत्पत्ति करने लगे थे। उसने एक प्रकार के गेरे कारखाना का प्रादुर्भाव हुआ था, जिनमें यान्त्रिक शक्ति के बिना पुराने क्रिस्म के औजारों में ही काम होता था, पर जिनमें शिल्पियों की स्वतन्त्र सत्ता का ह्रास होकर धनिकों का प्रभाव बढ़ता जाता था। पर अब नये वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण यान्त्रिक शक्ति और नई मशीनों का जो प्रारम्भ हुआ, उसने तो इन 'कारखानों' के महत्त्व को बहुत अधिक बढ़ा दिया। धनिक पूजीपतियों के लिये यह सुगम हो गया, कि वे अपने रुपये में इतन व मशीन खरीद कर सम्पूर्ण व्यवसाय को अपने हाथ में कर लें, और शिल्पियों को पूर्णतया अपना वशवर्ती बना लें।

व्यावसायिक क्रान्ति ने आर्थिक उत्पादकों को दो श्रेणियों में विभक्त कर दिया—पूजीपति और मजदूर। धीरे-धीरे मजदूरों को अपनी दुर्दशा का ज्ञान हुआ, और उन्होंने अपने को संगठित कर अपनी दशा को उत्तम करने व अपने अधिकारों की मांग के लिये सधर्म प्रारम्भ किया। पूजीपतियों व मजदूरों का पारस्परिक सधर्म व्यावसायिक उत्पत्ति का एक महत्त्वपूर्ण परिणाम है।

(४) व्यावसायिक नगरों का विकास—बड़े-बड़े कारखानों के विकास के कारण नगरों की आबादी बढ़ने लगी। देहातों के गृह-व्यवसाय नष्ट होने लगे, और उनके कारीगर शहरों के कारखानों में मजदूरी करने के लिये आने लगे। जिन नगरों में बड़े कारखानों के लिये सुविधाएँ थी, उनका बड़ी तेजी के साथ विकास हुआ। १७६० में लिबरपूल की आबादी चालीस हजार थी। १८४१ में वह बढ़कर दो लाख अठाइस हजार हो गई। इसी प्रकार, इसी काल में मैनचेस्टर की आबादी पैतालीस हजार से बढ़कर तीन लाख हो गई। १७६० में लकाशायर की आबादी १,६६,००० थी। १९०१ में वह बढ़कर ४,५००,००० तक पहुँच गई। सन् १८०० में सारे यूरोप में केवल अठारह नगर ऐसे थे, जिनकी जनसंख्या एक लाख से ऊपर थी। एक सदी बाद ऐसे नगरों की संख्या २०० में भी ऊपर पहुँच गई थी। व्यावसायिक नगरों का विकास व्यावसायिक क्रान्ति का एक बहुत महत्त्वपूर्ण परिणाम है। इन विशाल नगरों का जीवन देहातों व कस्बों के सीधे-सादे सरल जीवन से बहुत ही भिन्न है। देहात के स्वतन्त्र वातावरण में रहनेवाला किसान व शिल्पी अब इन महानगरियों के नग वायुमंडल में निवास करने के लिये बाधित हुआ।

(५) नया श्रेणिभेद—मध्यकालीन यूरोप में जागीरदार सामन्तो का प्रभाव सबसे अधिक था। सामन्त, पादरी और सर्वसाधारण जनता, जिसमें किमान व शिल्पी सब अन्तर्गत् थे, ये तीन श्रेणियाँ उस समय में विद्यमान थीं। पर अब नया श्रेणिभेद उत्पन्न हुआ। कारखानों के मालिक पूँजीपतियों का महत्त्व अब मध्यकाल के सामन्तो की अपेक्षा अधिक बढ़ गया। पूँजीपति और मजदूर—ये दो श्रेणियाँ प्रबल रूप में बन गईं। मजदूर पूर्णतया पूँजीपतियों पर आश्रित हो गये। सामाजिक दृष्टि से स्वतन्त्र होते हुए भी उनकी स्थिति गुलामी से अच्छी नहीं रही। पर पूँजीपति और मजदूर इन दो श्रेणियों के साथ-साथ इस समय एक तीसरी श्रेणि का भी विकास होने लगा। इसे हम शिक्षित मध्यश्रेणि कह सकते हैं। कारखानों में यान्त्रिक शक्ति और जटिल मशीनों का संचालन करने के लिये ऐसे शिक्षित शिल्पियों की आवश्यकता थी, जो विज्ञान में विद्वान् होते। साथ ही, कारखानों का हिसाब रखने व्यापार की नीति का निर्माण करने व माल का प्रचार करने के लिये कुशल शिक्षित पुरुषों के बिना काम नहीं चल सकता था। मध्यश्रेणी के ये शिक्षित लोग स्वयं पूँजीपति न होते हुए भी समाज में अनुल्लेख्य प्रभाव रखने लगे। नये आर्थिक जीवन में व्यापारी, महाजन, वकील आदि का महत्त्व बढ़ने लगा, और इन सब में मिलकर एक तीसरी श्रेणी—शिक्षित मध्यश्रेणी—का विकास हुआ। धीरे-धीरे अपने प्रभाव की दृष्टि से इसका वही महत्त्व बनने लगा, जो मध्यकाल में पादरियों का था। शिक्षा और ज्ञान के प्रचार के कारण इस श्रेणी के लोगों के लिये समाज और सरकार—दोनों पर अपना प्रभाव बढ़ा सकना बहुत सुगम था। प्रेम, समाचारपत्र, और पुस्तकों के प्रचार के कारण यह श्रेणी अपने विचारों का प्रसार भी सुगमता से कर सकती थी। परिणाम यह हुआ, कि धीरे-धीरे समाज का नेतृत्व इसके हाथ में जाने लगा।

(६) पारिवारिक जीवन पर असर—व्यावसायिक क्रान्ति ने पूर्ण आर्थिक उत्थान का कार्य प्रधानतया पुरुष करते थे। स्त्रियाँ घर का काम करती थीं, और आर्थिक क्षेत्र में भी अपने पुरुषवर्ग की सहायता करती थीं। इसमें सर्वसाधारण जनता में भी पारिवारिक जीवन सुखमय तथा अक्षुण्ण बना रहता था। पर बड़े कारखानों के प्रादुर्भाव के कारण जब शिल्पी लोग देशालों में शहरों में मजदूरी की तलाश में जाने लगे, तो पारिवारिक जीवन पर इसका बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। शहरों में रहने की जगह की कमी थी। मादरों के लिये सम्भव नहीं था, कि वे शहरों में परिवार के योग्य स्थान प्राप्त कर सकें। एक एक कोठरी में अनेक मजदूर एक साथ निवास करते थे। उनके लिये अपनी स्त्री व बच्चा को साथ रख सकना कठिन था। परिणाम यह हुआ, कि पारिवारिक जीवन की शान्ति व सुख नष्ट होने लगा। साथ ही, आजीविका की तलाश में बहुत सी स्त्रियाँ व बच्चे नौ कारखानों में मजदूरी करनी शुरू कर दीं। मशीनों से चलनेवाले कारखानों में काम करने के लिये शारीरिक शक्ति व शिल्पनैपुण्य की विशेष आवश्यकता नहीं थी। उनमें स्त्री व बच्चे भी सुगमता से काम कर सकने लगे। पूँजीपतियों को इसमें लाभ था, कि वे स्त्रियों व बच्चों को मजदूरी पर रखें, क्योंकि उनकी मजदूरी की दर कम होती थी। पुरुषों का भार फिरने लगे और स्त्रियाँ व बच्चे की बड़ी संख्या में कारखानों में काम करने लगीं। उच्चों के नैतिक के लिये यह बात बहुत हानिकारक थी। स्त्रियों के स्वास्थ्य पर भी इसका

बहुत प्रतिकूल असर पड़ता था। वाद में ऐसे बहुत से कानून बनाये गये, जिनमें स्त्रियाँ व वच्चा को पूँजीपतियों के लोभ का शिकार बनने से बचाने का उद्योग किया गया। पर इसमें सन्देह नहीं, कि शुरू में व्यावसायिक क्रान्ति ने जहाँ पारिवारिक जीवन की सुन-शान्ति का नष्ट किया, वहाँ स्त्रियों व वच्चों के स्वास्थ्य व भविष्य पर भी बहुत प्रतिकूल पभाव डाला। वस्तुतः, उस युग में पूँजीपतियों ने भय प्रकार से गरीबों की असहाय दशा का फायदा उठाया और गरीब व अमीर का भेद निरन्तर अधिक-अधिक बढ़ता गया।

(७) वैयक्तिक स्वतन्त्रता का सिद्धान्त—इस युग में पूँजीपतियों की मनमानी का किसी भी प्रकार से विरोध कर सकना मुमकिन नहीं था। कारण यह, कि एक तरफ तो अभी स्वेच्छाचारी एकतन्त्र शासन विद्यमान थे, लोकतन्त्र शासन का भलीभाँति विकास नहीं हुआ था, और दूसरी तरफ इस समय के विचारक “वैयक्तिक स्वतन्त्रता” के सिद्धान्त के अनुयायी थे। इस सिद्धान्त के अनुसार यह समझा जाता था, कि राज्य तो व्यवसाय के क्षेत्र में किसी प्रकार का हस्तक्षेप या नियन्त्रण नहीं करना चाहिये। पूँजीपति जीरो मजदूर के पारम्परिक भ्रमन्ध उनके स्वेच्छापूर्वक किये गये ठीके पर आश्रित हैं। किसी ने मजदूर को विवश नहीं किया, कि वह नाममात्र की मजदूरी पर दिन में साढ़े पाँच घण्टे तक काम करे। यदि वह चाहे तो उसे पूरी स्वतन्त्रता है, कि वह नाकरी छोड़ दे। प्रत्येक मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं विधाता है, वह अपने भले-बुरे को स्वयं भली भाँति समझता है। यदि उसे खूला छोड़ दिया जाय, तो वह अपनी योग्यता और कार्यक्षमता के अनुरूप स्वयं उचित म्यान प्राप्त कर लेगा। इसी प्रकार, वस्तुओं की कीमते उपलब्धि और मांग के नियम पर आश्रित हैं। अर्थशास्त्र का यह नियम स्वयं वस्तुओं की कीमत को ठीक करता रहता है। राज्य तो ओर से इसमें हस्तक्षेप करना ठीक वैसा ही है, जैसे जल को नीचे की ओर बहने से रोकना।

इन विचारों का परिणाम क्रिया में बहुत भयंकर हुआ। इसमें पूँजीपतियों को गरीब लोगों की असहाय दशा का अनुचित लाभ उठाने का सुवर्णय अवसर हाथ लगा। उनके कारखानों में नौ वर्ष की आयु में भी बच्चों के बालक काम के लिये रखे जाते थे, और उन्हें बारह से पन्द्रह घण्टे तक प्रतिदिन काम करने के लिये विवश होना पड़ता था। इतने समय तक काम करने के बाद वे जिन मकानों में विश्राम करने के लिये जाते थे, वे गन्दे और तग होते थे। एक-एक कमरे में दर्जनों वच्चे, मर्द व स्त्रियाँ एक साथ रहने के लिये विवश होती थीं।

वाद में वैयक्तिक स्वतन्त्रता के इस हास्यास्पद सिद्धान्त के विरुद्ध भी प्रतिक्रिया शुरू हुई। लोगों ने आन्दोलन शुरू किया, कि कारखानों पर सरकार का नियन्त्रण होना चाहिये, और यह नियन्त्रण सर्वसाधारण जनता के हित में हो। इसके लिये वोट देने का अधिकार केवल अमीरों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिये। मजदूरों के अपने संगठन भी अपने हितों की रक्षा के लिये बनने शुरू हुए, और धीरे-धीरे कारखानों की दशा में सुधारों का प्रारम्भ हुआ।

(८) व्यापार का विस्तार—व्यावसायिक क्रान्ति के कारण व्यापार का बहुत विस्तार हुआ। पहले लोग प्रायः अपनी सभी आवश्यकताओं को स्वयं पूरा करने का प्रयत्न करते थे। गाव पाय आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर होते थे। पर बड़े-बड़े कारखानों

के विकास के साथ-साथ भिन्न-भिन्न व्यवसायों के पृथक्-पृथक् केन्द्रों का विकास प्रारम्भ हुआ। मैन्चेस्टर और लकाशायर वस्त्र-व्यवसाय के लिये व शैफील्ड तथा वर्मिपम लोह-व्यवसाय के लिये प्रसिद्ध होने लगे। जब एक केन्द्र में प्रधानतया एक ही व्यवसाय केन्द्रित हुआ, तो शहरों का पारस्परिक व्यापार बढ़ना विलकुल स्वाभाविक था। इसी प्रकार विविध देश अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के कारण पृथक् व्यवसायों में विशेषता प्राप्त करने लगे। इस से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भी बहुत वृद्धि होने लगी।

इसमें सन्देह नहीं, कि व्यावसायिक क्रान्ति के परिणाम अच्छे व बुरे—दोनों प्रकार के थे। इसके कारण शुरु में गरीब शिल्पियों की बहुत दुर्दशा हुई। उन की स्थिति स्वतन्त्र व प्रतिष्ठित शिल्पी के वजाय पराश्रित मजदूर की हो गई। पर शहरों में आने से वे ज्ञान के उस प्रकार को भी धीरे-धीरे प्राप्त करने लगे, जिससे उन्हें अपनी स्थिति व अधिकारों का भलीभांति परिज्ञान हो गया। कुछ ही समय बाद वे अपने हितों व अधिकारों की रक्षा केलिये संघर्ष भी करने लग गये। अब न केवल उनकी आर्थिक स्थिति सन्तोषजनक है, पर साथ ही राज्य पर भी उनका अतुल्य प्रभाव है। राज्य के राजनीतिक जीवन में उनका महत्त्व अब सबसे अधिक है। मानव समाज की उन्नति का ढग यही है, कि एक परिवर्तन पहले अपने कुपरिणाम भी उत्पन्न करता है, पर धीरे-धीरे बुराई का अन्त करके मनुष्य उन्नति के मार्ग पर अगसर हो जाता है।

## ५ अन्य देशों में औद्योगिक क्रान्ति

व्यावसायिक क्रान्ति के क्षेत्र में नेतृत्व इङ्ग्लैण्ड ने किया, पर अन्य यूरोपियन देश भी उसके प्रभाव से वंचित नहीं रहे। फ्रांस में राज्यक्रान्ति ने जिस नवजीवन को उत्पन्न किया था, उसके कारण वहाँ के लोगो ने यांत्रिक शक्ति और नई मशीनों को अपनाने में देर नहीं की। सन् १७८५ में कपड़े का पहला बड़ा कारखाना फ्रांस में खुला। इसके लिये ग्ग मशीन उद्भूत-लैण्ड में मँगाई गई थी। नेपोलियन ने वस्त्र व्यवसाय को उन्नत करने के लिये उर उत्साह दिया। परिणाम यह हुआ, कि १८१५ तक फ्रांस में भी चार लाख मनुष्य प्रति वर्ष कपड़े के रूप में परिवर्तित की जाने लगी। सन् १८३१ तक यह संख्या दस लाख हो गई। फ्रांस में भी वस्त्र व्यवसाय में हजारों मजदूर काम करने लगे। १८३१ में इस प्रकार के मजदूरों की संख्या ढाई लाख से ऊपर थी। स्ट्रिके अनिश्चित, रेशम जार उन के कपड़ों के व्यवसाय में भी फ्रांस ने बहुत उन्नति की। लियो जार लैन्ड के नगर रार्मी कपड़ों के लिये समार भर में प्रसिद्ध हो गये। सान्बुन, नेल् शराब, मागत, पडी, गागा आदि अनेक व्यवसायों में फ्रांस इङ्ग्लैण्ड में भी जागे बट गया।

उन्नीसवीं सदी के शुरु में इङ्ग्लैण्ड और फ्रांस, दो ही देश यूरोप में व्यवसायिक दृष्टि से सब अधिक उन्नत थे। यही कारण है, कि साम्राज्यवाद के क्षेत्र में भी इन्हीं दो देशों में संघर्ष सब से प्रवृत्त था। अफ्रीका, भारत व एशिया के अन्य देशों में इङ्ग्लैण्ड और फ्रांस अपना-अपना प्रभुत्व कायम करने के लिये प्रयत्नशील थे।

जापान ने व्यावसायिक क्रान्ति का प्रारम्भ १८८५ के लगभग हुआ। उसने पहले बड़ा-बड़ा उद्योग प्राप्त मध्यकाल की शैली में ही होनी थी। जर्मनी के इस क्षेत्र में पिछले

बहुत प्रतिभूल असर पड़ता था। बाद में ऐसे बहुत से कानून बनाये गये, जिनसे स्त्रियों व बच्चों को पूजीपतियों के लोभ का शिकार बनने से बचाने का उद्योग किया गया। पर इसमें सन्देह नहीं, कि शुरू में व्यावसायिक क्रान्ति ने जहाँ पारिवारिक जीवन की मुय-शान्ति को नष्ट किया, वहाँ स्त्रियों व बच्चों के स्वास्थ्य व भविष्य पर भी बहुत प्रतिकूल प्रभाव डाला। वस्तुतः, उस युग में पूजीपतियों ने सब प्रकार से गरीबों की अमहाय दशा का फायदा उठाया और गरीब व अमीर का भेद निरन्तर अधिक-अधिक बढ़ता गया।

(७) वैयक्तिक स्वतन्त्रता का सिद्धान्त—इस युग में पूजीपतियों की मनमानी का किसी भी प्रकार से विरोध कर मरना मुमकिन नहीं था। कारण यह, कि एक तरफ तो अभी स्वेच्छाचारी एकतन्त्र शासन विद्यमान थे, लोकतन्त्र शासन का भलीभांति विकास नहीं हुआ था, और दूसरी तरफ इस समय के विचारक “वैयक्तिक स्वतन्त्रता” के सिद्धान्त के अनुयायी थे। इस सिद्धान्त के अनुसार यह समझा जाता था, कि राज्य को व्यवसाय के क्षेत्र में किसी प्रकार का हस्तक्षेप या नियन्त्रण नहीं करना चाहिये। पूजीपति जीर मजदूर के पारस्परिक सम्बन्ध उनके स्वेच्छापूर्वक किये गये ठीके पर आश्रित हैं। किसी ने मजदूर को विवश नहीं किया, कि वह नाममात्र की मजदूरी पर दिन में बारह व पन्द्रह घण्टे तक काम करे। यदि वह चाहे तो उसे पूरी स्वतन्त्रता है, कि वह नाकरी छोड़ दे। प्रत्येक मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं विधाता है, वह अपने भले-बुरे को स्वयं भली भांति समझता है। यदि उसे खुला छोड़ दिया जाय, तो वह अपनी योग्यता और कार्यश्रमता के अनुरूप स्वयं उचित स्थान प्राप्त कर लेगा। इसी प्रकार, वस्तुओं की कीमतें उपलब्धि और मांग के नियम पर आश्रित हैं। अर्थशास्त्र का यह नियम स्वयं वस्तुओं की कीमत को ठीक करता रहता है। राज्य की ओर से इसमें हस्तक्षेप करना ठीक वैसा ही है, जैसे जल को नीचे की ओर बहने से रोकना।

इन विचारों का परिणाम क्रिया में बहुत भयकर हुआ। इससे पूजीपतियों को गरीब लोगों की अमहाय दशा का अनुचित लाभ उठाने का सुवर्णाय अवसर हाथ लगा। उनके कारखानों में नौ वर्ष की आयु में भी कम के बालक काम के लिये रखे जाते थे, और उन्हें बारह से पन्द्रह घण्टे तक प्रतिदिन काम करने के लिये विवश होना पड़ता था। इतने समय तक काम करने के बाद वे जिन मकानों में विश्राम करने के लिये जाते थे, वे गन्दे और तग होते थे। एक-एक कमरे में दर्जनों बच्चे, मर्द व स्त्रियाँ एक साथ रहने के लिये विवश होती थीं।

बाद में वैयक्तिक स्वतन्त्रता के इस हास्यास्पद सिद्धान्त के विरुद्ध भी प्रतिक्रिया शुरू हुई। लोगों ने आन्दोलन शुरू किया, कि कारखानों पर सरकार का नियन्त्रण होना चाहिये, और यह नियन्त्रण सर्वसाधारण जनता के हित में हो। इसके लिये वोट देने का अधिकार केवल अमीरों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिये। मजदूरों के अपने संगठन भी अपने हितों की रक्षा के लिये बनने शुरू हुए, और धीधीरे-धीरे कारखानों की दशा में सुधारों का प्रारम्भ हुआ।

(८) व्यापार का विस्तार—व्यावसायिक क्रान्ति के कारण व्यापार का बहुत विस्तार हुआ। पहले लोग प्रायः अपनी सभी आवश्यकताओं को स्वयं पूरा करने का प्रयत्न करते थे। गांव प्रायः आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर होते थे। पर बड़े-बड़े कारखानों



के विकास के साथ-साथ भिन्न-भिन्न व्यवसायों के पृथक्-पृथक् केन्द्रों का विकास प्रारम्भ हुआ। मैनचेस्टर और लकाशायर वस्त्र-व्यवसाय के लिये व शैफील्ड तथा वर्मिंघम लोह-व्यवसाय के लिये प्रसिद्ध होने लगे। जब एक केन्द्र में प्रचुरता एक ही व्यवसाय केन्द्रित हुआ, तो शहरो का पारस्परिक व्यापार बढ़ना विलकुल स्वाभाविक था। इसी प्रकार विविध देश अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के कारण पृथक् व्यवसायों में विशेषता प्राप्त करने लगे। इस में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भी बहुत वृद्धि होने लगी।

इसमें सन्देह नहीं, कि व्यावसायिक क्रान्ति के परिणाम अच्छे व बुरे—दोनों प्रकार के थे। इसके कारण शुरू में गरीब शिल्पियों की बहुत दुर्दशा हुई। उन की स्थिति स्वतन्त्र व प्रतिष्ठित शिल्पी के बजाय पराश्रित मजदूर की हो गई। पर शहरो में आने से वे ज्ञान के उस प्रकार को भी धीरे-धीरे प्राप्त करने लगे, जिसमें उन्हें अपनी स्थिति व अधिकारों का भलीभांति परिज्ञान हो गया। कुछ ही समय बाद वे अपने हितों व अधिकारों की रक्षा के लिये सघन भी करने लग गये। अब न केवल उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी है, पर साथ ही राज्य पर भी उनका अनुल प्रभाव है। राज्य के राजनीतिक जीवन में उनका महत्व अब सबसे अधिक है। मानव समाज की उन्नति का ढग यही है, कि एक परिवर्तन पहले अपने कुपरिणाम भी उत्पन्न करता है, पर धीरे-धीरे बुराई का अन्त करके मनुष्य उन्नति के मार्ग पर जगसर हो जाता है।

## ५ अन्य देशों में औद्योगिक क्रान्ति

व्यावसायिक क्रान्ति के क्षेत्र में नेतृत्व इङ्ग्लैण्ड ने किया, पर अन्य यूरोपियन देश भी उसके प्रभाव से बचन नहीं रहे। फ्रांस में राज्यक्रान्ति ने जिस नवजीवन को उत्पन्न किया था, उसके कारण वहाँ के लोगों ने यांत्रिक शक्ति और नई मशीनों को अपनाने में देर नहीं की। सन् १७८५ में कपड़े का पहला बड़ा कारखाना फ्रांस में खुला। इसके लिये सब मशीन इङ्ग्लैण्ड से मँगवाई गई थी। नेपोलियन ने वस्त्र व्यवसाय को उन्नत करने के लिये बड़ा उत्साह दिखाया। परिणाम यह हुआ, कि १८१५ तक फ्रांस में भी चार लाख मन रुई प्रति वर्ष कपड़े के रूप में परिवर्तित की जाने लगी। सन् १८३१ तक यह संख्या बढ़कर सोलह लाख मन तक पहुँच गई। फ्रांस में भी वस्त्र व्यवसाय में हजारों मजदूर काम करने लगे। १८३१ में इस प्रकार के मजदूरों की संख्या टाई लाख से ऊपर थी। रुई के अतिरिक्त, रेशम और ऊन के कपड़ों के व्यवसाय में भी फ्रांस ने बहुत उन्नति की। लियो और लील् के नगर रेशमी कपड़ों के लिये ससार भर में प्रसिद्ध हो गये। साबुन, तेल, शराब, कागज, घड़ी, शीशा जादि अनेक व्यवसायों में फ्रांस इङ्ग्लैण्ड से भी आगे बढ़ गया।

उन्नीसवीं सदी के शुरु में इङ्ग्लैण्ड और फ्रांस, दो ही देश यूरोप में व्यवसायिक दृष्टि से सभ्य अधिक उन्नत थे। यही कारण है, कि साम्राज्यवाद के क्षेत्र में भी इन्हीं दो देशों में सघन सब से प्रवृत्त था। अफ्रीका, भारत व एशिया के अन्य देशों में इङ्ग्लैण्ड और फ्रांस अपना-अपना प्रभुत्व कायम करने के लिये प्रयत्नशील थे।

जर्मनी में व्यावसायिक क्रान्ति का प्रारम्भ १८४५ के लगभग हुआ। उससे पहले वहाँ आर्थिक उत्पत्ति प्रायः मध्यकाल की शैली में ही होती थी। जर्मनी के इस क्षेत्र में पिछड़

जाने का प्रमुख कारण वहाँ राजनीतिक एकता का अभाव था। उन्नीसवीं सदी के मध्य तक भी जर्मनी में बहुत से छोटे-बड़े राज्य थे, जो प्रायः परस्पर लड़ते रहते थे। पर एक बार जब प्रिंस बिस्मार्क के कर्तृत्व में जर्मनी राजनीतिक दृष्टि से एक व शक्तिशाली हो गया, तो व्यावसायिक क्षेत्र में उन्नति करने में उसने असाधारण समता प्रदर्शित की। उन्नीसवीं सदी के अन्त तक जर्मनी किसी भी प्रकार इंग्लैंड व फ्रांस में व्यावसायिक क्षेत्र में कम नहीं रहा था।

बेल्जियम, डेनमार्क, हालैंड और स्वीडन जटाग्रही सदी के अन्त में ही व्यावसायिक क्रान्ति के प्रभाव में आने लगे थे। पर स्पेन, इटली, आस्ट्रिया और तब उन्नीसवीं सदी के अन्त तक इस महान् आर्थिक परिवर्तन के प्रभाव में प्रायः अछूते ही बने रहे। उनमें उन्नीसवीं सदी के अन्त व बीसवीं सदी के प्रारम्भ में व्यावसायिक क्रान्ति के चिह्न प्रकट होने शुरू हुए, और प्रथम यूरोपीय महायुद्ध (१९१४-१८) के प्रारम्भ तक भी उन देशों की व्यावसायिक दशा इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी की अपेक्षा बहुत पिछड़ी हुई रही।

यूरोप में मध्यकाल का अन्त होकर आधुनिक (माउर्न) युग के आने में कितना महत्वपूर्ण कार्य फ्रांस की राज्यक्रान्ति व उसमें उत्पन्न हुई क्रान्ति की लहर ने किया, उतना ही व उससे भी कहीं अधिक कार्य इस औद्योगिक क्रान्ति ने किया। विज्ञान का उपयोग शिल्प की उन्नति के लिये करके यूरोप के जनसमाज ने एक ऐसे युग का श्रीगणेश किया है, जिसके कारण मनुष्य प्रकृति की शक्तियों व भौतिक जगत् पर निरन्तर विजय प्राप्त करना जा रहा है, और इनको मानवसमाज के सुख, समृद्धि और उत्कर्ष के लिये प्रयुक्त करने में समर्थ हो रहा है।

चौदहवा अध्याय

## राष्ट्रीयता की भावना का विकास

### १. राष्ट्रीयता का प्रादुर्भाव

मनुष्यों में शुरू से यह प्रवृत्ति रही है, कि जिन लोगों की नस्ल, भाषा, धर्म, रीति-रिवाज और ऐतिहासिक परम्परा एक हो, वे परस्पर मिलकर एक समूह में संगठित हो। इस प्रकार के एक समूह लोगों में समूह की जाति या कबीला कहते हैं। जब एक जाति किसी एक निश्चित भूखण्ड पर बस कर अपना एक राज्य बना लेती है, अपने को एक शासन में संगठित कर लेती है, तब वह 'राष्ट्र' कहाने लगती है। इन प्रकार के राष्ट्रों की यह स्वाभाविक आकांक्षा रहती है, कि वह अपनी पृथक् स्वतन्त्र सत्ता को कायम रखें, पड़ोसी राष्ट्रों व किसी शक्तिशाली सम्राट् द्वारा अपनी स्वतन्त्रता व पृथक् सत्ता पर आंच न आने दे। जाति, राष्ट्र या राष्ट्रीयता की यह भावना मानव इतिहास की एक अत्यन्त प्रबल शक्ति है। प्राचीन ग्रीस व उन्नीसवीं के छोटे-छोटे विविध राज्य इसी प्रकार की जातियों द्वारा निर्मित हुए थे। उन्हें ठीक ज़रूरी में राष्ट्र समझा जा सकता था। बाद में मैसिडोनियन और रोमन सम्राटों ने इन राष्ट्रों की स्वतन्त्रता का अन्त कर इन्हें अपने अधीन कर लिया। रोमन सम्राटों के विशाल साम्राज्य में विविध भाषा बोलनेवाले अनेक नमलों के लोग निवास करते थे। रोमन लोगों ने अपने साम्राज्य में एकता स्थापित करने का प्रयत्न अवश्य किया, पर वे विविध जनसमूहों की राष्ट्रीय भावना को पूर्णतया नाश नहीं कर सके।

रोमन साम्राज्य के पतन के बाद, उसके भग्नावशेष पर जिन विविध राज्यों का निर्माण हुआ, उनकी तह में भी राष्ट्रीयता की भावना काम कर रही थी। इङ्ग्लैण्ड, फ्रांस, स्पेन, और पोर्तुगाल इसके उदाहरण हैं। पर मध्यकालीन यूरोप की सामन्तपद्धति में यह सम्भव नहीं था, कि राज्य का आधार राष्ट्रीयता की भावना बनी रहती। इस युग के विविध महन्वाकांक्षी राजा अपने वंशवर्ती सामन्तों की सहायता से अपनी शक्ति का विस्तार करने, अन्य राजाओं को अपने अधीन करने और दूसरे राजा के सामन्तों को अपना वंशवर्ती बनाने में सदा तत्पर रहते थे। इस का परिणाम यह हुआ, कि आस्ट्रिया के सम्राट् इटली को और स्पेन के सम्राट् हालैण्ड को अपने अधीन करने में सफल हुए। शार्लमेगन, फिलिप द्वितीय आदि मध्यकाल के शक्तिशाली राजाओं के राज्यक्षेत्र का आधार राष्ट्रीयता न होकर उनकी अपनी शक्ति व विविध सामन्तों को वंशवर्ती रखने की क्षमता ही थी।

फ्रांस की राज्यक्रान्ति ने जिन नई शक्तियों व प्रवृत्तियों को जन्म दिया, राष्ट्रीयता की भावना उनमें प्रमुख है। जो लोग धर्म, भाषा, नस्ल, रीति-रिवाज और ऐतिहासिक परम्परा के अनुसार एक हैं, उनका अपना पृथक् राज्य होना चाहिये, और इस राज्य में

किमी स्वेच्छाचारी राजा का शासन न होकर सर्वसाधारण जनता का लोकमत के अनुसार शासन होना चाहिये, यह मिटान्त फ्रांस की राज्यक्रान्ति की मुख्य देन है। इसी कारण जब सोलहवा लुई पेरिस में भाग निकला, तो एक फ्रांसीसी ने कहा था, 'यदि राजा भाग गया, तो कोई बात नहीं। फ्रेंच राष्ट्र तो विद्यमान है।' लुई का कहना था—'यह जनता ही होती है, जिससे वस्तुतः राज्य का निर्माण होता है।' राष्ट्रीयता की भावना फ्रेंच राज्य-क्रान्ति में बड़ी प्रबलता में काम कर रही थी। यही कारण है, कि जब पुरानी एस्टेट्स जनरल को नया रूप दिया गया, तो उसका नाम 'राष्ट्रीय सभा' रखा गया। फ्रांस के देहातों में क्रान्ति के दिनों में लोग कहा करने थे—हम नार्मान्डी या ब्रिटानी के निवासी नहीं हैं, अपितु फ्रांस के निवासी हैं। 'राष्ट्र की जय हो' के नारे में उन दिनों का सम्पूर्ण फ्रांस गूँज उठा था। मारे यूरोप के अनेक राजाओं की सम्मिलित शक्ति का मुकाबला फ्रांस जो सफलता के साथ कर सका था, उसका आधारभूत कारण राष्ट्रीयता की यही भावना थी। नैपोलियन ने जो यूरोप भर के राजाओं को परास्त किया था, उसका कारण भी यही भावना थी। नैपोलियन जहाँ कहीं भी आक्रमण करता था, वही कहता था, कि मैं जनता को, राष्ट्रा को स्वेच्छाचारी राजाओं के अत्याचारों से मुक्त कराने के लिये युद्ध कर रहा हूँ। वह आक्रान्त देशों की जनता से यही अपील करता था, कि वे स्वेच्छाचारी राजाओं के अत्याचारपूर्ण शासन के विरुद्ध विद्रोह कर राष्ट्रीय शासन की स्थापना करें। इसमें सन्देह नहीं, कि नैपोलियन के आक्रमणों ने यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के प्रसार में बड़ी सहायता पहुँचाई। इटली, पोलैण्ड, जर्मनी, स्पेन आदि सब देशों में नैपोलियन द्वारा ही नवयुग का सन्देश पहुँचा। पर जब नैपोलियन ने अपने को सम्राट् उद्घोषित कर रोमन साम्राज्य की पुरानी परम्परा का पुनरुद्धार करने का प्रयत्न किया, तो यह नव-प्रसारित राष्ट्रीय भावना ही उसके मार्ग में सबसे बड़ी बाधक बनी। जिस युद्ध में नैपोलियन का पतन हुआ, वह 'राष्ट्रों का युद्ध' कहा जाता है। निम्नलिखित, राष्ट्रीयता की भावना ने ही नैपोलियन के खिलाफ उस शक्ति को एकत्र किया था, जिसके सम्मुख वह विद्वज्जीवी वीर भी खड़ा नहीं रह सका। राष्ट्रीयता का जो सन्देश नैपोलियन ने दिया था, उसे यूरोप ने अपना लिया, यद्यपि इस सन्देश के वीर प्रसारक की सत्ता को यूरोप की नई प्रादुर्गत राष्ट्रशक्ति ने सहन नहीं किया।

## २ १८१५ के बाद राष्ट्रीयता की भावना

नैपोलियन के पतन के बाद यूरोप का पुनः निर्माण करने के लिये जो राजनीतिज्ञ वीएना में एकत्र हुए थे, उन्होंने राष्ट्रीयता की भावना की पूर्णतया उपेक्षा की। इन राजनीतिज्ञों का प्रयत्न यह था, कि यूरोप के पुराने राजवंशों की सत्ता व अधिकारों का पुनरुद्धार करे। वीएना की कांग्रेस द्वारा फ्रांसकी राज्यक्रान्ति के सब चिह्नों को नष्ट कर पुराने यूरोप की स्थापना की गई। पर इतिहास में जो शक्ति एक बार उत्पन्न हो जाती है, उसे सदा के लिये दबा सकना सम्भव नहीं होता। १८१५ के बाद उन्नीसवीं सदी का सम्पूर्ण यूरोपियन इतिहास वीएना की कांग्रेस की कृति के विरुद्ध प्रतिक्रिया व क्रान्ति की प्रवृत्तियों की सफलता के लिये किये गये संघर्ष का इतिहास है। राज्यक्रान्तियों द्वारा जनसाधारण

में एक जागति उत्पन्न हो गई थी। इसी जनमाधारण ने राष्ट्रीय भावना को अपनाया, और यह अपना ध्येय बनाया, कि जो लोग राष्ट्रीय दृष्टि से एक हैं, उनका पृथक् संगठन हो, और इस स्वतन्त्र संगठन में लोकमत के अनुसार शासन हो। उन्नीसवीं सदी में यूरोप में इटली, जर्मनी, बेल्जियम, ग्रीस आदि कितने ही राज्यों का पुनः संगठन राष्ट्रीयता के सिद्धान्त के अनुसार किया गया, और सर्वत्र देशभक्त लोग इसी सिद्धान्त की सफलता के लिये कार्य करने लगे।

**नया साहित्य**—उन्नीसवीं सदी का यूरोप का इतिहास देशभक्ति और राष्ट्रीयता की भावना में ओतप्रोत है। बर्न्सार्थ जैसे कवि ने काम की राज्यशान्ति की दृष्टि में रचित हुए लिखा था—‘प्रणीत होता है, मानवता ने एक बार फिर जन्म लिया है।’ इस काल के सभी अग्रज कवियों की रचनाएँ नई भावनाओं का प्रतिपादन करती हैं। शैली, कीट्स, वायरन, कार्लिज आदि सभी प्रमुख अग्रज कवियों की रचनाओं पर राष्ट्रीयता की भावना और नवयुग की छान स्पष्ट रूप से चित्रित है। उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भिक भाग में जनता पर सर्वत्र जो अन्याचार हो रहे थे, शैली ने उनके विरुद्ध आवाज उठाई। वायरन अपने समय के वस्त्र-निर्धारों और सामाजिक बन्धन का विरोधी था। शैली और वायरन—दोनों को कुछ समय के लिये अपने देशों बाहर भी रहना पड़ा था, और वायरन ने नौ तीन के स्वतन्त्रता-संग्राम में हाथ भी मिलाया था। उन्नीसवीं सदी के इंग्लिश साहित्य ने नई भावनाओं के प्रसार के लिये बहुत कार्य किया। इंग्लैण्ड में विविध राजनीतिक पक्षों द्वारा वार्षिक लोकमत शासन की जो स्थापना हुई, उसका बहुत कुछ श्रेय उस युग के साहित्य को दिया जा सकता है। न केवल इंग्लैण्ड, अपितु फ्रांस, जर्मनी, इटली आदि सभी देशों के साहित्यिक इस समय में राष्ट्रीयता के अनुयायी थे। यह युग देश-प्रेम और राष्ट्र-भक्ति का था।

नैपोलियन के आक्रमणों के कारण जर्मनी का बड़ा भाग फ्रांस की अधीनता या प्रभाव में आ गया था। इस स्थिति में वहाँ भी अनेक ऐसे साहित्यिक व कवि उत्पन्न हुए, जिन्होंने राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की भावना को प्रसारित करने का उद्योग किया। फीष्टे ने राष्ट्रीय भक्ति को मनुष्य का पवित्रतम कर्तव्य प्रतिपादित किया। प्फैजर का कहना था, कि “जिस प्रकार आत्मा के लिये शरीर की सत्ता अनिवार्य है, वैसे ही मानव समाज के लिये राष्ट्रीय भावना अवश्यम्भावी है।” शैन्कनडार्फ, क्यूनर आदि कितने ही कवि व साहित्यिक इस युग में जर्मनी में उत्पन्न हुए, जिन्होंने देशभक्ति और राष्ट्रीयता पर बहुत अधिक बल दिया। मैटरनिख ने इन लेखकों की रचनाओं को अनैतिक कहा, और अनेक इस प्रकार की आज्ञाएँ प्रकाशित की, जिनका उद्देश्य इस नये साहित्य के प्रचार को रोक देना था। मैटरनिख के आदेश से अनेक लेखकों को गिरफ्तार भी किया गया। पर मैटरनिख जैसे शक्तिशाली शासक के लिये भी यह सम्भव नहीं था, कि वह जर्मन राज्यों में विकसित होते हुए देश-प्रेम व स्वतन्त्र भावना को नष्ट कर सके। गैटे का कथन था, कि १७९२ में समार के इतिहास में एक नये युग का प्रादुर्भाव हुआ है। गिलर निरंकुश शासन के विनाश और मानव समाज की उन्नति का कट्टर पक्षपाती था। प्रसिद्ध जर्मन विचारक हीगल कट्टर राष्ट्रवादी था। उसका विचार था, कि राष्ट्रीयता के सिद्धान्त पर आश्रित राज्यों द्वारा

ही मसाले में एकता स्थापित हो सकती है। जर्मनी के विविध राज्यों की पृथक्-पृथक् सर्वोपरि मता का अन्त कर प्रिंस बिस्मार्क जो एक शक्तिशाली सुसंगठित जर्मनी का निर्माण कर सका, उसका श्रेय उन जर्मन विचारकों व साहित्यिकों को ही दिया जाना चाहिये, जिन्होंने कि अपने देश को राष्ट्रीय एकता के लिये तैयार कर दिया था।

इसी युग में इटली में भी अनेक ऐसे साहित्यिक उत्पन्न हुए, जो इटालियन राष्ट्र की एकता की ओर जनता का ध्यान आकृष्ट कर रहे थे। मन्जोनी ने अपने उपन्यासों में एकतन्त्र निरंकुश शासन की निन्दा कर लोकतन्त्रवाद का समर्थन किया। कार्डुस्सी इटालियन एकता का प्रबल पक्षपाती था, और रोमन कैथोलिक चर्च की शक्ति को इटली की स्वतन्त्रता का शत्रु समझता था। मैजिनी ने इटली की राष्ट्रीय एकता और जनता के शासन की स्थापना के लिये विशेष रूप से उद्योग किया। आगे चलकर इटली जो एक सुसंगठित राज्य के रूप में परिणत हो सका, उसमें इन साहित्यिकों का बड़ा हाथ था।

उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध में फ्रांस में जिन लेखकों, कवियों व साहित्यिकों ने राष्ट्रीयता और लोकतन्त्रवाद का प्रबल रूप में समर्थन किया, उनमें विक्टर ह्यूगो, गालो त्रिया, लामार्तीन और वात्जाक के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

**गुप्त समितियाँ**—न केवल साहित्य द्वारा, अगिन्तु गुप्त समितियों द्वारा भी इस युग में राष्ट्रीयता और देशभक्ति का प्रचार किया जा रहा था। साहित्य के प्रचार पर इस समय की सरकारें अनेक प्रकार की पाबन्दियाँ लगाती थीं। परिणाम यह हुआ, कि इस भावना का प्रचार गुप्त समितियों द्वारा होने लगा। दक्षिणी इटली में कारबोनारी नाम की एक गुप्त समिति संगठित हुई, जिसका उद्देश्य 'राष्ट्रीय एकता' और 'राजनीतिक स्वतन्त्रता' की स्थापना करना था। १८२० में स्पेन, पोर्तुगाल और इटली में जो क्रान्तियाँ हुईं, उनमें इस समिति का बड़ा हाथ था। १८३० और १८४८ में फ्रांस में गुप्त होकर क्रान्ति की जो लहरे यूरोप भर में व्याप्त हुईं, उनमें भी इस गुप्त समिति का कर्तृत्व बड़े महत्त्व का था। १८३१ में मैजिनी ने 'युवक इटली' नामक समिति का संगठन किया। इसके सत्र सदस्य यह प्रण कर रहे थे, कि वे इटली की राष्ट्रीय एकता और स्वतन्त्रता के लिये प्राणपण से प्रयत्न करेंगे। १८४८ की क्रान्ति के समय में इस समिति के सदस्यों ने महत्त्वपूर्ण भाग लिया। मैजिनी अपनी राष्ट्रीय भावना को केवल इटली तक सीमित नहीं रखना चाहता था। उसकी यह योजना थी, कि 'युवक इटली' के समान ही 'युवक हंगरी', 'युवक पोलैण्ड' और 'युवक आयरलैण्ड' का संगठन करे, और इन देशों में भी राष्ट्रीय एकता व स्वतन्त्रता की स्थापना हो। मैजिनी का स्वप्न था, कि सारे यूरोप में राष्ट्रीय भावना जगीभूत हो, और राजाओं के स्वेच्छाचारी शासनों का अन्त होकर 'युवक यूरोप' का प्रादुर्भाव हो।

मैजिनी का यह स्वप्न आगे चलकर पूर्ण भी हुआ। यूरोप के सभी देशों में राष्ट्रीयता के सिद्धान्त के अनुसार राज्यों का निर्माण हुआ, और इन नये राष्ट्रों में लोकतन्त्र सरकारों की स्थापना हुई। पर इसके लिये जनता को घोर संघर्ष करना पड़ा। उन्नीसवीं सदी के यूरोप के इतिहास पर हम अगले अध्यायों में जो प्रकाश डालेंगे, उसमें इसी संघर्ष का वृत्तान्त होगा।

### ३ नये शासन-विधानों का निर्माण

उन्नीसवीं सदी के यूरोप के राजनीतिक इतिहास पर विचार करने हुए हम बात की उम्मीद नहीं की जा सकती, कि इस युग में प्रायः सब देशों में नये शासन-विधानों का निर्माण किया गया। राष्ट्र मार्च के अनुसार १८०० से १८८० तक के अस्सी सालों में यूरोप के विविध देशों में जो नये शासन-विधान बने, उनकी संख्या ३०० से भी ऊपर थी। ये शासन-विधान उन नई राजनीतिक भावनाओं के मूर्तस्वरूप थे, जो इस समय यूरोप में जोर पकड़ रही थीं। जिन देशों में क्रान्ति द्वारा नई सरकार की स्थापना होती थी, उनमें तो नये शासन-विधान का निर्माण होना ही था, पर अन्य देशों में भी समझदार राजा लोग लोकमत की बढ़ती हुई शक्ति को अनुभव कर रियायत के रूप में शासन-विधान का निर्माण करते थे, ताकि जनता को आज़िज रूप में मनुष्य के रूप में मान्यता से देश की रक्षा की जा सके। पर यह ध्यान में रखना चाहिये, कि इन शासन-विधानों की सफलता इस बात पर निर्भर थी, कि जनता कितनी जागृत है, और उसमें नई प्रवृत्तियाँ कितनी जोर पकड़ चुकी हैं।

राष्ट्रीयता के सिद्धान्त के अनुसार राज्यों का निर्माण, निरपेक्ष स्वतन्त्राचार्य राज-सत्ता का अन्त और लोकतन्त्रवाद का विकास—ये तीन उन्नीसवीं सदी के राजनीतिक इतिहास की प्रमुख घटनाएँ थीं। इस काल के इतिहास का अनुशीलन करते हुए इन्हें दृष्टि में रखना आवश्यक है।

आर्थिक क्षेत्र में, इस युग में जागीरदारों और सामन्तों की शक्ति का ह्रास होकर पूँजी-पतियों और शिक्षित मध्यवर्गीय मजदूर बढ़ रहा था। इस समय आर्थिक शक्त के अतिरिक्त राजनीतिक शक्ति भी उनके हाथों में आ रही थी। उन्नीसवीं सदी के लोकतन्त्रवाद का अभिप्राय ही पूँजीपति और मध्यवर्गीय के शासन से था। पर धीरे-धीरे सर्वसाधारण—विमान और मजदूर जनता भी अपने महत्त्व का अनुभव करने लगी थी। वोट के अधिकार के विस्तार में सर्वसाधारण लोग भी राजनीतिक शक्ति के प्रयोग में हाथ बटाने लगे थे, और इस शक्ति का उपयोग कर वे अपने आर्थिक हितों की रक्षा में तत्पर हो रहे थे। उन्नीसवीं सदी के इतिहास के इस पहलू पर भी हम आगे चलकर यथास्थान अधिक विस्तार से प्रकाश डालेंगे।

## फ्रांस की तीसरी राज्यक्रान्ति

### १. राजसत्ता का अन्त

१८४८ की क्रान्ति का महत्व---नई और पुरानी प्रवृत्तियों में जिस प्रकार यूरोप भर में संघर्ष चल रहा था, उस पर हम पहले प्रकाश डाल चुके हैं। फ्रांस की पहली राज्यक्रान्ति ने गिन नवीन भावनाओं को उत्पन्न किया था, वे भयंकर विरोध के होते हुए भी धीरे-धीरे सफलता प्राप्त कर रही थी। मनुष्य जाति की दशा एक जीवित प्राणी के समान होती है। इस कारण उसमें आकस्मिक परिवर्तन नहीं हो सकते। क्रान्ति की प्रवृत्तियाँ भी एकदम मानव समाज को परिवर्तित नहीं कर सकती थीं। वे पुरानी प्रवृत्तियों में संघर्ष कर रही थी, और धीरे-धीरे सफल होती जाती थीं। पहली राज्यक्रान्ति ने फ्रांस को बहुत कुछ प्रदान दिया था। उसमें लोकतन्त्रवाद और गणतंत्र्यता के विचार भरीभाँति उत्पन्न हो गये थे। १८३० की दूसरी राज्यक्रान्ति ने इन सिद्धान्तों को भलीभाँति स्थापित कर दिया था, कि राजा चुनने का अधिकार जनता का है। देश का शासन जिस ढंग में होना है, वह निश्चित करना भी जनता का कार्य है। अब १८४८ की तीसरी क्रान्ति ने फ्रांस को राजनीतिक दृष्टि से बहुत आगे बढ़ा दिया। इस क्रान्ति का प्रभाव केवल फ्रांस तक ही सीमित नहीं रहा। पहली और दूसरी क्रान्तियों के मद्देन १८४८ की तीसरी राज्यक्रान्ति की लहरें भी यूरोप के बड़े भाग में व्याप्त हो गईं। १८३० की अपेक्षा १८४८ की क्रान्ति अधिक प्रचल तथा व्यापक थी। यूरोप भर में जो नई प्रवृत्तियाँ कार्य कर रही थी, वे १८४८ में एकदम बड़े वेग के साथ फूट पड़ी थी। यद्यपि क्रान्ति का प्रथम प्रस्फोट इटली में हुआ था, तो भी फ्रांस की क्रान्ति बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसीलिये हम सबसे पूर्व उसी का वर्णन करेंगे। उन्नीसवीं सदी में फ्रांस क्रान्तिकारी यूरोप का सबसे प्रमुख केन्द्र स्थान था।

लुई फिलिप के विरोधी दल---१८३० की क्रान्ति द्वारा फ्रांस की जनता ने स्वेच्छाचारी राजा चार्ल्स दशम को पदच्युत कर अपनी इच्छा से लुई फिलिप को राजगद्दी पर बिठाया था। शुरू शुरू में लुई फिलिप ने जनता की इच्छा के अनुसार शासन करने का प्रयत्न किया। पर उसे सफलता नहीं हुई। उसके विरोधियों की कमी नहीं थी। लुई फिलिप के विरोधियों को निम्नलिखित भागों में बाँटा जा सकता है। (१) बूँदों वगैरे के पक्षपाती—य लोग समझते थे, कि फ्रांस की राजगद्दी का वास्तविक स्वामी बूँदों वगैरे कोई व्यक्ति ही हो सकता है। चार्ल्स दशम का पौत्र अभी विद्यमान था। ये लोग उसे ही राजगद्दी का अधिकारी समझते थे, और उसे हेनरी पचम कहते थे। इस दल में प्रधानतया कुलीन और पुरोहित श्रेणियों के लोग थे। सख्या में कम होते हुए भी इनका प्रभाव कम नहीं था।



(२) नैपोलियन के पक्षपाती—इन का मत था, कि फ्रांस की राजगद्दी पर नैपोलियन के वंशजों का अधिकार होना चाहिये। इनकी सम्मति में 'नैपोलियन' इस नाम में ही कोई ऐसा जादू था, जो फ्रांस की सब समस्याओं को दान की बात में हल कर सकता था। (३) रिपब्लिकन डर—लुई फिलिप के मन्त्रों प्रवृत्त रिपब्लिकन दल के लोग थे। इनकी सम्मति में लुई फिलिप का शासन लोकतन्त्रवादी और क्रान्ति के सिद्धान्तों के अनुकूल नहीं था। ये १७९३ के क्रान्तिमय गणतन्त्रपूर्ण दिना को याद करते थे, और चाहते थे, कि एक बार फिर उसी दग की क्रान्ति हो। फ्रांस में पूर्ण लोकतन्त्र रिपब्लिक की स्थापना इनका उद्देश्य था। उन्हें लिये उन्होंने अनेक गुप्त समितियों का भी संगठन किया था। बड़े नगरों में सर्वत्र इन समितियों की शाखाएँ नियमान्त थीं।

इन समय फ्रेंच जनता का बड़ा भाग अपनी दशा में असंतुष्ट था। कल-कारवानों और बानों की उन्नति के साथ-साथ श्रमी लोगों की समस्या निरंतर बढ़ती जाती थी। ये श्रमी शहरों में रहते थे, और देशान्त के लोगों के समान भोले-भाले नहीं थे। राजनीतिक और सामाजिक समस्याएँ इनके लिये अज्ञेय रम्य नहीं थी। ये लोग कहते थे—हमने रिपब्लिक का जमाना देखा, नैपोलियन का शासन देखा, फिर बूढ़ों सम्राटों का स्पेच्छाचार भी देखा, हमारी हाथत तो किसी ने भी अच्छी नहीं हुई। यदि फ्रांस में वैसा राजस्त्ता या रिपब्लिक भी स्थापित हो गई, तो हमें क्या ? 'कोउ नृप होय हमें का हानी', 'चेरि छाडि नहि होउव रानी', इस बात के तथ्य को ये लोग खूब अच्छी तरह अनुभव करते थे। वैसा राजस्त्ता या रिपब्लिक किसी ने भी इन श्रमियों या किसानों की दशा को सुधारने का प्रयत्न नहीं किया था। लुई फिलिप के शासन में मध्यश्रेणी के लोग बहुत असंतुष्ट नहीं थे। मध्यश्रेणी ने ही उसे राजगद्दी पर ठिठाया था, और उन्हीं को वोट का अधिकार भी प्राप्त था। वही पार्लियामेंट के लिये भद्रम्य चुने जाते थे, टेम्पो का फैसला करते थे, और कानून बनाते थे। पर सर्वसाधारण लोग ? इन्हें वोट का अधिकार प्राप्त नहीं था, शासन में इनका कोई हाथ नहीं था। इनके लिये लुई फिलिप की पार्लियामेंट का शासन भी वैसा ही था, जैसा कि लुई सोलहवें का चार्ल्स दशम का। ये असंतुष्ट लोग हमेशा क्रान्ति के लिये तैयार रहते थे। क्रान्ति में इन्हें कोई हानि नहीं पहुँच सकती थी। इन्हें तो अव्यवस्था, परिवर्तन और क्रान्ति ने लाभ ही लाभ था। रिपब्लिकन दल को इनका बड़ा भरोसा था। क्रान्ति शुरू होते ही ये लोग उसमें जी-जान से सम्मिलित हो सकते थे।

लुई फिलिप के शासन का अन्त करने में इन किसानों और मजदूरों का ही हाथ नहीं था, उदार विचारों के पट्टे लिये समझदार लोग भी उसके विरुद्ध थे। धीरे-धीरे लुई फिलिप का शासन भी पुराने स्पेच्छाचारी एकतन्त्रत्व की ओर झुका जाता था। १८३० की क्रान्ति की लहर ने जब पोलैण्ड, जर्मनी और इटली में विद्रोह की अग्नि को भड़का दिया, तो उदार विचारों के ये लोग उनकी सहायता करने के पक्ष में थे। वे आशा करते थे, कि लुई फिलिप—जिन्होंने कि क्रान्ति के कारण ही राजगद्दी प्राप्त की है, अवश्य ही अन्य देशों के क्रान्तिकारियों से सहायता पहुँचाने में साफ इत्तफाक कर दिया। इसके अनिश्चित, लुई फिलिप का प्रधानमन्त्री गुडजो प्रोटेस्टेण्ट धर्म को माननेवाला था। उस

समय के फ्रांस में धर्म पर्याप्त महत्त्व रखता था। फ्रांस की रोमन धार्मिक अन्तता इस बात को नहीं सहन कर सकती थी, कि उनका प्रधानमन्त्री प्रोटेस्टेण्ट धर्म का अनुयायी हो। लुई फिलिप के पक्षपाती लोग बहुत कम थे। मध्ययुगीन के अमीर लोग ही, जिनका पार्लियामेंट में प्राधान्य था और जो वैध राजमता के नाम पर अपनी मनमानी करने में समर्थ हो रहे थे, उसके शासन के एकमात्र आधार थे।

**विद्रोह का प्रारम्भ**—रिपब्लिकन लोग लुई फिलिप के शासन का अन्त करने के लिये भरसक कोशिश कर रहे थे। उमको कत्तल करने के लिये भी छ बार प्रयत्न किया गया, पर सफलता नहीं हुई। कई स्थानों पर विद्रोह भी हुए, पर सरकार ने उन्हें सुगमता से शान्त कर दिया। राजा पर तरह-तरह के आक्षेप किये जान लगे, उसवारों में उनका मजक उड़ाया जाने लगा। इन सब बातों का परिणाम यह हुआ, कि राजा ने अपने विरोधियों को कुचलने के लिये प्रचण्ड उपायों को प्रयुक्त करने का निश्चय किया। जासूसों की सख्या बढ़ा दी गई, गुप्त भूमिगतियों को तोड़ दिया गया, प्रेम की स्वतन्त्रता छीन ली गई, और लोगों को स्वतन्त्रतापूर्वक सभा करने से रोक रखा गया। इन सब उपायों का परिणाम यह हुआ, कि जनता उत्तेजित हो गई, और आगिर १८४८ में एक बार फिर फ्रांस में विद्रोह की अग्नि प्रचण्ड हो उठी, जिसके कारण लुई फिलिप के शासन का अन्त हो गया और रिपब्लिक स्थापित हुई।

## २. क्रान्ति की प्रगति

**क्रान्ति का सूत्रपात**—यह क्रान्ति किस प्रकार हुई, इसका वर्णन करने की आवश्यकता है। १८४७ में सुधार के पक्षपाती उदार विचारों के लोगों ने फ्रांस भर में मनाए करने का निश्चय किया। इन मभाजों का उद्देश्य यह था, कि एक प्रार्थना-पत्र पर अधिक से अधिक लोगों के हस्ताक्षर करवाये जाए और इस प्रार्थना-पत्र द्वारा राजाकी सेवा में यह निवेदन किया जाए, कि देश को सुधारों की आवश्यकता है, और विशेष रूप से बोट के अधिकार को अधिक विस्तृत किया जाना चाहिये। इन सार्वजनिक सभाओं का परिणाम यह हुआ, कि सारे देश में राजनीतिक जागृति फैल गई, और सुधारों के लिये आन्दोलन अत्यन्त प्रचण्ड हो गया। सरकार को यह आन्दोलन सह्य नहीं था। हुन्म जारी किया गया, कि कोई सभा सरकार की अनुमति के बिना न की जावे। पर जनता इस प्रकार की मनमानी आज्ञा को यूही मान लेने वाली नहीं थी। २२ फरवरी, १८४८ को प्रसिद्ध अमेरिकन क्रान्तिकारी वाशिङ्गटन का जन्मदिन था। लोगों ने निश्चय किया, कि इस दिन पेरिस में एक भारी सहभोज का आयोजन किया जाए। एक जुलूस का भी संगठन किया गया। राष्ट्रीय स्वयसेवक दल और विद्यार्थी बड़े शौक से इस जुलूस की प्रतीक्षा कर रहे थे। पर लुई फिलिप की सरकार इस प्रदर्शन को कुचलने के लिये तुली हुई थी। उसने जुलूस और सहभोज—दोनों को रोक दिया। पर लोगो ने इस आज्ञा नहीं माना। जुन्म की मद तैयारियां हो चुकी थी। २२ फरवरी को प्रातःकार सरकार की आज्ञा का उल्लंघन कर बड़ी धूमधाम के साथ जुलूस निकाला गया। विद्यार्थी और मजदूर बड़े उत्साह के साथ जुलूस में शामिल हुए। 'सुधारों की जय' के नारों के साथ जुलूस ने पेरिस की गलियों में धूमना

प्रारम्भ किया। लोग नमस्त गते थे, एक बड़ी बान हो रही है, राजाज्ञा का खुल्लम-खुल्ला उत्थपन किया जा रहा है। पर गरम ने गरम रिपब्लिकन व साम्यवादी नेता को भी यह खयाल नहीं था, कि आज क्रान्ति हो जानेवाली है। क्रान्ति का किसी को स्वप्न में भी ध्यान नहीं था। जोज में भरे हुए लोग नरकारी हुक्म को तोड़ने के लिये निकल पड़े थे। अब एक बार लागो से आज के उत्थपन करने का मात्र प्रयत्न हो जाए, तो उसे ज़ाबू में रख सकना अशुभव हो जाता है। अन्यथा और विद्रोह की गतिधारा चलती हो गई। गुटों और द्वादमाओं का अपना काम करने का सुवर्णविमर हाथ लग गया, दूकानें लुटने लगी। बाजारों में मोनपिन्दी शुरू हो गई। दम् जाफ़स्मिक तूफान में राजा आन्ध्रगर्भकित रह गया। इस दशा में जनता को शान्त करने के लिये राजा को घोषणा करनी पड़ी, कि उनके मनोवाञ्छित सुधार स्वीकृत कर लिये जावेंगे।

लुई फिलिप का अन्त—सम्भवतः, १८८८ की शान्ति यही पर समाप्त हो जाती। क्रान्तिगरिया के लिये यही पर्याप्त था। उन्होंने राजा को जनता की इच्छा के सम्मुख झुकने के लिये विवश कर दिया था। वे वैध राजसत्ता में मनुष्य हो सकते थे। परन्तु इसी बीच में एक ऐसी घटना हो गई, जिसने बाईस फरवरी के प्रचण्ड आन्दोलन को एक भयंकर क्रान्ति के रूप में परिणत कर दिया। उस समय में फ्रांस का प्रधान मंत्री गुडज़ो था। लोग उसमें बहुत अमनष्ट थे। तेईस फरवरी को बहुत से लोग उसके मकान के चारों तरफ घेरे हो गये। सरकार को डर आ, कि कहीं गुडज़ो के भयान पर हमला न हो जावे। गोली चराने का हुक्म दिया गया। गालियों की बौछार से नेईस आदमी मरकर गिर गये, और तीस के लगभग बुरी तरह घायल हुए। क्रान्ति के समय पुलिस प्रायः इसी तरह की गलती किया करती है। भीड़ को तितर बितर करने के और भी तरीके थे, पर शक्ति के मद से मस्त हुई पुलिस ने निहत्थी जनता पर गोलियाँ चलाने में सकोच नहीं किया। गोला-बारी का समाचार सुनकर लोगो में उत्तेजना फैल गई। मृत लोग शहीद बना दिये गये। बड़ी धूम-धाम से उनकी लाशों का जुलूस निकाला गया। लाशों को देखकर लोग भडक गये। पहले दिन तो 'मुबारो की जय' के नारे लगाये जा रहे थे। अब उनकी जगह पर 'रिपब्लिक की जय' के नारे शुरू हुए। गोलाबारी का जिम्मेवार राजा को ठहराया गया, और जनता राजसत्ता का ही अन्त कर देने के लिये उतावली हो उठी। बाईस फरवरी को लोग वैध राजसत्ता में मनुष्य थे। पर अगले दिन ? गोली चल चुकने के बाद ? राजसत्ता के अन्त और रिपब्लिक की स्थापना के अतिरिक्त अन्य कोई बात उन्हें सन्तुष्ट नहीं कर सकती थी।

चौथीस फरवरी को पेरिस भर में लड़ाई शुरू हो गई। बाजारों और गलियों में मोर्चा-बन्दी कर ली गई। कुछ मिश्रकर १५०० मोर्चे बनाये गये थे। दीवारों पर बड़े-बड़े इस्तिहार चिपकाये गये। उनमें लिखा था—“लुई फिलिप भी हमें उसी तरह कत्ल करता है, जैसे दसवां चातस करता था। लुई को भी चार्म के पाप भेज दो।” लोग हथियारों की दूध में निकल पड़े। जो कुछ हाथ में आया, वही लेकर क्रान्ति के वीर राजसत्ता के अन्त और रिपब्लिक की स्थापना के लिये पेरिस की गलियों का चक्कर काटने लगे। राजा ने सिपाहियों को हुक्म दिया—लोगों को गोली से उड़ा दो। पर सिपाहियों ने गोली चलाने से

उत्कार कर दिया। क्रांति की भावनाओं से मिणाही भी अछूते नहीं बने थे। क्रांतिकारियों की भीड़ ने तुलुसरी के राजपासाद को बर लिया। राजमहल की विडकियों पर गोलियों की बाछार होने लगी। लुई फिलिप बचटा गया। जब राज्य को छोड़ कर भाग जाने के सिवा अन्य कोई मार्ग उसके सम्मुख न था। अपने पोते 'पेरिस के काउण्ट' को राजगद्दी पर बिठा कर उसने फ्रांस से भाग जाने का निश्चय किया। लुई ने अपना वेश बदल लिया, और अपने को 'गोल्ड स्मिथ' बताकर वह ग्रेट ब्रिटेन पहुचने में सफल हो गया। प्रजातन्त्री गृहजो ने भी उसका अनुसरण किया। इस बीच में क्रांतिकारियों की भेंट राजपासाद की गोदने-फोडने से लगी हुई थी। झूल के सम्पूर्ण साज सामान को छूट दिया गया। राजमहामन को आग लगा दी गई। लोग कहते थे—इस गद्दी की त्यागपत्र है ? फ्रांस में अब सदा के लिये रिपब्लिक ही कायम रहेगी।

**सामयिक सरकार**—राजसत्ता का अन्त हो गया। उसकी जगह अब नवीन सरकार के स्थापित करने की समस्या सम्मुख उपस्थित हुई। १८४८ की यह क्रांति अकस्मात् ही पाठभूत हो गई थी। लोग इसके लिये तैयार नहीं थे। इसलिए लुई फिलिप के फ्रांस छोड़ कर ग्रेट ब्रिटेन भाग जाने के बाद विविध दलों के लोग भावी सरकार का निर्माण करने के लिये विचार करने लगे। साम्यवादी रिपब्लिकन दल के नेता पूर्वी पेरिस के गेट स्ट्रिट में एकत्रित हुए। उनका खयाल साम्यवादी दल की रिपब्लिक स्थापित करने का था। साम्यवाद के गल्ले झण्डे को फहराते हुए उन्होंने उद्घोषित किया, कि फ्रांस में रिपब्लिक की स्थापना की जाती है। प्रत्येक नागरिक को हक है, कि वह मजदूरी प्राप्त कर सके। मजदूरों को अपने सघ बनाने का भी अधिकार है। इसी प्रकार से अन्य भी बहुत से साम्यवादी सिद्धान्तों को उद्घोषित किया गया। जब पूर्वी पेरिस में साम्यवादी लोग अपने दल की रिपब्लिक की उद्घोषणा कर रहे थे, उसी समय पेरिस के पश्चिमी भाग में सामान्य रिपब्लिकन दल के नेता पुरानी राष्ट्र प्रतिनिधि सभा के भवन में एकत्रित हुए। उन लोगों ने भी राजसत्ता का अन्त करके रिपब्लिक के स्थापित होने की उद्घोषणा की। आसिर, दोनों दलों के लोगों की सम्मिलित बैठक हुई। इसमें सामयिक सरकार का निर्माण किया गया, जो निश्चय हुआ, कि स्थिर रूप से रिपब्लिकन सरकार का महत्त्व करने और नवीन ज्ञान-विद्यान का निर्माण करने के लिये एक राष्ट्रीय महामन्त्र का नियुक्ति कराया जावे। इस महामन्त्र के लिये प्रतिनिधि चुनने का अधिकार फ्रांस के प्रत्येक वालिक पुरुष को दिया गया। ५ मार्च १८४८ का दिन निर्वाचन के लिये निश्चित किया गया। इस सामयिक सरकार के प्रमुख सदस्य लामार्तीन, लुई ब्ले, लेदु रोला और अरागो थे।

**साम्यवादी व्यवस्था**—राष्ट्रीय महामन्त्र के निर्वाचन और स्थायी सरकार को प्रतीक्षा किने बिना ही सामयिक सरकार ने मुद्रों का कार्य प्रारम्भ कर दिया। सामयिक सरकार में साम्यवादी लोगों का बहुत जोर था, क्योंकि फ्रांस का प्रमुख साम्यवादी अर्बेगास्त्री लुई ब्ले इस सरकार में 'सार्वजनिक कार्यसचिव' के पद पर नियुक्त था। इस सरकार ने अपनी साम्यवादी योजनाओं को क्रियान्वित रूप से क्रिया में परिणत किया। वेकार मजदूरों को काम दिवाने के लिये 'राष्ट्रीय कारखाने' की स्थापना की गई। जो आदमी चाहे, मजदूरों की 'राष्ट्रीय सेना' में भरती हो सकता था। राज्य के पास इन वेकार मजदूरों के लिये कोई काम न

था, पर उहे मनुष्ट करने के लिये ही नये-नये कार्यों की सृष्टि की गई। लाई रोदने और किले बनाने के लिये सभा रुपये गोज के हित्नात्र से प्रत्येक आदमी को मजदूरी दी जाने लगी। पहच प्रती मर्या में ब्रेकार गोज राष्ट्रीय मजदूर मेना में मरती हुण। बीरे-बीरे इन सैनिकों की मर्या एक शाल के भी ऊपर पहुच गई। मर्या राज्य से अधिक रूपया प्रतिदिन वेवल पेरिस के ब्रेकारों को मनुष्ट करने के लिये अनावश्यक कार्या पर खर्च किया जाने लगा। राज्य के पास अनन्त धन नहीं था, पर ब्रेकारों की मर्या अनन्त थी। 'राष्ट्रीय मजदूर सेना' सरकार के लिये एक सम्म्या बन रही थी। परन्तु मापत्रिक सरकार में साम्यवादी ढल का जोर था। उम्मे असतुष्ट करने का साहस पर्यकार को नहीं हो सकता था। जागिर, समझदार रिपटिब्लन नेनाओ ने एक मोचनपूर्ण चाल मर्या। उन्होंने प्रस्ताव किया, कि मजदूरों की दशा का सुधार करने के लिये एक पदम् उपसमिति का निर्माण कर दिया जावे, जो विशेष रूप से इसी कार्य में लगी रहे। लुई ब्ला को इन उपसमिति का प्रयास बनाया गया। साम्यवादियों ने समझा, इस उपसमिति द्वारा हम अपने उद्देश्य को भलीभांति पूर्ण कर सकेंगे। पर यह उनकी भारी भूत थी। वस्तुतः, इस उपसमिति ने कारण जगका प्रभाव सरकार में कम हो गया। ये मजदूरों ने कार्य करने, सुन्दर-सुन्दर व्याख्यान देने और अपने उदात्त मिटानों की व्याख्या करने में मग्न हो गये। अपनी योजनाओं को क्रिया में परिणत करने के लिये उन्हें धन की आवश्यकता थी, पर धन उनके पास नहीं था। धन सरकार की स्वीकृति के बिना नहीं मिल सकता था और सरकार में साम्यवादियों का प्रभाव कम हो गया था। तब वे अपनी योजनाओं को स्वीकृत नहीं करा सकते थे।

मजदूर उपसमिति ने अपना कार्य गजे जोर-शोर से प्रारम्भ किया। एक मार्च के दिन मजदूर पार्लियामेंट की योजना तैयार हुई। उसके लिये प्रत्येक व्यवसाय के प्रतिनिधि बुलाये गये। इस मार्च को मजदूर पार्लियामेंट का अधिवेशन प्रारम्भ हुआ। पार्लियामेंट के लिये वह भवन चुना गया, जिसमें पहले कुर्गिन मरदारों की सभा का अधिवेशन हुआ करता था। यह वही भवन था, जिसमें पहले अनेक बार मजदूरों के विरुद्ध अनेकविध कानूनों का निर्माण हुआ था। इसी भवन में कुर्गिनो के विशेष अधिकारों की रक्षा के लिये कितने ही प्रयत्न किये जा चुके थे। परन्तु १० मार्च, १८४८ के दिन इस शानदार भवन में मजदूरों की दशा को सुधारने के लिये उगल सोचे जा रहे थे। कितना महान् और अद्भुत परिवर्तन था। लुई ब्ला अपने जादेश को न रोक सका। अपने प्रारम्भिक भाषण में उसने कहा— 'जिन आसनों पर पहले गोटे किनारियों में विभूषित कोट पहने हुए लोग विराजमान हुआ करते थे, आज उन पर मैं क्या देखना हूँ? आज उन पर ते लोग बैठे हैं, जिनके कपड़े रमानदार मेहनत के कारगाहों-चिथटे हो गये हैं।' मजदूर पार्लियामेंट ने अपना कार्य बड़े उत्साह से प्रारम्भ किया। सम्भवतः, यह पत्रला ही अवसर था, जब कि फ्रांस भर के मजदूरों के प्रतिनिधि अपनी सम्म्याओं पर विचार करने के लिये एक स्थान पर एकत्रित हुए थे। पर यह पार्लियामेंट बहुत कुछ नहीं कर सकी। इसके पास योजनायें तो बहुत थी पर रुपये का गर्वथा अभाव था। लुई ब्ला चाहता था, कि मजदूरों की सहयोग समिति कायम की जावे, जिनके सदस्य अपनी पैदावार के अपने आप मालिक हों। पर रुपये के अभाव में वह क्या करता? वह असहाय था।

### ३. फ्रांस की द्वितीय रिपब्लिक

राष्ट्रीय महासभा—उपर राष्ट्रीय महासभा का निर्वाचन हो चुका था। चार सई को इस महासभा का अधिवेशन प्रारम्भ हुआ। महासभा के बहुमन्यक सदस्य सामान्य रिपब्लिकन तल के थे। साम्यवादी तल के प्रतिनिधि बहुत कम थे। फ्रांस के देहाती लोगों को साम्यवादी योजनाओं में कोई सहानुभूति नहीं थी। साम्यवाद लोगों के लिये अभी एक नया पिढान्त था। उसका प्रचार अभी पेरिस के मजदूरों में ही हुआ था। पेरिस के बाहर के सर्वसाधारण लोग उसे सर्वथा उगेडा की दृष्टि में देखते थे। यही कारण था, कि नवीन प्रतिनिधियों ने देश के लिये शासन-विधान तैयार करने में पूर्व 'राष्ट्रीय कारखानों' और 'राष्ट्रीय मजदूर सेना' के सम्बन्ध में व्यवस्था करने का मकल्य किया। इन बेकार मजदूरों पर राज्य को प्रतिदिन सवा लाख के लगभग रुपये खर्च करने पड रहे थे। अन्त काल तक इतना रुपया एक अनावश्यक कार्य पर खर्च करते रहना फ्रांस की शक्ति में बाहर था। इसलिये राष्ट्रीय महासभा ने निश्चय किया, कि 'राष्ट्रीय कारखानों' को बन्द कर दिया जावे, और मजदूर सेना बर्खास्त कर दी जावे। इस निश्चय का परिणाम यह हुआ, कि लाख से अधिक आदमी एकदम बेकार हो गये। पेरिस के इन्ही लोगों ने १८४८ की राज्यक्रान्ति के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य किया था। राजमत्ता का अन्त कर रिपब्लिक की स्थापना करने में इनका बडा हाथ था। इन्होंने अनुभव किया, कि सरकार ने हमसे विश्वासघात किया है। ये गरीब बेकार लोग अब भूखे मरने लगे थे। ये कहते थे, रिपब्लिक की स्थापना से हमें क्या लाभ हुआ? लुई फिलिप के जमाने में हमारी जो दशा थी, वही अब भी है। क्रान्ति के बाद हमें जो काम मिला था, वह भी अब सरकार ने हमसे छीन लिया। वस्तुतः, इन लोगों के असन्तुष्ट होने के प्रबल कारण विद्यमान थे। इन्होंने सरकार का मुकाबला करने का निश्चय किया। यदि पहले इनकी सहायता में राजसत्ता का अन्त किया सकता था, तो अब रिपब्लिकन सरकार को भी ये अच्छा सवक सिखा सकते थे।

साम्यवादी क्रान्ति—बेकार मजदूरों ने विद्रोह कर दिया। पेरिस के उन मुहलो में जहा मजदूरों की बस्तिया थी, मोर्चाबन्दी कर ली गई। मजदूर लोग हथियार लेकर निकल पडे। तेईस जून से छब्बीस जून तक चार दिन निरन्तर पेरिस को गलियों में लडाई जारी रही। चार दिनों में दस हजार आदमी कतल हो गये। इस विद्रोह को शान्त करना सरकार के लिये सुगम कार्य न था। विद्रोह ने इतना प्रचण्ड रूप धारण कर लिया था, कि किसी एक व्यक्ति को एकाधिकारी (डिक्टेटर) बनाने की आवश्यकता अनुभव हुई। सेनापति कैविञ्जा को यह पद दिया गया, और उसने बडी क्रूरता से विद्रोह को शान्त किया। मजदूर लोग कुशल योद्धा नहीं थे, उन्हें हथियार चलाने का अच्छा अभ्यास नहीं था। इसके अतिरिक्त वे भूखे और नगे भी थे। सरकार की सघी हुई सेनाओं का मुकाबला कर सकना उनके लिये आसान बात न थी। वे परास्त हो गये। सरकार ने उनसे भयकर बदला लिया। बिना किसी मुकदमे के, चार हजार से अधिक आदमियों को देशनिकाला दे

दिया गया। अनेक मजदूर नताओं को बाजार के बीच में गोली से उड़ा दिया गया। ग्यारह हजार आदमी जेल में डाल दिये गये। मजदूर दल के वत्तीस अखबारों को बन्द कर दिया गया। उनके सम्पादकों और लेखकों को कठोर सजाए दी गई। सम्भवतः, इतिहास में समाजवादी क्रान्ति का यह प्रथम विस्फोट था। बीसवीं सदी में इस ढंग की अनेक क्रान्तियाँ रूस, चीन और पूर्वी यूरोप के अनेक देशों में हुई, और उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई। राजनीतिक स्वतन्त्रता के साथ-साथ आर्थिक स्वतन्त्रता की स्थापना के लिये यह पहला प्रयत्न था, जिसका सूत्रपात फ्रांस में हुआ। पर इस समय इसे सफलता नहीं प्राप्त हो सकी। मजदूर-विद्रोह शान्त हो गया, पर सरकार के इन अत्याचारों का परिणाम यह हुआ, कि गरीब मजदूर लोग रिपब्लिकन दल में सर्वथा विमुक्त हो गये। अब फ्रांस की जनता दो भागों में विभक्त हो गई—मध्य श्रेणी के लोग और सर्वसाधारण गरीब लोग। इस समय राजमत्ता मध्यश्रेणी के हाथ में थी। वे गरीब मजदूरों को घृणा की दृष्टि से देखते थे। राज्यक्रान्ति ने एतन्त्र राजमत्ता का तो अन्त कर दिया था, पर अभी शासनसूत्र सर्वसाधारण जनता के हाथ में नहीं आया था। मनुष्य जाति ने लोकसत्ता की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम तो उठाया था, पर लोकसत्ता का वास्तविक आदर्श उनकी पहुँच से अभी काफी दूर था।

नया शासन-विधान—इस ढंग में मजदूरों की समस्या का हल कर राष्ट्रीय महा-सभा नवीन शासन-विधान तैयार करने के कार्य में व्यापृत हुई। प्रथम प्रश्न यह था, कि शासन का प्रकार क्या हो? महामभा में कुछ लोग राजसत्ता के भी पक्षपाती थे। परन्तु उनकी संख्या बहुत कम थी। इसलिए यह बात तो सुगमता से ही निश्चित हो गई, कि शासन का प्रकार रिपब्लिकन रहेगा। साम्यवादी सिद्धान्तों का निराकरण करने के लिये यह बात भी उद्घोषित की गई, कि सम्पत्ति पर वैयक्तिक अधिकार अक्षुण्ण रखा जायगा। इनके अतिरिक्त, साम्यवाद का स्पष्ट रूप से भी किरोध किया गया। नवीन शासन-विधान में कानून बनाने का कार्य एक राष्ट्रप्रतिनिधि सभा के सुपुर्द किया गया, जिसके सदस्यों की संख्या ७५० रखी गई। प्रतिनिधि सभा के सदस्य तीन वर्ष के लिए चुने जावें, यह व्यवस्था की गई। इस एक सभा को कानून बनाने के सम्पूर्ण अधिकार दे दिये गये। इसका नियन्त्रण करने के लिए किसी दूसरी सभा की रचना नहीं की गई। शासन-विभाग का अध्यक्ष राष्ट्रपति को बनाया गया, जिसे जनता के वोटों द्वारा चार वर्ष के लिये निर्वाचित किये जाने की व्यवस्था की गई। क्रान्ति के सिद्धान्तों की फिर से उद्घोषणा की गई। दान प्रथा को उखाड़ा गया और यह निश्चय किया गया, कि राजनीतिक अपराधों के लिये किसी व्यक्ति को प्राणदण्ड न दिया जा सके।

राष्ट्रपति नेपोलियन—नवीन शासन-विधान चार नवम्बर को बनकर तैयार हुआ। अब प्रश्न यह था, कि राष्ट्रपति के पद पर किस व्यक्ति को निर्वाचित किया जावे। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिये १० दिसम्बर, १८४८ का दिन निश्चित किया गया। इस महत्वपूर्ण पद के लिये प्रमुख उम्मीदवार तीन व्यक्ति थे—लेदु रोला मजदूर दल का उम्मीदवार था। सेनापति कैबिजा रिपब्लिकन दल की तरफ से खड़ा हुआ था। यह वही सेनापति था, जिसने जुलाई के मजदूर-विद्रोह को बड़ी क्रूरता के साथ शान्त किया था। इनके

अतिरिक्त, रिपब्लिकन दल की ओर से ही एक अन्य भी उम्मीदवार था, जिम्का नाम लुई नैपोलियन था। यह प्रसिद्ध विजेता नैपोलियन प्रथम का भतीजा था। निर्वाचन में लुई नैपोलियन को सफलता प्राप्त हुई। उस अकेले को ५४ लाख वोट मिले, जबकि उसके प्रति-द्वन्द्वियों को कुल मिलाकर केवल २० लाख वोट प्राप्त हुए थे। नैपोलियन के नाम में कुछ ऐसा जादू था, जो उसकी मृत्यु के एक सन्ततिवाद भी उसके भतीजे की इम असाधारण सफलता में सहायक हुआ था। राष्ट्रपति निर्वाचित हो कर लुई नैपोलियन न रिपब्लिक के प्रति भक्ति की शपथ ली, और उद्घोषित किया—“फ्रांस ने जो कुछ इस समय स्थापित किया है, उसे गैर कानूनी तरीकों से परिवर्तित करने की जो कोई आदमी कोशिश करेगा, उसे मैं देश का दुश्मन समझूंगा।”

नैपोलियन ने स्वयं किस प्रकार अपनी इम प्रतिज्ञा का पालन किया, इस पर हम आगे चलकर प्रकाश डालेंगे। यहाँ इतना निर्देश कर देना पर्याप्त है, कि अपने मुप्रसिद्ध चर्चा की तरह उसने भी पहले रिपब्लिक के प्रधान की स्थिति में अपनी वैयक्तिक शक्ति का बढ़ाना प्रारम्भ किया, और बाद में वह धीरे-धीरे ‘सम्राट्’ के पद तक पहुँच गया। १८०४ में वह राष्ट्रपति चुना गया था, और १८५२ में वह सम्राट् बन गया। फ्रांस की दूसरी रिपब्लिक पूरे चार वर्ष तक भी कायम नहीं रह सकी। इतने बड़े में समय में ही रिपब्लिक का अंत होकर राजसत्ता की स्थापना हो गई। वस्तुतः, अभी तक भी फ्रांस की जनता ने रिपब्लिक और लोकसत्तावाद के महत्व को पूर्णतया अनुभव नहीं किया था। पर वे लोग जो सदियों से राजकीय मामलों को एक ऐसी चीज समझते थे, जो कि उनकी पहुँच से बाहर है, जिससे उनका कोई सम्बन्ध नहीं है, वे अब एकदम फ़ैमे बदल सकते थे। नैपोलियन सम्राट् बन गया, रिपब्लिकन दल की क्लबों में इस पर टीका टिप्पणी हो गई, कुछ अखबारों में चर्चा हो गई, पर सर्वसाधारण लोग ? उन्हें इससे क्या प्रयोजन था ?

पर इसमें सन्देह नहीं, कि १८४८ की राज्यक्रांति ने फ्रांस को लोकतन्त्र के मार्ग पर बहुत अधिक आगे बढ़ा दिया। इसी क्रांति में पहले पहल राजनीतिक क्रांति के साथ-साथ आर्थिक और सामाजिक क्रांतियों का भी सूत्रपात हुआ था। फ्रांस में कुछ समय तक साम्यवादी लोगों का जोर रहा। अन्य बहुत से अधिकारों की तरह मनुष्य का यह भी प्राकृतिक अधिकार है, कि वह अपनी रोजी कमाने के लिये मजदूरी प्राप्त कर सके—इस सिद्धान्त को पहली बार क्रिया में परिणत किया गया। वेशक, इसके लिये किया गया प्रयत्न बुरी तरह से असफल हुआ। पर इसमें आश्चर्य की क्या बात है ? मनुष्य जाति इतनी पुरानी होती हुए भी हमेशा एक बालक की तरह रहती है, जिसे एक नई चीज सीखने के लिये बार-बार गिरना पड़ता है। राजनीतिक समानता और स्वतन्त्रता मनुष्य जाति के लिये नई बातें थी—इन्हें सीखने में उसे कितनी देर लगी। अब तक भी फ्रांस उसे पूर्णतया नहीं सीख सका था। फिर आर्थिक और सामाजिक स्वतन्त्रता व समानता का तो प्रश्न ही क्या था ? ये बातें तो लोगों के लिये एक असम्भव तथा अक्रियात्सक कल्पना के अतिरिक्त और कुछ नहीं थी।

क्रान्ति की अन्य लहरों के समान १८४८ की राज्यक्रान्ति भी केवल फ्रांस तक ही सीमित नहीं रही। फ्रांस से एक प्रकार का ज्वालामुखी उठा था, जिसकी लपटों ने शीघ्र ही यूरोप के बड़े भारी हिस्से को व्याप्त कर लिया।



सोलहवा अध्याय

## क्रान्ति की तीसरी लहर

### १ आस्ट्रियन साम्राज्य में क्रान्ति का प्रारम्भ

मध्य यूरोप के मध्यमे प्राचीन तथा शानदार हाब्सबुर्ग राजवंश के अधीन मुख्यतया तीन प्रदेश थे— आस्ट्रिया, हंगरी और बोहेमिया। इनके अतिरिक्त इटली के कतिपय प्रदेश भी इसी राज्यवंश के अधीन थे। १८४८ की राज्यक्रान्ति इन विस्तृत प्रदेशों पर दावानल के समान प्रकट हुई, और कुछ देर के लिये ऐसा प्रतीत होने लगा, कि हाब्सबुर्ग वंश का प्राचीन वैभव अब खाक में मिल जायगा, और आस्ट्रिया के साम्राज्य की समाप्ति हो जायगी।

आस्ट्रियन साम्राज्य का स्वरूप—आस्ट्रियन साम्राज्य में क्रान्ति किस प्रकार हुई, इसका वर्णन करने में पूर्व यह स्पष्ट करना आवश्यक है, कि इस अद्भुत साम्राज्य का क्या स्वरूप था। आस्ट्रियन साम्राज्य में किसी एक जाति व राष्ट्रीयता का निवास नहीं था, बहुत से राष्ट्र उसके अन्तर्गत थे। बोहेना के पश्चिम के प्रदेश प्रधानतया जर्मन लोगों से आबाद थे। दक्षिण में कार्निओला, स्टीरिया, कैरिन्थिया, और इस्ट्रिया के प्रदेशों में स्लाव लोगों का निवास था। उत्तर में (बोहेमिया और मोरेविया में) चेक लोग बसते थे। उस की सीमा के प्रदेशों में पोल लोग आबाद थे। यह प्रदेश वस्तुतः पोलैण्ड का ही एक भाग था। उस अभागे देश के टुकड़े हो जाने के बाद यह आस्ट्रिया के हिस्से में आ गया था। हंगरी के राज्य में—यह राज्य आस्ट्रिया के अधीन न होते हुए भी वहाँ के राजा के अधिपत्य में था—केवल हंगेरियन या मघयार लोगों का ही निवास नहीं था, उनके अतिरिक्त उसमें रुमानियन, क्रोटियन और सर्बियन लोग भी बसते थे। आल्प्स की पर्वतमाला के दक्षिण में लोम्बार्डी और वेनेटिया के प्रदेश भी आस्ट्रियन सम्राट के अधीन थे, यद्यपि इनमें इटालियन लोगों का निवास था। इस प्रकार आस्ट्रियन साम्राज्य में जर्मन, चेक, स्लाव, हंगेरियन, पोल, क्रोटियन, रुमानियन, सर्बियन और इटालियन इन विविध प्रकार के लोगों की सत्ता थी। इन सबकी भाषा पृथक्-पृथक् थी। न केवल भाषा, पर मस्कृति, सभ्यता, नसल, जाति, रहन-सहन और इतिहास—सब दृष्टियों से ये एक दूसरे से भिन्न थे। इन विविध जातियों का एक शासन में रह सकना बड़ी अद्भुत बात थी। पुराने जमाने में तो यह बात बिल्कुल मामूली थी, क्योंकि उस समय लोगों में राष्ट्रीयता का भाव ही उत्पन्न नहीं हुआ था। पर अब उन्नीसवीं सदी में, नैपोलियन के युद्धों के बाद यूरोपियन जनता में राष्ट्रीयता की नवीन भावना की अनुभूति उत्पन्न हो चुकी थी। अब इन विविध जातियों में स्वभाग्य-निर्णय का विचार प्रचल हो गया था।

और इनके लिये किसी विदेशी स्वेच्छाचारी शासन के अधीन रह सकना सम्भव नहीं रहा था। इन सब प्रदेशों, में अब स्वतन्त्रता की भावना प्रादुर्भूत हो चुकी थी। उदार विचारों के लोग सब स्थानों पर अपना कार्य कर रहे थे।

शासन का प्रकार—आस्ट्रियन साम्राज्य का शासन भी जदभुत प्रकार का था। आस्ट्रिया में हाप्सबर्ग राजा फर्डिनन्द प्रथम का एकतन्त्र स्वेच्छाचारी शासन था। मन्त्री लोग केवल राजा के प्रति ही उत्तरदायी थे। राजा जिसे चाहता, मन्त्रिपद पर नियुक्त करता, जिसे चाहता बर्खास्त करता। कानून बनाने, नये टैक्स लगाने या राजकीय आमदनी को खर्च करने के लिये जनता की किसी भी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं थी। अखबारों और पुस्तकों पर पुलिस का कठोर निरीक्षण था। अध्यापक लोग शिक्षणालयों में क्या पढ़ाते हैं, थियेट्रो में क्या दृश्य दिखाये जाते हैं—इन सब बातों पर भी पुलिस कड़ी निगरान् रखती थी। सरकार को फिकर रहती थी, कि कोई नया विचार आस्ट्रिया में प्रवेश न कर जाय। लोगों को देश से बाहर जाने-आने की स्वतन्त्रता नहीं थी। प्रत्येक यात्री के लिये पासपोर्ट लेना आवश्यक था। इन बाधाओं का परिणाम यह था, कि आस्ट्रिया के विद्वान् पश्चिमी यूरोप के ससर्ग से सर्वथा वंचित थे। फ्रान्स और ब्रिटेन में जो नवीन विचार धाराएँ चल रही थी, आस्ट्रिया में उनका प्रवेश रोक दिया गया था। मँटरनिय बड़े अभिमान के साथ कहा करता था, कि वैज्ञानिक शैली आस्ट्रिया के विश्वविद्यालयों तक में प्रविष्ट नहीं हो सकी है। मध्यकाल की प्रायः सभी समस्याएँ अभी तक भी आस्ट्रिया में विद्यमान थी। कुलीन जमींदारों के अधिकार अक्षुण्ण बने हुए थे। किसानों को कोई स्वतन्त्रता व अधिकार प्राप्त नहीं थे। जमींदार की अनुमति के बिना वे अपना गांव तक को नहीं छोड़ सकते थे। चर्च की अवस्था भी वही थी, जो राज्यक्रान्ति में पूर्व फ्रान्स में थी। राजकीय पदों पर केवल रोमन कैथोलिक ही नियत किये जा सकते थे। चर्च का प्रभाव असाधारण था।

हंगरी आस्ट्रिया से पृथक् था। परन्तु आस्ट्रिया का राजा ही उसका भी राजा होता था। हंगरी में अब तक मध्यकाल की सामन्तपद्धति विद्यमान थी। सम्पूर्ण शासन-शक्ति कुछ कुलीन जमींदारों के हाथ में थी। ये लोग मनमानी तरीके से देश का शासन करते थे। नाम को हंगरी में पार्लियामेंट विद्यमान थी, जिसमें दो सभाएँ होती थी। द्वितीय सभा में बड़े जागीरदार सदस्य होते थे, और प्रथम सभा के लिए छोटे जागीरदार अपन प्रतिनिधि निर्वाचित करते थे। हंगरी की इस पार्लियामेंट में क्रोट, रुमानियन और स्लोवाक लोगों को प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं था। सर्वसाधारण हंगेरियन लोग भी शासन सम्बन्धी सब अधिकारों से वंचित थे। जनता भी कोई इच्छा रख सकती है, इस बात की कुलीन जागीरदारों को कल्पना तक नहीं थी। यह ध्यान में रखना चाहिए, कि पोल, चैक और स्लाव लोगों के प्रदेश आस्ट्रिया के राज्य के अन्तर्गत थे, और क्रोटियन, रुमानियन, सर्बियन और स्लोवाक लोगों के प्रदेश हंगरी के अधीन थे। इन दोनों राज्यों का निर्माण सर्वथा अस्वाभाविक तथा राष्ट्रीयता के सिद्धांत के प्रतिकूल था। इनमें केवल राष्ट्रीयता के सिद्धान्त का ही खून नहीं हो रहा था, अपितु लोकसत्तावाद का तो इनमें निशान तक भी नहीं था।

परन्तु विचार हवा की तरह होते हैं। कृत्रिम तरीकों से उन्हें रोक सकना सम्भव

नहीं होता। फर्डिनन्ड और मँटरनिख के सब प्रयत्नों के बावजूद भी समानता, स्वतन्त्रता और भ्रातृभाव के विचार आस्ट्रियन साम्राज्य में भी पहुँच चुके थे। वहाँ पर भी लोग स्वेच्छाचारी राजमत्ता का अन्त कर लोकतन्त्र शासन को स्थापित करने का स्वप्न ले रहे थे। यही कारण है, कि जब १८४८ में क्रान्ति की नई लहर प्रारम्भ हुई, तो आस्ट्रियन साम्राज्य की विविध जातियों में भी साहस का सञ्चार हुआ। वे भी स्वेच्छाचारी शासन से मुक्त होने के लिए उत्सुक हो उठी।

**मँटरनिख का पतन**—जिस समय २२ फरवरी, सन् १८४८ की फ्रेञ्च राज्य-क्रान्ति का समाचार मँटरनिख ने सुना, तो वह बहुत चिन्तित हुआ। उसने कहा—“मैं एक बूढ़ा हकीम हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ, कि माध्य और अमाध्य रोगों में क्या भेद होता है। यह बीमारी घातक है।” निस्सन्देह, मँटरनिख ठीक था। १३ मार्च, १८४८ को वीएना में एक जलूम निकाला गया। विद्यार्थी और मजदूर बहुत बड़ी सख्या में इसमें सम्मिलित हुए। ये लोग ‘मँटरनिख हाय-हाय’ के नारे लगाते जाते थे। आखिर, जलूस ने मँटरनिख के मकान को घेर लिया। मँटरनिखकी उमर साठ साल से ऊपर थी, उसके बाल पक चुके थे। वह समय के रूप को खूब पहचानता था। उसने ताड़ लिया, कि अब परत्याग करके आस्ट्रिया छोड़ जाने के सिवा अन्य कोई उपाय नहीं है। वह ग्रेट ब्रिटेन चला गया। उसका पुराना बूढ़ा दोस्त वेलिङ्गटन का ड्यूक उसका स्वागत करने के लिए तैयार था। दोनों बूढ़े मित्रों ने अपनी आयु के शेष दिन शान्ति के साथ व्यतीत किये। दोनों ही अपने जमाने में लोकतन्त्र प्रवृत्तियों के कट्टर दुश्मन रह चुके थे। निस्सन्देह, जिन्दगी के शेष के दिनों को व्यतीत करने हुए ये पुराने मित्र ‘घोर कलिकाल’ को कोसा करते थे और उन सुन्दर दिनों की याद करते थे, जब उनकी इच्छा के प्रतिकूल एक पत्ता तक भी नहीं हिल सकता था।

मँटरनिख के प्रस्थान का उत्सव वीएना में बड़ी धूम-धाम से मनाया गया। पुराने नमाने और स्वेच्छाचार के इस आधारस्तम्भ के पतन का समाचार सुनकर जनता को नभार प्रसन्नता हुई। अब राजा फर्डिनन्ड प्रथम शासन-सुधार करने के लिए बाधित हुआ। ग्रेन पर से कठोर निरीक्षण हटा लिया गया। सामन्तपद्धति के अवशेषों को नष्ट किया गया। कर्मीनों के विशेषाधिकार छीन लिये गये। नवीन शासन-विधान तैयार किया गया, और उसमें जनता को पर्याप्त अधिकार दिये गये। पर क्रान्तिकारी लोग इतने से ही मन्तुष्ट नहीं थे, वे पूर्ण लोकतन्त्र शासन स्थापित करने को उत्सुक थे। क्रान्तिकारियों के ज़ान्दोलन ने राजा घबराया। उसकी उमर पक चुकी थी, अंग शिथिल हो गये थे। प्रचण्ड विरोध को सह सकने की शक्ति उसमें नहीं रही थी। वह वीएना से भागकर इन्सब्रुक चला गया, और क्रान्तिकारियों को राजधानी में मनमानी करने का अवसर मिल गया।

**नवीन शासन-विधान और क्रान्ति की विफलता**—नवीन शासन-विधान तैयार करने का गिग गण्ट्रीय महासभा बुलाई गई। सब वालिग पुरुषों को इस महासभा के लिए प्रतिनिधि चुनने का हक दिया गया था। हंगरी के अतिरिक्त आस्ट्रियन साम्राज्य के सम्पूर्ण प्रदेशों के प्रतिनिधि इस महासभा में सम्मिलित हुए। बाईस जुलाई, १८४८ को वीएना में महासभा का अधिवेशन प्रारम्भ हुआ। महासभा में उदार विचारों के सदस्यों का बहुमत

या । पर राजसत्ता को सर्वथा नष्ट कर देने के पक्ष में बहुत कम सदस्य थे । आखिर, वृहत् के बाद यह निश्चय किया गया, कि आस्ट्रिया में वैध राजसत्ता की स्थापना की जावे । राजा को वापस लौट आने के लिए निमन्त्रण भेजा गया । अगस्त, १८१८ में वह अपनी राजधानी में लौट आया । अभी नये शासन-विधान को तैयार करने का कार्य समाप्त नहीं हुआ था, कि हंगरी, बोहेमिया, क्रोटिया और उत्तरी इटली में क्रान्तियों के समाचार जाने लगे । वीएना के लोग इन समाचारों को पढ़कर भडक गये । वे समझते थे, कि क्रान्ति का पूर्ण किया जाना चाहिये । ढीली-ढाली कार्यवाही में कुछ न बनेगा । गलियों और बाजारों में मोर्चाबन्दी शुरू हो गई, और सर्वसाधारण जनता हथियार लेकर निकल पड़ी । युद्ध-सचिव को लैम्प के एक गम्भे से बाधकर कत्ल कर दिया गया । यह दशा देख कर राजा फर्डिनण्ड फिर भाग पड़ा हुआ । वीएना में दुवारा क्रान्ति हो गई । राष्ट्रीय महामना वैध राजसत्ता की स्थापना के लिये जो कार्य कर रही थी, वह बीच में ही रह गया ।

यद्यपि राजा वीएना छोड़कर भाग गया था, पर इस बात उमने अधिक माहम प्रदर्शित किया । उसने सेना को हुंम दिया, कि विद्रोहियों को गोली में उड़ा दो । शाही फौज ने वीएना पर हमला किया । विद्रोहियों और फौज में बातायदा लड़ाई हुई । आखिर, युद्ध में क्रान्तिकारी परास्त हुए । ३१ अक्टूबर को शाही सेना ने वीएना जीत लिया, और आस्ट्रिया की क्रान्ति असफल हो गई । जनता ने अपने अधिकारों के लिये जो सिर उठाया था, उसे वरी तरह से कुचल दिया गया ।

पर यह नहीं समझना चाहिये कि १८४८ की क्रान्ति में आस्ट्रिया के क्रान्तिकारी पूर्णतया असफल रहे । मेटर्निख का अब सदा के लिये पतन हो गया था । यह कोई साधारण बात नहीं थी, क्रान्ति की यह भारी विजय थी । इतना ही नहीं, क्रान्ति को कुचलकर फर्डिनण्ड ने नवम्बर १८४८ में जब दुवारा वीएना में प्रवेश किया, तब उसे भी आवश्यकता अनुभव हुई, कि शासन-विधान की उद्घोषणा की जाय । निस्सन्देह, यह शासन-विधान जनता और क्रान्तिकारियों की इच्छा के अनुरूप नहीं था, पर इसके कारण कम से कम इतना तो हो ही गया था, कि आस्ट्रिया में एक बाकायदा शासन-विधान की स्थापना हो गई थी ।

**हंगरी में राज्यक्रान्ति**—आस्ट्रियन साम्राज्य में हंगरी की क्या स्थिति थी, इस बात पर पहले प्रकाश डाला जा चुका है । हंगरी में दो आन्दोलन चल रहे थे । (१) आस्ट्रिया के राजा की अधीनता से मुक्त होकर अपना पृथक् स्वतन्त्र राज्य स्थापित किया जाए, और (२) लोकतन्त्र शासन की स्थापना की जाय । हंगेरियन स्वाधीनता के आन्दोलन के प्रमुख नेता कॉस्सुथ और डीक थे । सरकार भरसक कोशिश कर रही थी, कि इस आन्दोलन को कुचल दिया जावे । शासनसुधार के पक्ष में व्याख्यान देना भी वहाँ जुर्म समझा जाता था । प्रेस के ऊपर कड़ा निरीक्षण था । पुस्तकों, अखबारों या पर्चों द्वारा किसी भी प्रकार राजनीतिक आन्दोलन नहीं किया जा सकता था । प्रसिद्ध हंगेरियन नेता कॉस्सुथ को इसलिये जेल की सजा दी गई, क्योंकि उसने हस्तलिखित रूप से नवीन राजनीतिक विचारों को फैलाने का प्रयत्न किया था । पर सरकार के अत्याचारों के बावजूद भी हंगरी में स्वाधीनता का आन्दोलन निरन्तर उन्नति करता गया । जिस समय

मार्च, १८४८ में पहली बार वीएना में विद्रोह हुआ, तो हंगेरियन लोगो में भी उत्साह उत्पन्न हुआ, और उन्होंने विद्रोह करने का सकल्प किया। इस दशा में आस्ट्रिया के सम्राट् को शासन-सुधार की माग को स्वीकार करने के लिये बाधित होना पड़ा। हंगरी के लिये एक पृथक् मन्त्रिमण्डल की रचना की गई। कॉस्सुथ और डीक उसके सदस्य बनाये गये। इतना ही नहीं, सामन्तपद्धति को नष्ट किया गया और कुलीनो के विशेषाधिकार छीन लिये गये। सब लोग कानून की दृष्टि में एक समान कर दिये गये, इस प्रकार हंगरी से मध्यकाल का अन्त हुआ, और क्रान्ति के सिद्धान्त क्रिया में परिणत किये गये। अब हंगरी को सरकार आस्ट्रिया से सर्वथा पृथक् हो गई, यद्यपि दोनों देशों का राजा एक ही रहा। नवीन शासन-विधान में भाषण, लेखन और मुद्रण की स्वतन्त्रता को स्वीकार किया गया। सब लोगो को यह अधिकार दिया गया, कि वे अपने विश्वासों के अनुसार धर्म का अनुसरण कर सकें। राजकीय इमारतों पर हंगरी का अपना राष्ट्रीय झंडा फहराने लगा, और हंगरी की राष्ट्रीय आकांक्षाएं पूरी हुई। क्रान्ति की जो लहर वीएना में असफल हो गई थी, वह हंगरी में बहुत कुछ सफल हो गई। वहां न केवल उदार शासन व वैध राजसत्ता का प्रारम्भ हुआ, अपितु हंगरी की सरकार आस्ट्रिया से सर्वथा पृथक् भी हो गई।

क्रान्ति की विफलता—परन्तु हंगरी के राज्य में अनेक ऐसी जातिया भी निवास करती थी, जो हंगेरियन लोगो में सर्वथा भिन्न थी। क्रोटियन, रुमानियन और सर्बियन लोगो को हंगरी की स्वतन्त्रता में कोई भी लाभ न था। नये शासन-विधान में इन्हें कोई भी अधिकार नहीं मिले थे। क्रान्ति की लहर ने इन पर भी असर डाला था। य भी अपनी राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिये आन्दोलन कर रहे थे। क्रान्ति के इस काल में इन जातियो ने भी अनेक विद्रोह किये। आस्ट्रियन सरकार इनकी सहायता कर रही थी। हंगरी की स्वाधीनता से आस्ट्रिया को बहुत नुकसान पहुँचा था। इसलिये आस्ट्रियन सरकार का खयाल था, कि विद्रोहियों की सहायता करने से हंगरी की हानि होगी। आस्ट्रिया को इन कार्यवाही का परिणाम यह हुआ, कि हंगरी ने आस्ट्रिया से पूर्णतया सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया। अब तक आस्ट्रियन राजा ही हंगरी का भी सम्राट् होता था। अब हंगेरियन लोगो ने अपने को पूर्णतया स्वाधीन उद्घोषित कर रिपब्लिक की स्थापना की, और कॉस्सुथ को अपना राष्ट्रपति निर्वाचित किया। इस पर आस्ट्रिया ने हंगरी के विरुद्ध वाक्यदा युद्ध की उद्घोषणा कर दी। रूस ने भी आस्ट्रिया का साथ दिया। इन दो शक्तिशाली राज्यों का मुकाबला कर सकने की सामर्थ्य हंगरी में नहीं थी। वह परास्त हुआ, और कॉस्सुथ टर्की भाग गया। यहाँ से वह ग्रेट ब्रिटन और अमेरिका गया। उसने भग्नक कोशिश की, कि ये देश हंगरी की सहायता करें। पर वह सफल नहीं हो सका। अपने देश की स्वाधीनता के लिये कोशिश करते-करते १८१४ में इटली उसकी मृत्यु हो गई। काम्थ तो हंगरी छोड़कर टर्की भाग जाने में समर्थ हुआ था, पर अन्य बहुत से नेता पकट लिये गये थे। उन्हें प्राणदण्ड दिया गया, और हंगरी फिर आस्ट्रिया के अधीन हो गया। वहाँ स्वाधीन शासन को नष्ट कर फिर से आस्ट्रियन शासन की स्थापना की गई। १८८८ में हंगरी में क्रान्ति सफल हो गई थी, पर एक वर्ष बाद ही पुराना जमाना फिर विजयी हो गया। हंगरी की स्वाधीन रिपब्लिक कुछ मास तक ही जीवित रह सकी। शीघ्र

ही वहा फिर आस्ट्रिया का आधिपत्य कायम हो गया ।

**चैक क्रान्ति—१८४८ की क्रान्ति** की लहर ने वोहेमिया पर भी प्रभाव डाला । १५ मार्च के दिन चैक देशभक्त बहुत बड़ी सख्या में प्राग में एकत्रित हुए । उन लोगो ने निश्चित किया, कि एक विशाल प्रार्थनापत्र तैयार किया जाय, और उसमें राजनीतिक अधिकारो और शासन-सुधार के लिये सम्राट से प्रार्थना की जाय । प्रार्थनापत्र तैयार कर, के चैक नेताओं की एक मण्डली ने सम्राट की मेवा में प्रस्थान किया । फॉडनड क्रान्तियों से घबराया हुआ था । उमने चैक लोगो के प्रार्थनापत्र को स्वीकृत कर लिया । परन्तु वोहेमिया की स्वाधीनता की समस्या बहुत जटिल थी । वोहेमिया में केवल चैक लोग ही नहीं बसते थे, जर्मन लोगो की सख्या भी वहा कम नहीं थी । ये जर्मन लोग वोहेमिया की स्वतन्त्रता का विरोध करते थे । वे समझते थे, कि यदि वोहेमिया स्वतंत्र हो जायगा, तो चैक लोग हमें कुचल देंगे । जर्मन लोगो के विरोध पर विचार करने तथा स्वतन्त्र चैक राज्य का संगठन करने के लिये प्राग में एक विशाल महामभा बुलाई गई । वोहेमिया भर से चैक तथा उनसे सम्बद्ध मोरेवियन, रुयेनियन, सर्बियन और क्रोटियन आदि जातियों के प्रतिनिधि इस महासभा में सम्मिलित हुए । अभी इस महामभा ने अपना कार्य समाप्त नहीं किया था, कि कुछ जोशीले नौजवानों ने प्राग में स्थित आस्ट्रियन सेनापति विन्डिशग्रेट्स के खिलाफ आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया । वे उसके विरुद्ध नारे लगाने लगे । लोगो को जोश आ गया । चैक जनता भड़क उठी, विद्रोह हो गया । प्राग की गलियो में लड़ाई प्रारम्भ हो गई । विन्डिशग्रेट्स के मकान पर हमला कर दिया गया । अब विन्डिशग्रेट्स को मौका मिला । उसने विद्रोह को शान्त करने के लिये भयकर उपाय प्रयुक्त किये । शहर पर गोलावारी की गई । विद्रोह को दबा दिया गया । वोहेमिया में क्रान्तिकारियो से बुरी तरह बदला लिया गया । जो शासन-सुधार किये गये थे, उन्हें भी वापस ले लिया गया । क्रान्ति असफल हो गई ।

इस प्रकार हाप्सबुर्ग सम्राट के सभी प्रदेशों में—आस्ट्रिया, हंगरी और वोहेमिया में १८४८ में क्रान्तियां हुई । पर कहीं पर भी वे पूर्णतया सफल न हो सकी । एतन्त्र स्वेच्छाचारी शासन ही सम्पूर्ण आस्ट्रियन साम्राज्य में कायम रहा । पर इतना निश्चित है, कि १८४८ की इस क्रान्ति की लहर ने सम्पूर्ण आस्ट्रियन साम्राज्य में सामन्तपद्धति तथा अन्य मध्यकालीन संस्थाओं को जबरदस्त धक्का पहुँचाया । जनता में क्रान्ति की भावना प्रादुर्भूत हो चुकी थी, और नये युग के अभ्युदय की स्वाभाविक प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई थी ।

## २. जर्मनी में क्रान्ति का प्रभाव

**जर्मन आन्दोलन का स्वरूप—**उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध में जर्मनी एक राज्य नहीं था । इस काल में जर्मनी में अनेक राज्य थे, जिनमें प्रमुख प्रशिया था । यद्यपि विविध जर्मन राज्य एक सघ में संगठित थे, पर यह राज्यसघ बहुत ही ढीलाढाला तथा अपूर्ण था । क्रान्ति की लहर जर्मनी में दो प्रकार से प्रभाव डाल रही थी । जर्मन देशभक्त एक तरफ तो अपने-अपने राज्यों में स्वेच्छाचारी राजसत्ता का अन्त कर जनता का शासन

स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे थे, दूसरी तरफ उनकी आकांक्षा सम्पूर्ण जर्मनी को दृढ़ सगठन में सगठित करने की भी थी। 'जर्मनी एक राष्ट्र है,' 'जर्मनी हमारी मातृभूमि है,' यह भावना प्रादुर्भूत हो गई थी, और जर्मन नवयुवक अपने देश की राष्ट्रीय एकता और स्वाधीनता के लिये उतावले हो रहे थे। १८४८ से पूर्व ही जर्मनी में नवीन विचारों का प्रवेश हो चुका था। परन्तु फ्रांस की तृतीय राज्यक्रान्ति द्वारा जब सम्पूर्ण यूरोप में नवीन उत्साह और साहस का संचार हुआ, तो जर्मनी भी उसके प्रभाव से वंचित नहीं रह सका।

**प्रशिया में क्रान्ति**—जस्ट्रियन प्रधानमन्त्री मेटर्निख के पतन का समाचार बर्लिन में तेरह मार्च, १८४८ के दिन पहुँचा। अत्र लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेटर्निख स्वेच्छाचारी एकतन्त्र शासन का आधार-स्तम्भ था। उसके टूट जाने के समाचार से जर्मन क्रान्तिकारियों का उत्साह द्विगुणित हो गया। लोग झुठठे हो गये। जुलूस बन गया। भीड़ राजमहल के चारों ओर एकत्रित हो गई। रिपब्लिकन लोगों में बड़ा जोश था। वे हमले के लिये जनता को भड़का रहे थे। प्रशिया के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने हुक्म दिया कि राजप्रसाद में लोगों को हटा दिया जाए। इसपर पुलिस ने गोली चला दी। कुछ लोग मारे गये। अब क्या था? जनता जोश में जा गई। रिपब्लिकन लोग हथियार लेकर निकल पड़े। सारे शहर में विद्रोहाग्नि भड़क उठी। लड़ाई प्रारम्भ हो गई। राजा ने जब गदर का समाचार सुना, तो घबरा गया। उसने प्रतिज्ञा की, कि जनता की सम्पूर्ण शिकायतें दूर कर दी जायेंगी, और वह स्वयं जर्मनी को एक सूत्र में सगठित करने के लिए यत्न करेगा। इस पर जनता शान्त हो गई। विद्रोह में जो लोग मारे गये थे, उनकी सख्या दो सौ थी। ये सब शहीद बन गये। सारे बर्लिन शहर में शहीदों का जुलूस निकाला गया। जब जुलूस राजप्रसाद के सम्मुख पहुँचा, तो लोगों ने राजा से कहा—“आओ, अपनी फौजों की करतूत देख जाओ।” राजा महल के एक झरोखे पर प्रकट हुआ। जनता फिर उत्तेजित हो गई। उन्होंने क्रोध से चिल्लाकर कहा—‘अपनी टोपी उतार लो’ राजा क्या करता? उस बेचारे ने अपनी टोपी उतार दी। लोग इतने पर भी सतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने फिर चिल्लाकर कहा—‘नीचे आओ।’ प्रशिया का राजा नीचे उतर आया। जनता के सम्मुख वह असहाय था। उसे मजबूर किया गया, कि शहीदों के सम्मुख सिर झुकाये, उनके प्रति सम्मान प्रकट करे। इतना ही नहीं, राजा की तरफ से यह आज्ञा भी प्रकाशित की गई, कि ‘शहीदों’ के कतल के लिये सारे शहर में शाक मनाया जावे। २८ मई, १८४८ को प्रशिया का नया शासन-विधान बनाने के लिये बर्लिन में सविधान परिषद् का आयोजन किया गया। परिषद् ने प्रशिया के लिये वैध राजसत्ता के सिद्धान्त को दृष्टि में रखकर सविधान तैयार किया। पर कुलीन जागीरदारों के विरोध के कारण यह सविधान क्रिया में परिणत नहीं हो सका। बाद में १८५० में राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने स्वयं अपने राज्य के लिये एक सविधान घोषित किया, जिसमें राजा के अधिकारों को कायम रखते हुए पार्लियामेंट की व्यवस्था की गई।

**अन्यत्र क्रान्ति**—प्रशिया के अतिरिक्त अन्य जर्मन राज्यों में भी क्रान्ति के चिन्ह प्रकट हुए। १८४८ के मार्च और एप्रिल—इन दो महीनों में जर्मनी के अधिकांश राज्यों में क्रान्तियाँ हुईं। प्रायः सर्वत्र एकतन्त्र शासनो का अन्त कर वैध राजसत्ता की स्थापना

की गई, और विविध जर्मन राज्यों में नवीन शासन-विधान तैयार किये गये। एकदम सम्पूर्ण जर्मनी में जागृति सी उत्पन्न हो गई।

फ्रांकोर्ट की राष्ट्रीय महासभा—नवीन विचार के लोग इतने से ही मन्तुष्ट नहीं थे। वे जनता के अधिकारों के साथ-साथ राष्ट्रीय एकता की स्थापना के लिये भी उत्सुक थे। इस उद्देश्य में सम्पूर्ण जर्मनी के उदार नेताओं ने फ्रांकोर्ट नामक नगर में एक राष्ट्रीय महामभा का मगठन किया। इसमें कुल मिलाकर ५६८ प्रतिनिधिममिलित हुए। १७ मई, १८४८ को फान गागर्न नामक राष्ट्रीय नेता के सभापतित्व में महामभा का अधिवेशन प्रारम्भ हुआ। अपने प्रारम्भिक भाषण में फान गागर्न ने उद्घोषित किया, कि हम लोग सम्पूर्ण जर्मनी के लिये एक शासन विधान का निर्माण करने के लिये यहाँ एकत्रित हुए हैं। राज्य की स्वामित्व शक्ति वस्तुतः जनता में निहित है, और हम लोगों ने जर्मनी के भाग्यनिर्णय का अधिकार जनता में ही प्राप्त किया है। महामभा में मुख्यतया दो दल थे, एक दल वैध और लोकतन्त्र राजमन्ता का पक्षपाती था, और दूसरा दल रिपब्लिक की स्थापना करना चाहता था। शासन-विधान का स्वरूप क्या हो, जनता के आचारभूत अधिकार कौन से निश्चित किये जावे—इन बातों की बहस में समाधारण देर लग गई। यह विलम्ब जर्मनी में नवीन प्रवृत्तियों की सफलता के लिये बहुत घातक था। क्रान्ति का जोश ठंडा पड़ रहा था। ज्यों-ज्यों देर होती जाती थी, लोगों की दृष्टि में फ्रांकोर्ट की राष्ट्रीय महासभा का महत्त्व भी कम होता जाता था। इसके अनिरिक्त, कुछ अन्य भी प्रश्न थे, जिनका निर्णय कर सकना बहुत कठिन था। अब तक जर्मन राज्यमन्त्र में आस्ट्रिया भी सम्मिलित था। पर आस्ट्रियन राज्य में बहुत से ऐसे प्रदेश भी अन्तर्गत थे, जिनके निवासी जर्मन जाति के नहीं थे। जर्मन राज्यसभ में उन प्रदेशों को सम्मिलित करना फ्रांकोर्ट में एकत्रित देशभक्तों को समुचित प्रतीत नहीं होता था। अतः उन्होंने यह निर्णय किया, कि नवीन जर्मन राज्यसभ में आस्ट्रिया के केवल उसी प्रदेश को सम्मिलित किया जाए, जिसमें जर्मन लोग बसते हैं। यह निर्णय राष्ट्रीयता की दृष्टि में ठीक था, पर साथ ही अक्रियात्मक भी था। आस्ट्रिया का कुछ हिस्सा जर्मन राज्यसभ में सम्मिलित हो, और शेष न हो—यह व्यवस्था कभी क्रिया में नहीं आ सकती थी। आस्ट्रिया का राजा भी इससे कभी सन्तुष्ट नहीं हो सकता था। एक अन्य प्रश्न यह था, कि सगठित जर्मनी का सम्राट् कौन हो ? अधिकांश लोग राजसत्ता के पक्षपाती थे, रिपब्लिक का पक्ष प्रबल नहीं था। अतः यह भी निर्णय करना आवश्यक था, कि सम्राट् के पद पर किसे अधिष्ठित किया जावे। इस ऊँचे पद के लिये दो उम्मीदवार थे—प्रशिया का राजा और आस्ट्रिया का सम्राट्। आस्ट्रिया को नाराज कर आखिर यह फैसला किया गया, कि प्रशिया के राजा को जर्मन राज्यसभ का सम्राट् बनाया जावे। परन्तु जब यह निर्णय प्रशिया के राजा के सम्मुख पेश किया गया, तो वह सन्तुष्ट नहीं हुआ। उसने क्रोध में भर कर कहा—“मैं असली राजमुकुट चाहता हूँ, फ्रांस में लुई फिलिप की तरह गन्दी नाली में उठाकर मुकुट को सिर पर रख लेना मुझे पसन्द नहीं है।” प्रशिया का राजा नहीं चाहता था, कि जनता के वोटों से, जनता की इच्छा से इस बात का फैसला हो कि उसे सम्राट् बनाया जाए। वह अपने बाहुबल से सम्राट् बनना चाहता था। मध्यकाल की यही



गौरवमयी परम्परा थी ।

असफलता—प्रशिया का राजा यदि जर्मनी का सम्राट् पद स्वीकार करने से इनकार कर देता, तो कोई बड़ी बात न होनी । पर उमने क्रान्ति तथा नई प्रवृत्तियों का खुल्लमखुला विरोध करना भी प्रारम्भ कर दिया । पिछले दिनो प्रशिया मे जो नवीन सुधार किये गये थे, वे सब वापस ले लिये गये । अन्य जर्मन राज्यों ने भी प्रशिया का अनुकरण किया । सभी जगह क्रान्ति को कुचलने का प्रयत्न प्रारम्भ हो गया ।

प्रतिक्रिया का प्रारम्भ—फ्राकफोर्ट की राष्ट्रीय महासभा परेशान थी । बना बनाया खेल बिगड रहा था । माल भर की मेहनत व्यर्थ जा रही थी । क्रान्तिकारियों के सम्मुख अब कोई मार्ग न था । जर्मनी मे लोकमतावाद तथा राष्ट्रीय एकता को स्थापित करने मे उन्हें भारी असफलता हो रही थी । निराश होकर उन्होंने विद्रोह का आश्रय लेने का निश्चय किया । अनेक स्थानों पर गदर हुए । पर प्रशिया की सेना उन्हें कुचल देने के लिये उद्यत थी । सेना ने बुरी तरह मे विद्रोहों को शान्त किया । इतना ही नहीं, प्रशियन सरकार ने हुसम दिया, कि राष्ट्रीय महासभा से प्रशियन प्रतिनिधि वापस चले आवें । अन्य अनेक राज्यों ने प्रशियाका अनुसरण किया । अब केवल १०५ प्रतिनिधि ही महासभा मे शेष रह गये । इन लोगों ने फ्राकफोर्ट को छोड कर स्टुटगार्ट मे अपना कार्य प्रारम्भ किया । पर वहा भी वे आराम से नहीं बैठ सके । वर्ट्म्बर्ग के राजा ने अपनी सेना को हुक्म दिया कि “राष्ट्रीय महामभा” को भग कर दे । १८ जून, १८४८ को ‘महासभा’ के अवशिष्ट प्रतिनिधियों को भी तिनर-वितर कर दिया गया । जर्मनी की जो नवीन प्रवृत्तिया फ्राकफोर्ट की राष्ट्रीय महामभा के रूप मे सगठित होकर प्रकट हुई थी, उन्हें बहुत कुछ सफलता भी प्राप्त हो रही थी । पर पुराना जमाना अभी बहुत प्रबल था, अन्त मे वही विजयी हुआ । प्रशिया का एकतन्त्र स्वेच्छाचारी शासन आखिर इन प्रवृत्तियों को नष्ट करने मे पूर्णतया सफल हो गया ।

१८४८ की क्रान्ति की लहर के बाद भी सम्पूर्ण जर्मनी मे एकतन्त्रस्वेच्छाचारी शासन होकाम रहे । राष्ट्रीय एकता की तरफ जो पग बढ़ाया गया था, वह भी सफल नहीं हुआ । पर इनमे सन्देह नहीं, कि नई प्रवृत्तियों की भावी सफलता के लिये मैदान अवश्य तैयार हो गया । यह नहीं समझना चाहिये, कि मन् १८४८ की क्रान्ति जर्मनी मे सर्वथा असफल रही, या फ्राकफोर्ट की राष्ट्रीय महामभा ने कोई कार्य नहीं किया । हम देखेंगे कि कुछ समय बाद ही जर्मनी राष्ट्रीय दृष्टि मे एक हो गया, और स्वाधीनता तथा लोकतन्त्र शासन की ओर भी पर्याप्त रूप मे अग्रसर हुआ । यह सब इतनी सुगमता से न हो सकता, यदि १८४८ की घटनाएँ उसके लिये मार्ग ताल न कर देती ।

### ३. इटली मे क्रान्ति की लहर

सम्पूर्ण इटली में क्रान्तियः—यह बात पहले स्पष्ट की जा चुकी है, कि वीएना की कांग्रेस के बाद उत्तरी इटली के अधिकांश भाग पर आस्ट्रिया का आधिपत्य था । इटालियन लोग न केवल स्वाधीनता के लिये प्रयत्न कर रहे थे, अपितु राष्ट्रीय एकता की स्थापना भी उनका प्रधान उद्देश्य था । मैटरनिख के पतन के बाद इटालियन देश-

भयतो मे अपूर्व साहस का संचार हुआ। सबसे पहिले, मिलान मे विद्रोह हुआ। मिलान नगरी से आस्ट्रियन सेना को परास्त कर बाहर निकाल दिया गया। धीरे-धीरे सम्पूर्ण लॉम्बार्डी आस्ट्रियन सेनाओं तथा कर्मचारियों मे खाली हो गया। मिलान का अनुसरण वेनिस् ने किया। वेनेटियन लोग भी विद्रोह के लिये मन्न हो गये। एक बार फिर वेनिस् की प्राचीन रिपब्लिक का उद्धार हुआ। सार्डिनिया के राजा चार्ल्स एल्बर्ट ने मिलान और वेनिस् के विद्रोहो मे क्रान्तिकारियों की सहायता की। क्रान्ति केवल उत्तरी इटली तक ही सीमित नहीं रही। धीरे-धीरे सम्पूर्ण इटली विद्रोहाग्नि मे उद्दीप्त हो गया। नेपल्स, रोम, टस्कनी और पीडमोन्ट—मध्य स्थानों पर जनता ने विद्रोह किये। नवीन गामन-विज्ञान की स्थापना की गई, और सर्वत्र वैध राजभत्ता के मिद्वान्त की विजय दृष्टिगोचर होने लगी। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय एकता के लिये भी उद्योग किया गया और सार्डिनिया के राजा को संगठित इटालियन राष्ट्र का नेता मान लिया गया। पोप पायस दशम और नेपल्स का वूर्वी वशी राजा भी राष्ट्रीय भावना की लहर मे बहकर सार्डिनिया के राजा को इटली का नेता मानने के लिये उद्यत हो गये। कुछ देर के लिये ऐसा नजर आने लगा, कि इटली की सब राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा पूर्ण होकर ही रहेगी।

आस्ट्रिया के साथ युद्ध—परन्तु अभी उपयुक्त समय नहीं आया था। पुराना जमाना अभी बहुत प्रबल था। आस्ट्रियन सेनाएँ कुछ देर के लिये परास्त अवश्य हो गई थी, पर उत्तरी इटली मे सदा के लिये उन्हें खदेड करना मुगम कार्य नहीं था। आस्ट्रियन सेनापति राडेत्स्की क्वाड्रिलेटरल नामक स्थान पर आश्रय लेकर इटालियन विद्रोह को शान्त करने की तैयारियाँ कर रहा था। यदि इटालियन लोग परस्पर मिलकर उसका मुकाबला करते, तो उनकी सफलता निश्चित थी। पर उनमे वास्तविक एकता अभी उत्पन्न नहीं हुई थी। सार्डिनिया का राजा चार्ल्स एल्बर्ट अकेला आस्ट्रिया को परास्त नहीं कर सकता था। यद्यपि कुछ समय के लिये ऐसा प्रतीत होने लगा था, कि इटली मे राष्ट्रीय एकता की स्थापना हो गई है, पर आस्ट्रिया के साथ युद्ध प्रारम्भ होने ही वह क्षणिक एकता काफूर की तरह उड गई। पोप पायस दशम ने कहा—हमारा काम शान्ति स्थापित करना है, युद्ध नहीं। आस्ट्रिया रोमन कैथोलिक चर्च का सबसे पक्का मित्र है, हम उससे किसी भी दशा मे लडाई नहीं कर सकते। नेपल्स के राजा ने भी पीठ फेर ली। टस्कनी ने भी सहायता करने से इनकार कर दिया। अब आस्ट्रिया की शक्तिशाली सेनाओं का मुकाबला करनेवाले रह गये—सार्डिनिया, लॉम्बार्डी, वेनेटिया, परमा और मोडना। इनके लिये आस्ट्रिया का मुकाबला कर सकना सुगम नहीं था। चार्ल्स एल्बर्ट के नेतृत्व में उन्होंने बड़ी वीरता से आस्ट्रिया का मुकाबला किया। पर वे परास्त हो गये और एल्बर्ट को सन्धि करने के लिये बाधित होना पडा।

रोम में क्रान्ति—इस बीच मे क्रान्ति की प्रवृत्ति इटली मे निरन्तर प्रबल होती जाती थी। इसी प्रवृत्ति से फ्लोरेन्स में रिपब्लिक की स्थापना हुई। खास रोम में भी विद्रोह हुआ। पोप का शासनाधिकारी रोस्सी कतल कर दिया गया। पायस दशम भाग खडा हुआ। उसे नेपल्स के राजा के यहा शरण लेने के लिये बाधित होना पडा। १८४९ के फरवरी मास में रोम मे राष्ट्रीय महासभा बुलाई गई, और पोप के शासन का अन्त कर रिपब्लिक की

उद्घोषणा कर दी गई ।

असफलता—उपर मॉडिनिया के राजा और आस्ट्रिया में सन्धि देर तक कायम न रह सकी। मार्च, १८४९ में फिर युद्ध आरम्भ हो गया। पर यह युद्ध देर तक जारी न रहा। पांच दिन में ही इसका फैमला हो गया। तेईस मार्च के दिन नोवारा के रणक्षेत्र में एल्वर्ट की बुरी तरह से पराजय हुई। उसने निराश होकर अपने लडके विक्टर एमेनुअल द्वितीय के पक्ष में राजगद्दी का परित्याग कर दिया। भविष्य में यही विक्टर एमेनुअल द्वितीय इटली की राष्ट्रीय एकता का संस्थापक बना। पर अब कुछ समय के लिये राष्ट्रीय एकता तथा स्वाधीनता के सब प्रयत्न असफल हो गये। विजयी आस्ट्रियन सेनाओं ने सम्पूर्ण इटली में क्रान्ति का विनाश किया। मिलान, वेनिस, फ्लारेन्स तथा रोम में जिन नवीन रिपब्लिकन राज्यों की स्थापना हुई थी, उन सब को नष्ट कर पुराने एकतन्त्र शासनो को स्थापित किया गया। रोम, टस्कनी और वेनिस में पुराने शासनो का पुनरुद्धार हुआ। अनेक राज्यों के नवीन शासन-विधानो को नष्ट कर दिया गया। पर आस्ट्रिया की सम्पूर्ण शक्ति विक्टर एमेनुअल द्वितीय के राज्य से नवीन शासनविधान को नष्ट न कर सकी। मॉडिनिया और पीडमोंट के इस नये राजा ने नवीन शासन-विधान को कायम रखा। इस राजा ने न केवल नवीन शासन-विधान को नष्ट नहीं किया, पर साथ ही इटली भर के उदार विचारों के लोगो को अपने दरबार में आश्रय भी प्रदान किया। सार्डिनिया का दरबार उदार तथा नवीन प्रवृत्तियों का एक महत्वपूर्ण आश्रयस्थान बन गया। इटालियन देशभक्त आशा करते थे, कि यही राजा उनके देश का उद्धार करेगा। निस्सन्देह, वे निराश नहीं हुए। किस प्रकार विक्टर एमेनुअल द्वितीय ने उनकी आशाओं को पूर्ण किया, इस पर हम आगे चलकर प्रकाश डालेंगे।

क्या १८४८ की क्रान्ति इटली में असफल हो गई थी? यदि ऊपर से देखा जाए, तो वह सफल नहीं हुई। पर यदि गम्भीर दृष्टि से विचार करें, तो उसने इटली की भावी राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिये मार्ग तैयार कर दिया था, और यह कोई कम बात न थी।

## ४ अन्य देशों पर क्रान्ति का प्रभाव

इंग्लैंड में चार्टिस्ट आन्दोलन—यूरोप का शायद ही कोई देश ऐसा रहा हो, जिस पर १८४८ की क्रान्ति की लहर ने प्रभाव न डाला हो। इंग्लैंड में शासन-सुधार के लिये जा आन्दोलन चल रहा था, १८४८ में उसे बहुत बल मिला। १८३२ में जो सुधार किये गये थे, उनसे केवल मध्य-श्रेणी के लोगो को ही अधिकार प्राप्त हुए थे। सर्व-साधारण जनता—किसानों और मजदूरों की उनसे कोई भी लाभ नहीं पहुँचा था। इसलिये १८४८ से पूर्व ही वहाँ और अधिक शासन-सुधार के लिये आन्दोलन प्रचल हो रहा था। १८३८ में 'चार्टिस्ट आन्दोलन' के नाम से एक नवीन आन्दोलन इंग्लैंड में प्रारम्भ हुआ था। इस समय फ्रामिस प्लेस ने सुप्रसिद्ध मंगना चार्टा के अनुकरण में एक नवीन चार्टर तैयार किया। इस चार्टर में मुख्यरूप से निम्नलिखित बातों की मांग की गई थी—वोट देने का अधिकार सब बालिग पुरुषों को दिया जाय। वोट गुप्त पद्धति (बैलेट) द्वारा दिये जावें। पार्लियामेंट के चुनाव के लिये देश को ऐसे निर्वाचक-मण्डलों में

विभक्त किया जावे, जिनमें एक-एक प्रतिनिधि निर्वाचित हो। 'हाउस आफ कामन्स' का सदस्य बनने के लिये सम्पत्ति की शर्त उठा दी जाय, और सदस्यों को निश्चित वेतन दिया जाय। १८३९ में श्रीमती लोगों की एक पार्लियामेन्ट लण्डन में हुई। इसमें भी एक प्रार्थनापत्र तैयार किया गया, जिस पर बाहर लाख लोगों के हस्ताक्षर कराये गये। इस प्रार्थनापत्र में देश की पार्लियामेन्ट में प्रार्थना की गई थी, कि चार्टर की मांग का स्वीकृत किया जाने। प्रार्थनापत्र को स्वीकृत करने का प्रश्न तो दूर रहा, हाउस आफ कामन्स ने उस पर विचार तक नहीं किया। परिणाम यह हुआ कि मार्चजनीक सभाओं और असबारी द्वारा चार्टर का आन्दोलन निरन्तर जारी रहा। १८४२ में एक नया प्रार्थनापत्र तैयार हुआ, जिस पर तीस लाख आदमियों के हस्ताक्षर कराये गये थे। पर इससे भी कोई लाभ नहीं हुआ।

विशाल प्रार्थनापत्र—यह स्थिति थी, जब १८४८ में फ्रांस में राज्यक्रान्ति की नवीन लहर प्रारम्भ हुई। इंग्लैण्ड में चार्टिस्ट लोग पत्रों में ही शासन-सुधार के लिये आन्दोलन कर रहे थे। उनका संगठन बहुत दृढ़ था। सब मिलाकर ५०० के लगभग चार्टिस्ट मीटिंग-हॉल इंग्लैण्ड में स्थापित थी। इनके सदस्यों की संख्या भी पचास हजार के लगभग थी। यूरोप की क्रान्तियों का समाचार सुनकर इनके उत्साह का ठिकाना न रहा। वे लोग नी कुछ कर दिखाने को उतावले हो उठे। सर्वत्र बड़ी-बड़ी सभाओं की आयोजना की गई। आन्दोलन ने अत्यन्त प्रचण्ड रूप धारण कर लिया। १० एप्रिल, १८४८ को लण्डन में एक बहुत बड़ी सभा बुलाई गई। इसमें पांच लाख के लगभग आदमी सम्मिलित हुए। एक तीसरा प्रार्थनापत्र तैयार किया गया, और उसपर साठ लाख आदमियों के हस्ताक्षर कराये गये। इतने लोगों के हस्ताक्षर करा सकना सुगम बात नहीं। मारे देश में प्रचण्ड आन्दोलन हो रहा था। लोग समझते थे, पना नहीं क्या होनेवाला है। एक बहुत बड़े जुलूम की योजना बनायी गई। पर उस समय के प्रधानमंत्री वेलिंग्टन के ड्यूक ने उनकी अनुमति नहीं दी। सरकार की ओर से अतिरिक्त पुलिस सगठित की गई। नये सिपाही भर्ती किये गये। इन सिपाहियों की संख्या एक लाख सत्तर हजार थी। सरकार की इस भारी ताकत का मुकाबला कर सकना चार्टिस्ट लोगों के लिये कठिन था। वे घबरा गये। जुलूम नहीं निकल सका। पर तीसरा प्रार्थनापत्र पार्लियामेन्ट के सम्मुख पेश किया गया। यह प्रार्थनापत्र साठ लाख दस्तखतों के कारण इतना बड़ा हो गया था, कि इसे ढोने के लिये छ गाड़ियों की जरूरत हुई थी।

असफलता—विवेचना के बाद मालूम हुआ कि प्रार्थनापत्र में बहुत से हस्ताक्षर जाली थे। इससे चार्टिस्ट लोग बहुत बदनाम हो गये। उनका आन्दोलन मन्द पड़ गया। चार्टिस्ट आन्दोलन एक बलबुले की तरह उठा था, और बलबुले की तरह ही वह फट भी गया। पर इसमें सन्देह नहीं, कि १८४८ में इंग्लैण्ड में भी क्रान्ति का भारी तूफान उठ खड़ा हुआ था। यद्यपि सरकार के मजबूत हाथों ने उसे शान्त कर दिया, पर चार्टिस्ट लोगों की जो मांगें थी, उनका पूर्ण होना अवश्यम्भावी था। कुछ वर्षों बाद ही वे सब क्रिया में परिणत हो गईं। इंग्लैण्ड के शासन-विधान के विकास पर हम एक पृथक् अध्याय में विशेष रूप से प्रकाश डालेंगे।

**हालैण्ड में शासन सुधार**—क्रान्ति की लहर ने हालैण्ड पर भी प्रभाव डाला। जनता की मांग थी, कि शासन सुधार किया जावे। हालैण्ड के राजा विलियम द्वितीय को लोकमत के सम्मुख मिर झुकाने के लिये बाधित होना पड़ा। एक कमीशन नियत किया गया, जिसे शासन में सुधार करने का कार्य सुपुर्द किया गया। इस कमीशन ने जो नवीन शासन-विधान तैयार किया, उसने हालैण्ड के एकतन्त्र शासन को वैध राजसत्ता के रूप में परिवर्तित कर दिया। इस नये शासन-विधान को जनता में स्वीकृत कराने के लिये राष्ट्रीय महामभा का अधिवेशन बुलाया गया। महामभा ने नये शासन-विधान को स्वीकृत कर लिया, और नवम्बर, १८४८ में वह क्रिया में भी परिणत कर दिया गया। नवीन शासन-विधान में मन्त्रिमण्डल को राष्ट्रप्रतिनिधि सभा के प्रति उत्तरदायी बनाया गया, धार्मिक विश्वासों और पूजा-पाठ की सब लोगो को स्वतन्त्रता दी गई, और जनता के जन्मसिद्ध अधिकार उद्घोषित किये गये। परिणाम यह हुआ, कि हालैण्ड का शासन भी एक लोकतन्त्रवैध राजसत्ता के रूप में परिवर्तित हो गया।

**स्विट्जरलैण्ड**—हालैण्ड की तरह स्विट्जरलैण्ड के शासन-विधान में भी १८४८ में अनेक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किये गये। इससे पूर्व वहाँ पर जो शासन-विधान विद्यमान था, वह १८१५ में बना था। स्विट्जरलैण्ड के विविध प्रदेशों (कैन्टनों) में शासनमूत्र कुछ जमीर लोगो के हाथ में था। जनता इस दशा से असन्तुष्ट थी। उदार विचारों के लोग उसको परिवर्तित करने के लिये आन्दोलन कर रहे थे। यही नहीं, वहाँ धार्मिक प्रश्न भी बड़ा विकट था। रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेन्ट लोगो में सब्ब विरोध था। लूसर्न, उरी और जुग—इन तीन कैन्टनों ने, जिनमें कि रोमन कैथोलिक लोगो की बहुसंख्या थी, शेप देश से पृथक् होकर अपने लिये एक कैथोलिक सघ का संगठन कर लिया था। उदार और राष्ट्रीय विचारों के लोग इससे बहुत चिन्तित थे। आखिर, कैथोलिक सघ को युद्ध द्वारा परास्त किया गया, और १८४८ में समस्त देश को नये सिरे से संगठित कर नवीन शासन-विधान की स्थापना की गई। स्विट्जरलैण्ड में जो शासन-विधान वर्तमान समय में प्रचलित है, उसका प्रधान टाचा १८४८ के क्रान्तिकारी साल में ही तैयार किया गया था।

**डेन्मार्क**—१८४८ की क्रान्ति की लहर ने डेन्मार्क पर भी प्रभाव डाला। वहाँ पर भी शासन-सुधार किये गये, और राजसत्ता को अनेक अंशों में लोकमत के अधीन कर दिया गया।

**अन्य देशों पर प्रभाव**—स्पेन, पोलैण्ड और आयरलैण्ड भी क्रान्ति की लहर से जूझते नहीं बचे। पोलैण्ड में अनेक स्थानों पर विद्रोह हुए, पर ये विद्रोह मामूली किस्म के थे। उनमें लोगो की स्थिति पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। आयरलैण्ड में भी विद्रोह हुआ, पर इंगलिश लोगो ने उसे बड़ी मृगमता से शान्त कर दिया।

इतना ही नहीं, क्रान्ति की लहर ने अटलांटिक सागर को पार कर अमेरिका पर भी जमर डाला। वहाँ दास-प्रथा को अन्त करने के लिए जो आन्दोलन चल रहा था, क्रान्ति की लहर से उसे बहुत बल मिला।

१८४८ में क्रान्ति की जो लहर उठी थी, वह सम्पूर्ण यूरोप पर एक प्रचण्ड तूफान के रूप में व्याप्त हो गई थी। मारा यूरोप उससे एक भयंकर भूकम्प के समान हिल गया

था। शक्तिशाली सम्राटों के राजसिंहासन डावाडोल हो गये थे, और मदियों के दृढ़मूल विशेषाधिकारों और विपमताओं को उसमें भारी आघात पहुँचा था। परन्तु फिर भी प्रायः सभी देशों में क्रान्ति असफल रही। पुराने जमाने की मर्यादाएँ और स्वेच्छाचारों राजशक्ति क्रान्ति को कुचलने में समर्थ रही। उस समय के लोग इसमें क्या परिणाम निकालते थे ? वे समझते थे, कुछ बिगड़े दिमाग हमेशा व्यवस्था और शान्ति को नग करने लिए उत्सुक रहते हैं। दुनिया तो हमेशा में ऐसी ही चली आ रही है, कुछ लोगों को शासन करना है, दूसरों को शासन में रहना है। बड़े लोग हमेशा बड़े ही रहेंगे। गरीब मजदूर उनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं ? पाचों उँगलियाँ तथा कभी बराबर हाँ सकती हैं ? निस्सन्देह, १८८८ की घटनाओं ने अन्तर्निगन्त्रा इन विचारों को सत्य सिद्ध कर दिया था। परन्तु वास्तविकता क्या थी ? अब एक मदी गुजर जाने के बाद हम क्या देखते हैं ? १८८८ के क्रान्तिकारी जो कुछ चाहते थे, वह सब कुछ तो किया में परिणत हो ही चुका है, पर दुनिया अब उसमें भी बहुत आगे बढ़ गई है। १८८८ के क्रान्तिकारी विचार आज अनेक जगहों में पिछड़े हुए लोगों के ग्याल प्रतीत होते हैं। मानव उन्नति का यही क्रम है। १८८८ की क्रान्ति की ठहर ने असफल होकर भी लोग में एक नवीन दृष्टि, नवीन कल्पना और नवीन भावना को उत्पन्न कर दिया था। क्रान्ति का उद्दिष्ट स्थान अभी बहुत दूर था। वहाँ एक दीड़ में नहीं पहुँचा जा सकता था। पर उसके लिए हाथ-पैर हिलाना तो अनिवार्य ही था। १८८८ में एक बार जनता ने पूरी कोशिश के साथ उस ओर भागने की कोशिश की। पर उसके हाथ-पैर पुराने जमान की जजीरो में जकड़े हुए थे। १७९३ और १८३० की तरह इस बार भी जनता की सम्पूर्ण शक्ति इन जजीरो को तोड़ने में ही खर्च हो गई। पर क्या इन जजीरो को तोड़ फेंकना और जरा देर के लिए हाथ-पैरों को खुलेतीर पर हिला-डुला करना सामान्य बात थी ? नहीं, क्रान्ति की यह कोई मामूली सफलता नहीं थी।

सतरहवा अध्याय

## नैपोलियन तृतीय का शासन

### १ सम्राट् नैपोलियन तृतीय का अभ्युदय

लुई नैपोलियन का प्रारम्भिक जीवन—१८४८ की राज्यक्रान्ति के बाद लुई नैपोलियन बोनापार्ट किम प्रकार फ्रेंच रिपब्लिक का राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ, इसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। लुई नैपोलियन का जन्म सन् १८०८ में टुइलरी के राजप्रासाद में हुआ था। उसका शैशवकाल बहुत ही सुख और वैभव के साथ व्यतीत हुआ था। उस समय फ्रांस का भाग्यविधाता नैपोलियन बोनापार्ट था। बोनापार्ट परिवार के सब व्यक्ति ऊँचे से उँचे राजकीय सम्मान प्राप्त कर रहे थे। लुई नैपोलियन का लालन-पालन भी राजकुमारों के समान हुआ। पर उसके सुख-वैभव के ये दिन देर तक न रहे। वाटर्ल् के रणक्षेत्र में परास्त हो जाने के कारण जब नैपोलियन का पतन हुआ, और पुराने वृद्धों राजवश के आधिपत्य का पुनरुद्धार किया गया—तब बोनापार्ट परिवार के व्यक्ति अत्यन्त दुर्दशाग्रस्त हो गये। १८१६ में जब लुई नैपोलियन की आयु केवल आठ वर्ष की थी, उसे फ्रांस छोड़कर विदेशों में चले जाना पड़ा। उसके यौवन का अधिकांश भाग स्विट्जरलैण्ड और जर्मनी में व्यतीत हुआ। अभी नैपोलियन बोनापार्ट का पुत्र “रोम का बादशाह” जीवित था। नैपोलियन के सम्पूर्ण भक्त उसी को अपना नेता मानते थे। ‘नैपोलियन’ इस नाम में एक अद्भुत जादू था। बहुत से लोग इस प्रकार के थे, जो फ्रांस में फिर नैपोलियन का आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। वे सब “रोम के बादशाह” का ही अपना नेता मानते थे। पर १८३२ में जब नैपोलियन द्वितीय या “रोम के बादशाह” की मृत्यु हो गई, तो नैपोलियन-दल का नेता लुई नैपोलियन बना। १८३२ के बाद सोलह वर्ष तक वह निरन्तर फ्रांस का भाग्यविधाता बनने के लिये षड्यन्त्र करता रहा। वह बड़ा उत्तम लेखक था। अपने लेखों में वह सदा यही प्रदर्शित करता था, कि मैं क्रान्ति का प्रबल पक्षपाती हूँ। नैपोलियन के नाम में एक अद्भुत जादू तो था ही, उसके अतिरिक्त लुई नैपोलियन के क्रान्तिकारी विचारों ने उसे और भी अधिक लोकप्रिय बना दिया था। १८४० में नैपोलियन प्रथम के भौतिक अवशेष सेन्ट हेलेना से पेरिस लाये गये। उस समय सम्पूर्ण फ्रांस में असाधारण रूप से उत्साह तथा जोश का संचार हुआ। जनता वीरो की हमेशा पूजा करती है। नैपोलियन के गौरवमय कृत्यों को फ्रेंच लोग कैसे भुग्न सकते थे। उन्होंने अपने राष्ट्रीय वीर की अस्थियों के प्रति असाधारण सम्मान और श्रद्धा का प्रदर्शन किया। इस दशा में लुई नैपोलियन का महत्व और भी अधिक बढ़ गया। प्रथम नैपोलियन की महत्ता से उसके भतीजे ने भी लाभ उठाया। लुई नैपोलियन

भी वीरो की तरह पुजने लगा। परिणाम यह हुआ कि अपने राज्य-शासन की रक्षा के लिये उस समय के राजा लुई फिलिप ने यह आवश्यक समझा, कि लुई नैपोलियन को जेल में डाल दिया जाए। कैद होने से लुई नैपोलियन की लोकप्रियता और भी अधिक बढ़ गई। लोग उसे शहीद समझने लगे। १८४६ में वेश बदल कर वह जेल में भाग निकला और इंग्लैंड जा पहुँचा।

**द्वितीय फ्रेंच रिपब्लिक का राष्ट्रपति—** इङ्ग्लैंड जाकर वह उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा करता रहा। १८४८ में जब फ्रांस में राज्यक्रांति हुई, तो लुई नैपोलियन अपने देश वापस लौट आया और क्रांतिकारियों में सम्मिलित हो गया। राष्ट्रीय महामुखा में वह चार स्थानों से प्रतिनिधि चुना गया था, यह उसकी लोकप्रियता का अच्छा प्रमाण है। राष्ट्रपति पद के लिये वह भी उम्मीदवार पड़ा हुआ। नैपोलियन दल तो उसका समर्थक था ही, रिपब्लिकन दल के बहुत से लोग भी उसी के पक्ष में थे। परिणाम यह हुआ, कि निर्वाचन में उसे असाधारण सफलता मिली। अपने मुद्रमित्र चचा नैपोलियन बोनापार्ट की तरह वह भी फ्रेंच रिपब्लिक का राष्ट्रपति बन गया।

**२ दिसम्बर, १८५१ का पड्यन्त्र—**राष्ट्रपति बनकर नैपोलियन तृतीय ने अपने वैयक्तिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने का यत्न किया। इसके लिये आवश्यक था, विविध राजनीतिक दलों को सन्तुष्ट किया जाए। फ्रांस की अधिकांश जनता रोमन कैथोलिक धर्म की माननेवाली थी। इसलिये जब रोम में पोप के विरुद्ध जनता ने विद्रोह किया, तो लुई नैपोलियन ने पोप की सहायता की। इसके अनिर्वास्त, कैथोलिक लोगों को सन्तुष्ट करने के लिये ही उसने शिक्षा का कार्य भी पादरियों के सुपुर्द कर दिया। उस समय फ्रांस मजदूरों का बहुत जोर हो रहा था, अतः उन्हें सन्तुष्ट करने के लिये भी कार्य नहीं कर सकता था। मजदूरों को खुश करने के लिये लुई नैपोलियन ने अनेक नये कानूनों का निर्माण किया। वृद्धावस्था में मजदूरों के लिये पेन्शन तक की व्यवस्था की गई। मध्य श्रेणी के लोगों को सन्तुष्ट करने के लिये व्यापार और व्यवसाय के संरक्षण को दृष्टि रखकर अनेक नई व्यवस्थाएँ की गईं। इस प्रकार, अपनी स्थिति को मजबूत करके लुई नैपोलियन ने शासन-विधान में ऐसे परिवर्तन कराने का उद्योग प्रारम्भ किया, जिनसे वह दुबारा फिर राष्ट्रपति निर्वाचित हो सके। परन्तु राष्ट्रप्रतिनिधि सभा ने इन स्वीकृत नहीं किया। जब नैपोलियन ने देखा, कि अन्य कोई उपाय नहीं रहा है, तब उस कानून का उल्लंघन कर पड्यन्त्र करने का निश्चय किया। २ दिसम्बर, १८५१ के दिनांक प्रातः काल जब लोग सोकर उठे, तो उन्होंने देखा कि पेरिस की सब गलियों में दीवारों पर बड़े-बड़े इश्टिहार लगे हुए हैं, जिनमें कि नैपोलियन तृतीय ने उद्घोषणा की है, कि राष्ट्रप्रतिनिधि सभा को बर्खास्त किया जाता है, और भविष्य में वोट देने का अधिकार सवालिग पुरुषों को दे दिया जायगा। राष्ट्रप्रतिनिधि सभा ने एक कानून द्वारा वोटों का अधिकार को बहुत सीमित कर दिया था। जो लोग टैक्स देते थे, वे ही वोट का हक रखते थे। इस कानून से सर्वसाधारण जनता में बहुत असन्तोष था। नैपोलियन ने इसी असन्तोष से लाभ उठाया, और सब लोगों को वोट का अधिकार देकर जनता की सहानुभूति को प्राप्त कर लिया। सार्वजनिक मताधिकार की उद्घोषणा के अनन्तर नैपोलियन ने जनता से यह



आवेदन किया, कि नवीन शासन-विधान को तैयार करने का कार्य मेरे सुपुर्द कर दिया जावे।

इस इशतिहार के साथ ही गिरफ्तारियों का सिलसिला भी पारम्भ कर दिया गया। सत्ताईस हजार के लगभग रिपब्लिकन नेताओं को गिरफ्तार किया गया, या देशनिकाला दे दिया गया। इस कार्यवाही से जब पेरिस में विद्रोह हुआ, तो सेना की सहायता ली गई। विद्रोहियों पर निर्दयता से गोलावारी की गई। १५० से भी अधिक आदमी गोली से उड़ा दिये गये। नैपोलियन तृतीय का पड़्यन्त्र सफल हो गया। सेना पहिले से ही उसके काम में थी। कोई आदमी उसका विरोध नहीं कर सका। जिमने उसके विरुद्ध आवाज उठाई, उसे कुचल दिया गया।

इसके बाद नैपोलियन ने जनता के सम्मुख निम्नलिखित प्रस्ताव उपस्थित किया—  
“फ्रेंच जनता की इच्छा है कि लुई नैपोलियन बोनापार्ट का शासन कायम रहे। अतः जनता उने अधिकार देती है कि २ दिसम्बर, १८५१ की उद्घोषणा के आधार पर एक नवीन शासन-विधान का निर्माण करे।” इसीम वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक फ्रेंच पुरुष को इस प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में वोट देने का अधिकार दिया गया। ७७ लाख ४० हजार वोट प्रस्ताव के पक्ष में आये, और ६ लाख ४६ हजार विरोध में। इस वोट का परिणाम यह हुआ, कि लुई नैपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एकमात्र भाग्यविधाता बन गया।

नवीन शासन-विधान का निर्माण—जनवरी, १८५२ में नवीन शासन-विधान तैयार हो गया। इसके अनुसार नैपोलियन को चार वर्ष के स्थान पर दस वर्ष के लिये राष्ट्रपति नियत किया गया। उसे यह भी अधिकार दिया गया कि वह अपना मन्त्रिमण्डल स्वयं नियत करे। व्यवस्थापन विभाग में तीन सभाएँ रखी गई—(१) राज्य-परिषद—इसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाए, और यह कानूनों का मसविदा तैयार करने का काम करे। (२) व्यवस्थापिका सभा—इसके सदस्यों की संख्या २५० हो, और इन्हें निर्वाचित करने के लिये सम्पूर्ण वालिग पुरुषों को वोट का अधिकार प्राप्त हो। यह सभा प्रस्तावित कानूनों पर बहस करे, और उन पर अपना मत निश्चित करे। (३) सीनेट—इसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा जन्म भर के लिये की जाए, और इसका कार्य इस बात का सवाल रखना हो, कि कोई कानून शासन-विधान के विरुद्ध स्वीकृत न हो सके। इस नये शासन विधान द्वारा वास्तविक राज्यशक्ति राष्ट्रपति के हाथों में दे दी गई थी। तीन सभाओं में से दो के सदस्यों की नियुक्ति उसी के अधीन थी। अब लुई नैपोलियन को अपनी मनमानी करने का पूर्ण अवसर था। दस साल के लिये उसकी गद्दी सुरक्षित थी। मन्त्रियों को उसने नियत करना था, और अधिकांश व्यवस्थापक भी उसने ही नियत करने थे। अब वह फ्रांस का एकमात्र भाग्य-विधाता बन गया था।

सम्राट् नैपोलियन तृतीय—परन्तु नैपोलियन तृतीय इतने से ही मन्तुष्ट नहीं था। अभी एक कदम बाकी थी। अभी वह सम्राट् नहीं बना था। उसकी माता वचन से ही उसे कहा करती थी—जिस नाम के साथ बोनापार्ट लगा होता है, वह ससार में कोई असाधारण काम कर दिखाने के लिए उत्पन्न होता है। लुई नैपोलियन अपने चचा का अनुकरण करने के लिए उत्सुक था। वह राष्ट्रपति न रहकर सम्राट् बनना चाहता था। वास्तविक शासन शक्ति उसके हाथ में आ ही चुकी थी। अब केवल एक कदम और शेष था।

उसके लिए भी उपयुक्त अवसर प्राप्त होने में देर नहीं लगी।

१८५२ में शासन-सूत्र को अपने हाथों में लेकर लुई नैपोलियन ने सम्पूर्ण फ्रांस की यात्रा की। सब जगह उसका बड़ी वृम्वाम के साथ स्वागत हुआ। अनेक समाचार-पत्रों के सवाददाता उसके साथ थे। यात्रा के समाचार बड़े जोर शोर से अखबारों में छप रहे थे। उसके पक्षपाती सवाददाता बड़े विस्तार में इन सवादों को अखबारों में प्रकाशित करवा रहे थे, कि किस प्रकार स्थान-स्थान पर लुई नैपोलियन का स्वागत हो रहा है, किस प्रकार जनता 'सम्राट् की जय' के नारों के साथ उसका अभिनन्दन कर रही है। वस्तुतः, 'नैपोलियन बोनापार्ट' इस नाम में ही कोई ऐसा जादू था, जिसमें कि वह जहाँ कहीं भी पहुँचता था, लोग उसके दर्शनो के लिये एकत्रित हो जाते थे। अम्मी नैपोलियन अब नहीं था, पर उसकी छाया मौजूद थी। इस यात्रा के बाद १ दिसम्बर, १८५० को नैपोलियन ने सीनेट के सम्मुख भाषण करने हुए कहा, कि जनता की वास्तविक इच्छा यह है कि मुझे सम्राट् नियुक्त किया जावे। सीनेट में यह प्रस्ताव स्वीकृत होने में देर नहीं लगी। इसके बाद सम्पूर्ण फ्रेंच जनता की सम्मति इस प्रस्ताव पर हो गई। अम्मी लाल से अधिक वोट प्रस्ताव के पक्ष में आये। नैपोलियन की हार्दिक आकांक्षा पूर्ण हो गई। फ्रांस में रिपब्लिक के स्थान पर एक बार फिर राजसत्ता की स्थापना हो गई।

## २. सम्राट् नैपोलियन का शासन

शासन विषयक सघर्ष—नैपोलियन तृतीय ने १८५० में १८७० तक राज्य किया। वह एक पड़्यन्त्र द्वारा सम्राट् बना था। पर इस में जनता में विशेष असन्तोष नहीं हुआ। देहात के लोग इसमें सन्तुष्ट थे। राजसत्ता के प्रति भक्ति की भावना अभी उनमें विद्यमान थी। नैपोलियन के कुल के प्रति भी उनमें आदर था। मध्य श्रेणि के व्यवसायी व व्यापारी लोग भी नैपोलियन के पक्षपाती थे। साम्यवाद मजदूर-वर्ग में जिस ढंग से जोर पकड़ रहा था, मध्य श्रेणि के पूँजीपति लोग उसमें बहुत चिन्तित थे। उन्हें अनुभव होता था, कि लोकतन्त्र रिपब्लिक द्वारा साम्यवाद की प्रवृत्ति को बल मिलता है। अतः उनका अपना हित इसी में है, कि राजसत्ता कायम रहे, और नैपोलियन तृतीय का अबाधित शासन स्थिर हो। रोगन कैथोलिक जनता उसके पक्ष में थी, क्योंकि वह फ्रांस के बाहर भी कैथोलिक चर्च की सहायता के लिये सदा उद्यत रहता था। नैपोलियन चाहता था, कि फ्रांस की राजगद्दी उसके अपने वंश में स्थिर रहे। इसीलिये उसने १८५३ में स्पेन की एक कुलीन कुमारी यूजेनी के साथ विवाह किया। इससे उसे एक सन्तान भी हुई, जो इतिहास में 'प्रिंस इम्पीरियल' के नाम से प्रसिद्ध है। नैपोलियन तृतीय और साम्राज्ञी यूजेनी इस बात के लिये उत्सुक थे, कि यह प्रिंस इम्पीरियल उनके बाद फ्रांस का सम्राट् बने।

पर नैपोलियन तृतीय के विरोधी भी कम न थे। बूवों और ओर्लियन वंशों के पक्षपातियों का अभी फ्रांस में अभाव नहीं था। बूवों वंश का कुमार कात द शाम्बोर इस समय आस्ट्रिया में निवास कर रहा था, और वहाँ रहते हुए अपने राजकुल के अतीत वैभव का पुनरुद्धार करने के प्रयत्न में था। पर फ्रांस में बूवों वंश के पक्षपातियों की सत्या

अधिक नहीं थी। बहुसंख्यक कुलीन लोग लुई फिलिप के ओर्लियन वंश का फिर से उद्धार करनेके पक्ष में थे। पर नैपोलियन तृतीय के सनमे प्रबल विरोधी रिपब्लिकन दल के लोग थे। पड़्यन्त्र द्वारा नैपोलियन सम्राट् तो बन गया था, पर रिपब्लिकन लोग उसका विरोध करने के लिये तले हुए थे। पेरिस और अन्य बड़े नगरों में इस दल के लाखों अनुयायी थे। इस युग के अनेक फ्रेच साहित्यिक, विचारक और ऐतिहासिक भी रिपब्लिक के पक्षपाती थे। इनमें थियर्स, लुई ब्र्या, विस्टर ह्यूगो और ज्यार्ज सा के नाम विशेषरूप से उल्लेखनीय हैं। ये लोग अपने साहित्य द्वारा नैपोलियन का विरोध और रिपब्लिक का समर्थन करने में तत्पर थे।

सम्राट् बनकर जो नया शासन-विधान नैपोलियन ने जारी किया, उसके अनुसार पहला चुनाव सन् १८५७ में हुआ। इसमें रिपब्लिकन दल के केवल पांच प्रतिनिधि व्यवस्थापिका सभा में निर्वाचित हुए। इनका नेता ओलिविए था। ये पांच सदस्य व्यवस्थापिका सभा में नैपोलियन का विरोध करने के लिये प्रयत्नशील थे।

इसमें सन्देह नहीं, कि नैपोलियन तृतीय के शासनकाल में फ्रांस में शान्ति और समृद्धि कायम रही। उसके आन्तरिक शासन पर हम इसी प्रकरण में आगे प्रकाश डालेंगे। पर विदेशी नीति में नैपोलियन को अधिक सफलता नहीं हुई। उसने फ्रांस को अनेक ऐसे युद्धों में फंसा दिया, जिनके कारण जनता में बहुत असन्तोष हुआ। विदेशी युद्धों में फ्रांस के घन और जन की बहुत हानि हुई, और राष्ट्रीय दृष्टि से भी फ्रांस को उनसे कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। नैपोलियन की इस विदेशी नीति और युद्धों पर हम आगे चलकर प्रकाश डालेंगे। यहाँ इतना निर्देश कर देना पर्याप्त है, कि इन युद्धों के कारण रिपब्लिकन दल का जोर बढ़ने लगा, और १८६३ के निर्वाचन में इस दल के सदस्यों की संख्या ५ से बढ़कर ३५ हो गई। इस निर्वाचन में नैपोलियन के विरोधियों को बीस लाख से भी अधिक वोट प्राप्त हुए थे। इस समय व्यवस्थापिका सभा में विरोधी दल का नेता थियर्स था। वह चाहता था, कि फ्रांस में इंग्लैण्ड के समान वैध राजसत्ता की स्थापना हो, नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहे, और मन्त्रिमण्डल सम्राट् के प्रति उत्तरदायी न होकर व्यवस्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायी हो।

फ्रांस के रिपब्लिकन दल और लोकतन्त्र के पक्षपाती अन्य दल शासन-सुधार के लिए आन्दोलन में तत्पर थे। नैपोलियन ने भरसक कोशिश की, कि ये दल सफल न हो। उसने प्रेम की स्वतन्त्रता पर अनेक बाधाएँ उपस्थित की। पर लोकतन्त्रकी भावना इससे दबी नहीं। १८६९ के निर्वाचन में नैपोलियन के विरोधियों को और अधिक सफलता मिली। उन्हें तीस लाख से भी अधिक वोट मिले। इस दशा में नैपोलियन अधिक समय तक लोकमत की उपेक्षा नहीं कर सका। विवश होकर, १८७० में उसने शासन सम्बन्धी अनेक सुधार किये। इनके अनुसार यह व्यवस्था की गई कि मन्त्रिमण्डल व्यवस्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायी हो। ओलिविए को प्रधानमन्त्री के पद पर नियत किया गया। यह भी व्यवस्था की गई, कि राज्य की तीन सभाओं में से अन्यतम सीनेट की स्थिति वही बना दी जाए, जो इंग्लैण्ड में हाउस आफ लार्ड्स की थी। सीनेट के सदस्यों को मनोनीत करने का कार्य अब भी सम्राट् के हाथ में ही रखा गया, पर अब सीनेट मन्त्रिप्रस्तावों और कानूनों

पर उसी ढंग से विचार कर सकती थी, जैसे कि व्यवस्थापिका सभा करती थी। ओलिविए के परामर्श से इन नये शासन-सुधारों पर भी लोकमन लिया गया। ७३,५८,००० वोट सुधारों के पक्ष में आये, और १५,७१,००० विरोध में। पेरिस और अन्य बड़े नगरों के लोगों ने सुधार के विरोध में वोट दिये थे। उन नगरों में ऐसे राजनीतिक दलों का जोर था, जो लोकतन्त्र रिपब्लिक के अतिरिक्त किसी अन्य व्यवस्था में मन्तव्य नहीं हो सकते थे।

पर फ्रांस में देर तक नये शासन सुधारों के अनुसार शासन नहीं हो सका। चौथी बार फ्रांस में एक बार फिर राज्यक्रान्ति हो गई। नैपोलियन तृतीय को अपना राजमहिमान छोड़ना पड़ा, और रिपब्लिक की स्थापना हुई।

**आन्तरिक शासन—**नैपोलियन तृतीय के शासन में फ्रांस की अच्छी उन्नति हुई। अनेक नये बँक खुले। व्यापार और व्यवसाय बहुत बढ़े। रेल, मटक, नहर आदि के निर्माण में बहुत में मजदूरों को कार्य मिला। जंगलों के विकास के लिये विशेष उद्योग किया गया। बहुत में नये जंगल लगवाये गये। नदियों पर बहुतमें नये पुल बनवाये गये। अनेक मार्गजनिक इमारतें खड़ी की गईं। दलदलों को सुखाने की योजना बनायी गई। पेरिस को सुन्दर तथा समृद्ध बनाने के लिये अनेक उद्योग किये गये। अनेक पार्क और उद्यानों की सृष्टि की गई। कृषि की उन्नति के लिये विशेष रूप में प्रयत्न किया गया। कृषि-सम्बन्धी शिक्षा का प्रसार करने के लिये देशान्त में प्रारम्भिक कृषि विद्यालय स्थापित किये गये। अच्छे फल, अनाज और पशुओं के लिये विविध पारिर्तापिकों की व्यवस्था की गई। लोगों में खेती सम्बन्धी जानकारी को बढ़ाने के लिये अनेक कृषि-सभाओं का गठन किया गया। इन सब प्रयत्नों का परिणाम यह हुआ, कि खेती ने बहुत तरक्की की, जिसके कारण किसानों की हालत सुधरने लगी। उनके झोपड़े मनुष्यों के रहने लायक अच्छे नये मकानों में परिवर्तित हो गये। इस युग में फ्रांस कृषि के क्षेत्र में कितना उन्नत था, इसका अनुमान इस बात से किया जा सकता है, कि १८६० में वहाँ २३,५०,००,००० कुशल गेहूँ उत्पन्न हुआ था। इसी साल रूस में २२,७०,००,००० कुशल और अमेरिका में १४,२०,००,००० गेहूँ पैदा हुआ था। फ्रांस, रूस और अमेरिका के क्षेत्रफल को दृष्टि में रखकर इस युग में फ्रांस की कृषि सम्बन्धी समृद्धि को भलीभाँति समझा जा सकता है।

मजदूरों की दशा सुधारने के लिये भी अनेक नियम बनाये गये। श्रमियों को अपने सध बनाने का अधिकार है, यह बात कानून द्वारा स्वीकृत की गई। इससे पूर्व श्रमियों को अपने सध तक बनाने का अधिकार प्राप्त न था। श्रमी लोग हड़ताल कर सकते हैं, यह अधिकार भी अब स्वीकृत किया गया। कारखानों में काम करते हुए अगर कोई मजदूर घायल हो जाए या मर जाए, तो उसके परिवारवालों की सहायता की उत्तरदायिता राज्य ने अपने ऊपर ले ली। मजदूरों की भी सहोद्योग समितियों को संगठित करने का प्रयत्न किया गया।

व्यापार और व्यवसाय की उन्नति के लिये भी प्रयत्न किया गया। सड़कों और रेलवे की उन्नति ने व्यापार में बहुत सहायता पहुँचाई। वकों के प्रसार से व्यवसाय के लिये पूँजी प्राप्त कर सकना सुगम हो गया। डाकखानों का विस्तार किया गया। फ्रांस से बाहर जाने वाले निर्यात माल की मात्रा अब एक अरब रुपये से भी ऊपर पहुँच गई। पेरिस के व्यापारी

इस काल को 'व्यापार का सुवर्णीय युग' के नाम से पुकारते थे। यह कहना तो कठिन है, कि इस उन्नति का श्रेय नैपोलियन तृतीय को ही दिया जाना चाहिये। पर इसमें सन्देह नहीं, कि उसके शासन में फ्रांस में जो शान्ति और व्यवस्था विद्यमान थी, उसने इस आर्थिक उन्नति और समृद्धि में बहुत सहायता पहुँचाई। अठारहवीं सदी में जिस व्यावसायिक क्रांति का इंग्लैण्ड में प्रारम्भ हुआ था, उन्नीसवीं सदी के शुरु में वह फ्रांस में भी प्रवेश कर गई थी। उसके कारण अब फ्रांस के व्यापारी और व्यापारी आर्थिक उन्नति में तत्पर थे। नैपोलियन तृतीय का व्यवस्थित शासन उनके प्रयत्न में सहायक अवश्य था।

यद्यपि फ्रांस आर्थिक दृष्टि में उन्नति कर रहा था, पर राजनीतिक स्वतन्त्रता की दृष्टि से वह बहुत पीछे रह गया था। लोगों को लिखने, बोलने और मुद्रण की स्वतन्त्रता नहीं थी। अखबारों पर कड़ी निगाह रखी जाती थी। विश्वविद्यालय के अध्यापकों को नैपोलियन के प्रति भक्ति की शपथ लेनी पड़ती थी। इतिहास और दर्शनशास्त्र का अध्ययन नैपोलियन को पसन्द नहीं था। अनेक विश्वविद्यालयों में इनका अध्ययन ही बन्द कर दिया गया था। अध्यापकों को आज्ञा दी गई थी, कि वे अपनी दाढ़ी को मुड़ा कर रखें, ताकि उनकी "शकलों से भी अराजकता का कोई निशान प्रकट न हो सके।" गुप्तचरों की कोई सीमा नहीं रही थी। लोगों का कोई भी कार्य गुप्तचरों की आख से नहीं बच पाता था। सरकार और मन्त्रालय की आलोचना करना भारी अपराध था। दो हजार से अधिक लोगों को केवल इसी अपराध में केंद किया गया था, क्योंकि उन्होंने सरकार की आलोचना की थी।

इसमें सन्देह नहीं, कि नैपोलियन तृतीय कुशल और वृद्धिमान् शासक था। अपनी नीति-कुशलता और वृद्धिमत्ता से वह पर्याप्त सफलता के साथ शासन करने में समर्थ हुआ। उसके पतन के प्रधान कारण वे वैदेशिक युद्ध थे, जिनका हम अभी उल्लेख करेंगे।

### ३ साम्राज्य विस्तार

फ्रांस में जिस ढंग से व्यवसायिक उन्नति इस युग में हो रही थी, उसका निदर्शन ऊपर किया जा चुका है। फ्रेंच पूंजीपति अनुभव करते थे, कि उनके लिये यह आवश्यक है, कि फ्रांस के भी अपने उपनिवेश हों, उनका भी अपना साम्राज्य हो, जहाँ से फ्रेंच व्यवसायी कच्चा माल सस्ते दाम पर प्राप्त कर सकें, और जहाँ फ्रांस का तैयार माल निश्चिन्तता के साथ विक्रम करे। साम्राज्यवाद के प्रथम संघर्ष में फ्रांस ब्रिटेन द्वारा परास्त हो चुका था। भारत के साम्राज्यविस्तार के प्रयत्न में फ्रेंच लोगों के मुकाबले में इंग्लिश श्रेष्ठ सफल हुए थे। उत्तरी अमेरिका में कनाडा भी फ्रांस के हाथ से निकलकर अंग्रेजों के हाथ में चला गया था। पर फ्रेंच लोग इससे निराश नहीं हुए। १८३० में उन्होंने अल्जीरिया पर अपना प्रभुत्व कायम कर लिया था। अटलाण्टिक महासागर में स्थित न्यू बेलिडोनिया भी लगभग इसी समय फ्रांस के अधिकार में आ गया था। १८५८ में फ्रांस ने पूर्वी एशिया में कोचीन-चायना और अनाम पर अपना अधिकार स्थापित किया। १८६० में चीन की राजसत्ता की निर्बलता से लाभ उठाकर अन्य यूरोपियन देशों के समान फ्रांस

ने भी चीन के साथ व्यापार के लिये अनेक मुविगाए प्राप्त कर ली, और मम्ब्रतट के साथ के अछे बड़े चीनी प्रदेश पर व्यापारिक आविपत्य कायम कर लिया। १८६३ में कम्बोडिया का सुविस्तृत प्रदेश फ्रांस के मग्दाग में आ गया। अफ्रीका और एशियाम यूरोप के विविध देश क्रिम द्वाग में अपना प्रभुत्व स्थापित कर रहे थे, इस मम्ब्रव में हम एक पृथक् अध्याय में अधिक विस्तार के साथ लियेंगे। पर यहाँ यह बात देना आवश्यक है, कि नैपोलियन तृतीय के शासनकाल में ही फ्रांस ने कम्बोडिया, कोचीन-चायना, अनाम आदि में अपने प्रभुत्व की स्थापना की थी।

मेक्सिको पर प्रभुत्व स्थापित करने का असफल प्रयत्न—यह हम पहले लिख चुके हैं, कि शुरू में मेक्सिको स्पेन के साम्राज्य के अन्तर्गत था। १८२३ ई० में वह स्पेन की अधीनता से स्वतन्त्र हुआ था, और वहाँ लोकतन्त्र रिपब्लिक की स्थापना की गई थी। पर मेक्सिको के लोग अग्न देश में सुव्यवस्थित शासन स्थापित करने में असमर्थ रहे थे। वहाँ की सरकार अनेक विदेशी पञ्जीनिया की कर्जदार थी, जिनमें स्पेन, फ्रांस और ब्रिटेन प्रमुख थे। इस विदेशी कर्ज को अदा कर सकना मेक्सिको की सरकार के लिये सुगम न था। कर्ज की रकम को अदा कर सकना तो दूर रहा, १८३१ में यह स्थिति थी, कि दो साल का सूद भी मेक्सिकन सरकार अदा नहीं कर पाई थी। इस दशा में फ्रांस, स्पेन और ब्रिटेन के पञ्जीपतियों ने अपनी-अपनी सरकारों में सहायता की अपील की। नैपोलियन तृतीय ने सोचा, मेक्सिको की इस दुर्दशा का उपयोग अपने साम्राज्य-विस्तार के लिये किया जा सकता है। उन दिनों मयुक्त राज्य अमेरिका में दाम्पत्या को नष्ट करने के प्रश्न पर गृह-कलह चल रहा था। अमेरिकन राष्ट्रपति मुनरो ने जिस मुनरो सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था, वह इस समय प्रयुक्त नहीं किया सकता था, क्योंकि सयुक्तराज्य अमेरिका की अपनी स्थिति ही इस समय डावावाध थी। इस दशा में नैपोलियन तृतीय ने स्पेन और ब्रिटेन की सरकार को इस बात के लिये प्रेरित किया, कि वे अपनी सेनाएँ मेक्सिको भेजे, ताकि वहाँ की सरकार पर कर्ज की अदायगी के लिये जोर डाला जा सके। स्पेन और ब्रिटेन इसके लिये तैयार हो गये। पर उन्होंने इस कार्य में देर तक फ्रांस की सहायता नहीं की, और अकेले फ्रांस ने ही अपनी एक सेना को मेक्सिको पर कब्जा करने के लिये भेज दिया। १८६२ में नैपोलियन द्वारा भेजे गये तीस हजार सैनिकों ने मेक्सिको पर आक्रमण किया। मेक्सिको जीत लिया गया, और १८६३ में फ्रांस का मेक्सिको पर कब्जा हो गया। नैपोलियन ने प्रस्ताव किया, कि आस्ट्रिया के सम्राट् के भाई मैक्समिलियन को मेक्सिको का सम्राट् बनाया जाय। इससे उसे आशा थी, कि आस्ट्रिया जैसे शक्तिशाली राज्य की सहानुभूति उसे प्राप्त हो जायगी, और वह सुगमता से मेक्सिको को अपने प्रभाव में ला सकेगा। मैक्समिलियन ने मेक्सिको का सम्राट् बनना स्वीकार कर लिया, और फ्रेंच सेनाओं की सहायता से उसे सम्राट् पद पर अविष्टित भी कर दिया गया।

पर इस बीच में सयुक्तराज्य अमेरिका के गृह कलह का अन्त हो चुका था। यह राज्य इस बात को नहीं सह सकता था, कि अमेरिकन महाद्वीप में यूरोपियन राज्य इस ढंग से हस्तक्षेप करें। अमेरिका ने मुनरो-सिद्धान्त की दुहाई देकर मैक्समिलियन और फ्रांस का

विरोध किया, और उसके प्रोत्साहन से मेनिमको में विद्रोह हो गया। सम्राट् मैक्सिमिलियन विद्रोहियों की गोली का शिकार हुआ, और फ्रेच सेनाओं को मेक्सिको छोड़कर वापस लौट आने के लिये (फरवरी, १८६७) विवश होना पड़ा। सम्राट् नैपोलियन तृतीय की यह भारी जम्फलता थी। अमेरिकन महाद्वीप में फ्रांस के साम्राज्यविस्तार का जो प्रयत्न नैपोलियन तृतीय ने किया था, वह असफल हो गया था।

## ४ विदेशी युद्ध और पतन

जिन विदेशी युद्धों के कारण नैपोलियन तृतीय का पतन हुआ, उनका विशद रूप से वर्णन अगले अध्यायो में किया जायगा। वे सब युद्ध इटली, आस्ट्रिया और जर्मनी के साथ सन्ध रक्ते हैं, और उनका विवरण इन देशों के इतिहास में देना अधिक उपयुक्त रहेगा। पर इस प्रकरण में भी उनका अत्यन्त मक्षेप के साथ उल्लेख कर देना अनुचित नहीं है।

नैपोलियन तृतीय की महत्वाकांक्षा थी, कि अपने चचा का अनुकरण कर यूरोप के विदेशी मामलों में भी हस्तक्षेप करे। १८५४-५६ के त्रीमियन युद्ध में उसने रूस के विरुद्ध टर्की की सहायता की। इस युद्ध में फ्रांस को ७५ हजार मैनिक मारे गये, और सवा अरब रुपये खर्च हुए। पर फ्रांस को इससे लाभ क्या हुआ? कुछ नहीं, यद्यपि नैपोलियन यह गर्व जवस्य कर सकता था, कि शान्तिपरिपद् का अधिवेशन उसकी छत्रछाया में पेरिस में हो रहा है। १८५९ में जब उत्तरी इटली ने आस्ट्रियन शासन के विरुद्ध विद्रोह किया, तब नैपोलियन ने इस शर्त पर इटली की सहायता करना स्वीकृत किया, कि नीस और सेवाय के प्रदेश फ्रांस को दिये जायेंगे। ये दोनों प्रदेश उसे मिल गये, पर युद्ध की समाप्ति के पूर्व ही नैपोलियन युद्ध से अलग हो गया, और इसका परिणाम यह हुआ कि इटली और आस्ट्रिया दोनों ही उसके विरुद्ध हो गये। नैपोलियन तृतीय का मुख्य युद्ध प्रशिया के साथ हुआ। १८७० के इस फ्रेको-प्रशियन युद्ध का वर्णन हम आगे चलकर विस्तार से करेंगे। यहाँ इतना लिखना पर्याप्त है, कि विस्मार्क के नेतृत्व में प्रशिया जर्मनी को जिस ठग से सगठित कर रहा था, वह नैपोलियन को विलकुल भी सह्य नहीं था। रूहइन नदी के समीपवर्ती प्रदेश पर प्रशिया जैसे शक्तिशाली राज्य का प्रभाव स्थापित हो जाए, यह बात नैपोलियन की दृष्टि में फ्रांस के लिये घातक थी। वह युद्ध के लिये उपयुक्त अवसर ढूँढ रहा था। जब किसी काम को करने के लिये इरादा बन चुका हो, तो उसके लिये बहाना ढूँढने में देर नहीं लगती। नैपोलियन प्रशिया की बढ़ती हुई शक्ति को नष्ट करने के लिये तुला हुआ था। इसके लिये उसे शीघ्र ही उपयुक्त अवसर प्राप्त हो गया।

स्पेन की स्वेच्छाचारी साम्राज्ञी इसाबेला के विरुद्ध जनता ने विद्रोह कर उसे राज्य-च्युत कर दिया था। स्पेनिश लोगों के सम्मुख प्रश्न यह था, कि अब राजगद्दी पर किसे बिठाया जाय? आखिर, उन्होंने प्रशिया के राजा के भाई लियोपोल्ड को इस पद के लिये स्वीकृत किया। ज्योंही नैपोलियन ने इस समाचार को सुना, वह आगबबूला हो गया। प्रशिया और स्पेन—दो शक्तिशाली राज्यों की राजगद्दियों पर होहेन्डोल्लर्न राजवंश का शासन हो, यह बात नैपोलियन कैसे सह सकता था? उसने इस प्रस्ताव का सख्त

विरोध किया। उसने उद्धोषणा की, कि फ्रांस इस बात को कभी भी सहन नहीं करेगा। नैपोलियन के विरोध का यह परिणाम हुआ, कि लियोपोल्ड ने स्वयमेव राजगद्दी की उम्मीदवारी का परित्याग कर दिया। पर नैपोलियन तो युद्ध के लिये तुला हुआ था। उसने उद्धोषित किया, कि लियोपोल्ड की ओरसे उम्मीदवारी का परित्याग कर देना ही मुझे मन्तुष्ट करने के लिये पर्याप्त नहीं है। प्रशिया को प्रतिज्ञा करनी चाहिये, कि भविष्य में भी कभी होहन्ट्सोलर्न वंश का कोई कुमार स्पेन की राजगद्दी का उम्मीदवार नहीं होगा। निम्नदेह, नैपोलियन की यह ज्यादाती थी। पर वह तो प्रशिया की ज़मीन को नष्ट करने के लिये युद्ध का अवसर ढूँढने को उत्सुक था। यह जवमग उसे प्राप्त हो गया। प्रशिया और फ्रांस—दोना देशों में युद्धकी तैयारी होने लगी। प्रशिया युद्धनीति में बहुत अधिक उन्नति कर चुका था। उसकी सेनाएँ बहुत ही रणकुशल तथा मर्था हुई थीं। फ्रांस उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। २ दिसम्बर, १८७० को सीडन के रणक्षेत्र में नैपोलियन तृतीय की बुरी तरह पराजय हुई। दो दिन बाद इस भयकर पराजय का समाचार पेरिस पहुँचा। लोगो में सनसनी फैल गई। पार्लियामेण्ट का भवन उत्सुक जनता द्वारा घेर लिया गया। 'रिपब्लिक की जय' के नारों में आकाश गूँज उठा। व्यवस्थापिका सभा में प्रस्ताव पेश किया गया, कि नैपोलियन और उसके वंश को राज्यच्युत किया जावे। प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। गेम्बेटा नाम के रिपब्लिकन नेता के नेतृत्व में योग एकत्रित हुए, और तीसरी बार फ्रांस में रिपब्लिक की स्थापना की गई।

इस बीच में नैपोलियन तृतीय फ्रांस में भागकर ग्रेट ब्रिटेन पहुँच गया था। उसका शेष जीवन वही पर व्यतीत हुआ।

नैपोलियन तृतीय के पतन के क्या कारण थे? उसका शासन एकतन्त्र और म्वेच्छाचारी था। लोकतन्त्र शासन का ढोंग कायम होते हुए भी यह सर्वथा स्पष्ट था, कि फ्रांस में जनता का शासन न होकर एक व्यक्ति का शासन है। समय को देखते हुए यह बात देर तक सहन नहीं की जा सकती थी। यही कारण है, कि लोगो में असन्तोष के चिह्न प्रकट होने शुरू हो गये थे। इसके अतिरिक्त, नैपोलियन तृतीय ने अपनी वैदेशिक नीति में भी भारी भूलें की थीं। इन्हीं भूलों का परिणाम था, कि फ्रेको-प्रशियन युद्ध में अन्य कोई भी देश उसकी सहायता के लिए अग्रसर नहीं हुआ था।



अठारहवा अध्याय

## इटली की स्वाधीनता

### १ स्वाधीनता के लिए संघर्ष

नैपोलियन प्रथम के युद्धों के बाद इटली में राष्ट्रीय एकता की अनुभूति उत्पन्न हो चुकी थी। रोम के प्राचीन गौरव की स्मृति लोग अभी भूले नहीं थे। किसी समय इटली ने सभ्य संसार पर पर हुकूमत की थी। विद्या, विज्ञान, कला, संगीत, वर्म आदि सब क्षेत्रों में संसार इटली का मित्र मानता था। इटालियन देशभक्त अपने इतिहास से ग्लोभाति परिचित थे। वे एक बार फिर अपने देश को संसार का शिरोमणि देखने को उत्सुक थे। नैपोलियन ने जब सम्पूर्ण इटली को जीतकर एक “इटालियन राज्य” की स्थापना की थी, तब इस विदेशी शासन से अन्य हानियाँ चाहे कितनी ही क्यों न हुई हों, पर वह लाभ अवश्य हुआ था, कि इटालियन लोग भगीभाति अनुभव करने लग गये थे, कि हम सब एक देश के वासी हैं, और हम सबको एक राष्ट्र में ही संगठित रहना चाहिये। नैपोलियन के पतन के बाद प्रतिक्रिया का काल प्रारम्भ हुआ। वीएना की कांग्रेस द्वारा यूरोप की जिस प्रकार पुन व्यवस्था की गई, उसमें जनता की इच्छा और राष्ट्रीय भावनाओं पर जग भी ध्यान नहीं दिया गया। इटली के विविध राज्यों में पुराने राजवंशों का पुनरुद्धार किया गया। उत्तरी इटली के अधिकांश प्रदेश पर (लोम्बार्डी और वेनेटिया पर) आस्ट्रिया का शासन स्थापित किया गया। १८२०, १८३० और १८४८ में यूरोप में क्रान्ति की जो लहरें चली, उन सब ने इटली पर प्रभाव डाला। न्यान स्थान पर विद्रोह हुए। पर देशभक्त अपने प्रयत्नों में सफल नहीं हो सके। विशेषतया, १८४८ की क्रान्ति की असफलता के कारण इटली में बहुत मुर्दानगी छा गई थी। हजारों शासक कैंद में पड़े मट रहे थे, मैकडो तलवार के घाट उतार दिये थे। जो किसी प्रकार मृत्यु व जेल से बच सके थे, वे विदेशों में भागकर अपनी जान बचा रहे थे। विदेशों में स्थायी अवसर की प्रतीक्षा करते रहने के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग उनके सम्मुख शेष नहीं रहा था। १८४८ की क्रान्ति ने इटली में भयंकर रूप धारण कर लिया था। उसकी असफलता के बाद वहाँ प्रतिक्रिया भी उतनी ही भयंकर हुई थी।

इटली के विविध राज्य—वीएना की कांग्रेस (१८१५) के बाद इटली में जो विविध राज्य विद्यमान थे, उनका निदर्शन आवश्यक है। दक्षिणी इटली में नेपल्स के राज्य का शासन वूर्वों वंश के हाथ में था। नैपोलियन प्रथम के पतन के बाद जब इटली में वहाँ के पुराने विविध राजवंशों का पुनरुद्धार हुआ, तो नेपल्स का शासन वूर्वों राजवंश के फर्डिनेन्ड के मृत्युद दिया गया। फर्डिनेन्ड मेटरनिख का कट्टर अनुयायी था, और अपने राज्य में

उसी के सिद्धान्तों का अनुसरण कर रहा था। मध्य इटली में पोप का शासन था। पोप के शासन-सम्बन्धी सिद्धान्त मध्ययुग के थे, और वह न केवल धार्मिक स्वतन्त्रता को, अपितु राजनीतिक स्वातन्त्र्य को भी महत्त्व नहीं करना था। उत्तरी इटली में लोम्बार्डी और वेनेटिया के प्रदेश मीचे आस्ट्रिया के अधीन थे। उत्तरी इटली में परमा, मोडेना, टस्कनी और लूका के रूप में चार अन्य राज्य विद्यमान थे, जिनमें आस्ट्रिया के हाब्सबुर्ग वंश की पञ्च-पृथक् शाखाओं का शासन था। ये सब राजा आस्ट्रिया के सम्राट के हाथों में कठपुतरी के समान थे। पीडमोंट और सार्डिनिया एक राजा के शासन में थे और इनका राजा भी स्वेच्छाचारी निरंकुश रूप में ही शासन कार्य का संचालन करता था। मिसरी का द्वीप नेपल्स के राजा के हाथों में था। १८१५ के बाद इटली के देशभक्तों के सम्मुख तीन प्रमुख समस्याएँ थी—(१) इटली के जो प्रदेश आस्ट्रिया के विदेशी शासन में हैं, उन्हें स्वतन्त्र करना, (२) इटली के शासन को लोकतन्त्रवाद के अनुकूल बनाना, और (३) इटली की राष्ट्रीय एकता को स्थापित करना।

**स्वाधीनता के लिये विषय भर्ष—**१८१५ के बाद यूरोप के विविध देशों में स्वतन्त्रता और राष्ट्रीयता के लिये जो भर्ष हुए, उनका उल्लेख पहले जगहों में किया जा चुका है। इटली भी इन आन्दोलनों से अछूता नहीं बचा था। कार्बोन्तारी आदि अनेक गुप्त समितियाँ इटली में संगठित थीं, जिनमें सम्मिलित देशभक्त अपने देश में स्वाधीनता की स्थापना के लिये प्रयत्नशील थे। इन्हीं के प्रयत्न में १८०० में नेपल्स में विद्रोह हुआ था, और वहाँ के राजा फर्डिनेन्ड को वैध राजमन्ता की स्थापना के लिये वचनबद्ध होना पड़ा था। १८२१ में पीडमोंट में विद्रोह हुआ, और वहाँ के युवराज (जो आगे चलकर चार्ल्स एल्वर्ट के नाम से पीडमोंट का राजा बना) ने विद्रोहियों के साथ महानुभूति प्रदर्शित की। पर इटालियन स्वाधीनता के ये भर्ष सफल नहीं हो सके। मेटर्निख की प्रेरणा और सहायता से शीघ्र ही इन्हें दबा दिया गया। बहुत से इटालियन देशभक्त इस समय अपनी मातृभूमि को छोड़कर विदेशों में आश्रय लेने के लिये विवश हुए। इसी समय मेजिनी के हृदय में यह विचार उत्पन्न हुआ, कि आल्प्स की पर्वतमाला से लेकर समुद्र पर्यन्त एक विशाल व सुसंगठित इटालियन राष्ट्र का निर्माण होना चाहिये। यही मेजिनी आगे चलकर इटली का प्रसिद्ध नेता बना, और इसके सम्बन्ध में इसी अध्याय में आगे अधिक विस्तार के साथ लिखा जायगा।

१८३० की क्रान्ति की लहर ने इटली पर बहुत प्रभाव डाला। अनेक स्थानों पर विद्रोह हुए, पर इस अवसर पर भी देशभक्तों को अपने प्रयत्नों में सफलता नहीं हुई। १८३१ में मेजिनी ने 'युवक इटली' नाम से एक नई समिति की स्थापना की। इटालियन देशभक्तों के प्रयत्न जिस प्रकार असफल हो रहे थे, मेजिनी उससे निराश नहीं हुआ। वह कहता था—“नये विचार तभी फलते-फूलते हैं, जब शहीदों के खून से उनका सिंचन किया जाय।” १८३० की क्रान्ति की लहर के असफल होने के बाद भी इटली की विविध गुप्त समितियाँ अपने कार्य में तत्पर रही। १८४४ में वान्दीरा बन्धुओं ने आस्ट्रियन नौसेना की नौकरी का परित्याग कर विद्रोह का झण्डा खड़ा किया। नेपल्स की मेनाओं ने इन सबको गिरफ्तार कर लिया और नौ विद्रोहियों को गोली से उड़ा दिया गया। मरते समय भी उनकी जवान

से "इटली चिरजीवी हो" यह ध्वनि गज रही थी।

इटली के अन्य सब राज्यों के राजा तो मेटर्निय के पदचिन्हों पर चल रहे थे, पर पोडमोन्ट की स्थिति कुछ भिन्न थी। १८३१ में वहाँ के राजा मिहासिन पर चार्ल्स एटवर्ट आरुढ़ हुआ था। १८२१ के विद्रोह में उमने देशभक्तों के साथ सहानुभूति प्रदर्शित की थी। राजा बनने के बाद भी वह इटालियन राष्ट्रीयता और लोकतन्त्रवाद के विचारों के प्रति महानुभूति रखता रहा। जागे चलकर इटली में जो राष्ट्रीय एकता स्थापित हुई, उसका केन्द्र पोडमोन्ट ही बना। १८४८ की क्रान्ति की लहर ने इटली पर बहुत प्रभाव डाला। उसके विविध राज्यों में जिम प्रकार अनेक क्रान्तियाँ हुईं, और वे सफल नहीं हो सकीं, इसका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। पर इटली के देशभक्त और क्रान्तिकारी अपने प्रयत्नों में अमफल होकर भी निराश नहीं हुए थे। परस्पर एकमत न होते हुए भी वे अपने-अपने ढंग में देश की राष्ट्रीय एकता और स्वाधीनता के लिये उद्योग में लगे थे।

**रिपब्लिकन दल**—इटली को किस प्रकार स्वाधीन किया जावे, इस विषय में सब देशभक्त आपस में एकमत नहीं थे। एक दल रिपब्लिक का पक्षपाती था। ये लोग राज-सत्ता से तग आ चुके थे। नेपोल्स आदि के विविध राज्यों के राजाओं ने पिछले दिनों में गाननमुधार की प्रतिज्ञाएँ करके किस प्रकार उनका उल्लंघन किया था—इस बात की कटु स्मृति इनके सम्मुख थी। रिपब्लिकन दल के लोग समझते थे, कि सम्पूर्ण राजवशों और राज-गद्गियों का अन्त कर इटली भर में एक रिपब्लिक स्थापित किये बिना देश का उद्धार नहीं हो सकता। इस दल का प्रधान बड़ा नेता मेजिनी था। मेजिनी का जन्म सन् १८०५ में हुआ था। उसका पिता डाक्टर था, और वह फ्रेंच राज्यक्रान्ति का बड़ा पक्षपाती था। बचपन में ही मेजिनी ने अपने पिता से फ्रेंच राज्यक्रान्ति और रिपब्लिकन शासन की गौरवमय कमाओ का श्रवण किया था। उसके हृदय में गुरु से ही क्रान्तिकारी भाव प्रबल हो गये थे। उस समय इटली में फ्रांस के क्रान्तिमय इतिहास का पढ़ना भी भयंकर अपराध था। पर मेजिनी के पिता ने अपने पुस्तकालय में चिकित्सासम्बन्धी ग्रन्थों के पीछे फ्रांस की क्रान्ति के साथ सम्बन्ध रखने वाली पुस्तकें छिपा रखी थी। मेजिनी इन्हें छिप-छिपकर पढ़ा करता था। क्रान्तिकारी साहित्य के पढ़ने से मेजिनी के हृदय में अपने देश को स्वाधीन कराने तथा प्रबल की रिपब्लिक स्थापित करने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हो गई थी। इसीलिये वह इटली की क्रान्तिकारी गुप्त मस्या 'कार्बोनारी' का सदस्य बन गया। यह सस्था १८१५ में स्थापित हुई थी, और इसका उद्देश्य एकतन्त्र स्वेच्छाचारी शासन का अन्त कर लोकतन्त्र की स्थापना करना था। कार्बोनारी की शाखाएँ यूरोप भर में व्याप्त थी, और इसके सदस्यों की सस्या गया तक पहुँची हुई थी। १८३० में मेजिनी गिरफ्तार हो गया और सेवोना के किले में बंद कर दिया गया। यहाँ रहते हुए उसने गुप्तलिपि में अपने साथी क्रान्तिकारियों से पत्र-व्यवहार प्रारम्भ किया और जेल में बन्द रहते हुए भी क्रान्ति के लिये प्रयत्न करना बन्द नही किया। सेवोना की कैद में ही मेजिनी ने अनुभव किया, कि कार्बोनारी जैसी गुप्त समितियाँ स देश का उद्धार नहीं हो सकती। यदि वस्तुतः इटली की उन्नति अभीष्ट हो, तो जनता में और विशेषतया नवयुवकों में ऊँचे विचारों और नवीन आदर्शों का संचार करना चाहिये। जब तक लोगों में नवीन विचारों का भलीभाँति प्रचार नहीं होगा, और इटली के

नवयुवक अपने देश की स्वतन्त्रता और एकता के लिये तीव्र जाकाशा अनुभव नहीं लगेगे, स्वाधीनता का स्वप्न लेना सर्वथा निरर्थक है। इसी उद्देश्य में जेल में मुक्त के बाद उसने 'युवक डटली' नामक एक नवीन समस्या का संगठन किया। इसमें मदेह कि इस समस्या में डटली में बहुत जागृति हुई। लोग नवीन युग की रूपना करने और पराधीनता के बन्धनों को तोड़कर स्वाधीन व संगठित इटालियन राष्ट्र के लिए लिये जनता में प्रबल उत्सुकता उत्पन्न हुई। मेजिनी के अनुयायी रिपब्लिक के पाती थे। राजाओं में उन्हें कोई विश्वास नहीं था। छोटे-छोटे राज्यों का अन्त वे एक शक्तिशाली इटालियन राष्ट्र की स्थापना करना चाहते थे।

**पोप का पक्षपाती दल**—इटालियन देशभक्तों का दूसरा दल पोप के नेतृत्व में संगठन करना चाहता था। इस दल के लोग रोमन कैथोलिक धर्म के कट्टर अनुयायी उनका मत था, कि सम्पूर्ण इटली में केवल एक ही ऐसा व्यक्ति है, जिसके असा प्रभाव और अद्भुत सामर्थ्य के कारण सम्पूर्ण देश की विपरीत हुई शक्तियाँ को एक संगठित किया जा सकता है। यह व्यक्ति है पोप। इस दल का प्रधान नेता कि नामक महानुभाव था।

**वैध राजसत्तावादी दल**—परन्तु इटली का भविष्य इन दोनों दलों के हाथ में नहीं इनके अतिरिक्त एक तीसरा दल भी था, जो सार्डिनिया और पीडमोंट के राजा कि एमेनुअल द्वितीय के नेतृत्व में सम्पूर्ण इटली को संगठित करना चाहता था। यह नव राजा बहुत प्रतिभाशाली, उन्नत विचारों का तथा माहमी व्यक्ति था। १८४८ में पारि और पीडमोंट के पहले राजा चार्ल्स एबर्ट ने आस्ट्रिया के साथ जिम प्रहार लड़ाई लड़े और जिस तरह इटालियन देश-भक्तों का साथ दिया था, उसमें लोगों को प्रबल जा गई थी कि भविष्य में भी देश का उद्धार इसी राजवंश द्वारा हो सकता है। एक उत्तराधिकारी विक्टर एमेनुअल द्वितीय ने वैध राजसत्ता के सिद्धान्तों को स्वीकार लिया था, और उसने अपने राज्य में नवीन मन्त्रान्तों पर आश्रित शासन-विधान स्थापना भी कर दी थी। इसका परिणाम यह था, कि उदार विचारों के लोग उसे मानते थे।

**कावूर**—इस दल का प्रधान नेता कावूर था। उसका जन्म सन् १८१० में हुआ वह पीडमोंट का रहनेवाला था। इटली में उस समय जो उदार आन्दोलन चल रहा उनका कावूर पर वचन में ही प्रभाव पड़ा था। क्रान्तिकारियों के समर्थन में जाकर एकतन्त्र स्वेच्छाचारी शासन का कट्टर विरोधी बन गया था। अपना सासारिक जीवन एक सेनानायक के रूप में प्रारम्भ किया, पर शीघ्र ही सैनिक जीवन से तंग उसने उसका परित्याग कर दिया। इसके बाद उसने अपना अधिकांश समय राजनी और आर्थिक प्रश्नों के अध्ययन में व्यतीत किया। इसी उद्देश्य से अपने गेट ब्रिटेन, और जर्मनी की यात्रा की। इन देशों से जब वह वापस आया, तो वह अपने देश के उ के लिये भावी कार्यक्रम का निश्चय कर चुका था। यही कारण था, कि पुलिस उसे की दृष्टि देखती थी, और हमेशा उस पर कड़ी निगाह रखती थी। ब्रिटिश शासन सबसे अधिक पसन्द था। रिपब्लिक उसे पसन्द नहीं आती थी। वह कहता था, '

होना चाहिये, पर उसकी शक्ति को सीमित करने के लिये निश्चित शासन-विधान और न्यायव्यवस्था की सभाएँ भी होनी चाहिये। वीरे-वीरे कानूर का प्रभाव बढ़ता गया और १८४८ की क्रान्ति के समय जब पीडमोंट में राष्ट्रीय महासभा का संगठन हुआ, तो लोगो ने अनुभव किया कि कावूर मामूली आदमी नहीं है, उसमें राष्ट्र का संचालन करने के लिये आवश्यक सब गुण विद्यमान हैं। पीडमोंट और मार्टिनिया के लिये जो नवीन शासन-विधान १८४८ में बना था, उसके निर्माण में कावूर का बड़ा हाथ था। इसमें सदेह नहीं, कि न केवल सर्वसाधारण जनता पर राजा व राजदरबार के लोग भी वीरे-वीरे यह अनुभव करने लग गये कि कावूर ही एक ऐसा व्यक्ति है जो इटली की समस्याओं को सुलझा सकता है।

समस्याएँ—१८५२ में कावूर को पीडमोंट और मार्टिनिया के सम्मिलित राज्य का प्रधानमंत्री बनाया गया। उस समय उसकी आयु केवल ब्यालीस वर्ष की थी। विक्टर एमैन्युअल द्वितीय को कावूर पर पूरा भरोसा था। योग्य राजा को योग्य मंत्री मिल गया था। प्रधान मंत्री के पद पर जाने ही कावूर ने अनुभव किया, कि इटली का उद्धार करने के लिये निम्नलिखित समस्याओं को हल किये बिना कार्य न चलेगा—

(१) इटली की एकता और स्वाधीनता के लिये उत्तरी इटली में आस्ट्रिया के आधिपत्य को नष्ट करना अवश्यम्भावी है। इस कार्य का नेतृत्व पीडमोंट को ही ग्रहण करना होगा। पर पीडमोंट अकेला इसे नहीं कर सकता। इस कार्य के लिये एक तरफ तो सम्पूर्ण इतालियन राज्यों का सहयोग प्राप्त करना चाहिये, और दूसरी तरफ विदेशी सहायता के लिये भी उद्योग करना चाहिये।

(२) आस्ट्रिया को पराजित करने के लिये अन्य इतालियन राज्यों का सहयोग किस प्रकार प्राप्त किया जाए, इस समस्या को हल कर सकना सुगम नहीं था। यद्यपि इटली में राष्ट्रीयता और स्वाधीनता के लिये आन्दोलन चल रहे थे, पर इन आन्दोलनकर्त्ताओं में एकता नहीं थी। सबके कार्यक्रम भिन्न-भिन्न थे। साथ ही, विविध राजाओं को एक उद्देश्य में संगठित कर सकना तो उस समय सर्वथा असम्भव ही प्रतीत होता था।

(३) आस्ट्रिया यूरोप का अन्यन्त प्रभावशाली तथा प्रबल राज्य था। उसके विरुद्ध अन्य राष्ट्रों की सहायता प्राप्त कर सकना पीडमोंट जैसे मामूली राज्य के लिये सुगम कार्य नहीं था। साथ ही, विविध राजाओं में जनता की भावनाओं के विरुद्ध एक होकर मुकाबला करने की प्रवृत्ति भी अब तक नष्ट नहीं हुई थी।

पीडमोंट की उन्नति—इन सब कठिनाइयों का सामना कावूर ने बड़ी योग्यता और नीतिकृश्रता के साथ किया। अपने राज्य को उन्नत किये बिना किसी भी कार्य में सफलता नहीं हो सकती थी, अतः सबसे पहले पीडमोंट की उन्नति पर ध्यान दिया गया। व्यापार और व्यवसाय की उन्नति करने के लिये विशेष रूप से प्रयत्न किये गये। मुक्त द्वार वाणिज्य की नीति का अवलम्बन कर विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन दिया गया। कारखानों को राष्ट्रीय सहायता दी गई। रेलवे का विस्तार किया गया। दलदलो और ऊँड़ प्रदेशों का सभर खेतों के रूप में परिवर्तित किया गया। शिक्षा की उन्नति की गई। पीडमोंट तीसरे दिन इनी रात चांगुनी उन्नति हुई। देखते-देखते पीडमोंट ही का कहीं पहुँच गया। राष्ट्रीय शक्ति और सहायता से देश वास्त की वास्त में उन्नति कर जाते हैं। राज्य क्या है ?

मनुष्यों का अपने हित के लिये सामूहिक प्रयत्न ही तो है। अठारहवीं सदी तक प्रायः सम्पूर्ण समार में राज्य छोटे-से शासकों के वैयक्तिक मुय के साधनमात्र होते थे। पर उन्नीसवीं सदी में जब राज्यों के स्वरूप में परिवर्तन हुआ, शासकों ने अपनी शक्ति का प्रयास सचमुच मनुष्यों की सामूहिक उन्नति के लिये करना प्रारम्भ किया, तो सर्वतोमुखी समष्टि में जिस वेग में सहायता मिली, उसका वर्णन कर सकना असम्भव है। कावूर के प्रयत्न में पीडमोंट छोटे ही समय में बहुत उन्नति कर गया।

**सम्पूर्ण इटालियन जनता का सहयोग**—पर केवल पीडमोंट की अपनी उन्नति में कुछ नहीं हो सकता था। उसकी कुल आबादी पचास लाख में अधिक नहीं थी। इतना छोटा सा राज्य आस्ट्रिया को परास्त नहीं कर सकता था। उन राष्ट्रीय एकाता के इस महान् कार्य के लिये सम्पूर्ण इटली के सहयोग की आवश्यकता थी। राजाओं ने यह सहयोग प्राप्त नहीं हो सकता था, और न कावूर ने उसके लिये प्रयत्न ही किया। उसने क्रान्तिकारियों के अन्य दलों के साथ वातचीत की, और उन्हें पीडमोंट के राजा को केन्द्र बनाकर अपने देश का उद्धार करने के लिये तैयार किया। मेजिनी जैसे रिपब्लिकन तथा गेरिबान्डी जैसे क्रान्तिकारी उसकी सहायता के लिये उद्यत हो गये। यदि राजा और शासक देशोद्धार के पवित्र कार्य में कावूर के साथ सम्मिलित नहीं हुए, तो क्या हानि थी? जनता उससे हार्दिक सहानुभूति थी, क्रान्तिकारी दलों का सहयोग उसे प्राप्त था। कावूर की उद्देश्यपूर्ति के लिये यही बहुत काफी था। कार्वोनारी, युवक इटली जादि सब मन्त्रियों ने उसका साथ दिया। इटली के सब देशभक्त तथा विचारशील लोग उसके साथ हो गये। कट्टर रोमन कैथोलिक लोगों को अपने पक्ष में करना कठिन था। कावूर ने उनका खल कर विरोध किया। अपने राज्य पीडमोंट से तो उसने जेमुअट सम्पदा के लोगों को वहिष्कृत तक कर दिया। इस प्रकार यदि विविध इटालियन राजाओं और शासकों का नहीं, तो कम से कम बहुसंख्यक जनता का सहयोग प्राप्त करने में वह अवश्य सफल हुआ।

**विदेशी सहायता**—विदेशी सहायता प्राप्त कर सकना अधिक कठिन था। पर कावूर ने इस कार्य में भी असाधारण सफलता प्राप्त की। वह भलीभाँति समझता था, कि आस्ट्रिया के विरुद्ध यदि किसी अन्य देश की सहायता प्राप्त की जा सकती है, तो वह देश फ्रांस है। वह कहा करता था—‘हम चाहे पसंद करे या न करे, पर यह निश्चित है कि हमारा भाग्य फ्रांस पर आश्रित है। शीघ्र ही यूरोप के रंगमंच पर जो नाटक खेला जायगा, उसमें हम फ्रांस के साथ होंगे।’ फ्रांस से मैत्री स्थापित करने के लिये वह बहुत उत्सुक था, और इसके लिये उपयुक्त अवसर प्राप्त करने में उसे देर न लगी। १८५४ में प्रसिद्ध क्रीमियन युद्ध प्रारम्भ हुआ। इसमें फ्रांस, टर्की और ब्रिटेन एक ओर थे, और रूस दूसरी ओर। १८५५ में कावूर ने क्रीमियन युद्ध में फ्रांस का साथ दिया, और अपने १७ हजार सैनिक क्रीमिया के रणक्षेत्र में भेज दिये। क्रीमियन युद्ध की समाप्ति पर सन्धि के लिये पेरिस में जो परिषद् हुई, उसमें पीडमोंट की तरफ से कावूर भी सम्मिलित हुआ। यूरोपियन राज्यों से परिचय प्राप्त करने, फ्रांस से मित्रता करने और इटालियन स्वाधीनता के दावे को अन्य लोगों के सम्मुख पेश करने का यह सुवर्णवसर था। कावूर ने इसका भलीभाँति उपयोग किया। उसने सन्धि परिषद् में एकत्रित राजनीतिज्ञों को अच्छी तरह

यह समझाने का प्रयत्न किया, कि उत्तरी इटली पर आस्ट्रिया का कब्जा यूरोप की शान्ति के लिये बहुत भयकर बात है। जब तक इटली स्वाधीन नहीं होगा, यूरोप में शान्ति कायम नहीं रह सकती। पेरिस की सन्धि परिपक्व में कावर को अच्छी सफलता मिली। पीडमोंट जैसे छोटे से राज्य का प्रतिनिधि यूरोप के अच्छे राजनीतिज्ञों में गिना जाने लगा।

**नैपोलियन तृतीय से समझौता**—उप समय फ्रांस का सम्राट् नैपोलियन तृतीय था। सम्राट् बनने में पूर्व वह इटली में रह चुका था, और कार्विनारी सभा का सदस्य भी था। १८३० की क्रान्ति में वह क्रान्तिकारी स्वयं सेवक के रूप में पोप के विरुद्ध लड़ चुका था। इटालियन स्वाधीनता के आन्दोलन में उसे महानुभूति थी। मान्य ही, वह यह भी समझता था, कि फ्रांस की राजगद्दी में नैपोलियन द्वारा हस्तगत की है। लोग मेरे सम्राट्-पद को उभी दशा में सहन करेंगे, जब कि मैं अपने चचा की तरह गौरवमय विजयों से जनता को चक्काचंध कर दूंगा। यदि इटली को स्वाधीन करने के लिये आस्ट्रिया में युद्ध उद्घोषित कर दिया जाए, तो निम्नन्देह फ्रेंच लोग उसे पसन्द करेंगे। एक बार फिर फ्रेंच सेनाएँ उत्तरी इटली में प्रवेश करेंगी। नैपोलियन के बाहुबल के सम्मुख आस्ट्रिया परास्त हो जायगा। इतिहास अपने को दोहरायागा। इटली में जो नवीन शासन कायम होगा, वह निम्नन्देह फ्रांस का आधिपत्य स्वीकृत करेगा। नैपोलियन तृतीय की इन महत्वाकांक्षाओं को किम प्रकार इटली के लाभ के लिये प्रयुक्त किया जा सकता है, इस बात को कावर खूब समझता था। पेरिस की सन्धि-परिपक्व के समय इन दोनों राजनीतिज्ञों में बातचीत थी। आखिर दोनों में समझौता हो गया। नैपोलियन ने कहा, यदि आस्ट्रिया से युद्ध शुरू करने के लिये तुम कोई बहाना ढूँढ लो, तो मैं दो लाख फ्रेंच सैनिकों के साथ तुम्हारी सहायता करने के लिये तैयार हूँ। दोनों राजनीतिज्ञों ने स्वीकार किया कि यदि उत्तरी इटली से आस्ट्रियन शासन का अन्त हो जाए, तो नीस और सेवॉय के प्रदेश—ये फ्रांस और इटली के—फ्रांस को दे दिये जायेंगे, और आस्ट्रिया की अवीनता से मुक्त हुए लोम्बार्डी और वेनेटिया के प्रदेशों पर पीडमोंट का कब्जा रहेगा, और उत्तरी इटली के अन्य प्रदेशों के पीडमोंट द्वारा हस्तगत कर लेने में भी फ्रांस को कोई आपत्ति न होगी।

इस प्रकार विदेशी सहायता भी प्राप्त हो गई। कावर के सम्मुख जो विकट समस्याएँ विद्यमान थी, सब हल हो गईं। अब केवल उद्देश्य को पूर्ण करना शेष था।

## २ स्वाधीनता संग्राम का प्रारम्भ

बान्द तैयार हो गया था, अब उसे केवल नीली दिखाने की जरूरत थी। कावर युद्ध के लिये बहाना ढूँढ रहा था। उधर आस्ट्रिया भी लड़ाई के लिये अवसर देख रहा था। पीडमोंट की उन्नति उसे शूल की तरह चुभ रही थी। कावर की चालों से भी वह सर्वथा अपरिचिन न था। आस्ट्रियन राजनीतिज्ञ समझते थे, जितनी देर होगी, उतना ही हमारा नुकसान है, उतनी ही पीडमोंट की शक्ति बढ़ती जायगी। इस दशा में युद्ध शुरू होने में क्या देर हो सकती थी? आखिर, युद्ध शुरू हो गया।

**युद्ध का प्रारम्भ**—कावर के इशारे से लोम्बार्डी और वेनेटिया में विद्रोह हो रहे थे। आस्ट्रिया इनमें बहुत तग आ गया था। उधर पीडमोंट में प्रशिया के दग पर बड़े

जोर शोर से सैनिक संगठन किया जा रहा था। आस्ट्रिया को समझ नहीं पड़ता था, कि उसके अपने साम्राज्य में निरन्तर विद्रोहों को किस प्रकार शान्त किया जाय? काबूर के आदमी अपना कार्य कर रहे थे। उनकी सहायता के कारण लोम्बार्डी और वेनेटिया के क्रांतिकारियों की हिम्मत बढ़ती जाती थी। आगिर, आस्ट्रिया ने पीडमोंट को नोटिस दिया, कि तीन दिन के अन्दर-अन्दर नई भर्ती हुई सेनाओं को बर्खास्त कर दिया जाय। काबूर तो युद्ध चाहता ही था। उसने आस्ट्रियन नोटिस की कोई परवाह नहीं की। ११ अप्रिल, १८५९ के दिन आस्ट्रिया और पीडमोंट में युद्ध प्रारम्भ हो गया।

काबूर सब तैयारी पहले ही कर चुका था। समग्र इटली देशभक्ति और राष्ट्रीयता के भावों में प्रदीप्त हो गया। सर्वत्र स्वयमेवक भर्ती होने लग। स्वाधीनता की लहर ने सम्पूर्ण देश को व्याप्त कर लिया। यूरोप के अन्य देशों की सहायता भी पीडमोंट के साथ थी। आस्ट्रिया जैसे शक्तिशाली राज्य का पीडमोंट जैसे तुच्छ राज्य पर आक्रमण किसी को भी पसन्द नहीं था। फ्रांस तो पहले से ही तैयार बैठा था। शट नैपोलियन की सेनाएँ इटली पहुँच गई। काबूर ने पीडमोंट की पार्लियामेंट में भाषण देने हुए कहा—अब जगती पार्लियामेंट सारे इटली की होगी, केवल पीडमोंट की नहीं। निम्नन्देह, वह ठीक था।

यह युद्ध केवल दो मास तक जारी रहा। मजन्टा और माफेगिनो के युद्धों में आस्ट्रियन सेनाएँ बुरी तरह से परास्त हुईं। विक्टर एमैन्युअल द्वितीय ने बड़ी मुशाम के नाम लोम्बार्डी की राजधानी मिलान में प्रवेश किया। टस्कनी, परमा और मोडेना के राज्यों में हाप्सबुर्ग वंश के विविध राजाओं को राज्यच्युत कर दिया गया। पोप के राज्य के उत्तरी प्रदेशों ने भी उद्घोषित किया, कि हम पोप के अधीन न रहेंगे। ये सब प्रदेश पीडमोंट के राज्य में सम्मिलित होना चाहते थे। जनता की यही इच्छा थी।

**नैपोलियन तृतीय का युद्ध से पृथक् होना—**इटालियन स्वाधीनता का यह नयाम इस प्रकार पूर्ण सफलता के साथ चल रहा था, कि सम्पूर्ण यूरोप ने बड़े ही आश्चर्य के साथ यह सवाद सुना, कि नैपोलियन तृतीय आस्ट्रिया के साथ सन्धि करने को उद्यत है। बात यह थी, कि पीडमोंट की असाधारण सफलता में नैपोलियन घबरा गया था। वह समझता था, कि यदि इटालियन लोग इसी प्रकार सफल होते रहे, तो इटली अत्यन्त शक्तिशाली राज्य बन जायगा, और उसे फ्रांस की सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। इटली की राष्ट्रीय एकता से फ्रांस को कोई लाभ न था। अपने पड़ोस में एक शक्तिशाली स्वतन्त्र राज्य की स्थापना नैपोलियन को पसन्द न थी। इसके अतिरिक्त, युद्ध कितना भयंकर होता है, इसका नैपोलियन तृतीय को कोई अनुभव न था। उसके चाचा को युद्ध में वास्तविक आनन्द आता था, पर नैपोलियन तृतीय में साहस और वीरता का अभाव था। वह समझता था, कि आस्ट्रियन लोगों को वेनेटिया से बाहर निकालने में कमसे कम तीन लाख सैनिकों की आवश्यकता होगी। इतने सैनिकों को जुटा सकने की नैपोलियन को कोई आशा नहीं थी। साथ ही, इस बात की भी खबर थी, कि प्रशिया आस्ट्रिया की सहायता के लिये तैयारी कर रहा है, और स्वाभाविक रूप से प्रशिया फ्रांस पर ही आक्रमण करेगा। इन सब कारणों से नैपोलियन ने यही उचित समझा, कि शटपट आस्ट्रिया से सन्धि कर ली जाए। उसने पीडमोंट को सूचना तक देने की आवश्यकता नहीं समझी।



**ज्यूरिच की सन्धि**—नैपोलियन के इस प्रकार युद्ध में पृथक् हो जाने का परिणाम यह हुआ, कि पीडमोंट को भी आस्ट्रिया में मन्वि करने के लिये विवश होना पड़ा। यद्यपि काबूर की इच्छा थी, कि अकेले ही युद्ध को जारी रखा जाए, पर राजा विक्टर एमेनुअल इससे सहमत नहीं था। वह भलीभांति अनुभव करता था, कि फ्रांस की सहायता के बिना आस्ट्रिया को परास्त कर सकना असम्भव है। उप दशा में इटली और आस्ट्रिया के युद्ध की समाप्ति हो गई, और १० नवम्बर, १८५९ के दिन ज्यूरिच नामक स्थान पर दोनों राज्यों ने परस्पर सन्धि कर ली। इस सन्धि द्वारा लोम्बार्डी का प्रदेश पीडमोंट को प्राप्त हुआ। वेनेटिया आस्ट्रिया के ही अधीन रहा। नीम जीर मेवाय फ्रान्स को मिले, और परमा, मोडेना तथा टस्कनी को पीडमोंट ने अपने कब्जे में कर लिया। ज्यूरिच की सन्धि से इटालियन देशभक्तों की वास्तविक जाकाधा पूर्ण नहीं हो सकी। वेनेटिया का आस्ट्रिया के अधीन रहना उन्हें शूल की तरह चुभ रहा था। इस के अतिरिक्त, मध्य तथा दक्षिणी इटली अभी राष्ट्रीय एकता के सूत्र में सम्बद्ध नहीं हुए थे। वहाँ अनेक पृथक् राज्य अब भी विद्यमान रहे। राष्ट्रीय संगठन के आदर्श को पूर्ण करने के लिये अभी एक प्रयत्न की और आवश्यकता थी। इसे सम्पन्न होने में भी बहुत देर नहीं लगी। राष्ट्रीय एकता और स्वाधीनता की जिस प्रचण्ड भावना को १८५९ में अमान्यारण सफलता प्राप्त हुई थी, वही नविय में भी काम आई। शीघ्र ही, इटली एक संगठित व स्वतन्त्र राष्ट्र बन गया।

### ३ राष्ट्रीय एकता की स्थापना

आस्ट्रिया परास्त हो गया था। उत्तरी इटली के अधिकांश प्रदेशों पर विक्टर एमेनुअल द्वितीय का आधिपत्य स्थापित हो चुका था। इस समय शेष इटली को पीडमोंट के साथ सम्मिलित करने के लिये जो आन्दोलन प्रारम्भ हुआ, उसमें किसी विदेशी शक्ति की सहायता प्राप्त नहीं की गई। वह इटालियन राष्ट्रीयता की अपनी कृति थी। सम्पूर्ण इटली को राष्ट्रीय एकता में पुराने राजवंश जो बाधा डाल रहे थे, उसे जनता ने अपने ही प्रयत्न में नष्ट कर दिया। इस नवीन आन्दोलन का नेता प्रधान नेता गेरीवाल्डी था।

**गेरीवाल्डी**—गेरीवाल्डी का जन्म नीस नामक स्थान पर सन् १८०७ में हुआ था। जे रोमानो की शिक्षा प्राप्त हुई थी। उसकी प्रवृत्तियाँ गुरु से ही रिपब्लिकन थी। मेजिनी के सम्मिलित कर वह सम्पूर्ण इटली में एक रिपब्लिक स्थापित करने के लिये उद्योग कर रहा था। उसी अपराध में सरकार की उस पर कोप-दृष्टि हो गई, और उसे दक्षिणी अमेरिका भाग जान के लिये बाधित होना पड़ा। वहाँ पर भी वह शान्त नहीं बैठ सका। उन दिनों दक्षिणी अमेरिका में लेटिन-अमेरिकन लोग स्वाधीनता प्राप्त करने के लिये कोशिश कर रहे थे। गेरीवाल्डी उनमें सम्मिलित हो गया। दस वर्ष तक वह निरन्तर अमेरिकन स्वाधीनता-युद्ध में युद्ध करता रहा। इसके बाद वह अपने देश वापस लौट आया। स्वतन्त्रता के लिये जहाँ भी प्रयत्न हो रहा हो, गेरीवाल्डी सर्वत्र सहायता करने को उद्यत था। १८८७ में इटली में यह लहर बड़ी तीव्र थी, कि पोप पायस दशम के नेतृत्व में इटली की राष्ट्रीय एकता स्थापित की जाए। गेरीवाल्डी इससे सहमत नहीं था, पर सच्चे सिपाही के भाव में यह मोचने की आवश्यकता नहीं थी, कि उसकी अपनी सम्मति क्या है। उसके



क्रान्तिकारी गैरीवाल्डी

लिये इतनी बात ही पर्याप्त थी, कि इटली की स्वाधीनता तथा राष्ट्रीय एकता के लिये प्रयत्न हो रहा है। वह उसमें सम्मिलित हो गया। अगले वर्ष १८४८ में इटली में क्रान्ति हुई।

पीडमोंट के नेतृत्व में इटालियन लोग आस्ट्रिया को परास्त करने के लिये सन्नद्ध हो गये। गेरीवाल्डी ने डमयुद्ध के लिये ३००० स्वयंसेवक एकत्रित किये। परन्तु १८४८ की क्रान्ति नफल नहीं हो सकी। क्रान्तिकारियों पर भयङ्कर अत्याचार किये गये। गेरीवाल्डी फिर अपना देश छोड़कर अमेरिका चला गया। डेढ़ बार उसने न्यूयार्क में कारोवार शुरू किया। बारोवार में उसे अच्छी सफलता मिली। काफी धन कमाकर वह फिर इटली वापस आया, और अपने देश के समीप ही कपरेरा नाम का एक टापू खरीद कर उसमें आराम में रहने लगा। पर गेरीवाल्डी को अब भी शान्ति नहीं थी, वह इटली के आन्दोलनों का बड़े ध्यान से अध्ययन कर रहा था। १८५९ में कावूर की नीतिनिपुणता में जब आस्ट्रिया के साथ युद्ध प्रारम्भ हुआ, तब गेरीवाल्डी उसमें सम्मिलित हो गया। लोम्बार्डी में आस्ट्रियन सेनाओं को बाहर निकालने में उसने बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया था।

**सिसली पर आक्रमण**—पर गेरीवाल्डी का वास्तविक कार्य १८६० में शुरू होता है। इन समय इटालियन देशभक्तों के सम्मुख सबसे बड़ी समस्या दक्षिणी इटली को अपने साथ सम्मिलित करने की थी। दक्षिणी इटली में—नेपल्स और सिसली में—बूर्जोय वग का एक पुराने ढंग का राजा राज्य करता था, जो राष्ट्रीय एकता, स्वाधीनता, शासन-सुधार आदि सम्पूर्ण नवीन भावनाओं का कट्टर विरोधी था। नेपल्स के इस राजा को परास्त करना कावूर के सम्मुख सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। आखिर, गेरीवाल्डी ने यह कार्य अपने हाथ में लिया। एक हजार स्वयंसेवकों के साथ उसने सिसली में प्रवेश किया। ये स्वयंसेवक लाल कुरते पहनते थे, इनका वेग बहुत मजबूत होता था। इतिहास में ये लोग 'लाल कुडती' के नाम से प्रसिद्ध हैं। मई, १८६० में अपनी 'लाल कुडती' सेना के साथ गेरीवाल्डी सिमली पहुँच गया। सिसली की जनसंख्या तीस लाख में कम नहीं थी। पर गेरीवाल्डी का मुकाबला करनेवाला वहाँ कौन था? जनता की सहानुभूति उसके साथ थी, बात की बात में सिमली गेरीवाल्डी के अधीन हो गया।

**नेपल्स की अधीनता**—गेरीवाल्डी ने उद्घोषित किया, कि मैं विक्टर एमेनुअल द्वितीय की तरफ से सिसली का शासन अपने हाथों में लेता हूँ। सिसली की जनता ने उसका साथ दिया। विक्टर एमेनुअल द्वितीय के अधीन होकर उन्हें हार्दिक प्रसन्नता थी। जनता में राष्ट्रीय एकता की जो भावना उत्पन्न हो चुकी थी, वस्तुतः वह अपना कार्य कर रही थी। गेरीवाल्डी तो उसमें निमित्तमात्र था। सिसली में रहते हुए गेरीवाल्डी के स्वयंसेवकों की संख्या एक हजार से बढ़कर चार हजार तक पहुँच गई। इस सेना को लेकर उसने नेपल्स की ओर प्रस्थान किया। वहाँ पचास हजार देशभक्त उसके आगमन की बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे थे। नेपल्स पर हमला किया गया। बूर्जोय राजा फ्रांसिस द्वितीय उसका मुकाबला नहीं कर सका। नेपल्स जीत लिया गया, और फ्रांसिस द्वितीय देश छोड़कर भाग गया। गेरीवाल्डी नेपल्स का भी शासक बन गया।

**राष्ट्रीय एकता की स्थापना**—गेरीवाल्डी की इच्छा थी, कि अब रोम पर आक्रमण कर उसे भी अपने अधीन कर लिया जाए। यदि वह रोम पर आक्रमण करता, तो उसे अवश्य ही सफलता प्राप्त हो जाती। पर कठिनाता यह थी, कि फ्रांस इस बात को सहन करने के लिये तैयार नहीं था। फ्रेंच लोग रोमन कैथोलिक धर्म को मानने वाले थे। वे पोप

की राजधानी का इस प्रकार 'अपमान' कभी सहन न कर सकने, और नैपोलियन तृतीय को इटालियन एगना के मार्ग में रोड़े जटकाने का एक उत्तम अवसर हाथ लग जाता। इसीसे रोम पर आक्रमण करने का प्रचार छोट दिया गया, और विस्टर एमेनअल द्वितीय न रोम को छोड़कर पोप के अन्य सब प्रदेशों को अपने हस्तगत कर लिया। रोम पर पोप का स्वामित्व अधुण रहा। परन्तु नेपोलम, मिसली और पोप का राज्य (रोम को छोड़कर) अब विस्टर एमेनअल द्वितीय के अधीन हो चुके थे। मध्य और दक्षिणी इटली के प्रदेश भी अब राष्ट्रीय एकता क्रम में संगठित हो गये थे।

कावूर की मृत्यु—१८६१ के दिन इटली की राष्ट्रीय महामाया का अभिवेशन प्रारम्भ हुआ। महामाया के लिये टर्गिन नगर चुना गया था। इटली की स्वाभाविक राजधानी रोम अभी तक पोप के अधीन थी। इसीसे यहाँ अधिवेशन नहीं किया जा सकता था। १७ मार्च को राष्ट्रीय महामाया ने विस्टर एमेनअल द्वितीय को इटली का राजा स्वीकृत किया। इस प्रकार इटली की राष्ट्रीय एकता स्थापित हुई, और कावूर का स्वप्न पूर्ण हो गया। अपने कार्य को पूरा कर १८६१ में कावूर की मृत्यु हो गई। वह कार्यभार में बहुत अधिक थकान से चुका था, पर जानी आकांक्षा के पूर्ण हो जाने से उसके हृदय में वास्तविक प्रसन्नता थी।

इटली की राष्ट्रीय एकता के पूर्ण होने में अभी दो रुमिया शेष थी। वेनेटिया अभी तक भी आस्ट्रिया के अधीन था और रोम पर पोप का शासन था। इटालियन देशभक्त इन दोनों प्रदेशों के अभाव में अपने राष्ट्र को पूर्ण नहीं समझते थे। परन्तु उन्हें प्राप्त करने के लिये भी शीघ्र ही अवसर उपस्थित हुए, और इटालियन राजनीतिज्ञों ने उनका बड़ी कुशलता से प्रयोग किया।

वेनेटिया की प्राप्ति—१८६६ में आस्ट्रिया और प्रशिया में युद्ध प्रारम्भ हुआ। इन युद्ध में इटली ने प्रशिया की सहायता की। इटली और प्रशिया दोनों ने एक साथ आस्ट्रिया पर आक्रमण किया। इटली को परास्त कर सकना आस्ट्रिया के लिये कठिन नहीं था। शीघ्र ही, उसकी सेनाएँ पराजित होकर लौट आईं। पर आचिरकार युद्ध में प्रशिया की विजय हुई और आस्ट्रिया परास्त हुआ। सन्धि परिपद में इटली भी विजयी प्रशिया के साथ सम्मिलित हुआ, और अपनी हार्दिक मनोकामना—वेनेटिया की प्राप्ति—को पूर्ण करने में समर्थ हुआ। आस्ट्रिया के विरुद्ध प्रशिया की सहायता करने का यह अच्छा और न्याय्य इनाम था। दो छोटे-छोटे प्रदेश और ये, जो वेनेटिया के साथ ही आस्ट्रिया के अधीन थे—ट्रेंट और ट्रिएस्त। इटली की कोशिश थी, कि इन्हें भी इस अवसर पर प्राप्त कर ले। पर इसमें उसे सफलता नहीं हुई। १९१८ तक ये प्रदेश आस्ट्रिया के ही अधीन रहे। राष्ट्रीय इटली को यह बात काटे की तरह चुभती रही। आखिर, १९१४-१८ के यूरोपीय महायुद्ध की समाप्ति पर जब आस्ट्रिया परास्त हुआ, तब इटली इन प्रदेशों को भी अपने साथ सम्मिलित करने में सफल हुआ।

रोम की प्राप्ति—रोम को अपने साथ मिलाने का अवसर १८७० में उपस्थित हुआ। फ्रांस की सहायता से पोप रोम में अपने अधिकार को अधुण बना सकने में समर्थ था। नैपोलियन तृतीय की ओर से भेजी हुई एक फ्रेंच सेना हमेशा रोम में मौजूद रहती थी, और

इटालियन देशभवतो के सब प्रयत्नों का मुकाबला करती रहती थी। १८७० में फ्रांस और प्रशिया में युद्ध शुरू हुआ। प्रशिया का मुकाबला करने के लिये नैपोलियन को बाधित होना पड़ा, कि अपनी सेनाओं को रोम में वापस बुला ले। जब पोप गया कर सकता था ? विक्टर एमैनुअल द्वितीय ने चाहा, कि पोप से किसी प्रकार का समझौता हो जाए। पर वह तैयार नहीं हुआ। इस पर एक इटालियन सेना ने रोम पर आक्रमण कर दिया। रोमन जनता की महानुभूति भी आक्रान्ताओं के पाथ थी। पोप भागकर अपने एक राजप्रासाद में जा छिपा, और रोम पर इटालियन सेना का कब्जा हो गया। रोम-निवासियों में इस प्रश्न पर सम्मति ली गई, कि वे इटली के साथ सम्मिलित होना चाहते हैं या नहीं ? एक लाख तीस हजार वोट पक्ष में आये, और पन्द्रह सौ वोट विरोध में। पोप ने बार-बार अपने कैथोलिक भक्तों और अनुयायियों का अपनी सहायता के लिये जावाहन किया, बार-बार फतवे (वूल) निकाले, पर किसी का कुछ प्रभाव न हुआ। इटली की अधिकांश जनता कैथोलिक धर्म का माननेवाली थी। पर उसने पोप के फतवों पर कोई ध्यान नहीं दिया। तीन सदी पहले पोप की उँगली के इशारे पर मारा यूरोप युद्ध के लिये तैयार हो सकता था। पर अब जमाना बदल चुका था। धर्म का स्थान अब राष्ट्रीयता ने ले लिया था।

यह सर्वथा स्वाभाविक था, कि मगठिन इटली की नवीन राजधानी रोम को बनाया जाय। १८७१ में राजा, दरबार और पार्लियामेन्ट—सब रोम में चले आये। रोम में पार्लियामेन्ट का उद्घाटन करते हुए विक्टर एमैनुअल ने कहा—हमारी राष्ट्रीय एकता स्थापित हो गई है जब हमारा कार्य अपने राष्ट्र को महान् तथा समृद्ध बनाना है। वस्तुतः इटली के सम्मुख अब यही कार्य था। इसमें उसे अमाधारण सफलता हुई। शीघ्र ही इटली यूरोप के प्रमुख राज्यों में गिना जाने लगा।

पोप की स्थिति—इस अध्याय को समाप्त करने से पूर्व यह बताना आवश्यक है, कि रोम के अधिकृत हो जाने के बाद पोप की क्या स्थिति रह गई। एक हजार वर्ष के लगभग रोम पर पोप का अबाधित प्रभुत्व था। पर अब उसका यह अधिकार नष्ट हो गया। १८७१ के मई मास में इटली की पार्लियामेन्ट ने एक कानून पास किया, जिसमें यह उद्घोषित किया गया, कि पोप को वार्षिक मामलों में पूर्ण स्वाधीनता रहेगी, और उसके व्यक्तित्व को राजा के समान पवित्र समझा जायगा। वह स्वतन्त्र राजाओं के समान शान-शौकत में रह सकेगा, और उसे यह भी अधिकार होगा, कि विदेशों में अपने दूत भेजे और विदेशी दूत उसके दरबार में आवें। अपने राजप्रासाद तथा उसके चारों ओर के छोटे से प्रदेश में वह स्वतन्त्र राजा के समान रहेगा, और इटालियन सरकार का कोई कर्मचारी उसके 'राज्य' में प्रवेश नहीं कर सकेगा। यह भी व्यवस्था की गई, कि इटालियन राज्यकोष में पोप को प्रतिवर्ष उन्नीस लाख रुपये पेशन के तौर पर दिये जाया करेंगे। पर पोप इन व्यवस्थाओं में मन्गुट नहीं हुआ। उसने न केवल पेशन लेने से इन्कार किया, पर साथ ही एक उद्घोषणा प्रकाशित की, जिसमें कि इटालियन सरकार के कार्यों का विरोध किया गया और रोम पर अपना अधिकार स्थापित किया गया। परन्तु पोप की इन उद्घोषणाओं की ओर ध्यान न देकर अब कोई न रहा था।

उन्नीसवा अध्याय

## जर्मनी का संगठन

### १. राष्ट्रीयता एकता का प्रादुर्भाव

राष्ट्रीयता की भावना—जर्मनी में राष्ट्रीयता की भावना को उत्पन्न करने के लिये जो विविध तत्त्व कार्य कर रहे थे, उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। फ्रेंच राज्यक्रान्ति के समय क्रान्ति की नवीन प्रवृत्तियों ने जर्मनी पर बहुत प्रभाव डाला था। विशेषतया, नैपोलियन की विजयों के अनन्तर विविध जर्मन राज्यों में एकता की आवश्यकता अनुभव होने लग गई थी। कतिपय राज्यों को मिलाकर नैपोलियन ने जिम स्प्र का निर्माण किया था, उसके कारण जर्मन लोगों को एक संगठन में रहने का अभ्यास भी प्रारम्भ हो गया था। १८१५ में वीएना की कांग्रेस में स्टाइन जैसे जर्मन देशभक्तों ने इस बात पर बहुत जोर दिया था, कि विविध जर्मन राज्यों को एक सूत्र में संगठित किया जाए। उस समय जर्मन जनता की मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। विविध राजवंशों का पुनरुद्धार किया गया और राजवंशों तथा कुलीन श्रेणी के हितों को दृष्टि में रखकर राज्यों की नई व्यवस्था की गई। देशभक्तों की इच्छाओं की उपेक्षा कर वीएना में जिस जर्मन राज्यसंघ का निर्माण किया गया था, उसमें कुल मिलाकर ३८ राज्य सम्मिलित थे। पर इन राज्यों का संगठन सुदृढ़ नहीं था। प्रत्येक राजा पूर्णतया स्वतन्त्र था। जर्मन राज्य सँघ की एक राजसभा बनायी गई थी, जिसमें अधिवेशन फ्राकफोर्ट में होते थे। पर इस सभा के सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित नहीं होते थे, राजा ही उन्हें मनोनीत करते थे। राजसभा में कोई प्रस्ताव तब तक स्वीकृत नहीं समझा जाता था, जब तक कि सम्पूर्ण प्रतिनिधि उसमें सहमत न हो। यदि किसी एक राज्य का प्रतिनिधि भी किसी प्रस्ताव के विरोध में हो, तो उसे अस्वीकृत समझा जाता था। इस व्यवस्था का परिणाम यह था, कि सुधार व उन्नति की कोई भी बात फ्राकफोर्ट की राजसभा में पास न हो सकती थी। राजा लोग जर्मनी की राष्ट्रीय एकता और जनता के अधिकार—दोनों के विरोधी थे। परन्तु जनता में स्वाधीनता और राष्ट्रीयता की प्रवृत्तियाँ काम कर रही थी। गुप्त समितियाँ इन सिद्धान्तों के प्रचार में विशेषरूप से तत्पर थीं। विश्वविद्यालयों में रात दिन इनकी चर्चा रहती थी। विद्यार्थियों के दिमागों में नये विचार घर कर गये थे। संगीत, कविता, व्याख्यान, नाट्य—आदि साधनों स्वाधीनता और राष्ट्रीयता का प्रचार किया जा रहा था। यही कारण है, कि १८३० और १८४८ में जर्मनी में भी अनेक स्थानों पर क्रान्तियाँ हुईं। यद्यपि ये क्रान्तियाँ कहीं भी पूर्णतया सफल नहीं हो सकीं, तथापि इनसे इतना लाभ अवश्य हुआ कि जनता में जागृति उत्पन्न हो गई। विशेषतया, १८४८ में फ्राकफोर्ट में राजसभा की सर्वथा उपेक्षा कर जिस राष्ट्रीय

महामभा की स्थापना की गई थी, उसने राष्ट्रीय एकता के लिये मैदान तैयार करने में बहुत सहायता पहुँचाई। एक बार जर्मन लोगो ने अच्छी तरह अनुभव कर लिया, कि हम सब एक हैं, और हमारे राष्ट्र को शीघ्र ही सगठित होना चाहिये। राजाओ के विरोध से फ्राफोर्ट की महामभा सफल न हो सकी। पर उसने जो कार्य किया था, वह व्यर्थ नहीं गया।

**आर्थिक दृष्टि से एकता की आवश्यकता**—राष्ट्रीयता की प्रवृत्ति के अतिरिक्त कुछ आर्थिक कारण भी थे, जो जर्मनी को एक राष्ट्र बनाने के लिये ताम्र कर रहे थे। जर्मनी के सब राज्य अपने को एक दूसरे में सर्वथा पृथक्-पृथक् समझते थे। इसका परिणाम यह था, कि सबके व्यापारिक कानून पृथक्-पृथक् थे। सबमें आयात और निर्यात माल पर कर लिये जाते थे। इसका असर व्यापार पर गया होता था, इसे एक उदाहरण द्वारा सुगमता में समझा जा सकता है। फुन्डा और आटनबुर्ग के बीच की दूरी केवल १२५ मील है। यदि कोई व्यापारी अपना माल लेकर फुन्डा में आटनबुर्ग जाता था, तो उसे ३४ राजकीय सीमाओं को पार करना पड़ता था। जर्मन में प्रत्येक चार मील चल चुकने के अनन्तर उसे नवीन राजकीय सीमा में गुजरना होता था, और वहाँ चुगी आदि तरह-तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। व्यापारी लोग इस से बहुत तंग थे। १८१० में व्यापारियों की एक सभा ने फ्राफोर्ट की राजसभा से शिकायत की थी, कि हैम्बुर्ग से आस्ट्रिया या वर्लिन से स्विट्जरलैण्ड तक जाने के लिये दस राज्या को पार करना पड़ता है, और उस व्यापारी को, जिसने एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल ले जाना हो, दस विविध व्यापारी कानूनों तथा चुगी के कायदों का अनुशीलन करना होता है। जर्मन व्यापारियों के लिये यह कितनी बड़ौत समस्या थी, इसका अनुमान सहज में किया जा सकता है।

**व्यापार-संघ**—इसी का परिणाम हुआ, कि १८३४ में अनेक जर्मन राज्यों ने परस्पर मिलकर व्यापारिक प्रयोजनों के लिये एक व्यापार-संघ (डुशालफेराइन) का सगठन किया। इसमें १७ राज्य सम्मिलित हुए। इन राज्यों में आन्तरिक व्यापारी माल पर कोई चुगी नहीं लगती थी, पर जब विदेशों से कोई माल इस संघ में प्रविष्ट होता था, तब उस पर चुगी ली जाती थी। धीरे-धीरे अन्य जर्मन राज्य भी इस संघ में सम्मिलित हो गये। वे नदीभाति अनुभव करने थे, कि व्यापारी दृष्टि से जर्मन राज्यों का हित इसी बात में है, कि मिलकर एक सब का निर्माण कर लें। व्यापार-संघ ने जर्मनी की राष्ट्रीय एकता में बहुत सहायता पहुँचाई। आर्थिक हित मानवीय मामलों में बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जब आर्थिक दृष्टि से जर्मन लोगो को एकता अवश्यम्भावी प्रतीत हो रही थी, तब राजनीतिक तथा राष्ट्रीय एकता की उपयोगिता का अनुभव करना बहुत कठिन न था।

**प्रशिया की महत्वाकांक्षा**—यह पहले प्रदर्शित किया जा चुका है, कि १८१५ में बने जर्मन राज्यसंघ में दो राज्य सबसे प्रमुख थे—आस्ट्रिया और प्रशिया। अपनी प्रभुता स्थापित करने के लिये इन दोनों में संघर्ष चल रहा था। प्रशिया के अविकाश निवासी जर्मन नागरिक थे। आस्ट्रिया के राज्य में जर्मन लोगो की कमी नहीं थी, पर हाप्सबुर्ग वंश के आस्ट्रियन प्रदेशों ने बहुत से लोग चैक, स्लाव आदि गैर-जर्मन जातियों के भी थे। यही कारण था, कि राष्ट्रीय दृष्टि से सगठित जर्मन राज्य में आस्ट्रिया का प्राधान्य नहीं हो

मकता था। उपलिखे जास्ट्रिया चाहता था, कि जर्मनी का संगठन बहुत ही कमजोर तथा छीला-छाया रहे। जर्मनी में राष्ट्रीयता की भावना विकसित हो जाने पर गैर-नमन जानियों द्वारा आवाद जास्ट्रिया उसमें कभी भी महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं कर सकेगा, उस बात को प्रशिया पूर्व समझता था। जर्मनी में जास्ट्रिया ने जो सर्वाच्च स्थान प्राप्त किया हुआ था, उसे नाष्ट करने का एक अच्छा और सरल उपाय यह था, कि प्रशिया जर्मन राष्ट्रीयता का पक्षोपेक्ष करे। प्रशिया ने इसी उपाय का प्रयोग किया। प्रशिया के उत्कर्ष के लिये जो विविध राजनीतिज और नेता कार्य कर रहे थे, उन्होंने जर्मनी की राष्ट्रीय भावनाओं का साथ दिया। व्यापार-संघ का निर्माण प्रशिया के नेतृत्व में ही हुआ था। जास्ट्रिया उस संघ का प्रया की दृष्टि से दयता था, और वह उसमें सम्मिलित नहीं हुआ था। प्रशिया उस व्यापार-संघ का प्रमुख प्रवर्तक था। फ्रांकोर्टे की सन्मति के रूप में जास्ट्रिया के नेतृत्व में जिस जर्मन राज्यसंघ का निर्माण हुआ था, जर्मन जनता उसमें सर्वथा विरुद्ध थी। परन्तु प्रशिया के नेतृत्व में संगठित व्यापार-संघ की उपयोगिता में किसी भी देशभक्त को सन्देह नहीं था।

प्रशिया की सेना—मैनिक दृष्टि में प्रशिया जिस प्रकार अमानादग उत्पत्ति कर रहा था, उस पर भी कुछ प्रकाश डालने की आवश्यकता है। नैपोलियन के युद्धों में प्रशिया जिस प्रकार फ्रांस द्वारा पराजित हुआ था, उनमें प्रशियन नेता बहुत उद्धिग्न थे। डमरिय टिलसिट की सन्धि के बाद उन्होंने मेना के पुनः संगठन का उपक्रम किया। शान्तहोस्ट की प्रेरणा से प्रशिया में वाधित मैनिक सेवा की पद्धति जारी हो गई। प्रन्सेन पुष्प के सिद्धे आवश्यक था, कि वह मैनिक शिक्षा प्राप्त करे और कुछ निश्चित समय तक मेना में काम करे। निश्चित समय के समाप्त हो जाने पर उसे इजाजत थी, कि वह अपनी इच्छा में कोई स्वतन्त्र कार्य कर सके। पर निश्चित समय के बाद भी आवश्यकता पडने पर उसे मैनिक सेवा के लिये बुलाया जा सकता था। इस पद्धति में देश के सम्पूर्ण युवक सेना में भर्ती रहते थे, और सेवाकाल के समाप्त हो जाने पर भी आवश्यकता पडने पर उन्हें सेना में भर्ती किया जा सकता था। इस प्रकार देश के मैनिक कार्य के योग्य आयु के सम्पूर्ण पुष्प प्रशियन सेना में सम्मिलित होने के लिये उद्यत रहते थे। इस पद्धति का परिणाम यह हुआ, कि प्रशियन सेना यूरोप भर में सबसे आगे बढ़ गई। आगे चलकर अन्य देशों ने भी प्रशिया का अनुसरण किया, और अपने यहां वाधित मैनिक सेवा की प्रणाली का प्रारम्भ किया। प्रशिया की यह अद्वितीय सेना न केवल अपने देश के लिये युद्ध करने की सदा उद्यत रहती थी, पर प्रशिया के नेतृत्व में इसे जर्मनी के संगठन के लिये भी प्रयुक्त किया जा सकता था। वेशन, यह प्रशियन सेना बहुत ही पुराने टग के आदर्शों से मंचालित होती थी, पर इसमें सन्देह नहीं, कि जर्मन देशभक्त अपने देश की राष्ट्रीय एकता के लिये इस पर भरोसा कर सकते थे।

समस्याएँ—१८६० में इटली में राष्ट्रीय एकता की स्थापना हो जाने से जर्मन लोगों में भी उत्साह का संचार हुआ। इटालियन संगठन का कार्य पीडमोंट के राजा विक्टर एमैनुअल द्वितीय के नेतृत्व में हुआ था। इससे जर्मन लोगों में यह विचार और भी प्रबल हो गया, कि जर्मनी की राष्ट्रीय एकता भी प्रशिया के नेतृत्व में अधिक सुगमता से सम्पादित की



जा सकती है। इस समय जर्मन लोगो के सम्मुख दो मुख्य कार्य थे—

(१) आस्ट्रिया के प्रभुत्व से छुटकारा पाना, और (२) विशुद्ध जर्मन राज्यों का प्रशिया की सरक्षा में सुदृढ़ सगठन का स्थापित करना।

ये दोनों कार्य जर्मनी में किस प्रकार किये गये, इस पर हमें अब विचार करना है।

## २. विस्मार्क का अभ्युदय

विलियम प्रथम का राज्यारोहण—सन् १८६१ में प्रशिया की राजगद्दी पर विलियम प्रथम आरूढ़ हुआ। राज्यारोहण के समय उसकी आयु ६३ वर्ष की थी। अपनी युवावस्था में वह प्रशियन सेना में शामिल होकर नैपोलियन प्रथम के विरुद्ध लड़ाई लड़ चुका था। उसका सम्पूर्ण जीवन सैनिक के रूप में ही व्यतीत हुआ था। सैनिक जीवन का उमे बढ़ा गीक था। उसे विश्वास था, कि प्रशिया का भाग्य सेना पर ही आश्रित है। राजा के दैवी अधिकार में उसे जरा भी सन्देह नहीं था। वह समझता था, कि प्रशिया के लिये सर्वोत्तम शासन एकतन्त्र स्वेच्छाचारी राजा का ही हो सकता है। परन्तु साथ ही वह यह भी समझता था कि राजा को जनता का लाभ चाहनेवाला, परिश्रमी, दयालु, ईमानदार और वृद्धिमान होना चाहिये। निस्सन्देह, उसमें ये सब गुण विद्यमान थे। वह अपने राज्य में एक लोकोपकारी पर जवर्दस्त राजा के समान शासन करना चाहता था। इसमें सन्देह नहीं कि अपने उद्देश्य में उसे सफलता भी प्राप्त हुई। प्रशिया को उन्नत तथा शक्तिशाली बनाने में विलियम प्रथम ने असाधारण क्षमता से कार्य किया।

सैनिक सुधार—सेना को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिये विलियम प्रथम चाहता था, कि वाधित सैनिक सेवा की पद्धति में कुछ सुधार किये जावे। उसका प्रस्ताव था, कि प्रत्येक आदमी को तीन वर्ष तक आवश्यक रूप से सैनिक सेवा करनी चाहिये। इससे पूर्व वाधित सैनिक सेवा का काल केवल दो वर्ष का था। सैनिक सेवा के बाद दो वर्षों तक प्रत्येक आदमी को हर्ष समय में सेना में भर्ती के लिये तैयार रहना होता था, यद्यपि छावनी में रहने की आवश्यकता नहीं होती थी। विलियम इस काल को भी दो वर्ष के स्थान पर चार वर्ष कर देना चाहता था। इस प्रकार उसकी योजना के अनुसार प्रत्येक आदमी को अपनी युवावस्था के तीन वर्ष सैनिक सेवा के लिये अर्पित करने पड़ते थे। विलियम प्रथम का खयाल था, कि उसकी योजना के अनुसार साढ़े चार लाख प्रशियन सैनिक हमेशा युद्ध के लिये तैयार रहेंगे, और उनके अतिरिक्त जितने भी सैनिकों की आवश्यकता होगी, भर्ती कर सकना कठिन नहीं होगा। इस सेना का मुकाबला यूरोप का कोई भी देश न कर सकेगा। इस परिवर्तन का प्रस्ताव प्रशिया की लोकसभा (लाण्डटाग) में पेश किया गया। परन्तु वहाँ वह स्वीकृत न हो सका। परिणाम यह हुआ, कि विलियम ने अपनी सहायता के लिये प्रधान-मन्त्री के पद पर विस्मार्क को नियत किया। विस्मार्क ने जनता की इच्छा की परवाह न कर, लोकसभा तक की उपेक्षा करके विलियम की योजना को त्रिधा में परिणत किया। प्रशिया के सम्मुख जर्मनी के सगठन का मुख्य श्रेय इस विस्मार्क को ही प्राप्त है। अपने समय में यूरोप का कोई भी राजनीतिज्ञ विस्मार्क का मुकाबला नहीं कर सका था। यह विस्मार्क कीन था? इसका परिचय देना आवश्यक है। उन्नीसवीं सदी में यूरोप

ने जो अनेक अत्यन्त प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ उत्पन्न किये, विस्मार्क उनमें से एक था।

**प्रिंस विस्मार्क**—विस्मार्क का जन्म उस समय में हुआ था, जब वीएना की कांग्रेस के अधिवेशन हो रहे थे। प्रधानमन्त्री बनने के समय उसकी आयु ४७ वर्ष की थी। वह प्रशिया के एक प्रसिद्ध कुलीन जागीरदार घराने में उत्पन्न हुआ था। प्रशिया के कुलीन जागीरदार—जो इतिहास में 'जुन्कर' के नाम से प्रसिद्ध है—जनता के अधिकारों के कट्टर विरोधी थे। जनता भी अपना शासन अपने आप कर सकती है, यह बात उनकी समझ में ही न आती थी। विस्मार्क के अपने विचार भी इसी ढंग के थे। वह प्रशियन जुन्करों का अच्छा प्रतिनिधि था। जिस समय वह विज्जगिद्यालय में पढ़ता था, उसे पटाई लिबाई का जरा भी ध्यान नहीं रहता था। यह सदा गगन पीने और कुश्नी लडने में रत रहता था। शिक्षा समाप्त कर वह सरकारी नौकरी में प्रविष्ट हुआ। पर नियन्त्रण उसे वहाँ भी महान था। नियन्त्रण का उल्लंघन करने के अपराध पर उसे नौकरी में बर्खास्त कर दिया गया। इसके बाद उसने अपनी जागीरदारी में आगम में रहना प्रारम्भ किया। १८४३ में वह प्रशियन राजसभा का (डीट) का सदस्य निर्वाचित हुआ। उदार विचारों के विरोध में पुराने ढंग के कुलीन लोगों का जो दल राजसभा में था, विस्मार्क उसमें सम्मिलित हो गया, और शीघ्र ही उसने इस दल में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया। वह 'शासन-विधान' को 'रही कागज का टुकड़ा' नाम से सम्बोधित किया करता था। वह कहा करता था, क्या यह 'रही कागज का टुकड़ा' परमेश्वर द्वारा नियत किये गये राजा और उसकी प्रजा के बीच में मध्यस्थ का कार्य कर सकता है? उसका कहना था कि उदार विचारों के लोग बेवकूफ हैं। यदि उन्हें काबू में न रखा जायगा, तो राज्य तबाह हो जायगा। १८४८ में प्रशिया में जब विद्रोह हुआ, तो विस्मार्क ने राजसत्ता की रक्षा के लिये क्रिमानों की एक फौज मगटिन की। वॉलिन के विद्रोह को कुचलने में इस फौज ने खूब काम किया। राजा को अपनी रक्षा करने की जितनी परवाह स्वयं थी, उससे कहीं अधिक विस्मार्क को थी। फ्राकफोर्ट की राष्ट्रीय महासभा की असफलता का समाचार जब विस्मार्क ने सुना, तो उसकी प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। वह खुशी से नाच उठा। मैटरनिख और वेल्लिङ्गटन की तरह विस्मार्क भी नई प्रवृत्तियों का कट्टर विरोधी था। उससे एक सन्तति पूर्व यूरोप के प्रायः सभी राजनीतिज्ञ उसी की तरह के थे। पर अब उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में जमाना बदल चुका था, और इसीलिये विस्मार्क के ये विचार बहुत अद्भुत तथा पुराने ढंग के मालूम होते थे। यह नहीं समझना चाहिये, कि विस्मार्क कोई असाधारण रूप से पुराने ढंग का आदमी था। वीएना की कांग्रेस में यूरोप भर के जो प्रतिनिधि एकत्रित हुए थे, वे सब उसी के ढंग के थे। पर अब इतने समय के बाद विस्मार्क के ये विचार बहुत भद्दे, असामयिक और अनुचित प्रतीत होते थे।

फ्राकफोर्ट की राष्ट्रीय महासभा की असफलता के अनन्तर १८५१ में फिर से जर्मन राज्यसंघ की पुरानी राजसभा का उद्धार किया गया। विलियम प्रथम ने विस्मार्क को इस राजसभा में प्रशिया का प्रतिनिधि नियत किया। आठ वर्ष तक वह इस सभा का सदस्य रहा। राष्ट्रीय एकता की भावना इस समय जर्मनी में प्रादुर्भूत हो चुकी थी। फ्राकफोर्ट की राजसभा चाहे कितने ही पुराने ढंग के लोगों की सभा क्यों न हो, पर राष्ट्रीयता की गूँज ई। में

समय-समय पर सुनाई दे ही जाती थी। यही राजसभा एक ऐसी सगठित सस्था थी, जिसमें सम्पूर्ण जर्मनी के प्रतिनिधि एकत्रित होते थे, और जहाँ राष्ट्रीय एकता के प्रश्नों पर विचार होता रहता था। विस्मार्क को इस सभा में जर्मन एकता की समस्या का अनुशीलन करने का अच्छा अवसर मिला। यहाँ उसका यह विश्वास बहुत दृढ़ हो गया, कि जर्मनी में राष्ट्रीय एकता की स्थापना प्रशिया द्वारा ही की जा सकती है। इस विश्वास को क्रिया में परिणत करने की प्रबल आकांक्षा भी उसमें यही उत्पन्न हुई।

१८५९ में विस्मार्क को रूस में प्रशियन राजदूत के पद पर नियत किया गया। यहाँ उसे रूसी भाषा सीखने और जार से मित्रता करने का अच्छा अवसर हाथ लगा। १८६२ में उसे फ्रान्स में राजदूत बनाया गया। इन पदों पर कार्य करने के कारण विस्मार्क यूरोपियन राजनीति का अनुभवी पण्डित बन गया था। बड़े-बड़े राजनीतिज्ञों से उसने परिचय प्राप्त कर लिया था, और वह अच्छी तरह जान गया था कि राजनीति की शतरंज किस प्रकार खेली जाती है।

**प्रधान मन्त्री विस्मार्क**—१८६२ में ही, जब कि विलियम प्रथम प्रशियन लोकसभा द्वारा अपने सैनिक सुधार सम्बन्धी प्रस्तावों को स्वीकृत कराने में असमर्थ हुआ, उसने पुराने ढंग के विचारों के कट्टर पक्षपाती और स्वेच्छाचारी राजसत्ता के प्रबल समर्थक विस्मार्क को प्रधानमन्त्री के सर्वोच्च राजकीय पद पर नियत किया। पहले विस्मार्क ने कोशिश की, कि अपनी नीति-चतुरता से लोक-सभा में सैनिक सुधार के मसविदे को स्वीकृत करा लिया जाए। पर इस कार्य में उसे असफलता हुई। आखिर, उसने स्वेच्छाचार का आश्रय लिया और लोकसभा की सर्वथा उपेक्षा कर शासन करना उसने अपना ध्येय बना लिया। राजा उसके साथ था। व्यवस्थापन विभाग की अन्यतम सभा—राजसभा भी, जिसमें कि कुलीन जागीरदार 'जुनक्रो' का प्राधान्य था, उसके साथ थी। फिर उसे किस बात की परवाह हो सकती थी? देश के शासन-विधान की उसने सर्वथा उपेक्षा की। लोकसभा उसके बजट को पाम नहीं करती थी। इससे विस्मार्क का क्या विगडता था? वह कहता था, राज्य की आवश्यकता है, कि टैक्स वसूल होने चाहिये। 'राज्य की आवश्यकता' के नाम पर उसने किनी भी प्रकार की मनमानी करने में सकोच नहीं किया। लोकसभा ने सैनिक सुधार दिल को पाम नहीं किया था। पर विस्मार्क को इस बात की क्या चिन्ता थी। वह कहता था, राज्य की आवश्यकता है, अतः सैनिक सगठन में सुधार होना ही चाहिये। इसी नाम पर लोकसभा के विरोध की उपेक्षा कर, उसने सेना में मनोवांछित सुधार किये। उसके स्वेच्छा-चार से राजा, रानी और राजकुमार तक भी सब घबरा गये। वे डरते थे, कि विस्मार्क की नीति से कहीं विद्रोह न हो जाए। पर विस्मार्क उन्हें समझता था—विद्रोह से क्या डरना है? १८७१ में मृत्यु हुई, या फ्रान्स के तख्ते पर। दोनों प्रकार की मृत्यु एक समान रूप से सम्मानास्पद है। विस्मार्क की इस हिम्मत का ही नतीजा था, कि राजा विलियम प्रथम जनता की उपेक्षा करने के लिये तैयार हो गया। विस्मार्क इतना सख्त और साहसी था, कि बूले तौर पर उमका किसी के लिये भी विरोध कर सकना सम्भव नहीं था। सब लोग उस से डरते थे।

अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिये विस्मार्क का विश्वास था, कि सेना को शक्तिशाली

बनाना चाहिये। वह कहा करता था—इस समय के महत्वपूर्ण प्रश्ना का निर्णय व्याख्यातों और प्रस्तावों द्वारा नहीं होगा, उनका हल करने के लिये तो ग्यून बहाने की आवश्यकता होगी। उसी कारण सेना को मजबूत करने के लिये उसने लोकमभा की जगह भी परवाह नहीं की। उसके राजनैतिक उद्देश्यों का परिगणन इस प्रकार किया जा सकता है—

- (१) प्रशिया की सैनिक शक्ति को अद्वितीय और अजेय बनाना चाहिये।
- (२) सैनिक बल का प्रयोग कर प्रशिया का विस्तार किया जाए, और राजनैतिक शक्ति में वृद्धि की जाए।
- (३) युद्ध द्वारा आस्ट्रिया को जर्मन राज्यसंघ में विलीन निकाटना चाहिये।
- (४) आस्ट्रिया को बहिष्कृत कर प्रशिया के नेतृत्व में सम्पूर्ण जर्मन राज्यों का नवीन और सुदृढ़ संगठन स्थापित करना चाहिये।
- (५) इसके अनन्तर, सैनिक शक्ति में अद्वितीय जर्मनी को सम्पूर्ण यूरोप की प्रमुख शक्ति बना देना चाहिये।

विस्मार्क ने इन उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिये जिस प्रकार प्रयत्न किया, उस पर हम क्रमशः विचार करेंगे।

### ३ डेन्मार्क के साथ युद्ध

लोकसभा के बहुमत की सर्वथा उपेक्षा कर विस्मार्क ने वांछित सैनिक सेना की पद्धति को अधिक विस्तृत किया। इन आर मोट्टके जैसे सुयोग्य सेनापतियों की अजीबना में प्रशियन सेना ने बड़ी उन्नति की। शीघ्र ही प्रशियन सेना यूरोप भर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गई। अब विस्मार्क ने अनुभव किया, कि अपने कार्यक्रम को क्रिया में परिणत करने का उपयुक्त समय आ गया है।

**हॉल्स्टाइन और श्लेस्विग की समस्या**—अपनी शक्ति को प्रदर्शित करने का पहला अवसर डेन्मार्क के साथ युद्ध में उपस्थित हुआ। जर्मनी और डेन्मार्क के बीच में दो प्रदेश थे, जो सदियों से डेन्मार्क के राजा के अधीन चले आते थे। इनके नाम हैं—श्लेस्विग और हॉल्स्टाइन। हॉल्स्टाइन की प्रायः सम्पूर्ण जनता जर्मन जाति की थी। श्लेस्विग में आधे जर्मन बसते थे, और आधे डेन। ये दोनों प्रदेश डेन्मार्क के राजा के अधीन अवश्य थे, पर ये डेन्मार्क के हिस्से नहीं थे। डेन्मार्क और इनका राजा ही एक था, अन्य किसी प्रकार की एकरता इनमें न थी। शासन इनका डेन्मार्क से पृथक् था। हॉल्स्टाइन जर्मन राज्यसंघ में भी सम्मिलित था, और इसके राजा की हैसियत में डेन्मार्क का राजा भी उपर्युक्त संघ में अपने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार रखता था। उन्नीसवीं सदी में यूरोप के अन्य देशों के समान डेन्मार्क में भी राष्ट्रीयता की लहर चल रही थी, और डेन लोग अपनी राष्ट्रीय उन्नति के लिये प्रयत्न कर रहे थे। राष्ट्रवादी डेन देशभक्त लोगों की आकांक्षा थी, कि हॉल्स्टाइन और श्लेस्विग के प्रदेशों को भी डेन्मार्क में सम्मिलित कर लिया जाय, ताकि उनके देश की शक्ति अधिक बढ़ सके। पर जर्मन लोग इसके विरोध में थे। न केवल इन प्रदेशों के जर्मन निवासी, पर साथ ही जर्मनी के लोग भी डेन देशभक्तों की इस आकांक्षा का विरोध कर रहे थे। १८६३ में डेन्मार्क के राजा निश्चिन्त दशम ने अपने देश के राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रभाव में आकर

उद्धोषणा की, कि श्लेश्विग को डेन्मार्क में सम्मिलित कर लिया गया है, और इस कारण अब शासन-विधान में आवश्यक परिवर्तन किये जावेंगे। जर्मन लोग इस उद्धोषणा को नहीं सह सकने थे। प्रशिया ने इसका विरोध किया। विस्मार्क ने सोचा, कि डेन्मार्क में लड़ाई शुरू करने का यह अच्छा मौका है, और इस युद्ध से प्रशिया को बहुत लाभ होगा। श्लेश्विग और हॉल्स्टाइन के महत्वपूर्ण प्रदेशों को हड़पने का इस से अच्छा अवसर फिर हाथ न आयेगा। उसने आस्ट्रिया को इन प्रदेशों की समस्या का निपटारा करने में सहायता देने के लिये आमन्त्रित किया।

आस्ट्रिया चाहता था, कि विजित प्रदेशों का वटवारा किस प्रकार किया जायगा, इसका फैसला पहले ही कर लिया जाय। पर विस्मार्क ने कहा, कि यह बात बाद में निश्चित की जा सकेगी। आस्ट्रिया इसके लिये तैयार हो गया, और दोनों राज्यों की तरफ से सम्मिलित रूप से डेन्मार्क को अन्तिम सूचना दी गई, कि शीघ्र ही नवीन शासन-विधान का अन्त कर श्लेश्विग के प्रदेश को डेन्मार्क से पृथक् कर दिया जाय। पर क्रिश्चियन दशम इसे स्वीकृत करने के लिये उद्यत न हुआ। आखिर, प्रशिया और आस्ट्रिया की सम्मिलित सेनाओं ने १८६४ में डेन्मार्क पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में डेन्मार्क परास्त हो गया, और उसके राजा को न केवल श्लेश्विग और हॉल्स्टाइन, पर साथ ही लायनबुर्ग के प्रदेश को भी विजेताओं के मुपुर्द कर देने के लिये बाधित होना पड़ा। प्रशिया और आस्ट्रिया जैसे शक्तिशाली राज्यों के सम्मुख डेन्मार्क की हसियत ही क्या थी? उसकी बुरी तरह से पराजय हुई।

सन्धि—परन्तु लूट के माल के बँटवारे पर विजेताओं में मतभेद हो गया। विस्मार्क की इच्छा थी, कि तीनों प्रदेशों को प्रशिया में मिला लिया जाए। आस्ट्रिया चाहता था, कि इन्हें जर्मन राज्यसंघ में स्वतन्त्र रूप से सम्मिलित किया जावे। आखिर, दोनों में सन्धि हो गई। विस्मार्क अनुभव करता था, कि अभी आस्ट्रिया से युद्ध करने का समय नहीं आया है, अतः सन्धि कर लेने में ही उसे फायदा नजर आता था। सन्धि के द्वारा विजित प्रदेशों की जो व्यवस्था हुई, वह इस प्रकार थी—(१) लायनबुर्ग को प्रशिया ने खरीद लिया। दूसरा मूल्य आस्ट्रिया को दिया गया। (२) श्लेश्विग प्रशिया को प्राप्त हुआ। प्रशिया इसे प्राप्त करने को बहुत उत्सुक था। कील का प्रसिद्ध बन्दरगाह इसी प्रदेश में ही स्थित था। (३) हॉल्स्टाइन पर आस्ट्रिया ने अपना कब्जा जमा लिया।

इन सन्धि में आस्ट्रिया और प्रशिया—दोनों को एक बराबर लाभ हुआ। पर विस्मार्क इनकेवल क्षणिक समझौता मात्र ही समझता रहा था। आस्ट्रिया को परास्त करने के लिये वह उद्युक्त अवसर की प्रतीक्षा में था। यह अवसर भी उसे शीघ्र ही मिल गया।

## ६ आस्ट्रो-प्रशियन युद्ध और उत्तरी जर्मन राज्यसंघ का निर्माण

युद्ध की तैयारी—विस्मार्क के सम्मुख अगला कार्य यह था, कि आस्ट्रिया को परास्त कर उस जर्मन राज्यसंघ में विलिखित करे। पर यह कार्य डेन्मार्क जैसे छोटे से राज्य को परास्त कर देने के समान सुगम नहीं था। आस्ट्रिया यूरोप के सब से अधिक शक्तिशाली और प्राचीन राज्यों में से एक था। उसके साथ युद्ध यूरोप के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता था। अतः विस्मार्क ने पहले यह उचित समझा, कि अन्य

राज्यों की नज़र देख ले। ग्रेट ब्रिटेन आस्ट्रियन युद्ध में किसी प्रकार में हस्तक्षेप करेगा, इसकी कोई सम्भावना नहीं थी। रूस के जार एलेक्जेंडर द्वितीय से विस्मार्क पहले ही मित्रता कर चुका था। फ्रांस का तथा रूस होगा, यह अनिश्चित था। अतः विस्मार्क स्वयं फ्रांस के सम्राट् नैपोलियन तृतीय से मिलने के लिये गया। नैपोलियन को राष्ट्रीयता के सिद्धान्त की बड़ी वृत्ति थी। कम से कम वह प्रदर्शित तो यही करता था। अतः विस्मार्क ने उसे समझाया, कि हम लोग जर्मनी में राष्ट्रीय एकता को स्थापित करने के लिये प्रयत्न कर रहे हैं। आस्ट्रिया इस प्रयत्न में सबसे बड़ा विघ्न है। अतः इस विघ्न को दूर करने के शुभ कार्य में नैपोलियन को प्रशिया की सहायता करनी चाहिये। विस्मार्क ने केवल गुप्त सिद्धान्तों की ही विवेचना नहीं की। उसने नैपोलियन को ठोस लालच भी दिया। जिस प्रकार कावूर ने आस्ट्रिया के विरुद्ध फ्रांस की सहायता प्राप्त करने के लिये नीम आग मेवाय के प्रदेश पेश किये थे, इसी प्रकार विस्मार्क ने वेल्जियम और रूढ़न की घाटी के कुछ प्रदेशों को प्रदान करने का जिक्र किया। विस्मार्क को केवल यही अभीष्ट था, कि फ्रांस आस्ट्रिया के साथ न मिल जाए। युद्ध में नैपोलियन की सहायता प्राप्त न कर सकना उसे अमममय पनीन होता था। आखिर, नैपोलियन उदासीन रहने से लिये नैया हो गया। उसने सोचा, कि प्रशिया और आस्ट्रिया आपस में लड़कर निर्वन्त हो जायेंगे, और फ्रांस के लिये उत्तर दिशा में भी अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकना सुगम हो जायगा। उस विचार में नैपोलियन ने यही निश्चय किया, कि आस्ट्रिया को सहायता न दी जाए। इटली में राष्ट्रीय एकता स्थापित हुए भी अभी अधिक समय नहीं हुआ था। नवीन इटालियन राज्य वेनेटिया को आस्ट्रिया की अधीनता में मुक्त कराने के लिये उत्सुक था। अतः विस्मार्क के लिये यह बहुत सुगम था, कि इटली की सहायता आस्ट्रिया के विरोध में प्राप्त कर लें। उसने इटली में समझौता किया, कि आस्ट्रिया के परास्त हो जाने पर वेनेटिया उसे दे दिया जायगा और युद्ध शुरू होने पर इटली दक्षिण की तरफ से आस्ट्रिया पर आक्रमण करेगा।

**युद्ध का प्रारम्भ**—सब तैयारी हो चुकी थी, अब युद्ध के लिये कोई उपयुक्त अवसर ढूँढना ही बाकी था। श्लेस्विग और हॉल्स्टाइन के प्रदेशों के बारे में प्रशिया और आस्ट्रिया में जो सन्धि हुई थी, उसकी शर्तों के सम्बन्ध में झगड़े की कोई बात दृढ़ निकाल सकना मुश्किल नहीं था। जून, १८६६ में ऐसा मौका मिल गया, और प्रशिया ने आस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध उद्घोषित कर दिया। इस युद्ध में अनेक जर्मन राज्यों ने आस्ट्रिया का साथ दिया।

**सेडोवा का युद्ध**—तीन जुलाई के दिन सेडोवा या क्यूनिगगेटज के रणक्षेत्र में बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी गई, जिसमें आस्ट्रिया की पराजय हुई। सेडोवा के युद्ध के साथ ही आस्ट्रिया-प्रशियन युद्ध प्रायः समाप्त हो गया। तीन सप्ताह से भी कम समय में विस्मार्क की सेनाओं ने इस बात का फैसला कर दिया, कि प्रशिया और आस्ट्रिया में से किसे जर्मनी का नेतृत्व करना है। इसके बाद एक-एक करके उन जर्मन राज्यों पर हमला किया गया, जिन्होंने आस्ट्रिया का साथ दिया था। उन सबको बुरी तरह से परास्त किया गया। आस्ट्रिया की सेनाएँ इतनी बुरी तरह से परास्त हो गई थी, कि विलियम प्रथम और उसके अनेक सेनापतियों की यह इच्छा थी, कि आस्ट्रिया की राजधानी वीएना पर हमला कर दिया जाय। पर विस्मार्क ने इसका विरोध किया। वह इसे जर्मन-संगठन के महत्वपूर्ण कार्य में व्यर्थ की बाधा सम-



### प्रिस विस्मार्क (१८१५-१८६८)

बना था। उसके विरोध के कारण वीएना पर आक्रमण करने का विचार छोड़ दिया गया।

सन्धि—२३ अगस्त, १८६६ के दिन प्राग में आस्ट्रिया और प्रुशिया में सन्धि हो गई। इस सन्धि के अनुसार (१) १८१५ में वीएना की कांग्रेस द्वारा आस्ट्रिया के नेतृत्व में जो जर्मन राज्यसंघ बना था, उसे वरखास्त कर दिया गया, (२) इलेक्विग और हात्स्टाइन—दोनों प्रदेश प्रुशिया को दिये गये, (३) वेनेटिया इटली को दिया गया और (४) आस्ट्रिया को हरजाना देने के लिये मजबूर किया गया।

**प्रशिया का विस्तार**—इतना ही नहीं, आस्ट्रो-प्रशियन युद्ध से प्रशिया को अन्य भी जनेक लाभ हुए। हेनोवर, हेस्से-कैसल, नासो आर फ्रांकोर्ट—इन चार राज्यों को प्रशिया ने अपने साथ सम्मिलित कर लिया। इन राज्यों ने गत युद्ध में आस्ट्रिया की सहायता की थी। उन इनकी पृथक् सत्ता का अन्त कर प्रशिया के साथ मिश्र लेने में विस्मार्क को कुछ भी अनौचित्य नजर न आता था। लायनबर्ग, श्लेस्विग जोरहा-मंडाइन पर तो प्रशिया ने अपना अधिकार जमा ही लिया था। इस प्रकार अब आस्ट्रो-प्रशियन युद्ध के परिणामस्वरूप प्रशिया को तीन नवीन प्रदेश प्राप्त हुए, उनका क्षेत्रफल हावैड में दुगुना था। उनकी आबादी भी पचास लाख में अधिक थी। इन प्रदेशों की प्राप्ति में प्रशिया इतना बड़ा हो गया, कि सम्पूर्ण जर्मनी का दो-तिहाई प्रदेश और दो-तिहाई जनता उसके अधीन हो गई। अब प्रशिया की कुल आबादी ढाई करोड़ में भी अधिक थी। वह यूरोप के प्रमुख राज्यों में एक हो गया था। इस स्थिति में शेष जर्मन राज्यों का अपने साथ मगठिन करना बहुत कठिन नहीं था। अन्य सब जर्मन राज्य मिलकर भी प्रशिया के सम्मुख नवधा नगण्य थे।

**उत्तरी जर्मन राज्यसंघ**—अब जगत्का प्रश्न जर्मन राज्यों को नये सिरे में मगठिन करने का था। प्रशिया की इच्छा थी, कि सम्पूर्ण जर्मन राज्यों को मिलाकर जर्मन राज्यसंघ की रचना की जावे। पर अभी यह सम्भव नहीं था। दक्षिणी जर्मनी में चार राज्य थे, जो पर्याप्त शक्तिशाली थे। इनके नाम हैं, बवेरिया, वाउन, वुट्टम्बर्ग और हन्से डामेस्टाट। विस्मार्क भलीभांति अनुभव करता था, कि अभी इन राज्यों को अपनी इच्छा के अनुसार जर्मन संघ में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। अतः उन्होंने यही उचित समझा, कि इन चार राज्यों को छोड़कर शेष जर्मनी का मगठन बनाया जावे। यह मगठन 'उत्तरी जर्मन राज्यसंघ' के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें प्रशिया के अनिरीजित डक्कीम अन्य छोटे-छोटे राज्य सम्मिलित थे। इस नवीन राज्यसंघ का निर्माण करते हुए तीन बातों का खयाल रखा गया था—

(१) राज्यसंघ के सम्पूर्ण निवासियों को शासन में अधिकार दिये जाए। इसके लिए यह व्यवस्था की गई, कि संघ की एक व्यवस्थापिका सभा के लिये सम्पूर्ण जनता को प्रत्यक्षरूप से अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार रहे।

(२) प्रशिया की महत्ता को कायम रखा जाए। इसके लिये प्रशिया के राजा को सम्पूर्ण राज्यसंघ का अध्यक्ष बनाया गया, और व्यवस्थापन-विभाग में प्रशिया के प्रतिनिधियों की बहुसंख्या कायम रखी गई।

(३) अन्य राज्यों को भी संघ में सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त हो, इसके लिये एक मन्त्र-सभा का निर्माण किया गया, जिसमें प्रत्येक राज्य का—चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो—कम से कम एक वोट रखा गया।

**मगठन**—उत्तरी जर्मन राज्यसंघ का अध्यक्ष प्रशिया का राजा होता था। वह अपना प्रधानमन्त्री स्वयं नियुक्त करता था। प्रधानमन्त्री व्यवस्थापन विभाग के प्रति उत्तरदायी नहीं होता था। व्यवस्थापन-विभाग में दो सभाएँ थी—(१) मन्त्रसभा (बुन्दसराट्) —इसमें सब राज्यों के राजाओं के प्रतिनिधि सम्मिलित होते थे। प्रत्येक राज्य का कम से कम एक-एक प्रतिनिधि अवश्य होता था। (२) लोकसभा (रीपटाग) —सम्पूर्ण जनता



इसके लिये प्रतिनिधि निर्वाचित करती थी। वोट का अधिकार सब वालिग पुम्पो को दिया गया था। विस्मार्क जैसे पुराने विचारों के राजनीतिज्ञ के रहते हुए भी वोट का यह मुविस्तृत अधिकार वस्तुतः आश्चर्यजनक है। असली बात यह है, कि इतिहास की प्रवृत्तियों को रोक सकना भी किसी व्यक्ति के लिये, चाहे वह कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, अभी सम्भव नहीं होता। निस्सन्देह, विस्मार्क की शक्ति असाधारण थी। पर समय की लहर उसमें भी अधिक प्रवल थी। जर्मन जनता अपने अधिकारों के लिये अनेक सघर्ष कर चुकी थी। अब उसकी उपेक्षा कर सकना सुगम कार्य न था।

उत्तरी जर्मन राज्यसंघ की रचना इस ढंग से की गई थी, कि वेवेरिया आदि दक्षिणी राज्यों को सम्मिलित करने का जिस समय भी मौका आये, तो शासन-विधान का निर्माण नये सिरे से न करना पड़े। उन्हें अपने अन्दर सम्मिलित करने की गुंजाइश पहले से ही रख ली गई थी। कुछ समय के बाद जब इसके लिये अवसर उपस्थित हुआ, तो फ्रीमी महत्त्वपूर्ण परिवर्तन के बिना ही वे राज्य जर्मन संघ में सम्मिलित कर लिये गये।

## ५ फ्रैंको-प्रशियन युद्ध और सगठित जर्मन साम्राज्य की स्थापना

कारण—नैपोलियन तृतीय का खयाल था, कि आस्ट्रिया और प्रशिया का युद्ध बहुत देर तक चलेगा। दोनों राज्य आपस में लड़कर कमजोर हो जायेंगे और फ्रांस को अपनी शक्ति का विस्तार करने का अच्छा अवसर प्राप्त होगा। पर उसके सब मुख-स्वप्न मिट्टी में मिल गये, जब कि सेडोवा की लड़ाई में आस्ट्रिया परास्त हो गया, और प्रशिया की विजय हुई। प्रशिया दिन दूनी और रात चौगुनी उन्नति कर रहा था। उसकी सेना यूरोप में सबसे अधिक शक्तिशाली थी। उसके नेतृत्व में अधिकांश जर्मन राज्यों का सगठन भी हो चुका था। नैपोलियन अपने पड़ोस में इस प्रकार के शक्तिशाली राष्ट्र का प्रादुर्भाव सहन नहीं कर सकता था। वह चाहता था, कि इसे प्रारम्भ में ही नष्ट कर दिया जाए। प्रशिया जिस प्रकार तेजी से उन्नति कर रहा था, उससे यह निश्चित था, कि वह शीघ्र ही फ्रांस का भयकर प्रतिस्पर्धी बन जायगा। नैपोलियन इस बात को कब सहन कर सकता था? प्रशिया और फ्रांस के हित आपस में टकराते भी थे। वेवेरिया, वाउन, वुर्टेम्बर्ग और हम्ब-जर्मस्टाट—ये चार दक्षिणी जर्मन राज्य अभी तक जर्मन राज्यसंघ में सम्मिलित नहीं हुए थे। विस्मार्क इन्हें भी अपने संघ में मिलाना चाहता था। पर नैपोलियन का हित इस बात में था, कि ये जर्मनसंघ में पृथक् रहे। वह इन्हें अपने प्रभाव में रखने के लिये इच्छुक था। प्रथम नैपोलियन द्वारा स्थापित 'दक्षिणी जर्मन राज्यसंघ' का स्वयं लेकर वह भी उन राज्यों को अपने प्रभाव में, और यदि हो सके, तो सुरक्षा में रखने को उत्सुक था। उसके अनिश्चित नैपोलियन कुछ कर दिखाने के लिये भी उतावला हो रहा था। शासन-विधान का उद्देश्य फ्रांसीसी पद्धति द्वारा वह सम्राट् पद पर पहुँचा था। इस गौरवास्पद पद को कायम रखने के लिये शानदार विजयों की जरूरत थी। मैक्सिको में अपना शासन स्थापित करने के प्रयत्न में उसे भारी निराशा का सामना करना पड़ा था। फ्रेंच लोग इस बात से बहुत नाराज थे। नैपोलियन का प्रभाव कम होता जा रहा था। जब वह चाहता था, कि विजयों द्वारा जनता के हृदय में फिर से अपने प्रभाव को स्थापित करे। इसके अनिश्चित,

नैपोलियन प्रशिया में विजेपरूप से नाराज भी था। आस्ट्रिया को परास्त कर प्रशिया का जिस ढग से उत्कर्ष हो रहा था, उसे फ्रांस अपने लिये अत्यन्त हानिकारक समझता था। सेडोवा के युद्ध में जब आस्ट्रिया परास्त हुआ, तो फ्रांस के मार्शल रादो ने कहा था—“सेडोवा में वस्तुतः फ्रांस की पराजय हुई है।” प्रसिद्ध फ्रेच राजनीतिज्ञ थोयर्स ने इस युद्ध का समाचार सुनकर कहा था—“जो कुछ हुआ है, वह फ्रांस के लिये सबसे बड़ी विपत्ति है। पिछले चार सदियों में फ्रांस के लिये अपनी बोर विपत्ति की कोई घटना नहीं हुई थी।” नैपोलियन तृतीय भी आस्ट्रिया की पराजय में बहुत दुःखी था। पर वह बाहर में यह कहकर सतोंप प्रगट करता था, कि अभी तो जर्मन भाषा बोलनेवाले लोग या जर्मन राष्ट्र तीन भागों में विभक्त है, दक्षिणी जर्मन राज्य अभी प्रशिया के नेतृत्व में संगठित नहीं हुए हैं, और आस्ट्रियन-जर्मन भी अपनी पृथक् सत्ता रखते हैं। नैपोलियन तृतीय का कहना था, कि जर्मन राष्ट्र के और अधिक संगठन को किसी भी प्रकार सहन नहीं करना चाहिये। यदि सम्पूर्ण जर्मन लोग एक विशाल राष्ट्र के रूप में संगठित हो गये, तो उसमें यूरोप के राज्यों का शक्ति-समुत्तुलन नाट हो जायगा। इसीलिये वह उस वान के लिये उन्मुक्त था, कि प्रशिया की बढ़ती हुई शक्ति के मुकाबले में फ्रांस को भी अधिक शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न किया जाय।

इस दृष्टि से नैपोलियन तृतीय ने पहले यह उद्योग किया, कि प्रशिया को इन वान के लिये तैयार करले कि फ्रांस अपनी सीमा का विस्तार रूइन नदी तक कर सके। रूइन नदी के दक्षिण व पश्चिम के जर्मन प्रदेशों को वह अपनी अधीनता में लाने के लिये उत्तुक्त था। इन प्रदेशों का बड़ा भाग ववेरिया राज्य के अन्तर्गत था। यद्यपि ववेरिया प्रशिया ने बढ़ते हुए प्रभाव को सहन नहीं कर सकता था, पर जर्मन लोगों में राष्ट्रीयता की भावना इतनी प्रबल हो चुकी थी, कि नैपोलियन को अपने इस उद्देश्य में सफलता नहीं हुई। अब नैपोलियन ने यह प्रयत्न किया, कि बेल्जियम को जीत कर फ्रांस के अन्तर्गत कर ले। बेल्जियम के लोग जाति में फ्रेच हैं, और फ्रेच भाषा बोलते हैं। यह ऐतिहासिक घटनाओं का ही परिणाम था, कि बेल्जियम एक पृथक् राज्य के रूप में विद्यमान था। अतः नैपोलियन को यह सर्वथा उचित व सुगम प्रतीत होता था, कि वह उसे जीतकर फ्रांस का अंग बना ले। उसे आशा थी, कि प्रशिया इस कार्य में उसका विरोध नहीं करेगा। पर विस्मार्क कूटनीतिज्ञ था। वह अपने पड़ोसी राज्य फ्रांस को शक्तिशाली नहीं बनने देना चाहता था। उसने नैपोलियन तृतीय का विरोध किया, और इस बात का आश्वासन देने से इनकार कर दिया, कि बेल्जियम पर फ्रेच आक्रमण की दशा में वह उदासीन रहेगा। जब १८७० में फ्रांस और प्रशिया में युद्ध शुरू हुआ, तो इस वान का भय था, कि कहीं इङ्ग्लैण्ड फ्रांस की सहायता न करे। विस्मार्क की कूटनीति ने बेल्जियम की समस्या से लाभ उठाया, और नैपोलियन तृतीय ने उसकी उदासीन स्थिति की उपेक्षा कर उसे जीत लेने की योजना के सम्बन्ध में प्रशिया से जो बातचीत की थी, उस सबको लण्डन के प्रसिद्ध मगधारापत्र ‘टाइम्स’ में प्रकाशित करा दिया। इङ्गलिश लोग अपने हितों को दृष्टि में रखकर बेल्जियम की उदासीनता और पृथक् सत्ता को बहुत महत्व देते थे। वे नैपोलियन तृतीय के विरुद्ध हो गये, और यही कारण है, कि फ्रांस और प्रशिया के

युद्ध (१८७१) में इङ्ग्लैण्ड ने फ्रांस की सहायता नहीं की, यद्यपि इङ्गलिश लोग भी प्रशिया के उत्कर्ष को यूरोप की शान्ति और शक्ति-समुत्तुलन के लिये हानिकारक समझते थे।

रूहाइन नदी के प्रदेशों और वेल्जियम के सवध में निराश होकर नैपोलियन ने लुक्समबुर्ग की ओर ध्यान दिया। इस छोटे से राज्य की जनसंख्या दो लाख थी, जो जाति और भाषा की दृष्टि से फ्रेंच ही थी। हालैंड का वंशक्रमानुगत राजा ही लुक्समबुर्ग का भी ग्राण्ट ड्यूक होता था। यह राज्य जर्मन राज्यसंघ का सदस्य भी रहा था, और जर्मनी में जो व्यापार-संघ बना था, उसमें भी सम्मिलित था। प्रशिया की एक सेना भी उसमें इस उद्देश्य से रहा करती थी, कि फ्रांस उस पर आक्रमण न कर सके। नैपोलियन तृतीय ने विचार किया, कि लुक्समबुर्ग को हालैंड के राजा से खरीद लेना चाहिये, ताकि फ्रांस की शक्ति और स्थिति का उत्कर्ष हो। ऐसा करके नैपोलियन तृतीय सत्कार के सम्मुख यह प्रदर्शित करना चाहता था, कि उसके नेतृत्व में फ्रांस का उत्कर्ष हो रहा है, और प्रशिया की बढ़ती हुई शक्ति को समुत्तुलित करने में वह भलीभांति समर्थ है। पर लुक्समबुर्ग की कीमत के सम्बन्ध में हालैंड के राजा से समझौता नहीं हो सका। मामला यूरोप के अन्य देशों को भी ज्ञात हो गया, और प्रशिया ने इसका बहुत विरोध किया। रूहाइन के प्रदेशों और वेल्जियम के मामले में निराश होकर नैपोलियन तृतीय प्रशिया और उसके प्रधान मन्त्री बिस्मार्क से इतना अधिक चिढ़ गया था, कि सम्भवतः लुक्समबुर्ग के प्रश्न को लेकर ही फ्रांस और प्रशिया में युद्ध शुरू हो जाता। पर इङ्ग्लैण्ड और रूस के हस्तक्षेप के कारण इस समय उन में समझौता हो गया। लुक्समबुर्ग की पृथक् सत्ता कायम रही, पर प्रशिया इन बातों के लिये राजी हो गया, कि अपनी सेना को उस प्रदेश से हटा ले।

इसमें सन्देह नहीं, कि इस समय फ्रांस और प्रशिया के सम्बन्ध बहुत कटु हो गये थे। दोनों ही युद्ध के द्वारा अपने विरोध का फैसला करने के लिये उत्सुक थे। प्रशियन सेनापति मोन्टेके का कथन था—“युद्ध की अपेक्षा कौन सी बात अधिक अभिनन्दनीय है, आखिर युद्ध करना ही होगा।” फ्रांस समझता था, कि प्रशिया के उत्कर्ष के कारण उसकी अपनी स्थिति बहुत नाजुक हो गई है। प्रशिया भी फ्रांस को ही अपने मार्ग में सबसे बड़ा बाधक समझता था। इन सब कारणों के साथ ही यह भी ध्यान में रखना चाहिये, कि फ्रांस और प्रशिया—दोनों राज्यों में राष्ट्रीयता की भावना बड़े तीव्र रूप में व्याप्त हो रही थी। राष्ट्रीयता बहुत अच्छी चीज है, पर दुनिया की प्रत्येक अच्छी चीज की तरह इसकी भी अतिमात्रा नुकसान पहुँचाती है। राष्ट्रीयता सिखाती है, कि एक किस्म के लोग एक साथ निवास करें, साथ मिलकर अपनी उन्नति करें, किसी दूसरे किस्म के लोगों के अधीन न होकर अपनी इच्छा और आदर्शों के अनुसार अपनी उन्नति करें। यहां तक तो ठीक है। पर कुछ आगे और बढ़िये। यदि राष्ट्रीयता को बहुत आगे बढ़ा दिया जाए, तो उसका मतलब यह भी हो जाता है, कि दुनिया में हम ही हम रहे, और कोई जीने ही न पाए। फ्रांस और प्रशिया दोनों इसी बीमारी के शिकार थे। पहले किसी जमाने में इन दोनों राज्यों की संरक्षक राष्ट्रीयता के खिलाफ थी। पर अब समय बदल चुका था। अब आमक लोग स्वयं अपने हित के लिये इस लोकप्रिय सिद्धान्त का उपयोग कर रहे थे। दोनों देशों के जग-बागों में अपने राष्ट्र के विस्तार के लिये आन्दोलन चल रहा था। प्रशिया कहता था—

हमें नीचे दक्षिण की तरफ बढ़ना चाहिये। फ्रांस कहता था—हमें उत्तर में रूहाइन नदी तक तो अवश्य ही पहुँचना चाहिये। फ्रेच अखबार लिखते थे—वॉलिन पर चढ़ चलो। प्रशियन अखबार लिखते थे—पेरिस पर चढ़ चलो। इस दशा में युद्ध गुरु होने में कितनी देर लग सकती थी ?

**स्पेन की राजगद्दी का मामला**—दोनों देश युद्ध के लिये उतावले हो रहे थे। आखिर, उन्हें अपनी आकांक्षा पूर्ण करने का उपयुक्त अवसर मिल गया। १८०८ में स्पेन की म्वेच्छा-चारी साम्राज्ञी इसाबेला के विरुद्ध जनता ने विद्रोह कर उसे राज्य-च्युत कर दिया था। अब प्रश्न यह था, कि स्पेन की राजगद्दी पर किसे बिठाया जाय। विस्मार्क ने अपनी नीति-कुशलता से स्पेनिश नेताओं को इस बात के लिये तैयार कर लिया, कि वे प्रशिया के राजा विलियम प्रथम के कुटुम्बी लियोपोल्ड को अपना राजा निर्वाचित करे। नैपोलियन तृतीय इस बात को नहीं सह सका। पेरिस के अखबारनवीसों ने प्रशिया के विरुद्ध जहर उगलना प्रारम्भ किया। प्रशिया के हाहेनडोर्शोर्न वंश के इन उत्कर्ष को वे भला कब सहन कर सकते थे ? उन्होंने कहना शुरू किया, कि लियोपोल्ड के स्पेनिश राज्यमहिमान पर आदृष्ट हो जाने से स्पेन पर प्रशिया का प्रभुत्व स्थापित हो जायगा, और यह बात यूरोप की शान्ति के लिये खतरनाक होगी। फ्रांस के विरोध का परिणाम यह हुआ, कि लियोपोल्ड ने स्वयमेव राजगद्दी की उम्मीदवारी का परित्याग कर दिया। पर नैपोलियन को इनने में सन्तोष नहीं हुआ। वह तो युद्ध के लिये तुला हुआ था। उसने उद्घोषित किया, कि लियोपोल्ड की तरफ से राजा बनने के लिये उम्मीदवारी का परित्याग कर देना ही फ्रांस के सन्तोष के लिये काफी नहीं है। प्रशिया की ओर में प्रामाणिक रूप से यह उद्घोषणा की जानी चाहिये, भविष्य में भी हाहेनडोर्शोर्न वंश का कोई कुमार स्पेन की राजगद्दी के लिये उम्मीदवार नहीं होगा। प्रशिया में स्थित फ्रेच राजदूत ने अपने सम्राट की यह भाग विलियम प्रथम के सम्मुख उपस्थित की। विलियम ने इसे स्वीकृत करने से इनकार कर दिया। विस्मार्क ने जान बूझकर इस घटना को प्रशिया के समाचारपत्रों में इस ढंग में प्रकाशित करवाया, ताकि लोग समझें कि फ्रेच राजदूत ने विलियम का अपमान किया है। प्रशियन लोग अपने राजा के अपमान का समाचार पढ़कर भडक गये। दोनों देश युद्ध के लिये पहले से ही तैयार बैठे थे। १९ जुलाई, सन् १८७० के दिन फ्रांस की राष्ट्र प्रतिनिधि सभा के सम्मुख प्रशिया के विरुद्ध युद्ध उद्घोषित करने का प्रस्ताव उपस्थित किया गया। विरोध में केवल १० वोट आये। उसी दिन युद्ध की उद्घोषणा कर दी गई। दोनों देश एक दूसरे पर आक्रमण करने के लिये सन्नद्ध हो गये।

**युद्ध का प्रारम्भ**—युद्ध शुरू हो गया। नैपोलियन को आशा थी, कि वेवेरिया आदि दक्षिणी जर्मन राज्य उसकी सहायता करेंगे, पर उसे निराश होना पड़ा। जर्मनी में राष्ट्रीयता की भावना बहुत प्रबल हो चुकी थी। सम्पूर्ण जर्मनी हथियार लेकर फ्रांस के खिलाफ उठ खड़ा हुआ। बात की बात में दस लाख जर्मन सैनिक रूहाइन नदी को पार कर फ्रांस पर आक्रमण करने के लिये चल पड़े।

**सीडन का युद्ध**—जर्मन सेनापतियों की योजना थी, कि भेट्ज और स्ट्रास्तबुर्ग के दुर्गों में स्थित फ्रेच सेना को परास्त कर पेरिस पर आक्रमण किया जायगा। इन दोनों दुर्गों

को घेर लिया गया, और फ्रांस की आगे बढ़ती हुई शक्तिशाली सेना का सीडन के रणक्षेत्र में मुकाबला किया गया। १ सितम्बर, १८७० को सीडन में फ्रांस और जर्मनी का युद्ध हुआ, जिसमें फ्रांस की बुरी तरह से पराजय हुई। सम्राट् नैपोलियन तृतीय अपने ७१ हजार सैनिकों के साथ जर्मन लोगों के हाथ में कैद हो गया।

**पेरिस का आत्मसमर्पण**—उधर मेट्ज और स्ट्रास्सबुर्ग के घेरे जारी थे। इन दुर्गों को जीतने की भी प्रतीक्षा न कर जर्मन सेनाओं ने पेरिस पर आक्रमण कर दिया। पेरिस घेर लिया गया। फ्रेंच लोगों ने बड़ी वीरता के साथ शत्रुओं का मुकाबला किया। खाद्य पदार्थों की अत्यन्त कमी हो गई, पर इससे भी फ्रेंच लोग घबराये नहीं। उन्होंने कुत्ते, बिल्ली, चूहे और पक्षी—सब खा लिये। और तो और रहा, चिडियाघर के जानवरों पर भी हाथ साफ कर दिया गया। इस दुरवस्था में भी पेरिस के लोगों ने हिम्मत न हारी। सामयिक सरकार के नेता गैम्पेटा ने बैलून पर बैठकर पेरिस से प्रस्थान किया, और बोदियो पहुँचकर पेरिस की रक्षा के लिये सेना एकत्रित करना प्रारम्भ कर दिया। इस बीच में २७ अक्टूबर को मेट्ज परास्त हो गया था, और वहाँ के १ लाख ७३ हजार लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया। कुछ दिनों बाद स्ट्रास्सबुर्ग भी जीत लिया गया। इस स्थिति में पेरिस के लिये और अधिक मुकाबला करना व्यर्थ था।

**फ्राकफोर्ट की सन्धि**—भूख और ठण्ड के कारण लोग तग आ गये थे। २८ जनवरी, १८७१ के दिन सामयिक सन्धि कर ली गई। फ्राकफोर्ट में स्थायी सन्धि के लिये परिषद् की आयोजना की गई। आखिर, १० मई, १८७१ को दोनों देशों में सन्धि हो गई, जो फ्राकफोर्ट की सन्धि के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी मुख्य शर्तें निम्नलिखित थी—

(१) फ्रांस तीन अरब रुपया हर्जाने के तौर पर जर्मनी को दे।

(२) जब तक यह हरजाना वसूल न हो, तब तक जर्मन सेना उत्तरी फ्रांस पर अपना कब्जा कायम रखे।

(३) आल्सेस और लारेन के प्रदेश जर्मनी को दे दिये जावें।

फ्रांस के लिये ये शर्तें बहुत कठोर थी। विशेषतया, आल्सेस और लारेन के प्रदेशों का जर्मनी के साथ सम्मिलित किया जाना फ्रेंच लोगों को बहुत असह्य था। इन प्रदेशों के बहुसंख्यक निवासी फ्रेंच जाति के थे। पुराने जमाने में ये पृथक् राज्य के रूप में रहे थे, और पवित्र रोमन साम्राज्य के अन्तर्गत समझे जाते थे। इस कारण जर्मनी इन पर अपना दावा समझता था। पर अब राष्ट्रीयता के युग में इन प्रदेशों के फ्रेंच लोगों का जर्मनी के अन्तर्गत किया जाना बहुत अनुचित तथा न्यायविरुद्ध अनुभव किया जा रहा था। आल्सेस और लारेन के फ्रेंच निवासी भी किसी भी तरह जर्मन लोगों के साथ नहीं रहना चाहते थे। यही कारण है, कि आल्सेस और लारेन के बहुत से लोग अपने घरों का परित्याग कर इस समय फ्रांस जा वसे।

फ्राकफोर्ट की सन्धि का ही परिणाम था, कि फ्रांस और जर्मनी में दुश्मनी की जड़ जम गई। हरजाना अदा करने के लिये फ्रेंच लोगों को बड़ी-बड़ी कुरबानियाँ करनी पड़ी। उत्तरी फ्रांस में जर्मन सेना मौजूद थी। उसकी सत्ता को फ्रेंच लोग नहीं सह सकते थे। पर वे क्या करते? विवश थे। जब तक हरजाने की सम्पूर्ण रकम वसूल नहीं हो गई, यह

सेना फ्रांस से न हटी।

**जर्मन साम्राज्य की स्थापना**—फ्रेको-जर्मन युद्ध अभी समाप्त भी न हुआ था, कि विस्मार्क ने जर्मन सगठन को पूर्ण करने के लिये प्रयत्न प्रारम्भ कर दिया। दक्षिणी जर्मनी के चारों राज्यों से पृथक्-पृथक् सन्धि की गई। अन्य राज्यों की अपेक्षा उन्हें कुछ अधिक सुभीते दिये गये, जिनके कारण वे जर्मन राज्य-संघ में सम्मिलित होने के लिये तैयार हो गये। 'राज्य-संघ' का नाम बदलकर 'साम्राज्य' कर दिया गया, और इस नवीन जर्मन-साम्राज्य के अध्यक्ष को सम्राट् की पदवी दी गई। प्रशिया का राजा अब जर्मन सम्राट् भी बन गया। पेरिस के आत्मसमर्पण के दस दिन पूर्व १८ जनवरी, १८७१ को वर्साय के राजप्रासाद के शीशमहल में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण उत्सव की आयोजना की गई। इस उत्सव में जर्मनी के विविध राजा बड़ी शान से अपने-अपने आसनो पर बैठे थे। बीच में एक ऊँची वेदी पर प्रशिया का राजा विलियम प्रथम विराजमान था। वेरिया के राज-प्रतिनिधि ने खड़े होकर अपने साथी राजाओं की तरफ से विलियम की सेवा में साम्राज्य का राजमुकुट पेश किया। इसके अनंतर विस्मार्क ने जर्मन साम्राज्य के निर्माण का उद्घोषणा-पत्र पढ़ा। जिस राष्ट्रीय एकता के लिये जर्मन लोग इनके समय में उत्सुक थे, आगिर प्रशिया के नेतृत्व में और विस्मार्क के प्रयत्न से वह सम्पन्न हो गई।

उत्तरी जर्मन राज्य-संघ के सगठन को ही कुछ परिवर्तित कर के जर्मन साम्राज्य का सगठन बनाया गया। यह नवीन सगठन १९१८ की जर्मन राज्यक्रान्ति तक कायम रहा। विस्मार्क जर्मन साम्राज्य का प्रथम प्रधान मन्त्री बना। विस्मार्क के जीवन की सबसे प्रधान महत्वाकांक्षा अब पूर्ण हो चुकी थी।

**विस्मार्क का कर्तृत्व**—इसमें सन्देह नहीं, कि प्रिंस विस्मार्क का जर्मनी के उत्कर्ष में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। यह उसी के कर्तृत्व का परिणाम था, कि जर्मनी एक राष्ट्र के रूप में सगठित हो सका। अनेक छोटे-बड़े राज्यों में विभक्त होना जर्मनी की उन्नति में सबसे बड़ी बाधा थी। श्लेस्विग और हालस्टाइन के जिन प्रदेशों को उसने डेन्मार्क से पृथक् कर प्रशिया में सम्मिलित किया, वे वस्तुतः जर्मन थे। रूहाइन के प्रदेशों को नैपोलियन तृतीय के शासन व प्रभाव में आने देने में बाधा डालकर भी उसने जर्मन राष्ट्रीयता की बड़ी सहायता की। आस्ट्रिया को पृथक् कर पहले उत्तरी जर्मन-संघ और फिर जर्मन साम्राज्य का सगठन कर उसने जर्मन राष्ट्र के विकास को पूर्ण किया। जर्मनी के लिये उसने वही महत्वपूर्ण कार्य किया, जो सतरहवीं सदी में रिशिल्यू ने फ्रांस के लिये किया था।

इसमें सन्देह नहीं, कि विस्मार्क लोकतन्त्रवाद का विरोधी था। पर समय की गति को देखते हुए उसने जर्मन साम्राज्य में पार्लियामेन्ट का निर्माण किया था, और वोट के अधिकार को भी बहुत विस्तृत किया था। विस्मार्क कूटनीतिज्ञ, सफल शासक और मयोग्य सेनानी था। उसके कर्तृत्व से जर्मनी की अमाधारण उन्नति हुई।

बीसवा अध्याय

## इंग्लैण्ड में सुधार का काल

१ पुराना इंग्लैण्ड

फ्रांस की राज्यक्रांति से पूर्व इंग्लैण्ड यूरोप में सबसे अधिक उन्नत और प्रगतिशील देश माना जाता था। उदार विचारों के लोग उसकी शासनपद्धति को आदर्श समझते थे। फ्रांस मान्तस्व्यू और वाल्टेयर जैसे उदार और क्रान्तिकारी विचारकों ने इंग्लिश शासनपद्धति की बड़ी प्रशंसा की थी, और यूरोप के अत्याचार-पीडित लोगों के सम्मुख उसी को आदर्श रूप में पेश किया था। इंग्लैण्ड में पार्लियामेंट की स्थापना हो चुकी थी। हाउस आफ कामन्स के सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित होते थे। प्रत्येक कानून पार्लियामेंट द्वारा स्वीकृत होने पर ही लागू हो सकता था। कानून के अनुसार ठीक तरह से न्याय करने के लिये वाकायदा न्यायालयों का भी संगठन बहा हो चुका था। राजा की इंग्लैण्ड में सत्ता अवश्य थी, पर पार्लियामेंट और स्वतन्त्र न्यायालयों की सत्ता के कारण वह यूरोप के अन्य राजाओं के समान एकतन्त्र और स्वेच्छाचारी नहीं था। उसकी शक्ति कानूनों द्वारा सीमित थी। इंग्लैण्ड में वैध राजसत्ता की स्थापना का प्रारम्भ फ्रेंच राज्यक्रान्ति से लगभग एक सदी पहले से हो चुका था।

**स्वेच्छाचारी राजसत्ता और उसके विरुद्ध संघर्ष**—इंग्लिश लोगों ने इस उन्नत शाननविधान को कैसे और कब प्राप्त किया, इसकी कथा बहुत बड़ी है। उसे यहाँ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। मध्यकाल में इंग्लैण्ड में पार्लियामेंट विद्यमान थी। पर यह पार्लियामेंट बड़े-बड़े सामन्तों की सभा के अतिरिक्त कोई चीज नहीं थी। राजा इसके कार्य में यथेष्ट रूप से हस्तक्षेप किया करता था। यह पार्लियामेंट राजा के हाथ में कठपुतली के समान होती थी। सत्रहवीं सदी में इंग्लैण्ड में स्टुअर्ट वंश के राजा राज्य करते थे। ये पूर्णरूप से स्वेच्छाचारी और एकतन्त्र थे। राजा के दैवी अधिकार में इनका दृढ़ विश्वास था। स्टुअर्ट वंश का पहला राजा जेम्स प्रथम कहा करता था—“ईश्वर क्या कर सकता है, इस पर आशंका करना नास्तिकता और धर्मद्रोह है। इसी प्रकार राजा क्या कर सकता है, इस बात पर विचार करना या यह समझना कि राजा यह काम नहीं कर सकता, राजद्रोह और राजा का अपमान करना है।” जेम्स प्रथम और उसके उत्तराधिकारी स्टुअर्ट वंशी राजा अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि समझते थे, और अपने ईश्वरविहित अधिकारों में जनता द्वारा किसी भी प्रकार की बाधा व नियन्त्रण को नहीं सह सकते थे। उनके स्वेच्छाचार का परिणाम यह हुआ, कि सन् १६४२ में जनता ने विद्रोह कर दिया, और राजा और जनता में वाकायदा लड़ाई शुरू हो गई। इस मुद्द में राजा परास्त हुआ।

सेना फ्रांस से न हटी।

**जर्मन साम्राज्य की स्थापना**—फ्रेको-जर्मन युद्ध अभी समाप्त भी न हुआ था, कि विस्मार्क ने जर्मन सगठन को पूर्ण करने के लिये प्रयत्न प्रारम्भ कर दिया। दक्षिणी जर्मनी के चारों राज्यों में पृथक्-पृथक् सन्धि की गई। अन्य राज्यों की अपेक्षा उन्हें कुछ अधिक सुभीते दिये गये, जिनके कारण वे जर्मन राज्य-संघ में सम्मिलित होने के लिये तैयार हो गये। 'राज्य-संघ' का नाम बदलकर 'साम्राज्य' कर दिया गया, और इस नवीन जर्मन-साम्राज्य के अध्यक्ष को सम्राट् की पदवी दी गई। प्रशिया का राजा अब जर्मन सम्राट् भी बन गया। पेरिस के आत्मसमर्पण के दस दिन पूर्व १८ जनवरी, १८७१ को वर्साय के राजप्रासाद के शीशमहल में एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण उत्सव की आयोजना की गई। इस उत्सव में जर्मनी के विविध राजा बड़ी शान से अपने-अपने आसनों पर बैठे थे। बीच में एक ऊँची वेदी पर प्रशिया का राजा विलियम प्रथम विराजमान था। बवेरिया के राज-प्रतिनिधि ने खड़े होकर अपने साथी राजाओं की तरफ से विलियम की मेज़ा में साम्राज्य का राजमुकुट पेश किया। इसके अनंतर विस्मार्क ने जर्मन साम्राज्य के निर्माण का उद्घोषणा-पत्र पढ़ा। जिस राष्ट्रीय एकता के लिये जर्मन लोग इतने समय से उत्सुक थे, अखिर प्रशिया के नेतृत्व में और विस्मार्क के प्रयत्न से वह सम्पन्न हो गई।

उत्तरी जर्मन राज्य-संघ के सगठन को ही कुछ परिवर्तित कर के जर्मन साम्राज्य का सगठन बनाया गया। यह नवीन सगठन १९१८ की जर्मन राज्यक्रान्ति तक कायम रहा। विस्मार्क जर्मन साम्राज्य का प्रथम प्रधान मन्त्री बना। विस्मार्क के जीवन की सबसे प्रधान महत्वाकांक्षा अब पूर्ण हो चुकी थी।

**विस्मार्क का कर्तृत्व**—इसमें सन्देह नहीं, कि प्रिम विस्मार्क का जर्मनी के उत्कर्ष में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है। यह उमी के कर्तृत्व का परिणाम था, कि जर्मनी एक राष्ट्र के रूप में सगठित हो सका। अनेक छोटे-बड़े राज्यों में विभक्त होना जर्मनी की उन्नति में सबसे बड़ी बाधा थी। श्लेस्विग और हालस्टाइन के जिन प्रदेशों को उसने डेन्मार्क से पृथक् कर प्रशिया में सम्मिलित किया, वे वस्तुतः जर्मन थे। रूहाइन के प्रदेशों को नैपोलियन तृतीय के शासन व प्रभाव में आने देने में बाधा डालकर भी उसने जर्मन राष्ट्रीयता की बड़ी सहायता की। आस्ट्रिया को पृथक् कर पहले उत्तरी जर्मन-संघ और फिर जर्मन साम्राज्य का सगठन कर उसने जर्मन राष्ट्र के विकास को पूर्ण किया। जर्मनी के लिये उसने वही महत्त्वपूर्ण कार्य किया, जो सतरहवीं सदी में रिशिल्यू ने फ्रांस के लिये किया था।

इसमें सन्देह नहीं, कि विस्मार्क लोकतन्त्रवाद का विरोधी था। पर समय की गति को देखते हुए उसने जर्मन साम्राज्य में पार्लियामेन्ट का निर्माण किया था, और वोट के अधिकार को भी बहुत विस्तृत किया था। विस्मार्क कूटनीतिज्ञ, सफल शासक और मयोग्य सेनानी था। उसके कर्तृत्व से जर्मनी की अमाधारण उन्नति हुई।



बीसवा अध्याय

## इंग्लैण्ड में सुधार का काल

१ पुराना इंग्लैण्ड

फ्रांस की राज्यक्रांति से पूर्व इंग्लैण्ड यूरोप में सबसे अधिक उन्नत और प्रगतिशील देश माना जाता था। उदार विचारों के लोग उसकी शासनपद्धति को आदर्श समझते थे। फ्रांस मान्तेस्स्यू और वाल्टेयर जैसे उदार और क्रान्तिकारी विचारकों ने इंग्लिश शासनपद्धति की बड़ी प्रशंसा की थी, और यूरोप के अत्याचार-पीडित लोगों के सम्मुख उसी को आदर्श रूप में पेश किया था। इंग्लैण्ड में पार्लियामेंट की स्थापना हो चुकी थी। हाउस आफ कामन्स के सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित होते थे। प्रत्येक कानून पार्लियामेंट द्वारा स्वीकृत होने पर ही लागू हो सकता था। कानून के अनुसार ठीक तरह से न्याय करने के लिये वाकायदा न्यायालयों का भी संगठन बहा हो चुका था। राजा की इंग्लैण्ड में सत्ता अवश्य थी, पर पार्लियामेंट और स्वतन्त्र न्यायालयों की सत्ता के कारण वह यूरोप के अन्य राजाओं के समान एकतन्त्र और स्वेच्छाचारी नहीं था। उसकी शक्ति कानूनों द्वारा सीमित थी। इंग्लैण्ड में वैध राजसत्ता की स्थापना का प्रारम्भ फ्रेंच राज्यक्रान्ति से लगभग एक सदी पहले से हो चुका था।

स्वेच्छाचारी राजसत्ता और उसके विरुद्ध संघर्ष—इंग्लिश लोगों ने इस उन्नत शासनविधान को कैसे और कब प्राप्त किया, इसकी कथा बहुत बड़ी है। उसे यहाँ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। मध्यकाल में इंग्लैण्ड में पार्लियामेंट विद्यमान थी। पर यह पार्लियामेंट बड़े-बड़े सामन्तों की सभा के अतिरिक्त कोई चीज न थी। राजा इसके कार्य में व्यष्ट रूप से हस्तक्षेप किया करता था। यह पार्लियामेंट राजा के हाथ में कठपुतली के समान होती थी। सत्रहवीं सदी में इंग्लैण्ड में स्टुअर्ट वंश के राजा राज्य करते थे। ये पूर्णरूप से स्वेच्छाचारी और एकतन्त्र थे। राजा के दैवी अधिकार में इनका दृढ़ विश्वास था। स्टुअर्ट वंश का पहला राजा जेम्स प्रथम कहा करता था—“ईश्वर क्या कर सकता है, इस पर आशंका करना नास्तिकता और धर्मद्रोह है। इसी प्रकार राजा क्या कर सकता है, इस बात पर विचार करना या यह समझना कि राजा यह काम नहीं कर सकता, गजद्रोह और राजा का अपमान करना है।” जेम्स प्रथम और उसके उत्तराधिकारी स्टुअर्ट वंशी राजा अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि समझते थे, और अपने ईश्वरविहित अधिकारों में जनता द्वारा किसी भी प्रकार की बाधा व नियन्त्रण को नहीं सह सकते थे। उनके स्वेच्छाचार का परिणाम यह हुआ, कि सन् १६४२ में जनता ने विद्रोह कर दिया, और राजा और जनता में वाकायदा लड़ाई शुरू हो गई। इस मुद्द में राजा परास्त हुआ।

उसे गिरफ्तार कर लिया गया, और सन् १६४९ में उसे फासी पर चढ़ा दिया गया। जनता द्वारा कतल किये जाने वाले इस राजा का नाम चार्ल्स प्रथम था, और यह जेम्स प्रथम के बाद इंग्लैण्ड का राजा बना था। चार्ल्स प्रथम को कतल कर इंग्लिश जनता ने रिपब्लिक की स्थापना की। क्रोमवेल इस रिपब्लिक का पहला राष्ट्रपति बना। पर अभी रिपब्लिको का युग नहीं आया था। कुछ ही वर्षों बाद सन् १६६० में रिपब्लिक की समाप्ति हो गई, और स्टुअर्ट वंश का चार्ल्स द्वितीय फिर इंग्लैण्ड का राजा बन गया। चार्ल्स द्वितीय भी राजा के दैवी अधिकारों में विश्वास रखता था, और राज्यकार्य में जनता का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप महन नहीं कर सकता था। पर वह बुद्धिमान् और कार्यकुशल राजा था। उसने अपने शासनकाल में जनता को सन्तुष्ट करने के लिये अनेक कानून जारी किये। चार्ल्स द्वितीय की मृत्यु के बाद १६८५ में उसका लड़का जेम्स द्वितीय राजगद्दी पर बैठा। उसने अपने पिता की नीति का परित्याग कर फिर स्वेच्छाचारी नीति का आश्रय लिया। परिणाम यह हुआ, कि १६८८ में जनता ने फिर विद्रोह कर दिया। जेम्स द्वितीय को राजगद्दी से च्युत कर विलियम तृतीय को इंग्लैण्ड की राजगद्दी सभालने के लिये निमन्त्रित किया गया। यह विलियम तृतीय नीदरलैण्ड (हॉलैण्ड) का राजा था, और उसकी धर्मपत्नी मेरी इंग्लैण्ड के राजवंश की थी। जेम्स द्वितीय विलियम का मुकाबला नहीं कर सका। वह परास्त हो गया, और 'जनता की इच्छा में' विलियम तृतीय इंग्लैण्ड का राजा बना।

**वैध राजसत्ता की स्थापना**—इंग्लिश जनता की यह महान् विजय थी। विलियम तृतीय को जनता ने अपनी इच्छा में राजा बनाया था। इसलिये वह स्टुअर्ट वंश के राजाओं के समान एकतन्त्र व स्वेच्छाचारी नहीं हो सकता था। राजा की शक्ति को सीमित करने के लिये पार्लियामेन्ट में इस समय एक विधान पेश किया गया, जिसे 'बिल आफ राइट्स' या 'अधिकार-विधान' कहते हैं। इसमें मुख्यतः निम्नलिखित अधिकारों को प्रतिपादित किया गया था—राजा देश के किसी कानून का उल्लंघन न कर सके। पार्लियामेन्ट की स्वीकृति के बिना राजा कोई नया टैक्स न लगा सके। पार्लियामेन्ट में सदस्यों को भाषण देने की पूर्ण स्वतन्त्रता रहे। क्रूरता से युक्त सजाए न दी जाएँ, सजा में अत्यधिक जुरमाने भी न किये जाएँ। प्रत्येक नागरिक को अधिकार हो, कि वह राजा के सम्मुख अपने प्रार्थना-पत्र पेश कर सके। इसी प्रकार के अन्य भी बहुत से अधिकार इस 'बिल आफ राइट्स' द्वारा जनता को दिये गये। विलियम तृतीय ने इन्हें स्वीकृत किया, और जनता ने उसे अपना राजा माना।

जेम्स द्वितीय को राज्यच्युत कर और अपनी इच्छा से विलियम तृतीय को राजगद्दी पर बिठाकर इंग्लिश जनता ने सचमुच बड़ा भारी काम कर दिखाया था। इसे ही इतिहास में 'इंग्लिश राज्यक्रांति' कहते हैं। इस समय से (१६८८ से) इंग्लैण्ड में राजाओं के अपरिमित स्वेच्छाचार का सचमुच अन्त हो गया, और पार्लियामेन्ट की शक्ति निरन्तर बढ़ने लगी। इसी बात को दृष्टि में रखकर यूरोप के उदार विचारक और क्रान्तिकारी लोग इंग्लिश शासन-पद्धति की बड़ी प्रशंसा करते थे, और उसे अन्य यूरोपियन राज्यों के लिये अनुकरणीय और आदर्श समझते थे।

शासन-पद्धति के दोष—यह सब कुछ होते हुए भी उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ में इङ्ग्लैण्ड की शासन-पद्धति लोकतन्त्र व जनता की इच्छा पर आश्रित नहीं थी। वहाँ पार्लियामेंट वेशक थी, पर उसके सदस्यों का चुनाव जिस ढंग से होता था, उसमें बहुत से दोष थे। वोट का अधिकार भी बहुत कम लोगों को प्राप्त था। देश की आबादी में निरन्तर परिवर्तन आते रहते हैं। अनेक नगर जो किसी जमाने में बड़े समृद्ध और आबाद थे, आगे चल कर उजड़ जाते हैं, और अनेक नवीन नगरों का विकास हो जाता है। इसलिये उचित यह है, कि समय-समय पर निर्वाचन-क्षेत्रों का नये सिरे से सगठन होता रहे। पर इङ्ग्लैण्ड में पार्लियामेंट के चुनाव के लिये इस बात की कोई आवश्यकता नहीं समझी जाती थी। कई सदी पहले से जो निर्वाचन-क्षेत्र वहाँ चले आते थे, वे ही अब उन्नीसवीं सदी में भी विद्यमान थे। गैटन के निर्वाचन क्षेत्र में पाच, आरफोर्ड में बीस और मिडिलहर्स्ट में तेरह वोटर थे। पर इन पुराने उजड़े हुए नगरों से पार्लियामेंट के लिये वाकायदा प्रतिनिधि निर्वाचित होते थे। ओल्ड सेरम में जब कोई भी आबादी नहीं रही थी, डन्विच नगर तो समुद्र में डूब चुका था, पर फिर भी इनकी ओर से निर्वाचित हुए प्रतिनिधि वाकायदा पार्लियामेंट में पहुँचते थे। इस प्रकार के उजड़े हुए नगरों की संख्या बहुत काफी थी। उनके प्रदेश जिन अमीर लार्डों की जमींदारी में थे, वे ही अपनी तरफ से किन्हीं महान्भावों को नामजद करके पार्लियामेंट में भेज देते थे। दूसरी ओर अनेक ऐसे नवीन नगरों का विकास हो गया था, जिनसे एक भी प्रतिनिधि निर्वाचित नहीं होता था। व्यावसायिक क्रान्ति के कारण अनेक विशाल नगर इस समय विकसित हो गये थे, जिनकी आबादी लाखों में पहुँच रही थी। मॉन्चेस्टर, बर्मिंघम और लीड्स जैसे नये बसे हुए व्यवसाय-प्रधान नगरों का कोई भी प्रतिनिधि पार्लियामेंट में नहीं पहुँचता था। लार्ड जॉन रसल ने इस दशा को दृष्टि में रखकर एक भाषण में कहा था, कि यदि कोई विदेशी यात्री हमारे देश में आये तो उसे यह देखकर कितना आश्चर्य होगा, कि यहाँ हरियावल से पूर्ण अनेक मैदान जिनमें वनस्पतियाँ तो बहुत हैं, पर इन्सान का नामोनिशान भी नहीं है, पार्लियामेंट के लिये वाकायदा प्रतिनिधि चुनते हैं, और उन विशाल नगरों से जो व्यवसाय और व्यापार आदि के महत्त्वपूर्ण केन्द्र हैं, एक भी प्रतिनिधि निर्वाचित नहीं होता, यद्यपि पार्लियामेंट मनुष्यों के प्रतिनिधियों से बनती है, वनस्पतियों व हरियावल के प्रतिनिधियों से नहीं।

वोट का अधिकार भी बहुत कम लोगों को था। उस समय वोट देना नागरिकता के लिये कोई आवश्यक अधिकार नहीं माना जाता था। नगरों में केवल अमीर व्यापारियों को ही वोट का अधिकार प्राप्त था। व्यापारी लोग आपस में मिलकर किसी व्यक्ति को पार्लियामेंट के लिये चुन देते थे। देहातों में वोट का अधिकार केवल उन लोगों को था, जिनके पास अपनी मिल्कियत में ऐसी जमीन हो, जिसकी आमदनी कम से कम तीस रुपया वार्षिक हो। उस जमाने में तीस रुपया वार्षिक आमदनी की जागीर का मालिक होना कोई मामूली बात नहीं थी। देहातों में ऐसे लोग बहुत कम थे, जो इतनी जमीन के स्वामी हो। इस दशा का परिणाम यह था, कि इङ्ग्लैण्ड में बालिग पुरुषों की जिननी आबादी थी, (स्त्रियों और नाबालिग बच्चों को निकालकर) उसके केवल पाच फीसदी

लोगों को ही वोट देने का अधिकार मिला हुआ था। स्कॉटलैण्ड की कुल आबादी बीस लाख से ऊपर थी, पर उसमें वोट का अधिकार केवल तीन हजार आदमियों को था। वूट के ताल्लुके की आबादी १४ हजार थी, पर उसमें वोट केवल २३ आदमी थे। अनेक ताल्लुकों में तो वोटरो की संख्या केवल एक-एक थी।

इतना ही नहीं, निर्वाचन में रिश्वत भी खूब चलती थी। रिश्वत को बुरा नहीं समझा जाता था। वह खुले तौर पर ली दी जाती थी। हमारे पक्ष में वोट दो और एक वूट के लिये हम कितनी कीमत प्रदान करेंगे, इस बात का खुला विज्ञापन उम्मीदवारों की ओर से दिया जाता करता था। वोट खुले तौर पर डाले जाते थे। इसका परिणाम यह होता था, कि सर्वसाधारण वोटर स्वतन्त्रता के साथ वोट नहीं दे सकते थे। उन्हें इस बात का भय बना रहता था, कि उनका जमींदार कहीं उन पर नाराज न हो जाए।

इन सब बातों का परिणाम यह था, कि इङ्ग्लैण्ड में पार्लियामेंट और उसके प्रति उत्तरदायी मन्त्रिमण्डल के होते हुए भी लोकतन्त्र गान्धन विद्यमान नहीं था। वहाँ की पार्लियामेंट की अन्यतम सभा हाउस आफ लार्ड्स तो बड़े जागीरदारों और कुलीन श्रेणियों के लोगों की सभा थी ही। दूसरी सभा हाउस आफ कामन्स पर भी उन्हीं का प्रभुत्व था। वे जिसे चाहते, प्रतिनिधि चुनवा सकते थे। इस प्रकार हाउस आफ कामन्स भी नाम की ही जनता के प्रतिनिधियों की सभा थी। बम्बुन, कुलीन और जागीरदार श्रेणियों के नामजद किये हुए सदस्यों का ही उसमें प्रभुत्व होता था।

## २ शासन में सुधार

**सुधार के प्रयत्नों की विफलता**—इङ्ग्लैण्ड की गामन-वृद्धि में जो दोष थे, उन्हें वहाँ के अनेक राजनीतिज्ञ अनुभव करते थे। अठारहवीं सदी में ही इन बुराइयों के विरुद्ध आन्दोलन प्रारम्भ हो गया था। पार्लियामेंट के सम्मुख शासन-सुधार के लिये अनेक मसविदे भी पेश किये गये थे। १७७० में लार्ड चैयम और उसके बाद उसके प्रसिद्ध पुत्र पिट ने शासन-सुधार सम्बन्धी प्रस्ताव उपस्थित किये थे। पर अभी इन प्रस्तावों का कोई फैसला नहीं हुआ था, कि उधर फ्रांस में राज्यक्रान्ति हो गई। कुछ ही दिनों में क्रान्ति ने भयंकर रूप धारण कर लिया, और यूरोप भर की सरकारें उसे कुचल डालने के लिये सन्नद्ध हो गईं। इङ्ग्लैण्ड ने भी राज्यक्रान्ति के विरुद्ध जिहाद शुरू किया। १८१५ तक इङ्ग्लैण्ड तथा अन्य यूरोपियन राज्य फ्रेच राज्यक्रान्ति और नैपोलियन के विरुद्ध युद्ध करने रहे। इस समय इङ्ग्लैण्ड में किसी भी सुधार-संबन्धी प्रस्ताव का स्वीकृत हो सकता असम्भव था। लोग कहते थे, यदि इङ्ग्लैण्ड में भी जनता को अधिकार दिये जाएंगे, तो उसका वही नतीजा होगा, जो फ्रांस में अवदृष्टिगोचर हो रहा है। १८१५ में वीएना की कांग्रेस के बाद यूरोप भर में प्रतिक्रिया का काल शुरू हुआ। समानता, स्वतन्त्रता और भ्रातृभाव की नई प्रवृत्तियों का स्थान कुलीनों के विशेषाधिकारों और राजा के स्वेच्छाचारी एकतन्त्र शासन ने लिया। यूरोप के अनेक शक्तिशाली राजाओं ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया, जिसका उद्देश्य ही क्रान्ति की प्रवृत्तियों और उदार विचारों को कुचलना था। इस समय सब जगह एकतन्त्र और स्वेच्छाचारी शासन कायम हो रहे थे। इङ्ग्लैण्ड में भी अनुदार

(टोरी) दल का प्रभुत्व था। इस दल के लोग शासन-सुधारों के खिलाफ थे। मेटरनिख का पसिद्ध मित्र ड्यूक आफ वेल्सिंग्टन इस समय इंग्लैण्ड का प्रधानमंत्री था। उसके रहते रहते हुए सुधार की आशा ही कैसे की जा सकती थी। इसी लिये इस काल में सुधार के बजाय ऐसे कानून पास किये गये, जिनका उद्देश्य नवीन विचारों व नई प्रवृत्तियों को कुचलना था। सन् १८१९ में ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा 'सिक्स एक्ट्स (छ कानून)' पास किये गये, जिनसे जनता को स्वतन्त्र रूप से भाषण करने, लिखने और सार्वजनिक सभाएं करने में अनेक रुकावटें डाली गईं।

**क्रान्ति की लहर—**१८३० में यूरोप में क्रान्ति की दूसरी लहर शुरू हुई। फ्रांस, और इटली, स्पेन आदि विविध देशों में क्रान्तियां हुईं। इंग्लैण्ड भी क्रान्तिकी इस लहर से अछूता नहीं रहा। नये विचारों के लोग पहले भी अपना कार्य कर रहे थे, अब उनमें नवजीवन आ गया। लोकमत सुधारों के पक्ष में हो गया, और पार्लियामेंट में उदार (लिबरल) दल के लोगों की शक्ति बढ़ गई। ड्यूक आफ वेल्सिंग्टन को त्यागपत्र देना पड़ा, और उसके स्थान पर सुधारवादी उदार दल का प्रधान नेता लार्ड जॉन रसल प्रधान मंत्री बना। १८३१ के मार्च मास में रसल ने सुधार के लिये मसविदा पेश किया। हाउस आफ कामन्स में इसका घोर विरोध हुआ। पर रसल इससे घबराया नहीं। वह जानता था, कि देश का लोकमत उसके साथ है। उसने हाउस आफ कामन्स को बर्खास्त कर दिया और नया निर्वाचन कराया। नये हाउस में उदार दल का बहुमत था। अब हाउस आफ कामन्स में इस मसविदे के पास होने में देर नहीं लगी। पर हाउस आफ लार्ड्स में इसे स्वीकृत करा सकना आसान बात नहीं थी। वहां कुलीन जागीरदारों का प्रभुत्व था। वे लोग सुधारों के प्रबल विरोधी थे। उन्होंने इसे अस्वीकृत कर दिया। अब एक नई समस्या उत्पन्न हुई। जनता सुधार चाहती थी, और लार्ड लोग उसके मार्ग में रुकावट थे। आखिर, लार्ड रसल ने राजा को इस बात के लिये तैयार कर लिया, कि सुधारों के पक्षपाती इतने नये लार्ड बना दिये जावें, ताकि यह मसविदा हाउस आफ लार्ड्स में पास हो सके। इस दशा में अधिक विरोध निरर्थक था। जून, १८३२ में हाउस आफ लार्ड्स ने भी सुधार के मसविदे को स्वीकृत कर लिया।

**१८३२ के सुधार—**१८३२ के सुधार-विधान ने इंग्लैण्ड की शासन-पद्धति के उन भागों को दूर करने का प्रयत्न किया, जिनका हम पहले प्रकरण में वर्णन कर चुके हैं। इस विधान द्वारा ५६ ऐसे नगरों में प्रतिनिधि भेजने का अधिकार छीन लिया गया, जिनकी आबादी दो हजार से भी कम थी। कुछ नगर ऐसे थे, जिनकी आबादी दो हजार से तो अधिक थी, पर चार हजार से कम थी। पहले उनसे भी दो-दो प्रतिनिधि निर्वाचित होने थे। अब उनमें एक-एक प्रतिनिधि भेजने की व्यवस्था की गई। ऐसे नगरों की संख्या २ थी। ३२ नये नगरों को दो-दो प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया। २० नये नगरों को एक-एक प्रतिनिधि भेजने का हक मिला। इसी तरह देहानों की भी नये सिरे में व्यवस्था की गई। आबादी के हिसाब से नये निर्वाचनमण्डलों का विभाग किया गया, और यह निर्णय हुआ कि समय-समय पर आबादी की दृष्टि से निर्वाचक-मण्डलों का पुनः संगठन होता रहे। १८३२ के सुधार-विधान में वोट के अधिकार में भी परिवर्तन किया गया। देहानों में उन सब लोगों को वोट का अधिकार

मिला, जो ७५० रुपया वार्षिक लगान देने हों, या इनके लगान की भूमि के स्वामी हों। शहरों में वे गवर्नर वोटर बना दिये गये, जो १५० रु० वार्षिक क्रिया के मकान में रहते हों, या इनके क्रिया के मकान के स्वामी हों। इस प्रकार वोट देने का अधिकार पहले की अपेक्षा कुछ अधिक विस्तृत हो गया। पर यह ध्यान में रखना चाहिये, कि १८३२ के इन सुधारों द्वारा वोट का अधिकार बहुत कम लोगों का मिला था। हिमाचल लगाया गया है कि उस समय इंग्लैंड में कुल मिलाकर ६०,२३,७५२ वार्षिक पुरुष थे, जिनमें से केवल ८,३९,५१९ पुरुषों को ही वोट का अधिकार दिया था। सर्वसाधारण किमान व मजदूर इस अधिकार में सर्वथा वंचित रखे गये थे। उस जमाने में ७५० रु० वार्षिक लगान देना या शहरों में १५० रु० वार्षिक क्रिया के मकान में रहना कोई मामूली बात नहीं। केवल उच्च मध्यमश्रेणी के लोग ही इस सुधार-विधान में लाभ उठा सकते थे। सर्वसाधारण जनता—किसान और मजदूर लोग अब भी राजनीतिक अधिकार में सर्वथा वंचित थे।

**चार्टर्ड आन्दोलन**—सुधार-विधान अभी क्रिया रूप में परिणत होता शुरू भी नहीं हुआ था, कि उसके विरुद्ध आन्दोलन प्रारम्भ हो गया। किमान और मजदूर लोगों ने पुनः मात्र को मताधिकार प्राप्त हो, इसके लिये आन्दोलन शुरू कर दिया। स्थान-स्थान पर सार्वजनिक सभाओं का आयोजन किया गया। १८३८ में सर्वसाधारण जनता ने एक उद्घोषणा-पत्र (चार्टर) तैयार किया, जिसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित ७ मांगें पेश की गई थी—(१) सब वार्षिक पुत्तों को वोट का अधिकार दिया जाय। (२) वोट गুলे तीर पर न लिये जाएँ, अपितु पत्रियों द्वारा लिये जाया करे। (३) पार्लियामेंट का सदस्य होने के लिये सम्पत्ति की कोई शर्त न रखी जाए। (४) पार्लियामेंट के सदस्यों को निश्चित वेतन मिला करे। (५) पार्लियामेंट का निर्वाचन वार्षिक रूप में हो। (६) निर्वाचन-मण्डलों का फिर से सगठन किया जाए, और इसके लिये देश को नये व एक बराबर विभागों में विभक्त किया जाए।

वर्तमान समय में ये मांगें बहुत मामूली प्रतीत होती हैं। इंग्लैंड में इस समय ये प्रायः स्वीकृत भी की जा चुकी हैं। पर उसीसवीं सदी के मध्यभाग में इन्हें बहुत क्रान्तिकारी समझा जाता था। चार्टिस्ट लोग इनके लिये घनघोर आन्दोलन कर रहे थे। स्थान-स्थान पर सभाएँ की जाती थी। जुलूस निकाले जाते थे, जोशीली कविताएँ गाई जाती थी, और गरमागरम वक्तृताएँ दी जाती थी। सरकार इन मांगों को अत्यन्त खतरनाक समझती थी। उदार और अनुदार दोनों दलों के लोग इनके खिलाफ थे। वे अपनी सारी शक्ति से इस चार्टिस्ट आन्दोलन को कुचल डालने के लिये उत्सुक थे। सन् १८३९ में इस चार्टर पर लाखों मनुष्यों के हस्ताक्षर कराये गये, और उसे पार्लियामेंट की सेवा में उपस्थित किया गया। पर वहाँ उसके अस्वीकृत होने में देर नहीं लगी। अधिकांश सदस्य उसके विरोध में थे, और इसी कारण वह स्वीकृत न हो सका।

सन् १८४० में 'नैशनल चार्टर एसोशियेशन' की स्थापना हुई। इसकी शाखाएँ इंग्लैंड के प्रायः सभी नगरों में कायम की गईं। इस एसोशियेशन की तरफ से चार्टर के लिये प्रचण्ड आन्दोलन शुरू हुआ। कुछ लोग तो हिंसात्मक उपायों के भी पक्षपाती थे, और खुल्लमखुल्ला उनका प्रचार कर रहे थे। कई स्थानों पर दंगे भी हुए, पर पुलिस ने

उन्हें बड़ी मुश्किल से शान्त कर दिया। सरकार ने जनता के आन्दोलन को शान्त करने के लिये इस समय बड़ा भारी प्रयत्न किया हुआ था।

सन् १८४८ में फ्रांस में फिर राज्यक्रान्ति हुई। फ्रांस की क्रान्ति का प्रभाव अन्य देशों पर भी पड़ा। सारे यूरोप में क्रान्ति की एक नई लहर व्याप्त हो गई। क्रान्ति की इस नई लहर ने चार्टिस्ट आन्दोलन में नवजीवन का संचार किया। एक नया चार्टर तैयार किया गया और उस पर साठ लाख मनुष्यों के हस्ताक्षर कराये गये। इतने हस्ताक्षर प्राप्त करने के लिये सम्पूर्ण देश में बड़ा भारी आन्दोलन किया गया था। इस विशाल चार्टर को हाउस आफ कॉमन्स की सेवा में प्रस्तुत करने के लिये बहुत बड़ी तैयारी की गई। एक विशाल जुलूस निकालने की योजना बनाई गई, जिसमें पांच लाख मनुष्य शामिल हों। साठ लाख हस्ताक्षरों से युक्त यह चार्टर इतना बड़ा था, कि छ गाड़ियों पर आया था। सरकार को इस बात की आशंका थी, कि इस जुलूस के कारण शान्ति-रक्षा सम्भव नहीं। अतः जुलूस को गैर-कानून उद्घोषित कर दिया गया और एक लाख सत्तर हजार सिपाही लण्डन के विविध स्थानों पर अमन और चैन की रक्षा के लिये नियुक्त कर दिये गये। पुलिस की इतनी तैयारी के कारण चार्टिस्ट लोग गड़बड़ न कर सके। चार्टर को पार्लियामेंट के सम्मुख पेश किया गया, पर इस बार भी वह स्वीकृत न हो सका। जांच करने पर मालूम हुआ, कि उस पर बहुत से लोगों के हस्ताक्षर जाली थे। इस कारण चार्टिस्ट नेता बदनाम भी हो गये, और पुलिस की सतर्कता के कारण यह आन्दोलन कुछ ही समय में शिथिल पड़ गया।

यद्यपि चार्टिस्ट आन्दोलन समाप्त हो गया, पर शासन-सुधार की भावना का अन्त नहीं हुआ। चार्टिस्ट आन्दोलन के समय जनता में भारी कार्य हुआ था, चार्टर के सिद्धान्तों का नैतिक प्रचार किया गया था। इसके कारण प्रत्येक राजनीतिक दल में कुछ न कुछ गणसुधारों के पक्षपाती हो गये थे। परिणाम यह हुआ, कि समय-समय पर विविध नए पार्लियामेंट के सम्मुख शासन-सुधार-संबंधी मसविदे उपस्थित करने लगे। इन मसविदों का स्वीकृत हो सकना कोई साधारण बात नहीं थी, क्योंकि पार्लियामेंट के बहु-संख्यक सदस्य अब भी सुधारों के विरोधी थे। पर इसमें सन्देह नहीं, कि इन मसविदों के गणसुधार की मांग निरन्तर अधिक-अधिक प्रबल होती जाती थी, और धीरे-धीरे पार्लियामेंट के प्रायः सभी सदस्य यह स्वीकार करने लगे थे, कि कुछ न कुछ सुधार आवश्यक हैं।

सन् १८६५ में पार्लियामेंट में उदार दल का फिर बहुमत हो गया, और लार्ड रसेल प्रधानमंत्री बने। उनके मन्त्रिमण्डल के सबसे प्रभावशाली सदस्य श्रीयुत ग्लेडस्टन थे। ग्लेडस्टन ने सन् १८३२ के वादके निर्वाचन में पार्लियामेंट में प्रवेश किया था। शुरू में वे उदार दल के अनुयायी थे। पर धीरे-धीरे उनके विचारों में परिवर्तन आने लगा, और वे सुधारों के पक्षपाती हो गये। उन्होंने उदार-दल का परित्याग कर दिया, और वे शीघ्र ही उदार-दल के एक महत्वपूर्ण सदस्य बन गये। श्रीयुत ग्लेडस्टन बहुत उच्चकोटि के वक्ता थे, और उनकी राजनीतिज्ञता का सिक्का सब लोग मानते थे। लार्ड रसेल के प्रधानमंत्री बनने पर ग्लेडस्टन ने सन् १८६६ में शासन-सुधार के लिये एक मसविदा पार्लियामेंट

के सम्मुख पेश किया। इसमें मतदाताओं को पहले की अपेक्षा अधिक विस्तृत करने का प्रयत्न किया गया था। अनुदार दल तो इसके विरोध में था ही, पर उदार दल के भी बहुत से सदस्य इसके विपक्ष में थे। उनकी सम्मति में अभी इस मसविदे के लिये समय नहीं आया था। परिणाम यह हुआ, कि पार्लियामेन्ट में यह स्वीकृत न हो सका, और लार्ड रसल के मन्त्रिमण्डल को त्यागपत्र देना पड़ा।

**१८६७ का सुधार-विधान**—जब अनुदार दल के नेता लार्ड डर्बी प्रधानमंत्री बने। उनके मन्त्रिमण्डल के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य श्रीयुक्त डिजरायली थे। लार्ड डर्बी हाउस आफ लार्ड्स में थे, अतः हाउस आफ कामन्स का नेतृत्व डिजरायली ही करते थे। डिजरायली उच्च कोटि के राजनीतिज्ञ थे। अनुदारदल का मन्त्रिमण्डल होने के कारण जनता का स्वाभाविक रूप से खयाल था, कि यह सरकार सुधारों की विरोधी है, और उसमें गामन-सुधार सम्बन्धी कोई आशा रखना सर्वथा निरर्थक है। इसलिये मारे देश में सुधार के लिये तीव्र आन्दोलन प्रारम्भ हुआ। स्थान-स्थान पर सभाएँ संगठित की गईं। पुरुषमात्र को वोट का अधिकार होना चाहिये, इसके लिये प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने लगे। एक बार फिर मन् १८३२ के दृश्य दृष्टिगोचर होने लगे। मारे इंग्लैण्ड में एक प्रकार की हलचल मी मच गई। लोग सरकार की अवज्ञा तक करने के लिये उद्यत हो गये। लण्डन के हाउड पार्क में तो दगो तक की नीवत आ गई। इस दशा को देखकर डिजरायली जैसे चाणक्ष राजनीतिज्ञ ने यह भलीभाँति अनुभव कर लिया, कि गामन-सुधार की माग बहुत प्रबल है, और उसे स्वीकृत किये बिना काम नहीं चलेगा। मन् १८६७ में, उसने स्वयं गामन-सुधार सम्बन्धी एक मसविदा पार्लियामेन्ट के सम्मुख उपस्थित किया। पार्लियामेन्ट में इसका घोर विरोध हुआ। उदार दल के लोग डिजरायली पर हँसते थे, और कहते थे कि अब वह उन्हीं सुधारों को स्वयं पेश कर रहा है, जिनका वह जन्म भर विरोध करता रहा है। अनुदार दल के बहुत से सदस्य सुधारों के विरोधी थे ही, वे भी डिजरायली के इस मत-परिवर्तन से बहुत क्रुद्ध हुए। पर आखिर डिजरायली का यह शासन-सुधार-सम्बन्धी मसविदा बहुमत से स्वीकृत हो गया।

मन् १८६७ के इस सुधार-विधान से वोट का अधिकार पहले की अपेक्षा बहुत विस्तृत हो गया। मतदाताओं की संख्या पहले की अपेक्षा प्रायः दुगुनी हो गई। इसके अनुसार शहरों में उन सब लोगों को वोट का अधिकार मिल गया, जिनके शहर की सीमा में अपने मकान हो, या जो कम से कम १५० रु० वार्षिक किराये के मकान में रहते हो। देहाती में उन सब लोगों को वोट का अधिकार दिया गया, जिनकी कम से कम ७५ रु० वार्षिक आमदनी की अपनी जायदाद हो, या जो कम से कम १८० रु० वार्षिक लगान देते हो। यद्यपि अब भी वोट के लिये सम्पत्ति की शर्तों को कायम रखा गया था, पर इसमें सन्देह नहीं, कि पहले की अपेक्षा मतदाताओं की संख्या अब पर्याप्त बढ़ गई थी। इस विधान द्वारा इंग्लैण्ड ने लोकतन्त्र शासन की ओर एक बहुत महत्वपूर्ण पग बढ़ाया था। १८६७ के बाद भी शासन-सुधारों की यह प्रक्रिया जारी रही, और धीरे-धीरे इंग्लैण्ड का शासन पूर्णतया लोकतन्त्रवाद के अनुसार हो गया।



इक्कीसवाँ अध्याय

## आस्ट्रिया-हंगरी और रूस की प्रगति

### (१) आस्ट्रिया-हंगरी का सगठन

१८६१ के शासन सुधार—हाप्सबुर्ग राजवश द्वारा शासित प्रदेशों में १८४८ की क्रान्ति की लहर किस प्रकार असफल हुई थी, इस बात पर पहले प्रकाश डाला जा चुका है। हंगरी के देशभक्त कुछ समय के लिये अपना पृथक् स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर अन्त में फिर आस्ट्रिया सरकार के अधीन रहने के लिये बाधित हुए थे। यही दशा बोहेमिया की थी। आस्ट्रिया में दो बार राजा को वीएना छोड़कर भागना पड़ा था। पर आखिरकार पुरानी प्रवृत्तियाँ सफल हुईं, और हाप्सबुर्ग वंश का स्वेच्छाचारी शासन सर्वत्र फिर से स्थापित हो गया। १८५९ में जब इटालियन लोगो ने आस्ट्रिया की अधीनता से मुक्त होने के लिये युद्ध प्रारम्भ किया, और लोम्बार्डी का प्रदेश आस्ट्रियन आधिपत्य से निकल गया, तब सम्राट् फ्रांसिस जोसेफ की आँखें खुलीं। इटली का अनुकरण कर अन्य भी अनेक स्थानों पर विद्रोह हुए, और सम्राट् ने गम्भीरता के साथ सुधार का कार्य प्रारम्भ किया। फ्रांसिस जोसेफ नव-युवक सम्राट् था। वह १८४८ की क्रान्ति के दिनों में राजगद्दी पर आरुढ़ हुआ था। उसके चाचा फर्डिनेन्ड ने क्रान्ति में घबराकर २ दिसम्बर, १८४८ को राजगद्दी छोड़ देने में ही अपना कल्याण समझा था। फ्रांसिस जोसेफ ही वह सम्राट् था, जिसने क्रान्ति की ज्वालाओं को शान्त कर फिर से एकतन्त्र शासन की स्थापना की थी। अब उसने अनुभव किया, कि जनता को सन्तुष्ट रखने के लिये सुधार किये बिना काम नहीं चलेगा। उसने मध्यकाल की बहुत सी बुराइयों को नष्ट कर अनेक सुधार किये, जिससे लोगो की शिकायतें बहुत कुछ दूर हुईं। सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह थी, कि १८६१ में सम्पूर्ण साम्राज्य—आस्ट्रिया, हंगरी और बोहेमिया—के लिये एक शासन-विधान की रचना की गई। सबके शासन को वीएना में केन्द्रित किया गया, और सम्पूर्ण साम्राज्य के लिये व्यवस्थापन का कार्य दो मन्त्रियों के सुपुर्द हुआ, (१) कुलीन सरदारों की सभा—इसमें वंश-जमानुगत कुलीन सरदार लोग सम्मिलित होते थे। इनके अतिरिक्त सम्राट् की तरफ से जिन्हें बड़े ऊँचे खिताब दिये जाते थे, उन राजसम्मानित लोगो में से भी कुछ को सरकार इस सभा का सदस्य मनोनीत करती थी। (२) दूसरी सभा सर्वसाधारण जनता के प्रतिनिधियों की थी। यद्यपि वोट का अधिकार बहुत विस्तृत नहीं था, पर फिर भी मध्य श्रेणी के प्रतिनिधि इस सभा में सम्मिलित हो सकते थे। १८६१ में आस्ट्रियन साम्राज्य का शासन पूर्णतया एकतन्त्र और स्वेच्छाचारी नहीं रहा था, वह एक प्रकार से वैध राजसत्ता बन गया था। इस जश में आस्ट्रिया जर्मनी में पर्याप्त जागे था। यद्यपि लोकतन्त्रवाद का कुछ प्रवेश आस्ट्रिया में हो गया था, पर

उसकी वास्तविक समस्या अभी हल नहीं हुई थी। आस्ट्रियन साम्राज्य में कोई एक जाति निवास नहीं करती थी। आस्ट्रिया के असली जर्मन लोगों के अतिरिक्त उसमें अन्य भी बहुत सी जातियों का निवास था। ये सब अपने को स्वाधीन करने का प्रयत्न कर रही थी। यदि इन जातियों की दृष्टि से देखा जाय, तो १८६१ के मुघारो द्वारा स्थापित वैध राजसत्ता वास्तविक असंतोष को दूर करने में सर्वथा असमर्थ थी।

१८६६ के आन्दोलन—१८६६ में सेडोवा के युद्ध में पराजित हो जाने के अनन्तर आस्ट्रिया जर्मनी में पृथक् हो गया था। जर्मन राज्यसंघ की जटिल समस्याओं से अब उसका कोई सम्बन्ध न रहा। अनेक सदियों में वह जर्मन लोगों का नेतृत्व कर रहा था। पर प्रगिया के अभ्युदय ने उस नेतृत्व का अन्त कर दिया, और आस्ट्रिया के ८० लाख के लगभग जर्मन लोग अपनी जाति के अन्य लोगों में पृथक् हो गये। १८६६ के बाद हाप्सबुर्ग राजवंश का ध्यान पश्चिम की तरफ से हटकर पूर्व की तरफ जाना शुरू हुआ। आस्ट्रिया अब जर्मनी के स्थान पर बाल्कन प्रायद्वीप में अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिये प्रयत्न करने लगा। १८६६ में ही वेनेटिया का भी प्रदेश आस्ट्रिया की अधीनता में निकल गया था। सेडोवा की पराजय और वेनेटिया की स्वतन्त्रता के कारण आस्ट्रिया के विरुद्ध विद्रोह की प्रवृत्तियाँ फिर बलवती हो गईं। विशेषतया हंगेरियन लोगों ने १८६१ के शासन-विधान का घोर विरोध प्रारम्भ कर दिया। वे पहले भी इसके प्रति अपना असन्तोष प्रकट कर रहे थे। इसीलिये वे व्यवस्थापिका सभाओं में सम्मिलित ही न होने थे। हंगेरियन लोग स्वयं तो नवीन शासन में असहयोग कर ही रहे थे, साथ में बोहेमियन, पोल और क्रोटियन आदि लोगों को भी अपना अनुसरण करने के लिये भडका रहे थे। १८६६ में इस आन्दोलन ने बहुत प्रचण्ड रूप धारण कर लिया। हंगेरियन लोग कहते थे, कि हमारा देश मदा में एक पृथक् व स्वतन्त्र राज्य के रूप में रहा है। आस्ट्रिया से हमारा सम्बन्ध केवल इतना था, कि दोनों राज्यों का राजा ही एक था। इसके अतिरिक्त अन्य कोई सम्बन्ध आस्ट्रिया और हंगरी में नहीं था। हंगेरियन लोगों की माँग यही थी, कि १८६१ के शासन-विधान का अन्त कर फिर से उनके पृथक् राज्य की स्थापना की जाए।

समझौता (ऑसग्लाइख)—अन्त में सम्राट् फ्रांसिस जोसेफ हंगेरियन देशभक्तों की माँग को स्वीकृत करने के लिये बाधित हुआ, जिसके कारण १८६७ में आस्ट्रिया और हंगरी में समझौता हो गया, और नवीन शासन-विधान की रचना की गई। इतिहास में १८६७ का यह शासन-विधान 'समझौते' (ऑसग्लाइख) के नाम से प्रसिद्ध है। इस समझौते के अनुसार फ्रांसिस जोसेफ ने स्वीकार किया, कि मैं दो पृथक् व स्वतन्त्र राज्यों का पृथक् रूप से राजा हूँ। ये राज्य निम्नलिखित हैं—

(१) आस्ट्रियन साम्राज्य—जिसमें कुल मिलाकर १७ प्रान्त सम्मिलित थे। असली आस्ट्रिया के अतिरिक्त बोहेमिया, मोरेविया, कैरिन्थिया, कर्निओला आदि प्रदेश इसमें ऐसे भी शामिल थे, जिसमें अनेक जर्मन-भिन्न जातियाँ निवास करती थी।

(२) हंगरी का राज्य—इसमें भी हंगेरियन लोगों के अतिरिक्त क्रोटियन और स्लावोनियन जातियों का निवास था।

आस्ट्रियन साम्राज्य की राजधानी वीएना थी, और हंगरी की बुडापेस्ट। दोनों राज्यों

के शासन-विधान पृथक्-पृथक् थे। दोनों की व्यवस्थापिका सभाएं, और मन्त्रिमण्डल आदि भी सर्वथा पृथक् थे। परन्तु कुछ मामले ऐसे भी थे, जिनका शासन सम्मिलित रूप से होता था। विदेशों के साथ सम्बन्ध, सन्धि-विग्रह, सेना, तटकर आदि उभयनिष्ठ मामलों के लिये दोनों राज्य एक थे। इस सम्मिलित राज्य को आस्ट्रिया-हंगरी कहते थे। आस्ट्रिया-हंगरी की स्थल और जल सेना एक थी, मुद्रा-पद्धति एक थी, और तोल, माप आदि के मान एक थे। तट-कर की पद्धति भी सम्मिलित राज्य की एक ही थी। यह एक अद्भुत किस्म का सघ था। दो राज्य एक दूसरे से सर्वथा पृथक् होते हुए भी कुछ मामलों के लिये एक बने हुए थे।

**सम्मिलित राज्य का शासन**—इन सम्मिलित विषयों का शासन करने के लिये आस्ट्रिया-हंगरी का उभयनिष्ठ राजा तीन मन्त्री नियत करता था—परराष्ट्र सचिव, युद्ध सचिव और अर्थ सचिव। ये तीनों मन्त्री एक अद्भुत प्रकार की सम्मिलित पार्लियामेन्ट के प्रति उत्तरदायी होते थे, जिसे कि “प्रतिनिधिमण्डल” (डैलीगेशन) कहते थे। इस प्रतिनिधिमण्डल का एक भाग आस्ट्रिया की व्यवस्थापिका सभा द्वारा निर्वाचित होता था, और हंगरी की व्यवस्थापिका सभा दूसरे भाग के चुनती थी। प्रतिनिधिमण्डल में कुल मिलाकर १२० सदस्य होते थे। ६० सदस्य आस्ट्रिया चुनता था, और ६० हंगरी। प्रतिनिधिमण्डल का अधिवेशन एक बार वीएना में होता था, और एक बार बुडापेस्ट में। दोनों राजधानियों में वारी-वारी से अधिवेशन होते थे, ताकि दोनों को समान रूप से महत्वपूर्ण समझा जाए। प्रतिनिधिमण्डल के दोनों भागों का अधिवेशन पृथक्-पृथक् होता था। आस्ट्रियन प्रतिनिधि-मण्डल अपना कार्य जर्मन भाषा में करता था, और हंगेरियन प्रतिनिधिमण्डल हंगेरियन भाषा में। जब कभी दोनों भागों में मतभेद हो जाता था, तो उनका सम्मिलित अधिवेशन किया जाता था। पर इस अधिवेशन में वहस नहीं होती थी, केवल वोट ही लिये जाते थे। इस प्रकार आस्ट्रिया और हंगरी अपनी स्थिति को एक बराबर रखते हुए अपने सम्मिलित विषयों का संचालन किया करते थे।

१८६७ के “समझौते” के बाद आस्ट्रिया और हंगरी दोनों राज्यों का शासन पृथक् रूप में होता रहा। इनके शासन-विधानों का विस्तार से उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना निर्देश करना पर्याप्त होगा, कि आस्ट्रिया के व्यवस्थापन विभाग में दो सभाएं थीं। एक सभा में कुलीन जागीरदार लोग सम्मिलित थे, और दूसरी में सर्वमाधायण जनता के प्रतिनिधि। पर वोट का अधिकार बहुत कम लोगों को था। मन्त्रिमण्डल व्यवस्थापन विभाग के प्रति उत्तरदायी था। हंगरी के शासन का ढांचा भी ठीक इसी प्रकार का था। वहां भी वोट का अधिकार बहुत कम लोगों को प्राप्त था। आस्ट्रिया और हंगरी दोनों में उत्तरदायित्वपूर्ण वैध शासन की स्थापना तो हो गई थी, पर वास्तविक जनता को अभी बहुत कम अधिकार प्राप्त थे। वोट का अधिकार जितना अधिक विस्तृत होगा, लोकतन्त्र शासन उतना ही पूर्ण होगा। पर इन राज्यों में यह बात न थी। यही कारण है, कि उदार विचारों के लोग शासन-सुधार के लिये निरन्तर आन्दोलन करते रहे।

**अत्यसह्यक जातियों की समस्या**—परन्तु आस्ट्रिया-हंगरी की वास्तविक समस्या राजतन्त्र शासन स्थापित करने की नहीं थी। इस अद्भुत साम्राज्य में जिन विविध जातियों

का निवास था, उनका जिक्र पहले अनेक बार किया जा चुका है। राष्ट्रीयता की भावना उन सब जातियों में प्रादुर्भूत हो चुकी थी, और वे अपनी राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिये आन्दोलन कर रही थी। हंगरी की सफलता के कारण उनकी हिम्मत बहुत बढ़ गई थी। उनका असन्तोष बार-बार फूटकर प्रकट होता रहता था। उन्हें किस प्रकार सन्तुष्ट किया जाए, आस्ट्रियन सरकार के सम्मुख यह अत्यन्त विकट समस्या हमेशा उपस्थित रहती थी। इसका वास्तविक इलाज एक ही था, वह यह कि इनकी राष्ट्रीय भावनाओं को स्वीकृत कर लिया जाए और हंगरी के समान इन्हे भी पृथक् राज्य के रूप में पंक्तिबद्ध कर दिया जाए। पर हाप्सबुर्ग वंशके सम्राट तथा आस्ट्रिया के जर्मन निवासियों को यह बात कभी समझ में नहीं आई। वे शक्ति के प्रयोग द्वारा इन जातियों को अपनी अधीनता में रखने का प्रयत्न करते रहे। कुछ समय तक उन्हें सफलता भी प्राप्त होती रही, पर आखिर १९१८-१९ के महायुद्ध के समय इन्हीं जातियों ने आस्ट्रिया-हंगरी के साम्राज्य का विनाश कर दिया।

**बोहेमिया में चैक स्वतन्त्रता का आन्दोलन**—आस्ट्रियन साम्राज्य में जो विविध जातियाँ बसती थी, उनमें सबसे अधिक उन्नतिशील बोहेमिया के चैक लोग थे। १८६८ में उन्होंने यह आन्दोलन करना आरम्भ किया, कि हमें भी हंगरी के समान स्वतन्त्रता प्राप्त होनी चाहिये। वे कहते थे, हम भी एक पृथक् राष्ट्र हैं, और आस्ट्रिया के साथ हमारा सम्बन्ध भी केवल इतना ही है, कि आस्ट्रिया का राजा ही हमारा भी राजा है। अतः बोहेमिया को हंगरी के समान ही एक पृथक् राज्य के रूप में स्वीकृत किया जाना चाहिये, और फ्रांसिस जोसेफ का बोहेमिया की राजधानी प्राग में भी पृथक् राज्याभिषेक होना चाहिये। यह आन्दोलन निरन्तर प्रचण्ड रूप धारण करता गया, और आखिर १८७१ में फ्रांसिस जोसेफ ने चैक लोगों के दावे को स्वीकृत कर लिया। परन्तु जर्मन (आस्ट्रियन) और हंगेरियन लोग इस बात को न सह सके। उन्होंने कहा—अन्य जातियाँ भी बोहेमिया का अनुसरण करेगी, और इस सिलसिले का अन्त कहा जाकर होगा? जर्मन और हंगेरियन लोगों को इन विविध स्लाव जातियों से बड़ी तीव्र घृणा थी। वे इन्हें स्वतन्त्र नहीं देखना चाहते थे। इनके तीव्र विरोध के कारण फ्रांसिस जोसेफ अपने वचन को पूर्ण नहीं कर सका। चैक आन्दोलन को क्रूरता से शान्त किया गया। पर इसमें सन्देह नहीं, कि सब प्रकार के अत्याचारों को सहते हुए भी चैक तथा अन्य लोग अपनी राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिये निरन्तर प्रयत्न करते रहे। ये जातियाँ अवश्य ही अपने उद्देश्य में सफल हो जाती, अगर इनमें आपस में विरोध और ईर्ष्या के भाव न होते। शोचनीय बात यह थी कि ये सब भी आपस में एक न हो सकती थी। आस्ट्रियन सरकार इन्हे लडाती रहती थी। १९वीं सदी में राष्ट्रीयता की भावना के इतने प्रबल होते हुए भी हाप्सबुर्ग शासक अपने शासन में जो इतने सफल हुए, उसका कारण राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा और विद्वेष के ये ही भाव थे। अन्यथा वे इन विविध जातियों पर कभी शासन न कर सकते। आस्ट्रियन सरकार ने चैक आदि विविध स्लाव जातियों के स्वाधीनता-आन्दोलन को ही कुचलने का प्रयत्न नहीं किया, उसकी यह भी प्रबल आकांक्षा थी, कि इन जातियों को पूर्णतया जर्मन (आस्ट्रियन) रंग में रँग दे। इसी उद्देश्य से १८६९ में सम्पूर्ण साम्राज्य के शिक्षणालयों में जर्मन भाषा का अध्ययन वाधित रूप से जारी किया गया। अन्य प्रकार से भी कोशिश की गई, कि स्लाव लोग जर्मन सभ्यता

का अनुसरण करने में गौरव अनुभव करे। इन जातियों की धार्मिक भावनाओं को भी उपेक्षा की गई। ये प्रायः कैथोलिक धर्म को माननेवाली थी, पर ऐसे कानून बनाये गये, जिनसे जो अधिकार कैथोलिक लोगों को प्राप्त थे, वे गैर-कैथोलिकों को भी मिल गये। इसी प्रकार हंगरी में भी स्लाव, रूमनियन आदि जातियों को दवाने तथा उनकी सभ्यता को नष्ट करने के लिये प्रयत्न किये गये। प्रत्येक शिक्षणालय में हंगेरियन भाषा को बाधित रूप में प्रचलित किया गया। जिलों और शहरों के पुराने नामों को बदलकर हंगेरियन भाषा के नये नाम रखे गये। हंगेरियन लोगों की सख्या कुल आबादी के आधे से भी कम थी, पर उनकी कोशिश यह थी, कि कोई गैर-हंगेरियन व्यवस्थापिका सभामें निर्वाचित ही न हो सके। इसी प्रयत्न का यह परिणाम था, कि व्यवस्थापिका सभा में हंगेरियन लोगों का हमेशा प्रभुत्व रहता था। वे जो कुछ चाहते थे, कर सकते थे।

**परराष्ट्र नीति**—अब आस्ट्रिया-हंगरी की साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति जर्मनी या इटली के क्षेत्र में चरितार्थ नहीं हो सकती थी। जर्मन राज्यसभ में अब उसके लिये कोई स्थान न था। इटली उसकी अधीनता से मुक्त हो चुका था, और अब यह सम्भव नहीं रहा था कि आस्ट्रिया उसे फिर से अपने अधीन कर सके। अब उसके सम्मुख एक ही मार्ग था। वह बाल्कन प्रायद्वीप में अपनी महत्त्वाकांक्षाओं को पूर्ण कर सकता था। वहाँ उसके विस्तार के लिये उपयुक्त क्षेत्र विद्यमान था। परन्तु उधर रूस भी इसी क्षेत्र में अपने साम्राज्यवाद का जाल फैला रहा था। रूस विविध स्लाव जातियों को अपनी अधीनता और सुरक्षा में संगठित करना चाहता था। इस प्रकार बाल्कन प्रायद्वीप में आस्ट्रिया और रूस के स्वार्थ आपस में टाकरा खाते थे।

## (२) रूस में नवयुग का प्रारम्भ

**आधुनिक युग में रूस का महत्व**—वर्तमान समय में रूस ससार में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। वह सयुक्तराज्य अमेरिका के समान ससार का सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य है, और विश्व के विविध राज्यों का नेतृत्व करने के लिये अमेरिका का प्रबल प्रतिद्वन्दी है। समाजवाद (कम्युनिज्म) के रूप में उसने जिस नई आर्थिक व सामाजिक व्यवस्था का प्रारम्भ किया है, उसके कारण उसका महत्त्व बहुत अधिक बढ़ गया है। रूस न केवल स्वयं एक विशाल देश है, पर रूसी लोग एक ऐसे सुविस्तृत राज्यसभ (यूनियन) का भी नेतृत्व करते हैं, जिसमें रूसी-भिन्न अनेक जातियों का समावेश है। इस रूसी सोवियट यूनियन का पुराना स्वरूप एक साम्राज्य के रूप में था, जिसे अब एक विशाल सभ-रिपब्लिक के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। यह रूसी रिपब्लिक न केवल पूर्वी यूरोप में, अपितु एशिया में भी अपने प्रभाव को विस्तृत करने के लिये प्रयत्नशील है। यही कारण है, कि इस समय ससार के विविध राज्यों में रूस का महत्त्व बहुत अधिक बढ़ गया है। पर उन्नीसवीं सदी के यूरोप के इतिहास में रूस का इतना महत्त्व नहीं था। फ्रांस, जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन इस युग में रूस की उपेक्षा बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण थे। पर हममें सन्देह नहीं, कि रूस की वर्तमान शक्ति और महत्त्व का स्तूपान उन्नीसवीं सदी में ही गुरु हो चुका था, और इसीलिये यह आवश्यक है, कि हम रूस के इतिहास पर

कुछ अधिक विशद रूप से प्रकाश डाले।

**रूस के उत्कर्ष का प्रारम्भ**—अठारहवीं सदी के अन्त में रूस की क्या दशा थी, इसका उल्लेख हम मक्षिप्त रूप में कर चुके हैं। १७६२ में १७९६ ई० तक रूस के राजमहासन्ध पर जारीना कैथराइन द्वितीय विराजमान थी। अपने साम्राज्य का विस्तार करने के उद्देश्य से इसने पोलैण्ड का अगभग करने में विशेष तत्परता दिखाई थी, और पोलैण्ड के प्राचीन राज्य के अच्छे बड़े भाग को अपने अधीन कर लिया था। उन्नीसवीं सदी के शुरू तक रूस यूरोप में अच्छा महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर चुका था, और वहाँ की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में उसका अच्छा स्थान था।

पन्द्रहवीं सदी तक रूस में किसी एक शक्तिशाली राजा का व्यवस्थित शासन नहीं था। सारा देश अनेक छोटे-बड़े राज्यों में विभक्त था, और ये सब रूसी राजा चीन के मंगोल सम्राट की अधीनता स्वीकृत करने थे। पन्द्रहवीं सदी में जब मंगोल साम्राज्य की शक्ति क्षीण होनी शुरू हुई, तो ये रूसी राज्य स्वतन्त्र हो गये। रूस के इन विविध राज्यों में मास्को का राज्य सबसे अधिक शक्तिशाली था। १५४७ ई० में मास्को के राजा इवान (जो इतिहास में भयंकर इवान के नाम से प्रसिद्ध है) ने जार या सम्राट की उपाधि धारण की, और अन्य रूसी राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकृत करने के लिये विवश किया। पर सोलहवीं सदी के ये जार सभ्यता और मस्कूनि की दृष्टि में यूरोपीय लोगों की अपेक्षा चीन के अधिक समीप थे। सदियों तक चीन के मंगोल सम्राटों की अधीनता में रहने के कारण इन पर चीन का बहुत प्रभाव था। इनका दरबार चीन के ढंग पर सज्जित था, और रूसी सम्राट व उसके दरबारी सिर पर पगड़ी बांधकर दरबार में उपस्थित हुआ करते थे।

**पीटर द ग्रेट**—१६७२ ई० में मास्को की राजगद्दी पर पीटर द ग्रेट आरुढ़ हुआ। इस समय तक पश्चिमी यूरोप के देश उन्नति की दौड़ में शीघ्रता के साथ आगे बढ़ने लग गये थे। यूरोप में व्यापारिक क्रान्तिका सूत्रपात हो चुका था, और अमेरिका के विशाल महाद्वीप का भी यूरोपियन लोग पता कर चुके थे। अफ्रीका का चक्कर काटकर उन्होंने एशिया के विविध देशों में भी व्यापार के लिये आना-जाना शुरू कर दिया था। अमेरिका में यूरोपियन लोगों के उपनिवेश भी बसने शुरू हो गये थे। एशिया और अमेरिका के व्यापार के कारण स्पेन, फ्रांस, इङ्ग्लैण्ड आदि देश बहुत अधिक सम्पन्न और समृद्ध हो रहे थे। पीटर ने अनुभव किया, कि रूस उन्नति की दौड़ में यूरोप के अन्य राज्यों के मुकाबले में बहुत पीछे रह गया है। १६९७ में उसने स्वयं जर्मनी, हालैण्ड और इङ्ग्लैण्ड की यात्रा की। पीटर बहुत ही चाणाक्ष व्यक्ति था। उसने पश्चिमी यूरोप के इन देशों की व्यावसायिक और व्यापारिक उन्नति का भलीभाँति अध्ययन किया, और यह निश्चय किया कि रूस की उन्नति के लिये वह भी कोई कसर नहीं उठा रखेगा। अपने देश को वापस जाते हुए वह जर्मनी से बहुत से शिल्पियों और वैज्ञानिकों को भी अपने साथ ले गया, और वहाँ जाकर उसने उन सुधारों का प्रारम्भ किया, जो रूस की उन्नति में बहुत अधिक सहायक हुए। उसने बहुत से रूसी विद्यार्थियों को इस उद्देश्य से हालैण्ड, इङ्ग्लैण्ड आदि भेजा, ताकि वे वहाँ जाकर शिल्प सीखें। विदेशियों को रूस में बसने के लिये भी उसने प्रोत्साहित किया। वह रूसी

दरबार के मगोलियन रंग ढग को जरा भी पसन्द नहीं करता था। इसलिये उसने स्वयं पश्चिमी यूरोप के कुलीन व राजघराने के लोगोके समान रहना शुरू किया, और अपने अमीर उमराओ को भी इसी ढग से रहने के लिये प्रेरित किया। सत्रहवीं सदी में रूस की जलशक्ति न के बराबर थी। पीटर द ग्रेट अनुभव करता था, कि नाविक शक्ति के बिना रूस के लिये उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो सकना सम्भव नहीं होगा। अतः उसने यत्न किया, कि जहाँ रूस रहन-सहन, शिल्प और ज्ञान के क्षेत्र में पश्चिमी यूरोप के देशों का समकक्ष हो, वहाँ वह नाविक शक्ति में भी उन्नति करे। इन उद्देश्यों को सम्मुख रखकर उसने अपने राज्य में अनेक सुधार किये। उसने अपनी प्रजा को प्रेरित किया, कि वे पगड़ी बाबना और लटकते हुए चोगे पहनना छोड़कर यूरोपियन पोशाक को अपनावे, मित्रया जनानखाने में रहने के बजाय ममाज में पुरुषों के साथ कन्वे से कन्वा मिठाकर चले, और रूसी लोग नये युग के ज्ञान विज्ञान को अपनावे। उसने अपने शासन का पुनः संगठन किया और सेना को नये ढग की शिक्षा प्रदान की। रूस की जलशक्ति के विकास के लिये पीटर ने बाल्टिक सागर के तट पर एक नये नगर की स्थापना की, जिसका नाम सेण्ट पीटर्सबुर्ग रखा गया। पीटर का प्रयत्न था, कि यह एक प्रथम श्रेणी का बन्दरगाह बने, और रूस की जलशक्ति इस नगर में केन्द्रित रहे।

पीटर जिस ढग से रूस की शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न कर रहा था, उसका यह परिणाम हुआ, कि स्वीडन उसके खिलाफ उठ खड़ा हुआ। उन दिनों स्वीडन की राजगद्दी पर चार्ल्स अष्टम विराजमान था, जो बड़ा प्रतापी और महत्वाकांक्षी राजा था। अपने पड़ोसी राज्यों से उसके अनेक युद्ध हुए। शुरू में वह सर्वत्र विजयी रहा। डेनमार्क और पोलैण्ड को उसने परास्त किया। पर पीटर द ग्रेट के साथ युद्ध में उसे सफलता नहीं हुई। १७०९ ई० में रूसी सेनाओं द्वारा वह बुरी तरह से परास्त हुआ, और टर्की के सुलतान के यहाँ आश्रय लेने के लिये विवश हुआ। चार्ल्स अष्टम का प्रयत्न था, कि तुर्क सुलतान को अपने साथ मिलाकर पीटर का मुकाबला करे। पर अपने उद्देश्य में वह सफल नहीं हो सका, और रूस के साथ सघर्ष करते-करते १७१८ में एक युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई। चार्ल्स की मृत्यु के बाद स्वीडन और रूस में सन्धि हो गई, और इस सन्धि के परिणामस्वरूप बाल्टिक सागर के पूर्वी तट पर स्थित लिबोनिया, एस्थोनिया आदि अनेक प्रदेश (जो पहले स्वीडन के अधीन थे) रूस को प्राप्त हुए। इन प्रदेशों के प्राप्त हो जाने से रूस की पश्चिमी सीमा नमूदतक तक पहुँच गई, और उसे अपनी जलशक्ति के विकास का अपूर्व अवसर प्राप्त हो गया। पर पीटर इतने से ही सतुष्ट नहीं हुआ। उसने कालामागर (वर्ग्रेन मी) और कैस्पियन सागर की दिशा में भी रूस के साम्राज्य को विस्तृत करने का प्रयत्न किया। १७२५ ई० तक पीटर ने रूस का शासन किया, और इसमें सन्देह नहीं, कि उसके सुदीर्घ शासनकाल (१६७२-१७२५) में रूस यूरोप के अच्छे उन्नत और शक्तिशाली राज्यों में गिना जाने लगा।

**पीटर के उत्तराधिकारी—**१७२५ ई० में पीटर द ग्रेट की मृत्यु के बाद रूस के जो राजा हुए, वे प्रतापी व महत्वाकांक्षी नहीं थे। पर १७६२ में उनकी राजगद्दी पर फिर एक सुयोग्य साम्राज्ञी आरुढ़ हुई, जिसका नाम जारिना कैथरिन् द्वितीय था।

कैथराइन ने पीटर द ग्रेट के कार्य को अधिक पूर्णता के साथ सम्पन्न किया, और उसके शासनकाल में रूस ने बहुत उन्नति की। १७९५ ई० में जब फ्रांस में राज्यक्रान्ति बड़ी तेजी के साथ प्रगति कर रही थी, कैथराइन द्वितीय की मृत्यु हुई, और उसका लड़का पाल रूस का सम्राट् बना। फ्रेंच क्रान्तिकारियों के विरुद्ध युद्ध करने के लिये जोगुट दस समय बन रहे थे, पाल भी उनमें शामिल हुआ। इसी पाल का उत्तराधिकारी अलेक्जेंडर प्रथम (१८०१-१८२५) था, जिसने कि नैपोलियन के साथ घनघोर संघर्ष किया था, और जिसके नेतृत्व में वीणना की कांग्रेस के बाद पवित्र मित्र-मण्डल का निर्माण हुआ था। उन्नीसवीं सदी में रूस के जिन एकतन्त्र स्वेच्छाचारी पर शक्तिशाली सम्राटों ने यूरोप की राजनीति में महत्वपूर्ण भाग लिया, उनके सम्मन्ध में अब हम कुछ अधिक विस्तार के साथ परिचय देने का प्रयत्न करेंगे।

### ३. रूस में एकतन्त्र स्वेच्छाचारी सम्राटों का शासन

अलेक्जेंडर प्रथम (१८०१-१८२५)—नैपोलियन के पतन में रूस के चार अलेक्जेंडर प्रथम का बड़ा हाथ था। वीणना की कांग्रेस में यूरोप के जो महान् राजनीतिज्ञ इकट्ठे हुए थे, अलेक्जेंडर उनमें बहुत ऊँचा स्थान रखता था, और 'पवित्र मित्रमण्डल' का विचार उसी के दिमाग से उत्पन्न हुआ था। इसमें सन्देह नहीं, कि शुरू में अलेक्जेंडर उदार विचारों का पक्षपाती था। उसकी शिक्षा ला हार्प नामक उदार मंत्रिमन्त्रिणा की संरक्षा में हुई थी, और फ्रांस की राज्यक्रान्ति ने उस पर बहुत प्रभाव डाला था। शुरू में नैपोलियन का वह बड़ा आदर करता था। यदि अलेक्जेंडर अपने विचारों को क्रिया में परिणत कर सकता, तो रूस अब से बहुत पहले एक उन्नत देश बन जाता। पर अलेक्जेंडर में एक बड़ी कमजोरी थी। उसकी प्रकृति स्थिर नहीं थी। धीरे-धीरे उस पर मेटर्निख के जादू ने असर करना शुरू किया, और वह अपने उदार विचारों को सर्वथा भूल कर स्वेच्छाचारी शासन का बड़ा भारी पक्षपाती बन गया। सन् १८२० में अलेक्जेंडर की फौज में एक मामूली सा विद्रोह हुआ। इससे वह इतना परेशान हुआ, कि उदार विचारों का प्रचण्ड विरोधी बन गया। उसका यह दृढ़ विश्वास हो गया, कि स्वतन्त्रता और उदार विचार धर्म, व्यवस्था और समाज के घोर शत्रु हैं, और मसार में शान्ति कायम रखने का एक मात्र उपाय यही है, कि स्वतन्त्रता के भावों को कुचलने के लिये कोई भी कसर बाकी न रखी जावे। इसके बाद से अलेक्जेंडर क्रान्ति की भावनाओं को कुचलने में मेटर्निख का प्रधान सहायक हो गया।

रूस की समस्याएँ—अलेक्जेंडर के विशाल रूसी साम्राज्य में किसी एक जाति का निवास नहीं था। उसमें विविध भाषाओं को बोलनेवाले अनेक जातियों के लोग बसते थे। रूसी लोगों के अतिरिक्त उसमें मुख्यतया फिन, जर्मन, पोल, यहूदी, तातार, आर्मीनियन, ज्यार्जियन और मगोलियन जातियाँ निवास करती थीं। इस प्रकार रूस में भी दो मुख्य समस्याएँ थीं। एक राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की और दूसरी लोकतन्त्र शासन स्थापित करने की। फिन, जर्मन, पोल आदि जातियों में राष्ट्रीय भावना उत्पन्न हो रही थी, और वे इस बात को अनुभव करने लगी थी, कि रूसी लोग विदेशी हैं, और हमें विदेशियों के



शासन में नहीं रहना चाहिये। विशाल रूसी साम्राज्य में रूसी भाषा ही सर्वत्र प्रयुक्त होती थी। शिक्षणालयों में सब जगह रूसी भाषा पढ़ाई जाती थी। इस बात को अन्य जातियों के लोग सहन नहीं कर सकते थे। फ्रांस की राज्यक्रान्ति द्वारा राष्ट्रीय भावना की जो लहर शुरू हुई थी, वह रूसी साम्राज्य में बसने वाली इन विविध जातियों पर भी प्रभाव डाल रही थी, और ये भी अपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिये हाथ पैर पटकने लगी थी। दूसरी समस्या लोकतन्त्र शासन स्थापित करने की थी। रूस का शासन पूर्णतया एकतन्त्र और स्वेच्छाचारी था। राजा (जार) जो चाहता था, करता था। वह जिसे चाहता, मन्त्री व राजकर्मचारी बनाता, जिसे चाहता उसके पद से बर्खास्त कर देता। कोई लोक-सभा या प्रतिनिधि सभा उस समय रूस में नहीं थी। रूस के बहुत से देशभक्त इस दुर्दशा का अनुभव कर रहे थे, और अपने देश में भी लोकतन्त्र शासन स्थापित कर जनता को स्वतन्त्र कराने का स्वप्न ले रहे थे। जार ने इन नये उदार विचारों को कुचलने के लिये शक्ति भर कोशिश की। अखबारों पर कड़ी निगाह रखी गई। यूनिवर्सिटियों में नवीन विज्ञानों का पढ़ना रोक दिया गया। जो प्रोफेसर उदार व स्वतन्त्र विचारों के पक्षपाती थे, उन्हें निकाल दिया गया।

**गुप्त समितियों का प्रारम्भ**—पर इन सब उपायों के प्रयुक्त करने पर भी रूस के साम्राज्य में उदार विचारों का प्रवेश रुका नहीं। धीरे-धीरे रूस के अनेक स्थानों पर गुप्त समितियों का संगठन शुरू हुआ। जब रूसी देशभक्तों के लिये खुले तौर पर कार्य कर सकना सम्भव न रहा, तो उन्होंने गुप्त उपायों का आश्रय लिया और वे पड़्यन्त्र तैयार करने में लग गये।

**प्रथम विद्रोह**—एक दिसम्बर, सन् १८२५ को अलेक्जेंडर प्रथम (१८०१-१८२५) की मृत्यु हुई। क्रान्तिकारी गुप्त समितियों ने इस अवसर का पूर्णतया उपयोग किया। अलेक्जेंडर के मरते ही उन्होंने विद्रोह का झण्डा खड़ा कर दिया। अनेक स्थानों पर जनता ने विद्रोह किया। पर क्रान्तिकारियों की शक्ति अभी बहुत न्यून थी। उन्हें कुचलने में जरा भी समय न लगा। अनेक क्रान्तिकारी नेताओं को प्राण दण्ड मिला, और जनता में आतंक जमाने के लिये अनेकविध उपायों को प्रयोग में लाया गया।

**निकोलस प्रथम (१८२५-१८५५) और उसकी नीति**—अलेक्जेंडर के बाद उसका लड़का निकोलस प्रथम रूसी साम्राज्य का जार (सम्राट्) बना। राजगद्दी पर बैठते ही जो विद्रोह हुआ था, उसके कारण निकोलस प्रथम की नीति बहुत कठोर तथा क्रूर हो गई थी। उसका यह दृढ़ विश्वास हो गया था, कि पश्चिमी यूरोप की स्वतन्त्रतायुक्त वायु का प्रवेश रूस में किसी भी भाँति नहीं होना चाहिये। इसके लिये उसने बड़े कठोर उपायों का आश्रय लिया। उसने आज्ञा दी, कि कोई भी यात्री बाहर से रूस में प्रवेश न कर सके। इसी तरह कोई भी रूसी नागरिक अनुमति के बिना देश से बाहर यात्रा, व्यापार, अध्ययन या अन्य किसी कार्य के लिये न जा सके। जो पुस्तकें बाहर से रूस में जानी थीं, उनके निरीक्षण का पूरा प्रबन्ध किया गया। जिनमें नवीन विचारों या विज्ञानों का आभास भी पाया जाता था, उन्हें रूस में प्रविष्ट न होने दिया जाता था। बहुत से गुप्तचर यूनियनिस्टों, अखबार, प्रेस, थियेटर आदि का निरीक्षण करने के लिये विशेष रूप में नियत

किये गये, ताकि उनमें कही नवीन विचार प्रविष्ट न हो जाए। गुप्तचरो को इस बात का पूरा अधिकार दे दिया गया, कि वे जिस व्यक्ति को चाहे गिरफ्तार कर सकें।

**पोल विद्रोह (१८३०-३१)**—निकोलस प्रथम ने अपने विशाल साम्राज्य में क्रान्ति की प्रवृत्तियों को कुचलने के लिये जो कुछ भी सम्भव था, किया। पर उसे पूर्णतया सफलता नहीं हुई। मन् १८३० में जब फ्रांस में क्रान्ति की लहर एक बार फिर प्रारम्भ हुई, तो उसका जमर रूस पर भी पड़ा। पोल लोगों ने वारसा में विद्रोह कर दिया। रूसी कर्मचारी निकालकर बाहर कर दिये गये। वारसा पर क्रान्तिकारियों का कब्जा हो गया। सामयिक सरकार की स्थापना कर ली गई, और पोल लोगों ने २५ जनवरी, १८३१ को अपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता को उद्घोषित कर दिया। पर पोलैण्ड अपनी स्वाधीनता को देर तक कायम नहीं रख सका। शीघ्र ही रूसी सेनाओं ने उस पर आक्रमण कर दिया। पोल लोग शक्तिशाली रूसी सेना का मुकाबला नहीं कर सके। वे परास्त हो गये। पोल लोगों पर भयंकर अत्याचार किये गये। ४५ हजार पोल परिवारों को अपने देश में बहिष्कृत कर कोकेशस के पहाड़ों पर केवल इमलिये भेज दिया गया, ताकि पोल लोगों में अपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का स्वप्न ही नष्ट हो जाए। नवीन भावनाओं ने जो दूसरा प्रयत्न रूस के विशाल साम्राज्य में हुआ, वह भी निकोलस के हाथों द्वारा बुरी तरह कुचल दिया गया।

**रूसी चर्च**—जार के एकतन्त्र स्वेच्छाचारी शासन में रूस का चर्च उसका प्रधान महा-यक था। रूसी साम्राज्य में ईसाई धर्म का प्रचार कोन्स्टेन्टिनोपल के पादरियों द्वारा हुआ था। मध्यकाल में ईसाई धर्म के दो मुख्य संगठन थे। एक रोमन कैथोलिक चर्च, जिसका केन्द्र रोम में था, दूसरा ग्रीक कैथोलिक चर्च, जिसका केन्द्र कोन्स्टेन्टिनोपल था। क्योंकि रूस में ईसाइयत का प्रचार कोन्स्टेन्टिनोपल के पादरियों द्वारा हुआ था, अतः यह स्वाभाविक था, कि वह ग्रीक कैथोलिक चर्च के संगठन के अन्तर्गत रहे। कई सदियों तक यह अवस्था कायम रही, और रूस के ईसाई कोन्स्टेन्टिनोपल के पेट्रिआर्क को अपना धार्मिक नेता मानते रहे। जिस प्रकार रोमन कैथोलिक चर्च के मुखिया को पोप कहते थे, उसी तरह ग्रीक कैथोलिक चर्च के मुखिया को पेट्रिआर्क कहा जाता था। पन्द्रहवीं सदी में कोन्स्टेन्टिनोपल को तुर्क आक्रान्ताओं ने जीत लिया। तुर्क लोग मुसलमान थे। उस समय से ग्रीक कैथोलिक चर्च का केन्द्र कोन्स्टेन्टिनोपल नहीं रह सका। रूस के सम्राटों को खयाल आया, कि ग्रीक कैथोलिक चर्च में जो स्थान पहले कोन्स्टेन्टिनोपल के पेट्रिआर्क का था, वह अब हमारा होना चाहिये। उस समय से रूस के जार ही वहाँ के चर्च के भी अधिपति हो गये। चर्च राज्य का ही एक अंग बन गया। इस समय जब सम्पूर्ण यूरोप में स्वतन्त्रता की लहर चल रही थी, और लोग धार्मिक मामलों में भी अपने विचारों को स्वाधीन रखना चाहते थे, यह सर्वथा स्वाभाविक था, कि रूसी लोगों में भी धार्मिक स्वतन्त्रता के भाव उत्पन्न हो, और वे अपने को सरकारी चर्च की अधीनता से मुक्त करने का प्रयत्न करें। जार इस प्रवृत्ति को बड़ी चिन्ता की निगाह से देखता था। उसका विश्वास था, कि रूस में एकता स्थापित रखने के लिये आवश्यक है, कि रूसी चर्च के प्रभुत्व को कायम रखा जाय और उसके सब मन्तव्यों को अधुण्य रखा जाय। इसलिये निकोलस प्रथम ने रोमन कैथोलिक, प्रोटेस्टेन्ट,

यहूदी आदि विधर्मियों पर कठोर अत्याचार किये। जो जादूमी रूमी चर्च को छोड़ता था, उसे दण्ड दिया जाता था, और अनेक प्रकार से इस बात का प्रयत्न किया जाता था, कि मर-हारी चर्च का प्राधान्य अधुण रूप में बना रहे और उनके विरुद्ध कोई विद्रोह न हो।

**क्रीमियन युद्ध**—निकोलस प्रथम ने जहाँ अपने साम्राज्य में नवीन भावनाओं को कुचलने का पूरा प्रयत्न किया, वहाँ अपनी शक्ति को बढ़ाने की तरफ भी पूरा ध्यान दिया। वह प्रबल साम्राज्यवादी था। उसने बालकन प्रायद्वीप की ईर्ष्या जनता का पक्ष लेकर तुर्की साम्राज्य के मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू किया। उसकी नीति को ग्रेट ब्रिटेन न सह सका। परिणाम यह हुआ, कि दोनों राज्यों में युद्ध शुरू हो गया, जो इतिहास में क्रीमियन युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। इस युद्ध पर हम अगले अध्याय में प्रकाश डालेंगे।

अभी क्रीमियन युद्ध समाप्त नहीं हुआ था, कि सन् १८५५ में निकोलस प्रथम की मृत्यु हो गई।

## ४ रुस में सुधारों का प्रारम्भ

**अलेक्जेंडर द्वितीय**—निकोलस प्रथम के बाद अलेक्जेंडर द्वितीय रुस का सम्राट बना। उसका शासनकाल १८५५ से १८८१ तक था। जब वह राजगद्दी पर बैठा, तो क्रीमियन युद्ध जारी था, और उसमें रुस की निरन्तर पराजय हो रही थी। लोग इस बात को बड़ी तीव्रता से अनुभव कर रहे थे, कि जारशाही का एकतन्त्र और स्वेच्छाचारी शासन बिना विकृत और दोषपूर्ण है। सुधारों की आवश्यकता सर्वत्र अनुभव की जा रही थी। जार अलेक्जेंडर द्वितीय भी अपने साम्राज्य की असली हालत में अपरिचित न था। वह बहुत समझदार तथा चाणाक्ष व्यक्ति था। उसने इस बात को भली भाँति समझ लिया, कि सुधारों के बिना रुस का उद्धार सम्भव नहीं है। उसने अपनी सहायता के लिये जो मन्त्री नियत किये, वे भी बुद्धिमान् और समय के अनुसार कार्य करनेवाले थे। यही कारण है, कि अलेक्जेंडर द्वितीय के शासनकाल में रुस में बहुत से महत्वपूर्ण सुधार हुए, जिनके कारण देश की दशा में बहुत परिवर्तन आ गया।

**दासप्रथा का अन्त**—रूमी साम्राज्य में सर्वसाधारण जनता की दशा बहुत शोचनीय थी। यूरोप के अन्य देशों में इस समय तक दासप्रथा या भूमिदास प्रथा (सर्कंटम) का अन्त हो चुका था। पर रुस के आधे के लगभग निवासी उन्नीसवीं सदी में भी इन प्रथाओं के शिकार थे। एक लेखक ने हिसाब लगाया है, कि सन् १८६० में रुस में भूमि-दाना की मर्यादा चार करोड़ मत्तर् लाब थी। रुस की सम्पूर्ण भूमि जार या अन्य कुलीन जागीरदारों की मन्विद्यत थी। इन जमीनों पर खेती का काम स्वतन्त्र किसान लोग नहीं करते थे। स्वतन्त्र किसान उस समय रुस में थे ही नहीं। जमींदारों की जागीरों दो भागों में बँटी होती थी, एक जिसकी पैदावार पर जमींदार का हक होता था जार दूसरी तिन्नीरी पैदावार में किसान (जो स्वतन्त्र न होकर भूमिदास के रूप में रहता था) अपना गुजारा करता था। जमींदार के हिस्सेवाली जमीन को किसान लोग बिलकुल मुक्त में चोतने चोते थे। नज़ाह में तीन दिन उन्हें अपने जमींदार की जमीन की खेती पर लगाने पड़ते थे। इन प्रथा के बदले में उन्हें कुछ भी उजरत नहीं दी जाती थी। किसान लोग अपने नाशिक की

जमीन को छोड़कर कहीं अन्यत्र नहीं जा सकते थे। रूस के किसानों की दशा दासों में कुछ ही अच्छी थी। वे अभी अर्धदास के रूप में विद्यमान थे।

रूस के किसान अपनी इस दुर्दशा को सहन नहीं कर सकते थे। अनेक बार उन्होंने विद्रोह किये, जिन्हें बड़ी क्रूरता के साथ कुचला गया। पर अत्याचारों से किसान-विद्रोह घटने के स्थान पर निरन्तर बढ़ते ही जा रहे थे। अलेक्जेंडर द्वितीय के समय में किसानों की समस्या इतना विकट रूप धारण कर चुकी थी, कि उसे वाधित होकर उनकी ओर ध्यान देना पड़ा था। इसी समय अमेरिका में दाम प्रथा का अन्त करने के लिये गोर आन्दोलन चल रहा था। १८६१ में दाम प्रथा के प्रश्न पर ही बड़ा गृह-युद्ध का प्रारम्भ हुआ, जिसके द्वारा अब्राहम लिन्कन ने इस घृणित प्रथा की समाप्ति की। रूस में अलेक्जेंडर द्वितीय ने वही कार्य किया, जो अब्राहम लिन्कन ने अमेरिका में किया था। तीन मार्च, १८६१ के दिन उसने एक उद्घोषणा प्रकाशित की, जिसके द्वारा किसानों को दामना से मुक्त कर दिया गया। इस उद्घोषणा द्वारा यह व्यवस्था की गई, कि जमींदारों की जमीनों का एक हिस्सा तो उनकी ही मलिकियत रहे, पर दूसरा हिस्सा उनकी मलिकियत में न रहकर किसानों के पास चला जाए। इसके लिये जमींदारों को कीमत देने करने की व्यवस्था की गई, क्योंकि जार जमींदारों को नागज नहीं करना चाहता था। उस समय तो जर्मनी की कीमत सरकार की ओर से अदा कर दी गई, पर यह व्यवस्था की गई, कि इन कीमत को वार्षिक किस्तों में किसानों में वसूल किया जाए। किसानों को अपनी जमीनों की मार-गुजारी तो देनी ही थी, अब उसके साथ में जमीन की कीमत की वार्षिक किस्त और देनी पड़ी। इससे उन पर टैक्स का बोझ बहुत बढ़ गया। उन्हें अपनी स्वतन्त्रता की कीमत स्वयं अदा करनी पड़ी। स्वतन्त्रता की यह कीमत किसानों के लिये बहुत महँगी पड़ी। वे टैक्सों के बोझ से बहुत बुरी तरह दब गये।

**निहिलिज्म**—इस समय रूस की सर्वसाधारण जनता में बहुत से आन्दोलन चल रहे थे। यद्यपि जारशाही के कर्मचारी नये विचारों को रोकने के लिये जी जान में कोशिश में लगे थे, पर नवीन विचार हवा की तरह होते हैं जिन्हें रोक सकना बहुत कठिन होता है। फ्रांस में राज्यक्रान्ति से पहले जिस तरह अनेक सुधारक और विचारक जनता के विचारों में परिवर्तन ला रहे थे, उसी प्रकार अब रूस में भी अनेक लोग नये विचारों को फैलाने में तत्पर थे। रूस में इन नवीन विचारकों को निहिलिस्ट कहते थे। निहिलिस्ट लोग रूस में जहाँ कहीं भी अन्याय, अत्याचार और कुगतिथि को देखते थे, वही उसके खिलाफ आवाज उठाते थे। राज्य का स्वेच्छाचारी शासन, चर्च का धर्मान्वित स्वरूप और पुरानी प्रथाओं की अनुचित दासता उन्हें समान रूप से असह्य थी। वे रूस में नवयुग लाना चाहते थे। वे मनुष्यों को कहते थे, अपनी अकल से काम लो, और समाज की रचना बुद्धिपूर्वक सोच समझ कर करो।

शुरू-शुरू में निहिलिस्ट आन्दोलन बिल्कुल शान्तिमय था। पर जारशाही के कर्मचारी इस क्रान्तिकारी आन्दोलन को सहन नहीं कर सकते थे। उन्होंने निहिलिस्ट नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू किया। शीघ्र ही रूस की जेल निहिलिस्ट लोगों से भर गई। बहुत से लोगों को साइबेरिया भी भेज दिया गया। जार और उसके कर्मचारी किसी भी

प्रकार के नवीन विचारों को सहन नहीं कर सकते थे। रूसी सरकार के इन अत्याचारों का यह परिणाम हुआ, कि शान्तिमय आन्दोलन सफल न हो सका। निराशा होकर लोगों ने गुप्त उपायों का प्रयोग करना शुरू किया। रूस के बहुत से नवयुवकों को अब यह विश्वास हो गया था, कि सरकारी आतंक का मुकाबला आतंक द्वारा ही करना चाहिये। जनता में सुधार और लोकतन्त्र शासन के लिये कितनी उत्कट आकांक्षा विद्यमान है, इसे प्रदर्शित करने का एक ही उपाय लोगों के पास रह गया था, और वह यह कि वे खूनसरावी, हिंसा और शारीरिक शक्ति का प्रयोग करें, और इस तरह सरकार तथा सत्तार का ध्यान अपनी ओर खींचें। रूस के सैकड़ों नवयुवक आतंकवाद और खूनसरावी की ओर इस समय जो इतनी तेजी से खिंचने लगे, उसका कारण यह नहीं था, कि उन्हें खून बहाने का शौक था या उन्हें मनुष्य जाति से घृणा थी। इसका एकमात्र कारण यह था, कि उनकी सम्मति में अपनी मातृभूमि को बन्धनों और अत्याचारों से मुक्त करने का अन्य कोई उपाय नहीं था। अपने देश की उन्नति के लिये वे बड़ी से बड़ी कुरबानी कर रहे थे।

उधर सरकार क्रान्तिकारी लोगों पर भयंकर अत्याचार कर रही थी, इधर क्रान्तिकारी भी चुप नहीं बैठे थे। जार को मारने के लिये अनेक प्रयत्न किये गये। जार की स्पेसल ट्रेन को उड़ाने की कोशिश की गई। सेण्ट पीटर्सबुर्ग के जिस प्रासाद में जार रहता था उसे एक क्रान्तिकारी ने बास्तू से उड़ा दिया। यह क्रान्तिकारी तरखान के रूप में राजप्रासाद में नौकरी करता था, और मौका पाकर उसने यह भयंकर काण्ड किया था। पर जार को कतल करने के ये सब प्रयत्न व्यर्थ गये। क्रान्तिकारियों का सगठन बड़ा दब था। हथियार तैयार करने के उनके अपने कारखाने थे। वे अपने गृहकु गुप्तचर रखते थे। क्रान्तिकारी दल के प्रत्येक सदस्य को अपने नेताओं की आज्ञा का आखिरी मोर्चा पालन करना आवश्यक था। अपने दृढ़ सगठन के कारण उन्हें अनेक स्थानों पर सफलता भी हुई। कुछ ही समय में जार के छ उच्च पदाधिकारी और तो सरकारी गुप्तचर क्रान्तिकारियों द्वारा कतल कर दिये गये। इन कतलों के कारण रूस में बड़ी हलचल मची। अखिर, जार का विचार होकर यह स्वीकृत करना पड़ा, कि शासन व्यवस्था में सुधार किये बिना कार्य चरमकना असम्भव है। एक नवीन शासन-विधान तैयार किया गया, जिसमें जनता का अनेक महत्वपूर्ण अधिकार दिये गये। जार ने अभी इस नये शासन-विधान पर हस्ताक्षर किये ही थे, कि १३ मार्च, १८८१ के दिन क्रान्तिकारियों ने उसे भी कतल कर दिया।

**जेलजेण्डर तृतीय**—जेलजेण्डर द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका लड़का जेलजेण्डर तृतीय रूस का जार बना। उसका शासन काल १८८१ में १८९४ तक था। जेलजेण्डर द्वितीय के कतल में वे सुधार, जिन पर उसने अपने कतल के कुछ घण्टे पहले ही हस्ताक्षर किये थे, ऐसे ही रखे रह गये। उन्हें क्रिया में परिणत नहीं किया गया। जेलजेण्डर तृतीय के शासन में भी क्रान्तिकारियों को कुचलने के लिये भरपूर कोशिश की गई। जनता पर बंदोबस्त में कठोर अत्याचार किये गये। इस बाल में रूस की जेले मंद राजनीति बढियो ने पूर्ण रहती थी। सैकड़ों हजारों क्रान्तिकारियों को साइबेरिया भेज दिया गया था। लोगों पर कोटे भी इस समय खुले तौर पर निर्दयता के साथ लगाये जाते थे। जेलजेण्डर तृतीय भी निकोलस प्रथम का अनुयायी था। उसका मन्तव्य था, कि स्वतन्त्रता

और नई भावनाओं का एक ही परिणाम हो सकता है, और वह यह कि राष्ट्र का विनाश हो जाए।

उन्नीसवीं सदी में रूस के राजा और प्रजा में यह भयंकर भ्रमण निरन्तर जारी रहा। यदि रूस के शासक जनता के साथ कुछ भी सहानुभूति का वर्तन करने और लोगों की मांगों को निर्दयतापूर्वक न कुचलने, तो क्रान्तिकारी आतंकवादी दल बड़ा उतना प्रबल कभी न होने पाता। रूस के नवयुवकों के सम्मुख अपनी शिकायतों को पेश करने का जब अन्य कोई उपाय न रहा, तो उन्होंने विषय होकर इन उपायों का अवलम्बन किया। उन्होंने अपनी स्वतन्त्रता के लिये जो कष्ट उठाये, वे इतिहास में बन्नुत अद्वितीय हैं।

**साहित्यिक जागृति**—इस काल में रूस में बहुत से ऐसे साहित्यमेवी और लेखक उत्पन्न हुए, जिन्होंने देश में नवीन भावनाओं का प्रसार करने में बड़ी सहायता की। तुर्गनेव, पुशकिन, टाल्स्टाय और दोस्तोईव्स्की इनमें सबसे मुख्य हैं। तुर्गनेव बड़ा भारी उपन्यास लेखक था। अपने अपने उपन्यासों में रूसी किसानों की दुर्दशा का जो मार्मिक वर्णन किया, उसमें विचारशील लोगों का ध्यान उनकी ओर आकृष्ट हुआ। किसानों को दाम्भता में मुक्त करने के लिये जो कानून अलेक्जण्डर द्वितीय के समय में बने, उनमें तुर्गनेव के उपन्यास बहुत सहायक हुए। पुशकिन बड़ा भारी कवि था। उसकी कविताओं ने रूस में नवजीवन का संचार किया। दोस्तोईव्स्की क्रान्तिकारी दल का एक नेता था। उसे आजन्म साइबेरिया निवास का दण्ड मिला था। उसने अपने उपन्यासों में रूस की जान्मा को ससार के सम्मुख रखा है। रूस की समस्याओं का जितना सुन्दर वर्णन उसके ग्रन्थों में मिलता है, उतना अन्यत्र मिलना कठिन है। लियो टाल्स्टाय अपने समय के सबसे बड़े साहित्यसेवियों में एक था। सारा सारा उसकी प्रतिभा का निष्का मानता है। उसने अपनी कहानियों और उपन्यासों में निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धान्त का बड़ी प्रबलता के साथ प्रतिपादन किया है। अपने ग्रन्थों द्वारा एक नवीन विचारसरणी भी उसने जनता के सम्मुख रखी है।

थद्यपि रूस में अभी शासन-सुधार नहीं हुए थे, वहाँ की राजनीतिक समस्याएँ अभी सोलहवीं सदी से आगे नहीं बढ़ी थीं, पर इन लेखकों और क्रान्तिकारियों के प्रयत्न में रूस की जनता में जागृति उत्पन्न हो गई थी, और वहाँ नवयुग का सूत्रपात होने लगा था।

वाईसवाँ अध्याय

## टर्की और बाल्कन प्रायद्वीप के विविध राज्य

### १ उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ में टर्की की दशा

पुरातन इतिवृत्त—मध्यकालीन इतिहास में पूर्वी यूरोप का बड़ा भाग तुर्की साम्राज्य के अन्तर्गत था। ओथमान (मृत्युकाल, १३२६ ई०) के नेतृत्व में तुर्क जाति ने एशिया माइनर में प्रवेश किया था। ओथमान के पश्चात् विविध तुर्क सुलतान अपने आविर्भाव की सीरिया, अरब और ईजिप्ट में विस्तृत करते रहे। १४५३ में मुहम्मद द्वितीय ने पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कोन्स्टेन्टिनोपल पर आक्रमण किया। पवित्र रोमन सम्राट विघर्मी तुर्कों से अपनी राजधानी की रक्षा कर सकने में असमर्थ रहे। कोन्स्टेन्टिनोपल परास्त हो गया, और यूरोप में तुर्कों का प्रवेश शुरू हुआ। पन्द्रहवीं सदी में पूर्वी यूरोप में आस्ट्रिया के हाब्सबुर्ग वंशी सम्राट और वेनिस की रिपब्लिक अत्यन्त प्रबल थे। दो शताब्दियों तक ये तुर्क आक्रान्ताओं के साथ निरन्तर संघर्ष में व्याप्त रहे। इस काल में बाल्कन प्रायद्वीप का बड़ा भाग तुर्कों की अधीनता में आ गया। कुछ समय के लिये तो तुर्क साम्राज्य की पश्चिमी सीमा यूरोप के जर्मन प्रदेशों से आ लगी। १६८३ में तुर्क सेनाओं ने वीएना पर भी आक्रमण किया, पर वे हाब्सबुर्ग वंश की इस राजधानी को विजय नहीं कर सकी। पोलैण्ड के प्रतापी राजा जॉन सोबिएस्की की सहायता से आस्ट्रियन सम्राट ने वीएना में तुर्क लोगों को पराजित किया। १६८४ में आस्ट्रिया, पोलैण्ड और वेनिस ने मिल कर एक पवित्र-संघ का निर्माण किया, जिसका उद्देश्य विघर्मी तुर्कों से ईसाई यूरोप की रक्षा करना था। पन्द्रह वर्षों तक यह पवित्र-संघ तुर्कों के साथ निरन्तर संघर्ष करता रहा। १६९९ में रूस का प्रतापी सम्राट पीटर द ग्रेट भी इस संघ में शामिल हो गया, और इन चार शक्तिशाली राज्यों की सम्मिलित शक्ति का यह परिणाम हुआ, कि तुर्क लोग यूरोप में और अधिक आगे नहीं बढ़ सके।

अठारहवीं सदी में तुर्क साम्राज्य की शक्ति क्षीण होनी शुरू हुई। १७३१ ई० में रूस की सुप्रसिद्ध जारिना कैथेरिना द्वितीय ने काला सागर के तट पर स्थित नीमिथा के अन्तर्गम्य को और एजाफ के समुद्र तट पर विद्यमान प्रदेश को जीत लिया। ये प्रदेश पहले टर्की के अधीन थे। इनको विजय कर लेने का परिणाम यह हुआ, कि रूसी साम्राज्य की दक्षिणी सीमा काला सागर के साथ आ लगी, और रूस ने टर्की के मामलों में हस्तक्षेप करना प्रारम्भ किया।

उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ में टर्की की दशा—१८१५ ई० में नैपोलियन ने पतन के समय यह स्थिति थी, कि क्षेत्रफल की दृष्टि से तुर्क साम्राज्य यूरोप में रूस के बाद सबसे

बड़ा था। उसकी उत्तरी सीमा नीस्टर नदी थी। मोल्डेविया और बलेचिया के प्रदेश उसके अन्तर्गत थे। इन्हीं प्रदेशों से मिलकर आजकल का रूमानिया का राज्य बना है। इनके दक्षिण का सम्पूर्ण बाल्कन प्रायद्वीप तुर्की साम्राज्य के अन्तर्गत था। बोस्निया, हेर्जेगोविना, सर्बिया, बल्गेरिया, अल्बेनिया, रूमानिया और ग्रीस—ये सब प्रदेश उसके अधीन थे। बाल्कन प्रायद्वीप में केवल दो ही ऐसे छोटे-छोटे प्रदेश थे, जो उसके अधीन नहीं थे। डान्मेटिया का समुद्रतट तथा मोन्टेनिग्रो का पहाड़ी राज्य, ये दो प्रदेश ही उस समय बाल्कन प्रायद्वीप में स्वतन्त्र थे। ये प्रदेश भी पहले टर्की के अधीन थे। पर अठारहवीं सदी के शुरू में डानीलो नामक पादरी के नेतृत्व में उन्होंने तुर्क शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, और रूस की सहायता से आने पर पृथक् स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर लिये थे। टर्की ने इनकी पुन विजय के लिये अनेक प्रयत्न किये, पर अन्त में विवश होकर १७९१ में उसने इन की स्वतन्त्रता सत्ता को स्वीकार कर लिया। ईगियन सागर के विविध द्वीप भी टर्की के अधीन थे। यूरोप से बाहर एशिया माइनर, पैलेस्टाइन, मैसोपोटामिया, आर्मीनिया और अरब भी तुर्की साम्राज्य के अन्तर्गत थे। अफ्रीका में ईजिप्ट में लेकर अल्जीरिया तक टर्की का आधिपत्य स्वीकृत किया जाता था।

**साम्राज्य की विविध जातियाँ—**इस विशाल साम्राज्य में किसी एक जाति का निवास नहीं था। केवल एशिया माइनर ही एक ऐसा प्रदेश था, जिसमें तुर्क जाति प्रचुर संख्या में बसती थी। साम्राज्य के शेष सब प्रदेशों में तुर्क-भिन्न अन्य जातियों का निवास था। मध्यकाल में जब राष्ट्रीयता के भाव लोगों में उत्पन्न हुए नहीं हुए थे, इन विविध प्रकार की जातियों का एक शासन में रह सकना कोई असम्भव व असाधारण बात नहीं थी। पर अब उन्नीसवीं सदी में, जब कि सर्वत्र राष्ट्रीयता का सिद्धान्त प्रसारित हो रहा था, टर्की का यह विशाल साम्राज्य बहुत ही अस्वाभाविक प्रतीत होता था। यही कारण है, कि उन्नीसवीं सदी में अनेक जातियों ने तुर्की शासन के विरुद्ध विद्रोह कर अपनी राष्ट्रीय स्वाधीनता की प्राप्ति करने का उद्योग प्रारम्भ किया। आज वह समय आ चुका है, जब कि तुर्क साम्राज्य उसी प्रदेश तक सीमित रह गया है, जहाँ कि तुर्क जाति का ही प्रधानतया निवास है। पर यह दशा एकदम नहीं आ गई, इसके लिये एक सदी तक निरन्तर संघर्ष की आवश्यकता हुई। सत्तार के आधुनिक इतिहास में राष्ट्रीयता की यह विजय बहुत महत्वपूर्ण है।

उत्तरी अफ्रीका में प्रधानतया ऐसी जातियाँ निवास करती थी, जिनका मूल अरब व वर्वर कहा जा सकता है। अरब में तो मुख्य रूप से अरब लोग ही बसते थे। पर कहीं-कहीं कुर्द और पर्शियन लोग भी विद्यमान थे। यही दशा अरब के उत्तर में विद्यमान उस उपजाऊ अर्द्धचन्द्राकार घाटी की भी थी, जिसमें कि प्राचीन काल में बैबिलोनियन, असीरियन और कैलिडियन साम्राज्यों का विकास हुआ था। सीरिया में यहूदी लोगों का प्राधान्य था। अरब और एशिया माइनर के बीच में स्थित टौरस पर्वत माला के पहाड़ी प्रदेशों में आर्मीनियन और कुर्द जातियों का निवास था। एशिया माइनर में तुर्कों के अतिरिक्त आर्मीनियन तथा ग्रीक लोग भी पर्याप्त संख्या में रहते थे।

यह तो हुई एशिया और अफ्रीका में विद्यमान तुर्की साम्राज्य की बात। अधिक जटिल समस्या तुर्की साम्राज्य के यूरोपियन प्रदेशों की थी। वहाँ अनेक जातियाँ निवास करती



थी, जो नसल, भाषा, सभ्यता, संस्कृति, धर्म आदि सब दृष्टियों से एक दूसरे से सर्वथा भिन्न थी, और जिनकी तुर्क शासको के साथ तो कोई समता थी ही नहीं। इनमें अल्बेनियन, ग्रीक, यूगोस्लाव या सर्व, बल्गर और रूमानियन सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे।

अल्बेनियन जाति का निवास ग्रीस के उत्तर-पश्चिम में स्थित पहाड़ी प्रदेशों में था। १८९३ में इनकी कुल आबादी १५ लाख के लगभग थी। ये लोग बड़े शूरवीर, लड़ाकें तथा स्वतन्त्र प्रकृति के थे। सभ्यता की दृष्टि से ये पश्चिमी यूरोप के लोगों से बहुत पीछे थे। ये अपने छोटे-छोटे गावों में बसते तथा कृषि द्वारा अपने जीवन का पालन करते थे। इनके विविध परिवारों तथा ग्रामों में निरन्तर लड़ाई जारी रहती थी। ये लोग उन्नीसवीं सदी में भी प्रायः जङ्गली तथा पिछड़ी हुई दशा में ही थे।

ग्रीक लोगों की आबादी ९० लाख के लगभग थी। वर्तमान ग्रीक लोग प्राचीन ग्रीकों के सीधे वंशज नहीं कहला सकते। ग्रीस में अनेक जातियों के परस्पर मिश्रण की प्रक्रिया बहुत होती रही है, और वहाँ के वर्तमान निवासी इन विविध जातियों के मिश्रण के ही परिणाम हैं। उन्नीसवीं सदी में ग्रीक लोग प्रयाप्त उन्नत तथा सभ्य थे। वे शहरों में निवास करते थे, और व्यापार द्वारा अपनी आजीविका कमाते थे। पश्चिमी यूरोप में जो नई प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हो रही थी, उनसे भी वे अच्छी तरह परिचित थे, और इस कारण अपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिये भी उत्सुक थे।

रूमानियन जाति के लोगों की संख्या १ करोड़ २० लाख थी। वे मोल्डेविया, वेलेचिया और ट्रासिलवेनिया में निवास करते थे। सभ्यता की दृष्टि से ये बहुत पिछड़े हुए थे। उनका अच्छा बड़ा भाग अभी पशु-पालन द्वारा ही जीवन व्यतीत करता था।

वाल्कन प्रायद्वीप में निवास करनेवाली जातियों में युगो-स्लाव या सर्व लोग अन्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। पूर्वी यूरोप में स्लाव जातियों का बहुत महत्व था। सर्व लोग विशाल स्लाव जाति की ही दक्षिणी शाखा थे। यूरोप भर के स्लाव के लोगों में एक प्रकार की एकानुभूति का भाव विद्यमान था। उस भावना से लाभ उठाकर ये भी अपने जातीय गौरव की स्थापना तथा टर्की की अधीनता से मुक्त होने के लिये प्रयत्न करते रहते थे। इस समय में युगो-स्लाव लोगों की संख्या ८० लाख के लगभग थी।

बल्गर लोग प्रधानतया बल्गेरिया में निवास करते थे। अनेक ऐतिहासिकों का विचार है, कि ये लोग तुर्कों की तरह मध्य एशिया से ही आये थे। इस समय में उनकी आबादी ५५ लाख के लगभग थी।

तुर्क लोग प्रायः सम्पूर्ण वाल्कन प्रायद्वीप में बसे हुए थे। पर इन प्रदेशों में उनकी आबादी बहुत अधिक नहीं थी। तुर्क लोग शासकों के रूप में अपने साम्राज्य के सब प्रदेशों में रहते थे। शासित जातियों से वे कोई सम्बन्ध नहीं रखते थे, उन्हें वे नीची निगाह से देखते थे। परन्तु उनमें एक विशेषता थी। जो कोई आदमी इस्लाम को स्वीकृत कर लेता था, तथा तुर्की भाषा को अपना लेता था, उसे वे अपने समान समझने लगते थे। तुर्की साम्राज्य में विद्यमान सब मुसलमान व तुर्क भाषा-भाषी लोग तुर्क समझे जाते थे। यही कारण है, कि वर्तमान समय में जिन लोगों को तुर्क कहा जाता है, उनमें से बहुत कम ऐसे हैं, जो वस्तुतः तूरानियन जाति के हों। अधिकांश लोग ऐसे हैं, जिन्होंने तुर्की

धर्म तथा सभ्यता को स्वीकार कर लिया है।

केवल जातियों की दृष्टि में ही तुर्की साम्राज्य में अनेक विविधताओं तथा भेदों की सत्ता नहीं थी, साथ ही उसमें धार्मिक भेदों की भी कमी न थी। तुर्क लोग सुन्नी मुसलमान थे। पर शिया, बहावी आदि विविध मुसलिम सम्प्रदायों को मानने वाले अनेक लोग भी तुर्की साम्राज्य में बसते थे। मुसलमान जनता में भी धार्मिक एकता न थी। मुसलमानों के अतिरिक्त यहूदी तथा ईसाई धर्मों को मानने वाले विविध लोग भी तुर्की साम्राज्य में निवास करते थे। ईसाइयों में मुख्य भेद तीन थे—रोमन कैथोलिक, ग्रीक कैथोलिक और ज्योजियन (जार्मीनियन)। इन तीनों ईसाई सम्प्रदायों के अनुयायी तुर्की साम्राज्य में बहुत बड़ी संख्या में निवास करते थे। तुर्क लोग इन्हें काफिर समझते थे, और घृणा की दृष्टि से देखते थे।

तुर्क साम्राज्य की समस्याएँ—इस विवरण में भलीभांति समझा जा सकता है, कि तुर्की साम्राज्य कितना अस्वाभाविक और राष्ट्रीयता के सिद्धान्त के विपरीत था। यूरोप में आस्ट्रिया और तुर्की—ये दो साम्राज्य इस प्रकार के थे, जो नई प्रवृत्तियों की दृष्टि में बहुत अनुचित और अस्वाभाविक थे। यही कारण है, कि समय के आधुनिक इतिहास में इनका विनाश करके अपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की स्थापना करने के लिये विविध जातियाँ निरन्तर प्रयत्न करती रही। आस्ट्रिया की तरह टर्की में भी केवल राष्ट्रीयता की ही समस्या न थी। राजा का एकमात्र अधिकार वहाँ के शासन का आधारभूत सिद्धान्त था। लोकतन्त्र प्रवृत्तियाँ इस स्वेच्छाचारी शासन को कभी सहन नहीं कर सकती थीं। टर्की का शासन किस ढंग से होता था, यह बताने की विशेष आवश्यकता नहीं है। मध्यकाल में सम्पूर्ण यूरोप में जिस ढंग के एकतन्त्र स्वेच्छाचारी शासन विद्यमान थे, वैसा ही शासन टर्की में भी था। भेद केवल इतना था, कि टर्की का शासन सम्राट व सुल्तान होने के साथ-साथ इस्लाम का धार्मिक नेता व खलीफा भी होता था। इस कारण उसकी स्थिति और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती थी। टर्की में शासन इतना विकृत हो चुका था, कि राज्य के प्रधान पद नीलाम किये जाते थे। जो सबसे अधिक कीमत देता था, वही राजकीय पद प्राप्त कर लेता था। इस प्रकार भारी रकम सुल्तान को प्रदान कर जो लोग राजकीय पदाधिकारी बनते थे, वे स्वाभाविकरूप से अपने पद को निजी आमदनी बढ़ाने का साधन मात्र समझते थे। परिणाम यह था, कि टर्की का शासन बहुत ही विकृत हो गया था।

शासन में सुधार करने तथा टर्की की उन्नति के लिये कई सुल्तानों ने उन्नीसवीं सदी में प्रयत्न प्रारम्भ किया। सलीम तृतीय (१७८९-१८०७) और महमूद द्वितीय (१८०८-१८३९) इनमें प्रमुख हैं। विशेषतया महमूद द्वितीय ने अपने सम्पूर्ण जीवन को टर्की की उन्नति और शासन-सुधार में खपा दिया, पर इसका कोई विशेष परिणाम नहीं हुआ। टर्की पुराने जमाने और धार्मिक सकीर्णता के दलदल में इतना अधिक फसा हुआ था, कि उसके अपने सुल्तान के प्रयत्न भी प्रायः निरर्थक ही रहे।

तुर्की साम्राज्य में जो नई प्रवृत्तियाँ कार्य कर रही थी, उन्हें हम दो भागों में बाट सकते हैं—(१) विविध जातियाँ अपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिये उद्योग कर रही थी,

और (२) तुर्क लोगो में अनेक दल इस प्रकार के संगठित हो रहे थे, जो नई रोशनी से परिचित थे, और जो अपने देश से पुराने जमाने का अन्त कर नवीन युग की स्थापना करने को उत्सुक थे। ये दोनों कार्य इस समय सम्पन्न हो चुके हैं। ये किस प्रकार सम्पन्न हुए, यही हमें प्रदर्शित करना है।

## २ बाल्कन राज्यों में राष्ट्रीय जागृति का प्रादुर्भाव

**राष्ट्रीय भावना**—अठारहवीं सदी में ही बाल्कन राज्यों में राष्ट्रीय जागृति का प्रारम्भ हो चुका था। यद्यपि इस प्रायद्वीप में सदियों तक तुर्कों का शासन कायम रहा था, तथापि विविध जातियों में एकता उत्पन्न नहीं हुई थी। बाल्कन प्रायद्वीप अनेक पर्वत-मालाओं से आच्छादित है। इन पहाड़ियों के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना बहुत सुगम नहीं है, और इसी कारण विविध प्रदेशों में बसी हुई विविध जातियों में परस्पर एकता का प्रादुर्भूत हो सकना भी सरल बात नहीं थी। तुर्की शासन इन विविध जातियों को तुर्क सभ्यता और संस्कृति सिखाकर अपने अन्दर मिश्रित कर लेने में भी अमफल रहा था। अब जब कि उन्नीसवीं सदी में तुर्की शासन क्षीण हो रहा था, अव्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ रही थी, इन विविध जातियों में अपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की भावना का प्रादुर्भूत होना सर्वथा स्वाभाविक था। पश्चिमी यूरोप में राष्ट्रीयता की प्रवृत्ति उत्पन्न हो चुकी थी। फ्रेंच राज्यक्रान्ति तथा नैपोलियन के युद्धों से यूरोप राष्ट्रीयता की लहर से आप्लावित हो रहा था। बाल्कन राज्यों पर भी उसका प्रभाव पड़ना अनिवार्य था। पश्चिमी यूरोपियन जातियों का अनुसरण कर बाल्कन जातियाँ भी अपने राष्ट्रीय राज्यों का स्वप्न लेने लग गई थी। उनकी इस आकांक्षा को उसकाने में अनेक यूरोपियन राज्य-विशेषतया रूस सहायता प्रदान कर रहे थे। क्रीमिया की विजय के बाद रूस की सीमा काला सागर से आ लगी थी, और वहाँ के महत्वाकांक्षी सम्राट् इस प्रयत्न में थे, कि टर्की की निर्वलता और बाल्कन जातियों की राष्ट्रीय भावना से लाभ उठाकर इस क्षेत्र में अपने प्रभाव का विस्तार करें। आस्ट्रिया की शक्ति भी जर्मनी में क्षीण हो रही थी, और उसके सम्राट् यह अनुभव करते थे, कि उनकी शक्ति के विस्तार का उपयुक्त क्षेत्र बाल्कन प्रायद्वीप ही हो सकता है। रूस और आस्ट्रिया, इन दोनों राज्यों का हित इस बात में था, कि टर्की कमजोर हो जाए, और बाल्कन प्रायद्वीप की लूट द्वारा वे अपना राज्य-विस्तार कर सकें। तुर्क साम्राज्य के विविध प्रदेशों में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की जो भावना विवक्षित हो रही थी, उसके कारणों को संक्षेप में इस प्रकार लिख सकते हैं—(१) बाल्कन प्रायद्वीप की भौगोलिक परिस्थितियाँ, जो पृथक्त्व की भावना को प्रोत्साहित करती थीं। (२) तुर्क शासकों की इस उद्देश्य में विफलता, कि वे ईसाई लोगों को दंगल में दीक्षित कर सकें। (३) तुर्क सम्राटों की निर्वलता। (४) रूस आदि विदेशी राज्यों द्वारा राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की भावना के लिये प्रोत्साहन।

**सर्व विद्रोह**—ये कारण थे, जिनमें बाल्कन राज्यों में राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिये संघर्ष प्राग्गम हुआ। १८०४ में युगोस्लाव व सर्व लोगो ने विद्रोह किया। इस विद्रोह का नेता यान पेट्रोविच था। यह सर्वियन विद्रोह निरन्तर अधिक-अधिक गम्भीर रूप धारण

करता गया। विद्रोही लोग वेलग्रेड (सर्बिया का मुख्य नगर) के सूबेदार मुस्तफा पाशा को कतल करने में समर्थ हुए। तुर्की सरकार ने जो सेनाएँ विद्रोह को शान्त करने के लिये भेजी, उन्हें परास्त कर दिया गया। रूस ने सर्व लोगों की सहायता की। ज्यार्ज पेट्रोविच के नेतृत्व में सामयिक सर्बियन सरकार भी संगठित कर ली गई। १८१२ तक यह विद्रोह व स्वाधीनता-संग्राम जारी रहा। पर आगिरकार, तुर्की सरकार विद्रोह को शान्त करने में सफल हुई। ज्यार्ज पेट्रोविच ने आस्ट्रिया भागकर अपने प्राण बचाये, और सर्व लोग फिर से तुर्क शासकों के काबू में आ गये।

१८१२ के विद्रोह में असफल होकर भी सर्व लोगों में राष्ट्रीय स्वाधीनता का आन्दोलन वन्द नहीं हुआ। १८१५ में फिर विद्रोहाग्नि प्रचंड हो उठी। इस बार मिलोश नाम का एक सर्व सरदार इस विद्रोह का नेता बना। मिलोश बहुत योग्य व्यक्ति था। वह न केवल अच्छा योद्धा था, पर साथ ही राजनीतिक दाव पेंच में भी दक्ष था। कुलीन श्रेणी का होने के कारण सर्वसाधारण लोगों में उसका प्रभाव भी बहुत अधिक था। १८१३ में मिलोश को अपने प्रयत्न में सफलता हुई। वह तुर्की सुल्तान से यह मनवाने में समर्थ हुआ, कि सर्बियन लोगों को स्थानीय मामलों में स्वतन्त्रता दी जाए, वे हथियार रख सकें और कुछ हद तक अपना शासन भी अपने आप कर सकें। इसके बाद भी स्वाधीनता का आन्दोलन जारी रहा। पर सर्बिया की सफलता का वास्तविक प्रारम्भ उस समय हुआ, जब कि रूस ने खुल्लमखुल्ला सर्व आन्दोलन का पक्षपोषण प्रारम्भ किया। १८२६ में रूस के सम्राट् ने तुर्की सुल्तान को विवश किया, कि वह अपनी विद्रोही सर्व प्रजा में समझौता करले। रूस में स्लाव लोग बहुत बड़ी सस्या में निवास करते हैं, सर्बियन लोग भी स्लाव जाति के ही हैं। इस जाति-सम्बन्ध के नाते तथा अपनी साम्राज्य-विस्तार विषयक आकाक्षाओं को पूर्ण करने के लिये रूस सर्बियन आन्दोलन से पूर्ण महानुभूति रखता था। रूस के सम्राट् के जोर देने पर सुल्तान को विवश होना पड़ा, और आखिर वह इस बात के लिये तैयार हो गया, कि सर्बिया को टर्की की अधीनता में स्वतन्त्र तथा पयक् राज्य के रूप में स्वीकृत कर लिया जाय। इस प्रकार सर्बियन स्वतन्त्रता की नींव पड़ी। १८२६ से सर्बिया एक पयक् राज्य के रूप में परिवर्तित हो गया। यद्यपि सर्बिया द्वारा टर्की की अधीनता स्वीकृति की गई थी, और उसे भेट भी वार्षिक रूप से दी जाती थी, तो भी सर्बिया की यह स्वाधीनता कम महत्वपूर्ण नहीं थी। कुछ समय बाद मिलोश को नवीन सर्बियन राज्य का राजा निर्वाचित किया गया, और यह निश्चित हुआ कि सर्बिया की राजगद्दी मिलोश के वंश में ही स्थिर रहे। १८२९ से सर्बिया वस्तुतः एक स्वतन्त्र राज्य बन गया था। यद्यपि वेलग्रेड तथा अन्य बड़े शहरों में तुर्की फौज अब भी रहती थी, तो भी सर्बियन लोगों को अपनी राष्ट्रीय आकाक्षाओं को पूर्ण करने का उपयुक्त अवसर प्राप्त हो गया था और वे स्वाधीन राष्ट्र के रूप में अपना विकास करने लग गये थे।

**ग्रीस की स्वतन्त्रता**—सर्बिया की तरह ग्रीस में भी राष्ट्रीय स्वाधीनता की आकाक्षा प्रादुर्भूत हो चुकी थी। ग्रीक लोग काफी सभ्य तथा उन्नत थे। वे नगरों में निवास करते थे, और व्यापार उनका प्रधान पेशा था। समुद्र तट के अत्यन्त विस्तृत होने के कारण भी ग्रीस को अनेक लाभ प्राप्त थे। ग्रीस का प्राचीन गौरव भी लोगों के सम्मुख था।

प्लेटो, आरिस्टॉटल और परिकलीज की पवित्र भूमि इस समय तुर्कों द्वारा पदाक्रान्त हो रही थी। न केवल ग्रीस के निवासी, अपितु अन्य यूरोपियन लोग भी इस दशा को अत्यन्त शोचनीय समझते थे। राष्ट्रीयता की जो लहर पश्चिमी यूरोप में सर्वत्र व्याप्त हो रही थी, वह अब ग्रीस में भी प्रविष्ट हुई, और वहाँ के निवासी भी अपने देश की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिए आतुर हो उठे। १८२१ में ग्रीक स्वतन्त्रता-संग्राम प्रारम्भ हुआ। मोरिया (प्राचीन पेलोपोनिसस) में विद्रोह की अग्नि प्रचण्ड हो गई। पादरियो ने भी क्रान्तिकारियों का साथ दिया। ईसाई पादरी तुर्कों को काफिर समझते थे। उनके विरुद्ध खूब घृणा का प्रचार किया गया। हजारों मुसलमान पुरुष, स्त्री और बच्चों को कतल कर दिया गया। उधर तुर्क लोगों ने भी अत्याचार करने में कसर न छोड़ी। कोन्स्टेन्टिनोपल में स्थित ग्रीक कैथोलिक चर्च के नेता (पेट्रिआर्क) को कतल कर दिया गया। सर्वत्र ग्रीक प्रजा पर नयकर अत्याचार होने लगे। पर ग्रीक विद्रोह शान्त न हो सका। २७ जनवरी, १८२२ के दिन ग्रीक लोगों ने अपनी राष्ट्रीय स्वाधीनता का वाक्यादा ऐलान कर दिया। दोनों तरफ से निरन्तर लड़ाई जारी रही। ग्रीक लोगों ने बड़ी वीरता के साथ तुर्कों का नामना किया। यूरोप के अन्य राज्य इस स्वाधीनता-संग्राम को उपेक्षा की दृष्टि से न देख सके। यद्यपि मेटर्निख आदि पुराने जमाने के पक्षपातियों की सहानुभूति सुलतान के साथ थी, पर यूरोप भर के उदार तथा नये विचारों के लोग ग्रीक विद्रोह का समर्थन सुनकर अत्यन्त प्रसन्नता अनुभव कर रहे थे। ग्रीक लोगों की सहायता करने के लिए अनेक राज्यों में आन्दोलन प्रारम्भ हुआ। विशेषतया दार्शनिकों, कवियों और नाट्यिक लोगों को ग्रीस के साथ बड़ी सहानुभूति थी। वे प्लेटो और सुकरात की जन्म-भूमि का इस प्रकार म्लेच्छ तुर्कों द्वारा अपमानित होना नहीं देख सकते थे। परिणाम यह हुआ, कि जगह-जगह पर ग्रीक स्वतन्त्रता-युद्ध को सहायता पहुँचाने के लिए स्वयंसेवक भर्ती किये जाने लगे। इङ्ग्लैण्ड का प्रसिद्ध कवि लार्ड बायरन स्वयंसेवक के रूप में ग्रीक लोगों की सहायता करने के लिए आगे बढ़ा। १८२७ में यूरोप के अनेक देशों में ग्रीस के पक्ष में लोकमत इतना प्रबल हो गया, कि इङ्ग्लैण्ड, फ्रांस और रूस की सरकारों ने सम्मिलित रूप से सुलतान से अनुरोध किया, कि ग्रीस की स्वतन्त्रता को स्वीकार कर लिया जाय। इन राज्यों का कहना था, कि ग्रीस तथा उसके समीपवर्ती द्वीपों में जो अराजकता मची हुई है, उससे यूरोप के व्यापार को बहुत नुकसान पहुँच रहा है, अतः ग्रीक लोगों को सन्तुष्ट कर शीघ्र ही शान्ति तथा व्यवस्था की स्थापना करनी चाहिए। टर्की का सुलतान इन बाह्य राज्यों के हस्तक्षेप को सहन न कर सका, और उसने उनकी पराधीनता की। परिणाम यह हुआ, कि इन तीनों राज्यों के सम्मिलित जहाजी बेटे ने सुलतान की शक्ति का मुकाबला किया। अक्टूबर, १८२७ में नैवेरिनो नामक स्थान पर सुलतान का जहाजी बेटा परास्त हो गया। उधर रूसी सेना उत्तर की तरफ से गमन करती हुई कान्स्टेन्टिनोपल तक पहुँच गई थी। इस दशा में भी सुलतान सन्धि करने के लिए उद्यत न हुआ। उसने काफिरों के विरुद्ध जिहाद की घोषणा की। इस पर रूसी सरकार ने टर्की से वाक्यादा लड़ाई शुरू कर दी। मोल्डेविया और वेलेचिया के प्रदेशों में भी रूसी सेनाएँ लगे लगे, उनमें भी राष्ट्रीय स्वाधीनता की आकांक्षा विद्यमान थी। वे भी

बहुत पहले से अपने को स्वतन्त्र कराने का प्रयत्न कर रहे थे। अब रूस ने उद्घोषित किया, कि हम न केवल ग्रीस को उसके स्वातन्त्र्य-युद्ध में सहायता प्रदान करेंगे, पर साथ ही मोल्डेविया और वेलेचिया को भी तुर्की शासन में मुक्त कराकर रहेंगे। रूमनियन लोग भी अपनी स्वाधीनता का यह उत्तम अवसर प्राप्त कर टर्की के विरुद्ध विद्रोह करने को उद्यत हो गये। इस स्थिति में सन्धि कर लेने के अतिरिक्त सुलतान के सम्मुख अन्य कोई मार्ग शेष न रहा। वह सन्धि के लिये तैयार हो गया। १८२९ में एड्रियानोपल में सन्धि कर ली गई। इसके अनुसार, ग्रीक तथा रूमनियन लोगों की स्वाधीनता को स्वीकृत किया गया। रूस ने इस युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण भाग लिया था, उसे तुर्की समुद्र में अनेक व्यापारिक सुविधाएँ प्राप्त हुईं। हम के लिये काला सागर (ब्लैक सी) में भूमध्यसागर तक पहुँचने का मार्ग, जो टर्की के प्रभाव तथा अधीनता में था, अन्त्यतः महत्व रक्खता था। उसमें अनेक सुविधाएँ प्राप्त कर वह अपने उद्देश्य में बहुत कुछ मफल हो गया।

यद्यपि ग्रीक लोगों की स्वाधीनता को एड्रियानोपल की सन्धि द्वारा १८२९ में ही स्वीकृत कर लिया गया था, पर ग्रीस की सीमाएँ तथा निश्चित की जाएँ और टर्की के साथ उसका क्या सम्बन्ध रहे, यह निश्चित होने में कुछ समय लगा। आगिर, १८३० में ग्रीस को पूर्ण रूप से स्वाधीन मान लिया गया। अब टर्की का उस पर कोई आधिपत्य न रहा। पहले ग्रीक लोगों की इच्छा थी, कि वे अपने देश में रिपब्लिक की स्थापना करें। राष्ट्रपति भी निर्वाचित कर लिया गया था। पर पारस्परिक मतभेदों तथा दलबन्धियों के कारण ग्रीक लोग रिपब्लिक न बना सके। अन्त में यह निश्चय हुआ, कि राजसत्ता की स्थापना की जाय। वेरिया के राजकुमार ओटो को राजगद्दी अर्पित की गई, और ग्रीस एक स्वतन्त्र राजसत्तात्मक राज्य के रूप में परिवर्तित हो गया।

एड्रियानोपल की सन्धि द्वारा ही रूमनियन लोगों की स्वाधीनता को भी स्वीकृत किया गया था। उनके प्रदेशों का भी एक पृथक् राज्य बना दिया गया, जो कि रूमनिया के नाम से प्रसिद्ध है। टर्की के साथ इसका केवल इतना सम्बन्ध रखा गया, कि रूमनिया को प्रतिवर्ष एक निश्चित धनराशि भेंट के रूप में टर्की को देनी होती थी।

### ३ बाल्कन प्रायद्वीप में अन्तर्राष्ट्रीय सघर्ष का प्रारम्भ

अन्तर्राष्ट्रीय सघर्ष के कारण—ग्रीस के तुर्की साम्राज्य से निकल जाने पर टर्की की शक्ति बहुत कुछ क्षीण हो गई थी। अन्य यूरोपियन राज्यों ने समझा, कि अपनी शक्ति का विस्तार करने का यह सुवर्णवसर है। उन्होंने बाल्कन प्रायद्वीप में अपना प्रभाव कायम करने के लिये सघर्ष प्रारम्भ कर दिया। इस सघर्ष को ठीक-ठीक समझने के लिये पहले कुछ बातों पर ध्यान देना आवश्यक है—

(१) रूस का उत्तरी समुद्र उत्तरी ध्रुव के बहुत समीप है, और वहाँ अत्यधिक ठण्ड पड़ती है। अतः शीत ऋतु में वह जम जाता है, और सामुद्रिक आवागमन का मार्ग बन्द हो जाता है। रूस के पास सामुद्रिक आवागमन का केवल एक ही मार्ग ऐसा है, जो सारे साल खुला रहता है, वह है काला सागर (Black Sea) से डाडेंनेल्स और बोस्पोरस के जलडमरूमध्यों में गुजरकर ईजियन सागर में आना और फिर वहाँ से भूमध्यसागर में

पहुँच जाना। डाडेनल्स और वोस्पोरस के जलडमरूमध्यों के दोनों तरफ के प्रदेशों पर किसका राज्य है, यह बात रूस के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यदि इन प्रदेशों पर कोई शक्तिशाली राजा राज्य करता हो, और वह रूस का विरोध करने के लिये उतारू हो जाए, तो रूस के व्यापार को बहुत नुकसान पहुँच सकता है। साथ ही रूस के जमी जहाजों के बेड़े के लिये भी यही एकमात्र मार्ग है। यदि इस मार्ग से अन्य देशों के जमी बेड़े भी स्वतन्त्रतापूर्वक आ जा सकें, तो यह बात रूस के लिये अत्यन्त खतरनाक हो हो सकती है। इन बातों को सम्मुख रखकर यह सुगमता से समझा जा सकता है, कि रूस का हित इस बात में था, कि या तो टर्की का मुलतान उसके प्रभाव को स्वीकृत करे और उसे डम मार्ग में पूर्ण रूप से सुविधाएँ प्रदान करे, और या टर्की की शक्ति क्षीण हो जाए, और बाल्कन प्रायद्वीप में जो विविध स्वतन्त्र राज्य स्थापित हो, वे रूस को अपना संरक्षक मानें। रूस के लिये यह दूसरा उपाय अधिक सम्भव तथा क्रियात्मक था। कारण यह कि बाल्कन प्रायद्वीप में अनेक इस प्रकार की जातियाँ निवास करती थी, जो जातीय दृष्टि से रूस की जातियों से मिलती जुलती थी। साथ ही, इस प्रायद्वीप के लोगों का धर्म भी रूसी लोगों के धर्म के समान था। ईसाइयत का जो सम्प्रदाय रूस के अधिकांश भाग में प्रचलित था, वही बाल्कन प्रायद्वीप में भी विद्यमान था। टर्की के मुसलमान गानकों के विरुद्ध बाल्कन प्रायद्वीप की ईसाई प्रजा का पक्ष लेकर रूस सुगमता से उन्हें अपने प्रभाव तथा संरक्षा में ला सकता था।

(२) एशिया में इस समय जो विविध यूरोपियन राज्य अपना साम्राज्य बना रहे थे, उनमें रूस और ग्रेट ब्रिटेन प्रमुख थे। ब्रिटेन भारतवर्ष को अपनी अधीनता में ला चुका था। रूस प्रचान्त महानगर तक उत्तरी एशिया में अपना अधिकार स्थापित कर चुका था। अनेक स्थानों पर इन दोनों साम्राज्यों की सीमाएँ मिलती भी थी। दोनों को एक दूसरे में भय था।

इसके अतिरिक्त, ब्रिटेन के लिये अपने पूर्वी साम्राज्य तक पहुँचने का मार्ग स्वेज के स्थलडमरूमध्य के बिना अन्य कोई न था।<sup>१</sup> इस मार्ग के आसपास के प्रदेशों पर किसका राज्य है, यह बात ब्रिटेन के लिये अत्यन्त महत्व रखती थी। यदि रूस टर्की की शक्ति को नष्ट कर बाल्कन प्रायद्वीप पर अपना प्रभाव कायम कर ले, तो वह स्वेज के इस मार्ग के बहुत नजदीक तक पहुँच जाता था। एशियाई साम्राज्य के अपने सबसे शक्तिशाली प्रतिद्वन्द्वी का अपने एक मात्र मार्ग के इतने समीप पहुँच जाना ब्रिटेन को कभी

१ स्वेज की नहर १८६९ में बनकर तैयार हुई थी। पर स्वेज का मार्ग उससे पहले भी प्रयोग में आता था। उस समय ग्रेट ब्रिटेन तथा अन्य यूरोपियन राज्यों के जहाज पहले एलेक्जेंड्रिया पहुँचते थे। वहाँ उनका माल-असबाब उतार दिया जाता था। जे काफ़िशो द्वारा स्थलमार्ग से स्वेज पहुँचाया जाता था। वहाँ अन्य जहाज तैयार रहते थे। उन पर सब माल लाद दिया जाता था और फिर वे नये जहाज पूर्व में भारत आदि की तरफ आते थे। १८६९ के बाद स्वेज की नहर के कारण यूरोप से पर्व की तरफ जहाजों का सीधा आना-जाना प्रारम्भ हो गया।

सह्य नहीं हो सकता था। टर्की की ताकत बहुत कम थी। ब्रिटेन को उससे कोई डर नहीं था। अतः उसका हित इसी बात में था, कि टर्की नष्ट न होने पाए, और उसकी थोड़ी बहुत शक्ति कायम रहे, ताकि रूस बाल्कन प्रायद्वीप पर अपना प्रभाव न जमा सके। इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि बाल्कन राज्यों और टर्की के सम्बन्ध में रूस और ब्रिटेन की नीति एक दूसरे में सर्वथा विरुद्ध थी। वे परस्पर टक्कर खाती थी।

(३) रूस और ग्रेट ब्रिटेन के इन परस्पर-विरुद्ध हितों के अतिरिक्त एक और बात है, जिस पर हमें दृष्टि रखनी चाहिये। टर्की के सुल्तान का प्रधान मामन्त राजा ईजिप्ट का पाशा था। वह बहुत शक्तिशाली तथा महत्वाकांक्षी था। टर्की की शक्ति को क्षीण होते देखकर वह भी अपने को स्वतन्त्र करने तथा अपने राज्य को बढ़ाने के प्रयत्न में था। यूरोपियन राज्यों के सम्मुख यह भी समस्या थी, कि वे टर्की को सहायता दें या ईजिप्ट को। फ्रांस किस प्रकार उत्तरी अफ्रीका में साम्राज्य विस्तार के लिये प्रयत्नशील था, इसका उल्लेख आगे चलकर किया जायगा। ईजिप्ट के पाशा की स्या स्थिति हो, यह बात उसके लिये अत्यन्त महत्व की थी। ब्रिटेन भी इसकी उपेक्षा नहीं कर सकता था। इस दशा में विविध यूरोपियन राज्य परस्पर जो दाव-पेच चल रहे थे, उन्होंने बाल्कन प्रायद्वीप सम्बन्धी इस अन्तर्राष्ट्रीय मघर्ष की ओर भी पेशीदा बना दिया था।

ईजिप्ट से युद्ध—ग्रीस के स्वातन्त्र्य-युद्ध की समाप्ति पर १८३२ में ईजिप्ट के शक्तिशाली पाशा मोहम्मद अली ने अपने अधिपति सुल्तान महमूद द्वितीय के विरुद्ध युद्ध उद्घोषित कर दिया। सीरिया और पेल्लेस्टाइन को अपने अधीन कर ईजिप्सियन सेना एशिया माइनर में प्रवेश करने लगी। अब सुल्तान को चिन्ता हुई। उसने ब्रिटेन, फ्रांस और रूस से सहायता की प्रार्थना की। ब्रिटेन और फ्रांस ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। पर रूस इस अवसर पर टर्की की सहायता के लिये आगे बढ़ा। इस समय तक रूस का यह खयाल था, कि तुर्की सुल्तान से मित्रता स्थापित कर उसे अपने प्रभाव में लाया जा सकता है। रूसी सेनाओं ने कोन्स्टेन्टिनोपल की तरफ प्रस्थान किया। जब यह समाचार ब्रिटेन और फ्रांस ने सुना, तो वे घबरा गये। रूस की इस बढ़ती हुई शक्ति तथा प्रभाव को वे सहन नहीं कर सकते थे। उन्होंने हस्तक्षेप किया, और टर्की तथा ईजिप्ट में समझौता कराने का उद्योग प्रारम्भ हुआ। एशिया माइनर के दक्षिण-पूर्वी प्रदेश तथा सीरिया पर ईजिप्सियन पाशा की सूबेदारी (जिसका अभिप्राय उसका स्वतन्त्र शासन था) स्थापित की गई, और इस प्रकार उसे सन्तुष्ट किया गया। रूस ने टर्की की सहायता करने के लिये हाथ बढाया था, अतः उसे दो अत्यन्त महत्वपूर्ण सुविधाएँ प्राप्त हुई (१) बोस्पोरस और डार्डेनेल्स के जल-डमरूमध्यों के बीच से रूस के जगी जहाज स्वतन्त्रतापूर्वक आ जा सके, और अन्य किसी राज्य को यह अधिकार प्राप्त न हो। (२) जब टर्की पर कोई शत्रु आक्रमण करे, तो रूस उसकी सहायता करे। यह सन्धि रूस के लिये बहुत लाभदायक थी। रूस टर्की का एक प्रकार से संरक्षक बन गया था, और काला सागर का समुद्र-तट केवल उसीके जगी जहाजों के लिये सुरक्षित रह गया था। रूस यही दो बातें चाहता था, दोनों अब उसे पूर्ण रूप से प्राप्त हो गई थी।

जब यूरोप के अन्य राज्यों को इस सन्धि का पता लगा, तो उनके रोष की सीमा



न रही। अखबारों में गरम लेख निकलने लगे। ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस इस सन्धि का विरोध करने के लिये आपे से बाहर हो गये। रूस का विरोध करने के लिये जगी जाहजों का एक बेड़ा तुर्की समुद्र में भेज दिया गया। उधर रूस भी लड़ाई की तैयारी करने लगा, और युद्ध के बादल आकाश में मड़राने लगे। ऐसा प्रतीत होता था, कि अब लड़ाई हुए बिना न रहेगी। पर कुछ समय के लिये लड़ाई की घड़ी टल गई। अन्दर-अन्दर आग बबक रही थी, पर अभी वह सुलग कर ज्वालाओं के रूप में प्रगट नहीं हुई।

ईजिप्ट से दूसरा युद्ध—१८३३ में ईजिप्ट के पाशा और तुर्की सुलतान में परस्पर सन्धि हो गई थी। पर यह सन्धि देर तक कायम न रह सकी। सुलतान इस बात से बहुत दुखी था, कि सीरिया का प्रदेश उसके हाथ से निकलकर पाशा के पास चला गया था। उसने लड़ाई के लिए तैयारी की। १८३९ में टर्की ने ईजिप्ट के खिलाफ युद्ध उद्घोषित कर दिया। परन्तु इस बार उसकी और भी बुरी तरह से पराजय हुई। यदि यूरोपियन राज्य हस्तक्षेप न करते, तो शायद टर्की बचता भी नहीं। पर ग्रेट ब्रिटेन इस कमजोर राज्य का बिनाश नहीं सह सकता था। उसका अपना हित इस बात में था, कि टर्की की मत्ता कायम रहे। यूरोपियन राज्यों के हस्तक्षेप के कारण टर्की की रक्षा तो हो गई, पर अब प्रश्न यह उत्पन्न हुआ, कि सन्धि किस प्रकार की जाय। फ्रांस ईजिप्ट के पक्ष में था, और ग्रेट ब्रिटेन टर्की के। रूस तो १८३३ की सन्धि के अनुसार टर्की का संरक्षक ही बना हुआ था। अब जो १८४० में नई सन्धि हुई, उसमें रूस को उन विशेषाधिकारों का परित्याग करना पड़ा, जो उसने १८३३ में प्राप्त किये थे। वॉस्पोरम और डाडेंनेल्स के जल-डमरूमध्यों में जगी जहाजों को ले जाने का एकाधिकार अब उसके पास नहीं रह गया, और टर्की पर से उसकी संरक्षता भी नष्ट हो गई। १८४० की सन्धि द्वारा ईजिप्ट के पाशा की शक्ति को सीमित किया गया, और यूरोपियन राज्यों ने टर्की की रक्षा में ही अपना हित समझा।

अन्तरीप सम्बन्धी समझौता (१८४१)—सन् १८४० की सन्धि के अनुसार टर्की की स्थिति बहुत कुछ सभल गई थी। ईजिप्ट के सामन्त राजा मोहम्मद अली ने अपने अधिपति टर्की के सुलतान के विरुद्ध जो युद्ध शुरू किया था, वह अब समाप्त हो गया था। फ्रांस इससे असंतुष्ट था। वह टर्की के खिलाफ ईजिप्ट का सहायक था। अब वह इस बात के लिए उत्सुक था, कि १८४० की सन्धि (जो लण्डन में होने के कारण लण्डन की सन्धि के नाम से प्रसिद्ध है) क्रिया में परिणत न होने पाए। उसने फिर मोहम्मद अली को टर्की के विरुद्ध उकसाया। फ्रांस में नई सेनाएँ संगठित की गईं। ब्रिटेन इस स्थिति में शान्त नहीं रह सकता था। वह ईजिप्ट के विरुद्ध टर्की की सहायता करने को उद्यत था। ऐसा प्रतीत होता था, कि एक बार फिर टर्की के प्रश्न पर युद्ध का प्रारम्भ होना अवश्यम्भावी है। पर यूरोप के राजनीतिज्ञों ने इस बार अधिक समझदारी का काम लिया। आखिर, फ्रांस और इंग्लैण्ड में समझौता हो गया, जो अन्तरीप सम्बन्धी समझौते (स्ट्रेट्स कन्वेंशन) के नाम से प्रसिद्ध है। इस समझौते में फ्रांस और इंग्लैण्ड के अतिरिक्त आस्ट्रिया, प्रशिया और रूस भी सम्मिलित हुए। इसके अनुसार टर्की ने इस बात को स्वीकार किया, कि मोहम्मद अली पाशा न केवल ईजिप्ट का

व्यक्तमानुगत रूप से स्वामी रहेगा, पर साथ ही सीरिया के जिन प्रदेशों पर उसका प्रभुत्व है, उन पर भी उसका तथा उसके वंशजों का स्वामित्व कायम रहेगा। साथ ही, यह भी स्वीकृत किया गया, कि वीस्पोरम और डार्डेनेल्स के जलडमरूमध्यों को टर्की के अतिरिक्त अन्य किसी राज्य के जमीन, जहाज प्रयुक्त नहीं कर सकेंगे।

**राजनीतिक दाव पेंच—**१८८० में १८७३ तक टर्की और बाल्कन प्रायद्वीप के मामलों में इसी प्रकार राजनीतिक दाव पेंच जारी रहे। हम चाहता था, कि टर्की पर जाना आविषत्य कायम करे। पहले वह मित्रता की नीति में टर्की को अपने काबू में करना चाहता था। १८३२-३३ के युद्ध में ईजिप्ट के गिलाफ टर्की की सहायता उमने इसीलिए की थी, कि इसमें वह टर्की का मरझक बन सकेंगा। सामयिक तौर पर उसे अपने उद्देश्य में सफलता भी हुई थी। पर उसके बाद जो घटनाएँ हुई, उनमें वह भली भाँति समझ गया कि इस नीति द्वारा उसे सफलता नहीं मिल सकती। अब उमने नई नीति का अनुसरण करना शुरू किया। उमने सोचा, यदि टर्की के साम्राज्य को नष्ट कर अपने कब्जे में कर लिया जाय, तो ठीक रहेगा। परन्तु इस उद्देश्य में ग्रेट ब्रिटेन उसका सबसे बड़ा विरोधी था। अतः हमी सम्राट् ने विचार किया, कि तुर्की साम्राज्य को नष्ट कर यदि उसका एक हिस्सा ब्रिटेन को प्रदान कर दिया जाय तो सम्भवतः काम चल जायगा। ब्रिटेन यही तो चाहता है, कि स्वेज के मार्ग पर उसका कब्जा रहे। यदि ईजिप्ट तथा स्वेज के प्रदेश उसे मिल जाए, तो उसे लाभ ही लाभ है। हम अपने लिये ब्रिटेन से यही मनवाना चाहता था, कि कोन्स्टेन्टिनोपल पर कब्जा करने का उसे अधिकार रहे, और बाल्कन प्रायद्वीप के विविध क्रिश्चियन राज्य (जो कि तुर्की साम्राज्य के नष्ट होने पर स्वतन्त्र रूप से स्थापित कर दिये जायेंगे) उसकी मरझा में रहे। रूस समझता था, कि इस सौदे में ब्रिटेन को भी पूरा लाभ है, वह इसके लिये तैयार हो जायगा और यदि रूस तथा ब्रिटेन टर्की के मामले में एकमत हो जाएँ, तो अन्य किसी यूरोपियन राज्य की हिम्मत न होगी, कि उनकी सम्मिलित नीति का विरोध कर सके।

इसी उद्देश्य को दृष्टि में रखकर १८४४ में रूसी सम्राट् ने इङ्ग्लैण्ड की यात्रा की। पर वहाँ विदेशी राजनीति के पंडितों ने उसके विचार का स्वागत नहीं किया। १८५३ में यही विचार फिर ब्रिटिश राजदूत के सम्मुख सेण्ट पीटर्सबुर्ग में उपस्थित किया गया। पर इस बार भी ब्रिटेन ने रूस की योजना से असहमति प्रकट की। बात यह थी, कि ब्रिटेन एशिया के साम्राज्य में अपना सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी रूस को ही समझता था। वही रूस यदि कोन्स्टेन्टिनोपल पर कब्जा कर बाल्कन प्रायद्वीप पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित कर ले, तो उसकी शक्ति की सीमा ही न रहेगी। स्थल में तो रूस बहुत अधिक शक्ति रखता ही था, अब जल में भी उसे अपने शक्ति-विस्तार का सुवर्णवसर प्राप्त हो जायगा। ईजिप्ट और स्वेज पर यदि ब्रिटेन का कब्जा कायम हो भी जाता, तो उसे विशेष लाभ न था। अपने पड़ोस में ही शक्तिशाली रूस का होना उसके लिए एक भयकर खतरा था। ब्रिटेन रूस की शक्ति को इस प्रकार बढ़ते हुए कभी न देख सकता था। यही कारण है, जिससे उसने रूसी योजना को अस्वीकृत कर दिया। अब रूस के सम्मुख एक ही मार्ग था,

वह यह कि ब्रिटेन का विरोध कर वह टर्की पर अपना कब्जा कायम करने का प्रयत्न करे। डार्डेनेल्स और बोस्पोरस के जलडमरूमध्य तथा उनके समीपवर्ती प्रदेश उसके लिए कितने महत्वपूर्ण थे, यह पहले प्रदर्शित किया जा चुका है। रूस जिस तरह भी सम्भव हो, उन्हें अपनी अधीनता में लाना चाहता था। युद्ध द्वारा अपनी शक्ति परीक्षा के सिवा अब उसके सम्मुख अन्य कोई उपाय न था।

## ४. क्रीमियन युद्ध

**युद्ध का सूत्रपात**—ब्रिटेन की ओर से निराश होकर रूस टर्की के विरुद्ध युद्ध उद्घोषित करने के लिए उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा में था। ऐसा अवसर १८५३ में उपस्थित हो गया। ईसाइयों के पवित्र स्थान पेल्लेस्टाइन और जेरुसलम अनेक सदियों से तुर्की साम्राज्य के अन्तर्गत थे। यूरोप भर के ईसाई यात्री वहाँ तीर्थयात्रा के लिए जाया करते थे। इसके सिवा, इन प्रदेशों की अधिकांश आबादी ईसाई धर्म को मानने वाली थी। तुर्क सुलतान उनसे जिस प्रकार का व्यवहार करता है, इस सम्बन्ध में शिकायतों का अवसर सदा विद्यमान रहता था। १८५३ में जेरुसलम के ईसाई यात्रियों की अनेक शिकायतें रूस के सम्राट के कानों तक पहुँची। रूस का सम्राट अपने को तुर्की साम्राज्य की ईसाई प्रजा का स्वाभाविक संरक्षक समझता था। उसने समझा, टर्की के खिलाफ लड़ाई शुरू करने का यह अच्छा मौका है। मार्च, १८५३ में उसने सुलतान के नाम एक अन्तिम सूचना (अल्टिमेटम) जारी की, जिसमें यह मांग की गई कि सुलतान रूसी सम्राट को ईसाई प्रजा का संरक्षक स्वीकृत कर ले।

रूसी सम्राट के इस कार्य को ग्रेट ब्रिटेन कभी नहीं सह सकता था। उस समय टर्की में ब्रिटिश राजदूत के पद पर लार्ड स्ट्रेटफोर्ड विद्यमान था। उसने सुलतान को प्रेरित किया, कि वह रूस की मांग को स्वीकृत न करे। परिणाम यह हुआ, कि रूसी राजदूत ने टर्की में प्रस्थान कर दिया। ब्रिटेन तो रूस के विरुद्ध टर्की की सहायता करने को तैयार था ही, उधर फ्रांस ने भी टर्की का पक्ष लिया। फ्रांस का अधिपति इस समय नैपोलियन तृतीय था। उसने उद्घोषित किया, कि सुलतान से जो सन्धिया पहले हो चुकी है, उनके अनुसार टर्की की कैथोलिक प्रजा का संरक्षक फ्रांस है। रूस को कोई अधिकार नहीं है, कि वह ईसाइयों के मामले में हस्तक्षेप कर सके। रूसी राजदूत के टर्की से चले आने पर भी कुछ महीने तक ममझौते के लिए बातचीत जारी रही। परन्तु सुलह के प्रयत्नों में सफलता नहीं हो सकी। आखिर, १८५४ में युद्ध प्रारम्भ हो गया। इसमें फ्रांस और ब्रिटेन रूस के विरुद्ध टर्की की सहायता कर रहे थे। इतिहास में यह युद्ध 'क्रीमियन युद्ध' के नाम से प्रसिद्ध है। काला सागर में एक अन्तरीप है, जिसका नाम क्रीमिया है। यह युद्ध प्रधानतया क्रीमियन अन्तरीप में ही लड़ा गया था, इसीलिए इसे क्रीमियन युद्ध कहते हैं।

**क्रीमिया का युद्ध**—यह क्रीमियन युद्ध दो वर्ष तक जारी रहा। दोनों पक्षों को बहुत नष्ट नुकसान उठाना पड़ा। ५ लाख से अधिक आदमियों का इस युद्ध में सहारा हुआ। जग्गो रुपये नष्ट हुए। इतने जन और धन का सहारा करके भी ब्रिटिश तथा

फ्रेच लोग रूस को बहुत नुकसान नहीं पहुँचा सके। त्रीमियन अन्तरीप के दक्षिण भाग में स्थित सेवेस्टपोल के घेरे में ही उनकी अत्यधिक शक्ति व्यय हो गई। इस दशा में युद्ध को जारी रखना उन्हें बहुत उपयोगी प्रतीत नहीं होता था। उधर रूस भी युद्ध से तंग आ गया था। उसे यह भी खतरा था, कि कहीं आस्ट्रिया भी शत्रुओं के साथ सम्मिलित न हो जाए। आस्ट्रियन सरकार भी वात्कन प्रायद्वीप में अपनी शक्ति विस्तृत करना चाहती थी। उसकी इस आकांक्षा में रूस सबसे बड़ी रुकावट था। आस्ट्रिया ने समझा, उसे परास्त करने का यह अच्छा मौका है। यदि आस्ट्रिया भी रूस के विरुद्ध युद्ध उद्घोषित कर देता, तो टर्की का पक्ष बहुत प्रबल हो जाता। इस दशा में रूस ने भी यही उपयुक्त समझा, कि सन्धि कर लेने में ही अपना हित है।

पेरिस की सन्धि—३० मार्च, १८५६ को सन्धि हो गई। यह इतिहास में पेरिस की सन्धि के नाम से मशहूर है। सन्धि की मुख्य शर्त निम्नलिखित थी—

(१) तुर्की साम्राज्य की स्वतन्त्रता को विविध राज्यों ने मामूहिक रूप में स्वीकृत किया। (२) सबने इस बात को स्वीकृत किया, कि तुर्की साम्राज्य के आन्तरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप न करे। (३) काला सागर को युद्ध की दृष्टि में उदानीन माना गया, और यह व्यवस्था की गई कि कोई भी राज्य वहाँ पर अपने जहाज़ों का बेड़ा न रख सके, और न ही उसके तट पर युद्ध के लिये सामान जटा सके। (४) रूमानिया और सर्बिया में रूस अपना संरक्षण का अधिकार मानता था। उसने इस अधिकार का परित्याग किया, और सब राज्यों ने इन दोनों देशों की स्वतन्त्रता को कायम रखने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। (५) बल्गेरिया का प्रदेश माल्डेविया (रूमानिया) को दिया गया। यह प्रदेश डेन्यूब नदी के मुहाने पर स्थित था, और पहले रूस के अधिकार में था। इस प्रकार इस सन्धि में रूस को बहुत नीचा देखना पड़ा, और ब्रिटेन की नीति को पूर्ण सफलता मिली। टर्की के साम्राज्य को कायम रखकर रूस की महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश रखा जा सकता है, ब्रिटेन के इस विचार को पूर्णरूप से सफलता प्राप्त हुई।

तेईसवा अध्याय

## संयुक्त राज्य अमेरिका

### १ अमेरिका का प्रसार

संयुक्त राज्य अमेरिका का वर्तमान युग में महत्त्व—ससार के आधुनिक इतिहास में संयुक्त राज्य अमेरिका का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है। वह विश्व के दो सबसे अधिक शक्तिशाली राज्यों में से एक है, और राज्यों के उस समुदाय का नेतृत्व करता है, जो सम्पत्ति पर वैयक्तिक स्वत्व के अधिकार को स्वीकृत करते हुए लोकतन्त्र शासन का अनुसरण करते हैं। इस दशा में यूरोप के आधुनिक इतिहास को लिखते हुए हमारे लिये यह आवश्यक हो जाता है, कि इस अत्यन्त शक्तिशाली राज्य के इतिवृत्त पर भी हम सक्षेप के साथ प्रकाश डालें, क्योंकि अमेरिका की शक्ति के विकास को स्पष्ट किये बिना यूरोप के आधुनिक इतिहास को भलीभाँति स्पष्ट नहीं किया जा सकता।

स्वाधीनता की प्राप्ति—अमेरिका में ब्रिटिश लोगों के उपनिवेश किस प्रकार बसने लगे हुए, और सन् १७७६ में उन्होंने ब्रिटेन के विरुद्ध विद्रोह कर किस प्रकार स्वतन्त्रता प्राप्त की, इसका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। स्वाधीन होने के बाद इन उपनिवेशों ने अपने को एक संघराज्य (संयुक्तराज्य) में संगठित किया था। १७७६ में अमेरिका के इन उपनिवेशों की कुल मख्या तेरह थी, और ये अटलांटिक महासागर के तट पर बसे हुए थे। इन राज्यों की अपनी-अपनी पृथक् सरकारें थी, और आन्तरिक मामलों में ये सर्वथा स्वतन्त्र थे। पर अपने सर्वमान्य हितों की रक्षा के लिये इन्होंने अपने को एक संघ में संगठित कर लिया था। राज्यों और उनके संघ के शासन-विधान लोकतन्त्रवाद के अनुसार बनाये गये थे।

पश्चिम की ओर प्रसार—१७९० में संयुक्तराज्य अमेरिका की कुल आबादी चालीस लाख के लगभग थी। इसमें सात लाख नीग्रो थे, और शेष तेतीस लाख ब्रिटिश व अन्य यूरोपियन जातियों के गौराङ्ग लोग थे। इस समय अमेरिका की सबसे बड़ी नगरी फिलेडेल्फिया थी, और उसकी जनसंख्या बयालीस हजार के लगभग थी। न्यूयार्क में उस समय केवल तेतीस हजार मनुष्यों का निवास था। उन्नीसवीं सदी के शुरू होने पर संयुक्तराज्य अमेरिका की दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होनी शुरू हुई। प्रशान्त महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच में जो विशाल भूखण्ड है, उसका बड़ा भाग जबतक प्रायः खाली पड़ा था। अमेरिकन वस्तियाँ इसके पूर्वी तट के साथ-साथ ही विकसित हुई थीं। अब इन अमेरिकन लोगों ने पश्चिम की ओर आगे बढ़कर नई वस्तियों का विकास शुरू किया। १७८७ में कुछ साहसी लोग मिसिसिपी नदी के उत्तर-

पश्चिमी प्रदेश में जाकर बसने लगे, और वहाँ उन्होंने मिचिगन के राज्य का विकास किया। १८०३ में मिसिसिपी नदी के पश्चिम में लुइसियाना के प्रदेश को आबाद करना शुरू किया गया, और वहाँ इल्लिनीय, मिमूरी आदि अनेक नये राज्यों का विकास हुआ। ये प्रदेश कृषि के लिये बहुत उपयुक्त थे, और उनमें अमेरिका के श्वेताङ्ग लोग नीग्रो गुलामों के श्रम से बड़े-बड़े खेतों के निर्माण में तत्पर थे। अटलाण्टिक महासागर के तटवर्ती दक्षिणी प्रदेश कपास की खेती के लिये अत्यन्त उपयुक्त थे। व्यावसायिक क्रान्ति का असर अमेरिका पर भी पड़ रहा था, और वहाँ भी मूल कानूनों तथा कपड़े बुनने के लिये नये कारखानों का निर्माण हो रहा था। इन कारखानों में कपास की माग बहुत अधिक थी, और कपास की खेती के लिये उपयुक्त भूमि का बड़े-बड़े खेतों में परिवर्तित किया जा रहा था, जिनमें नीग्रो लोग गुलाम के रूप में बड़ी संख्या में काम करने लगे थे। पश्चिम की ओर जो अमेरिकन लोग निरन्तर आगे बढ़ रहे थे, उसमें एक हेतु यह भी था, कि मुद्गर पश्चिम के प्रदेश जंगलों से अच्छादित थे, और उन जंगलों में गेंदे बहुत से जन्तु प्रचुर संख्या में रहते थे, जिनकी फर (गाल) बहुत कीमती होती थी। इन जन्तुओं का शिकार कर इनकी फर को खूब ऊँची कीमत पर बेचकर अपना कमाने के आकर्षण में बहुत से साहसी अमेरिकन लोग पश्चिम की ओर आगे बढ़ने लगे, और धीरे-धीरे वे प्रशान्त महासागर तक पहुँच गये। इस विशाल भूखण्ड में जावागमन की मुविधा के लिये नये मार्गों का भी निर्माण किया गया। अमेरिका में नई वस्तियाँ बसाकर समृद्ध होने का अच्छा अवसर है, यह बात जब यूरोप के लोगों को ज्ञान हुई, तो वहाँ में बहुत से लोग अपनी मातृभूमि को सदा के लिये नमस्कार कर अमेरिका में बस जाने के लिये प्रेरित हुए। १८१४ के बाद उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध में यूरोप के प्रायः सभी राज्यों में लोकतन्त्र-वाद और राष्ट्रीयता की प्रवृत्तियाँ निर्वल हो रही थी, और मेटरनिख के नेतृत्व में राजा व कुलीन श्रेणियों के लोग स्वेच्छाचारी व निरकुश शासन की स्थापना के लिये प्रयत्नशील थे। इस दशा में मध्यश्रेणी के साहसी लोगों ने इसी बात में अपना हित समझा, कि वे अमेरिका जाकर अपने भाग्य को आजमावे। इटली, हॉलैण्ड, फ्रांस, ब्रिटेन, बाल्कन प्राय-द्वीप, और ग्रीस आदि सब जगह से लोग अमेरिका में जाकर बसने लगे, और नई वस्तियों के लिये जन व धन की कमी नहीं रही। इस समय में संयुक्तराज्य अमेरिका कितनी तेजी से उन्नति कर रहा था, इसका अनुमान इस बात से किया जा सकता है, कि जहाँ १७९० में उसकी जनसंख्या केवल चालीस लाख थी, १८१२ में वह बढ़कर साढ़े बहत्तर लाख हो गई थी। चालीस साल बाद १८५२ में यह जनसंख्या दो करोड़ तीस लाख तक पहुँच गई थी। १७९० से १८५२ तक केवल ६२ सालों में इस देश की जनसंख्या में छ गुना की वृद्धि हो गई थी। ज्यों-ज्यों अमेरिकन वस्तियों का पश्चिम और दक्षिण की ओर प्रसार होता जाता था, नये राज्यों का भी संगठन होता जाता था, और ये नये राज्य अमेरिका के केन्द्रीय सभ में सम्मिलित कर लिये जाते थे। १८१६ में इण्डियाना को, १८१७ में मिसिसिपी के राज्य को, १८१८ में इल्लिनीय को, १८१९ में एलेवामा को, १८२० में मेन को और १८२१ में मिसूरी को संयुक्तराज्य अमेरिका के सभ में सम्मिलित किया गया। यह प्रक्रिया इसी ढंग से वाद में भी जारी रही।

राष्ट्रीय एकरूपता का अभाव—संयुक्तराज्य अमेरिका के निवासी दो प्रकार के थे, गौराङ्ग और नीग्रो। देश की जनसंख्या की वृद्धि के साथ-साथ नीग्रो लोगों की आबादी भी निरन्तर बढ़ती जाती थी। इन नीग्रो लोगों की बहुसंख्या गुलाम थी। कपास, ईख, आदि की खेती जिस प्रकार अमेरिका की खाली पड़ी हुई उपजाऊ जमीन पर बड़े परिमाण में शुरू हुई थी, उससे इन नीग्रो गुलामों की मांग बहुत बढ़ गई थी। गौराङ्ग लोग इन्हें घृणा की दृष्टि में देखते थे और इन्हें नागरिकता का कोई भी अधिकार देने के लिये तैयार नहीं थे। यह बात अमेरिका में राष्ट्रीय एकता के विकास में बहुत बाधक थी। साथ ही, यद्यपि अमेरिका के विविध राज्य एक सघ में संगठित थे, पर इनके निवासियों में एकानुभूति का प्रायः अभाव था। विर्जिनिया के निवासी अपने को विर्जिनियन समझते थे अमेरिकन नहीं। यही बात न्यूयार्क, पेनसिलवेनिया, मेन, न्यू इङ्ग्लैंड, ज्योर्जिया, मैसैचुएट्स आदि अन्य राज्यों के निवासियों के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। एक सघ-सरकार और एक राष्ट्रीय झण्डे के रहते हुए भी विविध अमेरिकन राज्यों में एकता की भावना भलीभाँति विकसित नहीं हुई थी। यही कारण है, कि कनाडा की सीमा पर उत्पन्न हुई कतिपय समस्याओं के कारण जब १८१२ में संयुक्तराज्य अमेरिका को ब्रिटेन के साथ युद्ध करने की आवश्यकता हुई, तो अनेक अमेरिकन राज्यों ने इस युद्ध के लिये अपनी सेनाएँ भेजने से इनकार कर दिया। उन्नीसवीं सदी के मध्य तक भी अमेरिकन सघ के अन्तर्गत राज्य यह मानते थे, कि राज्य की प्रभुत्वशक्ति उनमें निहित है, सघ राज्य प्रभुत्व-शक्ति-सम्पन्न (सोविरन) नहीं है। यही कारण है, कि सघ सरकार द्वारा जारी किये हुए कानूनों व आदेशों को स्वीकार करने से भी वह अनेक बार इनकार कर देते थे।

## २. गृह-युद्ध

दासप्रथा की समस्या—उन्नीसवीं सदी में यूरोप में दासप्रथा के विरुद्ध भावना उत्पन्न हो चुकी थी। ससार के सम्य लोग यह अनुभव करने लगे थे, कि दासप्रथा मानव सभ्यता के प्रतिकूल है, और किसी मनुष्य को गुलाम बना कर रखना समुचित नहीं। यही कारण वीएना की कांग्रेस (१८१४) में दासप्रथा के विरुद्ध भी एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था, और यूरोप के अनेक राज्य इस प्रथा को नष्ट करने के लिये आवश्यक कार्रवाई कर रहे थे। अमेरिकन सघ-सरकार भी यह निश्चय कर चुकी थी, कि १८०८ के बाद नये नीग्रो गुलाम अफ्रीका से अमेरिका में नहीं लाये जा सकेंगे। पर यह बात अमेरिका के उन राज्यों लिये हितकर नहीं थी, जो कृषिप्रधान थे। इस समय अमेरिका के विविध राज्य आर्थिक दृष्टि से दो दिशाओं में उन्नति कर रहे थे—(१) उत्तरी राज्य व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में विशेष रूप से प्रगति कर रहे थे। इन राज्यों में बहुत से कल कारखाने स्थापित हो चुके थे, जिनमें सूती कपड़े, जूते, ऊनी वस्त्र, चमड़े का सामान व आदि की वस्तुएँ बड़े परिणाम में बन रही थी। इन कारखानों में मशीनों की सहायता का प्रयोग होता था, और इनमें आर्थिक उत्पत्ति के लिए गुलामों का विशेष उपयोग नहीं था। इन राज्यों के निवासियों के लिये यह सम्भव था, कि वे अपने क्षेत्र में दासप्रथा का

अन्त कर देना हानिकारक न समझे । (२) दक्षिणी राज्यों का आर्थिक जीवन कृषि पर आश्रित था । इनकी आमदनी का प्रधान साधन कपास, ईप आदि की खेती थी, जो इनमें बहुत बड़े परिणाम में होती थी । खेती के लिये उपयुक्त व यान्त्रिक शक्ति में संचालित होने वाले यन्त्रों का विकास उस समय तक नहीं हुआ था । अतः इन राज्यों के किसान अपनी खेती के लिये गुलामों के श्रम पर ही निर्भर करते थे । उन्हें यह समझ में नहीं आता था कि दासप्रथा का अन्त हो जाने के बाद वे अपना कृषिकार्य किस प्रकार सम्पन्न कर सकेंगे ।

दासप्रथा नष्ट की जाय या नहीं, इस प्रश्न पर उत्तर और दक्षिण के राज्यों में मतभेद निरन्तर बढ़ता गया । १८३० के बाद यह मतभेद कलह का रूप धारण करने लगा, और १८४० के बाद दासप्रथा की समस्या अमेरिकन राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बन गई । अटलान्टिक महासागर और मिमिसिपी नदी के बीच के सब दक्षिणी प्रदेशों में लोग दासप्रथा को एक स्वाभाविक व आवश्यक बात समझते थे । इन प्रदेशों में जावे के लगभग आबादी गुलामों की थी, और गौराङ्ग किसानों की खेती इन गुलामों पर ही आश्रित थी । बहुरसयक गुलामों को अमेरिका में आवाद हुए एक महीने अधिक समय हो चुका था, वे अंग्रेजी भाषा बोलते थे, ईसाई धर्म का अनुसरण करते थे, और पाश्चात्य गृहन-सहन को अपना चुके थे । पर उनकी स्थिति पूर्णतया दासों की थी, और उन्हें नागरिक स्वतन्त्रता का कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं था । दक्षिणी राज्यों के गौराङ्ग निवासियों को इसमें कोई भी आपत्तिजनक बात प्रतीत नहीं होती थी । वहाँ के सब राजनीतिक नेता, विचारक व पादरी लोग इस प्रथा को सर्वथा उचित व स्वाभाविक समझते थे, और नीग्रो लोगों के लिये भी लाभदायक बताते थे । इसके विपरीत उत्तरी राज्यों का कथन था, कि यह प्रथा जहाँ मानव सभ्यता के लिये लज्जा की बात है, वहाँ दक्षिणी राज्यों की आर्थिक उन्नति में भी बाधक है । इसका परिणाम यह हुआ, कि उत्तर में एक नये दल का संगठन हुआ, जे मानवता के इस कलक को मिटा देने के लिये अग्रसर हुआ । इस दल का प्रधान नेता विलियम लायड गैरिसन नाम का एक युवक था, जो अपने समाचार पत्र लिबरेटर द्वारा दासप्रथा का तीव्र विरोध करने में तत्पर था । इस दल के लोग दासप्रथा के विरुद्ध केवल प्रचार ही नहीं कर रहे थे, अपितु साथ ही दासों को इस बात के लिये उकसाने में भी तत्पर थे, कि वे अपने मालिकों के पान से भागकर स्वतन्त्रता प्राप्त कर लें । जो दास भागकर उत्तरी राज्यों में पहुँचने में समर्थ होते थे, यह दल उनकी पूरी तरह से सहायता करता था । १८३० से १८६० तक अकेले ओहयो राज्य में चालीस हजार से भी अधिक गुलाम लोग भागकर उत्तर में पहुँचे, और इस दल ने उनको आश्रय देने में कोई भी कसर उठा नहीं रखी । दासप्रथा विरोधी दल की शाखाएँ सब जगह स्थापित की गई थी । १८४० में इस दल की २००० के लगभग शाखाएँ अमेरिका के विविध नगरों व ग्रामों में खुल चुकी थी, और उनके सदस्यों की संख्या भी दो लाख के लगभग हो गई थी ।

१८४८ में कैलिफोर्निया के प्रदेश में सोने की खाने उपलब्ध हुई । सुवर्ण की प्राप्ति द्वारा समृद्ध होने के आकर्षणसे हजारों आदमी इस नये प्रदेश में जाकर बसने शुरू हुए । १८४९ में कैलिफोर्निया की जनसंख्या अस्सी हजार से ऊपर पहुँच गई । जब कैलिफोर्निया



को संयुक्तराज्य अमेरिका में सम्मिलित करने का प्रश्न उत्पन्न हुआ, तो दासप्रथा की समस्या ने बड़ा विकट रूप धारण किया। दासप्रथा के विरोधी कहते थे, कि इस नये राज्य में इस घृणित प्रथा को प्रविष्ट नहीं होने देना चाहिये। ऐसा प्रतीत होता था, कि कैलिफोर्निया के प्रश्न पर अमेरिका में गृहकलह का प्रारम्भ हुए बिना नहीं रहेगा। पर देश के नेताओं की वृद्धिमत्ता के कारण यह प्रश्न अधिक गम्भीर रूप धारण नहीं कर सका। कैलिफोर्निया के प्रश्न पर १८५० में समझौता हो गया, और दासप्रथा का प्रश्न भी कुछ समय के लिये दब गया।

इस समय अमेरिका के विचारशील लोगों में दासप्रथा के विरुद्ध भावना निरन्तर बढ़ रही थी। अनेक लेखक ऐसे साहित्य के निर्माण में तत्पर थे, जो इस घृणित प्रथा के प्रति जनता का ध्यान आकृष्ट कर रहा था। १८५२ में “टाम काका की कुटिया” नामक उपन्यास प्रकाशित हुआ, जिसकी तीन लाख प्रतियाँ एक साल से भी कम समय में विक गईं। इस एक पुस्तक ने अमेरिका में दासप्रथा के विरुद्ध भावना को उत्पन्न करने में जो कार्य किया, वह हजारों सभाओं, व्याख्यानो व पुस्तिकाओं द्वारा भी नहीं हुआ था। दासप्रथा के विरोध में जो लोग इस समय विशेष रूप से कार्य कर रहे थे, उन में अब्राहम लिंकन का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

**विद्रोह का प्रारम्भ**—१८६० में संयुक्तराज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का नया चुनाव होना था। लिंकन राष्ट्रपति पद के लिये उम्मीदवार था। वह सफल हुआ, और उसके राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाने पर दासप्रथा की समस्या ने अत्यन्त विकट रूप धारण कर लिया। दासप्रथा के पक्षपाती राज्यों को अब यह विश्वास हो गया, कि राष्ट्रपति लिंकन इस प्रथा को नष्ट करने के लिये सब प्रकार के उपायों को प्रयोग में लायेगा। २० दिसम्बर, १८६० को दक्षिणी कैरोलिना के राज्य में एक कान्वेंशन हुआ, जिसने यह घोषणा की, कि वह अमेरिकन संघ से पृथक् होता है, और संघराज्य से उसका अब कोई सम्बन्ध नहीं है। १ फरवरी, १८६१ को छ अन्य राज्यों ने भी विद्रोह का झंडा खड़ा किया। इन्होंने न केवल संयुक्तराज्य अमेरिका से अपने पृथक् हो जाने की घोषणा की, अपितु साथ ही यह भी उद्घोषित किया, कि हम अपना एक नया संघ बनाते हैं। इस संघ का एक संविधान भी तैयार कर लिया गया, और इसके राष्ट्रपति पद पर श्री डेविम को निर्वाचित कर दिया गया।

**युद्ध का सूत्रपात**—९ जनवरी, १८६१ को अमेरिकन संघराज्य का एक जहाज दक्षिणी कैरोलिना के समुद्र तट पर पहुँचा। वहाँ उस पर हमला किया गया। अब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी, कि युद्ध के अतिरिक्त किसी अन्य उपाय से इस विवाद को समाप्त कर सकना सम्भव प्रतीत नहीं होता था। राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो जाने के बाद अब्राहम लिंकन ने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की थी, कि संयुक्तराज्य अमेरिका के रूप में जो संघ स्थापित किया गया था, वह अखण्डनीय और शाश्वत है, उसकी अखण्डनीयता को किसी भी प्रकार नष्ट नहीं होने दिया जायगा। लिंकन ने विद्रोही राज्यों को वापस लाने के लिये एक स्वयं-सेवक सेना का संगठन किया। विद्रोही राज्यों ने भी अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा के लिये सेना एकत्र की, और दोनों पक्षों में युद्ध का प्रारम्भ हो गया।

**गृह युद्ध**—दासप्रथा के विरोधी उत्तरी राज्यों की कुल जनसंख्या इस समय २,२०,००,००० थी। उनमें २५ लाख सैनिक इस युद्ध के लिये एकत्र किये गये। दासप्रथा के पक्षपाती दक्षिणी राज्यों की कुल आबादी इस समय १०,००,००० थी, जिनमें से ३५,००,००० व्यक्ति गुलाम थे। उन्होंने भी बारह लाख से अधिक सैनिक युद्ध के लिये भरती किये। १८६१ में उत्तरी और दक्षिणी राज्यों में वाकायदा युद्ध शुरू हो गया, जो चार साल के लगभग तक जारी रहा। उत्तरी राज्य न केवल सैनिकों की संख्या की दृष्टि से लाभ में थे, अपितु व्यावसायिक उन्नति के कारण उनके पास युद्ध के साधनों की भी प्रचुरता थी। अतः युद्ध में उनकी विजय हुई। दक्षिणी राज्यों को इस बात के लिये विवश किया गया कि वे संपत्ति से पर्याप्त न हो सकें, और उसके अंग बनकर ही रहें। इस युद्ध में कुल मिलाकर ६,१८,००० आदमी काम जाये। उत्तरी राज्यों के ३,६०,००० सैनिक नाट हुए, और दक्षिणी राज्यों के २,५८,०००। युद्ध के कारण दोनों पक्षों का जो व्यय हुआ, वह पन्द्रह अरब रुपये में भी अधिक था। इतने धन और जन की हानि के बाद अमेरिका में यह बात तय हुई कि मध्य की एकता को कायम रखना है, और अमेरिकन राष्ट्रीयता विविध राज्यों की पृथक् भावना में अधिक ऊँचा ध्यान रखनी है।

अमेरिका के इतिहास में इस गृह-युद्ध को दो नामों से लिखा जाता है। उत्तरी राज्यों में इसे 'महान् विद्रोह' कहा जाता था, और दक्षिणी राज्यों में 'राज्यों का युद्ध'। अब भी अमेरिकन ऐतिहासिक इसे प्रायः इन्हीं नामों से लिखते हैं। पर हमने इसे गृह-युद्ध का नाम दिया है, क्योंकि यह संयुक्त राज्य अमेरिका की घरेलू लड़ाई थी, जिसमें अन्ततोगत्वा इस बात का अन्तिम रूप में निर्णय हो गया, कि इस देश में राज्य की प्रभुत्व-शक्ति सघ सरकार में निहित है, न कि उसके अन्तर्गत विविध राज्यों में। जब सघ सरकार दासप्रथा का अन्त करना चाहती है, तो किसी राज्य की सरकार को यह अधिकार नहीं है, कि वह उसके विरोध में खड़ी हो सके, या अपने राज्य को मध्य में पृथक् कर सके।

**दासप्रथा का अन्त**—१८६३ में राष्ट्रपति लिंकन ने एक घोषणा प्रकाशित की, जिसके अनुसार सब दासों को स्वतन्त्र कर दिया गया। शुरू में यह व्यवस्था की गई थी, कि गुलामों को स्वतन्त्र करते हुए उनके मालिकों को राज्य की ओर से हरजाना दिया जाय। कोलम्बिया के प्रदेश में जब सबसे पहले ३००० गुलामों को स्वतन्त्र किया गया, तो उनके मालिकों को प्रति गुलाम १००९ रुपये हरजाने के रूप में दिया गया था। पर बाद में हरजाने की व्यवस्था को हटा दिया गया। दक्षिणी राज्यों के लोग विद्रोही थे, अतः सघ सरकार ने यह उचित समझा, कि उनकी सम्पत्ति को जब्त कर लिया जाय, और क्योंकि गुलाम भी उनकी सम्पत्ति के अंग थे, अतः उन्हें भी जब्त करके स्वतन्त्र कर दिया गया, और इसके लिये उनके मालिकों को कोई हरजाना देने की आवश्यकता नहीं समझी गई।

**गृह-युद्ध में यूरोपियन राज्यों का रुख**—अमेरिका के इस गृह-युद्ध में यूरोप के प्रायः सभी राज्य उदासीन रहे। ग्रेट ब्रिटेन इस युद्ध से लाभ उठाने को उत्सुक था। वहाँ की सरकार ने दक्षिणी राज्यों के नये सघ को स्वीकार भी कर लिया था, और वह उन्हें

युद्ध में सहायता देने के लिये भी उद्यत थी। इसी प्रकार फ्रांस का राजा नैपोलियन तृतीय भी इस युद्ध से लाभ उठाकर अमेरिकन महाद्वीप में मैक्सिको की विजय के लिये योजना बना रहा था। पर इन दोनों राज्यों में ऐसे लोगों की कमी नहीं थी, जो दास-प्रथा को नष्ट करने के लिये राष्ट्रपति लिंकन के उद्योग से सहानुभूति रखते थे। दासों को स्वतन्त्रता प्रदान करने के सम्बन्ध में जो घोषणा लिंकन ने १८६३ में प्रकाशित की थी, उसके कारण यूरोप का लोकमत उत्तरी राज्यों के बहुत अनुकूल हो गया था। यूरोप के प्राय सभी राज्य इस समय तक दासप्रथा को नष्ट कर चुके थे। १८६१ में इस तक ने इस प्रथा का अन्त कर दिया था। इस दशा में दासप्रथा के पक्षपाती दक्षिणी राज्यों का पक्ष लेकर किसी भी यूरोपियन राज्य का अमेरिकन गृहयुद्ध में सम्मिलित हो सकना सुगम बात नहीं थी। इस कारण यूरोपियन राज्य इस युद्ध में उदासीन ही रहे।

**नीग्रो जाति से व्यवहार—**गृहयुद्ध की समाप्ति पर अमेरिका की सघ-सरकार ने ऐसे अनेक कानून पास किये, जिनका उद्देश्य नीग्रो लोगों को स्वाधीनता और समानता प्रदान करना था। १८६८ में संविधान में संशोधन करके नीग्रो लोगों को भी नागरिकता के अधिकार दिये गये। १८७० में एक अन्य कानून द्वारा नीग्रो लोगों को भी वोट का अधिकार प्रदान किया गया। पर स्वतन्त्र हुए गुलामों को अपना निर्वाह करने के लिए सहायता की आवश्यकता थी, अतः १८६५ में ही एक नये राजकीय विभाग की स्थापना कर दी गई थी, जिसका नाम था, 'स्वतन्त्र हुए मनुष्यों का विभाग' (फ्रीड मैनस् व्यूरो)। इस प्रकार अमेरिका में नीग्रो जाति के लोगों को समान समझने और उनके साथ समता का व्यवहार करने का प्रयत्न किया जा रहा था। पर दक्षिणी राज्यों में इनके प्रति जो विद्वेष का भाव विद्यमान था, उसे एकदम नष्ट नहीं किया जा सकता था। इसी लिए कू-क्लक्स-क्लान संस्था की वहा स्थापना हुई, जो नीग्रो लोगों पर अनेक प्रकार से अन्याचार करना ही अपना कर्तव्य समझती थी। साथ ही इन राज्यों में ऐसे भी अनेक कानून स्वीकृत किये गये, जिनके कारण नीग्रो लोगों को सामाजिक व सार्वजनिक जीवन में हीन व नीच समझा जाता रहा। होटलो, शिक्षणालयों, सिनेमाघरों व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर उनके साथ भिन्न व्यवहार होता रहा, और अव्वीसवीं सदी के मध्य भाग में भी अमेरिका में नीग्रो लोगों के प्रति अनुचित व्यवहार जारी है।

### ३ उन्नीसवीं सदी में अमेरिका की उन्नति

उन्नीसवीं सदी के मध्यभाग तक संयुक्तराज्य अमेरिका आर्थिक दृष्टि से बहुत उन्नत नहीं हुआ था। नगरों की दशा अभी बहुत पिछड़ी हुई थी। उस समय तक अमेरिका के नगरों में मन्द पानी को बाहर निकालने के लिये न नालियां बनी थी, न उनकी सड़को व गलियों में गमनी की समुचित व्यवस्था थी, और न सड़कें ही पक्की बनी थी। शहरों में पहरों के लिए पुलिस का भी ठीक इन्तजाम नहीं था। १८५७ में न्यूयार्क नगर में सबसे पहले एनी पुलिस तैनात की गई, जो बाकायदा बरदी पहनती थी। इस समय वाशिंगटन नगरी का यह दशा था, कि उसकी सड़को पर सूअर, गौंरें व सांड खुले तौर पर फिरा करते व बार लागो के पीने के लिए ताजा जल मिलने का भी कोई सतोपजनक प्रबन्ध नहीं

था। शहरों में जो गाड़िया चलती थी, उनमें घोड़े जुते थे। यद्यपि शहरों की दशा इतनी पिछड़ी हुई थी, पर उनकी आवादी में निरन्तर वृद्धि हो रही थी। नये शहरों का भी विकास हो रहा था। जो वस्तिया पहले छोटे-छोटे गावों के रूप में थी, वे अब शीघ्रता से बड़े नगरों का रूप धारण कर रही थी। यूरोप में लोग बहुत बड़ी संख्या में अमेरिका में बसने के लिए आ रहे थे। १८४८ के बाद जब यूरोप में एक बार फिर क्रांति की प्रवृत्तिया असफल हुई, और अनेक राज्यों में राजाओं का स्वैच्छाचारी शासन स्थापित हुआ, तो बहुत से यूरोपियन लोग अपने देशों की राजनीतिक दशा में असंतुष्ट हो कर सुदूर अमेरिका में जा बसने के लिए प्रेरित हुए। १८४५ में १८५५ तक के दस सालों में अकेले आयरलैंड में दस लाख में भी अधिक नर-नारी अमेरिका जाकर आवादी हुए। इस समय में जायसिंग लोग ब्रिटेन के विदेशी शासन में बहुत असंतुष्ट थे, और बड़ी संख्या में अपनी मातृभूमि का परित्याग कर अमेरिका जा रहे थे। इसी प्रकार इटली, ग्रीस, बोहेमिया आदि देशों में भी लाखों की संख्या में स्त्री-पुरुष प्रति वर्ष अमेरिका जाकर आवादी होते थे। एशिया में चीन और जापान में भी हजारों व्यक्ति हर साल अमेरिका जाया करते थे।

अमेरिका में जाकर इन विदेशी लोगों के लिए कार्य प्राप्त कर मकाना कठिन नहीं था। इस समय अमेरिका के विशाल भूखण्ड की आर्थिक दशा बड़ी तेजी के साथ उन्नत हो रही थी। १८५९ में वहाँ मिट्टी के तेल के कुओं का खोदा जाना शुरू हुआ। अमेरिका में तेल के विशाल व विस्तृत क्षेत्र विद्यमान थे, जिनमें कुओं का निर्माण कर मिट्टी का तेल निकाला जाना शुरू हुआ, और उसे माफ कर समार के विविध प्रदेशों में भेजा जाने लगा। कोयला, लोहा, सोना आदि की खानें भी इसी समय खोदी जानी शुरू हुईं। कृषि के लिये यान्त्रिक उपकरणों का प्रयोग प्रारम्भ हुआ, और अमेरिका की कपास बहुत बड़े परिणाम में ब्रिटेन आदि देशों में जाने लगी। १८६० से १९१० तक पचास वर्षों में अमेरिका में खेतों की सत्या तिगुनी हो गई। १९१० में जिस भूमि पर अमेरिका में खेती की जाती थी, उसका विस्तार ६३,५०,००,००० एकड़ था। यह विशाल भूमि प्रति वर्ष ६३,५०,००,००० बुशल गेहूँ, २,८८,६०,००,००० बुशल मक्की और १,१६,९०,००० गांठे कपास की उत्पन्न करती थी। ईख आदि की खेतों इससे पृथक् थी। अमेरिका में पशुपालन के व्यवसाय ने भी इस युग में असाधारण उन्नति की। पश्चिमी अमेरिका के सुविस्तृत चरागाहों में जो करोड़ों पशु पाले जाते थे, उनका उपयोग जहाँ दूध, मक्खन आदि के लिए था, वहाँ साथ ही मांस के लिए भी उनका प्रयोग होता था। जिस प्रकार इस समय कृषि के क्षेत्र में अमेरिका ने असाधारण उन्नति की, वैसे ही व्यापार और व्यवसाय के क्षेत्र में भी उसने अद्भुत कर्तृत्व का प्रदर्शन किया। विशेषतया, उत्तर और पूर्व के राज्यों में कल कारखानों का बड़ी तेजी से विकास हुआ। खानों और तैल-कूपों के विकास के कारण कल कारखानों के विकास में बहुत सहायता मिली, और लोहा, फौलाद और सूती ऊनी व रेशमी वस्त्र आदि के व्यवसायों के विकास के कारण देश के आर्थिक जीवन में एक क्रांति सी उपस्थित हो गई। कृषि और व्यवसाय की उन्नति से अमेरिका के ग्रामों और नगरों के स्वरूप में भारी परिवर्तन आना शुरू हुआ, और

कुछ ही समय में न्यूयार्क, वाशिंगटन, शिकागो आदि नगरों के स्वरूप आमूल चूल रूप से परिवर्तित हो गये। वैज्ञानिक आविष्कारों ने इस परिवर्तन में भारी सहायता की। रेलवे लाइनों के निर्माण से एक प्रदेश में दूसरे प्रदेशों में आना-जाना बहुत सुगम हो गया, और देश के आन्तरिक व बाह्य व्यापार में बहुत सुविधा हो गई। डायनमो द्वारा विजली उत्पन्न करने के सिद्धान्त का परिज्ञान १८३१ में ही हो चुका था। १८४४ में विजली के खम्बे अमेरिका में यत्र-तत्र दिखाई देने लगे थे, और विजली की तारों का सर्वत्र जाल सा बिछना शुरू हो गया था। १८७६ में टेलीफोन यन्त्र का आविष्कार हुआ, और इससे व्यापार व्यवसाय की उन्नति में बहुत सहायता मिली।

इसमें सन्देह नहीं, कि उन्नीसवीं सदी के अन्त तक संयुक्त राज्य अमेरिका उन्नति के मार्ग पर बहुत अधिक आगे बढ़ गया था, और वह संसार के अत्यधिक उन्नत देशों में गिना जाने लगा था। गृहयुद्ध के बाद उन्नीसवीं सदी में अमेरिका ने कितनी तेजी के साथ उन्नति की, इसका अनुमान इससे किया जा सकता है, कि १८६० में जहाँ अमेरिका की सम्पूर्ण राष्ट्रीय सम्पत्ति १६,००,००,००,००० डालर थी, वहाँ १९१८ तक वह बढ़ कर ३,५०,००,००,००,००० डालर हो गई थी। इस काल में प्रतिवर्ष उत्पन्न होने वाले कोयले में ९७ गुना की, लोहे में ७१ गुना की, गेहूँ में ९ गुना की, कपास में ६ गुना की और मक्का में ५ गुना की वृद्धि हुई। अमेरिका में पूर्व से पश्चिम तक जाने वाली रेलवे का पहले पहल निर्माण १८६९ में हुआ था। पचास साल बाद १९१९ तक अमेरिका में रेलवे लाइन का इतना अधिक विस्तार हो था, कि वहाँ की रेलवे लाइन सारी पृथ्वी को दस बार घेर सकती थी।

आर्थिक उत्कर्ष के साथ-साथ अमेरिका की जनसंख्या में भी निरन्तर वृद्धि होती गई। हम पहले लिख चुके हैं, कि अठारहवीं सदी के अन्त में, इस देश की कुल आबादी चालीस लाख के लगभग थी। एक मदी बाद उन्नीसवीं सदी के अन्त तक यह जनसंख्या दस करोड़ के लगभग तक पहुँच गई थी। इस प्रकार तेजी से बढ़ती हुई आबादी को पाल मकान अमेरिका के लिये इसी कारण सम्भव था, क्योंकि वहाँ कृषि और व्यवसाय के लिये अपार क्षेत्र विद्यमान था।

## ४ संयुक्त राज्य अमेरिका की राजनीति

जिम समय अमेरिकन उपनिवेशों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह कर स्वतन्त्रता प्राप्त की, तब (१७७६ में) उनकी संख्या केवल तेरह थी। १८२९ तक संयुक्त-राज्य अमेरिका के अन्तर्गत राज्यों की संख्या बढ़कर छत्तीस तक पहुँच गई थी। ज्यों-ज्यों प्रशासन महाभाग की तरफ पश्चिम में वसतिपा वसती गई, इन राज्यों की संख्या भी बढ़ती गई। इन समय इन राज्यों की संख्या ४८ है। १९१२ ई० तक पूरे ४८ राज्य अमेरिका के मध्य में सम्मिलित हो चुके थे। इन सब राज्यों का क्षेत्रफल अखण्ड भारत के दुगुने के लगभग है, यद्यपि उनकी जनसंख्या भारत की अपेक्षा तिहाई से भी कुछ कम है।

साम्राज्य विस्तार—पर अमेरिकन लोगों को अपने इस विशाल भूखण्ड में भी संतोष नहीं था। यद्यपि इस मुविम्बूत देश में उन्हें खेती, व्यवसाय आदि के विकास का अपरिमित

अवसर था, तथापि वे साम्राज्य विस्तार के लिये प्रवृत्त थे। १८६७ में अमेरिका ने स्पेन से अलास्का के प्रदेश को क़य कर लिया। अलास्का का प्रदेश उत्तरी प्रशान्त महासागर में स्थित है, और इसे ज़रिगत रू लेने में अमेरिका को एक ऐसा भूगण्ट प्राप्त हो गया, जो उसके अपने क्षेत्र में बाहर है। कुछ समय बाद उसने पमोआ के द्वीप पर अपना अधिकार स्थापित किया। १८९८ में हवाई द्वीप अमेरिका के प्रभुत्व में आ गया। उसी समय प्रशान्त महासागर में स्थित मिटवे और वेक सदृश छोटे द्वीपों पर भी अमेरिका ने कब्ज़ा किया। स्पेन और अमेरिका के युद्ध के बाद (१८९८) स्पेन पर अमेरिका का प्रभुत्व स्थापित हुआ, और पोटा रीको उसके हाथ में आ गया। स्पेन और अमेरिका के इसी युद्ध के बाद फिलिपीन, द्वीपसमूह स्पेन की अधीनता में मुक्त होकर अमेरिका के साम्राज्य के अन्तर्गत हुआ। इस द्वीप समूह में ३१४१ द्वीप सम्मिलित हैं, और उनकी जनसंख्या एक करोड़ से अधिक है। फिलिपीन के लोग अमेरिका के शासन में बहुत असंतुष्ट थे। उसलिये उन्होंने १९०० में विद्रोह किया, पर यह सफल नहीं हो सका, और अमेरिकन शासकों ने इसे बुरी तरह से कुचल दिया। १९१७ में विर्जिन द्वीप को अमेरिका ने डेन्मार्क में प्राप्त किया, और इस प्रकार अमेरिका का साम्राज्य निरन्तर उन्नति करता गया। चीन में भी अमेरिका ने व्यापार आदि की अनेक सुविधाएँ व विशेष अधिकार प्राप्त किये।

**पनामा कैनल का निर्माण**—उन्नीसवीं सदी में संयुक्त राज्य अमेरिका इस बात के लिये बहुत उत्सुक था, कि मध्य अमेरिका में एक ऐसी नहर का निर्माण करे, जिनमें कि अटलाण्टिक सागर से प्रशान्त महासागर को जाने के लिये दक्षिणी अमेरिका का चक्कर काटने की आवश्यकता न रहे। ऐसी नहर के न होने में अमेरिकन जहाजों को पूर्व में पश्चिम की ओर जाने के लिये दक्षिणी अमेरिकन महाद्वीप का चक्कर मारना अनिवार्य था, और इसमें समय व धन का व्यर्थ अपव्यय होता था। मैक्सिको के दक्षिण में पनामा के निचले सिरे पर जहाँ उत्तरी और दक्षिणी अमेरिकन महाद्वीप आपस में मिलते हैं, स्थल इतना कम चौड़ा है, कि उसके बीच में एक नहर का निर्माण करने में प्रशान्त और अटलाण्टिक सागरों को सुगमता से मिलाया जा सकता है। १८८१ में फ्रेंच पनामा कम्पनी ने नहर बनाने के कार्य को अपने हाथ में लिया। पर आठ साल के निरन्तर प्रयत्न के बाद भी इसमें उसे सफलता नहीं हुई। इसी बीच में १८९८ में स्पेन और अमेरिका का युद्ध हुआ, जिसमें अमेरिकन लोगों ने इस नहर के निर्माण की आवश्यकता को और भी अधिक तीव्रता के साथ अनुभव किया। १९०३ में पनामा में एक स्वतन्त्र रिपब्लिक की स्थापना हो गई थी, और इस नई रिपब्लिक को संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता व सरक्षा प्राप्त थी। पनामा ने उस स्थान को संयुक्त राज्य अमेरिका को स्थिर रूप से पट्टे पर देना स्वीकार कर लिया, जहाँ पर कि नहर का निर्माण किया जाना था। यह प्रदेश लम्बाई में दस मील था। १९०४ में पनामा कैनल का निर्माण प्रारम्भ हुआ और १९१४ में यह कार्य पूर्ण हो गया। यद्यपि इसमें कुल मिलाकर एक अरब के लगभग रुपये का व्यय हुआ, पर इस नहर के निर्माण के कारण न्यूयार्क से जलमार्ग द्वारा मन्फ्रासिस्को जाने की दूरी में ७८०० मील की बचती हो गई। अब इस नहर से हजारों जहाज प्रतिवर्ष आते जाते हैं। अमेरिका के लिये इसका उतना ही महत्त्व है, जितना कि एशिया और यूरोप के लिये स्वेज कैनल का है।

**पैन अमेरिकन आन्दोलन**—इस इतिहास में हम अनेक बार मुनरो-सिद्धान्त का उल्लेख कर चुके हैं। मध्य और दक्षिणी अमेरिका के अनेक राज्य पहले स्पेन के साम्राज्य के अन्तर्गत थे। उन्होंने स्पेन की अधीनता से मुक्त होकर स्वतन्त्रता प्राप्त की थी। वीएना की कांग्रेस (१८१४) के बाद जब यूरोप के अनेक स्वेच्छाचारी राजाओं ने क्रान्ति की प्रवृत्तियों को कुचलने के उद्देश्य से होर्ली एलायन्स (पवित्र मित्रमण्डल) का निर्माण किया, तो संयुक्त राज्य अमेरिका को यह डर लगा, कि वही यूरोप के ये निरंकुश राजा अमेरिकन राज्यों की स्वाधीनता में भी स्पेन के राजा का पक्ष लेकर हस्तक्षेप न करें। इसलिये १८२३ में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति मुनरो ने इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था, कि पुरानी दुनिया (यूरोप) के शासक नई दुनिया (अमेरिका) के मामलों में किसी भी प्रकार हस्तक्षेप न करें। बीसवीं सदी के शुरु में राष्ट्रपति हजवेल्ट ने इस मुनरो सिद्धान्त की व्याख्या करते हुए यह प्रतिपादित किया था, कि अमेरिकन महाद्वीप में यूरोप के हस्तक्षेप को रोकने के लिये यह आवश्यक है, कि संयुक्त राज्य अमेरिका इस महाद्वीप के अन्य राज्यों की रक्षा का भार अपने ऊपर ले। इसके बिना मुनरो सिद्धान्त को क्रिया में परिणत कर सकना सम्भव नहीं है। इसी नीति का अनुसरण कर संयुक्तराज्य अमेरिका ने मध्य व दक्षिणी अमेरिकन महाद्वीप के अनेक छोटे पर स्वतन्त्र राज्यों पर अपना संरक्षण व नियन्त्रण स्थापित करना प्रारम्भ किया। पनामा कैनल का प्रदेश और पोटो रीको तो सीधे उसके अधिकार में थे ही, क्यूबा पर भी उसका आधिपत्य स्थापित था। अब सातों दोमिंगो और हैदती के राज्यों पर भी संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपना संरक्षण कायम कर लिया। निकारगुआ और हान्ड्रस के स्वतन्त्र राज्यों की आर्थिक नीति पर भी अमेरिका ने अपना आर्थिक नियन्त्रण स्थापित किया, और इस प्रकार अनेक स्वतन्त्र राज्य उसके प्रभाव में आ गये। इस प्रक्रिया द्वारा उस आन्दोलन का प्रारम्भ हुआ, जिसे 'पैन-अमेरिकन' कहा जाता है, और जिसका उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सम्पूर्ण अमेरिकन महाद्वीप के राज्यों व संयुक्तराज्य अमेरिका के नेतृत्व में एक सूत्र में संगठित करना है।

**अमेरिका और यूरोप**—संयुक्तराज्य अमेरिका की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का आधारभूत सिद्धान्त यह था, कि यूरोप के देश अमेरिकन महाद्वीप के मामलों में हस्तक्षेप न करें, और विदेशी मामलों में अमेरिकन महाद्वीप के विविध राज्य संयुक्तराज्य के नेतृत्व को स्वीकार करें। इस सिद्धान्त का यह परिणाम हुआ, कि यूरोप के शक्तिशाली राज्य अमेरिका में अपने प्रभाव का विस्तार करने के प्रयत्न में बचने लगे। जिन दिनों अमेरिका में गृहयुद्ध जारी था, फ्रांस के राजा नैपोलियन तृतीय ने मैक्सिको में अपने साम्राज्य का विस्तार करने का उद्योग किया। नैपोलियन तृतीय के इस प्रयत्न के सम्बन्ध में हम पहले लिख चुके हैं। उसे आशा थी, कि गृहयुद्ध में दक्षिणी राज्यों की विजय होगी, और संयुक्त राज्य अमेरिका की शक्ति क्षीण हो जायेगी। इसी आशा से उसने मैक्सिको में अपनी सेनाएँ भेजी थीं। हम पहले बता चुके हैं, कि नैपोलियन को अपने प्रयत्न में सफलता नहीं हुई, और वह मैक्सिको को अपनी अधीनता में लाने में असमर्थ रहा। उन्नीसवीं सदी के अन्त में (१८७५ में) वेनेजुएला की सीमा के प्रश्न पर ब्रिटेन और अमेरिका में बहुत विवाद उत्पन्न हुआ। पर अमेरिका ने मुनरो सिद्धान्त की दुहाई देकर ब्रिटेन को इस बात के लिये

विवश किया, कि इस अगड़े का निवटारा पच-निर्णय द्वारा किया जाय । इस अवसर पर संयुक्तराज्य अमेरिका के सेक्रेटरी आफ स्टेट श्री ओलने ने स्पष्ट रूप में घोषणा की थी, कि “उम अमेरिकन महाद्वीप पर आज संयुक्तराज्य अमेरिका की प्रभुता प्रायः निर्विवाद है।” अमेरिका अपनी इस नीति में सदा सफल रहा, और स्पेन के साम्राज्य के पतन के बाद कोई यूरोपियन राज्य अमेरिकन महाद्वीप में हस्तक्षेप नहीं कर सका ।

मुनरो पिढान्त के कारण जिस प्रकार यूरोपियन राज्यों ने अमेरिकन महाद्वीप के मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया, वैसे ही संयुक्तराज्य अमेरिका भी यूरोप की राजनीति में अपने को पृथक् रखता रहा । मानवता के नाम पर उमने कतिपय अवसरों पर यूरोप के राज्यों को अपने विचारों में अवश्य अवगत किया और उनकी कतिपय नीतियों का प्रतिवाद भी किया, पर यूरोप के अगड़ों में वह प्रायः अलग ही रहता रहा । पृथक् रहने की नीति का सबसे पहले उल्लेख १७१८-१८ के महायुद्ध में हुआ, जब कि संयुक्तराज्य अमेरिका ने जर्मनी के विरुद्ध मित्रराष्ट्रों के पक्ष में शामिल होना स्वीकार किया । इस महायुद्ध के बाद अमेरिका अपने को यूरोप की राजनीति में पृथक् नहीं रख सका है । नई वैज्ञानिक उन्नति के कारण मनुष्य ने देश और काल पर ऐसी अनाधारण विजय प्राप्त कर ली है, और ससार के विविध देश एक दूसरे में इतने समीप आ गये हैं, कि अब अमेरिका के लिये यह सम्भव नहीं रहा है, कि वह अपने को यूरोप व एशिया की राजनीति में पूर्णतया पृथक् रख सके ।



चौबीसवाँ अध्याय

## साम्यवाद की नई लहर

### १ सामाजिक सगठन सम्बन्धी नये विचार

सन् १७५० से १८५० तक, एक शताब्दी के काल में यूरोप में विज्ञान, शिल्प और व्यवसाय के क्षेत्र में जो भारी प्रगति हुई थी, उसका सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह था, कि मध्यकाल के जागीरदारों की अपेक्षा पूँजीपतियों का महत्व अधिक बढ़ गया था। इनके पास धन, वैभव और शक्ति—सब कुछ थे। इनके अतिरिक्त डाक्टर, वकील, इंजीनियर, व्यापारी, प्रोफेसर, सम्पादक, दूकानदार आदि के रूप में जो एक शिक्षित मध्यश्रेणी विकसित हो गई थी, वह धन में पूँजीपतियों की अपेक्षा हीन होती हुई भी बुद्धि और ज्ञान में उनकी अपेक्षा किसी प्रकार भी कम नहीं थी। शिक्षा और ज्ञान के विस्तार के साथ इस श्रेणी ने यह विचार करना प्रारम्भ कर दिया था, कि क्या समाज में पूँजीपतियों का प्रभुत्व और मजदूरों की गरीबी व असहायपन उचित और न्याय्य है। साथ ही, मजदूर श्रेणी के लोग भी शहरों में निवास करने के कारण अब शिक्षा से सर्वथा वंचित नहीं रहे थे। धीरे-धीरे व अपने अधिकारों व दुर्दशा का अनुभव करने लगे थे, और यह सोचने लगे थे, कि क्या समाज का वर्तमान सगठन न्याय और औचित्य पर आश्रित है।

फ्रांस की राज्यक्रान्ति के बाद यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के साथ-साथ लोकतन्त्रवाद की लहर भी जोर पकड़ रही थी। राज्य में किसी एक व्यक्ति या श्रेणी का प्रभुत्व न होकर माधारण जनता का शासन होना चाहिये, यह विचार प्रायः सबको स्वीकार्य था। परन्तु माधारण जनता की समस्या केवल वोट का अधिकार मिल जाने में ही हल नहीं हो जाती। राजनीतिक स्वतन्त्रता के साथ-साथ आर्थिक स्वतन्त्रता भी होनी चाहिये, और यदि राजनीतिक दृष्टि से सब नागरिक समान हैं, तो आर्थिक दृष्टि से भी उनकी विषमता नष्ट होनी चाहिये, ये विचार धीरे-धीरे सिर उठाने लगे थे। स्वेच्छाचार और एकतन्त्र शासन के विरुद्ध जो लहर फ्रांस में शुरू हुई थी, वह केवल राजनीतिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रह सकती थी। यह स्वाभाविक था, कि पूँजीपतियों के एकाधिपत्य के विरुद्ध भी आवाज بلند हो, और लग एक नये सामाजिक सगठन का स्वप्न देखने लगे। वस्तुतः फ्रांस की राज्यक्रान्ति एक लहर के समान थी, जो सब विघ्न बाधाओं का मुकाबला करते हुए निरन्तर आगे बढ़ती जाती है। उसने जिन प्रवृत्तियों को जन्म दिया था, वे केवल राजनीतिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रह सकती थी। यदि स्वाधीनता, समानता और प्रभुत्व के सिद्धान्त राजनीतिक क्षेत्र में सही हैं, तो आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में भी उनका प्रयोग होना ही चाहिये। यही कारण है, कि अठारहवीं सदी के अन्त में

साम्यवादी विचारों को और अधिक बल मिला। १८४८ की क्रान्ति के समय विचारकों ने आर्थिक क्षेत्र में भी क्रान्ति का उद्घोष किया था। १७८९, १८३० और १८४८ की क्रान्तियों के अवसर पर भी नोयल बावेफ आदि कतिपय क्रान्तिकारियों ने इस बात का प्रबल रूप में प्रयत्न किया था, कि साम्यवादी सिद्धान्त की स्थापना की जाय।

## २ साम्यवाद का प्रारम्भ

**नोयल बावेफ**—साम्यवाद का प्रारम्भ अठारहवीं सदी में ही हो चुका था। १७९५ में नोयल बावेफ नामक एक लेखक ने लिखा था—“जब मैं देखता हूँ, कि गरीबों के तन पर न कपड़े हैं, और न पैरों में जूते, गरीब लोग ही कपड़े और जूते बनाने हैं, पर उन्हें ही ये उम्मेदाल के लिये नहीं मिलते, और जब मैं उन लोगों का खयाल करता हूँ, जो स्वयं कुछ भी काम नहीं करते, पर उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं, तो मेरा यह विश्वास दृढ़ हो जाता है, कि राज्य जब भी जनसाधारण के विरुद्ध कुछ लोगों का पड़यन्त्र मात्र है।” नोयल बावेफ ने ये उद्घार तब प्रकट किये थे, जब बुरा राजवश के एकतन्त्र स्वेच्छाचारी शासन का फ्रांस में अन्त हो चुका था, और राष्ट्रीय लोकतन्त्र शासन की स्थापना हो गई थी। नोयल बावेफ का खयाल था, कि सम्पूर्ण सम्पत्ति राष्ट्र की हो जानी चाहिये, और समाज से विपन्नता और गरीबी का जन्म होना चाहिये। उस दशा को लाने का उपाय यह है, कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो, तो उसकी सब सम्पत्ति पर राष्ट्र का स्वामित्व स्थापित कर लिया जाय। नोयल बावेफ ने अपने समाचार-पत्र द्वारा इन विचारों का खूब प्रचार किया। उसके विचार दूर-दूर तक फैल गये। अपने साम्यवादी विचारों में क्रिया में परिणत करने के लिये नोयल बावेफ ने पड़यन्त्र का भी आश्रय लिया। उसने एक गुप्त समिति संगठित की, जिसका नाम “समान लोगों की साजिश” था। जैकोबिन दल के अनेक सदस्य इसमें सम्मिलित थे। यह साम्यवादी व्यवस्था को स्थापित करने के लिये सब तैयारी कर चुकी थी, कि पुलिस को इसके पड़यन्त्र का पता चल गया। उसके प्रमुख नेता पकड़ लिये गये, और १७९६ में नोयल बावेफ भी गिरफ्तार कर लिया गया। अगले साल अपने अनेक साथियों के साथ उसे मृत्युदण्ड मिला। फ्रांस की लोकतन्त्र सरकार उसके विचारों को शान्ति और व्यवस्था के लिये खतरनाक समझती थी। निःसन्देह, नोयल बावेफ फ्रेंच साम्यवाद का पिता था।

**सा सिमो**—नोयल बावेफ को मौत के घाट उतार दिया गया, पर उसकी मृत्यु के साथ उसके विचारों की समाप्ति नहीं हो गई। धीरे-धीरे इङ्ग्लैण्ड और फ्रांस के विविध विचारकों ने उसी की विचारसरणी का अनुसरण कर लेख व ग्रन्थ लिखने शुरू किये, और साम्यवाद के विचार निरन्तर जोर पकड़ने लगे। इस युग के अन्य साम्यवादी विचारकों में हेनरी सा सिमो (१७६०-१८२५) बहुत प्रसिद्ध है। उसका विचार था, कि भूमि और पूँजी पर व्यक्तियों का स्वामित्व न होकर उन्हें राष्ट्र की सम्पत्ति होना चाहिये। विरासत की प्रथा को उड़ाकर सब सम्पत्ति पर राष्ट्र का स्वामित्व स्थापित किया जा सकता है। प्रत्येक मनुष्य को अपनी शक्ति व क्षमता के अनुसार काम करना चाहिये, और उसे अपनी आवश्यकता के अनुसार वेतन मिलना चाहिये, यह उसका मन्तव्य था। अपने विचारों

का प्रचार करने के लिये उसने अनेक ग्रन्थों की रचना की, जिनमें 'नई क्रिश्चियनिटी' सबसे प्रसिद्ध है। सा सिमो स्वयं एक समृद्ध व्यक्ति था, पर अपने विचारों का क्रिया में परिणत करने के उद्देश्य से उसने जो अनेक परीक्षण किये, उनमें उसकी सब सम्पत्ति नष्ट हो गई। चालीस वर्ष की आयु में उसे पचास रुपये मासिक वेतन पर नौकरी करने के लिये विवश होना पड़ा। वस्तुतः, सा सिमो एक विचारक मात्र था। उसमें यह क्षमता नहीं थी, कि अपने विचारों को क्रिया में परिणत करने के लिये एक नये आन्दोलन को जन्म दे सके। पर इसमें सन्देह नहीं, कि उसके विचारों ने फ्रांस में साम्यवाद के प्रादुर्भाव में बहुत सहायता पहुँचाई।

**फूरियर**—फूरियर (१७७२-१८३७) नाम के एक अन्य फ्रेंच विचारक ने साम्यवाद को क्रियात्मक रूप देने के लिये एक योजना भी प्रस्तुत की थी। उसका खयाल था, कि ऐसे छोटे-छोटे समाज बनाने चाहिये, जिनमें से प्रत्येक में १८०० के लगभग सदस्य हों। ये सब सदस्य मिलकर आर्थिक उत्पत्ति करें। सब एक साथ स्वतन्त्र, सुखी और शान्तिमय जीवन व्यतीत करें। सब को अपनी-अपनी आवश्यकता के अनुसार एक निश्चित भाग प्रदिश दी जाय। यह राशि देने के बाद जो कुछ बचे, उसे इस अनुपात से पूँजी, श्रम और विशेष योग्यता-सम्पन्न व्यक्तियों में बांट दिया जाय, कि जिनकी पूँजी लगी है, उन्हें दोष वचन का  $\frac{1}{3}$  भाग, श्रमियों को  $\frac{1}{3}$  भाग और विशेष योग्यता प्रदर्शित करने-वाले व्यक्तियों को  $\frac{1}{3}$  भाग मिल जाय। फूरियर की योजना को लोगो ने बहुत पसन्द किया। वसिय के समीप इस प्रकार के समाज की स्थापना भी १८३२ में कर दी गई, पर उसे सफलता नहीं मिली। बाद में फ्रांस और अमेरिका में अन्य भी अनेक समाज उसकी योजना के अनुसार स्थापित किये गये। पर वे भी ज्यादा समय तक कायम नहीं रह सके।

**रावर्ट ओवन**—इंग्लैण्ड में साम्यवाद का प्रारम्भ रावर्ट ओवन (१७७१-१८५९) द्वारा हुआ था। वह स्वयं एक धनिक व्यक्ति था, और स्काटलैण्ड में अनेक कपड़ों की मिलों में हिस्सेदार था। उसने अपनी मिलों में मजदूरों के साथ न्याय करने का प्रयत्न किया। उन्हें मनुष्यवत् दर देने मजदूरी दी गई, उनके निवास के लिये साफ सुथरे घर बनाये गये, उनके बच्चे के लिये पाठशालाये खोली गईं, और कारखानों में काम करने की हानत भी मजदूरों के अनुकूल मुखद बनायी गई। रावर्ट ओवन ने यह व्यवस्था की, कि उनकी मिलों में पूँजी पर पाँच फीसदी से अधिक मुनाफा न किया जाय। इतना मुनाफा देने के बाद जो कुछ बचे, उस सब को मजदूरों की दशा सुधारने में खर्च कर दिया जाय। इसके कारण यू. लनर्क, जहाँ रावर्ट ओवन की मिलें विद्यमान थी, एक आदर्श नगर बन गया। कहते हैं कि तीस साल तक इस नगर में कोई वारदात नहीं हुई। शराबखोरी की आदत लोगो में दूर हो गई, जो मजदूरों की दशा अत्यन्त सन्तोषजनक हो गई। इसमें सन्देह नहीं, कि रावर्ट ओवन एक क्रियात्मक सुधारक था। उसने व्यावसायिक कान्ति के कारण उत्पन्न हुए शोषण को दूर करने का सफल प्रयत्न किया, और इस कारण उसकी प्रसिद्धि दूर-दूर तक फैल गई। उसने अपना धन, मन, धन मजदूरों की दशा को सुधारने में लगाकर एक नया समाज का निर्माण करने का उद्योग किया। उसका विचार था, कि यू. लनर्क में जो प्रकार से एक आदर्श समाज का निर्माण हुआ है, वैसा ही अन्यत्र भी सब जगह हो,

और फिर विश्व भर के इस प्रकार के समाजों का एक मधु बना दिया जाय। इसी उद्देश्य से वह १८०५ में अमेरिका गया और इण्डियाना में न्यू हामनी नामक प्रदेश में अपने विचारों के अनुसार एक नव समाज की स्थापना की। पर इसमें उसे सफलता नहीं हुई। आखिर, १८२८ में वह लण्डन वापस लौट आया, और शेष जीवन को वहाँ रहकर अपने विचारों के प्रचार में व्यतीत किया।

उसी समय यूरोप में कनिंगहम जैसे विचारक उत्पन्न हुए, जो क्रिश्चियन सोशलिस्ट कहलाते हैं। इङ्ग्लैण्ड में उनका नेता चार्ल्स क्रिगमन्टे था। क्रिगमन्टे एक प्रसिद्ध साहित्यिक हुआ है, जिन्होंने अपने उपन्यासों में उन बुराइयों का सर्वांग रूप में चित्रण किया है, जो व्यावसायिक जीवन में गृही प्रतिस्पर्धा द्वारा उत्पन्न होती हैं। क्रिगमन्टे का कथन था, कि यदि ईसाई धर्म के सिद्धान्तों के अनुसार समाज का निर्माण किया जाय, तो उसका स्वल्प साम्यवाद के अनुरूप ही होगा।

**मजदूरों की दशा में सुधार का प्रयत्न**—फ्रांस और इङ्ग्लैण्ड के ये साम्यवादी एक आदर्श समाज की कल्पना कर उसे जनता के सम्मुख उपस्थित कर रहे थे। शिक्षित मध्य-श्रेणी के विचारों पर इस कल्पना का बहुत असर हुआ। ये साम्यवादी विचारक कहते थे, कि आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप न करने की नीति ठीक नहीं है। इनके कारण पूँजीपतियों को मजदूर वर्ग के शोषण का अवसर मिलता है, क्योंकि गरीब मजदूर शक्तिशाली धनिकों का मुकाबला नहीं कर सकते। राज्य का यह कर्तव्य है, कि ऐसे बान्धन बनाये जाएँ, जिनमें मजदूरों की दशा सुधरे और उन्हें निश्चित घण्टों में अधिक काम करने के लिये विवश न किया जा सके। उनके निवास की उचित व्यवस्था हो, उनके बच्चों की शिक्षा का प्रबन्ध हो, और कारखानों की दशा मजदूरों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचानेवाली न हो। फूरियर और रावर्ट ओवन ने जिस प्रकार के समाज की कल्पना की, उसमें मजदूरों की दशा को सुधारने के लिये विशेष ध्यान दिया गया था। यह बात उस समय की शिक्षित मध्य-श्रेणी को भी उचित जान पड़ी। उन्नीसवीं सदी के मध्य तक (१८३० और उसके बाद) इङ्ग्लैण्ड और फ्रांस—दोनों देशों में राजनीतिक शक्ति मध्य-श्रेणी के हाथ में आ गई थी। १८३२ के सुधार कानून के अनुसार इङ्ग्लैण्ड में मध्य-श्रेणी को वोट का अधिकार पूर्णरूप में प्राप्त हो गया था, और पार्लियामेन्ट में इस श्रेणी का प्रतिनिधित्व भी पर्याप्त मर्यादा में हो गया था। यही दशा फ्रांस में थी। इस मध्य-श्रेणी को यह भ्रमोभासि समझ में आता था, कि मजदूरों की दशा को सुधारने के लिये राज्य की ओर से कानून बनने चाहिये, और आर्थिक क्षेत्र में राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिये। पर इस समय मजदूर श्रेणी में और भी अधिक उग्र विचार प्रचारित होने लग गये थे, और गरीब सर्वमाधारण जनता साम्यवाद के एक नये स्वरूप का स्वप्न देखने लगी थी।

**लुई ब्ले**—इस नई विचारधारा का प्रवक्तृ लुई ब्ले (१८११-१८८२) था। इस फ्रेंच साम्यवादी का कहना था, कि राजनीतिक शक्ति मध्य-श्रेणी के हाथ में निकलकर सर्वमाधारण जनता के हाथों में आनी चाहिये, और वोट का अधिकार प्रत्येक मनुष्य को मिलना चाहिये। राजनीतिक सुधारों का उद्देश्य केवल यह है, कि सामाजिक सगठन में परिवर्तन होना सम्भव हो सके। राजनीतिक शक्ति प्राप्त करके मजदूरों को चाहिये,

कि वे सरकार, न्यायालय, मेना और अन्य सरकारी विभागों पर अपना कब्जा कर ले, अगर इस प्रकार प्राप्त हुई शक्ति का उपयोग व्यवसाय और समाज के क्षेत्रों में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने में करे। इन परिवर्तनों का स्वरूप यह होना चाहिये, कि कारखानों पर शक्तियों का स्वामित्व समाप्त होकर राष्ट्र का स्वामित्व स्थापित हो जाय। शुरु में राज्य के पास उतनी पूँजी नहीं होगी, कि वह सारे व्यवसायों का स्वयं मालिक हो सके। अतः नागरिकों को यह प्रेरणा करनी होगी, कि वे व्यवसायों में पूँजी लगाने। इसके लिये उन्हें मुद्र उचित दर से देना होगा। पर व्यवसायों का संचालन राज्य करेगा। उद्योग-ज्यो धीरे-धीरे बर्माई में राज्य के पास काफी धन एकत्र हो जायगा, व्यक्तियों की पूँजी की आवश्यकता नहीं रहेगी। उन दशा में राज्य व्यवसायों व कारखानों का पूर्णतया स्वामी हो जायगा, और मजदूर लोग स्वयं व्यवसाय का संचालन करने लगेंगे। कारखानों के विविध प्रयोजनों का चुनाव भी मजदूर करेंगे, और सच्चे अर्थों में आर्थिक लोकतन्त्र शासन स्थापित हो सकेगा। गुरु-गुरु में प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता व कार्यक्षमता के अनुसार मजदूरी मिलेगी, पर उद्योग-ज्यो शिक्षा बढ़ेगी, और सब मजदूर अपनी उत्तरदायिता नैतिकता समझने लगेंगे, मजदूरी की दर भी सबके लिये एक समान हो जायगी।

लर्ड व्हा के विचारों का मजदूर समाज पर बहुत अपर हुआ। उन्होंने अनुभव किया, कि उनका उद्धार इन्हीं विचारों से हो सकता है। हजारों की सख्या में मजदूर लोग लुई व्हा के अनुयायी हो गये, और वोट के अधिकार के लिये आन्दोलन करने लगे। उन्होंने यह भी कहना शुरू कर दिया, कि वैयक्तिक सम्पत्ति घोर पाप है, और कारखानों पर राज्य का अन्तः प्रभुत्व होना चाहिये। १८४८ में फ्रांस में फिर राज्यक्रान्ति हुई, जिसके कारण सब बालिग पुरुषों को वोट का अधिकार प्राप्त हो गया। सर्वसाधारण मजदूर जनता को वोट का अधिकार मिल जाने से सरकार पर उनका प्रभाव बहुत बढ़ गया, और नई सरकार ने स्पष्ट रूप से घोषणा की, कि मजदूरों की दशा में सुधार व उन्नति करना उसका प्रमुख उत्तर है। लर्ड व्हा को इस नयी सामयिक सरकार का सद्रम्य निश्चय किया गया, और उन्होंने जनता वनाई गई कि सरकारी रुपये में नये व्यवसाय जारी किये जावे, जिनमें कि वे कारखानों को रोजी दी जा सके। पर अभी तक भी सरकार में शिक्षित मध्य-श्रेणी का जोर था। मजदूरों को वोट का अधिकार मिल गया था, उनके कुछ प्रतिनिधि भी सरकार में जाये थे, पर वास्तविक शक्ति अभी मध्य-श्रेणी के हाथों में ही थी, और इस श्रेणी को क्रान्तिकारी परिवर्तन समझ में नहीं आता था, कि राज्य की ओर से नये कारखानों पर मजदूरों की मलाई की दृष्टि से स्थापित किये जाएँ। इन लोगों ने लर्ड व्हा की योजना का निरासा में परिणत नहीं होने दिया। परिणाम यह हुआ, कि मजदूरों में असन्तोष फैलता गया, और जर्मन पेरिस के निराश मजदूरों ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को सरकार के साथ बुझा दिया गया। लर्ड व्हा को आत्मरक्षा के लिये लगभग भागना पड़ा। सर्व-जनता में साम्यवाद की जो क्रान्तिकारी लहर शुरू हुई थी, उसका इस प्रकार से समाप्त हो गया।

## ३. कार्ल मार्क्स

जर्मनी में साम्यवादी आन्दोलन—सन् १८५० तक डब्ल्यू. एंड ऑर फ्राम में साम्यवाद का आन्दोलन बिल्कुल शिथिल पड़ गया था। पर शीघ्र ही जर्मनी में इसका पुनरुद्धार हुआ। जर्मनी में साम्यवादी आन्दोलन का प्रधान नेता कार्ल मार्क्स (१८१८-१८९८) था। इसे साम्यवाद का प्रधान व प्रमुख जाचार्य माना जाता है। पर उससे पूर्व भी जर्मनी में साम्यवाद का बीजारोपण हो चुका था। १८३० की क्रान्ति की लहर के बाद व्युत्पन्न ने एक गुप्त समिति की स्थापना की थी, जिसका नाम था—‘मनुष्य के अधिकार’। उस समिति को यह विश्वास था, कि राजनीतिक क्रान्ति के साथ-साथ सामाजिक क्रान्ति होना भी आवश्यक है। उसकी ओर से एक घोषणापत्र प्रकाशित हुआ था, जिसका प्रथम वाक्य यह था—‘झोपड़ियों में भुग्न शान्ति कायम हो और राजप्रासादों का विनाश हो’। १८३६ में पेरिस में काम करनेवाले जर्मन मजदूरों ने एक सम्मेलन कायम की, जिसका नाम ‘न्याय-संघ’ था। इस संघ में सामाजिक व आर्थिक समस्याओं पर बाद-विवाद हुआ करता था, और सदस्य लोग यह मोचा करते थे, कि समाज का संगठन फिर प्रसार परिवर्तित किया जाय, जिससे कि वह न्याय और औचित्य के अनुकूल बन सके। कार्ल मार्क्स और एन्जल्स इस संघ के प्रमुख सदस्यों में से थे। मजदूरों के अतिरिक्त पेरिस में शिक्षा पानेवाले जर्मन विद्यार्थी व अन्य शिक्षित लोग भी इस संघ के सदस्य बन गये थे। तीरे-बीरे यह संघ बहुत जोर पकड़ता गया। जर्मनी, ब्रिटेन, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड में भी इसकी शाखाएँ कायम हुईं।

लास्सेल—पेरिस में रहते हुए जो जर्मन लोग साम्यवाद की लहर के प्रभाव में आये उनमें फर्डिनेंड लास्सेल (१८२५-१८९८) का नाम उल्लेखनीय है। लास्सेल जानि ने यहूदी था, और स्वयं एक शिक्षित व समृद्ध व्यापारी था। पर लुई व्ला के सम्पर्क में आकर वह साम्यवाद का अनुयायी हो गया था। १८४८ में जब क्रान्ति की लहर फिर गूढ़ हुई, तो लास्सेल ने मार्क्स और एन्जल्स के साथ मिलकर जर्मनी के व्यावसायिक केन्द्र रूहराइन नदी की घाटी में विद्रोह फैलाने का प्रयत्न किया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और छ मास की जेल हुई। साम्यवादी विद्रोह का यह प्रयत्न तो असफल हो गया, पर लास्सेल ने अपने शेष जीवन को साम्यवादी विचारों के प्रसार में लगा दिया। लास्सेल का कहना था, कि राज्य का काम केवल पुलिस का ही नहीं है। बाह्य और आन्तरिक शत्रुओं से देश की रक्षा करना राज्य का प्रथम कर्तव्य अवश्य है, पर उनके कर्तव्यों की इतिवृत्ति यही पर नहीं हो जानी। राज्य का यह भी प्रधान कार्य है, कि अपने नागरिकों का अधिकतम कल्याण व हित सम्पादित करे। इसके लिये उसे समाज, कारखानों व सम्पूर्ण आर्थिक जीवन पर नियन्त्रण स्थापित करना होगा।

कार्ल मार्क्स का साम्यवादी घोषणा पत्र—कार्ल मार्क्स भी पेरिस में ही साम्यवादी आन्दोलन के प्रभाव में आया था। १८४८ के अन्तिम वर्ष में उसने एन्जल्स के साथ मिलकर एक साम्यवादी घोषणापत्र प्रकाशित किया, जिसमें मुख्यतया निम्नलिखित सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया था—

(१) मानव-समाज अनेक श्रेणियों में विभक्त है। इन श्रेणियों में निरन्तर संघर्ष चलता रहता है। एक श्रेणी पहले सम्पत्ति कमाकर समृद्ध हो जाती है, और फिर राजनीतिक शक्ति भी अपने हाथ में कर लेती है। पहले शक्ति जागीरदार सामन्तों के हाथ में थी। व्यावसायिक क्रान्ति के कारण समाज में पूँजीपतियों का प्रभुत्व हो गया। राजनीतिक शक्ति भी इन पूँजीपतियों के हाथ में आ गई। नगरों के विकास व समृद्धि के साथ-साथ शिक्षित मध्य श्रेणी का महत्त्व बढ़ने लगा, और उन्होंने आन्दोलन द्वारा राजनीतिक शक्ति को प्राप्त कर लिया। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी, जब तक कि मजदूर श्रेणी शिक्षित मध्य-श्रेणी के स्थान पर स्वयं सब शक्ति प्राप्त नहीं कर लेगी। एक जिन प्रकार १७८९ में पूँजीपति और मध्यश्रेणियों ने जागीरदार सामन्तों की सम्पत्ति व शक्ति को नष्ट किया, उसी प्रकार अब मजदूर श्रेणी के लोग मध्यश्रेणी की वैयक्तिक सम्पत्ति को नष्ट कर सारी सत्ता अपने हाथ में कर लेंगे।

(२) मजदूर साम्यवादी समाज तब बनेगा, जब कि विरासत की प्रथा नष्ट हो जायगी, पिता की मृत्यु के बाद उसका पुत्र पिता की सम्पत्ति को उत्तराधिकार में नहीं प्राप्त कर सकेगा। सम्पूर्ण भूमि, कल-कारखाने, माल-दुलाई और यातायात के साधन, व आर्थिक उत्पत्ति के अन्य सब साधन राज्य की सम्पत्ति बन जायेंगे और सम्पत्ति व्यक्तियों के स्वामित्व में रहेंगी ही नहीं। सब मनुष्यों को बाधित होकर श्रम करना होगा। श्रम विषय विना कोई मनुष्य ज़ामदनी नहीं प्राप्त कर सकेगा। सबको बाधित रूप से व मुफ्त शिक्षा दी जायगी, ताकि सब को योग्यता प्राप्त करने का समान अवसर मिले। फिर अपनी-अपनी योग्यता व सामर्थ्य के अनुसार सबको श्रम करना होगा। कारखाने व खेत सब राज्य की सम्पत्ति होंगे।

(३) इस नये साम्यवादी राज्य में सब मजदूरों को, चाहे वे मानसिक व बौद्धिक श्रम करने वाले हों, और चाहे शारीरिक श्रम करनेवाले, अपने श्रम की पूरी-पूरी कीमत संचायेंगे। क्योंकि सब लोगों को योग्यता व शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर होगा, तब सबको श्रम भी अपने सामर्थ्य के अनुरूप करना होगा। किसी को शिकायत का मौका नहीं होगा, और इसलिये समाज में श्रेणियों व वर्गों के संघर्ष का स्वयं अन्त हो जायगा। समाज में केवल एक ही श्रेणी रह जायगी—यह होगी मजदूर श्रेणी। यह होना परमावश्यक है, क्योंकि मानव-समाज की उत्पत्ति इसी प्रक्रिया में हो रही है। यदि शान्तिपूर्वक यह परिवर्तन न हो पाया, तो अच्छा है। अन्यथा, शक्ति का उपयोग करके यह परिवर्तन लाया होगा। यह हुए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि इतिहास की सब घटनाएँ इसी की ओर निदेश कर रही हैं।

(४) इस महत्वपूर्ण क्रान्ति के लिये विश्व भर के मजदूरों को आपस में मिलकर काम करना चाहिये। मजदूर श्रेणी के हितों को अन्य सब बातों के ऊपर रखना चाहिये। मजदूर श्रेणी के हित का अपेक्षा भी मजदूर श्रेणी के हितों का अधिक महत्त्व देना इस क्रान्ति के लिये आवश्यक है। इस समाजवादी क्रान्ति में साम्यवादी श्रेणियों का पक्ष लाना जनता के पक्ष खोलने के लिये है ही क्या, सिवाय अपनी गुलामी की जड़ों को तोड़ने का प्रयत्न ही होना है। सब दलों के विचारों और मजदूरों, आपस में

मिलकर एक हो जाओ।

इस घोषणापत्र को प्रकाशित कर कार्ल मार्क्स अपने माथियों के साथ जर्मनी वापस लौट गया। उन दिनों क्रान्ति की लहर फ्रांस से शुरू होकर सारे यूरोप को व्याप्त कर रही थी। जर्मनी भी उसके असर में नहीं बचा था। मार्क्स की स्वाभाविक इच्छा थी कि इस क्रान्तिकारी काल में अपने देश में काम करे पर जर्मनी में क्रान्ति को विरोध सकलना नहीं मिली। मार्क्स पर गजट्रोह का मुहदमा चलाया गया, और उसे देश-निकास दिया गया। अब वह लण्डन आकर बस गया। वहीं पर अपने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'यूर्जी' (कैपिटल) लिखकर पूर्ण की। यह पुस्तक साम्यवादियों की 'बाइबल' कही जाती है। साम्यवादी आन्दोलन के इतिहास में कार्ल मार्क्स द्वारा प्रकाशित उद्घोषणापत्र का बहुत ऊँचा स्थान है। यह माना जाता है, कि उसमें साम्यवाद का प्रामाणिक रूप से प्रतिपादन किया गया है। ससार की शायद ही कोई ऐसी भाषा हो, जिसमें इस उद्घोषणापत्र का अनुवाद न हुआ हो। इस उद्घोषणापत्र को अब तक भी साम्यवाद की आधारशिला के रूप में स्वीकार किया जाता है।

राबर्ट आबेन और लुई ब्ल्ला जैम पुगने साम्यवादियों में कार्ल मार्क्स का मन बहुत भिन्न है। मार्क्स के मतानुसार शक्ति सर्वसाधारण विमान मजदूर जनता के हाथ में आनी चाहिये। समाज में इस आधारभूत क्रान्ति को लाये बिना यदि व्यवसाय राज्य के अर्थात् हो जाए, तो उसका परिणाम यही होगा, कि वास्तविक शक्ति विहित मध्य-श्रेणी के हाथ में बनी रहेगी, और सर्वसाधारण मजदूर जनता उनके द्वारा शापित होती रहेगी। आवश्यकता इस बात की है, कि किसान मजदूर जनता एक श्रेणी के रूप में संगठित हो जाय और फिर सारी शक्ति को मध्य-श्रेणी के हाथ में छीन कर अपने हाथ में कर ले। जब राज्यशक्ति जनता के हाथ में आ जायगी, भूमि व पूँजी पर व्यक्तियों का स्वामित्व न रहेगा, और सब लोग श्रमी की हैसियत में काम करने लगेंगे, तो स्वयं एक ऐसे वर्ग-विहीन समाज का निर्माण हो जायगा, जिसमें कोई किसी का शोषण नहीं कर सकेगा।

**कार्ल मार्क्स की विचारधारा—**साम्यवादी उद्घोषणा में कार्ल मार्क्स ने जिन विचारों का प्रतिपादन किया था, जहाँ वे साम्यवाद की आधारशिला है, वहाँ मान ही उसके विविध ग्रन्थों में प्रतिपादित विचार आधुनिक युग के साम्यवादी विचारकों के लिये सर्वमान्य भी हैं। अतः उसके अन्य विचारों का भी यहाँ उल्लेख करना उपयोगी है। दार्शनिक क्षेत्र में प्रसिद्ध जर्मन विचारक हीगल ने जिन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया था, कार्ल मार्क्स ने आर्थिक वा सामाजिक क्षेत्र में उनका अनुसरण किया। उसका कथन था, कि क्रिया के बाद प्रतिक्रिया होती है, और फिर उसके कारण सन्तुलन स्थापित होता है। इस समय पूँजीवाद का युग है, यह आवश्यक है, कि इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया हो। इस प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप जब सन्तुलन होगा, तो साम्यवादी व समाजवादी (कम्युनिस्ट) समाज की स्थापना होगी। अतः पूँजीवाद का विनाश आर समाजवाद की स्थापना एक अवश्यम्भावी प्रक्रिया है।

कार्ल मार्क्स ने उस सिद्धान्त का भी प्रतिपादन किया, जिसे 'इतिहास की आर्थिक व्याख्या वा सिद्धान्त' कहा जाता है। इसके अनुसार मानव-समाज की विविध संस्थाएँ



व व्यवहार आर्थिक परिस्थितियों के परिणाम है। जिन्हें हम सत्य व सनातन सस्थाएँ समझते हैं, जिन्हें हम मनुष्य की प्रकृति का अग मानकर स्थिर व शाश्वत रूप से स्वीकार करते हैं, वे सब मनुष्य की आर्थिक दशा के विकास के साथ-साथ विकसित हुई हैं। आर्थिक परिस्थिति में परिवर्तन आने पर उनमें भी परिवर्तन आ जाना अवश्यम्भावी है। अपने मन्तव्य को स्पष्ट करने हुए कार्ल मार्क्स ने विशद रूप से प्रतिपादित किया, कि किस प्रकार सामन्तश्रद्धा के समय के जागीरदारों की शक्ति व पता का ह्रास व्यावसायिक क्रान्ति के कारण हुआ किस प्रकार पूँजीपति श्रेणी का विकास हुआ और किस प्रकार सब आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक शक्ति इस पूँजीपति श्रेणी के हाथों में आ गई। मनुष्य जाति का इतिहास वस्तुतः विभिन्न आर्थिक श्रेणियों के पारस्परिक संघर्ष का इतिहास है। पूँजीवाद के विकास द्वारा एक ऐसी नई श्रेणी का प्रादुर्भाव हो गया है, जो कारखानों में मशीन के पुर्जों के उभान कार्य करती है, जिसकी सत्था निरन्तर बढ़ रही है, और नगरों में निवास के कारण जो शिक्षा, ज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में निरन्तर उन्नति कर रही है। विशाल कल कारखानों के विकास के कारण उन लोगों की मर्गा निरन्तर कम हो रही है, जो कि व्यवसायपति हैं। धीरे-धीरे सब व्यवसायकति-पय स्वल्पसंख्यक व्यक्तियों के स्वामित्व में आते-जाते हैं, और जब कारखानों में काम करने वाले मजदूरों में अपनी श्रेणी की पृथक्ता की भावना भलीभाँति विकसित हो जायगी, तब इस श्रेणी के लिये व्यावसायिक जीवन पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेने में कोई भी कठिनाई नहीं रहेगी। पूँजीपति और मजदूर श्रेणियों में यह संघर्ष अवश्यम्भावी है, क्योंकि यह ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया के अनुरूप है। यह भी निश्चित है, कि इस संघर्ष में मजदूर श्रेणी की विजय होगी, क्योंकि यह बात भी ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया के अनुसार है। अतः कार्ल मार्क्स का कहना था, कि इस संघर्ष में “मजदूरों को कुछ भी खोना नहीं है, सिवाय उन जमीनों के जिनमें वे बंधे हुए हैं। उनके सम्मुख विजय का विशाल क्षेत्र खुला पड़ा है। अतः समग्र भर के मजदूरों, परस्पर मिलकर एक हो जाओ।”

कार्ल मार्क्स ने जिस मिद्धान्त का प्रतिपादन किया था, वह अब बहुत कुछ क्रिया में परिणत हो चुका है। रूस, चीन, चेको-स्लोवाकिया आदि में इसी के अनुसार क्रान्तियाँ हुई हैं। हिटलर और मुसोलिनी ने पूँजीपतियों और मजदूरों के हितों में समन्वय व साम-जस्य स्थापित करने का जो प्रयत्न किया, वह सफल नहीं हो सका।

कार्ल मार्क्स ने अपने इन विचारों को प्रसारित करने के लिये १८६४ में ‘मजदूरों के अन्तर्राष्ट्रीय संघ’ की स्थापना की। शीघ्र ही इसकी शाखाएँ यूरोप में सर्वत्र कायम हो गईं। सन् १८६६ में जिनेवा में इस संघ का प्रथम महासम्मेलन हुआ। फिर प्रतिवर्ष इसी प्रकार के वार्षिक सम्मेलन होने लगे। इनमें न केवल साम्यवादी मिद्धान्तों पर वाद-विवाद होते थे, पर उनका प्रचार करने के लिये क्रियात्मक उपायों पर भी विचार किया जाता था। फ्रांस की राज्यक्रान्ति के समय साम्यवाद के जिस मिद्धान्त का प्रचारोपण मात्र हुआ था, उन्नीसवीं सदी के मध्यभाग में वह यूरोप भर में एक प्रबल शक्ति बनता जा रहा था।

मजदूरों की दशा में सुधार—समाज के नये संगठन की कल्पनाओं के कारण यूरोप

की शिक्षित जनता इस बात की आवश्यकता को स्वीकार करने लगी थी, कि गरीब मजदूर श्रेणी की अवस्था में सुधार करने का प्रयत्न होना चाहिये। इसीलिए उन्नीसवीं सदी में डेङ्गलैण्ड, फ्रांस आदि देशों में बहुत से ऐसे कानून पास हुए, जिनका उद्देश्य काम करनेवाले मजदूरों की दशा में सुधार करना था। इन सुधारों की पीठ पर जो प्रेरक शक्ति थी, वह साम्यवादियों द्वारा प्रचारित वे विचारधाराएँ ही थीं, जो सामाजिक विपमता और उससे उत्पन्न अन्याय को बड़े विषम रूप में जनता के सम्मुख रख रही थी।

**नई प्रवृत्तियाँ—**उन्नीसवीं सदी के यूरोप में जो शक्तियाँ मानव-समाज के संगठन और स्वरूप को परिवर्तित करने के लिये काम कर रही थी, उनका यहाँ एक बार फिर निर्देश कर देना उपयोगी है। (१) व्यावसायिक क्रान्ति—इसके द्वारा मनुष्य के आर्थिक जीवन में भारी परिवर्तन आ रहा था। (२) राजनीतिक क्रान्ति—इसके द्वारा राष्ट्रीयता की भावना और लोकतन्त्र शासन की स्थापना की माग निरन्तर प्रबल हो रही थी। (३) नई विचार धाराएँ—शिक्षा और ज्ञान के प्रसार के कारण शिक्षित विचारकों ने यह सोचना प्रारम्भ कर दिया था कि विपमता और अन्याय का अन्त कर किस प्रकार एक सुखी समाज की रचना की जाय। इस नये समाज की रचना किस प्रकार हो, इस सम्बन्ध में विचारकों में भारी मतभेद थे, पर वर्तमान समाज को परिवर्तित करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में सब विचारक एकमत थे।

मध्यकाल की सामन्तपद्धति में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति कतिपय कुलीन जागीरदारों के हाथों में थी। व्यावसायिक क्रान्ति के कारण समाज में पूँजी-पतियों व व्यवसायी श्रेणियों का महत्व बढ़ने लगा। राज्यक्रान्ति की जो लहर अठारहवीं सदी के अन्त में यूरोप में शुरू हुई, उसने राज्यशक्ति को जागीरदारों में छीनकर इस मध्य-श्रेणी के हाथ में दे दिया। पर राजाओं के एकतन्त्र स्वेच्छाचारी शासन के अन्त आर कुलीन जागीरदार श्रेणी के प्रभाव व शक्ति के ह्रास से सर्वसाधारण जनता की दशा में विशेष परिवर्तन नहीं आया। यही कारण है कि उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध में जब ब्रिटेन में राज्यशासन का संचालन पार्लियामेंट द्वारा हो रहा था, और मन्त्रिमण्डल जनता द्वारा निर्वाचित पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी था, तब भी वहाँ के कारखानों में बच्चे और स्त्रियाँ दिन में बारह व सोलह घण्टे प्रतिदिन तक कार्य करने के लिये विवश थीं। उन्हें वोट का अधिकार प्राप्त नहीं था, और देश के शासन में उनकी कोई आवाज नहीं थी। वालिग पुरुषों की बहुसंख्या भी वोट के अधिकार से वंचित थी। उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में इस दशा में बहुत सुधार हुआ। वोट के अधिकार को सर्वत्र विस्तृत किया गया। बीसवीं सदी में स्त्रियों को भी प्रायः सर्वत्र वोट का अधिकार दिया गया। पर सर्व-साधारण मजदूर व किसान जनता की दशा में इससे भी विशेष उन्नति नहीं हुई। इसमें सन्देह नहीं कि, सर्वसाधारण जनता को वोट का अधिकार मिल जाने से अनेक देशों की राजनीति में मजदूर दल जोर पकड़ने लगा, और कतिपय राज्यों में राज्यशक्ति भी इस दल के हाथ में आ गई। पर साम्यवादी इतने से ही सन्तुष्ट नहीं हैं। वे राजनीतिक क्षेत्र के समान आर्थिक क्षेत्र में भी स्वाधीनता और समानता के सिद्धान्तों को क्रिया में परिणत करने के लिये प्रयत्नशील हैं।

## पुराना और नया साम्राज्यवाद

### १ यूरोप का मध्यकालीन साम्राज्यवाद

पन्द्रहवीं सदी तक यूरोप के लोग अपने महाद्वीप से बाहर के देशों से सर्वथा अपरिचित थे। उस समय आवागमन के साधनों में जरा भी उन्नति नहीं हुई थी। महासमुद्र के पार जाना-जाना बहुत कठिन था। दिग्दर्शक यन्त्र के भी आविष्कृत न होने के कारण सामुद्रिक व्यापार समुद्र-तट के साथ-साथ ही होता था। इस दशा में यह बात कल्पित भी नहीं की जा सकती थी, कि कोई यूरोपियन देश समुद्र पार कर एशिया व अफ्रीका के किसी देश को अपने अधीन करे, और इस प्रकार अपने साम्राज्य का विस्तार करे। अमेरिका तो उस समय तक ज्ञात भी न हुआ था। इस प्रकार मध्यकाल में यूरोपियन राज्यों के साम्राज्यवाद का अभिप्राय इतना ही था, कि वे एक दूसरे पर आक्रमण करे और यूरोप के अधिक से अधिक प्रदेश पर अपना शासन स्थापित करे। मध्यकालीन यूरोप में अनेक ऐसे राजा हुए हैं, जिन्होंने कि यूरोप के बहुत बड़े भू-भाग पर शासन किया। उस समय में साम्राज्यवाद का अभिप्राय यही था।

**व्यापार के पुराने मार्ग—**परन्तु पन्द्रहवीं सदी के अन्तिम भाग में एक नई प्रवृत्ति प्रारम्भ हुई। यूरोप और एशिया का पारस्परिक व्यापार बहुत समय से चला आता था। मलक्का, जावा और सुमात्रा से मसाले और भारतवर्ष से हीरे, मोती, कीमती रत्न, चन्दन, मलमल आदि विविध बहुमूल्य वस्तुएँ प्रभूत परिमाण में यूरोपियन देशों में जाती थी। इस व्यापार के दो मार्ग बहुत प्रसिद्ध थे। भारतवर्ष में कालीकट में उदय होता हुआ व्यापारिक माल मक्का पहुँचता था, और वहाँ ऊँटों के काफिलों पर लादकर उसे नील नदी पर पहुँचाया जाता था। नील नदी से होता हुआ यह माल कैरो और जेम्बेज़िया पहुँचता था, और वहाँ से इसे फिर वेनिस के जहाजों में लादकर भूमध्य-सागर के बन्दरगाहों में लाया जाता था। दूसरा रास्ता पर्सिया की खाड़ी से होकर जाता था। भारतवर्ष में कालीकट, गोआ और दिउ होता हुआ यह माल जोर्मुज पहुँचता था। वहाँ से यह दजला और फ़ारस नदियों के मुहानों पर स्थित प्रसिद्ध नगर बग़दाद में जाता था। बग़दाद में यह माल ऊँटों के काफिलों पर लदता था, और इस प्रकार पर्सिया माइनर व पश्चिमी बन्दरगाहों—एन्टियोक, बेरुत आदि में पहुँचा दिया जाता था। वहाँ से फिर इटालियन व्यापारी इस माल को भूमध्यसागर द्वारा यूरोप के विविध देशों में पहुँचा देने थे। इन व्यापारी मार्गों पर दृष्टिपात करने से यह बात स्पष्ट हो जायगी, कि जो पुराने और पर्सिया माइनर पर किस राज्यशक्ति का आधिपत्य है, वह बात उस देश-

पार की सुरक्षितता के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण थी। १४५३ में प्रसिद्ध तुर्क आक्रान्ता मुहम्मद द्वितीय ने कोन्स्टेन्टिनोपल को जीत लिया, और सम्पूर्ण एशिया माइनर पर अपना शासन कायम कर लिया। तुर्कों की इस विजय से पूर्व और पश्चिम के व्यापारी मार्ग सुरक्षित नहीं रहे। इससे पूर्व इन प्रदेशों पर अरब लोगों का शासन था। अरब लोग सम्यता की दृष्टि से बहुत उन्नत थे और स्वयं व्यापारी थे। वे व्यापार का महत्व अच्छी तरह समझते थे, और उसमें किसी भी प्रकार की बाधा नहीं डालते थे। परन्तु तुर्क लोग अभी जगली थे। सम्यता की दृष्टि से उन्होंने विशेष उन्नति नहीं की थी। अरबों के सम्य साम्राज्य पर उनके आक्रमण वही स्थिति रखते थे, जो कि भारत में गुप्त साम्राज्य पर हूणों के।

**नये मार्गों की खोज**—इन अभ्यस्त तुर्कों की विजयों से व्यापार के ये महत्वपूर्ण मार्ग बहुत कुछ बन्द हो गये, और यूरोपियन राज्यों को यह चिन्ता हुई, कि व्यापार के लिये किसी नये मार्ग का आविष्कार करें। इस क्षेत्र में पोर्तुगाल और स्पेन ने विशेष तत्परता प्रदर्शित की। उनके प्रयत्न में भारत आदि पूर्वी देशों तक पहुँचने के लिये जिस नये मार्ग का यूरोप के लोगों को परिज्ञान हुआ, और किम प्रकार कोलम्बस ने अमेरिकन महाद्वीप का पता लगाया, इस विषय पर इस इतिहास में पहले प्रकाश डाला जा चुका है।

**नई खोज के परिणाम**—पन्द्रहवीं सदी के अन्तिम भाग में यह जो नवीन प्रवृत्ति प्रारम्भ हुई थी, इसके दो अत्यन्त महत्वपूर्ण परिणाम हुए। (१) कोलम्बस को अचानक ही जो विशाल भूमिखण्ड व महाद्वीप प्राप्त हो गया था, वह बहुमूल्य खनिज पदार्थों की दृष्टि से बहुत समृद्ध था। यूरोपियन देशों ने इस नवीन सम्पत्ति में लाभ उठाना प्रारम्भ किया। कोलम्बस को स्पेन के राजा ने भेजा था, इसलिये स्वाभाविक रूप में नवीन प्राप्त हुए प्रदेशों पर स्पेन का आधिपत्य कायम हुआ। अमेरिका की खानों से अनन्त सोना व चादी स्पेन जाने लगी, और देखते-देखते स्पेन का वैभव दिन दूना रात चौगुना वृद्धि को प्राप्त होने लगा। स्पेन की होठ में अन्य यूरोपियन राज्य भी अमेरिका के विशाल भूखण्ड में सोना चादी की ढूँढ में फिरने लगे, और इन्हे इस नये महाद्वीप में अपने-अपने उपनिवेश बसाने की चिन्ता प्रारम्भ हुई। इस प्रकार यूरोपियन देशों में औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा का प्रारम्भ हुआ। यूरोप के लिये यह सर्वथा नई बात थी। (२) पोर्तुगीज लोगों ने सामुद्रिक व्यापार का जो नया मार्ग ढूँढा था, उससे पश्चिमी यूरोप के देशों ने एशिया में आना-जाना प्रारम्भ कर दिया। पहले वे व्यापार के उद्देश्य से ही भारतवर्ष, मोलक्को, चीन आदि पूर्वी देशों में आते-जाते थे। उन्होंने स्थान-स्थान पर अपनी व्यापारी कोठिया कायम की। सबसे पहले पोर्तुगाल और उसके बाद हालैण्ड, इङ्ग्लैण्ड और फ्रांस के व्यापारियों ने पूर्वी व्यापार पर अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयत्न प्रारम्भ किया। इस प्रयत्न के कारण विविध देशों में परस्पर संघर्ष का होना सर्वथा स्वाभाविक था। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के कारण वे आपस में लड़ने लगे। साथ ही कुछ समय बाद इन व्यापारियों को यह भी अनुभव हुआ, कि जिन एशियाई देशों के साथ वे व्यापार करते हैं, उनकी राजनीतिक दशा इतनी खराब है, कि उन पर सुगमता से अपना शासन भी कायम किया जा सकता है। व्यापार के लिये भी यह राजनीतिक

आधिपत्य बहुत उपयोगी होगा। इस अनुभव का परिणाम यह हुआ, कि विविध यूरोपियन देश एशियाई राज्यों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिये परस्पर सघर्ष करने लगे। यूरोप के इतिहास में यह विलकुल नई बात थी। एशिया में अपने साम्राज्य स्थापित करने का प्रयत्न, जिसका वास्तविक मूल व्यापारिक लाभ था, इसमें पूर्व यूरोपियन देशों ने नहीं किया था।

इस प्रकार यह ध्यान में रखना चाहिये, कि फ्रांस की राज्यक्रान्ति से पूर्व मध्यकाल में (पन्द्रहवीं सदी से अठारहवीं सदी तक) यूरोपियन साम्राज्यवाद के दो रूप थे— उपनिवेशों का विस्तार और पूर्वी देशों के साथ व्यापार। इन्हीं बातों को सम्मुख रखकर विविध यूरोपियन देश अपने-अपने साम्राज्यों का निर्माण कर रहे थे।

**मर्केन्टाइल सिस्टम**—वर्तमान समय में उपनिवेश विस्तार का जो लाभ समझा जाता है, इस पुराने काल में वह लोगों की दृष्टि में नहीं आया था। उस समय में उपनिवेश प्राप्ति के ये लाभ समझे जाते थे—(१) उपनिवेश से कच्चा माल यथेष्ट परिणाम में प्राप्त किया जा सकता है, अतः अपने उपनिवेश होने से कच्चे माल के लिये किसी अन्य देश पर आश्रित होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उपनिवेश को जिस तैयार माल की जरूरत हो, उसे वह अपने मूल देश से (जिसका कि वह उपनिवेश है) ही प्राप्त किया करे। इस प्रकार अपने निर्यात माल के लिये भी सुरक्षित बाजार प्राप्त हो सकेगा। (२) उस समय में यूरोप के लोग भी बहुत धर्मप्राण थे। ईसाइयत के प्रचार के लिये धर्म-प्रचारक सदा उत्सुक रहते थे। इन धर्म-प्रचारकों को उपनिवेशों के अमली निवासियों को ईसाई बनाने का सुवर्णावसर उपलब्ध होता था।

उपनिवेश विस्तार में आधारभूत विचार यह कार्य कर रहा होता था, कि उपनिवेश अन्य किसी देश के साथ व्यापार न कर सके, उसे जिस माल की बाहर से जरूरत हो, उसे अपने मूल देश से ही मगावे। इससे मूल देश का विदेशी व्यापार बढ़ता था, और उसे अपने निर्यात माल के लिये ऐसा बाजार प्राप्त हो जाता था, जहाँ कि वह यथेष्ट कीमत पर अपना माल बेच सकता था, क्योंकि उसका प्रतिस्पर्धी वहाँ अन्य कोई नहीं होता था। इसी प्रकार, उपनिवेश अपना कच्चा माल केवल मूल देश को ही भेज सकते थे। उनका खरीदार केवल एक होता था, इसलिये वह यथेष्ट कीमत पर—जो कि बहुत कम होती थी, क्योंकि खरीदार केवल एक ही था—कच्चे माल को खरीद सकता था। इस पद्धति से मूल देश बहुत लाभ उठाते थे। उपनिवेश आर्थिक लूट के साधनमात्र बने हुए थे। अनेक इस प्रकार के बान्धन बनाये गये थे, जिनसे कि उपनिवेश पूर्णतया मूल देश पर आश्रित रहे। इसी पद्धति को व्यापारिक पद्धति (मर्केन्टाइल सिस्टम) कहा जाता है।

**मर्केन्टाइल सिस्टम का ह्रास**—यह मर्केन्टाइल सिस्टम बहुत समय तक कायम नहीं रह सका। धीरे-धीरे इसमें क्षीणता आने लगी। इसकी क्षीणता के तीन मुख्य कारण थे—

(१) व्यावसायिक क्रान्ति—इंग्लैण्ड में अठारहवीं सदी के अन्तिम भाग में व्यावसायिक क्रान्ति प्रारम्भ हुई। उसके कारण बहुत बड़े परिमाण में माल तैयार होने लगा। बड़े बड़े कारखाने खुले, और उनके लिये कच्चे माल की जरूरत बहुत बढ़ गई। तैयार

माल की बिक्री के लिये भी उपनिवेशों के अतिरिक्त अन्य बाजारों की आवश्यकता अनुभव होने लगी। इङ्ग्लैण्ड का तैयार माल केवल उपनिवेशों में ही नहीं खप सकता था, और न उसके थोड़े से उपनिवेश कच्चे माल की माग को ही पूरा कर सकने थे। इसलिये मर्केन्टाइल पद्धति की सर्कीर्ण मर्यादाएँ टूटने लगी, और लोग व्यापार को विस्तृत करने की फिरार करने लगे।

(२) व्यावसायिक क्रान्ति के कारण जो नई परिस्थिति उत्पन्न हुई थी, उसका दृष्टि में रखकर अनेक अर्थशास्त्रियों ने एक नये ढंग में विचार करना प्रारम्भ किया। वे कहते थे, कि आर्थिक क्षेत्र में भी उसी प्रकार में प्राकृतिक व स्वाभाविक नियम कार्य कर रहे हैं, जैसे कि भौतिक क्षेत्र में। भौतिक क्षेत्र में मनुष्य क्या करता है? स्वाभाविक नियमों का पता लगाता है, और उन्हें जानकर उनके अनुकूल ही अपना कार्य करता है। उन नियमों का उल्लंघन करने का प्रयत्न वह नहीं करता। यदि मनुष्य प्रकृति के इन नियमों में हस्तक्षेप करेगा, तो नुकसान ही उठावेगा। इसी प्रकार आर्थिक क्षेत्र में भी जो स्वाभाविक नियम कार्य कर रहे हैं, मनुष्य को चाहिये कि उनका पता लगाए, और फिर उन्हें जानकर उनके अनुसार ही कार्य करे, उनमें हस्तक्षेप न करे। इङ्ग्लैण्ड में आइस म्मिथ आर फ़ास में तूँजों इस सिद्धान्त के प्रमुख प्रतिपादक थे। इनका खयाल था, कि आर्थिक क्षेत्र में 'खुला छोड़ दो' 'जैसा होता है होने दो', 'हस्तक्षेप न करो' की नीति का अनुसरण करना ही मानव समाज के लिये हितकर है। इस सिद्धान्त को दृष्टि में रखकर वे उन सब कानूनों का विरोध करते थे, जो कि 'मर्केन्टाइल पद्धति' की क्रिया में परिणत करने के लिये बनाये गये थे। ये विदेशी व्यापार पर किसी भी प्रकार का तट-कर लगाने के विरोधी थे, और मुक्त-द्वार वाणिज्य (फ्री ट्रेड) की नीति का समर्थन करते थे। इन अर्थशास्त्रियों के विरोध का परिणाम यह हुआ, कि लोग मर्केन्टाइल पद्धति में विमुख होने लगे।

(३) उपनिवेशों में जो लोग बसते थे, वे प्रायः मूल देश के निवासियों के ही वंशज होते थे। वे यह सहन नहीं कर सकते थे, कि उनका उपयोग दूसरों के लाभ के लिये किया जाए। मूल देश अपने लाभ के लिये उपनिवेशों का जिस ढंग से उपयोग करना चाहते थे, वह उपनिवेशवासियों को सह्य नहीं था। परिणाम यह हुआ, कि पहले ब्रिटेन के अमेरिकन उपनिवेशों ने विद्रोह किये, और उसके बाद स्पेन के दक्षिणी अमेरिकन उपनिवेशों ने। ये अपने विद्रोहों में सफल भी हुए। इनकी सफलता से मर्केन्टाइल पद्धति को बड़ा धक्का लगा। उपनिवेशों की स्वतन्त्रता को देखकर यूरोप के राजनीतिज्ञ सोचने लगे, कि उपनिवेश प्राप्ति के लिये इतने धन-जन का व्यय करना सर्वथा निरर्थक है। साथ ही, यूरोप में लोकतन्त्रवाद की जो नई लहर चल रही थी, वह इस सिद्धान्त का प्रतिपादन करती थी, कि प्रत्येक राष्ट्र को स्वभाग्यनिर्णय का अधिकार होना चाहिये। उपनिवेश भी इस लहर से अछूते नहीं रहे थे। वे स्वभाग्यनिर्णय के सिद्धान्त को सम्मुख रखकर यह कदापि सहन नहीं कर सकते थे, कि मूल देश उनके मामलों में हस्तक्षेप करे या उनकी रीति नीति का संचालन करे। इस दशा में यूरोप के राजनीतिज्ञों को उपनिवेश रखने का कोई विशेष लाभ दृष्टिगोचर नहीं होता था।

उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक 'मर्केंटाइल पद्धति' पर आश्रित यूरोप के पुराने औपनिवेशिक साम्राज्य प्रायः नष्ट हो गये थे। स्पेन का विशाल साम्राज्य अब पूर्णतया क्षीण हो चुका था। अमेरिका में क्यूबा और पोर्टो रिको के अतिरिक्त अन्य कोई प्रदेश उसके अधीन नहीं रहा था। प्रशान्त महासागर में स्थित फिलिपीन द्वीपसमूह तथा अफ्रीका के कुछ प्रदेश ही अभी तक भी उसके अधीन थे। अमेरिका में न्यू आम्स्टर्डम का उपनिवेश तथा अफ्रीका में केप कोलीनी भी हालैंड की अधीनता से निकल चुके थे। फ्रान्स का विशाल अमेरिकन साम्राज्य नष्ट हो गया था। ब्राजील पोर्तुगाल की अधीनता में मुक्त हो चुका था। सर्वत्र औपनिवेशिक साम्राज्यों का ह्रास हो गया था। इस अवस्था में केवल एक ही देश था, जो कि एक भावी महान् साम्राज्य की नींव डाल रहा था, यह देश था ब्रिटेन। यद्यपि अमेरिकन उपनिवेशों की स्वाधीनता के कारण ब्रिटेन के औपनिवेशिक साम्राज्य को बहुत क्षति पहुँची थी, तथापि सामुद्रिक आधिपत्य के संघर्ष में हालैंड और फ्रान्स को परास्त कर ब्रिटेन अब असाधारण उत्कर्ष को प्राप्त हो रहा था। पर ब्रिटेन का यह साम्राज्य मर्केंटाइल पद्धति के पुराने सिद्धान्त पर आश्रित नहीं था। यूरोप का पुराना साम्राज्यवाद अब समाप्त हो चुका था, उसका स्थान अब साम्राज्यवाद के नवीन सिद्धान्तों ने ले लिया था। ये सिद्धान्त कौन से थे, इस पर हम अब विचार करेंगे।

## २ नवीन साम्राज्यवाद का प्रारम्भ

**नये साम्राज्यवाद का स्वरूप**—उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में यूरोप में नवीन साम्राज्यवाद का प्रारम्भ हुआ। इसका स्वरूप मुख्यतया राष्ट्रीय तथा आर्थिक था। राष्ट्रीयता की जो नवीन भावना यूरोपियन राज्यों में उत्पन्न हुई थी, वह अब अत्यन्त प्रबल रूप धारण कर रही थी। यूरोपियन राज्य समझते थे, ससार में हमी सर्वोत्कृष्ट हैं, और सारी पृथिवी हमारे ही भोग तथा उत्कर्ष के लिये बनायी गई है। इस भाव से प्रेरित होकर वे अपने अतिरिक्त अन्य किसी को ससार में जीने नहीं देना चाहते थे। साथ ही, साम्राज्यवाद के विकास में उनका उद्देश्य आर्थिक भी था। यूरोप में कल-कारखानों के विकास ने जो व्यावसायिक क्रान्ति हुई थी, उसके कारण प्रत्येक देश अपनी आवश्यकता में अधिक पदार्थ उत्पन्न करने में समर्थ हो गया था। इन अतिरिक्त पदार्थों की बिक्री के लिये उन्हें बाजारों की आवश्यकता थी। इनकी ढूँढ में यूरोपियन राज्य उन्नति की दौड़ में पीछे रहते हुए अफ्रीकन तथा एशियाई देशों में अपने-अपने 'प्रभाव-क्षेत्र' बनाने की प्रयत्न करने लगे, और इसी प्रवृत्ति से एक नये प्रकार का साम्राज्यवाद विकसित हुआ, जो अब तक जारी है। इसमें सन्देह नहीं, कि जिन कारणों से यह नये टग का साम्राज्यवाद विकसित हुआ उनके नष्ट हो जाने पर यह स्वयं ही नष्ट हो जायगा, और ससार के इतिहास में एक नवीन युग का प्रारम्भ होगा। पर अभी तक राष्ट्रीय और आर्थिक साम्राज्यवाद का यह युग विद्यमान है। हमें इसके विकास के कारणों तथा स्वरूप पर गम्भीरता तथा ध्यान से विचार करना चाहिये।

**कारण**—इस नवीन साम्राज्यवाद के विकास के चार मुख्य कारण थे—(१)

व्यावसायिक क्रान्ति के कारण मानव समाज के आर्थिक संगठन में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था। मध्यकाल में आर्थिक उत्पत्ति बहुत छोटे पैमाने पर हुआ करती थी। एक देश में जो माल उत्पन्न होता था, वह उस देश के लिये भी पर्याप्त नहीं होता था। उस समय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का भी विशेष महत्व नहीं था। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिये न तो माल ही होता था, और न उसे एक देश से दूसरे देश में ले जाने के लिये समुचित माध्यम ही सुरक्षित रूप में विद्यमान थे। परन्तु व्यावसायिक क्रान्ति के बाद आवश्यकता में अफ्रीका माल उत्पन्न होने लगा। भाप में चलने वाले जहाजों के बन जाने से गुरुदूर्वर्ती देशों में व्यापार करना भी बहुत आसान हो गया। रेलवे, तार, डाकखाना, टेलीफोन आदि के आविष्कार में मनुष्य ने देश और काल पर अभूतपूर्व विजय स्थापित की। समार के मुदूरवर्ती देश अब एक दूसरे के बहुत समीप हो गये। लण्डन से भारतवर्ष जाना केवल तीन सप्ताह का कार्य रह गया। अन्तर्राष्ट्रीय बैंकों की स्थापना तथा विदेशी हुण्डी के प्रचलन में रुपये का आवागमन भी बहुत सुगम हो गया। बीमा कम्पनियों की कृपा में व्यापार का खतरा भी दूर हो गया। इस दशा में यूरोप के उन्नतिशील राज्य अपने माल के लिये नये बाजार ढूँढने की फिरफिर करने लगे। प्रत्येक देश अधिक से अधिक माल तैयार करना चाहता था, और उसको बेचकर अधिक से अधिक मुनाफा उठाने की कोशिश करना था। इस अवस्था में विविध देशों में परस्पर प्रतिस्पर्धा का होना सर्वथा स्वाभाविक था। अपने माल को दूसरे के मुकाबले में बचाकर निश्चिन्तता के साथ बेचने का एक ही उपाय था, वह यह कि पिछड़े हुए देशों में, जहाँ पर अपना माल बेचना सुगम तथा सम्भव था, अपने प्रभावक्षेत्र कायम किये जाएँ, जिससे कि अपने सिवा कोई अन्य देश उनमें व्यापार की नुविधा न रख सके। ये प्रभावक्षेत्र जिस प्रकार भी सम्भव हो, अपने ऊपर आश्रित होने जाएँ। धीरे-धीरे यदि ये अपने सुरक्षित राज्य बन जाएँ और फिर पूर्णतया अपने अधीन हो जाएँ, तो बहुत ही उत्तम हो। व्यापार के लिये यह प्रक्रिया अत्यन्त आवश्यक थी। इसके बिना विदेशी व्यापार सुरक्षित नहीं रह सकता था।

(२) मध्यकाल में शासन शक्ति वंशक्रमानुगत राजा तथा उसके कुलीन श्रेणी के दरबारियों के हाथ में थी। फ्रेंच राज्यक्रान्ति के बाद यह शासनशक्ति जनता के हाथों में आ गई, पर सम्पूर्ण जनता का शासन स्थापित न हो सका। शासनशक्ति मध्य श्रेणी के पास थी, जिसने कि व्यावसायिक क्रान्ति से लाभ उठाकर धन तथा स्थिति प्राप्त कर ली थी। वोट का अधिकार मध्यश्रेणी के लोगों को ही प्राप्त था। समाज में जो लोग अमीर थे, व्यवसाय तथा व्यापार के कारण जिनका समाज में सम्मान था, वे ही शासन का भी संचालन करते थे। अपने हितों का उन्हें खूब ध्यान था। शासनशक्ति प्राप्त कर अपने स्वार्थों को पूर्ण करने में वे सदा तत्पर रहते थे। अपने व्यापारिक माल को दूसरे देशों में खपाना तभी सम्भव था, जब कि अपने साम्राज्य का विस्तार किया जाए। साथ ही, मध्यश्रेणी के लोगों के पाम पूँजी भी बहुत बड़े परिणाम में संचित हो रही थी। यह पूँजी व्यवसाय तथा व्यापार में मुनाफा उठाकर संचित की गई थी। इस विशाल पूँजी को कहीं अच्छे सूद पर अथवा अच्छे मुनाफे की आशा



में लगाना अत्यन्त आवश्यक था। यह भी तभी हो सकता था, जब कि विदेशों पर अपना आधिपत्य कायम किया जाए। इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि मध्य श्रेणी के लोगो वा, जो कि उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में विविध यूरोपियन राज्यों के शासन सूत्र के संचालक थे, यह निज स्वार्थ हो गया था, कि वे साम्राज्यवाद का अनुसरण करें। नामनग्नित उनके हाथ में थी ही, वे इस शक्ति का उपयोग कर आने जाधिक हित का साधन करने में कटिबद्ध हो रहे थे।

(३) राष्ट्रीयता का उदय भी इस साम्राज्यवाद के विकास में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। राष्ट्रीयता के भावों से प्रेरित होकर यूरोप के विविध राज्य सत्तार में अपनी शक्ति का विस्तार करने के लिए आतुर थे। नि सन्देह, राष्ट्रीयता बहुत अच्छी चीज है। प्रत्येक ऐसे जनसमाज को, जो धर्म, भाषा, सभ्यता, संस्कृति आदि की दृष्टि में एक हो, अपनी विशेषताओं को सामूहिक रूप से विकसित करने तथा उसके लिए अपना पृथक् संगठन बनाने का पूर्ण अधिकार है। इस हद तक राष्ट्रीयता किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकती। पर व्यक्तिवाद की अन्य सब प्रवृत्तियों की तरह राष्ट्रीयता में भी एक हानि है। राष्ट्र इस बात को भूल जाते हैं, कि पृथ्वी पर अन्य लोगों को भी जीना है, सारे सत्तार का निर्माण उनके लिए ही नहीं किया गया है। राष्ट्रीयता के आवेग में राज्य अन्य देशों के हितों और अधिकारों का ध्यान नहीं रखते। वे समझते हैं, कि सत्तार में हमें अपना राज्य-विस्तार करने और अपना राजनीतिक, धार्मिक तथा आर्थिक उत्कर्ष स्थापित करने का अमर्यादित अधिकार है। इस वृत्ति का परिणाम साम्राज्यवाद होता है। उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में यूरोप के सब प्रमुख राज्य राष्ट्रीयता की देवता की उपासना में तत्पर थे। वे अपने देश के उत्कर्ष के लिए सत्तार भर में जहाँ कहीं भी अवसर प्राप्त हो, वहाँ दूसरे देशों को अपने अधीन करने तथा उनमें अपना हित-साधन करने के लिये प्रयत्नशील थे।

(४) उन्नीसवीं सदी में यूरोप की आबादी बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही थी। १८०० में ब्रिटेन की आबादी १,६०,००,००० थी, १९०० में वह बढ़कर ४,१०,००,००० हो गई। इसी प्रकार इस एक शताब्दी में जर्मनी की आबादी २,१०,००,००० से ५,६०,००,०००, तथा आस्ट्रिया-हंगरी की २,३०,००,००० से ४,००,००,०००, इटली की १,८०,००,००० से ३,२०,००,०००, और रूस की ३,९०,००,००० से ११,१०,००,००० हो गई। इसी काल में सम्पूर्ण यूरोप की आबादी १८,०३,००,००० से बढ़कर ४०,००,००,००० हो गई। इस बढ़ती हुई आबादी पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पहले यूरोप में आबादी कम होने में वहाँ जो अनाज तथा अन्य खाद्य सामग्री उत्पन्न होती थी, वह वहाँ के निवासियों के भरण-पोषण के लिये पर्याप्त होती थी। पर इतनी तीव्रता से बढ़ती हुई आबादी यूरोप में उत्पन्न भोजन सामग्री में जरा गुनार नहीं आती थी। इस अवस्था में यूरोपियन लोगों के सम्मुख केवल दो मार्ग थे—एक यह कि वह देशों में लोग दूसरे देशों में जाकर बस जाएँ, एशिया, अफ्रीका तथा अमेरिका में बहुत अधिक भूमि उपलब्ध थी, जिनमें अपने उपनिवेश बनाने का अभी मौका था। दूसरा मार्ग यह था, कि यूरोपियन राज्य व्यवसायों की उन्नति में विशेष रूप से लग

जाए, और व्यावसायिक पदार्थों को दूसरे देशों में बेचकर उसके बदले में भोजन सामग्री अन्य देशों से प्राप्त करे। व्यावसायिक कान्ति इस समय तक हो चुकी थी, उसके कारण यूरोपियन देशों में बहुत बड़े परिणाम में तैयार माल उत्पन्न हो रहा था। उसे बेचकर साथ सामग्री प्राप्त कर सकना बहुत सुगम था। यूरोपियन देशों ने इन दोनों उपायों का अवलम्बन किया। उपनिवेशों पर उन्होंने बहुत ध्यान दिया। उनकी उपयोगिता अब सब स्वीकार करने लगे। लोगों की सख्या में यूरोपियन लोग अमेरिका, अफ्रीका और आस्ट्रेलिया आदि में जाकर बसने लगे। साथ ही, व्यावसायिक पदार्थों की उत्पत्ति बहुत बड़े पैमाने पर शुरू की गई। उन तैयार माल के बदले में यूरोपियन देश अन्य अन्य देशों में कच्चा माल प्राप्त करने लगे। यह प्रवृत्ति साम्राज्यवाद के विकास में बहुत सहायक हुई। उपनिवेशों की कदर बढ़ने में वे तो साम्राज्य के महत्वपूर्ण अंग बने ही, साथ ही अपने तैयार माल को अन्यत्र खपाने के लिये स्थिर बाजारों की आवश्यकता भी अनुभव की गई। इसी में 'प्रभाव क्षेत्र' 'संरक्षित राज्य' तथा 'साम्राज्य' बनाने की प्रवृत्ति शुरू हुई। आर्थिक साम्राज्यवाद के विकास में आवादी की यह वृद्धि एक अन्यन्त महत्वपूर्ण कारण थी।

यूरोप के नये साम्राज्यवाद के विकास के कारणों की विवेचना समाप्त करने में पूर्व एक अन्य बात का भी संक्षिप्त रूप में निर्देश कर देना अत्यन्त आवश्यक है। इस साम्राज्यवाद की सफलता में ईसाई पादरियों का धर्म प्रचार भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ईसाई लोगों में शुरू में यह प्रवृत्ति रही है, कि विविध देशों में अपने धर्म का प्रचार कर काफिर लोगों को नरक के गढ़ों में गिरने में बचाया जाए। रोमन कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेन्ट—ईसाई धर्म के दोनों मुख्य सम्प्रदाय इस कार्य में बहुत उत्साह प्रदर्शित करते रहे हैं। सोलहवीं शताब्दी के शुरू में जब कि यूरोपियन लोगों ने महासमुद्रों के पार आना जाना शुरू किया, तब ईसाई पादरी भी अपने कार्य में रुचि-बद्ध हो गये। वे अमेरिका, अफ्रीका, एशिया—सर्वत्र स्वच्छन्द रूप से विचरने लगे। उनके धार्मिक वेश को देखकर कोई उनपर नन्देह नहीं करता था। बहुत से ईसाई प्रचारक सचमुच ईमानदार थे, वे वस्तुतः ईसाई धर्म के प्रचार के लिये ही प्रयत्न करते थे। पर ऐसे धर्म प्रचारकों की भी कमी नहीं थी, जो धर्म के आवरण में अपने सामारिक हितों का सम्पादन किया करते थे। धार्मिक वेश का लाभ उठाकर ये दूसरों के गुप्त भेदों का सुगमता से पता लगा लेते थे, और अपने राज्यों को उनकी सूचना देते रहते थे। साम्राज्यवादी राष्ट्र तो इन धर्मप्रचारकों को अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने का साधन मात्र समझते थे। यदि अकस्मात् कोई पादरी किसी सुदूर देश में मारा गया, तो इन साम्राज्यवादी देशों को अच्छा वहाना मिल जाता था। उनके घात के कोई भी कारण क्यों न हो, उसमें चाहे पादरी का अपना ही दोष क्यों न हो,—ये साम्राज्यवादी उस अभाग्य देश पर आक्रमण करने का अच्छा मौका प्राप्त कर लेते थे। एशिया तथा अफ्रीका के बहुत से देशों में इन पादरियों को ही निमित्त बनाकर युद्ध आरम्भ किये गये। इस प्रकार ईसाई लोगों का धर्म प्रचार भी यूरोप के बढ़ते हुए साम्राज्यवाद में बहुत सहायक सिद्ध हुआ।

### ३ ईसाई धर्म प्रचारक और साम्राज्यवाद

**सांस्कृतिक साम्राज्य**—हमने पिछले प्रकरण में यह जिक्र किया था, कि ईसाई धर्म-प्रचारका द्वारा भी यूरोपियन देशों के साम्राज्य विस्तार में सहायता मिली थी। आधुनिक युग के इतिहास में ईसाई धर्म का प्रचार एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना है। पाचवीं सदी ई० पू० में बौद्ध धर्म का देश-विदेश में प्रसार शुरू हुआ था। कुछ सदियों के बाद महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित अष्टांगिक आर्यमार्ग चीन, जापान, कोरिया, तुर्किस्तान, लाओ, बर्मा, स्याम, मलाया, इण्डो-चायना, अफगानिस्तान आदि सर्वत्र फैल गया। बौद्ध धर्म के इस प्रसार के साथ-साथ भारतीय भाषा, सभ्यता, साहित्य, ज्ञान, रहन-सहन नम्रुति आदि का भी इन सुदूरवर्ती देशों में प्रसार हुआ, और कतिपय शताब्दियों के लिए भारत का सांस्कृतिक साम्राज्य ससार के बहुत बड़े भाग में स्थापित हो गया। आठवीं सदी में इसी ढंग से इस्लाम का प्रसार हुआ। इस्लाम का प्रादुर्भाव अरब में हुआ था, अतः उसके विदेशों में प्रसार के साथ-साथ अरब सभ्यता और संस्कृति का भी विस्तार हुआ, और कुछ सदियों तक अरब लोग अपने विशाल सांस्कृतिक साम्राज्य की स्थापना में समर्थ हुए।

ईसाई धर्म इस्लाम की अपेक्षा पुराना है। इसका प्रादुर्भाव पश्चिमी एशिया के जन्मभूमि प्रदेश पैलेस्टाइन में हुआ था। यह प्रदेश प्राचीन समय में रोमन साम्राज्य के अन्तर्गत था। शुरू में ईसाई प्रचारक रोमन साम्राज्य के विविध प्रदेशों में अपने धर्म का प्रचार करते रहे। पाचवीं सदी तक यूरोप के अनेक प्रदेशों को उन्होंने ईसाई धर्म में दाक्षित कर लिया था। मध्यकाल में प्रायः सम्पूर्ण यूरोप ईसाई धर्म का अनुयायी हो गया था, और रोम के पोप को अपना धर्मगुरु स्वीकार करता था। पर आधुनिक युग में ईसाई धर्म का प्रचार यूरोप के बाहर अमेरिका, अफ्रीका, एशिया आदि सर्वत्र हुआ है। प्रायः सभी देशों में ईसाई प्रचारक अपने मिशन स्थापित कर बहुत से लोगों को अपने धर्म में दीक्षित करने में समर्थ हुए हैं। ईसाई धर्म के इस विस्तार से जहाँ यूरोप के राजनीतिक उत्कर्ष में सहायता मिली है, वहाँ साथ ही यूरोप की राजशक्ति ने ईसाई धर्म की उत्कृष्टता की भावना का प्रसार करने में भी सहायता पहुँचाई है। वर्तमान युग में यूरोप के ईसाई लोग ससार में सर्वत्र अपना सांस्कृतिक साम्राज्य स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील हैं। ईसाइयों का यह सांस्कृतिक साम्राज्य आधुनिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है।

**प्रारम्भिक ईसाई प्रचारक**—मध्यकाल में जब यूरोपियन लोगों ने नये प्रदेशों की खोज करने की प्रवृत्ति शुरू हुई, तो ईसाई धर्म प्रचारकों ने भी उसमें हाथ बटाया। मार्को पोलो नामक यात्री जब पर्यटन करते हुए चले गये, तो अनेक ईसाई मिशनरी भी उनके साथ थे। मंगोल सम्राट कुबले खा के दरबार में जब मार्को पोलो उपस्थित हुआ तो दो पादरी भी उसके साथ गये। चौदहवीं सदी के शुरू में अनेक ईसाई प्रचारक चीन की राजधानी पeking गये, वहाँ उन्होंने वाइवल का तान्त्रिक भाषा में अन्वेषण किया, और अनेक तान्त्रिक लोगों को ईसाई धर्म में दीक्षित करके उन्हें धर्म प्रचार के लिये

तैयार किया। पन्द्रहवीं सदी में जब यूरोप के लोगों ने अमेरिकन महाद्वीप का पता लगाया, और स्पेनिश व पोर्तुगीज लोगों ने इस महाद्वीप में अपनी बस्तियाँ बसानी शुरू की, तो ईसाई प्रचारकों को भी वहाँ अपने कार्य का अवसर मिला। मेक्सिको और पेरू के असली निवासी सभ्यता की दृष्टि में अच्छे उन्नत थे। वे पत्थर के मकानों में रहते थे, और मन्दिरों में प्रतिष्ठित देवी-देवताओं की पूजा किया करते थे। ईसाई मिशनरियों ने यत्न किया, कि उन्हें आने वाले धर्म में दीक्षित करें। पर मेक्सिको और पेरू की अजटक सभ्यता के लोग ईसाई धर्म को स्वीकार करने के लिये उद्यत नहीं हुए। इस पर यूरोपियन लोगों ने उन पर घोर अत्याचार किये। १५२० में उन्होंने यह आज्ञा जारी की, कि अजटक लोग अपने धार्मिक विश्वासों के अनुसार पूजा पाठ न कर सकें। वहाँ पाच विंशति की नियुक्ति की गई, और सारे प्रदेश को धार्मिक दृष्टि में इन विंशति के अधीन कर दिया गया। ईसाई लोग अजटक जाति को अपने धर्म का अनुयायी नहीं बना सके, अतः उन्होंने उसे सर्वथा नष्ट कर देने के मार्ग का आश्रय लिया। बाद में अमेरिका के आर्थिक जीवन को विकसित करने के लिये जो नीग्रो लोग अफ्रीका में गुलाम के रूप में लाये गये, उन्हें भी ईसाई बनाया गया, और इसका परिणाम यह हुआ कि अमेरिका में बसने वाले यूरोपियन लोगों के साथ-साथ उनके नीग्रो गुलाम भी ईसाई धर्म के अनुयायी हो गये।

भारत में पहले-पहल जो यूरोपियन जाति अपने प्रभाव का विस्तार कर रही थी, वह पोर्तुगीज थी। उसने भी इस देश के निवासियों को बल प्रयोग द्वारा ईसाई धर्म में दीक्षित करने का प्रयत्न किया। पोर्तुगीज लोग भारत के हिन्दुओं में वही बर्ताव करना चाहते थे, जो कि स्पेनिश लोगों ने अमेरिका की अजटक जाति के साथ किया था। उन्होंने भारतीयों पर घोर अत्याचार किये। भारत के पश्चिमी समुद्रतट पर गोआ के समीप उनका पहले-पहल प्रवेश हुआ था, वहाँ जनता को बलपूर्वक ईसाई बनाया गया। इस युग के ईसाई प्रचारकों में फ्रांसिस बसेवियर का नाम विशेष रूप में उल्लेखनीय है। उसने न केवल दक्षिणी भारत में, अपितु समुद्र तट के साथ-साथ के प्रदेशों में चीन और जापान तक ईसाई धर्म के प्रचार का उद्योग किया। सोलहवीं सदी के अन्त तक ईसाई प्रचारकों का एक जाल सा एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में फैल गया था।

**प्रोटेस्टेन्ट धर्म का प्रचार**—रोमन कैथोलिक चर्च के विरुद्ध विद्रोह करके लूथर आदि सुधारकों के नेतृत्व में जो अनेक प्रोटेस्टेन्ट सम्प्रदाय विकसित हुए थे, उनका उल्लेख इस इतिहास में पहले किया जा चुका है। शुरू में प्रोटेस्टेन्ट सम्प्रदायों ने अपने धार्मिक विश्वासों का विदेश में प्रचार करने के लिये कोई प्रयत्न नहीं किया। पर यूरोपियन राज्यों की सरकारें धार्मिक विषय में बहुत असहिष्णु थीं। राजा जिस सम्प्रदाय का अनुयायी हो, प्रजा उसके अतिरिक्त किसी अन्य सम्प्रदाय का अनुसरण करे, यह उसे सह्य नहीं था। इंग्लैण्ड के राजाओं ने रोमन कैथोलिक चर्च के विरुद्ध विद्रोह कर राजकीय सुरक्षा में इंगलिश चर्च की स्थापना की थी। पर इंग्लैण्ड में ऐसे लोगों की कमी नहीं थी, जो पोप के आधिपत्य के समान चर्च पर राजा के आधिपत्य को भी बुरी बात समझते थे। ये प्रोटेस्टेन्ट लोग डिसेन्टर व प्यूरिटन कहाते थे। सत्रहवीं और अठारहवीं सदियों के स्वच्छाचारी निरकुश इंगलिश राजा अपने धार्मिक प्रभुत्व को न माननेवाले

उन प्रोटेस्टेंट सम्प्रदायों को सहन करने के लिये तैयार नहीं थे। परिणाम यह हुआ, कि डिसेन्टर व प्यूरिटन लोग बहुत बड़ी संख्या में अपनी मातृभूमि को सदा के लिये अस्कार कर अटलाण्टिक महासागर के पार अमेरिका में जा बसने के लिये विवश हुए। वहाँ उन्होंने यह प्रयत्न किया, कि अमेरिका के मूल निवासियों को (यूरोप के लोगों के भारी भ्रम के कारण जो रेड इन्डियन कहाने हैं) अपने सम्प्रदायों में दीक्षित करें। इसी प्रकार फ्रांस के इयुजनों सम्प्रदाय के लोग व जर्मनी के प्रोटेस्टेंट (लूथर के अनुयायी) लोग भी अपनी मातृभूमि का परित्याग कर अमेरिका में जा बसने और वहाँ के मूल निवासियों को ईसाई बनाने के लिये प्रयत्नशील हुए। इस युग में हालैंड के पर्यटक सुदूर पूर्व में जावा, मलक्का, फारमूसा, सीलोन आदि में समुद्र द्वारा पहुँच रहे थे, और वहाँ अपने व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करने में तत्पर थे। इसी प्रकार कतिपय उच्च जर्मन लोग अफ्रीका के अवीसीनिया आदि प्रदेशों का अवगाहन करने में लगे थे। अनेक ईसाई प्रचारक भी इन लोगों के साथ इन देशों में गये, और वहाँ उन्हें ईसा मसीह के धर्म का सन्देश देना प्रारम्भ किया। आस्ट्रिया का एक कुलीन जागीरदार, फॉन वेल्स धर्म-प्रचारक बनकर उच्च गायना में गया, और डेन्मार्क के राजा फ्रेडरिक चतुर्थ ने भारत में ईसाई धर्म का प्रसार करने के लिये एक मिशन की स्थापना की। इस युग में सारे यूरोप में विधर्मियों को ईसाई बनाने के लिये अपूर्व उत्साह था। १७९५ में इंग्लैंड में 'लण्डन मिशनरी सोसायटी' नाम से एक नई संस्था की स्थापना की गई। इस सोसायटी ने दो लाख रुपया एकत्र किया, और साउथ सी द्वीपों में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिये मिशनरियों को भेजा। १७९२ और १८९२ के बीच के एक सदी के समय में ग्रेट ब्रिटेन में पैतृस मिशनरी संस्थाएँ इस उद्देश्य से कायम हुईं, कि वे पृथिवी के विभिन्न प्रदेशों में ईसाई धर्म के प्रसार का उद्योग करें। इन संस्थाओं के लिये करोड़ों नया यूरोप के विविध राज्यों में एकत्र किया गया, और हजारों मुशिक्षित नवयुवक मिशनरी का कार्य करने के लिये अग्रसर हुए। इन संस्थाओं का स्वरूप अनेक प्रकार का था। कतिपय संस्थाएँ अफ्रीका, एशिया आदि के पिछड़े हुए प्रदेशों में चिकित्सालय चालकर अपने कार्य का विस्तार करती थीं। इनके मेडिकल मिशन चिकित्सा द्वारा जनता की सेवा कर उन्हें अपने प्रभाव में लाने का उद्योग करते थे। कतिपय संस्थाओं ने पिछड़े हुए प्रदेशों में स्कूल व कालिज खोलकर विद्यार्थियों को अपने असर में लाने का प्रयत्न किया। इसी प्रकार वाइवल सोसायटी नाम से अनेक संस्थाएँ स्थापित की गईं, जो विदेशों में वाइवल का प्रचार करने के लिये उद्योग करती थीं।

साम्राज्यवाद में सहायता—यूरोप के लोग अच्छी तरह अनुभव करते थे, कि ईसाई धर्म का प्रचार उनके लिये अत्यन्त लाभदायक है। धर्म प्रचार के कार्य में जो बराबर सहायता प्रतिवर्ष यूरोपियन लोग खर्च कर रहे थे, और जो हजारों नवयुवक अपने घरों का परित्याग कर विदेशों में जा रहे थे, उसका उद्देश्य विशुद्ध रूप से धार्मिक नहीं था। यूरोपियन राज्य इस तथ्य को पमझूते थे, कि ईसाई धर्म का प्रचार समाज की सभ्यता व संस्कृति के प्रसार में परम सहायक होगा। यूरोपियन सभ्यता की उन्नति की भावना जहाँ एशिया और अफ्रीका के देशों में उनके साम्राज्य को स्थिर

रूप से उनके अधीन रखने में सहायक होगी, वहाँ साथ ही नये प्रदेशों को भी उनके प्रभाव में लाने के लिये उपयोगी होगी। यूरोप के ये श्वेतांग ईसाई प्रचारक एशिया और अफ्रीका के लोगों को अपने में हीन समझते थे, और उनके साथ समता का व्यवहार नहीं करते थे। इसीलिये कतिपय स्थानों पर जनता में उनके विरुद्ध भावना प्रवृत्त हो जाती थी, और कभी-कभी ईसाई प्रचारक कत्ल भी कर दिये जाते थे। ऐसी घटना यूरोपियन राज्यों के लिये अत्यन्त उत्तम अवसर उपस्थित कर देती थी, और इसे निमित्त बनाकर वे इन प्रदेशों को विजय कर लेने या उन्हें अपनी सुरक्षा में ले आने में जरा भी मर्काच नहीं करते थे। चीन आदि एशियाई राज्यों में यूरोप के विविध देशों ने जो अपने प्रभाव का विस्तार किया, उसमें यह प्रक्रिया बहुत सहायक हुई।

एशिया व अफ्रीका में कार्य करनेवाले ईसाई पादरी केवल धर्म प्रचार ही नहीं करते थे, साथ ही वे इस बात का भी सूक्ष्मता के साथ निरीक्षण करते थे, कि इन प्रदेशों में आर्थिक उन्नति की किफ तब तक गुंजाइश है। बहुमूल्य यूरोपियन पादरी मजिस्ट्रिट होते थे, और उनके लिये यह जान सकना जरा भी कठिन नहीं था, कि उस प्रदेश के जगलों में कौन सी कीमती वस्तुएँ उपलब्ध हैं, वहाँ किस चीज की मांग है, वहाँ में कौन सा कच्चा माल क्रय किया जा सकता है, और यूरोप का कौन सा माल वहाँ सुगमता से बिक सकता है। इन सब बातों का भलीभाँति अनुशीलन कर वे यूरोप की पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखते थे, और उन्हें पढ़कर यूरोप के पूँजीपति, व्यवसायी व व्यापारी लोग इन देशों की ओर आकृष्ट होने लगे। वे वहाँ जाकर नई कम्पनियाँ खड़ी करते थे, और एशिया व अफ्रीका के लोगों को मस्ती मजदूरी पर रखकर वहाँ और व्यवसायों का विकास करते थे। यूरोप के लोगों ने जो चीन, अनाम, म्याम, इण्डोचायना, इण्डोनीसिया, अफ्रीका आदि में अरबों रुपया विविध व्यवसायों में लगाया, उसके लिये आवश्यक परिज्ञान उन्हें ईसाई मिशनरियों द्वारा ही प्राप्त हुआ था। यूरोप के आर्थिक व राजनीतिक साम्राज्य के विकास में इन धर्म प्रचारकों द्वारा बहुत सहायता मिली थी। यही कारण है, कि न केवल यूरोप के पूँजीपति ही, अपितु वहाँ की सरकारें भी इन ईसाई मिशनों की दिल खोलकर सहायता करती थी।

हमें यहाँ यह भी स्वीकार करना होगा, कि ईसाई मिशन एशिया व अफ्रीका के निवासियों के लिये भी अनेक दृष्टियों से उपयोगी सिद्ध हुए। ईसाई धर्म तो सम्भवतः हिन्दू धर्म, इस्लाम और बौद्ध धर्म से किसी भी प्रकार अधिक उत्कृष्ट नहीं था। पर यूरोप के प्रचारक जिस सभ्यता के प्रतिनिधि थे, वह ज्ञान-विज्ञान के असाधारण विकास के कारण अवश्य उत्कृष्ट थी। एशिया और अफ्रीका के लोगों ने इन यूरोपियन प्रचारकों के सम्पर्क में आकर यह अनुभव किया, कि वे उन्नति की दौड़ में बहुत पीछे रह गये हैं। वे भी यूरोप से ज्ञान विज्ञान सीखकर उन्नति के लिये तत्पर हुए, और इस प्रकार एशिया तथा अफ्रीका में विद्या का पुनः जागरण प्रारम्भ हुआ। सभ्यता के इतिहास में यह बात अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखती है।

## ४ साम्राज्य निर्माण के लिये सघर्ष

ईसाई धर्म प्रचारक यूरोपियन राज्यों के साम्राज्य विस्तार के लिये केवल मैदान तैयार करने का ही काम करते थे। उनसे यूरोप के साम्राज्यवादियों को सहायता अवश्य मिलनी थी, पर यूरोप के विविध देश जो नये-नये प्रदेशों को अधिगत करने के लिये प्रयत्नशील थे, उनके प्रेरक हेतु धार्मिक न होकर आर्थिक और राष्ट्रीय थे। पन्द्रवी सदी में यूरोप के लोगों में नये प्रदेशों की खोज करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई। उस समय तक व्यवसायिक क्रान्ति शुरू नहीं हुई थी। पूर्वी देशों तक पहुँचने के मार्ग पर तुर्कों लोगों का आधिपत्य स्थापित हो जाने के कारण ही यूरोपियन लोग एशिया आने जाने का नया रास्ता ढूँढ़ निकालने के लिये प्रवृत्त हुए थे। इस प्रयत्न में उन्हें अमेरिका का परिज्ञान हुआ, और उसके कारण यूरोपियन लोगों को अपना प्रसार करने के लिये एक विशाल भण्ड प्राप्त हो गया। साथ ही अफ्रीका का चक्कर लगाकर जब वे भारत आदि पूर्वी देशों में पहुँचे, तो वहाँ अपने व्यापार को बढ़ाने तथा व्यापार द्वारा धन कमाने का नया क्षेत्र भी उनके लिये खुल गया। यूरोप के आर्थिक जीवन में ये बातें महान् परिवर्तन उत्पन्न कर रही थी। इन्हीं के कारण यूरोप में व्यापारिक क्रान्ति हुई, और आर्थिक जीवन में मध्यकाल की आर्थिक श्रेणियों (गिल्ड) का स्थान वनपतियों द्वारा संचालित कारखाने (फैक्टरी) लेने लगे। अठारहवीं सदी के अन्त में इङ्ग्लैण्ड में व्यावसायिक क्रान्ति हुई, और धीरे-धीरे फ्रांस, बेल्जियम आदि अन्य देशों ने भी नये यान्त्रिक आविष्कारों का प्रयोग कर आर्थिक उत्पत्ति के तरीकों में परिवर्तन करना शुरू किया। व्यावसायिक क्रान्ति के कारण यूरोप में विविध प्रकार का माल प्रचुर मात्रा में तैयार होने लगा, और इस माल को पिछड़े हुए देशों में बेचकर धनी बनने के उद्देश्य से यूरोप के विविध देश अपने साम्राज्य-विस्तार के लिये प्रवृत्त हुए। पर साम्राज्य-विस्तार का पहला युग उन्नीसवीं सदी के शुरू तक समाप्त हो गया था। अमेरिका के विशाल महाद्वीप में जो विविध उपनिवेश इङ्ग्लैण्ड, फ्रांस, स्पेन और पोर्तुगाल ने स्थापित किये थे, वे प्रायः सब स्वतन्त्र हो गये थे। जो कतिपय प्रदेश यूरोपियन राज्यों के हाथों में शेष रहे थे, वे भी स्वतन्त्रता के लिये प्रयत्नशील थे, और इङ्ग्लैण्ड आदि देश अपनी पुरानी औपनिवेशिक नीति में परिवर्तन कर उनमें आन्तरिक स्वतन्त्रता की स्थापना के लिये दिवंगत हो रहे थे। आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड आदि का भी अभी विकास नहीं हुआ था, और फ्रांस, इङ्ग्लैण्ड, बेल्जियम आदि ने एशिया और अफ्रीका में अपने जो विशाल साम्राज्य जगें बसाये स्थापित किये, उनका भी अभी प्रारम्भ नहीं हुआ था। यद्यपि ब्रिटेन भारत के बड़े भाग का अपनी अधीनता में ला चुका था, पर वहाँ भी उसकी नियति अभी पूर्णतया पुरजित नहीं हुई थी। स्थूल रूप से यह कहा जा सकता है, कि साम्राज्य प्रसार की जो पहली चर पन्द्रहवीं सदी के जन्म में शुरू हुई थी, उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ तक वह नहीं सींग हा गई थी।

द्वितीय व्यावसायिक क्रान्ति—इस दशा में उन्नीसवीं सदी के मध्यभाग में दूसरी व्यावसायिक क्रान्ति हुई। वैज्ञानिक आविष्कारों द्वारा मनुष्य ने प्रकृति पर नया भारी

विजय स्थापित करनी शुरू की थी, उसमें अब अमावारण उन्नति हुई। विजली की शक्ति का उपयोग यन्त्रों के संचालन के लिये किया जाने लगा। कच्ची धातु में लोहे और फौलाद को तैयार करने के लिये अत्यन्त उन्नत साधनों का आविष्कार हुआ। भाप और विजली की शक्ति से चलने वाली विशाल मशीनों द्वारा आर्थिक उत्पत्ति बहुत बड़े परिमाण में होने लगी। रेल, तार और टेलीफोन के आविष्कार के कारण देश और काल पर आश्चर्यजनक विजय स्थापित हुई, और उसके कारण समार के विविध देश एक दूसरे के बहुत समीप आ गये। भाप में चलने वाले विशाल जहाजों का निर्माण शुरू हुआ, और हजारों टन वजन के बड़े-बड़े जहाज महासमुद्रों की छाती को चीरते हुए पृथ्वी का चक्कर लगाने लगे। इस दशा में यूरोप के देश अपने क्षेत्र को बहुत मकीर्ण व छोटा अनुभव करने लगे। उन्हें आवश्यकता प्रतीत हुई, कि वे अपना विस्तार करें। उनके विशाल-काय कारखानों में जो सब प्रकार का माल प्रचुर मात्रा में तैयार होता था, उसे केवल अपने देश में खपा सकना सम्भव नहीं था। ब्रिटन, फ्रांस आदि देश अनुभव करने थे, कि साम्राज्य विस्तार के बिना उनका काम नहीं चल सकता। द्वितीय व्यावसायिक क्रान्ति के कारण जो नई आर्थिक परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी, वह उन्हें विवश कर रही थी, कि वे पृथिवी के पिछड़े हुए देशों को भी अपने प्रभाव में ले आवें। पहली व्यावसायिक क्रान्ति में जहा मशीन इजन का आविष्कार हुआ था, और उद्भूत के वनपति लोग यान्त्रिक शक्ति का उपयोग कर कारखानों का निर्माण करने के लिये तत्पर हुए थे, वही इस द्वितीय व्यावसायिक क्रान्ति द्वारा पाश्चात्य समार के हाथ में प्रकृति की ऐसी शक्तियाँ आ गई थी, जिनमें कि वे बहुत अधिक मात्रा में आर्थिक उत्पत्ति कर सकते थे। वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण उनके पास अब ऐसे अस्त्र-गन्ध भी आ गये थे, एशिया और अफ्रीका के पिछड़े हुए देश जिनके मुहान्वले में नहीं ठहर सकते थे। यूरोप के साम्राज्यवाद की सफलता में यह वैज्ञानिक उन्नति प्रधान हेतु थी।

**उग्र राष्ट्रीयता—**फ्रांस की राज्यक्रान्ति के बाद राष्ट्रीयता की प्रवृत्ति को बहुत बल मिला, और यूरोप के विविध राज्यों का निर्माण राष्ट्रीयता के सिद्धांत के अनुसार होने लगा। फ्रांस और ब्रिटेन तो पहले ही राष्ट्रीय दृष्टि में संगठित थे। उन्नीसवीं सदी के मध्य-भाग में जर्मनी और इटली में भी राष्ट्रीय एकता की स्थापना हुई। ये राष्ट्रीय राज्य यह अनुभव करने लगे, कि उनकी सभ्यता और संस्कृति अन्य सब देशों की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट है। उनमें यह भी विचार उत्पन्न हुआ, कि वे अपने प्रभाव क्षेत्र को विस्तृत कर न केवल अपनी राष्ट्रीय उन्नति में समर्थ होंगे, अपितु मानव सभ्यता के विकास में भी इससे सहायता मिलेगी। ब्रिटिश लोग अनुभव करने थे, कि भारत में उनका शासन भारतीयों के लिये हितकर है, और भारत, वरमा, सीलोन, अफ्रीका आदि के विविध प्रदेशों में शासन स्थापित कर वे मानव समाज का बहुत हित व कल्याण कर रहे हैं। उनके शासन से इन पिछड़े हुए देशों को उन्नति के मार्ग पर अगसर होने का अपूर्व अवसर मिल रहा है। एक प्रसिद्ध ब्रिटिश राजनीतिज्ञ का कहना था, कि समार की सभ्यता और इतिहास में एंग्लो-सैक्सन जाति को एक सर्वप्रमुख शक्ति बनकर रहना है, और यह बात प्रकृति का ही एक विधान है। फ्रेंच नेता समझते थे, कि उपनिवेश-विस्तार



फ्रांस के लिये जीवन-मरण का प्रश्न है, इसके बिना फ्रांस का जीवन ही सम्भव नहीं है। जर्मनी का विचार था, कि जर्मन लोगों को भी पृथिवी पर प्रमुख और उभयवृत्त स्थान प्राप्त होना चाहिये। अमेरिकन राष्ट्रपति रूजवेल्ट का कहना था, कि ससार के इतिहास में अमेरिकन लोगों को महत्वपूर्ण हाथ बटाना है। पाश्चात्य ससार के सभी देश उन्नीसवीं सदी में यह समझने लगे थे, कि भगवान ने उन्हें सभ्यता के प्रसार और पिछड़े हुए एशियन और अफ्रीकन लोगों को सभालने का पवित्र कार्य सुपुर्द किया है। श्वेताङ्ग लोग मानव समाज में सर्वोत्कृष्ट स्थान रखने हैं, और उन्हें सारे ससार का नेतृत्व करना है, यह विचार यूरोप में एक स्वयंसिद्ध सत्य माना जाता था। यूरोपियन लोगों को विश्वास था कि न केवल उनकी सभ्यता सर्वोत्कृष्ट है, अपितु नस्ल की दृष्टि से भी वे और लोगों की अपेक्षा ऊँचे हैं। इसीलिये वे ससार के विविध भागों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना मन्वा उचित और आवश्यक समझते थे।

जार्जिक और राष्ट्रीय हेतुओं में प्रेरित होकर यूरोप के विविध राज्य उन्नीसवीं सदी के मध्यभाग में एक बार फिर साम्राज्य-विस्तार के लिये प्रवृत्त हुए। इस बार उनके विस्तार का क्षेत्र प्रधानतया एशिया और अफ्रीका में था। उन्होंने सारी पृथिवी का भलीभाँति अवगाहन किया। अफ्रीका के सघन जंगलों में, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के दुर्गम प्रदेशों में और महासमुद्रों के बीच में स्थित छोटे बड़े टापुओं में यूरोप के साहसी लोग जाने जाने शुरू हुए। बीसवीं सदी के प्रारम्भ तक यह दगा आ गई थी, कि पृथिवी का शायद कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं बच रहा था, जहाँ यूरोप के लोगों ने पदार्पण न किया हो। इन विविध प्रदेशों पर यूरोप का प्रभावक्षेत्र भी वही तेजी से स्थापित हो रहा था। एशिया और अफ्रीका के जो प्रदेश यूरोप के साम्राज्यवाद के शिकार नहीं भी हुए थे, वे भी किसी न किसी रूप में उनके प्रभाव में आ गये थे। प्रत्येक यूरोपियन राज्य इस बात के लिये कटिबद्ध था, कि पृथिवी के अधिक से अधिक प्रदेश पर अपना साम्राज्य या प्रभावक्षेत्र कायम करे। यूरोप में भी जो देश आपेक्षिक दृष्टि में पिछड़े हुए थे, वे पश्चिमी यूरोप के उन्नत देशों की साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के शिकार हो रहे थे।

## ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार

### १ ब्रिटिश साम्राज्य

मसाल के इतिहास में अब तक जितने साम्राज्यों का विकास हुआ है, ब्रिटिश साम्राज्य सम्भवतः उनमें सबसे बड़ा है। साम्राज्य निर्माण के कार्य में ब्रिटिश लोगों को असाधारण सफलता प्राप्त हुई है।

इस साम्राज्य के स्वरूप को ठीक प्रकार से समझने के लिये हम इसे चार भागों में विभक्त कर सकते हैं—(१) उपनिवेश—कनाडा, न्यू फाउण्डलैंड, आस्ट्रेलिया, यूजीलैण्ड और दक्षिणी अफ्रीका, (२) भारतीय साम्राज्य, (३) क्राउन कालोनियाँ, (४) संरक्षित राज्य, तथा राष्ट्रसंघ द्वारा सौंपे गये राज्य। इसमें से जो १८३१ ईस्वी तक ब्रिटिश साम्राज्य ने अन्तर्गत हो गये थे, उन पर हम इस अध्याय में प्रकाश डालेंगे।

### २ औपनिवेशिक राज्य

#### क—कनाडा

कनाडा में ब्रिटिश शासन—कनाडा पहले फ्रेंच उपनिवेश था। पन्द्रहवीं सदी के अन्तिम भाग में जब कोलम्बस ने अमेरिका का पता लगाया, तो अनेक यूरोपियन जातियों ने इस नवीन भूखण्ड पर अपने उपनिवेश बसाने प्रारम्भ किये। कनाडा में फ्रेंच लोग बसे, और यह प्रदेश सन् १७६३ तक उन्हीं लोगों के हाथ में रहा। सप्तवर्षीय युद्ध की समाप्ति पर सन् १७६३ में कनाडा ब्रिटिश लोगों के अधीन हो गया। ब्रिटेन के लिये कनाडा का शासन करना सुगम कार्य न था। वहाँ के निवासी भाषा, धर्म, जाति आदि की दृष्टि से ब्रिटिश लोगों से सर्वथा भिन्न थे। परन्तु धीरे-धीरे वहाँ ब्रिटिश लोगों की संख्या बढ़ने लगी। अठारहवीं सदी के अन्तिम भाग में जब अमेरिका के ब्रिटिश उपनिवेशों में (जो कि वर्तमान समय में संयुक्तराज्य अमेरिका के नाम से विख्यात है) विद्रोह हुआ, तो बहुत से राजभक्त उपनिवेशवासी कनाडा में जाकर बस गये। सब अमेरिकन लोग राज्यक्रान्ति के समर्थक नहीं थे। बहुत से ऐसे भी थे, जो ब्रिटिश छत्रछाया में निवास करने में ही अपना कल्याण समझते थे। इसलिये जब अमेरिकन राज्यक्रान्ति सफल हो गई, तो ये लोग पड़ोस के ब्रिटिश उपनिवेश कनाडा में जाकर बस गये। इनके अतिरिक्त, ब्रिटेन में जाकर वहाँ बसने वाले लोगों की संख्या भी कम नहीं थी। आवादी की वृद्धि तथा बेकारी के कारण बहुत से ब्रिटिश लोग प्रतिवर्ष अपनी मातृभूमि को छोड़कर बाहर चले जाते थे। पहले 'लोग

अमेरिका में आबाद हुआ करते थे। पर अब उसके स्वाधीन हो जाने के कारण इनका क्षेत्र बढ़ गया, और ये लोग कनाडा में जाकर बसने लगे। इन नये निवासियों से अपर कनाडा, न्यू ब्रुन्स्विक, नोवा स्कोटिया, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड तथा न्यूफाउण्डलैंड का विकास हुआ। ब्रिटिश लोग ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका से आते गये, और कनाडा के विद्याल व विस्तृत प्रदेशों में बसते गये। ये बिखरी हुई बस्तिया ही धीरे-धीरे वाकायदा संगठित उपनिवेशों के रूप में परिणत हो गईं। प्रत्येक उपनिवेश की अपनी-अपनी सरकार थी, और इनके शासक लोग ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते थे।

**स्वाधीनता का आन्दोलन**—शुरू-शुरू ने इन उपनिवेशों के शासन में उपनिवेश-वासियों का कोई हाथ न था। सम्पूर्ण शासन ब्रिटिश सरकार द्वारा संचालित होता था। पर धीरे-धीरे लोकतन्त्रवाद के सिद्धान्तों का उनमें भी प्रवेश किया गया, और उपनिवेश-वासियों को शासन में अधिकार दिये जाने लगे। पर कनाडा के निवासी इन साधारण मुद्दों में सतुष्ट नहीं हो सकते थे। 'स्वभाग्य निर्णय' तथा 'लोकतन्त्र शासन' के सिद्धान्तों को क्रिया में परिणत करने के लिये उनमें घोर आन्दोलन चल रहा था। इसीलिए १८३७ में कनाडा में विद्रोह हो गया। इस विद्रोह का स्वरूप प्रायः वैसा ही था, जैसा कि लगभग आधी सदी पहले के अमेरिकन विद्रोह का था। पर भेद यही है, कि कनाडा की शक्ति सफल नहीं हो सकी। पर इसमें सन्देह नहीं, कि असफल होकर भी कनाडियन शक्ति ने ब्रिटिश शासकों की आखें खोल दी। उन्हें जब आवश्यकता अनुभव हुई, कि वे कनाडा-वासियों की शिकायतों को सुनें, और उनके असन्तोष को दूर करने का प्रयत्न करें।

**लार्ड डर्हम के प्रस्ताव**—इसी उद्देश्य को दृष्टि में रखकर लार्ड डर्हम को कनाडियन समस्या का अध्ययन करने तथा उसका हल करने के उपायों को सुझाने के लिये नियत किया गया। लार्ड डर्हम ने पांच मास कनाडा में व्यतीत किये, और सब बातों का भली भाँति अनुशीलन कर वह इस परिणाम पर पहुँचे, कि जब तक कनाडा के उपनिवेशों का अपने साथ सम्बन्ध रखनेवाले सम्पूर्ण मामलों में पूरा-पूरा अधिकार न दिया जायगा, तब तक उनकी समस्या का हल नहीं हो सकेगा। इसके लिये उसने प्रस्ताव किया कि (१) लोअर कनाडा और अपर कनाडा को मिलाकर एक सभ में संगठित किया जाए, और कनाडा के इस सभ में इस बात की गुंजाइश रखी जाए कि अन्य समीपवर्ती उपनिवेश भी उसमें यथा समय सम्मिलित किये जा सकें। (२) प्रत्येक उपनिवेश में लोकतन्त्रवाद के अनुसार स्वराज्य की स्थापना की जाए और मन्त्रिमण्डल को व्यवस्थापिका सभा के उत्तरदायी बनाया जाए।

**उपनिवेशिक स्वराज्य का प्रारम्भ**—ब्रिटिश साम्राज्य के जायज इतिहास में लार्ड डर्हम की यह रिपोर्ट बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। इसे उपनिवेशिक स्वराज्य की नींव माना जाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार १८४० में लोअर और अपर कनाडा को मिलाकर एक कर दिया गया, तथा उनकी व्यवस्थापिका सभा का गठन हुआ। मन्त्रिमण्डल को व्यवस्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। लोअर कनाडा के प्रतिनिधि रूप में एक पार्लर की व्यवस्था की गई, जिसे ब्रिटिश

सरकार नियत करती थी। कुछ समय पश्चात् अन्य उपनिवेशों में (जो अमेरिका के उत्तर में विद्यमान थे) भी इसी पद्धति का अनुसरण किया गया। नोवा स्कोटिया, न्यू ब्रिस्विक् आदि अन्य उपनिवेशों में भी कुछ ही वर्षों में औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना हुई। वीरे-वीरे ये सब उपनिवेश कनाडा के साथ (फिडरेशन) में सम्मिलित कर लिये गये, और कनाडा के आधुनिक उपनिवेश का प्रादुर्भाव हुआ। इस सघ में सम्मिलित विविध उपनिवेशों व प्रान्तों में अपनी-अपनी पृथक् व्यवस्थापिका सभाएँ तथा उनके प्रति उत्तरदायी मन्त्रिमण्डल भी विद्यमान हैं, और साथ ही सब की पृथक् केन्द्रीय पार्लियामेन्ट है, जो सम्पूर्ण सघ के साथ सम्बन्ध रखनेवाले विषयों का मन्त्रालय करती है।

**केन्द्रीय शासन**—केन्द्रीय सरकार का संगठन निम्नलिखित प्रकार में है—पार्लियामेन्ट में दो सभाएँ हैं, सीनेट और लोकसभा। सीनेट के सदस्य गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत किये जाते हैं, और वे जन्म भर सदस्य पद पर रहते हैं। लोकसभा के सदस्यों को जनता चुनती है। मन्त्रिमण्डल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहता है। गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा की जाती है। यद्यपि उसे वोटों का अधिकार प्राप्त है, पर ब्रिटिश सम्राट की तरह उसका यह प्रतिनिधि भी अपने डम अधिकार का प्राय उपयोग नहीं करता। विदेशी मामलों के अतिरिक्त अन्य सब विषयों में कनाडा पूर्णतया स्वतन्त्र राज्य के समान है।

लार्ड डर्हम द्वारा प्रतिपादित नीति में ब्रिटेन का अपने उपनिवेशों के प्रति रुख बहुत कुछ परिवर्तित हो गया है। यदि अठारहवीं सदी के अन्तिम भाग में अमेरिकन उपनिवेशों के साथ भी ब्रिटेन यही वर्तव करता, तो सम्भवतः वे कभी ब्रिटिश साम्राज्य से पृथक् न होते। औपनिवेशिक स्वराज्य के मिद्वान्त से जहाँ उपनिवेश क्रियात्मक दृष्टि से पूर्णतया स्वतन्त्र हैं, वहाँ वे ब्रिटिश साम्राज्य के महत्वपूर्ण अंग भी हैं। इसने ब्रिटेन का उत्कर्ष बहुत बढ़ गया है।

**कनाडा का विस्तार**—कनाडा के लिये पश्चिम दिशा में प्रशान्त महासागर की तरफ अपना विस्तार करने के लिये अनन्त क्षेत्र पड़ा हुआ है। कनाडा की सरकार का जितने प्रदेश पर अधिकार है, वह सम्पूर्ण यूरोप व संयुक्त राज्य अमेरिका की अपेक्षा भी बड़ा है। इस विशाल भूखण्ड के जङ्गलों को साफ कर वहाँ बसने के लिये अभी बहुत ज्यादा गुंजायश है। लाखों मनुष्य प्रतिवर्ष यूरोप व अमेरिका से कनाडा पहुँचते हैं, और इन शून्य प्रदेशों को आबाद करते हैं। कनाडा में खनिज पदार्थों की भी कमी नहीं है। खानों से प्राप्त होनेवाले बहुमूल्य पदार्थों के लोभ से बहुत से मनुष्य हर साल कनाडा पहुँचते हैं। आवागमन के साधनों के उन्नत हो जाने के कारण पश्चिमी कनाडा को आबाद करना भी सुगम हो गया है। चार सुदीर्घ रेलवे हैं, जो कनाडा को पूर्व से पश्चिम तक—अटलाण्टिक महासागर से प्रशान्त महासागर तक—मिलाती हैं। इनमें से कनाडियन पैसिफिक रेलवे का ही विस्तार बारह हजार मील है। इन रेलों का परिणाम यह हुआ है, कि पश्चिम के प्रदेश लगातार आबाद होते जाते हैं, और नये-नये प्रदेश एक राज्य का रूप धारण कर कनाडा के सघ में सम्मिलित होते जाते हैं। मनिटोवा १८७० में

संघ में सम्मिलित हुआ, ब्रिटिश कोलम्बिया १८७१ में, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड १८७३ में, एल्बर्टा और सस्कचेवन १९०५ में। कनाडा की आबादी भी बड़े वेग से बढ़ रही है। १८१५ में उसकी आबादी केवल पांच लाख थी, १९२५ में एक सदी बाद वह बढ़कर नब्बे लाख हो गई थी।

**न्यू फाउण्डलैण्ड**—न्यू फाउण्डलैण्ड कनाडा के संघ के बहुत समीप स्थित है। पर अब तक वह कनाडा-संघ में सम्मिलित नहीं हुआ है। वह एक स्वतन्त्र पृथक् उपनिवेश के रूप में विकास कर रहा है। उसमें भी औपनिवेशिक स्वराज्य विद्यमान है, और वह भी अन्य उपनिवेशों के समान ही स्थिति रखता है।

## ख—आस्ट्रेलिया

आस्ट्रेलिया अपने आप में ही एक महाद्वीप है, जो अकेला सयुक्तराज्य अमेरिका व यूरोप के प्रायः बराबर है। जिस समय यूरोपियन लोगो ने इसमें प्रवेश किया, तब वहां कुछ मूल जातियां निवास करती थी, जो सभ्यता की दृष्टि से उन्नत न थी। यूरोपियन लोगो को उन्हें नष्ट करने में तथा इस विशाल भूखण्ड पर यथेष्ट वस्तियां बसाने में कोई विशेष दिक्कत नहीं हुई। आस्ट्रेलिया का अधिकांश भाग शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, इसलिए वहां की जलवायु बहुत उत्तम तथा स्वास्थप्रद है। उत्तरी आस्ट्रेलिया में जल की कमी है, सिंचाई का यथोचित प्रबन्ध न होने के कारण अभी उसमें वस्तियां ज्यादा नहीं बस सकी हैं। पर दक्षिणी तथा पूर्वी आस्ट्रेलिया बहुत उपजाऊ है। वहां खेती बहुत हो सकती है। साथ ही, वहां बहुत से खनिज पदार्थ भी पाये जाते हैं। इसलिए इन प्रदेशों में यूरोपियन लोग विशेष रूप से आबाद हुए हैं। आस्ट्रेलिया के दक्षिण में समीप ही विद्यमान टस्मानिया का टापू भी अपने उत्तम जलवायु, उपजाऊ जमीन तथा खनिज पदार्थों की प्रचुरता के कारण बहुत प्रसिद्ध है। वहां भी पाश्चात्य लोग प्रचुर संख्या में आबाद हुए हैं, और वह व्यापार तथा व्यवसाय का केन्द्र बन गया है।

**आस्ट्रेलिया में यूरोपियन लोगो का प्रवेश**—सोलहवीं सदी में जब पोर्तुगीज लोग मलायो के द्वीपों की ढूँढ में पूर्वी देशों की छानबीन कर रहे थे, तब उनके अनेक मत्लाह इस महाद्वीप में भी पहुँचे थे। पर वे वहां पर बसे नहीं, और न ही उन्होंने व्यापार के लिये वहां कोई कोठी ही बनाई। १६४२ में टस्मान नामक एक उच्च मत्लाह ने आस्ट्रेलिया के दक्षिण में विद्यमान उस टापू का पता लगाया, जो आजकल उस ही के नाम से टस्मानिया कहा जाता है। इसी टस्मान ने आस्ट्रेलिया के पूर्व में विद्यमान एक विशाल द्वीप नमूर का पता लगाया, जिसका नाम न्यूजीलैंड रखा गया। इस प्रकार यद्यपि इन द्वीपों का पता पहले-पहल उच्च लोगो ने लगाया, पर वे वहां पर बसे नहीं। कैप्टिन कुक नाम के एक अंगरेज मत्लाह ने अठारहवीं सदी में इन प्रदेशों के चक्कर लगाये, और उन्हीं की आज्ञाओं के कारण इंग्लिश लोगो का ध्यान इन द्वीपों की तरफ आकृष्ट हुआ। न्यूजीलैंड व न्यू वाइल्ड का चक्कर काटकर १७६९-७० में कैप्टिन कुक ने पश्चिम की तरफ आस्ट्रेलिया की ओर प्रस्थान किया। पहले-पहल आस्ट्रेलिया में वह जिस स्थान पर पहुँचा, वहां की जमीन बहुत ही गंदी-गंदी तथा हरी-हरी थी। इसलिए उसने उसका नाम 'ग्रीनलैंड' रखा।

(हरी-भरी खाड़ी) रखा। कैप्टिन कुक ने इस प्रदेश पर ब्रिटिश लोगो का झण्डा खड़ा किया और ब्रिटिश सम्राट के नाम पर इस पर अधिकार कर लिया। ग्रेट ब्रिटेन के वेल्स प्रदेश से यह प्रदेश मिलता-जुलता है, यह समझकर इसका नाम 'न्यू साउथ वेल्स' रखा गया।

ग्रेट ब्रिटेन ने इस प्रदेश का उपयोग सबसे पूर्व 'काला पानी' के रूप में प्रारम्भ किया। १७८८ में ७५० अभियुक्त अपना दण्ड भोगने के लिये वहाँ भेजे गये। आस्ट्रेलिया में इंगलिश लोगो की यह पहली वस्ती थी, जो अपराधी कैदियों में शुरू हुई। इसके बाद प्रतिवर्ष कैदी वहाँ भेजे जाने लगे, और न्यू साउथ वेल्स की आवादी निरन्तर बढ़नी गई। कुछ समय बाद इंगलिश लोगो ने अनुभव किया, कि ये प्रदेश भेड़ पालने के लिये बहुत उपयुक्त है, और यहाँ उन का व्यवसाय बहुत तरक्की कर सकता है। इस दृष्टि में १७९० में बहुत सी भेड़ इंग्लैण्ड से आस्ट्रेलिया भेजी गई। कृषि और भेड़ पालकर उन एकत्रित करना—ये दो पेग इस नई वस्ती में खूब तरक्की करने लगे। जमीन बिल्कुल नई थी, इसलिये बहुत उपजाऊ थी। परिणाम यह हुआ, कि आस्ट्रेलिया में ब्रमे हुए लोगो को खूब फायदा होने लगा। नफे में आकृष्ट होकर बहुत से स्वतन्त्र मनुष्य भी आस्ट्रेलिया जाने लगे, और कैदियों की वस्ती के साथ-साथ स्वतन्त्र लोगो की वस्ती भी वहाँ विकसित होने लगी। बोटनी बे के उत्तर में एक स्थान था, जो बन्दरगाह बनाने के लिये बहुत उपयुक्त था। वहाँ सिडनी का बन्दरगाह विकसित हुआ। न्यू साउथ वेल्स के बाद टस्मानिया तथा पश्चिमी आस्ट्रेलिया में भी कैदियों को भेजा जाना शुरू हुआ और इन कैदियों द्वारा ही वहाँ पर वस्ति बसनी प्रारम्भ हुई। १८५१ में आस्ट्रेलिया में अनेक स्थानों पर सोने की खानें उपलब्ध हुईं, जिनसे आकृष्ट होकर हजारों मनुष्य प्रतिवर्ष ब्रिटेन से आस्ट्रेलिया पहुँचने लगे। पूँजीपति और मजदूर—दोनों ही प्रचुर मख्या में वहाँ जाने शुरू हुए। सोने की खानों की वजह से आस्ट्रेलिया की बहुत शीघ्रता में तरक्की हुई। कैदियों की अपेक्षा स्वतन्त्र मनुष्य वहाँ बहुत अधिक बढ़ गये। इन स्वतन्त्र मनुष्यों ने इस बात का विरोध करना शुरू किया कि कैदी लोग उनके प्रदेशों में बसाये जाएँ। इस आन्दोलन का परिणाम यह हुआ, कि आस्ट्रेलिया को 'काला पानी' के रूप में प्रयुक्त करना बन्द कर दिया गया।

१७८८ में आस्ट्रेलिया की आवादी केवल ७५० थी। बढ़ते-बढ़ते १९२१ में वह ५५ लाख से ऊपर पहुँच गई थी। न्यू साउथ वेल्स, टस्मानिया और पश्चिमी आस्ट्रेलिया के अतिरिक्त विक्टोरिया, क्वीन्सलैण्ड तथा दक्षिणी आस्ट्रेलिया—इन तीन उपनिवेशों का वहाँ और विकास हुआ। ये उपनिवेश कैदियों की वस्ती के रूप में कभी प्रयुक्त नहीं हुए। इसमें कृषि, ऊँच के व्यवसाय तथा सोने की खानों से आकृष्ट होकर स्वतन्त्र मनुष्य समय-समय पर बसते गये, और इसी के परिणामस्वरूप वाकायदा उपनिवेशों का विकास हो गया। पहले प्रत्येक उपनिवेश की सरकार अलग-अलग थी। कैदियों की वस्तियों में फौजी शासन होता था और स्वतन्त्र मनुष्यों पर ब्रिटेन द्वारा भेजे हुए गवर्नर शासन करते थे। पर बाद में धीरे-धीरे इन आस्ट्रेलियन उपनिवेशों में स्वराज्य का प्रारम्भ किया गया। कैदियों की वस्तियों से भी फौजी शासन उठा लिया गया। प्रत्येक उपनिवेश में व्यवस्थापिका सभा और उसके प्रति उत्तरदायी मन्त्रिमण्डल की स्थापना की गई।

**सयराज्य का निर्माण**—यह सर्वथा स्वाभाविक था, कि समयान्तर में इन उपनिवेशों में—जिनके निवासियों की भाषा, जाति, धर्म, सभ्यता, संस्कृति सब एक थी, एक राज्य की स्थापना हो। इसीलिये एक आस्ट्रेलियन संघ (फिडरेशन) बनाने के लिए उन्नीसवीं सदी के अन्तिम भाग में आन्दोलन प्रारम्भ हुआ। बहुत समय तक इस प्रश्न पर बहस होती रही। १८९१ में सब उपनिवेशों के प्रतिनिधि एक राष्ट्रीय महासभा (कान्वेंशन) के रूप में एकत्रित हुए, और उन्होंने आस्ट्रेलियन संघ के लिये शासन-व्यवस्था की रचना की। इस शासन विधान को जनता की सम्मति के लिये उपस्थित किया गया। जनता द्वारा स्वीकृत कराके इसे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सम्मुख पेश किया गया। कुछ परिवर्तनों के साथ यह वहाँ पास हो गया, और सन् १९०० में स्वीकृत हुए ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक एक्ट द्वारा आस्ट्रेलियन संघ का निर्माण हुआ। आस्ट्रेलियन नव म कुल मिलकर छ राज्य व उपनिवेश अन्तर्गत हैं—न्यू साउथ वेल्स, टस्मानिया, विक्टोरिया, क्वीन्सलैण्ड, दक्षिणी आस्ट्रेलिया और पश्चिमी आस्ट्रेलिया। इन राज्यों की अपनी-अपनी पृथक् सरकारें हैं। प्रत्येक राज्य में अपनी अपनी व्यवस्थापिका सभाएँ और मन्त्रिमण्डल हैं।

### ग—न्यूजीलैण्ड

**न्यूजीलैण्ड का विकास**—आस्ट्रेलिया के दक्षिण-पूर्व में १२०० मील की दूरी पर न्यूजीलैण्ड का उपनिवेश स्थित है। इसमें दो बड़े तथा अन्य बहुत से छोटे-छोटे द्वीप हैं, जिन सबको मिलाकर न्यूजीलैण्ड का उपनिवेश कहते हैं। इस उपनिवेश का विस्तार ४८ ट्रिलेन में सवाये के लगभग है। उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ में ही ब्रिटिश लोगों ने इस द्वीप में जाना शुरू कर दिया था। १८१४ से बहुत से ईसाई मिशनरी न्यूजीलैण्ड के मूल निवासियों को अपने धर्म में दीक्षित करने का भी उद्योग करने लगे थे। न्यूजीलैण्ड के मूल निवासी 'मओरी' लोग हैं, जो सभ्यता की दृष्टि से अफ्रीका के नीग्रो व आस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के समान बहुत पिछड़े हुए न थे। सर जार्ज गे ने इनके सम्बन्ध में इस प्रकार लिखा था—“बहुत अशो में यह अत्यन्त ऊँची जाति है। ये बड़े उत्कृष्ट योद्धा हैं, ये बड़े वाग्मी, समझदार, अभिमानी तथा सीधे लोग हैं। उन्होंने मेरे साथ जो व्यवहार किया है, उसमें उन्होंने मेरे भावों तथा सहानुभूति को जीत लिया है।” इसमें स्पष्ट है, कि इन 'मओरी' लोगों को अपने धर्म में दीक्षित कर लेना या उन्हें सबका नष्ट कर देना बहुत सुगम कार्य न था। 'मओरी' लोगों ने अंग्रेजों से अनेक घनघोर युद्ध किये। आखिर, १८४० में दोनों जानियों में परस्पर सुलह हो गई। 'मओरी' लोगों ने महारानी विक्टोरिया को अपना अधिपति मानना स्वीकृत कर लिया। उस वकालत में उनके निवास के लिये एक निश्चित प्रदेश जलग कर दिया गया, जिसमें निवास स्वतन्त्रतापूर्वक वहाँ निवास कर सकें। मओरी लोगों में निवृत्तार करके अंग्रेजों ने न्यूजीलैण्ड के टापुओं में अपनी वस्तियाँ बसानी प्रारम्भ की। इस कार्य के लिये ब्रिटिश में एक कम्पनी कायदा बनाई गई थी, जिसका नाम था—'न्यूजीलैण्ड कंपनी'। इसने इस द्वीप-समूह को अग्राह करने का निरन्तर प्रयत्न किया।

उन के व्यवसाय के लिये भेड़ों को पालने की न्यूजीलैण्ड में भी बहुत मुविधा थी। इसमें आकृष्ट होकर बहुत से अंगरेज वहां जा बसे। साथ ही, कुछ वर्षों के बाद जब आस्ट्रेलिया की तरह न्यूजीलैण्ड में भी सोने की खानें मिल गईं, तब तो बहुत बड़ी संख्या में अंगरेज लोग वहां जाकर आबाद होने लगे। न्यूजीलैण्ड का बड़ी शीघ्रता में विकास हुआ, और रोजगार के लिये उपयुक्त स्थान ढूँढने की धुन में अंगरेजों ने 'मओरी' लोगों की वस्तियों में भी हस्तक्षेप करना शुरू किया। परिणाम यह हुआ, कि १८६० और १८७१ में 'मओरी' लोगों ने दो बार विद्रोह किये। इन्हें बड़े भयंकर रूप से कुचला गया। उसके बाद फिर भी 'मओरी' विद्रोह नहीं हुए हैं।

सब का शासन विधान—न्यूजालैण्ड के विविध प्रदेशों में जो बस्निया बस रही थी, १८५१ में उनकी संख्या छ थी—आकलैण्ड, वेग्लिंगटन, न्यू प्लाडमाउथ, (ये न्यूजीलैण्ड के उत्तरी द्वीप में हैं), नेल्सन, आटागो और केंटरबरी (ये दक्षिणी द्वीप में हैं)। १८५२ में इन सबको संगठित कर एक शासनविधान की व्यवस्था की गई। ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा स्वीकृत एक एक्ट के अनुसार इन छठों बस्तियों व राज्यों में पृथक् स्थानीय स्वराज्य की स्थापना की गई, और साथ ही विविध बस्तियों को मिलाकर एक केन्द्रीय संघ का निर्माण किया गया। संघ की शासनव्यवस्था इस प्रकार बनाई गई—व्यवस्थापन विभाग में दो संभाए रखी गईं, कौन्सिल और प्रतिनिधि-सभा। कौन्सिल के सदस्य गवर्नर-जनरल द्वारा नियत किये जाने और प्रतिनिधि संभा के सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित होने की व्यवस्था की गई। मन्त्रिमण्डल प्रतिनिधि संभा के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। गवर्नर-जनरल की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा की जाने की व्यवस्था रखी गई।

एकात्मक (यूनिटरी) राज्य का निर्माण—यह पद्धति १८७५ तक जारी रही। पर न्यूजीलैण्ड में बहुत से टापू हैं, और धीरे-धीरे इन टापुओं में भी बस्तियां बसनी गईं। इन सब में प्रान्तीय स्वराज्य की स्थापना कर सकना कठिन था, और इतने सारे प्रान्तों के हो जाने से केन्द्रीय सरकार की शक्ति भी बहुत कम हो जाती थी। इसलिए १८७६ में प्रान्तीय स्वराज्य का अन्त कर न्यूजीलैण्ड में एक मजबूत केन्द्रीय लोकतन्त्र सरकार की स्थापना की गई।

### घ—दक्षिणी अफ्रीका

प्रारम्भिक इतिहास—अफ्रीकन महाद्वीप के सबसे दक्षिणी सिरे पर एक अन्तरीप है, जिसे सदाशा का अन्तरीप (केप आफ गुड होप) कहते हैं। इस पर सबसे पहले डच लोगों ने अपना अधिकार किया था, और वे ही लोग यहां पर आबाद हुए थे। फ्रेच राज्यक्रान्ति के अनन्तर हालैण्ड फ्रांस के अधीन हो गया था, और नैपोलियन के फ्रेच सम्राट् बन जाने पर यह देश उसके साम्राज्य का अंग बन गया था। क्योंकि हालैण्ड नैपोलियन के अधीन था, इसलिए इस अन्तरीप में विद्यमान केप कालोनी (अन्तरीप-उपनिवेश) नामक डच उपनिवेश पर भी नैपोलियन का अधिकार था। नैपोलियन की शक्ति को नष्ट करने के लिए जब ब्रिटेन ने अनवरत रूप से संघर्ष प्रारम्भ किया, तब



यूरोप से हजारों मील की दूरी पर स्थित इस उपनिवेश पर नैपोलियन या हालैंड का अधिकार कायम न रह सका, और यह ग्रेट ब्रिटेन के कब्जे में आ गया। वीणना की कांग्रेस में (सन् १८१४) केप कोलोनी पर ब्रिटेन के अधिकार को स्वीकृत कर लिया गया। तब से यह प्रदेश ब्रिटेन के ही अधीन है। जिस समय केप कोलोनी ब्रिटेन के हाथ में आया, उस समय उसकी आबादी निम्नलिखित प्रकार से थी—(क) २७,००० गौर वर्ण के मनुष्य, जो प्रायः सभी उच्च जाति के थे। (ख) ३०,००० नीग्रो तथा मूल्य जाति के गुलाम, (ग) १७,००,००० हांटेन्टोन्ट जाति के लोग, जो उस प्रदेश के मूल निवासी थे। १८२० के बाद ब्रिटिश लोगों ने निरन्तर इस प्रदेश में जाना तथा बसना प्रारम्भ किया। परन्तु गौरवर्ण के लोगों की अधिक संख्या उच्च जाति की ही रही। उच्च जाति प्रायः किसान थे। वे अपनी भाषा, रीति-रिवाज तथा सभ्यता को किसी भी दशा में छोड़ना नहीं चाहते थे। उनकी रक्षा के लिए वे मर मिटने को उद्यत रहते थे। केप कोलोनी के अपने अधिकार में आ जाने पर ब्रिटिश शासकों ने कोशिश की कि इंगलिश भाषा, रीति-रिवाज तथा सभ्यताओं को वहाँ पर प्रयोग में लाए। उच्च किसान, जो बोअर नाम से प्रसिद्ध हैं, इस बात को सहन नहीं कर सके। वे नहीं चाहते थे, कि उनके प्रदेश में अंग्रेजी भाषा उपयोग में आए और इंगलिश डग से न्यायालयों का संगठन किया जाय। सन् १८३३ में अंग्रेजी सरकार ने निश्चय किया, कि दास-प्रथा का अन्त कर दिया जाय। बोअर लोग प्रायः दासों द्वारा ही खेती का कार्य किया करते थे। दास-प्रथा का अन्त कर देने से उन्हें भारी नुकसान था। दासों को मुक्त कराने के लिए ४५ करोड़ के लगभग रुपये ब्रिटिश सरकार ने खर्च किये, पर बोअर लोगों की दृष्टि में यह कीमत बहुत कम थी। वे इससे सन्तुष्ट नहीं हुए।

**बोअर लोगों का महाप्रस्थान**—ब्रिटिश शासकों के इस व्यवहार से तब आकर बोअर लोगों ने निश्चय किया, कि केप कोलोनी को—जिसे कि उन्होंने स्वयं या उनके पुरजाने पहले-पहल आबाद किया था, मराने के लिये छोड़ कर उत्तर में अपने लिये नई भूमियाँ बसा लें। बोअर लोगों का यह 'महाप्रस्थान' १८३६ में शुरु हुआ। अपने सब माल-जमनाबों को बड़े-बड़े ढाँड़ों पर (जिनमें बैल जुते होते थे) लादकर दम हजार बोअर लोग उत्तर की ओर चल पड़े। केप कोलोनी के उत्तर में उस समय भयंकर जंगल थे, जिनमें बहुत सी जंगली जातियाँ निवास करती थीं। बोअर लोगों ने इन जंगलों को माफ किया, और दो नये उपनिवेश बनाये। ये नये उपनिवेश नैटाल तथा ओरेन्ज नदी की धारों में बसाये गये थे। कुछ समय तक बोअर लोग अपने नये प्रदेशों में स्वतन्त्रता के साथ बसत रहे। ब्रिटिश लोगों ने उनमें हस्तक्षेप नहीं किया। पर यह दशा देर तक नहीं रह सकी। नैटाल समुद्र तट पर स्थित था। ब्रिटिश लोग नहीं चाहते थे, कि समुद्र-तट के जिन महत्वपूर्ण स्थानों पर एक विदेशी राज्य का भ्रम हो जाए। इसलिए उन्होंने चार्ज (जिस समय यह पोर्ट नैटाल कहा जाता था, और नैटाल प्रदेश का मुख्य नगर तथा बन्दरगाह था) पर अधिकार करने के लिये एक नौ नौ भेजी। १८४२ में ब्रिटिश तथा उच्च सेनाओं में युद्ध हुआ। उच्च सेना परास्त हो गई, और नैटाल ब्रिटिश लोगों के कब्जे में आ गया। नैटाल तथा ओरेन्ज के स्वतन्त्र उच्च राज्य जो भी अपने अधीन करना चाहते थे। १८४८

मे उन्होंने उस पर भी आक्रमण किया, और डच लोगों को परास्त कर अपने अधिकार में कर लिया।

बोअर लोग एक बड़ी विकट समस्या का सामना कर रहे थे। इंगलिश लोग उन्हें शान्ति से नहीं रहने देना चाहते थे। यदि ब्रिटिश शासक केवल अपना राज्य ही स्थापित करते, तो उन्हें कोई विशेष आपत्ति न भी होती, पर ब्रिटिश लोग अपनी भाषा, संस्कृति, गत्या आदि को प्रचलित किये बिना नहीं रह सकते थे, और बोअर लोगों के लिये यह सह सकना असम्भव था। परिणाम यह हुआ, कि एक बार फिर बोअर लोगों ने महा-प्रस्थान शुरू किया। ओरेन्ज उपनिवेश के उत्तर में बाल नदी के पार एक नया उपनिवेश बोअर लोगों द्वारा बसाया गया, जो अब ट्रान्सवाल के नाम से प्रसिद्ध है। ब्रिटिश लोग सम्भवतः इसमें भी हस्तक्षेप करते, पर उनकी सम्मति में इसका कोई अधिक महत्व नहीं था। यह मुख्यतया पशुओं के लिये चरागाह का ही काम दे सकता था। इसलिये ब्रिटिश लोगों ने यही उपयुक्त समझा, कि इसे जीतकर अपने अधीन करने की तकलीफ न उठाई जाए। १८५२ में ब्रिटिश तथा बोअर लोगों में सन्धि हो गई, जिसके अनुसार अंगरेजों ने ट्रान्सवाल में बोअर लोगों की स्वाधीनता को स्वीकृत कर लिया, और साथ ही यह विश्वास दिलाया, कि इस प्रदेश में बाअर लोग स्वतन्त्रतापूर्वक रह सकेंगे, और ब्रिटिश लोग उसमें किसी प्रकार में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दो वर्ष पश्चात् १८५४ में ओरेन्ज उपनिवेश की भी स्वाधीनता स्वीकृत कर ली गई, और वह 'ओरेन्ज का स्वतन्त्र राज्य' के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार अब दक्षिणी अफ्रीका में कुल चार उपनिवेश हो गये, जिनमें से दो—केप कोलोनी और नैटाल—अंगरेजों के अधीन थे, और शेष दो—ओरेन्ज का स्वतन्त्र राज्य तथा ट्रान्सवाल—बोअर लोगों के।

### ३. भारतवर्ष

यूरोप के विविध लोगों ने किस प्रकार भारत में व्यापार का प्रारम्भ किया, इस देश की राजनीतिक दुरवस्था से लाभ उठाकर उन्होंने किस प्रकार यहाँ अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयत्न किया, और इस प्रयत्न में किस प्रकार अन्त में ब्रिटेन की सफलता हुई, इसका वृत्तान्त मसार के आधुनिक इतिहास में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पर भारतीय पाठकों के लिये लिखे गये इस इतिहास में इसका विवरण देना उपयोगी नहीं होगा। हमारे सब पाठक इस वृत्तान्त से भली-भाँति परिचित ही होंगे। पर यह निदेश करना आवश्यक है, कि ग्रेट ब्रिटेन की सरकार ने भारत को विजय करने के लिये कोई सेनाएँ नहीं भेजी। जिस समय नये प्रदेशों की खोज के लिये व पूर्वी देशों के साथ व्यापार का विकास करने के लिये यूरोप के लोग प्रवृत्त हुए, तो इङ्ग्लैण्ड में एक कम्पनी की स्थापना हुई, जिसका नाम ईस्ट इण्डिया कम्पनी था, और जिसका उद्देश्य भारत के साथ व्यापार करके समृद्ध होना था। इस कम्पनी के प्रतिनिधियों ने भारत के मुगल बादशाहों से व्यापार सम्बन्धी अनेक सुविधाएँ प्राप्त की, और समुद्र तट पर अनेक कोठिया स्थापित की, जो कम्पनी के व्यापार का केन्द्र होती थी। अंग्रेजों के समान पोर्तुगीज, डच और फ्रेञ्च लोग भी भारत के साथ अपना इसी ढंग का व्यापार विकसित

करने के लिये तत्पर थे ।

जीरङ्गजेव की साम्प्रदायिक नीति के कारण दिल्ली के मुगल बादशाहों की शक्ति बहुत क्षीण हो गई थी । अठारहवीं सदी के मुगल बादशाह बहुत निर्बल थे, और उनके नाम के विरुद्ध राजपूतों, मराठों और सिक्खों ने विद्रोह का झण्डा खड़ा कर दिया था । मुगल बादशाहत में राष्ट्रीय अनुभूति का अभाव था । अतः विविध प्रदेशों पर शासन करनेवाले सूबेदार लोग भी अवसर प्राप्त होने पर अपनी शक्ति बढ़ाने व स्वतन्त्र राजाओं व नवाबों के समान शासन करने के लिये उद्यत रहते थे । मुगल बादशाहत की शक्ति के आधार उसके विविध सरदार, सूबेदार, सामन्त और सैनिक ही थे । यदि बादशाह निर्बल हो, तो इनमें स्वाभाविक रूप से स्वच्छन्द हो जाने की भावना जोर पकड़ने लगती थी । अनेक बड़े सूबों के शासक वंशक्रमानुगत रूप से अपने प्रदेशों का शासन करते थे, राज्य के अनेक उच्च पद भी वंशक्रमानुगत रूप से चलते थे । उस समय भारत में न राष्ट्रीयता की भावना थी, और न लोकतन्त्रवाद की सत्ता थी । इस दशा में यूरोप की विविध व्यापारी कम्पनियों को इस देश के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अवसर मिल गया । यहाँ की राजनीतिक दुर्दशा से लाभ उठाकर अपनी राजनीतिक मना हम देश में स्थापित की जा सकती है, यह विचार सबसे पहले फ्रांस के लोगों में उपलब्ध हुआ था । झूले पहला यूरोपियन राजनीतिज्ञ था, जिसने भारत में फ्रांस का साम्राज्य स्थापित करने का स्वप्न लिया । पर फ्रेच लोगों को अपने प्रयत्न में सफलता नहीं मिल सकी । इसका एक प्रमुख कारण यह था, कि अठारहवीं सदी में फ्रांस में वृद्धि का निरंकुश व स्वेच्छाचारी शासन था, और भारत में फ्रेच लोग व्यापार के विस्तार का जो प्रयत्न कर रहे थे, उसका संचालन फ्रांस की इस निरंकुश सरकार द्वारा ही होता था । इसके विपरीत, ब्रिटेन की ईस्ट इण्डिया कम्पनी ब्रिटिश सरकार से क नियन्त्रण में प्रायः स्वतन्त्र थी । अतः उसके लिये यह अधिक सुगम था, कि वह समय और परिस्थिति के अनुसार स्वतन्त्रता के साथ कार्य कर सके । झूले के प्रधान इंगलिश प्रतिद्वन्द्वी क्लाइव को यह आवश्यकता नहीं थी, कि वह अपने प्रत्येक कार्य के लिये सरकार से अनुमति ले । इसके विपरीत झूले को अपने कार्यों के लिये फ्राम की सरकार का मुँह रटना पड़ता था, और इस युग की फ्रेच सरकार सर्वथा विकृत और दुर्दशाग्रस्त थी । भारत के विविध राजाओं, नवाबों व सूबेदारों के पारस्परिक झगड़ों का लाभ उठाकर अन्त में ब्रिटेन की ईस्ट इण्डिया कम्पनी इस देश के बड़े भाग में अपना शासन स्थापित करने में समर्थ हुई । उन्नीसवीं सदी के मध्य भाग तक प्रायः सम्पूर्ण भारत में अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो गया था, और इस देश के विविध राजा व नवाब उनकी शक्ति में आ गये थे ।

यद्यपि भारत में राष्ट्रीय एकता की भावना का प्रायः अभाव था, पर यहाँ की जनता इन विधर्मी और विदेशी शासकों से सर्वथा असंतुष्ट थी । ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन में भारत में अपने शासन को अपनी आर्थिक समृद्धि का माधनमात्र समझने का भाव आया । अपनी आर्थिक नीति का संचालन इसी उद्देश्य से होता था, कि कम्पनी की आमदनी में निरन्तर वृद्धि हो । साथ ही, भारत के अंग्रेजी शासन इस देश के धार्मिक विश्वास व

पुरानी परम्पराओं की जरा भी परवाह नहीं करते थे। इस दशा का परिणाम यह हुआ, कि उनके शासन के विरुद्ध भावना इस देश में निरन्तर जोर पकड़ती गई, और १८५७ में यह भावना एक राज्यक्रान्ति के रूप में परिवर्तित हो गई। परन्तु ५७ की यह राज्य-क्रान्ति सफल नहीं हो सकी, अंग्रेजों ने उसे कुचलने में समर्थ हुए, और भारत में अंग्रेजी शासन की जड़ें और भी मजबूत हो गईं। ५७ की क्रान्ति के बाद भारत का शासन ब्रिटिश सरकार ने आने वालों में ले लिया। इस विगलदश पर ब्रिटिश शासन स्थापित हो जाने के कारण ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार व शक्ति में बहुत अधिक वृद्धि हुई।

## ४ क्राउन कोलोनी

कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका, न्यूजीलैंड और न्यू फाउण्डलैंड मदन औपनिवेशिक राज्यों और भारत के अतिरिक्त अन्य भी बहुत से छोटे-छोटे प्रदेश ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत थे, जो क्राउन कोलोनी के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनमें से बहुत-संख्यक प्रदेश अब तक भी ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत हैं। उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ में जब नैपोलियन यूरोप में अपने आधिपत्य को स्थापित करने में व्यस्त था, समुद्र के क्षेत्र में ब्रिटेन की शक्ति अजेय थी। यही कारण है, कि फ्रान्स द्वारा अधिगत अनेक प्रदेशों को इस अवसर से लाभ उठाकर ब्रिटेन ने अपने अधीन कर लिया था। क्योंकि नैपोलियन के युद्धों के कारण हालैंड भी फ्रांस के अधीन हो गया था, अतः अनेक उच्च प्रदेश भी इस अवसर पर ब्रिटेन ने अपने अधीन कर लिये थे। वीएना की कांग्रेस (१८१४) में जब यूरोप की पुनर्व्यवस्था की गई, और नैपोलियन के साम्राज्य का नये सिरे से निवृत्त किया गया, तो इन विविध प्रदेशों को ब्रिटेन ने अपनी अधीनता में रखा, और इस प्रकार वे विभिन्न प्रदेश ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत हुए, जो अब क्राउन कोलोनी कहते हैं। इसी समय मोरिशस का द्वीप ब्रिटेन ने फ्रान्स से प्राप्त किया, क्योंकि भारत के सामुद्रिक मार्ग की दृष्टि से यह भी बहुत महत्वपूर्ण था। १८१९ में सिंगापुर ब्रिटेन को अधीनता में आ गया। सुदूर पूर्व जाने के सामुद्रिक मार्ग के लिये यह प्रदेश भी अत्यन्त महत्व का था। १८३९ में अदन पर ब्रिटेन का प्रभुत्व स्थापित हुआ।

यहाँ हमारे लिये यह सम्भव नहीं है, कि ब्रिटेन के सब क्राउन कोलोनियों के सन्बन्ध में उल्लेख कर सकें। इस इतिहास में केवल इतना निर्देश करना पर्याप्त होगा, कि ये कोलोनी एशिया, अमेरिका, अफ्रीका आदि सर्वत्र फैले हुए हैं। सुदूर पूर्व के बहुत से द्वीप ब्रिटेन के अधीन हैं। भारत के दक्षिण में सीलोन (लंका) की स्थिति १९४७ तक एक क्राउन कोलोनी के समान थी। अटलाण्टिक महासागर में वेस्ट इन्डिज के अनेक द्वीप ब्रिटेन के आधिपत्य में हैं, और भूमध्य सागर में जिब्राल्टर, माल्टा आदि अनेक प्रदेशों में व द्वीपों पर ब्रिटेन का शासन स्थापित है। ब्रिटेन के सामुद्रिक आधिपत्य के लिये ये कोलोनी बहुत उपयोगी हैं। इन सबके शासन का प्रकार भी एक नहीं है। कुछ कोलोनी ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त हुए गवर्नर द्वारा शासित होते हैं, और उनके शासन में जनता का कोई हाथ नहीं है। कुछ कोलोनी ऐसी भी हैं, जिनके शासन में जनता का सहयोग लिया जाता है।

सत्ताईसवा अध्याय

## यूरोप का विस्तार

### १ यूरोप और एशिया

एशिया का इतिहास बहुत पुराना है। ससार के प्राचीन इतिहास में सभ्यता का ग्रीगणेश इसी भूखण्ड में हुआ था। इतिहास के किसी अज्ञात प्राचीन काल में एशिया में ही अनेक जातियों ने जाकर यूरोप में सभ्यता का विकास किया था। बाद में भी एशिया और यूरोप का परस्पर सम्बन्ध कायम रहा। यूरोप अपनी सभ्यता के लिये अनेक अंशों में एशिया का ऋणी है। भारत, अरब और चीन के ससर्ग से समय-समय पर बहुत सी बातें यूरोप ने एशिया से सीखी। राजनीतिक दृष्टि से भी इन दो महाद्वीपों का सम्बन्ध बहुत पुराना है। यद्यपि आधुनिक युग में एशिया के अधिकांश देश यूरोपियन लोगों के राजनीतिक प्रभाव में रहे हैं, पर पहले यह बात नहीं थी। जब हम प्राचीन और मध्य-कालीन इतिहास पर दृष्टि डालते हैं, तो हमें ज्ञात होता है कि ईसा से कई सदी पूर्व एशिया के लोग यूरोप पर आक्रमण कर वहाँ अपने राजनीतिक प्रभाव को स्थापित करने में समर्थ रहे थे। पर्शियन, टूण, मगयार, तार्तार, अरब और तुर्क आक्रान्ताओं ने समय-समय पर यूरोप के ऊपर आक्रमण कर वहाँ अपना प्रभुत्व स्थापित किया था।

परन्तु मतरहवी मदी में इस स्थिति में परिवर्तन जाना शुरू हुआ। ग्रीस-रोम जातियों ने व्यापार के लिये एशिया में प्रवेश करना प्रारम्भ किया। यूरोप में समय-समय उन्नति के पथ पर आरुढ़ था। वहाँ विद्या की पुनर्जागृति हो चुकी थी और मानसिक व बौद्धिक स्वतन्त्रता की भावना लोगों में उत्पन्न हो गई थी। जनता ने अपनी बुद्धि से काम लेना प्रारम्भ कर दिया था। नये-नये आविष्कार हो रहे थे। व्यापारिक वृत्ति ने लोगों के सम्मुख नये क्षेत्र, नई आकांक्षाएँ और नये मार्ग खो दिये थे। कृषि तथा व्यवसाय के क्षेत्र में जो वृत्ति हो रही थी, वह यूरोपियन लोगों के जीवन और स्थिति में बड़ा भारी परिवर्तन ला रही थी। यूरोपियन लोगों में नव-जीवन का संचार हो रहा था। उधर दूसरी ओर एशिया की हालत उस समय अच्छी नहीं थी। एशिया के प्रायः सभी देशों में राजनीतिक शक्ति शिथिल हो गई थी, जनता में राष्ट्रीय जीवन का अभाव था। जिन परिस्थितियों और कारणों से यूरोप में नव-जीवन का प्रादुर्भाव हो रहा था, वे एशिया में अभी प्रारम्भ नहीं हुए थे। यहाँ परिणाम यह हुआ, कि यूरोपियन लोग एशिया पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने में सफल हो गये।

इस ध्यान में रखना चाहिये कि एशिया के लोग अफ्रीका व अमेरिका के मनु-

निवासियों के समान असभ्य व अर्द्धसभ्य नहीं थे। एशिया की जनता सभ्यता की दृष्टि से बहुत उन्नत थी। यदि धर्म, साहित्य, कला और विचार आदि की दृष्टि में देखा जाय, तो एशिया के देश यूरोप में किसी भी अंश में पीछे न थे। यही कारण है, कि यूरोपियन लोग एशिया में उस ढंग से अपना साम्राज्य-विस्तार नहीं कर सके, जिस तरह उन्होंने अमेरिका व अफ्रीका में किया। उन महाद्वीपों में उन्होंने वहाँ के मूल निवासियों को प्रायः नष्ट कर देने का प्रयत्न किया। अमेरिका में आज करोड़ों स्वतंत्र लोग बसते हैं, जो यूरोपियन जातियों के वंशज हैं। वहाँ के मूल निवासी या तो नष्ट कर दिये गये हैं, और या पूर्ण रूप से यूरोपियन सभ्यता में दीक्षित कर लिये गये हैं। यही प्रक्रिया अफ्रीका में हो रही है। पर एशिया में स्वतंत्र लोगों की कुछ जावादी दस लाख से अधिक नहीं है, जब कि एशिया के लोगों की संख्या एक अरब से भी अधिक है। यूरोपियन लोगों के लिये यह असम्भव है, कि वे एशियन लोगों को नष्ट कर सकें व पूर्णतया अपनी सभ्यता में दीक्षित कर सकें। धीरे-धीरे एशियाई लोग उन नव विद्वानों व विज्ञानियों को सीखते जाते हैं, जिनके कारण यूरोपियन लोग उन्हें अपनी अधीनता में लाने में समर्थ हुए थे। अब वह समय भी आ गया है, जब कि एशिया में यूरोप का आधिपत्य प्रायः नष्ट हो गया है, और एशियाई लोग फिर अपनी सभ्यता व संस्कृति का स्वतन्त्र रूप में विकास करने में समर्थ हो रहे हैं। एशिया का यह पुनः जागरण उन्नीसवीं सदी के अन्तिम भाग में प्रारम्भ हो गया था।

हम इस अध्याय में इस बात पर प्रकाश डालेंगे, कि विविध एशियाई देशों में यूरोपियन जातियों का प्रभुत्व किस प्रकार स्थापित हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका के एक शक्तिशाली व सुसंगठित राज्य बन जाने पर वह भी एशिया में अपने साम्राज्य के प्रसार में तत्पर हुआ। यूरोप और अमेरिका के गौरांग लोग एशिया में जो अपना प्रभाव प्रसारित कर रहे थे, उसके मुख्य साधन निम्नलिखित थे—(१) पिछड़ी हुई जातियों द्वारा आवाद प्रदेशों का अवगाहन कर उन पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना। हम ने साइबीरिया में जो अपना साम्राज्य विस्तृत किया, वह इसी ढंग से हुआ था। (२) ईसाई मिशनरियों द्वारा प्रचार। चीन में यूरोपियन लोगों का प्रवेश इसी साधन द्वारा हुआ। (३) व्यापार द्वारा। भारत में ब्रिटिश लोगों ने अपना प्रभुत्व व्यापार का आश्रय लेकर ही स्थापित किया। चीन, ईरान आदि देश भी व्यापार के प्रसार द्वारा ही यूरोपियन देशों के प्रभाव में आये। (४) युद्ध द्वारा, विविध एशियाई देशों की राजनीतिक दुरवस्था में लाभ उठाकर यूरोपियन लोगों ने वहाँ अनेक युद्ध किये, और इन युद्धों में विजयी होकर वे वहाँ अपना प्रभुत्व स्थापित करने में समर्थ हुए।

एशिया में गौराङ्ग लोगों की प्रभुत्व की स्थापना के विविध युगों को हम निम्नलिखित भागों में विभक्त कर सकते हैं—

(१) रूसी साम्राज्य का उत्तरी एशिया में प्रसार—यूराल पर्वत के पूर्व में उत्तरी एशिया का जो विशाल प्रदेश साइबीरिया के नाम से प्रसिद्ध है, उस पर रूसी लोगों ने अपना प्रभुत्व सोलहवीं सदी में स्थापित करना शुरू किया था। सत्रहवीं सदी में रूसी लोग सम्पूर्ण साइबीरिया को अपनी अधीनता में ला चुके थे। इस युग में ब्रिटिश, फ्रेंच,

डच, पोर्तुगोज आदि अन्य यूरोपियन लोग एशिया के विविध देशों से व्यापार का सम्बन्ध स्थापित करना तो शुरू कर चुके थे, पर उनका राजनीतिक प्रभुत्व अभी कहीं स्थापित नहीं हुआ था।

(२) अठारहवीं सदी में इङ्ग्लैण्ड और फ्रांस भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना के लिये प्रवृत्त हुए।

(३) उन्नीसवीं सदी में चीन और पूर्वी एशिया के अन्य देशों पर यूरोप के राज्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित करना शुरू किया। इसी समय आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड व प्रशान्त तट हिन्द महासागरों के विविध द्वीपों में यूरोप के लोगों ने अपने उपनिवेशों का विकास किया, और अपने राजनीतिक प्रभुत्व को स्थापित किया।

बीसवीं सदी के शुरू तक यह स्थिति आ गई थी, कि जापान के अतिरिक्त प्रायः अन्य नव यूरोपियन देश किसी न किसी रूप में यूरोप व अमेरिका के प्रभाव में आ चुके थे। टंगन, तिब्बत, सिआम आदि जो देश राजनीतिक दृष्टि से अभी स्वतन्त्र थे, वे भी किसी न किसी रूप में किसी न किसी यूरोपियन राज्य के प्रभाव में थे।

## २. रूस का एशिया में प्रसार

पन्द्रहवीं सदी तक रूस अनेक छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था, और इनके राजा व पदार्थ प्रायः आपस में लड़ते थे। तेरहवीं सदी में चगेज खा (११६२-१२२७) ने अपने विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जो पूर्व में प्रशान्त महासागर से शुरू होकर पश्चिम में कम्पियन सागर तक विस्तृत था। चगेज खा के उत्तराधिकारियों ने साम्राज्य विस्तार की प्रक्रिया को जारी रखा। चगेज खा का पौत्र बातू खा बड़ा प्रतापी और महत्वाकांक्षी था। १२३६ में उसने यराल नदी को पार कर रूस पर आक्रमण किया, और वीरे-वीरे रूस के सब राज्यों को विजय कर लिया। रूस के विविध राजा मंगोल सम्राट की अधीनता में स्वीकृत करने पर, और नियमित रूप में कर व उपहार आदि देकर उसे सतुष्ट रखते थे। पन्द्रहवीं सदी तक रूस मंगोल साम्राज्य के अधीन रहा। यद्यपि रूस के जलन्तरीय शासन में मंगोल लोग हस्तक्षेप नहीं करते थे, और वहाँ के विविध राजाओं को यह स्वतन्त्र था, कि वे अपने-अपने क्षेत्र में स्वेच्छाचारपूर्वक शासन करते रहे, पर इसमें मन्देह नहीं, कि वे मंगोल सम्राट के वशवर्ती व अधीन थे। रूस के इन विविध राजाओं में मास्को का राजा सबसे अधिक शक्तिशाली था, और चीन के मंगोल दरबार में उसकी विशेष प्रतिष्ठा थी। पन्द्रहवीं सदी में मंगोल साम्राज्य की शक्ति क्षीण होने लगी, और प्रभुत्व में लान उठाकर १४८० में मास्को के राजा ने अपनी स्वतन्त्रता घोषित कर दी। मंगोल सम्राट के जो प्रतिनिधि रूस में कर व उपहार वसूल करने के लिये नियुक्त होते, उन्हें तब तक रुक दिया गया, और रूस मंगोल साम्राज्य की अधीनता में मुक्त हो गया। अब रूस के राजाओं ने मास्को के राजा का अपना अधिपति स्वीकृत किया, और उन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों में मंगोल सम्राट की उपाधि धारण की। इसी चतुर्थ के पूर्व-जो मास्को का राजा जयसूरी राजाओं को अपना नामान्त बना चुके थे, और इसी कारण से एक मुनगटिन व शक्तिशाली केन्द्रीय शासन की स्थापना हो गई थी।

मास्को के राजा केवल रूस में अपना स्वतन्त्र शासन स्थापित करके ही सतुष्ट नहीं हुए, साथ ही उन्होंने साम्राज्य विस्तार के लिये भी प्रयत्न शुरू किया। यूराल के पूर्व में मंगोल व तार्तार लोगों का शासन था। १४०९ ई० में एक रूसी सेना ने यूराल को पार कर मंगोल लोगों पर आक्रमण किया। एक महीने तक रूसी और तार्तार लोगों में निरन्तर युद्ध होते रहे। अन्त में मंगोल व तार्तार लोग परास्त हुए, और रूसी लोगों के लिए यूराल के पूर्व में अपना प्रसार करने का मार्ग साफ हो गया। इस प्रकार एशिया में उस विशाल रूसी साम्राज्य का विकास शुरू हुआ, जो मंगोल के इतिहास में वस्तुतः अद्भुत और अद्वितीय है।

**रूसी साम्राज्य की विशालता**—इसमें पूर्व कि हम एशिया में रूस के साम्राज्य-विस्तार का इतिहास लियें, यह उल्लिखित करना उपयोगी होगा, कि यह साम्राज्य कितना विस्तृत व विशाल है। एशिया में रूस का यह साम्राज्य पश्चिम में पूर्व तक ४,००० मील लम्बा है। इसकी चौड़ाई दक्षिण में उत्तर तक ३,००० मील के लगभग है। इसका कुल क्षेत्रफल ६३,३५,००० वर्गमील है। वर्तमान समय में रूस के सोवियत यूनियन में जितना भूखण्ड अन्तर्गत है, उसका तीन चौथाई एशिया में है, और एशिया के ये प्रदेश राष्ट्रीयता (भाषा, जाति, नस्ल आदि) की दृष्टि से रूस में सर्वथा भिन्न हैं। एशिया की सम्पूर्ण भूमि का ४० फी मही भाग रूसी साम्राज्य के अन्तर्गत है। भौगोलिक दृष्टि से एशियाई रूस को चार भागों में विभक्त किया जा सकता है —

साइबीरिया—	४७,३०,००० वर्गमील
काजकस्तान—	१०,५६,००० वर्गमील
मध्य एशिया—	४,७८,००० वर्गमील
ट्रांस काकेशिया—	७१,००० वर्गमील

**सर्वयोग—** ६३,३५,००० वर्गमील

इतने विशाल भूखण्ड को रूस किस प्रकार अपनी अधीनता में लाने में समर्थ हुआ इसका विवरण यूरोप के आधुनिक इतिहास में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

**साइबीरिया पर अधिकार**—सोलहवीं सदी में तार्तार (मंगोल) लोगों को परास्त कर चुकने के बाद रूसी लोगों के लिए पूर्व में साइबीरिया में अपना प्रसार करने का मार्ग खुल गया था। उस समय साइबीरिया में किसी उन्नत सभ्यता का विकास नहीं हुआ था। इस प्रदेश में आबादी बहुत कम थी, और इसके निवासी प्रायः असभ्य और जंगली थे। साइबीरिया में अनेक ऐसे जन्तुओं का निवास था, जिनकी खालें (फर) बहुत कीमती होती थी। यूरोप के वाजारों में ये फरें बहुत ऊँचे मूल्य पर विकती थीं। इनसे आकृष्ट होकर बहुत से रूसी शिकारी व व्यापारी साइबीरिया जाने लगे। साइबीरिया के मूल निवासियों को अपने वश में लाने में इन्हें कोई कठिनाई नहीं हुई। सोलहवीं सदी में फरों के इस व्यापार ने अच्छी उन्नति की। इस युग में रूस से जो माल विदेशों में विक्री के लिए जाता था, साइबीरिया की फरें उसमें सबसे प्रमुख स्थान रखती थीं। राज्य की ओर से इन रूसी शिकारियों और व्यापारियों को प्रोत्साहन मिलता था। धीरे-धीरे ईसाई



प्रचारको ने भी साइबीरिया जाना शुरू किया। उनका प्रयत्न था, कि साइबीरिया के जमभ्य लोगों को ईसाई धर्म में दीक्षित कर लिया जाय। उन दिनों इस प्रदेश में न मडके थी, और न कोई रास्ते ही थे। सारा प्रदेश झाडियो व जगलो से आच्छादित था। नदियो के साथ-साथ रूस के शिकारी, व्यापारी और पादरी आगे बढ़ते थे, और अनुकूल स्थानों पर डेरे डालकर रहते थे। साइबीरिया में रूस के इस प्रसार का स्वरूप प्रायः वैसा ही था, जैसा कि संयुक्तराज्य अमेरिका में ब्रिटिश व अन्य यूरोपियन लोगों का। अमेरिका में ब्रिटिश व फ्रेंच लोगों की वस्तियां शुरू-शुरू में अटलाण्टिक सागर के तटवर्ती प्रदेशों पर स्थापित हुई थी। धीरे-धीरे ये लोग पश्चिम की ओर आगे बढ़ते गये, और समयान्तर में हजारों मील की दूरी पार कर प्रशान्त महासागर तक पहुँच गये। ठीक इसी प्रकार रूसी लोग यूराल को पारकर पूर्व की ओर आगे बढ़ते गये, और बाद में प्रशान्त महासागर तक जा पहुँचे। सत्रहवीं सदी के शुरू तक (१६१८) रूसी लोगों की वस्तियां ओब नदी के तट पर ओब्डोरोस्क और वेरेजोव में, और इर्तिश नदी के तट पर तोबोल्स्क और तारा में स्थापित हो गई थी। इर्तिश नदी से आगे भी कुछ रूसी लोग पहुँच चुके थे, और इन्होंने तोम्स्क और कुज़नेत्स्क में अपनी वस्तियां कायम कर ली थी। तोम्स्क को अपना आधार बनाकर वे येनीसेई और अन्नारा नदियों की ओर आगे बढ़े। १६३० में उन्होंने याकुत्स्क को आवादी किया, और अगले बीस सालों में (सत्रहवीं सदी के मध्य तक) रूसी लोग पूर्व में आमूर नदी तक और प्रशान्त महासागर के तट पर ओरवोस्क तक पहुँच गये। इन प्रदेशों में जो विविध जातियां निवास करती थी, उन्हें जीतने में रूसी लोगों को कोई कठिनाई नहीं हुई। यूरोप में लोग जिन अस्त्र-शस्त्रों का सत्रहवीं सदी में प्रयोग करते थे, उनके सम्मुख इन जसभ्य जातियों के लिये ठहर सकना सम्भव नहीं था। ये परास्त हो गई, और साइबीरिया के इस सुविस्तृत प्रदेश पर रूस का आधिपत्य स्थापित हो गया। यद्यपि साइबीरिया में रूस का प्रसार उन शिकारियों, व्यापारियों व पादरियों द्वारा हुआ था, जो वन कमाने व धर्म प्रचार के उद्देश्य से निरन्तर आगे बढ़ रहे थे, पर रूसी लोगों की इन नई वस्तियों पर रूसी सरकार का आधिपत्य होता था, और इस प्रकार साइबीरिया रूसी साम्राज्य के अन्तर्गत होता जाता था। शुरू में रूसी लोग साइबीरिया के उन्हीं प्रदेशों में गये, जहाँ फरे बहुतायत में मिलती थी। उनकी प्रारम्भिक वस्तियां पर व अन्य कीमती पदार्थों को एकत्र करने की केन्द्रभावा थी। पर धीरे-धीरे रूसी लोगों ने यह भी अनुभव किया, कि साइबीरिया के अनेक प्रदेश खेती के लिए भी उपयुक्त हैं। अब तक साइबीरिया में निवास करने वाले रूसी लोग अन्न के लिये रूस पर ही निर्भर रहते थे। पर अठारहवीं सदी में उन्होंने वहाँ खेती भी प्रारम्भ की। १७१६ में जोम्स्क में और १७१८ में मेरीलानिस्क आवादी हुए। इन वस्तियों को आधार बनाकर रूसी लोगों ने दक्षिणी साइबीरिया में विस्तार शुरू किया। दक्षिण के ये प्रदेश खेती के लिये उपयुक्त थे। इस कारण धीरे-धीरे बहुत से रूसी किसान इन प्रदेशों में बड़े पैमाने पर खेती करने के लिये आने लगे। अठारहवीं सदी के मध्यभाग में साइबीरिया में रूस के द्वितीय प्रसार का प्रारम्भ हुआ। इन समय रूसी लोग केवल परा व अन्य जसभ्य जातियों की उपलब्धि के लिये ही साइबीरिया में नहीं आ

रहे थे, अपितु स्पेती के विकास के लिये भी वे बड़ा बड़ी समस्या में आवाद होने लगे थे।

दक्षिणी साइबेरिया में आग बढ़ते हुए रूसी लोग आमूर नदी की दक्षिणी घाटी में भी गये। यह प्रदेश कृषि के लिये बहुत उपयुक्त था। पर इस पर चीन का अधिकार स्वीकृत किया जाता था, और यहाँ चीनी किसान बहुत बड़ी समस्या में आवाद थे। प्रशान्त महासागर के समीप के इस सुदूरवर्ती प्रदेश को चीन के मुकाबले में अधिकृत कर सकना उस की शक्ति के बाहर था। परिणाम यह हुआ, कि यद्यपि रूसी लोग मत्तर्हवी सदी के मध्यभाग तक आमूर की घाटी में पहुँच चुके थे, पर १६८९ में वे इस प्रदेश को छोड़ देने के लिये विवश हुए। उन्नीसवीं सदी के मध्यभाग (१८५८) में रूसी लोगों ने चीन की राजनीतिक निर्वलता में लाभ उठाकर आमूर के क्षेत्र पर अपना अधिकार पुनः स्थापित किया, और इस प्रकार रूस के लिये उत्तरी चीन और कोरिया में अपने आधिपत्य को विस्तृत करने के लिये मार्ग साफ हो गया। आमूर प्रदेश के रूस के हाथ में आ जाने से प्रशान्त महासागर का ऐसा समुद्रतट भी उसको प्राप्त हो गया, जो नौकानयन की दृष्टि से साल के बारहों महीनों में अनुकूल परिस्थिति रचना है। इस प्रदेश में अपने आधिपत्य को दृढ़ करने व आर्थिक दृष्टि में उसे उन्नत करने के लिये रूस ने यहाँ अनेक रेलवे लाइनों का निर्माण किया।

**ट्रांस-कोकेशिया पर रूस का प्रभुत्व**—अठारहवीं सदी में ट्रांस-कोकेशिया का प्रदेश अनेक छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था। पूर्वी ज्यार्जिया पर्सिया के अधीन था, और पश्चिमी ज्यार्जिया पर टर्की का प्रभुत्व था। इन प्रदेशों के विविध सरदार जहाँ पर्सिया और टर्की की अधीनता स्वीकृत करते थे, वहाँ आपस में भी निरन्तर मर्प करने रहते थे। नादिरशाह ने पश्चिमी ज्यार्जिया पर भी आक्रमण किये थे, और उसके हमलों के कारण इस देश की बहुत दुर्दशा हुई थी। नादिरशाह की मृत्यु के बाद उसके विशाल साम्राज्य में अव्यवस्था और अराजकता उत्पन्न हो गई, और इस स्थिति में लाभ उठाकर हेरेनिलयम द्वितीय ने ज्यार्जिया में अपने स्वतन्त्र राज्य की स्थापना की। पर पर्सिया और टर्की ज्यार्जिया के स्वतन्त्र राज्य को सहने के लिये तैयार नहीं थे। उन्होंने उस पर आक्रमण शुरू कर दिये। इस स्थिति में ज्यार्जिया के राजाओं के सम्मुख एक ही मार्ग था, वह यह कि वे रूस को अपना संरक्षक स्वीकार करे, और उसकी सहायता से अपनी स्वतन्त्रता व पृथक् सत्ता की रक्षा करें। परिणामस्वरूप १७८३ में ज्यार्जिया और रूस में सन्धि हो गई, जिसके अनुसार रूस ने ज्यार्जिया की रक्षा करना स्वीकार किया। पर रूस के संरक्षण से भी ज्यार्जिया की समस्याओं का अन्त नहीं हो गया। १७९५ में पर्सिया के शाह खा आगा मुहम्मद ने ज्यार्जिया पर आक्रमण किया, और वहाँ धन व जन का बुरी तरह से विनाश किया। इस दशा में ज्यार्जिया के राजा ज्यार्ज सप्तम को अपनी रक्षा का केवल यही उपाय समझ आया, कि वह पूरी तरह से अपने को रूस के अधीन कर दे। १८०१ में ज्यार्जिया का राज्य रूसी साम्राज्य के अन्तर्गत हो गया। १८०२ में रूसी सेनाओं ने ज्यार्जिया के अतिरिक्त ट्रांसकोकेशिया के अन्य प्रदेशों पर भी आक्रमण शुरू किये। इन प्रदेशों में विविध मंगोल व तुर्क खान स्वतन्त्रता के साथ शासन करते थे। ये रूसी सेनाओं का मुकाबला नहीं कर सके, और १८०५ तक सम्पूर्ण

कोकेशिया रूस के अधिकार में आ गया।

मध्य एशिया पर रूस का प्रभुत्व—अठारहवीं सदी के मध्यभाग (१७६०) में या के नादिरशाह ने मध्य एशिया पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। जिस प्रकार शहाह ने भारत पर आक्रमण कर वहाँ अपना स्थायी शासन स्थापित करने का ग नही किया, वैसे ही मध्य एशिया में भी उसने अपना शासन स्थायी रूप में कायम किया। उसके आक्रमणों के कारण इस प्रदेश में अराजकता छा गई, कोई राजशक्ति नहीं रही, और इस स्थिति से लाभ उठा कर वहाँ अनेक खान (सरदार) स्वतन्त्र में शासन करने लगे। अठारहवीं सदी के अन्त तक मध्य एशिया में तीन खानों के स्थिर रूप में स्थापित हो गये थे, जिनकी राजधानियाँ क्रमशः बोखारा, खीव और तन्द थी। इन तीन राज्यों में उजबेक, ताजिक, किरखिज और तुर्कमान आदि अनेक जातियों का निवास था। मध्य एशिया के ये तीनों राज्य जहाँ आपस में युद्ध करते रहते वहाँ साथ ही वे पड़ोस के अन्य राज्यों पर भी आक्रमण करते रहते थे। उन्नीसवीं के प्रारम्भ तक कोकन्द के खान ने काजकस्तान के बड़े भाग को जीतकर अपने त कर लिया था, और ताशकन्द का प्रसिद्ध नगर उसकी अधीनता में आ गया। कोकन्द के खान बड़े शक्तिशाली व समृद्ध थे। पामीर से शुरू कर सीर दरया और की पश्चिमी सीमा तक उनका राज्य विस्तृत था। पर मध्य एशिया के खानों का उत्कर्ष देर तक कायम नहीं रहा। उन्नीसवीं सदी के मध्य भाग में अपने साम्राज्य विस्तार करते हुए रूस ने उन पर आक्रमण शुरू कर दिया। कैस्पियन सागर के तट को गार बनाकर रूसी सेनाएँ मध्य एशिया में निरन्तर आगे बढ़ती गईं। १८६० तक कान्द, मरकन्द आदि रूस की अधीनता में आ गये थे। १८७३ में खीव और ८८ में मर्व पर रूस का अधिकार कायम हो गया था। उन्नीसवीं सदी के समाप्त होने पूर्व सम्पूर्ण मध्य एशिया पर रूस का आधिपत्य स्थापित हो चुका था। इन प्रदेशों पर ने प्रभुत्व को स्थिर करने के लिये रूस ने अनेक रेलवे लाइनों का निर्माण किया। ८८ तक ट्रान्स-कैस्पियन रेलवे बनकर तैयार हो चुकी थी। १८९८ में इस रेलवे की शाखा अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित कुश्क तक मिला दी गई थी। १९०६ मध्य एशिया में अन्यत्र भी रेलवे लाइनों का निर्माण किया गया। मध्य एशिया विजय के कारण रूस की सीमा पश्चिम, अफगानिस्तान, भारत और चीन में आ मिली और एशिया में उसका राजनीतिक महत्त्व बहुत बढ़ गया था।

### ३ यूरोपियन जातियों का चीन में प्रवेश

चीन और यूरोप का प्राचीन सम्बन्ध—चीन और यूरोप में पारस्परिक सम्बन्ध प्राचीन काल में था। रोमन साम्राज्य के बाजारों में चीन का माल बिकता करता था। बाद रोमन सम्राट मार्सिन जोरिलियस ने एक दूत-मंडल को चीन के सम्राट की सेवा में भेजा था। मध्यकाल में अनेक ईसाई पादरियों ने चीन में ईसाई मत का प्रचार करने का प्रयत्न किया। तेरहवीं सदी में वेनिस का प्रसिद्ध यात्री मार्कोपोलो चीन के सम्राट के दरबार में राजदरबार में आया था। उस समय इस प्रसिद्ध चीनी सम्राट के दरबार

में अन्य भी बहुत से विदेशी दूत, व्यापारी और पर्यटक विद्यमान थे। चीन के लोग विदेशियों से घृणा नहीं करते थे। वे उनका उत्साहपूर्वक स्वागत करते थे, और उनसे लाभ उठाते थे।

**यूरोप के साथ व्यापार**—पन्द्रहवीं सदी के अन्त में अफ्रीका का चक्कर काटकर पोर्तुगीज लोगों ने पूर्वी देशों में पहुँचने का प्रयत्न प्रारम्भ किया। यह प्रयत्न किन परिस्थितियों में और किन कारणों में शुरू हुआ था, उसका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। सबसे पूर्व सन् १५१६ में पोर्तुगीज व्यापारी चीन के वन्दरगाहों में आये। उस समय चीन में मिंग वंश के सम्राटों का शासन था। ये सम्राट् विदेशियों को मन्देह की दृष्टि में न देखकर उनका स्वागत करते थे। मिंग वंशी सम्राटों में प्रोन्माहन पाकर पोर्तुगीज व्यापारी अधिक-अधिक सख्या में चीन आने-जाने लगे। ये लोग यूरोपियन वस्तुओं को चीन की मण्डियों में बेचकर वहाँ में चाय और रेशम खरीदते थे। चीन की चाय और रेशम आजकल की तरह उस समय भी प्रसिद्ध थे। सन् १५३७ में पोर्तुगीज लोगों ने कैंटन के समीप मकाओ नामक स्थान पर थोड़ी सी जमीन पट्टे पर ले ली, और वहाँ अपनी व्यापारिक कोठी का निर्माण किया। इसके बाद अन्य यूरोपियन जातियों ने भी चीन में प्रवेश शुरू किया। पोर्तुगीजों के बाद डच और इंगलिश व्यापारी भी वहाँ पर गये, और व्यापार करने लगे। चीनी लोग न केवल इनका विरोध नहीं करते थे, अपितु इनके सम्पर्क से लाभ उठाने का भी प्रयत्न करते थे। बहुत से यूरोपियन पादरी भी इस समय चीन में ईसाई मत का प्रचार कर रहे थे। लाखों चीनी नर नारी ईसाई धर्म में दीक्षित भी होते जा रहे थे। चीन में धार्मिक सहिष्णुता बहुत पहले से विद्यमान थी। वहाँ के लोग विधर्मी ईसाई पादरियों को भी घृणा की दृष्टि में नहीं देखते थे।

सन् १५१६ से १७२४ तक यही दशा रही। इस बीच में चीन की राजनीतिक दशा में बहुत परिवर्तन हो गया था। सत्रहवीं सदी में माचू नामक एक मंगोल जाति ने उत्तर में की तरफ से चीन पर आक्रमण किया और मिंग वंश के शासन को नष्ट कर अपना राज्य स्थापित कर लिया। पर यूरोपियन लोगों के प्रति पुरानी नीति ही अब भी जारी रही थी। धीरे-धीरे यूरोपियन लोग अपनी स्थिति का दुरुपयोग करने लगे। उन्होंने चीन के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना प्रारम्भ किया। ईसाई पादरी भी धर्म-प्रचार करते हुए विशुद्ध धार्मिक दृष्टि को ही अपने सम्मुख नहीं रखते थे। वे धार्मिक क्षेत्र का उल्लंघन कर राजनीतिक मामलों में टांग अडाने में भी सकोच नहीं करते थे। परिणाम यह हुआ कि चीनी सरकार ने यूरोपियन लोगों के लिये अनेक प्रतिबन्ध लगा दिये। यूरोपियन लोगों के लिये केवल कैंटन का वन्दरगाह ही खुला रहने दिया गया। अन्य सब वन्दरगाह उनके लिये बन्द हो गये। अब वे केवल कैंटन में ही व्यापार के लिये आ-जा सकते थे। उनके लिये चीन के आन्तरिक प्रदेशों में प्रवेश या सकना भी सम्भव नहीं रहा था।

**अफ्रीम युद्ध**—पर यूरोपियन जातियाँ इस अवस्था को नहीं सह सकती थीं। यद्यपि चीन के मामलों में हस्तक्षेप करने का उन्हें कोई भी अधिकार नहीं था, पर वे अपनी शक्ति का प्रयोग कर जबरदस्ती उसके साथ व्यापार करने और उस पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिये प्रयत्नशील थीं। इंग्लैण्ड इस कार्य में सब का अगुआ बना।

ब्रिटिश लोग चीन में अफीम का व्यापार किया करते थे। उस समय तक भारतवर्ष ईस्ट इण्डिया कम्पनी के हाथ में आ चुका था। भारत में अफीम बहुत बड़े परिमाण में उत्पन्न कराई जाती थी, और उसे चीन के एकमात्र खुले हुए बन्दरगाह कैंटन में ले जाकर बेचा जाता था। ब्रिटिश लोगों की कोशिश से चीनी लोगों को अफीम खाने की आदत पड़ गई थी, और चीन में अफीम की बहुत खपत थी। अफीम के व्यापार में ईस्ट इण्डिया कम्पनी को डेढ़ करोड़ रुपये वार्षिक की आमदनी होती थी। धीरे-धीरे चीनी सरकार ने अनुभव किया, कि अफीम बहुत हानिकारक वस्तु है, और उसका प्रचार अपने देश में रोकना चाहिये। इसलिये उन्होंने चीन में अफीम का प्रवेश कानून द्वारा बन्द कर दिया। पर ब्रिटिश व्यापारी धोखे से अफीम को चीन में पहुँचाते रहते थे। सन् १८३९ में चीनी सरकार ने ब्रिटिश व्यापारियों की गतिविधि की देख-रेख करने के लिये एक खास कमिश्नर की नियुक्ति की। उसने ब्रिटिश व्यापारियों को हुकुम दिया, कि वे अपनी सारी अफीम सरकार के संपूर्ण कर दे। पर ब्रिटिश व्यापारी इसके लिये तैयार नहीं हुए। आखिर, चीनी सरकार की पुलिस ने कैंटन के इन व्यापारियों को गिरफ्तार करने का प्रयत्न किया। इङ्गलैण्ड इस बात को कब सह सकता था। उसके लिये यह राष्ट्रीय सम्मान का प्रश्न था। असली बात तो यह है, कि इङ्गलैण्ड चीन से युद्ध करने के लिये किसी बहाने की प्रतीक्षा कर रहा था। अब उसे उपयुक्त बहाना मिल गया। १८४० में इङ्गलैण्ड ने चीन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। यह युद्ध इतिहास में 'अफीम युद्ध' के नाम से प्रसिद्ध है। यह १८४२ तक जारी रहा। अन्त में चीन को सन्धि करने के लिये विवश होना पड़ा। सन् १८४२ में नानकिंग की सन्धि द्वारा इस अफीम युद्ध का अन्त हुआ। नानकिंग की सन्धि के अनुसार (१) कैंटन के सिवाय चार अन्य बन्दरगाह भी, जिनके नाम अमोय, निगयो, फूचो और शशाई हैं, विदेशी व्यापार के लिये खोल दिये गये, (२) हांगकांग इङ्गलैण्ड को प्राप्त हुआ और (३) चीन को साढ़े छ करोड़ के लगभग रुपया हरजाने के तौर पर इङ्गलैण्ड को देना पड़ा।

तोर्गिस्तन की सन्धि—नानकिंग की इस सन्धि से विदेशी लोग चीन में अधिकारिक मर्यादा में जाने लगे। इङ्गलैण्डियों के अनुकरण में अमेरिकन, फ्रेन्च, डच, बेल्जियम और जर्मन लोग भी चीन में जाने शुरू हुए। उन्होंने भी चीनी सरकार में पृथक्-पृथक् सन्धियाँ की, और धर्म-प्रचार तथा व्यापार के निमित्त चीन में प्रवेश प्रारम्भ किया। यूरोपियन लोग अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिये धर्म-प्रचार को गद्य माधन बनाते थे। चीन में यद्यपि इन पाश्चात्य देशों के पादरी ऊपर से धर्म-प्रचार कर रहे थे, पर वस्तुतः वे अपने देशों के प्रभुत्व के लिये मार्ग नाफ करने में लगे थे। सन् १८५८ में एक फ्रेन्च पादरी चीन में मारा गया। फ्रान्स ने समझा कि यह चीन पर आक्रमण करने का अच्छा बहाना है। उसने इङ्गलैण्ड की सहायता में चीन के विरुद्ध युद्ध उद्घाटित कर दिया। इस युद्ध का अन्त तीन्मिन के सन्धि के द्वारा हुआ। तीन्मिन की सन्धि के अनुसार (१) छ अन्य बन्दरगाह विदेशियों के लिये खोल दिये गये। (२) चीनी सरकार ने रैलाई पादरियों की रक्षा की उत्तरदायिता अपने ऊपर ले ली। (३) याङ्त्से-किंग नदी में व्यापार करने का अधिकार विदेशियों को दिया गया, और (४) हर्बिन

के तीर पर एक बड़ी रकम फ्रांस और ब्रिटेन को दी गई ।

चीन में यूरोपियन प्रभुत्व का प्रसार—अब चीन विदेशियों के लिये पूर्णतया खुल गया था । वे स्वच्छन्दतापूर्वक उसके साथ व्यापार कर सकते थे । पर यदि विदेशी यूरोपियन लोग केवल व्यापार तक ही सीमित रहते, तो कोई हानि की बात न थी । पर वे चीन की निर्धनता में लाभ उठाकर अपनी शक्ति का उपयोग कर रहे थे, और इस प्रकार के अधिकार प्राप्त करते जाते थे, जिन्हें किसी भी प्रकार न्याय्य तथा उचित नहीं समझा जा सकता । ये अधिकार निम्नलिखित थे—

(१) जिन बन्दरगाहों में पाश्चात्य लोगों को व्यापार का अधिकार मिला था, वहाँ वे अपनी वस्तियाँ भी बसाते जाते थे । इन वस्तियों में चीनी सरकार का कोई अधिकार नहीं रहता था । ये पूर्णतया यूरोपियन लोगों के शासन में होनी थीं । इनके अपने न्यायालय अपनी पुलिस और अपनी सरकार होती थी । ये एक प्रकार से चीन में विदेशियों के उपनिवेश होते थे, जिन पर चीनी सरकार का किसी भी प्रकार का हक नहीं होता था । चीन के राजनीतिक अपराधी उनमें उसी तरह आश्रय पा सकते थे, जैसे डकैत व फ्राम में । विदेशी लोग न केवल इन वस्तियों में ही चीनी सरकार की अश्रीनता स्वीकृत नहीं करते थे अपितु वे चीन में जहाँ कहीं भी हो, अपने को चीनी सरकार के कानूनों से मुक्त मानते थे । उन्हें चीनी सरकार की जरा भी परवाह न होती थी ।

(२) बन्दरगाहों की 'वस्तियों' में विदेशी मेनाएँ स्वच्छन्द रूप से रहती थी । विदेशी जगो जहाज बन्दरगाहों पर अड्डा डाले रहते थे, और चीनी समुद्र तट पर स्वच्छन्द रूप से घूमते रहते थे । चीनी सरकार विदेशियों की इस जवर्दस्ती के सम्मुख अमहाय थी ।

(३) चीन को तटकर के सम्बन्ध में स्वतन्त्रता नहीं थी । सन्धियों द्वारा पाश्चात्य लोगों ने चीन को मजबूर किया था, कि विदेशी माल पर पाँच फी मदी से अधिक आयात-कर न लगा सके । इस आयात-कर को बढ़ा सकना सन्धियों में परिवर्तन किये बिना चीनी सरकार के लिये असम्भव था । आयात-कर के अभाव से चीन को दो भारी नुकसान हो रहे थे । एक तो उसकी व्यावसायिक उन्नति सर्वथा रुकी हुई थी । यूरोपियन मुकाबले से अपने देश के व्यवसायों की रक्षा सरक्षण-कर की नीति का आश्रय लेकर ही की जा सकती थी । पर सरक्षण-कर लगाने के लिये चीनी सरकार स्वतन्त्र नहीं थी । दूसरी हानि यह थी, कि आयात-कर कम होने से सरकारी आमदनी बहुत कम रहती थी । आयात-कर राष्ट्रीय आय का बहुत महत्वपूर्ण साधन होता है । इस आय से वचित होकर चीनी सरकार अपना बजट पूरा करने के लिये कर्ज लेने को मजबूर होती थी । विदेशी लोग चीन को अपना कर्जदार बनाने के लिये विशेष रूप से उत्सुक थे । उसे बड़ी सुगमता से कर्ज मिल जाता था । धीरे-धीरे चीन अपने उत्तमर्ण देशों के काबू में आता जा रहा था ।

यूरोपियन लोगों को चीन में व्यापार करने की खुली छुट्टी मिल गई थी । बन्दरगाहों पर उनका पूरा कब्जा था । वे चीन में जहाँ चाहें, स्वच्छन्दता से आ जा सकते थे । आर्थिक दृष्टि से भी चीन को उन्होंने अपने काबू में कर रखा था । पर यूरोपियन लोग इतने से ही सतुष्ट नहीं रह सकते थे । उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में उन्होंने चीन के अधिक से अधिक

प्रदेश पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिये उद्योग प्रारम्भ किया। चीन बहुत विस्तृत तथा समृद्ध देश था। पर वहाँ की सरकार की हालत अच्छी नहीं थी। लोग भी शान्ति-प्रिय और भोले-भाले थे। यूरोपियन लोगों को और चाहिये ही क्या था? उन्होंने समझा अच्छा गिकार है, इसे हाथ से नहीं जाने देना चाहिये। विविध यूरोपियन देशों ने चीन के विविध प्रदेशों पर अपना कब्जा करना शुरू कर दिया। इङ्ग्लैण्ड ने १८८५ में बर्मा पर अधिकार कर लिया। इससे पहले बर्मा चीन की अधीनता स्वीकृत करता था। फ्रांस अनाम, टोन्किन और कम्बोडिया के प्रदेशों में अपना जाल फैला रहा था। सन् १८८३ में चीन और फ्रांस में वाक्यादा लड़ाई छिड़ गई। चीन परास्त हुआ, और ये सब प्रदेश फ्रांस की सरक्षता में आ गये। आगे चलकर ये ही 'फ्रेच इण्डोचायना' के नाम से प्रसिद्ध हुए। उर्वर उत्तर की ओर में रूस अपना पैर पसार रहा था। उसने आमूर नदी के प्रदेशों को हड़प कर साइबेरिया में मिला लिया।

## ४ दक्षिण-पूर्वी एशिया

पन्द्रहवीं सदी के अन्त में जब पोर्तुगीज लोगों ने अफ्रीकन महाद्वीप का चक्कर काटकर समुद्र के मार्ग से पूर्वी एशिया में आना जाना शुरू किया, तो वे न केवल भारत आये, अपितु सुदूर पूर्व में भी गये। १५११ में उन्होंने मलक्का पर अपना अधिकार कर लिया और मलाया, मियाम आदि के राजाओं के आपसी झगड़ों का लाभ उठाकर उनके आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप शुरू किया। १५२५ में स्पेनिश लोग भी इस क्षेत्र में प्रविष्ट हुए, और सोलहवीं सदी के अन्त में डच, ब्रिटिश और फ्रेच लोगों ने भी सुदूर पूर्व के इन देशों में व्यापार के लिये आना शुरू किया। ब्रिटिश और फ्रेच लोगों ने अठारहवीं सदी में भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिये संघर्ष प्रारम्भ कर दिया था, इस कारण वे दक्षिण-पूर्वी एशिया में अपने आधिपत्य की स्थापना पर विशेष ध्यान नहीं दे सके। पर पोर्तुगीज, स्पेनिश और डच इन प्रदेशों में अपनी व्यापारिक कोठियों को कायम करने और विविध राजाओं के पक्ष व विपक्ष में लड़कर उन्हें अपने प्रभाव में लाने में तत्पर रहे। फिजिपीन द्वीपसमूह पर स्पेन अपना प्रभुत्व स्थापित करने में समर्थ हुआ, और पोर्तुगीज लोगों के मुकाबले में डच लोग सुदूर पूर्व को अपने प्रभाव में लाने में सफल हुए। अफ्रीकन महाद्वीप का दक्षिणी भाग (केप कोलोनी) डच लोगों के कब्जे में था। उस आधार बनाकर वे दक्षिणपूर्वी एशिया को अपने अधीन करने के लिये प्रयत्नशील थे। सत्रहवीं सदी में जावा उनके अधीन हो गया था, और बैन्टम (१६१०) व बटेविया (१६१९) में उन्होंने अपनी प्रधान वस्तियाँ कायम कर ली थी। तावा की केन्द्र बनाकर डच लोगों ने पूर्वी एशिया के विविध द्वीपों (ईस्ट इन्डिज) पर अपने प्रभाव का प्रसारण शुरू किया। उन्नीसवीं सदी में सुमात्रा, पश्चिमी बोर्नियो, ब्रावी आदि द्वीपों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने में वे समर्थ हुए, और इस प्रकार पूर्वी एशिया के उन विस्तृत आधिपत्य का विस्तार हुआ, जो आगे चलकर इन्डोनीशिया के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

सुदूर पूर्व के सब द्वीप डच लोगों की अधीनता में नहीं आये। उनमें में फिजि, पोर्तुगीज और ब्रिटिश लोगों के प्रभुत्व में भी आये। यहाँ हमारे लिये यह सम्भव नहीं

है, कि इन विविध यूरोपियन राज्यों के पूर्वी एशिया में प्रसार के सम्बन्ध में अधिक लिख सके। ब्रिटेन के अधीनस्थ प्रदेशों में सबसे महत्वपूर्ण मलाया प्रायद्वीप व उसके समीपवर्ती द्वीप थे। मलक्का पहले पोर्तुगीजों के हाथ में था, बाद में वह डच लोगों के अधीन हुआ, और १८२८ में उस पर ब्रिटेन का अधिकार हो गया। १८१९ में सिंगापुर ब्रिटेन को प्राप्त हुआ, और इसे केन्द्र बनाकर ब्रिटिश लोगों ने मलाया में अपने प्रभाव का प्रसार गुरु किया। बीरे-बीरे सम्पूर्ण मलाया ब्रिटेन के पभुत्व में आ गया। मलाया का एक भाग (स्ट्रेट मेटलमेन्ट) ब्रिटेन के सीधे शासन में था, शेष मलाया (फिडरिटेड मलाया राज्य और फिडरेशन के बाहर के मलाया राज्य) के विविध राजा (सुल्तान) ब्रिटेन की अधीनता को स्वीकार करने थे। स्ट्रेट मेटलमेन्ट का केन्द्र सिंगापुर था, जो ब्रिटेन के पूर्वी साम्राज्य के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण बन्दरगाह है। मलाया पर अब तक भी ब्रिटेन का पभुत्व कायम है, यद्यपि वहाँ भी ब्रिटेन की स्थिति डावाडोल है।

इण्डो-चायना किम प्रकार फ्रांस के अधिकार में आया, उसका निर्देश पहले किया जा चुका है। इस राज्य का निर्माण कम्बोडिया, कोचीन-चायना, चम्पा, अनाम, टोन्-किन और लेआम के प्रदेशों द्वारा हुआ है। चीन के आन्तरिक मामलों में हम्पशेयर करने उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में ये प्रदेश फ्रांस ने अधिकृत किये, और वहाँ अपना साम्राज्य स्थापित किया।

## ५ यूरोपियन जातियों का अफ्रीका में प्रवेश

अफ्रीका बहुत बड़ा महाद्वीप है। उसका क्षेत्रफल १,१४,६२,००० वर्गमील है। आकार में वह पूरे यूरोप से तिगुना है। उन्नीसवीं नदी के प्रारम्भ तक यूरोप के सम्य निवासियों को इस विशाल महाद्वीप के सम्बन्ध में बहुत कम परिचय था। उत्तरी अफ्रीकन प्रदेशों के अतिरिक्त शेष अफ्रीका के विषय में वे केवल समुद्र तट की ही जानकारी रखते थे। इस सुविस्तृत भूखण्ड में कौनसी जातियाँ निवास करती हैं, इनमें कौनसे पहाड़, नदियाँ व झीलें हैं, इसकी भौगोलिक और प्राकृतिक दशा किस प्रकार की है—इन सब बातों का कुछ भी परिचय यूरोपियन लोगों को नहीं था। अफ्रीका के जंगलों, पशुओं तथा अद्भुत निवासियों के विषय में अनेक विचित्र गाथाएँ यूरोप में अवश्य प्रचलित थी, पर उन लोगों ने इसमें प्रवेश कर इसका परिचय प्राप्त करने के लिये कोई विशेष उद्योग नहीं किया था।

अफ्रीका का उत्तर-पूर्वी कोना ईजिप्ट या मिसर कहलाता है। प्राचीन समय में यह एक अत्यन्त उन्नत सभ्यता की रगभूमि था। केवल ईजिप्ट में ही नहीं, उत्तरी अफ्रीका के अन्य भी कई प्रदेशों में प्राचीन समय में सभ्यता का विकास हुआ था। कार्थेज व्यापार का बड़ा भारी केन्द्र था, और ईसा से कई सदी पूर्व एक अत्यन्त विशाल और समृद्ध नगर बन चुका था। रोमन साम्राज्य के विस्तार के समय में उत्तरी अफ्रीका उसके अन्तर्गत था। आगे चलकर सानवी सदी में जब इस्लाम का उत्कर्ष हुआ, तो अरबों ने उत्तरी अफ्रीका के इन प्रदेशों को विजय कर लिया, और अपने अनेक राज्य वहाँ स्थापित किये। अरब लोग बड़े सहसी और बीर थे। वे केवल उत्तरी अफ्रीका पर आधिपत्य



व्यापित करके ही सतुष्ट नहीं हुए, अपितु सहारा का मरुस्थल पार कर उन्होंने मध्य तथा दक्षिण अफ्रीका में भी प्रवेश करने का प्रयत्न किया। मध्य अफ्रीका के निवासियों के साथ उनका व्यापारिक सम्बन्ध विद्यमान था, ऊँटों के काफिलों पर सहारा को पारकर वे दक्षिणी प्रदेशों में व्यापार के लिये आया जाया भी करते थे। इसी प्रकार अफ्रीका के पूर्वी तट पर उन्होंने अनेक व्यापारिक केन्द्र कायम किये थे, और दक्षिण में मैडागास्कर तक वे व्यापार के लिये आते जाते थे। अपने परिचित प्रदेशों का नक्शा बनाने तथा उनकी भौगोलिक और प्राकृतिक दशा को लेखबद्ध करने का प्रयत्न भी अरब लोगों ने किया था। यूरोपियन लोगो को अफ्रीका के सम्बन्ध में पहले पहल परिचय अरब लोगों द्वारा ही प्राप्त हुआ था। स्पेन अरब साम्राज्य के अधीन था, वहाँ के लोगों का अरबों के साथ घनिष्ट सम्बन्ध था। इसीलिये सबसे पहले स्पेन तथा उसके पड़ोसी पोर्तुगाल को अफ्रीका के विषय में परिचय हुआ।

पन्द्रहवीं सदी के उत्तरार्द्ध में जब यूरोपियन जातियों ने पूर्वी देशों तक पहुँचने के लिये नवीन मार्गों को ढूँढना प्रारम्भ किया, तो पोर्तुगीज लोगों ने अफ्रीका का चक्कर काटकर पूर्व में जाने की कल्पना उत्पन्न हुई। पर इन पोर्तुगीज लोगों की दृष्टि में अफ्रीका का कोई महत्त्व न था। उसमें प्रवेश कर उसके निवासियों का पता लगाना उनकी दृष्टि में कोई उपयोग नहीं रखता था। भारत आदि पूर्वी देशों के साथ व्यापार उनका लाभदायक था, कि अफ्रीका में प्रविष्ट होने की आवश्यकता ही पोर्तुगीज लोगों को अनुभव नहीं होती थी। पर धीरे-धीरे अफ्रीका का एक उपयोग यूरोपियन लोगों को ज्ञात हुआ। अमेरिका का इस समय तक पता लग चुका था। विविध यूरोपियन देश, जिनमें स्पेन सबसे प्रमुख था, वहाँ अपने उपनिवेश बसा रहे थे। इन नई वस्तियों के लिये गुलामों की जरूरत थी। अमेरिका के मूल निवासी गुलामी के लिये उपयुक्त न थे, इसलिये अमेरिका के ह्वशियों को जहाजों पर लाकर अमेरिका ले जाया जाने लगा, और वहाँ उनकी बिक्री प्रारम्भ हुई। शीघ्र ही यह एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण व्यापार बन गया, और बहुत से लोग गुलामों का क्रय-विक्रय कर धनी होने लगे। हालैण्ड, ब्रिटेन, फ्रांस आदि विविध देशों ने इस घृणित व्यापार के लिये विविध जड़ें अफ्रीका में बनाये हुए थी, और यूरोपियन लोग विविध उपायों से ह्वशियों को पकड़ कर उन्हें अमेरिका भेजते थे। उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ तक यूरोपियन लोगों की दृष्टि में अफ्रीका तो यहाँ एवमात्र उपयोग था। इसी प्रकार अफ्रीका के पूर्वी तट पर अरब लोग भी गुलामों का व्यापार करते थे। उस समय के लोग इस व्यापार को घृणित नहीं समझते थे। आर्थिक दृष्टि से तो गुलामों के क्रय-विक्रय में प्रत्यक्ष लाभ था ही, पर आर्थिक दृष्टि से तो लोग इसे अच्छा समझते थे। उस समय ईसाई पादरी कहते थे, कि दान-धन और तथा धर्म द्वारा अनुज्ञात है, और ह्वशी लोग ईसाइयों की शरण में आकर परलोक में शान्ति तथा शान्ति प्राप्त करेंगे। यह व्यापार कितने बड़े पैमाने पर होता था, उसका अनुमान इस बात से किया जा सकता है, कि सन् १७११ में जेम्स ब्रिटेन ने १०० हजार गुलामों का व्यापार में लगे हुए थे, और वे एक बार में सैताल्लस हजार गुलामों को टा मरते थे। १८०४ में विविध देशों के गुलाम व्यापार के जड़ें इस प्रकार थे—हालैण्ड के १५, ब्रिटेन

के १८, पुर्तगाल के ८, डेनमार्क के ४ और फ्रांस के ३। इन विविध अड्डों में लाखों गुलाम प्रति वर्ष अमेरिका तथा यूरोप के विविध बाजारों में विक्रय के लिए पहुँचाये जाते थे।

अमेरिका और फ्रांस की राज्यक्रान्तियों ने जिन नवीन विचार-वागों का प्रारम्भ किया, उनमें इस गुलाम व्यापार के विरुद्ध भी भावना उत्पन्न हुई। सन् १८०७ में ब्रिटिश पार्लियामेन्ट ने गुलाम व्यापार के विरुद्ध प्रस्ताव स्वीकृत किया। इसी प्रकार का प्रस्ताव सन् १८१४ में वीएना की द्वारा कांग्रेस भी स्वीकृत किया गया। धीरे-धीरे इस घृणित पथा का अन्त होना प्रारम्भ हुआ, और इसके कारण यूरोपियन लोगों की दृष्टि में अफ्रीका का उपयोग भी कम होने लगा। जब तक यूरोपियन लोग इसी व्यापार के लिए अफ्रीका आते जाते थे, अब इसके बन्द हो जाने पर उन्हें उसका कोई भी उपयोग प्रतीत नहीं होता था।

उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ में सन् १८१५ में अफ्रीका की दशा निम्नलिखित प्रकार में थी—उत्तरी अफ्रीका के बड़े भाग पर टर्की के मुलतान का आधिपत्य माना जाता था। ईजिप्ट, ट्रिपोली, ट्यूनिस् और अल्जीरिया तुर्की साम्राज्य के अन्तर्गत समझे जाते थे, यद्यपि उनके शासक क्रियात्मक दृष्टि में स्वतन्त्र थे। उत्तरी अफ्रीका में मोरक्को तुर्की साम्राज्य के अन्तर्गत नहीं था, वहाँ एक स्वतन्त्र मुलतान राज्य करता था। मेनेगल नदी के मुहाने पर (पश्चिमी तट पर) फ्रांस का कब्जा था। पूर्वी तट पर मैडागास्कर द्वीप के ठीक सामने के कुछ प्रदेश पुर्तगाल के कब्जे में थे। ब्रिटिश लोग केप कोलोनी पर कब्जा कर चुके थे, और अफ्रीका के पश्चिमी तट पर उनके अन्य भी कई छोटे-छोटे अड्डे विद्यमान थे। शेष स्विसुत अफ्रीका अभी यूरोपियन लोगों के लिए एक अनरिचित, अज्ञात और रहस्यमय भूखण्ड था। उसके सघन जंगलों, विस्तृत झीलों और अद्भुत निवासियों के सम्बन्ध में उन्हें कुछ भी परिचय नहीं था।

गुलाम व्यापार के दिनों में भी अनेक यूरोपियन लोग अफ्रीका के अन्दरनी हिस्सों में प्रवेश करने का प्रयत्न करते रहते थे। विजेपतया, रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेन्ट ईसाई पादरी अफ्रीका के ह्वशी निवासियों को सद्धर्म का संदेश पहुँचाने के लिए बहुत उत्सुक रहते थे। अनेक व्यापारी भी अफ्रीका में मिलने वाले हाथी दात, आबन्स, गोद, रबड़ आदि कीमती पदार्थों को प्राप्त करने के लिए काफी दूर-दूर तक अन्दर चले जाते थे। इन पादरी तथा व्यापारी लोगों द्वारा अफ्रीका के सम्बन्ध में बहुत सी अद्भुत बातें यूरोप में फैल रही थी, और बहुत से साहसी लोग केवल ज्ञानवृद्धि की दृष्टि से भी इस विशाल महा-द्वीप का आलोडन करने के लिए अग्रसर हो रहे थे। गुलाम व्यापार के बन्द हो जाने पर यह प्रवृत्ति और भी अधिक बढ़ गई। गुलामों के अतिरिक्त अन्य व्यापारिक वस्तुओं को अधिगत करने के लिए विविध साहसी व्यापारी अफ्रीका में प्रवेश करने लगे। पादरियों के लिए अब यह सम्भव नहीं रहा था, कि ह्वशियों को गुलाम बनाकर उनकी आत्माओं का उद्धार कर सकें। पर उन्हें इन 'पथभ्रष्ट' लोगों को मार्ग प्रदर्शित करने तथा 'सद्धर्म' में लाने की उत्सुकता इतनी अधिक थी, कि वे उन्हीं के घरों में जाकर उन्हें ईसा का संदेश सुनाने के लिए प्रयत्नशील होने लगे। सबसे बढ़कर साम्राज्यवाद

की खूब यूरोपियन लोगों को अफ्रीका में प्रविष्ट होने के लिए प्रेरित कर रही थी।

यहाँ हमारे लिए यह सम्भव नहीं है, कि हम यूरोप के उन गाहसी पुरुषों का विस्तृत विवरण दे सकें, जिन्होंने प्रकृति और मनुष्य—दोनों के भयकर प्रकोप की जरा भी परवाह न कर अफ्रीका के दुर्गम प्रदेशों का अवगाहन किया, और यूरोपियन जातियों के लिए इन पर अधिराज्य स्थापित करने का मार्ग साफ कर दिया। उनका वृत्तान्त उन्मथाम न नी अधिक मनोरञ्जक है उनके साहसिक कार्य पुरानी वीर गाथाओं की भी मात करते हैं। निस्सन्देह, ससार के इतिहास में उनका स्थान बहुत ऊँचा है। पर हम इस इतिहास में उनका केवल निर्योही कर सकते हैं। इंग्लैण्ड की 'रायल जियोग्राफिकल सोसायटी' का नरक्षण में नील नदी का उद्गम स्थान ढूँढने के लिए प्रयत्न गुरु किया गया, और उसके लिए ब्रिटिश लोग मध्य अफ्रीका में बहुत दूर अन्दर तक प्रविष्ट हुए। सन् १८५८ में भूमध्यरेखा के ठीक नीचे एक विंगाल झील का पता लगाया गया, और इसका नाम 'विक्टोरिया नियाञ्जा' रखा गया। सन् १८६४ में सर सेमुअल वार्कर ने विक्टोरिया नियाञ्जा के उत्तर-पश्चिम में एक अन्य झील का पता लगाया, और उसका नाम 'ए वर्ट नियाञ्जा' रखा। इसी समय लिविङ्गस्टोन नाम का एक अन्य साहसी मिशनरी अफ्रीका के मध्य भाग का अवगाहन कर रहा था। अफ्रीका की खोज करने वालों में इस लिविङ्गस्टोन का प्रमुख स्थान है। सन् १८४० में १८७३ तक इसने अपना प्रायः सारा समय टीबी कार्य में व्यतीत किया। सन् १८५१ में वह पूर्व की तरफ से अफ्रीका में प्रविष्ट हुआ, और पाँच साल तक मध्य अफ्रीका के विविध प्रदेशों का अवगाहन करते हुए १८५६ में वह पश्चिमी तट पर पहुँच गया। इसी तरह उसने अफ्रीका के अन्य प्रदेशों की भी यात्राएँ कीं। उसके यात्रा-वृत्तान्तों से सारे सभ्य ससार में एक प्रकार की हलचल सी मच गई, और लोगों का ध्यान अफ्रीका की ओर विशेष रूप से आकृष्ट हुआ। अफ्रीका के अवगाहकों में लिविङ्गस्टोन के बाद स्टेनली का नाम बहुत प्रसिद्ध है। उसने लिविङ्गस्टोन की मृत्यु के दो वर्ष पूर्व सन् १८७१ में अपना कार्य प्रारम्भ किया, और अफ्रीका के विविध प्रदेशों का खूब अच्छी तरह आलोडन किया। लिविङ्गस्टोन की मृत्यु अफ्रीका में ही हो गई थी। पर स्टेनली १८९८ में सफल यूरोप वापस लौटने में सफल हुआ। उसके यात्राविवरणों ने अफ्रीका के प्रति यूरोपियन लोगों को और भी अधिक आकर्षित किया, और विविध यूरोपियन देश इस अद्भुत और विशाल भूखण्ड में प्रवेश पाने तथा अपने राज ठठाने के लिए विशेष रूप से आनुर हो गए।

अफ्रीका में प्रवेश पाने का प्रयत्न करने वाले यूरोपियन देशों में बेल्जियम सबसे मूर्ख था। उन दिनों बेल्जियम का राजा लिओपोल्ड द्वितीय था। वह बहुत ही चांगरा था। होशियार व्यक्ति था। स्टेनली की यात्राओं से वह बहुत प्रभावित हुआ, और उसने अफ्रीका में प्रवेश कर उसे अपने प्रभाव में लाने का प्रयत्न प्रारम्भ किया। स्टेनली जल्दी ही जान गया था, पर अंग्रेजों ने उसकी तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया। कारण यह कि वे अपने अपने अनेक दिनों ब्रिटेन के अधीन थे, और अंग्रेज लोग वहाँ जाकर लोगों ने उल्लूक नहीं किया। और अंग्रेज लोगों के इस नपुंसकता वृत्तान्त हम पढ़ते-लिखते चूकते हैं। स्टेनली की यात्राओं ने प्रोत्साहित होकर लिओपोल्ड द्वितीय ने सन् १८७६ में अपनी राजधानी

बुसतस में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया, और उसमें अफ्रीका का अवगाहन करने तथा वहाँ के निवासियों को सभ्यता तथा धर्म का पाठ पढ़ाने के उपायों पर विचार किया गया। उन्नीसवें सम्मेलन में लियोपोल्ड ने अफ्रीका के अवगाहन के लिए एक 'अन्तर्राष्ट्रीय सभा' का संगठन किया। सन् १८७९ में स्टेनली ने इस सभा की सरक्षा में एक बार फिर अफ्रीका के लिए प्रस्थान किया, और वहाँ के विविध राजाओं में मन्वि कर उनके प्रदेशों को 'अन्तर्राष्ट्रीय सभा' के अधीन किया।

लियोपोल्ड की अन्तर्राष्ट्रीय सभा जिस नेजी ने अफ्रीका के विविध प्रदेशों को अपनी सरक्षा में ला रही थी, उसे अन्य यूरोपियन राष्ट्र सहन नहीं कर सके। विशेषतया इंग्लैण्ड और पोर्तुगाल ने उसका विरोध किया। इन देशों के प्रयत्न में अफ्रीका की परिस्थिति पर विचार करने के लिए एक अन्य अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन किया गया। इस कांग्रेस की बैठक नवम्बर, सन् १८८४ में बर्लिन में प्रारम्भ हुई। स्विट्जरलैण्ड के अतिरिक्त अन्य सब यूरोपियन राज्यों तथा नवयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि इस कांग्रेस में सम्मिलित हुए थे। इस कांग्रेस ने कोन्गो नदी में सीधे जानेवाले प्रदेशों पर लियोपोल्ड की 'अन्तर्राष्ट्रीय सभा' का अधिकार स्वीकृत किया, और इन्हें 'कोन्गो के स्वतन्त्र राज्य' के रूप में परिवर्तित कर दिया। कोन्गो के स्वतन्त्र राज्य का अधिपति लियोपोल्ड द्वितीय को स्वीकृत किया गया। पर यह ध्यान रहे, कि कोन्गो पर बेल्जियम का आधिपत्य नहीं माना गया था, उस पर लियोपोल्ड द्वितीय का वैयक्तिक रूप से अधिकार स्वीकृत किया गया था। साथ ही यह भी व्यवस्था की गई थी, कि इस राज्य में कोन्गो, नीगर तथा उनकी सहायक नदियों में नौकायन की सबको स्वतन्त्रता रहे, और किसी राज्य को इसमें व्यापार आदि के लिए आने-जाने में न रोकता जा सके।

कोन्गो के स्वतन्त्र राज्य में लियोपोल्ड द्वितीय का शासन बहुत क्रूर तथा अत्याचारपूर्ण था। उसमें वहाँ के मूल निवासियों पर घोर अत्याचार किये जाते थे। लियोपोल्ड कोन्गो की जमीन पर अपना हक सम्प्रतिष्ठा था, और उस पर खेती करने के लिए वहाँ के निवासियों को जबरदस्ती गुलाम बनाने का प्रयत्न कर रहा था। रेलवे का विस्तार करने और खड्ड एकत्रित करने आदि के लिए भी अफ्रीकन लोगों पर जबरदस्ती की जा रही थी। बेल्जियन लोगों के अत्याचारों की कथाएँ सभ्य सत्तार के समाचारपत्रों में प्रकाशित हो रही थी, और यूरोप तथा अमेरिका का लोकमत उनके बहुत विरुद्ध होता जाता था। इस दशा में कोन्गो के स्वतन्त्र राज्य के शासन में परिवर्तन किया जाना अवश्य सम्भाव्य था। आखिर, सन् १९०८ में बेल्जियम की सरकार ने इस राज्य को प्राकायदा अपने अधीन कर लिया और उसके सुशासन के लिए प्रयत्न प्रारम्भ किया। सन् १९०८ में कोन्गो बेल्जियम की अधीनता में आ गया।

उन्नीसवीं सदी के अन्तिम वर्षों में यूरोप के प्रायः सभी प्रमुख राज्य अफ्रीका की लूट में अपना-अपना हिस्सा प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हो गये थे। इंग्लैण्ड, फ्रांस, जर्मनी, पोर्तुगाल आदि विविध राज्य इस बात के लिए उत्सुक थे, कि जितने भी प्रदेशों पर सम्भव हो, अपना आधिपत्य स्थापित करें। बेल्जियम के राजा लियोपोल्ड द्वितीय ने जो उदाहरण उपस्थित किया था, सब देश पूर्ण उत्साह के साथ उसका अनुकरण करना

चाहते थे । अफ्रीका के वास्तविक निवासियों की तथा इच्छा है, उनका भी अपनी मातृ-भूमि पर कोई अधिकार है, इन प्रश्नों पर विचार करने की यूरोपियन देशों को कोई अभि-प्राप्ति नहीं थी । उनकी दृष्टि में अफ्रीका का विनाश भूखण्ड उनके निवास तथा शासन के लिए युक्त पड़ा था । सन् १८९० में यूरोप के ये सम्य देश अफ्रीका के टुकड़े कर उन्हें आपस में बांट लेने के लिए कटिबद्ध हो गये । जो अफ्रीका कुछ साल पहले तक एक अज्ञात व अपरिचित देश था, जिसमें भयकर जीव-जन्तु व मनुष्य स्वच्छन्द रूप से जहाँ चाहें विचरते थे, अब यूरोपियन राज्यों में विभक्त होना शुरू हो गया ।

अठारहवीं अध्याय

## विज्ञान, साहित्य और कला

### १ वैज्ञानिक उन्नति

फ्रांस की राज्यक्रांति के समय और उन्नीसवीं सदी में जो विविध राजा, मेनापति व राजनीतिक नेता यूरोप में हुए, उनका हमने उस इतिहास में विगद रूप में वर्णन किया है। साथ ही, हमने उन विचारकों का भी उल्लेख किया है, जिन्होंने मानव समाज के राजनीतिक और अर्थिक संगठन के सम्बन्ध में नये विचारों का प्रतिपादन किया था। इन नये विचारों के कारण मनुष्य जाति किस प्रकार उन्नति के माग पर अग्रसर हुई, इसका भी हम विवेचन कर चुके हैं। पर सम्भवतः, मानव के हित और कल्याण के लिये जितना कार्य वैज्ञानिकों द्वारा हुआ है, उतना राजाओं, मेनापतियों, राजनीतिज्ञानताओं और विचारकों द्वारा नहीं हुआ। उन्नीसवीं सदी में यूरोप में बहुत से ऐसे वैज्ञानिक हुए, जिन्होंने अपने आविष्कारों द्वारा मनुष्यों के जीवन की परिस्थितियों में मौलिक परिवर्तन किया, और जिनके कारण बीसवीं सदी का मनुष्य ऐसा सुखी जीवन व्यतीत करने में समर्थ हो रहा है, जैसा कि शायद उसने पहले कभी नहीं विताया था। विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति के कारण वर्तमान युग का मानव प्रकृति पर महान् विजय स्थापित कर सकने में समर्थ हुआ है।

**विकासवाद का सिद्धान्त**—उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ तक यूरोपियन लोग यह मानते थे, कि पृथिवी पर मनुष्य को उत्पन्न हुए ६,००० साल के लगभग हुए हैं। ईश्वर ने सबसे पहले आदम और ईव को उत्पन्न किया, और इस जोड़े में सम्पूर्ण मनुष्य जाति की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार यूरोप के लोग यह मानते थे, कि सर्वशक्तिमान् भगवान् ने अपनी अद्भुत शक्ति का प्रयोग कर पृथिवी, सूर्य चन्द्र, तारा, नक्षत्र, ग्रह आदि सब सृष्टि का निर्माण किया, और पृथिवी पर वृक्ष, वनस्पति, जीव, जन्तु, मनुष्य आदि उत्पन्न किये। इन सबको बनाते हुए ईश्वर को छ दिन लगे। इन छ दिनों में वह इतना थक गया, कि सातवें दिन (रविवार) उसने पूर्ण रूप से विश्राम किया। सृष्टि की उत्पत्ति का यह चित्रण ईसाइयों के धर्मग्रन्थ बाइबल में दिया हुआ है, और इसे प्रमाण रूप से स्वीकार कर यूरोप के सब ईसाई यह विश्वास करते थे, कि ससार और मनुष्य की उत्पत्ति इस ढंग से छ दिनों में ईश्वर द्वारा की गई थी। अठारहवीं सदी के अन्त तक यूरोप में एक भी ऐसा विचारक उत्पन्न नहीं हुआ था, जो इन धार्मिक सिद्धान्त में किसी भी प्रकार का सन्देह प्रकट करे।

सबसे पहले जेम्स हटन नामक स्काच वैज्ञानिक ने १७९५ में इस मन्तव्य के विरुद्ध आवाज उठाई। उसने कहा, पृथिवी का वैज्ञानिक रूप से अनुशीलन करके मुझे यह प्रतीत

ज्ञाता है, कि पृथिवी का निर्माण कब हुआ, उसका कोई चिह्न नहीं मिलता। ऐसा ज्ञात होता है, कि पृथिवी बहुत अधिक पुरानी है, और वह किसी एक निश्चित दिन न बनकर धीरे धीरे बनी है। हटन के इस मन्तव्य से उन युग के विद्वानों में बहुत खलबली मची, और उनके खिलाफ एक तूफान या उड़ खड़ा हुआ। १८३० में सर चार्ल्स लायल ने प्रतिपादित किया, कि पृथिवी का निर्माण अनन्त युगों में धीरे-धीरे विकास द्वारा हुआ है। जब पृथिवी मिट्टी से शुरू हुई, तो इस मिट्टी के कारण पहाड़ों का निर्माण हुआ। वर्षा और जल की बाढ़ द्वारा घाटिया बनी। जल के कारण जब चट्टानों की मिट्टी घुलनी शुरू हुई, तो इस नरम मिट्टी से पृथिवी के जो भाग आच्छादित हो गये, उन पर वनस्पति व पौधों की उत्पत्ति होने लगी। जिस प्रक्रिया द्वारा पृथिवी अपने वर्तमान रूप में आई है, वह अब भी जारी है, और उससे पृथिवी के स्वरूप में निरन्तर परिवर्तन हो रहा है। १८६३ में लायल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'मनुष्य की प्राचीनता' (एण्टिक्विटी आफ मैन) प्रकाशित की। इसमें उन्होंने प्रतिपादित किया, कि पृथिवी की निचली सतहों में जो मानव अवशेष मिले हैं, उनमें यह स्वीकार करना होगा, कि अब से कम से कम एक लाख वर्ष पूर्व मनुष्य पृथिवी पर निवास करता था। फ्रेच वैज्ञानिक व्यूफो ने सबसे पहले इस सिद्धान्त की स्थापना की, कि न केवल पृथिवी, अपितु उस पर विद्यमान सब जीव-जन्तु भी विकास की प्रक्रिया द्वारा ही अपने वर्तमान रूप में आये हैं। जीवों की विविध नसलों का व्यापक अनुशीलन करके यह भलीभांति समझा जा सकता है, कि सब जीव-जन्तु एक ही प्रारम्भिक 'जीव' से विकसित हुए हैं। एक अन्य फ्रेच विद्वान लॅमार्क ने व्यूफो के मन्तव्य की पुष्टि की, और यह सिद्ध किया, कि न केवल विविध जीव-जन्तु, अपितु मनुष्य भी विकास की प्रक्रिया का ही परिणाम है।

जीव-जन्तु अपितु मनुष्य भी विकास की इसी प्रक्रिया का परिणाम है। अन्य जन्तुओं से विकसित होते हुए ही मनुष्य ने अपने वर्तमान रूप को प्राप्त किया है।

ईसाई धर्म के धर्मशास्त्रियों ने विकासवाद का घोर विरोध किया। उनका खयाल था, कि इस सिद्धान्त से ईसाई धर्म को भारी आघात पहुँचेगा। पर वैज्ञानिक लोगो ने इसका स्वागत किया। ब्रिटेन में वाल्टन ने डार्विन के मत की पुष्टि में एक अत्यन्त उत्कृष्ट पुस्तक लिखी। हर्वर्ट स्पेन्सर ने विकासवाद का पोषण करते हुए यह प्रदर्शित किया, कि समाज-शास्त्र, आचरणशास्त्र और मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी यह सिद्धान्त भलीभाँति लागू होता है। प्रसिद्ध जर्मन विद्वान हैकल ने विकासवाद की पुष्टि करते हुए प्रतिपादित किया, कि मनुष्य का विकास धीरे-धीरे हुआ है, और चिपाजी की दशा तक पहुँचने हुए उसे २६ भिन्न-भिन्न रूपों में से गुजरना पड़ा है। फ्रेच विद्वान नेना ने धर्म के क्षेत्र में विकासवाद को प्रयुक्त किया, और प्रदर्शित किया कि प्रारम्भिक मनुष्य के धार्मिक विचार किस प्रकार धीरे-धीरे क्रिश्चियन सिद्धान्तों के रूप में विकसित हुए हैं। पादरियों के विरोध के बावजूद भी यह सिद्धान्त निरन्तर लोकप्रिय होता गया। पोप पायस दशम ने घोषित किया था, कि डार्विन का मत विकृत मन का परिणाम है। पर बाद में उमाडे धर्मशास्त्रियों ने भी इस मत का विरोध करना बन्द कर दिया। वर्तमान समय में प्रायः सभी वैज्ञानिक विकासवाद को स्वीकृत कर चुके हैं, और यह सिद्धान्त न केवल भौतिक विज्ञानों का अपितु सामाजिक विज्ञानों का भी आधार बन गया है।

**रसायन शास्त्र**—उन्नीसवीं सदी में रसायन शास्त्र ने भी बहुत उन्नति की। जान डाल्टन ने प्रतिपादित किया, कि प्रकृति के सब पदार्थ परमाणुओं द्वारा बने हुए हैं। जल उद्भजन और ओपजन के परमाणुओं द्वारा मिलकर बनता है। इसी प्रकार कार्बोनिक एसिड का निर्माण कार्बन और ओपजन के परमाणुओं द्वारा होता है। जान डाल्टन ने यह भी मालूम किया, कि विविध तत्वों के परमाणु किस अनुपात में मिलकर विविध पदार्थों को बनाते हैं, और उन तत्वों का वैज्ञानिक रूप में कितना वजन होता है। स्टीउन् के विद्वान बर्जेलियस और इटली के वैज्ञानिक आवोगादो ने इस परमाणु सिद्धान्त को और अधिक विकसित किया, और यह प्रतिपादित किया, कि परमाणु (एटम) और भी अधिक सूक्ष्म वस्तु में बने होते हैं, जो प्रोटोन कहते हैं। वैज्ञानिकों ने प्रयत्न किया, कि उन तत्वों का पता करें, जिनके परमाणुओं द्वारा विविध पदार्थ निर्मित होते हैं। धीरे-धीरे उन्होंने ऐसे ९२ तत्वों का पता किया और इन तत्वों के परिज्ञान से रसायनशास्त्र के विभाग में बहुत अधिक सहायता मिली।

रसायन शास्त्र के विकास के कारण वैज्ञानिकों ने बहुत से पदार्थों का कृत्रिम रूप में निर्माण किया। विविध प्रकार के रंग, आल्कोहल, खाद, सुगन्ध, चमड़ा, रबड़, औषधि आदि रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बनाये जाने लगे। मानव समाज के हित व कल्याण के लिये जो विविध प्रकार की वस्तुएँ अपेक्षित हैं, विज्ञान की सहायता से उनका निर्माण शुरू हुआ। रासायनिक खादों की सहायता से जमीन की उपज-शक्ति बढ़ाई जाने लगी। खेत की मिट्टी का रासायनिक विश्लेषण करके यह मालूम किया जाने लगा, कि वह मिट्टी किस फसल के लिये अधिक उपयुक्त है, और एक विशेष प्रकार की फसल को पैदा



करने के लिये उसमें किस प्रकार का खाद डाला जाना चाहिये। शहरों में पीने के पानी को नुद्ध व दोषरहित करने के लिये भी रसायनशास्त्र का उपयोग किया गया। कारखानों में तैयार होनेवाले विविध प्रकार के माल को अधिक उत्तम व टिकाऊ बनाने के लिये रासायनिक प्रक्रियाओं की मदद ली जाने लगी।

**विद्युत् शक्ति**—अठारहवीं सदी के अन्तिम भाग में गत्वानी और वोल्टा नामक दो इटालियन वैज्ञानिकों ने पहले-पहले विजली की बेटरी का आविष्कार किया था। विजली का परिचय इसमें पहले भी यूरोपियन लोगों को था। रगड द्वारा विजली को वे पैदा भी करते थे। पर बेटरी का निर्माण कर उससे उत्पन्न विद्युत् शक्ति क्रियात्मक रूप से उपयुक्त हो सकती है, इसका पहले-पहल परिज्ञान इन इटालियन वैज्ञानिकों ने ही किया था। उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ में अम्पेअर् और अरगो नामक फ्रेंच वैज्ञानिकों ने यह प्रदर्शित किया कि विजली और चुम्बक का घनिष्ठ सम्बन्ध है, और विजली द्वारा चुम्बक गति को उत्पन्न किया जा सकता है। इस आविष्कार का यह परिणाम हुआ, कि टेलीग्राफ, टेलीफोन, वायरलैस (बेतार की तार) व विजली के अन्य उपकरणों का नूतनता हुआ। इसी समय फेरेडे ने डायनमो का आविष्कार किया। डायनमो के आविष्कार में विजली का प्रचुर परिमाण में उत्पादन सम्भव हुआ, और रोशनी आदि के लिये उसका उपयोग किया जाने लगा। जब एक बार मनुष्य ने बेटरी और डायनमो द्वारा विजली के उत्पादन के ढंग को जान लिया, तो उसने अनेक इस प्रकार की मशीनों का निर्माण शुरू किया, जिनमें हमारे जीवन का ढग ही बिल्कुल बदल गया। शहरों की सड़कें और गलियों में विजली की रोशनी दिखाई देने लगी, स्कान तेज व नमकदार प्रकाश में जगमग हो गये, जोर छोटे के स्थान पर विद्युत् शक्ति से चलनेवाली गाड़ियां प्रयोग में आने लगी। कारखानों में भी विद्युत् शक्ति का उपयोग होने लगा।

उन्नीसवीं सदी के अन्त तक वैज्ञानिकों ने यह भी गालूम किया, कि वस्तुतः प्रकृति के सब तत्व एक हैं। जो पदार्थ हमें ठोस, द्रव या गैस रूप में दृष्टिगोचर होते हैं, वस्तुतः उनमें कोई तात्विक भेद नहीं है। कोई पदार्थ जो हमें ठोस, द्रव या गैस रूप में उभलव्य होता है, उसका कारण केवल यह है, कि उसे इन विविध रूपों में आने के लिये उष्णता की कम या अधिक अपेक्षा होती है। इस परिज्ञान ने भौतिक विज्ञान की उन्नति में बहुत सहायता दी, और अनेक नये यन्त्र व उपकरण आविष्कृत किये गये।

**ज्योतिष-—**ज्योतिष शास्त्र बहुत प्राचीन है। पर उन्नीसवीं सदी में वैज्ञानिकों ने दूरबीनों द्वारा नक्षत्र-मण्डल के सम्बन्ध में वाक्यावली और निश्चित रूप में परिज्ञान प्राप्त करना शुरु किया। विविध तारा, नक्षत्र आदि आकार में कितने विचित्र हैं, पृथ्वी से वे कितनी दूरी पर स्थित हैं, इस सम्बन्ध में नये-नये तथ्यों को मालूम किया जाने लगा। वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से ज्योतिषशास्त्र में असाधारण उन्नति की।

**चिकित्सा शास्त्र —**१८३८ में प्लाडवैन आर श्वान्न नामके दो जर्मन वैज्ञानिकों ने इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया, कि जिस प्रकार भौतिक जगत् के विविध पदार्थ छोटे-छोटे परमाणुओं द्वारा बने हैं, वैसे ही प्राणियों के शरीर भी छोटे-छोटे अवयवों से बने होते हैं। ये अवयव (जिन्हें सेल कहा जाता है) अपने आप में जीवित बनाए हैं। जिस प्रकार एकान बहुत सी ईंटों से मिलकर बना होता है, वैसे ही प्राणियों के शरीर भी करोड़ों छोटे-छोटे अवयवों (सेल) से मिलकर बने होते हैं। मनुष्य के शरीर में इन अवयवों की संख्या २,६०,००,००० होती है। इस अवयव-सिद्धान्त ने विविध बीमारियों के स्वरूप को समझने व उनकी चिकित्सा के नये तरीकों के आविष्कार में बहुत सहायता पहुँचाई। प्राणिशास्त्र (वायलोजी) के आधार में यही सिद्धान्त काम कर रहा है। १८६३ में कीटाणु (बैक्टीरिया) का पता किया गया। ये कीटाणु विविध आकार के बहुत छोटे-छोटे जंतु होते हैं, जिन्हें यदि एक छाटन में रखा जाय, तो एक इंच लम्बाई में चार हजार कीटाणु आ जावेंगे। इसमें इनके अत्यन्त लघु आकार की कल्पना की जा सकती है। ये कीटाणु सर्वत्र व्याप्त हैं। वायु, जल, मिट्टी, वनस्पति आदि सर्वत्र वे विद्यमान हैं, और विविध रोगों के साथ उनका घनिष्ठ सम्बन्ध है। कीटाणु-सिद्धान्त का प्रधान प्रवर्तक पास्त्यूअर था। वह फ्रांस का निवासी था, और उसने अनेक परीक्षणों द्वारा यह प्रदर्शित किया, कि शराब, दही आदि के रूप में जो परिवर्तन पदार्थ में आता है, उसका कारण ये कीटाणु ही हैं। साथ ही, विविध रोग इन कीटाणुओं द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। पास्त्यूअर ने यह भी प्रदर्शित किया, कि इन कीटाणुओं का विनाश कर किस प्रकार रोगों की चिकित्सा भी की जा सकती है। हैजा, इन्फ्लूएन्जा, मलेरिया, टायफाइड, तपेदिक, जुवाम, मलेरिया आदि विविध बीमारियों में किस प्रकार ये कीटाणु कारण होते हैं, वैज्ञानिकों ने यह बात भी प्रदर्शित की, और इन कीटाणुओं का विनाश करने के लिये विविध चिकित्साओं का भी प्रारम्भ किया। पास्त्यूअर ने स्वयं पागल कुत्ते के काटने का इलाज इस सिद्धान्त के अनुसार आविष्कृत किया था। केवल रोगों की चिकित्सा के लिये ही नहीं, अपितु इन्हीं रोकने के लिये भी कीटाणु सिद्धान्त को प्रयुक्त किया गया। बूक आदि द्वारा रोगों के कीटाणु फैलने हैं, इसलिये नगरों की म्युनिसिपैलिटियों ने इस बात का प्रचार

किया, कि लोग सड़कों व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर नूके नहीं। गले-सड़े फलों, अण्डों व उमरी तरह की अन्य गन्धगी को सार्वजनिक स्थानों पर फेंकने से लोगों को रोका गया। मिठाई आदि भोज्य पदार्थ को भी विक्रेता लोग ढक कर रखे इसकी व्यवस्था की गई। स्वास्थ्य रक्षा के नियमों पर सरकारों ने विशेष रूप से ध्यान देना शुरू किया। इन सब बातों का परिणाम यह हुआ, कि यूरोप में बीमारियों का फैलना बहुत कुछ रुक गया। उन्नीसवीं सदी के शुरू में चेचक एक ऐसा रोग था, जिसमें बहुमख्यक जनता वच नहीं पाती थी। पर बीसवीं सदी के शुरू तक यह रोग यूरोप में प्रायः समाप्त हो गया था। यही बात टिफ, हुआ आदि अन्य छूत की बीमारियों के विषय में भी कही जा सकती है। यंगपियन लोगों के स्वास्थ्य में जो यह आमाधारण उन्नति हुई, उसका श्रेय मुख्यतया कीटाणुनिदान को ही है।

उन्नीसवीं सदी में शल्य चिकित्सा में भी बहुत उन्नति हुई। पहले शल्यक्रिया (ऑपरेशन) बहुत कष्टप्रद होते थे। यूरोप के लोगों को किसी ऐसी औषधि का ज्ञान नहीं था, जो मासिक रूप से बीमार को बेहोश कर सके, और उसे शल्यक्रिया के कष्ट या अनुभव न होने पाए। १८४६ में डा० वैरन नामक अमेरिकन चिकित्सक ने एक नयी औषधि का आविष्कार किया, जिससे शल्यक्रिया पीड़ा रहित रूप में की जा सकती थी। १८४७ में क्लोरोफार्म का आविष्कार हुआ। इन औषधियों के परिज्ञान से पूर्व शल्यक्रिया न केवल रोगी के लिये अपितु चिकित्सक के लिये भी अत्यन्त कष्टप्रद होती थी। उन्नीसवीं सदी के कारण ऑपरेशन बहुत कम किये जाते थे। वोस्टन के हास्पिटल में जहाँ १८४६ में पूर्व साल भर में केवल ३७ ऑपरेशन होते थे, वहाँ क्लोरोफार्म के आविष्कार के बाद इन ऑपरेशनों की संख्या बढ़कर ३७०० तक पहुँच गई। क्लोरोफार्म के ईजाद हो जाने से शल्यक्रिया अत्यन्त सरल हो गई है, और चिकित्सक निश्चिन्तता के साथ अपना काम कर सकता है। १८७६ में उन अनेक औषधियों और प्रक्रियाओं का आविष्कार हुआ, जिनमें शल्यक्रिया के उपकरणों, रुई, पट्टी आदि को कीटाणुरहित किया जाता है। इन आविष्कारों के कारण अब शल्यक्रिया स्वतरे से प्रायः विरहित हो गई है। एम्बर के कारण चिकित्सकों का कार्य और भी अधिक सुगम हो गया है।

जादि कितनी ही ऐसी वस्तुएँ तैयार करता है, जिनकी अठारहवीं सदी में कल्पना भी सम्भव नहीं थी।

(२) हमने इस इतिहास के एक पहले अध्याय में द्वितीय व्यावसायिक क्रान्ति का उल्लेख किया है। अठारहवीं सदी के अन्त में डचलैण्ड में जो प्रथम व्यावसायिक क्रान्ति हुई थी, उसके कारण मध्यकाल की आर्थिक श्रेणियों (गिल्ड) का अन्त होकर फैक्ट्रियों का विकास हुआ था। पर उन्नीसवीं सदी के वैज्ञानिक आविष्कारों द्वारा आर्थिक उत्पत्ति के प्रकार में और अधिक अन्तर आया। भाप, नेल व विजली से चलनेवाले विशाल कारखानों का विकास हुआ, और आर्थिक उत्पत्ति में छोटे परिमाण के उत्पादकों का स्थान बड़े बड़े पूंजीपति लेने लगे। जायन्ट स्ट्रोक कम्पनियों का विकास हुआ, और बड़ी-बड़ी कम्पनियों का स्थान वे विशालकाय ट्रस्ट लेने लगे, जिन्होंने सम्पूर्ण व्यवसाय को ही अपने अधिकार में कर लिया। व्यवसायों का संचालन व्यक्तियों के हाथों में न रहकर राज्य के अधीन होना चाहिये, यह विचार इसी कारण उत्पन्न हुआ, क्योंकि वैज्ञानिक आविष्कारों द्वारा आर्थिक उत्पत्ति के ढंग में ऐसे परिवर्तन हो गये थे, जिनमें उत्पन्न का कार्य व्यक्तियों के हाथों में रह सकना सम्भव ही नहीं रहा था।

(३) देश और काल पर विजय स्थापित करने में वैज्ञानिक आविष्कारों द्वारा बहुत सहायता मिली। पन्द्रहवीं सदी के अन्त में अटलाण्टिक महासागर को पार करने में कोलम्बस को ७० दिन लगे थे। उन्नीसवीं सदी के शुरु में नैपोलियन के पास पोंडे में अधिक तेज चलने वाली कोई सवारी नहीं थी। १८१४ में वीएना की कांग्रेस में यूरोप के जो राजनीतिज्ञ एकत्र हुए थे, न उनके पास मोटरकारें थी, और न उन्हें वीएना पहुँचाने के लिये रेलगाड़ियों की ही सत्ता थी। ये राजनीतिज्ञ आपस में विचार विनिमय करने के लिये न टेलीफोन प्रयुक्त कर सकते थे, और न वीएना की कांग्रेस के समाचारों को यूरोप के विभिन्न देशों में पहुँचाने के लिये तार व रेडियो ही विद्यमान थे। वीएना की कांग्रेस जिस राजप्रासाद में हो रही थी, उसमें विजली की रोगनी की तो बात ही न्ना, गैस की रोशनी भी नहीं थी। उसे प्रकाशित करने के लिये मोमवत्तियाँ ही प्रयोग में लाई जा रही थी। पर उन्नीसवीं सदी का अन्त होने में पूर्व वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण यूरोप का जीवन कितना परिवर्तित हो गया था। यूरोप में सर्वत्र रेलवे लाइनों का जाल-सा बिछ गया था। टेलीग्राफ, टेलीफोन, वायरलेस आदि द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर समाचार को पहुँचा सकना सम्भव हो गया था, और विजली की रोगनी से यूरोप के प्रायः सभी नगर जगमगाने लगे थे। रेलवे, भाप से चलनेवाले जहाज, टेलीग्राफ, टेलीफोन आदि के कारण ससार के विविध देश एक दूसरे के बहुत समीप आ गये थे, और मनुष्य देश और काल पर असाधारण विजय प्राप्त करने में समर्थ हुआ था।

(४) देश और काल पर विजय के कारण मनुष्य जाति ने अन्तर्राष्ट्रीयता के मार्ग पर भी अग्रसर होना प्रारम्भ कर दिया था। फ्रांस, बेल्जियम, इटली आदि की राष्ट्रीय सीमाएँ मानव समाज की एकता में कृत्रिम रूप से बाधा उपस्थित करती हैं, यह विचार विकसित होने लगा था। इस विचार का विकास विशेष रूप से बीसवीं सदी में हुआ, और इस पर हम यथास्थान प्रकाश डालेंगे।

## २. साहित्य

**शिक्षा का प्रसार**—उन्नीसवीं सदी में यूरोप में साहित्यिक क्षेत्र में भी बहुत उन्नति हुई। प्रेस के आविष्कार के कारण इस समय पुस्तकें व पत्र पत्रिकाएँ बहुत सुलभ हो गईं थीं। बड़े-बड़े कारखानों में कागज भारी मात्रा में बनता था, और उसका मूल्य बहुत कम होता था। इस प्रकार के प्रेस कायम हो गये थे, जो एक घण्टे में हजारों प्रतियाँ छाप सकने थे। पुस्तकें न केवल सुलभ थीं, अपितु उनका मूल्य भी कम होता था। इस दशा में शिक्षा का प्रसार बहुत तेजी के साथ हो रहा था। उन्नीसवीं सदी के अन्त तक यूरोप में शिक्षा का इतना अधिक प्रसार हो गया था, कि फ्रांस में निरक्षर लोग केवल १४ प्रतिशत रह गये थे। इस समय यूरोप के विविध देशों में निरक्षर लोगों की संख्या इस प्रकार थी—ब्रिटेन ४ प्रतिशत, इटली ३७ प्रतिशत, हंगरी ३३ प्रतिशत, आस्ट्रिया १४ प्रतिशत, बेल्जियम १३ प्रतिशत, बल्गेरिया ६० प्रतिशत, ग्रीस ५७ प्रतिशत, पोर्तुगाल ६९ प्रतिशत, रमानिया ६० प्रतिशत, रूस ७० प्रतिशत, सर्बिया ७८ प्रतिशत और स्पेन ४६ प्रतिशत। हमें मन्देह नहीं, कि यूरोप के अनेक देशों में इस समय भी अशिक्षित लोग बहुत बड़ी संख्या में विद्यमान थे, पर साथ ही यह भी स्वीकार करना होगा, कि उन्नीसवीं सदी में यूरोप ने शिक्षा के क्षेत्र में असाधारण उन्नति की थी। फ्रांस की राज्यक्रान्ति के समय यूरोप का कोई भी देश ऐसा नहीं था, जिसमें शिक्षित लोग २० प्रतिशत में अधिक हों।

**साहित्य**—शिक्षा के प्रसार के साथ-साथ इस समय यूरोप में साहित्य भी निरन्तर उन्नति कर रहा था। इङ्ग्लैण्ड में महारानी विक्टोरिया का काल (१८३७ में १९०३) साहित्यिक दृष्टि से स्वर्णीय युग माना जाता है। फ्रांस में राज्यक्रान्ति द्वारा जो चेतना जागरूक उत्पन्न हुई थी, उसने वहाँ के साहित्यिक जीवन को भी प्रभावित किया और उन्नीसवीं सदी में वहाँ अनेक ऐसे लेखक और विचारक उत्पन्न हुए, जिनका सिक्का सारा संसार मानता है। जर्मनी, रूस, स्पेन, स्वीडन आदि सर्वत्र उन्नीसवीं सदी साहित्यिक प्रतिभा की सदी थी। गद्य, पद्य, नाटक, आलोचनात्मक साहित्य, इतिहास आदि सब प्रकार की पुस्तकें इस युग में प्रकाशित हुईं। मध्यकाल तक साहित्य का मयम जविक प्रचलित व लोकप्रिय प्रकार पद्य था। उस युग के साहित्यिक अपने विचारों व मनोभावों का प्रकट करने के लिये पद्य का ही आश्रय लेते थे। लघी वृत्त गद्य के प्रचार के कारण

वहुसंख्यक पाठक अवश्य परिचित होंगे। उन्नीसवीं सदी के इङ्गलिश साहित्य के ये उज्ज्वल रत्न थे। डिफेन्स ने अपने उपन्यासों में इङ्गलिश जनता के पीड़ित लोगों का बड़ा मार्मिक चित्र खींचा है। न्यायालयों में न्याय प्राप्त करने में जनता को किम प्रकार देर लगती है, जेल में कैदियों को कैमरे घोर कण्ट उठाने पड़ते हैं, गरीबखानों में आश्रय प्राप्त गरीबों के साथ कैमरा दुर्व्यवहार होता है, इन सब बातों पर डिफेन्स ने बड़े सुन्दर रूप में प्रकाश डाला है। डिफेन्स के उपन्यासों का उन्नीसवीं सदी के सुधारक धर्मग्रन्थ के समान अनुशीलन करने थे। कार्लाइल ने जानी कृतियों द्वारा जनता का ध्यान उन बुराइयों की तरफ आकृष्ट किया था, जो व्यावसायिक क्रान्ति के कारण इङ्गलैण्ड में उत्पन्न हो गई थी। कार्लाइल अनुभव करता था, कि व्यावसायिक क्रान्ति के कारण जो भौतिक उन्नति यूरोप में हुई है, वह जनता के अध्यात्म को पूर्णतया कुचल रही है। रस्किन नये युग के परिवर्तनों को चिन्ता की दृष्टि में देखता था, और मनुष्यों का ध्यान पुराने युग के सरल व सुखमय जीवन की ओर आकृष्ट करना था। मैकाले फ्रेंच राज्यक्रान्ति द्वारा उत्पन्न हुई प्रवृत्तियों का खट्टर विरोधी था। पर भौतिक क्षेत्र में मनुष्य जो उन्नति कर रहा था, मैकाले उसका स्वागत करता था। उनका मत था, कि स्वतन्त्रता के साथ-साथ मनुष्य के लिये उपयोगिता और प्रगति की भी आवश्यकता है। मिसेज ब्रॉनिङ्ग ने इङ्गलिश जनता का ध्यान कारखानों में काम करने वाले बालकों की दुर्दशा की ओर आकृष्ट किया था। इङ्गलैण्ड की फैक्ट्रियों में सुधार के लिये जो अनेक कानून बनें, मिसेज ब्रॉनिङ्ग की कविताएँ उनमें बहुत सहायक हुईं। यँकरे और ज्यार्ज ईलियट ने अपनी कृतियों में सम्पत्ति के परिग्रह की बुराइयों को प्रदर्शित किया। इङ्गलैण्ड के ये विविध साहित्यसेवी अपनी रचनाओं द्वारा जनता में अपने विचारों का प्रसार करने में बहुत सफल हुए, और इसमें सन्देह नहीं, कि इनमें जनता को विविध सामाजिक व राजनीतिक समस्याओं पर निष्पक्ष रूप से विचार कर सकने का अवसर मिला।

उन्नीसवीं सदी के फ्रेंच साहित्यिकों में आँनारे द वाल्जाक, थियरे ह्यूगो, अलजान्द्र द्यूमा, मोपासा, ज्यार्ज साँ और एमिल जोला सबसे प्रसिद्ध हैं। वाल्जाक ने बहुत से ऐसे उपन्यास लिखे, जिनमें कुलीन व उच्च श्रेणियों के विकृत जीवन, भोग विलास और मूर्खताका बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। वाल्जाक साहित्य में 'यथार्थवाद' का बड़ा पक्षपाती था, और उसके गन्थों में कल्पना व भावुकता की अपेक्षा यथार्थता को अधिक महत्त्व दिया गया है। द्यूमा, मोपासा और एमिल जोला आदि की कृतियाँ फ्रेंच साहित्य के अमूल्य रत्न हैं, और उनके अनुवाद ससार की प्रायः सभी उन्नत भाषाओं में हो चुके हैं। उन्नीसवीं सदी में फ्रांस क्रान्ति के क्षेत्र में सम्पूर्ण यूरोप का नेतृत्व करता था। इन फ्रेंच साहित्यिकों ने भी साहित्य के क्षेत्र में यूरोप का नेतृत्व किया। इन्होंने अपने ग्रन्थों में समाज के विविध वर्गों के जो सजीव चित्र चित्रित किये, और जिस प्रकार अपने युग की समस्याओं पर अपने विचार प्रकट किये, उससे जनता को विचार करने के लिये बहुत सामग्री उपलब्ध हुई।

इस युग के रूसी साहित्यिकों में गोगोल, तुर्गनेव, टाल्स्टाय, गोर्की और चैखोव के नाम विश्वविदित हैं। गोगोल ने अपने गन्थों में रूस की कुलीन श्रेणी और विशेष-

नया ग्रामकवर्ग के विकृत जीवन को चित्रित किया। साथ ही सर्वसाधारण रूमी जनता किम प्रकार अर्द्धदास का जीवन व्यतीत करती थी, और इन अर्द्धदासों का जीवन कितना दयनीय था, इसका बड़ा मार्मिक विवरण गोगोल के ग्रन्थों में मिलता है। तुर्गनेव बहुत प्रसिद्ध क्रान्तिकारी लेखक था। रूस में जारशाही के विरुद्ध जो क्रान्तिकारी आन्दोलन चल रहे थे, उनका तुर्गनेव के ग्रन्थों में बड़ा सजीव चित्रण है। मनुष्य मनुष्य के प्रति किम प्रकार का बोधत्म व्यवहार करता है, युद्ध कितनी भयकर चीज है, वह मनुष्य को किम प्रकार जगली पशुओं की अपेक्षा भी नीच बना देती है, इन बातों की और विचारशील जनता का ध्यान आकृष्ट करने के लिये टाल्स्टाय ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। गोर्की स्वयं उग्र क्रान्तिकारी था। समाजवाद के प्रसार में उसकी रचनाओं का बड़ा हाथ था। रूसी समाजवादियों (बोल्शेविकों) के लिये गोर्की की पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण हैं, और उनसे इस क्रान्तिकारी सिद्धान्त के प्रचार में बहुत सहायता मिली है। चेखोव के ग्रन्थों में रूस के बदलते हुए समाज का बड़ा सुन्दर चित्रण किया गया है, और साथ ही यह भी प्रदर्शित किया गया है, कि जागीरदार श्रेणी की आन्तरिक दशा कितनी हीन और विकृत थी।

उत्तरीमवी मदी के जर्मन लेखकों में हाइन, मान्न और हाप्टमान्न के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। स्वीडन के साहित्यकों में स्ट्रिन्डबर्ग और नार्वे के लेखकों में इवसन विग्रहप्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार के अन्य बहुत से साहित्यिक इस युग में यूरोप के अन्य देशों में भी उत्पन्न हुए, और उनकी कृतियों के कारण यूरोप के साहित्यिक क्षेत्र में एक नवश्रवण उपस्थित हो गया।

### ३. कला

वनने शुरू हुए, और इन सबको मिलाकर अर्कम्स्ट्रा (मग्निलित वाद्य) का प्रारम्भ किया गया, जिसमें बहुत से वादक विविध प्रकार के वाद्यों का उपयोग कर एक मग्निलित संगीत का प्रादुर्भाव करते हैं। पहले यूरोप में संगीत में वाद्य की अपेक्षा मानव वाणी का अधिक महत्व होता था, पर जब वाणी की मर्यादा के साथ-साथ वाद्य उपकरणों की मधुर स्वरलहरी का भी महत्व बढ़ने लगा। उपकरणों के लिये भी संगीत की रचना की जाने लगी, और मानव वाणी की अपेक्षा किन्हीं किन्हीं वाद्य यन्त्रों की सहायता में उच्च कोटि के संगीत का सृजन प्रारम्भ हुआ। इन वाद्य संगीत के विकास में ब्राबर, वाग्नर और वर्दी ने प्रमुख भूमिका ली। जिस प्रकार उन्नीसवीं सदी में राजनीतिक व साहित्यिक क्षेत्र में राष्ट्रीय भावना कार्य कर रही थी, वैसे ही संगीत में भी राष्ट्रीय प्रवृत्तियाँ विकसित हुईं। वाग्नर जर्मन राष्ट्रियता का प्रबल समर्थक था, और वर्दी इटालियन राष्ट्रियता का। इन दो संगीतकारों ने जर्मनी और इटली में राष्ट्रीय एकता की अनुभूति के लिये बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया। इनके संगीत जर्मनी और इटली के विविध राज्यों को समान रूप में प्रभावित करते थे। फ्रांस में बार्तोळोम्य और नेन में पीटर शैकोव्स्की संगीत के सर्वप्रसिद्ध आचार्य हुए। संगीत की इस सर्वोत्तम उन्नति ने यूरोप के जनसमाज के मुख, सतोष व आह्लाद के लिये बड़ा काम किया। संगीत एक ऐसी अभिव्यक्ति है, जो भाषा व जाति-भेद की विशेष अपेक्षा नहीं रखती। इसीलिये इन विश्व-प्रसिद्ध संगीतकारों का कार्य केवल उनके अपने देशों तक ही सीमित नहीं रहा। समार के प्रायः सभी देशों पर उनकी कला का प्रभाव पड़ा।

**चित्रकला**—संगीत और साहित्य के समान चित्रकला भी मनोभावों को अभिव्यक्त करने का अत्यन्त उत्तम साधन है। उन्नीसवीं सदी में यूरोप में अनेक ऐसे चित्रकार उत्पन्न हुए, जिन्होंने इस क्षेत्र में असाधारण रूप में उन्नति की। यहाँ हमारे लिये यह सभव नहीं है, कि इनकी कला के सम्बन्ध में जरा भी विशद काम ले लिख सके। इन कलाविदों के नाम का उल्लेख करना ही इस इतिहास के लिये पर्याप्त होगा। यजेन दलाक्रोआ (फ्रांस), फ्रासिस्को गोआ (स्पेन), जॉन रीन्स्ट्रेल (इङ्ग्लैण्ड), कामिल बोरो (फ्रांस), गुस्ताव कूबेर् (फ्रांस), औरी दामिए (फ्रांस) आदि कितने ही चित्रकार उन्नीसवीं सदी में यूरोप में हुए, जिन्होंने अपनी कला द्वारा नये विचारों व भावनाओं को अभिव्यक्त किया। इन क्षेत्र में फ्रांस यूरोप में सर्वप्रधान स्थान रखता है। कदाचित् माने, पॉल केजान् आदि कितने ही कलाकारों ने वहाँ चित्रकला सम्बन्धी नये सम्प्रदायों का प्रवर्तन किया। ये लोग मानते थे, कि जिस प्रकार भाषा और लिपि मानव भावनाओं को अभिव्यक्त करने के साधन हैं, वैसे ही चित्रकला का प्रयोजन भी मनोभावों और विचारों को प्रकट करना है। इस कार्य में इन्होंने असाधारण रूप से सफलता भी प्राप्त की।

**स्थापत्य कला**—उन्नीसवीं सदी में स्थापत्य कला में भी असाधारण उन्नति हुई। इस युग के सबसे प्रसिद्ध स्थापति चार थे—चार्ल्स डन्मार्क (डन्मार्क), वैनोवा (इटली), आगुस्त रोदा (फ्रांस), और गॉडन्स (अमेरिका)। इन चारों में भी आगुस्त रोदा अपनी कला का सबसे बड़ा आचार्य था। उसका मन्तव्य था, कि उत्कृष्ट कला के लिये प्रतिमा के अयवों का सुन्दर होना आवश्यक नहीं है। उत्कृष्ट कला वह है, जो प्रकृति के अनु-



कूल हो। प्रस्तर में वास्तविकता को चित्रित करना ही उसका उद्देश्य था। आधुनिक युग की स्थापत्य कला में बोदा का बहुत उच्च स्थान है, और वर्तमान समय के कितने ही चित्रकार उसे अपना आदर्श मानते हैं।

## ४ विज्ञान और धर्म

उन्नीसवीं सदी में जब यूरोप में विकासवाद का सिद्धान्त विकसित हुआ, तो ईसाई धर्म-गान्धियों ने उसका घोर विरोध किया। उनका विचार था, कि विज्ञान के नाम से जिन नये सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया जा रहा है, वे धर्म की जड़ पर कुठाराघात करते हैं। उन किसी भी मनुष्यों को उनपर विश्वास नहीं करना चाहिये। पर धीरे-धीरे प्रोटेस्टेन्ट लोगों ने विज्ञान के साथ समझौता करना शुरू किया। उनका कहना था, कि मनुष्य को सत्य की खोज के लिये प्रमाणवाद पर ही आश्रित नहीं रहना चाहिये, अपितु अपनी बुद्धि का उपयोग कर परीक्षणों द्वारा भी सत्य की खोज करनी चाहिये। प्रोटेस्टेन्ट सम्प्रदाय का प्रादुर्भाव ही रोम के पोप के विरुद्ध विद्रोह करके हुआ था। अतः उनके लिये यह कठिन नहीं था, कि इन वैज्ञानिक सिद्धान्तों की सत्यता को भी वे स्वीकार कर लें। पर प्रोटेस्टेन्ट लोगों ने भी नये वैज्ञानिक तथ्यों को सुगमता के साथ स्वीकृत नहीं कर दिया। उनमें इस प्रश्न पर भारी विवाद हुआ, और कुछ प्रोटेस्टेन्ट पादरी तो इसी प्रश्न पर फिर रोमन कैथोलिक चर्च के अन्यायी हो गये। रोमन कैथोलिक शासक वर्ग में तो वैज्ञानिक तथ्यों को किसी भी प्रकार स्वीकृत करने के लिये तैयार नहीं हुए। पर बाद में उन्होंने भी अपने को यह कहकर समझाना शुरू किया, कि धर्म का सम्बन्ध तो भगवान और मनुष्य की आत्मा से है। विज्ञान द्वारा जो नये सिद्धान्त प्रतिपादित किये जा रहे हैं, उनका सम्बन्ध भौतिक जगत् से है, और इस जगत् में वैज्ञानिक आविष्कारों की मान्यता को स्वीकृत किया जा सकता है। इसी कारण पार लियोनार्डो ने स्वयं एक वेधशाला का निर्माण कराया, जिसमें ज्योतिष सम्बन्धी तथ्यों की परीक्षा या प्रयत्न किया गया। उसने आसन्न क्रेच वैज्ञानिक पाम्प्यूअर को उसकी आज्ञा के लिये वहाँ भी दी। पर सब पोपों की विज्ञान के सम्बन्ध में यह वृत्ति नहीं थी। पाप्युस दशम और बेनेडिक्ट पन्द्रहवें ने नई नई वैज्ञानिक सिद्धान्तों को किसी भी प्रकार से स्वीकृत करने के लिये उद्यत नहीं हुए थे।

रोमन कैथोलिक के सम्बन्ध में भी समाजवाद आदि जो नये विचार उन्नीसवीं सदी में प्रतिपादित हो रहे थे, किश्चियन पादरी उनके भी सख्त विरोध में थे। यही कारण है कि उनमें समाजवादी विचारों ने धर्म और चर्च के विरुद्ध आवाज उठाई। पर बाद में पार लियोनार्डो समझ कर सन्तोष करने लगे, कि धर्म का क्षेत्र मनुष्य और भौतिक जगत् के समान सामाजिक संगठन में भी मनुष्य अपनी बुद्धि का उपयोग कर नये विचारों का अनुसरण कर सकता है।

पर ईसाई धर्मवादी समाज संगठन सम्बन्धी नये विचारों को स्वीकार करने में उद्यत नहीं हुए, पर उन्होंने मानव समाज के दुश्मनों को दूर करने के लिये और इस जगत् में नये विचारों का अनुसरण कर सकने के लिये अनेक नये प्रयत्न क

प्रारम्भ किया। उसी उद्देश्य से मर्तिन फौज (मार्टिन लूथर) मनुष्य की प्रकृति को समझने के लिए, जिसके साथ लोग-गोड़ों की सेवा करना जेल में कैदियों का काम था, वह अपने देना और गरीबों के कष्टों को दूर करना है। ईसाई धर्म के विविध चर्चों ने अब जर्मनी के राजा पर विशेष रूप से ध्यान देना प्रारम्भ किया। इसी-लिये उन्होंने स्त्रियाँ और बच्चों की दया को सुधारने, बलक के विरुद्ध प्रचार करने, गरीबों को दूर करने और इसी प्रकार के अन्य कार्यों के लिये युक्त करना शुरु किया। इन सब प्रयत्नों का परिणाम यह हुआ कि धर्म-स्वतन्त्रता और युद्धवाद के इस वैज्ञानिक युग में भी चर्च का प्रभाव जाग्रत रहा। मनुष्य चर्च में बुद्धिजीवी लोग, राज-चर्च के धार्मिक सन्तव्यों में विश्वास नहीं करते, परन्तु उनके लोकप्रचार के कार्यों की उपयोगिता को स्वीकार करने हैं।

चर्च भी अब समय को आवश्यकताओं की दृष्टि में रगड़ अपने मन्त्रों और सिद्धांतों में परिवर्तन करने के लिये तत्पर है। उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्ध में ईसाई चर्च लोक-तन्त्रवाद का विरोधी था, पर अब वह मनुष्य-मानव की समता और मानव अधिकारों का समर्थक बन गया है। साम्यवादी आन्दोलनों का शुरू में चर्च ने बहुरी विरोध किया, पर अब वह भी इस बात को स्वीकार करता है कि पक्षी-पतियों हो मजदूरों के प्रति अनुचित बरताव करना चाहिये। विज्ञान के साथ उत्का जो विरोध था, वह भी अब प्रायः समाप्त हो गया है, और ईसाई धर्माचार्य भी अब वैज्ञानिक योजन द्वारा मनुष्य के परिज्ञान की आवश्यकता को स्वीकार करने लग गये हैं। पर साथ ही यह भी सत्य है कि अब सर्व-साधारण जनता पर चर्च का वह प्रभाव नहीं रह गया है, जो उन्नीसवीं सदी के मध्य भाग तक था।







## ७. व्यापारिक क्रांति

पन्द्रहवीं सदी के अन्त में नये प्रदेशों को खोज निकालने की जो प्रवृत्ति यूरोप में शुरू हुई थी, उसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं। उस प्रवृत्ति ने न केवल विशाल अमेरिकन महाद्वीप में उपनिवेश बनाने का अक्सर यूरोपियन देशों को प्रदान किया, अपितु अफ्रीका के विविध प्रदेशों को हमनगत करने और एशिया के साथ व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करने में उन्हें प्रेरित किया। उसने यूरोप के लोगों के सम्मुख व्यापार का एक विज्ञान क्षेत्र खोल दिया और उसमें लाभ उठाकर वे आर्थिक समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर होने लगे।

नये प्रदेशों के परिज्ञान के कारण यूरोप की आर्थिक दशा में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन आया, उसे व्यापारिक क्रांति के नाम से कहा जाता है।

**व्यापारिक क्रांति का स्वरूप**—पहले यूरोप के सामुद्रिक व्यापार का वह भूमध्यसागर व अटलान्टिक महासागर के नटवर्ती प्रदेशों तक ही सीमित था। अब यूरोपियन नाविक अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में जाने-जाने लगे। उनके व्यापार सुदूरवर्ती इण्डोचायना, इण्डोनीशिया, भारत, अमेरिका और अफ्रीका जैसी देशों के साथ व्यापार के लिये तत्पर हुए। जहाजों का आकार अधिक विशाल होने लगा। पन्द्रहवीं सदी के अन्त में सभ्यताओं के विनाश द्वारा स्पेनिया लोगों को सोना और चांदी अफ्रीका की माण में लूट में प्राप्त हुए। अमेरिका में उन बहुमूल्य धातुओं की जो अनेक नई नौकाएँ खोजी गई थी, उनसे भी सोना चांदी बहुत बड़ी मात्रा में यूरोप पहुँचने लगा। अफ्रीका का एशिया के साथ व्यापार के कारण भी यूरोपियन लोगों को बहुत अधिक आर्थिक लाभ हुआ। धन की वृद्धि से महाजनो की बहुत उत्पत्ति हुई। बहुत से नये बैंक खुले। व्यापार के लिये अधिक पूँजी की आवश्यकता होती थी। इसलिये जायन्ट स्टॉक कम्पनियों का संगठन शुरू हुआ और करोड़ों रुपये की पूँजी से नई-नई कम्पनियाँ खोलीं प्रारम्भ हुईं। ईस्ट इण्डिया कम्पनी इस प्रकार की कम्पनियों का एक अच्छा उदाहरण है। इन जायन्ट स्टॉक कम्पनियों के हिस्से बाजार में खुले तौर पर विक्रित थे और इससे स्टॉक एक्सचेंज का भी प्रारम्भ हुआ, जो यूरोप के आर्थिक जीवन में एक सर्वथा नई चीज थी। आर्थिक उत्पत्ति के लिये अभी यूरोप में यान्त्रिक शक्ति का प्रयोग शुरू नहीं हुआ था। तैयार करने का उत्पादन पुराने तरीके से कारीगरों द्वारा ही किया जाता था, जो अपने घर पर बैठकर हाथ से सब काम करते थे। पर व्यापार का क्षेत्र और परिमाण अब पहले की अपेक्षा बहुत अधिक विशाल हो गया था।

व्यापार के सम्बन्ध में इस युग में (१५०० से १७५० तक) जिस नीति का अनुसरण किया जाता था, उसे मर्कन्टाइल सिस्टम कहा जाता है। इस नीति के अनुसार यूरोप का प्रत्येक देश यह यत्न करता था, कि वह अधिक से अधिक मात्रा में अपना माल और देशों को बेचे। आयात की अपेक्षा उसका निर्यात अधिक रहे, ताकि अपने माल के बदले में प्रचुर परिमाण में सोना चांदी प्राप्त की जा सके। वह देश समृद्ध समझा जाता था, जो अपने माल की कीमत के रूप में अन्य देशों से सिक्का (सोने या चांदी का) प्राप्त कर सके। इसलिये इस युग में प्रत्येक राज्य यह प्रयत्न करता था, कि अपने व्यवसाय को उत्तम रूप

और उसका तैयार माल अन्यत्र विककर राज्य की समृद्धि में सहायक हो। स्पेन, इङ्ग्लैण्ड, फ्रांस आदि देश इसी नीति का अनुसरण कर इस युग में धनी होने के लिये प्रयत्नशील थे।

**व्यापारिक क्रान्ति के परिणाम—(१)** व्यापारिक क्रान्ति का सब से महत्त्वपूर्ण परिणाम व्यावसायिक क्रान्ति का प्रादुर्भाव था, जो अठारहवीं सदी के अन्तिम भाग में यूरोप में शुरू हुई। अधिक से अधिक माल तैयार करने की प्रवृत्ति ने यूरोप के शिल्पियों को इस बात के लिये प्रेरणा दी, कि वे उत्पादन के नये तरीकों का अवलम्बन करें। हम इस व्यावसायिक क्रान्ति पर एक पृथक् अध्याय में प्रकाश डालेंगे। पर यहाँ यह ध्यान में रहना चाहिये, कि व्यवसायों के लिये नये साधनों के अवलम्बन के लिये जो प्रेरणा यूरोप के लोगों को प्राप्त हुई, उसका मूल कारण व्यापारिक क्रान्ति ही थी।

(२) सामाजिक क्षेत्र में व्यापारिक क्रान्ति ने अनेक महत्त्वपूर्ण परिणाम उत्पन्न किये। यूरोप के लोग दूर-दूर के देशों में व्यापार के लिये आने-जाने लगे, उन्हें नये देशों व नये लोगों से परिचय हुआ। इसमें उनकी दृष्टि अधिक विशाल हुई। वे अनेक नई वस्तुओं का अपने जीवन में उपयोग करने लगे। चाय और काफी का प्रयोग उन्होंने इसी युग में शुरू किया। तमाखू से भी पहले पहल परिचय उन्हें इसी समय में हुआ। अमेरिका और अफ्रीका के विशाल प्रदेशों में बसने व व्यापार के लिये यूरोपियन लोग बड़ी मक्या में जाने लगे। इससे यूरोप में जनसंख्या घटने लगी। इस समय तक यूरोप के किमानों की दशा अर्द्ध-दास की सी थी। आबादी के कम होने से इस दशा में अन्तर आने लगा और अफ्रीका के हब्शी गुलामों के कारण यूरोपियन किमानों को गुलामी से छुटकारा पाने में सहायता मिली। मध्यश्रेणी के लोगों को व्यापार और व्यवसाय द्वारा समृद्ध होने का अनुभव अवसर प्राप्त हुआ और धीरे-धीरे उनका महत्त्व बढ़ने लगा। अठारहवीं सदी में यूरोप में राज्यक्रान्ति की जो लहर प्रारम्भ हुई, उसका नेतृत्व मध्यश्रेणी के इन लोगों ने ही किया। मध्यश्रेणी में जो आत्मसम्मान और अपने महत्त्व की भावना प्रादुर्भूत हुई थी, उसका कारण यह व्यापारिक क्रान्ति ही थी।

(३) व्यापारिक क्रान्ति के राजनीतिक परिणाम और भी अधिक महत्त्वपूर्ण थे। व्यापार के विस्तार के कारण स्पेन, फ्रांस, इङ्ग्लैण्ड, प्रशिया आदि राजकीय आमदनी में असाधारण रूप से वृद्धि हो रही थी। राज्यकोष में अपार धन का संचय प्रारम्भ हो गया था। इस धन का उपयोग राजा लोग अपनी शक्ति को बढ़ाने में कर सकते थे। अब उन्हें यह आवश्यकता नहीं रही थी, कि वे अपनी शक्ति के लिये सामन्तों व अमीर उमराओं पर आश्रित हों। वे अपने धन के बल पर स्वयं भूत (वेतन प्राप्त कर के काम करनेवाली) सेना का निर्माण कर सकते थे और उसका उपयोग देश में शान्ति स्थापित रखने तथा अपने राज्य का विस्तार करने के लिये कर सकते थे। सामन्त पद्धति के ह्रास और केन्द्रीय सरकार की शक्ति की वृद्धि में इस स्थिति से बहुत सहायता मिली। मध्यश्रेणी के जिन लोगों की समृद्धि और शक्ति व्यापारिक क्रान्ति द्वारा बढ़ रही थी, वह सामन्तों और अमीर उमराओं की स्थिति के प्रबल विरोधी थे। उन्होंने सामन्तों को वशवर्ती करने में राजाओं की सहायता की। और जब इस मध्यश्रेणी ने अनुभव किया, कि राजाओं का शासन निरकुश और स्वेच्छाचारी है, तब वह उन के भी विरुद्ध उठ खड़ी हुई। इसी बात ने राज्य-

राजतियों को जन्म दिया। मध्य-यूरोप की शक्ति का प्रादुर्भाव व्यापारिक शक्ति का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण परिणाम था। मुविस्नन सामुद्रिक व्यापार के कारण व्यापारियाँ, समुद्र व्यवसायियाँ, महानगरों आदि की जा नहीं एक श्रेणि इस समय यूरोप में उत्पन्न हुई थी, उमने पहले राजाओं का राज्य देश सामन्तों व जागीरदारों की शक्ति का अन्त किया और फिर राजाओं की शक्ति का नियन्त्रित करने के लिये वे राजसत्ता की स्थापना के लिये व लोकसत्तात्मक शासन का कार्य करने के लिये राजराजतियों का स्थापन किया।

**आधुनिक युग के चिह्न**—यूरोप के इतिहास में हम जिसे आधुनिक युग कहते हैं, उस के स्थापन में व्यापारिक शक्ति बहुत अधिक सहायक सिद्ध हुई। इस नये युग के चिह्न निम्नलिखित हैं—(१) व्यावसायिक शक्ति—जिसके कारण यूरोप के आर्थिक जीवन में महान परिवर्तन हो रहा था, (२) राजराजतियों—जिसके कारण यूरोप का राजनीतिक जीवन एक नया स्वरूप ग्रहण कर रहा था, और (३) राष्ट्रीयता की भावना, जो लोकसत्तात्मक शासन का स्वाभाविक परिणाम थी। लोकसत्तावाद के प्रारम्भ से पहले भी व्यापारिक शक्ति के कारण जब अन्य देश अपने को अधिक में अधिक समृद्ध बनाने के लिये प्रयत्नशील था, तब यह भावना प्रादुर्भूत होने लगी थी, कि विविध राज्य अपना पृथक् व्यक्तित्व रखते हैं, और उनकी उन्नति में उन राज्य के नव निवासियों की भी उन्नति है। राष्ट्रीय भावना के विकास में यह विचार अत्यन्त महत्व था, इसमें कोई सन्देह नहीं।



तीसरा अध्याय

## अठारहवीं सदी के अन्त में यूरोप की दशा

### १ विविध राज्य

हमने यूरोप के इस आधुनिक इतिहास का प्रारम्भ फ्रांस की राज्यशान्ति (१७८९) से किया है। इसमें पहले का इतिहास भी हमने पिछले दो अध्यायों में संक्षेप के साथ दे दिया है। इसमें मन्देह नहीं, कि इसमें यूरोप के आधुनिक इतिहास को समझने में सहायता मिलेगी। पर अब यह आवश्यक है, कि अठारहवीं सदी के अन्तिम भाग में यूरोप के विविध राज्यों की जो दशा थी, उसका संक्षिप्त रूप में चित्रण कराया जाय। १७८९ में यूरोप का नक्शा वर्तमान यूरोप के नक्शे में बहुत भिन्न था। उस समय यूरोप के प्रमुख राज्य निम्नलिखित थे।

(१) फ्रांस—अठारहवीं सदी में यूरोप का सबसे अधिक शक्तिशाली व समृद्ध राज्य फ्रांस था। उसके उत्कर्ष का प्रधान श्रेय तेरहवें लुई (१६१०-१६४३) के प्रधान मंत्री रिशिल्यू को है, जिसने कि सामन्तों की शक्ति को नष्ट कर राज्य की केन्द्रीय सरकार की शक्ति को बढ़ाने के लिए विशेषरूप से प्रयत्न किया था। रिशिल्यू के उद्योग का यह परिणाम था, कि फ्रांस में सामन्तों और जागीरदारों के किलों का भूमिमात् कर दिया गया था और वे अपने-अपने प्रदेशों में स्वतन्त्र शासकों के तौर पर रहने के बजाय राजा के दरबार में दरबारी के रूप में निवास करने में अधिक गौरव अनुभव करने लगे थे। चौदहवें लुई (१६४३-१७१५) के समय में फ्रांस के राजा की शक्ति और गौरव में और भी अधिक वृद्धि हुई। बर्माय में स्थित उसका राजप्रासाद और राजदरबार यूरोप के विविध राजाओं के लिये आदर्श के समान थे। उसके समय में फ्रांस की आन्तरिक समस्याओं का पूर्णरूप में अन्त हो गया था और सारे देश में शान्ति तथा व्यवस्था स्थापित हो गई थी। चौदहवां लुई राजा के देवी अधिकार के सिद्धांत में विश्वास रखता था और अभिमान के साथ कहा करता था—“राज्य क्या है, मैं ही तो राज्य हूँ।” वह निरंकुश और स्ववेच्छाचारी रूप में अपने राज्य का शासन करता था और कानून बनाने, टैक्सों की दर निर्धारित करने व अन्य राज्यकार्य के लिये लिये किसी पार्लियामेंट की आवश्यकता को स्वीकार नहीं करता था। उसने राज्य-विस्तार के लिये भी बहुत प्रयत्न किया। उसका विचार था, कि फ्रांस की स्वाभाविक सीमा उत्तरपूर्व में रूहाइन नदी और दक्षिण पूर्व में जाल्पिन की पर्वतमाला है। बेल्जियम पर भी वह अपना अधिकार स्थापित करने के लिये उत्सुक था। यह देश उस समय स्पेन के अधीन था। लुई ने स्पेन के राजा चार्ल्स द्वितीय (१६६५-१७००) के साथ लड़ाई की घोषणा कर दी और बेल्जियम के अनेक

प्रदेशों पर जाना फ़र्ज़ा कायम कर लिया। चौदहवें लुई की महत्वाकांक्षाओं के कारण यूरोप में जो अनेक युद्ध हुए, उनका यही उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। इतना निर्देश कर देना पर्याप्त होगा, कि उसके समय में फ्रांस की अमाधारण उन्नति हुई और फ्रांस यूरोप की प्रधान राजनीतिक और सैनिक शक्ति बन गया।

चौदहवें लुई के बाद उसका प्रपौत्र पन्द्रहवें लुई (१७१५-१७७४) के नाम में फ्रांस की राजगद्दी पर आसूट हुआ। राजा के पद पर अभिषिक्त होने के समय उसकी आयु केवल पाच वर्ष की थी, वह स्वयं राज्यकार्य को नहीं सभाल सकता था। उसका पावन-पोषण भोग-विलास और जहङ्गार के बानावरण में हुआ। दरबार में अमीर उमरावों की बन आई और राज्यकोष का धन पानी की तरह बहाया जाने लगा। राजा को जब भी दबी माना जाता था, उसके स्वैच्छाचार पर किसी भी प्रकार का अकुश नहीं था। पर शासन की क्षमता में अब क्षीणता आ गई थी। पन्द्रहवें लुई का काल फ्रेंच राजसत्ता की शक्ति के ह्रास का समय था। इसी समय में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध (१७५६-१७६३) लड़ा गया, जिसमें मुख्यतया फ्रांस और इङ्ग्लैण्ड साम्राज्य-विस्तार के क्षेत्र में एक दूसरे के साथ संघर्ष में लगे थे। भारत में क्लाइव और डुर्गे का सङ्घर्ष इसी समय हुआ और उत्तरी अमेरिका में जो बहुत से उपनिवेश फ्रेंच लोगों ने बनाये थे, वे इसी युद्ध के परिणामस्वरूप फ्रांस के हाथ से निकलकर ब्रिटेन के हाथ में चले गये। सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। साम्राज्य विस्तार के क्षेत्र में वह इङ्ग्लैण्ड में बुरी तरह पराजित हुआ और उसका राज्यकोष इस युद्ध में बहुत कुछ खाली हो गया। पर यूरोप में फ्रांस की स्थिति अभी अच्छी मजबूत बनी रही और उसके राजाओं के वैभव तथा भोगविलास में कोई अन्तर नहीं आया।

१७७४ में फ्रांस की गद्दी पर सोलहवा लुई आसूट हुआ। राज्यक्रान्ति इसी के शासन-काल में हुई। इसके शासनकाल पर हम आगे अधिक विस्तार में विचार करेंगे।

(२) अस्ट्रिया—यूरोप में फ्रांस का प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी आस्ट्रिया था, जिसके राजा हाप्सबुर्ग राजवंश के थे। पवित्र रोमन सम्राट का गौरवपूर्ण पद इसी वंश के राजाओं में चला आता था। यद्यपि इस पद के कारण आस्ट्रिया के राजाओं की शक्ति में कोई वृद्धि नहीं होती थी, पर इसमें सन्देह नहीं कि इससे उनका गौरव और सम्मान बहुत अधिक था और वे पवित्र रोमन साम्राज्य के सम्पूर्ण क्षेत्र पर अपना एक प्रकार का प्रभुत्व अनुभव करते थे। आस्ट्रिया के हाप्सबुर्गवंशी राजाओं के अपने शासन में निम्नलिखित प्रदेश थे—(१) आस्ट्रिया, जिसकी राजधानी विएना थी, इसके निवासी जर्मन जाति के थे और जर्मनी के अन्य निवासियों से इनका कोई विशेष भेद नहीं था। (२) बोहेमिया और मोरेविया, इनके निवासी चेक जाति के थे। मध्यकाल में इनका अपना पृथक् स्वतन्त्र राज्य था, पर अब अठारहवीं सदी में ये हाप्सबुर्ग वंश के राजाओं के अधीन थे। (३) हंगरी, इसकी स्थिति एक पृथक् राज्य के समान थी, यद्यपि इसका राजा वही होता था, जो कि आस्ट्रिया का राजा हो। हंगरी के राज्य में केवल हंगेरियन और मग्यार लोगों का ही निवास नहीं था, अपितु रूमानियन, क्रोट और सर्व लोग भी उस में अच्छी बड़ी संख्या में निवास करते थे। (४) मिलान, इटली के उत्तरी

प्रदेश में आल्प्स की पर्वतमाला के दक्षिण में मिलान का राज्य था, जहाँ के निवासी इटालियन जाति के थे। आस्ट्रिया के हाप्सबुर्ग वंश के राजा इन के भी शासक थे।

(५) बेल्जियम, यह देश पहले (चार्ल्स द्वितीय के समय में) स्पेन के अधीन था, फ्रांस के चौदहवें लुई ने इसे अपने अधीन करने का प्रयत्न किया और बाद में उटरेख्ट की सन्धि (१७१३) द्वारा इस पर आस्ट्रिया का अधिकार हो गया। बेल्जियम के निवासी जाति की दृष्टि से फ्रेंच थे।

इस प्रकार आस्ट्रिया के हाप्सबुर्ग सम्राट बहुत से ऐसे प्रदेशों के राजा थे, जो राष्ट्रीय दृष्टि से आस्ट्रिया के स्वाभाविक अंग नहीं थे। आस्ट्रियन साम्राज्य-विस्तार की दृष्टि से बहुत विनाश था, पर विविध जातियों के लोगों से परिपूर्ण होने के कारण उनकी शक्ति सुदृढ़ नहीं थी। जब राष्ट्रीय भावना का यूरोप में विकास हुआ, तो आस्ट्रिया के लिये मिलान, बेल्जियम, बोहेमिया आदि की सत्ता बहुत अधिक हानिकारक सिद्ध हुई।

अठारहवीं सदी के यूरोपियन राजाओं में यह प्रवृत्ति थी, कि वे अपने राज्यों में एक केन्द्रीय सुदृढ़ शासन की स्थापना करें और अपनी प्रजा को एक सूत्र में संगठित करने का प्रयत्न करें। सम्राट जोसेफ द्वितीय (१७६५-१७९०) ने आस्ट्रियन साम्राज्य में भी इस नीति का अनुसरण किया। इसीलिये उसने अपने सब प्रदेशों में जर्मन भाषा का प्रचार करने का उद्योग किया। जर्मन को राजभाषा के पद पर अधिष्ठित किया गया और सर्वत्र शासन कार्य जर्मन में किया जाने लगा। साम्राज्य को तेरह प्रान्तों में विभक्त कर उन पर शासन करने के लिये सम्राट की ओर से सूवेदार नियत किये गये। इस नीति का परिणाम यह हुआ कि बेल्जियम, मिलान, बोहेमिया आदि में बहुत असन्तोष हुआ, वहाँ राष्ट्रीय भावना को बल मिला और कई स्थानों पर विद्रोह भी हुए।

इस प्रकार, अठारहवीं सदी के अन्तिम भाग में विनाश आस्ट्रियन साम्राज्य का संगठन बहुत गिरा था, उसकी विशालता ही उसकी सबसे बड़ी निर्बलता थी और इसी कारण आस्ट्रिया यूरोप की राजनीति में महत्वपूर्ण हिस्सा लेने में बहुत सफलता नहीं प्राप्त कर सकता था।

(३) जर्मनी—पवित्र रोमन साम्राज्य में जहाँ आस्ट्रिया सम्मिलित था, वहाँ साथ ही वे बहुत से राज्य भी अन्तर्गत थे, जिन्हें स्थूल रूप से जर्मनी कहा जाता था। अठारहवीं सदी में जर्मनी किसी एक राज्य का नाम नहीं था। उस समय जर्मनी में कुल मिलाकर ३६० के लगभग राज्य अन्तर्गत थे। इनमें कोई राजनीतिक एकता नहीं थी। इनमें एकता केवल एक बात की थी, वह यह कि ये सब वीएना के हाप्सबुर्गवंशी सम्राट (पवित्र रोमन सम्राट) की अधीनता स्वीकार करते थे, यद्यपि यह अधीनता केवल नाम मात्र की थी। जर्मनी के ३६० राज्यों में से बहुतों का शासन अमीर उमरावों के अधीन था, जो अपना पद व राज्य सम्राट से प्राप्त करते थे। कुछ राज्यों का शासन चर्च के उच्च अधिकारियों के हाथ में था, जो अपने-अपने क्षेत्र में स्वतन्त्र राजाओं के समान राज्य करते थे। जर्मनी के ३६० राज्यों में पचास ऐसे थे, जिनका क्षेत्र केवल किसी एक नगर तक सीमित था। इन नगर-राज्यों का शासन नगर-सभाएँ करती थी, जिनमें कतिपय बड़े भूमिपति व व्यापारी सम्मिलित होते थे। नगर-राज्यों को इस ढंग से अपना शासन

स्वयं करने का अधिकार भी पवित्र रोमन सम्राट में सीधा प्राप्त होता था। जर्मन राज्या में प्रशिया, वेस्ट्रिया, वरटमबर्ग, सैसमनी और हैनोवर ही ऐसे राज्य थे, जिन्हें महत्वपूर्ण कहा जा सकता था। इनमें भी प्रशिया ही शक्ति और महत्व सबसे अधिक था। वहाँ के राजा होहेन्टोलर्न वंश के थे और अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिये निरन्तर उद्योग कर रहे थे। प्रशिया के राजाओं में फ्रेडरिक दि ग्रेट (१७४०-१७८६) का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उसने अपने प्रयत्न में प्रशिया को एक अत्यन्त शक्तिशाली व समृद्ध राज बना दिया। उसकी सेना अत्यन्त सुसज्जित और प्रबल थी। उसका उपयोग कर फ्रेडरिक ने अपने राज्य का पूरा अच्छी तरह विस्तार किया। पवित्र रोमन साम्राज्य के अन्त होने के कारण प्रशिया हान्सबर्ग वंश के सम्राट पद को स्वीकृत करता था, पर इस कारण उसने आस्ट्रिया के साथ युद्ध करने में सकोच नहीं किया और फ्रेडरिक ने आस्ट्रिया के साथ अनेक लड़ाइयाँ लड़ीं। १७७२ में उसने पोलैण्ड में भी कुछ प्रदेशों को विजय कर लिया और इस प्रकार पोलैण्ड के अगभाग की उस प्रक्रिया का प्रारम्भ हुआ, जिस पर इस इतिहास में हम यथास्थान विचार करेंगे। फ्रेडरिक केवल विजेता ही नहीं था, अपितु साथ ही कुशल शासक और विद्वानों का आश्रयदाता भी था। अठारहवीं सदी के पुराने पियन राजाओं में उसका स्थान बहुत ऊँचा था।

बहुत से राज्यों में विभक्त होने के कारण अठारहवीं सदी में जर्मनी का राजनीतिक दृष्टि से अधिक महत्व नहीं था। जर्मनी के विविध राजा एक दूसरे में ईर्ष्या रखते थे। उनके लिये यह तो सम्भव ही नहीं था, कि वे परस्पर मिलकर कार्य करें। इसके विपरीत, वे प्रायः आपस में लड़ते भी रहते थे। पवित्र रोमन सम्राट की आज्ञा में रहना तो दूर रहा, वे उसके साथ मुकाबले में आने में भी सकोच नहीं करते थे। इस स्थिति का यह परिणाम था, कि जर्मनी में उस समय अव्यवस्था और अशांति छाई हुई थी। राष्ट्रीय एकता व देशभक्ति की भावना उस समय तक जर्मनी में विकसित नहीं हुई थी।

(४) इटली—जर्मनी के समान इटली भी अठारहवीं सदी में अनेक छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था। इनमें पीडमोंन्ट, टस्कनी, जिनोआ, वेनिस, सिसली, मोडेना, लोम्बार्डी और परमा मुख्य थे। इन विविध राज्यों में परस्पर एकता की कोई अनुभूति नहीं थी। इटली एक राष्ट्र है, यह विचार उस समय तक उत्पन्न नहीं हुआ था। इटालियन राज्यों की निर्बलता से लाभ उठाकर फ्रांस और आस्ट्रिया जैसे शक्तिशाली राज्यों उन पर अपना प्रभाव व आधिपत्य स्थापित करने में तत्पर थे। अनेक राज्यों में तो ऐसे राजवंश का शासन था, जो इटालियन लोगों के लिये विदेशी थे और जो फ्रांस, आस्ट्रिया व स्पेन की कूटनीतिक कारण वहाँ अपना प्रभुत्व स्थापित करने में समर्थ हुए थे। इटालियन राज्यों के ये विविध राजा निरकुश और स्वेच्छाचारी रूप से अपने-अपने क्षेत्र में शासन करते थे। यद्यपि कभी-कभी राजा शासन-सुधार और प्रजा की उन्नति के लिये प्रयत्नशील थे, पर कहीं भी शासन में जनता को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था।

(५) रूस—इसमें सन्देह नहीं, कि यूरोप के सब राज्यों में रूस सबसे अधिक विशाल था, उसकी जनसंख्या भी सबसे अधिक थी। अठारहवीं सदी से पूर्व ही रूस उत्तरी एशिया पर अपना आधिपत्य स्थापित कर चुका था और इस कारण उसका साम्राज्य बहुत

विशाल व विस्तीर्ण था। पर उन्नति की दृष्टि से वह पश्चिमी यूरोप के देशों के मुकाबले में बहुत पीछे था। पीटर दि ग्रेट (१६७२-१७२५) के समय में रूस पश्चिमी यूरोप के घनिष्ठ सम्पर्क में आया और वहाँ के लोगों ने उन्नति के मार्ग पर कदम बढ़ाना शुरू किया। पीटर के प्रयत्न से रूस का शासन सुसंगठित और शक्तिशाली बना तथा रूसी सेना यूरोप की अत्यन्त शक्तिशाली सेनाओं में गिनी जाने लगी। अठारहवीं सदी के अन्तिम भाग में रूस की राजगद्दी पर कैथरिन् द्वितीय विराजमान थी। वह एक जर्मन राजकुमारी थी और उसका विवाह रूस के सम्राट पीटर तृतीय के साथ हुआ था। बाद में उसने अपने पति को राज्यच्युत कर राजसिंहासन पर स्वयं अधिकार कर लिया और ३४ साल तक (१७६२-१७९६) बड़ी दृढ़ता के साथ रूस का शासन किया। कैथरिन् ने उस नीति को क्रिया में परिणत करने का विशेष रूप से प्रयत्न किया, जिसका प्रारम्भ पीटर दि ग्रेट ने किया था। रूस के शासन को सुसंगठित कर कैथरिन् ने राज्यविस्तार के लिये भी प्रयत्न किया। इस नीति से यूरोप के अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उथल-पुथल हुई, उसका उल्लेख हम अगले एक अध्याय में करेंगे। यहाँ इतना निर्देश कर देना ही पर्याप्त है, कि फ्रांस और आस्ट्रिया के समान रूस भी इस समय एक शक्तिशाली राज्य था और उसने यूरोप की राजनीति में निरन्तर अधिकाधिक भाग लेना शुरू कर दिया था।

(६) स्पेन—पन्द्रहवीं और सोलहवीं सदियों में स्पेन यूरोप का सबसे अधिक शक्तिशाली और वैभवपूर्ण राज्य था। अमेरिका में उपनिवेश विस्तार द्वारा उसकी समृद्धि बहुत अधिक बढ़ गई थी। सोलहवीं सदी में स्पेन के राजा यूरोप के अनेक प्रदेशों पर अपना आधिपत्य स्थापित करने में समर्थ हुए थे। फिलिप द्वितीय (१५५६-१५९८) स्पेन के अतिरिक्त मिलान, नीदरलैंड, सिसली और दक्षिणी इटली का भी अधिपति था, अमेरिकन उपनिवेश तो उसकी अधीनता में थे ही। पर स्पेन का यह उत्कर्ष देर तक कायम नहीं रह सका। १५८१ में नीदरलैंड उसकी अधीनता से मुक्त हो गया। कुछ समय बाद इंग्लैंड ने स्पेन के सामुद्रिक वेड़े को कड़ी चोट पहुँचाई। स्पेन और इंग्लैंड का यह संघर्ष इतिहास में 'स्पेनिश आर्मडा का युद्ध' के नाम से विख्यात है। फिलिप द्वितीय के समय में स्पेन की राजनीतिक शक्ति निर्बल होनी शुरू हो गई और वह निरन्तर अधिकाधिक निर्बल हो जाती गई। फिलिप के उत्तराधिकारी अपनी शक्ति को सभालने में असमर्थ रहे। अठारहवीं सदी में चार्ल्स तृतीय (१७५९-१७८८) और चार्ल्स चतुर्थ (१७८८-१८००) स्पेन के अच्छे कुशल और योग्य राजा थे। उन्होंने स्पेन की आन्तरिक समृद्धि की ओर विशेष ध्यान दिया। पर उनकी विदेशी नीति बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं थी। उन्होंने फ्रांस के साथ सन्धि करके एक गुट बनाया था, जिसे 'पारिवारिक गुट' कहते हैं, क्योंकि स्पेन का राजवंश पारिवारिक दृष्टि से फ्रांस के वूर्वों वंश के साथ सम्बद्ध था। जब १७८९ में फ्रांस में राज्यक्रान्ति हुई और कुछ समय बाद वूर्वों वंश के शासन का वहाँ अन्त हो गया, तो अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से स्पेन की स्थिति बहुत निर्बल हो गई। यही कारण है कि स्पेन के लोग फ्रेंच क्रान्तिकारियों से अपने देश की रक्षा करने में असमर्थ रहे।

(७) इंग्लैंड—यूरोप के विविध राज्यों में इंग्लैंड का स्थान बहुत महत्व का था। व्यापारिक क्रान्ति में उसने बहुत महत्वपूर्ण भाग लिया था, और वह न केवल

अमेरिका में अपने विविध उपनिवेश स्थापित करने में समर्थ हुआ था, अपितु भारत में भी अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिये प्रयत्नशील था। स्पन की सामुद्रिक शक्ति का परास्त कर नाविक दृष्टि में वह यूरोप की सबसे प्रबल शक्ति बन गया था। इङ्ग्लैण्ड के राजा भी निरंकुश और स्वैच्छाचारी थे। अठारहवीं सदी के पूर्वार्द्ध में स्टुअर्ट राजवंश के राजाओं के 'देवी अधिकार' के सिद्धान्त पर आश्रित शासन की समाप्ति कर वैध राजसत्ता की स्थापना का जो उद्योग उद्बलित लोगों ने किया था, अगले एक अर्धशताब्दी में उस पर हम अधिक विस्तार के साथ प्रकाश डालेंगे। पर वैध राजसत्ता की स्थापना का यह प्रयत्न अभी पूर्ण रूप में सफल नहीं हुआ था। अठारहवीं सदी के उत्तरार्द्ध में इङ्ग्लैण्ड का राजा जार्ज तृतीय (१७६०-१८२०) था। उसका यही प्रयत्न था, कि फ्रान्स, स्पेन, रूस आदि के राजाओं के समान वह निरंकुश व स्वैच्छाचारी रूप से शासन करे, पार्लियामेंट की उपेक्षा करे और लोकमन पर जरा भी ध्यान न दे। टोरी (कन्जर्वेटिव) पार्टी के नेता इस प्रयत्न में उसके सहायक थे। अमेरिकन उपनिवेशों में ब्रिटिश आधिपत्य के विरुद्ध जो विद्रोह हुआ, उसमें जार्ज तृतीय और उसके टोरी मन्त्री लार्ड नार्थ की नीति विचार रूप से कारण थी। इस युग के ब्रिटिश राजनीतिज्ञ और विचारक क्रान्तिकारी प्रवृत्तियों के विरोधी थे। यही कारण है, कि जब फ्रान्स में राज्यक्रान्ति हुई, तो उस का विरोध न केवल टोरी पार्टी ने किया, अपितु पिट, फॉक्स और बर्क मध्य द्विग (लिवरल) नेनाम ने भी उसके विरोध में आवाज उठाई। पर इसमें सन्देह नहीं, कि अठारहवीं सदी के इङ्ग्लैण्ड वैध राजसत्ता की ओर महत्त्वपूर्ण कदम उठा चुका था और इसलिये अनेक नव क्रान्तिकारी विचारकों के मत में इङ्ग्लिश शासनपद्धति बहुत उत्तम और अनुकरणीय थी।

(८) पोलैण्ड—सोलहवीं सदी तक पोलैण्ड यूरोप का एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य था। भाषा और नस्ल की दृष्टि से पोल लोग रूसी लोगों से बहुत कुछ भिन्न जुलते थे। पर पीटर द ग्रेट के नेतृत्व में सतरहवीं सदी में जब रूस उन्नति के मार्ग पर नज़ के साथ अग्रसर हो रहा था, तभी पोलैण्ड की अवस्था निरन्तर निर्वल और अव्यवस्थित होती जाती थी। वहाँ किसी एक शक्तिशाली केन्द्रीय शासन का विकास नहीं हो पाया, सामन्तों और जागीरदारों की शक्ति अक्षुण्ण बनी रही। नाम को तो पोलैण्ड में पार्लियामेंट विद्यमान थी और वहाँ राजा भी निर्वाचित हुआ करता था। पर वस्तुतः यह पार्लियामेंट बड़े-बड़े जागीरदारों की सत्ता थी, और कोई भी जागीरदार पार्लियामेंट के निर्णय का रद्द (वीटो) कर सकता था। इन जागीरदारों को केवल अपने स्वार्थ से मतलब था, देश की एकता व सार्वजनिक हित का विचार भी इनके सम्मुख कभी न आता था। किनता की दशा अर्द्ध-दासों के समान थी। इस दशा में यदि पोलैण्ड की राजशक्ति निरन्तर शीघ्र होती जाती, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात थी? पोलैण्ड की न कोई प्राकृतिक सीमाएँ थी, और न ही वहाँ के राजाओं ने एक प्रबल सेना के संगठन पर ध्यान दिया था। मध्य काल के राजाओं के समान अठारहवीं सदी में भी पोलैण्ड की सैनिक शक्ति सामन्तों और जागीरदारों की अपनी निज सेनाओं पर निर्भर करती थी और ये सामन्त एक सूत्र में संगठित होना जानते ही नहीं थे। इस दशा में यह स्वाभाविक था, कि पड़ोस के प्रबल राज्य पोलैण्ड को अपना शिकार समझे। रूस, आस्ट्रिया और प्रशिया की सीमाएँ पोलैण्ड न

लगती थी और ये तीनों राज्य इस बात के लिये उत्सुक थे, कि पोलैण्ड का अग-भग करके उसके प्रदेशों को अपने अधीन कर ले। १७७२ ई० में पोलैण्ड का पहला बंटवारा हुआ। इसके बाद १७९३ में दूसरी बार और १७९५ में तीसरी बार पोलैण्ड का अग भग किया गया। १७९५ में पोलैण्ड की एक पृथक राज्य के रूप में सत्ता नष्ट हो गई और उसके सब प्रदेश रूस, आस्ट्रिया और प्रशिया ने आपस में बांट लिये। पोलैण्ड के इस अग-भग के सम्बन्ध में इस इतिहास में आगे चलकर हम अधिक विस्तार से लिखेंगे।

(९) स्वीडन—अठारहवीं सदी के शुरू में स्वीडन एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य था। बाल्टिक सागर के पूर्व और दक्षिण के अनेक प्रदेश उसके अन्तर्गत थे और इस कारण बाल्टिक सागर की स्थिति एक स्वीडिश झील के समान थी। पर रूस और प्रशिया की बढ़ती हुई शक्ति के सम्मुख स्वीडन नहीं टिक सका। अठारहवीं सदी के अन्त तक बाल्टिक सागर के पूर्व और दक्षिण के सब प्रदेश उसके हाथ में से निकल गये और स्वीडन की शक्ति बहुत कुछ क्षीण हो गई।

स्वीडन का शासन एक वंशक्रमानुगत राजा के अधीन था। यद्यपि वहाँ पार्लियामेंट (रिक्सडाग) की सत्ता थी, पर शासन में उसका विशेष महत्व नहीं था। १७८९ में स्वीडन का राजा गुस्तवस तृतीय (१७७१-१७९२) था, जिसे शासन और मैन्य संचालन सम्बन्धी अपरिमित अधिकार प्राप्त थे।

(१०) डेनमार्क और नार्वे—अठारहवीं सदी के उत्तरार्द्ध में नार्वे और स्वीडन का शासन एक ही राजा के हाथ में था, यद्यपि नार्वे को डेनमार्क का अधीनस्थ राज्य समझा जाता था। इन दोनों देशों का शासक क्रिश्चियन सप्तम (१७६६-१८०८) था, जो अपने मन्त्रिमण्डल के सहयोग से राज्य की उन्नति और शासन-मुद्धार के लिये प्रयत्नशील था।

(११) हॉलैण्ड—नाम को तो हॉलैण्ड में रिपब्लिक विद्यमान थी, पर वस्तुतः उसका प्रधान शासक वंशक्रमानुगत होता था। अठारहवीं सदी के उत्तरार्द्ध में हॉलैण्ड का शासक विलियम पंचम (१७६६-१७९५) था, जो एक पार्लियामेंट के परामर्श के अनुसार शासन करता था। पर हॉलैण्ड में लोकतन्त्र शासन या वैध राज्यसत्ता निरन्तर असफल हो रही थी और सारी राजशक्ति विलियम पंचम के हाथों में केन्द्रित होनी जाती थी।

(१२) स्विट्जरलैण्ड—अठारहवीं सदी में यूरोप भर में स्विट्जरलैण्ड ही वस्तुतः ऐसा राज्य था, जहाँ सही अर्थों में रिपब्लिक विद्यमान थी। पर यह स्विस् रिपब्लिक भी लोकतन्त्र न होकर श्रेणितन्त्र थी और उसकी शासनशक्ति कतिपय सम्पन्न परिवारों के हाथों में थी। स्विट्जरलैण्ड में जर्मन, फ्रेंच और इटालियन—तीन भाषाओं को बोलनेवाले व तीन जातियों के लोगों का निवास था। स्विस् रिपब्लिक तेरह कैंटनों (राज्यों) की संघ थी और ये कैंटन क्रियात्मक दृष्टि से स्वतन्त्र राज्यों की स्थिति रखते थे। अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से स्विट्जरलैण्ड यूरोप में कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखता था और वहाँ के निवासी अपने पर्वत प्रधान प्रदेशों में स्वतन्त्रता का उपभोग करते हुए सुख और शान्ति के साथ जीवन व्यतीत करते थे।

अठारहवीं सदी के अन्तिम भाग में, १७८९ में, यूरोप के ये ही प्रमुख राज्य थे। इन्हें दृष्टि में रखने से यूरोप के आधुनिक इतिहास को समझने में अच्छी सहायता मिलेगी।

## २ शक्ति-समुत्तुलन का सिद्धांत

**यूरोप की एकता**—यूरोप के सब निवासी राष्ट्रीय दृष्टि से एक नहीं हैं। वहाँ अनेक भाषाएँ बोली जाती हैं, अनेक नस्लों के लोग वहाँ निवास करते हैं, उनकी रीति-रिवाज ऐतिहासिक परम्परा आदि भी एक-दूसरे से बहुत भिन्न हैं। पर इन सब विभिन्नताओं के होने हुए भी यूरोप के विविध राज्यों में एक प्रकार का सादृश्य और एक प्रकार की एकता है, जो यूरोप को एशिया, अफ्रीका आदि से पृथक् करती है। इस एकता का आधार निम्नलिखित है—

(१) यूरोप के सब देशों पर प्राचीन ग्रीक साहित्य, दर्शन और कला का प्रभाव है। सर्वत्र ग्रीक साहित्य का आदर्श के साथ अनुशीलन किया जाता है, और विविध देशों के विद्वान अपने साहित्यिक व दार्शनिक जीवन के लिये प्राचीन ग्रीक का आश्रय लेते हैं। जिस प्रकार प्राचीन सस्कृत साहित्य ने भारत के विविध प्रान्तों में एक प्रकार की सांस्कृतिक एकता स्थापित की हुई है, वैसे ही ग्रीक साहित्य द्वारा यूरोप के विविध राज्यों में एकता की सत्ता है। ग्रीक साहित्य के समान ही प्राचीन लैटिन साहित्य द्वारा भी यूरोप की एकता में सहायता प्राप्त होती है।

(२) किसी समय में यूरोप का बड़ा भाग रोमन साम्राज्य के अन्तर्गत था। रोमन शासकों का यह प्रयत्न था, कि वे अपने सारे साम्राज्य में एक रोमन कानून को प्रचलित करें। रोम की सस्थाओं, कानून और भाषा का असर अभी तक भी यूरोप से पूर्णतया मिटा नहीं है और इस के कारण यूरोप के विविध देशों में अनेक बातें एक सद्गति विकसित हुई हैं।

(३) यूरोप के प्रायः सभी निवासी ईसाई धर्म के अनुयायी हैं। मध्यकाल में जब ईसाई रोम के पोप को अपना धार्मिक गुरु मानने लगे और धार्मिक क्षेत्र में उम के अधिकार को स्वीकार करते थे। राजनीतिक दृष्टि से यूरोप अनेक राज्यों में विभक्त था, पर राम का धार्मिक साम्राज्य सर्वत्र विद्यमान था। फ्रांस में इटालियन पादरी और जर्मनी में फ्रेंच पादरी चर्च के ऊँचे पदों पर नियुक्त होते थे। चर्च की एकता ने मध्यकाल में यूरोप में इस ढंग की एकता उत्पन्न कर रखी थी, जिस के महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता। धार्मिक सुधारणा के कारण रोमन कैथोलिक चर्च का प्रभुत्व सारे यूरोप में कायम नहीं रहा, इंग्लैण्ड आदि कई देशों में राष्ट्रीय चर्चों की स्थापना हुई, पर फिर भी ईसाई धर्म के उस प्रभाव का सर्वथा लोप भी नहीं हुआ, जिसके कारण यूरोप के लोग परस्पर एकानुभूति रखते थे। धर्म की एकता मनुष्यों में एकानुभूति पैदा करती है, और धार्मिक सुधारणा के बाद भी यह अनुभूति पूर्णतया नष्ट नहीं हुई।

(४) मध्यकाल में जब पवित्र रोमन साम्राज्य अपने उत्कर्ष पर था, यूरोप का अच्छा बड़ा भाग राजनीतिक दृष्टि से भी एक शासन में था। इसमें सन्देह नहीं, कि पवित्र रोमन साम्राज्य के कारण यूरोप के बहुत से लोगों में एकता की भावना विद्यमान थी।

**राष्ट्रीय राज्यों का विकास**—मध्यकाल के यूरोपियन राज्यों की विशेषता उनकी सामन्तपद्धति थी। सोलहवीं सदी में सामन्त-पद्धति का ह्रास हुआ और इंग्लैण्ड, फ्रांस, स्पेन, रूस आदि राज्यों में शक्तिशाली केन्द्रीय शासन की स्थापना हुई। सामन्ता



के पारस्परिक युद्धों का अन्त होने से राज्यों में आन्तरिक व्यवस्था और शान्ति की भी स्थापना हुई। शक्तिशाली केन्द्रीय शासनो के विकास का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि फ्रांस, इङ्ग्लैण्ड आदि देशों में एक प्रकार की एकता की भावना उत्पन्न होने लगी। फ्रेंच राजा द्वारा शासित सब प्रदेश एक थे, उसके दरबार में एकत्र हुए सब अमीर उमरा एक भाषा बोलते थे, एक संस्कृति के रंग में रंगे हुए थे और अपने राजा के राज्य को एक देश समझते थे। इस दशा का परिणाम यह हुआ, कि धीरे-धीरे फ्रांस एक राष्ट्र बनने लगा और उस के निवासियों में राष्ट्रीयता की अनुभूति विकसित होने लगी। यही प्रक्रिया इङ्ग्लैण्ड, स्पेन, एशिया आदि में भी हुई। मध्यकाल की समाप्ति पर यूरोप में जो नये प्रकार के राज्य प्रकट होने लगे, उन्हें हम राष्ट्रीय राज्य (नेशन स्टेट) कह सकते हैं।

राष्ट्रीय-राज्यों के विकास का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ, कि यूरोप के विविध देशों में जो एकता की अनुभूति प्राचीन व मध्यकाल में विद्यमान थी, वह नष्ट होने लगी। फ्रांस, प्रशिया व इङ्ग्लैण्ड पृथक् राष्ट्र हैं, और उनकी सम्पूर्ण शक्ति अपने राष्ट्रीय उत्कर्ष में ही लगनी चाहिए, इस विचार ने राज्यों के परस्पर विरोध और विद्वेष को बहुत अधिक बढ़ा दिया। यूरोप में अन्तराष्ट्रीयता की भावना निर्बल होने लगी और वहाँ के लोग क्रिश्चियन धर्म पर आश्रित यूरोपियन संस्कृति की अपेक्षा अपने राष्ट्रीय गौरव और राष्ट्रीय उत्कर्ष को अधिक महत्व देने लगे।

**शक्ति समुत्तुलन का सिद्धान्त**—इस दशा में यह सर्वथा स्वाभाविक था, कि यूरोप के विविध राज्य केवल अपने हित का ध्यान रखें, अन्य सब राज्यों को पराया व अपना प्रतिस्पर्धी समझें और अपनी विदेश नीति का इस ढंग से संचालन करें, जिससे कि अपने राज्य का हित सम्पादित हो सके। इस स्थिति में उस सिद्धान्त का विकास हुआ, जिसे शक्ति-समुत्तुलन (बैलेन्स ऑफ पावर) कहते हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार यूरोप के विविध राज्यों का यह प्रयत्न रहता था, कि कोई एक राज्य यूरोप में इतना प्रबल व शक्तिशाली न हो जाय, कि अन्य राज्य उसके सम्मुख अपने को असहाय अनुभव करें। यदि किसी राज्य की शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाती थी, तो अन्य राज्य परस्पर सन्धि द्वारा उसके विरुद्ध एक गुट का निर्माण कर लेते थे और इस गुट में सम्मिलित राज्य शक्तिशाली राज्य से अपनी रक्षा करने का प्रयत्न करते थे। इस प्रकार, यूरोप में राजशक्ति का समुत्तुलन कायम रहता था और कोई राज्य इस स्थिति में नहीं होता था कि अन्य सबको अपना वशवर्ती बना सके।

सोलहवीं सदी में स्पेन बहुत अधिक शक्तिशाली था। परिणाम यह हुआ, कि फ्रांस और इङ्ग्लैण्ड के नेतृत्व में यूरोपियन राज्यों ने उसके विरुद्ध गुट का निर्माण किया। सत्रहवीं सदी में जब फ्रांस की शक्ति बढ़ने लगी, तो आस्ट्रिया, इङ्ग्लैण्ड आदि उसके विरुद्ध हो गये और इस कारण चौदहवां लुई जैसा शक्तिशाली राजा भी मनमानी कर सकने में असमर्थ रहा। अठारहवीं सदी में जब इङ्ग्लैण्ड की सामुद्रिकशक्ति असाधारण रूप से उन्नत हुई, तो फ्रांस के नेतृत्व में अनेक यूरोपियन राज्य उसके विरुद्ध संगठित हो गये, और फ्रांस की सहायता के कारण ही अमेरिकन उपनिवेश ब्रिटेन की अधीनता में मुक्त होने में समर्थ हुए। फ्रांस की राजशक्ति के परिणामस्वरूप जब नैपोलियन यूरोप में

बहुत प्रचल हो गया तो उस शक्ति-समनुलन के मिथ्यात्व के कारण ही बहुत से यूरोपियन राज्य उसने विघ्न सगठित हो गये और उन्होंने सम्मिलित रूप में नेपोलियन का मुकाबला किया।

अठारहवीं सदी के उत्तरार्द्ध में यूरोप में अन्तर्गोष्ठीय भावना का सर्वथा अभाव था। यराप की एकता सर्वथा लुप्त हो चुकी थी, राष्ट्रीय अनुभूति के कारण प्रत्येक राज्य अपने को पूर्णतया स्वतन्त्र व स्वच्छन्द समझता था। उस दशा में शक्ति-समनुलन का मिथ्यात्व ही उनके अन्तर्गोष्ठीय सम्बन्धों का निश्चित कर्ता था।

### ३ यूरोप की दशा

आधुनिक समय में यूरोप ने जिस प्रकार अमाधायण उत्पत्ति की है, उस बात को मनी-भाति समझने के लिये यह उपयोगी होगा, कि हम अठारहवीं सदी के अन्तिम भाग में, फ्रांस की राज्यक्रान्ति के शुरू होने के समय, यूरोप को क्या अवस्था थी, उनका भी मक्षेप के साथ प्रदर्शन कर दें। फ्रांस की राज्यक्रान्ति का उन्निहान लिखने हुए हमने उस विषय पर अधिक विस्तार से विचार किया है। जो दशा फ्रांस की थी, वही प्रायः अन्य राज्यों की भी थी। पर फिर भी यहाँ मक्षिप्त रूप में यूरोप के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक जीवन का उल्लेख करना उपयोगी होगा।

**सामाजिक जीवन—**१७८९ में यूरोप का समाज अनेक श्रेणियों में विभक्त था। ये श्रेणियाँ निम्नलिखित थी, कुलीन, पादरी, किसान (स्वतन्त्र और अर्द्धदास), मध्यश्रेणि और मजदूर। विविध श्रेणियों के मनुष्यों में केवल जमीर और गरीब का ही भेद नहीं था, अपितु उनके अधिकार स्थिति आदि में भी भेद था। कुलीन श्रेणि के लोग समाज में सर्वोच्च स्थान रखते थे, उनकी स्थिति केवल राजा व राजपरिवार के व्यक्तियों से निचले दर्जे की थी। यूरोप की सब जमीन जागीरदारों में विभक्त थी और इन जागीरों के स्वामी कुलीन श्रेणि के लोग समाज में बहुत ऊँचा व प्रतिष्ठित स्थान रखते थे। ये जागीरदार मध्यकाल के सामन्तों के उत्तराधिकारी थे। इनकी राजनीतिक व सैनिक-शक्ति नष्ट हो गई थी, पर इनकी सामाजिक स्थिति अब भी कायम थी। ये बड़ी शान-शौकत के साथ अपनी जागीरों में निवास करते थे और वहाँ इनके बड़े-बड़े प्रासाद, जो प्रायः किले के रूप में होते थे, अब तक विद्यमान थे। इन्हें अनेक ऐसे विशेषाधिकार प्राप्त थे, जो सर्वसाधारण जनता को प्राप्त नहीं थे। कानून की दृष्टि में इनकी स्थिति साधारण जनता की अपेक्षा ऊँची थी।

व्यापारिक क्रान्ति के कारण यूरोप में सर्वत्र मध्यश्रेणि का महत्व बढ़ रहा था। इङ्ग्लैण्ड में मध्यश्रेणि का निर्माण निम्नलिखित लोगों द्वारा हुआ था—(१) कुलीन परिवारों के कनिष्ठ पुत्र—जागीर का स्वामी जागीरदार का बड़ा लड़का होता था, अतः उसके कनिष्ठ पुत्र व्यापार, राजकीय सेवा व वकालत आदि पेशों का अनुसरण करते थे। (२) देहात के छोटे जागीरदार, जिनकी स्थिति बड़े कुलीन जागीरदारों और किसानों के बीच की होती थी,। (३) व्यापारी वर्ग, व्यावसायिक क्रान्ति के कारण बहुत से साहसी व अध्यवसायी लोग व्यापार में लगकर अच्छा धन कमाने लगे थे। धनी हो जाने

पर भी इन्हे कुलीन श्रेणि की स्थिति प्राप्त नहीं हुई थी। फ्रांस, स्पेन आदि में भी इसी ढंग की मध्यश्रेणि का विकास हो रहा था। यह श्रेणी शिक्षित थी, सम्पन्न थी और साथ ही अध्यवसायी भी। पर सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में इसकी स्थिति सम्मानित नहीं थी। क्रान्तिकारी प्रवृत्तियों के प्रसार में यह बात एक महत्वपूर्ण कारण बनी।

पादरी लोग दो प्रकार के थे, उच्च स्थिति के पादरी और साधारण भिक्षु। इस युग में चर्च के पास अपार सम्पत्ति थी और उनके बड़े अधिकारी कार्डिनल, आर्कबिशप, बिशप और एबट बड़े कुलीन जागीरदारों के समान जीवन व्यतीत करते थे। बड़े-बड़े ईसाई मठ सर्वत्र विद्यमान थे और इनके महन्तों का जीवन बड़ी शान-शोकत व विलास में व्यतीत होता था। छोटे पादरी, जो प्रायः भिक्षुओं का जीवन बिताते थे, स्थिति में महन्तों से बहुत हीन थे। उनकी स्थिति मध्यश्रेणि व उममें भी निम्नश्रेणि के लोगों के समान थी। वे प्रायः शिक्षित होते थे और यही कारण है, कि क्रान्ति की भावना उन्हें भी प्रभावित कर रही थी। वे बड़े पादरी व महन्तों के भोगमय जीवन से ईर्ष्या और अपनी दशा से असन्तोष अनुभव करते थे। यही कारण है, कि राज्यक्रान्ति के युग में उनकी सहानुभूति क्रान्तिकारियों के साथ थी।

मजदूर श्रेणि के लोग शिन्पी व कारीगर थे। बड़े कारखानों का विकास इस समय तक नहीं हुआ था। कारीगर लोग अपने मकान पर रहकर तैयार माल का उत्पादन करते थे और स्वयं ही उसे बाजार में बेचते थे। बूढ़े, लहार, जुलाहा, दर्जी, मोची, नाई, जिल्द-साज, छीपी आदि के सब शिल्प इन कारीगरों द्वारा संचालित होते थे, और प्रत्येक शिल्प के कारीगर पृथक्-पृथक् अपनी श्रेणियों (गिल्ड) में संगठित थे। इन श्रेणियों के सम्बन्ध में इसी अध्याय में हम अधिक विस्तार के साथ लिखेंगे। शिल्पी लोग आर्थिक दृष्टि से समृद्ध नहीं थे, उनकी स्थिति मध्यश्रेणि की अपेक्षा हीन थी।

जनता का सबसे बड़ा भाग किसानों का था। इस समय में यूरोप के सभी देश कृषि-प्रधान थे। इंग्लैंड में किसानों की संख्या ८० प्रतिशत और फ्रांस में ९० प्रतिशत थी। अन्य देशों में तो किसान और भी अधिक संख्या में थे। ये किसान दो प्रकार के थे, स्वतन्त्र और अर्द्धदास (सर्फ)। स्वतन्त्र किसानों की अपेक्षा अर्द्धदासों भी संख्या बहुत अधिक थी। जागीरदार लोगों की जमीन पर किसान लोग खेती करते थे, और अपनी जमीन व सत्ता के लिये जमींदार पर निर्भर रहते थे। देहात में जागीरदारों के किलेनुमा बड़े-बड़े राजप्रासाद थे, जिनके पड़ोस में ये किसान लोग कच्चे व छोटे-छोटे झोपड़ों में निवास करते थे। जिन मकानों में ये किसान रहते थे, उन्हीं में उनके पशु भी बांधे जाते थे। जमींदार जब चाहे, किसानों (स्वतन्त्र किसानों) को बेदखल कर सकता था। अर्द्धदास जमींदार की जमीन को बिना किसी उजरत के जातते अपने पारिश्रमिक के रूप में उन्हें कुछ जमीन दे दी जाती थी, जिसकी पैदावार का वे स्वयं उपभोग कर सकते थे। उन्हें अनेक प्रकार से जमींदार की बेगार भी करनी पड़ती थी। किसान प्रायः अशिक्षित होते थे। संसार के समाचारों व प्रगति में सर्वथा अपरिचित रहते हुए अपनी दुर्दशा को अपना भाग्य समझकर सतोष अनुभव करते थे। जमींदार के प्रति उन्हें एक विशेष प्रकार का अनुराग था, उसे वे अपना स्वामी, अन्नदाता व भाग्यविधाता समझते थे। अपनी स्थिति

मे अन्तोप व शान्ति की भावना का उनमें प्रायः अभाव था। यही कारण है, कि शान्ति के युग में उन्होंने बहुत अपने जमींदारों का साथ दिया।

आर्थिक जीवन—अठारहवीं सदी में यूरोप में बड़े व समृद्ध नगरों का विकास नहीं हुआ था। उस युग में यूरोप का सबसे बड़ा नगर पेरिस था, जिसकी जनसंख्या ३ लाख के लगभग थी। यूरोप का दूसरा बड़ा नगर लण्डन था, जिसकी जनसंख्या पाँच लाख से कुछ कम थी। व्यापारिक शान्ति के कारण लण्डन ग्रेट ब्रिटेन के आर्थिक जीवन का केन्द्र बन गया था, इसीलिये उसकी आबादी उतनी ज़रूरी थी। ब्रिटेन में उस समय केवल १५ ऐसे नगर थे, जिनकी जनसंख्या बीस हजार से ज्यादा थी। वहाँ ८६ नगर ऐसे थे, जिनकी आबादी पाँच हजार और बीस हजार के बीच में थी। अन्य सब कस्बे व गाँव ५००० से भी कम जनसंख्या वाले थे। बर्लिन, वीणा आदि यूरोपियन नगरों की जनसंख्या अठारहवीं सदी के उत्तरार्द्ध में दो लाख के लगभग थी। शहरों की सड़कें प्रायः कच्ची थीं। पानी निकालने का समुचित प्रबंध नहीं था। यही कारण है, कि अठारहवीं सदी के अन्त तक वर्षा के समय लण्डन, पेरिस और बर्लिन जैसे नगरों में घुटना तक पानी एकत्र हो जाता था। राजपथों पर सवारी गाड़ियों और पैदल चलनेवालों के लिये पृथक् व्यवस्था नहीं थी। सड़कें प्रायः तंग होती थीं और दोनों ओर की इमारतों के कारण उनमें दिन के समय भी रोशनी का अभाव रहता था। रात के समय सड़कों को प्रकाशित करने का समुचित व्यवस्था नहीं थी और गलियों व सड़कों की सफाई का प्रबंध करने के लिये किसी संगठन का भी अभाव था। प्रायः सब नगरों के चारों ओर जिल बन्दी व ऊँची दीवारें थीं, जिनके कारण लोग छोटे से क्षेत्र में भिचकर निवास करते थे।

शहरों की आबादी का बड़ा भाग शिल्पियों व कारीगरों का होता था। अठारहवीं सदी के मध्यभाग तक न यान्त्रिक आविष्कार हुए थे और न व्यावसायिक शान्ति का सूत्रपात हुआ था। कारीगर लोग अपने मकानों पर पुराने किस्म के ओजारों में काम करते थे। सब प्रकार के शिल्पी श्रेणियों (गिल्ड) में संगठित थे। बडई, लोहार, जुन्न दर्जी, नाई—सबकी अपनी-अपनी 'श्रेणियाँ' होती थीं। प्रत्येक कारखाने में एक आचार्य (मास्टर व उस्ताद) और उसके साथ कतिपय अन्तेवासी (शागिर्द) होते थे। ये अन्तेवासी आचार्य के घर में पुत्र के समान निवास करते हुए उसने शिल्प की शिक्षा ग्रहण कर लेते थे और आर्थिक उन्नति में आचार्य की सहायता करते थे। एक किस्म के शिल्प के सब आचार्य मिलकर अपनी 'श्रेणि' (गिल्ड) संगठित करते थे और इस श्रेणि के नियमों का पालन करते थे। श्रेणि द्वारा यह निश्चय किया जाता था कि अन्तेवासी को किन शर्तों पर रखा जाय, वह कितने सालों तक शागिर्दी करे और फिर किन शर्तों पर वह अपना पृथक् कारखाना खोल सके। बहुधा, श्रेणि द्वारा यह भी निश्चय होता था कि माल को किस कीमत पर बेचा जाय व उसे तैयार करने के लिये किस सामग्री का उपयोग किया जाय। श्रेणि में सम्मिलित आचार्य व अन्तेवासी केवल वही माल तैयार कर सकते थे, जिसका अनुमति वह श्रेणि से प्राप्त कर लेते थे। सुनार साहूकार का काम नहीं कर सकते थे और लोहार हथियार नहीं बना सकते थे, क्योंकि विविध प्रकार के हथियार बनानेवाले शिल्पियों की अपनी पृथक् श्रेणियाँ होती थीं। इन श्रेणियों (गिल्ड) के कारण माल बढ़िया बनता

था और विविध कारीगर कीमत के मामले में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे। श्रेणियों के नियमों व कानूनों को राज्य भी स्वीकार करता था।

व्यापारिक क्रान्ति के कारण श्रेणियों के संगठन में कुछ ढिलाई आने लगी थी। विदेशी व्यापार के लिये जिस माल की आवश्यकता थी, नये पूंजीपति व्यापारी उसे बड़े परिमाण में तैयार कराने के लिये उत्सुक रहते थे। अतः कतिपय पूंजीपतियों ने शिल्पियों को अपनी नौकरी में रखकर बड़े पैमाने पर माल तैयार कराने की कोशिश प्रारम्भ कर दी थी। यान्त्रिक शक्ति से चलनेवाले कारखानों की स्थापना से पहले ऐसे कारखाने कायम होने शुरू हो गये थे, जिनमें सैकड़ों की संख्या में कारीगर लोग एक छत के नीचे बैठकर निश्चित वेतन के बदले में मजदूरी करते थे। इसी बीच में वैज्ञानिक आविष्कारों यूरोप के आर्थिक जीवन में भारी परिवर्तन लाना प्रारम्भ कर दिया। यान्त्रिक शक्ति के आविष्कार के कारण पूंजीपतियों द्वारा संचालित कारखानों के मुकाबले में पुराने ढंग की 'श्रेणियों' के लिये अपनी सत्ता को कायम रख सकना सम्भव नहीं रहा। इसी का परिणाम यह व्यावसायिक क्रान्ति थी, जिसने यूरोप के आर्थिक जीवन को एकदम परिवर्तित कर दिया था। इस व्यावसायिक क्रान्ति पर हम अगले एक अध्याय में विस्तार में विचार करेंगे।

**धार्मिक जीवन—**अठारहवीं सदी में यूरोप में तीन धर्म विद्यमान थे, ईसाई, यहूदी और इस्लाम। मुसलमानों का क्षेत्र तुर्क साम्राज्य तक सीमित था। यूरोप के दक्षिण-पूर्वी कोने में तुर्कों का सुविस्तृत साम्राज्य था, जिसमें बालकन प्रायद्वीप का बड़ा भाग अन्तर्गत था। तुर्क लोग इस्लाम के अनुयायी थे। यहूदी लोगों का पृथक दश कोई नहीं था, वे प्रायः सम्पूर्ण यूरोप में फैले हुए थे। उनका निवास प्रायः बड़े नगरों में था, जहाँ साहूकारों और व्यापार द्वारा वे अपना निर्वाह करते थे। ईसाई लोग यहूदियों में घृणा करते थे और उनके निवास के लिये शहरों में पृथक स्थान सुरक्षित रखे जाते थे। उनके अधिकार भी नियन्त्रित होते थे और उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार व्यवसाय आदि का अनुसरण करने की स्वतन्त्रता नहीं होती थी।

पर यूरोप के निवासियों का प्रधान धर्म ईसाईयत था। अठारहवीं सदी में ईसाइयों के प्रमुख सम्प्रदाय तीन थे—(१) रोमन कैथोलिक (२) ग्रीक आर्थोडोक्स और (३) प्रोटेस्टेन्ट। इटली, स्पेन, फ्रांस, पोर्तुगाल, आयरलैण्ड, आस्ट्रिया, पोलैण्ड और बेल्जियम में प्रधानतया रोमन कैथोलिक धर्म का प्रचार था। रूस और पूर्वी यूरोप के देशों के निवासी ग्रीक आर्थोडोक्स चर्च के अनुयायी थे। इंग्लैण्ड, जर्मनी और उत्तरी यूरोप के विभिन्न देश प्रोटेस्टेन्ट सम्प्रदाय का अनुसरण करते थे। धार्मिक सुधारणा के कारण किस प्रकारांनेक देशों में रोमन कैथोलिक चर्च के विरुद्ध विद्रोह हुआ और वहाँ राष्ट्रीय चर्चों की स्थापना हुई, इसका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। राष्ट्रीय भावना और नये विचारों के प्रसार के कारण चर्च का प्रभाव अब कम होने लगा था। पर यूरोप में अभी साम्प्रदायिक स्कीर्णता और धार्मिक विद्वेष में विशेष न्यूनता नहीं आई थी। रोमन कैथोलिक देशों में जनता को धर्म के मामले में स्वतन्त्रता अभी प्राप्त नहीं हुई थी। अन्य सम्प्रदायों के लोगों को यह अधिकार नहीं था, कि वे अपने विचारों व विश्वासों के अनुसार धार्मिक अनुष्ठानों को स्वतन्त्रता के साथ कर सकें। आशिक रूप में यही बात प्रोटेस्टेन्ट देशों के सम्बन्ध

मे भी नहीं जा सकती है। इङ्ग्लैण्ड में उन सम्प्रदायों के अनुयायियों पर अनेक प्रकार के अत्याचार किये जाते थे, जो इङ्गलिश चर्च को नहीं मानते थे। रोमन कैथोलिक लोगों का अठारहवीं सदी के अन्त तक भी इङ्ग्लैण्ड में राजकीय पदों पर नियत नहीं किया जा सकता था और न ही उन्हें यह अनुमति थी, कि वे अपने धार्मिक अनुष्ठानों को सार्वजनिक रूप में कर सकें। ग्रीक आर्थोडॉक्स चर्च का संगठन रोमन कैथोलिक चर्च से बहुत कुछ मिलता-जुलता था। पर रोम के पोप के समान उसका कोई एक प्रधान अधिकारी नहीं था। एक पोप की बजाय उसके अनेक पेट्रियार्क होते थे।

सांस्कृतिक जीवन--अठारहवीं सदी में यूरोप में शिक्षणालयों व यूनिवर्सिटियों की कमी नहीं थी। प्रायः सभी देशों में अच्छे-बुरे विद्यापीठ विद्यमान थे। पर ये शिक्षा-संस्थाएँ प्रायः चर्च के अधीन थीं। रोमन कैथोलिक देशों में तो शिक्षापद्धति का मंचालन ही चर्च द्वारा होता था। प्रोटेस्टेन्ट देशों में भी शिक्षणालयों पर चर्च का बहुत प्रभाव था। इस स्थिति में यह सम्भव नहीं था, कि शिक्षणालय बुद्धिस्वातन्त्र्य व स्वतन्त्र विचार के फेद बन सकें। अठारहवीं सदी के बहुसंख्यक शिक्षणालयों का चानावरण मसीही और मनुजित होता था। उनमें केवल कुलीनों व धनियों की मतान ही शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। सर्व-साधारण जनता को पढ़ने-लिखने का न कोई अवसर था और न वह इसकी आवश्यकता ही अनुभव करती थी। यही कारण है, कि उस समय तक यूरोप में शिक्षित लोगों की संख्या बहुत कम थी। शिक्षणालयों की पाठविधि में धर्म, लैटिन ग्रीक आदि का महत्व अधिक था। जिसे आजकल विज्ञान कहा जाता है, उसका उस समय के विद्वानों को न विशेष परिचय था और न ही उसके महत्व को वे स्वीकार करते थे।

चर्च द्वारा संचालित व नियन्त्रित विद्यापीठों में विज्ञान के प्रति उद्योग के वाक्पद भी यूरोप के विचारकों का ध्यान विज्ञान की ओर आकृष्ट होने लगा था। तेरहवीं सदी में रोजर बेकन नामक विद्वान ने सत्य की खोज के लिये तीन साधनों का प्रतिपादन किया था, सही तौर पर निरीक्षण, परीक्षण, और वैज्ञानिक उपकरण। बेकन का कहना था, कि किसी पदार्थ या मिद्धान्त के ठीक-ठीक स्वरूप को समझने के लिये शास्त्रीय प्रमाणों पर आश्रित न रहकर निरीक्षण, परीक्षण और वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग करना चाहिये। उस युग के यूरोपियन विद्वानों ने बेकन के मत पर कोई ध्यान नहीं दिया, वे ख्रिश्चन शास्त्रों के आधार पर ही सत्य असत्य का निर्णय करते रहे। पर आज ससार के विद्वान सत्यनिर्णय के सम्बन्ध में रोजर बेकन की स्थापना को पूरी तरह अपना चुके हैं। सोलहवीं सदी के अन्त और सत्रहवीं सदी के प्रारम्भिक काल में फ्रांसिस बेकन (१५६१-१६२६) नाम का एक अन्य विद्वान इङ्ग्लैण्ड में हुआ, जिसने कि बुद्धिस्वातन्त्र्य पर बहुत जोर दिया। उसका कथन था, कि मनुष्य जब एक बार प्रमाणवाद और अन्वेषविश्वास के जाल से अपने को मुक्त कर लेगा, तो आश्चर्यजनक उन्नति का मार्ग उसके लिये खुल जायगा, वह ऐसे-ऐसे आविष्कारों को करने में समर्थ होगा, जिसकी अभी कल्पना भी नहीं की जा सकती।

चर्च के मन्तव्यों और विश्वासों की उपेक्षा कर अनेक विद्वान परीक्षण द्वारा सत्य की खोज में तत्पर होने शुरू हो गये थे। ऐसे कतिपय विद्वानों का उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। वैज्ञानिक तथ्यों के आविष्कार से यूरोप के लोगों के हाथ में ऐसे साधन आने प्रारम्भ

हो गये, जिनसे वे प्रकृति पर विजय स्थापित करने में समर्थ हुए । व्यावसायिक क्रान्ति और नवयुग के सूत्रपात में इसमें असाधारण सहायता मिली ।

हमने इस अध्याय में अठारहवीं सदी के अन्तिम भाग के यूरोप का संक्षेप से निदर्शन किया है । आगे के अध्याय में हम यूरोप के आधुनिक इतिहास को नियमित रूप में प्रारम्भ करेंगे । अब तक हमने केवल उन बातों का उल्लेख किया है, जिनको जानना यूरोप के आधुनिक इतिहास को समझने के लिये अनिवार्य है । अन्य अनेक बातें जो इस दृष्टि से उपयोगी हैं, वे हमने जान-बूझकर नहीं लिखी हैं । उन्हें इस इतिहास के विविध अध्यायों में विषय को स्पष्ट करते हुए दिया गया है, क्योंकि हमारी दृष्टि में उन्हें वहाँ लिखना पाठकों के लिये अधिक उपयोगी होगा ।

चौथा अध्याय

## फ्रान्स में राज्यक्रान्ति का प्रारम्भ

### १ राज्यक्रान्ति से पूर्व फ्रान्स की दशा

एकतन्त्र राजा—राज्यक्रान्ति से पूर्व फ्रान्स में स्वेच्छाचारी एकतन्त्र राजा राज्य करते थे। ये राजा वंशवर्मानुगत होते थे और अपने को ईश्वर के मित्रा किमी अन्य के सम्मुख उत्तरदायी न समझते थे। इनकी इच्छा ही कानून थी। ये जिसे चाहते, राजकीय पद पर नियत करते, जिसे चाहते पद-च्युत करते। राजा अपनी इच्छा से जनता पर कर लगाता था और राजकीय आमदनी को अपनी इच्छानुसार ही खर्च करता था। मन्त्रि और विग्रह का अधिकार केवल राजा को था। वह अपनी इच्छा से प्रजा से किमी भी प्रकार की सलाह बिना लिये, किमी राजा व देश से लडाईं शुरू कर सकता था। वह जिसे चाहे बंद कर सकता था, जिसे चाहे सजा दे सकता था। लुई १६वां अभिमान में कहा करता था —“यह कानून है, क्योंकि मेरी ऐसी ही इच्छा है। राज्य की प्रभुत्व शक्ति मुझ में निहित है। कानून बनाने का हक केवल मुझे है, इसके लिये मुझे किमी पर आश्रित रहने व किमी का सहयोग लेने की आवश्यकता नहीं।” फ्रान्स के राजाओं का शासन-सम्बन्धी मूल सिद्धांत यह था, कि राजा पृथिवी पर परमेश्वर का प्रतिनिधि है। वह राजा है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे राजा बनाया है। जिस प्रकार सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड पर परमेश्वर ब्रह्माण्ड के विविध प्राणियों की किसी भी प्रकार की सम्मति बिना लिये स्वेच्छा से शासन करता है, उसी प्रकार राजा अपने राज्य में प्रजा की सम्मति पर जरा भी आश्रित हुए बिना अपनी इच्छा से शासन करता है। यदि राजा दयालु है, प्रजा का सौभाग्य है। यदि राजा अत्याचारी है, तो किसी का क्या बस है। परमेश्वर के शासन में आधिया आती है, तूफान आते हैं, महामारिया फैलती हैं, भूकम्प आते हैं—इन सब ईश्वरीय विधानों के सम्मुख मनुष्य क्या कर सकता है? कुछ नहीं। अपने पापों का फल समझकर चुप रह जाने के सिवा मनुष्य की गति ही क्या है? इसी प्रकार यदि राजा अत्याचार करता है, कर से जनता को पीड़ित करता है, निरपराधियों को सुली पर चढ़ाता है, तो इन राजकीय विधानों के सम्मुख मनुष्य का क्या बस है? मनुष्य को यह सब राजकीय प्रकोप भी चुपचाप सहना ही चाहिये?

फ्रान्स के राजा इसी पुराने सिद्धान्त को माननेवाले थे। अधिकांश जनता भी यही विश्वास रखती थी। राजा बड़ी शानशौकत से, हजारों पार्श्वचरों और अनुचरों के साथ वर्साय के राजप्रासाद में निवास करता था। पेरिस से १२ मील दूर राजा और उसके दरबारियों के भोग-विलास का केन्द्र यह वर्साय नगर विराजमान था। इसकी कुल आबादी ८० हजार थी। ये इतने लोग राजा और उसके दरबार की आवश्यकताओं को पूर्ण करने



के लिये ही इस सुन्दरी नगरी में निवास करते थे। राजा का महल तीस करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया था। यह विपुल धनराशि जनता में क्रूर के रूप में वसूल की जाती थी। राज-दरबार में १५ हजार आदमी थे। अकेली रानी के नौकरों की संख्या ५०० से ऊपर थी। राजा के खर्च की कोई हद न थी। राजा की अपनी घुडसाल पर ही सालाना एक करोड़ रुपये से अधिक खर्च आता था। ५० लाख के लगभग रुपये खाने-पीने में उड़ा दिये जाते थे। राजा के आनन्द-प्रमोद, शान-शोक और भोग-विलास का खर्च ६ करोड़ रुपया सालाना से कम न था।

यह भोग-विलास प्रधान, स्वेच्छाचारी, एकतन्त्र शासन जनता के लिये असह्य न होता, यदि इसमें क्षमता होती। पर फ्रांस का इस समय का शासन बहुत ही ढीला ढाला तथा विच्छिन्न खल हो गया था। राजा तथा उसके कर्मचारियों को शासन की कोई पत्र ह न थी। उन्हें परवाह थी, अपने आमोद-प्रमोद की, अपने सम्मान की और आराम की जिन्दगी की। चौदहवें लुई के समय में फ्रांस का एकतन्त्र शासन जिस प्रकार शक्ति, भज्जत और प्रचण्ड था, वह दशा अब नहीं रही थी। फ्रांस का इस समय का राजा सोलहवा लुई चौदहवें लुई के समान ही निरकुश और स्वेच्छाचारी था, पर उसके शासन में शक्ति और क्षमता का सर्वथा अभाव था। ऐसा शासन देर तक कायम नहीं रह सकता था। जब उसे क्रान्ति का धक्का लगा, तब वह उसका मुकाबला नहीं कर सका। वह पुराने खोखले वृक्ष की तरह लड़खड़ा कर गिर गया।

राजा की स्वेच्छाचारिता—राजा की स्वेच्छाचारिता अनेक अंशों में सीमा को लाघ चुकी थी। फ्रांस के राजा जिसको चाहते, गिरफ्तार कर सकते थे। केवल राजा ही नहीं, उसके रिश्तेदारों, कृपापात्रों, कर्मचारियों और सरदारों को भी यह अद्भुत अधिकार प्राप्त था। राजा एक किस्म के “मुद्रित-पत्र” (लेट्र द काशे) जारी किया करता था, इन पर राजा की मुद्रा लगी होती थी और किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने तथा सजा देने का हुक्म जारी किया गया होता था। किसको गिरफ्तार किया जाय, उसके नाम की जगह खाली रहती थी। कितनी और क्या सजा दी जाय, इसका स्थान भी खाली रहता था। जिस आदमी के पास यह “मुद्रित-पत्र” मौजूद हो, उसे केवल इन खाली स्थानों को भर देना होता था। वे “मुद्रित-पत्र” की खाना पूरी कर जिसे चाहते, गिरफ्तार करवा देते और जो सजा चाहते, दिलवा देते। राजा को यह जानने की जरूरत भी नहीं थी कि किसे और क्या सजा दी जा रही है। ये “मुद्रित-पत्र” भी एक सौगात थे, एक उपहार थे, एक कृपा थी—जिसे राजा बड़ी उदारता के साथ अपने कृपापात्रों को प्रदान किया करते थे। कितने निरपराध इन “मुद्रित-पत्रों” से कष्ट भोगते थे, इसका अनुमान सहज में ही किया जा सकता है।

राजकीय कर—फ्रांस की जनता पर जो टैक्स लगाये जाते थे, वे दो प्रकार के थे—प्रत्यक्ष और परोक्ष। परोक्ष टैक्सों में नमक, शराब, तमाखू और आयात व निर्यात माल पर लगाये गये टैक्स प्रमुख थे। नमक पर कर की मात्रा बहुत अधिक थी। इस कर से जनता बहुत कष्ट में थी। नमक जैसी उपयोगी वस्तु उन्हें बहुत ही महंगी कीमत में प्राप्त होती थी। इन करों को वसूल करने का तरीका बहुत ही अजीब था। अमीर आदमियों व कम्प-

नियो को टैक्स वसूल करने का ठीका राज्य की तरफ से दिया जाता था। ये ठेकेदार एक निश्चित वनराशि देकर सनमाना टैक्स वसूल करने का हक प्राप्त कर लेते थे। इन्हें अपनी जेब भरने से मतलब था। जनता ही जवमिया ही जरा भी परवाह किये बिना ये अपने स्वार्थ की दृष्टि में सपका टैक्स वसूल करते थे।

प्रत्यक्ष-कर भूमि तथा अन्य प्रकार की सम्पत्ति में होनेवाली आमदनी पर लिया जाता था। पर इस तरह का टैक्स प्रसार का था, कि अमीरों पर बहुत ही कम बोझ पड़ता था। गरीबों पर टैक्स का भार बहुत अधिक था। मामूली किसान अपनी जमीना में जो कुछ पैदा करते थे, उसका आधा उन्हें भूमि-कर के रूप में राज्य को दे देना होता था। पर बड़े-बड़े जमींदार राज्य-कर में प्रायः मुक्त ही रहते थे।

विविध करा में जो आमदनी होती थी, राजा उसका उपयोग अपनी इच्छा में करता था। राजा के निज खर्च और राज्य के खर्च में कोई भेद न था। राजा जितना चाह, खर्च कर सकता था। वह जो बिल बना दे, राजकर्मचारियों को आव मीचकर उसे स्वीकार करना पड़ता था। वे कोई आपत्ति न कर सकते थे।

लोक सभाओं का अभाव—फ्रांस में कानून बनाने के लिये या राजकीय विषयों पर विचार करने के लिये कोई ऐसी लोक-सभा नहीं थी, जिनमें जनता के प्रतिनिधि एकत्रित हो सके। निस्सन्देह, पुराने समयों में फ्रांस में भी एक उस प्रकार की सभा थी, जिसे 'एस्टेट्स जनरल' कहते थे, पर सन १६१४ के बाद उसका एक भी अधिवेशन नहीं हुआ था। लोग यह भी भूल गये थे, कि इस 'एस्टेट्स जनरल' के क्या मगठन और निरसन थे। अब तो फ्रांस पर राजा का अवाधित शासन था। उसने अपनी मदद के लिए कुछ सभाएँ बनाई थी, पर ये राजा की अपनी सृष्टि थी। ये राजा के सम्मुख उत्तरदायी थीं, उसकी इच्छा पर अवलम्बित थी। इनका प्रयोजन यही था, कि राजा अपने नामान्व राजकीय कार्यों से भी निश्चित हो सके, वह सब चिन्ताओं से मुक्त हो कर मौज में अपने कृपापात्रों के साथ आमोद-प्रमोद में विलीन रह सके।

राष्ट्रीयता का अभाव—फ्रांस पर एक राजा का अवाधित राज्य था, इससे ऊपर से देखने पर तो यह मालूम होना था कि फ्रांस एक देश है—एक राष्ट्र है। पर वास्तविकता यह नहीं थी। यद्यपि जर्मनी, इटली और आस्ट्रिया आदि के मुकाबले में फ्रांस राष्ट्रीय दृष्टि से बहुत अधिक सगठित था, पर सच्चे अर्थों में अभी वही राष्ट्रीयता का उदय नहीं हुआ था। जनता में एक राष्ट्र की भावना का अभी अभाव था। भिन्न-भिन्न प्रदेशों के लोग अपने को फ्रांसीसी न समझकर उस-उस प्रान्त का निवासी समझते थे। पुराने जमाने में फ्रांस में अनेक राजाओं व सामन्तों का शासन था। फ्रांस अनेक छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त था। अब ये विविध राज्य नष्ट हो चुके थे, पर उनकी स्मृति अब भी मौजूद थी। यह स्मृति केवल मनुष्यों के हृदय में ही नहीं थी, अपितु देश के कानूनों और विविध सस्थाओं में भी विद्यमान थी। अब तक भी इन प्रदेशों में से बहुतों की सीमा पर आयात और निर्यात कर लगते थे। अगर कोई व्यापारी फ्रांस के दक्षिणी समुद्र तट से माल लाद कर उत्तर में ले जाना चाहे तो रास्ते में अनेक स्थान पर उसके माल की तलाशी होती थी, अनेक स्थान पर उसे चुंगी देनी पड़ती थी। ये आयात और निर्यात कर स्पष्ट

रूप में यह जताते थे, कि फ्रांस अब भी एक देश नहीं है, अनेक देशों का समूह है। इन विविध प्रदेशों में टैक्स वसूल करने के नियम तथा ढंग भी एक दूसरे से पृथक् थे।

फ्रांस अब भी एक राष्ट्र नहीं बना था, इसका सबसे अच्छा प्रमाण यह है, कि उसमें कानून की कोई एक पद्धति प्रचलित नहीं थी। दक्षिणी फ्रांस में विशेषतया रोमन कानून का प्रचार था। पर उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी फ्रांस में, २८५ क्रिस्म के कानून प्रयोग में आ रहे थे। ये विविध कानून फ्रांस के मध्यकालीन विभेदों के अवशेष थे। इन भिन्न-भिन्न कानूनों के रहते हुए फ्रांस में एक राष्ट्र की भावना कैसे उत्पन्न हो सकती थी ?

**सामाजिक रचना**—फ्रांस की सामाजिक रचना स्वतन्त्रता पर आश्रित न होकर जन्म मूलक स्थिति पर आश्रित थी। सब फ्रेंच लोगों के अधिकार एक समान न थे। कुछ लोग विशेष अधिकार रखते थे और कुछ के कोई भी अधिकार न थे। कुछ लोग बड़े थे और कुछ लोग छोटे। कुछ लोग कुलीन सम्प्रदाय जाते थे और कुछ लोग नीचे। फ्रांस में सामाजिक संगठन का आधार-भूत सिद्धान्त यह था, कि सब मनुष्य एक समान और स्वतन्त्र नहीं हैं। कुछ लोग स्वभावतः ही बड़े हैं, विशेष अधिकार रखते हैं, अमीर हैं, और दूसरे स्वभावतः ही छोटे हैं, अधिकार रहित हैं और गरीब हैं। रूमो का प्रसिद्ध सिद्धान्त “पर-मेस्वर ने सब मनुष्यों को एक समान और स्वतन्त्र उत्पन्न किया है” उस समय फ्रांस में केवल कुछ विचारकों के दिमाग में ही था, क्रिया में नहीं।

फ्रांस की जनता को हम तीन श्रेणियों में बांट सकते हैं—कुलीन श्रेणी, पुरोहित श्रेणी और सर्वसाधारण जनता। इनमें से कुलीन और पुरोहित श्रेणियाँ विशेष अधिकारों से युक्त थीं, ऊँची समझी जाती थीं और सग्या में बहुत कम होने पर भी बहुत अधिक प्रभाव रखती थीं। सर्वसाधारण जनता की उनके मुकाबिले में न कोई स्थिति थी और न कोई अधिकार।

फ्रांस की सम्पूर्ण भूमि का एक चौथाई भाग कुलीन श्रेणी की सम्पत्ति था। ये कुलीन लोग मध्यकालीन सामन्तपद्धति के अवशेष थे। इनकी राजनीतिक स्थिति अब क्षीण हो चुकी थी, पर सामाजिक और आर्थिक अधिकार अभी वैसे ही कायम थे। राज्य, सेना और चर्च के सब उच्च पद इन्हीं के लिये सुरक्षित थे। अनेक प्रकार के टैक्सों से ये बरी थे। ये समझते थे, हमें रुपये पैसे के रूप में टैक्स देने की क्या जरूरत है ? हम तो अपना टैक्स तलवार में देते हैं। जो कुलीन लोग अमीर होते थे, वे बड़ी शान-शौकत के साथ राज दरबार में राजा के इर्द गिर्द निवास करते थे। वहाँ इन के भोग-विलास की कोई सीमा न थी। इनका पैशा केवल माँज उड़ाना ही न होना था, अपितु दरबार की साजिशों से भी इन्हें फुरसत न मिलती थी। इन की जमीन किमान लोग जोतते थे। जमीन की फिक्र करने की इन्हें कोई जरूरत न थी। राज्य के बड़े-बड़े पद, खास तौर पर आमदनीवाले पद—नीलाम हुआ करते थे और ये कुलीन लोग उन्हें खरीदने के लिये सदा उत्सुक रहते थे। ये पद इनकी शान को बढ़ाते थे, और साथ ही आमदनी को बढ़ाने में भी सहायक होते थे, क्योंकि उस समय फ्रांस के शासन में रिश्वतखोरी का बाजार बहुत गरम रहता था।

परन्तु कुलीन श्रेणी के सभी लोग अमीर न थे। बहुत से कुलीन लोग जूए, शराब तथा इसी प्रकार के अन्य व्यसनो में पैसे रहने के कारण ऋणी होकर तबाह हो गये थे।

एक कुलीन के मरने पर उसकी सम्पत्ति का दो तिहाई हिस्सा सब में बड़े लडके को मिलता था, बाकी तिहाई हिस्सा छोटे लडके में बांट दिया जाता था। विरासत के इस कानून में भी बहुत से कुलीन लोग गरीब हो गये थे। पर गरीब होने पर भी उनके अधिकारों में कोई कमी न आती थी। उनका रहन-सहन मामूली किसानों का सा ही था, उनके कुलीन की आमदनी साधारण किसानों से भी कम थी। पर इन के अधिकार अक्षुण्ण थे। ला-डुहो मजाक में कहा करते थे कि ये “कृतराज खाने या जोहड़ के महान् और गतिमान सामन्त हैं।”

पुराने कुलीन लोगों में से बहुतों की इस प्रकार दुर्दशा हो गयी थी। दूसरी तरफ़ राज की कृपा ने अनेक लोगों को श्रीमन्त बना दिया था। स्पेच्छाचारी एकतन्त्र राजा का कृपा कटाक्ष में बहुत से साधारण जादमी कुलीनों की श्रेणी में पहुँच गये थे। सर्वसाधारण लोगों में उन्हें घरानों के लिये एक विशेष प्रकार का आदर भाव होता है। वे उन्हें जहाँ से अच्छी स्थिति में देखने के लिये अभ्यस्त होते हैं। उन कुलीनों के विशेष अधिकार का उपभोग करना उन्हें नहीं चुभता। पर जब कोई उन्हीं की तरह का मामूली जादमी विशेष अधिकारों को प्राप्त कर लेता है, तब तब उन्हें अन्याय हो जाता है। फ्रांस की जनता की दृष्टि में राजा की कृपा से कुलीन बने हुए उन मामूली लोगों के विशेष अधिकारों की तरह में चुभते थे। इसी प्रकार कुलीनता के रोग को कायम रखने के लिये जाति सम्मृद्धि अत्यन्त आवश्यक होती है। गरीबी की हालत में कुछ समय तक तो खानदान का रोग काम करता है, पर कुछ समय बाद ही वह काफ़र की तरह उठ जाता है। फ्रांस में गरीब कुलीनों का रोग भी इसी प्रकार निरन्तर क्षीण हो रहा था। पर कुलीनता के विशेष अधिकार इन्हें प्राप्त थे और जनता को ये मालूम न थे।

**चर्च की स्थिति**—वार्मिक सुधारणा का युग इस समय समाप्त हो चुका था। फ्रांस में अभी रोमन कैथोलिक चर्च का ही आधिपत्य था। यह चर्च राज्य के अन्दर एक दूसरे राज्य के समान था। इसकी अपनी सरकार और अपने राजकर्मचारी थे। फ्रांस में बहुत सी भूमि चर्च की मिल्कियत थी। किसी-किसी प्रदेश में तो ४० फीसदी जमीन चर्च की सम्पत्ति थी। इस जमीन से चर्च को भारी आमदनी थी। इसके सिवाय चर्च तब लोगों से कर वसूल करता था। जमीन की उपज का दसवा हिस्सा चर्च को कर रूप में जाता था। हिसाब लगाया गया है, कि चर्च की कुल आमदनी तीस करोड़ रुपये वार्षिक लगभग थी। चर्च की जमीनों और सम्पत्ति पर राज्य कोई कर न लेता था। चर्च जो कर वसूल करता था, वह केवल रोमन कैथोलिक लोगों से ही नहीं, अपितु प्रोटेस्टेंट और यहूदी लोगों से भी लिया जाता था। इन सब कारणों से चर्च के प्रभाव और शक्ति की कोई सीमा न थी। राज्य के बाद उसी का स्थान सर्वाच्च था। इस अत्यन्त प्रभावशाली चर्च के सचालकों का महत्व उस समय में कितना होगा, इसका अनुमान कर सकना कठिन नहीं है।

चर्च का सचालन करनेवाली पुरोहित-श्रेणी को हम दो भागों में बांट सकते हैं—उच्च पुरोहित और सामान्य पुरोहित।

उच्च पुरोहितों की संख्या ६००० के लगभग थी। ये आर्कबिशप, बिशप, एवं

आदि चर्च के ऊँचे पदों पर नियत थे। इनके प्रभाव और समृद्धि की कोई सीमा नहीं थी। ये बड़े-बड़े कुलीन श्रीमन्तों की तरह शान-शौकत और भोग-विलास से जीवन व्यतीत करते थे। धार्मिक कर्तव्यों की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं था। इनमें से बहुत से राजदरबार में मौजूद किया करते थे, और कुलीन लोगों की तरह राजदरबार में अन्दरूनी सज्जिशों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने में ही अपने जीवन की सफलता समझते थे। इनमें से बहुतों की आमदनी लाखों रुपये साल थी। इस आमदनी का उपयोग अनाथों और बीड़ितों की सहायता में न होकर सहभोजों और शराब की दावतों में होता था। बहुत से उच्च पुरोहितों का पर-मेस्वर में विश्वास तक नहीं था, फिर भी वे चर्च के ऊँचे-ऊँचे पदों पर विराजमान थे।

चर्च के वास्तविक कर्तव्यों का सम्पन्न सामान्य पुरोहित करते थे। इनकी सख्या सवा लाख के लगभग थी। ये सर्वसाधारण जनता में से लिये जाते थे। देहातों में इनका निवास था, और ये ही धार्मिक विधि-विधानों और कर्मकाण्डों का सम्पादन करते थे। ये लड़कों को पढ़ाते थे और मामूली लोगों की तरह सुख या दुःख में दिन काटते थे। इन्हें बहुत थोड़ा वेतन मिलता था। सारा काम ये करते थे, पर बेफिकरी से पेट भर सकना भी इनके लिये दूभर था। चर्च की विशाल आमदनी का बहुत थोड़ा हिस्सा इनके पाले पड़ता था। उसका फल तो वे लोग प्राप्त करते थे, जो राजा के साथ बर्साय में मौजूद उड़ाते थे। यही कारण है, कि सामान्य पुरोहितों के हृदय में उच्च पुरोहितों के प्रति विद्वेष की भावना थी और राज्यक्रान्ति के समय में उन्होंने जनता का साथ दिया।

इस काल में फ्रांस के अन्दर जनता को धार्मिक स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं थी। यद्यपि फ्रांस की अधिकांश जनता रोमन कैथोलिक धर्म को माननेवाली थी, पर यहूदियों और प्रोटेस्टेंटों की सख्या भी कम नहीं थी। फ्रांस के कानून के मुनाबिक प्रत्येक आदमी के लिये, चाहे वह यहूदी या प्रोटेस्टेंट धर्म को माननेवाला क्यों न हो, चर्च के—जो कि रोमन कैथोलिक था—अधीन होना आवश्यक था। सब आदमियों को चर्च के अधीन होना होता था और चर्च के कर्तव्यों को देना पड़ता था। रोमन कैथोलिक लोगों के अतिरिक्त अन्य लोगों के विवाह तक गैर कानूनी समझे जाते थे। उनकी मृत्यु के बाद उनके कैथोलिक रिश्तेदार सम्पत्ति के मालिक बनने के लिये दावा कर सकते थे, और इस प्रकार उनके वास्तविक उत्तराधिकारियों से विरासत के हक को छीन सकते थे। विधर्मीयों को अपने विश्वासों के अनुसार स्वतन्त्रतापूर्वक धार्मिक कृत्यों तक को करने का अधिकार नहीं था। जब भी धार्मिक स्वतन्त्रता के लिये फ्रांस में कोशिश की गई, पुरोहितों ने उसका विरोध किया।

एक तरफ जव फ्रांस के कानून के अनुसार धार्मिक स्वतन्त्रता को पूर्णतया रोक दिया गया था, दूसरी तरफ नास्तिकता की प्रवृत्ति बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही थी। सर्वसाधारण जनता में ही नहीं पुरोहितों और उच्च पुरोहितों में भी नास्तिकता की लहर बड़ी तेजी से चल रही थी।

कुलीन श्रेणी—इन कुलीन और पुरोहित (उच्च पुरोहित) श्रेणियों के विशेषाधिकार अनेक प्रकार के थे। अपनी-अपनी जमींदारियों से कई किस्म की आमदनी वे रिवाज के आधार पर प्राप्त करते थे। विवाह आदि विशेष अवसरों पर किसी खास खर्च के आ पड़ने पर ये बड़े जमींदार अपने आसामियों तथा अपनी जमींदारी के निवासियों से

तरह-तरह के नजराने वसूल करते थे। तो मान्य उन के उलाहने में जाता था, उसका वह कर लेते थे। स्वतन्त्र किसानों से उनकी उपाज का योग हिस्सा पान करने थे। इसके अलावा से कई हिस्से के कारोबार, जो जाड़े की चारों तरफ, जगमगाता जाति, उनके विश्व दृष्टि से कर सकता था जोर कर रोमा के नियम आवश्यक था कि उन कामों को उन्हीं के पास पाना में कराना। जमीन के दाय-विदाय के समय में उनकी रीति का पालना हिस्से में बड़े जमींदार प्राप्त करने थे। जिसका उपाज पान जातिगत था। उस के लिए वह भी जमीन सुरक्षित रखी जाती थी, ताकि जानवर तथा में पूरा बट सक। नदीक व किसान किसान के उन जानवरों का हिस्सा हिस्से का नुस्खान नहीं पहुँचा सकते थे, वह वे उनके पनों का बचाव ही पान कर रहे। जमींदारों के बदतरगाना में पड़े हुए हानि करने निषाणों के नेता का उजाड़ने करने थे, पर किसी के पान हिस्से में नहीं उठा भी सके। तरह-तरह के जानवर—जिनका निहार पल्लव जमींदार भव प्राप्त करता था, पनों की बचाव ही मचाने रहते थे, पर कई हिस्से उन्हें पान नहीं सकता था। जमींदारों के उन विश्वासपात्रों में योग पान आ गये थे, पर वे प्रेम थे।

फ्रांस में कुलीन और पुरोहित श्रेणियाँ के लोगों का पुराना जायादी दो या दार्ष्टिक पान से अधिक नहीं थी। जब जनता—जिन की जायादी कई तरह के दाय-विदाय थी, जिसका में थी? इस पद-पाधारण जनता का हम तीन भागों में बाँट सकते हैं—मध्य श्रेणी के लोग शहरों के मजदूरी पेशा लोग और देशान्तों के किसान लोग।

**मध्य श्रेणी**—मध्य श्रेणी में वे लोग सम्मिलित थे, जो पुराने व पुरोहित श्रेणी के थे और जो हाथ से मेहनत किये बिना अन्य तरीका में आमदनी पान करने में मत्त थे जैसे वकील, चिकित्सक, साहित्यिक लेखक व कवि व्यापारी, माहिर, कलाकार व नर्तक, सरकारी नौकर और छोटे-बड़े कारखानों के मालिक। ऐसे लोगों की संख्या बीस लाख के लगभग थी। फ्रांस की सम्पत्ति, विभाग, विद्या और नौ पेशा की मध्य श्रेणी के लोगों के पास था। तरह-तरह के कारोबार और निजाम में वे लोग लगातार अमीर होते जाते थे। राजा और कुलीन श्रेणी के लोग इनसे अपना कर्ज लेते थे। महान के तौर पर इनकी शक्ति और प्रतिष्ठा निरन्तर बढ़ रही थी। इनकी श्रेणी के लोग बहुत से विचारक दार्शनिक तथा लेखक उत्पन्न हुए थे, जो फ्रांस में पहली बार संसद न्याय की नई वस्तु को पंदा कर रहे थे। सामाजिक दृष्टि में नव प्रकार उन्नत तथा उत्तम होने हुए भी इनके राजनीतिक अधिकार कोई न थे। राजनीतिक अधिकारों की दृष्टि से इनकी वही हसियत थी, जो कि एक नये भूखे किसान की थी। यही कारण है कि जन असन्तोष निरन्तर बढ़ रहा था। ये लोग अपनी वर्तमान दशा से असन्तोष अनुभव कर रहे थे। योग्यता और सम्पत्ति की दृष्टि से ये कुलीन श्रेणी के बराबरी के थे, पर अधिकार की दृष्टि से इनकी कोई गिनती न थी। जब फ्रांस में राज्यक्रान्ति हुई, तो इन्हीं लोगों ने उसका सबसे अधिक साथ दिया। क्रान्ति में इन्हें स्पष्ट रूप से अपनी इस दुरवस्था के अन्त होने की सम्भावना नजर आ रही थी।

**मजदूर श्रेणी**—शहरों के मजदूरी पेशा लोगों की संख्या २५ लाख के लगभग थी। शहरों का व्यावसायिक जीवन उस समय या तो आर्थिक श्रेणियों (guilds) में संगठित

था, या छोटे-छोट कारखानों में। जो मजदूर इन श्रेणियों के सदस्य थे, उनकी हालत बहुत बुरी न थी। पर श्रेणियों के कड़े कायदे उनकी स्वतन्त्रता के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट थे। जो मजदूर कारखानों में काम करते थे, उनकी दशा बहुत खराब थी। उन्हें बहुत थोड़ा वेतन मिलता था, उन्हें बहुत अधिक समय तक काम करना पड़ता था। उनकी मेहनत बहुत ही थकानेवाली तथा कष्टप्रद होती थी। इन मजदूरों का किसी प्रकार का संगठन नहीं था। ये अपनी हालत से बहुत असन्तुष्ट थे। जब राज्यक्रान्ति हुई, तो यही मजदूरों पेशा लोग थे, जो बड़े उत्साह के साथ सब तरह की अव्यवस्था और दशा मचाने के लिये उसमें शामिल हो गये। क्रान्ति में इन्होंने गवाना कुछ नहीं था। क्रान्ति में इनकी मौज ही मौज थी। बिना पसीना बहाये क्रान्ति के समय ये उसमें बहुत अधिक प्राप्त कर सकते थे, जितना कि इन्हें मजदूरों से मिलता था।

**किसान श्रेणी**—देहातों के किसानों की सराया दो करोड़ के लगभग थी। ये कुल जनता के अस्सी फी सदी थे। पर इनकी हालत सबसे अधिक खराब थी। ये ग्रामों में कुलीन श्रेणी के जमींदारों की जागीरों में निवास करते थे। आधे के करीब किसान अभी तक 'भूमिदास' व 'अर्द्धदास' थे, जो अपनी इच्छानुसार अपने मालिक की जमीन को छोड़कर कहीं बाहर नहीं जा सकते थे। इन्हें बाधित होकर अपने मालिक की जमीन को जोतना पड़ता था। पर शेष आधे किसान स्वतन्त्र थे। वे जहाँ चाहे आ-जा सकते थे, और जमीनों पर अपने हक को बेच व खरीद सकते थे। जमीनों पर इनका हक मान लिया गया था और बहुत से किसान अपनी जमीन के मालिक भी बन गये थे। परन्तु किसान चाहे अभी भूमिदास की दशा में हों, चाहे स्वतन्त्र हों, और चाहे अपनी जमीन के स्वयं मालिक हों, विविध किस्म के टैक्सों से दबे हुए थे। ऐसे किसानों को ही लीजिये, जो अपनी जमीन के आप मालिक थे। राजा उनमें टैक्स लेता था, जमींदार उनसे नजराने लेता था और चर्च उनमें आमदनी का दमवा हिस्सा वसूल करता था।

यह नहीं समझना चाहिये कि फ्रान्स के किसानों की दशा इस समय में असाधारण रूप से खराब थी। वास्तविकता तो यह है, कि उनकी दशा अन्य देशों के किसानों की दशा से बहुत काफी अच्छी थी। क्रान्ति के लिये यह जरूरी नहीं है कि लोग बहुत पददलित हों, बहुत अत्याचार-पीड़ित हों। जनता भयकर से भयकर अत्याचारों से सताई हुई रह सकती है, और हो सकता है कि उसको अपनी स्थिति से जरा भी असंतोष न हो। हजारों साल तक मनुष्य जाति का अधिकांश भाग दास-प्रथा का शिकार रहा है। दास की दशा में लोग भयकर से भयकर अत्याचारों को दैवी विधान समझकर सहन करते रहे हैं। क्रान्ति के लिये जनमाधारण की दशा ऐसी होनी चाहिये, कि वे अत्याचारों को अनुभव कर सकें, अपनी दुर्दशा को समझ सकें। फ्रान्स में क्रान्ति सफलता से हो सकी, इसका कारण यह भी था, कि सर्वसाधारण लोगों की हालत इस हद तक उन्नत हो गई थी कि वे अपने ऊपर किये गये अत्याचारों को—अपनी दुर्दशा को अनुभव कर सकते थे। ज्यों-ज्यों उनकी दशा सुधरती गई, वे अपने जमींदारों को ठाकू समझने लगे, चर्च के दशाश कर को लूट समझने लगे और राजा के अनुत्तरदायी शासन को अनुचित बताने लगे। यूरोपियन देशों में फ्रांस ही सबसे पहले अत्याचारों के खिलाफ विद्रोह करने के लिये अग्रसर हुआ, इसका प्रधान

कारण यही था कि वहाँ के जनसाधारण की दशा पर्याप्त अच्छी थी।

यह सब हाते हुए भी यह न भूलना चाहिये कि फ्रांस के अधिकांश किसान नून, नंगे ओर गरीब थे। जमींदारों के अधिकार के विशेषाधिकार जहाँ एक तरफ उनके वेतों को उजाड़े बिना नहीं छोड़ते थे, वहाँ दुर्भिक्ष, अतिवृष्टि तथा अनावृष्टि आदि प्राकृतिक विपत्तियाँ भी उनकी तबाही करने में किसी प्रकार की रुकावट नहीं रहने देती थी। फ्रांस के किसानों पर विविध प्रकार के करों का बोझा उतना अधिक था, कि उनके पास यदि अपने गुजारे के लिये भी अनाज बच जावे, तो उसे वे बड़ी भारी गनीमत्त समझते थे।

**व्यापार और व्यवसाय**—फ्रांस के व्यापार और व्यवसाय इस काल में ग्रीष्म-परन्तु निरन्तर उन्नति कर रहे थे। व्यापारिक क्रान्ति का प्रभाव यूरोप के सभी देशों में दृष्टिगोचर होना शुरू हो गया था। उनके कारण फ्रांस में ऐसे लोगों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही थी, जो आन्तरिक और बाह्य व्यापार द्वारा धनी होने जा रहे थे। उस समय में यान्त्रिक शक्ति से चलनेवाले यानों का आविष्कार नहीं हुआ था। इसलिए पेरिस से मार्सेय तक जाने में ११ दिन लगते थे। जलमार्ग द्वारा पेरिस में आता तक १८ दिन लगते थे। पर इसमें सन्देह नहीं, कि जल और स्थल दोनों प्रकार के मार्गों को उन्नत करने का उस समय में पर्याप्त प्रयत्न किया जा रहा था। मई १७८८ में ३६ हजार मील नहर बन चुकी थी। करोड़ों रुपया सड़कों और पुतों के लिये खर्च किया जा रहा था। इन नियरों को तैयार करने के लिये फ्रांस में एक विद्यालय की भी स्थापना हो चुकी थी। उस सब प्रयत्नों का परिणाम था, कि फ्रांस का व्यापार काफी अच्छी गति में निरन्तर उन्नति कर रहा था। परन्तु इस व्यापारिक उन्नति में फ्रांस का एक देश न होना सबसे बड़ी बाधा थी। जगह-जगह पर चुगी देना तथा माल को खोलना व्यापारियों के लिये बहुत कष्ट-प्रद था और इससे आन्तरिक व्यापार की उन्नति में बहुत रूकावट उत्पन्न होती थी।

व्यापारिक क्रान्ति के कारण पुराने जमान की आर्थिक श्रणियों (गिल्ड) का स्वातन्त्र्य कारखाने ले रहे थे। इन कारखानों में पूँजीपतियों की अर्धानता में बहुत से मजदूर काम करते थे। आर्थिक उत्पत्ति का सारा काम ये मजदूर करते थे, पर व्यवसाय पर इनका कोई हक नहीं था, ये मशीनों की तरह पूँजीपति के हित के लिये काम करते थे। बदले में इन्हें मजदूरी मिलती थी, जिसकी दर बहुत कम होती थी। इन कारखानों की बजह से एक इस प्रकार की श्रेणी उत्पन्न हो रही थी, जो शहरों में रहती हुई, नई लहरों से जानकारी रखती हुई और आर्थिक उत्पत्ति का सारा कार्य करती हुई भी सर्वथा असहाय थी। इस श्रेणी के लोगों को अभी अपनी शक्ति और महत्व का ज्ञान नहीं हुआ था। पर फिर भी वे अपने हितों को कुछ-कुछ समझने लगे थे और इसी का परिणाम था, कि यद्यपि फ्रांस की राज्यक्रान्ति राजनीतिक स्वाधीनता की स्थापना के लिये विशेष रूप से प्रयत्न कर रही थी तथापि आर्थिक समस्या की कुछ झलक उसमें विद्यमान थी।

**राज्यक्रान्ति से पूर्व का फ्रांस**—राज्यक्रान्ति से पूर्व फ्रांस की जो दशा थी, उसका संक्षेप में इस प्रकार प्रकट कर सकते हैं—

(१) राजा स्वेच्छाचारी और निरकुश था। राजा की इच्छा ही कानून थी। जनता को नागरिक व राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं थी। भाषण, विचार व प्रेस की स्वतन्त्र-



न्रता का अभाव था। राजा व उसके कृपापात्र व राजकर्मचारी स्वेच्छापूर्वक जिसे चाहे गिरफ्तार कर सकते थे। अदालतों में निर्णय करते हुए ज्यूरी पद्धति सर्वथा अज्ञात थी। सारे देश के लिये एक कानून नहीं थे। प्रादेशिक दृष्टि से कानून पृथक्-पृथक् थे और साथ ही जनता की विविध श्रणियों के लिये भी। सरकारी टैक्सों की स्वीकृति पार्लियामेन्ट से नहीं ली जाती थी, राजा अपनी इच्छानुसार टैक्स लगाता था। पार्लियामेन्ट उस युग में थी ही नहीं। सरकारी कर्मचारी जनता पर अत्याचार करते थे और रिश्वतखोरी द्वारा अपने को समृद्ध बनाने में प्रयत्नशील रहते थे। पुराने समय से स्थानीय स्वशासन की जो कतिपय सस्थाएँ चली आती थी, उन्हें भी नष्ट करने का प्रयत्न किया जा रहा था। राज्य जनता से जो टैक्स वसूल करता था, उसे खर्च करने के लिये वाकायदा बजट बनाने की पद्धति उस समय नहीं थी। राजा व उसके मन्त्री उसका व्यय स्वेच्छापूर्वक करते थे।

(२) चर्च बहुत समृद्ध व शक्तिशाली था। निरकुश व स्वेच्छाचारी शासन में वह राजा का प्रधान सहायक था। बड़े महन्त और पादरी अपने धार्मिक कर्तव्यों की उपेक्षा कर राजदरवार की साजिशों में भाग लिया करते थे और भोग-विलास में जीवन व्यतीत करते थे। जनता को धार्मिक विश्वास व पूजा के सम्बन्ध में स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं थी। चर्च की इस विकृत दशा के कारण जनता में, विशेषतया विद्वानों और विचारकों में नास्तिकता का प्रसार हो रहा था।

(३) सामाजिक जीवन श्रेणिभेद पर आश्रित था। कुलीन श्रेणी अब तक भी अनेक ऐसे विशेषाधिकारों का उपभोग करती थी, जो सामन्तपद्धति के अवशेष थे। मध्यश्रेणी के शिक्षित व सम्पन्न लोगों की सख्या निरन्तर बढ़ रही थी, पर राजनीतिक दृष्टि से उनका कोई महत्व नहीं था। देहातों की बहुसंख्यक जनता अभी अर्द्ध-दास की दशा में थी।

(४) शिक्षा चर्च के अवीन थी, इसलिये इस युग के शिक्षणालय ज्ञान व प्रकाश के केन्द्र न होकर पुरानी परिपाटी की साम्प्रदायिक शिक्षा को अधिक महत्व देते थे। बहु-संख्यक जनता अशिक्षित थी। पुस्तकों को प्रकाशित करने के लिये सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी और इस कारण ज्ञान का विस्तार स्वतन्त्र रूप से नहीं हो सकता था।

(५) शहरों में निवास करनेवाली मध्यश्रेणी और मजदूर जनता में असन्तोष बहुत अधिक था। उनमें क्रान्ति की भावना निरन्तर जोर पकड़ती जा रही थी।

## २ क्रान्ति की भावना का प्रादुर्भाव

अठारहवीं सदी के उत्तरार्द्ध में यूरोप के सभी देशों की लगभग वही हालत थी, जिसका हमने ऊपर वर्णन किया है। इस पुराने जमाने के खिलाफ मव से पहले राज्यक्रान्ति फ्रांस में हुई, इसका कारण यह नहीं है, कि फ्रांस की दशा अन्य देशों से अधिक खराब थी। वस्तुतः फ्रांस की दशा अन्य देशों से कहीं अच्छी थी। क्रान्ति सबसे पहले फ्रांस में हुई, इसका प्रधान कारण वह क्रान्ति की भावना है, जो अनेक विचारकों द्वारा फ्रांस में उत्पन्न की जा रही थी। इस समय तक यूरोप के दिमाग पुराने अन्ध-विश्वासों की जकड़ से बहुत कुछ छुटकारा पा चुके थे। लोग अपने दिमागों से स्वच्छन्दतापूर्वक विचार करने लग गये थे। वे किसी बात पर केवल इसीलिये विदवास नहीं कर लेते थे, बल्कि बहुत सी

सदियों में गणतन्त्र ब्रह्म ही मानने जाये। या धार्मिक गणतन्त्र में वंशा लिखा है, अर्थात् राजा की वंश-परम्परा पर कानून बन जाय। राजा की प्रवृत्ति उसमें पैदा हो जाय। जो राजा परिणाम में निजने विचारक ऐसे उत्पन्न हुए, जिन्होंने मनुष्य जाति में राजा का राज म चले जा रहे विश्वास के जागे पन्नात्मक चिन्तन लगाया और न सिर्फ जनता के सम्मुख पेज किया। फ्रांस में भी उसी प्रकार के बहुत से विचारक, जो जाति की भावना का जनता में उत्पन्न कर रहे थे। ये विचारक कान के और उत्तम उदाहरण विचारक का विषय पर हम मध्यम में प्रकाश डालने हैं—

**माल्थ्यू**—उसका जन्म १७८३ में १७५५ तक है। वह मध्य कुलीन श्रेणी का था। अपने राजा के दैवी अधिकार के सिद्धान्त के विरोध में जायज उठाई। माल्थ्यू का कहना था कि राजा ईश्वरीय विधान की कृति नहीं है। वह अनिष्टों की रचना है, यद्यपि के विराम में राजमन्त्रियों का प्रादुर्भाव होता है। माल्थ्यू ने फ्रांस के जाति विधान के मुकाबले में उद्गार के जाति-विधान की बहुत अधिक प्रशंसा की। वह कहता था कि इंग्लैंड का जाति समार में सर्वोत्तम है, क्योंकि उसमें नागरिकों की स्वतन्त्रता सुरक्षित है। माल्थ्यू न ही मध्यम पहले राज्य की विभिन्न शक्तियों का पृथक्-पृथक् करने के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था। राजशास्त्रियों को हम तीन भागों में बांट सकते हैं—जाति व्यवस्थापन (जाति-निर्माण) और न्याय। माल्थ्यू का सिद्धान्त था, कि ये तीनों शक्तियाँ एक ही व्यक्ति के हाथ में न होकर पृथक्-पृथक् होनी चाहिये। यह सिद्धान्त राजशासन के प्रमुख सिद्धान्तों में से एक है और वर्तमान काल में सब लोग इसे मानते हैं। पर अठारहवीं सदी के लिये यह सिद्धान्त एक नई चीज थी। फ्रांस के एकतन्त्र स्वेच्छाचारी शासन में माल्थ्यू का यह सिद्धान्त किसी भी तरह लागू नहीं हो सकता था।

**वाल्टेयर**—वाल्टेयर कुलीन श्रेणी का न होकर मध्य श्रेणी का था। अपने समय के अत्याचारों और अन्यायों का उसे प्रत्यक्ष अनुभव था। वह अच्छी तरह जानता था कि जब कोई कुलीन सरदार गुस्से में आकर मारने पीटने लगता है, तो उसकी मार जितनी मजबूत होती है। वह अच्छी तरह समझता था, कि बान्सीय की जेल में एक वर्ष बन्दी रहना कितना कष्टप्रद होता है। कुछ समय तक वाल्टेयर राजदरबार में रहा। पर वह देर तक वहाँ न रह सका। उसे फ्रांस छोड़कर प्रशिया और इंग्लैंड भागना पड़ा। वाल्टेयर का पुराने जमाने के अन्याय और विषमता से प्रचण्ड घृणा थी। उसका विश्वास था, कि इस पुराने जमाने को जड़ से उखाड़ देने में ही भला है। वह किसी किस्म के समझौते को सहन नहीं कर सकता था। वह कहता था, हम नवीन युग की आधारशिला तभी स्थापित कर सकेंगे, जब कि पुराने जमाने के नाम को भी पृथिवी में मिटा दिया जावेगा। इसलिए पुराने जमाने के विरुद्ध प्रचार को ही उसने अपना मुख्य कार्य बनाया। उसने चर्च और राज्य—दोनों की बुराइयों के ऊपर जबरदस्त हमले किये। उसकी शैली बहुत जोरदार थी। व्यङ्ग्य लिखने में वह सिद्धहस्त था। वाल्टेयर लोकतन्त्र शासन का पक्षपाती नहीं था। वह कहा करता था कि सौ चूहों की बजाय एक शेर का शासन मुझे अधिक पसन्द है। यदि लोकतन्त्र शासन का पक्षपाती नहीं था, तो एकतन्त्र शासन का तो बड़ा भारी दुश्मन था।

चर्च और राज्य के दोषों के विरुद्ध उसने जो पुस्तकें लिखीं, उनके कारण लोगों का ध्यान उनकी बुराइयों की तरफ आकृष्ट हुआ और लोग इन दोषों को नष्ट कर एक नवीन युग की कल्पना करने लगे।

रूसो—क्रान्ति की भावना को प्रादुर्भूत करने में सबसे प्रधान स्थान रूसो का है। रूसो केवल दोष-प्रदर्शन का ही कार्य नहीं करता था, वह न वीन युग की कल्पना का विधायक था, वह मानव-समाज का एक नवीन सगठन चाहता था। उसके विचार में मनुष्य जाति का भूतकाल बहुत ही उज्ज्वल था। एक समय ऐसा था, जब सब लोग स्वतन्त्र थे, कोई किमी का दाम न था, कोई पराधीन न था, सब एक दूसरे के बराबर थे। न उस समय में लोगों को टैक्स देने पड़ते थे, न लडाइया होती थी, न कोई राजा था, न कोई प्रजा थी। वह सुवर्णीय समय सदा के लिये स्थिर न रह सका। जिसे आजकल 'सभ्यता' कहा जाता है, उसके प्रादुर्भाव के साथ मनुष्यों में वैयक्तिक सम्पत्ति की उत्पत्ति हुई और इस वैयक्तिक सम्पत्ति के पैदा होने ही मनुष्यों में लोभ, मोह आदि प्रकट होने लगे। वह सुवर्णीय युग समाप्त हो गया और विषमता, अत्याचार व पराधीनता का युग आ गया। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सामाजिक सविदा (Social Contract) का प्रारम्भ उसने इन शब्दों से किया है—

“मनुष्य स्वतन्त्र उत्पन्न होते हैं, पर वह सर्वत्र जजीरो में जकड़े हुए पाये जाते हैं। कुछ लोग अपने को दूसरों का भालिक समझते हैं, पर वस्तुतः वे दूसरों की अपेक्षा भी अधिक गुलाम होते हैं। यह परिवर्तन कैसे आ गया? मैं नहीं जानता। इस परिवर्तन को किस प्रकार न्याय्य और समुचित कहा जा सकता है? मेरा विश्वास है, कि इस प्रश्न का उत्तर मैं दे सकता हूँ।”

रूसो ने इस प्रश्न का उत्तर यह दिया है, कि मानव समाज व राज्य में जनता की इच्छा ही सर्वोपरि है, सरकार की न्याय्यता इसी जनता की इच्छा पर आश्रित है। जनता शासन करने के लिये किमी एक आदमी को—जैसे राजा—नियत कर सकती है, पर उस आदमी की सत्ता जनता की इच्छा पर ही निर्भर है। जनता अपनी इच्छा को कानून की शक्ल में प्रकट करती है जिसके अनुसार राजा को शासन करना चाहिए।

ये विचार अठारहवीं सदी के लोगों के लिये 'भयानक क्रान्तिकारी' विचार थे। जनता की इच्छा कानून है, राजा की इच्छा कानून नहीं है, यह भाव फ्रांस की राज्यक्रान्ति में प्रधान रूप में काम कर रहा था। रूसो की विचार-सरणी के अनुसार राज्य का निर्माण जनता की आपस की सविदा (Contract—ठीका) द्वारा हुआ, अतः राज्य में लोकमत ही सर्वोपरि होना चाहिये। वह शासन-पद्धति सर्वोत्तम है, जिसमें बहुमत के अनुसार शासन होता है। रूसो के ये सिद्धान्त एक नये सदेश के समान सम्पूर्ण यूरोप में व्याप्त हो गये। फ्रांस के क्रान्तिकारियों के लिये रूसो के विचार 'धार्मिक-सिद्धान्तों' का सा महत्व रखते थे। रूसो ने केवल पुराने जमाने की आलोचना ही नहीं की, अपितु नवीन युग का चित्र भी लोगों के सम्मुख उपस्थित किया। लोगों ने अनुभव किया, कि यह नवीन चित्र बहुत ही सुन्दर है। वे उसके अनुयायी हो गये।

दिदरो—क्रान्ति की भावना को जन्म देनेवाले विचारकों में दिदरो भी बहुत महत्वपूर्ण

स्थान रखता है। दिदरो ने एक विशाल विश्वकोष को प्रकाशित करने की योजना की और इसके लिये बहुत से वैज्ञानिक और विद्वानों को अपने साथ एकत्रित किया। इस विश्वकोष का उद्देश्य यह था, कि उस समय के सम्पूर्ण ज्ञान को सरल भाषा में उपस्थित किया जाय, ताकि पढ़े लिख लोग सुगमता से उन सब विषयों का ज्ञान प्राप्त कर सकें, जिन्हें जानने का उन्हें अन्यथा अवसर नहीं मिलता। दिदरो और उस के साथी किसी पर जाने नहीं करना चाहते थे। उनका विचार था, कि जहाँ तक भी हो सके, दूसरों के विषय से बचा जाय। परन्तु ज्ञान को चाहे किनने ही सरल स्वरूप में पेश किया जाय, वह बहुत से लोगों के लिये अप्रतिजनक हो ही जाता है। राज्य क्या चीज है, चर्च का प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ, जनता के क्या अधिकार हैं—इत्यादि विषयों पर यदि अच्छी तरह प्रकाश डाला जाय, तो एकतन्त्र राजाओं व विशेषाधिकार प्राप्त पुरोहितों को यह सब किस प्रकार सह्य हो सकता है? वस्तुतः, सत्य ज्ञान को सरल रूप में पेश करना ही अल्पविश्राम का और अज्ञान पर आश्रित लोगों के लिये सब में अधिक कष्टप्रद होता है। विश्वकोष के इन लेखकों ने ज्ञान का जिस प्रकार जनता के सम्मुख उपस्थित करना प्रारम्भ किया, वह राजा तथा चर्च को सह्य न हो सका। इस विश्वकोष द्वारा जनता को विचार करने के लिये सामग्री मिल रही थी। वे इस ग्रन्थ को पढ़कर स्वयं यह सोच सकते थे, कि किस मन्त्र के क्या गुण व दोष हैं? इस प्रकार विश्वकोष की यह योजना क्रान्ति की भावना को प्रादुर्भूत करने में बहुत ही सहायक थी। १७५२ में इस विश्वकोष के प्रथम दो ग्रन्थ प्रकाशित हुए। प्रकाशित होते ही राजा के मन्त्रियों ने उद्घोषित किया, कि ये ग्रन्थ राजसत्ता तथा धर्म के खिलाफ हैं, अतः इन्हें नहीं पढ़ना चाहिये। पर उस उद्घोषणा के बावजूद भी विश्वकोष के अन्य खण्ड बड़ी तेजी से प्रकाशित होते गये। ग्राहकों की मन्त्र्या बटने लगे और विश्वकोष का प्रचार तेजी से होना शुरु हुआ। पर साथ ही विरोध भी बढ़ता गया। विरोधी कहने लगे, कि यह विश्वकोष मानव-समाज और धर्म की जड़ पर कुठाराघात करनेवाला है। राजशक्ति ने फिर हस्तक्षेप किया। विश्वकोष के अब तक सात खण्ड निकले थे। उनके विक्रय को रोक दिया गया और अगले खण्डों को प्रकाशित करने का लाइसेन्स वापिस ले लिया गया। पर दिदरो ने अपना काम बन्द नहीं किया। दम नाल वाद उसने विश्वकोष के दस खण्ड और निकाले, और इस प्रकार अपने महान् ग्रन्थ का पूर्ण कर दिया। सरकारी विरोध के होने पर भी विश्वकोष की विक्री बन्द नहीं हुई।

इस विश्वकोष में एकतन्त्र राजसत्ता, धार्मिक असहिष्णुता, दास प्रथा, अन्यायपूर्ण टैक्स, सामन्तपद्धति, फौजदारी कानून आदि सभी विषयों पर विस्तार से विचार किया गया था, और इस विचार का ढग इस प्रकार था कि इन सब के दोष पाठकों के सम्मुख आ जाते थे। क्रान्ति की भावना के लिये यह ग्रन्थ बहुत ही उपयोगी था।

क्वेसने—क्वेसने लुई १५वें का राजवैद्य था। इसने उन बहुत से विद्वानों को अपने पास आश्रय दिया था, जिन्हें 'अर्थशास्त्री' कहा जाता है। ये 'अर्थशास्त्री' व्यापार, व्यवसाय और आय-व्यय आदि आर्थिक विषयों पर विचार करते थे और अपने समय की आर्थिक बुराइयों का विरोधकर सुधार की योजनाएँ पेश करते थे। इनका प्रधान सिद्धान्त यह था, कि आर्थिक जगत् में 'खुला छोड़ दो' की नीति का अनुसरण करना चाहिये। प्रकृति के

अन्य क्षेत्रों की तरह आर्थिक क्षेत्र में भी बहुत से स्वाभाविक नियम काम करते हैं। मनुष्य को चाहिये, कि उन्हें पता लगाये और उन्हीं के अनुसार अपने कार्यों को मर्यादित करे। यह स्पष्ट है, कि मनुष्यों के आर्थिक कार्यों में यदि राजा की तरफ से हस्तक्षेप होगा, तो वह प्राकृतिक नियमों के प्रतिकूल होगा। अतः राजा को चाहिये, कि 'खुला छोड़ दो' की नीति का अनुसरण करे। उस समय के राजा आर्थिक क्षेत्र में अनेक प्रकार से हस्तक्षेप करते थे। उस समय में व्यापार के मार्ग में अनेक प्रकार की बाधाएँ थी, श्रमियों के मग-ठनों के लिये अनेक प्रकार की स्कावटे थी। 'अर्थशास्त्री' लोग इन सब का जोरदार तरीके से विरोध कर रहे थे।

**छपी हुई पुस्तिकाएँ**—इन सुप्रसिद्ध लेखकों और विचारकों के अतिरिक्त अन्य भी बहुत से लोग थे, जो अपने समय के प्रश्नों और समस्याओं पर गम्भीरता के साथ विचार करने लगे थे। इस काल में समाचार-पत्र प्रकाशित नहीं होते थे। वर्तमान काल में लोकमत को उत्पन्न करने के तथा जनता को मार्ग प्रदर्शित करने का काम प्रधानतया समाचार-पत्र करते हैं। उस समय तक समाचार-पत्रों का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, पर छोटे-छोटे ट्रैक्ट व पुस्तिकाएँ बड़े परिमाण में छपने व प्रकाशित होने लग गई थी। छापाखाना यूरोप में प्रवेश कर चुका था, और हजारों की तादाद में छपे हुए पर्चे फ्रांस के बाजारों में दृष्टि-गोचर होने लगे थे। ये पर्चे लोगों की आखें खोलने लग गये थे। लोग इन्हें शौक से पढ़ते थे, और इन पर बहस करते थे। उन सब बातों पर विचार होना अब प्रारम्भ हो गया था, जिन्हें अब से पहिले विचार करने के लायक ही नहीं समझा जाता था। यह परिवर्तन क्रान्ति की भावना को उत्पन्न करने के लिये बड़ा भारी कार्य कर रहा था।

**न्यायालयों के अधिकार**—लोकमत इन छपे हुए पर्चों से केवल प्रकट ही नहीं होता था, अपितु शासन पर भी उसका प्रभाव पड़ना शुरू हो गया था। यद्यपि उस काल में कोई ऐसी लोकसभाएँ न थी, जिनमें जनता के प्रतिनिधि लोकमत को प्रकट करने का अवसर प्राप्त कर सकें, पर ऐसे साधनों का सर्वथा अभाव भी नहीं था, जिनसे राजा के स्वेच्छाचार को रोका जा सके। इस प्रकार के साधनों में सर्वप्रथम वे 'न्यायालय' थे, जिन्हें 'पार्लमा' कहा जाता था। इनका नाम ही इङ्ग्लैण्ड की 'पार्लियामेन्ट' से मिलता है, स्वरूप नहीं। ये न्यायालय सख्या में १३ थे, जिनमें सर्वप्रथम पेरिस का न्यायालय था। इनमें केवल मुकदमों का निर्णय ही नहीं होता था। इनका यह भी दावा था, और यह दावा सर्वथा उपयुक्त था कि राजा जब किसी नये कानून का निर्माण करे, तो उसे पहले इनके पास रजिस्टर्ड करने के लिये भेजे, क्योंकि जब तक कोई कानून इनके रजिस्ट्रो में दर्ज न होगा, तब तक ये उस का प्रयोग किस प्रकार कर सकेंगे? यद्यपि कानून बनाने का एकमात्र हक राजा को ही था, पर यदि ये न्यायालय किसी कानून को पसन्द नहीं करते तो उसे अपने पाम दर्ज करने के स्थान पर उसके विरुद्ध एक आवेदनपत्र राजा की सेवा में भेज देते थे। इन आवेदनपत्रों को वे केवल राजा की सेवा में ही नहीं भेजते थे, अपितु उसकी हजारों प्रतियाँ छपवाकर जनता में वितरित भी कर देते थे। इन छपी हुई प्रतियों से जनता को यह भलीभाँति ज्ञात हो जाता था, कि पार्लमा ने राजा के किस कानून का और किन आधारों पर विरोध किया है।

अब राजा पार्लमा द्वारा भेजा हुआ उस प्रकार का आवेदनपत्र प्राप्त करना था, वह उसके तान्त्रिकों को तीन माग देने थे। या तो वह पार्लमा के विरोध को स्वीकार कर अपने प्रतिपक्ष को वापिस ले ले, या उसमें उचित परिवर्तन कर दे, या पार्लमा की बैठक का अपने सम्मुख बुलाकर आने ही श्रीमन्त्र ने उसे हुसम दे, कि वह उस कानून को रजिस्टर्ड करे। इस दबाव में पार्लमा के पास अन्य कोई मार्ग न था। उसे वापिस होकर उस कानून का अपने पास दर्ज करना पड़ता था। अन्त में राजा की उच्छा ही विजयी होती थी।

पर वीर-मिरे पार्लमा ने अपनी शक्ति बटाती जान की। उसने यह भी दावा कर शर किया, कि उसकी उच्छा के विरुद्ध जो कानून दर्ज कराये जाते हैं, वे अन्त में न्याय नहीं पसन्दे जा सकते। न्याय करना तो पार्लमा के हाथ में ही था, अतः वे मजे में किसी कानून की उपेक्षा कर सकते थे।

पार्लमा की इस प्रवृत्ति का परिणाम यह हुआ, कि सर्वसाधारण जनता राजकीय मामलों में बहुत दिलचस्पी लेने लगी। योशमन का प्रतिक्रम करने में पार्लमा द्वारा प्रस्तावित आवेदन-पत्रों ने बहुत बड़ा काम किया। योंग उस व्रान पर विचार और ब्रह्म रूप लगे, कि राजा ने जो कानून जारी किये हैं, वे उचित हैं या नहीं, वे न्याय्य हैं या नहीं।

**अमेरिकन क्रान्ति का प्रभाव**—फ्रांस में तान्त्रिकी भावनाओं को उत्पन्न करने में कुछ अन्य घटनाओं ने भी बहुत सहायता की। सन् १७७६ में अमेरिकन स्वाधीनता का संग्राम लड़ा गया था। अमेरिका ने उद्बलित आधिपत्य के विरुद्ध स्वतन्त्रता प्राप्त की थी। ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त होकर अमेरिका ने अपने देश में योशमन शासन का विधान किया। क्रान्ति की भावनाओं की इस स्थूल मूर्तिमान् विजय ने सब जगह क्रान्तिकारियों के हृदयों को उत्साह से भर दिया। अमेरिकन स्वाधीनता-संग्राम में सहायता पहुँचाने के लिये हजारों की सख्या में फ्रांसीसी युवक स्वयमेवक बनकर गये थे। ये लोग अपनी आँखों से अपने स्वप्नों को क्रिया में परिणत होते देखकर अपने देश में वापिस आये थे। इनके हृदय स्फूर्ति से परिपूर्ण थे। पुराने जमाने का अन्त कर नवीन युग की स्थापना के लिये इन्हे बड़ा उत्साह था। अमेरिका की स्वाधीनता ने फ्रांस में भी नवीन भावनाएँ बड़ी तेजी से हिलोरे लेने लग गई थी।

उस समय के राजा इन नई प्रवृत्तियों से सर्वथा बेफिकर हो, यह बात नहीं थी। बखुली हुई आँखों से इन नवीन लहरों को देख रहे थे। पर इनके वास्तविक महत्व को समझने की क्षमता उनमें नहीं थी। उनका विचार था, कि कुछ मामलों से परिवर्तनों से काम चल जायगा। उन्होंने अनेक सुधार किये भी। कुलीन और पुरोहित श्रेणियों के अधिकारों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये। कानूनों में भी संशोधन हुआ। पर यह सब अपर्याप्त था। इन सबसे तो क्रान्ति की भावना और भी बलवती होती गई। इन थोड़े से परिवर्तनों से जनता सन्तुष्ट कैसे हो सकती थी? इन्होंने तो उसकी हिम्मत को और भी अधिक बढ़ा दिया। क्रान्ति की जो भावना विचारकों द्वारा प्रारम्भ की गई थी, वह निरन्तर बढ़ती ही गई और अन्त में राज्यक्रान्ति के रूप में फूट पड़ी। जिस समय सुधार तथा परिवर्तन जनता की माग व आवश्यकताओं से बहुत पीछे रह जाते हैं, उस समय क्रान्ति के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं रहता।

### ३ सोलहवें लुई का शासन

सन् १७७४ में पन्द्रहवें लुई की मृत्यु हुई। उसके शासनकाल में जो अमफल युद्ध लड़े गये थे, उनका वर्णन करने की हमें आवश्यकता नहीं है। पर इतना ध्यान में रखना चाहिये, कि इनसे फ्रांस को कोई लाभ तो हुआ नहीं था, अपितु बहुत से प्रदेश उसकी अधीनता से निकल गये थे। इतना ही नहीं, इन युद्धों में खर्च इतना अधिक हुआ था, कि फ्रांस का राजकोश सर्वथा दिवालिया हो गया था। लोगों पर टैक्सों का बोझ पहले ही इतना अधिक था, कि नये टैक्स नहीं लगाये जा सकते थे। ऐसे समय में राज्य को दिवालिया होने से बचाने का केवल एक ही उपाय था, वह यह कि खर्च में कमी की जाय। पर फ्रांस की सरकार का इस ओर जरा भी ध्यान नहीं था। उसे प्रति वर्ष पचास करोड़ के लगभग घाटा हो रहा था। राजकीय मामलों का संचालन दरबारी कर रहे थे, शासन में वैश्याओं का बड़ा हाथ था। राजा के कृपापात्र खुले हाथ कोश को लुटा रहे थे। इन भयानक दशा में फ्रांस को अनाथ छोड़कर १५वां लुई इस लोक से भ्रम के लिये विदा हो गया और उसकी जगह पर उसका लड़का सोलहवां लुई राजगद्दी पर बैठा।

**राजा १६वां लुई**—राजसिंहासन पर बैठते समय १६वें लुई की आयु केवल १६ वर्ष की थी। उसकी शिक्षा राजदरबार के विकृत वातावरण में हुई थी। उसे शिकार खेलने तथा जामोद-प्रमोद में मस्त रहने में बड़ा आनन्द मिलता था। अपनी कमजोरियों तथा जयोग्यताओं के वावजूद भी वह एक भलामानस युवक था। उसका दिल अच्छा था। यदि वह अधिक उद्योगशील तथा मजबूत होता, तो अवश्य ही अपनी प्रजा का कुछ भला कर सकता।

**उनकी रानी**—लुई का विवाह मेरी आतोआत नाम की राजकुमारी से हुआ था। उस समय में बहुत से विवाह राजनीतिक उद्देश्य से किये जाते थे। उस समय में राजा और राजवन्शों के विवाह का मतलब था, राज्यों का विवाह या सन्धि। इसी किस्म की एक सन्धि—१७५६ में हुई आस्ट्रिया और फ्रांस की सन्धि—को सुदृढ़ करने के लिये आस्ट्रियन राजकुमारी का विवाह १६वें लुई से कर दिया गया था। यह मेरी आतोआत बहुत ही उथली तथा जाराम-मनन्द स्त्री थी। उसे आचार-व्यवहार का कोई ख्याल नहीं था। राज दरबार के रीति-रिवाज तक उसकी दृष्टि में कोई महत्व न रखते थे। उसके दिल में जो जाता, वही वह करती। राजा से उसे स्नेह नहीं था, वह उसके भारी तथा जालमी तन में घृणा करती थी। उसके बहुत से कृपापात्र तथा स्नेहपात्र थे। इन्हें सहायता देने के लिये वह जो चाहती थी, करती थी। उसे उचित अनुचित का कोई विचार न था।

**तुर्जों (१७७४-१७७६)**—राजगद्दी पर बैठते ही १६वें लुई ने तुर्जों को अपना प्रधान मन्त्री बनाया। यह तुर्जों फ्रांस का सबसे योग्य अर्थशास्त्री था। वह केवल विद्वान् ही नहीं था, उसे शासन का क्रियात्मक अनुभव भी था। अपने कार्य को सँभालते ही तुर्जों ने सबसे पहले मितव्ययिता पर ध्यान दिया। वह अच्छी प्रकार अनुभव करता था कि फ्रांस को दिवालिया होने से बचाने तथा टैक्स के बोझ को हलका करने का एकमात्र उपाय

मितव्ययिता है। मितव्ययिता का सबसे उत्तम ढंग यही था, कि राजदरबार के महत् व्यय को कम किया जाय। वर्गीय में भोग-विलास और शान-शीकत पर जो भारी रकम खर्च होती थी, उसमें कमी की जाय। पर खर्च को कम करना कोई हमी खेल न था। राज दरबारी उपरि लिये कब तैयार हो सकते थे? वे जो मोज उड़ा रहे थे, उसे छोड़ना उनके लिये कैसे सम्भव था? वे रात-दिन राजा के आगमन रहते थे। उठते-बैठते, बात पीते हर समय वे राजा के साथ रहते थे। उन्हें ऐसे मौकों की कमी न थी, जब वे उन आदमी के खिलाफ—जिसे वे न चाहते हों, राजा के कान भर सकें। तूर्जा तो केवल काम काज के समय ही राजा से मिलता था। उसका प्रभाव इन दरबारियों के मुकाबल में क्या हो सकता था? तूर्जा १७७४ में अपने पद पर नियुक्त हुआ था। १७७६ में उस अपने पद से पृथक् होना पड़ा। बड़े-बड़े अमीर उसका उसके इतने विरुद्ध हो गये थे, कि उसके लिये कार्य करना असम्भव हो गया। तूर्जा के मामले बड़ी-बड़ी योजनाएँ थी। वह राष्ट्रीय ऋण को संगठित करना चाहता था, वह बजट का निर्माण वैज्ञानिक ढंग करना चाहता था। वह टैक्स की पद्धति में परिवर्तन करना चाहता था। वह व्यापार को विविध बाधाओं को हटाकर मुक्तद्वार वाणिज्य की नीति का अवलम्बन करना चाहता था। वह फ्रांस में लोकसभाओं की स्थापना करने के पक्ष में था। पर उसकी मंत्र योजनाएँ यूँ ही बरी रह गईं। तूर्जा राजा को अपनी योजनाओं को मनवाने में असमर्थ हुआ। वह १६वाँ एक निर्वल व्यक्ति था, और वह अपने दरबारियों के विरोध में कोई कार्य करने का साहस नहीं कर सकता था। निराश होकर एक दिन तूर्जा ने राजा से यह कहा—“माफ़िये यह न भूलिये, कि निर्वलता के कारण ही चार्ल्स प्रथम (इंग्लैण्ड का स्टुअर्ट राजा) का सिर धड़ से अलग किया गया था।” सोलहवें लुई ने इसका यह उत्तर दिया—“ठीक है, सारे देश में केवल दो व्यक्ति हैं, जिन्हें वस्तुतः जनता से प्यार है, तूर्जों और मैं।” पर उसने तूर्जों को अपने पद से बर्खास्त कर दिया। वह अपने दरबारियों के सम्मुख असहाय था।

**नैकर**—तूर्जों के बाद नैकर को प्रधान मन्त्री बनाया गया। यह नैकर स्विटजरलैंड का रहनेवाला था और पेरिस में महाजनी करता था। उसने बजट के आय और व्यय का समुत्तुलित करने के लिये टैक्स के तरीके में बहुत से सुधार प्रस्तावित किये और राष्ट्रीय ऋण लेने की योजना की। पर कुलीन और पुरोहित श्रेणियों को उसकी ये योजनाएँ पसन्द न आईं। असली बात तो यह है, कि सुधार के लिये जो भी वास्तविक और सच्चे प्रयत्न उस समय में किये जा सकते थे, उनसे इन विशेषाधिकार प्राप्त श्रेणियों को कुछ न कुछ हानि अवश्य ही पहुँचती थी, परन्तु ये ऐसे किसी भी प्रस्ताव का स्वागत करने के लिये उद्यत न थे, जिससे उनपर जरा भी आघात आती हो। इन लोगों ने सब तरह से नैकर का विरोध करना शुरू किया। उसे विदेशी कहकर बदनाम किया गया। उसे प्रोटेस्टेंट कहकर विधर्मी बताया गया। रानी ने उसको बर्खास्त करने के लिये बड़ा जोर दिया। परिणाम यह हुआ, कि नैकर को भी उसी राह पर जाना पड़ा, जिस पर तूर्जों गया था। पर जाने से पहले वह एक महत्त्वपूर्ण कार्य कर गया। उसने राजा को एक आवेदन पत्र लिखा, जिसमें फ्रांस की आर्थिक दशा का ठीक-ठीक विवरण दिया गया था। इस आवेदन पत्र की अस्सी हजार प्रतियाँ छपाई गईं। जनता ने इसे बड़े उत्साह तथा शोक से पढ़ा। पहली बार उन्हें